

भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास

बिपन चंद्र



22 cm
Page 214
Rs. 450/-



अनामिका प्रकाशन

..... PUBLIC LIBRARY

SLR R R L F NO .

SLR NO R R L F / ~~SEN~~ 31,619

अनामिका प्रकाशन

106 बी, एल. आई. जी., अशोक विहार III

दिल्ली 110052

Gifted By :

Raja Rammohun Roy Library Foundation

Block-DD-34, Sec-I & It Lake City,

CALCUTTA-700 064

आई. एस. बी. न. 81-85150-24-9

©बिपन चंद्र

अनुवाद : डी. आर. चौधरी

प्रथम अंगरेजी संस्करण · 1960

'दि राइज एंड ग्रोथ आफ इकनामिक

नेशनलिज्म इन इंडिया' का अनुवाद

अनामिका प्रकाशन, 106 बी, एल. आई. जी., अशोक विहार III
द्वारा प्रकाशित एवं प्रभात आफसेट प्रेस, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित।

द्वितीय संस्करण की भूमिका

मुझे खुशी है कि एक लंबे अंतराल के बाद मेरी पुस्तक का हिंदी संस्करण आखिर प्रकाशित हो रहा है। 19 वीं सदी के अंतिम पच्चीस वर्षों के दौरान, औपनिवेशिक भारत में घटित आर्थिक परिवर्तनों के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्पष्ट समझ विकसित हुई। यही नहीं, औपनिवेशिक विश्व का यह पहला आंदोलन था जिसमें भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की बड़ी प्रभावपूर्ण मीमांसा प्रस्तुत की गई और यह बताया गया कि इसका अल्पविकास और आर्थिक गतिरोध से क्या संबंध है। इस मीमांसा के आधार पर राष्ट्रवादियों ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक व्यापक आर्थिक रणनीति का विकास किया।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने यह तर्क भी दिया कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन न तो प्राक्-औपनिवेशिक अतीत से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है और न क्रूर प्रकृति अथवा जलवायु और भौगोलिक स्थिति का परिणाम है। यह तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उपनिवेशीकरण का नतीजा है। और इस पिछड़ेपन की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी भारतीय जनता की घोर गरीबी जो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्वरूप, उसके आधारभूत लक्षणों और उसकी आर्थिक क्रियाविधि के विश्लेषण का सिलसिला शुरू किया।

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सार तत्व उन तौर-तरीकों में निहित था जिनका सहारा लेकर ब्रिटेन भारत के आर्थिक अधिशेष को हड़प लेता था। पहले तो करारोपण, लूट तथा उपहार, अंग्रेजों को व्यापक स्तर पर रोजगार मुहैया कराने और एशिया तथा अफ्रीका में फैले ब्रिटिश साम्राज्य को जीतने और फिर उसपर शासन करने के लिए भारतीय सेना के उपयोग के माध्यम से वह प्रत्यक्ष रूप से उस अधिशेष को आत्मसात कर लेता था। दूसरे, मुक्त व्यापार तथा असमान विनिमय की छद्म, परोक्ष और जटिल पद्धति थी जिसने भारत को ब्रिटेन का पिछलग्गू बना दिया था : वह कच्चे माल और खाद्य सामग्री का निर्यात करता था और बने-बनाए सामान का आयात करता था। तीसरे, शोषण का नया दौर आया जिसमें आधुनिक बागानों, यातायात के साधनों, खानों, उद्योगों, बैंक, व्यापार आदि में पूंजी-निवेश को माध्यम बनाया गया।

उपनिवेशवाद द्वारा आर्थिक विकास की उपेक्षा की आलोचना करते हुए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने राज्य के प्रकायों के सिद्धांत के रूप में अहस्तक्षेप-सिद्धांत और मुक्त व्यापार की नीति पर जोरदार

हमला किया । इसके बजाय उन्होंने भारत के उद्योगीकरण में राज्य की सक्रिय भूमिका और विकास के आरंभिक दौर से गुजर रहे भारतीय उद्योगों के लिए शुल्क-दर-संरक्षण की मांग की ।

राष्ट्रवादियों ने अपनी उपनिवेशवाद-विषयक आलोचना को धन की निकासी के सिद्धांत में अंतिम रूप दिया । इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की पूरी कार्यविधि को जनता के सामने उघाड़कर रख दिया ।

हालांकि राष्ट्रवादियों ने किन्हीं नए आर्थिक सिद्धांतों की खोज नहीं की, फिर भी उन्होंने भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और उसके अल्पविकास की सुसंगत, समेकित और परस्पर संबद्ध तस्वीर पेश की । उन्होंने आर्थिक विकास के प्रति एक समन्वित दृष्टि का विकास भी किया और कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे वित्त, यातायात, विदेश-व्यापार और कृषि-क्षेत्र में वृद्धि को अपने आप में विकास का घटक मानने से इनकार कर दिया । इन सभी को संपूर्ण अर्थव्यवस्था से उनके संबंध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । इस समन्वित आर्थिक ढांचे के अंतर्गत, राष्ट्रवादियों ने यह दावा किया कि आर्थिक विकास का सार आधुनिक विज्ञान और तकनीलाजी के आधार पर तीव्र औद्योगिक विकास में निहित है ।

औपनिवेशिक अल्पविकास के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे अलग और नितांत भिन्न नीतियों को सामने रखा जो वैकल्पिक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हों ।

इन राष्ट्रवादियों के आर्थिक चिंतन की सबसे कमजोर कड़ी थी उनका कृषि-विषयक दृष्टिकोण—विशेष रूप से जमींदार-किसान संबंध की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच-पड़ताल करने में उनकी असफलता । कराधान की उच्च दर पर आधारित राजकीय लगान नीति की उन्होंने उचित ही आलोचना की । इसलिए उन्होंने जमीन पर कम लगान तय किए जाने की मांग की । किंतु कृषि-संबंधों का जो उत्तरोत्तर सामंतीकरण या जमींदारीकरण हो रहा था उन्हें महत्व देने में अधिकतर राष्ट्रवादी असफल रहे ।

कुछ अपवादों को छोड़कर आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेशी पूंजी के प्रवेश का विरोध किया क्योंकि इसमें आर्थिक निर्भरता और प्रभुत्व के और बढ़ जाने का खतरा था । भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की भूमिका के बारे में उन्होंने बहुत गहरी समझ विकसित की । उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि वास्तविक आर्थिक विकास तभी संभव है जब मुख्यतः देशी पूंजी पर निर्भरता रहे ।

परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी गतिविधियों और आर्थिक चिंतन का गठन उसी ढांचे के अंतर्गत करना था जिसे उन्नीसवीं सदी में उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रवादियों ने विकसित किया था । फिर आगे चलकर हमारे स्वतंत्र राज्य के संस्थापकों ने जो आर्थिक रणनीति अपनाई उसपर भी इस ढांचे का भारी प्रभाव पड़ना था ।

आधुनिक राष्ट्रवादी चिंतन का राजनीतिक प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण रहा । आरंभिक राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासकों और भारतीय जनता के हितों में निहित मूलभूत अंतर्विरोध को भी उजागर किया । आर्थिक मुद्दों पर उनके आंदोलन ने भारतीय जनमानस पर औपनिवेशिक शासकों के वैचारिक प्रभुत्व को अंदर-ही-अंदर कमजोर किया । जिन कारकों ने भारत पर ब्रिटिश शासन संभव बनाया उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे

हैं । यह विचार बड़ी सावधानी से विकसित किया गया था । राष्ट्रवादी आर्थिक आंदोलन ने धीरे-धीरे, कदम-दर-कदम, एक-एक मुद्दे पर विचार करते हुए इस विश्वास की जड़ काट दी और ब्रिटिश शासन के नकारात्मक, शोषक और अल्पविकासमूलक चरित्र को उजागर किया । ब्रिटिश शासन के मूल उद्देश्य और चरित्र में यह अविश्वास कालांतर में राजनीतिक क्षेत्र में भी फैलना था और विश्व के अत्यंत सशक्त साम्राज्यवाद-विरोधी जन-आंदोलन को जन्म देना था । आरंभिक राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन की बड़ी ही मजबूत आधारशिला रखी ।

बिपन चंद्र

आमुख

यह पुस्तक 'भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व की आर्थिक नीतियाँ (1880 से 1905)' शोध प्रबंध का संशोधित रूप है, जो 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० की उपाधि के लिए स्वीकार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऊँचे और भिन्न स्तर तक ले जाए जाने से पहले राष्ट्रीय नेताओं की जो आर्थिक नीतियाँ रहीं, उन्हीं की जाँच करना इस पुस्तक का उद्देश्य है।

मैंने उन सभी व्यक्तियों को नेता माना है जिन्होंने आर्थिक प्रश्नों पर उभर रहे राष्ट्रीय जनमत को बनाने और दिशा देने का कार्य किया। इसी तरह मैंने इस अध्ययन में न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रांतीय सम्मेलनों, दूसरी लोक संस्थाओं एवं विधान परिषदों की कार्यवाहियों तथा प्रमुख राष्ट्रवादी व्यक्तियों के व्याख्यानों तथा रचनाओं पर, अपितु उन राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं पर भी निर्भर किया है जो उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य मंच और जनमत के प्रभावशाली निर्माता थे। वास्तव में उस समय निरंतर क्रियाशील और सुसंगठित किसी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के अभाव में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तब तक इस प्रकार का संगठन नहीं बन पाई थी, और तब तक विशाल और आम सभाओं की परंपरा भी नहीं प्रारंभ हुई थी, राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने ही दैनंदिन प्रशासन में विरोध पक्ष की भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रस्ताव तथा उनकी कार्यवाहियाँ भी मात्र जितना राष्ट्रवादी समाचारपत्रों के माध्यम से छनकर जनता तक पहुँच पाती थी उसी सीमा तक जनमत को बनाने में समर्थ हो पाती थीं। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय की बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं को उनके मालिक और संपादक व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वयं कुछ हानि उठाकर भी राष्ट्रवादी पत्र के रूप में निकालते थे। इतना ही नहीं बहुत से संपादकों का शहरी निम्न मध्यवर्गीय जीवन से घनिष्ठ संबंध था।

मैंने अंगरेजी या आंग्ल भाषा में प्रकाशित तत्कालीन अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं का जिनमें 'मराठा', 'हिंदू', 'अमृत बाजार पत्रिका', तथा 'बंगाली' सम्मिलित हैं मूल रूप में अध्ययन किया है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के

अध्ययन के लिए मैंने विभिन्न प्रांतों के लिए अप्रकाशित 'रिपोट्स आन द नेटिव प्रेस' का उपयोग किया है। 'रिपोट्स आन दि नेटिव प्रेस' में भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणियों व लेखों का साप्ताहिक संधिपत्र या पूर्ण विवरण सरकार द्वारा दिया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक, जब से कि इन रिपोर्टों में भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले समाचारपत्रों की सामग्री का भी समावेश किया जाने लगा, बंबई रिपोर्ट में अंगरेजी और भारतीय भाषाओं दोनों के समाचारपत्रों की सामग्री रहती थी, जबकि अन्य प्रांतों की रिपोर्टों में केवल भारतीय भाषाओं के पत्रों की। ये रिपोर्टें पूर्ण रूप से गोपनीय थीं और केवल डिवीजनल कमिश्नर या इससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों को ही उपलब्ध होनी थीं। उनमें सामग्री के निष्पक्ष एवं सही पुनः प्रस्तुतीकरण में उच्च स्तर का निर्वाह किया जाता था, हालांकि कुछ रिपोर्टों, विशेषकर मद्रास की रिपोर्ट के विवरण पर्याप्त नहीं रहते थे।

प्रस्तुत कृति में उन नमाम व्यक्तियों, संस्थाओं और पत्र-पत्रिकाओं को राष्ट्रीय माना गया है जिन्होंने भारत को एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में देखा, जहां के लोगों के हित एवं नियति व्यापक अर्थ में साझे थे, जिनका अंतिम लक्ष्य अपने लोगों के लिए स्वशासन प्राप्त करना था और जिन्होंने सामाजिक विषयों पर मुट्ठी भर लोगों के दृष्टिकोण को अपनाने की बजाय देश की समस्त या अधिकांश जनता के दृष्टिकोण में मोचने की चेष्टा की। इस विषय में वसोटी इस बात को माना गया है कि वे क्या दावा करते थे, न कि इस बात को कि वे व्यवहार में क्या चाहते थे। इस दूसरे पहलू का शोध प्रबंध के मुख्य भाग में विस्तार से विश्लेषण किया गया है। दूसरे शब्दों में मैंने केवल उनको राष्ट्रीय नेता नहीं माना है जिन्होंने खुद-आम भारत को एक राष्ट्र या इस की जनता के साझे राजनीतिक भाग्य को मानने में इनकार किया, या उन्हें जो खुल्लमखुल्ला थोड़े से लोगों के प्रतिनिधि बन कर सामने आए। इस प्रकार मैंने हिंदू-मुस्लिम और पारसी मप्रदायवादियों तथा 1888 के बाद के 'रामन गणतंत्र' और 1901 के बाद के 'हिंदुस्तान जैसे समाचारपत्रों' का छोड़ दिया है। 'दि ब्रिटिश इंडिया एगोसिएशन' तथा 'हिंदू पेट्रियट' को भी छोड़ दिया है क्योंकि 1881 तक वे अपना मौलिक राष्ट्रीय स्वरूप खो चुके थे और खुलकर जमींदारों के हितों की वकालत करने लगे थे।

इस अध्ययन में मेरी मंच इस बात में उतनी अधिक नहीं रही है कि किसी आर्थिक विचारधारा या नीति के जन्मदाता कौन थे जितनी कि उसके प्रचारको तथा प्रचार की सीमा और उसके पीछे चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के परिमाण और प्रकार में। पाद टिप्पणियों में बहुत से नेताओं एवं समाचारपत्रों का हवाला इसलिए दिया गया है ताकि इस प्रयत्न में उस काल में व्यापक रूप से प्रचलित कुछ नीतियों को प्रकाश में लाया जाए। इसी प्रकार मैंने यह जानने की चेष्टा नहीं की है कि अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार उक्त राष्ट्रवादी रुख और नीतियां सही थी या नहीं। मैंने अपने आप को इस बात तक ही सीमित रखा है कि राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा और कैसे कहा तथा हम इससे उनकी आधारभूत आर्थिक और राजनीतिक समझ तथा दृष्टिकोण के बारे में क्या जान सकते हैं। उपर्युक्त पहले कार्य को करने के लिए तो उस काल के भारत का एक गृह

आर्थिक इतिहास ही लिखना पड़ेगा और सभवतः इससे भी बहुत कुछ अधिक करना पड़ेगा। मैंने समकालीन आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए गीण स्रोतों का उपयोग किया है।

निश्चय ही यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रवाद के साम्प्रदायिक आधार के बारे में नहीं है जिसके मूल में वर्ग तथा दूसरे मानवीय संबंध होते हैं बल्कि यह इसके सैद्धांतिक कार्यक्रम संबंधी पहलुओं के बारे में है। यो पहले को जाने बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि प्रारंभिक राष्ट्रीय नेताओं के मानस में पड़े आर्थिक यथार्थता के प्रतिबिम्ब का यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि यद्यपि सामाजिक संबंधों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं फिर भी इन संबंधों के बारे में लोगों की समझ उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधि के लिए निर्णायक होती है। इस प्रकार किसी आंदोलन के द्वारा यथार्थ को समझने, इसके लक्ष्यों का निर्धारण करने और सही दिशा में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले राजनीतिक एवं बौद्धिक साधनों का अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना कि आंदोलन को जन्म देने वाली सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों का अध्ययन। अतः यह अध्ययन औपनिवेशिक आर्थिक संबंधों के विकास या भारत की आधुनिक आर्थिक शक्तियों या वर्गों के उदय की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करता। हमारी समस्या 1880 में 1905 के बीच भारत में 'अंगरेजी साम्राज्यवाद के आर्थिक आधार एवं नीतियों की राष्ट्रीय बोध शक्ति के क्रमिक विकास के साथ साथ एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए एक वैकल्पिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास का अध्ययन करना रही है। मुझे आशा है कि मैं उप-परिणाम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अवदूतों की बौद्धिक क्षमता के स्तर और उनकी राजनीतिक एवं बौद्धिक ईमानदारी तथा साहस को प्रकाश में लाने में भी सफल हुआ हूँ। प्रस्तुत अध्ययन में उद्धरणों की अधिकता के मूल में राष्ट्रीय आर्थिक आंदोलन के प्रकार तथा विशेषता को सही-सही रूप में प्रकाश में लाने की इच्छा ही निमित्त कारण रही है। प्रायः राष्ट्रीय नेताओं का किसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का तरीका उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि स्वयं वह दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त उसे मूल रूप में प्रस्तुत करने से उनके अर्थशास्त्रीय ज्ञान का स्वरूप भी और अधिक अच्छी तरह सामने आ जाता है। हर हालत में, जैसा कि विस्टन चर्चिल ने कहा है 'मौके पर कही गई एक बात बाद में कही गई हजार बातों के बराबर होती है'।

मैं अपने उन बहुत से मित्रों का अत्यधिक आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य में मेरी सहायता की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डा० विशेश्वर प्रसाद का मैं कितना ऋणी हूँ, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अध्ययन का आरंभ मैंने पूर्णतः उनके प्रोत्साहन से ही किया। मुझे विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए उन्होंने धैर्य व प्रेमपूर्वक मेरा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने उदारतापूर्वक इस अध्ययन का प्राक्कथन लिखने की भी कृपा की है। उनकी निरंतर बहुमूल्य समालोचना और सुझावों के बावजूद इसमें यदि बहुत सी गलतियाँ रह गई हों तो उसका एकमात्र कारण मेरे अपने ज्ञान की अपूर्णता है। मोहित सेन, बी० एम० भाटिया, सुलेख

गुप्ता, ओ० पी० कौशिक और सब्यसाची भट्टाचार्य जैसे मित्रों ने पांडुलिपि के अंशों को पढ़ा है और बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मैं अपनी 1961-63 की एम० ए० कक्षा का ऋणी हूं साथ ही विशेषकर श्री अजितकुमार सूद का भी, जिन्होंने शोध प्रबंध के अंतिम रूप से टंकण संबंधी अनेक छोटे-मोटे कार्य किए तथा मेरे साथ लगातार धैर्यपूर्वक विचार-विमर्श किया।

मैं अपने कालेज, हिंदू कालेज, के अधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे दो वर्ष के अध्ययन के लिए अवकाश दिया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे राकफेलर फाउंडेशन द्वारा इतिहास विभाग को दिए गए अनुदान में से शिक्षावृत्ति प्रदान की।

मैं इस अवसर पर हिंदू कालेज पुस्तकालय (दिल्ली), दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी (दिल्ली), दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स लाइब्रेरी (दिल्ली), सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी (नई दिल्ली), पालियामेंट लाइब्रेरी (नई दिल्ली), इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स लाइब्रेरी (नई दिल्ली), एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी (बंबई), गोखले इंस्टिट्यूट आफ इकनामिक्स ऐंड पालिटिक्स (पूना), फरगुसन कालेज लाइब्रेरी (पटना), इंडियन एमोसिएशन लाइब्रेरी (कलकत्ता), और सघरना ब्राह्मो समाज लाइब्रेरी (कलकत्ता) के पुस्तकालयों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा। स्व० श्री हेमन्त प्रसाद घोष ने मुझे पुस्तकों, पेम्फलेटों व समाचारपत्रों की कतरनों के निजी संग्रह को प्रयोग करने की आज्ञा दी, श्री एच० सी० मित्रा ने अपने घर पर 'डान' पत्रिका को पढ़ने, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', व 'केसरी मराठा' ट्रस्ट के प्रबंधकों ने इन समाचारपत्रों की पुरानी फाइलों को देखने तथा कायस्थ सभा इलाहाबाद के अधिकारियों ने 'हिंदुस्तान रिव्यू' और 'कायस्थ समाचार' की पुरानी फाइलों के प्रयोग करने की आज्ञा दी। मैं विशेष रूप से इन सबका आभारी हूं। मैं नेशनल आरकाइवज आफ इंडिया नई दिल्ली और नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बिना किसी मंकोच के अपना सहयोग दिया।

अंत में मैं अपनी धर्मपत्नी ऊषा चंद्र को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा करने में हर चरण पर मुझे बहुमूल्य सहायता दी। उन्होंने पांडुलिपि के हर पन्ने को पढ़ा, कीमती सुझाव दिए, आवश्यकता पड़ने पर मुझे प्रोत्साहन दिया तथा टाइप व प्रूफ-प्रति को ठीक करने में मेरी सहायता की। वास्तव में यदि भाषा एवं छपाई की कोई गलतियां इस पुस्तक में रह गई हों तो इसके लिए मेरे साथ वह भी जिम्मेवार हैं।

बिपन चंद्र

अनुक्रम

अध्याय 1 भारत की निर्धनता	1
क्या भारत दरिद्र था / 4	
दरिद्रता का प्रमाण / 7	
क्या दरिद्रता बढ़ रही थी / 11	
दरिद्रता के कारण / 18	
अध्याय 2 औद्योगिक विकास : एक	51
स्वदेशी उद्योग-धंधों का ह्रास / 51	
आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन / 56	
पूंजी की कमी / 60	
तकनीकी शिक्षा / 61	
उद्यम की भावना / 63	
अध्याय 3 औद्योगिक विकास : दो	82
विदेशी पूंजी की भूमिका / 82	
राज्य की भूमिका / 93	
स्वदेशी / 98	
अध्याय 4 विदेश व्यापार	126
राष्ट्रीय दृष्टिकोण / 127	
विदेश व्यापार के लाभ / 130	
अनाजों का निर्यात / 138	
निष्कर्ष / 141	
अध्याय 5 रेलों की भूमिका	152
संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा / 152	
रेल विस्तार की गति: राष्ट्रवादी दृष्टिकोण / 156	

रेलों का आर्थिक प्रभाव /	157
ब्रिटिश उद्देश्य /	163
भारतीय कसौटी /	165
संगठन का स्वरूप /	168
रेलें बनाम सिंचाई /	171
निष्कर्ष /	175

अध्याय 6 शुल्क पद्धति

193

कपास आयात शुल्क की समाप्ति, 1878-82 /	193
कपास आयात शुल्क की समाप्ति का राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध /	196
राजनीतिक अर्थ /	198
आयात करों का पुनः आरोपण /	201
1894 और 1896 के कर और कपास शुल्क अधिनियम /	203
राजनीतिक प्रभाव /	208
1899 का चीनी आयात शुल्क /	211
चीनी शुल्क अधिनियम, 1902 /	218
विभिन्न प्रकार के प्रश्न /	219
निष्कर्ष /	221

अध्याय 7 मुद्रा और विनिमय

241

सरकारी मुद्रानीति /	242
भारतीय नेतृत्व की प्रारंभिक प्रतिक्रिया /	245
राष्ट्रवादियों द्वारा मुद्रा परिवर्तन का विरोध /	246
निम्न विनिमय के लाभ /	248
भारतीय वित्त में विनिमय की भूमिका /	249
रुपये की मूल्यवृद्धि के हानिप्रद प्रभाव /	254
राजनीतिक आशय /	258
विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता /	259
निष्कर्ष /	264

अध्याय 8 श्रमिक वर्ग का उदय

286

फैक्टरी ऐक्ट और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, 1881 /	289
1891 का फैक्टरी ऐक्ट और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया /	295
भारतीय खान अधिनियम, 1901 /	302
राष्ट्रवादी नीति का आधार /	304
1882 का बागान श्रम और अंतर्देशीय उत्खनन अधिनियम /	307
उपाय /	313
असम श्रम और उत्खनन अधिनियम, 1901 /	314
मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 1903 /	315
व्यापक संबंध /	315
जी. आई. पी. रेलवे सिगनल वालों की हड़ताल /	318
नए दृष्टिकोण का प्रारंभ /	322

अध्याय 9 कृषि का विकास : एक

349

- भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य / 350
- बुराइयाँ / 352
- उपचार / 355
- भूराजस्व का स्थाई बंदोबस्त / 359

अध्याय 10 कृषि का विकास : दो

387

- किसान और जमींदार / 387
- 1885 का बंगाल टेनेसी ऐक्ट / 392
- पट्टेदारी संबंधी कानून, 1880-1905 / 402
- किसान और साहूकार / 404
- दकन खेतिहर सहायता अधिनियम, 1879 / 406
- धरती के संक्रमण पर प्रतिबंध / 408
- वैकल्पिक उपचार / 412
- पूंजीनिष्ठ खेती / 413
- कृषि और उद्योग / 417

अध्याय 11 लोकवित्त : एक

442

- कराधान / 444
- कराधान के कारण अन्याय / 451
- भारतीय दृष्टिकोण के कुछ पक्ष / 452
- राजस्व के स्रोत / 453
- आय कर / 453
- राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आशय / 461
- नमक कर / 463
- नमक कर पर गद्दूआदियों के प्रभार के कारण / 467
- कराधान के वैकल्पिक साधन / 470
- राजनीतिक सीख / 472
- निष्कर्ष / 473
- उत्पाद राजस्व / 474
- अफीम से प्राप्त होने वाला राजस्व / 477

अध्याय 12 लोकवित्त : दो

512

- व्यय / 512
- सैनिक व्यय / 517
- ऊँचा सैन्य व्यय तथा सुझाए गए उपाय / 520
- अमैमिक व्यय / 528
- ब्रिटेन और भारत के बीच व्यय-विभाजन / 535
- कल्याणकारी कार्यों में व्यय / 536
- सरकारी कोश पर लोकप्रिय भारतीय नियंत्रण / 542

अध्याय 13 धन की निकासी

572

निकासी की संगणना / 577

निकासी का उद्भव / 580

निकासी के आर्थिक प्रभाव / 582

निकासी में कटौती / 594

निकासी सिद्धांत में विश्वास न रखनेवाले कुछ भारतीय / 595

निकासी सिद्धांत के आलोचक / 597

राजनीतिक आशय / 605

अध्याय 14 भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था

636

राज्य की भूमिका / 640

भूमि लगान : कर अथवा किराया / 643

उन्मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण / 645

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें / 649

अध्याय 15 आर्थिक राष्ट्रवाद

660

भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप और उद्देश्य का विश्लेषण / 660

आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध / 665

ग्रंथसूची

680

अनुक्रमणिका

691

अध्याय 1

भारत की निर्धनता

‘यदि यह सिद्ध किया जा सके कि अंगरेजी शासनकाल में भारत भौतिक संपन्नता की दृष्टि से पहले की तुलना में और अधिक पिछड़ गया है—तो इसे मैं आत्मनिंदा मानने को एकदम तैयार हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस स्थिति में हमें भारत को अपने नियंत्रण में रखने का कोई अधिकार नहीं।’ जार्ज हेमिन्टन, भारत सचिव

‘भारत की घोर दरिद्रता इतनी अधिक उद्देगजनक है कि किसी भी अन्य देश की सरकार इस प्रकार की स्थिति में इस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक सोचने को विवश होती, अन्यथा देश में क्रांति हो गई होती।’ जनरल आफ पूना सावर्जनिक सभा¹

1857 के विद्रोह के तत्काल बाद की दशाब्दियों में शिक्षित भारतीयों, पनपती, राष्ट्रीय भावना के उभरते नेताओं, की यह एक आम धारणा थी कि भारत में अंगरेजी शासन जनता के लिए काफी लाभदायक था। किंतु समय के बीतने पर और राजनीतिक चेतना तथा गतिविधि के बढ़ने के परिणामस्वरूप इन लाभों के महत्व तथा इनकी उपयोगिता में संदेह किया जाने लगा यद्यपि लगभग हमारे अध्ययन काल (1880-1905) तक भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का एक वर्ग अंगरेजी प्रभाव में इस देश में आई कानूनी, सांविधानिक तथा अन्य भौतिकेतर परिणतियों को न केवल वांछनीय ही मानता था अपितु उन्हें अभि-स्वीकार भी करता था।² सामान्य रूप से यह धारणा बढ़ती गई कि आर्थिक दृष्टि से अंगरेजी शासन का परिणाम निराशाजनक ही नहीं प्रत्युत कदाचित् हानिकारक भी था। 1867 में दादाभाई नौरोजी पहले ही कह चुके थे, ‘जनसमूह आज तक अंगरेजी शासन के लाभों को समझ ही नहीं पाया है।’³ 1871 में उन्होंने लिखा—‘देश निरंतर दरिद्र तथा पंगु बनता जा रहा है।’⁴ 1865-66 में उड़ीसा में पड़े अकाल के साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में⁵ भारत में पड़े दुर्भिक्षों की श्रृंखला ने देश को इस बुरी तरह से जकड़ा कि उसके भयंकर परिणाम ने अंगरेजों द्वारा स्वतः प्रस्तुत विदेशी शासन में शांतिपूर्वक तथा सामान्य गति से उन्नतिशील भारत के चित्र को भ्रकभोर कर रख दिया और साथ ही

विबश प्रजा की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए शासकों को विबश कर दिया ।⁸

प्रारंभ में बहुत से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि उनके शासक और ब्रिटिश जनता भारत की यथार्थ स्थिति से अपरिचित है ।⁹ अतएव वे ब्रिटिश जनता, संसद तथा प्रशासकों को वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए एवं समस्याओं की विषमता के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए देश की सही स्थिति की पूरी जांच-पड़ताल कराना चाहते थे ।¹⁰ इसके अतिरिक्त उनकी इच्छा थी कि भारतीयों की वर्तमान आर्थिक स्थिति अवश्य ही अपने सही रूप में जाची तथा आकी जाए और इस संदर्भ में भारतीयों की आर्थिक स्थिति की यथार्थ आवश्यकताओं को भी उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाए ताकि शासक प्रभावशाली ढंग में इसे समझ सकें और सुधार के सर्वोत्तम ढंग निकाल सकें ।¹¹ इसके अलावा भारतीय, अपनी एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना के प्रति सजग होकर, भारत में समकालीन ब्रिटिश अर्थनीतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी निश्चित करना चाहते थे । इससे पूर्व भारतीयों का इन नीतियों के प्रति दृष्टिकोण तथा राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में उनकी कार्यनीति ब्रिटिश नीतियों के मूल्यांकन और उनके आर्थिक परिणामों से ही प्रभावित होती थी ।¹²

1870 में भारतीय नेताओं ने अपने देश की आर्थिक बुराईयों की गहरी छानबीन आरंभ की । 27 जुलाई 1870 को दादाभाई नौरोजी ने कला-परिषद लंदन की बैठक में अपना प्रसिद्ध लेख 'भारत की आवश्यकताएं और साधन' पढ़ा ।¹³ इस लेख में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया : 'क्या इस समय भारत अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन की स्थिति में है ?' और फिर इसका उत्तर उन्होंने नकारात्मक दिया ।¹⁴ 1873 में अल्पजीवी बंगाली त्रैमासिक 'मुखर्जी मँगजीन' के पृष्ठों में भोलानाथ चंद्र ने भारत में अंगरेजों की आर्थिक नीति पर घातक प्रहार किया ।¹⁵ 1876 में दादाभाई नौरोजी ने अपना 'दी पावर्टी आफ इंडिया' नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया ।¹⁶ 1870 के अंत में महादेव गोविन्द रानाडे ने पूना में 'सार्वजनिक मभा' त्रैमासिक पत्रिका निकाली तथा जी० वी० जोशी के साथ लगभग दो दशान्दियों तक भारतीय अर्थनीति का और व्यावहारिक रूप में उसके सभी अंगों का अत्यंत सजीव और सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया ।¹⁷ सत्य तो यह है कि सामयिक विषयों पर लेख लिखनेवाले प्रत्येक तत्कालीन भारतीय ने भारत की आर्थिक स्थिति पर या तो लेख अथवा पुस्तकें लिखी, अथवा इस विषय पर सार्वजनिक मंच में या 'चैंबर आफ कोमिल' में भाषण दिए । इस प्रकार व्यावहारिक रूप से उस समय के राजनैतिक क्षेत्र का सारा साहित्य प्रधान रूप में आर्थिक विषयों से ही संबंधित था । 1901-1903 में आर० सी० दत्त के दो खंडोंवाले बहुमूल्य ग्रंथ 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' ने इन छानबीनों को अपने चरम शिखर पर पहुंचा दिया । उपर्युक्त ग्रंथ अंगरेजी राज्य में भारतीयों के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा आर्थिक स्थिति आदि के दृष्टिहान को प्रस्तुत करने के विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कर्तव्यपालन के रूप में ही लिखा गया था । वस्तुतः उस समय पराधीन भारत की आर्थिक दुर्दशा की गाथा का वर्णन करना तथा भारतीयों की दरिद्रता के गहरी जड़ पकड़े हुए कारणों का विश्लेषण करना कर्तव्य कर्म ही था ।¹⁸

भारतीयों की जांच-पड़ताल के आगे बढ़ते ही उनके कष्टों की सूची अधिकाधिक लंबी होने लगी। आर्थिक स्थिति को काले-घुघले रंग में रंगा जाने लगा और यह विश्वास फैल गया कि भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत की अभूतपूर्व समृद्धि की चर्चा तथा भारत को गण्य-मान्य समृद्ध देश बनाने का आदर्श वाक्य सत्य से कोसों दूर है।¹⁹ शीघ्र ही दरिद्रता का विषय भारत की सभी आर्थिक समस्याओं की चर्चाओं पर हावी होने लगा और भारतीय नेता इस विषय को सर्वोच्च महत्व प्रदान करने लगे। दादाभाई नौरोजी ने इसे एक ऐसी गिला, एक ऐसा तत्व तथा एक ऐसी कसौटी बताया जो अपने निपटारे में या तो ब्रिटेन को भारत के लिए वरदान बना देगी अथवा ईश्वर जाने कौन सी भयंकर विपत्ति उपस्थित करेगी।¹⁸ इस दरिद्रता को अनेकों ने इस प्रकार से परिभाषित किया : 'आज की बहुत बड़ी समस्या'²⁰, 'सभी प्रश्नों का प्रश्न'²¹, 'भारत की समग्र आर्थिक दुर्दशा की मूल व्याप्ति'²², 'सर्वोच्च समस्या'²³। 1901 में आर० सी० दत्त ने लिखा था, 'मेरे विचार में ब्रिटिश राज्य के किसी प्रदेश में कोई भी प्रश्न भारत की वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक विषम नहीं।'²⁴ जबकि उग्रवादी दल के एक प्रवक्ता विपिनचंद्र पाल ने उसी वर्ष अपने संघर्षपरक साप्ताहिक 'न्यू इंडिया' के प्रथम अंक में ही लिखा : 'मेरे विचार में नौरोजी भारत को व्यग्र बनानेवाली सभी उलझनभरी समस्याओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक संपीड़क आर्थिक समस्या है।'²⁵ न्यायाधीश रानाडे ने 1892 में अपने 'इंडियन पोलिटिकल इकोनामी' निबंध में राजनैतिक प्रश्नों की अपेक्षा आर्थिक समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था।²⁶ अपने जन्मकाल से ही राजनीति में 'उग्रवादी' तथा 19वीं शताब्दी के प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय समाचार पत्र 'अमृत-बाजार पत्रिका' ने 2 जुलाई 1885 के अंक में लिखा : 'सत्य तो यह है कि यदि भारतीयों को केवल भरपेट भोजन और कुछ अश्वों में न्याय ही उपलब्ध हो सके तो वे सन्तुष्ट होकर अंगरेजी राज्य के अधीन रहने को तैयार हैं।'²⁷ भारतीय नेता भारत में अंगरेजी शासन के सभी कृत्य इस कसौटी पर परखते थे कि²⁸ वे करोड़ों भारतीयों की दशा को किस रूप में प्रभावित करते हैं? और क्या देश की प्रगति अंततः देश की आर्थिक स्थिति में किसी भी रूप में सुधार लाती है?²⁹

भारत में अंगरेज अधिकारी भी भारतीयों द्वारा निर्धनता की समस्या को सर्वोच्च महत्व देने के प्रति जागरूक थे और उन्होंने इस चुनौती को अपने प्रशासन की सफलता के मापदंड के रूप में स्वीकार किया। तदनुसार 15 अगस्त 1894 को 'हाउस आफ कामंस' में भारत सचिव सर हेनरी फीलर ने कहा :

'मैं इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ कि सरकार ने भारत में विद्यमान अपने सारे शासन-तंत्र के साथ भारत की सामान्य समृद्धि को बढ़ावा दिया है या नहीं और भारत ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक प्रांत के रूप में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है अथवा बुरी? : यही एक मापदंड है।'³⁰

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयतावाद के प्रारंभिक काल में निर्धनता की समस्या भारतीय राजनैतिक मंच का केंद्रबिंदु बनी रही। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रवक्ताओं और उभरते भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने केवल इसी एक समस्या पर दीर्घ काल तक बहस

चलाई। तत्कालीन परिस्थिति में लोगों की रुचि का अन्य कोई भी ऐसा विषय न था जिसके बारे में शासक और शासित के विचारों में इतना गहरा मतभेद रहा हो और ऐसा बाद-विवाद भी किसी अन्य विषय पर कम हुआ होगा, जिसने इससे अधिक क्रोध तथा तीव्र निंदा को उकसाया हो।³¹

क्या भारत दरिद्र था

इस गंभीर विवाद का प्रथम पक्ष निर्धनता के अस्तित्व का प्रश्न था। दादाभाई नौरोजी भारत में व्याप्त अपरिमित निर्धनता के अस्तित्व का उद्घोष करनेवाले प्रथम गण्य-मान्य नेता थे। उन्होंने 1876 में अपने निबंध 'पावर्टी इन इंडिया' में घोषणा की : 'भारत कई प्रकार से गंभीर रूप से विपन्न है और दरिद्रता में दबा हुआ है।'³² बहुसंख्यक भारतीय जनता को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उपयुक्त साधन प्राप्त नहीं हैं।³³ उन्होंने दरिद्रता को अपना 'विशिष्ट विषय'³⁴ बनाया तथा अपने 'जीवन के लक्ष्य', भारत की वास्तविक स्थिति के प्रति अंगरेजी जनता को जगाना, की पूर्ति के लिए वर्षों तक सारे इंग्लैंड में अभियान जारी रखा।³⁵ वृद्धावस्था के साथ यह महान वृद्ध पुरुष (ग्रैंड ओल्ड मैन) कोमल होने की अपेक्षा अधिकाधिक उग्र बनते गए तथा कठोर शब्दों का ही नहीं प्रयुक्त हिंसापरक भाषा का भी प्रयोग करने लगे। 1881 में उन्होंने 'भारत की दुर्भाग्यग्रस्त हृदय-विदारक तथा खून खौलानेवाली स्थिति' की भर्त्सना की³⁶ और दुखी भाव में उन्होंने कहा, 'इस समय जहां तक अंगरेजी भारत का संबंध है, उसमें आज प्राच्य वैभव की बात आलंकारिक वर्णन अथवा एक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।'³⁷ 1895 में उन्होंने घोषित किया : 'भारत भूखा मर रहा है, अपर्याप्त भोजन पर रहने को विवश भारतवासी हल्के से घबके में भी मरने की स्थिति में हैं।'³⁸ 1900 में उन्होंने कहा, 'सत्य यह है कि भारतवासी एक प्रकार के दाम हैं। उनकी दशा अमरीकी दामों से भी बुरी है क्योंकि अमरीकी दामों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो करते हैं।'³⁹

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 में इस प्रश्न को उठाया और शीघ्र ही भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को अपने कार्यक्रम का एक अंग बना लिया।⁴⁰ 1891 में अपने सातवें अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया : 'पूरी पांच करोड़ जनता, जिसकी संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है—एक शोचनीय स्थिति में घंसी हुई मुखमरी के कगार पर खड़ी है और प्रति दशवर्ष लाखों व्यक्ति सचमुच ही मुखमरी के कारण मृत्यु का प्रास बनते हैं।'⁴¹ यह प्रस्ताव प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन में बराबर दोहराया जाने लगा।⁴² परवर्ती कांग्रेस सभापतियों ने निर्धनता की समस्या को अपने वार्षिक भाषणों का अनिवार्य भाग बनाते हुए ही उनका उपसंहार किया।⁴³ राष्ट्रवादी लेखकों और वक्ताओं ने तो निर्धनता को अपनी रुचि का विषय ही बना लिया।⁴⁴ उदाहरणार्थ 1881 के प्रारंभ में ही एक अनाम लेखक ने 'जरनल आफ दी पूना सार्वजनिक सभा' में घोषित किया, 'भारत की उजागर घोर दरिद्रता इतनी अधिक उद्देगजनक है कि किसी भी अन्य देश की सरकार इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार न करने की स्थिति में क्रांति का सामना करने को विवश होती।' ⁴⁵ भारत का प्रेस भी निरंतर प्रतिदिन, प्रतिस्पन्दाह भारत की आर्थिक

दुर्दशा तथा दुर्भाग्य के रोने को वाणी देता रहा।⁴⁶ भारतीयों की स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया गया - 'दुर्भाग्यपूर्ण', 'गंभीर', 'शोचनीय', 'दयनीय' तथा 'निरीह जंतुओं से भी सर्वथा हीन और विकृत'। भारतीयों को इस रूप में चित्रित किया गया 'भुखमरी से अर्धमृत', 'जीव मात्र अवशिष्ट', 'साक्षात् रेंगती, मिमियाती तथा लुढ़कती दरिद्रता'।⁴⁷ कुछ समाचारपत्रों ने भारतीय दरिद्रता का सजीव चित्र पेश किया। उदाहरणार्थ बंगला पत्र 'सुलभ दैनिक' ने भारतीय नागरिक की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया -

'वह अपनी जीवनशक्ति खो चुका है, वह अपना प्राणतत्व नष्ट कर चुका है। उसका रक्त चूस लिया गया है और अर्थनीति की दृष्टि से देखा जाए तो वह वास्तव में हड्डियों का ढांचा मात्र होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह आधा भूखा है, आधा नगा है। उसका दैनिक आहार थोड़े से चावल और बहुत से कदमूल तथा पौधों के पत्तों हैं। उसने जीवन में कभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं लिया। उसके वस्त्र फटे हुए चीथड़े मात्र हैं। उसका निवासस्थान एक टूटी-फूटी भोपड़ी मात्र है, जो मौसम के कष्टों से उसकी रक्षा ही नहीं कर पाती।'⁴⁸

1896 में लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित मराठी साप्ताहिक 'वेमरी' में 'शिवाजीज अटरन्सेम' शीर्षक से पद्य प्रकाशित हुए, जिनमें शिवाजी ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत देश की दुर्दशा पर इस प्रकार में शिकायत करते हुए दिखाए गए हैं - हाय ! हाय ! यह मैं अपनी आँखों से देश की विनाशलीला को देख रहा हूँ... हाय ! यह कैसा विनाश का ताड़व नृत्य है। ...ममृद्धि समाप्त हो चुकी है और उसके बाद स्वास्थ्य भी। देश में दुर्भाग्य का दानव सारे देश को अकान के शिकजे में जकड़े हुए है।⁴⁹ इसी पत्र के 26 जनवरी 1893 के अंक में पंजाब के 'विक्टोरिया पेपर' में यहाँ तक दृढ़तापूर्वक कहा गया कि भारतीयों को खाना-पीता बतानेवाले भारतीय वस्तुतः देशद्रोही हैं।⁵⁰

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान उस समय वर्ग विशेष ही दशा पर न होकर सर्व-साधारण की दशा पर ही केंद्रित था। देश के विशाल जनसमूह की घोर दरिद्रता और उनकी आर्थिक दुर्दशा ही चिंता तथा विचार के विषय थे।⁵¹ उस समय समाज के निम्न तथा मध्य वर्ग के खेतिहरों की स्थिति इस प्रकार थी, वे भुखमरी के शिकार थे, सिकुड़कर ठठरी मात्र बन गए थे, उनके चेहरे भुर्रियों से भरे हुए थे। उन बेचारों को दिन निकलने से अंधेरा होने तक उस थोड़े से भोजन के लिए कठोर श्रम करते करते थककर चूर हो जाना पड़ता था, जो देश के अपेक्षाकृत अधिक दरिद्र करोड़ों लोगों को सामान्य काल में भी बड़ी कठिनाई में मिल पाता था। वे प्रायः आँधे भूखे रहते थे तथा अकाल पड़ने पर तो कीड़ों-मकोड़ों के समान मरते थे। इस प्रकार देश की संपन्नता और विपन्नता की सही कसौटी के लिए जनता के अक्षेपक निम्नवर्ग को ही लिया गया।⁵² कृषकवर्ग के अंतर्गत भी कृषि-श्रमिकों की स्थिति की ही तीव्र भर्त्सना की गई।⁵³ क्योंकि ये ही लोग थे जो वर्ष के प्रारंभ से अतः तक कभी पर्याप्त भोजन उपलब्ध न होने के कारण दुखी रहते थे।⁵⁴

राष्ट्रीय भावना के प्रमुख प्रवक्ताओं ने दरिद्रता की समस्या के कारण की खोज

मे देखा कि वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण होने की अपेक्षा उत्पादन की ही कमी है। उन्होंने अनुभव किया कि यह प्रश्न अपने आपमें चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो कि सभी लोगों के बीच किसके द्वारा और किन स्रोतों से सारी आय वितरित की जाती है किंतु इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारत का कुल उत्पादन यहाँ के निवासियों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? ⁵⁵ समस्या को जब इस दृष्टिकोण से देखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं करता और यह सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया कि देश का उत्पादन देश में ही रहना चाहिए। ⁵⁶ अतएव भारत के अर्थशास्त्रियों ने भारतीयों की आर्थिक समृद्धि के लिए कुल उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। ⁵⁷ निर्धनता की समस्या के इस विशिष्ट विश्लेषण ने भारतीय राजनीति के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति ने निर्धनता को व्यापक राष्ट्रीय प्रश्न बनाया तथा उसके उन्मूलन की समुक्त मांग के प्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्न वर्गों को विभाजित करने के बदले उन्हें संगठित करने में सहायता दी। ⁵⁸ यह विश्लेषण ही भारतीय आर्थिक विकास के लिए किसी सीमा तक अपवादात्मक सिद्धांत (किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मार्ग से भिन्न मार्ग पकड़ना) के लिए उत्तरदायी था। बहुत सारे भारतीयों ने निर्धनता की समस्या व आर्थिक विकास के अभाव के कारण को इन रूपों में देखा, उत्पादन क्षमता तथा योग्यता में गिरावट और आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत निम्न दर। ⁵⁹

कुछ समय तक तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत की घृणित तथा विषम दरिद्रता के अस्तित्व को स्वीकार तक नहीं किया। वर्तमान तथा भूतपूर्व सरकारी अधिकारियों ने वास्तविकता के विपरीत कृपकों की सम्पन्न तथा समुष्ट दशा का चित्र ही प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा, भारतीयों के चरम अभाव के सतत अभियोग से पीड़ित होकर 1885-88 में भारत के वायसराय लार्ड डफरिन ने 1887 में भारतीय समाज के निम्न वर्गों की दशा की गुप्त सरकारी जाच-पड़ताल का आदेश दिया। जाच-पड़ताल के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया परंतु भारत सरकार ने 1888 में प्रातीय प्रतिवेदनो के आधार पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया। प्रस्ताव के परिशिष्ट 'ए' में प्रतिवेदनो का संक्षेप प्रस्तुत किया गया। ⁶⁰ प्रातीय प्रतिवेदन इस बारे में एकमत थे कि भारत में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं। किसानों के अपेक्षाकृत निम्न वर्ग की स्थिति भी अभी कोई विशेष चिन्तनीय नहीं, ⁶¹ सामान्य वर्षों में तो लोगों के पास आवश्यकता से अधिक सामग्री संचित हो जाती है। ⁶² 1893 में भारत सरकार इसमें भी अधिक आशावादी थी। 1881-91 तक 'भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति' पर प्रातीय प्रतिवेदनो की समीक्षा करते हुए सरकार ने घोषणा की कि देश समृद्ध दशा में है। ⁶³ तृतीय दशवार्षिक नैतिक तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन (थर्ड डिमिनिशल मार्गल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट) (1891-92) में इस बात की पुष्टि की गई कि, क्रमशः और निरंतर बढ़ते हुए जीवनस्तर के संदर्भ में खेतिहर किसानों की दशा भौतिक दृष्टि में आत्मनिर्भरता की है। ⁶⁴ गैरसरकारी ब्रिटिश लेखकों ने सरकारी मत की पुष्टि की तथा कम उत्तरदायी होने के कारण उन्होंने अपने मत को अधिक खूबकर अभिव्यक्त किया। ⁶⁵

दरिद्रता का प्रमाण

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का भारत में व्याप्त दरिद्रता को प्रमाणित करने का सर्वाधिक प्रचलित ढंग था, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के लेखों से अवतरण उद्धृत करना। इसका स्पष्ट उद्देश्य विरोधी को उसी के शस्त्र से परास्त करना था। अधिकांशतः उद्धृत दो अवतरण सर डब्लू हटर की पुस्तक 'इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया' तथा सर चार्ल्स एनोट की 'टिप्पणी' में क्रमशः इस प्रकार थे प्रथम, 'भारत की चालीस करोड़ जनता अपर्याप्त भोजन पर जीवन निर्वाह करती है।' द्वितीय, 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आधी खेतिहर जनता पूरे के पूरे वर्ष के बीतने पर भी एक बार भरपेट भोजन नहीं कर पाती।' ⁶⁶

प्रति व्यक्ति की आय के अनुपात के अंको को प्रायः साध्य रूप में उद्धृत किया जाता था। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में बाटकर ये आंकड़े निकाले जाते थे। इस अकेली अनुक्रमणिका में प्राप्त आर्थिक योगक्षेम की न्यूनता अथवा अभाव का उपयोग समस्या को उजागर करने, उसे नाटकीय रूप देने तथा अन्य देशों के समकालीन निवासियों के स्तर से तुलना करने में किया जाता था। ⁶⁷ इसके अतिरिक्त ये स्पष्ट तथा सुबोध अंक अपने में तर्क का साम करते थे, ठोस आधार लिए ये आंकड़े ⁶⁸ ऐसा जादू का प्रभाव रखते थे कि उनमें अशिक्षित भारतीयों की जड़-बुद्धि भी सचेत हुए बिना न रह सकी। ⁶⁹

सांख्यिकी गणना के आधार पर आनुपातिक प्रति व्यक्ति आय का प्रथम विवरण प्रस्तुत करने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। उन्होंने 1873 में सरल किन्तु प्रभावी ढंग का प्रयोग करते हुए गणना की कि 1867-68 में ब्रिटिश भारत की मत्र करोड़ जनसंख्या की कुल राष्ट्रीय आय 3 4 अरब ०० है, अथवा दूसरे शब्दों में, इस देश की आय बीस रुपये प्रति व्यक्ति है। ⁷⁰ दादाभाई अपने इस निष्कर्ष के मोटे अनुमान में भली प्रकार परिचित थे परन्तु उनकी दृष्टि में उन्हें उस समय तक उपलब्ध सांख्यिकी सूचना का यही सर्वोत्तम सम्भव अनुमान था। ⁷¹ परवर्ती वर्षों में 'बीस रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अंक' राष्ट्रीय आंदोलन का सगठन मंत्र बन गया तथा इस अंक को विनाशात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा भाषणों में बड़े विस्तार से उद्धृत किया गया।

दादाभाई द्वारा प्रस्तुत चित्र इतना अधिक धिनीना था कि अधिकारियों के लिए उस समय दादाभाई द्वारा अपनाए गए उसी सरल तथा सुबोध सांख्यिकी आधार पर ही उसका उत्तर ढूँढना आवश्यक हो गया। 1882 में भारत सरकार ने वित्त सदस्य मेजर ऐवेलीन तथा डेविड बार्बर द्वारा तैयार किए गए तख्तीने को प्रचारित किया, जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत की कुल आय सवा पाच अरब रुपये और प्रतिव्यक्ति आय 27 ०० कूती गई थी। ⁷² 1901 में लार्ड कर्जन ने घोषणा की कि 1897-98 में प्रति व्यक्ति आय तीस रुपये थी। ⁷³ जब विलियम डिगबी ने सांख्यिकी तर्कों के शस्त्र से इस अंक पर प्रहार किया, ⁷⁴ तो भारत सरकार के लेखा विभाग के एक उच्चाधिकारी फ्रेड जे० एटकिंसन बचाव के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 'रायल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी' के सामने 1902 में एक

पेपर पढा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश भारत की आनुपातिक प्रतिव्यक्ति आय 1875 में 30.5 रुपए के मुकाबले 1895 में 39.5 रुपए संगणित की।⁷⁵

भारतीय नेता प्रमुख रूप से भारत में व्याप्त निर्धनता को ही प्रमाणित करना चाहते थे, अतः कानूनी अथवा सांख्यिकी दावपेंचों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यही कारण था कि दादाभाई नोरोजी के अंकों की सत्यता पर विश्वास करते हुए भी तथा यह मानते हुए भी कि प्रति व्यक्ति आय का सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया बेरिंग-कर्जन तख्तीना एक तो अपनी ही त्रुटियों की जाच में पूर्वग्रह से मुक्त नहीं, दूसरे वह अतिरंजित भी है फिर भी वे उस पर इमलिए विचार-विमर्श करने को नैयार हो गए कि उसमें भी बराबर भारत की घोर दरिद्रता प्रकट होती थी।⁷⁶

प्रति व्यक्ति आय के अंक अपने आपमें भारतीय दरिद्रता के स्पष्ट उद्घोषक थे। भारतीय प्रवक्ताओं का मत था कि भारत की दरिद्रता -- तुलनात्मक जोर मापेक्ष -- दोनों रूपों में है; अतः भारत की वास्तविक दरिद्रता की सही जानकारी एक तो तभी मिल सकती है जब भारत की आय की तुलना दूसरे देशों की आय में की जाए, अथवा मानव की मूल आवश्यकताओं से उसका अंतर दिखाया जाए, अतः उन्होंने यह सिद्ध करने का बीड़ा उठाया कि इन मानदंडों से भी भारतीयों की स्थिति अपेक्षाकृत विषम ही सिद्ध होती है। उन्होंने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय पर विचार किया और उसके उपरान्त अन्य देशों की आय से उसकी तुलना के प्रश्न पर विचार किया। उत्तर सर्वथा प्रतिकूल था। यह तुलना एक बार फिर तालिका के रूप में प्रायः मरल-सुबोध सांख्यिकी शब्दावली में अभिव्यक्त की गई।⁷⁷ भारतीय नेताओं के अनुसार, तालिकाबद्ध तुलना भारतीयों की आर्थिक स्थिति का अंधकारमय रूप प्रस्तुत करती है। यह प्रमाणित करती है कि कुप्रशासित टर्की जैसे देश भारत की अपेक्षा प्रति व्यक्ति दुगुना उत्पादन करते हैं अथवा भारत इंग्लैंड में उन्नीस गुना पीछे है, अथवा भारत की दरिद्रता की तुलना में अत्यंत निष्पीडित तथा कुप्रशासित रूस भी अपेक्षाकृत समृद्ध है।⁷⁸ इस प्रकार हमारे अध्ययनकाल तथा उसके परवर्ती वर्षों में यह एक व्यापक धारणा बन गई थी कि सम्य संसार में भारत दरिद्रतम देश है।⁷⁹ यह धारणा भारतीयों के हृदय में निर्धनता के प्रति सशक्त तथा गहन चिंतन की सूचक थी।⁸⁰

भारतीय नेताओं ने अगला प्रश्न प्रति व्यक्ति आवश्यक व्यय का उठाया। उनके विचार में समस्या के सही रूप को देखने के लिए आनुपातिक आय की जांच वर्तमान जीवननिर्वाह व्यय के संदर्भ में ही की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सामान्य भारतीय की आय इतनी अपर्याप्त है कि वह बेचारा मनुष्य होने के नाते अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। उनका यह भी विचार था कि भारत में निर्धनता की व्यापकता का विषय इस प्रकार अनाक्रम्य घरातल पर अवस्थित हो जाएगा। फलतः भारतीय राष्ट्रवादियों में अर्थशास्त्र के पंडितों ने इस दिशा में जांच-पड़ताल प्रारंभ कर दी। उन दिनों जीवननिर्वाह व्यय के अथवा पोषण स्तर के अध्ययन का अस्तित्व ही नहीं था। इसके लिए प्रवासी कुलियों, अकाल-कायों में लगे श्रमिकों, सामान्य कृषि श्रमिकों, भारतीय सिपाहियों, खेतिहरों तथा जेल के कैदियों के जीवन की

आवश्यकताओं जैसे बिखरे अनुमानों पर निर्भर करना पड़ता था। उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम पाई गई कि उससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं थी।⁸¹ जेल के कैदियों के भोजन और भरण-व्यय के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय की तुलना भारत की स्थिति का सर्वाधिक प्रभावी विवरण था। दादा-भाई नौरोजी ने विभिन्न प्रांतों के 1867-68 के प्रतिवेदनों के आधार पर जेल में कैदी के भोजन और वस्त्रों पर सरकारी खर्च की गणना इस प्रकार से प्रस्तुत की⁸² :

सेंट्रल प्राविसेज	31 रु०
पंजाब	27 रु० 3 आने
नार्थ-वैस्ट प्राविसेज	21 रु० 13 आने
बंगाल	31 रु० 11 आने
मद्रास	53 रु० 2 आने
बंबई	47 रु० 7 आने

इस "११.१" की संगणना कुछ एक अन्य भारतीय लेखकों द्वारा भी की गई।⁸³ जेल के कैदियों पर होनेवाले प्रति व्यक्ति व्यय-अंक के साथ प्रति व्यक्ति आय की तुलना से यह निकर्ग स्वतः स्पष्ट तथा आत्मनिरूपक हो गया कि अनुकूल ऋतु में भी भारत का उत्पादन एक अपराधी को मिलनेवाले भोजन की तुलना में भी पर्याप्त नहीं। फिर थोड़ी-बहुत विलासिता के लिए, सामाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं के लिए, दुख-सुख के अवसरों पर होनेवाले खर्चों के लिए तथा बुरे दिनों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था एवं पूर्ति आदि का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है।⁸⁴ इस प्रकार वे सही तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीयों की बड़ी संख्या स्थायी रूप से भुखमरी की शिकार है और न्यूनतम जीवन-स्तर से नीचे रहती है।

दादाभाई नौरोजी, जी० वी० जोशी, जी० सुब्रह्मण्य अय्यर तथा सुरेंद्रनाथ ब्रैनर्जी जैसे नेताओं ने यह सम्यक् रूप से अनुभव किया कि 'औसत' शब्द एक आर्थिक कल्पना होने के कारण अपार दोषों को छुपा देता है, क्योंकि जनता का अपेक्षाकृत अधिक निर्धनवर्ग तो औसत आय का पूरा भाग ले ही नहीं पाता है। औसत प्रति व्यक्ति आय में तो विदेशी पूँजीपतियों, मिजिल सर्विस के उच्च वेतनभोगियों, विदेशी अधिकारियों, बड़े-बड़े भूमिपतियों, शहरी व्यापारियों, नगर तथा ग्राम के मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्यवर्गीय लोगों की आय सम्मिलित है। अतएव समाज के निम्न वर्गों की आय तो प्रति व्यक्ति औसत आय से बहुत नीची होगी और इस रूप में प्रति व्यक्ति औसत आय के अंक से अनुमित स्थिति की अपेक्षा उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा।⁸⁵

इसके अतिरिक्त लगातार आनेवाले विनाशकारी दुर्भिक्षों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्या पर पूरा प्रकाश डाला और जनता की दयनीय दरिद्रता तथा स्थायी भुखमरी का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य वर्षों में भारत की स्थायी दरिद्रता को

अपेक्षाकृत अधिक बड़ी बुराई के रूप में सूचित किया। उन्होंने 'राष्ट्र की पूर्ण क्षीणता का भोंडा फोडा', 'इस देश में बहुसंख्यक जनता के चरम दुर्भाग्य, उसकी उदासीनता और विवशता के अतिरिक्त प्रमाण को प्रस्तुत किया', 'अन्य सभी तथ्यों और अंकों से बढ़कर निष्कर्ष रूप में भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को स्पष्ट प्रमाणित किया।' ... वस्तुतः वे भारत की दरिद्रता के 'बाह्य चिह्न' थे।⁹⁰

राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को प्रमाणित करने के लिए निश्चित प्रमाणों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों और लेखकों द्वारा देश में समृद्धि और संपन्नता सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत तर्कों का प्रबल खंडन करना भी प्रारंभ कर दिया। भारतीयों की संपन्नता के सूचक किसी भी वस्तुगत मानदंड के अभाव में ब्रिटिश प्रवक्ताओं ने व्यक्तिगत मानदंड को अपनाने का मार्ग ग्रहण किया। उनका तर्क था कि भारतीय जनता अपनी इच्छानुरूप ही समृद्ध है। भारतीयों की निम्न आय उनकी दरिद्रता की सूचक न होकर उनकी आवश्यकताओं की स्वल्पता की ही द्योतक है।⁹¹ इस प्रकार निरीक्षण रूप में देखने पर भारत की स्पष्ट दिखाई देनेवाली दरिद्रता जनता की सीमित आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने पर संबंधी भिन्न रूप ग्रहण कर गई। इस तर्क का निर्देशक पक्ष यह था कि बेतुहरी की सन्तुष्टि का अर्थ तथ्यतः उनकी संपन्नता भी है। 1880-91 के वर्षों की 'बंगाली रिपोर्ट' ने भारतीयों की भौतिक स्थिति पर इस प्रकार टिप्पणी की : 'बंगाल का किसान अपने मानदंड के आधार पर ही जाचे जाने पर प्रसन्न तथा संपन्न पाया गया है।'⁹² उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की रिपोर्टें निरन्तरवाते ने तो इस तथ्य पर आश्चर्य प्रकट किया कि कृषक किस प्रकार घटिया खाना खाता है जबकि वह बहुत से अच्छे खाने-पीने लोगों की अपेक्षा अधिक मोटा न मंत्री, पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न अवश्य है।⁹³ इस तर्क का पापक सिद्धांत यह कल्पना थी कि धार्मिक शिक्षा तथा दीर्घ काल से प्रचलित सामाजिक मूल्यों के कारण भारतीय कृषक भौतिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की अपेक्षा आध्यात्मिक सतों में अधिक रुचि रखता है।⁹⁴ ब्रिटिश भूतपूर्व तथा वर्तमान अधिकारी भारतीयों की प्रतिवर्षिक आय की यूरोप के लोगों की आय से तुलना की प्रवृत्ति के मुकाबले व्यावहारिक और सांकेतिक सिद्धांत पर आधुनिक विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लग। उनमें से अपेक्षाकृत अधिक गंभीर व्यक्तिगणों ने घोषित किया जीवन आवश्यकताओं और मूल्यों में गहरे अंतर के कारण यूरोप के लोगों के साथ भारतीयों के जीवन निर्वाह तथा जीवन स्तर की तुलना एक अर्थहीन चेष्टा है। उनकी जाच-पट्टाल तो देश की अपनी आवश्यकताओं के सदर्भ में ही करनी उचित है।⁹⁵ कम मतर्क सरकारी अधिकारी तो टिप्पणी करते हुए इस सीमा तक बढ़ गए कि तुलना की दृष्टि से यूरोप के बेतुहरी की अपेक्षा भारत के किसान की दशा बेहतर है। इसी प्रकार सामान्य भारतीय कृषक को प्राप्त सुख सुविधाओं की दृष्टि से उनकी तुलना यूरोप के बहुत बड़े भाग में विद्यमान किसानों से करते हुए जान स्ट्रेचे ने 1898 में यह मत व्यक्त किया 'निस्संदेह भारतीय कृषक ही अधिक लाभसंपन्न है।'⁹⁶ मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर ग्रांट डफ 1887 में एक पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख में पहले ही यह दृष्टिकोण प्रकट कर चुके थे।⁹⁷ छोटे अधिकारी तो और भी अधिक असंतोख थे।

ढाका का कमिशनर 1888 में इस चौकानेवाले परिणाम पर पहुँचा अपनी आवश्यकताओं के मदर्भ में बंगाल का किसान विश्व में समृद्धतम है। हुगली का कलक्टर टायनर भी उद्धृतता में पीछे नहीं था। उसने यहाँ तक लिखा इस जिने के दरिद्रतम वर्ग की स्थिति इंग्लैंड के उसी वर्ग की स्थिति की तुलना में सभी दृष्टियों से निम्नकोच रूप से बेहतर कही जा सकती है। '...और मुझे इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं कि हज़ारों-हज़ार निर्धन अंगरेज भारतीयों के साथ स्थान परिवर्तन करने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे।'⁹⁴

भारतीय नेताओं ने इस विचारधारा के आधारभूत दृष्टिकोण का सर्वथा क्रूर तथा भावनाशून्य⁹⁵ बताया। उन्होंने बड़ी तीव्रता से इस मिथ्याता का अस्वीकार किया कि भारतीयों की आवश्यकताएँ सीमित हैं⁹⁶ अथवा वे जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेने तथा उनकी आवश्यकता अनुभव करने के अयोग्य हैं।⁹⁷ उनके वर्तमान निम्न जीवनस्तर का उनकी स्थिति में सुधार के अधिकार को नकारने के पापक तत्व के रूप में नहीं लिया जा सकता।⁹⁸ विषय का सार इस प्रकार था

ब्रिटेन ने प्रथम उनसे साधन छीन लिए उन्हें अधिक उत्पादन के अयोग्य बना दिया, अर्वागट तन्त्र साधना की सीमा तक उन्हें अपनी आवश्यकताओं का ध्यान को विवश कर दिया और फिर उन्हें कोसना शुरू कर दिया। घाव पर नमक छिड़कने हुए उन्हें कहना प्रारंभ कर दिया इसका तुम्हारी आवश्यकताएँ सीमित हैं। तुम्हें अवश्य ही सीमित आवश्यकताओं का धन निर्धन व्यक्ति बन रहना चाहिए। तुम्हारे लिए चावल हम तुम्हें अधिक उदारता से मगर चावल रखने की अनुमति दे देंगे थोड़े से वस्त्र और आश्रय प्रदान है। बन्नी बन्नी मानवीय आवश्यकताओं की मनुष्य और सुखों का उपभोग ना हमारे लिए है। तुम्हें हमारे भाउ के टुकड़े के रूप में हमारे पशुओं के समान हमारी दासता करनी चाहिए और हमारे लिए श्रम करना चाहिए।⁹⁹

भारतीय नेताओं ने वैराग्यपरक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिकता के नाम पर निर्धनता को महिमा देने की प्रवृत्ति की निन्दा की। उन्होंने भौतिक सुख-सुविधाओं को बहुत उच्च स्थान दिया।¹⁰⁰ उन्होंने राष्ट्र की भौतिक उत्पादन में सभाविन वृद्धि के साथ राष्ट्र की भौतिक संपदा में वृद्धि की इच्छा को जोड़ दिया क्योंकि उनके अनुसार भौतिक समृद्धि के अपरान्त परिमाण का मानवीय आवश्यकताओं की सृष्टि में सापेक्ष संबंध है।¹⁰¹ उनकी मारी आर्थिक गतिविधि का दूर दरिद्रता को दूर करना था न कि अप्रसन्नता का। उन्होंने अपना तात्कालिक नक्षत्र भूखे मरने लागे के लिए गरीबों के दो टुकड़े जुड़ना बनाया और इस रूप में उनके तर्क का सार यह था कि बेचारे भारतीयों की सीमित आवश्यकताओं की भी सृष्टि नहीं होती।¹⁰²

क्या दरिद्रता बढ़ रही थी

राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र ज़ाच-पड़ताल तथा बहुत बड़े क्षेत्र और बहुत बड़ी जनसंख्या को बहुत बुरी तरह प्रभावित करनेवाले और साथ ही संपन्नता का पर्दाफाश करनेवाले दुर्भिक्षों की निरंतरता के फलस्वरूप मारे देश में व्याप्त घोर दरिद्रता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को न्यूनाधिक रूप में न केवल भारतीय जनता ने ही अपितु शासकवर्ग ने भी निर्विवाद

रूप से स्वीकार किया। 1888 की आर्थिक जांच पर प्रस्ताव में यह तो कहा गया था कि खेतिहरों के निम्न वर्गों की स्थिति भी वर्तमान में ऐसी नहीं जिसे चिंता का विषय कहा जा सके किंतु यह भी स्वीकार किया गया कि देश के सभी भागों में बहुसंख्यक जनता के अभावग्रस्त होने के प्रमाण उपलब्ध है¹⁰³, और यह कथन अतिशयोक्ति नहीं कि उस देश के बहुत बड़े भूभाग के छोटे किसान तथा मजदूर, दो समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते।¹⁰⁴ 1898 में 'लायल दुर्भिक्ष आयोग' ने यह पाया कि कृषक जनता का निम्नवर्ग अभी घोर दरिद्रता के शिकंजे में इतना कसा हुआ है कि उसके पास सामान्य वर्षों में भी पर्याप्त भोजन नहीं होता।¹⁰⁵ अपनी वायसरॉय के अंतिम वर्षों में लार्ड कर्जन ने स्पष्टता से स्वीकार किया : 'भारत में पर्याप्त, यहाँ तक कि पर्याप्त से बहुत अधिक दरिद्रता है।¹⁰⁶ मेजर बेरिंग तथा लार्ड कर्जन द्वारा प्रसारित प्रति व्यक्त आय के अनुमान यद्यपि अन्य रूपों में विवादास्पद है तथापि उनमें प्रभावशाली ढंग से भारतीय जनसमुदाय की घोर दरिद्रता का पता चलता है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के बीतते-बीतते भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता के विश्वास में सत्य के रूप में प्रचार और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।

भारत के उदीयमान राष्ट्रीय नेतृत्व तथा ब्रिटिश प्रशासकों के मध्य प्रचार-मुद्द का केंद्र एक अन्य अधिक विस्फोटक यह प्रश्न बन गया कि 'भारत की दरिद्रता पहले की अपेक्षा बढ़ रही है अथवा घट रही है?'¹⁰⁷ यह प्रश्न इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि इसके उत्तर में एक निर्णय निहित था और इसीलिए दोनों पक्षों ने इस प्रश्न को उस रूप में प्रस्तुत किया 'भारत ब्रिटिश उपनिवेश बनने पर पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है अथवा बुरी स्थिति में है?'¹⁰⁸ भारत में विद्यमान ब्रिटिश अधिकारी देश में व्यापक दरिद्रता के प्रश्न की अपेक्षा इस प्रश्न पर अधिक संवेदनशील थे क्योंकि भारत का पूर्वापेक्षा दरिद्र होते जाना मानने का अर्थ केवल आत्मनिंदा ही नहीं था प्रत्युत उसके गंभीर राजनीतिक प्रतिघात भुगतना भी था। उच्च ब्रिटिश अधिकारी सत्य के इस रूप में भली प्रचार परचित थे। भारत सचिव लार्ड जार्ज हेमिलटन ने समस्या की इस चुनौती को स्वीकार करने हुए 16 अगस्त 1901 को 'हाउस आफ कामंस' में घोषणा की 'यदि यह सिद्ध किया जा सके कि हमारे प्रशासन में भारत भौतिक संपन्नता की दृष्टि में और अधिक पिछड़ गया है तो मैं इसे एकदम आत्मनिंदा मानने को तैयार हूँ तथा स्वीकार करता हूँ कि इस स्थिति में हम भारत को और अधिक समय तक अपने नियंत्रण में रखने के विश्वमनीय अधिकारी नहीं।'¹⁰⁹ यह विषय इस दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि रंग को अभी स्वीकार ही नहीं किया गया तो उसके कारणों और उपचारों के ढूँढने का क्या लाभ हो सकता था?

वर्षों तक भारतीय नेता इसी स्थिति को सिद्ध करने में लगे रहे कि भारत दरिद्र ही नहीं प्रत्युत दिन-प्रतिदिन दरिद्रतर होता जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई और उत्तरोत्तर अधिक गहरी जड़ पकड़ती हुई निर्धनता को दिखाने के लिए अथक और निरंतर प्रयत्न किए। उदाहरणार्थ गोपालकृष्ण गोखले ने इसे 1902 के अपने प्रसिद्ध बजट-भाषण का केंद्रबिंदु बनाया और उसके बाद इस समस्या के सभी पक्षों पर विचार करने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के जनसमुदाय की

भौतिक स्थिति निरंतर बढ से बढतर होती जा रही है तथा यह दृष्टिगोचर है कि यह स्थिति विश्व के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत सर्वाधिक दुखद स्थिति है।¹¹⁰ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने द्वितीय अधिवेशन में ही भारतीय जनता की विशाल संख्या की बढ़ती हुई दरिद्रता के अपने दृढ़ विश्वास को वाणी दी¹¹¹ तथा एक के पश्चात दूसरे अधिवेशन में इस प्रस्ताव को दोहराया। राष्ट्रीय प्रेस ने भी प्रतिदिन बढ़ती दरिद्रता को 'स्पष्टगोचर' तथा 'पूर्णतः सिद्ध वास्तविकता' कहते हुए अत्यंत उग्रता से उसकी घोर निंदा की।¹¹²

दूसरी ओर, भारत में रहनेवाले ब्रिटिश अधिकारी तथा सामान्यतः सभी ब्रिटिश लेखक यह मानते रहे कि ब्रिटिश राज्य से भारतीय जनता की भौतिक दशा निरंतर न केवल सुधर रही है प्रत्युत देश की संपन्नता में वृद्धि भी हो रही है। उनके अनुसार दरिद्रता की कल्पना सर्वथा निराधार और पूर्ण रूप में पाखंड है। मत्त यह है कि भारत पहले से ही समृद्धि के राजपथ पर चलना शुरू कर चुका है; अतः उसका भविष्य उज्ज्वल तथा उत्साहवर्धक है।¹¹³ इस सिद्धांत के प्रबलतम समर्थक व्याख्याता लार्ड कर्जन थे जिन्होंने बार-बार, यहां तक कि लगभग अपने सभी बजट भाषणों में इस विषय को उठाया।¹¹⁴ 1901 में उन्होंने जैसा हम पूर्व निर्देश कर चुके हैं, संगणना द्वारा यह सिद्ध किया कि भारत की 1882 में 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1898 में 30 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। वृद्धि की इस दर से अमंतीय प्रकट करते हुए भी उन्होंने दावा किया कि आर्थिक गतिविधि निश्चित रूप में प्रगति की ओर उन्मुख है, अवनति की ओर नहीं।¹¹⁵ 1901 तक तो वे और अधिक विश्वस्त हो गए थे। उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले जैसे भारतीय नेताओं का उपहास करते हुए, 'तपती धूप में वर्षा होने की बात कहकर आत्मरक्षा के लिए छाता ताननेवालों' से उनकी तुलना करते हुए बलपूर्वक कहा कि भारत सभी दिशाओं में दृष्ट-पुष्टता, क्षमता और संपन्नता के संकेतों का स्पष्ट प्रदर्शन कर रहा है।¹¹⁶ 1906 तक तो उनका यह निश्चित मत था कि भारत की भौतिक प्रगति न केवल भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व घटना है प्रत्युत विश्व के किसी भी देश के इतिहास की एक विरल घटना है।¹¹⁷

प्रतिद्वंद्वी विवादों की विस्तृत परीक्षा के समय दोनों पक्षों ने समान रूप से स्वीकृत परंतु भिन्न विधे में और विपरीत रूप में विश्लेषित निर्देशकों पर न केवल तर्क-वितर्क किया प्रत्युत भारतीय नेताओं ने भौतिक संपन्नता संबंधी कतिपय पक्षों पर सहमत होते हुए भी यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय संपन्नता संबंधी बड़े कारणों के अभाव में ये पक्ष आवश्यकता से अधिक कमजोर पड़ गए थे।

राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में दुर्भिक्ष भारत की दरिद्रता के स्पष्ट प्रमाण थे। दुर्भिक्षों की निरंतर बढ़ती हुई तीव्रता, प्रसार तथा विनाशनीला¹¹⁸ भारत की बढ़ती हुई अशक्तता के पक्के प्रभिसूचक थे।¹¹⁹ इसके विपरीत ब्रिटिश दृष्टिकोण यह था कि दुर्भिक्ष प्राकृतिक प्रकोप के परिणाम थे और इनके साथ मानवीय प्रयत्नों का कोई संबंध नहीं था।¹²⁰ भारतीयों की दृष्टि में खेतिहरों पर बढ़ता हुआ ऋण तथा भूमि जोतनेवालों द्वारा भूमि न जोतनेवालों के हाथों भूमि की बिक्री, साधनों के बढ़ते अभाव के सूचक थे।¹²¹ कुछ एक ब्रिटिश अधिकारियों तथा लेखकों ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर

दिया कि ऋणग्रस्तता खेतिहरों की निर्धनता की दशा की सूचक है।¹²² विकल्पतः उन्होंने ऋणग्रस्तता को निर्धनता का कारण माना, परिणाम नहीं।¹²³ जी० वी० जोशी और गोखले ने भी अकाल और प्लेग से अलग हटकर बढ़ती हुई मृत्यु-दर के आंकड़े प्रस्तुत करके यह दिखाने का प्रयत्न किया कि बहुत अधिक जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिलता।¹²⁴ एक ओर जहाँ भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीय संपन्नता के दावे को झूठा सिद्ध करने के लिए निश्चयात्मक प्रमाण जुटा रहे थे, वहाँ वे अब यह भी मानने लगे थे कि वस्तुतः प्रमाण जुटाने का उत्तरदायित्व तो निश्चित धारणा के प्रस्तोताओं का ही है।

ब्रिटिश प्रवक्ताओं ने इतिहास को बहुत बड़ा न्यायाधीश मानकर उसके आगे अपील करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनका मतव्य था कि ब्रिटिश राज्य के सापेक्षिक भौतिक परिणामों पर निर्णय देने में पूर्व तुलना के लिए यह देखना चाहिए कि ब्रिटिश पूर्ववर्ती शासकों के अधीनस्थ भारत की क्या दशा थी। इस तुलनात्मक विवेचन में उनका तर्क था कि अंगरेजों के आने से पूर्व भारत अत्यधिक दरिद्र था और ब्रिटिश राज्य का पक्ष इस दृष्टि से उज्ज्वल है।¹²⁵ भारतीय नेता अपने अतीत पर आधारित निर्णय को स्वीकार करने पर सहमत थे। कुछ एक महानुभावों ने तो बड़ी तत्परता से मान लिया कि भारतीय दरिद्रता की जड़े इतिहास के अनुराल में हैं और इस प्रकार दरिद्रता एक पुरानी, बहुत पुरानी विगमन में प्राप्त बुराई है।¹²⁶ भारत अतीत में कभी समृद्धि का भंडार नहीं रहा।¹²⁷ परन्तु उनमें से बहुतों की मान्यता यह थी कि वर्तमान युग की दरिद्रता और दुर्भाग्य अतीत के किसी भी युग में नहीं रहे।¹²⁸ इनमें आज के भारत को जकड़ने वाला अंगरेजी राज्य सबसे बड़ा अभिशाप है।¹²⁹ उनमें से कुछ एक ने तो यह प्रमाणित करने की चेष्टा भी की कि अकबर तथा अन्य भारतीय शासकों के समय भारतीयों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी।¹³⁰ कुछ एक राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं ने तो अतीत का गौरव-गान किया और अतीत की समृद्धि और गरिमा के विनाश पर उच्च स्वर से विनाश किया।¹³¹ गेल्फंड नडी के इस विषय प्रश्न ने बड़ी सफाई से सरकारी दृष्टिकोण का खंडन किया—क्या अंगरेज व्यापारी भारत में गरीबों के दुखों के निवारण के लिए इस देश में आने को आकृष्ट हुए थे? अथवा उनके अपने ऐतिहासिक कथन के अनुसार, क्या वे इस देश की संपत्ति में आकृष्ट होकर यहाँ आये थे?¹³²

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा लेखकों ने भारत में असंख्य विभिन्न मूल्यवान् धातुओं के बढते हुए आयात तथा उनके फलस्वरूप लोगों के पाम उन धातुओं के संबित भंडार को देश की बढ़ती हुई संपत्ति को निश्चित संकेत के रूप में ग्रहण किया।¹³³ उनमें से एक महानुभाव फेड जे० एर्टकिंसन ने तो 1902 में संगणना की कि 1800-1895 की अवधि में भारत ने 141,705,000 पौंड का मोना तथा 4792,403,000 पौंड की चाँदी आयात की है। सिक्को आदि के लिए कटौती के पश्चात् उसने आंकड़ों से सिद्ध किया कि भारत की संबित आय 26 रु० प्रति व्यक्ति है।¹³⁴ उल्लेखनीय यह है कि उसका यह तर्क भारतीय नेताओं को किसी प्रकार दिग्भ्रान्त न कर सका। भारतीय नेताओं ने यह स्वीकार किया कि 19वीं शताब्दी की पूरी अवधि में मूल्यवान् धातुओं का आयात हुआ है परन्तु

इसे वे बढ़ती समृद्धि का अथवा राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी का लक्षण मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चांदी के कुल आयात का बहुत बड़ा भाग संग्रह अथवा आभूषणों के काम न आकर मुद्रा की अनिवार्य आर्थिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के ही काम आता है। आयातित चांदी प्रमुख रूप से मुद्रानिर्माण के ही काम आती है जिसकी मांग इन वर्षों में भूराजस्व की नकद अदायगी तथा देश के विदेश व्यापार के आर्थिक भुगतान के कारण काफी बढ़ गई थी।¹³⁵ मुद्रानिर्माण, टूट-फूट तथा राजकोष-जमा आदि के पश्चात् आयातित मूल्यवान धातुओं का अवशिष्ट जनता की बढ़ती समृद्धि को दिखाने के लिए प्रयोग किया जानेवाला एक तुच्छ प्रमाण ही था।¹³⁶ इतना ही नहीं, इस तुच्छ राशि का उपयोग भी प्रमुख रूप से उच्च तथा मध्यवर्ग के लोग ही करते हैं। यह धातु तो कदाचित् ही जनता के निम्नवर्ग के हाथ में पहुंच पाती है।¹³⁷ दादाभाई नौरोजी ने जोर देते हुए कहा कि सोना-चांदी के आयात संपत्ति में शुद्ध बढ़ोत्तरी नहीं करते क्योंकि उनका उद्देश्य व्यापार के निश्चित मंतुलन को बनाए रखना नहीं है। भारत का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक है। इन मूल्यवान धातुओं के आयात के बदले उसी मूल्य की अन्य वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है अतः इस रूप में मूल्यवान धातुओं के आयात से संपत्ति में वृद्धि की अपेक्षा जीवननिर्वाह के साधनों की हानि ही अधिक होती है।¹³⁸

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने हर्षोत्फुल्ल होकर वर्ष-प्रतिवर्ष मूल्य और परिमाण में शीघ्र गति से फैलने भारत के विदेश व्यापार को देश की बढ़ती संपन्नता के माध्यम रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ओर यह तर्क प्रस्तुत किया कि केवल बढ़ती संपन्नतावाला देश ही नियमित रूप से और ऊंची दर पर विदेशी सामग्री के आयातों में वृद्धि कर सकता है। दूसरी ओर उनका तर्क था कि बढ़ते हुए निर्यातों में किसानों की जेबें अधिकाधिक भर रही होगी।¹³⁹ भारतीय नेताओं ने इस प्रपंच के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। विदेश व्यापार के प्रति उनके दृष्टिकोण की समीक्षा तो आगे के एक अध्याय में प्रस्तुत की गई है। यहां इतना लिखना पर्याप्त होगा कि उनके अनुसार विदेश वाणिज्य लाभ का साधन न होकर राष्ट्रीय क्षति का ही एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि आयात से थोड़े से लाभ की अपेक्षा बहुत बड़ी हानि इस रूप में होती है कि स्वदेशी उत्पादकों के अपने क्षेत्र से हट जाने से औद्योगिक उदामीनता छा गई है। इसके अतिरिक्त आयातों में वृद्धि देश के योगक्षेम में बढ़ोत्तरी की अपेक्षा देश में धन के निकास में वृद्धि की ही समेतक है। मजे की बात यह है कि उसकी बुराईया तो भारतीयों को भुगतनी पड़ती है और उसके लाभों का आनंद विदेशी लेते हैं।¹⁴⁰

ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने निरंतर सुघरते हुए भारत के राजस्व की ओर संकेत किया जो करों के अतिरिक्त बोरु को बढ़ाए बिना ही बढ़ता जा रहा था। उन्होंने राजस्व के प्रमुख विषयों द्वारा लचीलापन दिखाते हुए जाने के लिए तथा क्रयशक्ति और समृद्धि के सूचक साधनों से प्राप्ति में निरंतर विकास के लिए अपने आपको बधाई दी।¹⁴¹ उन्होंने देश में सुविधाओं और समृद्धि के सीमांत में सुधार के स्रोतों के रूप में सीमा-शुल्क, टांक कर, नमक कर, आय कर, मुद्रांक तथा उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि

का उल्लेख विशेष रूप से किया।¹⁴³ भारतीय, जिनके दृष्टिकोण को गोपालकृष्ण गोखले ने सभी राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा बहुप्रशंसित 1902-3 के अपने बजट भाषणों में प्रसारता और प्रबलता से प्रस्तुत किया था, राजस्व में बढ़ोतरी को देश की भौतिक प्रगति का संकेत मानने को सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ऊँचा कराधान देश की दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है।¹⁴³ वह राजस्व के खातो में विकास को भारतीय जनता की दरिद्रता के निवारण का सूचक मानने के ब्रिटिश दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि उत्पादन राजस्व में वृद्धि राष्ट्र की संपन्नता की अपेक्षा राष्ट्र के विनाश और दुर्भाग्य के पथ पर बढ़ने की सूचक है। एक सम्य सरकार को इस स्थिति का अनुमोदन करने के बदले उसकी निंदा करनी चाहिए।¹⁴⁴ सीमाशुल्क में वृद्धि केवल यथादृष्ट विदेश व्यापार के प्रसार मात्र की ज्ञापक है जिसकी निन्दा पहले ही की जा चुकी है। केवल दो करो, आयकर तथा बिक्रीकर, से प्राप्त आय देश की भौतिक स्थिति का ज्ञान करा सकती है। आयकर मध्यवर्ग की और बिक्रीकर जनसाधारण की स्थिति के परिचायक हैं।¹⁴⁵ यह निर्देश किया गया कि आयकर से प्राप्त होनेवाली आय वर्षों से न्यूनाधिक रूप में स्थिर ही रही है।¹⁴⁶ बिक्रीकर की आय भी जनसंख्या के विस्तार के अनुपात में नहीं बढ़ी है।¹⁴⁷ नमक जैसी मानवीय उपयोग की मूल तथा आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट का सूचक यह तथ्य जनसमुदाय की भिरती दशा का सचमुच एक बहुत बड़ा साक्ष्य है।¹⁴⁸

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने कृषियोग्य भूमि के क्षेत्र में विस्तार तथा कृषि-उपज में वृद्धि को भारतीय संपन्नता के विकास के एक अन्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किया क्योंकि उनके अनुसार इनका परिणाम था कृषि आय में अपेक्षाकृत अधिकता तथा खाद्य पदार्थों की अपेक्षाकृत प्रचुरता से उपलब्धि।¹⁴⁹ भारतीय नेताओं ने इस तर्क का खंडन निम्नलिखित युक्ति से किया। उसके अनुसार देश में, विशेषतः पुराने प्रांतों में, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र नया कुल खाद्य-समरण बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ रहे।¹⁵⁰ इसके अतिरिक्त व्यापारिक फसलों के क्षेत्र की वृद्धि के मुकाबले खाद्य फसलों के क्षेत्र की वृद्धि भी नगण्य है।¹⁵¹ कृषिक्षेत्र का विस्तार कृषि उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि के परिणाम के अनुरूप नहीं।¹⁵² प्रत्येक स्थिति में यह विस्तार जंगलों, प्राकृतिक चरागाहों तथा परती धरती पर अनुचित कब्जों का ही परिणाम है।¹⁵³ इसके अतिरिक्त उन्होंने अंगरेजों के धरती की उत्पादकता में सुधार के दावे को गलत मानते हुए उसका प्रबल खंडन किया। उनके अनुसार धरती पर जनसंख्या के दबाव और उसके फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादकों के हट जाने से, घटिया धरती पर व्ययसाध्य खेती के विस्तार से¹⁵⁴ तथा निरंतर खाद के बिना ही फसल उगाते रहने से धरती की उर्वराशक्ति क्षीण हो जाने से उत्पादन घट गया है।¹⁵⁵ अतएव निष्कर्ष रूप में उनकी मान्यता थी कि भारत कृषि के क्षेत्र में निरंतर और भयंकर अपकर्ष से विपन्न होता जा रहा है जिसका परिणाम यहां बार-बार पड़नेवाले दुर्भिक्ष है।¹⁵⁶

सुधरती दशा का सरकारी तंत्र द्वारा प्रस्तुत एक रोचक साक्ष्य मूल्यों में वृद्धि था। उनके अनुसार यह एक सत्य था क्योंकि इससे एक ओर बेतिहरों की जेबें भारी हो रही

थीं और दूसरी ओर लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि से प्रेरित साध्यान्नों तथा अन्य उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी।¹⁵⁷ राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में मूल्यवृद्धि की भूमिका का तर्क सर्वथा निस्सार और भ्रांतिमूलक था। उन्होंने वर्षों तक तो आंशिक, स्थानीय तथा अस्थायी वृद्धि को छोड़कर देश में सामान्य अथवा उल्लेखनीय रूप में मूल्य वृद्धि को स्वीकार ही नहीं किया।¹⁵⁸ आगे चलकर उन्होंने मूल्यवृद्धि के तथ्य को तो स्वीकार किया परंतु उसकी सार्थकता का विश्लेषण भिन्न रूप से प्रस्तुत किया। उनके विचार में मूल्यवृद्धि क्रयशक्ति में वृद्धि की सूचक न होकर राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट की और कृषि उत्पादन में ह्रास की चेतक थी।¹⁵⁹ इसके अतिरिक्त यह कृषि उपजों के बढ़ते निर्यात तथा यूरोप के बाजारों की ऊंची कीमतों का प्रभाव था।¹⁶⁰ उनमें से कुछ एक ने संकेत किया कि किसी भी रूप में बढ़ी कीमतों का लाभ वास्तविक उत्पादक को न मिलकर बिचौलियों, ऋणदाता, साहूकारों तथा निर्यात व्यापारियों, द्वारा ही हड़प लिया जाता था।¹⁶¹ उन्होंने अविलंब यह भी संकेत किया कि खेती तथा अन्य प्रकार के श्रम कार्यों में लगे समाज के निम्नतम वर्ग के मजदूरों की आय बढ़ती कीमतों के साथ उसी गति से नहीं बढ़ी है। बल्कि कुछ लोगों की आय तो घट गई है। ऐसे लोगों का तथा उन छोटे किसानों का जिनके पास बेचने के लिए फानू अनाज नहीं होता और जिन बेचारों को अपनी आवश्यकता के साधान का कुछ भाग खरीदना पड़ता है, ऊंची कीमतों से समृद्धि के बदले दुर्भाग्य ही बढ़ा है।¹⁶²

आधुनिक उद्योगों तथा यातायात साधनों का उदय और विकास समकालीन भारतीय आर्थिक विकास का एक ऐसा पहलू था जिसे दोनों पक्षों ने प्रचारात्मकता से हटकर एक मत से समर्थन दिया तथा उसे आर्थिक क्षमता का स्रोत स्वीकार किया। परंतु इस संबंध में भी भारतीय अर्थशास्त्रियों ने स्वदेशी उद्योगों के द्रुतगामी ह्रास पर गंभीर चिंता और निराशा प्रकट की। इस औद्योगिक उदासीनता से भारतीय समाज द्वारा अनुभूत आजीविका की भारी क्षति की पूर्ति आधुनिक मशीनी उद्योग के विकास द्वारा होती दिखाई नहीं देती।¹⁶³ उल्लेखनीय यह है कि विदेशी धन का आधुनिक भारतीय उद्योगों पर प्रभुत्व लाभप्रद परिणामों के बहुत बड़े भाग को अपने अधिकार में कर लेता है।¹⁶⁴ उनकी दृष्टि में रेलें भी विशुद्ध वरदान रूप नहीं थीं।¹⁶⁵

भारतीय नेताओं ने एक दृष्टि से अंगरेजी प्रशासन को नीचा दिखाया। भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता और उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती गति के संबंध में उनकी धारणाएं दृढ़ थीं। वे सदैव इस तथ्य की सत्यता की परीक्षा के लिए तथा वास्तविकता को उसकी गहराई में देखने के लिए निष्पक्ष तथा खुली जांच-पड़ताल का समर्थन करते थे। वस्तुतः उन्होंने जांच-पड़तालों को भारत की दरिद्रता समस्या संबंधी अपने आंदोलन का अभिन्न अंग बना लिया। दादाभाई नौरोजी अपने संपूर्ण सक्रिय राजनीतिक जीवन में, अपने निबंधों में, हाउस आफ कामंस में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तथा सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडियन फाइनेंस ऐंड दि रायल कमीशन आन दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्स-पेंडीचर आफ इंडिया (विलेबी कमीशन) के सामने साक्ष्य देते हुए, निरंतर जांच-पड़ताल की मांग करते रहे।¹⁶⁶

राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1900 में भारतीयों की आर्थिक दशा की पूर्ण तथा निष्पक्ष जांच की मांग प्रस्तुत की।¹⁶⁷ 1901 में इंग्लैंड स्थित भारतीय अकाल संध ने भारत के बहुत से विशिष्ट ग्रामों की आर्थिक स्थिति की विस्तृत जांच की योजना बनाई तो कांग्रेस ने उस योजना को अपना हार्दिक समर्थन दिया।¹⁶⁸ भारतीय नेताओं ने 1882 की बार-बार जांच के और 1888 की डफरिन जांच के परिणामों के प्रकाशन का बार-बार आग्रह किया। उन्होंने इन प्रकाशनों को रोकने को विश्वासघात बताते हुए अपने खुद के खुले दावों की पूर्ति के प्रति उपेक्षा के लिए सरकारी तंत्र की अच्छी खबर ली।¹⁶⁹

दरिद्रता के कारण

भारत की बढ़ती दरिद्रता अथवा सपन्नता विषयक वाग्युद्ध दोनों पक्षों द्वारा प्रबल पराक्रम और उत्कट साहसपूर्वक लड़ा गया। यद्यपि यह मतभेद वर्षों तक भारतीय राजनीति को जीवन प्रदान करता रहा तथापि अधिकाधिक इसे दो तथ्यों की स्थापना में सफलता मिली, प्रथम, भारतीय जनता के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्ग का जीवन स्तर अत्यंत ही निम्न है। इतना अधिक निम्न है कि उसे और अधिक नीचे नहीं धकेला जा सकता। द्वितीय, यदि भौतिक प्रगति अथवा परागति नाम की कोई स्थिति है भी तो उसकी दर इतनी स्वल्प तथा अपने-आप में उसका क्षेत्र इतना सकुचित है कि उसे वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित ही नहीं किया जा सकता।¹⁷⁰ दूसरे शब्दों में भारत की भौतिक स्थिति दरिद्रता के निम्न स्तर पर स्थिरता की ही है।

भारतीय नेताओं की दृष्टि में भारत की अर्थव्यवस्था की गति की दिशा का प्रश्न इस दृष्टि में महत्वपूर्ण था कि इससे प्रमुख रूप से तो भारतीय जनता और सरकार का दरिद्रता की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था और दूसरे बाद में यह निर्णय करने में कि इसके लिए किसका दायित्व है—महायता भी ली जा सकती थी।¹⁷¹ अध्ययन काल की अवधि के अधिकांश वर्षों में उनका प्रमुख लक्ष्य भारत की विश्वसम्मत घोर दरिद्रता का उन्मूलन था न कि चिड़ियों द्वारा खेत चुगे जाने के बाद पछनाना था।¹⁷² विदेशी शासकों तथा भारतीय नेताओं ने देश की चरम दरिद्रता के लिए उत्तरदायी तत्वों की समीक्षा करने में तथा उनके सुलभाने में अधिक ध्यान दिया क्योंकि वे इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि आर्थिक विकास के मार्ग की बाधाओं को भली प्रकार जान लेने पर ही उनके हटाने के उपायों का अनुशासन अथवा प्रयोग किया जा सकता है।¹⁷³ समय-समय पर ब्रिटिश भारतीय लेखकों और अधिकारियों ने भारत की असाधारण दरिद्रता के मबघ में अनेक विश्लेषण प्रस्तुत किए। भारतीय राष्ट्रवादियों ने उन्हें प्रायः निस्तार, अपर्याप्त तथा असंतोषप्रद बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

ब्रिटिश प्रशासकों ने अनेक बार भारत की निर्धनता के लिए भारत की जनसंख्या के आकार व वृद्धि को दोष दिया। उनके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि आजीविका के साधनों को शीघ्रता से पीछे छोड़ती जा रही है और इस प्रकार निर्धनता को अनिवार्य बनाती जा रही है।¹⁷⁴ लार्ड डफरिन ने 1888 में सेंट ऐंड्रयूज के भोज में पूछा जब इस देश में बढ़े-बढ़े जिलों और इलाकों में जनसंख्या बाढ़ की तरह बढ़ती जा रही है और

उन इलाकों के लोग प्रतिवर्ष भूमि की अवधारणा शक्ति की उपेक्षा करके कई गुना बढ़ रहे हैं तो प्रस्तुत ऐसे भयंकर खतरे से बचाव के लिए क्या अवकाश रह जाता है ?¹⁷⁶ मजे की बात यह है कि उसके उत्तराधिकारी वायसराय लार्ड लैंसडौन ने 1891 में जनसंख्या की वृद्धि को देश के भौतिक विकास के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया था।¹⁷⁶ भारतीय नेताओं ने इस धारणा को पूर्ण रूप से ठुकराया। उन्होंने इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया कि भारत की जनसंख्या तेजी में कई गुना बढ़ रही है अथवा भारत एक बहुसंख्यक देश है अथवा जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है।¹⁷⁷ वास्तव में उनके अनुसार भारत में जनसंख्या की दर इतनी कम है कि भारतीयों के सहज आत्मसंयम पर बहुत-कुछ कहा जा सकता है जिस पर माल्थस के सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री इतना बल देते हैं और इसके लिए हम सही रूप में ही श्रेय के भागी हैं।¹⁷⁸ किसी भी रूप में जीवन के दयनीय स्तर का घनी आबादी के साथ कोई संबंध नहीं। उदाहरणार्थ पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश भारत की अपेक्षा अधिक घनी आबादीवाले होने पर भी क्या भारत की अपेक्षा अधिक समृद्ध नहीं हैं ?¹⁷⁹ और न ही घन की वृद्धि के साथ जनसंख्या की वृद्धि असंगत है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड को मिलाकर पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देशों की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक तेजी से कई गुना बढ़ रहा है, फिर भी उनकी भौतिक सुविधाएं घटने के बदले बढ़ रही हैं।¹⁸⁰ 1890 में जी०वी० जोशी ने 'भारत की आर्थिक स्थिति'¹⁸¹ पर अपने एक लेख, जो आज भी समकालीन आर्थिक विश्लेषण का विशिष्ट उदाहरण है, में भारत की जनसंख्या अतिरेक के वास्तविक स्वरूप की पोल खोली। उसका प्रारंभिक तर्क था कि जनसंख्या में वृद्धि अपने-आप में आवश्यक रूप में अथवा सदैव एक बुराई नहीं है, जैसा कि माल्थस सिद्धांत के अनुयायी अर्थशास्त्री मानते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जो देश भौतिक समृद्धि के साधनों की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं तथा विज्ञान, कौशल और श्रम द्वारा और अधिक विकास का अवकाश नहीं है, वहां जनसंख्या में वृद्धि एक बहुत बड़ी बुराई है तथा उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए परंतु यह तथ्य भारत जैसे अविकसित देशों पर लागू नहीं होता जहां उत्पादक संपत्ति के भौतिक साधन, मनुष्य के श्रम, कौशल तथा विज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे देशों में माल्थस सिद्धांत के अनुसार तो जनसंख्या की वृद्धि एक अभिशाप न होकर उसके सर्वथा विपरीत अपने-आप में समृद्धि का एक बहुत बड़ा साधन है। विश्व के दो बड़े औद्योगिक देशों, यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस के आर्थिक इतिहास इस मंतव्य के साक्ष्य हैं। यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या 1806 की 150 लाख के मुकाबले 1882 में 340.60 लाख हो गई है फिर भी इसी अवधि में वहां राष्ट्रीय आय 17 करोड़ पाँच से बढ़कर 124 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई है। फ्रांस में जहां 1780 की 260 लाख जनसंख्या 1882 में बढ़कर 376 लाख हो गई है, वहां 1600 लाख पाँच से राष्ट्रीय आय बढ़कर 9650 लाख पाँच हो गई है। स्पष्ट है कि इस उदाहरण में माल्थस के जनसंख्या में रेखागणित और उत्पादनों में अंकगणित की गति से वृद्धि का नियम गलत सिद्ध हो गया है। वस्तुतः इसका कारण यह है कि इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ है उत्पादक श्रम की वृद्धि और ऐसी वृद्धि जब श्रम तथा

संपत्ति को अधिक प्रभावी बनाने वाली स्थितियों के विकास के साथ जुड़ जाती है तो उसका निश्चित परिणाम होता है उत्पादन में वृद्धि। भारत में भी जनवृद्धि वांछनीय है क्योंकि इस देश के आर्थिक विकास के आधारभूत प्राकृतिक साधन असीम तथा अप्रयुक्त हैं। इस प्रकार निष्कर्ष सर्वथा स्पष्ट है कि भारत में बुराई की जड़ कल्पित अधिक जनसंख्या न होकर साफतौर से कम जनसंख्या है।¹⁸⁷ जी०बी० जोशी ने निम्नलिखित अवतरण में विषय का अधिक स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है :

जनसंख्या और उत्पादन में सदैव एक प्राकृत अनुपात रहता है जो प्रत्येक समाज के औसत जीवनस्तर का निर्धारण करता है। जब जनसंख्या और उत्पादन दोनों सामान्य तथा बराबर दर से आगे बढ़ते हैं और अनुपात बनाए रखते हैं तब राष्ट्र के जीवनस्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। इसके विपरीत जब जनसंख्या असामान्य गति से बढ़ती है और उत्पादन अपनी सामान्य स्थिति में रहता है तब सही अर्थों में अत्यधिक जनसंख्या का रोग माना जाता है। जब उत्पादन गिर जाए और जनसंख्या सामान्य गति से बढ़ रही हो तो उसे अपर्याप्त उत्पादन का रोग ही कहना चाहिए। पश्चिम की पूँजीपति राजनीतिक अर्थव्यवस्था केवल एक 'अनुपात' शब्द को ही देखती हुई दो नितांत भिन्न प्रकृति की बुराइयों को परस्पर मिला देती है। इसी रूप में वह भारत के संबंध में दोनों स्थितियों में 'अत्यधिक जनसंख्या' का प्रयोग करती है। जैसाकि हम पहले देख चुके हैं, यहां जनसंख्या सामान्य गति का अतिक्रमण करके नहीं बढ़ रही है और यदि देश का कुल उत्पादन आवश्यकता के परिमाण के अनुरूप नहीं बढ़ता जबकि देश में भौतिक साधनों की प्रचुरता है, तो यह स्पष्टतः राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा घोषित अत्यधिक जनसंख्या का रोग न होकर अपर्याप्त उत्पादन का ही रोग है जिसे धीरे लीन मान्यता नहीं देते।¹⁸²

इसके अतिरिक्त यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो भी उसके परिणामस्वरूप दरिद्रता में वृद्धि होना आवश्यक नहीं, क्योंकि तेजी से उद्योगीकरण करके इसका प्रतिकार किया जा सकता है। इस देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए रोटी जुटाने का प्रश्न इस समय निस्संदेह गंभीर है और दुर्निवार है; परंतु हमारी समझ में बढ़ते हुए मजदूरों के लिए पर्याप्त काम जुटाना उससे भी अधिक गंभीर और दुर्निवार प्रश्न है।¹⁸⁴ परोक्ष रूप से उस समय सभी भारतीय नेताओं ने यही सिद्धांत अपनाया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय कृषि पर सचमुच आवश्यकता से अधिक दबाव है परंतु यह दबाव अत्यधिक जनसंख्या का फल न होकर देशी उद्योग के बलपूर्वक विनाश तथा नियोजन के अभाव का परिणाम है और यह भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की देन है।¹⁸⁵ इस समय अत्यधिक जनसंख्या की बात कहना किसी व्यक्ति के रूप काटकर उसपर अपने को पालने में अशक्त अथवा काम करने में अयोग्य होने का 'वर्ण्य' करने के समान है।¹⁸⁶ यह कहा गया कि इन परिस्थितियों में अत्यधिक जनसंख्या का सिद्धांत, जिस समस्या में जनता का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है और यह दुखते घावों पर नमक छिड़कने के समान भयंकर रूप से पीड़ादायक तथा अपमानजनक है।¹⁸⁷

भारतीयों की दरिद्रता के संबंध में एक अन्य घिसा-पिटा सरकारी स्पष्टीकरण

1862 22.11.1952
Page 701
Po. 456/-

यह था कि भारतीय प्रकृति से उदार तथा फिजूलखर्च हैं जिसके फलस्वरूप वे विवाहो तथा अन्य सामाजिक उत्सवों में अपरिमित खर्च करते हैं।¹⁸⁸ 1888 की आर्थिक जाच के प्रतिवेदन में यह कहा गया, मितव्ययिता का अभाव भारतीयों की एक प्रमुख विशेषता है।¹⁸⁹ प्रत्येक प्रतिवेदन में विवाहो तथा अन्य दूसरे समारोहों में मुक्तहस्त से व्यय करने की प्रचलित प्रथा का उल्लेख है।¹⁹⁰ किसानों के निरतर कचहरियों में मुकदमेबाजी करने रहने को भी इसी फिजूलखर्ची का रूप बताया गया।¹⁹¹ कभी-कभी तो यह भी कहा गया कि भारतीय किसान और मजदूर उत्साहशून्य, बेसमझ और निराशापूर्ण कर्मचारी होने के कारण भला कैसे गरीब न हो ?¹⁹² भारतीय नेताओं ने बड़ी तीव्रता से इस धारणा का खंडन किया कि भारतीय अदूरदर्शी अथवा फिजूलखर्च हैं और फिजूलखर्ची भारतीयों का चरित्रगत मूल दोष है। इसके विपरीत सत्य यह है कि विश्व में भारतीय किसान स बढकर अधिक अल्पाहारी, मितव्ययी तथा सयमी कोई दूसरी जाति ही नहीं।¹⁹³ जहां तक विवाह तथा इसी प्रकार के अन्य समारोहों पर होनेवाले खर्चों का प्रश्न है, वास्तव में एक तो ऐसे अवसर विरल हैं और दूसरे उनपर होने वाले खर्चें स्वल्प ही हैं।¹⁹⁴ इन परिस्थितियों में ये खर्चें जनता की निर्धनता का कारण नहीं बन सकते।¹⁹⁵ क्या भारतीय जनता किसी भी स्थिति में कुछ क्षण मौज-मेला मनाने का अधिकार नहीं रखती ? क्या भारतीयों का सम्यता में, जीवन में, जीवन के लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक आनंदों के उपभोग में प्रगति का कोई अधिकार अथवा प्रयोजन नहीं ? क्या उन्हें सदा पशु के स्तर का जीवन ही जीना चाहिए ? उन्हें सामाजिक खर्च नहीं करने चाहिए ? क्या यह सब फिजूलखर्ची, जडता तथा चितनशक्ति का अभाव है ?¹⁹⁶ इस समस्या को एक भिन्न दृष्टि से देखते हुए अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से जी० वी० जोशी ने अपना मतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अपने साधनों की सीमा में न रहना भी अत्यधिक जनसंख्या की तरह एक सापेक्ष धारणा है। इसे दो रूपों में देखा जा सकता है : (1) आय से अधिक व्यय करना अथवा (2) आवश्यकता की अपेक्षा आय कम होना। यदि हमारी अर्जन शक्ति इतनी निम्न है जितनी कि इस समय है तो निश्चित है कि हमारी आय हमारे आवश्यक व्यय के स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि दोष हमारी फिजूलखर्ची और बचत न करने की प्रवृत्ति का नहीं प्रत्युत देश के उस औद्योगिक जीवन का है, जिसके कारण हमारा अर्जन इतना निम्न है।¹⁹⁷ भारतीय नेताओं ने भी जाच से पाया कि भारतीय किसान अन्य देशों के किसानों के मुकाबले उत्सवों और समारोहों के प्रति कोई विशेष अधिक रुचि नहीं रखता।¹⁹⁸ इसी प्रकार भारतीय किसान पर आलसी और कामचोर होने का दोष भी नहीं लगाया जा सकता। वस्तुतः वह विश्व में सर्वाधिक कठोर श्रम करनेवालों में एक है।¹⁹⁹ इसके अतिरिक्त भारतीय किसान में पाए जाने वाले दुर्गुण, अदूरदर्शिता, अज्ञान तथा निरुत्साह, कारण न होकर उसे अवसर तथा प्रेरणा के रूप में सुधार के लिए जुटाए गए अपर्याप्त आर्थिक प्रबोधों के परिणाम हैं। फ्रांस में 18वीं शताब्दी के अंत में सामंतवादी व्यवस्था के उन्मूलन पर वहां के किसानों के स्वभाव और रुचियों में हुए परिवर्तन के अध्ययन से इस तथ्य की सत्यता को आका जा सकता है।²⁰⁰ इस प्रकार निश्चित है कि किसानों की फिजूलखर्ची एक अलग प्रसंग है, वह

भारत की निर्धनता का बहाना न होकर एक सामाजिक रोग है। इस रूप में भारतीय नेताओं ने सामाजिक उत्सवों पर अनुचित तथा अधिक व्यय की भर्त्सना भी की तथा आत्मसंयम का प्रचार भी किया।²⁰⁰ जहां तक कचहरियों द्वारा किसान के गरीब होने का प्रश्न था, राष्ट्रवादियों की दृष्टि में इसके लिए स्वयं ब्रिटिश राज्य ही दोषी था, क्योंकि कचहरियां उसकी देन थीं, राष्ट्रवादियों ने तत्परता से इन कचहरियों को समझौता समितियों की स्थापना अथवा पुरानी पंचायत व्यवस्था के पुनरुद्धार द्वारा हटाने का समर्थन किया।²⁰¹

भारतीय नेताओं ने इस मत का भी खंडन किया कि भयंकर दर से मूद वसूलने वाले साहूकार ग्रामीण जीवन के विनाश का तथा भारत की दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण थे।²⁰² उनके दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण इसी ग्रंथ के दशम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। उनके विचार में किसानों की दरिद्रता में साहूकार की भूमिका गौण थी। वस्तुतः वह किसानों की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणभूत तत्व ही नहीं था। वह तो परिस्थितियों का कारण न होकर परिणाम था क्योंकि केवल पहले से ही अभावग्रस्त और असहाय किसान ही उसके पास सहायता के लिए जाते थे।

19वीं शताब्दी के अंत में जब बार-बार पड़ने वाले भयंकर अकालों से भारत विनाश का ऐसा बुरा शिकार बना कि उसने समस्त विश्व की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और जैसाकि हम पहले देख चुके हैं, उन्होंने भारत की दरिद्रता की समस्या को देश की राजनीति का प्रमुखतम प्रश्न बना दिया—दरिद्रता के कारणों को अकालों के उद्गमों से मिला दिया गया—तो ब्रिटिश अधिकारियों ने अकाल के वर्षों में और उसके परवर्ती वर्षों में फैले दुर्भाग्य तथा भौतिक पदार्थों के नाश को देखते हुए अकालों को भारत की दरिद्रता के लिए दोषी ठहराया। परंतु इस धारणा के विरुद्ध भारतीय नेताओं ने देशवासियों की दरिद्रता को ही निरंतर, तीव्र और विनाशकारी अकालों के लिए उत्तरदायी स्वीकार किया। इस प्रकार प्रश्न उठा कि अकालों के क्या कारण थे? लार्ड कर्जन ने उत्तर देने का दायित्व लेते हुए 1900 में अपनी सामान्य सशक्त शैली में कहा, 'अकालों का वास्तविक कारण समय पर वर्षा का न होना और उसके फलस्वरूप फसल का सूख जाना ही था। उसका तर्क था कि यदि भारत में पड़े बहुत बड़े सूखे के फलस्वरूप अपरिहार्य कृषि उत्पादन की भारी हानि को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी सरकार न तो आकाश पर नियंत्रण रख सकती है और न ही प्रकृति के इतने बड़े पैमाने पर विनाशकारी रूप की तथा उसके परिणामों की पहले से ही कल्पना कर सकती है।'²⁰³ 1902 तक तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल न्यूनाधिक रूप से यह मानने लगे थे कि भारत के अकाल ईश्वर का विधान थे और उन्हें रोकने अथवा हटाने की दिशा में मानव कुछ भी करने में असमर्थ है :

किसी सरकार को उस देश में पड़नेवाले अकालों को रोकने के लिए कहना, जिसकी मौसम संबंधी स्थिति ऐसी हो जैसी भारत देश की है और जिसकी जनसंख्या उस परिमाण में बढ़ रही हो जैसी इस समय भारत में बढ़ रही है, सर्वशक्तिमान विधाता के हाथ से विश्व का नियंत्रण छीनकर अपने हाथ में करने को कहना है।²⁰⁴ गत वर्ष

शरद ऋतु में केवल ईश्वर की ही कृपादृष्टि थी कि मानसून फिर से आ गया... फलतः इस शीत ऋतु में संभावित अकाल की स्थिति संपन्नता में बदल गई। विश्व की सर्वोत्तम सरकार एक क्षण में परिवर्तन को द्रुतगामी नहीं बना सकती और निकृष्टतम सरकार उसे विलंबित नहीं कर सकती।²⁰⁴

अकाल भारत में सदा से रहे हैं और आनेवाले अपरिमित समय तक पड़ते रहेंगे। एक सम्य सरकार तो अधिक से अधिक उनकी तीव्रता और विस्तार को ही घटा सकती है।²⁰⁵

दूसरी ओर राष्ट्रीय मान्यता यह थी कि दुर्भिक्ष प्रकृति के प्रकोप के फल न होकर मानव की असफलताओं के परिणाम है अतः वे रोके जा सकते हैं।²⁰⁶ यह ठीक है कि अकालों का तात्कालिक कारण वर्षा का अभाव है।²⁰⁷ परंतु स्थिति के इस विश्लेषण पर रुक जाना उचित नहीं। अपर्याप्त वर्षा अकालों का समुचित विश्लेषण नहीं क्योंकि सिंचाई जैसे वैज्ञानिक प्रयत्नों द्वारा प्रकृति को मानव के नियंत्रण में लाया जा सकता है।²⁰⁸ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय विषय यह है कि अति द्रुतगामी यातायात साधनों के होने पर भी किसी एक विशेष कोने में केवल एक ही फसल के बिगड़ जाने पर अकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? ²⁰⁹ आखिर सारे देश में एक साथ ही फसलें शायद ही कभी खराब होती हों? और ऐसा वर्ष कभी नहीं रहा जब देश का कुल खाद्य उत्पादन यहां की कुल जनसंख्या की पूर्ति के लिए अपर्याप्त पड़ा हो।²¹⁰ विचारणीय यह भी है कि यूरोप के बहुत सारे देश भी तो अकाल का शिकार बनते हैं परंतु फिर भी प्रायः वे इस भयंकर दानव के उत्पात से बच जाते हैं।²¹¹ इंग्लैंड तब भी भुखमरी का शिकार नहीं हुआ जब सामान्य वर्षों में ही उसका उत्पादन उसकी खाद्य आवश्यकताओं के मुकाबले कठिनता से 50 प्रतिशत था।²¹² भारत में सामान्य नियम के अनुसार या तो खाद्यान्नों का विदेशों से आयात किया जा सकता था अथवा देश में ही अतिरिक्त अनाज वाले क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों को अनाज भेजा जा सकता था।²¹³ इन दोनों संभावनाओं को न अपनाया यही सिद्ध करता है कि अकाल फसल के बिगड़ने का फल नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों के उपलब्ध संभरण को खरीदने के साधनों के अभाव के ही परिणाम है।²¹⁴ यदि भारतीय वर्षा के अभाव के एक ही धक्के को सहन करने का दम नहीं रखते तो यह तथ्य उनकी नितांत दरिद्रता को ही सिद्ध करता है।²¹⁵ अतएव दुर्भिक्षों का मूल तथा स्पष्ट कारण देश को जकड़ने वाली दरिद्रता है।²¹⁶ दुर्भिक्षों की तीव्रता तथा विस्तार से देशवासियों की अवरोध शक्ति घट रही है, सहनशक्ति का पूर्ण अभाव हो गया है, इसका ही परिणाम फसलों के बिगड़ने का अर्थ समग्र रूप से भुखमरी हो गया है।²¹⁷ फसलों का उजड़ना गरीबी का कारण नहीं बनता बल्कि गरीबी ही तंगी को अकाल का रूप दे देती है।¹⁹ एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यही कहा जा सकता है कि फसलों की असफलता ने भारतीय दरिद्रता पर केवल तीव्र प्रकाश ही डाला है।²¹⁸

भारतीय नेताओं ने सिद्ध किया कि प्रकृति को भारत की दरिद्रता के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देश को प्रकृति ने तो बहुत उपहार दिए हैं। इसके पास भौतिक साधनों का इतना बड़ा अक्षय भंडार है कि जिसे अतुल भने ही न कहा जाए परंतु वह अद्वितीय अवश्य है। भारत को भौतिक प्रगति के लिए अत्यंत

अनुकूल परिस्थितियों के रूप में प्रकृति से सौभाग्य का वरदान मिला हुआ है।¹²⁰ इस विश्लेषण ने समस्या को और अधिक कटु बना दिया और प्रश्न उठा कि जब देश सपन्न है तो देशवासी क्यों विपन्न हैं ?¹²¹

राष्ट्रवादियों ने अंगरेजों के भारत की दरिद्रता विषयक विश्लेषण को निस्सार तथा गक्षपातपूर्ण बताते हुए उसे अमान्य कर दिया। वे भारत की दरिद्रता के सही कारणों को जाचने के लिए प्रवृत्त हुए और अपनी खोज के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत की दरिद्रता पारंपरिक और अपरिहार्य नहीं। यह मानव निर्मित है अतः इसका विश्लेषण तथा निवारण किया जा सकता है।¹²² भारत कुछ एक आर्थिक तत्वों के फल-स्वरूप निर्धन है। उन तत्वों की खोज, समीक्षा तथा उनपर नियंत्रण किया जा सकता है।¹²³ इस प्रकार समस्या के प्रति शासक और शासित के दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर था जिसका अभी ऊपर निर्देश किया गया है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने भारत की दरिद्रता के दो संभव कारण प्रस्तुत किए। प्रथम, या तो यह प्रकृति के क्रूर कृत्यों का परिणाम है अतः यह असाध्य रोग है। कम से कम इस थोड़े से समय में तो इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता अथवा यह भारतीयों की अपनी सामाजिक अथवा आर्थिक त्रुटियों का फल है जिसका प्रतिकार यदि किया जा सकता है तो स्वयं भारतीयों द्वारा अपने आप ही किया जा सकता है।¹²⁴ इन दोनों अवस्थाओं में निर्धनता के अस्तित्व तथा निराकरण के लिए शासकों का कोई विशेष दायित्व नहीं।¹²⁵ दूसरी ओर भारतीय नेताओं ने भारत की दरिद्रता के जन्म के तत्वों और शक्तियों को रेखांकित किया। उनके अनुसार जिन तत्वों ने भारत की निर्धनता में वृद्धि की वे ब्रिटिश राज्य के वे जाने-अनजाने तत्व और शक्तियाँ थी जिन्हें पूरी ढील दी गई और जिनका प्रमुख रूप से प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन द्वारा प्रतिकार किया जा सकता था।¹²⁶ इस प्रकार इतिहास के एक विचित्र व्यंग्य के रूप में यह तथ्य सामने आया कि वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत पश्चिम प्रकृति के तथा वर्तमान सामाजिक शक्तियों के अपरिहार्य प्रभाव की भाग्यवादी धारणा को पुष्टि करता है और पिछड़ा हुआ पूर्व मनुष्य की प्रकृति और समाज को नियंत्रित तथा शासित करने की क्षमता को स्वीकार करता है।

भारतीय जनता की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणों और तदनुसार उसके निवारण के उपायों की खोज की धुन में ही भारतीय नेताओं ने कुछ एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न तैयार किए ताकि उनपर अपनी जाच-पड़ताल, वाद-विवाद तथा आंदोलन-केंद्रित कर सकें। अतः उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियाँ और दृष्टिकोण निर्धारित किए तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक तंत्र तथा उसकी प्रकृति को समझने की चेष्टा की। निर्धनता को हटाने के सर्वाधिक समय तथा आर्थिक नीतियों को कार्यरूप में परिणत करने के समय उनकी राजनीति चेतना एक रूप ग्रहण करती गई। इस विकास की प्रक्रिया का अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे। यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि निर्धनता की समस्या ने भारतीय नेताओं की सभी परवर्ती खोजों, मतभेदों तथा प्रचार आदि के लिए निरंतर संजीवनी का काम किया।

संदर्भ

1. दादाभाई नौरोजी के 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स' (मद्रास, तिथिरहित) (निर्देश के लिए इसे आगे 'स्पीचेज' से संकेतित किया जाएगा।) पृ० 669-670.

2. जिन लाभो की बहुधा घोषणा की जाती थी वे इस प्रकार थे

शांति, कानून और व्यवस्था, पश्चिमी शिक्षा, केंद्रीकृत प्रशासन, देश का राजनीतिक एकीकरण और इन सबके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का विकास, रेल, तार, अस्पताल आदि।

देखिए—सी० एल० पारीख द्वारा संपादित—नौरोजी के 'एसेज, स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स' (बम्बई 1887) (निर्देश के लिए इसे आगे 'एसेज' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 26-7, 37, 131-2 'स्पीचेज'—पृ० 235-6 इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाग 1, कांग्रेस प्रेसिडेंटो (अध्यक्षो) के एड्रेस (भाषण) मद्रास, तिथि-रहित, (निर्देश के लिए इसे आगे 'सी० पी० ए०' से संकेतित किया जाएगा।) पृ० 6-10 अंगरेजी शासन के अन्य लाभो की समीक्षा के लिए उदाहरण के रूप में देखिए, 'सी पी ए' में अनेक कांग्रेस अध्यक्ष पृ० 4, 81, 115, 307-11, 346, 375-6, 738 जी० बी० जोशी के 'राइटिंग्स ऐंड स्पीचेज' (पूना 1912), पृ० 616, आर० एन० मुघोलकर की रचना 'दि इकोनामिक कंडीशन आफ दि पीपल आफ इंडिया, इंडियन पानिक्टिस' (मद्रास, 1898), पृ० 3-8, एल्फ्रेड नडो 'दि पावर्टी आफ इंडिया', वही, पृ० 106, सी० बी० चित्तामणि पन्ना 'इंडिया ऐंड लार्ड कर्जन', हिंदुस्तान रिव्यू तथा 'कामस्थ समाचार' (निर्देश के लिए इसे आगे 'एच० आर०' से संकेतित किया जाएगा)—जून 1901, पृ० 451 आर० सी० दत्त द्वारा लिखित, 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया अर्ली ब्रिटिश रूल' (1901 में प्रथम प्रकाशित संस्करण का लंदन में 1956 में मुद्रित रूप) (निर्देश के लिए इसे आगे 'इ० एच०' से संकेतित किया जाएगा), पी० बी० एस० एन० बैनर्जी के 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स' (मद्रास, तिथिरहित) (संदर्भ के लिए इसे आगे 'एस० डब्ल्यू०' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 219-20, 258-9, 303-5, 331 इसके अतिरिक्त देखिए, 'दि अमृतबाजार पत्रिका' (निर्देश के लिए इसे आगे 'ए० बी० पी०' से संकेतित किया जाएगा)—दिसंबर 1878, 24 नवंबर 1897.

3 नौरोजी 'एसेज', पृ० 28

4 वही, पृ० 134-5 भोलानाथ चंद्र मुकुर्जी के मैगजीन (कलकत्ता) में 1875-6 में बिना नाम के प्रकाशित) अपने अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध परंतु अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण लेख, 'ए वाइस फार दि कामर्स ऐंड मैनूफैक्चरर्स आफ इंडिया'—(निर्देश के लिए इसे आगे 'एम० एस०' से संकेतित किया जाएगा) में लिखते हैं 'देश के लिए वास्तविक अर्थनीति को सुझाने में अक्षम भारतीयों ने अपने चारों ओर की थोड़ी चकाचौंध से चौंधिया कर अपने शासको पर विश्वास करते हुए उनके दृष्टिकोण को बिना किसी आलोचन-प्रत्यालोचन के स्वीकार कर लिया। भारतीयों ने वेदों के समान अंगरेजी अधिकारियों की व्यापार नीति पर अंधविश्वास ही किया; परंतु दिन-प्रतिदिन ज्ञान का प्रकाश उनके दिमाग की धुंध को साफ कर रहा है। भारतीय जितना अधिक गहराई से विचार करते गए उतना ही यह तथ्य अपने नग्न रूप में उनके सामने स्पष्ट होता गया कि अंगरेजी व्यापार नीति उन्नति के मार्ग को निरंतर सकीर्ण बनाती हुई उन्हें घोर खरब्रता की ओर ले जा रही है'

—खंड II 1873, पृ० 83-4

बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को अत्यंत ही सजीव

रूप में इन शब्दों में प्रकट किया 'सर्वप्रथम भारतीय अगरेजों के अनुशासन से अत्यंत चमत्कृत हुए। रेल, तार, सबको, पुलों तथा स्कूलों आदि ने उन्हें विस्मित-विभोहित कर दिया। उपद्रव समाप्त हो गए तथा लोग शांति और स्थिरता का आनंद भोगने लगे। लोग यह कहने लगे कि एक भ्रष्टा व्यक्ति भी खुले रूप में सोना लेकर बनारस से रामेश्वर तक की यात्रा कर सकता है, परंतु जिस प्रकार मदिरा का नशा दीर्घ काल तक नहीं बना रहता, उसी प्रकार भ्राति के कारण उत्पन्न यह मतिभ्रम भी काफी समय तक न बना रहा। लोग यह अनुभव करने लगे कि एक भ्रष्टा व्यक्ति भी खुला सोना लेकर यात्रा अवश्य कर सकता है परंतु दिन-प्रतिदिन सोना दुर्लभ होता जा रहा है'

—जी० पी० प्रधान तथा ए० के० भागवत के 'लोकमान्य तिलक' (बंबई, 1958) पृ० 72 से उद्धृत

और देखिए, 'बंगाली', 10 मई 1884, 'इंडियन स्पेक्टर', 18 मई 1884, 'मराठा' 21 दिसंबर 1884, 6 जून 1886, के 'मराठा' में प्रकाशित ए० एल० राय का लेख, जी० मुबहाष्य अय्यर की रचना 'सम इकोनामिक आस्पेक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (मद्रास, 1903) (निर्देश के लिए इसे आगे 'इ० ए०' से संकेतित किया जाएगा), पृ० 317 एल० एम० घोष की कृति 'सी० पी० ए०' पृ० 762

- 5 1901 (लंदन) में प्रकाशन के समय से ही भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए सचमुच पाठ्यपुस्तक बनने योग्य कृति 'प्रास्पेक्टस ब्रिटिश इंडिया' में पृ० 127, 8, 131 में विलियम डिगबी महोदय ने 1876-1900 तक 18 अकालों की क्रमशः गणना की है जिनमें चार तो अभूतपूर्व रूप से भयंकर अकाल थे
- 6 'परंतु हमसे भी गंभीर प्रश्न यह उठा कि भारत में इतने दुर्भिक्ष क्यों पड़ते हैं? भूख से मृत्यु-दर इतनी भयंकर क्या है? विश्व के किमी अन्य सभ्य देश में उन्होंने एस दुर्भिक्ष कभी नहीं सुना था'

आर० सी० दत्त 'स्पेसिज एंड पपर्स ऑन इंडियन क्वेश्चन्स 1897-1900' (कलकत्ता, 1908) (निर्देश के लिए इसे आगे 'स्पेसिज' संकेतित किया जाएगा), पृ० 36

इंडियन नेशनल कांग्रेस (सदस्यों के लिए इसे आगे 'आई० एन० सी०' से संकेतित किया जाएगा) के 1900 वर्ष का प्रस्ताव 11 भा देखिये

- 7 उदाहरण के लिए देखिए, नीरोजी, 'एसेज' पृ० 135, तथा 'जब आप हमारी वास्तविक इच्छाओं को जान लेंगे, तब न्याय करण इसमें मुझ लेशमात्र भी संदेह नहीं। वही, और भी देखिए सी० पी० ए०', पृ० 13, 22, 3, 91-2, 129, 149, 188, 324, 380, 397, 405, 475, 490, 532
- 8 उदाहरण के लिए देखिए, नीरोजी 'एसेज', पृ० 128
- 9 जी० के० गांधी 'स्पेसिज' (मद्रास 1916), पृ० 52
- 10 उदाहरण के लिए देखिए, नीरोजी पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (लंदन 1901) (निर्देश के लिए इसे 'पावर्टी' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 147 तथा आई० एन० सी० का 1900 का द्वितीय प्रस्ताव
- 11 उदाहरण के लिए देखिए, रानाडे 'एमज ऑन इंडियन इकॉनामिक्स' (बंबई, 1892) (निर्देश के लिए इसे 'एसेज' से संकेतित किया जाएगा), पृ० 191-2 तथा जी० बी० जाशी की पूर्वोक्त रचना, पृ० 754

12. नोरोजी : 'एसेज', पृ० 97-111.
13. वही, पृ० 97.
14. खंड 2-5, पृ० 1873-6.
15. नोरोजी . 'पावर्टी' पृ० 1-142 इसके अंतर्गत 1876 में लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा के सामने पढ़े गए लेख हैं तथा साथ ही लेखक की निम्नलिखित टिप्पणी सलग्न है :
ये टिप्पणियाँ अपने मूल प्रारूप में 'सिलेक्ट कमेटी ऑन इंडियन फाइनेंस' के सामने रखी गई थी । इनपर विचार भी हुआ था परंतु इन्हें प्रतिवेदन के साथ प्रकाशित नहीं किया गया था । मेरे विचार में इसका कारण कदाचित् यह है कि ये टिप्पणियाँ न तो अध्यक्ष (श्री आयटन) के मतव्य के अनुकूल थी और न ही तत्कालीन अवर भारत सचिव, सर ग्रांट डफ को मान्य थी
16. जी० बी० जोशी 19वीं शताब्दी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे । दुर्भाग्य से उनके सरकारी कर्मचारी (पहले वह सरकारी स्कूल के अध्यापक थे और फिर मुख्याध्यापक बने) होने से वह न तो प्रकाश में आ सके और न ही अपने समकालीन अपेक्षाकृत कम महत्व के व्यक्तियों के समान प्रसिद्धि ही प्राप्त कर सके । बीसवीं शताब्दी के पच्चीस वर्षों के भारतीय व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों में वरिष्ठ जी० जी० काले ने अपनी पुस्तक 'गोखले ऐंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस' में उल्लेख किया है, 'जोशी के प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्याओं के ज्ञान का अनिर्क्रमण लगभग अन्य कोई भारतीय नहीं कर सकता था ।' (पृ० 54) जे०के० गोखले ने जोशी को अपने दो गुरुओं (निर्माताओं) में से एक माना है । (जोशी के साथ दूसरा नाम जमिंदार रानाड का है । गोखले ने अपने भाषणों आदि को तैयार करने में प्राण सहायता के लिए जोशी के श्रम को बड़े सुंदर शब्दों में ज्ञापित किया है । देखिए, 'गोखलेज लैटर्स टु जोशी', दिनांक 16 अप्रैल 1897, 14 मई 1897 तथा 10 अप्रैल 1900 प्रतिम पत्र में अपने बजट भाषण की जन प्रशंसा का उल्लेख करते हुए गोखले ने लिखा था 'वस्तुतः यह आपका ही भाषण था, न कि मेरा । मैं प्रायः यह अनुभव करता हूँ कि इसका श्रेय स्वयं लेकर जनता के साथ मैं सचमुच छल ही कर रहा हूँ ।'
17. दत्त ई० एच० I, क्रमशः पृ० V तथा XIII
18. भोलानाथ चंद्र पूर्वोक्त स्थल खंड II, 2873, पृ० 84
19. नोरोजी 'ब्रिटिश राज्य के लाभ और भारत की दरिद्रता' पर 1888 में दिया गया भाषण. 'सी० एल० पारोख द्वारा संपादित' 'इन एमिनेंट इंडियंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स' (बंबई, 1892) (निर्देश के लिए इसे आगे 'एमिनेंट इंडियंस' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 161. 1876 से पूर्व उन्होंने इसे 'महत्वपूर्ण प्रश्न' अथवा इसमें भी अधिक 'आज का अतिगंभीर प्रश्न' बताया था (पावर्टी, पृ० 1).
20. हिंदू, 27 मई 1891
21. नोरोजी . सी०पी०ए०, पृ० 157 उन्होंने जोर देकर कहा था . 'यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर हमें अपनी सर्वोच्च शक्ति लगानी होगी ।'
22. जी० एस० अय्यर, ई०ए०, पृ० 9
23. बंगाली, 14 मार्च, 1902.
24. दत्त स्पीचेज ऐंड पेपर्स ऑन इंडियन क्वेश्चंस 1901 ऐंड 1902 (कलकत्ता, 1904) (निर्देश के लिए इसे आगे स्पीचेज II से संकेतित किया जाएगा), पृ० 86.

25. न्यू इंडिया (कलकत्ता), 12 अगस्त 1901 संपादकीय में आगे कहा गया है. 'और यह सत्य का उद्घाटन करता है कि सभी उन्नतादी राष्ट्रीय नेता प्रमुख रूप से भावात्मक राष्ट्रीयतावाद में रुचि नहीं लेते थे, और यद्यपि वे नवीन भारत को प्रभावित करने वाले किसी भी—राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक—प्रश्न, की उपेक्षा कदापि नहीं करना चाहते थे, तथापि वे आज की आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं के लिए निरंतर आंदोलन को ही अपना विशिष्ट विषय बनाना चाहते थे
26. रानाडे, एसेज, पृ० 5.
27. इसी पत्र ने 7 नवंबर 1894 के प्रक में इस दृष्टिकोण के एक अन्य मौलिक पक्ष की ओर इस प्रकार संकेत किया 'शरीर और आत्मा को एक साथ रख पाने के साधनों से हीन राष्ट्र कभी सतुष्ट नहीं हो सकता 'कभी स्वाभिमत नहीं हो सकता'
28. 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्पाति पद से अपने भाषण में दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की यदि अनंत भारत दुर्भाग्य के गढ़ में गहरे से गहरे घसता ही गया तो अंगरेजी राज्य से प्राप्त लाभ तथा अंगरेजी शासकों की सुंदर कल्पनाएं सर्वथा निरर्थक ही हो जाएगी
- सी०पी०ए०, पृ० 22
- सुरद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित 'दि बंगाली' ने 9 मार्च, 1902 में लिखा इस बात को कौन अस्वीकार करेगा कि अशक्त और भूखे लोगों के लिए कानून और व्यवस्था देने वाली एक अच्छी और वैज्ञानिक सरकार की अपेक्षा प्रतिदिन की रोटी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. निस्संदेह कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी चीजें हैं परंतु रोटी उनसे भी अधिक अच्छी है
- साथ ही देखिए, एस०एन० बनर्जी 'स्पीचेज' (1880-84 खंड II), (कलकत्ता 1885), पृ० 3, 5, सी०पी०ए०, पृ० 697, बंगाली, 28 जनवरी, 1882, मराठा 30 दिसंबर 1894; पी० मेहता : 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग' (इलाहाबाद, 1905) (निर्देश के लिए इसे आगे 'स्पीचेज' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 451, नौरोजी 'स्पीचेज' पृ० 389; भारतजीवन 11 दिसंबर, 'इन दी रिपोर्ट आन नेटिव प्रेम इन नार्थ-वेस्ट प्राविसेज ऐंड अवघ' (निर्देश के लिए इसे ओ 'आर०एन० पी०एन०' से संकेतित किया जाएगा) 19 दिसंबर 1899, एडवोकेट, 27 नवंबर (वही, 29 नवंबर, 1901)
29. कांग्रेस के 1902 के सत्र में तीसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जी० एम० अय्यर का तर्क था : कांग्रेस अपनी सारी शक्ति और सारा ध्यान, जहां तक संभव हो, विशिष्ट तथा अतिमहत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही केन्द्रित करे जनता की दरिद्रता का प्रश्न सर्वोच्च और ध्यानाकर्षक प्रश्न है. वस्तुतः इस एक प्रश्न का सतोषप्रद तथा सही समाधान ही अन्य सभी दिशाओं में देश के सुधार का एकमात्र आधार है।' रिपोर्ट आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस—1902 (निर्देश के लिए इसे आगे 'रिप०आई०एन०सी०' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 72 साथ ही देखिए एन०के०एन० अय्यर 'रिप०आई०एन०सी०'—1901, पृ० 142
30. ह्साई (चतुर्थ वर्ग), खंड 27. लगभग 1135.
31. 15 अगस्त, 1947 तक क्रोध और भर्त्सना जारी रही, भारतीय इतिहास के ब्रिटिश काल के इतिहासकारों में आज भी इस सबंध में मतभेद है
32. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 1
33. वही, पृ० 31.
34. नौरोजी; इन एमिनेंट इंडियंस, पृ० 161.

35. उनके द्वारा इंग्लैंड में अपने प्रिय विषय पर सैकड़ों भाषाओं में से अधिकांश उनकी उपर्युक्त तीन प्रकाशित कृतियों : 'एसेज, स्पीचेज 'ऐंड पावर्टी' में भी दिए गए हैं। बहुत सारे अन्य भाषण पूर्ण अथवा सक्षिप्त रूप में भारत में खोज का विषय हैं। आई०एन०सी० की ब्रिटिश कमेटी का 1890 से संदन से प्रकाशित जनरल.
36. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 161.
37. वही, पृ० 88.
38. नौरोजी : स्पीचेज, परिशिष्ट-ए, पृ० 6.
39. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 652.
40. प्रस्ताव II. 1886 के कांग्रेस के प्रतिवेदन की भूमिका में कहा गया है कि जनता में व्याप्त घोर दरिद्रता के प्रति किसी एक प्रतिनिधि ने भी किसी रूप में सदेह अथवा प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया। ब्रिटिश राज्य के प्रत्येक एकल प्रांत तथा उपप्रांत के सभी प्रतिनिधियों ने एक के उपरांत दूसरे ने अपने प्रांत के निम्न वर्ग में व्याप्त दुर्भाग्य के भुक्तभोगी होने का वर्णन किया। (पृ० 18).
41. प्रस्ताव III.
42. देखिए 1892 का प्रस्ताव X, 1893 का VII, 1894 का III, 1895 का XXII, 1896 का XII तथा XIII, और इसी प्रकार से अन्य.
43. उदाहरणार्थ : बारहवें कांग्रेसी सभापति आर०एम० सायानी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, 'भारत की जनता दरिद्र राष्ट्र है कि भारतीय दो समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते। सचमुच इनमें से कुछ भारतीय तो वास्तव में ही भुखमरी के शिकार हैं और बहुत सारे कठिनता से केवल एक समय का भोजन जुटा पाते हैं।' (सी०पी०ए०, पृ० 351) 1897 के सभापति सी. शंकरन नय्यर ने शोकविल्लल होकर कहा, 'भारत की दरिद्रता प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक रूप में अपने-आपको हमारे सामने स्वतः प्रकट कर रही है, (वही, पृ० 604) सी०पी०ए०, पृ० 506 में एन०पी० चदावरकर ने, सी०पी०ए०, पृ० 761 में एल०एम० घोष ने तथा अन्य बक्ताओं ने कांग्रेस मंच में वर्षों तक भारतीय जनता की निर्धनता का बिस्तृत विवरण प्रस्तुत किया.
44. प्रमाणस्वरूप, बंगाली किसान को उद्धृत करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उसके दुर्भाग्य की अत्यंत दयनीय स्थिति की, उसके भूखे मरते बच्चों की, सूखकर काटा बने उसके पशुओं की तथा सूखे-बजर पड़े उसके खेतों की दुखभरी कहानी का वर्णन करके बताया कि बस्तुतः उसकी दरिद्रता की गहराई का अथवा उसके दुर्भाग्य की अनन्यता का वर्णन करने में भाषा असमर्थ है. एस० एन० बनर्जी : स्पीचेज 1886-1890, खंड III (कलकत्ता, 1890), पृ० 13. 1890 में उन्होंने धनरेजों का ध्यान करोड़ों भारतीयों को अपमानित करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण और कुत्सित दरिद्रता की ओर खीना। (वही, पृ० 195) जस्टिस रानाडे ने 1890 में लिखा : 'इस प्रकार की दरिद्रता के अस्तित्व के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं।' 'इस देश की दरिद्रता तो विलक्षण है।' '.....हमें केवल अपने रास्ते पर चलना है और अपनी आर्थिक अवस्था के अत्यंत थोड़े पक्षों का अध्ययन करना है। यह सत्य हमारे सामने उजागर है कि हमारे साधन सीमित हैं।' 'एसेज, पृ० 182. उसी वर्ष जी०वी० जोशी ने लिखा : 'बढ़ती हुई असामान्य दरिद्रता समाज के निम्न स्तर के लाखों-करोड़ों को पहले से ही चूसने और अपमानित करनेवाली दरिद्रता' 'सारे देश में पहले से ही व्याप्त दुखों और दुर्भाग्य में और अधिक वृद्धि करने वाली दरिद्रता' पूर्वोद्धृत, पृ० 818. आर० एन० मधोलकर ने 1891 में कांग्रेस अधिवेशन में 'भारत की दरिद्रता' प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था, 'आज का भारत अत्यंत विषादपूर्ण तथा सर्वथा अप्राकृतिक चित्र प्रस्तुत करता है।'

- रिप०आई०एन०सी० 1891, पृ०19. आर०सी० दत्त ने 1901 में लिखा था : 'आज के भारतीयों की दरिद्रता की तुलना किसी भी सभ्य देश के नागरिकों से नहीं की जा सकती।' ई०एच० 1 पृ० 6. साथ ही देखिए, उनका 'इंग्लैंड और इंडिया' (लंदन, 1897) पृ०125-6. तथा 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया इन दी बिकटोरियन एज' (लंदन, छठा संस्करण, प्रथम 1903 में प्रकाशित) (निर्देश के लिए इसे आगे ई० एच० II से संकेतित किया जाएगा), पृ०5. भारत में कृषि-श्रमिकों की दरिद्रता के विस्तृत विवरण के लिए देखिए : ई०एच०II, पृ०606. 1902 में सी०वाई० चिंतामणि ने लिखा; 'दुर्भिक्ष और महामारी भारत की सामान्य प्रवृत्तियाँ बन गई हैं और मेरे देश के लाखों निरपराध और आतिथ्रिय नागरिक भुखमरी तथा उसके प्रभाव से मृत्यु का घास बन रहे हैं।' एच०आर०, जुलाई 1901 पृ०447, और देखिए 'मालवीय की 'स्पीचेज' मद्रास, तिथि-रहित).
45. रिब्यू आफ 'इंडियन साल्ट टैक्स' (भारत नमक कर की समीक्षा) जरनल आफ पूना 'सार्वजनिक सभा' (निर्देश के लिए आगे 'जे०पी०एम०एम०' से संकेतित किया जाएगा) जुलाई 1881, (खंड IV, सं०1) पृ० 60.
 46. ऐसे हवाले इतने अधिक हैं कि उन्हें यहां देना कठिन है, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'दि बंगाली', 'दि हिंदू', 'मराठा' और विभिन्न प्रान्तों के देसी प्रेस पर प्रतिवेदन तथा समीक्षाधीन अवधि के विभिन्न समाचारपत्र भारत की निर्धनता की टिप्पणियों से भरे पड़े हैं।
 47. उदाहरणार्थ देखिए, 'दि अमृतबाजार पत्रिका' 13 अप्रैल, 'इन दि रिपोर्ट आफ नेटिव प्रेम फार बंगाल' (निर्देश के लिए इसे आगे आर०एन०पी० बंग से संकेतित किया जाएगा) 24 अप्रैल, 1880, मित्रविलास—8 अक्टूबर, 'इन दि रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेम फार दि पंजाब, नार्थ वेस्ट प्राविसेज एंड अवघ' (निर्देश के लिए इसे आगे 'आर०एन०पी०पी०एन०' से संकेतित किया जाएगा), 7 अक्टूबर, 1880. 'संजीवनी'—14 जून, 'आर०पी०एन०बंग०'—21 जून 1884, निबंधमाला, मई, 'इन दि रिपोर्ट आन नेटिव प्रेम फार बंबई' (निर्देश के लिए इसे आगे 'आर०एन०पी०बंब' से संकेतित किया जाएगा) 23 नवंबर 1880. 'नैरग'—2 मार्च, 'आर० एन०पी०एन०'—10 मार्च, 1891. 'प्रपच, मित्रन—10 नवंबर, 'इन दि रिपोर्ट आन नेटिव प्रेम फार मद्रास' (निर्देश के लिए इसे आगे 'आर०एन०पी०एम०' से संकेतित किया जाएगा) 30 नवंबर, 1899 निबंधमाला—जून, 'आर० पी० एन० बंग'—31 दिसंबर 1881, 'वर्दवान संजीवनी', 30 दिसंबर, 'आर० पी० एन० बंग' 10 जनवरी, 1881. 'हिंदी प्रदीप', नवंबर, आर० एन० पी० पी० एन०... 11 नवंबर 1880, 'हरिशचंद्रिका' सं०8 (वही० 25 नवंबर 1880; 'बंगाली', 23 जनवरी, 1891 तथा 'हिंदू' 25 अप्रैल, 1884
 48. नवंबर 1895, 'आर०एन०पी०बंग', 9 नव० 1893
 49. रामगोपाल द्वारा लिखित 'लोकमान्य तिलक : ए बायोग्राफी' में उद्धृत (बंबई, 1956), पृ० 186-8. बाद में सरकार ने तिलक को बिद्रोह के अभियोग में दंडित करने के लिए इन पक्षों का उपयोग किया था।
 50. 'रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेम फार दि पंजाब' (निर्देश के लिए आगे आर०एन०पी०पी० से संकेतित किया जाएगा) 4 फरवरी, 1893.
 51. गोखले : स्पीचेज, पृ०16. 1873 के प्रारंभ में ही भोलानाथ चंद्र घोषित कर चुके थे : 'बहु-संख्यक जनसमुदाय को खुशहाल बनाए बिना देश की भौतिक संपन्नता की बात एक भ्रम, कल्पना तथा बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं।' पूर्वोद्धृत, पृ० 66 1881 में तिलक ने यह विचार

व्यक्त किया था : जब तक देश के बहुसंख्यक मेहनतकशों की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक आर्थिक दृष्टि से देश के सुधार की बात ही नहीं की जा सकती. डी०वी० ताम्हणकर के 'लोकमान्य तिलक' से उद्धृत (संदन, 1956), पृ० 319.

52. गोखले : स्पीचेज, पृ० 934 (तथा जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 753); क्रमशः नं० : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 106. गोखले : रिप०आई०एन०सी; 1895, पृ० 105. जी०सी० अय्यर : ई०ए०, पृ० 6; जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 818 देखिए। यू०पी० कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ए० नंदी ने 1898 में 'इंडियन पालिटिक्स' में प्रकाशित अपने एक निबंध 'पावर्टी आफ इंडिया' में स्पष्ट विज्ञापित किया कि वस्तुतः आज कृषक ही भारत हैं अर्थात् भारत व्यवहारिक रूप से कृषकों का ही देश है और यदि कृषकों की स्थिति दयनीय है तो अवशिष्ट अन्य भौतिक प्रगति का कोई मूल्य ही नहीं। उन्होंने ऐडम स्मिथ को उद्धृत किया : 'जिस समाज का अपेक्षाकृत विशाल समुदाय निर्धन और दुर्भाग्यग्रस्त है, वह कभी समृद्ध और विकसित नहीं कहा जा सकता।' (पृ० 106). उन्होंने आगे कहा : 'यह देखकर कैसे संतोष किया जा सकता है कि ऋण देने वाले साहूकार निर्धनों के दुर्भाग्य से लाभ उठा रहे हैं अथवा निर्यात व्यापारी देश के जीवन रक्त को ही चूसकर उससे ऊंचा मुनाफा कमा रहे हैं ? (पृ० 105). उन्होंने स्वीकार किया : ब्रिटिश राज्य में मुट्ठी भर राजा और नवाब धनी जमींदार हैं। मुट्ठी भर महाजन और व्यापारी भी धनी हैं। कुछ-एक व्यापारी और व्यवसायी भी खाते-पीते हैं। उन्होंने सारा सोना-चांदी इकट्ठा कर रखा है।' साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया : 'जनता का बहुत बड़ा ऋण : उर्वरता में गिरावट आ रहा है।' (पृ० 112) और देखिए एन०के०एन० अय्यर, रिप०आई०एन०सी० 1901, पृ० 140-1.
53. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 658; दन : ई०एच० II, पृ० 605-6; जी०एस० अय्यर : ई०ए०, पृ० 191
54. दत्त; ई०एच० II पृ० 606.
55. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 188, उनके 'एसेज' भी पृ० 98, स्पीचेज, पृ० 591.
56. नोरोजी : 'एसेज', पृ० 98, जोशी ने इस बात से इनकार किया कि भारतीय दरिद्रता का कारण धन का अममान वितरण है जैसा कि पश्चिम के कुछ देशों में है (पृ० 75) उन्होंने आगे बताया : हमारी समस्या समाजवादी समस्या नहीं है जिसे समाजवादी तरीकों से सुलझाया जा सके' (पृ० 753). 'हमारी दरिद्रता की बुराई कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित नहीं है हमारे यहाँ धन के वितरण में अधिक अमानता, एक वर्ग व दूसरे वर्ग में भ्रंतर, 'मजदूरों की मांग', 'पूँजी का दायित्व' और 'संपत्ति' का अधिकार' की समस्याएं नहीं हैं जिनका सुलझाना आवश्यक है।' (पृ० 819).
- 57, पी० के० गोपाल कृष्णन : 'डैवलपमेंट आफ इकोनामिक आइडिया इन इंडिया' ... 1880, 1950 (नई दिल्ली 1959), पृ० 183. जोशी ने इस बात पर बल दिया 'कि निर्धनता की समस्या अनिवार्य रूप से तथा निश्चित रूप से एक औद्योगिक समस्या है.'
58. जोशी : (पूर्वोद्धृत, पृ० 819) 'हमारी स्थिति अपवाद रूप है। प्रतिद्वंद्वी वर्गों के विरोध में खड़े सारे समाज का प्रश्न है। ... हमें न तो महारानी एलिजाबेथ के पंच कानून की आवश्यकता है और न ही फ्रांस की प्रांतीय सरकार के चित्राण में सजाने योग्य कानून की। ... हमें तो सामूहिक प्रयत्न की एक विस्तृत तथा बुद्धिमत्तापूर्ण योजना इसी संकेत से भारत में ब्रिटिश प्रभुता एकाएक वर्गभेदवादी बन गए और सारा दोष जमींदारों, साहूकारों और बकीलों पर

डालकर एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध करने के प्रयत्न में लग गए

59. द्वितीय अध्याय में इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। और देखिए, रामाडू एसेज, पृ० 23, 183, 185, 191 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 738, 760, 803-4, दत्त ई०एच०; पृ० VII, केसरी, 31 मार्च, (आर०एन०पी० बब, 4 अप्रैल, 1903) 'बढ़ते हुए हाथों के लिए उत्तरोत्तर काम की कमी तथा मनुष्यों के लिए खाद्यान्न की कमी' यह हमारी वर्तमान सामान्य औद्योगिक स्थिति की मक्षिप्त रूपरेखा है

(जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 804)

60. देखिए, भारत सरकार का प्रस्ताव, परिपत्र सं० 96 एफ/6-59, दिनांक 19 अक्टूबर, 1888 (फैमिन प्राग, सं० 19, दिसंबर 1888)।

61. वही, कड़िका 4

62. वही, परिशिष्ट-ए, मद्रास में यह पाया गया कि 6 रु० मासिक वेतनभोगी व्यक्ति सारे परिवारको पूरा महीना तीन सप्ताह प्रतिदिन चावल, बाजरा, ताड़ी अथवा मछली के साथ समुद्र के किनारे के पास का भोजन तथा सप्ताह में एक दो-बार हलाल किया मास खिला सकता है। बबई में खाद्य पदार्थों की अपर्याप्तता के अभियोग को पूरे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया। प्रांतीय सरकार ने मराठा प्रेस द्वारा क्षेत्र विशेष में निधनता को व्यापकता के अभियोग की चर्चा करते हुए इस बात से इनकार किया कि दक्षिण में कहीं भी व्यापक रूप से बुरी दशा है। मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त मि० मैकजी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निस्संदेह देश में निधनता है फिर भी अवस्था बुरी नहीं। लोग अच्छा खाते-पीते हैं। नार्थ-वेस्टर्न प्राविंसेज (उत्तर-पश्चिमी प्रांतों) में एटा के कमिश्नर मि० क्रूक ने विचार प्रकट किया 'खतिहर जनता हृष्टपुष्ट है और यह उनकी संपन्नता का प्रमाण है'

63. भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 27 नवंबर 1893 (राजस्व तथा कृषि विभाग) (सामान्य) फाइल सं० 95, क्रमांक 7) बंगाल के प्रतिवेदन में दावा किया गया है। 'निम्न वर्ग के लोग संपन्नता के ऊंचे और प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ने स्तर का आनन्द भोग रहे हैं'

64. 1891-2 तथा परवर्ती 9 वर्षों में भारत की स्थिति और नैतिक भौतिक प्रगति का प्रदशक विवरण (तृतीय दशवार्षिकी प्रतिवेदन) जे०ए० बेंस द्वारा तैयार किया गया (मदन, 1804) पृ० 427

65. उदाहरण के लिए, भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त सदस्य सर जान स्ट्रैची ने अपने 'इंडिया' (नया तथा अब सशोधित-परिवर्द्धित संस्करण, लंदन, 1894), में लिखा 'अब प्रत्येक किसान प्राचीन काल के बाहुणों अथवा जमींदारों जैसी वेशभूषा धारण करता है। .. उसकी पत्नी को प्रायः अवकाश रहता है। उसके चांदी के गहने चमकते रहते हैं। अपनी जीवन की आवश्यकताओं की तथा सामान्य विभास की पूर्ति के पश्चात् भी उसके पास गहने खरीदने के लिए निरंतर कुछ बचा रहता है।' (पृ० 303), और देखिए, जान स्ट्रैची रिचार्ड स्ट्रैची की 'दि फाइनेंस ऐंड पब्लिक बजट्स ऑफ इंडिया 1869-1881' (लंदन, 1882), पृ० 8. जार्ज बेन्ने की 'इंडियन पोलिटी' (मदन, 1884), पृ० 314, 340.

66. सर डब्ल्यू० इटर भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के महानिदेशक थे और सर चांसलर हिलट, गवर्नर जनरल की कौंसिल के सार्वजनिक निर्माण सदस्य थे। ये दोनों टिप्पणियां असंख्य लेखों और पुस्तकों में दुहराई गईं। उदाहरण के लिए देखिए. नोरोजी 'स्पीचेज', पृ० 567, मानवीय 'स्पीचेज', पृ० 227; जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 76, पी०सी० राज. 'दि पावर्टी प्राब्लम इन इंडिया' (कलकत्ता, 1893) (निर्वेक के लिए इसे आगे 'पावर्टी' से संकेतित किया जाएगा) पृ० 149;

नंदी : 'इन इंडियन पालिटिक्स', पृ० 115. मधोलकर : वही, पृ० 36. उस समय के राष्ट्रीय साहित्य में अधिकांशतया मिलने वाले अन्य अवतरणों में वे : लार्ड लॉरेंस (1864) का यह अवतरण : 'कुल मिलाकर भारत एक अति निर्धन देश है. बहुसंख्यक जनता कठिनाता से जीवन निर्वाह कर पाती है.' सर ई० बोरिंग (1881) का कथन : 'करदाता समाज अत्यन्त निर्धन है.' सर ए० कोलविन का कथन : 'भारत की जनता का बड़ा वर्ग इस प्रकार के व्यक्तियों का है जिनकी आय जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यक सामग्री के खरीदने के लिए कठिनाता से पर्याप्त है अतः वे जीवन के लिए अनिवार्य उपयोगी वस्तुओं के अभाव में जीवन बिताने को विवश हैं.' रैंडोल्फ चर्चिल तथा 1898 के अकाल आयोग के प्रतिवेदन को भी प्रायः उद्धृत किया जाता था. अनेक लेखकों और वक्ताओं ने 1888 की डफरिन जाच के परिणामों तथा जिला अधिकारियों के प्रतिवेदन को उद्धृत किया. देखिए, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 763-6. बी०एन०धर. रिप०आई०एन०सी०—1892, पृ० 102, ए०नदी : रिप०आई०एन०सी०—1894, पृ० 55-6, मधोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स' पृ० 36. एस०एन०बैनर्जी : सी०पी०ए०, पृ० 686.

67. देखिए, नोरोजी 'पावर्टी', पृ० 188, तुलनीय बी०के०आर०बी० राव : दि नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया 1931-32' (नदन 1940), पृ० 7. तथा पी०ए० वधवा और के० टी० मर्चेंट : 'आवर इकोनामिक प्राबलम' (बंबई, 1946) पृ० 522.
68. डेनियल थार्नर : 'लाग टर्म ट्रेड्स इन आउटपुट इन इंडिया इन इकोनामिक ग्रोथ : बाजील, इंडिया, एंड सोमैन कुजनिटस तथा इतर द्वारा संपादित (इरहम एन०सी० 1955) पृ० 105,
69. राव 'दि नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया-1931-2', पृ० 2.
70. उनकी संगणना विधि को जानने के इच्छुक व्यक्ति देखे उनकी 'पावर्टी' तथा 'अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया', पृ० 4-25, और पृ० 147-73. संक्षेपतः उन्होंने कुल वार्षिक कृषि उत्पादन में खानों, कारखानों, मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन तथा मामूली से विदेशी व्यापार के वार्षिक लाभ के साथ साथ बड़ी संख्या में होने वाले दैवी उत्पादों को गिन-जोड़कर 1867-8 की कुल राष्ट्रीय आय की संगणना की यहा यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने सेवाओं से प्राप्त आय को स्पष्ट रूप से आय नहीं माना क्योंकि उनका तर्क था कि यह वास्तविक आय न होकर पूर्व संचित आय का उपयोग मात्र है (पृ० 180-5 तथा 220) दादाभाई के राष्ट्रीय आय संबंधी विचार के औचित्य की समीक्षा के लिए देखिए : आर०पी० ममानो 'दादाभाई नोरोजी, दि ग्रैंड ओल्डमैन आफ इंडिया' (लदन 1939), पृ० 203-4 के०टी० शाह तथा के०जी०खंडात : 'बैल्थ ऐंड टैक्सेबल कैपेसिटी आफ इंडिया' (बंबई 1924) पृ० 7. बी०के०आर०बी० राव : 'ऐन एसे आन इंडियन नेशनल इनकम 1925-9' (लंदन 1939) पृ० 19-22 बाडिया और मर्चेंट : पूर्वोद्धृत, पृ० 520-3 सुरेंद्र जे० पटेल : 'लाग टर्म बेंचेंस इन आउटपुट ऐंड इनकम इन इंडिया,' 1896-1960. 'इन इंडियन इकोनामिक जनरल' जनवरी 1958 (खंड V, संख्या 3) पाल ए बरन : दि पोलिटिक्स इकोनमी आफ ग्रोथ' (भारतीय संस्करण, नई दिल्ली 1957) पृ० 36-7. दादाभाई के राष्ट्रीय आय संबंधी दृष्टिकोण के सैद्धांतिक गुण-दोषों की चर्चा किए बिना संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'राष्ट्रीय आय को कुल वास्तविक उत्पादन से जोड़ना' उनके दृष्टिकोण की उपयोगिता का एक प्रबल पक्ष था. वस्तुतः पिछड़े देशों में छिपी व्यापक बेकारी की सामाजिक क्षेत्त में सेवा पक्ष के एक बहुत बड़े भाग की परोपजीविता की तथा समाज के गठन संबंधी एवं संस्थागत परिवर्तनों उदाहरणार्थ पश्चिम के संपर्क में आने के समय से ही मूद्रा निर्माण अथवा उपयोगी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि आदि की सही जानकारी का तुलनात्मक

अथवा अन्य आर्थिक विश्लेषण के उद्देश्यों का सच्चा आधार उपभोग सामग्री का वास्तविक उत्पादन ही बन सकता है।

71. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 4. अपने निष्कर्षों की परिसमाप्ति पर दादाभाई ने टिप्पणी करते हुए लिखा : 'एक बात स्पष्ट है कि मैं उत्पादन के अवमूल्यन का दोषी नहीं हूँ।' (पावर्टी, पृ० 25). उन्होंने और अधिक स्पष्ट सूचनाओं का आग्रह करते हुए कहा : 'किसी भारतीय द्वारा पूरी सूचनाएं देने पर ही वर्ष-प्रतिवर्ष भारत की वास्तविक भौतिक स्थिति की सही रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है।' (वही, पृ० 147) सभी प्रकार की सीमाओं के होने पर भी उनका 20 इ० प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अंश इस क्षेत्र के सभी परवर्ती अनुसंधानों की कसौटी बना, यह उनके लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है।' (मसानी, पूर्वोद्धृत, पृ० 204) माह और ख़ात : पूर्वोद्धृत, पृ० 201, राय : 'एन एसे आन इंडियाज नेशनल इनकम—1925-29', पृ० 16-22.
72. डिग्वी : पूर्वोद्धृत, पृ० 364, 442-3. इस तख्तीने में कुल सामग्री के उत्पादन तथा सेवाओं को सम्मिलित किया गया था. उल्लेखनीय यह है कि भारत सरकार ने इन गणनाओं के सवाधार-भूत विस्तृत आँचों के प्रतिवेदनो को कभी प्रकाशित नहीं किया
73. किडिस्टन के साठे कर्जन : स्पीचेज खंड I-IV, (कलकत्ता 1900, 1902, 1904, 1906) खंड I, पृ० 289-90.
74. डिग्वी . पूर्वोद्धृत, अध्याय XII.
75. फेड जे० अतकिंसन : 'ए स्टेटिस्टिकल रिव्यू आफ दि इनकम ऐंड वैल्यू आफ गिटिल इंडिया' 'जनरल आफ दि रायल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी', खंड 65, भाग 2 (जून 1902), पृ 238
76. देखिए, नौरोजी : सी०पी०ए०, पृ० 160-1, स्पीचेज, पृ० 114, 527, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 758, मघोलकर : 'इन इंडियन पोलिटिक्स', पृ० 38, जी०सी० अय्यर : 'दि वायसराय आन दि इकोनामिक कडीशन आफ इंडिया', एच०आर० मई 1901, पृ० 355 ई ए, पृ० 37-8, गोखले : स्पीचेज, पृ० 17, दत्त : ई एच II, पृ० 603, एस० एन० बैनर्जी ने 1895 में पूना कांग्रेस में सम्पापति पद से दिए गए अपने भाषण में सारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के निष्कर्षों को इन शब्दों में प्रस्तुत किया : 'प्रति व्यक्ति आय बीस रुपये है अथवा सत्ताईस रुपये, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। सत्य यह है कि यह भारत की जनता की गहि़त दरिद्रता का एक विश्वमनीय प्रमाण है।' — (सी०पी०ए०, पृ० 257)

77. इंग्लैंड	41 पौंड	स्काटलैंड	32 पौंड	आयरलैंड	16 पौंड
यूनाइटेड किंगडम	35.2	फ्रांस	25.7		
रूस	9.9	ऑस्ट्रिया	16.3	जर्मनी	18.7
स्पेन	13.8	पुर्तगाल	13.6	इटली	12
हालैंड	26	डेनमार्क	23.2	बेल्जियम	22.1
स्विटजरलैंड	16	यूरोप	18	स्वीडन तथा	
				नार्वे	16.2
टर्की	4	ऑस्ट्रेलिया	43.4	यूनाइटेड	
				स्टेट्स	27.2
कनाडा	26.9			इंडिया	2

नौरोजी . स्पीचेज, पृ० 590, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 758, राय पावर्टी, पृ० 340, बैनर्जी .

- सी०पी०ए०, पृ० 257-8. आर० एम० सायानी : सी० पी० ए०, पृ० 346.
78. बैनर्जी : सी०पी०ए०, पृ० 257-8 'नोरोजी इन ऐमिनेंट इंडियन्स', पृ० 164, आर०एम० सायानी : सी०पी०ए०, पृ० 347, नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 310 क्रमशः.
79. 'नोरोजी इन ऐमिनेंट इंडियन्स', पृ० 164 और देखिए, उदाहरणार्थ बैनर्जी स्पीचेज, खंड III, पृ० 12, ए०बी०पी०, 30 मार्च 1882
80. बहुत से आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा है 'बहुत सी सांख्यिकी कठिनाइयों तथा सबद्ध मूल्यों में सैद्धांतिकता जूड़ी होने के कारण राष्ट्रीय आय के अक घनराष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखते.'—(बाडिया तथा मर्चेट : पूर्वोद्धृत, पृ० 523) परंतु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की तुलना के लिए सामान्य व्यवहार को ही उपयुक्त सूत्र (विधि) के रूप में ग्रहण किया जा सकता है.' देखिए कोलिन क्लार्कम : पूर्वोद्धृत, 'कठिनास आफ इकोनामिक प्रोग्रेस', पृ० 528. किसी भी ऐसे विषय में, जहां आय का घन अधिक गहरा है यहाँ तक कि उसे दो अथवा अधिक अंक से गुणा करके मापा जा सकता है जैसा कि तुलना द्वारा भारतीय नेताओं ने पाया था, इस प्रकार के घन की मायंकता 'त्वरित और अस्पष्ट' ही मानी जाएगी
81. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 25-31, जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 759-60, मधोलकर : रिप०आई०एन०सी०, 1891, पृ० 20, जे०सी० अय्यर ई ए, पृ० 28
82. नोरोजी : गवर्मी, पृ० 30 और 'स्पीचेज', परिशिष्ट-डी, पृ० 187.
83. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 759-60, मधोलकर : रिप०आई०एन०सी०, 1891, पृ० 19 और 'इन इंडियन पार्लिटमस', पृ० 38.
84. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 31. समस्या के इस पक्ष पर डफरिन की जांच तथा 1888 के प्रस्ताव ने सुदूर प्रकाश डाला। नोलोर (मद्रास) के सिविल सर्जन ने रिपोर्ट की कि जेल में रहने के कुछ बर उन्नत कैदियों का वजन बढ़ गया है मद्रास के राजस्व मंडल का उत्तर था कि इसका कारण जेल में अत्यंत उदारतापूर्ण भोजन का सभरण और कठोर श्रम न कराना है इसके अतिरिक्त जेल उसे घरेलू चिताओं से मुक्ति प्रदान करती है। 'प्रातीय प्रतिवेदनो पर आधुत सरकारी टिप्पणी का संक्षेप इस प्रकार से है . 'कैद की अवधि में वजन का बढ़ जाना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह स्थिति अन्य प्रांतों में भी पाई गई है.' देखिए, भारत सरकार का 19 अक्टूबर 1888 का प्रस्ताव, पूर्वोद्धृत परिशिष्ट-ए.
85. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 31. सी०पी०ए०, पृ० 260, स्पीचेज, पृ० 528, 580, परिशिष्ट, पृ० 186. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 62-3. बैनर्जी : सी०पी०ए०, पृ० 258. जी०सी० अय्यर . ई ए, पृ० 28. दादाभाई ने आय के वितरण में क्षेत्रीय असमानताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार किया. देखिए, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 186.
86. दत्त : ई एच II, पृ० 6 ए० बी० पी० 11 मार्च 1897. एन०एम० समर्थ रिप०आई०एन०सी०, 1896, पृ० 158-9, सायानी : सी०पी०ए०, पृ० 366, एडवोकेट, 2 फरवरी (आर०एन०पी० एन०, 4 फरवरी 1905) क्रमशः उदाहरणार्थ 'नोर भी देखिए, मालवीय स्पीचेज, पृ० 248, आई०एन०सी० 1966 का प्रस्ताव 12, आई०एन०सी० 1897 का प्रस्ताव 9, मो० मंकरन नंबर : सी०पी०ए०, पृ० 383, डो०ई०वाचा सी०पी०ए०, पृ० 360 दत्त : स्पीचेज II, पृ० 35. केसरी, 22 जून (आर०एन०पी० बर्बर, 26 जून 1897) दरिद्रता और अकाल के पारम्परिक सबध की विस्तृत जांच नीचे की गई है
87. साहं एलमिन ने 'दरिद्रता और संपन्नता को घनत सापेक्षिक शब्द' घोषित करते हुए अपनी राय

इस प्रकार स्पष्ट की : 'मैं यह नहीं मानता कि बहुसंख्यक जनता अपने को विपन्न समझती है। यदि उनकी आय कम है तो उसका कारण उनकी सीमित आवश्यकताएं हैं।' स्पीचेज (कलकत्ता 1899), पृ० 491.

88. भारत के भौतिक साधनों पर 1880-91 के प्रांतीय प्रतिवेदन, (जिमसा, 1894) बंगाल रिपोर्ट, पृ० 9.

89. बही, नार्थ वेस्ट प्रांतों तथा अवध का प्रतिवेदन, पृ० 19. और देखिए, रट्टेचे : इंडिया 1894, पृ० 301-3. ब्रिटिश प्रशासकों ने बार बार भारत के संबंध में सपन्नता के इस भाग्यवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। स्ट्रेचे ने लिखा : 'भारत के जलवायु में जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। भारतवासी की मिट्टी से लिपी-भुती भोपड़ी उसके अपने विचारानुसार झुड़ और विश्रामप्रद आश्रय है. . सामान्य स्थिति में उसके पास अपनी णच का आहार पर्याप्त मात्रा में रहता है।' '...उसके पास अधिक हस्त नहीं है परंतु अधिक बस्तों की उसे आवश्यकता भी नहीं। यहां तक कि शीत ऋतु में भी उसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता' (इंडिया : 1894, पृ० 301-3).

1888 की डफरिन जाच के लिए बहुत से मंडलों और प्रांतों के अधिकारियों ने इसी दृष्टिकोण पर आधारित अपने निष्कर्ष भेजे। उदाहरणार्थ, मालदा के कलक्टर ने लिखा . 'सामान्य वर्षों में एक छोटे से किसान के पास भी देश की जलवायु तथा उसकी अपनी प्रकृति के अनुरूप उसे दृष्टपुष्ट बनाने वाला आहार आवश्यकता से अधिक मात्रा में रहता है।' हुगली के कलक्टर का नो निश्चित मत था : 'भारतीय अपने मान्य दृष्टिकोण और अपने अपेक्षित स्तर के अनुसार सपन्न तथा संतुष्ट हैं।' (दुकतापूर्वक कहा गया) भारत सरकार का 19 अक्तूबर 1888 का प्रस्ताव, पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट ए

90. 'जनता की भौतिक स्थिति पर प्रांतीय प्रतिवेदन', 1880-91 बंगाल प्रतिवेदन, पृ० 9 तथा हुगली के कलक्टर ने भारत सरकार के 19 अक्तूबर 1888 के प्रस्ताव को उद्धृत किया, पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट-ए. तुलनीय—'भारत के आर्थिक प्रश्न पर विचार हुए यह विशेष रूप से कभी नहीं भूलना चाहिए कि धन सचय अथवा ऊंची आय की अपेक्षा मानसिक सुख तथा आत्मिक शांति की प्राप्ति ही भारतीयों का जीवन सत्य है।' गवर्नर जनरल की कौंसिल के स्वर्णीय सदस्य जे० डी० रोम ने प्रकाशनार्थान 'रियल इंडिया' में इसे ब्रिटिश राज्य की अनेक देनों में एक बहुत बड़ी देन बनाया' (लंदन 1908) पृ० 319-20.

91. दि बर्ड्स डिमिनियल मारल ऐंड मैटिगियल प्राइस रिपोर्ट, पृ० 419 और देखिए प्रस्ताव, पूर्वोद्धृत, पृ० 318. थोडोर मोरीसन 'इकोनामिक ट्रांजीशन इन इंडिया', पृ० 159-60. मोरीसन का मत था : 'अतुलनीय की तुलना से विचारों में उसभाव के अतिरिक्त कुछ भी परिणाम नहीं निकलता।' (पृ० 160)

92. इंडिया (1894) पृ० 301, जिन अकाल आयुक्तों को वह उद्धृत कर रहा था, उन्होंने यह मन्वेदार परंतु जोड़ी जो अनजाने तौर पर व्यर्थपूर्ण है 'यद्यपि उसकी आय अपेक्षाकृत थोड़ी और बड़े जोखिमों से भरी हुई है।' इसी प्रकार 1894 में भारत सचिव एच०एच० फौलर ने दुकतापूर्वक कहा : 'जलवायु की दृष्टि से श्रामीक भारत की दरिद्र जनता की इंग्लैंड की जनता की अपेक्षा आवश्यकताएं कम हैं और भारत का निर्धन इंग्लैंड के निर्धन की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक आसानी से कर सकता है।' हंसाई (चतुर्थ वर्ग) 15 अगस्त 1894, खंड 27, लपपप 1138-9.

93. नौरोजी की स्पीचेज से उद्धृत, पृ० 583. और देखिए अर्किंसन के लेख पर रीस की टिप्पणी, पूर्वोद्धृत, पृ 276.
94. बल दिया गया. भारत सरकार का 19 अक्तूबर 1888 का प्रस्ताव—पूर्वोद्धृत परिशिष्ट-ए. बहुत से अन्य सरकारी अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदनों में यही दृष्टिकोण अपनाया.
95. जी०सी० बय्यर : ई ए, पृ० 20.
96. दूसरी ओर आर०सी० दत्त ने लिखा : 'जीवन भर की भूख बेचारे अधिक निर्धन लोगों को आवश्यकता कम करने का प्रमाण देती है.' ई एच J, पृ० 22.
97. दादाभाई नौरोजी ने सकेत किया : 'बंबई निवासी धनी हिंदुओं और मुसलमानों की रहन-सहन की स्थिति तो देखिए.' एसेज, पृ० 134.
98. दादाभाई ने पूछा : एक समय ब्रिटेन के लोग इस देश के जंगलों में घूमते थे और उनकी आवश्यकताएं कुछ न थी. यदि वे उसी स्थिति में रहते तो आज का ब्रिटेन कैसा होता ?' (स्पीचेज, पृ० 311).
99. वही, पृ० 311-2.
100. जी०बी० जोशी ने इसे अत्यन्त स्पष्ट करते हुए कहा : 'मुख्य सुविधाओं का उच्च स्तर तो हमारे लिए एक प्रकार का अवशुद्ध नैतिक बल है जो हमें सकट काल में अधिक श्रम करने और कष्ट सहने के लिए उत्साहित करता है तथा परिस्थितियों पर विजय पाने के योग्य बनाता है. देश पर पड़ने वाला बुरे से बुरा सकट यदि देश के जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित नहीं करता, तो वह किसी भी रूप में भयकर अथवा शोचनीय नहीं कहा जा सकता. इसके विपरीत बल-पूर्वक घोषी गई शान्ति का बरदान यदि देशवासियों को अपने निम्न जीवन स्तर से समझौता करने के लिए विवश कर देता है तो उसे अभिशाप ही कहा जा सकता है. (पूर्वोद्धृत, पृ० 768).
101. गोपालकृष्णन . पूर्वोद्धृत, पृ० 183, तथा कांग्रेस का 1892 का नवां प्रस्ताव.
102. देखिए, आई०एन०सी० 1882 का प्रस्ताव 9 तथा कांग्रेस के इसी प्रकार के परवर्ती प्रस्ताव.
103. भारत सरकार का 19 अक्तूबर 1888 का प्रस्ताव, पूर्वोद्धृत कड़िका-4.
104. वही, परिशिष्ट-ए. अपने ही प्रस्ताव पर लांडे डफरिन का मत था . 'इस परिणाम से पर्याप्त संतुष्ट व्यक्ति या तो आशावादी है या कठोर प्रकृति का है.' लांडे डफरिन : स्पीचेज (कलकत्ता 1889) पृ० 241. वस्तुतः. प्रस्ताव के परिशिष्ट-ए में प्रकाशित बहुत से मंडलीय तथा प्रांतीय प्रतिवेदनों में भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता और दुर्भाग्य के अस्तित्व को प्रमाणित किया गया था सरकारी प्रस्ताव केवल यह सिद्ध करने में सफल हुआ कि भारत में स्थाई अकाल नहीं है वस्तुतः यह एक झुड़ सात्वना थी.
105. 1898 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन (कलकत्ता 1898) कड़िका, 591-2.
106. कर्जन; स्पीचेज, खंड III, पृ० 149, इसी प्रकार भारत सचिव जार्ज हैमिल्टन इस तथ्य से सहमत थे कि भारत में 'धनी जनसंख्या दरिद्र है. —इंडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 1902, लगभग 108.
107. लांडे कर्जन ने इस रूप में बड़ी विशदता से प्रश्न प्रस्तुत किया. —स्पीचेज खंड IV, पृ० 36. 1838 में ही बंगाली युवक सच से संबंधित बाबू रामगोपाण घोष ने इस प्रश्न की जाच पड़ताल करने की इच्छा व्यक्त की—'संपत्ति बढ़ रही है अथवा घट रही है ? क्या बहुसंख्यक जनता की सुविधाओं में विस्तार हो रहा है अथवा संकोचन ? तथा इस सबके क्या कारण हैं ?' रामगोपाण साय्याल के 'ए जनरल बायोग्राफी आफ बंगाल सैलिब्रिटीस' में उद्धृत (कलकत्ता

1889) पृ० 175.

108. और इस बात का उत्तर देना आवश्यक था : सापेक्षता का कोई तर्क प्रश्न को धूमिल नहीं कर सकता दोनों पक्ष सही नहीं हो सकते एक को तो गलत होना ही पड़ेगा—गुलनोय, डिगबी : पूर्वोद्धृत.
109. हम्राडें (चतुर्थ वर्ग) खंड XCIX लग० 1209. इसी प्रकार 3 फरवरी 1902 को उसने पुनः घोषणा की 'मैं एक से अधिक बार अपना मत व्यक्त कर चुका हूँ कि भारत में हमारे प्रशासन का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य केवल हमारा यह विश्वास है कि हम दखि भारतीय जनता को भौतिक दृष्टि से समृद्ध बना सकते हैं (इंडियन डिबेट्स 3 फरवरी 1902 लगभग 105).
110. गोखले स्पीचेज, पृ० 19 और देखिए, वही, पृ० 934, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 186 तथा स्पीचेज, परिशिष्ट-डी, पृ० 167. लालमाहन घोष : स्पीचेज (कलकत्ता 1883) पृ० 87 सी०पी०ए०, पृ० 756 मालवीय स्पीचेज पृ० 219, 238, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 738, 752-3. मधोलकर; 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 35, नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 101, वाचा : सी०पी०ए०, पृ० 560, जी०सी० अय्यर 3 ए, पृ० 6, दत्त : स्पीचेज II, पृ० 28 159
111. आई०एन०सी०, 1886 का प्रस्ताव II तथा वाचा : रिप०आई०एन०सी०, 1886, पृ० 60
112. उदाहरण रूप में देखिए हिंदू, 10 सित० 1884, 29 अगस्त 1887, 1 फरवरी 1888, मराठा, 21 दिसंबर 1884 11 नवंबर 1900, नेटिव ओपीनियन, 13 अप्रैल (आर०एन०पी०, बंबई, 19 अप्रैल 1884) नव विभाकर, 7 जनवरी (आर०एन०पी० बग 7 जून 1884) साधारणी, 27 जुलाई (वही, 27 अगस्त 1884). सजीवनी, 18 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1885) ज्ञान-प्रकाश, 19 मार्च (आर०एन०पी० बंबई 21 मार्च 1885) 'वाइस आफ इंडिया' द्वारा आवृत ममाचारपत्र (निर्देश के लिए आगे 'बी०ओ०आई०' में संकेतित किया जाएगा) अक्टूबर 1887 प्रबाला-गजट, 27 जून (आर०एन०पी०पी०, 7 जुलाई 1888) 'पैसा ब्रह्मचार', 13 अप्रैल (वही, 18 अप्रैल 1891) 'दोस्ते रिट' 12 जून (वही, 20 जून 1891) केसरी, 22 जून (आर०एन० पी० बंबई, 26 जून 1897). भारत जोवन, 25 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 3 अगस्त 1898) ए० बी० पी०, 17 जून 1898, 12 अक्टूबर 1901, बंगाली, 9 मार्च 1902.
113. नौरोजी . स्पीचेज (1886) में उद्धृत 'ग्रांट डफ' पृ० 583. पूर्वोद्धृत के अध्याय 1 में जान स्ट्रेची और रिचार्ड स्ट्रेची उद्धृत, 1888 के 'स्पीचेज' में डफरिन उद्धृत, पृ० 241, स्ट्रेची : 'इंडिया' (1894) पृ० 303. जनरल सर जार्ज चैसनी : 'इंडियन पालिटी' (लंदन 1894) पृ० 394 हेनरी फौलर-हंसाई (चतुर्थ वर्ग) 15 अगस्त 1894 खंड XXVIII लग० 1139. ऐलमन; स्पीचेज, पृ० 360-1. 1898 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन, कड़िका 592. 1901-2 और 9 पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि में भारत की स्थिति और उसकी नैतिक तथा भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रतिवेदन (चतुर्थ दशाब्दिक प्रतिवेदन होने के कारण) फ्रांस सी० ड्रेक द्वारा तैयार किया गया. (लंदन 1903). 1901-2 का आर्थिक वक्तव्य (कड़िका, 136). 1902-3 का वक्तव्य (कड़िका, 90). 1902-4 (कड़िका 117) 1902 में फ्रेड जे० अतकिंसन ने संगणना की कि 1875-95 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 29.5 प्रतिशत बढ़ गई है (पूर्वोक्त स्वर, पृ० 238).
114. कर्जन : स्पीचेज खंड I, पृ० 158, खंड II, पृ० 165, 288-90, खंड III, पृ० 148-9 तथा खंड IV, पृ० 36-7, 211-2.
115. वही, खंड II, पृ० 290. इसी प्रकार जार्ज हैमिल्टन ने वाचा किया : वक्षि संव नति के कारण यह सगण्य अगोचर सी हो गई है तथापि भौतिक अवस्था में निरंतरता बनी रही है—हंसाई

- (चतुर्थ वर्ग) 16 अगस्त 1901, खंड XCIX लग० 1208-9 तथा इंडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 1902, लगभग 108, 110.
- 116 वही, खंड III, पृ० 389.
- 117 वही, खंड IV, पृ० 212.
- 118 गन 19वीं शती के अंतिम पच्चीस वर्षों की अवधि में भारत को निर्धन बनाने वाले दुर्भिक्ष अपने विस्तार और तीव्रता में प्राचीन अथवा आधुनिक काल के इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण हैं (दत्त, ई एच I पृ० VI).
- 119 1902 में कांग्रेस सभापति के पद पर आसीन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने प्रश्न प्रस्तुत किया : 'क्या अपनी वंशोद्भूति की तीव्रता तथा बहुलता के साथ जनता की भौतिक अधोगति का मोन किंतु निर्णीत प्रमाण प्रस्तुत करने वाले इन दुर्भिक्षों की सार्थकता को नकारना संभव है ?' (सी० पी० ए०, पृ० 68) और देखिए, जी० सी० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० 1900, पृ० 29 दत्त : स्पेचर II, पृ० 28 तथा नीचे देखिए
- 120 डम दृष्टिकोण की विस्तृत जांच नीचे की गई है ।
- 121 जागी पूर्वोद्धृत, पृ० 420, पी०पी० पिल्ले : रिप०आई०एन०सी० 1892, पृ० 98, मधोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 39. नदी . वही, पृ० 166-7, जी०एम० अय्यर : भारत के खच्चों के प्रशासन पर रायल कमीशन का प्रतिवेदन (निर्देश के लिए इसे आगे वेलबी कमीशन से संकेतित किए गए) मिनिट्स आफ इविडेंस (साक्ष्य के सन्निप्ताम), खंड III पार्लियामेन्टरी पेपर्स (हाउस आफ कामंस) 1900 खंड 29 लगभग 130 प्रश्न 19615-6 तथा ई ए, पृ० 13. वाचा : सी०पी०ए०, पृ० 360, दत्त 'ओपन लेटर्स टू लार्ड कर्जन' (लार्ड कर्जन के नाम खुली चिट्ठियाँ) कलकत्ता 1904 (निर्देश के लिए इसे आगे 'ओपन लेटर्स' से संकेतित किया जाएगा), पृ० 17. बैनर्जी : सी०पी०ए०, पृ० 689, गोखले . स्पीचेज, पृ० 53, 1904 की आई०एन०सी०, का प्रस्ताव और प्रस्ताव पर भाषण, की रिप०आई०एन०सी०, 1904, पृ० 128 तथा नीचे अध्याय X
- 122 ऋणग्रस्तता आवश्यक रूप से न निर्धनता है और न ही दुर्दशा. सामान्य ऋणकर्ता की स्थिति की तुलना उम व्यक्ति से की जा सकती है जो बैंक में अपना चालू खाता रखता है और कभी-कभार अधिविक्रय करता (जमा पूँजी से अधिक निकालता) है, दि थर्ड डिस्टेंसियल मारल ऐंड मैटिरियल प्राग्रस रिपोर्ट, पृ० 435 एक अन्य सरकारी प्रकाशन इससे भी आगे बढ़ गया : 'ऋण तो आवश्यकताओं की अपेक्षा ससाधनों की अधिकता पर अधिकार का सूचक है।' प्राविशल रिपोर्ट आन दि मैट्रीयरन कडीशन आफ दि पीपुल. 1881-91, पृ० 8. आफ दि बंगाल रिपोर्ट तथा प्रेजिडेंसी डिबिजन और पटना के कमिशनरो तथा एन०डब्ल्यू०पी० ऐंड ओ० में एटा के कलक्टर सेंट्रल प्राविसेज में दमोह तथा भडारा के कमिशनरो के प्रतिवेदन तथा भारत सरकार के 19 अक्टूबर के प्रस्ताव का स्वयं सरकार द्वारा सक्षेप, पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट-ए
123. ऊपर देखिए, अध्याय X.
124. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 227, 769-70. गोखले, स्पीचेज, पृ० 18, 52.
125. भूतपूर्व सैनिक सदस्य जनरल जार्ज चिसनी ने 1894 में लिखा : 'संपत्ति हमारे शासन की ही सृष्टि है हमने भारत को गरीबी में जकड़ा हुआ पाया जैसाकि यह पहले से रहता आया है. यदि हम इस देश में न आते तो यह आज भी उसी प्रकार विपन्न होता.' (पूर्वोद्धृत, पृ० 397). लार्ड कर्जन ने 1904 में टिप्पणी की कि यदि आप आज के भारत की सिकंदर, अशोक, अकबर अथवा

औरंगजेब के भारत से तुलना करें तो पाएंगे कि पूरकाल में अनुभूत पराभितता की अपेक्षा आज भौतिक समृद्धि का स्तर काफी ऊँचा है. (स्पीचेज खंड IV, पृ० 37).

- 126 रानाडे : एसेज, पृ० 182.
127. राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल के विषयो में सक्रिय भाग लेने वाले एक भारतीय मुदा लेखक ने तो यहां तक स्वीकार किया कि 'भारतीय इतिहास की वैभव और सपन्नता की सभी विभिन्न अवस्थाओं और युगों में भारतीय कृषक जनता कुशल और विपन्न रही है' (राय पावर्टी, पृ० 199) परंतु उन्होंने साथ में यह अवश्य जोड़ा 'ब्रिटिश राज्य में तो दुर्भाग्य और अधिक विषम हो गया है' वही, पृ० 224, इसके साथ देखिए, मघोलकर : रिप०आई०एन०सी०—1891, पृ० 21
- 128 आनंद बाजार पत्रिका, 13 अप्रैल (आर०एन०पी०बग, 24 अप्रैल 1880)
129. नौरोजी पावर्टी, पृ० 579 कलकत्ता रिव्यू में एक भारतीय लेखक कैलाशचंद्र काजीलाल ने लिखा 'ब्रिटिश राज्य ने एक ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो इससे पूर्व किसी भी हिंदू अथवा मुगल शासक अथवा टीपू साहब अथवा पेशवा के राज्य में कभी नहीं रही (कलकत्ता रिव्यू अक्टूबर 1901, पृ० 309-10)
- 130 उदाहरणार्थ देखिए, सजीवनी, 14 जून (आर०एन०पी० बग, 22 जून 1884) ग्राम यात्रा प्रकाशिका 9 अगस्त (वही, 16 अगस्त 1884) एस०एन० बैंकर्स रिप०आई०एन०सी०—1896, पृ० 135-6 केसरी, 22 जून (आर०एन०पी० बर्बई, 26 जून 1897) तथा 14 जनवरी (वही, 18 जनवरी 1902) एन०के०एन० अय्यर रिप०आई०एन०सी०—1901, पृ० 140-1 सी०वाई० चिंतामणि 'दि इकोनामिक्स आसपेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' एच०आर०दिस० 1901, पृ० 485 6 बंगाली 22 अक्टू० 1903 साथ ही देखिए, नौरोजी स्पीचेज, पृ० 389 प्रथम और भागवत में उद्धृत तिलक, पूर्वोद्धृत पृ० 72 राय पावर्टी, पृ० 75
131. अमृत बाजार पत्रिका ने 22 मई 1884 में लिखा 'एक समय भारत विश्व में समृद्धतम देश था.' वर्षों तक एक के बाद एक दूसरे कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने भारत की विगत सपन्नता का गौरवगान किया 1899-1904 तक के आई०एन०सी० के प्रतिवेदन देखिए दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'पावर्टी ऐंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में 1853 में लिख एक निबन्ध 'दि स्टेट ऐंड दि गवर्नमेंट आफ इंडिया अंडर दि नेटिव रूलर्स' को 1901 में पुनः प्रकाशित किया इसमें उन्होंने अनेक ब्रिटिश लेखकों को उद्धृत करते हुए यह दिखाने की चेष्टा की कि 'मिकदर के आक्रमण की तिथि और उससे शताब्दियों पूर्व से लेकर मुगल शासनकाल तक भारतीय सपन्नता के उच्च स्तर पर थे' (पृ० 584) इसी निबन्ध की वास्तव में 1903 में जी०मी० अय्यर ने अपने 'सम इकोनामिक आसपेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में पुनः प्रकाशित किया और देखिए, नदी : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 103, 105, 110, रानाडे : 'दि राज्ज आफ मगठा पावर इन इंडिया' (बर्बई 1900) वास्तव में इसी बात के उल्लेख के लिए लिखा गया था और देखिए, आर० एन० सायानी 'ऐबस्ट्रैक्ट आफ दि प्रोसीडिंग्स आफ दि इपीरियल लेजिस्लेटिव काँसिल' (निर्देश के लिए इसे आगे एन०सी०पी० से संकेतित किया जाएगा) 1897 खंड XXXVI, पृ० 190 पी०ए० चारलू वही, पृ० 232.
132. 'इन इंडियन पालिटिक्स', पृ० 110.
133. नौरोजी की स्पीचेज में उद्धृत शॉट डफ, पृ० 610, फोर्लर : हसांड (चतुर्थ खंड), 15 अगस्त, 1894, खंड XXVIII, 1139-40; जे० पीले, बेल्बी बायोग, खंड III, प्रश्न 18235.

- चिसनी : पूर्वोद्धृत, पृ० 394. अतर्कितन पूर्वोक्त स्थल, पृ० 240-51 कर्जन स्पीचेज, खंड II, पृ० 289, खंड IV, पृ० 212 स्ट्रेची इंडिया (1903) पृ० 192
134. अतर्कितन पूर्वोक्त स्थल, पृ० 269 तथा 260 इसमें आधुषण भी शामिल थे
135. नोरोजी पावर्टी, पृ० 86-7 स्पीचेज, पृ० 612 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 661 मधोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 46
136. नोरोजी पावर्टी, पृ० 86-8, स्पीचेज पृ० 611-2 रानाडे एसेज, पृ० 188 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 660-3 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 46 आर० सी० दत्त 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 131 गोखले स्पीचेज, पृ० 16 और बेलबी कमीशन, खंड III, प्र० 18238 जी० एस० अय्यर वही, प्र० 18715
137. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 756 दत्त 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 132, नदी 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 112, गोखले स्पीचेज, पृ० 16 तथा बेलबी कमीशन खंड III प्र० 18238.
138. नोरोजी पावर्टी, पृ० 89-9 पुन उद्धरणोंय अपने एक अत्यंत सारगर्भित अवतरण में दादाभाई नोरोजी ने लिखा 'यदि मैं किसी व्यक्ति को 20 पौंड के मूल्य का सामान देता हूँ और बदले में पांच पौंड के मूल्य का दूसरा सामान और पांच पौंड मूल्य की चादी लेता हूँ तो यद्यपि मैंने बीस पौंड के बदले केवल दस पौंड ही प्राप्त किए हैं तथापि मैं पांच पौंड के लाभ में हूँ क्योंकि वे मुझे चादी के रूप में मिले हैं तब मेरी सपन्नता इस रूप में सचमुच सर्वथा ईर्ष्या से परे की वस्तु होगी *यस्य गतं सिद्धांत भ्रामक परिणाम प्रस्तुत करना है* हमके साथ ही उपर्युक्त परिस्थितियों पर उचित विचार किए बिना चादी के असंख्य आयातों के संबन्ध में लोगों का आश्चर्य इस प्रकार का है, जिस प्रकार एक छोटे से राटी के टुकड़े से सतुष्ट होने वाला बालक किसी बड़ी आय के व्यक्ति को पूरा रोटी खाते देख चकित होता है वह भोला बच्चा यह नहीं जानता कि रूखी-सूखी रोटी उस गरीब आदमी के जीवन निर्वाह का तुच्छ साधन है' (वही, पृ० 88) साथ ही देखिए, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 755-6 गोखले, बेलबी कमीशन, खंड III, प्र० 18239-43
139. जान स्ट्रेची और रिचार्ड स्ट्रेची पूर्वोद्धृत पृ० 312, 320 दि थर्ड डिस्निअल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 433, चिसनी पूर्वोद्धृत, पृ० 328, 394, स्ट्रेची इंडिया (1894), पृ० 304, एलगिन स्पीचेज, पृ० 360-1 कर्जन, स्पीचेज, खंड I, पृ० XXV तथा खंड II पृ० 289 फाइनेंशल स्टेटमेंट्स फार 1901-2 (1901-2 का वित्तीय प्रतिवेदन) (कड़िका, 127) 1902-3 का (कड़िका 14-5) 1903-4 (कड़िका 127) फोर्थ डिस्निअल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 332 जार्ज हैमिल्टन, हमांड (चतुर्थ वंश) 16 अगस्त 1901 खंड XCIX लगभग 1212-3 और इंडियन डिबेट्स (भारतीय विवाद) 3 फरवरी 1902 लगभग 110
140. नीचे IV अध्याय देखिए
141. कर्जन स्पीचेज खंड II, पृ० 450, और देखिए जार्ज हैमिल्टन 'इंडियन डिबेट्स', 3 फरवरी 1902, लगभग 110, फाइनेंशल स्टेटमेंट्स फार 1901 2 (कड़िका, 127) 1903-4 का (कड़िका, 35)
142. कर्जन स्पीचेज, खंड II, पृ० 450 और देखिए, वही, खंड III, पृ० 148, चिसनी पूर्वोद्धृत, पृ० 328, 332 फाइनेंशल स्टेटमेंट्स फार 1901-2 (कड़िका 109-11) 1902-3 का (कड़िका 97) 1903-4 का (कड़िका 115) 1904-5 का (कड़िका 45) फोर्थ डिस्निअल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट पृ० 332 मुद्राक शुल्क में बढ़ोतरी द्वारा सकेतित मुकुंदमेबाजी में

- बढ़ोतरी को भी भारतीय निर्धनता के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया नीचे देखिए
- 143 नीचे IX अध्याय देखिए
- 144 नीचे XI अध्याय में सीमा मुल्क प्रकरण देखिए इसके साथ ही देखिए, गोखले स्पीचेज, पृ० 17, मालवीय स्पीचेज, पृ० 380-1
- 145 गोखले स्पीचेज, पृ० 17
- 146 वही तथा 1904 की रिप० आई० एन० सी०, पृ० 166-7 मालवीय स्पीचेज, पृ० 381 इसके अतिरिक्त इस बात का स्पष्ट निर्देश किया गया कि इस कर से बहुत कम वसूली भारत की निम्नतम दरिद्रता को प्रमाणित करती है, नदी 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 119
- 147 गोखले स्पीचेज, पृ० 17 तथा 1904 की रिप० आई० एन० सी० पृ० 166 7
- 148 गोखले स्पीचेज, पृ० 18 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 200, 227 डी० ई० वाचा न काग्रस के अध्यक्षीय भाषण में निम्नलिखित आकड़े प्रस्तुत किए 1886 7 में प्रति व्यक्ति तथा 139 पौंड थी और 1899-1900 में 12 7 पौंड थी -सी०पी०ए० पृ० 603 बैंजर्जी सी०पी०ए०, पृ० 660
- 149 फोर्थ डिसिनियल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 332 कर्जन स्पीचन खंड II, पृ० 290 1 अतकिसन पूर्वोद्धृत, पृ० 215-20, 269 1901 में कर्जन न सगणना द्वारा सिद्ध किया कि कृषि भूमि का क्षेत्र 1880 में 1940 एकड़ के स्थान पर 1898 में बढ़कर 2170 एकड़ हो गया है अथवा दूसरे शब्दों में कृषि भूमि का विस्तार भव्य जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप हुआ है उसमें यह भी सिद्ध किया कि 1880 में 730 पौंड प्रति एकड़ उपज के मुकाबले 1898 में 840 पौंड उपज बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति के लिए खाद्यान्न प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं स्पीचेज, खंड II, पृ० 290-1 अतकिसन के अनुसार जो खाद्य उत्पादन 1875 में 1 701 पौंड प्रति दिन था, वह 1895 में बढ़कर 1 739 हो गया
- 150 जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 227, 334 335, 839 नदी 'इंडियन पालिटिक्स' पृ० 109 सायानी . सी०पी०ए०, पृ० 363, वाचा सी०पी०ए० पृ० 395, सायानी 15 फरवरी (जि० एन० पी० बग) 27 फरवरी 1890, गोखले स्पीचेज, पृ० 33 जोशी न 1890 में तथा 18/12-1888-9 की अवधि में बढ़ई मद्रास, नार्थवेस्ट प्राविंस तथा अवध और सट्टल प्राविंस तथा पंजाब में कृषि भूमि के क्षेत्र में 45 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में इन प्रांतों में जनसंख्या 110 लाख बढ़ी है (यदि सर डब्ल्यू० हटर का एक एकड़ का तीसरा-चौथा भाग खाद्यान्न प्रति व्यक्ति का तखमीना स्वीकार कर लिया जाए) तो 45 लाख एकड़ कृषि भूमि की कमी माननी पड़ेगी, पृ० 839
- 151 सायानी सी० पी० ए०, पृ० 363-4 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 900
- 152 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 839, सायानी सी० पी० ए०, पृ० 363
- 153 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 841-3, नदी 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 109
- 154 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 832, 835, 841, 844, 852, नदी 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 109
- 155 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 227, 333, 338, 753, गोखले स्पीचेज पृ० 19
- 156 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 836, गोखले स्पीचेज, पृ० 18, 32
- 157 थर्ड डिसिनियल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 428 रिपोर्ट आफ इंडियन फाइनेंस कमिशन, 1898, कड़िका 590, आर्थिक विवरण 1904-5 कड़िका 67
- 158 मोरोजी . पावर्टी, पृ० 66, 72, 79 जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 663, 898 जी० सी० अथर : 'रेलवेज इन इंडिया इन इंडियन पालिटिक्स'—पृ० 191 रेलवे की कमिशन, खंड III, प्रश्न

18693.

- 159 नौरोजी . पावर्टी, पृ० 69, 80 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 900
- 160 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 900 राय . पावर्टी, पृ० 174-5. जी० सी० अय्यर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 191 एच० आर—मई 1901, पृ० 352. बाद में इन दोनों धारणाओं को मूल्य तथा वेतन-वृद्धि की जाच समिति के प्रतिवेदन में दत्त द्वारा उल्लेखनीय समर्थन मिला, पृ० 61 और 'इपीरियल गजेट आफ इंडिया' (आक्सफोर्ड 1908) खंड III, पृ० 461
- 161 जी० सी० अय्यर ने बहुत से समाचारपत्रों तथा अन्य लेखों में इस दृष्टिकोण पर बार बार बल दिया सरल तथा स्पष्ट समीक्षा के लिए उनकी पुस्तक 'सम इकोनामिक आसपेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' से एक अवतरण निम्नलिखित है 'सत्य यह है कि मूल्यवृद्धि का लाभ बिचौलियों के हाथ में जाता है अधिकांशतया भारत के किसान अपने उत्पादन की निकासी के उपयुक्त समय और स्थिति को परख नहीं पाते बहुत के किसानों का उत्पादन तो इतना थोड़ा होता है कि वे इससे अपने परिवार का भी वर्ष के कुछ महीनों तक ही कठिनता से भरण-पोषण कर पाते हैं अवशेष की पूर्ति गांव में अथवा निकट के शहर में मेहनत करने से प्राप्त आय से की जाती है इस प्रकार भारतीय किसान अपने उत्पादन से स्वयं अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताएं, सरकार और साहूकार की मांगें पूरी नहीं कर सकता एक या दूसरे, प्रायः दोनों कारणों से उसे साहूकार से बड़ी ऊँची दर के मुँह पर ऋण लेना पड़ता है सरकार तथा साहूकार के दबाव बढ़ने पर ही वह अपने उत्पादन को अपनी इच्छा के विपरीत खास मौसम में मिलने वाले अथवा निकटवर्ती शहरों में अथवा समुद्री बंदरगाहों में मिल सकने वाले मूल्य से बहुत नीचे मूल्य पर बचने को विवश होता है बढ़ती कीमतों का लाभ कौन हड़प जाता है ? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह है कि आंशिक रूप से साहूकार और आंशिक रूप से किसान से सस्ते मूल्य पर अनाज खरीदकर महुँगे बाजार में बेचने वाला बिचौलिया' (पृ० 235) और देखिए, राय 'इंडियन फैमिस', पृ० 63 हिंदुस्तानी, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 21 अप्रैल 1892) गोखले : वेलबी कमीशन—खंड III, प्र० 18313, मराठा, 11 नवंबर 1902 वाचा सी० पी० ए०, पृ० 601
- 162 नौरोजी पावर्टी, पृ० 82, 85 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 228 राय पावर्टी, पृ० 176 और 'इंडियन फैमिस', पृ० 62-3 नदी पूर्वोद्धृत, पृ० 119-20 जी० एस० अय्यर वेलबी कमीशन, खंड III प्र० 18963, 19016 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 192 ई० ए० पृ० 223, 225-6, 259, मराठा, 16 नवंबर, 1902 वाचा सी० पी० ए०, पृ० 601 और देखिए, गोखले, वेलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18308
- 163 अध्याय II देखिए
- 164 अध्याय III देखिए
- 165 अध्याय IV देखिए
- 166 नौरोजी : पावर्टी, पृ० 147, 193 स्पीचेज, पृ० 124-44 सी० पी० ए०, पृ० 160-3, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 184, 188-189, वही, पृ० 308
167. आई० एन० सी०, 1900, प्रस्ताव II
168. आई० एन० सी०, 1902, प्रस्ताव IV आई० एन० सी०, 1903, प्रस्ताव XIII वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 566-7, 596-7 हिंदू, 28 नवंबर 1901. ए० बी० पी०, 27 फरवरी 1902, गोखले : स्पीचेज, पृ० 20, जी० सी० अय्यर : ई० ए०, पृ० 4, 6. आर० एन० पी० बंग में संसन्म पेपर

- 22 मार्च 1902 1807 में बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने ऐसी मांग का समर्थन किया था, देखिए, मराठा, 28 फरवरी 1897 एडवोकेट, 23 फरवरी, इंडियन मिरर, 28 फरवरी बिहार हैराल्ड, 27 फरवरी, इंडियन स्पोर्ट्स तथा वाइस आफ इंडिया (निर्देश के लिए इसे आगे आई० एस० वी० ओ० आई० से संकेतित किया जाएगा), 28 मार्च 1897
169. आई० एन० सी० 1903, प्रस्ताव III. एस० एन० बैंजॉर्न, पृ० 630-1 गोखले स्पीचेज, पृ० 20. और देखिए, वाचा सी० पी० ए०, पृ० 589, 595
170. अनेक सरकारी तथा अर्धसरकारी अधिकृत घोषणाओं में यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गया था देखिए ऊपर 1898 के अकाल आयोग ने एक प्रायः उद्धृत में टिप्पणी में कहा ऋतु सकट तथा घटिया फसल के कारण इस देश के समाज का अपेक्षाकृत निम्न वर्ग सुखमुविधाओं के निम्न स्तर तथा अभाव का जीवन सदा से जीता आया है और आज भी उसी रूप में जी रहा है यह निम्न वर्ग अपनी विशालता में मजदूरों तथा उपकुल्ल कारीगरों को बहुत बड़ी सख्या में समेटे हुए हैं. इस कठिन प्रश्न पर साक्ष्यों को सुनने तथा प्रस्तुत आकड़ों को देखने के उपरांत हम यह धारणा बना पाए हैं कि इन मजदूरों की आय पिछले बीस वर्षों में जीवन की आवश्यकताओं में मूल्यवृद्धि के उचित अनुपात में बढ़ी नहीं है वर्तमान दुर्भिक्ष का अनुभव यह सिद्ध नहीं कर पाया कि समाज के इस वर्ग के पास साधनों की प्रचुरता अथवा सहनशक्ति की अधिकता है यह वर्ग कम होने के बदेले और अधिक विशेषतः अधिक घनी आबादी वाले जिलों में धीरे धीरे फैलता जा रहा है उसकी पराभूतता अथवा परास्त होने की भावना क्षीण होने के बदेले और प्रबल हो होती जा रही है', (भारतीय अकाल आयोग 1898 का प्रतिवेदन, कड़िका-592) एक अमरीकी विद्वान जार्ज ब्लेक का नवीन अध्ययन, 'दि ऐग्रीकलचरल क्राप्स आफ इंडिया-1893-4 टू 1945-6 ए स्टैटिस्टिकल स्टडी आफ आउटपुट्स ऐंड ट्रेड्स', (अप्रकाशित, पांडुलिपि) पेसलवानिया विश्वविद्यालय के दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय अध्ययन विभाग न अनुमान लगाया है अध्ययन काल की अवधि में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खाद्य-उत्पादनो में निरंतर ह्रास हो रहा था 1893-94 वर्षों में उत्पादन 587 पौंड था, 1936-37 से 1945-6 तक यह गिरकर 399 पौंड हो गया—यंत्रों में उद्धृत पूर्वोद्धृत पृ० 123 एक अन्य समकालीन लेखक ने सगणना की है कि 'सभी साधनों से होने वाली भारत की प्रति व्यक्ति आय 1896 से 1945 में आठ प्रतिशत गिर गई थी'—युर्र जे० पटेल 'लाग टर्म चेंजेज इन आउटपुट ऐंड इनकम इन इंडिया 1896-1960' इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, जनवरी 1958, खंड V, स 3
171. वाचा सी० पी० ए०, पृ० 598
172. एन० पी० चंदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 512 दादाभाई नौरोजी ने 1898 की इंडियन करसी कमेटी को भेजे गए अपने एक बयान में बकालत करते हुए कहा, 'मान लीजिए, इस देश का भूतकाल खराब था, रक्तर्जित और अपमानजनक था, आप भविष्य को तो उत्तम, संपन्न और गौरवपूर्ण बनाकर दिखाइए' (पावर्टी, पृ० 548) जस्टिस रानाडे का तो सदा से यह विश्वास था कि विदेशी शासन में उन्नति अथवा अवनति के प्रश्न को तुलनात्मक रूप देना पुरातत्त्व विषयक इतिहास के प्रश्न के समान है हम सबके लिए व्यावहारिक प्रश्न तो देश की सामान्य रूप से सापेक्षिक नहीं, पूर्ण दरिद्रता और वर्तमान विवशता पर ध्यान केंद्रित करता है' उन्होंने यह स्वीकार किया कि 'कुछ सीमा तक तो स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण शिक्षाप्रद ही है'—(एसेज, पृ० 182)
173. जोशी पूर्वोद्धृत; पृ० 770 मालवीय स्पीचेज, पृ० 262-3. बत : 'इर्वीट ऐंड इंडिया—'

- पृ० 126. आई० एन० सी० 1900, प्रस्ताव II तथा परवर्ती कांग्रेस का प्रस्ताव. वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 539, दत्त : ई० एच० I, पृ० VI.
174. कर्जन : स्पीचेज, खंड III, पृ० 180 तथा वही, खंड II, पृ० 194, 289. भारत सरकार के 19 अक्टूबर 1888 में बंगाल सरकार का संक्षेप पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट-ए. चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 395.
175. डफरिन : पूर्वोद्धृत, पृ० 240-1.
176. लैसडोन : स्पीचेज (कलकत्ता) खंड II, पृ० 376 तथा थर्ड डिनमियल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 432-3 और जाजं हैमिल्टन-हमाडे (चतुर्थ वर्ग) 26 जुलाई 1900, खंड XLV लगभग 539; भारतीयों ने इस असर्गति के बड़े मजे से चटखारे लिए. एक ने तो तत्काल व्यंग्य करते हुए कहा कि सचमुच ही जनसंख्या की वृद्धि एक माघ दो प्रयोजन सिद्ध करती है. एक समय वह देश की भौतिक प्रगति का सूचक है तो दूसरे समय देश की बढ़ती दरिद्रता का कारण है. (नदी : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 107).
177. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 266-7, स्पीचेज, पृ० 620, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 773. जी० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०—1900, पृ० 29, एन० जी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 514. एम० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 684 पिरराजू रिप० आई० एन० सी०—1902, पृ० 75. दत्त : 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 132 स्पीचेज I, पृ० 26 ई० एच० आई०, पृ० VI माधारणी, 27 जलाई (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त 1884) हिंदू, 6 जुलाई 1898 मद्रास स्टैंडर्ड, 5 अगस्त, स्वदेश मित्रन, 5 अगस्त (आर० एन० पी० मद्र-10 अगस्त 1901).
178. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 773 तथा दत्त : सी० पी० ए०, पृ० 477 एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 684
179. नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 325-6, 621 ए० बी० पी०, 5 अगस्त 1886 राय : पावर्टी, पृ० 168-9.
180. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 620-1 स्पीचेज, पृ० 324, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 772 राय : पावर्टी, पृ० 197. दत्त : 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया' पृ० 132 ओपन लैंटर्न (खुली चिट्ठिया) पृ० 17 एन० पी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 514-5 एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 684 जी० एस० अय्यर : वेलबी कमीशन, खंड III प्र० 18648-9. रिप० आई० एन० सी० 1900, पृ० 29 हिंदू, 6 जुलाई 1853. सजीवनी, 15 फरवरी (आर० एन० पी०, बग, 22 फरवरी 1900) केसरी, 31 मार्च (आर० एन० पी० बंबई 4 अप्रैल 1903) एन० आर्गनवासाचारियर, रिप० आई० एन० सी० 1903, पृ० 66
181. पूना के 'सार्वजनिक मन्ना' के जनवरी तथा अक्टूबर 1890 के प्रको में प्रकाशित तथा उनके भाषणों और लेखों में पुनः तथाकथित.
182. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 773-5 (बल दिया गया).
183. वही, पृ० 774-5. कुछ वर्ष पूर्व अमृत बाजार पत्रिका ने 5 अगस्त 1886 को यही दृष्टिकोण बोड़े अस्पष्ट एवं असंबद्ध रूप में इन शब्दों में प्रस्तुत किया था : 'यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी उद्धृत सम्य राज्य में किन्हीं निश्चित विस्तृत सीमाओं के घतर्गत कृषि अथवा अन्य कार्यों में लगे लोगों की बोड़ी संख्या की अपेक्षा बड़ी संख्या को ही सामूहिक रूप से अधिक साधन जुटाए जा सकते हैं. तथा देखिए, नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 391—ब्रिटिश राज्य भारत पर अपना नियंत्रण छोड़कर देखा ले कि जनसंख्या की वृद्धि उनके द्वारा कल्पित अकाल और दरिद्रता का कारण है अथवा इसके सर्वथा विपरीत शक्ति और उत्पादन में वृद्धि का आधारभूत कारण है ? साथ में देखिए, बी० एस० अय्यर : वेलबी कमीशन, खंड III, प्रगन 18733-6.

184. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 852, तथा रानाडे : एसेज, पृ० 207, वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 600.
185. देखिए अध्याय II.
186. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 217.
187. पी० सी० राय : 'इंडियन कैमिस्ट' (भारतीय अकाल) (कलकत्ता 1901) पृ० 35 और नोरोजी : पावर्टी, पृ० 217. क्रमशः.
188. डफरिन : स्पीचेज, पृ० 240. थर्ड इनिशियल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 434. फोर्थ इनिशियल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 354. कर्जन : स्पीचेज, खंड III, पृ० 149. भारत सरकार का प्रस्ताव, सं० 1, दिनांक 16 जनवरी 1902 (कलकत्ता 1902) कंडिका 31.
189. भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 19 अक्तूबर 1888, पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट-ए.
190. कर्जन : स्पीचेज, पृ० 166, खंड II. भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 16 जनवरी 1903, पूर्वोद्धृत कंडिका 31.
191. भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 19 अक्तूबर 1888, पूर्वोद्धृत परिशिष्ट-ए.
192. दत्त : ई० एच० I, पृ० VI तथा रानाडे : 'लेट सा रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक' (भूमि कानून में सुधार तथा कृषि बैंक) जे० पी० एस० एस० अक्तूबर 1881 (खंड IV सं० 2), पृ० 55 (जी० ए० मानेकर के साक्ष्य के आधार पर यह लेख रानाडे का ही लिखा हुआ है, देखिए उनकी पुस्तक : 'ए स्केच आफ दि लाइफ ऐंड वर्क्स आफ दि लेट मिस्टर जस्टिस एम० जी० रानाडे' दो खंड, बंबई 1902, खंड I, पृ० 215) जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 778. राय : पावर्टी, पृ० 194-5. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 663-4 एन० जी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 516 दत्त : सी० पी० ए०, पृ० 478, 480, ओपन लैटर्स, पृ० 17, ई० एच० II, पृ० XIII एन० के० एन० अम्बर : रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 140. श्रीराम : एल० सी० पी० 190, खंड XLI पृ० 146-7. एस० एन० बेंनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 684-5. जे० बेंजामिन . रिप० आई० एन० सी०—1904, पृ० 128.
193. सामान्य किसान के विषय में भी सत्य यह है कि जीवन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत और अधिक श्रम करने के उपरांत भी वह बेचारा जीवन में समारोह के अवसर पर घर-गृहस्थी में आनंद मनाने के लिए मिट्टी के कुछ नए बरतनों, थोड़े बहुत जगली फूलों, गाव की टमटम, पेट भर खाना, घटिया पान-मुपारी तथा तबाकू के पत्तों और कहीं कहीं, कभी कभी, घटिया दिशावटी गहनों को जुटाने में ही टूटकर रह जाता है (पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 663) वस्तुतः भारतीय किसान के लिए कोई भी दिन उन्मत्त-समारोह का नहीं वह तो साग वषं सूर्योदय से सूर्यास्त तक कठोर श्रम करता है उसे वर्ष में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिलता. (ए० बी० पी०, 2 अगस्त, 1901).
194. नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 619 मन्देश मित्रन, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रैल 1897) नदी : 'इंडियन पार्लियामेंट', पृ० 117. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 663. जी० एस० अम्बर : ई ए, पृ० 14. एन० पी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 516, एस० एन० बेंनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 684-5.
195. नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 312 तथा वही, पृ० 619. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 664. एन० पी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 516.
196. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 775 और वाचा : रिप० आई० एन० सी० 1886, पृ० 61.

- 197 नौरोजी पावर्टी, पृ० 87-8 एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 515 स्वदेशमित्र, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एम, 30 अप्रैल 1897) मद्रास स्टैंडर्ड, 5 अगस्त तथा स्वदेश मित्र, 5 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 10 अगस्त 1901)
- 198 रानाडे 'लैंड सा रिफार्म ऐंड एग्रीकल्चरल बैंक्स', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 55 नौरोजी एसेज, पृ० 368 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 773 सी० सकरन नय्यर सी० पी० ए०, पृ० 384 एन० सी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 521 एन० के० एम० अय्यर—रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 140-1, दत्त ई एच II, पृ० XIII, 7-11
- 119 रानाडे एसेज, पृ० 52-3, 256 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 347 362 852 870 905 राय पावर्टी, पृ० 190
- 200 रानाडे एसेज, पृ० 326 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 852 राय पावर्टी, पृ० 191 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 78 बगानी, 24 मई 1901 एच० आर०, अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 31 मई 1902)
- 201 ए० बी० पी, 24 दिसंबर 1874 17 जुलाई 1884, 31 जनवरी 1892 2 जनवरी 1901 गनेश डब्ल्यू जोशी जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 80 4 मई 1879 को पूना में जनसभा में पारित प्रस्ताव, बही, पृ० 84 रानाडे : डिक्शन एग्रीकल्चरलिस्ट बिल—जे० पी० एस०—अक्तूबर 1878 (खंड II स० 2) पृ० 55 तुलनीय मानकर—पूर्वोद्धृत खंड I, पृ० 214) 'लैंड सा रिफार्म ऐंड एग्रीकल्चरल बैंक्स—पूर्वोक्त स्थल, पृ० 43-4, एल० एम० घोष स्पीचेज, पृ० 88 डि० 26 नवंबर 1885 बगानी, 12 मार्च 1892 राय पावर्टी पृ० 195, 236 एन० पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 518-9 दत्त सी० पी० ए०, पृ० 493, इंग्लैंड 'फैंड इंडिया', पृ० 147-8 स्पीचेज I, पृ० 14, 27 'ई एच I, पृ० XX जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1900, पृ० 29
- 202 ब्रिटिश दृष्टिकोण के लिए देखिए, डफरिन स्पीचेज, पृ० 240 जिसनी पूर्वोद्धृत, पृ० 395 कर्जन स्पीचेज, खंड II, पृ० 166 1901 के अकाल आयोग के अध्यक्ष सर एडोनी मंकडानल के डिग्री के नाम पत्र, डिग्री की पुस्तक में उद्धृत, पूर्वोद्धृत पृ० 323
- 203 कर्जन . स्पीचेज, खंड I, पृ० 313 4 'जब किसी देश के वासियों की बहुत बड़ी संख्या एक ऐसे उद्योग पर निर्भर हो जो स्वयं वर्षा पर निर्भर हो तो स्पष्ट है कि वर्षा न होने पर सारी कृषि पर निर्भर जनता का बुरी तरह से प्रभावित होना तथा वर्षा के पूर्णतः अभाव की स्थिति में जनता का विपन्न होना स्वाभाविक और निश्चित ही है,' भारत सरकार का 16 जनवरी 1902 का प्रस्ताव पूर्वोद्धृत, कड़िका-3 तथा फोर्थ डिस्ट्रिक्ट मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 332
- 204 कर्जन स्पीचेज, खंड III, पृ० 160 और देखिए एलगिन स्पीचेज, पृ० 345 जॉर्ज हैमिलटन 'इंडियन डिबेट्स', 3 फरवरी 1902 लगभग 108-9 स्टैंडर्ड 'इंडिया' (1903), पृ० 210
- 205 कर्जन स्पीचेज, खंड III, पृ० 160-1
- 206 दत्त स्पीचेज II, पृ० 56 नौरोजी, पावर्टी, पृ० 665 तथा 'प्रकृति कितनी भी क्रूर क्यों न हो अपर्याप्त वर्षा के कारण फसले कितनी भी यादी क्यों न हुई हो, अने आप में दुर्भाग्य और दुखरूप अकाल तथा सूखा, जिससे बहुसंख्यक जनता नष्ट हो गई है, रोके जा सकते थे। बाचा सी० पी० ए०, पृ० 356-7, और देखिए, आर० एम० मायानी एल० सी० पी०, 1897 खंड XXXVI, पृ० 19 एन० के० एन० नय्यर, रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 139
- 207 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 346, 853 'प्रधान ऐंड भागवत' से तिलक का उद्धरण, पूर्वोद्धृत, पृ० 102

- एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 514 दत्त 'ओपन लैटर्स', पृ० 18 राय कैमिस, पृ० 24 एन० के० रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 134 केसरी, 25 दिसंबर आर० एन० पी० बर्बई 29 दिस० 1900)
- 208 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 346, 869 हिंदू—2 अप्रैल 1900 रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1900, पृ० 134 दत्त 'ओपन लैटर्स', पृ० 18
- 209 ए०बी०पी०, 1 मार्च 1897 मधोलकर पूर्वोद्धृत, पृ० 33 आई० एन० सी० 1896 का प्रस्ताव XII, आई० एन० सी० 1900 का प्रस्ताव II आई० एन० सी०—1892 का प्रस्ताव III. दत्त ई० एच० I, पृ० VII राय कैमिस, पृ० 29-30
- 210 दत्त ई० एच० I, पृ० VII केसरी, 10 अप्रैल (आर० एन० पी० बर्बई 14 अप्रैल 1900) मद्रास स्टैंडर्ड, १ अगस्त स्वदेशमित्र, 5 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 10 अगस्त 1901) बाबा सी० पी० ए०, पृ० 537 तुलनीय—भारत सरकार कम से कम इस तथ्य से तो सतुष्ट हो सकती है कि भारत में खाद्यान्न सभरण की लगभग कोई कठिनता नहीं। यहाँ तक कि सूखे के दिनों में भी इस महाद्वीप में पर्याप्त खाद्य उपलब्ध है —भारत सचिव जार्ज हैमिन्टन वा 26 जुलाई 1900 को हाउस आफ कामंस में कथन, ईसाई (चतुर्थ वगं) खंड LXXXVI लगभग 1346
- 211 राय कैमिस, पृ० 78 और देखिए, एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 514 श्रीराम एल० सी० पी०, 1901 खंड XL पृ० 238 तथा एल० सी० पी०, 1902 XLI पृ० 147 ए० बी० पी०, 13 नवंबर 1901, एस०एन० बैनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 683, केमरी—21 जुलाई (आर० एन० पी० बर्बई, 25 जुलाई 1903)
- 212 जी० सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1900, पृ० 31 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 656 बाबा सी० पी० ए०, पृ० 559
- 213 नोरोजी पावर्टी, पृ० 656 और स्पीचज, पृ० 237 राय कैमिस पृ० 32 दत्त ई० एच० I, पृ० VII तथा ई० एच० II पृ० VI, बैनर्जी सी० पी० ए०, 683-4
- 214 वस्तुतः अन्न की न्यूनता अथवा अभाव नहीं प्रत्युत निर्धनता के कारण क्रयशक्ति के अभाव को ही वस्तुतः भारतीय अकाल कहा जाता है, (ए० बी० पी०, 22 मई 1892) और ज्ञानप्रकाश 16 जनवरी (आर० एन० पी० बर्बई, 18 जून 1879) साम प्रकाश, 1 दिस० (आर० एन० पी० बग, 6 दिस० 1884) मराठा 29 मार्च 1891 मधोलकर पूर्वोद्धृत, पृ० 38 नोरोजी पावर्टी, पृ० 656 केमरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बर्बई, 7 अप्रैल 1900) राय कैमिस, पृ० 31 बाबा सी० पी० ए०, पृ० 557 श्रीराम एल० सी० पी०, 1901 खंड XL पृ० 238 एम० के० पटेल रिप० आई० एन० सी०, 1902, पृ० 76 अगली, 9 मार्च 1902
- 215 गोखले बेलबी कमीशन, खंड III, प्रश्न 18314-8 भारत जीवन, 25 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 3 अगस्त 1898) तिलक रिप० आई० एन० सी०, 1900, पृ० 36 बैनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 684 केसरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बर्बई, 29 दिसंबर 1900) श्रीराम एल० सी० पी०—1902 खंड XLI पृ० 147
- 216 आई०एन०सी०—1896 का प्रस्ताव XII आई० एन० सी०—1897 का प्रस्ताव IX आई०एन० सी०—1901 का प्रस्ताव VII सी० सकरन नैय सी०पी०ए०, पृ० 383 जी०सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1900, पृ० 29 एन० के० एन अय्यर : रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 140 राय कैमिस, पृ० 29, नोरोजी स्पीचेज, पृ० 251. एस० एम० बैनर्जी . सी० पी० ए०, पृ० 683.

217. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 152. आई० एन० सी० — 1896 का प्रस्ताव XII. मधोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 33. आई०एन० सी०—1900 का प्रस्ताव II. चंद्रावरकर : सी०पी०ए०, पृ० 514. बाचा : सी० पी० ए०, पृ० 560. दत्त : ओपन लैंटर्स, पृ० 18. रामास्वामी अय्यर : रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 134 कंसरे हिंद, 22 सितंबर (आर० एन० पी० बंबई 28 सितंबर 1901).
218. यहां तक कि लोग अच्छी फसल के वर्षों में आधे भूखे रहते थे और जब बुरे दिन आते थे तो वे बेघारे शीघ्र ही मृत्यु का श्रास बन जाते थे—(नौरोजी : पावर्टी, पृ० 656). और देखिए, वर्षा के अभाव से तो देश के किसी भाग की ही फसल नष्ट होती है. वस्तुतः लोगों की दरिद्रता ही तीक्ष्ण अकालों को निमित्त करती है —(दत्त, ई एच II-पृ० 5)
219. ऊपर देखिए.
220. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 752. उपजाऊ धरती, उत्तम भौगोलिक स्थिति तथा उत्पादन के अनुकूल वातावरण की विविधता से सपन्न ऊंचे स्तर के खनिज साधनों से समृद्ध तथा अल्पव्ययी, विवेकी, शांतिप्रिय तथा परिश्रमी जनसंख्या वाला यह देश संपत्ति के उत्पादन और संचय के लिए अपवाद-रूपक सुविधाओं से सपन्न है. इस प्रकार की स्पृहणीय स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भारत न केवल कवियों द्वारा प्रशंसित अपितु इतिहासकारों तथा ममकालीन लेखकों द्वारा भी समर्थित ब्रह्म मे अतीत की श्रेष्ठता को प्राप्त न करे —(मधोलकर, पूर्वोद्धृत, पृ० 35). जी० एस० अय्यर ने अठारहवीं कांग्रेस को निदिष्ट किया, भारत के पास समृद्धि की पूर्वा-काक्षित आवश्यकताओं में एक है, सभी सभ्य कृषि उत्पादनों तथा दस्तकारियों को खपाने के लिए बहुत बड़ी मंडी है रिप० आई० एन० सी०—1902, पृ० 72. और, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 40. सी सकरन नैयर : सी० पी० ए०, पृ० 384. दत्त : स्पीचेज II पृ० 37. ई एच II, पृ० 611. एन० के० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 140-1 जी० सी० अय्यर ई ए—परिशिष्ट-ए, पृ० 3.
221. जान आदम : 'दि परमानेंट सेटलमेंट कंसेप्शन इन इंडियन पालिटिक्स', पृ० 80. जान स्ट्रुवी ने शायद 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट'—1878-9 कड़िका-2 में पहले ही इस विरोधाभास को अभिव्यक्ति दी थी
222. हमारे अपने ही देश के इतिहास का अध्ययन इस महान सत्य का बड़े विलक्षण ढंग से उद्घाटन करता है कि हम कितने विपन्न और कितने अपमानित हैं ? हमारा दुर्भाग्य श्रेणीबद्ध और शृंखला-बद्ध रूप में आता रहा है जिसकी प्रत्येक कड़ी का विश्लेषण किया जा सकता है. हम भाग्य के क्रूर हाथों के शिकार नहीं हुए, हम अभूतपूर्व सकटों का शिकार नहीं हुए और जहां परिस्थितियों ने वास्तव में ही हमारी नियति पर पूर्ण प्रभुत्व लगाया है, वहां भी यदि हम प्रयत्न करते तो आर्थिक रूप से उन परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकते थे और इसके फलस्वरूप देश का घोर कदाचित्त व्यापक रूप से विषय का चेहरा बदल सकते थे. —एस० एन० बैनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 26. अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 12 अगस्त 1886 के अंक में लिखा—भारत की दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास्तविक कारण ईश्वर की कृपणता न होकर मानव की लोभ-लालसा है
223. आर्थिक नियमों का तो यूरोप और एशिया में एक ही रूप है। यदि भारत दरिद्र है तो यह आर्थिक कारणों का ही व्यापारगत प्रभाव है। आर्थिक नियम तो अपने व्यापार में अचल और अपरिवर्तित रहते हैं. दत्त : ई एच II पृ० XVI-XVIII और देखिए उनकी पुस्तक; 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 144, स्पीचेज II, पृ० 63. ई एच I, पृ० VI, XII-XIV तथा बाचा : सी० पी० ए०, पृ० 560. 'बोड़ी पूर्व सूचना के लिए, भारतीय नेताओं द्वारा भारतीय दरिद्रता के लिए प्रायः प्रस्तुत कारण थे, 'भारत के देशी उद्योगों का विनाश और उसके फलस्वरूप देश का शोषण.

किसानों से भारी भू राजस्व की मांग, महंगा प्रशासन और परिणाम में ऊँचे कराधान तथा भारत से इंग्लैंड को धन की निकासी।'

224. 1900 में लार्ड कर्जन ने मद्रास महाजन सभा के सदस्यों को परामर्श दिया कि सरकार की आलोचना करने की अपेक्षा वे किसान को साहूकार और कानूनी कचहरियों से बचाने में अपना समय लगाएं. —कर्जन : स्पीचेज, खंड II पृ० 166 तथा देखिए, डफरिन : स्पीचेज, पृ० 241-2.
225. 1902 के भू-राजस्व प्रस्ताव ने समीक्षकों को चेतावनी दी कि वे स्वयं अपने द्वारा तथाकथित पहचाने रोग और सरकार के कर्तव्य अथवा शक्ति क्षेत्र के भ्रतर्गत उसके उपचार के प्रयोग के संबंध में अत्यंत विवृत विश्लेषण प्रस्तुत न करें. (बल दिया गया, पूर्वोद्धृत, कंडिका 31).
226. आई० एन० सी०—1891 का प्रस्ताव III. प्रस्ताव के उपसंहार में ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की जनता से अनुनय विनय की गई कि वह निस्संदेह शुभ इच्छाओं से प्रेरित होते हुए भी पर्याप्त रूप से असंतोषप्रद वर्तमान प्रशासन की वृत्तियों से और अधिक जनहानि न होने दें. —प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मदनमोहन मालवीय ने जोर दिया : इस प्रस्ताव में हम उन कारणों का उल्लेख कर रहे हैं जिसके लिए सरकार ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है और साथ ही हम वे उपचार सुझा रहे हैं जिनके प्रयोग का प्रत्यक्ष संबंध सरकार से है, परंतु यह तभी संभव है जब सरकार इस ओर ध्यान देने की चिंता करे. वस्तुतः यदि सरकार को अपने को सभ्य सरकार कहलाने की चिंता है तो इन उपचारों का प्रयोग उसका प्रमुखतम कर्तव्य है. —(मालवीय : स्पीचेज, पृ० 229) और देखिए, उदाहरणार्थ, नौरोजी . पावर्टी, पृ० 216-7, स्पीचेज, पृ० 225, 228, 306 परिशिष्ट पृ० 17, 78. एसेज, पृ० 368. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 785-6, 818. आई० एन० सी०; 1892 का प्रस्ताव IX. नैयर : सी०पी०ए०, पृ० 384. दत्त : 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 144. स्पीचेज II पृ० 37. ई एच II पृ० 611-2, 614. (वस्तुतः यही भावना उनके आर्थिक इतिहासों के दोनों खंडों की भूमिकाओं में सन्निहित है) जी० सी० अय्यर : बेलबी कमोजन खंड III प्र० 18644 ई-ए, पृ० 3. नंदी : 'इंडियन पामिटिक्स', पृ० 134. तिलक : रिप० आई० एन० सी०—1900, पृ० 36 तथा प्रधान एंड भागवत में उद्धृत,—पूर्वोद्धृत, पृ० 102, 143-4 वाचा : सी०पी०ए०, पृ० 626. एन० श्री निवास बरदाचारी : रिप० आई० एन० सी०—1903, पृ० 66. 9 मार्च 1902 के धक में 'बंगाली' ने टिप्पणी की : सरकार स्वाभाविक रूप से स्पष्ट कारणों से ही राष्ट्रीय दल द्वारा भारत के अकालों के संबंध में प्रस्तुत विश्लेषण को स्वीकार करने को उद्यत नहीं। क्योंकि इसकी स्वीकृति का अर्थ वर्तमान सारी प्रशासन व्यवस्था का ऐसे आधार पर पुनर्गठन होगा जो 'भारत पहले अंग्रेजों के लिए और बाद में भारतीयों के लिए' वाले सिद्धांत के विरुद्ध पड़ेगा।

अध्याय 2

औद्योगिक विकास : एक

भारतीयों की विशाल जनसंख्या कृषि में प्रशिक्षित है। भारतीय शारीरिक दृष्टि से कृषि के उपयुक्त हैं। वे कृषि को छोड़ अन्य किसी उद्योग में प्रवृत्त ही नहीं हो सकते।

साहब कर्जन

भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के दिन से ही इंग्लैंड की निश्चित नीति भारत को इंग्लैंड के शिल्पकारों और औद्योगिक व्यापारियों के लाभ के लिए कच्चा माल पैदा करने वाले देश के रूप में बदलने की रही है।

मुरेंड्रनाथ बनर्जी

स्वदेशी उद्योग-धंधों का ह्रास

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था, भारतीय कस्बों की हस्तकलाओं और ग्रामों के हस्तशिल्प उद्योगों के क्रमशः बढ़ते क्षय और विध्वंस के फलस्वरूप कृषि और उद्योग व्यवसायों के सदियों पुराने ऐक्य का छिन्न भिन्न होना।¹ 18वीं शताब्दी तक भारत की आर्थिक दशा अपेक्षित रूप से उन्नत थी तथा भारत की उत्पादन विधियां तथा उसके व्यापारिक और औद्योगिक संगठन विश्व के किसी भी अन्य देश में प्रचलित इस प्रकार की विधियों और संगठनों की तुलना में रखे जा सकते थे।² हां, 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से स्वदेशी उद्योग-धंधे या तो पुनरुद्धार की सीमा के बाहर जाकर नष्ट हो चुके थे या विनाश के पथ पर बढ़ते हुए अंतिम सांस ले रहे थे जबकि आधुनिक उद्योग ने अभी पर्याप्त उन्नति नहीं की थी।³

प्रारंभिक भारतीय नेताओं की प्रमुख आर्थिक समस्या थी, देश की औद्योगिक दशा। उन्होंने भारत की दरिद्रता का विश्लेषण अधिकांशतः स्वदेशी उद्योगों के विनाश के फल-स्वरूप औद्योगिक पंगुता तथा इस विनाश की पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए आधुनिक उद्योग के द्रुत विकास में असफलता के रूप में ही प्रस्तुत किया।⁴ प्रचलित विषयों पर लेख लिखनेवालों ने दिन-प्रतिदिन इस विषय पर अनवरत प्रहार किए तथा एक अथवा दूसरे उद्योग के विनाश पर निरंतर बिलाप किया।⁵ इस ह्रास की ऐतिहासिक प्रक्रिया

की खोज करते हुए उन्होंने बताया कि भारत कभी एक बहुत बड़ा शिल्प-उत्पादक राष्ट्र था और उसके औद्योगिक उत्पादन शताब्दियों तक एशिया तथा यूरोप के बाजारों की मांग की पूर्ति करते रहे हैं।⁸ इस देश के कताई-बुनाई तथा अन्य उद्योग-धंधों ने लाखों नर-नारियों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आजीविका जुटाई है।⁹ परंतु ब्रिटिश सत्ता के साथ यह सब कुछ लुप्त हो गया है। भारत ने अपना विदेशी बाजार ही नहीं खोया, प्रत्युत अपनी घरेलू मंडी भी खो दी है। इस समय भारत को बराबर बहुत बड़े परिमाण में विदेशी सामान का आयात करना पड़ रहा है।¹⁰ फलस्वरूप जो देश अपने देशवासियों के लिए 50 वर्ष पूर्व तक स्वयं वस्त्रों का उत्पादन करता था, आज वस्त्रों के लिए दूर के मालिकों पर निर्भर हो गया है। यही स्थिति हमारे रेशम, ऊन, चर्बी तथा खाल उद्योगों की है। कुल मिलाकर यही हमारी शोचनीय दशा है और इस सारी स्थिति की सामूहिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम पतन के उस भयंकर कगार पर खड़े हैं कि जहां से मामूली सा धक्का ही हमें निश्चित और पूर्ण विनाश के गहरे गड्ढे में धकेल सकता है।¹¹ आर०सी० दत्त के अनुसार, 'विदेशी उत्पादनों द्वारा भारतीय शिल्प-उत्पादनों की स्थानापन्नता ब्रिटिश भारत के इतिहास का निकृष्टतम अध्याय है'।¹² क्योंकि इसमें भारत के आर्थिक स्रोतों में हुए संकोच और भारतीयों की आजीविका में आई और अधिक कृच्छता तथा विषमता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।¹³ भारतीय नेताओं ने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था के कृषि संबंधी और उद्योग संबंधी क्षेत्रों के संतुलन में विकार ने और इसके फलस्वरूप औद्योगिक ह्रास ने न केवल राष्ट्रीय आय के एक बहुत बड़े तथा महत्वपूर्ण स्रोत को ही नष्ट-भ्रष्ट किया है प्रत्युत लाखों कारीगरों को परंपरागत व्यवसायों से वंचित करके उन्हें आजीविका के अन्य साधनों के अभाव के कारण, आजीविका के एकमात्र अवशिष्ट साधन कृषि पर अधिकाधिक निर्भर होने को विवश भी किया है।¹⁴ इस प्रकार हस्तशिल्प उद्योगों के ह्रास ने भूमि पर लोगों का दबाव बढ़ा दिया है।¹⁵ इसके फलस्वरूप भारत का ग्रामीकरण बढ़ता जा रहा है और भारतीयों की अकेले कृषि के ही विषम साधनों पर निर्भरता में वृद्धि हो रही है।¹⁶ भारतीय जनता के आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता के बढ़ते अनुपात से भारत के ग्रामीकरण के विस्तार को नापा जा सकता है।¹⁷ कृषि पर एकांत निर्भरता भी चिंतनीय है क्योंकि अनिश्चित वर्षा के रूप में प्रकृति की कृपा पर निर्भर होने के कारण यह एक अविश्वसनीय उद्योग है।¹⁸ इसके अतिरिक्त देश का ग्रामीकरण भी एक भयंकर आर्थिक रोग है क्योंकि कृषि भूमि के सीमित होने के कारण उसमें नए प्रवेश को खपाने की क्षमता नहीं है।¹⁹ विचारणीय यह है कि एकांततः और पूर्णतया कृषि पर निर्भर रहने वाले राष्ट्र का दरिद्र होना निश्चित ही है।²⁰ बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 के अकाल आयाग की राय का अनुमोदन करते हुए उसे उद्धृत किया : भारत के लोगों की अधिकांश दरिद्रता का तथा अभाव के दिनों में अनुभूत खतरों का मूल कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि अधिकांशतः भारतीय जनता के लिए एकमात्र व्यवसाय कृषि है।²¹ कृषि पर अवांछनीय भार कृषि संबंधी दक्षता को भी प्रभावित करता है।²² इसके अतिरिक्त इससे खेतों का उपभोग न हो जाता है, आवश्यकता से अधिक जुताई होने लगती है, घटिया और अनुत्पादक धरती

पर जुताई होने लगती है तथा जंगलों और चरागाहों पर अनुचित कब्जा किया जाने लगता है।²¹ इन सबका परिणाम ग्रामों की प्रच्छन्न बेकारी है।²² जी० वी० जोशी ने भी निर्देश किया कि एक ओर भूमि को अवांछनीय श्रमिकों का भार सहन करना पड़ता है और दूसरी ओर बचत के अभाव के फलस्वरूप भूमि में सुधार के लिए आर्थिक साधनों की कमी होती है।²³ भूमि पर दबाव खेतिहरों में सर्वथा अलाभकारी तथा बहुत ऊँचे किरायों पर घरती को लेने से विनाशकारी प्रतियोगिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।²⁴ इस प्रतियोगिता के कारण कृषि श्रमिक एक-दूसरे की मजदूरी का अवमूल्यन करते हैं।²⁵ रानाडे ने भी अनुभव किया कि आधुनिक भारत के ग्रामीकरण का अर्थ है उसे असम्य बनाना अर्थात् उसकी शक्ति, प्रतिभा और आत्मरक्षा की भावना का विनाश करना।²⁶ पारंपरिक उद्योग-धंधों के इस बढ़ते हुए विनाश के साथ उनके स्थान पर नवीन उद्योगों की स्थापना में असफलता का निकृष्टतम परिणाम यह था कि भारत का आर्थिक जीवन अधिकाधिक विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के अधीन हो गया था। विदेशी शासकों ने तुच्छ दृष्टि से भारत को ब्रिटिश अभिकर्ताओं द्वारा ब्रिटिश जहाजों पर लादने के लिए कच्चा माल उत्पन्न करनेवाली एक बस्ती के रूप में ही लिया। भारत का कच्चा माल ब्रिटिश कारीगरी और ब्रिटिश धन से वस्त्रों के रूप में परिणत होता था और फिर वही सामान ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत तथा अन्य अधीनस्थ राज्यों में ब्रिटिश व्यापार सघों के माध्यम से पुनः निर्यातित किया जाता था।²⁷ परंतु ग्रामीण तथा शहरी हस्त उद्योगों का यह द्रुत विनाश हुआ कैसे? क्या यह समय अथवा परिस्थितियों के परिवर्तन का अपरिहार्य परिणाम था? यदि ऐसा था तो यह एक दुःखद प्रतिक्रिया के विवा और कुछ नहीं था। इस संबंध में भी भारतीय नेताओं का विश्वास था कि मनुष्यों के नियंत्रण में बाहर की घटनाओं की भी भूमिका रही होगी। किंतु वस्तुतः भारत के उद्योग-धंधों का विनाश तो निश्चित रूप से हृदयहीन स्वार्थपरता तथा क्रूर अन्याय की एक करुण कहानी थी।²⁸ उन्होंने इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ब्रिटेन पर तथा भारत में स्थित ब्रिटिश अधिकारियों के कंधे पर ही डाला, जिन्होंने एक निश्चित सकल्प तथा विनाशक दृढ़ता के साथ²⁹ भारत के उद्योगों के विनाश की सुविचारित नीति का अनुसरण किया।³⁰

भारतीय नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटेन के व्यापारियों और शिल्प उत्पादकों के दबाव के कारण भारतीय उद्योगों पर उसके दुष्प्रभाव की चिंता किए बिना, और यहाँ तक कि उनके मूल्य पर भी, इंग्लैंड के विकासशील उद्योग को प्रोत्साहन देने को दृढ़संकल्प थे।³¹ उनके अनुसार भारत में ब्रिटिश नीति का द्विपक्षीय उद्देश्य था, एक तो ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन की क्षमता के लिए भारत को एक मूल्यवान मंडी बनाना, भले ही इसके लिए भारतीय उद्योग-धंधों के कुचलने के लिए विविध तीव्र साधन ही क्यों न अपनाने पड़ें।³² दूसरा, ब्रिटेन के तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों के लिए ब्रिटेन की बढ़ती हुई आवश्यकता के कच्चे माल को सस्ती दर और सुनिश्चित परिमाण में संतोषजनक सभरण के लिए भारत को कच्चे माल के उत्पादक कृषि देश के रूप में परिवर्तित करना।³³ इन दोनों उद्देश्यों की सिद्धि भारतीय उद्योग धंधों को आघात पहुँचाकर और

इस प्रकार भारतीय अर्थ व्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों की सहायक बनाकर ही की जा सकती थी।³⁴

भारतीय नेताओं को पूरा यकीन था कि ब्रिटेन ने अपने राजनीतिक नियंत्रण का दुरुपयोग करते हुए भारत और ब्रिटेन में व्यापार में प्रतियोगिता की अन्यायपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करके भारत के उद्योगों का बड़ी ही तत्परता और तेजी से विनाश किया है।³⁵ उन्होंने इतिहासकार एच० एच० विलसन के इस मत से सहमति प्रकट की कि विदेशी उत्पादन समान शर्तों पर समझौता अथवा बराबरी न कर सकने पर अपने प्रतियोगी को नीचा दिखाने और अंततः उसका गला घोटने के लिए राजनीतिक अन्याय के शस्त्र का प्रयोग करता है।³⁶ 1765 में बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन के प्रारंभ काल से यह कहा जाने लगा कि शासकों ने स्वदेशी हस्त शिल्पों को कुचलने के लिए आदेश जारी किए हैं।³⁷ 1813 और 1833 की संसदीय जांचों का एकमात्र उद्देश्य भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माताओं के स्वदेशी उत्पादनों को अपदस्थ करने के साधन खोजना था।³⁸ भारतीय नेताओं के अनुसार इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए खोजा गया अति महत्वपूर्ण उपाय था, भेदमूलक सीमा शुल्कों का कराधान। भारतीय उत्पादकों के लिए जहाँ प्रतिबंधों और अत्यधिक ऊँची शुल्क पद्धति के कारण अंगरेजी बाजार तेजी से संकुचित होता जा रहा था, वहाँ उन्मुक्त व्यापार लागू होने के कारण भारतीय बाजार अंगरेज व्यापारियों के लिए अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा था।³⁹ 1848 में भारत के इंग्लैंड को निर्यातों पर निषेधक करों को हटा दिया गया परंतु उस समय तक के कर अपना मंहारक प्रहार कर चुके थे।⁴⁰ भारत का आंतरिक व्यापार भी अंतर्देशीय सीमा शुल्कों तथा संक्रमण शुल्कों की प्रथा के लागू होने से प्रतिबंधित तथा संकुचित था तथा इससे अपने ही बाजार में स्वदेशी उत्पादनों में एक दूसरे के विरुद्ध भेदभाव पनपता था।⁴¹ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जुलाहों तथा अन्य दूसरे उत्पादकों पर एकाधिकारी नियंत्रण रखने के लिए, उन्हें अलाभकारी सस्ते दामों पर माल का उत्पादन करने के लिए विवश किया और इस प्रकार उन्हें अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ने को बाध्य करने के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया।⁴²

भारतीय अर्थनीति के विचारकों ने विदेशी शामकों द्वारा भारतीय उद्योग-धंधों के विनाश के सुविचारित प्रयत्नों की भूमिका पर विचार करते हुए अपने अंतिम विश्लेषण में इस तथ्य को तत्परता से अभिस्वीकार किया कि वाष्पशक्ति और उत्तम मशीनरी पर आधृत उत्पादन कला की श्रेष्ठता के कारण ही ब्रिटिश उत्पादक स्वयं भारत के बाजारों में ही भारतीय कारीगरों के उत्पादन के मुकाबले अपना बढ़िया और सस्ता उत्पादन खपा कर वास्तव में ही भारतीय उद्योग-धंधों को मंडी से बाहर धकेलने में सफल हुए हैं।⁴³ उदाहरणार्थ जस्टिस रानाडे ने इस तथ्य की पुष्टि की कि विदेश प्रतियोगिता विदेशी होने के कारण नहीं, प्रत्युत मानव श्रम के साथ प्राकृतिक शक्ति की प्रतियोगिता, अज्ञान और अकर्मण्यता के साथ सुनियोजित शिल्प कौशल तथा विज्ञान की प्रतियोगिता होने के कारण न केवल संपत्ति पर प्रत्युत उससे भी अधिक उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण दूसरों के कौशल, प्रतिभा तथा गतिविधि पर एकाधिकार को स्थानांतरित कर रही है।⁴⁴ बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं की मान्यता थी कि केवल शिल्प कौशल की श्रेष्ठता से भारतीय हस्तकौशल का

समूल विनाश संभव नहीं था।⁴⁵ वस्तुतः सत्य यह है कि इसमें सहायक तत्व थे, रेलवे के शीघ्र निर्माण के रूप में भारतीय यातायात साधनों का विकास⁴⁶ तथा भारत में उन्मुक्त व्यापार की अनुमति।⁴⁷ ये दोनों तत्व भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के ही राजनीतिक परिणाम थे। इसके अतिरिक्त उनका प्रश्न यह था कि भारत को पराजित करनेवाली इंग्लैंड की द्रुत गति से विकसित शिल्पकला की उत्कृष्टता का आधार क्या था ? उनके विचार में इस देश के तथा अन्य अधीनस्थ देशों के वामियों से अपरिमित धन की लूट से ही ब्रिटेन के मशीन उद्योग का पोषण और विकास संभव हुआ था।⁴⁸ कुल मिलाकर भारतीय नेताओं का यह मत था कि राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग से प्रेरित आर्थिक नियम लागू होने से अतीत में भारतीय शिल्पकला की इंग्लैंड के उद्योगों पर प्रतिष्ठित श्रेष्ठता समाप्त होकर विरोधी को हस्तारित हो गई है।⁴⁹ यह उल्लेखनीय है कि इस युग के जन नेताओं ने ग्रामों के शिल्पों और कलाओं के ह्रास और विस्थापन पर ध्यान देने के बजाय कस्बों के हस्त उद्योग-धंधों के विनाश पर ही⁵⁰ अपना ध्यान केंद्रित किया। इसमें भी उन्होंने न्यूनाधिक रूप में कच्चे माल के निर्यात तथा ग्राम पंचायतों के ह्रास और लोप के फल-स्वरूप भारतीय समाज के उच्च और मध्यवर्ग के लोगों की रुचियों में आए परिवर्तनों के प्रभावों की नज़र न कर दी।

राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी उद्योगों के ह्रास को भारत की दरिद्रता का मूल कारण मानते हुए जनता की भौतिक स्थिति में और अधिक गिरावट को रोकने के लिए तथा देश के आर्थिक पुनर्जागरण के लिए भारतीय हस्त उद्योग-धंधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, पुनर्नियोजन तथा आधुनिकीकरण को स्वाभावतः ही अपने कार्यक्रम का प्रमुख अंग बनाया।⁵¹ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार अपनी घोषणा को दोहराया कि देश में पड़नेवाले अकालों के निवारण की सही औषधि अन्यान्य उपायों के साथ वास्तव में नष्टप्राय स्वदेशी और स्थानीय कलाओं और उद्योगों के विकास को आगे बढ़ानेवाली नीति अपनाना है।⁵² इसके साथ ही भारतीय नेताओं ने यह भी स्पष्ट रूप से अभिस्वीकार किया कि अन्य देशों का अनुभव इस ओर संकेत करता है कि आज के मशीनी यंत्रों तथा विज्ञान उत्पादन के युग में सस्ते प्राकृतिक अभिकरणों द्वारा संचालित उद्योगों के मुकाबले में हस्तसंचालित उद्योग-धंधों के फलने फूलने की संभावना कम ही है।⁵³ इन लक्षणों के बावजूद कुछ एक नेताओं का विश्वास था कि भारतीय हस्तशिल्पों के ह्रास की प्रक्रिया कितनी ही अपरिहार्य क्यों न हो, उसका संशोधन और व्यवस्थापन इस रूप में हो सकता है और अवश्य होना चाहिए कि इससे लोगों को यथासंभव न्यूनतम कष्ट हो। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों में भी अपेक्षाकृत सुविधाजनक प्रक्रिया से बदलना चाहिए।⁵⁴ उनका सरकार पर एक अभियोग यह था कि उसने तकनीकी शक्तियों के प्रवर्तन में संशोधन अथवा नियंत्रण की कोई चेष्टा नहीं की।⁵⁵ इस संबंध में आर्थिक चिंतन की उन्नत गहराई लिए हुई जी० वी० जोशी की टिप्पणियों का विस्तृत पुनर्लेखन समुचित होगा :

...कोई भी समझदार, दूरदर्शी, अपनी सत्ता के प्रति जागरूक तथा दायित्वों को समझने वाली सरकार अपने अधिकृत देश के औद्योगिक गठन में ऐसे विनाशकारी मौलिक परिवर्तनों को उन्हें रोकने के सशक्त उपाय किए बिना कदापि न होने देती।

निस्मदेह हस्त उद्योगों का भाषशक्ति वाले उद्योगों में परिवर्तन सर्वथा अनिवार्य है और इसे किसी भी देश में रोका नहीं जा सकता, परन्तु भारत जैसे पिछड़े और अर्ध-विकसित देशों में स्पष्ट रूप से इन देशों की सरकारों का यह वैधानिक दायित्व है कि वह सामयिक और अस्थायी हस्तक्षेप द्वारा इस परिवर्तन को इस प्रकार से नियन्त्रित करे कि जिससे वह वहाँ के निवासियों के लिए लाभप्रद बन सके।⁵⁵

आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन

प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने आधुनिक उद्योगों की स्थापना और उन्नति पर तो सदैव बल दिया किन्तु आधुनिक उद्योगों के विकास के विरोध में अथवा विकल्प के रूप में हस्त-शिल्प उद्योगों के संरक्षण और पुनरुज्जीवन की इच्छा को कभी मन में स्थान नहीं दिया।⁵⁶ उन्होंने लगभग एक मत से यह स्वीकार किया कि आधुनिक मशीनों द्वारा देश के ग्रंथतंत्र का पूर्णरूप से परिवर्तन उनकी अर्थनीतियों का प्रमुख लक्ष्य तथा देश के सभी आर्थिक रोगों की अचूक औषधि है। भारतीयों द्वारा आधुनिक उद्योगों की स्वीकृति और कालान्त को आधुनिक भारत में उद्योगीकरण के अग्रदूत जस्टिस रानाडे ने अपने देशवासियों को संबोधित निम्नलिखित प्रबोधन में सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार प्रकट किया है हमें सर्वोत्तम शिक्षकों से सीखने के लिए यह ईश्वर द्वारा सुस्थापित व्यावहारिक कार्य है। 'हमें अपने कच्चे माल के स्तर को सुधारना है अथवा हमारी घरेलू की उत्तम स्तर की उत्पादन के अनुकूल न होने पर उसका आयात करना है। हमें सहयोग द्वारा श्रम और पूँजी को संगठित करना है और उन्मुक्त रूप से विदेशी कौशल तथा मशीनरी का तब तक आयात करना है जब तक हम अपने आप भली प्रकार कार्य करना सीख नहीं जाते हैं तथा उनकी सहायता की अपेक्षा छोड़ नहीं देते। हम बहुत अधिक पिछड़ गए हैं, अब हमें नए कामों में हाथ डालना है तथा और अधिक कठोर श्रम के लिए ईमानदारी से कमर कसनी है। यह एक नागरिक गुण है जो हमें सीखना है। यदि हम इस गुण को अपनाते हैं तो युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। इसके विपरीत यदि हम इस गुण की अपेक्षा करते हैं तो पराजय मुह बाएँ खड़ी है ... मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही कठोर श्रम सारे देश का धर्म बन जाएगा तथा प्राचीन भारत में स्थाई रूप से नवीन भावनाओं का बिगुल बजेगा।'⁵⁷

भारतीय नेताओं ने नए उद्योगों की स्थापना की दिशा में उठाए गए प्रत्येक पग का स्वागत किया तथा किसी भी प्रत्यक्ष रूप से यत्नसाध्य क्षेत्र में भारतीयों की निश्चेष्टता पर विलाप किया और उन्हें अपने सभी साधनों को जुटाकर उद्योग तथा व्यापार में प्रवृत्त होने के लिए प्रबोधित किया।⁵⁸ उनका युद्धघोष था : हमें अवश्य ही पूँजीपति तथा उद्यमी बनना चाहिए। अपने देश को व्यापारियों का देश, मशीन बनाने वालों का देश तथा दुकानदारों का देश बनाना चाहिए।⁵⁹ कुछ महानुभावों की दृष्टि में उद्योगीकरण जनता की प्रगति की एकमात्र भले न सही, अत्यधिक महत्वपूर्ण कसौटी अवश्य था।⁶⁰ यह एक-मात्र कसौटी थी जिसके आधार पर देश के आर्थिक विकास की गतिशीलता को देखा-परखा जा सकता।⁶¹

उद्योगीकरण के बहुत से बढ़ते हुए लाभों के कारण भारतीयों की दृष्टि में आधुनिक

उद्योगों पर बल देना सर्वथा न्यायसंगत था, क्योंकि वस्तुतः भारत की आर्थिक कठिनाइयों के मूल कारण अपूर्ण उत्पादन तथा अपूर्ण रोजगार ही थे। दरिद्रता तथा ह्रास के और अधिक विकास को रोकने की सही औषधि राष्ट्रीय संपदा को बढ़ाना तथा लाखों-करोड़ों लोगों को संपन्न बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह सब आधुनिक उद्योगों और उत्पादनों के विकास द्वारा ही संभव था।⁶² इसके अतिरिक्त भारत में अधिकांश जोतने योग्य भूमि को पहले ही जोता जा चुका था और इस प्रकार कृषि विस्तार अपनी सीमा पर पहुंच गया था।⁶³ इस स्थिति में आधुनिक उद्योग एक ऐसा अभिकरण था जिससे भूमि पर आबादी के बढ़ते हुए दबाव को कम किया जा सकता था तथा देश की निरंतर बढ़ती हुई आबादी की देहाती अपूर्ण रोजगारी और बेरोजगारी कम की जा सकती थी और साथ ही आजीविका के वैकल्पिक साधन जुटाए जा सकते थे।⁶⁴ इस प्रकार किसी भी रूप में आजीविका के अनिश्चित और संदिग्ध साधन, कृषि पर एकात निर्भरता को समाप्त करने के लिए तथा देश को और अधिक असम्य बनने से रोकने के लिए देश का उद्योगीकरण आवश्यक था।⁶⁵ उद्योगों के विकास से ही कच्चे माल के निर्यात तथा उत्पादनों के आयात से होने वाली देश की संपदा की निकासी, और श्रम तथा पूँजी की हानि आदि को घटाया जा सकता था।⁶⁶

कुछ एक भारतीय नेता एक अन्य दृष्टि, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की दृष्टि, से भी बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता मानते थे। उनके अनुसार आधुनिक उद्योगों में अधिक संपदा का ही उत्पादन नहीं होगा प्रत्युत उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य उत्पादक शक्तियों का पूर्ण और बहुमुखी विकास भी होगा।⁶⁷ कृषि और उद्योग द्वारा कुल उत्पादित पूँजी की राशि समान होने पर भी कृषि का संकीर्ण और सकुचित क्षेत्र आर्थिक विकास के निम्न स्तर को और इसके विपरीत उद्योग और वाणिज्य का क्षेत्र उन्मुक्त तथा उन्नत विक्रम को सूचित करता है।⁶⁸ इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता था कि औद्योगिकता मभ्यता के उच्च स्तर तथा विशिष्ट आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है।⁶⁹ साथ ही यह देश की संस्कृति, चरित्र और प्रतिभा के विकास और विस्तार में सहायक होती है।⁷⁰ 1890 में रानाडे ने लिखा : स्कूलों और कालेजों की अपेक्षा कारखाने और मिलें अधिक प्रभावशाली ढंग से राष्ट्र की गतिविधियों को जन्म दे सकती हैं।⁷¹ इसके अतिरिक्त संक्षेप में आधुनिक उद्योग ही एक ऐसी शक्ति है जो भारत के विभिन्न लोगों को सामान्य लाभ के आधार पर एक राष्ट्रीय सत्ता के रूप में मंगठित करने में सहायक हो सकती है।

राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों को कुछ समय के लिए एकता के सूत्र में अवश्य बांध सकता है परंतु इन अधिकारों की उपलब्धि पर हितों की समानता समाप्त हो सकती है। इसके विपरीत विभिन्न भारतीय राष्ट्रवादियों का एक बार वाणिज्य संगठन स्थापित हो जाना पर वह कभी अस्तित्वशून्य नहीं हो सकता। अतएव वाणिज्य और उद्योग संबंधी गतिविधि बड़ा सुदृढ़ संगठन है तथा भारत के महान राष्ट्र के निर्माण का एक सशक्त तत्व है।⁷²

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक देश के आधुनिक ढंग से उद्योगीकरण की मांग

को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई थी। समीक्षाधीन काल की अवधि में एक भी ऐसा राष्ट्रवादी समाचारपत्र अथवा लोकनायक नहीं था जिसने भारत में पश्चिमी तकनीक और उद्योग के प्रवर्तन और उन्नयन की वांछनीयता और उपयोगिता पर कभी संदेह किया हो अथवा उन्हें नकारा हो। बड़े पैमाने के पूंजीमूलक उद्योग के विरुद्ध अकेला स्वर कलकत्ता से प्रकाशित 'दि डान' पत्रिका के संपादक सतीशचंद्र मुखर्जी का था। 1905 से पूर्व के वर्षों में तो उनका महत्व अपेक्षाकृत कम था परंतु उसके उपरान्त उन्होंने प्रमुख-तया अपने बहुत सारे प्रसिद्ध शिष्यों के प्रभाव के कारण बंगाल के राजनीतिक जीवन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। संक्षिप्त रूप से इस संबंध में प्रस्तुत उनके विचार दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे। एक ओर वे कुछ रूपों में महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई नीति से मिलते जुलते थे और दूसरी ओर वे निगम पद्धति से मेल खाते थे।⁷³ उनके अनुसार आधुनिक उद्योग पद्धति में दो प्रमुख दोष थे। एक ओर यह पूंजीपतियों के एक छोटे से परंतु सुसंगठित अल्पसंख्यक वर्ग को जन्म देता है और दूसरी ओर यह भयंकर श्रम मंगठनों के रूप में श्रमिकों को इकट्ठा होने की प्रेरणा देता है जो विशेषतया भारत जैसे विशाल देश के लिए निश्चित रूप से एक स्थाई सामाजिक तथा राजनीतिक खतरा बन सकता है। इसके उपचार के लिए उन्होंने दो उपायों का सुझाव दिया। प्रथम, अधिकांश उद्योगों को पारिवारिक हस्तकलाओं के आधार पर संगठित किया जाए तथा बड़े पैमाने के पूंजीमूलक उद्योगों में केवल उन कुछ एक उद्यमों (इंजीनियरी, खान, रेलवे, आदि) को ही विकसित किया जाए जिनकी आवश्यकता समाज के बहुत बड़े वर्गों को व्यक्तिगत रूप में तथा पारिवारिक शिल्पों के लिए रहती है। द्वितीय, सामूहिक नैतिक जीवन का इस प्रकार से संयोजन करना चाहिए कि इसके अंतर्गत सामाजिक जीवनतंत्र में प्रत्येक वर्ग का एक निश्चित, सम्मानित तथा स्वतंत्र स्थान हो। प्रत्येक व्यक्ति पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना से इस प्रकार कार्य करे कि उससे सभी को समान रूप से लाभ मिले, सारे भारतीय समाज का समुक्त रूप में भौतिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक विकास हो।⁷⁴

कुछ एक अन्य भारतीय लेखकों ने भी पश्चिम की प्रतियोगिता और लोलुप प्रवृत्ति वाली औद्योगिक संस्थाओं की आलोचना की। उनके विचार में इन संस्थाओं ने सामाजिक संबंधों को भ्रष्ट करके रख दिया है और मनुष्य को 'अपने द्वारा अपने लिए जीने' पर बाध्य कर दिया है।⁷⁵ 'पूना मार्क्सवादी समाज' के अप्रैल 1893 के अंक में प्रकाशित 'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया' लेख के अज्ञात लेखक द्वारा समकालीन पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवाद पर निहित स्वर में घोषित अभियोग से बड़ा अभियोग किसी भी तत्कालीन अन्य लेखक द्वारा नहीं लगाया गया :

अतीत की सभी कुरताएं मिलकर भी अपनी तीव्रता में जीवन की आवश्यकताओं के असमान वितरण, धन संपत्ति के केंद्रीकरण, श्रम पर पूंजी की वैध दासता, अपर्याप्त आजीविका के कारण दुखों और वेदनाओं, भुखमरी से होने वाली असंख्य मृत्युओं तथा कुंठा और निराशा के कारण हुई अनभिलिखित आत्महत्याओं के रूप में प्रस्तुत दीर्घकाय दुर्भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकती।⁷⁶

इन लेखकों ने पश्चिमी औद्योगिकता के दोषों को जानते हुए भी उसे उसके मूल रूप में भी नकारा नहीं क्योंकि मूलतः वे लेखक पूर्वी जीवनपद्धति की अपेक्षा पश्चिमी जीवन-पद्धति में ही विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त वस्तुतः अब भारत के चाहने या न चाहने की कोई बात ही नहीं रह गई थी क्योंकि अब तक तो वह सांसारिक पूजावादी प्रणाली का एक अंग बन चुका था और अब उसके लिए अलग अलग रहना संभव ही नहीं था। अतएव उस समय अपरिहार्य मार्ग को स्वीकार करना, समय की माग के अनुसार अपने आपको ढालना तथा सभ्यता के बढ़ते कदम के साथ कदम मिलाना ही अधिक उपयुक्त था।⁷⁷

कालक्रम की दृष्टि में भारत में सर्वप्रथम नील चाय तथा काफी बागान के उद्योग ही शुरू हुए। उनका स्वामित्व एकाततः यूरोपीयों का था और वे पूर्णतः आधुनिक मशीनी आविष्कारों पर निर्भर नहीं थे। अतएव भारतीयों का इस ओर विशेष ध्यान ही नहीं गया। भारतीय नेता तो फैक्टरी उद्योग के प्रति दलित रहते और इनकी उन्नति के साथ ही अपना प्रमुख नाता जोड़े रहे। रेलवे का आगमन भारत में आधुनिक मशीनरी के प्रवेश की घोषणा थी और 1850 की अवधि में भारत में सूती कपड़ा, पटसन तथा कोयला खान उद्योग स्थापित हो चुके थे। अंतिम दो औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख रूप से यूरोपीय पूजा के अंतर्गत थे अर्थात् भारतीयों के उद्यम और आशा का केंद्र एकमात्र सूती कपड़ा उद्योग ही था। यही कारण है कि इसे अपने जन्मकाल से ही देश के कारखाना उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। 1879 में देश में 56 सूती मिलें थी और इनमें लगभग 43,000 व्यक्ति काम करते थे। इनमें 75 प्रतिशत कारखाने बंबई प्रांत में स्थित थे। 1882 में केवल 22 पटसन मिलें थी और उनमें से अधिकांश मिलें बंगाल में थी। इनमें लगभग 20,000 व्यक्ति कार्यरत थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1880 तक भारत में आधुनिक उद्योग का विस्तार अत्यंत स्वल्प था, पुनर्गति वह स्वल्प विस्तार भारतीय नेताओं और उद्यमियों के दूरदर्शी वर्ग में आधुनिक उद्योग के प्रति रुचि उत्पन्न करने में तथा उनके प्रलोभन को बढ़ाने में पर्याप्त समर्थ था। 1880 के उपरांत देश में औद्योगिक विस्तार में मंद होने पर भी निरंतरता ग्रहण की और इसके फलस्वरूप 1901-02 में भारत में 1,14,795 व्यक्तियों को सेवारत करनेवाली 36 पटसन मिलें, 1904-05 में 1,96,369 व्यक्तियों को आजीविका देने वाली 206 सूती कपड़ा मिलें और 1906 में लगभग 99,000 लोगों को काम देने वाले कोयला खान आदि उद्योग अस्तित्व में आए। इस अवधि में अपेक्षाकृत कम विस्तार से पनपने वाले अन्य उद्योग थे : रुई बेलन यंत्र, चावल, आटा और इमारती लकड़ी की मिलें, चमड़ा कमाने के कारखाने, ऊनी कपड़े की मिलें, कागज और चीनी मिलें तथा नमक, अभ्रक, शोरा, पेट्रोल तथा लोहा जैसी धातुओं के उद्योग, थोड़ी सी इंजीनियरी और रेलवे कर्मशालाएं तथा लोहे और पीतल की ढलाई करने के कारखाने भी अस्तित्व में आए।⁷⁸ स्पष्ट है कि हमारे अध्ययन के काल की अवधि में भारत में औद्योगिक प्रगति कुल मिलाकर बहुत ही धीमी थी तथा रुई और पटसन उद्योगों तक ही सीमित थी।⁷⁹ अतः यह स्वदेशी हस्तशिल्पों के विस्थापन की क्षतिपूर्ति में भी समर्थ नहीं थी।⁸⁰

यह स्वाभाविक था कि भारतीय नेताओं का ध्यान देश की औद्योगिक प्रगति को

विवक्षित करने वाले कारणों की जांच की ओर तथा साथ ही प्रयोग में लाए जाने वाले उपचारों की खोज की ओर जाता। सर्वप्रथम भारतीय नेताओं ने इंग्लैंड में तथा भारत में सरकारी क्षेत्र में व्यापक रूप से अत्यंत लोकप्रिय इस धारणा का खंडन तथा विरोध किया कि भारत के भाग्य में एक महान औद्योगिक देश बनना नहीं बंदा था और एक उष्ण कटिबंधीय देश होने के नाते उसकी प्राकृतिक भूमिका यूरोपीय देशों के प्राकृतिक तकनीकी और वैज्ञानिक अभिरुचि रखने वाले उत्पादकों के प्रयोग में आनेवाले कच्चे माल के उत्पादन की थी।⁸¹ भारत के अति प्राचीन काल से ही एक अत्यंत उपयुक्त महान उत्पादक देश होने के साक्ष्य में भारतीय नेताओं ने अनेक उत्पादन कलाओं में देश की अतीत की उपलब्धियों का उल्लेख किया।⁸² इसके अतिरिक्त उन्होंने इस तथ्य को स्वतःसिद्ध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि भारत आधुनिक उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल आदि का उत्पादक है और इस प्रकार यह स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक सस्ता उत्पादक देश होने के योग्य है।⁸³ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीयों में किसी भी देश को व्यावसायिक तथा औद्योगिक दृष्टि से महान बनाने में सहायक बहुत सी विशेषताएँ, दूरदर्शिता, प्रतिभा, कौशल, आत्मविश्वास तथा कठोर श्रम की क्षमता विद्यमान है।⁸⁴ फलतः भारतीय नेता कुछ एक अन्य मानवनिर्मित न कि ईश्वरनिर्मित वित्तीय बाधाओं को समुचित सामाजिक प्रयत्नों द्वारा मार्ग से हटा दिए जाने पर भारत के औद्योगिक भविष्य की उज्ज्वलता के संबंध में आशावादी ही नहीं थे, प्रत्युत पूर्ण रूप से विश्वस्त थे।⁸⁵

पूँजी की कमी

राष्ट्रवादी ग्रंथशास्त्रियों के अनुसार भारत के पास भूमि और श्रम की तो प्रचुरता थी, परंतु बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के मार्ग में, औद्योगिक चेष्टाओं के लिए अपेक्षित पूँजी की कमी एक बड़ी भारी अड़चन थी।⁸⁶ रानाडे ने लिखा कि जिस प्रकार भारत की भूमि प्यास से तड़प रही है, उसी प्रकार देश का उद्योग पूँजी के अभाव में झुलस रहा है।⁸⁷ पूँजी के अभाव की समस्या के दो पहलू थे: (क) जमा पूँजी तथा चालू बचत की विरलता।⁸⁸ इसके कारण थे, निकट भूतकाल में शांति और सुरक्षा का अभाव।⁸⁹ भारत की अत्यधिक निर्धनता, जिसके कारण सामान्य बचत असंभव न मही परंतु अति कठिन अवश्य थी।⁹⁰ हिंदुओं की सामाजिक प्रथाएँ तथा धार्मिक मान्यताएँ जिसके अनुसार वे संपदा के संग्रह की अपेक्षा उसके उपविभाजन में ही विश्वास रखते थे।⁹¹ लोगों की जेबें काटने वाले ऊँचे सरकारी कराधान⁹² तथा संपदा की आर्थिक निकासी, जिसके अंतर्गत समाज की मशकत बचतों का बहुत बड़ा भाग विदेशों को चला जा रहा था।⁹³ (ख) आधुनिक उद्योग की देश में उपलब्ध परंतु बिखरे हुए आर्थिक साधनों को संजोने तथा उन्हें गति देने में असफलता।⁹⁴ यह असफलता एक तो बड़े उद्यमों के प्रवर्तन तथा उनमें सफलता प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित पूँजीपतिवर्ग में पारस्परिक विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति के पारस्परिक सहयोग की भावना के तथा नियमित और संगठित रूप से कार्य संचालन की प्रवृत्ति में अभाव का⁹⁵ और दूसरे आधुनिक बैंकों जैसे अपेक्षित पर्याप्त साक्ष संगठनों के अभाव का परिणाम थी, और केवल इन्हीं साधनों के

जरिए असंख्य निवेशकों की छोटी बचतों को पूँजी के अभाव से ग्रस्त आधुनिक उद्योगों की ओर प्रवाहित किया जा सकता था।⁹⁶ बड़े पैमाने के उद्योगों का पूँजी को अपनी ओर न खींच पाने का आंशिक कारण यह भी था कि भारतीय घनाढ्य अनुद्यमी थे और वे किसी प्रकार का खतरा मोल लेने को उद्यत नहीं थे।⁹⁷

भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि संचित पूँजी की राशि रातोंरात नहीं बढ़ाई जा सकती परंतु उनका कथन यह था कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए भारत से होने वाली निकासी को रोककर⁹⁸ तथा भारतीयों में दृढ़तापूर्वक मितव्ययिता से रहने तथा बचत करने की प्रवृत्ति को पनपाकर चालू बचतें बढ़ाई जा सकती हैं।⁹⁹ इसके अतिरिक्त उन्होंने देश के उपलब्ध पूँजी स्रोतों के उपयुक्त उपयोग के लिए भी सुझाव दिए। उन्होंने जमींदारों और राजाओं का, देश के एकमात्र संपन्न व्यक्ति होने के नाते, देश के विकास-शील बड़े पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आने का परामर्श दिया।¹⁰⁰ उन्होंने लोगों से अपने गुप्त सचयों को बाहर निकालने का अनुरोध किया।¹⁰¹ उन्होंने आधुनिक बैंकों, बीमा कंपनियों आदि के माध्यम से उच्च साख मगठन की स्थापना की वकालत की जिसमें धन के छोटे छोंटे, बिखरे हुए निर्जाब कणों को निस्सीम विस्तार के योग्य सुनियोजित तथा मजबूत पूँजी में परिवर्तित किया जाए।¹⁰² उन्होंने सर्वाधिक बल 1854 में देशों में अत्यंत सफल सिद्ध होने वाली 'मिश्रित पूँजी समुदाय' नामक पूँजीवादी संस्था अपनाने के रूप में पारस्परिक विश्वास की प्रवृत्ति के प्रसार पर तथा वैयक्तिक प्रयासों के संयोजन पर दिया।¹⁰³ उन्होंने इस सबंध में दूसरे अभीष्ट उपायों (अगले अध्याय में विवेचित) के रूप में राज्य द्वारा सहायता और प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया।

तकनीकी शिक्षा

औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय बाधक तत्वों में प्रमुख था, भारत में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी। फलतः समीक्षाधीन अवधि में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बार-बार दुहराई गई महत्वपूर्ण मांगों में एक विशेष भाग थी, देश भर में तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए तकनीकी स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं की स्थापना।¹⁰⁴ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की चालू मांग अधिकांशतः उच्च वेतनभोगी विदेशी तकनीशियनों के आयात द्वारा ही पूरी की जाती है। इस प्रकार यह निश्चित दृष्टिकोण बना कि जब तक भारतीयों के अपने ही जनसमुदाय को उत्पादन और व्यापार के प्रत्येक विभाग को सुनियोजित करने, व्यवस्थित करने तथा निपुणता और सस्ती घरेलू कुशलता के साथ संचालित करने की दिशा में प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक बड़े पैमाने के उद्योग देश में कभी जड़ नहीं जमा सकते।¹⁰⁵ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1887 में अपने तृतीय अधिवेशन में तकनीकी शिक्षा के मामले को उठाया और मांग की कि सरकार को जनता की दरिद्रता को नजर में रखते हुए तकनीकी शिक्षा पद्धति के समुचित विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।¹⁰⁶ अपने अगले अधिवेशन में 1888 में कांग्रेस ने अन्यान्य वस्तुओं में सामान्य तकनीकी शिक्षा पद्धति लागू करने के प्रारंभिक कदम के रूप में देश की औद्योगिक

गिक स्थिति की जांच के लिए एक मिलेजुले आयोग की नियुक्ति का आग्रह किया।¹⁰⁷ 1891, 1892 और 1893 में उसने अपना अनुरोध दोहराया।¹⁰⁸ 1894 में उसने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना के औचित्य का प्रतिपादन किया।¹⁰⁹ कांग्रेस ने तदुपरांत प्रायः हर वर्ष अपनी इस मांग को दोहराया। 1904 में उसने देश में कम से कम एक पूर्णतः उपस्कृत केंद्रीय पालीटेक्निक संस्था की और विभिन्न प्रांतों में छोटे बड़े स्कूलों और कालेजों की स्थापना की वकालत की।¹¹⁰ इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में आविष्कृत तकनीकी शिक्षा पद्धति को आंशिक रूप से यूरोप महाद्वीप में और विशेष रूप से जर्मनी, अमरीका और जापान में बड़े पैमाने के उद्योगों की उन्नति में उपलब्ध उल्लेखनीय तथा स्पष्ट सफलता से भी भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धति की मांग को प्रोत्साहन मिला।¹¹¹

भारतीय नेता विश्वस्त थे कि तकनीकी सवर्ग के बारे में आधुनिक उद्योग की मांग की पूर्ति की दिशा में तब तक अग्रगति नहीं हो सकती जब तक कि सरकार स्वयं इस दिशा में उपक्रम न करे और देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार का बोझ अपने कंधे पर न ले।¹¹² कुछ एक नेताओं ने स्थानीय मंडलों तथा नगरपालिकाओं से अपने अपने क्षेत्रों में तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना के लिए अपनी धनराशि के कुछ भाग को समर्पित करने का प्रस्ताव किया।¹¹³ इस प्रकार उनका विचार था कि धन के अभाव के कारण तकनीकी शिक्षा को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यद्यपि वे सामान्यतः मित-व्ययी प्रवृत्ति के थे परंतु इस विषय में उन्होंने सरकार को इस क्षेत्र में आवश्यक धनराशि, वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, व्यय करने का परमर्श दिया।¹¹⁴ उनके अनुसार भारतीय युवकों द्वारा तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह के अभाव का प्रमुख कारण देश के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का अभाव था।¹¹⁵ अतएव सरकार से अनुरोध किया गया कि वह तकनीकी शिक्षा पानेवालों के लिए कार्य जुटाए और विशेषतः भारतीयों को सार्वजनिक निर्माण जंगल, तार विभागों और रेलवे में ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित करे।¹¹⁶ सरकार से बहुत अपेक्षा की गई थी और आशा के विपरीत सरकार का वास्तविक योगदान देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के विकास में वर्षों तक निराशाजनक रहा, अतः भारतीयों ने आगामी वर्षों में सरकार की तीव्र भर्त्सना की।¹¹⁷

भारतीय नेताओं ने जहां एक ओर देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार को सरकार का दायित्व बतलाया, वहां दूसरी ओर भारतीय जनता के खुद अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सामान्य रूप से सारी जनता से और विशेष रूप से शिक्षित वर्ग, लक्षपतियों, जमींदारों और रियासतों के शासकों से तकनीकी स्कूलों और कालेजों के खोलने के लिए तथा भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने के लिए सहाय-तार्थ छात्रवृत्तियों के निमित्त उदारतापूर्वक धन प्रदान करने का अनुरोध किया।¹¹⁸ 1876 में कलकत्ता की इंडिया लीग ने एक तकनीकी संस्था की स्थापना के रूप में अपने ही संस्था-धर्मों से तकनीकी शिक्षा प्रसार के आंदोलन को गति देने का प्रयत्न किया।¹¹⁹ 1899 में जब जे० एन० टाटा ने देश में उच्च वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान की उन्नति के लिए 30

लाख रुपयों का दान दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनके इस देश-भक्तिपूर्ण तथा उदार उपहार के प्रति कृतज्ञतापूर्ण प्रशंसा की अभिव्यक्ति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।¹²⁰ 1904 में कलकत्ता में के० सी० बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ए० एम० बोस तथा अन्य गण्यमान्य नेताओं के नेतृत्व में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की प्रगति के लिए एक संस्था का संगठन आत्मसहायता की दिशा में कदाचित्त एक सर्वाधिक सफल उदाहरण था। संस्था ने छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजने, भारतीय विशेषज्ञों को विदेशों से भारत लौटने में सहायता देने, नए उद्योगों को प्रारंभ करने तथा कलकत्ता की सेंट्रल लाइब्रेरी को संपन्न बनाने और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक लाख रुपया प्रतिवर्ष उगाहने का निश्चय किया। संस्था का वार्षिक न्यूनतम सदस्यता शुल्क चार आना निर्धारित किया गया।¹²¹

भारतीय नेताओं का ध्यान नई खुली तकनीकी संस्थाओं में दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा की प्रकृति की ओर भी गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारत में केवल चार इंजीनियरी कालेज थे जिनसे निकलनेवाले स्नातक विभिन्न सरकारी विभागों में खप जाते थे। कलकत्ता, मद्रास, बंबई और लाहौर के कला विद्यालयों में भी औद्योगिक अनुभाग थे। परंतु ये अनुभाग रई बुनने, मिट्टी के बरतन बनाने, नक्काशी करने, मीनाकारी करने, लकड़ी पर खूद करने, सोने-चादी तथा अन्य धातुओं के गहने बनाने के काम जैसे शिल्पों में ही प्रशिक्षण देने तक सीमित थे। 1902 में देश में औद्योगिक संस्थानों की संख्या बढ़कर 123 हो गई, परंतु इन सब संस्थानों में सामान्यतया प्रशिक्षण के विषय थे तक्षक कला, धातु कला, चर्म कला तथा सिलाई कला।¹²² राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे बहुत बुरा माना और सरकार की तकनीकी शिक्षा को अधिकांशतः तक्षक, लोहार और सुनार जैसे हस्त-कलाकारों की कार्य शैली में सुधार तक सीमित रखने की नीति की घोर भर्त्सना की।¹²³ उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया कि भारत के पास प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों का पहले से ही बड़ा भंडार है। देश को तो इस समय आधुनिक इंजीनियरों की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य नष्टप्राय अथवा विनाशोन्मुख उद्योगों को पुनर्जीवित करना नहीं, प्रत्युत बाहर से मंगाई जानेवाली सामग्री का उत्पादन करने वाले बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना करना है।¹²⁴ अतः इस शिक्षा में भारतीयों को आधुनिक मशीनों और मशीनी औजारों की चरम विकसित तकनीकी की सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी से पूर्ण परिचित कराने और उन्हें नए उद्योगों के संचालन में सहायता देने की सामर्थ्य होनी चाहिए।¹²⁵ यही कारण था कि भारतीयों ने जहां तकनीकी संबन्ध में विदेशी शिक्षण और प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया,¹²⁶ वहां देश में अत्युन्नत तकनीकी शिक्षा देनेवाले ऊंचे स्तर के संस्थान खोलने का भी दृढ़ता से समर्थन किया।¹²⁷

उद्यम की भावना

कुछ-एक भारतीय नेताओं के अनुसार देश के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण देश-वासियों में उपक्रम और उद्यम संबंधी अपेक्षित भावना का अभाव था।¹²⁸ 1825 में जी०बी० जोशी ने अत्यंत दुःख से कहा कि भारतीयों में व्यक्तिगत, स्वतंत्र तथा आत्म-

विश्वासपूर्ण उपक्रम के लिए आवश्यक कर्मशक्ति का अभाव शोचनीय है।¹²⁹ कुछ एक अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार भारतीयों में निम्नलिखित अन्य गुणों की कमी थी : पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास की भावना, जांच-पड़ताल की प्रवृत्ति, विचारों और कार्य व्यापार में स्वतंत्रता, साहस तथा आत्मविश्वास, संकल्प, साहस तथा दृढ़ निश्चय,¹³⁰ अतिरिक्त विरोध का मुकाबला करने और उस पर विजय पाने की तत्परता।¹³¹ नेताओं की दृष्टि में इन गुणों के अभाव का कारण राष्ट्रीय चरित्र की परंपरागत दुर्बलता नहीं थी अपितु देश में प्रचलित सामाजिक प्रथाएं, रीति-रिवाज तथा परंपराएं ही प्रमुख रूप से सामान्यतः भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए और विशेषतः भारतीयों में उद्यमी भावना के अभाव के लिए उत्तरदायी थी। भारत की जाति प्रथा एक ओर श्रम और पूँजी की गतिशीलता में बाधक थी और दूसरी ओर उच्चकुलीन प्रतिभाशाली नवयुवकों के तकनीक और उद्योग क्षेत्र में आने के मार्ग में एक बाधा थी, इसके फलस्वरूप उच्च प्रतिभा उच्च कौशल से विच्छिन्न हो गई थी।¹³² विदेश यात्रा पर प्रतिबन्धों ने भारतीय व्यापार के विदेशों में प्रसार को सकुचित कर दिया था।¹³³ भारतीय धार्मिक आदर्श एक ओर सतोष का प्रचार करते थे और दूसरी ओर धन के प्रति उत्कट प्रवृत्ति की निंदा करते थे। इसके फलस्वरूप भारतीयों की भौतिक सफलता की महत्वाकांक्षा दब गई थी तथा सामाजिक संपत्ति में वृद्धि का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन ठंडा पड़ गया था।¹³⁴ भारत में पूरी तरह निराशावाद व्याप्त था। यहाँ यह धारणा प्रचलित थी कि मानव जीवन का दुर्भाग्य पूर्वनिर्दिष्ट है तथा मानव की दशा को बेहतर बनाने के सभी प्रयत्नों की असफलता निश्चित है।¹³⁵ भारतीय रीति-रिवाजों तथा आचार-व्यवहारों के अनुसार भारतीयों का निवृत्ति, अकर्मण्यता, विश्रुति, उदासीनता तथा निरुद्योगिता का जीवन ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए आदर्श जीवन था।¹³⁶ भारतीय न प्राप्त होने वाली वस्तु की निरंतर खोज में विचारों व स्वप्नों की दुनिया में खोए रहते थे।¹³⁷ परंतु आधुनिक औद्योगिक सभ्यता पूर्णतः व्यापारिक थी।¹³⁸ अतः, भारतीयों की व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष की धारणा व जातपात की भावना उस समय भारत में सामाजिक चेतना के अभाव का कारण बनी।¹³⁹

जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में भारतीय समाजसुधारकों ने भारत में आधुनिक उद्योग तथा व्यापार के स्वस्थ विकास के लिए भारतीय सामाजिक रूढ़ियों में मूलभूत परिवर्तन का प्रचार किया।¹⁴⁰ रानाडे का कथन था 'सामाजिक व्यवस्था के दूषित होने पर उत्तम आर्थिक पद्धति के प्रवर्तन की आशा नहीं की जा सकती।'¹⁴¹ अतः सुधारकों ने लोगों से रीति-रिवाजों तथा परंपराओं के अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव से मुक्ति पाने तथा पश्चिम की नई प्रवृत्ति को अपनाने और नए दृष्टिकोण, पूँजीवादी प्रवृत्ति को मन में स्थान देने का अनुरोध किया।¹⁴² उन्होंने निम्नलिखित आधुनिक धारणाओं को प्रशंसनीय और स्पृहणीय घोषित किया : प्रगति तथा विज्ञान, विचार और कर्म की स्वतंत्रता, परिवर्तन तथा साहसिक कार्यों में रुचि, मन की आशावादिता तथा व्यावहारिकता, जीवन स्तर में सुधार की इच्छा, आदि आदि।¹⁴³ भारतीय नेताओं में अपेक्षाकृत पुरातनपंथी नेता कुछ एक सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को तो अनुभव करते थे परंतु हिंदुओं के आचार-

विचारों तथा नैतिक व्यवहारों में किसी प्रकार की क्रांति की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार भारत की सामाजिक संस्थाएं और परंपराएं अपने मूल रूप में उद्योगीकरण के सर्वथा अनुरूप थी। उनके अनुसार निस्संदेह आधुनिक व्यापार और उद्योग को बढ़ाने वाली इच्छा और व्यापार की कुछ एक प्रवृत्तियों को विकसित करने की आवश्यकता थी परंतु इस संबंध में उनका विश्वास था कि ये गुण हिंदुओं में अतीत काल में विद्यमान थे और सामाजिक और धार्मिक पतन के कारण अंतरिम अवधि में वे नष्ट हो गए थे। इसका उपचार अपने प्राचीन अतीत की ओर लौटना था, न कि पश्चिम के आगे भोली फैलाना।¹⁴⁰ जाति प्रथा की समस्या के प्रति उनका रवैया इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने एक ओर वेदों में प्रतिपादित चातुर्वर्ण्यव्यवस्था और व्यवहार की प्रशंसा की तथा दूसरी ओर आधुनिक काल में प्रचलित हजारों उपजातियों तथा छुआछूत की प्रवृत्ति की निंदा की।¹⁴¹

यह उल्लेखनीय है कि समीक्षाधीन काल की अवधि में राष्ट्रीय, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में उदीयमान आधुनिक उद्योग के साथ सामंजस्य लाने के लिए भारतीय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के प्रश्न को प्रमुखता नहीं मिल पाई। उस समय विदेशी शासकों के विरुद्ध राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष में संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता को ही अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम पचीस वर्षों में धर्म और संस्कृति के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के पुनः उद्गम की बाढ़ सी आ गई। जब इमे शासकों के वनीय रवैये का सामना करना पड़ा तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ा और उसने पश्चिमी पूँजीवादी सभ्यता के मानव की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रत्यक्ष असफलता की ओर मकन किया। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में समाजसुधार का काम गीछे पड़ गया। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुभव ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि पूँजीवादी उद्यम की भावना तथा उन्नत सामाजिक दृष्टिकोण के बीच किसी प्रकार का सहज अथवा स्वाभाविक संबंध नहीं। इसका प्रमाण यह था कि उदीयमान पूँजीवादी उद्यमी सामाजिक दृष्टि से दकियानूसी वर्गों, मारवाड़ी, जैन, भाटिया, चेटियार, खोजा, मेमन और बोहरा वर्ग के लोग थे, न कि बंगाल के प्रगतिशील ब्रह्मसमाजी अथवा पूना, बंबई या मद्रास के सामाजिक दृष्टि से उदार लोग। समय बीतने के साथ साथ संभवतः यह तथ्य भी स्पष्ट होता गया कि पूँजीवादी उद्यम की भावना के अभाव का कारण वस्तुतः औद्योगिक पूँजीवाद की अनुपस्थिति था, न कि कोई अन्य कारण।

बहुत से प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने देश में उद्यम संबंधी प्रवृत्ति के क्षेत्र की रिक्तता को व्यक्तिगत चेष्टा और उदाहरण से भरने का प्रयास किया। वे लोग आधुनिक उद्योगों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, व्यापार सदनों आदि की स्थापना के आंदोलन के प्रारंभिक पुरोगामियों में थे।^{146A} उदाहरणार्थ, 1855 में दादाभाई नौरोजी 'कामास' नामक व्यापार संस्था के भागीदार बन गए। यह लंदन में स्थापित होने वाला प्रथम भारतीय व्यापार-सदन था और 1869 में उन्होंने 'दादाभाई नौरोजी एंड कंपनी' के नाम से अपना व्यवसाय

चालू कर दिया।¹⁴⁷ रानाडे ने पूना में स्थापित 'काटन एंड सिल्क स्पिनिंग एंड वीविंग फैक्टरी', 'मैटल मैनुफैक्चरिंग फैक्टरी', 'दि पूना मकेंटाइल बैंक', 'दि पूना डाइंग कम्पनी', 'दी रिएं पेपर मिल' आदि के प्रवर्तन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।¹⁴⁸ गोखले के अनुसार : 'पिछले 20 वर्षों में पूना में उदित औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों में अधिकांश उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन, परामर्श तथा सहायता के लिए उनके आभारी हैं।'¹⁴⁹ भारत की कलाओं और उद्योगों की उन्नति के लिए नवोत्पन्न उत्साह से संपन्न यत्नशील व्यक्तियों में के०टी० तैलंग और फीरोजशाह मेहता ने तो 1870 में बंबई में एक साबुन का कारखाना ही खोल दिया।¹⁵⁰ वास्तव में फीरोजशाह मेहता का भारत के मिल उद्योग से घनिष्ठ संबंध था।¹⁵¹ तिलक ने भी थोड़े समय के लिए ही सही, 1891 में अपने दो मित्रों की साझेदारी में निजाम के अधीनस्थ प्रदेश लातूर में रुई से बिनोला निकालने वाला कारखाना चालू करने के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में अपने उत्साह का परिचय दिया।¹⁵² डी०ई० वाचा बड़े पैमाने की फूलती-फलती मोरारजी गोकुलदास और शोलापुर मिलों के प्रबंधक अभिकर्ता थे। वे बहुत वर्षों तक बंबई के मिलमालिक संघ की प्रबंध समिति के सदस्य रहे।¹⁵³ 19वीं शताब्दी के प्रमुख कांग्रेसी नेता आर०एन० मधोलकर बरार में आधुनिक उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वालों में एक थे। 1881-82 में उन्होंने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से बरार के प्रथम मिश्रित पृजी समुदाय बरार ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की तथा उसके सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में 1885 में उन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से बरार में प्रथम कपड़ा बुनने की मिल की स्थापना की। इसके अतिरिक्त एक तेल निकालने की मिल और रुई बिनने तथा सपीडन के अनेक कारखानों की स्थापना का पर्याप्त श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है।¹⁵⁴ कांग्रेस के एक अन्य बड़े नेता मदनमोहन मानवीय ने 1881 में इलाहबाद में 'देसी तिजारत कंपनी' की स्थापना में सहायता दी और कालांतर में प्रयाग में चीनी मिल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।¹⁵⁵ विस्तृत व्यापारों से संबंधित लाला लाजपतराय एक अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने एक प्रारंभिक भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक की हैसियत से अनेक रुई मिलों और रुई प्रेसों की स्थापना में सहायता की। वे कई निदेशक मंडलों के सदस्य थे।¹⁵⁶ बंगाल के राष्ट्रवादी नेता औद्योगिक क्षेत्र में इतने सक्रिय नहीं थे जितने पश्चिमी और उत्तरी भारत के नेता थे। किंतु वहा भी ए० एम० बोस, दुर्गामोहनदास और भुवनमोहन दास जैसे अन्य दो महानुभाव व्यक्तियों के साथ मिलकर 1880 में 'बंगाल बैंकिंग निगम' व्यावसायिक संघ की स्थापना की।¹⁵⁷ इसके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ए०एम० बोस तथा नरेंद्रनाथ सेन ने बंगाल में अपने वाणिज्यपरक प्रयासों से बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अवैतनिक सदस्य बनते हुए नाममात्र रूप से ही सही, अपने को उससे संबंधित रखा।¹⁵⁸

पूजी के आंतरिक साधनों और साहसवृत्ति का उपयोग करते हुए देश के उद्योगीकरण की अदम्य राष्ट्रीय आकांक्षा का एक रोचक उदाहरण है 'पैसा निधि'। रानीगंज (बंगाल) के तारापद मुकुर्जी ने 1865 में इंडियन मिरर में इस पैसा निधि के उद्देश्य, निर्धन और अशिक्षित लोगों की वृद्धि का उपयोग तथा नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय

अनुदान को स्पष्ट किया है। इस योजना को कुछ तत्कालीन नेताओं का समर्थन भी मिला। 1873 में बंबई के जी० वी० जोशी ने 'जनता पाई निधि' चालू करने का प्रयत्न किया परंतु वह केवल 150 रुपये उगाहने में ही सफल हो सके। 1899 में इस विचार से एक युवक अध्यापक ए० डी० काले इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा 'पैसा निधि' के लिए धन संग्रह का काम प्रारंभ कर दिया। इस निधि में प्रत्येक व्यक्ति से प्रति वर्ष केवल एक पैसा देने की अपेक्षा की जाती थी और यह संचित निधि आधुनिक उद्योग को प्रतिष्ठित करने और उसे लोकप्रिय बनाने में प्रयुक्त होती थी। साहसिक कार्य में काले को तिलक तथा अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं से प्रोत्साहन तथा समर्थन मिला। काले के अनुराग और श्रम को शीघ्र ही सफलता मिली और 1908 में इस 'पैसा निधि' की सहायता से महाराष्ट्र के तिलंगाना प्रदेश में शीशे का कारखाना (प्रशिक्षण केंद्र सहित) स्थापित किया गया।¹⁵⁹

भारतीय नेताओं ने औद्योगिक संघ बनाए, औद्योगिक सम्मेलनों का आयोजन किया तथा औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाईं। इन सबका उद्देश्य था औद्योगिकता के मिथान को आगे बढ़ाना, औद्योगिक और वाणिज्य संबंधी रुचि जागृत करना, उद्यम की भावना को उभारना, विश्वासपूर्ण तथा आशाजनक औद्योगिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विकसित औद्योगिक तत्त्वों का जनता में प्रसार करना, विभिन्न उद्योगों के अवसर और अवकाश के संबंध में उपयुक्त जानकारी देना, आदि।¹⁶⁰ इस दिशा में पथप्रदर्शक कार्य रानाडे महोदय का है जो 1890 में बने पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ के तथा उसी वर्ष पूना में प्रथम बार आयोजित होने वाले औद्योगिक सम्मेलन के प्रधान सयोजक थे। इसमें पूर्व में उस नगर में एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन भी कर चुके थे।¹⁶¹ उनकी इन सभी गतिविधियों में जी० वी० जोशी तथा महाराष्ट्र के एम० बी० नामजोशी आदि अन्य नेताओं ने भी महायत्ना की। 1890 से आगे के कई वर्षों तक प्रतिवर्ष औद्योगिक सम्मेलन आयोजित होते रहे तथा इन्होंने भारतीय औद्योगिक और आर्थिक समस्याओं पर विधि-पूर्वक तथा क्रमानुसार विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में इस दिशा में बहुत बड़ी सेवा की। वस्तुतः रानाडे तथा जोशी के भारतीय आर्थिक समस्याओं पर लिखे बहुत सारे सुप्रसिद्ध निबंध इन सम्मेलनों में पढ़ने के लिए लिखे गए परचे ही थे। पूना के अनुसरण में अक्टूबर 1891 में कलकत्ता में भी एक सम्मेलन हुआ।¹⁶² परंतु दुर्भाग्यवश यह सम्मेलन अपना विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया। निश्चय ही कलकत्ता को औद्योगिक प्रदर्शनियों के आयोजन में अधिक सफलता मिली। इस दिशा में प्रथम साधारण प्रयास जे० चौधरी तथा अन्य लोगों द्वारा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1890 में एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन था।¹⁶³ परंतु यह प्रयास अकेला ही सिद्ध हुआ, परवर्ती अधिवेशनों में यह परंपरा का रूप धारण न कर सका। 1900 में कांग्रेस ने अपने लाहौर के 16वें अधिवेशन में विधिवत इस मामले को उठाया और उसने औद्योगिक समस्याओं पर विचार करने के लिए कम से कम आधा दिन लगाने का निर्णय किया। उसने देश की औद्योगिक गति-विधि की प्रगति में कांग्रेस के संभावित सहयोग के रूप और दिशाओं पर विचार करने के लिए एक औद्योगिक समिति का बठन भी किया।¹⁶⁴ इस समिति के विचार-विवेचन के

फलस्वरूप ही 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस के अग के रूप में औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई¹⁶⁶ और उसके उपरांत यह कांग्रेस अधिवेशन की एक अविभाज्य परंपरा बन गई।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का यह भी मत था कि द्रुत उद्योगीकरण के भारतीय प्रत्यनों के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा सरकार की उन्मुक्त व्यापार की नीति थी। यह नीति देश के प्रारंभिक तथा अविकसित उद्योगों को, पश्चिम के ऊँचे स्तर पर सुनियोजित तथा सुविकसित उद्योगों के साथ, अपरिपक्व और असमान होने के कारण अनुचित प्रतियोगिता के लिए बाध्य करती थी। भारतीयों के इस दृष्टिकोण का तथा भारत सरकार की उन्मुक्त व्यापार नीति को लागू करने के विभिन्न उपायों के विरुद्ध उनके संघर्ष का इस पुस्तक के अगले अध्यायों में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भ

- 1 भारतीय हस्तकलाओं के विनाश का विवरण भारतीय अर्थशास्त्र की अनन्त पुस्तकों में उपलब्ध है सरल निर्देश के लिए देखिए, डी० आर० गाडगिल 'दि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इंडिया इन रीमेंट टाइम्स' (कलकत्ता, 1942 में चतुर्थ संस्करण का पुन मुद्रण) अध्याय III और XII आर० चौधरी 'दि इवोल्यूशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज' (कलकत्ता 1939) अध्याय I तथा बी० डी० बसु 'दि रुइन आफ इंडियन ट्रेड्स इंडस्ट्रीज' (कलकत्ता, 1935)
- 2 बेरा अनस्टे 'दि इकानामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' (लंदन, तृतीय संस्करण), पृ० 5
- 3 गाडगिल पूर्वोद्धृत, अध्याय III और XII, पृ० XXII, अनस्टे पूर्वोद्धृत, पृ० 5, 207
- 4 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषित किया कि भारत की बोर दरिद्रता के प्रमुख कारणों में एक था स्वदेशी शिल्प और उद्योग का ह्रास (प्रस्ताव III) जोशी का 1885 में कथन था तभी से बढ़ता हुआ विनाश, जिसे हम अपने विभिन्न हस्तशिल्प उद्योगों का सहसा पूर्णक्षय कह सकते हैं, वस्तुओं की शोचनीय स्थिति का मूल कारण है (पूर्वोद्धृत, पृ० 738) 1896 की कांग्रेस को संबोधित करते हुए आर० एन० मधोलकर ने सकेत किया, हमारी घनघोर और व्यापक दरिद्रता हमारे प्राचीन कला-शिल्पों तथा उद्योगों के ह्रास, लक्ष्मण पूर्ण विनाश का ही परिणाम है (रिप० आई० एन० सी० 1896, पृ० 157) भोलानाथ चट्ट ने 1876 में लिखा था नवीन प्रचलित शिल्पों और उद्योगों में किए गए सुधारों की अपेक्षा पुराने शिल्पों-उद्योगों पर किए गए प्रहार अधिक विचारणीय हैं वस्तुतः यह तो हमारे राष्ट्र के लिए करोड़ों गवाकर हजारों पाने के समान एक क्षुद्र सात्वना है (एम० एम० खड V, पृ० 5) उस युवक के राष्ट्रीय भाषणों और लेखों में इस प्रकार के असंख्य निर्देश उपलब्ध हैं उदाहरणार्थ देखिए, ऐजुकेशन गजट, 2 मई (आर० एन० पी० बग, 10 मई 1883) जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 632, 753, 778-79, 802-4 चार दत्त 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग 14 फरवरी 1885) वाचा रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 64, बर्देवान सजीवनो, 29 नवंबर, (वही, 10 दिस० 1887) जोश काविर बख्श रिप० आई० एन० सी० 1887, पृ० 142 पंजाबी अखबार, 21 अगस्त (आर० एन० पी०, 31 अगस्त 1889) खैर घदेश, 13 अक्तूबर (वही, 19 अक्तूबर 1889) राम 'पावर्टी', पृ० 85 निजामुलमुल्क, 16 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 20 जनवरी 1897) प्लरुत जीवन 20 नवंबर (वही, 1 दिसंबर 1897) नदी : पूर्वोक्त स्थल, पृ० 122 दत्त : सी०

- पी० ए, पृ० 489. वृतांत चिंतामणि, 15 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 15 मार्च 1900), हिंदुस्तान, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एन, 17 अप्रैल 1900) स्वदेशमित्र, 28 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 20 अप्रैल 1900) केसरी, 8 मई (आर० एन० पी० वब 12 मई 1900) मराठा, 11 नवंबर 1900, मद्रास स्टैंडर्ड, 21 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 25 जनवरी 1902), आई० एन० सी० 1902 और 1904 के प्रस्ताव III और III. एन० के० रामास्वामी अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 137. एम० के० पटेल रिप० आई० एन० सी०—1902, पृ० 77. जी० सी० अय्यर : ई ए, पृ० 218, 249. गोखले : स्पीचेज, पृ० 52. दत्त : ई० एच० II, पृ० 345 और, सी० पी० ए०, पृ० 469. बंगाली, 12 मार्च, 1902.
5. उदाहरण के रूप में देखिए, ए० बी० पी०, 5 अगस्त 1872 भोलानाथ चट्ट : एम० एम० खंड V (1876) पृ० 5. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 227, 780 गोखले : स्पीचेज, पृ० 52 आर० मो० दत्त ने अपनी दो खंडों वाली 'इकानामिक हिस्टरी आफ इंडिया' पुस्तक में तथा अनेक सम-कालीन पत्रों में प्रकाशित अपने लेखों में इस प्रक्रिया का बड़ा गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है. पो० री० राय ने भी अपनी पुस्तक 'दि पावर्टी प्रॉब्लम आफ इंडिया' में इन प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन किया है.
6. दत्त : स्पीचेज, II पृ० 106. नदी . पूर्वोक्त स्थल, 122. एस० एन० बैंबर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 691-2 जी० सी० अय्यर : ई ए, अध्याय XVI और XVII.
7. दत्त : ई० एच० I, पृ० 256.
8. भारत से इंग्लैंड को कपास के गट्टों के निर्यात-आकड़ों के लिए देखिए, दत्त : ई० एच० I, पृ० 295, ई० एच० II, पृ० 109. भारत में कपड़ों के आयात आंकड़ों के लिए देखिए, दत्त : ई० एच० I, पृ० 257, ई० एच० II, पृ० 108. तथा देखिए, एस० एन० बैंबर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 692-3.
9. रानाडे : एसेज, पृ० 185.
10. दत्त : 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 128.
11. दत्त : ई० एच० I, पृ० VII, VIII और देखिए के० सी० ए० चौधरी : रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 64. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 785. रानाडे : एसेज, पृ० 185 राय : पावर्टी, पृ० 93. मधोलकर : रिप० आई० एन० सी०—1898, पृ० 121. दत्त : ई० एच० I, पृ० VIII. गोखले : स्पीचेज, पृ० 52
12. रानाडे : एसेज, पृ० 27. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 784-5. दत्त : ई० एच० II, पृ० 103, 345. स्पीचेज II, पृ० 81. गोखले : स्पीचेज, पृ० 52.
13. आर० एन० मधोलकर : रिप० आई० एन० सी०—1890, पृ० 47. जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 785, 835. दत्त : 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 129. ई० एच० II, पृ० 345, बंगाली 12 मार्च 1902.
14. रानाडे : एसेज, पृ० 191, वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 624. दत्त : ई एच I, पृ० VIII ई० एच० II, पृ० VIII एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी०, 1902, पृ० 77. दत्त आदि के समान रानाडे ने भी यह अभिस्वीकार नहीं किया कि भारत प्राचीनतम काल से पूर्ण रूप से तथा एकांततः कृषि-प्रधान देश रहा है उन्होंने यह अवश्य कहा कि ब्रिटिश राज्य ने स्थिति की गंभीरता को और अधिक भयंकर बनाया है.—(एसेज, पृ० 183) साथ ही देखिए ट्रिब्यून (साहौर) 8 जुलाई (आई० एन० बी० ओ० आई०, 2 अगस्त, 1891)
15. दत्त ने संगणना की कि 80 प्रतिशत भारतीय जनता कृषि पर निर्भर है (ई० एच० I, पृ० IX)

- जोशी का अनुमान था कि लगभग 86 प्रतिशत औद्योगिक जनता भूमि से संबंधित थी (पूर्वोद्धृत, पृ० 784) और देखिए, बाचा : सी० पी० ए०, पृ० 624 एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 77.
- 16 रानाडे : एसेज, पृ० 26, 183 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 360 मघोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 44, केसरी, 11 नवंबर (आर० एन० पी० बग, 15 नवंबर 1902)
- 17 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 849-50, 868, मघोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 45.
- 18 दत्त : स्पीचेज I, पृ० 24 तथा देखिए, मराठा, 19 जून, 1881, 12 फरवरी 1882 सोमप्रकाश, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 11 फरवरी 1882) ए०बी०पी०, 22 मई, 1884, भारत मिहिर 17 जून (आर० एन० पी० बग 28 जून 1884) स्वदेश मित्रन, 5 मार्च (आर० एन० पी० एन०, मार्च 1885) रानाडे . एसेज, पृ० 27 राय . पावर्टी, पृ० 97 केसरी, 11 नवंबर (आर० एन० पी० बग 17 नवंबर 1902) एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 69
- 19 1880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन, भाग II, कठिका I इस अवतरण को अन्यो के अतिरिक्त रानाडे ने उद्धृत किया था, एसेज, पृ० 121 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 642 मघोलकर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 44 रिप० आई० एन० सी०—1899, पृ० 88-9
- 20 बी० सी० पाल : रिप० आई० एन० सी०—1888, पृ० 159 मघोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 47
- 21 रानाडे एसेज, पृ० 66, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 871, 874 ए० बी० पी०, 2 अगस्त 1901 मघोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 45 जी० सी० अय्यर, ई ए, पृ० 218
- 22 मराठा, 23 जनवरी 1881, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 700-2, 804, 840-52
- 23 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 702 इस विषय में उनके प्रश्न को 1880 के अकाल आयोग के प्रतिवेदन में पृ० 853 पर देखिए
24. वही, पृ० 350, 658
- 25 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 658 तथा जी० सी० अय्यर ई ए, अध्याय XII
- 26 रानाडे एसेज, पृ० 27
- 27 रानाडे एसेज, पृ० 90 तथा वही, पृ० 183, 185 हिंदू—16 जनवरी 1883 जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 675-76 मोखले स्पीचेज, पृ० 52 'इंडियन पीपल', 27 फरवरी 1903. दत्त स्पीचेज II, पृ० 42-3 ई० एच० पृ० VIII, 276 ई० एच० II, पृ० 114, 129, 518 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 116-7, 123-5 1873 में भोलानाथ चट्ट ने राजनीतिक दामता के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में भी दासता के गढ़ने में धकेलने वाली नीति की निंदा की (एम० एम० खड II, पृ० 110)
- 28 एस० एम० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 694
- 29 वन, ई० एच० I, पृ० VIII
- 30 भोलानाथ चट्ट, एम० एम०, खड V, पृ० 13 एस० एन० बैनर्जी, रिप० आई० एन० सी०—1896, पृ० 136 तथा सी० पी० ए०, पृ० 691, 694 पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 750 दत्त ई० एच० I, पृ० VIII और ई० एच० II, पृ० VIII. सी० आई० चित्तमणि 'इकानामिक आल्येक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया', एच० आर०, जनवरी 1902, पृ० 32 जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 125, 240
- 31 दत्त ई० एच० I, पृ० VIII, 261 ई० एच० II, पृ० VIII. IX. पिछली एक डेढ़ सताब्दी के ब्रिटिश शासकों की वाणिज्य नीति का आधार भारतीय उत्पादकों के हितों की अपेक्षा ब्रिटिश

उत्पादको के हित की रक्षा ही रहा है' तथा वही, पृ० 120.

- 32 भोलानाथ चद्र, एम०एम०, खंड V, पृ० 14, 15 हिंदू 16 जून, 1883. समय, 2 दिसंबर (आर० एन० पी० बग, 10 दिसंबर 1887) दत्त, ई० एच० II, पृ० 518 स्पीचेज, II, पृ० 108, 113. जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 125 ऊपर 27वीं पादटिप्पणी में उद्धृत नेतागण
- 33 भारत में अपने शासनकाल के प्रारम्भिक दिन से ही इंग्लैंड के उत्पादको और शिल्पकर्मियों के लाभ के लिए इस देश को कच्चे माल के उत्पादन की बस्ती के रूप में बदलना ब्रिटिश शासको की एक निश्चित नीति रही है (एम० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 691) तथा देखिए, भोलानाथ चद्र, एम०एम० खंड III, पृ० 99-100 ऊपर 27वीं पादटिप्पणी में उद्धृत नेतागण जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी—1902, पृ० 72 दत्त, ई०एच० I, पृ० VIII तथा ई०एच० II, पृ० 129, केसरी, 11 अप्रैल (आर० एन० पी० बग, 15 अप्रैल 1905). फलतः किसी समय ब्रिटिश सरकार की भारतीय कृषि के विकास पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति की ऊपर लिखे नेताओं उदाहरणार्थ केसरी, भोलानाथ चद्र तथा जी० एस० अय्यर द्वारा आलोचना की गई थी
- 34 दत्त, ई० एच० II पृ० 518 स्पीचेज, II पृ० 42
- 35 बाचा, सी० पी० ए०, पृ० 622 एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 694 डान, फरवरी 30 1903 पृ० 207, स्वदेश मित्र, 13 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 अगस्त 1903), हितकारी, अक्तूबर (आर० एन० पी० बग, नवंबर 1903, मधोलकर, रिप०आई०एन०सी० 1904, पृ० 102.
- 36 मिस 'हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया' विल्सन, काटोन्यूएशन पुस्तक I अध्याय VII. मधोलकर की 'इंडियन पालिटिक्स' में उद्धृत, पृ० 43 पी० मेहता. स्पीचेज, पृ० 750 दत्त, ई० एच० I पृ० 260-3 एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 692
- 37 दत्त, ई० एच० I, पृ० 45 जी० एम० अय्यर, ई ए, पृ० 250 चितामणि, एच० आर०, जनवरी 1902, पृ० 32
- 38 बाचा सी० पी० ए०, पृ० 623 दत्त ई० एच० I, पृ० 257 ई० एच० II, पृ० VIII स्पीचेज, II, पृ० 42 चितामणि, एच० आर०, जनवरी 1902, पृ० 32
- 39 भोलानाथ चद्र, एम०एम०, खंड V, पृ० 42 बाचा, रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 32 मधोलकर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 44, बाचा सी० पी० ए०, पृ० 625 एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 692-3, 696 जी० सी० अय्यर, ई ए, पृ० 242, चितामणि एच० आर० जनवरी 1902, पृ० 32 एल०एम० घोष०, सी०पी०ए०, पृ० 754 दत्त, ई०एच० I, पृ० 7 इनसे बढ़कर आर०सी० दत्त ने अपनी पुस्तक में, ई० एच० I, अध्याय III, XIV, XV में तथा ई० एच० II अध्याय, VII, VIII, IX में भेदमूलक चुगो दरों के तरीके की ओर उसके विनाशकारी प्रभाव की खोज की 1812-32 तक भा 3 के निर्यातकों के भारत से इंग्लैंड को निर्यात पर लगाए गए करों के सारणीबद्ध अध्ययन के लिए देखिए, दत्त स्पीचेज II, पृ० 117 1831 में तालिका रूप में 117 प्रतिष्ठित भारतीयों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका परम श्रेष्ठ महाराजा-धिराज की प्रिंसी कौंसिल को एक अपील भेजी गई थी जिसमें यह याचना की गई थी कि बंगाल के सूती और रेशमी कपड़े के इंग्लैंड को निःशुल्क अथवा बंगाल में खपने वाले ब्रिटिश वस्त्रों पर वसूल किए जाने वाले कपड़े की दर पर निर्यात की अनुमति प्रदान की जाए (बी० डी० बसु की पूर्वोद्धृत पुस्तक, पृ० 32-3 में उद्धृत)
- 40 दत्त स्पीचेज, II, पृ० 80. तथा ई० एच० II पृ० 123. चितामणि, एच० आर०, जनवरी 1902, पृ० 32.

41. दत्त : ई० एच० I, पृ० 303-04.
42. दत्त : ई० एच० I, पृ० VIII, 264-7. हितवादी, 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग, 7 नवंबर 1903).
43. कादिर बख्श, 'रिप० आई० एन० सी०—1887, पृ० 142. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 683, 785-6. राय . पावर्टी, पृ० 34. मघोलकर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 44. दत्त : ई० एच० I, पृ० VIII एस० एन० बैनर्जी . सी० पी० ए०, पृ० 694. एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 77 मघोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 103. यहाँ तक कि दत्त सहमत थे . 'भारत के हस्तकला उद्योग इंग्लैंड के भाप और मशीन उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकते.' (दत्त 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 81)
44. रानाडे . एसेज, पृ० 183 तथा पृ० 100
45. डान, फरवरी 1903, पृ० 207 तथा देखिए, वाचा . सी० पी० ए०, पृ० 623. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 680, 683-4 एम० एन० बैनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 694
46. देखिए, नीचे अध्याय 6 तथा 14 और ऊपर 39 की पादटिप्पणी
47. देखिए, नीचे अध्याय 5
48. हितवादी, 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग, 7 नवंबर 1903) जो० एस० अय्यर के अनुसार, ब्रिटिश साहसिकों ने भारत की निधि को खूब नुटा और इस प्रकार अपार भारतीय धन के अत्यधिक संग्रह के फलस्वरूप एक पूँजीपति वर्ग अस्तित्व में आ गया. इस धन के कारण इस वर्ग की साख बढ़ गई तथा शक्ति, उद्योग और साहस में गतिशीलता आ गई .. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत और आयरलैंड की नुट पर ब्रिटिश समृद्धि की आधारशिला बनी प्रकार से रखी जा चुकी थी (ई० ए० पृ० 243) तथा देखिए, ए० बी० पी० 27 अक्तूबर 1886. एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 695 बैनर्जी ने अपने कांग्रेस के भाषण में मुक्त आदम्स की पुस्तक, 'ला आफ सिविलाइजेशन ऐंड डिके' से एक अवतरण उद्धृत किया जिसे 19वीं शताब्दी में परवर्ती भारत पर बोलने और लिखने वालों का नियमित सहारा बनना था.
49. 'दि डान' फरवरी 1903, पृ० 207.
- 49-ए. इसमें अपवाद रूप से, पी० ए० चारलू, आई० सी० पी० 1899, खंड XXXVII, पृ० 177-8.
50. भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड 5, पृ० 2. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 738, 753 मगठा, 24 जनवरी 1886. इंदु प्रकाश, 25 जनवरी 1886. हिंदी बगवामी, 30 मार्च (आर० एन० पी०, बंग, 11 अप्रैल 1891) राय : पावर्टी, पृ० 98, 145. मघोलकर : रिप० आई० एन० सी०—1898, पृ० 121. ए० एन० बोस . सी० पी० ए०, पृ० 427. एम० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 691, 707. जो० सी० अय्यर : 9 ई ए, पृ० 171. दत्त : स्पीचेज, पृ० 24, 163. ई० एच० II, पृ० 519, 528, 612.
51. आई० एन० सी, 1896 का प्रस्ताव 12 और देखिए, 1888 का प्रस्ताव 10, 1897 का प्रस्ताव 9, 1899 का प्रस्ताव 13, 1902 का प्रस्ताव III.
52. रानाडे : एसेज, पृ० 193. 1898 में इकट्ठे कांग्रेस प्रतिनिधियों को आर० एन० मघोलकर ने सकेत किया : बाण्य शक्ति द्वारा संचालित करधों के साथ हथकरघे का मुकाबला इस प्रकार का है जिस प्रकार एक भाप-इंजन के साथ दौड़ में बैलगाड़ी का मुकाबला. (रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 121) और देखिए, जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 785, 974. वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 622. बी० एस० अय्यर : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 193.

- 53 यह कहा जा सकता है कि यह बुराई अपरिहार्य है... (परन्तु) क्या बिनाशकारी प्रक्रिया को और अधिक मद और क्रमिक नहीं बनाया जा सकता ताकि लोगों को इस कष्ट से अपने को उबारने का समय मिल जाए ?—जो० एम० अय्यर 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 193, और देखिए, दत्त ई० एच० I, पृ० 163 दत्त ने भी राबिन् टिप्पणी की, 'धन द्वारा उपलब्ध ऊँचे परिणामों के बावजूद यह कदापि सत्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने खेत अथवा कर्षण पर काम करते समय सम्मान में, योग्यता में, दूरदर्शिता में तथा आत्मनिर्भरता में अपने आप में सर्वोत्तम है और प्रत्येक सच्चा भारतीय आशा करता है गृह उद्योगों को पूँजीवाद के किसी न किसी प्रहार को सहना पड़ेगा (वहाँ, पृ० 518-9)
- 54 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 680, 785, दत्त ई० एच० II, पृ० 163
- 55 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 785
- 56 रानाडे एसेज, पृ० 193 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 974 राय पावर्टी, पृ० 106-7 आई० एन० सी० 1896, 97 तथा 1902 के क्रमशः प्रस्ताव XII, XI और III मधोलकर. 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 48 ए० एम० बास सी० पी० ए०, पृ० 427 जो० सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 126 एम० एन० बैंनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 691 राष्ट्रवादी पत्रों में देश के शीघ्रता से उद्योगीकरण की मांग को प्रायः ही अभिव्यक्त किया
- 57 रानाडे एसेज पृ० 119-20 (बल दिया गया) 1893 में भोलानाथचन्द्र ने देशवासियों से अपील की कि अन्य सभी बातों से ध्यान हटाकर उन्हें अपना सारा ध्यान एकमात्र उद्योगीकरण की ओर देना चाहिए उद्योगीकरण एक समुद्र के समान है तथा अन्य बातें छोटे मोटे नदी-नद के समान हैं—एम० एम० खड्ग II पृ० 111 तथा मराठा 13 फरवरी 1881 24 जनवरी 1886 बंगाली 26 अप्रैल 1884 ए० एस० मधोलकर. रिप० आई० एन० सी०—1886, पृ० 65 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 753, 816 राय पावर्टी, पृ० 98, 109, 129 जो० एम० अय्यर आई० एन० सी० 1901 पृ० 122, ई ए, पृ० 64-6, 85 एम० एन० बैंनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 301, 697 दत्त ई० एच० II, पृ० 528 ढाका गजट, 11 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 16 जुलाई 1904)
- 58 भोलानाथचन्द्र पूर्वोद्धृत, खड्ग V, पृ० 83 ए० बी० पी०, 16 जुलाई 1878, माडलिक पूर्वोद्धृत, पृ० 690, 'बहो पब्लिक ओपीनियन', 28 जून 1880 एंजुकेशन गजट, 2 मई (आर० एन० पी० बग, 10 मई 1883) प्रभात, 20 मई (वही, 28 मई 1883) बंगाली, 76 जुलाई 1888 बर्दवान सजीवनी, 29 नव० (आइ० एन० पी० बग, 10 दिस० 1887) रानाडे एसेज, पृ० 100, 118-9, तिलक इन केसरी, 18 फरवरी 1893 एम० एल० कारदीकर की लोकमान्य बालगंगाधर तिलक (पूना 1957) में उद्धृत, पृ० 111 राय पावर्टी पृ० 107, 109, 111, 129 मधोलकर 'इन इंडियन पालिटिक्स', पृ० 48 बंगाली 13 जुलाई 1900. जो० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी०, 1901, पृ० 127 बाबा इन सी० पी० ए०, पृ० 626, दत्त स्पीचेज II, पृ० 128
- 59 मराठा, 13 अप्रैल 1881.
- 60 सभ्यता के स्तर पर किसी देश की स्थिति की माप उसके लोगों के व्यावहारिक व्यवसायों, उनकी आजीविका के साधनों की सख्या और विराटता, उनके उद्योगों, उनके उद्यमों, उनके कौशल, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके कार्य-व्यापारों तथा उनके उत्पादन में सहायक प्राकृतिक शक्तियों के प्रयोग की सीमा से ही की जाती है प्रगति की माप कला और विश्व की औद्योगिक क्षमता से

- एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अपनी स्थापित श्रेष्ठता के आधार पर ही की जाती है. — 'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', जे० पी० एस० एस०, अप्रैल, 1893 (खंड सं० 4) पृ० 6. तथा जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 816, राय : पावर्टी, पृ० 43, 111, जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० — 1901, पृ० 124.
- 61 नेटिव ओपीनियन, 25 मई 1884. रानाडे : एसेज, पृ० 19. पी० ए० चारलू : आई० सी० पी० 1901, खंड-XI, पृ० 283 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 131.
62. भोलानाथ चट्ट : एम० एम, खंड 5, पृ० 2 नौरोजी : एसेज, पृ० 103 ए० बी० पी० 16 जुलाई 1704. अखबारे आम, 8 जनवरी, 1 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 11 जनवरी, 8 मार्च 1879). बह्मो पब्लिक ओपीनियन, 24 जून 1880. बाबे समाचार, 19 अगस्त (आर० एन० पी० ब० 20 अगस्त 1881) मराठा, 23 जनवरी 1881, 1 जनवरी, 12 फरवरी 1882, 24 जनवरी 1886. स्वदेशमित्रन, 17 दिसंबर (आर० एन० पी० एम०, 31 दिस० 1887) बर्दवान संजीवनी, 29 नवंबर (आर० एन० पी० बग 10 दिसंबर 1887) ए० एस० मुदालियर : रिप० आई० एन० सी० 1886, पृ० 65. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 751., 804-05. रानाडे एसेज, पृ० 121 केरल पत्रिका, 4 नवंबर (आर० एन० पी० एम० 30 नवंबर 1893) 'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 13 अखबारे आम, 30 जुलाई (आर० एन० पी०, पृ० 28, अगस्त 1897) भारत जीवन, 1 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 10 अगस्त 1898. आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव XIII तथा 1902 का प्रस्ताव III. सियासकोट पेश्वर, 1 मार्च (आर० एन० पी० पी० 10 मार्च 1900). मधोलकर . रिप० आई० एन० सी० — 1899, पृ० 89, केसरी, 23 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 28 जुलाई 1900) एन० सी० चंदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 524 पी० ए० चारलू : एन० सी० पी० 1901, खंड XI, पृ० 283 बाबा : सी० पी० ए०, पृ० 624 जी० एस० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 124-5 और ई ए, पृ० 65 'इंडियन नेशन' 23 दिस० 1901 (बी० ओ० आई० — 8 फरवरी 1902) पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 746 एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 79 तथा रिप० आई० एन० सी० — 1904, पृ० 115. दत्त : ई० एच० I. पृ० XIII. XIV.
- 63 रानाडे एसेज, पृ 207, जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 868
- 64 मराठा, 23 जनवरी, सितंबर 1881 नेटिव ओपीनियन, 25 मई 1884. जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 368, 751, 804-05, 851-3 रानाडे : एसेज, पृ० 113, 207. बी० एन० सी०, रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 95. राय . पावर्टी, पृ० 98 जी० एस० अय्यर : लांड कर्जन्स रिजल्यूशन आफ लैंड रेवेन्यू ऐंड फीमिन (लांड कर्जन का भूराजस्व तथा अकाल पर प्रस्ताव) एच० आर० फरवरी 1902, पृ० 148-9 एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी० — 1904, पृ० 114-5 'ऐग्रीकल्चर ऐंड इंडस्ट्री', का नीचे अध्याय 10 का संबंधित भाग.
- 65 मराठा, 19 जून 1881, 12 फरवरी 1882 स्वदेशमित्रन, 5 मार्च (आर० एन० पी० एम०, मार्च 1885) सहृषर, 6 मई (आर० एन० पी० बग, 16 मई 1885) रानाडे . एसेज, पृ० 25-6, 100, जोशी . पूर्वोद्धृत पृ० 642, 667 दत्त : स्पीचेज I, पृ० 24-5. केसरी, 11 नवंबर (आर० एन० पी० बंब, 15 नवंबर 1902).
- 66 ऐजुकेशन गजट, 2 मई (आर० एन० पी० बग, 10 मई 1883) बगाली, 26 अप्रैल 1884. मराठा, 24 जून 1886. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 645-8, 666-7. मधोलकर : रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 121. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 85. एच० एन० वैनर्जी : सी० पी० ए०,

- पृ० 637. मियासकोट पेपर, 24 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 6 सितंबर 1902) और देखिए नीचे अध्याय 4 और 13.
67. रानाडे : एसेज, पृ० 19. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 131.
68. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 829. के० टी० तैलंग : 'जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', खंड XI, पृ० 9, भाग I रानाडे . एसेज, पृ० 19.
69. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 616 और भोलानाथ चंद्र : एम० एम० खंड 5 पृ० 2, के० टी० तैलंग . 'फ्री ट्रेड ऐंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऐन इंडियन प्वाइंट आफ व्यू', (बंबई, 1877) पृ० 51-3.
70. रानाडे : एसेज, पृ० 19. 'दि ऐंक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 22-3. जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 266.
71. रानाडे : एसेज, पृ० 96
72. बगाली, 18 जनवरी 1902. और देखिए, ए० बी० पी० 16 जुलाई 1874. जमीयुल उलुम, 28 जून (आर० एन० पी० एन०, 7 जुलाई 1897) बगाली तो और आगे बढ़ा और 1900 में उसने यह विचार प्रकट किया, देशभक्ति का गुण व्यापार की भावना से जुड़ा हुआ है'. (6 जुलाई).
73. 'दि इंडियन इकानामिक प्रान्सम', 'दि डान' मार्च-जून, 1900
74. बहो, अप्रैल 1900, पृ० 265-6.
75. 'दि ऐंक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 8.
76. बहो, पूर्वोद्धृत, पृ० 8-9 और देखिए, जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 209
77. 'दि ऐंक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 11-2, जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 300, राय . पावर्टी, पृ० 110-1
78. भारत में आधुनिक उद्योग के विकास का प्रस्तुत सक्षिप्त विवरण प्रो० डी० आर० गाडगिल के यथ, 'दि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इंडिया', के 4, 6 तथा 8 अध्यायों पर आधारित है.
79. साथ ही देखिए, दत्त ई० एच० II, पृ० 520-1
80. इसी अध्याय पादटिप्पणी स० 4 देखिए और गाडगिल : पूर्वोद्धृत, पृ० 185.
81. इस दृष्टिकोण के प्रचलित होने के साक्ष्य के रूप में देखिए, 1916-18 के इंडियन इंडस्ट्रियल कमोशन का प्रतिवेदन, पृ० 2 तथा अनस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 210 अपने को भारत में औद्योगिक प्रवृत्तियों का प्रमुख सचालक मानने वाले लाई कर्जन तक ने 1903 में यह मत प्रकट किया : भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि कर्म में ही प्रशिक्षित है, व्यावहारिक (शारीरिक) दृष्टि से भी वह कृषि कर्म के ही योग्य है और वह कृषि कर्म को छोड़कर अन्य किसी उद्योग में प्रवृत्त नहीं होगी (स्पीचेज, खंड III, पृ० 133) भारतीयों द्वारा इस दृष्टिकोण को नकारने के सबंध में देखिए, भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड II, पृ० 557. के० टी० तैलंग : 'फ्री इंडियन ऐंड प्रोटेक्शन, पृ० 34-5 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 642. रानाडे : एसेज, पृ० 24-5. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 258-274
82. भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड II, पृ० 560-617 रानाडे : एसेज पृ० 24, 159-60 राय : पावर्टी, पृ० 82-4 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 258, 275, अध्याय 16, 17, 18, दत्त : स्पीचेज II, पृ० 79, 106. एस० एन० बैनर्जी ने 1903 में अध्याय पद से कांग्रेस को संबोधित करते हुए एक बहुत ही उपयुक्त तत्त्व का उल्लेख किया : यूरोपीय सर्वप्रथम हमारे कच्चे माल से नहीं प्रत्युत उत्पादित सामग्री की उत्कृष्टता से ही प्रभावित और आकृष्ट हुए थे. (सी० पी० ए०, पृ० 691).

83. भोलानाथ चट्ट : एम० एम०, खंड 11, पृ० १ रानाडे . एसेज, पृ० 24 राय : पावटी, पृ० 109.
जी० एम० अय्यर : ई ए, पृ० 145
84. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 668, रानाडे एसेज, पृ० 24 राय : पावटी, पृ० 109, जी० एम०
अय्यर . ई ए, पृ० 147, 149.
85. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 668, 742, रानाडे एसेज, पृ० 120, जी० एम० अय्यर ई ए,
पृ० 146-7
86. नीरोजी : एसेज, पृ० 105. ए० बी० पी०, 2 अप्रैल 1881 मराठा, 9 अगस्त 1885 जशा
पूर्वोद्धृत, पृ० 666, 741, 743 रानाडे . एसेज, पृ० 22, 91 2 गोखले . वेलबी क्याशन, खंड III,
प्रश्न 181-40 वाचा सी० पी० ए०, पृ० 625 जी० सी० अय्यर . वेलबी क्याशन खंड III,
प्रश्न 18675, 18680 ई ए, पृ० 145 लाजपत राय 'दि मैन इन हिज वर्ड' (ला० लाजपत
राय के भाषणों और लेखों का संग्रह) (मद्रास, 1907) पृ० 39-41 अपन साधना से ही बड़
पैमाने के उद्योग खड़ा कर सकने में समर्थ घनी वित्त-विनियोजकों की अनुपस्थिति पर बल दिया
गया —बंगाली, 28 जनवरी 1882 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 742
87. रानाडे : एसेज, पृ० 92
88. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 666, 741-2, 745, 803, रानाडे एसेज, पृ० 22, 11
89. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 793 रानाडे एसेज, पृ० 22.
90. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 761, 794-6, 803
91. रानाडे : एसेज, पृ० 23 और नीचे देखिए.
92. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 795 रानाडे एसेज, पृ० 91 तथा विल पर अध्याय 11
93. देखिए 'दि ट्रेन', अध्याय 13
94. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 747, 796 रानाडे : एसेज, पृ० 22, 41, जी० एम० अय्यर ई ए,
पृ० 146
95. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 740 और देखिए रानाडे एसेज, पृ० 22 जी० एम० अय्यर ई ए,
पृ० 150. लाजपतराय : पूर्वोद्धृत, पृ० 142.
96. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 797-8. रानाडे एसेज, पृ० 40, 42
97. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 746 रानाडे . एसेज, 22, 91.
98. देखिए नीचे अध्याय 13 'ट्रेन' पर.
99. मराठा, 13 फरवरी 1881 तथा जी० एम० अय्यर . रिप० आई० एन० सी०—1901,
पृ० 127.
100. ए० बी० पी०, 2 अप्रैल 1881 सवाद प्रभाकर, 9 मई (आर० एन० पी० बग 17 मई 1883)
मराठा, 9 अगस्त 1883 राय : पावटी, पृ० 127-7 अभीष्ट उलुम, 28 जून (आर० एन० पी०
एन० 7 जुलाई 1807) 26 मई 1903 में चारमिल ने लिखा राजा और जमींदार लोग कमर
कस ले और युद्ध में लड़ने को उद्यत हो जाए. इन दिनों धन की सहायता से देश के ससाधनों
का परिरक्षण तथा देश की प्रगति का संरक्षण ही सन्तियों का कर्तव्य कर्म है ...इन दिनों
उन्नत विचारोंवाला टाटा राजा तथा सैनिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. (आर० एन० पी०
बग, 6 जून 1901).
101. रानाडे : एसेज, पृ० 188.
102. जी० एम० अय्यर, ई ए, पृ० 15...तथा देखिए, वही, पृ० 150-4 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 797-8.

- रानाडे : एसेज, पृ० 43, 49, 118. जी० एम०, अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 127.
103. ब्राह्म पब्लिक ओपीनियन, 24 जून, 1880 बंगाली, 28 जनवरी 1882. बर्देबान सजीवनी, 27 मई (आर० एन० पी० बंग, 7 जून 1881) मराठा, 9 अगस्त 1885, हिंदू, 29 दिसंबर 1883. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 800, 806. रानाडे : एसेज, पृ० 193 ऐजूकेशन गजट, 13 नवंबर (आर० एन० पी० बंग 21 नवंबर 1891) भारत जीवन, 10 जुलाई (आर० एन० पी० 19 जुलाई 1891. मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 174. लाजपत राय : पूर्वोद्धृत, पृ० 39, 41.
104. कलकत्ता में 1883 में नेशनल कॉफ़ेस का प्रथम प्रस्ताव. बंगाली, 5 जनवरी 1884, मराठा, 20 जनवरी 1884, 9 अगस्त 1885, 19 सितंबर 1886. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 747-8. भारत-मित्र, 5 जून, नवविभाकर, 28 जुलाई, अक्रुलांत वक्ता, 5 सितंबर, सुरभि तथा सहचर, 30 सित० (आर० एन० पी० बंग, 14 जून, 2 अगस्त, 12 सित० 3 अक्टूबर 1884 क्रमशः). हिंदू, 21 जनवरी 1884, 3 जुलाई 1885, 10 अगस्त 1886, 21 अप्रैल 1902 इंदु प्रकाश, 23 जन० (बी० ओ० आई०, फरवरी 1886). बंगाली 17 अप्रैल और 31 जुलाई 1886. इंडियन नेशन, 2 अगस्त, ट्रिब्यून, 14 अगस्त, बिहार हेराल्ड. 17 अगस्त (बी० ओ० आई० अगस्त 1886), 'ढाका प्रकाश', 7 मार्च (आर० एन० पी० बंग, 11 सित० 1886); भारत मित्र, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग 17 अप्रैल 1886; सजीवनी, 4 सित०, भारतवासी, 4 सित०; नवविभाकर, साधारणी, 6 सित० (आर० एन० पी० बंग 11 सित० 1886); स्वदेशमित्र, 8 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, फरवरी 1886); एम० आर० एन० मधोलकर : रिप० आई० एन० सी० 1887, पृ० 137-8, एम० एन० बैनर्जी स्पीचेज ऐंड गइडिन्स (मद्रास, तिबिरहित) (निर्देश के लिए इसे आगे 'एम० ऐंड० डब्ल्यू' से संकेतित किया जाएगा), पृ० 260. सी० पी० ए० पृ० 696-7 टी० एन० सिंह . रिप०, आई० एन० सी० 1888, पृ० 150; जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 632, 666, 743 तथा और आगे; पावर्टी, पृ० 138-9 भारत जीवन 3 अक्टूबर (आर० एन० पी० ए०, 12 अक्टू० 1898); ए० एन० बोस . सी० पी० ए०, पृ० 427; ए० बी० पी० 2 मार्च, 3 मई 1901; मालवीय . स्पीचेज, पृ० 269; लाजपतराय . पूर्वोद्धृत, पृ० 39; एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 79 जी० एम० अय्यर . ई ए, पृ० 90, 97 'पैना अखबार', 22 फरवरी (आर० एन० पी० बी०, 8 मार्च 1922) श्रीराम : एल० सी० पी० 1903 खंड XVII, पृ० 103-04. मद्रास स्टैंडर्ड, 16 जन०, ट्रिब्यून, 15 जन० (बी० ओ० आई०, 6 फरवरी 1904). इंडियन पीपुल, 1 जन०, ऐडवोकेट, 24 जून (वही, 13 फर० 1904) तथा देखिए, कर्जन : स्पीचेज, खंड II पृ० 330.
105. जी० पी० एस० एस० जनवरी 1882. पृ० 31. पूना सार्वजनिक सभा की शिक्षा समिति द्वारा एक अपील.
106. प्रस्ताव VII.
107. प्रस्ताव X.
108. क्रमशः प्रस्ताव XIII, VIII, और XII.
109. प्रस्ताव XV.
110. प्रस्ताव II. जी० एस० अय्यर ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए तथा वर्तमान भारत सरकार की योजनाओं को प्रत्याशित करते हुए भारत की पांच बड़ी राजधानियों में मि० टाटा के 'विज्ञान

संस्थान' के समान पांच संस्थानों की स्थापना का अनुरोध किया, ई ए, पृ० 97.

111. टी० एन० सिंह, रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 156. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 745, 1059. एन० जी० बंशावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 525. मालवीय : स्पीचेज, पृ० 269. वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 628 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 92 तथा कर्जन : स्पीचेज, खंड II, पृ० 330.
112. इस मुद्दे पर आई० एन० सी० के प्रस्ताव के लिए ऊपर देखिए, पाद टिप्पणिया 106-110 और भारतमित्र, 3 जून (आर० एन० पी० बंग, 14 जून 1884) बंगाली, 31 जुलाई 1886, 27 अगस्त 1887, 4 सितंबर 1897, इंडियन नेशन; 2 अगस्त; ट्रिब्यून, 14 अगस्त; बिहार हेराल्ड, 17 अगस्त (बी० ओ० आई० अगस्त 1886); हिंदू 27 अक्तूबर 1884, 10 अगस्त 1886; मराठा 15 अगस्त 1886; जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 667, 811. मालवीय : स्पीचेज, पृ० 269 जी० एस० अय्यर . ई ए. पृ० 97-9 पैसा अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 15 अप्रैल 1899).
113. मराठा, 20 जनवरी 1884, जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 98
114. मराठा, 24 जून 1880; बंगाली, 31 जुलाई 1886; हिंदू, 10 अगस्त 1886; ट्रिब्यून, 14 अगस्त; (बी० ओ० आई०, अगस्त 1886). जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 745 आई० एन० सी० 1898, 1899. 1900, 1901 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XVIII, XV, VIII, XIV, और II. जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 99-100
115. राय : पावर्टी पृ० 140 हिन्दुस्तानी, 5 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 11 दिस० 1900) वाचा . सी० पी० ए०, पृ० 626
116. बंगाली, 31 जुलाई 1886, हिंदू, 10 अगस्त 1886, मराठा, 15 अगस्त 1886; इंडियन नेशन 2 अगस्त; ट्रिब्यून, 14 अगस्त, बिहार हेराल्ड, 17 अगस्त (बी० ओ० आई०, अगस्त 1883); बंगाली, 4 सितंबर 1897; हिंदुस्तानी, 5 दिसंबर (आर० एन० पी० एन०, 11 दिसंबर 1900).
117. नव विभाकर, 28 जुलाई (आर० एन० पी० बंग, 2 अगस्त 1884). भारतमित्र, 15 अप्रैल, सहचर, 14 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग, 24 अप्रैल 1886); साधारणी, 25 अप्रैल, ढाका प्रकाश, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग, 1 मई 1886); सुरभि और पताका, 12 मई (आर० एन० पी० बंग, 22 मई 1886), मृगनीघर, रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 90 भारत जीवन, 3 अक्तूबर, (आर० एन० पी० एन०, 12 अक्तूबर 1892) ए० एम० बोस सी० पी० ए०, पृ० 427-8. मराठा, 18 नव० 1900, श्रीराम . एन० सी० पी०—1903, खंड XLII. पृ० 103-4; मालवीय स्पीचेज, पृ० 269 लाजपतराय : पूर्वोद्धृत, पृ० 39 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 92. कांग्रेस ने 1898 के अपने चौदहवें अधिवेशन में अपनी दुई धारणा को इन शब्दों में व्यक्त किया : इस समय प्रचलित तकनीकी शिक्षा पद्धति पूर्णतः अपर्याप्त और असन्तोष-प्रद है (प्रस्ताव XVIII.) 1899, 1900 तथा 1901 के क्रमशः XVI, VIII तथा XIX प्रस्तावों में इस राय को दाहराया गया.
118. शिवाजी, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग; 9 अक्तू० 1880) पुना सार्वजनिक सभा की कार्य-कारिणी समिति द्वारा एक अपील, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1880, पृ० 30-31. 'पंजाबी अखबार', 10 नवंबर (आर० एन० पी० पी०, 14 नव० 1883), कलकत्ता में नेशनल कांफ़ेंस का प्रथम प्रस्ताव. बंगाली, 5 जनवरी 1884; मराठा, 20 अप्रैल 1884; नव विभाकर, 28 जुलाई (आर० एन० पी० बंग, 2 अगस्त 1884); जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 812. अमीरल रजुम, 28 जून (आर० एन० पी० एन०, 7 जुलाई 1897); भारत जीवन, 3 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०,

- 18 अक्टूबर 1898) अल्मोड़ा अखबार 8 अक्तू० (आर० एन० पी० एन०, 19 अक्तू० 1898). लाजपतराय : पूर्वोद्धृत, पृ० 40-1. नेटिव ओपीनियन, 30 जुलाई; इंदु प्रकाश, 31 जुलाई (आर० एन० पी० बंब, 2 अगस्त 1902).
119. जे० सी० बागल . 'हिस्ट्री आफ दि इंडियन एसोसिएशन,' 1876-1951 (कलकत्ता 1953) पृ० 10.
120. प्रस्ताव XVI. 1900 में इसी भावना की पुन. अभिव्यक्ति की गई. 1898 में कांग्रेस अध्यक्ष ए० एम० बोस ने पहले ही टाटा की देश के सच्चे लोकोपकारक के रूप में प्रशंसा की थी— (सी० पी० ए०, पृ० 456).
121. ए० बी० पी०, 11 मार्च, 23 जून 1904 कलकत्ता प्रेस ने सस्था का बड़े-बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया देखिए, बंगाली, 16 मार्च, 8 मितंबर 1904, ए० बी० पी० 23 जून 1904; इंडियन मिरर, 4 मई (आर० एन० पी० बंग, 14 मई 1904); तथा दुनिया प्रकाश, 7 अप्रैल (आर० एन० पी० बंब, 9 अप्रैल 1904)
122. 'इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया', 1909, खंड IV पृ० 436-9
123. मराठा 1, 15 अगस्त 1886, 18 नव० 1900, भारत मिहिर, 8 अप्रैल, नव विभाकर, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग, 17 अप्रैल 1886); सुबोध पत्रिका, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बंब, 12 फर० 1887), बंबई समाचार 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बंब, 16 अप्रैल 1887), हिंदुस्तानी, 5 दिसंबर (आर० एन० पी० एन०, 11 दिस० 1900) स्वदेशमित्र, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 2 मार्च 1901), वाचा सी० पी० ए०, पृ० 628, जी० एस० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 126. इंडियन पीपुल, 1 जन०; ऐंडवोकेट. 24 जन० (बी० ओ० आई०, 13 फर० 1904) तुलनीय ई० बी० हावेन 'टैक्नीकल एजुकेशन इन इंडिया', 'कलकत्ता रिव्यू' अप्रैल 1897 हावेन ने प्राथमिक तकनीकी शिक्षा पर नल दिया तथा उच्च तकनीकी शिक्षा की मांग का तिरस्कार किया
124. सुबोध पत्रिका, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बंब, 12 फरवरी 1887); बंबई समाचार, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बंब, 16 अप्रैल 1887), स्वदेशमित्र, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम० 2 मार्च 1901); इंडियन स्पेक्टेटर, 9 जून 1901, हिंदू, 23 फरवरी 1901; इंडियन पीपुल 1 जन०; ऐंडवोकेट, 24 जन० (बी० ओ० आई० 13 फरवरी 1904).
125. हमें हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि उच्च स्तर के नवयुवकों के हृदय को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यही लोग भारत की औद्योगिकता को नीचे से ऊपर उठाने में पुरोगामी बनेंगे (जी०एस० अय्यर : रिप०आई० एन० सी० 1901, पृ० 126) तथा पाद टिप्पणी 124 ऊपर और मराठा, 15 अगस्त 1886. भारतवासी, 4 सित० (आर० एन० पी० बंग, 11 सित० 1886). वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 627-8. इसके विरुद्ध भारतीय दृष्टिकोण को देखने के लिए देखिए, 'दि इंडियन इकानामिक प्रॉब्लम', 'दि डान' जून 1900, पृ० 31-2.
126. सपड़ा, पादटिप्पणियां 118 और 121 तथा जी० एस० अय्यर : ई ए. पृ० 98
127. देखिए ऊपर पादटिप्पणी 110 तथा 'भारतवासी', 4 सितंबर (आर० एन० पी० बंग, 11 सित० 1886) वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 628. आई० एन० सी०—1902 का प्रस्ताव IX. इंडियन पीपुल, 1 जनवरी, ऐंडवोकेट, 24 जनवरी (बी० ओ० आई०, 13 फरवरी 1904).
128. जे० एन० सिङ्घ : रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 156-7. आर० बोस : वही, पृ० 162.

- रानाडे . एसेज, पृ० 122, 187 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 4.
 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 149. बी०सी० पाल 'दि नेशनल प्रोग्रेस', 26 जनवरी 1903 को कलकत्ता में दिया गया एक भाषण, न्यू स्विट (कलकत्ता, 1907) पृ० 175.
129. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 740 तथा पृ० 826
130. बार० बोस रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 162
131. रानाडे एसेज, पृ० 122 तथा जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 740, 801-02, 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 4, 23 जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 149-50 लाजपतराय : पूर्वोद्धृत, पृ० 42
132. 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 23 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 625. मराठा, 1 फरवरी 1884 ; बंगाली, 17 दिसंबर 1901. मोक्षले : स्वीजेज, पृ० 1057 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 216.
133. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 625 बंगाली 17 मई 1902
134. रानाडे . एसेज, पृ० 23, 122 बी० सी० पाल 'दि नेशनल प्रोग्रेस', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 179-80; तथा देखिए जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 132-4 भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', के अज्ञातनाम लेखक ने संकेतित किया : आधुनिक सभ्यता अस्तित्व की स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी दशा को सुधारने, अपनी शक्तियों के विकास तथा जीवन की सुख-सुविधाओं में वृद्धि का अथवा प्रयास कर रहा है (पूर्वोक्त स्थल पृ० 5)
135. 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 5
136. वही, पृ० 3 जे० एन० सिंह, रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 157, जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 151
137. 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 5 जे० एन० सिंह रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 157
138. 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 5-6, 23 बी० सी० पाल, 'दि नेशनल प्रोग्रेस', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 186
139. जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 150 बी०सी० पाल 'दि नेशनल प्रोग्रेस', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 179
140. अज्ञात अनुसंधानों में सफलता के लिए हमें अपने निजी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है हमें उन पारंपरिक प्रतिबंधों से अपने आपको मुक्त करना है जो सुधार में बाधक हैं तथा विचारों को अस्पष्ट बनाने वाले और निर्णय को विपर्यस्त करने वाले पूर्वग्रहों एवं भावनाओं के त्याग से समझौते पर विवश करते हैं 'दि ऐंसीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 1-2
141. रानाडे 'मिसलेनियस राइटिंग्स' (बंबई 1915) पृ० 131 तुलनीय बी० सी० कर्वे, रानाडे . 'दि प्रोग्रेस आफ लिबरेटिड इंडिया', (पूना, 1944) रानाडे की इच्छा थी कि जनता का सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सारा जीवन पुनर्गठित करना चाहिए ताकि भारत के लोग आधुनिक व्यवसाय तथा उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायपरक दृष्टिकोण वाले बनें (पृ० 106).
142. वही, पृ० 116. जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 300 तथा भोलानाथ चट्ट—एच० एम० खड 5, पृ० 7-9
143. 'दि ऐंसीजेंसी आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 1-23 तथा ऊपर 130, 131 की पादटिप्पणियाँ.

144. भारत जीवन, 6 नवंबर (आर० एन० पी० एन०, 14 नवंबर 1899) प्रधान ऐड भागवत मे तिलक ने कहा—पूर्वोद्धत, पृ० 50, 63, 96. एन० जी० चदावरकर 'स्पीचेज ऐंड राइटिंग', एल० बी० कैकिनी द्वारा संपादित (बंबई, 1912), पृ० 75 (अन्यथा वह मुधारक वर्ग मे संबंधित था) लाजपतराय पूर्वोद्धत, पृ० 114-28
145. 1904 मे लाजपतराय ने अपना मत प्रकट किया : हमारे धर्मग्रंथो से इतनी पर्याप्त सामग्री है कि हम सामाजिक शक्ति और सुधार के लिए उस पर निर्भर कर सकते है (पूर्वोद्धत, पृ० 90) तथा वही, पृ० 73, 116, 122, 124 प्रधान ऐड भागवत में तिलक ने कहा—पूर्वोद्धत, पृ० 76-7, 119
146. प्रधान ऐड भागवत, मे तिलक ने कहा—पूर्वोद्धत, पृ० 63-4 लाजपतराय . पूर्वोद्धत, पृ० 76-7, 119
- 146-ए ए० सी० मजूमदार : 'इंडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास, 1917) पृ० 187
147. मसानी . पूर्वोद्धत, पृ० 71, 78
148. जी० ए० मनकर . पूर्वोद्धत, खंड I, पृ० 82-3.
149. गोखले स्पीचेज, पृ० 927
150. पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 747
151. दि इंडियन नेशन बिल्डर्स (मद्रास, निर्धारित), भाग I, पृ० 182
152. राम गो. . . पूर्वोद्धत, पृ० 42
153. 'दि इंडियन नेशन बिल्डर्स, भाग II, पृ० 93, 296
154. वही, पृ० 361, 372
155. वही, भाग I, पृ० 155 6
156. लाजपतराय : पूर्वोद्धत, इट्रोडक्शन, पृ० XXIII
157. 'ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन', 22 जनवरी, 8 अप्रैल 1880.
158. बंगाल नेशन चेबर आफ कामर्स—1887 का प्रतिवेदन, पृ० 71-2.
159. ये तथ्य पैसा निधि की रजन जयती धक (पूना, 1933) से लिए गए है
160. मराठा, 9 अगस्त 1885, 22 सितंबर 1895; रानाडे एसेज, पृ० 120, 180, जोशी . पूर्वोद्धत, पृ० 971-8 तथा डी० पी० कर्वे : पूर्वोद्धत, पृ० 106.
161. केलाक महादेव गोविंद रानाडे (कलकत्ता 1926) पृ० 321-2. गोखले . स्पीचेज, पृ० 927.
162. बंगाली, 12 सितंबर, 7 नवंबर 1891
163. एस० एन० बैनर्जी : 'ए नेशन इन मेकिंग' (आक्सफोर्ड प्रेस, 1925), पृ० 146.
164. आई० एन० सी०—1900 के प्रस्ताव VII और XXV.
165. बी० पट्टाभि सीतारमैया : 'दि हिस्ट्री आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस', 1883-1935. (मद्रास 1935) पृ० 68. प्रदर्शनियो को लोकप्रिय भारतीय समाचारपत्रो से प्रोत्साहन और समर्थन मिला. देखिए, बंगाली 18 जनवरी 1902; इंडियन नेशन 23 दिसंबर 1901, ऐडवोकेट—9 जनवरी 1902; इंडियन मिरर 19 जनवरी 1902; बी० ओ० आई०, 8 फरवरी 1902.

अध्याय 3

औद्योगिक विकास : दो

ब्रिटिश पूजी..... (भारत की) राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है।
लार्ड कर्जन

विदेशी, अधिकांशतया ब्रिटिश, पूजी का देश के संसाधनों के विकास में विनियोजन देशवासियों की आर्थिक दशा के सुधार में सहायक होने की अपेक्षा इस दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा ही सिद्ध हुआ है।
वर्णिमचन्द्र पाल

विदेशी पूंजी की भूमिका

भारत में एक ओर स्वदेशी पूजी की कमी थी और यहां के लोग संकोचवश अथवा खतरों में घबरकर नए क्षेत्रों में पूजी के निवेश से कतराते थे जिसके फलस्वरूप भारत के औद्योगिक विकास का क्षेत्र संकुचित और सीमित हो गया था तो दूसरी ओर ब्रिटिश पूजी अपने देश में पूरी तरह न खप पाने के कारण निवेश के लिए नए क्षेत्रों की खोज में थी। ब्रिटेन का विचार यह था कि इस ब्रिटिश पूजी को भारत के आर्थिक विकास की दृश्यता को भरने के काम में लगाया जाए तथा इसका प्रयोग उद्योगीकरण के विकास में किया जाए। ग्रेट ब्रिटेन के तथा भारत के अधिकारियों का विचार था कि ब्रिटिश पूंजी को भारत में आकृष्ट करने तथा सभी बाधाओं को हटाकर उसका प्रयोग करने से न केवल भारत के सभी आर्थिक रोगों का उपचार हो जाएगा प्रत्युत ब्रिटेन की अतिरिक्त पूंजी को भी सुरक्षित और लाभदायक विकास मिल जाएगा।¹

ब्रिटिश सत्ता ने भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रवाह को सुरक्षा और आकर्षण प्रदान किया। स्वदेशी पूजी तथा गाहस के अभाव तथा ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चता के परिणामस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में ब्रिटिश पूंजीपति ही भारत में आधुनिक उद्योगों के अग्रदूत तथा प्रधान प्रोत्साहक बने। इस पर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रिटिश पूजी का मूल निवेश अल्प था। भारतीय साम्राज्य की विजय का आधार भारतीय वित्त तथा यहीं से जुटाए गए कर्ज थे। 19वीं शती के पूर्वार्ध में जन्म लेने वाले व्यवसाय नए बैंक तथा

बागान उद्योग अधिकांशतया भारत स्थित ब्रिटिश अधिकाग्रियों की वचत की विनीय सहायता के ही परिणाम थे। फलस्वरूप ये हित भारत की लूट खसोट और भारत से उगाहे राजस्व के भारत में पुनर्निवेश के परिमाण के ही संकेतक थे। इनमें ब्रिटेन से निर्यातित पूँजी नहीं लगी थी।¹ 1837 के उपरांत ही भारत में उल्लेखनीय परिमाण में ब्रिटिश पूँजी निरंतर प्रवाहित होने लगी। 1854-1859 की अवधि में यह प्रवाह अपनी चरम सीमा पर था। इस अवधि में लगभग 1500 लाख पौंड निवेशित किए जा चुके थे।² दुर्भाग्यवश 19वीं शताब्दी में निवेशित विदेशी पूँजी की राशि का विश्वमनीय प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है। विदेशी पूँजी का एक बड़ा भाग उन मिश्रित पूँजी समुदायों द्वारा निवेशित किया गया था जिनका पंजीयन तो कहीं और हुआ था परंतु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उनका व्यापार भारत में होता था। संक्षेप में इस पूँजी की राशि की संगणना असंभव न होने पर भी कठिन अवश्य थी। फिर भी निवेशित विदेशी पूँजी के परिमाण की मामान्य रूप-रेखा 1909-11 के मध्य प्रकाशित तीन प्राक्कलनों में देखी जा सकती है। 1909 में एक अर्थशास्त्री लेखक ने संगणना की कि ब्रिटिश पूँजी का लगभग 4700 लाख पौंड भारत में निवेशित हो चुका था।³ 1910 में जार्ज पाइश द्वारा लगाए गए एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत और श्रीलंका 1909 तक ब्रिटिश पूँजी की 3650 लाख पौंड राशि खपा चुके थे।⁴ 1911 में एम० एफ० हावर्ड ने इस राशि को 4500 लाख पौंड कूता।⁵ इन अनुमानों की विशुद्धता को छोड़ देने पर भी इतना तो निश्चित है कि इस अवधि में भारत में निवेशित ब्रिटिश पूँजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी।

विस्तृत परीक्षण से भारत में विदेशी पूँजी की तीन विविष्ट विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के ब्रिटिश पूँजी के प्रति दृष्टिकोण की समीक्षा के समय इन्हें ध्यान में रखना उचित ही होगा। अब्बल तो 1870 के पश्चात चालू विदेशी पूँजी के वार्षिक ब्याज के रूप में विदेशों को भेजी गई धनराशि वार्षिक पूँजी के नाए अंतःप्रवाह की राशि से बढ़कर थी जिसका स्पष्ट अर्थ यह था कि 19वीं शती के पूरे अंतिम चरण में ब्रिटेन वास्तव में भारत में पूँजी का शुद्ध आयातक था, अथवा दूसरे शब्दों में, भारत में पूर्व निवेशित विदेशी पूँजी के एकांत लाभों से अर्जित विदेशी पूँजी का केवल भारत में ही नवीन निवेश नहीं होता था प्रत्युत ब्रिटिश धनकुबेर इन लाभों के कुछ अंश का विश्व के दूसरे भागों के विकास में भी उपयोग करते थे, दूसरे, ब्रिटिश निवेशक जहां भारत में अपनी फालतू पूँजी से निकास से स्रोतों की खोज के प्रति उत्सुक थे, वहां ब्रिटिश उत्पादक भी उसी उत्सुकता से भारत को अपने एकाधिकार की मंडी बनाए रखना चाहते थे। ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में शक्तिशाली थे अतः भारत सरकार को विवश होकर भारत में आधुनिक उद्योग को उत्साहित और कभी कभी निरुत्साहित करने की नीति भी अपनानी पड़ी। फलतः विदेशी पूँजी को प्रधानतया सरकारी ऋणों, रेलवे, विदेशी व्यापार, बैंक, खान तथा बागान उद्योगों के क्षेत्र में ही नियोजन उपलब्ध हो सका। इनके उत्पादकों ने ब्रिटिश उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता तो की ही नहीं, उलटे भारतीय बाजारों में उनके प्रवेश की सुविधाएं जुटाईं। सर जार्ज पाइश के अनुसार, 1909 में ब्रिटेन की भारत में कुल निवेशित 3650 लाख पौंड राशि में से केवल 250 लाख पौंड

व्यावसायिक और औद्योगिक सस्थाओं में निवेशित थी। स्पष्ट है कि इस प्रकार औद्योगिक निवेश का भाग अपेक्षाकृत और भी कम था।¹⁰ तृतीयतः, यद्यपि आधुनिक उद्योगों में निवेशित विदेशी पूँजी की राशि किसी भी मानदंड से तुच्छ थी तथापि उसने भारत के औद्योगिक मंच पर एकधिकार जमाए रखा तथा इस क्षेत्र में भारतीय पूँजी को दबा कर रखा। बहुत सारी पटसन मिलों, ऊन और सिल्क की मिलों, कामज मिलों, चीनी के कारखानों, चमड़े के कारखानों, लोहा तथा पीतल के ढलाई कारखानों के मालिक विदेशी निवेशक ही थे।¹¹ भारतीयों का प्रारंभ से ही प्रमुख भाग केवल सूती कपड़ा उद्योग में ही था किंतु यहाँ भी आंशिक पूँजी विदेशी थी प्रबंध अधिकांशतः विदेशी था तथा तकनीकी सवर्ग में अधिकांश का जबरदस्ती ही आयात करना पड़ता था।¹²

भारतीय राष्ट्रवादी नेता विदेशी पूँजी के उपयोग के संबंध में पर्याप्त समय तक संभ्रम, मतभेद तथा सकोच का शिकार बने रहे। प्रारंभ में विदेशी संरक्षण में जब रेलवे और नहरों, खानों, बागान और आधुनिक उद्योगों का आगमन हुआ, उस समय विदेशी पूँजी के भारत में अंतःप्रवेश का कोई विरोध नहीं हुआ, परंतु ज्योंही भारतीयों के स्वामित्व के उद्योग धीरे धीरे विकसित होने लगे और भारतीयों को विदेशी पूँजी के एकाधिकार के दुष्प्रभाव का पता चलना गया, त्योंही विदेशी पूँजी के विरुद्ध आलोचना की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीयों का एक वर्ग तो अब भी विदेशी पूँजी के उपयोग के पक्ष में था, परंतु बहुमत उसका तीव्र विरोधी था।¹³ राष्ट्रीय दृष्टिकोण में परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण दादाभाई नौरोजी है, जो पहले विदेशी पूँजी के प्रबल समर्थक थे परंतु कालांतर में उसके तीव्र आलोचक तथा प्रखर विरोधी बन गए।¹⁴ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ विदेशी पूँजी के निवेश के समर्थक अनेक भारतीय नेताओं ने उसके कुछ विशेष पहलुओं की निंदा की, वहाँ उसके विरोधी उससे होने वाले कुछ लाभों में सहमत थे। बहुमुख्य राष्ट्रवादी नेताओं का यह जटिल व डावाडोल दृष्टिकोण उनके मत की वास्तविकता में प्रायः असंबद्ध और कभी कभी तर्कहीन बना देता था। यह बात अवश्य है कि 1905 तक उन्होंने विदेशी पूँजी की तत्कालीन और आने वाले वर्षों में निभाई जानेवाली भावी भूमिका के संबंध में सशक्त और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी।

विदेशी पूँजी के उपयोग के समर्थक भारतीय नेताओं के एक वर्ग के समर्थन का आधार यह था कि भारत जैसा निधन देश अपनी देशी पूँजी से अपने नए उद्योगों का उपक्रम करने में असमर्थ है अतः उसे अपने उद्योगों और यानायात के माधनों के विकास तथा इसके फलस्वरूप अपने लोगों की भौतिक दशा को उन्नत बनाने के लिए निश्चित रूप से ही विदेशी पूँजी की जरूरत है।¹⁵ अमृतबाजार पत्रिका ने अपने 23 फरवरी 1903 के अंक में तो यह मत प्रकट किया वर्तमान परिस्थितियों में विदेशी पूँजी के अंतःप्रवाह का विरोध मूर्खतापूर्ण तथा आत्महत्या जैसा काम है। यह आशा की जानी थी कि विदेशी उद्यम एक उदाहरण और एक आदर्श का काम करते हुए स्वदेशी उद्योग और व्यापार को प्रेरणा प्रदान करेगा।¹⁶ इसमें वस्तुतः ही भारतीय उद्यमियों के लिए शिक्षक का कार्य करने की अपेक्षा की गई थी।¹⁷ राष्ट्रीय नेताओं के इस वर्ग का विश्वास था कि

ब्रिटिश निवेशकों को भारत में अपनी निधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए¹⁶ तथा भारतीयों को उन्हें ब्याज अथवा लाभों के भुगतान का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि मूलतः यह भुगतान उन मसाधनों की आय से ही किए जाते हैं जो विदेशी पूँजी के अभाव में अविकसित ही रह जाते।¹⁷

बहुसंख्यक भारतीय नेता विदेशी पूँजी के उपयोग के विरुद्ध थे। वे यह भी नहीं मानते थे कि उसके लाभदायक प्रभाव विपरीत परिणामों में बदलकर थे। उनके विश्वास का प्रारम्भिक तर्क यह था कि रेलें, नहरें, खानें, बागान और फैक्ट्रियाँ खोलने के रूप में उद्योगीकरण के अथवा भौतिक ससाधनों के विकास से देश की राष्ट्रीय संपत्ति और समृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव को, उद्योगीकरण की परिस्थितियों में और उनसे लाभान्वित होने वाले वर्ग के प्रश्न में पृथक् करके नहीं देखा जा सकता।¹⁸ उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय ससाधनों के विकास में अधिकांशतया योगदान विदेशी उद्यम का होने के कारण इस विकास के फलस्वरूप होने वाले लाभों में विदेशी पूँजीपति ही कृतार्थ होते थे तथा वे ही सारे उत्पादित अतिरिक्त धन को हड़प कर लेते थे।¹⁹ अतः कुछ एक थोड़े से आकस्मिक लाभ को छोड़कर विदेशी पूँजी का देश की समृद्धि में तथा देशवासियों की आर्थिक स्थिति के सुधार में न कोई योगदान था और न हो सकता था।²⁰ उनकी मान्यता थी कि वास्तव में विदेशी उद्यम न भारतीय जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को विदेशी पूँजीपतियों का निस्सहाय मजदूर बनाकर रख दिया था।²¹ इस प्रकार यह भारतीयों को अपने गारे मालिकों के कुलियों की अवस्था में ला रहा था।²² विदेशी पूँजी में भारतीय मसाधनों के विकास का वास्तविक अर्थ केवल उनका अविकसित ही नहीं था, प्रत्युत उन मसाधनों की लूट और शोषण भी था।²³ विदेशी पूँजी का भारत की समृद्धि का साधन बनना तो दूर रहा, वह उलटे असदिग्ध रूप से देश की बढ़ती हुई दरिद्रता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी।²⁴ अतएव विदेशी निवेश का और अधिक विस्तार वस्तुतः देश के विनाश की ही गति देगा और भारत को सदाई रूप से विदेशी पूँजी पर निर्भर रहने वाला बना देगा।²⁵ उनके अनुसार विदेशी पूँजी का नियोजन न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, प्रत्युत भावी भविष्य के लिए भी एक विकट आर्थिक और राजनीतिक खतरा उपस्थित करेगा, अतः इसमें देश को और भी अधिक सावधानी तथा सतर्कतापूर्वक बचाना चाहिए।²⁶ विपिनचन्द्र पाल ने विदेशी पूँजी के विरोध को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया है :

विदेशी, अधिकांशतः ब्रिटिश, पूँजी का देश के प्राकृतिक ससाधनों के विकास में विनियोजन वस्तुतः देशवासियों की आर्थिक दशा के वास्तविक सुधार में सहायक न होकर उलटे इस दिशा में एक बड़ी भारी और भयकर बाधा ही सिद्ध हुआ है। विदेशी पूँजी द्वारा देश का यह शोषण यहां की सरकार और जनता के लिए समान रूप से ही विनाश का खतरा उपस्थित करता है। ... यह जितना बड़ा राजनीतिक खतरा है उतना ही भयकर आर्थिक खतरा है। नव भारत के भविष्य की सुरक्षा इस दोहरे खतरे का शीघ्र और मूलभूत उपचार करने में ही है।²⁷

वास्तव में विदेशी पूँजी के विरोधियों की यह मान्यता थी कि केवल अपने आप

भारतीय पूँजीपतियों द्वारा औद्योगिकता की प्रक्रिया के उपक्रम और विकास किए जाने पर ही देश का वास्तविक आर्थिक विकास और सुधार संभव था; विदेशी पूँजीपति इस कार्य के संपादन में असमर्थ थे।¹⁰ जी० एस० अय्यर ने 1901 में कहा 'आधुनिक काल के अथवा प्राचीन काल के ऐसे किसी देश का कोई एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं जहाँ शासक जाति के हाने के नाते सभी संभव राजनीतिक और सामाजिक सुविधा प्राप्त विदेशी पूँजीपतियों ने शासित प्रदेश के लोगों की औद्योगिक समृद्धि में सहायता की हो।'¹¹ उन्होंने तो साथ में यह भी कहा, 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपने देशवासियों को ही अच्छे माल का उत्पादन अपने हाथ में लेने के योग्य बनाने के लिए शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने से देश में कुशल से इतर संपत्ति का उपार्जन किया जा सकता है।'¹²

आलोचकों की दृष्टि में विदेशी पूँजी अपने मूल में राष्ट्रविराधी थी, की क्योंकि यह भारतीय पूँजी की सहायता करने तथा उसे प्रोत्साहित करने के बदले उलटे खदेड़ कर उसे कुचल रही थी।¹³ विदेशी तकनीक अथवा मशीनरी की अपेक्षा न रखने वाले तथा भारतीयों के माँग व्यापार के स्वतंत्र अधिकारक्षेत्र बैंक जैसे व्यवसायों से भी विदेशी उद्यम भारतीय उद्यम को जबरदस्ती बाहर धकेल रहा था।¹⁴ भारतीय उद्यमी विदेशी पूँजीपतियों द्वारा अपना मार्ग अवरुद्ध हो पाते रहे हैं।¹⁵ जिस प्रकार अप्रतिबंधित विदेशी आयातों ने पहले भारत के शहरी उद्योगों को नष्ट किया है, उसी प्रकार अब विदेशियों के स्वामित्व के उद्यम ग्रामीण हस्तशिल्पों को नष्ट-भ्रष्ट करने में लगे हैं।¹⁶ विदेशी उत्पादनों की देश के उत्पादनों के साथ प्रतियोगिता और भी अधिक भयंकर है क्योंकि वह देश के मूल धर्म पर निर्भर है। समालोचकों का उन लोगों को जो यह मानते थे कि विदेशी पूँजी के अभाव में अविश्वसनीय रह जानेवाले माधनों के विदेशियों द्वारा विकसित किए जाने में कोई हानि नहीं, उत्तर था कि यह हानि आनेवाली पीढ़ियों को ही दिखाई पड़ेगी। कालान्तर में काफी वर्षों के बाद जब भारतीय पूँजी की विपुल राशि के निवेश तथा संचालन की स्थिति में हो जाएंगे तब उस समय उन्हें पता चलेगा कि औद्योगिक उद्यमों के बहुत सारे क्षेत्र विदेशियों ने पहले ही बुरी तरह से अपने अधिकार में कर रखे हैं और इस दिशा में नए उद्यमों के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार आज के क्षुद्र लाभों के लिए सारा भविष्य अधिकारमय हो जाएगा। अतः उनका बयान था कि इसकी अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि वर्तमान पीढ़ी को भी यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह स्थाई रूप में भारत के औद्योगिक क्षेत्र को पराधीन करने के रूप में देश के भविष्य और स्थाई लाभों का बलिदान कर दे।¹⁷ उन्होंने लार्ड कर्जन की इस टिप्पणी का भी तर्कपूर्वक विरोध किया 'सारा औद्योगिक और व्यापारिक विश्व एक प्रकार का क्षेत्र है, जिस पर कृषक का कृषि करनी है, और यदि स्थानीय व्यक्ति अपनी कुदाली में उस खेत की जुताई नहीं करना तो उसे अपने हल के साथ उसके खेत को जोतने के लिए आने वाले बाहरी व्यक्तियों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं।'¹⁸ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र, अधिकृत अथवा अनधिकृत, भारतीयों का ही है, किसी अन्य का नहीं,।¹⁹ और पूछा .

यदि बाइमराय के तर्क सही हैं तो हम जानना चाहेंगे कि फिर आस्ट्रेलिया और

दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध, अमरीका में चीनियों के विरुद्ध, इंग्लैंड में अमरीकी पूजीपतियों के आगमन के विरुद्ध तथा ब्रिटेन द्वारा अपने पूर्ण एकाधिकार के रूप में स्वीकृत बाजारों में सस्ते माल के प्रवाह के विरुद्ध विस्फोट के क्या कारण हैं ? यहां तक कि स्वयं लार्ड कर्जन ने अमरीकी तेल कंपनी को बर्मा की तेल खानों में काम करने की अनुमति क्यों नहीं दी ? क्या इन सबके कारण वही नहीं हैं जिनके लिए हमारे देशवासी विदेशी शोषण के विरुद्ध आपत्ति करते आ रहे हैं ?³⁸

वस्तुतः विदेशी पूजी के इन विरोधियों ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि भारत में विदेशी पूजी के निवेश के बिना औद्योगिक विवास संभव नहीं होगा।³⁹ वे इस विडंबना में सहमत नहीं थे कि या तो विदेशी पूजी का उपयोग कीजिए, अन्यथा पूजी से सर्वथा वंचित रहिए। उनके अनुसार वास्तविक विकल्प विदेशी और स्वदेशी पूजी के मध्य है। उनके अनुसार स्वदेशी पूजी का उदय और उसकी प्रौढ़ता प्राप्ति समय सापेक्ष भले ही हो परंतु विदेशी पूजी का आगमन और प्रयोग सचमुच ही उसे अपनी पूजी से या तो वंचित कर देगा या उसके उदय को विलंबित करेगा।⁴⁰

विदेशी पूजी के आलोचकों द्वारा विदेशी पूजी के प्रयोग के विरुद्ध प्रस्तुत तर्क यह था कि वह देश की रूची की देश के बाहर निकासी करती है क्योंकि विदेशी उद्यमी केवल अपनी पूजी के ब्याज की राशि ही नहीं प्रत्युत सारे ही लाभ भारत से बाहर भेज देते थे।⁴¹ उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विदेशी पूजी के निवेश ने संयुक्त राज्य अमरीका अथवा इंग्लैंड अथवा अन्य स्वतंत्र देशों में संबंधित राष्ट्रों और देशवासियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाए हैं। उन राष्ट्रों को इन लाभों के मूल्य के रूप में केवल पूजी का ब्याज ही देना पड़ा है।⁴² परंतु उन्होंने संकेत किया कि भारतीय लोगों को अपनी विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस विदेशी पूजी से कोई लाभ नहीं हो पाता। वस्तुतः इसके विपरीत उन्हें इससे हानि ही उठानी पड़ती है। वे विशिष्ट परिस्थितियां कौन सी थी, उनका विवरण इस प्रकार है

प्रथम, विदेशी पूजी का आयात स्वेच्छाप्रेरित नहीं था, वह विदेशी शासन के कारण बलपूर्वक लादा हुआ था। ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष प्रमाण, ऊंचे कराधान तथा विपुल सामग्री की निकासी दश की पूजी का बहुत बड़ा भाग स्वायत्त कर लेते थे, अतः देशवासियों के पास नाममात्र की पूजी अवशिष्ट रह पाती थी। इस स्थिति में पूजी की क्रमिक वृद्धि की संभावना लगभग असंभव थी। भारतीय पूजी की विरलता के कारण नए औद्योगिक क्षेत्रों के उपक्रम नहीं किए जा सकते थे अतः विदेशियों ने आकर इनपर अपना अधिकार कर लिया। प्रथम तो इस तरीके से भारतीय उद्यमियों के मार्ग में बाधा डाली गई और उसके उपरांत आर्थिक आवश्यकता का बहाना करके देश पर विदेशी पूजी बलपूर्वक थोप दी गई।⁴³ इस प्रकार भारतीय नेताओं का मतव्य था कि विदेशी पूजी भारत में इस देश की पूजी की वृद्धि के लिए नहीं, प्रत्युत उसके ह्रास के लिए, उसकी सेवा के लिए नहीं, प्रत्युत उसे अपने अधीन बनाने के लिए; इसके विकास के लिए नहीं, प्रत्युत इसके साधनों के अपहरण के लिए ही आई है।

द्वितीय, आलोचकों ने निर्दिष्ट किया कि विदेशी पूजी भारतीय पूजी को विस्थित

कर देती है। इसका कारण यह नहीं कि विदेशी पूँजीपति आर्थिक दृष्टि से अधिक योग्य हैं अथवा भारतीय पूँजीपति सकोची दृष्टि के हैं, अथवा विदेशी पूँजीपति अधिक उत्साही-साहसी हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा विदेशी पूँजी को आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, सभी प्रकार की रियायतों से उसकी सहायता की जाती है, उसे सभी प्रकार के प्रलोभन और विशिष्ट सुविधाएँ दी जाती हैं। उदाहरणार्थ लाभों की गारंटी, मुफ्त अथवा सस्ते दाम पर भूमि, उमके हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक तथा सांविधानिक उपाय आदि। इसके विपरीत स्वदेशी पूँजीपतियों को निरुत्साहित किया जाता है, उन्हें सभी साधनों से वंचित किया जाता है तथा उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार स्वदेशी और विदेशी पूँजी में न्यायोचित तथा समता के आधार पर प्रतियोगिता नहीं है। विदेशी पूँजीपति भारतीय पूँजीपतियों के मुकाबले अनुचित सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं।¹⁴

तृतीय, आलोचकों का तर्क था कि जहाँ अन्य देशों में विदेशी पूँजी के, विदेशी निधि के आयात द्वारा उस देश की पूँजी के आंतरिक मशीनी साधनों के विकास में सहायक होने से दोष किसी सीमा तक सतुलित हो जाते थे, वहाँ भारत में विदेशी पूँजी का निवेश इन देशों में विदेशी निधि का आयात नहीं करता था, क्योंकि इस देश में विदेशी पूँजी का प्रवाह स्वाभाविक न होकर अप्राकृतिक ही था। वस्तुतः इस देश में विदेशी निवेशकों ने अपने देश के साधनों से पूँजी संचित नहीं की, प्रत्युत भारत की पूँजी की ही प्रथम विदेशियों द्वारा नियंत्रित व्यापारों, बैंकों, उद्योगों तथा प्रशासनिक व्यय के माध्यम से विदेशों में निकासी हुई और पुनः उसका कुछ अंश निवेश पूँजी के रूप में लौटकर भारत आ गया। राष्ट्रीय खानों की दृष्टि से समीक्षा करने पर सारा कार्य व्यापार वाणिज्य पर अकांक्षित कोरा खेल तमाशा था।¹⁵ देश के व्यापार खाते के अध्ययन में यह भी स्पष्ट हो जाता था कि भारत वास्तविक विदेशी निधि का आयात नहीं करता था। दादाभाई नौरोजी ने 1887 में मकेत किया था कि यह स्मरणीय है कि भारत के शुद्ध आयात में सभी विदेशी ऋणों और निवेशों को जोड़ देने के बाद भी उसके शुद्ध निर्यात बचचढ़कर हैं।¹⁶ इस प्रकार भारत अपनी ही पूँजी से अपने ही शोषण की अपरिहार्य स्थिति में पहुँच गया है। 'बीत' समय में भारतीयों ने अपने ही राजनीतिक दमन के लिए अंगरेजों की ज़िम्मेदार सहायता की है, उसी प्रकार आज वे अपनी ही आर्थिक उदासीनता का कार्य संपन्न करने के लिए अंगरेजों की सहायता कर रहे हैं।¹⁷ यह एक रोचक तथ्य है कि देश की पूर्वनिष्कामित संपत्ति की विदेशी पूँजी के रूप में वापसी तथा भारत के विदेशी उद्यमियों द्वारा प्राप्त लाभों के पुनर्निवेश ने बहुत सारे भारतीय नेताओं को भ्रमजाल में उलझाए रखा तथा विदेशी पूँजी के प्रति आंतरिक रूप से असंगत प्रतीत होने वाली स्थिति को भी स्वीकार करने के लिए विवश किया। एक ओर उन्होंने विदेशी पूँजी के लाभों के निर्यात का विरोध किया तथा दूसरी ओर इन लाभों के पुनर्नियोजन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इससे स्वतः ही लाभों की राशि में वृद्धि हो जाती थी और उसका परिणाम भविष्य में संपत्ति का निष्कासन था।¹⁸ भारतीय नेताओं की यह असंगति उनकी गलत चिंतन प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक प्रकार में स्वाभाविक ही थी। उन्होंने इस जटिल प्रक्रिया को जो

कि आंतरिक विसंगतियों से परिपूर्ण थी, सही तौर पर व द्वंद्वात्मक रूप से समझा।⁴⁹ उनका कथन था कि विदेशी पूँजी में अर्जित लाभों के पुनर्निवेश ने धन की स्वतः विस्तृत होने वाली तथा कभी समाप्त न होने वाली निकासी की प्रक्रिया को जन्म दिया था। 1887 में दादाभाई नौरोजी ने लिखा, 'सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत की संपत्ति बाहर ले जाई जाती है और फिर उसी संपत्ति को ऋणों के रूप में यहां वापस लाया जाता है और फिर उन्हीं ऋणों पर ऊँचा ब्याज वसूल किया जाता है। इस प्रकार यह सारा दुश्चक्र अत्यंत घृणित तथा उत्तेजक रूप में चल रहा है।'⁵⁰ इसके फलस्वरूप इस समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण भी द्वंद्वात्मक था। उनके अनुसार चुनाव का प्रश्न विदेशी पूँजी की स्वीकृति अथवा उसे सहन करने में, तथा लाभों के निर्यात अथवा उनके पुनर्निवेश से ही संबंधित नहीं था, बल्कि दुश्चक्र के साथ गतिशील बन रहने और संपत्ति की निकासी को रोकने और औद्योगिक विकास के लिए स्वदेशी संपत्ति पर निर्भर रह कर इस दुश्चक्र को गतिशून्य करने का था। इस प्रकार दोनों रोगों में बचाव किया जा सकता है।

भारतीय नेताओं ने इस ओर भी संकेत किया कि विदेशी पूँजी की सहायता से भारत के विकसित होने वाले नए साधनों के लाभ अनंत सीमित थे क्योंकि यह अपनी विशिष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण देश की विशाल जनसंख्या के एक छोटे से भाग के लिए ही अतिरिक्त आजीविका जुटाती है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय मजदूरी निर्धन साधारण सी वृद्धि होती है।⁵¹ आजीविका की इस तुच्छ वृद्धि का प्रमुख भाग विदेशी उद्यमों के निर्माण तथा संचालन में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित तथा उच्च वेतन-भोगी अधीक्षक पदों पर एकाधिकार किए विदेशियों के पास चला जाता है।⁵² दुर्भाग्यवश राज्य व्यवसायों की भी बराबर यही स्थिति थी।⁵³ यह तथ्य भारतीयों को न केवल उनके न्यायमग्न अतिरिक्त आजीविका के अवसरों में वंचित करना था तथा उपभोग में वृद्धि करता था,⁵⁴ प्रत्युत अन्य अनेक महत्वपूर्ण तथा दूरगामी बुराइयाँ भी पैदा करता था। बहुत सारे विदेशी भागन को पूँजी के संचय और निवेश के लाभप्रद साधनों से वंचित करते हुए, अपने वेतन का बड़ा भाग विदेश में भेज देते थे।⁵⁵ इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी के विनियोग भारतीयों को औद्योगिक तकनीक और व्यापार संचालन में उन्नत प्रशिक्षण से वंचित करते थे। इस प्रकार विदेशी पूँजी का एक सगर्व घोषित लाभ व्यवहारतः उपलब्ध ही नहीं था तथा एक समृद्ध औद्योगिक व्यवसाय से लोगों को प्राप्त होने वाली शिक्षा और जानकारी सर्वथा अनुपलब्ध थी।⁵⁶ इसके साथ साथ नवीन आर्थिक नियोजन भी भारत में नहीं किए जाते थे प्रत्युत विदेशी उद्यमों की घरेलू व्यवस्था द्वारा स्वयं निवेशकों के अपने ही देश में किए जाते थे।⁵⁷ विदेशी पूँजी के आलोचकों की एक अन्य शिकायत यह थी कि यदि थोड़े बहुत भारतीयों को कुलियों और अकुशल मजदूरों के रूप में विदेशियों के अधीनस्थ बागों, खानों, फैक्ट्रियों तथा रेलवे में नौकरी मिलती भी है तो वहाँ उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। बहुतों को तो शोचनीय रूप में एक या दो आने प्रतिदिन के हिसाब से काम करना पड़ता है, जिससे वे अपना दुर्भाग्यग्रस्त जीवन भी नहीं जी पाते।⁵⁸ यह स्थिति भारतीयों को सचमुच ही जीवन्मृत श्रमिकों के स्तर पर ला रही है⁵⁹ तथा इस देश को 'पानी खींचने वालों का', 'लकड़ी काटने वालों का'⁶⁰ का और इससे भी

बढ़कर 'दासों का' देश बना रही है।⁶¹ भारतीयों को अपने ही देश में श्रीतदास की स्थिति से संतुष्ट होना पड़ता है।⁶² दादाभाई नौरोजी का कथन था कि 'वास्तव में वे तुच्छ दासों के रूप में ही कार्य करते थे। ब्रिटिश पूजीपतियों को अपने उत्पादन सौपने के लिए उन बेचारों ने अपनी ही घरती और अपने ही साधनों को पराधीन कर रखा था।'⁶³ फिर भी कुछ एक आलोचक आजीविका के नए साधनों को जन्म देने के लिए विदेशी पूँजी के स्वागत को तैयार थे परंतु वे इस दिशा में स्पष्ट सूचित करते थे कि इससे देश का वास्तविक आर्थिक विकास कदापि संभव नहीं।⁶⁴ उन्होंने यह भी स्पष्ट सूचित किया कि विदेशियों से मजदूरी के रूप में मिलने वाले इस तुच्छ वेतन से भारतीय सदा के लिए संतुष्ट नहीं रहेंगे। एक दिन वे निश्चित रूप से सदा के लिए कुली और मजदूर बनाए रखने की प्रवृत्ति के प्रति विरोध प्रकट करेंगे।⁶⁵

विदेशी पूँजी के विरोधियों ने यह मत भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया कि भारतीयों को मजदूरी के रूप में मिलने वाला पारिश्रमिक उनके संसाधनों के शोषण⁶⁶ तथा स्वदेशी उद्योग धंधों के विनाश⁶⁷ के परिप्रेक्ष्य में किसी भी कमीटी पर कमने पर सर्वथा तुच्छ तथा अपर्याप्त था। प्राकृतिक उपज संबंधी उद्योगों के संवध में तो यह स्वतः मिथ्या गण्य था। बागान उद्योगों के विषय में भी यह पर्याप्त अंशों में सत्य ही था। समालोचकों ने स्थिति को इस मंदर्भ में प्रस्तुत करने हुए अपना मत प्रकट किया कि खान उद्योगों का विदेशियों द्वारा शोषण एक अत्यधिक गंभीर प्रश्न है क्योंकि खानों से निकलने वाली सामग्री के चुक जाने पर उनको फिर से चालू करना संभव ही नहीं है।⁶⁸ विदेशियों द्वारा लूटे जाने की अपेक्षा अच्छा यही है कि खानों की संपदा खानों में ही दबी तथा अविकसित बनी पड़ी रहे ताकि कालांतर में भारतीय स्वयं उसका सदुपयोग कर सकें।⁶⁹ आलोचकों का कथन था कि एक वास्तविक भारतीय सरकार से कम से कम इतने आवश्यकता की अपेक्षा तो की जा सकती थी।⁷⁰ इसी प्रकार बागान उद्योग भी घरती की उर्वरता को समाप्त करते जा रहे थे।⁷¹ इन उद्योगों के संबंध में तो जी० वी० जोशी की टिप्पणी यह थी कि इनके द्वारा भारतीयों के प्रति अतिरिक्त अन्याय हुआ है क्योंकि प्रथम, राज्य ने सरकारी व्यय से अधिकांश बागान का विकास किया है और पुनः क्षतिपूर्ति किए बिना ही ये उद्योग विदेशियों को सौंप दिए गए हैं। उन्हें यहां पर भूमि भी नाममात्र की दरों पर दी गई है। वस्तुतः इन उद्योगों पर बहुत थोड़ी भी ही विदेशी पूँजी का निवेश हुआ है। ये उद्योग सामान्य रूप से भारतीय उद्यमियों को ही सुविधापूर्वक सौंपे जा सकते हैं।⁷²

भारतीय नेताओं की दृष्टि में विदेशी पूँजी के प्रयोग में उत्पन्न होने वाले आर्थिक खतरे के साथ साथ राजनीतिक खतरा भी था।⁷³ इस आलोचनापरक दृष्टिकोण का आधार यह विश्वास था कि विदेशी पूँजी द्वारा किसी देश में घुसने का अर्थ उस देश का राजनीतिक दमन है अथवा जिस प्रकार रानाडे ने कहा : व्यावसायिक तथा उत्पादन विशिष्टता स्वभावतः ही राजनीतिक प्रभुत्व में परिवर्तित हो जाती है।⁷⁴ यह सकारण संबंध इस तथ्य से भी सिद्ध था कि विदेशी पूँजी समय के साथ साथ निहित स्वार्थों, एक प्रबल विदेशी अभिजात तंत्र, को जन्म देती है⁷⁵ जो देश की प्रशासनिक नीतियों पर निरंतर बढ़ने वाले प्रबल प्रभाव को दृढ़ बनाने का कार्य करता है।⁷⁶ 'हिंदू' ने अपने 23 सितंबर

1889 के अंक में लिखा कि जिस देश में विदेशी पूँजी लगने लगती है, उस देश का प्रशासन तत्काल समृद्ध तत्वों के हाथ में चला जाता है।

भारतीय नेताओं की चिन्ता यह थी कि भारत जैसे पहले से ही विदेशी प्रशासन में अधिकृत देश में यह राजनीतिक खतरा और कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति में विदेशी निहित स्वार्थों में प्रेरित होकर देशवासियों की न्यायोचित राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं तथा उनकी राजनीतिक उन्नति के मार्ग का रोड़ा बनते हैं।⁷⁷ 23 सितंबर 1889 के अंक में हिंदू ने विलक्षण राजनीतिक दूरदर्शिता से यह भविष्यवाणी की कि यदि राजनीतिक सुधारों की अवधि में देश में विदेशी पूँजीपतियों के प्रभाव को बढ़ने दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सफलता के अवसरों को नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्वर विदेशी पूँजीपतियों के, 'साम्राज्य खतरे में है', के भयकर गर्जन में दबकर रह जाएगा।⁷⁸ कालांतर में जब कर्जन के शासनकाल में राजनीतिक प्रतिक्रिया इतनी अधिक उग्र हो गई कि उम्मेदगम प्रत्येक भारतीय जन नेता अनुभव करने लगा, तब मुरेद्रनाथ बैनर्जी के 'बंगाली' ने अवसरान्वित टिप्पणी की इस प्रतिक्रिया का मूल भारत में विदेशी पूँजी द्वारा प्रयुक्त प्रभाव ही है।⁷⁹ तथ्यात्मक दृष्टि में देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भारतीय नेताओं ने यह भली प्रकार समझ लिया था तथा स्पष्ट निश्चय किया था कि भारत सरकार और भारत के ब्रिटिश पूँजीपतियों में साठ-गाठ है तथा भारत सरकार ब्रिटिश पूँजीपतियों के हितों के अधीन है। इस दृष्टिकोण को 1903 में उस समय शचींद्रनाथ सिन्हा द्वारा मर्पादित, दनादावाद के 'इंडियन पीपुल' ने बड़ी स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया।

लार्ड कर्जन के साक्ष्य पर अंगरेजों का प्रशासनिक कार्य केवल शोषकों के शोषण कार्य में उनकी चाकरी करना है। बिना कुशल प्रशासन के व्यापार फल-फूट नहीं सकता और व्यापार के लाभरहित होने पर प्रशासन, प्रशासन नहीं कहला सकता। भारत सरकार सदैव वाणिज्यमदन की स्वीकृति तथा अधिकांशतः उसके आदेश के अनुसार ही कार्य करती है और यह गोरों के 'दायित्व' का रहस्य है।⁸⁰

और यहाँ तक कि रानाडे ने भी टिप्पणी की कि विदेशी आर्थिक प्रभुत्व ने विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व को और अधिक द्वेषजनक बना दिया है।⁸⁰

बहुत सारे भारतीय नेता समस्या के दूसरे पक्ष में भी अभिज्ञ थे कि यह मूलतः विदेशी शासन ही था जिसके कारण इस देश में विदेशी पूँजी ने एक बड़े भारी रोग का रूप ले लिया। यदि भारत एक स्वतंत्र देश होता, तो वह अमरीका जैसे अन्य स्वतंत्र देशों के समान संपत्ति की निकासी में मुक्त होता, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने ससाधनों के विकास के लिए स्वतंत्र होता, समान शर्तों पर विदेशी पूँजी से प्रतियोगिता के लिए स्वतंत्र होता, विदेशी पूँजी से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसे अपदस्थ करने में स्वतंत्र होता तथा उसका एक ऐसा स्वतंत्र प्रशासन होता जो स्वदेशी उद्यम को सहायता तथा प्रोत्साहन देता और यह देखता कि विदेशी पूँजी का प्रयोग स्वदेशी उद्यम के विकास में पूरक और सहायक सिद्ध हो।⁸¹

अधिकांश भारतीय नेता विदेशी पूँजी के नियोजन के राजनीतिक तथा आर्थिक

प्रतिघातों के अध्ययन के परिणामस्वरूप इस तथ्य पर सहमत थे कि भले ही भारत को विदेशी पूँजी की आवश्यकता हो परन्तु उसे विदेशी पूँजीपतियों की तो कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने ऋण पूँजी तथा औद्योगिक पूँजी के अंतर को समझा था तथा उसे रेखांकित किया था।¹² जहाँ औद्योगिक पूँजी उद्यम के सारे लाभों को हड़प लेती है तथा सारे क्षेत्र पर एकाधिकार जमा लेती है।¹³ वहाँ ऋण-पूँजी ब्याज के रूप में केवल एक निश्चित तथा निर्धारित राशि की ही अधिकारी होती है। इस प्रकार वह अवशिष्ट लाभों, और मूल धन की अदायगी के पश्चात्, सारे लाभों को उम देश में ही रहने देती है। इस प्रकार आवश्यकता होने पर स्वदेशी उद्यम के विकास के लिए विदेशी पूँजी उधार लेना तथा विदेशी तकनीकी लोगों से काम लेना तो बुरा नहीं, परन्तु सीधे विदेशी निवेश की तथा सीधे विदेशी पूँजीपतियों द्वारा अपने स्वामित्व के उद्योग के संचालन को अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए।¹⁴ दादाभाई नौरोजी का कहना था कि भारत को विदेशी पूँजी की उत्कट आवश्यकता है न कि उसकी पूँजी और उत्पादकों को हड़पने वाले अंगरेजी धावे की।¹⁵

इस दृष्टिकोण में दो दोष थे। भारतीय पूँजीपतियों के पास अधिकांश बड़े पैमाने के नए उद्योगों, खानों तथा परिवहन संस्थानों के संचालन के लिए न तो पर्याप्त पूँजी थी और न ही विदेशी पूँजी-बाजार में वांछित निधि के ऋण देने की अपेक्षित साख। इस स्थिति में विदेशी पूँजीपतियों को व्यक्तिगत रूप से इस देश में आने तथा अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र का स्वामित्व सम्भालने में किस प्रकार रोक जा सकता था? इस समस्या का राष्ट्रीयकरण के रूप में एक सर्वथा नवीन उत्तर देने के लिए 19वीं शताब्दी के प्रमुखतम नेता, दादाभाई नौरोजी तथा जी० वी० जोशी आगे आए। उन्होंने 60 वर्ष पीछे स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग का अपनी उल्लेखनीय सूक्ष्म दृष्टि से उस समय ही देख लिया था। उनका मुँभाव था कि विदेशी पूँजी के हानिप्रद आर्थिक तथा राजनीतिक दुष्परिणामों में बचकर उमंगे लाभान्वित होने का एकमात्र उपाय उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण था, जिनके लिए अपरिमित विदेशी धनराशि अपेक्षित थी। इस प्रकार की स्थिति में सरकार अपने राजस्वों की गारंटी पर ब्याज की थोड़ी दर पर विदेशों से पूँजी ऋण में ले सकती है तथा उसका देश के प्राकृतिक समाधनों के विकास के लिए उपयोग कर सकती है।¹⁶ यहाँ यह बनी प्रकार समझ लेना चाहिए कि उस समय राष्ट्रीयकरण की कल्पना केवल विदेशी पूँजीपतियों के प्रवेश को रोकने के उपाय के रूप में की गई थी। इसके सिवाय उसका समाजवाद के प्रवर्तन जैसा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सरकारी पूँजीवाद तब तक के लिए एक अंतरिम तथा अस्थायी उपाय था जब तक कि भारतीय उद्यमी इस पर्याप्त सीमा तक जागरूक तथा विकसित नहीं हो जाते कि इन उद्योगों को स्वदेशी पूँजीपतियों के हाथों में ही सौंपा जा सके।¹⁷

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन से हम इन परिणामों पर पहुँचते हैं : प्रथम, विदेशी पूँजी के उपयोग के समर्थक अथवा विरोधी भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारत में विदेशी निवेश के आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों तथा परिणामों के प्रति अत्यंत जागरूक थे। द्वितीय, सभी राष्ट्रवादी नेताओं का दृढ़ विश्वास था कि देश का वास्तविक औद्योगिक विकास देश के अपने प्रयत्नों तथा अपनी पूँजी पर निर्भर था। विदेशी पूँजी के प्रयोग के समर्थकों का

भी स्पष्ट मत यह था कि देश के सर्वथा अनुद्योगीकरण जैसी अपेक्षाकृत बड़ी बुराई की तुलना में उद्योगीकरण के लिए विदेशी पूँजी के निवेश की छोटी बुराई अपनाना ही अच्छा है। अधिकांश नेता तो विदेशी पूँजी के साधन द्वारा देश के औद्योगिक विकास के निष्पादन की अपेक्षा उसके स्थगन के ही पक्षधर थे। इस प्रकार समीक्षाधीन काल के राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में दलाल पूँजीवादी के दृष्टिकोण का न्यूनाधिक रूप में अभाव ही था। यहाँ यह भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादियों ने समवेत स्वर में औद्योगिक पूँजी के विकास का समर्थन किया था, न कि व्यापारिक पूँजी के विकास का। तृतीय, विदेशी उद्योगों के द्रुत विस्तार के कारण रेलवे आदि ने परोक्ष रूप में भारतीय उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया था। दोनों में शत्रुता अभी महत्वपूर्ण अथवा निर्णायक नहीं बन पाई थी। उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रश्न पर पूर्णतः मौन ही रही। 1885-95 की अवधि के अधिवेशनों में उसने इस प्रश्न पर न तो विचार विमर्श किया और न ही इस पर कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही सभापति पद में दिए गए किसी भाषण में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ। इस विषय पर कांग्रेस की ओर से प्रथम भाषण 1898 के अधिवेशन में जी० एम० अय्यर का था। हाँ, 20वीं शताब्दी के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक प्रयास बाल्यकाल में आगे बढ़ने लगे तथा विदेशी पूँजीपतियों में, जिन्हें अपने उद्यम का लाडल कर्जाने जैसा प्रबल उन्माद तथा शक्तिशाली वकील मिल चुका था, संघर्ष करने लगे। इसके फलस्वरूप 1900 के पश्चात् राष्ट्रवादी ममाचारपत्र तथा कांग्रेस मंच से वक्ता विदेशी पूँजी पर निरंतर तीव्र प्रहार करने लगे।

राज्य की भूमिका

भारतीय उद्यमी वर्ग के ज्ञान, शक्ति तथा पूँजी के अभाव की तथा उद्योगीकरण के मार्ग की प्रारंभिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सुरक्षा तथा सहायता के अभाव की पूर्ति राज्य की सहायता और सहयोग में ही कदाचित् संभव थी। अतः भारतीय नेता उद्योगीकरण की प्रक्रिया में राजकीय सहायता के प्रखर समर्थन में न्यूनाधिक रूप में एकमत ही थे।⁸⁸ उनका यह दृढ़ विश्वास था कि औद्योगिक प्रयास के प्रत्येक क्षेत्र तक प्रसृत सरकारी सहायता की व्यापक नीति के बिना तथा स्वदेशी तथा आधुनिक दोनों औद्योगिक उद्यमों की प्रत्येक रूप और दिशा में प्रगति संबंधी सरकार की प्रत्यक्ष, सूझबूझवाली तथा सहानुभूतिपूर्ण नीति के बिना देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। यद्यपि भारतीय अर्थशास्त्री नेताओं ने इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण सरकार के सामने काफी देर के बाद प्रस्तुत किया तथापि देश के उत्पादकों और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की मांग को सर्वप्रथम 1853 में कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा के नवीकरण के समय हाउस आफ कॉमंस को निवेदित प्रज्ञप्ति में प्रस्तुत किया।⁸⁹ 1891 में पूना में आयोजित द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन में निजी उद्योग को सरकार द्वारा सीधे वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की मांग प्रस्तुत की गई।⁹⁰ कांग्रेस ने 1902 में स्वदेशी कला और उत्पादन के उद्धार तथा विकास के लिए तथा नए उद्योग लगाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की मांग की।⁹¹ अन्य भारतीय नेताओं में कदाचित् जी० बी० जोशी और रानाडे इस नीति के

सबसे पहले तथा मुख्य समर्थक थे।⁹² इस संबंध में जी० सुब्रह्मण्यम के शब्दों में मीजी की वापसी के बाद आधुनिक उद्योग के प्रोत्साहन में जापानी सरकार की भूमिका भारतीय अर्थशास्त्री नेताओं के लिए अत्यधिक रोचक तथा आकर्षक सिद्ध हुई⁹³ और उन्होंने भारत सरकार से इसकी प्रतिस्पर्धा करने का अनुरोध किया।⁹⁴

भारतीय राष्ट्रवादियों ने औद्योगिक प्रयासों में सरकारी हस्तक्षेप की मांग की तथा उनकी भारतीयों के स्वामित्व के उद्योगों के प्रति भारत सरकार के सैद्धांतिक और व्यावहारिक बरताव के बारे में सरकार के साथ सीधी टक्कर हुई। ब्रिटिश शासकों ने अपने को तटस्थता सिद्धान्त का अनुयायी बताते हुए उस समय यह मत अभिव्यक्त किया कि औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सरकार अयोग्य है, अतः सभी ऐसे मामले निजी उद्यमियों पर ही छोड़ देने चाहिए।⁹⁵ इस प्रकार समीक्षाधीन अवधि के दौरान उद्योगों को प्राप्त सरकारी सहायता नगण्य सी ही थी। इस सहायता के दो रूप थे - तकनीकी शिक्षा की सर्वथा अपर्याप्त व्यवस्था तथा टूटे मन से औद्योगिक जानकारी के मंचय तथा प्रसार की चेष्टा।⁹⁶ इस क्षेत्र में सरकार के और अधिक प्रत्यक्ष तथा ऊर्जस्वी योगदान की मांग करने वाले भारतीयों को अपने आपको औद्योगिक प्रयासों के प्रबल समर्थक मानने वाले लार्ड कर्जन ने बुरी नगर से दूज शब्दों में लताड़ा - वर्तमान सरकार अथवा अन्य कोई भारतीय सरकार जादू की छड़ी घुमाकर ही इस विस्तृत देश की आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक स्थितियों में त्राति ला सकती है।⁹⁷

भारतीय अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में भारत की नीति की दिशा बदलने की चेष्टा की। उनका विश्वास था कि इस नीति का दृढ़ता से पालन करने का एकमात्र कारण शासकों का क्लामिकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में विश्वास व इसका अनुसरण ही था। अतः उन्होंने तटस्थता सिद्धान्त की सरकारी कार्यक्षेत्र में व्यावहारिकता पर, विशेषतः भारत जैसे आर्थिक दृष्टि में पिछड़े देश के मद्देन, कटु सैद्धांतिक प्रहार करने आरंभ कर दिए। तटस्थता सिद्धान्त के विरुद्ध किए गए सैद्धांतिक प्रहारों का विस्तृत विवरण डग पुस्तक के एक अगले अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी महान प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री नेता गन्नाडे ने भारतीय शासकों के वर्तमान तथा भूतकालीन आचरणों को उनकी सैद्धांतिक मान्यताओं के विरुद्ध बताया। उन्होंने यह निर्देश किया कि विगत वर्षों में सरकार ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यम के प्रवर्तन तथा उन्नयन में और भारत में ब्रिटिश पूँजीपतियों को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करने में प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भाग लिया है।⁹⁸ सरकार ने सर्वप्रथम रेल कंपनियों को सरकारी तौर पर गारंटी प्रदान की और बाद में सरकारी रेलों के निर्माणकार्य को अपने हाथ में लिया।⁹⁹ सरकार ने ही भारत में सरकारी खर्च पर और बड़े महंगे दामों पर कुनीन, चाय तथा काफी के पौधे उगाने के लिए बागान उद्योगों का प्रारंभिक प्रवर्तन किया है।¹⁰⁰ सरकार ने लोहा उद्योग की उन्नति के लिए उसे अनुकूल रियायतें देने के अतिरिक्त भूगर्भीय सर्वेक्षणों, प्रयोगात्मक परीक्षणों तथा उत्पादनों के रूप में राज्य की भारी धनराशि खर्च की है।¹⁰¹ उसने अपनी इच्छा से कितनी ही कोयला खानों पर लंबे समय तक काम किया है।¹⁰² इस प्रकार

सरकारी सहायता का सिद्धांत तो व्यावहारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ममभ नहीं आता कि उसी प्रकार की सहायता अब अन्यान्य औद्योगिक उद्यमों को प्रदान क्यों नहीं की जाती? इस समय किसी नए सिद्धांत के प्रस्थापन की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत इस तथ्य के निर्धारण की आवश्यकता है कि किस प्रकार के उद्योगों को राजकीय सहायता प्रदान की जाए। गत वर्षों के समान बागान और परिवहन साधनों को बढ़ावा देने के स्थान पर अब देश में आधुनिक उत्पादक उद्योगों के प्रोत्साहन में सरकारी सहायता का और अधिक लाभदायक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।¹⁰³

उद्योग को सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के कई भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण की, जिनके आवश्यकतानुसार एकल अथवा संयुक्त रूप से ग्रहण के लिए बहुत सारे भारतीय नेताओं ने वकालत की, मक्षिप्त समीक्षा निम्न-लिखित है

भारतीयों की दृष्टि में भारत के औद्योगिक विकास की प्रबलतम बाधाओं में से एक भारतीय औद्योगिक उद्यमियों के पास अपेक्षित पूँजी का अभाव था अतः उन्होंने उपलब्ध व्यापारिक तथा साहकारी पूँजी को औद्योगिक पूँजी में बदलने के लिए सरकारी सहायता की प्रबल आवश्यकता की मांग की। इस महान कार्य के संपादन के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए थे। प्रथम, ऋण प्रणाली को आधुनिक रूप में पुनर्गठित करना होगा ताकि देश के आंतरिक परंतु बिखरे हुए उपलब्ध साधनों को गतिशील बनाया जा सके।¹⁰⁴ यह नई भी प्रस्तुत किया गया कि ऋण प्रणाली का निजी विकास ऋणदाता तथा ऋणकर्ता के आपसी विश्वास पर निर्भर है अतः उनकी प्रक्रिया का अत्यंत मद होना निश्चित ही है। देश की विशाल धनराशि की तथा मार्बंदेशिक साख और विश्वास की एकमेव पात्र होने के कारण सरकार जमा और निकामी करने वाले बैंकों को सरकारी संरक्षण अथवा गारंटी देकर बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अपनी साख तथा अभिकरण का उपयोग कर सकती है।¹⁰⁵ राज्य के निर्देशन तथा नियंत्रण में कार्य करने वाले संयुक्त पूँजी-बैंको का बहुत दृढ़ जाल बिछाने की आवश्यकता थी।¹⁰⁶ इस कार्य में सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। उसे केवल बैंको को ऋण उगाहने की सुविधाएं जुटाना, मंडलीय शेष राशि को उपलब्ध कराना तथा नियंत्रक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना है।¹⁰⁷ इससे भी अधिक अच्छा यह है कि सरकार स्वयं प्राइवेट पूँजीपतियों को अपनी उचित देखरेख में ब्याज की थोड़ी दर पर अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था करे।¹⁰⁸ इसके लिए सरकार धन उधार ले सकती है अथवा बचत खातों पर निर्भर कर सकती है।¹⁰⁹ इस संबंध में रानाडे ने एक रोचक सुझाव यह दिया कि सरकार अथवा स्थानीय समितियां विशिष्ट वित्त निगमों की स्थापना करें। ये निगम सरकार से सस्ती दर पर रुपया उधार लें तथा भावी उद्योग-पतियों को अग्रिम ऋण प्रदान करें।¹¹⁰ इसके अतिरिक्त सरकार रेल कंपनियों के प्रति अपनाई सहायता की नीति के समान आधुनिक उद्योगों के प्रति अपनी नीति निर्धारित कर सकती है तथा पूँजी जुटाने वाले भारतीयों को न्यूनतम निश्चित ब्याज चुकाने की गारंटी देकर उन्हें नए उद्योगों में पूँजी लगाने को प्रेरित कर सकती है।¹¹¹ सरकार रेलों

के समान भारतीय पूँजीपतियों को विदेशी बाजार से ऋण लेने में गारंटी दे सकती है¹¹² तथा सस्ते ऋणों की प्राप्त के प्रतिफल के रूप में सरकार औद्योगिक व्यवस्था के देखभाल और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर सकती है, कालांतर में तो लाभों की भागीदार तक बन सकती है।¹¹³ सरकार से तो इससे भी और आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार कहा गया कि सरकार जन्म और शैशवकालीन प्रारंभिक कठिनाइयों से जूझते हुए पनपने वाले उद्योगों की अनुग्रहों अनुदानों के रूप में मीधे ही सरकारी कोष से सहायता करे¹¹⁴ ताकि वे उद्योग अपनी कठिनाइयों पर काबू पा सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।¹¹⁵

भारतीय नेताओं का सरकार से दूसरा अनुग्रह सरकारी तथा रेल भंडारों की क्रय संबंधी नीति के पुनर्निर्धारण का था। भारत में आयातित कुल उत्पादन सामग्री का उल्लेखनीय भाग इन भंडारों में था। आयातित सामग्री में ये वस्तुएं सम्मिलित थीं भारतीय सेना तथा पुलिस के उपयोग के उपकरण; नगर सुधार की सामग्री, जल, गैस, मलमूत्र व्यवस्था; मैडिकल स्टोरो तथा हस्पतालो के उपयोग की सामग्री, गोदी, पुलों, बिल्डिंगो तथा मड़को के बनाने के लिए लोहा तथा मीमेंट; तार तथा टेलीफोन के लिए अपेक्षित सामान; प्रशासन के उपयोग में आने वाली स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुएं। इन सबसे बढ़कर और अधिक सामान था। रेलों की पटरिया, पुल, गाड़ी के डिब्बे तथा रेलों के लिए भवन निर्माण की सामग्री। इन मंडारों के लिए थोड़े बहुत नगण्य सामान को छोड़कर प्रायः मारा ही सामान दुर्लभ हो खरीदा जाता था। फलतः भारतीय नेताओं की शिकायत थी कि सरकार की भंडारों की क्रयनीति भारतीय उत्पादकों के प्रति विद्वेषपूर्ण थी तथा ब्रिटिश उत्पादकों को सहायता पहुंचाती थी। उनका तर्क था कि सरकार इन भंडारों के लिए भारतीय उत्पादकों में माल खरीद कर भारतीय उत्पादकों के लिए लाभदायक दरों पर न्यूनतम मुद्रास्तर बाजार की गारंटी देकर भारतीय औद्योगिक प्रयत्नों को जबरदस्त प्रोत्साहन दे सकती है।¹¹⁶ पर्याप्त रोचक तथ्य यह है कि इस मांग का समर्थन भारत में कार्यरत कुछ एक ब्रिटिश पूँजीपतियों ने भी किया और इसे 1880 के अकाल आयोग का, लार्ड रिपन की सरकार का तथा 1916-18 की अवधि के भारतीय उद्योग आयोग का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ।¹¹⁷ अंततः इसका परिणाम यह निकला कि भारत स्थित फर्मों से भी माल खरीदा जाने लगा। इसके फलस्वरूप 1898 में लखनऊ के 'हिंदुस्तान' ने सरकार की भारत स्थित भारतीयों की फर्मों की उपेक्षा तथा यूरोपीयों के स्वामित्व की फर्मों से माल खरीदने की प्रवृत्ति का विरोध किया।¹¹⁸

भंडारों की सभी वस्तुएं भारत में उपलब्ध नहीं अथवा उत्पादित नहीं होतीं इस आपत्ति का उत्तर कुछ एक भारतीय नेताओं ने और भी अधिक मौलिक सुझाव के रूप में इस प्रकार दिया कि सरकार स्वयं इन वस्तुओं का उत्पादन करे।¹¹⁹ अनेक भारतीय लेखकों ने यह सुझाव तथा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष उद्यम को अपनाने का और इस प्रकार तटस्थता की नीति के परित्याग का सुझाव एक अन्य आधार पर भी दिया। उनका सुझाव था कि नए उद्योग के प्रारंभ करने में असंख्य विषम प्रकृतितगत कठिनाइयों के कारण सरकार को आगे आना चाहिए तथा उनकी व्यावहारिक उपयोगिता तथा लाभकारी चरित्र की परीक्षा करते हुए प्रारंभिक कठिनाइयों पर¹²⁰ काबू पाकर उद्यम का मार्ग प्रशस्त करना

चाहिए तथा निजी उद्यमियों को इस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।¹²¹

भारतीय नेताओं द्वारा भारतीय उद्योगों की उन्नति के लिए सरकार को सुझाए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय थे : वाणिज्य और उत्पादन के एक पृथक संविभाग की स्थापना¹²² जिसे उपलब्ध साधनों¹²³ को जुटाने की, सरकार और निजी कंपनियों की विशेषज्ञों के ज्ञान तथा कौशल से सहायता करने व परामर्श देने की, सर्वेक्षण आदि के द्वारा जानकारी के संग्रह तथा उसके व्यापक प्रसार की, शुल्क-पद्धति में संरक्षण प्रदान करने की, मशीनरी पर निर्यात शुल्क हटाने की तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो।¹²⁴ उद्योगीकरण की प्रक्रिया में राजकीय प्रोत्साहन की भारतीयों की मांग उस समय अपने चरम पर पहुंच गई जब 1904 में गोपालकृष्ण गोखले ने कुछ एक राजकीय आर्थिक योजनाओं की वकालत की। उस वर्ष के अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, 'वास्तव में परिस्थितियों की मांग यह है कि पूर्ण विवेक तथा दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए जनता की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए व्यापक तथा विस्तृत योजना बनाई जाए और फिर उसपर दृढ़ता तथा निरंतरता के साथ अमल किया जाए तथा लगभग वर्ष प्रतिवर्ष उसकी प्रगति की पूरी समीक्षा की जाए।' ¹²⁵

औद्योगिक प्रयासों में सरकारी सहायता की मांग में उल्लेखनीय स्पष्टता को देखते हुए इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि निष्कर्ष रूप में इस मांग को प्रधान रूप से तो भारतीय नेतावर्ग में अर्थशास्त्रियों ने ही अभिव्यक्त किया। उस समय राष्ट्रीय समाचारपत्रों तथा कांग्रेस के अधिवेशन में सामान्य रूप से इस बात की जोरदार मांग नहीं की गई। स्पष्टतः इस लाभकारी मांग के लिए उत्साहपूर्ण चेष्टा के अभाव का कारण यह व्यापक संदेह था कि क्या एक विदेशी सरकार, चाहे वह कितनी भी उदार क्यों न हो, अपने देश के उत्पादकों के हितों के विरुद्ध जाने वाली कोई नीति अपनाएगी? उदाहरणार्थ : जी० वी० जोशी द्वारा जनवरी 1890 के 'पूना सार्वजनिक मभा' जनरल में प्रकाशित एक लेख 'इकानामिक सिचुएशन इन 'इंडिया' में विश्लेषित राज्य की आर्थिक भूमिका का समर्थन करते हुए हिंदू ने अपने 3 फरवरी 1890 के अंक में पैनी अंतर्दृष्टि से लिखा :

स्वदेशी उद्योगों के प्रत्यक्ष विकास के लिए उन्हें यथासंभव किसी भी मूल्य पर कोई प्रोत्साहन न देकर उन्हें अवनत बनाए रखना ब्रिटिश राष्ट्र के हित में ही है। ब्रिटिश शासक भारत की अधीनता के फलस्वरूप एक सबसे बड़े लाभ की आशा करते और उसे यथार्थ में प्राप्त करते हैं कि भारत उन्हें अपने औद्योगिक उत्पादनों की खपत के लिए एक असीमित बाजार जुटाता है। इस प्रकार की परिस्थिति में पूना के लेखक के सुझाव के अनुरूप सरकार से कुछ भी करने की आशा की संभावना नहीं है।

31 मई 1890 के अंक में बंगबासी ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट रूप दिया :

निस्संदेह स्वदेशी उद्योगों के उद्धार और विकास के लिए सरकारी सहायता अति आवश्यक है परंतु क्या उस सरकार से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आशा

की जा सकती है जो न केवल विदेशियों की है, विरोधी धर्म वालों की है, प्रत्युत उन लोगों की है जो स्वयं उत्पादक और व्यवसायी हैं? तथ्य यह है कि अंगरेज उत्पादक भारतीयों द्वारा स्वदेशी उत्पादन की अत्यंत साधारण वस्तुओं के प्रयोग को भी फूटी आंख नहीं देख सकते और वस्तुतः वे तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक भारत में उत्पादित पदार्थों को भारतीय बाजार से बाहर न फिकवा दें। और यह अंगरेज उत्पादक ही अंगरेजी राष्ट्र हैं, जिनका हित अन्य सबके हितों से ऊपर है। इस हित की देखभाल और सुरक्षा ही अंगरेजी कूटनीति का उद्देश्य है।¹²⁶

भारतीय लोकमत के अन्य अनेक प्रवक्ताओं ने भी इसी प्रकार के संदेह प्रकट किए।¹²⁷ इन संदेहों का आधार उस समय ब्रिटिश विचारधारा पर आधिपत्य जमाए हुई औपनिवेशिक अर्थनीति के चरित्र का तथा ब्रिटिश की भारत में वास्तविक राजनीतियों का अध्ययन था। उनके अनुसार अपनी कथनी के प्रतिकूल व्यवहार करते हुए ब्रिटिश भारतीय सरकार व्यवहार में न केवल भारतीय उद्योग की सहायता में असफल रही है प्रत्युत उसने विदेशी प्रतियोगियों—जिन्होंने यहां के उद्योगों को आमूल-चून नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है—को सहायता देकर उसे हानि भी पहुंचाई है।¹²⁸ यह तथ्य उनके भय की सर्वोत्तम संपुष्टि करने वाला था।

स्वदेशी

भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा देश की बढ़ती दरिद्रता को रोकने तथा परंपरागत और आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपायों में वपों तक स्वीकृत तथा मर्मथित एक उपाय था स्वदेशी की भावना का प्रचार-प्रसार। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था भारत निर्मित सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी माल न खरीदना, उसका परित्याग और यहां तक कि उसका बहिष्कार। यद्यपि आधुनिक भारत के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन को 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अखिल भारतीय आंदोलन के समय उल्लेखनीय सफलता मिली तथापि स्वदेशी भावना की तत्काल तथा विस्तृत स्वीकृति के लिए तथा आंदोलन की उस विशिष्ट घटना में मिली प्रभावशाली सफलता के लिए गत दशान्दियों में ही उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत किया जा रहा था। वस्तुतः स्वदेशी भावना और स्वदेशी आंदोलन दोनों उतने पुराने हैं जितनी कि स्वयं उदीयमान राष्ट्रीय चेतना। सहज भाव से और अत्यधिक अव्यवस्थित तथा विच्छिन्न रूप से पनपे स्वदेशी आंदोलन को अपने प्रारंभिक वर्षों में ही न केवल अपने समय की मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाओं का, प्रत्युत भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों तथा असंख्य अप्रतिबद्ध लोगों के स्थानीय प्रयासों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हो गया। इस विषय पर प्रकाशित सामग्री की अत्यंत स्वल्पता के कारण इस आंदोलन के प्रारंभिक इतिहास का यहां संक्षिप्त विवेचन कदाचित अनुचित न होगा।

1849 में ही 'प्रभाकर' पत्र के लेखों में आयातित सामान के स्थान पर भारतीय उत्पादनों के प्रयोग का समर्थन करने वाले पूना के गोपाल राव देशमुख भारतीय जनता के प्रथम महानुभावों में एक थे।¹²⁹ बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के इतिहास का सूत्रपात

नवगोपाल मित्र के प्रयामों से होता है जिन्होंने 1867 में एक हिंदू अथवा राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया, जो नियमित रूप से चौदह वर्षों तक प्रतिवर्ष लगना रहा। अन्य राष्ट्र निर्माण मंथनी गतिविधियों के अलावा इस मेले के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारतीय शिल्पकला के उत्पादनो की प्रदर्शनी लगाकर स्वदेशी उत्पादनो के प्रयोग को बढ़ावा देना था।¹³⁰ नवगोपाल मित्र को इस क्षेत्र में प्रवृत्त तथा यत्नशील होने की प्रेरणा राजनारायण वसु से मिली। राजनारायण प्रारंभिक बंगाली राष्ट्रवादी नेताओं में आदरणीय ऋषि तुल्य थे। वह विदेशी उत्पादनो के परित्याग तथा स्वदेशी वस्त्रो व अन्य वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने वालो में अग्रणी थे।¹³¹

उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में स्वदेशी भावना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हो गई। 1870 में विश्वनाथ नारायण मित्र द्वारा संचालित नेटिव ओपीनियन ने देशप्रेम की भावना वाले लोगो में अनुरोध किया तथा उन्हें अपने देशवासियों से महंगे दाम पर भी स्वदेशी वस्तुओं के खरीदने का परामर्श दिया।¹³² 1872 में रानाडे ने पूना में आर्थिक विषयो पर एक सार्वजनिक भाषणमाला का आयोजन किया जिसमें उन्होंने स्वदेशी भावना को इस रूप में लोकप्रिय बनाया कि अपने देश के बने सामान भले ही विदेशी उत्पादनो से महंगे हों और उनकी अपेक्षा भले ही कम सतोपजनक हों, हमारे लिए उनको ही प्राथमिकता देना उचित है।¹³³ इन गौरवमंडित भाषणो ने श्रोताओं को इतना अधिक उत्तेजित किया कि उनमें से बहुतों ने जिनमें प्रमुख रूप से थे, गणेश वासुदेव जोशी,¹³⁴ जो अपनी लोकप्रियता में सार्वजनिक रूप में 'काका' के नाम से प्रसिद्ध थे तथा पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापको में तथा प्रधान सक्रिय कार्यकर्ताओं में अग्रणी थे और वासुदेव फडके ने जिन्होंने बाद में सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था उत्साहित होकर केवल स्वदेशी वस्त्र धारण करने तथा एकमात्र स्वदेशी वस्तुओं के ही प्रयोग की कसम खाई।¹³⁵ जी० बी० जोशी अपनी धोती, कुरते और साफे के लिए प्रतिदिन स्वयं सूत कातते थे, उन्होंने स्वदेशी सामान को लोकप्रिय बनाने तथा उसका प्रचार करने के लिए अनेक स्थानो पर दुकानें खोली तथा 1873 के तडक-भडक और धूमधाम वाले दिल्ली दरबार में अपने हाथो की बनी खादी की वेशभूषा में ही सार्वजनिक सभा का प्रतिनिधित्व किया।¹³⁶ फडके महोदय भी समान रूप में स्वदेशी के प्रचार के दीवाने थे। उन्होंने सैकड़ो युवको को स्वदेशी प्रयोग की कसम खाने को तैयार किया।¹³⁷ 1873 में 'रास्त गोफ्तार' ने अपने 13 जुलाई के अंक में मराठी के 'निश्चय पत्रिका' अथवा 'जन प्रस्ताव पत्र' का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया जिसके संबंध में कहा जाता है कि वह अनेकानेक लोगो द्वारा सयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होकर परिचलित किया जा रहा था। प्रस्ताव में लोगो का आह्वान किया गया था कि जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, उन्हें देश के अपने उद्योगों के द्रुत विनाश को रोकने के लिए विदेशी सामग्री खरीदना बंद कर देना चाहिए तथा थोड़े-बहुत महंगे तथा स्तर में थोड़े-बहुत घटिया होने पर भी अपने देश के उत्पादन ही खरीदने चाहिए।¹³⁸ 'हिंदु प्रकाश' के 23 अगस्त 1875 के अंक में भी इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त किए गए थे।¹³⁹ विपिनकृष्ण बोस के अनुसार 1874 में नागपुर में गृहनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक संगठन अस्तित्व में आ गया था।¹⁴⁰ उसी वर्ष केवल भारत

में ही उत्पादित सूती सामान के व्यापार के लिए बंगलौर में एक कंपनी का गठन किया गया। कंपनी ने मांचेस्टर के सामान का व्यापार करने का संकल्प किया।¹⁴¹ अमृत बाजार पत्रिका के 6 जनवरी 1876 के अंक में राजकोट के एक पाठक ने लिखा : 'हमने विदेशी सामान का इस्तेमाल न करने का संकल्प कर लिया है। हम एक ओर अंगरेजी सामग्री को अपदस्थ करने के साधनों की खोज का और दूसरी ओर जनता की स्वदेशी वस्तुओं के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।' ¹⁴²

'ए वाइस फार दि कामर्स ऐंड मैनूफैक्चर्स आफ इंडिया' शीर्षक से बंगाल मे 1873-76 की अवधि में मुकर्जी की पत्रिका में प्रकाशित विस्तृत लेख में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी के पक्ष में अपनी बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे विदेशी सामान की खरीद छोड़कर थोड़ी सी देशभक्ति का परिचय नो दें।¹⁴³ उन्होंने अपने देशवासियों के यूरोप में बने सामान के प्रति सामान्य उन्माद को अराष्ट्रीय प्रवृत्ति बताते हुए उसकी भर्त्सना की। इस संबंध में उन्होंने निर्देश किया :

अब अपने राष्ट्र के प्रति अत्यंत झूठे और राष्ट्रीय उत्पादनों की गिरावट के लिए प्रेरक लोग हैं : राजा, जमींदार, बाबू तथा हमारे बड़े बड़े कस्बों और शहरों के लोग। उत्कृष्टता तथा सस्तेपन की इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर चापलूमी और बुद्धिव्यामोह ही अधिक है। इस व्यवहार का वास्तविक कारण यही है। उनके इस विश्वासघान को रुचि-परिष्कार कहकर क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके इस आचरण मे देश के सर्वोत्तम हितों को आघात पहुंचता है।

उन्होंने अपनी जाति की अप्रतिम दासवृत्ति तथा भ्रष्टता पर विनाश किया परंतु आशा प्रकट की कि सदा के लिए सर्वस्व समाप्त नहीं हो गया है। उन्होंने राजनीति, दूरदर्शिता, तर्क तथा कौशल से अपने देशवासियों से विनष्ट समृद्धि की पुनः प्राप्ति के लिए नैतिक विरोध के शस्त्र का प्रयोग करने के रूप में विदेशी सामान का बहिष्कार करने का अनुरोध किया।¹⁴⁴ उनके इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक पूरे अवतरण को यहां प्रस्तुत करके ही उसे समझा जा सकता है :

कल की गलतियों से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति आज की बुद्धिमत्ता से की जा सकती है। किसी प्रकार के शारीरिक बल प्रयोग के बिना, किसी प्रकार के राजद्रोह के बिना तथा किसी प्रकार की सांविधानिक संकटकालीन सहायता के लिए प्रायश्ना के बिना ही, अपनी पूर्वस्थिति को पुनः प्राप्त करना सर्वथा हमारे अपने ही हाथ में है। और कुछ नहीं केवल हमारी सक्रिय सहानुभूति ने मांचेस्टर के लक्ष्य को सिद्ध किया है। हमारी सहानुभूति यदि उसके विरुद्ध हो तो उसका परिणाम भी निश्चित ही विपरीत होगा। हमारे लिए एकमात्र परंतु अत्यंत प्रभावशाली नैतिक विरोध के आखिरी शस्त्र का प्रयोग अपराध नहीं। हमें अंगरेजी सामग्री के प्रयोग न करने के संकल्प रूप सशक्त शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और फिर देखिए कि इस प्रकार के संकल्प की प्रवृत्ति के फलस्वरूप गलत विषयों को किस तरह ठीक किया जा सकता है।¹⁴⁵

1875 में ढाका के लोग पहले से ही नैतिक विरोध के इस शस्त्र के प्रयोग का निश्चय

तथा मांचेस्टर के वस्त्रो के बहिष्कार का संकल्प कर चुके थे।¹¹⁶ बंगाल के अनेक समाचारपत्रों ने अपने पाठकों से अंगरेजी वस्त्रों के प्रयोग को बंद करने तथा भारतीय मिनो को संरक्षण देने का अनुरोध किया।¹¹⁷

1880-1895 की अवधि के पंद्रह वर्षों में स्वदेशी की लहर देश में उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। जब भारत सरकार ने लकाशायर के उत्पादकों को सतुष्ट करने के लिए सूती कपड़ों पर आयात शुल्क हटा दिए तो सरकार की इस करनीति से स्वदेशी की लहर को बड़ा प्रोत्साहन मिला।¹¹⁸ पश्चिमी भारत के लोगों में स्वदेशी उद्योगों के विनाश के विरुद्ध तथा अंगरेजी मशीनों में बने सामान के प्रयोग के विरुद्ध रचित लोकप्रिय गीत बहुत प्रचलित हो गए।¹¹⁹ उस समय देश में एक शक्ति समझी जाने वाली अमृत बाजार पत्रिका ने 1881 में एक लोकप्रिय संगठन बनाने का प्रबल आह्वान किया ताकि भारत के ग्राहक उत्पादित सूती वस्त्रों के बहिष्कार का प्रचार करने हुए मांचेस्टर की चुनौती का सामना किया जा सके। भारत के सभी प्रमुख नगरों में अपने शिष्टमंडल भेजिए... भारत की सभी भाषाओं में इस्तहार छापिए। उसने स्वदेशी आंदोलन के भावी विकास का बड़ी बुद्धिमत्ता से पहले से ही देखते हुए यह मांग प्रस्तुत की कि विदेशी उत्पादनों के व्यापारियों के प्रति बहिष्कार का प्रयत्न करना चाहिए।¹²⁰

1881 में देशी उत्पादनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए इलाहाबाद में एक देशी तिजारा कंपनी शुरू की गई। मदनमोहन मालवीय इसके प्रमुख जन्मशानाओं में एक थे।¹²¹ 18 अप्रैल 1883 के कोहनूर के प्रतिवेदन के अनुसार लाहौर में कनिष्ठ शिक्षित भारतीयों ने 'इंडियन नेशनल ऐमसिएशन' नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इसके सदस्यों को एक लिखित शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी जिसके अंतर्गत यथामभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग उनके लिए अनिवार्य था।¹²² अजमेर में भी इसी प्रकार की संस्था के संगठन की सूचना मिलती है।¹²³ 1890 में ढाका कालेज के छात्रों ने एक स्वदेशी भंडार खोला।¹²⁴ बंबई के विभिन्न भागों में अंगरेजी वस्त्रों के स्थान पर भारतनिर्मित वस्त्रों के प्रयोग के प्रचार के लिए असंख्य जनसभाएं हुईं और इन बहुत सी सभाओं में नियुक्त प्रतिनिधियों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बंबई मिलमालिक संघ से सलाह और सहायता की याचना की।¹²⁵ देश के सभी भागों के भारतीय समाचारपत्रों ने भारतीयों से विदेशी माल का बहिष्कार करने का, एकमात्र भारतीय सामान के प्रयोग का, स्वदेशी उत्पादनों की बिक्री के लिए भंडार खोलने का तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकप्रिय संघों के संगठित करने का प्रबल अनुरोध किया। उत्तर-पश्चिमी प्रांतों तथा अवध के अल्मोड़ा अखबार ने 1 मई 1882 के अंक में, 'नसीमें आगरा' ने 7 जून 1889 के अंक में 'रहबर' ने 16 जुलाई 1889 के अंक में, 'हिंदुस्तानी' ने 11 अप्रैल 1894 के अंक में, पंजाब के 'इपीरियल अखबार' ने 9 फरवरी 1889 के अंक में, पंजाब पंच ने 30 जुलाई 1891 के अंक में, 'पैसा अखबार' ने 10 अगस्त 1891 के अंक में, 'अखबारे आम' ने 18 जुलाई 1895 के अंक में, मद्रास से, 'आर्य जन पारुपालिनी' ने 1 सितंबर 1889 के अंक में, बरार से 'बृहद समाचार' ने 22 जून 1891 के अंक में, बंबई से 'मराठा' ने 13 मार्च 1881 के तथा 8 जुलाई 1894 के अंकों में, 'नेटिव ओपीनियन' ने 26 मार्च 1891 के अंक में,

‘पूना वैभव’ ने 10 मई 1891 के अंक में, ‘हिंदू पंच’ ने 22 मार्च 1894 के अंक में, ‘आर्यो-दय’ ने 18 मार्च 1894 के अंक में, ‘मोदवृत्त’ ने 2 अगस्त 1894 के अंक में, बंगाल से ‘सोम प्रकाश’ ने 23 जनवरी 1882 के अंक में, ‘आनंद बाजार पत्रिका’ ने 27 मार्च 1882 के अंक में, ‘भारत मिहिर’ ने 16 मई 1882 के अंक में, ‘संजीवनी’ ने 14 जून 1884 के अंक में, ‘समय’ ने 22 जून 1882 के अंक में, ‘बंगबासी’ ने 16 तथा 23 नवंबर 1889 के और 2 मई 1891 के अंक में, ‘समय और साहित्य’ ने 5 अप्रैल 1891 के अंक में तथा ‘एजुकेशन गजट’ ने 5 जून 1891 के अंक में इस कार्यक्रम का बड़ा जोरदार समर्थन किया।¹⁵⁶ जनता तथा प्रशासकों में अधिक सुसंस्कृत तथा सम्मानित दिखाई देने के लिए पश्चिमी वस्त्रों तथा अन्य उत्पादनों का प्रयोग करने वालों की तीव्र भर्त्सना की गई। अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 19 जुलाई 1891 के अंक में लिखा :

विभिन्न प्रकार के यूरोपीय वस्त्रों की आवश्यकता केवल उन लोगों का है, जो अपने को छैलछबीला दिखाने के शौकीन हैं हम हिंदुओं की तो हजारों वर्ष पुरानी आदर्श संस्कृति है, हम इन रातोंरात धनी बन जाने वालों तथा सब प्रकार की सौम्यता को विकृत करने वालों की कलुषित रुचि में निश्चित रूप से वरेण्य मिद्ध हो सकते हैं। वस्तुतः इन लोगों के आचार-व्यवहार में तो अपने को सम्मानित एवं कुलीन दिखाने को कुछ होता नहीं अतः वे लोग धन से उपलब्ध होने वाले माधनों में ही अपने को ऊँचा दिखाने की चेष्टा करते हैं।

इस अवधि में स्वदेशी भावना को देश की मान्य जन-संस्थाएं भी अपनाने लगी। पश्चिमी भारत औद्योगिक संघ के तत्वावधान में हुए द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन में प्रमुख विधिवेत्ता, शिक्षाशास्त्री, उद्योगपति तथा लोकनायक, पूना के एम० बी० नामजोशी ने संस्था के सदस्यों में आग्रह किया कि वे आयातित वस्तुओं के स्थान पर भारतीय उत्पादनों के प्रयोग का प्रयत्न करें तथा अगले वार्षिक सम्मेलन में अपने प्रयत्नों के परिणामों की सूचना दें।¹⁵⁷ बंगाल में आयोजित पहले के कुछ एक प्रांतीय सम्मेलनों में स्वदेशी की आवश्यकता पर उत्साहपूर्वक बल दिया गया। इन सम्मेलनों में 1894 में बर्दवान में आयोजित सम्मेलन विशेष उल्लेखनीय है।¹⁵⁸ कांग्रेस मंच में यह नारा 1891 के अधिवेशन में उस समय मुनाई दिया जब पंजाब के प्रचंड कांग्रेसी नेता लाला मुरलीधर ने प्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आयातित सामान खरीदने का अर्थ अपने भाइयों के हृदय के रक्त में हाथ रंगना है।¹⁵⁹ 1894 में उन्होंने इस विषय को फिर उठाया और प्रतिनिधियों से विदेशी वस्त्रों तथा विलास सामग्री को छोड़ने तथा व्यवहार में भी निर्धनों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला बनकर दिखाने का अनुरोध किया। अधिवेशन के मवाददाता के अनुसार श्रोताओं ने लालाजी के इस अनुरोध पर देर तक प्रचंड जयजयकार की।¹⁶⁰

1896 में स्वदेशी आंदोलन उस समय प्रबल हो उठा जब राजनीतिक दृष्टि से सचेत सारा भारत भारतीय वस्त्रों पर बदले की भावना से लगाए गए सीमा शुल्क के विरुद्ध गुस्से से आगबबूला हो गया।¹⁶¹ बहुतों ने अनुभव किया कि धर्म तथा अन्य भेदभावों को भुलाकर सभी भारतीयों के लिए संगठित होने तथा लंकाशायर के वस्त्रों के बहिष्कार की शपथ खाते हुए ‘राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जागृत होने’ का उपयुक्त समय यही था।¹⁶² यह

भी अनुभव किया गया कि इस आंदोलन को कोरी प्रार्थनाओं, मौखिक विरोधों तथा प्रस्तावों से बहुत ऊपर ले जाने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। समय की मांग मांचेस्टर के साथ सभी प्रकार के व्यापार को बंद करने के संगठित प्रयास करने की थी।¹⁶³ भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग के केंद्र की गरिमा के अनुरूप बंबई प्रांत ने आंदोलन को नया आयाम देने का नेतृत्व किया। इस प्रांत के विभिन्न भागों में लंकाशायर के उत्पादनों का बहिष्कार करने के लिए मंस्थाओ और समितियों को संगठित किया गया।¹⁶⁴ बंबई प्रांत के सारे समाचारपत्र बहिष्कार के आंदोलन के समर्थन के लिए सक्रिय हो उठे।¹⁶⁵ स्वदेशी वस्त्र के अतिरिक्त न कुछ पहनने और न कुछ बेचने की सार्वजनिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने के लिए तथा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को सुगठित करने के लिए पूना, अहमदनगर, सतारा, बारमी, जलगाव, मनमाड तथा राजापुर में विशाल जनसभाएं हुईं। बंबई की गतिविधि की लोकप्रियता का परिचय अहमदनगर की स्वदेशी गतिविधि पर 17 मार्च 1896 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित एक रिपोर्ट¹⁶⁶ में प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि लंकाशायर के उत्पादनों के बहिष्कार के लिए स्थानीय समिति नगर के विभिन्न भागों में जनसभाओं का आयोजन तथा जिले के जन-साधारण में परिचालन के लिए परिपत्र तथा पुस्तिकाएं तैयार कर रही है। अंगरेजी वस्त्रों के बहिष्कार के लोकप्रिय दृढ़ निश्चय का प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट प्रमाण देने के लिए इसने एक जन-प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें जनता ने अपने अंगरेजी कपड़ों की होली जलाई।¹⁶⁷ टाइम्स के मवाददाता का कथन था कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए बिना मैकडों जटिन प्रश्नों का सामना किए गए अंगरेजी वस्त्र का एक टुकड़ा तक ले जाना संभव नहीं था। पूना के न्यू इंगलिश स्कूल के छात्रों ने भी अंगरेजी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने के लिए इसी प्रकार की जनसभा का आयोजन किया।¹⁶⁸ बहिष्कार आंदोलन की इस अपरिपक्व अवस्था में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।¹⁶⁹ बहिष्कार आंदोलन की नई लहर यद्यपि प्रमुख रूप से बंबई तक ही सीमित रही तथापि इसे देश के अन्य भागों के समाचारपत्रों से भी पूरा पूरा समर्थन मिला।¹⁷⁰

मूनी कपड़े पर कराधान के विरुद्ध जन-आक्रोश के कम होते ही स्वदेशी का आंदोलन भी शिथिल पड़ गया परंतु पूर्ण रूप से यह समाप्त कभी नहीं हुआ। समाचारपत्र स्वदेशी की आवश्यकता को लोगों के मस्तिष्क में उजागर करते रहे।¹⁷¹ 1899 में बनारस के 'भारत जीवन' ने देशभक्ति की भावना से आप्लावित भाषण देने वाले तथा लेख लिखने वाले भारतीय शिक्षितों से इस दिशा में देशवासियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की अपील की।¹⁷² संजीवनी कुछ वर्षों के उपरान्त 1905 में विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी प्रयोग के आह्वान का नेतृत्व करने वाला पत्र बन गया और उसने स्वदेशी कार्यक्रम की आवश्यकता तथा उसे लागू करने के उपायों और साधनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उसने अपेक्षित स्तर की स्वदेशी वस्तुओं की विद्यमानता से जनता के अपरिचय को तथा इन वस्तुओं की सुलभ प्राप्ति के लिए दुकानों तथा अभिकरणों के अभाव को स्वदेशी संघर्ष के मार्ग की बहुत बड़ी बाधाएं बताया। उसने इस बात की ओर भी संकेत किया कि बड़े बड़े थोक व्यापारी और छोटे दुकानदार यदि चाहें तो जनता को स्वदेशी

माल खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं।¹⁷³ पैसा अखबार ने 15 मार्च 1902 के अपने अंक में वचन दिया कि वह विदेशी वस्त्रों के प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा करने वाले देश-भक्तों के नाम प्रकाशित करेगा।¹⁷⁴

बख्शी जैश्रीराम ने कांग्रेस के मंच से चौदहवें अधिवेशन के प्रतिनिधियों से भारत में बनी सामग्री के प्रयोग का तथा उसके प्रचार के लिए संस्थाओं की स्थापना का अनुरोध किया।¹⁷⁵ 1901 में कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने सार्वजनिक रूप से कलकत्ता में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के प्रतिनिधियों तथा दर्शकों से प्रार्थना की कि वे यथा-संभव स्वदेशी उत्पादनों से निर्मित वस्त्र पहनकर ही अधिवेशन के सम्मेलनों में मम्मिलित हों।¹⁷⁶ आगामी वर्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कांग्रेस सभापति पद से स्वदेशी की अपील की।¹⁷⁷ 1902 में प्रथम बार कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की योजना को औपचारिक मान्यता देने के लिए उसे अहमदाबाद कांग्रेस की विषय समिति को मौपा परंतु उल्लेखनीय यह है कि प्रस्ताव को व्यापक समर्थन न मिलने के कारण समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया।¹⁷⁸ फिर भी बहुत सारे लोगों ने स्वदेशी विचारधारा को व्यावहारिक रूप देने के लिए उपयोगी उपाय जारी रखा। 1898 में पंजाब में 'स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा' नाम की एक संस्था विद्यमान थी जिसका घोषित उद्देश्य भारतीय वस्तुओं का स्तर सुधार और उनका उपयोग बढ़ाना था।¹⁷⁹ 1902 में पूना में एक लाख रुपए की माधारण धन-राशि से एक स्वदेशी दुकान खोली गई जिसे शीघ्र ही सफलता मिली।¹⁸⁰ उन्नीस वर्ष स्वदेशी आंदोलन के बंगाली अग्रदूत जे० चौधरी के सक्रिय नेतृत्व में कलकत्ता में 'इंडियन स्टोर्स लिमिटेड' खोला गया।¹⁸¹ आगामी वर्ष अहमदाबाद में 'स्वदेशी वस्तु संरक्षण मस्था' बनाई गई और इसका उद्घाटन दीवान बहादुर अब्बालाल साबेरलाल ने किया।¹⁸²

इस प्रकार भारत में स्वदेशी भावना का उद्भव और विकास हमारे अध्ययन काल की अवधि में एक खास रूप में हुआ जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए वे विदेशी वस्तुओं की तुलना में महंगी तथा स्तर में घटिया ही क्यों न हों।¹⁸³ विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोगों के व्यवहार में भले ही स्वदेशी भावना के पृथक अथवा संयुक्त रूप में अनेक उद्देश्य रहे हों परन्तु समीक्षा-धीन काल में इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक ही था, राजनीतिक नहीं। वस्तुतः इस भावना का जन्म ही भारत की अशक्त तथा शोचनीय औद्योगिक स्थिति की अनुभूति से हुआ था। इस आंदोलन के अस्तित्व का लक्ष्य इसी आशा में निहित था कि यह भारतीय उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देकर देश की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति का उद्धार और सुधार करने में सहायक होगा। स्वदेशी के अनेक प्रस्तावकों ने इस दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रतिपादन किया।¹⁸⁴ उदाहरणार्थ लोकमान्य तिलक के अंगरेजी भाषा के मुखपत्र 'मराठा' ने 2 अप्रैल 1896 के अंक में लिखा :

आंदोलन का उद्देश्य देशप्रेम की भावना का संचार है जिससे भारत में सूती उद्योग को प्रबल प्रोत्साहन मिल सके।... स्वदेशी वस्त्रों की व्यापक मांग क्षण-प्रतिक्षण अधिकाधिक व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही है। अतः विश्वास है कि शीघ्र ही इससे मशीनी सुधार को द्रुतगति तथा देश में पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।¹⁸⁵

एक महीने के बाद उसने (मराठा पत्र) आशाओं की आंशिक पूर्ति की सूचना दी और उल्लास प्रकट किया कि स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप बंबई प्रांत में कुल 13, बंबई में 7 और अहमदाबाद में 6 नई मिलें अस्तित्व में आ गई हैं और मिलों के लिए अधिक बढ़िया कपास उगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।¹⁸⁶ बंगाल में इस आंदोलन को निरंतर गतिशील बनाने वाले तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के० के० मित्र की 'संजीवनी' ने भी औद्योगिक लाभ को इस आंदोलन का उद्देश्य बताया।¹⁸⁷ मुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने भी 1902 की कांग्रेस के सभापति पद से दिए गए भाषण में इसी पक्ष को उजागर किया।¹⁸⁸

अनेक लोगों ने विदेशी प्रतियोगियों के हाथों घरेलू कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को निश्चित विनाश में बचाने के लिए स्वदेशी का प्रयोग तथा प्रचार किया।¹⁸⁹ यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी हस्तशिल्पकारों को स्वदेशी मशीन उत्पादकों की प्रतियोगिता से बचाने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

भारतीय राष्ट्रादियों द्वारा स्वदेशी की रक्षा और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रस्तुत तर्कों में एक सर्वाधिक आकर्षक तर्क यह था कि सरकार ने ब्रिटिश उत्पादकों की हित रक्षा के हेतु अथवा उन्मुक्त व्यापार सिद्धांत पर आस्था रखने के कारण भारत के नवजात उद्योगों से नितान्त आवश्यक संरक्षण देना अस्वीकार कर दिया है अतः अब लोगों को स्वयं ही प्रबल स्वदेशी आंदोलन चलाकर उसे संरक्षण देने का दायित्व लेना चाहिए।¹⁹⁰ इसके अनिश्चित यह अभियान न्यूनाधिक रूप से व्यावहारिक और सभ्य की परिधि में आता था। इसकी सफलता विदेशी सरकार की कृपा और इच्छा अथवा कानून में परिवर्तन पर नहीं प्रत्युत जनता के अपने प्रयागों तथा आत्मविश्वास पर निर्भर थी। वस्तुतः अधीन प्रजा के लिए यही तो एक साधन अवशिष्ट था।¹⁹¹ 1902 में मुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने कांग्रेस के सभापति पद से दिए गए भाषण में इस दृष्टिकोण को अत्यंत मुखरित रूप से प्रस्तुत किया। 'कानूनी व्यवस्था से स्वदेशी को संरक्षण देना भले ही असंभव हो परन्तु हम राष्ट्रीय संकल्प से तो यथाशक्ति उसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।'¹⁹²

राष्ट्रादियों के अनुसार सामान्य रूप से स्वदेशी आंदोलन और विशेष रूप से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार लंकाशायर के उन स्वार्थी उत्पादकों के विरुद्ध प्रभावी विरोध तथा प्रतिकार के उपयुक्त शस्त्र थे जो भारत के पनपते मूनी वस्त्र उद्योग को लूना-लगडा बनाने के लिए भारत सरकार पर अपना राजनीतिक प्रभाव डाल रहे थे। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन शस्त्रों से विदेशी उत्पादकों को इस प्रकार की हरकतों को छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है अथवा कम से कम उनके परिणामों का आनंद लेने से तो उन्हें वंचित किया ही जा सकता है। यह सब तभी संभव है जब सशक्त बहिष्कार आंदोलन द्वारा उनके मुनाफे कम किए जाएं।¹⁹³ मराठा ने 9 फरवरी 1896 के अंक में लिखा : 'यदि लंकाशायर की अतृप्त लोभवृत्ति को ही भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को लंकाशायर को नष्ट करने के लिए दृढ़ निश्चय करना है। भारत कुछ वर्षों के लिए लंकाशायर के वस्त्र का ही बहिष्कार कर ले तो माचेस्टर के अतिलोलुप व्यापारियों के होश ठिकाने आ जाएंगे।' विदेशी उत्पादकों के स्थान पर स्वदेशी उत्पादकों के प्रयोग के

आंदोलन का एक उद्देश्य यह भी था कि विदेशी उत्पादनों के फलस्वरूप भारतीय धन की निकासी को कम किया जा सके।¹⁸⁴

इस युग के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि इस युग के राष्ट्रीय नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को राजनीतिक युद्ध लड़ने के लिए प्रभावशाली शस्त्र के रूप में ग्रहण नहीं किया। यह बात नहीं कि स्वदेशी को राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग करने का विचार उनमें से कुछ के दिमाग में भी नहीं आया अथवा इसे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं मिली। 1891 में पूना वैभव ने जनता से अपील की कि वह 'कांसेंट ऐक्ट' को रद्द करवाने के लिए सरकार पर दबाव के रूप में अंगरेजी वस्त्रों का प्रयोग बंद कर दें।¹⁸⁵ 1894 में मराठी के 'मोदवृत्त' ने जिसके संपादक के० बी० काले को 1897 में राजद्रोह के अभियोग में नौ महीने का कारावास मिला था, वकालत की कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सरकार के विरुद्ध जनता की आम शिकायतें दूर कराने के शांतिपूर्ण संघर्ष के बहुत बड़े कार्यक्रम का एक अंग था।¹⁸⁶ काफी समय बाद 1901 में लखनऊ के विख्यात राष्ट्रीय साप्ताहिक 'एडवोकेट' ने तो स्वदेशी के प्रयोग को आत्म-रक्षा के लिए अपने पाम बचा एकमात्र शस्त्र बताया। उसके अनुसार इसी शस्त्र से हम आस्ट्रेलिया सरकार को आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों पर थोपे प्रतिबन्ध हटाने के लिए तथा हमारे प्रति तनिक शिष्ट जनों जैसा सम्म्य आचरण करने के लिए विवश कर सकते हैं।¹⁸⁷ भारतीय नेताओं के समक्ष चीनियों द्वारा अमरीकी सामान के मफल बहिष्कार का उदाहरण भी था।¹⁸⁸ ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अनुमान था कि स्वदेशी को राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग करने का अभी उपयुक्त समय नहीं था। किंतु 1880 में ही दादाभाई नौरोजी ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तथा न्यायमंगल भविष्यवाणी की थी कि वह समय अवश्य आएगा। लोकप्रिय गीतों द्वारा विदेशी उत्पादनों के आयात का रोकने की लोकप्रिय चेष्टा का निर्देश करने हुए उन्होंने लिखा था :

हाथ के बने महुंगे सामान के मुकाबले अंगरेजी मशीनों से बने सस्ते सामान के बहिष्कार को एक निस्सार चेष्टा मानकर आज हम उसका उपहाम भले ही कर लें परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन का पनपना और समय आने पर नया रूप ग्रहण करना निश्चित है। यदि अंगरेज अपने अविवेक का परिचय देते हैं तो इस समय के अंगरेजी वस्त्रों के विरुद्ध लिखे गीत समय आने पर अन्य अंगरेजी वस्तुओं के विरुद्ध भी स्वाभाविक रूप में प्रभावी प्रचार का कार्य करेंगे। परन्तु यदि भारत की वर्तमान पतन-प्रक्रिया जारी रहती है, यदि जनता का बहुत बड़ा वर्ग अंततः किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए निराशा अनुभव करने लगता है, यदि विवेक तथा सांसारिक अनुभव से रहित शिक्षित युवक ही जनता के नेता बनने लगते हैं तो यह दृष्ट से अनिष्ट की दिशा में, अंगरेजी वस्त्रों से अंगरेजी शासन की ओर एक अत्यंत छोटा सा कदम होगा। गीत तो वही रहेंगे परन्तु हां, शासन के बारे में एक अपशब्द चिंगारी का काम करेगा।¹⁸⁹

एक आर्थिक आंदोलन के रूप में भी समीक्षाधीन अवधि में स्वदेशी भावना एक सशक्त, अखिल भारतीय तथा सर्वव्यापक आंदोलन का रूप ग्रहण न कर सकी क्योंकि

राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने तथा पनपते भारतीय उद्योगपति वर्ग ने इसका विरोध किया। कहीं कहीं तो इस विरोध का मुखर रूप देखने को मिला परंतु अधिकांशतः आंदोलन के प्रति समर्थन के निषेध के रूप में ही इसने अपने को अभिव्यक्त किया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को देशप्रेम का प्रत्यक्ष रूप तो माना परंतु इसे व्यावसायिक दृष्टि से अव्यावहारिक, यहां तक कि लोकशक्ति का हानिप्रद मोड़ बताया।²⁰⁰ उनकी प्रमुख आपत्ति यह थी कि इस आंदोलन का प्रमुख आधार आर्थिक भ्रातियां हैं।²¹⁰ लोगों के लिए आयातित उत्तम और मध्यम दर्जे के वस्त्रों के प्रयोग को तिलाजलि देना संभव नहीं था। वे सदैव सस्ता और बढ़िया माल खरीदेंगे। यह सोचना भ्रान्ति थी कि देशप्रेम की अपीलों इस प्रवृत्ति को पलट देंगी। अतः इस प्रकार के सभी प्रयत्न अवश्य अमफल होंगे।²⁰² देशभक्ति की उत्कटता देश की विशाल जनता को विशुद्ध व्यापार के मार्ग से एक इंच भी इधर-उधर न हटा मकेगी।²⁰³ जनसाधारण का तो कहना ही क्या, यहां तक कि सुशिक्षित और विचारशील व्यक्तियों से भी इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वाचा का प्रश्न था : 'क्या वे ऐसा कर सकते थे ? उदाहरणार्थ आप उनकी महिलाओं और बच्चों से जरा साड़ियां और चोलियां, छोटें और छोटे वाले कपड़े पहनना छोड़ने को कहिए तो सही' ?²⁰⁴ अरुचिकर वास्तविकता यह थी कि एक साधारण उपभोक्ता चाहे वह किसी भी बौद्धिक स्तर का क्यों न हो, केवल देशप्रेम की भावुकता के वशीभूत होकर आर्थिक ध्रेष्ठता और सस्तेपन के कठोर मन्त्र की अपेक्षा करता हुआ अपनी स्वतंत्र इच्छा से आख नहीं मूढ़ सकता है।²⁰⁵ इसके अनिर्गुण भागनीय मिलें उस समय भारत द्वारा इंग्लैंड में आयातित वस्त्रों के परिमाण में उत्पादन की स्थिति में नहीं थी। भागनीय उद्यमियों के पास या तो मशीनें नहीं थी अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मशीनें खरीदने को पूंजी नहीं थी। वहिष्कार आंदोलन के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं कि वह एकदम ऐसे कारखाने लगा सके जो एक दिन में अथवा एक वर्ष में अथवा पांच वर्षों में सारे भारत के लिए उतने परिमाण में वस्त्र जुटा सकें जितने परिमाण में इस समय भारत इंग्लैंड से आयातित करता है।²⁰⁶ इस संदर्भ में वाचा ने टिप्पणी ही नहीं प्रत्युत भविष्यवाणी की कि भारतीय वस्त्र उद्योग को कदाचित अपनी अपेक्षित पूर्ण क्षमता प्राप्ति के लिए बीस वर्ष लगेगे²⁰⁷ और इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने का कदाचित वही उपयुक्त समय होगा। इस सारी बहस के पीछे यह तर्क काम कर रहा था कि मिलों का उत्पादन स्वदेशी आंदोलन के बाद नहीं प्रत्युत पहले बढ़ना चाहिए।²⁰⁸ यहां यह उल्लेखनीय है कि हथकरघों से बना वस्त्र देश में वस्त्र की आवश्यकता तथा मिल के उत्पादन के बीच के अंतर की पूर्ति कर सकता था। सत्य तो यह है कि स्वदेशी के विभिन्न समर्थकों ने उस समय यह सुझाव दिया भी था²⁰⁹ परंतु उस समय वाचा तथा उसकी विचारधारा के महानुभाव उसी प्रकार के भारतीय वस्त्रों में नहीं प्रत्युत भारतीय मिलों से निर्मित वस्त्रों के ही पक्ष में थे। स्वदेशी का अर्थ उन लोगों के लिए लंकाशायर के वस्त्र के स्थान पर भारतीय मिलों में बने वस्त्रों के प्रचार का साधन मात्र था। लंकाशायर के वस्त्रों के हटाने में हथकरघों की भूमिका को उन्होंने कोई महत्व ही नहीं दिया। उनका लक्ष्य भारतीय उद्योगों, उनकी प्रगति और सुधार को पुनः गतिशील बनाना था न कि सड़ी-

गली वस्तुओं को आश्रय देना।¹¹⁰ हथकरघों के वस्त्र को तो उन्होंने वस्त्र उद्योग के विकास से एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। उदाहरणार्थ 1901 में वाचा ने हथकरघा जुलाहों को मिलमालिकों के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए कपास सीमा शुल्क लगाने की निम्नोक्त शब्दों में निंदा की।

कररहित भारतीय सूत का प्रयोग करने वाले हथकरघा जुलाहों के उत्पादन मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की प्रतिगोचिता में है। अत्यंत दुर्दशाग्रस्त हथकरघा जुलाहों के दृष्टिकोण से निस्संदेह यह अच्छी बात है कि वे अपने उद्योग को उन्नत करें परंतु जहां तक मिलमालिकों का संबंध है, यह सार्वथा असहनीय है। यह तो संरक्षण के भीतर ही संरक्षण है।¹¹¹

अतएव सुविधापूर्वक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बर्बई की मिलों के मालिक तथा उनके राष्ट्रवादी प्रतिनिधि उस समय तक विदेशी वस्त्रों के बाह्यकार के पक्ष में नहीं थे जब तक भारतीय मिलें अप्रान्तशोधित मांग को पूरा करके विदेशी वस्त्रों का आयात को बंद करने की स्थिति में नहीं आ जाती। इसका अर्थ उनके अपने अनुमान के अनुसार तीस वर्ष थे।¹¹² उस समय वे खादी आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी महमत हा जाते क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि खादी के उस समय उनका प्रतिद्वंद्वी बन पाने की संभावना ही नहीं थी।¹¹³

स्वदेशी आंदोलन के औचित्य पर सदेह करने वालों के मन में छुपा हुआ एक और भय यह था कि ब्रिटिश उत्पादक भाग्य की नई मिलों को मशीनरी देने में इत्तार करके अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध बदले की भावना में काम कर सकते हैं। उनके विचार में शामक पक्ष सुदृढ़ और शांतिशाली था और उसके विरुद्ध शांति भारतीय पक्ष शोचनीय रूप में दुर्बल था। अतः उनके तथा मिलमालिकों के समर्थन के अभाव तथा उनके विरोध का विमर्शनिष्ठ दो बातों में किया जा सकता है। 1. उनका विश्वास था कि भारतीय मिलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता के लिए आंतरिक बाजार में पर्याप्त अवकाश है। इस बाजार का कृत्रिम रूप में अथवा जबरदस्ती किया गया प्रमाण उनके लिए अपेक्षित रूप में उपयोगी नहीं होगा क्योंकि देश में मोटे वस्त्र उद्योग पर पहले ही उनका एकाधिकार है और इससे उनके वास्तविक प्रतिद्वंद्वी हथकरघा उद्योग की सहायता मिलेगी और 2. अपनी आर्थिक शक्ति पर तथा जनता के बलिदान की भावना की क्षमता¹¹⁴ और सुदृढ़ता पर अविश्वास और विदेशी शागको की शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर आका जाना।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभावशाली वर्ग तथा मिलमालिकों के विरोध का परिणाम यह हुआ कि देश के राष्ट्रवादी शिक्षित मध्यवर्ग का व्यापक समर्थन उपलब्ध होने पर भी स्वदेशी आंदोलन देश का शक्तिशाली आंदोलन न बन पाया। यहां तक कि उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का औपचारिक समर्थन तक प्राप्त नहीं हो सका।

संदर्भ

1. भारत से बाहर निवेश के अन्य स्रोत धीरे धीरे न केवल ब्रिटिश पूंजी से प्रत्युत विश्व के सभी पूंजी उत्पादक देशों की पूंजी से भरते जा रहे हैं और यदि यही स्थिति नहीं तो वह समय खीघ्र आ जाएगा कि बैंकों में दीर्घकाल से खाली पड़ी हुई ब्रिटिश चालू पूंजी को वहां से निकालकर नए स्रोतों में लगाना होगा और इस रूप में 'आर्थिक गुस्साकरण' के नियम के अनुसार उसकी गति भारत की ओर ही होगी ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश संध्याओं द्वारा ब्रिटिश पूंजी को सुरक्षा प्राप्त होने से इसे भारत के लिए अतिरिक्त आकर्षक बनना चाहिए (कर्जन : स्पीचेज, खंड III, पृ० 134) इससे पूर्व वह घोषित कर चुका था कि ब्रिटिश पूंजी भारत की राष्ट्रीय प्रगति के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है (स्पीचेज, खंड I, पृ० 34). और भी देखिए, एलमिन : स्पीचेज, पृ० 489.
2. लिलंड हैमिल्टन जेम्स 'दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल टु 1875' (न्यूयार्क, 1927) पृ० 208.
3. वही, पृ० 225 तथा देखिए भारतीय अकाल आयोग 1880 का प्रतिवेदन भाग II, अनुभाग VIII, कड़िका 3.
4. पी० पी० गिल्ले की 'इकानामिक कडीशन इन इंडिया', (लंदन 1925) पृ० 281 में उद्धृत.
5. जार्ज पाइल . ग्रेट ब्रिटेन कैपिटल इनवेस्टमेंट इन इंडोचीनोइल कालोनीयल फारन कंट्रीज, जरनल आफ रायन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, खंड LXXIV, भाग II (जनवरी, 1911), पृ० 180.
6. 'पिल्ले' में पूर्वोद्धृत, पृ० 28
7. जेम्स . पूर्वोद्धृत, पृ० 230 1880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन भाग II, वगैरह VIII, कड़िका 3.
8. जार्ज पाइल पूर्वोद्धृत
9. जोशी : पूर्वोद्धृत, चार्टरफॉर्मिस पृ० 780 राय : पावर्टी, 113-4, 125-6
10. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 652, 757.
11. भारतीय अर्थशास्त्र के बहुत से विद्वानों ने ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हमारे बहुत सारे विद्वान लेखकों ने भी इस तथ्य की उपेक्षा की है (बबई, 1946). प्रोफेसर पी० ए० वाडिया तथा के० टी० मर्चेंट ने इस तथ्य को प्रामाणिकता दी है कि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद तक भारतीय नेताओं के पास विदेशी पूंजी के संबंध में कुछ कहने को ही नहीं था. उन्होंने लिखा है : 1922 तक भारतीय लोकमत ने भारत में विदेशी पूंजी के निवेश के संबंध में अपने आपको निश्चित रूप में अभिव्यक्त नहीं किया. फिसकल आयोग ने ही निर्देश किया था कि गवाहों ने अपना मत व्यक्त किया है कि कतिपय निश्चित प्रतिबंधों के बिना भारत में विदेशी पूंजी के प्रवेश को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए (पृ० 479-80).
12. 8 दिसंबर 1886 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत एक लेख में दादाभाई ने लिखा था : मैं सभी अंगरेज उद्योगियों से विनम्रपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वे भारत जाकर यथासंभव अधिकाधिक लाभ उपार्जित करें. वे हमें इससे बड़ा न कोई और लाभ पहुंचा सकते हैं और न ही अनुग्रह कर सकते हैं. वस्तुतः हमारे देश में अंगरेजों द्वारा निवेशित प्रत्येक कोड़ी हमारी स्थिति के सुधार में हमारे लिए महत्व रखती है (जरनल आफ ईस्ट इंडिया

एसोसिएशन, खंड III-1969, सं० 1, पृ० 13) तथा देखिए. नौरोजी : एसेज, पृ० 39-41, 102, 104 106, 124-7. 130-1, 135. विदेश पूंजी के उत्तरगामी विरोध के लिए देखिए : अधोलिखित विवेचन.

13. नौरोजी : एसेज पृ० 39-40, 106, 127 एम० एन० बैनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 190 हिंदुस्तान 21, 23, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 26 अगस्त 1888). केलाक : पूर्वोद्धृत में उद्धृत रानाडे का वक्तव्य पृ० 122 तथा 'एसेज', पृ० 105. हितवादी 13 जून (आर० एन० पी० बंग, 20 जून, 1891). ए० बी० पी०, 8 फरवरी 1895, 6 जनवरी, 15 अक्तूबर 1900, 10 अगस्त 1903. एम० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 270 आर० एम० सायानी, आई० सी० पी० 1897. खंड XXXVII, पृ० 524. हिंदुस्तान 8 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०, 11 अक्तूबर 1988).
प्रारंभिक वर्षों में दादाभाई का विचार था कि भारतीय धन और पूंजी के ब्रिटेन में अपरिहार्य निकासी के माध्यम से विदेशी पूंजी का आयात आंशिक रूप में निरोध तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप था.
14. दादाभाई नौरोजी ने इस मुद्दे के लिए जोन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत किया (एसेज, पृ० 104) तथा देखिए, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 789-90. आर० एम० मायानी, एल० सी० पी०, खंड XXXVII, पृ० 524
15. रानाडे : एसेज, पृ० 186
16. सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य इंग्लैंड से और अमरीका तक से पूंजीपतियों को भारत में उद्योग खोलने के लिए निर्मात्र और उत्साहित करना है (ए० बी० पी० 17 मार्च 1902). 'समाचार पत्रों ने तो विदेशी निवेशकों के प्रारूपों के प्रति उदासीनता और अनुदारता दिखाने के लिए भारत सरकार की निंदा की' तथा देखिए, एम० एन० बैनर्जी स्पीचेज I, पृ० 190 हिंदुस्तान. 21, 23, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 15 नव० 1898) ए० बी० पी०, 15 जुलाई 1893 और नौरोजी : ऊपर उद्धृत पादटिप्पणी सं० 12
17. हिंदुस्तान 21, 23, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 28 अगस्त 1898) एम० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 270.
18. जोशी : पूर्वोद्धृत, 756 हिंदू 23 फरवरी 1900, बंगाली 25 मई 1902 जी एम० अय्यर दि बिबटनी आन दि इकानामिक कडीशस आफ इंडिया, एच० आर०, जून 1901, पृ० 445-7. नौरोजी : स्पीच ऐट पोर्ट्स माउथ इंडिया 20 मार्च 1901, पृ० 140
19. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 250-1 382, 398 परिशिष्ट, पृ० 3 जी० एम० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 107 चैपियन, 30 जुलाई (आर० एन० पी० बंग, 5 अगस्त 1899) हिंदू 23 फरवरी 1900; बंगाली 25 मई 1901. विदेशी पूंजी के प्रवाह को कल्पना करने वालों को प्रत्युत्तर देते हुए डी० ई० बाबा ने 1898 में टिप्पणी की : जब तक देश में विदेशी लुटेरे बड़ी संख्या में टिड्डी दल की तरह फैले रहेंगे और इसके सत्व और मांस को खाते रहेंगे, तब तक यहां के लोग किस प्रकार शाश्वत हो सकते हैं ? विदेशी निवेशक एक तो अपने यहां के लोगों को दूसरे स्थानों पर खींच ले जाते रहेंगे और इसके अतिरिक्त समय आने पर पूंजी को भी लौटा लेंगे (रिप० आई० एन० सी०, 1890, पृ० 50).
20. लोकमित्र 24 दिसं० (आर० एन० पी० बंग, 30 दिसंबर 1889). दत्त : 'इंग्लैंड ऐंड इंडिया,' पृ० 132. चैपियन 30 जुलाई (आर० एन० पी० बंग, 5 अगस्त 1899) हिंदू 23 फरवरी 1902; बंगाली 25 मई 1901.

- 21 नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 133. तथा देखिए, बही, पृ० 240, 382, 398 परिशिष्ट पृ० 7 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 700
22. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 122 तथा देखिए, हिंदू 23 फरवरी 1900. न्यू इंडिया, 26 अगस्त, 1901
- 23 नौरोजी पावर्टी, पृ० 34, 568-9 स्पीचेज, पृ० 196. परिशिष्ट, पृ० 7 इंडिया 10 मई 1901 में प्रकाशित एक पत्र, पृ० 233 और स्पीचेज ऐट पोटंस माउथ, इंडिया, 20 मार्च 1903, पृ० 140 बंगाली 25 मई 1901, इंडियन पोपुल 23 फरवरी 1905, 'हिंदुस्तान रिब्यू' तथा 'कायम्य समाचार' के संपादक ने विदेशी पूँजी के प्रयोग को 'एक अन्तर्राष्ट्रीय लूट खसोट पद्धति' की सज्ञा दी (फरवरी 1903 पृ० 193) तथा गोखले, बेलजी आयोग, खंड III, पृ० 18140-1
- 24 नौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 3 बंगाली 25 मई 1901. जी० एस० अय्यर : 'लांड कर्जन का बजट भाषण—एच० आर०, अप्रैल 1903, पृ० 318
- 25 बंगाली 1 जून 1901 तथा मराठा 30 जून 1881
26. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 673, 700, 739-40 तथा नौरोजी : पावर्टी, पृ० 227 मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901) 18 जुलाई 1883 के 'भारत मिहिर' में एक लेखक ने मकेन किया . ब्रिटिश पूँजी अमरीकिया की स्थिति के सुधार के लिए और हिंदुस्तानियों को पृथ्वी से नामशेष करने तथा अफीकी हठिनियों को अमरीकियों के दास बनाने में तथा मिन्न को अपना उपनिवेश बनाने के लिए उत्तरदायी है (आर० एन० पी० बग, 21 जुलाई 1883).
27. न्यू इंडिया 12 अगस्त 1901 (बल दिया गया). न्यू इंडिया के अगल श्रक में उसने लिखा : वर्तमान आर्थिक और विनीय परिस्थितियों में हम इंग्लैंड के उद्यम द्वारा प्रवर्तित तथा ब्रिटिश पूँजी द्वारा संचालित प्रत्येक उद्योग को आर्थिक खतरे के एक नए श्रोत के रूप में देखने को विवश हो गए हैं (19 अगस्त 1901). 1890 में 'केसरी' में प्रकाशित एक लेख में तो यहा तक घोषित किया गया कि 'विदेशी पूँजी के गुणगान करने वाला महादेव रानाडे देशद्रोही है' (कैलाक में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 123).
28. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 757, केसरी 22 जून (आर० एन० पी० बग 26 जून 1897), दत्त . स्पीचेज, II, पृ० 82, एल० एम० घोष सी० पी० ए०, पृ० 781.
- 29 जी० एस० अय्यर रि० आई० एन० सी० 1901, पृ० 121 तथा मद्रास स्टैंडर्ड, 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901).
- 30 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 132 बाबा ने 1899 में टिप्पणी की : 'स्वदेशी पूँजी ही एकातत लाभदायक हो सकती है, वह पूँजी ही भावी पूँजी का सबधन करेगी' इसकी प्रक्रिया मद होने पर भी निश्चित अवश्य होगी (रिप० आई० एन० सी०, 1899, पृ० 59).
- 31 'भारत मिहिर' 17 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 21 जुलाई 1883). जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 682, 700 नौरोजी . स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 556 हिंदू 23 फरवरी 1900 जी० एस० अय्यर : बेलजी आयोग, खंड III, प्रश्न 18664 ई ए—परिशिष्ट, पृ० 2.
32. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 682
33. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ 782. बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 626, मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, जून 1901).
34. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 756, 779, 789. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 257

33. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 673, 700, 739-40, 746. गोखले : वेलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18140, 18145. मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901). जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी 1901, पृ० 74. ई ए, पृ० 123, 127.
36. कर्जन . स्पीचेज III, पृ० 141.
37. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 673. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 123.
38. एच० आर०, फरवरी 1903 का संपादकीय, पृ० 193-4 तथा जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 123.
39. उदाहरणार्थ देखिए, जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 124. स्वीकृत तथ्य के लिए देखिए, स्वयं, कर्जन : स्पीचेज, पृ० 140.
40. देखिए नीचे तथा अध्याय XIII 'दि ड्रेन'.
41. यद्यपि दादाभाई नौरोजी ने इस दृष्टिकोण का अत्यंत सशक्त तथा सुस्पष्टता से विश्लेषण किया था तथापि निकासी सिद्धांत के इस भविष्यवक्ता का समकालीन नेताओं ने भी व्यापक रूप से अनुमोदन किया. देखिए, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 38, 54, 567-8, स्पीचेज, पृ० 250-1, 395-6, 614 परिशिष्ट, पृ० 7-8, इन इंडिया, 2 सितंबर 1904. मराठा 30 जनवरी 1881, हिंदू 30 अक्तूबर 1885, 23 फरवरी 1900. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 756-7 राय : पावर्टी, पृ० 126. गोखले, वेलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18140, 18142, 18170, 18176. जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 107. रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 121. ई ए, पृ० 128. हितवादी 10 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 5 अगस्त 1899) स्वदेशमित्र 22 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 26 जनवरी 1901) बंगाली 25 मई 1901; न्यू इंडिया 18 नवंबर 1901; मराठा 7 दिसंबर 1902.
42. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 194. बंगाली 25 मई 1901; 1903 में भारतीय राष्ट्रवादियों पर बरसते हुए नाई कर्जन ने कहा :
विदेशी पूँजी के भारत में ग्रान प्रवाह के विरुद्ध प्रस्तुत तर्क कि यह भारतीयों को निर्धन बनाने का साधन है तथा यह देश की मर्पति को विदेशों में खींच ले जाता है, मुझे तो मूर्खतापूर्ण और खतरनाक मणिप्रय दिखाई देता है. जब ब्रिटेन ने अमरीका और चीन में अपनी पूँजी प्रवाहित की तो उन देशों के वासियों ने कभी यह शिकायकत नहीं की कि उनका सत्यानाश किया जा रहा है. विदेशी सरकार द्वारा मिस्र के साधनों और नील बाघनी व्यवस्था करने पर किसी को भी उस देश पर दया नहीं आई. आज अपने देश के लाभों का साधन बनने जा रहे रूस के उद्योगों का विकास विदेशी पूँजी तथा विदेशी मस्तिष्क द्वारा ही हुआ. अब जब अमरीका अपनी संचित पूँजी, अपनी आश्चर्यजनक आविष्कार क्षति, अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा आदि साधनों को हर्नैड में बाड़ ला रहा है तो हममें से कोई भी विदेशी निकासी से अपने जुसे जाने के दुर्भाग्य पर बैठकर आंसू नहीं बहाता (स्पीचेज, खंड III, पृ० 140-1).
43. नौरोजी . स्पीचेज, पृ० 152-3, 319, 312, 395 परिशिष्ट, पृ० 5, 7-8. पावर्टी, पृ० 34, 38, 135 दादाभाई नौरोजी और गोखले, वेलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18168-9, 18183-4. हिंदू, 23 फरवरी 1900 और अध्याय XIII 'दि ड्रेन' पर वेलबी आयोग को प्रस्तुत विवरण में 1900 दादाभाई ने लिखा : अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश शासनपद्धति ब्रिटिश भारतीयों को अपने ही उत्पादों अथवा साधनों का उपयोग नहीं करने देती, उन्हें पूँजीविहीन तथा असहाय बनाती है, तब विदेशी पूँजिपति आने हैं और बिनाश की बची-खुबी कसर पूरी कर देते हैं (स्पीचेज,

- पृ० 382) और हमारे लिए चाहने न चाहने को कुछ नहीं, सारी स्थिति अनिवार्यता की है। हमारे लिए यह कोई साधारण कारोबार की बात नहीं (वही, पृ० 319)
- 44 मराठा 30 जनवरी 1881. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 699-700, 786-825. नौरोजी : स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 57; हितवादी 10 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 18 फरवरी 1889) बंगाली 10 जून 1901. ऐडवोकेट 27 नवंबर (आर० एन० पी०, यू० पी०, 29 नवंबर 1902). जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 119-22, 132, 560-3 रंगालय 18 फरवरी, हितवादी 20 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 28 फरवरी 1901), इंडियन पीपुल 27 फरवरी 1903.
- 45 नौरोजी पावर्टी, पृ० 227, 567-9 स्पीचेज, पृ० 250, 382-3, 397, 615. परिशिष्ट, पृ० 7 स्पीचेज ऐट पोर्ट्समाउथ, इंडिया 20 मार्च 1903, पृ० 140 पर प्रतिवेदित; अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाषण, इंडिया 2 सितंबर 1904, पृ० 116 में प्रतिवेदित मद्रास स्टैंडर्ड्स 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901). जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 127-8, 166, 268 तथा लांड कर्जन का बजट भाषण, एच० आर० अप्रैल 1903, पृ० 318-9. युनाइटेड इंडिया, 24 फरवरी (वी० ओ० आई०, 14 मार्च 1903) दादाभाई नौरोजी ने लिखा . ब्रिटिश शासक प्रथम दर्जे के लुटेरे हैं वे प्रथम तो भारत को दीन-हीन और असहाय बना देंगे, फिर लूट के माल के कुछ भाग को अपना बताकर यहाँ ले आएंगे और उससे पुनः भारत की भूमि और श्रम साधनों का शोषण करेंगे (पावर्टी, पृ० 568). तुलनीय जैक्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 208. इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अन्त्य में इंग्लैंड के निवासी बागान बघको, व्यापारिक और बैंक सब्जी प्रतिष्ठानों तथा रूपयों में दी गई ऋणशक्ति के भागों के ही स्वामी थे। ये सारे अधिकार अपने बच्चों को शिक्षित करने अथवा शान जीवन व्यतीत करने के लिए भारत से इंग्लैंड लौटे अगरेज भारतीय अधिकारियों द्वारा बहा भी लाए गए थे ये सारे लाभ आंशिक रूप से भारतीय पूँजी की लूट-खसोट और आंशिक रूप से भारतीयों से उगाहे राजस्व के पुनर्निवेश के ही फल थे। ये ब्रिटिश पूँजी के निर्यात से उत्पादित नहीं थे इन लाभों की आय व्यावसायिक खाने में जुड़ती रही और फिर इससे भारत में प्रतिवर्ष आंशिक निकासी में स्वभावतः उल्लेखनीय वृद्धि होती गई
- 46 नौरोजी स्पीचेज, पृ० 382-3 तथा देखिए उनकी पावर्टी, पृ० 133
- 47 जी० एम० अय्यर 'लांड कर्जन पर स्पीच', एच० आर० अप्रैल 1903, पृ० 319 तथा देखिए, नौरोजी पावर्टी, पृ० 567 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 268
- 48 देखिए नोबे पार्सटिपणी 50
- 49 इस प्रकार हमारी स्थिति बहुत अव्यवस्थित है। उस बच्चे के समान है जिसे उसके स्नेही माता-पिता मिठाई देते हैं परंतु वह उसकी अजीर्णता के कारण उसके लिए बिस्कि का काम करती है इसी प्रकार विदेशी तत्व हमारी दुर्बल पाचनशक्ति को कुड़ाने वाला अधिकांश में बाहर फिकने वाला और थकावट से चूर करने वाला है इस समय भारत की स्थिति यह है कि प्रत्येक दूसरे राष्ट्र के लिए स्पर्धनीय इसे अपने लिए बिस्कीला प्रभाव डालने वाला प्रतीत होता है (नौरोजी : पावर्टी, पृ० 54)
- 50 नौरोजी . स्पीचेज, पृ० 615-6 1901 में इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए बी० सी० पाल ने लिखा . 'विदेशी पूँजी हमारे साधनों का शोषण कर रही है। 10 से 15 प्रतिशत की दर से लाभों की स्थायित्व कर रही है, इस प्रकार 7-10 वर्ष के भीतर वह अपने को दुगुना बनाने जा रही है। देश का शोषण। इस पूँजी का देश में पुनः निवेश हमारे ऊपर नया भार लादना होगा। इससे देश में आर्थिक पूँजी के विकास को निरंतरता मिलेगी तथा देश की बुद्धमरीचक

जनता और अधिक तथा स्थाई दरिद्रता का उपभोग करेगी' (न्यू इंडिया 18 नवंबर 1901). तथा देखिए, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 38, 567, स्पीचेज, पृ० 397. परिशिष्ट पृ० 6-7 तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज कांग्रेस में भाषण, इंडिया 2 सितंबर 1904, पृ० 116. 'मद्रास स्टैंडर्ड', 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901); बंगाली 1 जून 1901; जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 128.

51. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 228. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 699, 779, राय : पावर्टी, पृ० 322, 324, गोखले, बेलबी आयोग खंड III, प्रश्न 18146, 18156, 18171, 18176 जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०, 1898, पृ० 107 और एच० आर० जून 1910, पृ० 445, 447. बाबा : रिप० आई० एन० पी० 59; स्वदेशमित्र 22 जून (आर० एन० पी० एम०, 26 जनवरी 1901), हिंदू 13 जून 1904
52. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 54, 194, 228'. एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 270.
53. नौरोजी . पावर्टी, पृ० 228
54. वही, पृ० 194, 228.
55. वही, पृ० 54, 194, 228.
56. हिंदू, 6 अक्तूबर 1885 तथा जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 756, 779. नौरोजी . स्पीचेज, पृ० 398
57. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 194
58. नौरोजी स्पीचेज, पृ० 634. राय पावर्टी, पृ० 322. बाबा रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 59 स्वदेशमित्र 22 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 26 जनवरी 1901). जी० एस० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 121.
59. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 70
60. वही, पृ० 757 नौरोजी ऐंड गोखले बेलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18170 नौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 7 और पादटिप्पणी 21 तथा 22 उपर्युक्त
61. जी० एस० अय्यर : इंडियन रिव्यू फरवरी 1912, पृ० 83 तथा देखिए राय . पावर्टी, पृ० 324
62. न्यू इंडिया, 26 अगस्त, 2 सितंबर 1901.
63. 'स्पीच एण्ड पोर्ट्स माउथ इन इंडिया', 20 मार्च 1903, पृ० 140
64. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 699-700 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 107. एच० आर० अप्रैल 1903, पृ० 320 में प्रकाशित दन स्पीचेज II, पृ० 82.
65. युनाइटेड इंडिया 9 जून (इंडियन स्पेक्टेटर 9 जुलाई 1904). जी० एस० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 121
66. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 699; बंगाली 25 मई 1901 न्यू इंडिया 26 अगस्त 1901.
67. जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 249.
68. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 788 बंगाली 1 जून 1901, 17 फरवरी 1903 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० पी० 1902 पृ० 73-4. ई ए पृ० 127. हिंदू 13 जून 1904. केसरी 9 मई (आर० एन० पी० बव, 13 मई 1905).
69. बंगाली 9 जून 1901. दाबाभाई नौरोजी का जे० एन० टाटा को पत्र, तिथि 16 सितंबर 1902. ममानी की रचना में उद्धृत पूर्वोद्धृत, पृ० 448.
70. बंगाली, 17 फरवरी 1903. जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 127.
71. बंगाली, 1 जून 1901

- 72 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 688-9
- 73 उदाहरण के रूप में देखिए, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 700, हिंदू 10 अक्टूबर 1885
- 74 रानाडे एसेज, पृ० 186
- 75 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 673
- 76 1885 में जोशी ने लिखा राजनीतिक दृष्टि से यदि हम इतिहास का गलत अध्ययन नहीं करते तो यह निश्चित है कि धन संपत्ति की आर शक्ति का आकर्षण रहेगा तथा देश में सुदृढ़ विदेशी व्यापारिक हित राज्य में निश्चित रूप से अत्यंत कष्टदायक सक्रिय सत्त्व बनेंगे यह सब अपने निजी स्वार्थों तथा उद्देश्यों के लिए अपने वश भर शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करेंगे तथा सरकारी निर्णयों का अपने पक्ष में करने के लिए दबाव डालेंगे (पूर्वोद्धृत, पृ० 640) तथा देखिए वही, पृ० 700, बंगाली 10 जून 1901
- 77 मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901) बंगाली 10 जून 1901
- 77-ए देखिए लांडे डफरिन का भाषण तथि 6 नवंबर 1888
- ‘इन दायित्वों के साथ मातृभूमि के अपरिमित व्यावसायिक हितों का दायित्व भी जुड़ा है, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीया व महान लाभ के लिए सरकार को उधार दी गई अथवा रलव जैसे कतिपय उद्यमों में लगाई गई 2200 लाख पाउंड स्टर्लिंग की पूंजी करती है हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम देश में सर्वप्रथम इस दश के हितों का संरक्षण सर्वथा उचित ही है परंतु सा १० द्वारा उन लोगों के प्रति जिन्होंने सरकारी गारंटी के विश्वास पर भारत में साधनों के विकास में बहुत बड़ी रकम लगाई है अथवा जिनोंने शाही भारतीय सरकार के नियंत्रण पर अपनी पूंजी का निवेश किया है, अपने दायित्व को उपेक्षा एक कानूनी अपराध होगा यही स्थिति चायबागानों और नाल व खता, पटमन तथा अन्य इस प्रकार के उद्योगों में निजी ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा उत्पादन में निवेशित विपुल पूंजी का है क्योंकि उन्होंने भी इसी विश्वास पर पूंजी का निवेश किया है कि भारत में अंगरेजी शासन तथा अंगरेजी न्याय सुदृढ़ रहेगा’ (गवर्नर जनरल का भारत सचिव को प्रेषण, स० 67 तथि 6 नवंबर 1888)
- 78 बंगाली ने 10 जून के अंक में लिखा ‘ब्रिटिश पूंजी का देश में बढ़ता हुआ निवेश तथा उसपर भ्रष्ट चक्रवृद्धि ब्याज ही भारत सरकार की ब्रिटिश प्रवृत्ति तथा परंपराओं के पूर्ण तथा स्वतंत्र विकास में संचमूच ही बाधक है गत वर्षों से भारत सरकार की चरित्रगत यह नीति ही प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है सही कारण यह है कि वर्षों हमारे प्रतिनिधियों का बजट निर्माण में भाग नहीं लेने दिया जाता और यदि भारतीयों को यह अधिकार नहीं दिया जाता तो इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय संचमूच ही विदेशी शोषकों के हितों के विरुद्ध साधनों की खोज करेंगे
- 79 27 फरवरी 1903 इसी प्रकार पी० पी० पाल ने ‘न्यू इंडिया’ के 2 नवंबर 1902 के अंक में लिखा भारत सरकार यह दोहराते हुए स्वीकार कर चुकी है कि वह देश के प्राकृतिक साधनों के तथाकथित विकास के लिए भारत में यथासंभव अधिकाधिक ब्रिटिश पूंजी लाना चाहती है इस नियंत्रण के पश्चात् सरकार ब्रिटिश पूंजी तथा उसके अधिकारियों को उनके द्वारा मांगी जाने वाली सुरक्षा देने को विवश है भारतीयों को बजट के संबंध में बोलने देने के अधिकार से वंचित करने का वास्तविक कारण भी यही है ‘न्यू इंडिया’ के 11 दिसंबर 1902 के अंक में उन्होंने लिखा ‘कहने की आवश्यकता नहीं कि केवल बरिड बगास पर ही नहीं प्रत्युत सारे असहाय भारत पर अधिकांश ब्रिटिश पूंजी ही शासन करती है’ 14 फरवरी 1903 के अंक

में बंगाली ने टिप्पणी की : जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को मनचाहा रूप देता है, उसी प्रकार सरकार वाणिज्य सदन के हाथ में है और उसकी इच्छा से कार्य करती है' तथा देखिए, हिंदू 6 मार्च 1894 मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 1 जून 1901). बंगाली, 10 जून 1901. रंगालय 18 फरवरी; हितवादी 20 फरवरी; वसुमती 21 फरवरी (आर० एन० पी० बंग, 28 फरवरी 1903) सजीवनी 5 मार्च (आर० एन० पी० बंग, 14 मार्च, 1901), जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 120-2

80. रानाडे : एसेज, पृ० 66
81. नौरोजी . पावर्टी, पृ० 34, 135, 567-8 स्पीचेज, पृ० 322, परिशिष्ट, पृ० 55-6 गोखले, वेलबी आयोग, खंड III, प्र० 18170, जी० एस० अय्यर . वही, प्र० 19636, 19680-1, 19644 रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 121-2 मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901)
82. विदेशी पूँजी की महायत्ना से किसी देश के विकास में और विदेशी पूँजीपतियों द्वारा किमी देश के साधनों के शोषण में आकाश-गानाल का अंतर है (बंगाली, 25 मई 1901)
83. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 739
84. इस तर्क की सारी रूपरेखा का विकास उपलब्ध है . नौरोजी . पावर्टी, पृ० 228-9, जोशी . पूर्वोद्धृत, 673, 739; मराठा 30 अगस्त 1891, मद्रास स्टैंडर्ड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 1 जून 1901) जी० एम० अय्यर रिप० आई० एम० पी० 1901, पृ० 121-2 डी० जी० कर्वे के अनुसार, ब्रिटिश रानाडे भी इसी दृष्टिकोण के थे देखिए उनकी पुस्तक, रानाडे : दि प्रोफिट आफ़ लिबरेटेड इंडिया, पृ० XXIX.
85. नौरोजी पावर्टी, पृ० 229
86. 1881 में दादाभाई ने लिखा भारत की वर्तमान उदासीनता की निश्चित परिस्थितियों में अंगरेजी पूँजी से भारत के लाभ उठाने का असंदिग्ध रूप से सर्वोत्तम साधन सरकार द्वारा कार्यों का संचालन होगा. " भारत के निश्चित रूप से लाभान्वित होने की योजना यह होगी कि सरकार सभी प्रकार के पूँजीमापेक्ष सार्वजनिक कार्यों अथवा खानों अथवा सारे ही कागोबार को अपने हाथ में ले ले उनमें अंगरेजी पूँजी भले ही हो परंतु अंगिकरण स्वदेशी हो तथा केवल सर्वथा अपरिहार्य स्थिति में ही योग्य यूरोपीयों को उनका प्रधान बनाया जाए (पावर्टी, पृ० 228 तथा देखिए, वही, पृ० 229. जोशी के दृष्टिकोण को देखने के लिए देखिए उनकी राईटिंग एंड स्पीचेज, पृ० 672-3 तथा 746 और देखिए 'न्यू इंडिया' 16 दिसंबर 1901 इससे पूर्ववर्ती 'बाबू समाचार' के 18 मई 1880 के अंक का दृष्टिकोण तो और भी रोचक है : 'भारत में अभी अभी आविष्कृत सोने की खानों के विदेशी स्वामित्व पर आपत्ति करते हुए उमने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया क्योंकि देशवासी अपना समवाय बनाने में असमर्थ हैं अतः लोकहित में सरकार को खानों को खुदाई का कार्य अपने हाथ में ही लेना चाहिए इसके अतिरिक्त इन खानों के लाभों का उपयोग देशवासियों पर लादे करो के बोझ को कम करने में ही करना चाहिए (आर० एन० पी० बंग, 8 मई 1880).
87. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 672-3, 698 नौरोजी : पावर्टी, पृ० 229. इसके साथ ही जोशी महोदय सरकार की प्रवृत्ति को परखने और उसके विरुद्ध विरोध प्रकट करने में अत्यंत पटु थे. उन्होंने बागान जैसे उद्योगों को भारतीय निधि से और भारतीयों के व्यय तथा मूल्य पर विकसित करके विदेशी पूँजीपतियों को साधारण मूल्य दर पर सौंपने की तीव्र निंदा की (देखिए पृ० 699).

और यह कि व्यवहार में सरकार भारतीयों की नही प्रत्युत विदेशी उद्यमियों की सहायता कर रही थी तथा उन्हें उपदान प्रदान कर रही थी (पृ० 825).

88. इस संबंध में एकमात्र उपलब्ध अपवाद बंगाली के .28 जुलाई 1883 के ग्रंथ का निम्नलिखित अवतरण है : न ही हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार एक सरकार दूर की कौड़ी लाने की बान छोड़कर व्यापार और वाणिज्य के विध्वंसक कानूनों को लौटाए बिना उन्हें उत्साहित कर सकती है.
89. उद्धृत : भोलानाथ चंद्र, राजा दिगंबर मिश्र (दो खंड) (कलकत्ता 1896) खंड I, पृ० 75.
90. मराठा 11 सितंबर 1891.
91. 1896 का प्रस्ताव III तथा देखिए प्रस्ताव XIII, 1899 का XIII 1901 का VIII.
92. जी० बी० जोशी के विचारों के लिए देखिए उनकी 'राटिसम ऐंड स्पीचेज', पृ० 743, 750, 785-6, 807. 1885 में उन्होंने लिखा : सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता यह है कि सरकार पूरे तौर से, दिल और दिमाग से, हमारे साथ हो. उसकी महायता के बिना हम अपनी वर्तमान दुर्बलता तथा ना-तैयारी की स्थिति में राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. इस भयंकर प्रतियोगिता के सामने, जिगके शिकार हम हैं. सरकार को राष्ट्र की सच्ची आवश्यकताओं को अवश्यमेव अभिस्वीकार करना चाहिए और मित्रतापूर्वक राष्ट्रीय उद्योगों के हित के लिये अपने को जोड़ना चाहिए (यही, पृ० 743). तथा देखिए, वही, पृ० 746; जस्टिस रानाडे के विचारों के लिए देखिए उनके निबंध, 'नीदरलैंड्स इंडिया ऐंड दि कल्चर सिस्टम', 'आइरन इंडस्ट्री पायनीयर अटैम्प्ट्स' और 'इंडिस्ट्रियल काफरेम' तथा देखिए, के० टी० तैलंग : 'ट्रेड ऐंड प्रोटेक्शन' (बंबई 1877) पृ० 49; 'बंबई समाचार' 8 जुलाई (आर० एन० पी० बंब, 9 जुलाई 1881); मराठा 14 फरवरी 1886, 22 सितंबर 1895, 18 नवंबर 1900, 30 मार्च 1902; बगवासी 31 मई (आर० एन० पी० बंग, 7 जून 1890). मालवीय स्पीचेज, पृ० 250. जी० एम० अय्यर : वेलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18661, और 'ई ए', पृ० 264, एन० के० एन० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 138. हिंदू 21 अप्रैल 1902. वृत्तान्त चिंतामणि, 15 मार्च (आर० एन० पी० एम, 15 मार्च 1900), पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 750. दत्त, ई० एच० II, पृ० XVII, स्पीचेज I, पृ० 24 सी० पी० ए०, पृ० 490-1. आर० सी० दत्त ने 1904 में बड़ीदा के राजस्व मंत्री बनने पर सर्वप्रथम कार्य यह किया कि उन्होंने निजी उद्यमियों को नए उद्योग खोलने में सहायता का वचन दिया. —जे० एन० गुप्ता लाइफ ऐंड वर्क आफ रमेशचंद्र दत्त (लंदन 1921) पृ० 402.
93. रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 123
94. वही, मराठा 12 सितंबर 1895, 18 जनवरी 1900, दत्त : ई० एच० I, पृ० 289. गोखले : स्पीचेज, पृ० 28.
95. भारतीय उद्योग आयोग 1916-18 का प्रतिवेदन, पृ० 2. 1880 के अकाल आयोग ने इस नीति का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया. उसने यद्यपि देश के उद्योगीकरण की आवश्यकता पर बल दिया तथापि उसने स्वतः सिद्ध सत्य के रूप में यह अनुभव किया कि राज्य के किसी भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता. उसने इस प्रकार के हस्तक्षेप से बहुत बड़ा खतरा यह है कि एक तो इससे व्यापार के सशक्त सिद्धांतों के प्रसार को ठेस पहुंचेगी तथा दूसरे निजी उद्यम के प्रवर्तन में भी बाधा उपस्थित होगी. -- हमारा विश्वास है कि परोक्ष उपायो, रेलवे के विस्तार तथा स्थानीय व्यापार और विदेशी वाणिज्य के विकास

आदि से ही लक्ष्य प्राप्त होगी उद्योग की किसी शाखा विशेष को अनिश्चित सहायता देने से कोई भी लाभ नहीं होगा. (रिपोर्ट ऑफ इंडियन फैमिन कमिशन-1880, भाग II अनुभाग कंडिका, 2 तथा 3).

96. भारतीय उद्योग आयोग 1916-18 का प्रतिवेदन, अध्याय VIII तथा अनस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 210.
97. कर्जन : स्पीचेज II पृ० 164.
98. रानाडे : एसेज, पृ० 88, 165, 166
99. वही, पृ० 33, 86-7.
100. वही, पृ० 32, 89 तथा देखिए जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 743, 809.
101. रानाडे : एसेज, पृ० 165
102. वही, पृ० 94.
103. वही, पृ० 87-9, 91, 95 उदाहरणार्थ रानाडे द्वारा प्रस्तुत स्थिति का निम्नलिखित तीखा उपस्थापन देखिए : रेलवे नीति के समर्थकों के लिए आपत्ति प्रस्तुत करना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस सिद्धांत को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि सरकार को रेलवे अथवा नहरों के लिए अथवा चाय, काफी उद्योगों के प्रवर्तन के लिए धन जुटाने का कोई अधिकार ही नहीं — (वही, पृ० 91) और देखिए, जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 740, 809, मराठा 18 नवंबर, 1900
104. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 797, 812 रानाडे : एसेज, पृ० 91
105. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 797 तथा वही, पृ० 812, 826 रानाडे एसेज, पृ० 91 2, 190, 193 जी० एम० अय्यर . ई ए, पृ० 155
106. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 812.
107. वही तथा रानाडे : एसेज, पृ० 190, 193 जी० एम० अय्यर, ई ए पृ० 163 5
108. रानाडे : एसेज, पृ० 89, 92-3, 178, 193. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 797.
109. रानाडे : एसेज, पृ० 95. जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 797 दि इंडियन स्पेक्टेटर ने अपने 26 अक्टूबर 1884 के अंक में यह इच्छा प्रकट की कि सरकार इंग्लैंड में श्रृंगार ले और भारतीयों को श्रृंगार दे
110. रानाडे : एसेज, पृ० 95-6
111. वही, पृ० 177 तथा वही, पृ० 89, 169, 189. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 809-10 एम० बी० नामजोशी, मराठा 30 अगस्त 1891 में; द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा, 11 सितंबर 1891. हितावादी 10 फरवरी (आर० एन० पी० बंग, 18 फरवरी 1892) स्वदेश-मित्र, 13 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 17 अक्टूबर 1903) जी० एम० अय्यर, ई ए, पृ० 264 या गारंटी लोहा और इस्पात जैसे उद्योग के लिए विशेष रूप से आवश्यक थी क्योंकि इस उद्योग में प्रारंभिक कतिपय प्रयोगात्मक वर्षों में लाभ की आशा नहीं की जा सकती। अतः इनमें कोई पूंजीपति तब तक पूंजीनिवेश का साहम नहीं करेगा जब तक उसे पर्याप्त उदार रियायतों का विश्वस्त आश्वासन, प्रतिभूत रेलवे कंपनियों को पूंजी पाने में सहायक आश्वासन जैसा न मिले. (रानाडे : एसेज, पृ० 168-9)
112. मराठा 9 अगस्त 1885, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 746.
113. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 747. रानाडे : एसेज, पृ० 137.
114. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 747.
115. वही, पृ० 648, 680, 689, 747-8, 810, 826. रानाडे : एसेज, पृ० 89, 189, 193, हिंदू,

- 23 मार्च 1885 द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा 11 सितंबर 1891, मराठा 30 मार्च 1902 राय . 'पावर्टी', पृ० 143 जी० एम० अय्यर, ई० ए० पृ० 155
- 116 1887 की राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार में अनुरोध किया कि वह पहले से ही अस्तित्व में आए आदेशों पर और अधिक कठोर आचरण करके भारतीय उत्पादनों को सरकारी कार्यों के उपयोग में लाकर उन्हें प्रोत्साहित करे... प्रस्ताव VII और दखिण, इंदु प्रकाश, 19 मई (आर० एन० पी० बब, 15 जून 1881) बंबई समाचार 6 जुलाई (वही, 9 जुलाई 1881), बंबई क्रानिकल 19 नवंबर, हिनेच्छु 23 नवंबर; गुजराती 19 नवंबर, ववई समाचार 20 नवंबर, अखबार सौदागर 20 नवंबर (वही, 25 नवंबर 1882) लोकमित्र, 26 नवंबर (वही, 2 दिसंबर 1882), रास्त गुप्तार 10 जुलाई (वही, 16 जुलाई 1887), ए० बी० पी०, 14 अप्रैल 1881, 23 मार्च 1882, नव विभाकर 20 जून, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग 2 जुलाई, 6 अगस्त 1881); चारुवृत्त 8 जुलाई (वही, 16 जुलाई 1881), बग 11 मार्च, 9 सितंबर 1882 काशी सार्वजनिक सभा का स्मरण प्रपत्र, 1886 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन, पृ० 451, मराठा 14 फरवरी 1886, हिंदुस्तानी 6 अक्तूबर आर० एन० पी० एन०, 8 अक्तूबर 1891) अखबारे आम 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०, 1 नवंबर 1887), केसरी 23 सितंबर (आर० एन० पी० बाबे 27 सितंबर 1890), रानाडे एसेज, पृ० 178, 189, 190, 193 के० जी० नाट्ट, इन मरगा 10 अगस्त 1891 में उद्धृत द्वितीय उद्योग सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा 11 सितंबर 1891 एम० के० नय्यर, रिप० आई० एन० गी० 1895, पृ० 74 राय पावर्टी, पृ० 39-40
- 117 कलकत्ता के व्यापारमंडल का 31 जनवरी 1890 का अभिभाषण, कर्जन स्पीचेज पृ० 33 पर उद्धृत, 1880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन उद्योग आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की औद्योगिक प्रगति को तीव्र बनाने के लिए भारत में सरकार के तथा रेलों के भंडार खरीदने के उपायों में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए
- 118 30 जून (आर० एन० पी० एन०, 6 जुलाई 1898)
- 119 युनाइटेड इंडिया 11 अगस्त (बी० ओ० आर्द० 31 अगस्त 1894), मराठा 14 फरवरी 1886. रानाडे एसेज, पृ० 189, 193 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 810
- 120 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 743
121. वही, पृ० 743, 813, 819-20 रानाडे एसेज, पृ० 32-3, 193 नेटिव ओपिनीयन 20 दिसंबर 1885, हिंदू 21 अप्रैल 1902, 1870 के वर्षों में बंबई के स्वदेशी पत्रों का यह एक अत्यंत लोकप्रिय सुभाव था उदाहरणार्थ देखिए गुजरात मित्र, 22 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 27 जनवरी 1871) जामे जमशेद 21 मार्च (वही, 22 मार्च 1873) शमशेर बहादुर, 12 अप्रैल (वही, 12 अप्रैल 1873), बंबई समाचार 16 दिसंबर (वही, 22 दिसंबर 1873) 6 जून 1886 के मराठा ने सरकार से देश के खनिज साधनों के विकास को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया ताकि इससे अन्य उद्योगों के खोलने में सहायता मिले.
- 122 द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा 11 सितंबर 1892 और रानाडे एसेज पृ० 178.
- 123 रानाडे : एसेज, पृ० 177 जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 743. मराठा, 22 सितंबर 1895
124. अंतिम तीन उपायों की चर्चा इस पुस्तक के अन्य भागों में की गई है.
125. गोखले : 'स्पीचेज', पृ० 70

126. आर० एन० पी० बंग, 7 जून 1890.
127. 1900 में आर० सी० दत्त ने लिखा : यह सोचना संभव है कि औद्योगिक विकास को दृष्टि में रखकर काम करने वाली सरकार हमारी पीढ़ी की अवधि में ही जापान के लोगों में प्रचलित उत्तम ढंगों से भारत के परिश्रमी और कुशल व्यक्तियों को भी परिचित कराती, परंतु अपने ही लाभों के लिए काम करने वाले विदेशी व्यापारियों तथा प्रतियोगी उत्पादकों से इस उद्देश्य की पूर्ति होना कदापि संभव नहीं यही कारण है कि इस दिशा में कभी कोई प्रयत्न नहीं हुआ. (ई० एच० I, पृ० 289) और देखिए गुजरात मित्र, 22 जन० (आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी 1871) राजनारायण बोस : 'स्टडीज इन बंगाल रेनेसा', ए गुप्ता द्वारा संपादित (कलकत्ता 1958), पृ० 210 पर उद्धृत; भोलानाथ चंद्र. एम० एम० खंड : 1876, पृ० 12 राय : पावर्टी, पृ० 124-5. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 125-6 जमीयुल उलूम, 28 जून (आर० एन० पी० एन०, 7 जुलाई 1897) ठाका गजट, 11 जुलाई (आर० एन० पी० बंग, 16 जुलाई 1904). बहुत बड़े आशावादी रानाडे भी इस संबंध में प्रासंगिक संवेह और निराशा प्रकट करने को विवश हो गए. उदाहरणार्थ, हम इस देश में सरकार से उस प्रकार का कुछ करने की आशा नहीं कर सकते, जिस प्रकार फ्रांस और जर्मनी की सरकारों ने अपन पोत व्यापार और चीनी उद्योगों के लिए किया है, तथा सरकार को दिए जाने वाले सामान्य करों में से उपदान, अधिदान इन निरर्थक विवेचन में शक्ति का प्रयोग उसका अपव्यय ही है (एमेज, पृ० 189).
128. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 780, 786, 801 दत्त ई० एच० I, पृ० 251 तथा देखिए अध्याय II
129. रामगोपाल : पूर्वोद्धृत, पृ० 15-16.
130. शिवनाथ शास्त्री : 'मैन आई हैव सीन' (कलकत्ता 1919), पृ० 190.
131. बिपिनचंद्र पाल : 'मिमोरीज आफ माई लाइफ ऐंड टाइम्स (कलकत्ता 1932) पृ० 264 और शिवनाथ शास्त्री : पूर्वोद्धृत, पृ० 200.
132. 3 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 9 जुलाई 1870)
133. कर्वे : पूर्वोद्धृत
134. ये अर्थशास्त्री तथा सांख्यिक राय बहादुर जी० बी० जोशी जी के नाम से जाने जाते थे
135. कर्वे. पूर्वोद्धृत, पृ० XX प्रधान ऐंड भागवत पूर्वोद्धृत, पृ० 8 रामगोपाल पूर्वोद्धृत, पृ० 13.
136. प्रधान ऐंड भागवत : पूर्वोद्धृत, पृ० 8, 10 रामगोपाल. पूर्वोद्धृत, पृ० 18
137. रामगोपाल : पूर्वोद्धृत, पृ० 13
138. आर० एन० पी० बब; 19 जुलाई 1873. तथा 'आर्यमित्र', 13 जुलाई (वही).
139. वही, 28 अगस्त 1875 और बोध मुधाकर 5 फरवरी (वही, 15 फरवरी 1879; मुबोध पत्रिका 20 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1879).
140. बी० के० बोस : स्ट्रे टाट्स (कलकत्ता 1919) पृ० 47. बोस ने आगे लिखा कि नागपुर के लोहारों से बातचीत कर ली गई है और वे छुरे कैचिया बनाने को तैयार हो गए हैं. वे छुरे तथा कैचिया इस उद्देश्य से ही उगाही गई विशेष धनराशि में खरीदे गए और देश के विभिन्न भागों में भेजे गए. जुलाहों के करघा उत्पादन को मस्ता बनाने के लिए उनके प्रयोग में आने वाले अविकसित उपकरणों को भी मुधारने के प्रयास किए गए हैं (पृ० 47).
141. 15 दिसंबर 1874 के इंग्लिशमैन द्वारा उद्धृत बंगलौर हैराल्ड, जैसा कि भोलानाथ चंद्र द्वारा प्रस्तुत एम० एस०, खंड V, 1876, पृ० 12.

142. उसी में प्रस्तुत.
143. वही, खंड II, 1873, पृ० 621.
144. वही, खंड V, 1876, पृ० 10-2.
145. वही, खंड 1876, पृ० 12.
146. बी० बी० मजूमदार : हिस्टरी आफ पालिटिकल थाट : फ्राम राममोहन टु दयानंद (1821-84) खंड I, : बंगाल (कलकत्ता 1934) पृ० 379.
147. उदाहरणार्थ : भारत मिहिर, 15 मार्च ए० बी० पी०, 16 मार्च (आर० एम० पी० बंग 25 मार्च 1876).
148. शुल्कनीति की समीक्षा के लिए देखिए अध्याय 6.
149. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 207.
150. 8 दिसंबर 1881 और 10 फरवरी 1881
151. मालवीय : रपीचेज, पृ० 22.
152. आर० एन० पी० पी० एन०, 26 अप्रैल 1883.
153. संजीवनी, 9 फरवरी (आर० एन० पी० बंग, 16 फरवरी 1884) पत्र के संवाददाता ने आगे यह सूचना दी कि उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के निवासी, बंगाली, पंजाबी, राजपूत और मराठे, सभी सदस्य बन रहे हैं.
154. केलाक . पूर्वद्वित, पृ० 122.
155. बंबई मिलमालिक संघ का 1895 का प्रतिवेदन, पृ० 2.
156. संदर्भ के लिए विभिन्न संबद्ध प्रांतों के नेटिव प्रेस के संबंधित सप्ताहों के प्रतिवेदनो को देखिए. 5 जून 1891 के ग्रंथ में एजुकेशन गजट ने वकालत करते हुए लिखा : भारतीय उत्पादनों की अच्छाई-बुराई की चिंता किए बिना उनके प्रति ठीक उम्मी प्रकार महानुभूतिशील होना चाहिए, जिन प्रकार व्यक्ति अपने माता-पिता के गुण-दोषों की चिंता किए बिना उनका आदर करते हैं.
157. मराठा, 30 अगस्त 1891.
158. ए० सी० मजूमदार : इंडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास, 1917) पृ० 188.
159. और जब श्रोताओं ने 'नही' 'नही' कहा तो लालाजी भडक उठे और बोले : हा ! मैं कहता हूँ, हां ! अपने चारों ओर देखिए, ये भाड़फानूस, ये लैप और ये यूरोप में बनी कुर्तियां और मेजे, चुस्त कपड़े, टोपियां, अंगरेजी कोट, स्त्रियों की टोपियां, फ्राक, चांदी से मढ़ी हुई बेतें और आपके घरों की विलासितापूर्ण सजावट आदि, ये सब और कुछ न होकर भारत के दुर्भाग्य के उपहार हैं, भारत की भुखमरी के विजयस्तंभ हैं. आपने जो भी रुपया यूरोप के बने सामान पर खर्च किया है, वह प्रत्येक रुपया आपने अपने गरीब भाइयों से लूटा है, अपने ईमानदार कारीगरों से लूटा है जिसके फलस्वरूप अब वे बेचारे रोटी कमाने के योग्य तक नहीं रहे (रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 21).
160. रिप० आई० एन० सी 1894, पृ० 38.
161. इस पुस्तक का अध्याय 6 देखिए. 15 मार्च 1896 के ग्रंथ में मराठा ने लिखा : यह इस अन्याय का ज्वलंत प्रमाण है कि शिक्षित भारतीय मान्चेस्टर के वस्त्रों के विरुद्ध धर्मगुरु का प्रचार कर रहा है.
162. मराठा 15 मार्च 1896 तथा वही, फरवरी 1896; बंग निवासी 9 फरवरी (आर० एन० पी० बंग, 15 फरवरी 1896) तथा देखिए धारावार वृत्त (6 फरवरी आर० एन० पी० बंग, 8

- फरवरी 1896) अण्णोदय 16 फरवरी, ज्ञान सागर 17 फरवरी (वही, 22 फरवरी)
163. अमृत बाजार पत्रिका ने 3 फरवरी 1896 के अंक में लिखा भारत के सभी प्रधान नगरों में वैतनिक अधिकर्ता नियुक्त कीजिए और उन्हें महायन्त्रों के लिए सहायक दीजिए पत्रिका के अनुसार इस उद्देश्य के लिए धन सीधे मिनमालिनी की जेना से आना चाहिए और 'देशी मित्र' 20 फरवरी, नागा समाचार 15 फरवरी, अण्णोदय 16 फरवरी, ज्ञान सागर 17 फरवरी, जगदादश 16 फरवरी, प्रभाकर 19 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 22 फरवरी 1896)
164. मराठा 15 मार्च 1896
165. जामे जमशेद 24 जनवरी (आर० एन० पी० बग, 25 जन० 1896), मोदवृत्त 30 जनवरी और जगदादश 26 जनवरी (वही, 1 फरवरी 1896), सुबोध पत्रिका 5 फरवरी, धारवार वृत्त 6 फरवरी, अण्णोदय 2 फरवरी (वही, 8 फरवरी 1896), मराठा 9 फरवरी 15 मार्च 1896 और महाराष्ट्र से नटित औपनिष्यन 2 फरवरी, 26 मार्च 1896, तथा दक्षिण पादलिपणी 161
166. आर० एन० पी० बग, 22, 29 फरवरी 1896 तथा नीचे 169 की पादलिपणी में प्रस्तुत मदर्थ
167. 2 मार्च 1896 के न्याय मिथु के अनुसार उस वर्ष अंग्रेजी फुडो के बड़े मोटे मोटे गन्धर होली की जाग में फेंके गए, आर० एन० पी० बग, 7 मार्च 1896
168. जगदहितेच्छा 7 मार्च (आर० एन० पी० बग 14 मार्च 1896)
169. बर्वाई बगद (पब्लिश) गोपनाय विभाग 1 विश्व शाखागृह द्वारा लिखित हिस्ट्री आफ मि० बी० जी० निरुध अगुस्त 1890, प्राग 29 (डिपोजिट) पृ० 14
170. देखिए, ए० बी० पी० 5 फरवरी 1896 मजीवनी 1 फरवरी (आर० एन० पी० बग 8 फरवरी 1896) नारुमिहिर 3 फरवरी (वही 15 फरवरी 1896) बग निवासी 9 फरवरी (वही), सहचर 11 मार्च (वही 11 मार्च 1896) मजीवनी 14 मार्च (वही) द्वारा गजट 23 मार्च (वही 24 मार्च 1896) बगान विहार गहरांड 14 अप्रैल (आर० एन० पी० बग आई०, 17 मई 1896) विहार में उन्नत दीपिका 22 फर० (आर० एन० पी० बग 18 अप्रैल 1896) उडिया और नाममन्नार 7 अप्रैल (वही 23 मई 1896) सार्वजनिकता 1 मिन० (वही, 14 नवंबर 1896) उडामा और मद्रास में स्टैंडर्ड 23 मार्च (आर० एन० पी० बग आई०, 10 मई 1896) मद्रास में हिंदुस्तानी 12 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 19 फर० 1896), नागरी नोबद 13 फरवरी (वही, 26 फर० 1896), गृहवर 24 फर० (वही 4 मार्च 1896, नजमल हिंद, 29 फरवरी अजमने हिंद 7 मार्च और जमाना, 5 मार्च (वही, 11 मार्च 1896), अलमोडा अखबार 9 मई और उत्तर-पश्चिम प्रान्त तथा अखबार से नमीमे आगरा 7 मई (वही, 12 मई 1896)
171. दक्षिण ए० बी० पी०, 14 नवंबर 1898 अखबारे आम, 30 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 28 अगस्त 1897), नमीमे आगरा, 15 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 21 जुलाई 1897) ग्याजुल अखबार 28 नवंबर (वही 6 दिसंबर 1898), सुरमाण-रोजगार, 24 अप्रैल (वही, 10 मई 1899), भारत जीवन 26 जून (वही, 5 जुलाई 1899) और 17 जुलाई (वही, 22 जून 1901), मजीवनी 14 नवंबर (आर० एन० पी० बग 26 जुलाई 1902), प्रजाबधु 7 सितंबर (वही, 13 सितंबर 1902), पैसा अखबार 15 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 29 मार्च 1902), बगाली 12 मार्च, 27 सितंबर 1902, मराठा 17 अगस्त 1902 सूर्योदय प्रकाशित, 18 मई (आर० एन० पी० एम०, 21 मई 1904)
172. 26 जून (आर० एन० पी० एन० 5 जुलाई 1899)

- 173 14 नवंबर (आर० एन० पी० पी० बग, 23 नवंबर 1901)
- 174 आर० एन० पी० पी०, 29 मार्च 1902
- 175 रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 125
- 176 इंडियन डेनो मिरर, 22 दिसंबर (आर० एन० पी० एन० 28 दिसंबर 1901) भाग्य जीवन ने 14 नवंबर के अंक में इस सुझाव का बड़ा जोरदार समर्थन किया (आर० एन० पी० एन० 15 नवंबर 1898) सजीवनी ने 12 दिसंबर 1901 के अंक में लिखा हिंदुओं में पवित्र अवसरों पर रेशम पहनने की प्रथा है मातृभूमि की पूजा से बढ़कर कोई पवित्र अवसर नहीं और मातृ-भूमि की पूजा के स्थल पहाड़ों में विदेशी मामान में बनी वेपमूया वाले व्यक्ति को कभी प्रविष्ट नहीं होना चाहिए (आर० एन० पी० बग, 21 दिसंबर 1901)
- 177 सी० पी० ए० मे 636
- 178 मजूमदार पूर्वोद्धृत, पृ० 188
- 179 बड़शो नैमीगाम, रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 125
- 180 मराठा 17 अगस्त 1902
- 181 बंगाली 26 सितंबर 1902, वस्तुतः वह एक तरह का स्वदेशी महार 1896 में ही खोल चुक था (रागत पूर्वोद्धृत, पृ० 124)
- 182 प्रजाबधु, 18 जनवरी (आर० एन० पी० बग, 24 जून 1903) और 15 फरवरी (वही, 21 फरवरी 1904).
- 183 यह काफी मजेदार बात है कि स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादकों द्वारा कीमते घटाने का सुझाव किसी ने भी नहीं दिया जबकि स्वदेशी उत्पादक अल्प उद्योग में काफी ऊंचे नाम कमा रहे थे
- 184 संक्षेप तथा पुनरावृत्ति न होने देने के लिए हम यहां इस विषय पर उपलब्ध अमूल्य सद्भावों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अधिकांश तो ऊपर प्रस्तुत किए ही जा चुके हैं.
- 185 और मद्रास स्टैंडर्ड, 23 मार्च (आई० एम० बी० ओ० आई० 10 मई 1896)
- 186 17 मई 1896
- 187 उदाहरणार्थ, 14 मार्च 1896 का अंक (आर० एन० पी० बग, 21 मार्च 1896)
- 188 सी० पी० ए०, पृ० 636-7
- 189 उदाहरणार्थ देखिए, बी० के० बोस पूर्वोद्धृत पृ० 47 भोलानाथ चट्ट. एम० एम०, खंड V 1876, पृ० 10-2 सजीवनी, 22 जून (आर० एन० पी० बग, 28 जून 1884) नसीमे आगरा, 7 जून (आर० एन० पी० एन० 12 जून 1889) ए० बी० पी०, 12 जुलाई 1891 पूना वंभव, 10 मई (आर० एन० पी० बग, 16 मई 1891) भारत जीवन, 26 जून (आर० एन० पी० एन० 5 जुलाई 1899)
- 190 मराठा 13 मार्च 1881, बृहद समाचार 22 जून (आर० एन० पी० बग, 27 जून 1891), मराठा 15 मार्च 1896 प्रजाबधु 7 सितंबर (आर० एन० पी० बग 13 सितंबर 1902) बंगाली 26 सितंबर 1902
- 191 और भी देखिए, भोलानाथ चट्ट एम० एम०, खंड V 1896, पृ० 32 बंगाल रिवेसा में राजनारायण बोस का उद्धरण इन पृ० 210, मराठा 9 फरवरी 1896. एडवोकेट, 1 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 10 फरवरी 1901)
192. सी० पी० ए०, पृ० 636.

193. देखिए, सुबोध पत्रिका 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बब०, 26 अप्रैल 1879), मराठा 13 मार्च 1881, ए० बी० पी० 10 फरवरी 1881. सोम प्रकाश, 23 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 28 जनवरी 1882) आनन्द बाजार पत्रिका, 27 मार्च (वही, 8 अप्रैल 1882) भारत मिहिर, 6 मई (वही, 27 मई 1882) पूना वैभव, 10 मई (आर० एन० पी० बब, 16 मई 1891) हिंदुस्तानी, 11 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 18 अप्रैल 1789), मराठा 8 जुलाई 1894 1896 में परवर्ती तथा अधिक प्रचंड अभिव्यक्ति के लिए देखिए पृ० 130 ऊपर सी० वाई० चिंतामणि की इंडियन पालिटिक्स सिस दि म्यूटिनी (इलाहाबाद, 1937) में एक रोचक विवरण इस प्रकार है : बी० के० मधोक वायसराय की कौंसिल में वस्त्र उद्योग पर आयात शुल्क हटाने के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने वाले दिन घर के बूने वस्त्र पहनकर वहां पहुंचे.
194. एम० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 617 और देखिए, सजीवनी 21 जून (आर० एन० पी० बग, 28 जून 1884) समय, 22 जून (वही, 27 जून 1885) सहचर, 11 मार्च (वही, 21 मार्च 1896) सुरमा ए रोजगार, 24 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 10 मई 1899) गोहरे हिंद, 26 जुलाई (आर० एन० पी० यू० पी० 2 अगस्त 1902) पैसा अखबार, 15 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 20 मार्च 1902).
195. 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 11 अप्रैल 1891)
196. 2 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 8 अगस्त 1894. वास्तविक तथ्य यह है कि 'मोदवूत' ने लोगो में स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग का, सरकारी कचहरियों में दीवानी या फौजदारी मुकदमे न ले जाने का तथा अपने आपको सरकारी नौकरी से स्वतंत्र रखने का अनुरोध करके एक प्रकार से असहयोग आंदोलन की ही पूर्वघोषणा कर दी थी
197. 1 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 2 फरवरी 1901)
198. तिलक रामगोपाल, पूर्वोद्धृत, पृ० 231
199. नौरोजी पावर्टी, पृ० 207
200. यह दृष्टिकोण मिलमालिक तथा उम समय कांग्रेस के संयुक्त सचिव और 1901 में राष्ट्रपति डॉ० ई० बाचा के 11 तथा 18 मार्च 1896 के टाइम्स आफ इंडिया के प्रयोग में प्रकाशित दो पत्रों में भनी प्रचार व्यक्त किया गया है इसके अनिश्चित उनके लेख, 'दि इकानामिक हेरेसीज आफ दि स्वदेशी मूवमेंट', इकानामिक इंडियन रिव्यू, मितंबर 1903 और यू० पी० कुकिल्लय का 'दि स्वदेशी मूवमेंट, इंडियन रिव्यू, दिसंबर 1903, 'दि डिस्कशन आफ दि प्लाइट आफ व्यू आफ दि क्रिटिकम आफ दि स्वदेशी मूवमेंट दैंट फालोज' ऊपर की स्रोत सामग्री पर आधारित है. और देखिए 'कैसे रहे हिंद, 8 मार्च (आर० एन० पी० बब, 14 मार्च 1896) और फोनेक्स, 1 अप्रैल (आई० एस० बी० ओ० आई० 17 मई 1890) बाचा ने निष्ठा . सकल्प देशप्रेम का सूचक है परंतु जब इस मकल्प को कार्यरूप में परिणत किया जाएगा तो यह खोखला तथा निरर्थक दकियानूसी विचार मात्र बनकर रह जाएगा
201. कुकिल्लय : पूर्वोक्त स्थल, पृ० 763.
202. बाचा टाइम्स आफ इंडिया, 12 मार्च 1896
203. कुकिल्लय : पूर्वोक्त स्थल, पृ० 763.
204. बाचा पूर्वोक्त स्थल, पृ० 11 मार्च 1896.
205. इकानामिक, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 541.
206. बाचा : पूर्वोक्त स्थल, 11 मार्च 1896.

207. वही.
208. इसका स्वदेशी पक्षीय उत्तर यह था - माग आने दीजिए, आपूर्ति हो जाएगी. (ए० बी० पी०, 12 जुलाई 1891) और देखिए, मराठा, 12 अप्रैल 1896, महाम स्टैंडर्ड, 23 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई०, 10 मई 1896).
209. उदाहरणार्थ, बगवासी 2 मई (आर० एन० पी० बग 9 मई 1891), तथा राजीवनी 14 नवंबर (वही 23 नव० 1901)
210. कुकिल्लय पूर्वोक्त स्थल, पृ० 763.
211. 3 मई 1901 का भाषण 'बर्बई मिलमालिक सघ का 1901 का प्रतिवेदन', पृ० 53 बर्बई मिलमालिक सघ का अध्यक्ष राष्ट्रवादी नेता नहीं था अतः 22 मार्च 1899 का सघ की माधारण वार्षिक बैठक में उसने अपने भाषण में श्रीर शक्ति स्पाट शब्दों में कहा हम मिलमालिक समता लाने वाले सीमाशुल्क को भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगिता की दृष्टि से भारत के लिए घातक मानकर उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं रखते हैं। जैसा कि सघ पहले ही स्पष्ट कर चुका है, लकाशायर के बढ़िया कपड़े में और भारत के माटे कपड़े में किसी प्रकार की प्रतियोगिता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि सीमाशुल्क ने हथकरघा जुलाहों को संरक्षण प्रदान किया है और इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि जहां हथकरघे वर्ष प्रतिवर्ष सूत की आपूर्ति का उत्तरोत्तर बढ़ाने जा रहा है, वहां 1896 के पश्चात् बर्बई में मशीनी करघों द्वारा छपन में बर्बई बढ़ोतरी नहीं हुई (बर्बई मिलमालिक सघ 1898 वर्ष का प्रतिवेदन, पृ० 85)
212. वाचा पूर्वोक्त स्थल, 18 मार्च 1896 1903 में नौराजी द्वारा वाचा का लिया पत्र समानी में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 450
213. इस बात पर कदाचित अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है 19वीं शती के अन्तिम पचीस वर्षों में भारतीय वस्त्र उद्योग ने लकाशायर के कपड़ों का व्यापार को धीरे धीरे देश के मोटे वस्त्र के क्षेत्र से निकाल फेंका परंतु यह अभी तक उत्तम तथा मध्यम कोटि के वस्त्रों का स्तरीय उत्पादन काफी मात्रा में नहीं कर पाया था बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वदेशी हथकरघा उद्योग माटे कपड़े के उत्पादन में तथा लकाशायर के उद्योग मध्यम तथा उत्तम वस्त्र के उत्पादन में भारतीय मिलों से प्रतियोगिता की स्थिति में थे अतः एक खास समय में तो स्वदेशी आंदोलन ने हथकरघा उद्योग को ही फूलने-फलने में योग दिया प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थिति अवश्य मौलिक रूप से बदल गई थी उस समय भारतीय मिलें मध्यम ही नहीं, उत्तम कोटि के वस्त्र का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगी थी — तुलनीय, परिमल राय, इंडियाज फारेन ट्रेड सिस 1870, नवम्बर 1914, पृ० 184).
214. 201 से 205 सख्या तक की पादटिप्पणियों में उद्धृत संदर्भ

अध्याय 4

विदेश व्यापार

पिछली अर्धशताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार का उल्लेखनीय विकास हुआ है और यह देश की समृद्धि में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निदर्शन है। — ज्ञान स्टैंचे

भारत के व्यापार को प्राकृतिक आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा और वह प्राकृतिक आधार यह होगा कि देश की बढ़ती जनसंख्या के सभरण की विशाल और अपरिमित मंडी मुख्य रूप से उसके स्वदेशी उत्पादनों के लिए ही सुरक्षित रखनी होगी तथा अवशिष्ट अतिरिक्त सामग्री का यहाँ अनुत्पन्न तथा अनुत्पादित सामग्री के विनिमय के रूप में निर्यात करना होगा। ऐसा करने से ही निकट भविष्य में भारत के पूर्ण आर्थिक विनाश की चेतावनी देने वाले सकट को टाला जा सकता है।

— जी० मुन्नाय्य अय्यर

19वीं शताब्दी में, विशेषतः 1850 के उपरांत भारत ने विदेश व्यापार में बहुत उन्नति की जिससे देश में वास्तव में ही व्यापारिक क्रांति का श्रीगणेश हो गया। आयात और निर्यात के परिणाम तथा मूल्य उल्लेखनीय गति में बढ़ गए।¹ उनके विस्तारक्षेत्र व स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आया। 19वीं शताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार के विकास का विवरण पृष्ठ 127 की तालिका में प्रस्तुत है :²

19वीं शताब्दी के दौरान भारत के आयात-निर्यात के ढाँचे में भी आमूल परिवर्तन हुए। 1813 से तथा पूर्व अतीत काल में ही जहाँ भारत सदैव निर्यात वस्तुओं का निर्यातक तथा मूल्यवान् धातुओं और विलास उत्पादनों का आयातक था वहाँ वह क्रमशः विशेषतः 1858 के पश्चात् प्रमुख रूप से कृषि संबंधी कच्चे सामान तथा खाद्य पदार्थों का निर्यातक तथा निर्यात सामान का आयातक बन गया। परंपरागत निर्यात की वस्तुओं, सूती और रेशमी वस्त्र तथा धागे, का स्थान धीरे धीरे कृषि के विविध उत्पादनों, प्रमुख रूप से कच्ची कपास और पटसन, चाय और काफी, अफीम, तिलहन तथा गेहूँ और चावल ने ले लिया। 1881-82 में तथा 1904-5 में कुल निर्यात का क्रमशः 17 प्रतिशत तथा

26 प्रतिशत भाग गेहूँ और चावल का था। आयातित सामग्री में सूती धागों और सूती कपड़ों, धातुओं, मशीनों, चीनी तथा तेलों का अनुपात बढ़ने लगा। 1881-2 में तथा 1904-5 में आयातित सूती उत्पाद ही कुल आयात का क्रमशः 24 तथा 39 प्रतिशत थे।

मूल्य लाख रुपयों में

वार्षिक औसत	आयात			निर्यात
"	1834-5 में	1838-9	7,32	11,32
"	1849-50 "	1853-4	15,85	20,02
"	1859-60 "	1863-4	41,06	43,17
"	1869-70 "	1873-4	41,30	57,84
"	1879-80 "	1883-4	61,81	80,41
"	1889-90 "	1893-4	88,70	108,67
"	1899-1900 "	1903-4	110,69	136,59
वर्ष	1904-5 "		143.92	174,14

टिप्पणी इन आयात में सरकारी भण्डारों के कोश के आयात-निर्यात सम्मिलित हैं

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत के विदेश व्यापार में यह एक नई तथा मुख्य प्रवृत्ति देखने को मिली कि एक ओर भारत में लोहा, इस्पात, मशीनें तथा कारखानों के घंघे निरंतर बढ़ने लगे तथा दूसरी ओर आधुनिक मशीनों के उत्पादन के रूप में सूती वस्त्रों और पटसन के मालों का निर्यात एक बार पुनः निर्यात व्यापार में स्थान पाने लगा तथा निरंतर उत्तरोत्तर महत्व प्राप्त करने लगा।

1856 के बाद सान वर्षों की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर सारी 19वीं शताब्दी में भारतीय विदेश व्यापार का एक उल्लेखनीय परंतु सामान्य तत्व था, आयात के मुकाबले निर्यात का निरंतर बढ़ता हुआ आधिक्य। इस तत्व ने भारतीय आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण

विदेश व्यापार के विषय में भारतीय नेताओं के चिन्तन को सक्रिय रूप से आकृष्ट अथवा प्रबलता से उत्तेजित नहीं किया क्योंकि इसका एक आंशिक कारण यह था कि यह आंदोलन का विषय नहीं बन सका, हा उन्होंने इस प्रश्न पर चिन्तन किया तथा उसके विविध पक्षों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की परंतु उसे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में कोरी वृद्धि को अपने आप में एक लाभ तथा विचारणीय विषय नहीं माना। उनके अनुसार विदेशी व्यापार केवल इस रूप में महत्वपूर्ण था कि यह भारत की अधोलिखित केंद्रीय आर्थिक समस्याओं को प्रभावित करता था : दरिद्रता, उद्योगीकरण तथा विदेशी आर्थिक शोषण। फलतः उन्होंने विदेश व्यापार के

विस्तार की विशुद्ध रूप में, अन्याय पक्षों से विच्छिन्न रूप में अथवा उसके लाभदायक अथवा घातक प्रभावों के सैद्धांतिक आधारों पर प्रशंसा अथवा निंदा करने से इंकार कर दिया।

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा प्रवक्ताओं के अनुसार विदेश व्यापार का द्रुति विकास देश के हित में था। उन्होंने प्रायः इसे जनता की बढ़ती हुई संपन्नता के प्रत्यक्ष प्रमाण बताया।³ भारतीय राष्ट्रवादियों ने कुल मिलाकर इस धारणा को स्वीकार नहीं किया। कुछ एक ने तो इस विश्वास पर ही शंका व्यक्त की कि भारत का विदेश व्यापार, विशेषतः देश के आकार और जनसंख्या के अनुपात में संपन्न स्थिति में है अथवा तीव्रगति से विकास कर रहा है। 1887 में ही दादाभाई नौरोजी ने निर्देश किया कि यूरोप के देशों के व्यापार के साथ और यहां तक कि ब्रिटिश राज्य के अन्य भागों के व्यापार के साथ भारत के विदेश व्यापार की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश भारतीय व्यापार कितना निकृष्ट है। आर० सी० दत्त, डी० ई० वाचा तथा जी० एम० अय्यर ने इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया।⁴ किसी भी रूप में उन्होंने विदेश व्यापार के विस्तार को अपने आप में समृद्धि का लक्षण अथवा हर्षोल्लास का कारण नहीं माना। सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के सामान्य लाभों को न नकारते हुए भी उन्होंने व्यापार की कुल मात्रा तथा मूल्य में वृद्धि को वास्तविक आर्थिक प्रगति के विश्वस्त सकेतक अथवा विशुद्ध हित मानना स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार यूरोप के व्यापारिक देशों के सबध में यह मापदंड सही हो सकता है क्योंकि वहां व्यापार की मात्रा राष्ट्रीय आय की स्थिति का पर्याप्त अंश में मंकेतक होती है परन्तु भारत अभी तक व्यावसायिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं था अतः उसके संबंध में यह कमीटी लागू नहीं होती थी। वस्तुतः इस देश के सबध में इस प्रकार के तर्कों का निष्कार, मिथ्या तथा भ्रामक होना ही अधिक मभव था।⁵ अर्थ सत्य होने के कारण यह और भी अधिक मयकर था। 'वगाली' ने 7 दिसंबर 1872 के अंक में लिखा : 'केवल ऊंची सख्याओं अथवा साधारण सक्रियता से व्यापार की सुदृढता का अनुमान उसी प्रकार मिथ्या सिद्ध हो सकता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आयु, लिंग तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना केवल उसके शरीर में रक्त-संचार को सक्रियता में ही उसके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना।⁶ राष्ट्रीय भौतिक उत्पादनो के विकास की दृष्टि में इसपर विचार करते हुए जी० वी० जोशी ने 1884 में बल देकर कहा : बड़ा हुआ विदेश व्यापार अपने आप में घरेलू उत्पादनो में वृद्धि का सूचक नहीं। व्यापार तो उत्पादनो का केवल वितरण करता है और प्रत्येक स्थिति में आवश्यक रूप से संभरण की सृष्टि नहीं करता।⁷ इस विषय को आर० सी० दत्त ने सही ढंग से पकड़ा और आसन्न भूत का हवाला देते हुए कहा :

1881-82 में लार्ड रिपन के शात और अपेक्षाकृत समृद्ध शासनकाल में भारत के कुल आयात और निर्यात 830 लाख स्टर्लिंग पौंड था। 1900-1 के संकट और दुर्भिक्ष के वर्षों में कुल निर्यात और आयात 1220 लाख पौंड थे। जो भारत को जानता है अथवा जिसने भारत के विषय में कभी कुछ सुना है, निश्चित रूप से कहेगा कि भारत 1900-01 की अपेक्षा 1881-82 में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में था और अधिक संपन्न था।⁸

भारत के विषय में विदेश व्यापार और राष्ट्रीय समृद्धि के बीच के सरल, सहेतुक संबंध को असंगत बनाने वाले तत्व कौन से थे ? इस विषय में भारतीय नेताओं के मत में एक कारण यह था कि भारतीय विदेश व्यापार का विस्तार स्वाभाविक, स्वतंत्र तथा आर्थिक गतिविधि के सामान्य पथ के रूप में नहीं हुई, था। अधिकारियों द्वारा इसे अस्वाभाविक रूप से बढ़ावा दिया गया था। अतः इस रूप में वह लादा हुआ, कृत्रिम, अस्वस्थ तथा आर्थिक दृष्टि से अशक्त था।⁹ हम आगे चलकर इसी अध्याय में भारतीय नेताओं के विचारों के अनुसार भारतीय विदेश व्यापार के विशद रूप तथा ढंग का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे परंतु यहाँ मक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उनके दृष्टिकोण का आधार यह विश्वास तथा आस्था थी कि भारत के भाग्य में केवल कृषि संबंधी कच्चे सामान का उत्पादन नहीं बढ़ा है। भारत को ऐसा देश बनाना अप्राकृतिक है क्योंकि इस देश की धरती थोड़ी और पूर्ति सीमित है जबकि थ्रम बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।¹⁰

द्वितीय, उनकी धारणा थी, इस मंत्रध में यह उनके मत को सर्वाधिक सुनिश्चित रूप देने वाला तत्व था, कि किसी देश के विदेश व्यापार की महत्ता का निर्णय उसके स्वरूप के विश्लेषण के द्वारा ही सही रूप में किया जा सकता है। उसकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का निर्णायक तत्व उसकी कुल मात्रा न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमयित सामान का स्वरूप तथा राष्ट्रीय कृषि और उद्योग पर उस विनिमय का प्रतिफल ही अपेक्षाकृत अधिक प्रबल निर्णायक तत्व है। वस्तुतः मौलिक प्रश्न यही था।¹¹ उन्होंने व्यापार के आकड़ों की पूरी जाच की और निर्यात की कच्चे सामान के प्रति तथा आयात के उत्पादित सामान के प्रति विध्वंसक तथा मपीडक प्रवृत्ति और उसके फलस्वरूप देश के क्षतिग्रस्त होकर केवल ब्रिटेन के कृषिक उपकरण के रूप में रह जाने की ओर संकेत किया।¹² उनमें से बहुतों को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि भारत की विपन्नता प्राकृतिक शक्तियों का दुर्णयनाम न होकर इंग्लैंड की भारत के प्रति निर्धारित नीति का ही कुफल था।¹³ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अवधि में स्वतः अनुभव किए जाने वाली व्यापार की विरोधी प्रवृत्ति, आधुनिक उद्योगों के उत्पादनो के निर्यात तथा मशीनरी, मिल्स की सामग्री और कच्चे सामान के आयात, की ओर उचित ध्यान दिया।¹⁴ उन्होंने प्रवाह के इस परिवर्तन का स्वागत किया परंतु इस प्रवृत्ति की क्षमता, सीमा तथा मंदता की ओर भी संकेत किया।¹⁵ आगे चलकर इसी अध्याय में तथा 'टैरिफ', 'करमी', 'एकमर्चेंज' आदि अध्यायों में दिखलाया गया है। वास्तव में विदेश व्यापार में यही एक प्रवृत्ति थी जिसे राजनीतिक दबाव के द्वारा प्रोत्साहित करने का उन्होंने प्रयत्न किया।

तृतीय, उनके विश्वास के अनुसार व्यापार के फूलने-फलने की परिस्थितियाँ और वातावरण भी विषय के अनुरूप अर्थात् विचारणीय तत्व थे। क्या देश को व्यापारिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है ? किसने इस व्यापार का संभालन किया है ? किसने इस व्यापार पर नियंत्रण रखा है ? और किसने इन लाभों का उपभोग किया है ? क्या व्यापार राष्ट्र की अवशिष्ट और विलास सामग्री का हुआ है अथवा राष्ट्र के उपयोग के आवश्यक सामान का ? व्यापारांतर क्या था और उसके क्या कारण थे ? किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने

से पूर्व उन्होंने इन कुछ एक जिज्ञासाओं को उठाया और उन पर विचार विमर्श किया।¹⁶

उनका निष्कर्ष यह था कि विदेश व्यापार के विस्तार को अपने आप में आर्थिक नीति का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। सर्वप्रथम इससे देश को होने वाली लाभ-हानियों पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए सतर्क विचारकों को व्यापार के कुल आकड़ों से भी आगे जाना पड़ा तथा उनके उद्गम की, उनके स्वरूप की तथा राष्ट्र-हित पर उनके प्रभाव की जांच करनी पड़ी।

विदेश व्यापार के लाभ

भारतीय नेताओं ने कुल मिलाकर विदेश व्यापार के व्यापक रूप से प्रचारित उपयोगी स्वरूप को भारतीय जनसाधारण के सदर्थ में मानने से इकार कर दिया। उन्होंने तो इसके विपरीत यह मन अभिव्यक्त किया कि समष्टि रूप में भारतीय जनता पर विदेश व्यापार का हानिप्रद प्रभाव ही पड़ा है।¹⁷ उन्होंने सर्वप्रथम बढ़ते निर्यातों के स्वरूप और उनके समघातकों की जांच की और उसके आधार पर उन्हें अपने आप में पनपती राष्ट्रीय समृद्धि का संकेत अथवा देश की संपदा जुटाने का साधन मानने से इकार कर दिया। उन्होंने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि आंशिक रूप से उत्पादित सामग्री के अतिरिक्त आयातों के भुगतानों के लिए कृषि संबंधी कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था और इनमें जनसाधारण के हितों को भयंकर क्षति उठानी पड़ रही थी।¹⁸ तथा आंशिक रूप में गाँरे शासकों की विध्वंसक रूप से महंगी नौकरियाँ देने के रूप में विदेशी शासन के बढ़ते स्वर्चों का चुकाना पड़ रहा था।¹⁹ उन्होंने इस दूसरे तत्व (महंगी नौकरियों) की सारी 19वीं शताब्दी में और उसके उपरांत आयात पर निर्यात की बढ़ती अधिकता के सदर्थ में जांच की। 1834-5 में 1838-9 तक के पाँच वर्षों की अवधि में निर्यात और आयात में वार्षिक अंतर औसत चार करोड़ रुपया था। 1869-70 में 1873-4 की अवधि में 16.5 करोड़ 1899-1900 में 1903-4 की अवधि में 25.9 करोड़ तथा 1904-5 में 30.2 करोड़ रुपया था।²⁰ भारतीय नेताओं ने भारतीय निर्यात और आयात के मध्य की लगभग अप्रतिबाधित तथा सतत वृद्धिशील 'गहरी खाई' का²¹ देखते हुए व्यापार के इस प्रकार के अनुकूल व्यापारोत्तर पर हर्षोल्लस हान के बदले इस दुर्दमनीय रूप में चिन्ताग्रस्त करने वाला तत्व बनाया।

राष्ट्रवादियों द्वारा इस समस्या का विश्लेषण उनकी उल्लेखनीय अर्थशास्त्रीय बुद्धिमत्ता का एक अन्यत्र राक्षस प्रमाण प्रस्तुत करता है। उनका कथन था कि आयात की अपेक्षा निर्यात की अधिकता वास्तव में अनिश्चित निर्यात नहीं थी अर्थात् यह अनुकूल व्यापारोत्तर नहीं था। यदि ऐसा होता तो इसमें सोना-चादी अथवा सामग्री अथवा उपयोगी पदार्थों के आयातों में वृद्धि हानी। बल्कि उनसे अनुमान यह एक विचित्र प्रक्रिया थी, विचित्र अनुकूल व्यापारोत्तर था, जिससे आयात की अपेक्षा देश का बदल में किसी रूप में कोई लाभ न पहुँचाने या निर्यात की अधिकता पर और बकाया राशियों के भुगतान पर कोई समघात ही नहीं था। दादाभाई नौरोजी ने आयात की अपेक्षा निर्यात की अधिकता की ओर संकेत किया कि न अतः न तो चादी के रूप में और न ही किसी

मामग्री के रूप में 1871 में अथवा उससे पूर्व किसी प्रकार का आयात हुआ है।¹² अपने 'दि पावर्टी आफ इंडिया' लेख में उन्होंने अपने भाव और भी अधिक सफलता के साथ अभिव्यक्त किए। भारत के पक्ष में व्यापारांतर और भारत को इसमें कभी न कभी लाभ प्राप्ति के सिद्धान्त पर विश्वास करने वाले लेखकों की प्रताड़ना करते हुए, उन्होंने कहा : वे महानुभाव इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए ही प्रतीत होते हैं कि निर्यात से प्राप्ति के रूप में भारत को एक भी पाई का अथवा सामान का लाभ नहीं होना और इस प्रकार देश को आयात में घाटा ही उठाना पड़ता है।¹³ 1898 की भारतीय करमी कमेटी को अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए दादाभाई और भी अधिक क्रुद्ध थे। उन्होंने वर्तमान स्थिति में भारतीय विदेश व्यापार को 'भारत पक्षीय व्यापारांतर' कहना विशुद्धतम रूप में भाषा का दुरुपयोग करना घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा 'यह न तो कोई व्यापार है ... और न ही व्यापारांतर।' भारत की प्रतिवर्ष 400,000 000 रुपये की विपुल राशि के बदले उसे कभी एक कीटी तक निजी धन के रूप में वापस नहीं मिलेगी।¹⁴ रानाडे को छोड़कर भारतीय नेताओं में अंग्रेजों ने बल देकर तत्काल यह निर्देश किया कि निर्यात की अधिकता में भारत को किसी प्रकार का व्यापारिक लाभ नहीं होगा।¹⁵

निर्यात की अधिकता को फिर किस रूप में ग्रहण करना चाहिए? इस दुःखद असमति का वास्तविक अभिप्राय क्या है? वस्तुतः भारतीय नेताओं के अनुसार निर्यात की अधिकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक और निश्चित ही थी

- (क) भारत पर विदेशों के बहुत ऋणों के व्याज के भुगतान के लिए,¹⁶
- (ख) द्रुतगति से बढ़ते हुए गृह प्रभागों को अथवा ब्रिटन में भारत सरकार के राबर्स जुटाने के लिए,¹⁷ तथा
- (ग) ब्रिटिश प्रशासकों, व्यापारियों, खेत मालिकों, और पूजीपतियों का इस देश के बने आर्थिक शोषण के फल के रूप में उगाहे अपने लाभ और वचन को अपनी जन्मभूमि में भेजने की व्यवस्था के लिए।¹⁸

मक्षेप में निर्यात और आयात का अंतर विदेशी शासकों द्वारा भारत पर बढ़ाए जाने वाले कर शुल्क का ही निदर्शन था।¹⁹ निर्यात की अधिकता में राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में ही बाधा नहीं उत्पन्नित होती थी प्रत्युत य भारत में इंग्लैंड को 'संपत्ति की निकासी' अथवा स्थानांतरण के रूपविशेष भी था। सोना-चांदी उपलब्ध न होने से निधि के इस एक पक्षीय स्थानांतरण का मामग्री का रूप ग्रहण करना ही था। अतः भारत द्वारा अनुकूल व्यापारांतर को बनाए रखना अनिवार्य था अथवा दूसरे शब्दों में निर्यात की अधिकता को भारतीय विदेश व्यापार के एक महत्वपूर्ण तत्व, न्यूनाधिक रूप से कानून का रूप लेना ही था। विदेश व्यापार, निर्यात की अधिकता तथा भारत में संपत्ति की निकासी के निकट संबंध पर सर्वप्रथम 1871 में दादाभाई नौरोजी ने ही टिप्पणी की।²⁰ कालांतर में 1895 में उन्होंने इसे इस प्रकार स्पष्टतः प्रस्तुत किया : अधिकांशतः यही एक अकेला तरीका है जिससे ब्रिटिश भारत के निर्धन लोगों द्वारा विदेशियों के निरंतर बढ़ते हुए कमर-तोड़ करों की व्यापार-लाभों की तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की

जाती है।¹¹ अन्य भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी इस तथ्य का अनुमोदन किया।¹² अपनी सामान्य सूक्ष्म दृष्टि से जोशी महोदय ने संकेत किया कि निर्यातों की अधिकता कुल संपत्ति की निकासी को अंशतः ही प्रदर्शित करती है¹³ तथा अधिक निर्यातों के रूप में इंग्लैंड को वार्षिक विशाल भुगतानों की विवशता हमारे निर्यातों के बहुत बड़े भाग को अनिवार्य स्वरूप प्रदान करती है।¹⁴ आर० सी० दत्त ने इस दूसरे पक्ष पर बल देने हुए लिखा : गृह अधिकारों के लिए भारत-से आर्थिक निकामी देश को सभव आयातों की अपेक्षा अधिक निर्यातों के लिए बाध्य करती है।¹⁵ इस प्रक्रिया की अनिवार्यता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भारत को 1896-1900 के दुर्भिक्ष के वर्षों में भी इस अधिकता को बनाए रखना पड़ा था।¹⁶ उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इस समय निर्यातों की अधिकता तथा कर शुल्कों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष होने के कारण लोकदृष्टि से छुपे हुए है परंतु अतीत में मंदैव ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के दिनों में कंपनी के निवेश साम्राज्य के राजस्व से खरीदे जाते थे अतः उन दोनों के बीच के संबंध न केवल प्रत्यक्षगोचर थे प्रत्युत उच्च अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से अभिस्वीकार भी किए जाते थे।¹⁷

अमृत बाजार पत्रिका ने, जिसके संपादक मोतीलाल घोष महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक विषयों को सहज बुद्धिमत्ता के स्तर पर लाने में सिद्धस्त थे, अपने 11 जनवरी 1896 के अंक में संपत्ति की निकासी और निर्यातों की अधिकता में घनिष्ठ तथा अपरिहार्य संबंध का विश्लेषण एक अन्य विधि से करते हुए स्पष्ट रूप में घोषित किया : वर्तमान विदेश व्यापार के अभाव में विदेशी शासक भारत के शोषण को जारी नहीं रख सकने थे। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के अभाव में भारत सचिव और मिनिस्टर तथा सेना अधिकारी भारत का रुपया ही ले पाते। भारत निरंतर अपने रुपए से रिक्त अवश्य होता जाता परंतु उसकी उपज दूसरे शब्दों में उसकी वास्तविक संपत्ति उसके अपने बच्चों के पोषण के लिए उसके अपने पास ही रहती।¹⁸

निर्यातों की अधिकता के इस विविष्ट पक्ष में संपत्ति की निकामी स्वतः मिट्टी थी, अतः अधिकांश भारतीय नेता इस स्वस्थ दिखाई देने वाले अर्थ-व्यवस्थापरक सिद्धांत पर प्रसन्न न हो सके। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार प्रकट की कि कृषि संबंधी कच्चे मान के बढ़ते हुए निर्यात कृषिपरक संपन्नता के सूचक न होकर यह संकेत करते हैं कि कृषि जगत की बहुसंख्यक जनता और अधिक अधीन बनती जा रही है। जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता जा रहा है तथा देश की सामग्रीगत शून्यता और फलस्वरूप दरिद्रता बढ़ती जा रही है।¹⁹ परंतु क्या यह उस उदार विदेशी शासन का मूल्य नहीं है जिसने देश और देशवासियों के लिए इतना कुछ किया है जैसा कि हम 'ड्रेन' अध्याय में दिखाएंगे। राष्ट्रवादियों ने मूलतः इसका स्वीकार करने से इकार कर दिया। इसके अतिरिक्त उनका मत था कि यह संबंध एक भिन्न विषय है। जी० बी० जोशी ने लिखा : और दृष्टियों से यह कुछ भी क्यों न हो, व्यापारिक दृष्टि से कहना चाहें तो इसे हानि ही माना जाएगा और देश के सामान्य व्यापार-खाने में देश के लाभ-हानि के इस सन्तुलन पर ध्यान देना ही होगा।²⁰

राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके उपरांत आयात, जो प्रायः अपने समय रूप में ही उत्पादित सामग्री का था, के समधान की जाच-पड़नाल की। जहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार बढ़ते आयात देश की बढ़ती क्रयशक्ति के सूचक थे, वहाँ भारतीय नेताओं की दृष्टि में ये भारत के उत्पादन को क्षतिग्रस्त करने का सबसे बड़ा कारण थे, राष्ट्रीय हानि के स्रोत थे तथा राष्ट्र की आर्थिक और औद्योगिक मृत्यु के पबल सूचक थे। विपक्ष का पूर्ण अध्ययन करने पर उन्होंने टिप्पणी की कि आयातित सामग्री न तो देशी उद्योगों को बढ़ाती है, न उनकी गण पूर्ति करती है, न ही नई आवश्यकताओं तथा नए उद्योगों को जन्म देती है अथवा तकनीकी ढंग में कहना चाहें तो यह किसी नई तथा प्रभावी मांग की सृष्टि नहीं करती है।¹¹ इसके विपरीत उन्मुक्त व्यापार की अनुकूल स्थिति में अपने सस्तेपन तथा स्पर्धा की योग्यता के कारण वह भारत के अपने वाजार में ही भारत की हस्तनिर्मित सामग्री को अपदस्थ कर रही है।¹² भारतीयों ने आयात व्यापार के इस पक्ष पर 1831 में उस समय ध्यान दिया जब लगभग सौ प्रतिष्ठित भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से एक प्रार्थना के रूप में शिकायत की कि आपके प्रार्थियों ने यह पाया है कि बंगाल में ग्रेट ब्रिटेन के वस्त्रों के प्रवेश ने हमारे व्यापार को लगभग नष्ट करके रख दिया है। इसके आयात में प्रतिवर्ष वृद्धि स्वदेशी उत्पादनों के लिए हानिकारक है।¹³ इसके उपरांत 1873 में भोलानाथ चंद्र ने देशवासियों को आयात के संबंध में इस प्रकार सावधान किया कि भारतीय उद्योग और गृहनिर्मित उत्पादनों के विनाश को शिखर पर पहुंचाने वाले इन आयातों को बरदान न समझकर अभिशाप ही मानना चाहिए।¹⁴ 1897 में आर० सी० दत्त ने टिप्पणी की कि भारत में आयात के मूल्य में वृद्धि का वास्तविक परिणाम यह निकला है कि भारत के शिल्पकला उद्योगों की इंग्लैंड के माप और मशीनी उद्योग से असम प्रतियोगिता में मृत्यु ही हो गई है। 1903 में गोखले ने घोषणा की कि विदेशी सामग्री का प्रायः प्रत्येक आयात देश की क्रयशक्ति में किसी प्रकार की वृद्धि करने का सूचक होना तो दूर रहा, वह तो उल्टे स्वदेशी उत्पादनों का ही केवल नदुरूप अपदस्थ करने का सूचक है। जी० सी० अय्यर ने इस समस्या का विश्लेषण और अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से किया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शेष पूर्ति तथा गृहविनिमय को सुदृढ़ नहीं करता। यह गृहविनिमय का स्थान लेता है अतः इस प्रकार यह उसका सर्वनाश करता है।¹⁵

जी० वी० जोशी आयात व्यापार के एक अन्य परोक्ष दुष्प्रभाव नगर शिल्प कलाओं के विध्वंस को प्रकट करने में समर्थ हुए। उनके अनुसार यह एक ओर उपभोग सामग्री के संचार की सीमा का तथा भीतरी मंडी के क्षेत्र का विस्तार करता था और दूसरी ओर जनता के एक पूरे वर्ग को बेकार करके अपरिमित सस्ते श्रम का आयोजन करता था। इसमें ही विदेशी पूँजी देश में घुसने तथा उत्पादक उद्योगों की स्थापना में समर्थ हुई है और अब इन उत्पादक उद्योगों से देश के दूरतम भाग में भी हमारे अपने उत्पादक उद्योगों का विध्वंस लगभग पूरा होने जा रहा है।¹⁶

भारतीय उत्पादनों के अपदस्थ करने की प्रक्रिया की सुस्पष्ट ढंग से रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय नेताओं ने कच्ची कपास के निर्यात तथा सूती वस्त्रों के आयात

को प्रायः ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।⁴⁷ उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि विविध आयातित सामग्री एक व्यापक क्षेत्र लिए हुए थी जिसमें चट्टाइयो, माचिसों से लेकर मिलों के सामान और मशीनें तक सम्मिलित थी, छातों से लेकर बत्तियां, पुस्तकें, जूनें और खिलौने सम्मिलित थे। यह सब स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि यह पतन कितना विस्तृत तथा गहरा है।⁴⁸

इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्पादित वस्तुओं के बढ़ते आयातों का लोकहित पर घातक प्रभाव था। उसने विविध और मध्यम रूप से सन्तुलित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर दी थी।⁴⁹ उसने लाखों हस्तशिल्पियों तथा कलाकारों को अपने परंपरागत कला-कौशल का छोड़ने के लिए बाध्य करके उन्हें तथा उनकी सतनियों को न केवल अपनी आजीविका के साधनों से वंचित किया था प्रत्युत आजिविका के लिए एकमात्र अर्वाण्ड और अनिश्चित स्रोत कृषि पर निर्भर रहने का भी विवश कर दिया था। बढ़ते आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम यह था कि अधिक से अधिक लोग कृषि की ओर धकेले जा रहे थे और इस प्रकार देश का ग्रामीकरण किया जा रहा था। देश की कृषि पर उत्तरोत्तर भार बढ़ता जा रहा था। और देश की राष्ट्रीय आय के स्रोत मनुचिन होने जा रहे थे तथा देशवासी दरिद्र में दरिद्रतर होते जा रहे थे।⁵⁰

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने विशुद्ध आर्थिक दृष्टिवाण में भी आयातों के परिणाम पर विचार किया। उन्होंने उत्पादित वस्तुओं के आयात और कच्चे माल के निर्यात पर समुच्चय रूप में विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि दोनों को एक साथ देखने पर दुगुनी क्षति स्पष्ट हो जाती है। सामग्री के निर्यात में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन की ओर परिवर्तन की प्रवृत्ति का अर्थ यह हुआ है कि भारत अपेक्षाकृत उच्च से निम्न आर्थिक गतिविधि की ओर मुड़ गया है, समृद्ध उद्योग की अपेक्षा कम लाभकारी कृषि को अपनाते लगा है, कुशल कारीगरों में अप्रशिक्षित मजदूरों की ओर अनिवार्य परिवर्तन से उसका श्रम न्यून उत्पादक हो गया है और इस सबके फलस्वरूप देश का पारिश्रमिकों और लाभों में अपरिमित आर्थिक हानि उठानी पड़ी है।⁵¹ यह सत्य है कि उपभोक्ता के रूप में अपेक्षाकृत उन्नत और सस्ता माल उपलब्ध होना भारत के लाभ में अवश्य रहे है परंतु उत्पादक और श्रमिक के रूप में इसका जो मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा है, वह सचमुच ही बहुत अनुचित रूप में महंगा है।⁵² इसके विपरीत यदि इस समय बाहर भेजे जाने वाले कच्चे माल को देश में ही रखा जा सके तो उसमें हमारी अपनी पूंजी और अपने श्रम को नए विकास के अवसर उपलब्ध होंगे।⁵³ मधोलकर महोदय के निम्नलिखित वक्तव्य में इस विषय पर राष्ट्रवादी स्थिति संक्षेप में इस प्रकार से विश्लेषित है

यदि कच्चा माल हमारे देशों को भेजने और तैयार माल वहां से मगाने के बदले यह देश कच्चे माल का स्वयं ही उत्पादन करता तो कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के बीच के अंतर का मूल्य समझत। इस देश में ही रहता और इस प्रकार वह रुपया देश के पारिश्रमिक में, कोष में और पूंजीपतियों के लाभों में पर्याप्त वृद्धि करता।⁵⁴

इसमें पूर्व जी० वी० जोशी महोदय ने 1888 में अपने एक लेख, 'दि सी बोर्ने ट्रेड आफ ब्रिटिश इंडिया' में इस हानि की स्थूल सांख्यिकी संगणना की चेष्टा की और इस परिणाम पर पट्टे कि एक स्थूल तख्तीने के अनुसार हमारी व्यापारिक स्थिति के कारण हमें पार्थिविको और लाभो में प्रतिवर्ष 58 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि तीन प्रतिशत की व्याज दर से पूँजीकृत यह राशि 1600 करोड़ रुपए हो जाती थी।¹⁵ उन्होंने यह भी निर्देश किया कि यह प्रक्रिया स्वदेशी सघटक प्रतिभा को अपदस्थ करने और मुचारा रूप में प्रगतिशील प्रत्येक समुदाय की गीढ़ मध्यवर्ग को दुर्बल बनाने के रूप में शांतिपूर्ण प्रभाव डालती है।¹⁶

यह वट आश्चर्य की बात है कि इस समय के भारतीय लेखको ने ग्रामीण और नागरिक हस्तशिल्पो हस्तकलाओं के विनाश की निंदा तो की परन्तु उनमें से किसी ने भी देश के ग्रामीण तथा देश की कृषि के व्यवसायीकरण के फलस्वरूप देश की कृषि और उद्योग के घनिष्ठ मंत्रियों के टूटन पर दुःख प्रकट नहीं किया। इसी पुस्तक के द्वितीय अध्याय में हम उसके कारणों का विश्लेषण वस्तुतः पहले ही कर चुके हैं कि भारतीय नेता बढ़ती उपयोगी वस्तुओं के प्रसार के अथवा उस रूप में भीतरी मंडी के विस्तार के विरुद्ध नहीं थे। आधुनिक उद्योगों, जिनका ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर विनाशक प्रभाव पड़ना अवश्यभावी था, के प्रवल समर्थक होने के कारण वे आंतरिक व्यापार के अथवा व्यापार के तद्रूप विकास के विरुद्ध नहीं थे। वे तो केवल व्यापार के वर्तमान ढाँचे के ही विरुद्ध थे। उनकी आपत्ति विदेशी उत्पादनों के ग्रामीण मंडी पर एकाग्र अधिकार के विरुद्ध थी जिनमें स्वदेशी उद्योगों को अपनी ही मंडी में तथा स्वदेशी उद्योगपतियों का अपने लाभों में और उजड़े हुए कारीगरों को नए उद्योगों में आजीविका कमान के अवसरों में वंचित कर दिया था। फलतः उन्होंने आधुनिक उद्योगीकरण के प्रवर्तन की प्रक्रिया की ओर अधिक ध्यान देते हुए अव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को विनाश में बचाने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

अधिकांश राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री तो इस दावे को भी स्वीकार नहीं करते थे कि कृषि उत्पादनों के बढ़ने हुए नियातों और उनके फलस्वरूप उनके मूल्यों में वृद्धि से कृषिकार्य में मलग्न पुरुषों का ही नहीं, किसी प्रकार का लाभ पहुँचा है। उदाहरणार्थ, 1873 में भोलानाथ चंद्र ने लिखा : भले ही उसके (भारतीय खेतिहर) के चारों ओर व्यापार का बहुत विस्तार हुआ है परन्तु अभी तक वह अभी प्रकार दीनहीन, अपमानित तथा अवहलिन है, जैसा वह पहले कभी था। वह अभी तक न तो साहूकार के पजों से मुक्त है और न ही गंदगी अमहायता तथा दुर्भाग्य से छुटकारा पा सका है।¹⁷ सर्वप्रथम, कई वर्षों तक कुछ अर्थशास्त्रियों की तो यह धारणा रही कि कृषिसामग्री के मूल्य घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे अथवा अधिक से अधिक स्थिर हैं।¹⁸ हा अधिकांशतः मान्य धारणा यह रहा कि कृषि-उत्पादनों की ऊँची मांगों और मूल्यों के लाभों का एक बहुत बड़ा भाग वास्तविक कृषक को नहीं मिल पाता क्योंकि उस बेचारे को ऊँचे और आवधिक राजस्वों अथवा मालिफ के भुगतान के लिए, साहूकार के मूलधन अथवा उसपर व्याज की मांग की पूर्ति के लिए तथा जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के संभरण के लिए फसल काटने के समय ही

प्रतिकूल शर्तों पर अपनी उपज को बेचना पड़ता है। वास्तविक लाभ तो राली ब्रदम जैसे विदेशी निर्यात व्यापारी तथा उनके भारतीय बिचोले उठाते हैं, जो किसानों की उपज को अत्यंत सस्ते दामों पर खरीदते हैं।⁵⁹ लाभों का दूसरा बड़ा भाग उन ऋणदाता साहूकार व्यापारियों को मिलता है जो किसान की फसल कटने से पहले ही उसे अपने पाम गिरवी कर लेते हैं।⁶⁰ केवल थोड़े-बहुत समर्थ किसान ही स्वेच्छा से और लाभ पर अपनी उपज को बेच पाते हैं और उनमें भी बहुत सारे वास्तव में छिपे साहूकार ही हैं।⁶¹ इसके अनि-रिक्त सरकार और जमींदार भूराजस्व और मालिगान में वृद्धि द्वारा लाभ के एक अन्य भाग को हड़प लेते हैं।⁶² इस प्रकार ग्रामीण जनमस्त्र्या का एक बहुत बड़ा भाग, त्रुपि श्रमिक और छोटे किसान, तो अपने उत्पादन में अधिक अन्न का उपभोग करता है। अतः वह तो प्रत्येक स्थिति में मूल्यवृद्धि से विमुक्त रूप में हानि उठाने वाला है।⁶³ इसमें भी बढ़कर जी० वी० जोशी ने हिमाब लगाया है कि यदि गृह स्वीकार कर भी लिया जाए कि विदेश व्यापार के फल का एकमात्र भोक्ता किसान हैं तो भी यह लाभ कृषि जनता को प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कुछ रूप में चार आने बैठता है और वह साधारण लाभ आजीविका, उद्योग की हानि जैम अपरिमित अहितो के मूल्य पर ही मिनता है जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है।⁶⁴

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य की आर भी ध्यान दिलाया कि विदेश व्यापार के बहुत से चाय, नील, काफी तथा पटसन पदार्थ जैसे सौदे विदेशी पूँजी और प्रयत्न के विनियोजन के ही परिणाम थे। अतः विदेशी पूँजीपति ही उनसे लाभ उठाते थे तथा ये लोग इनके आयातों तथा उत्पादनो से होने वाले सभी लाभों में से भारतीयों की श्रमवृत्ति के रूप में उनका भाग छोड़कर अवशिष्ट सारे लाभ इस देश से अपने देश को ले जाते थे।⁶⁵ यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि रानाडे ने समकालीन लगभग सभी राष्ट्रवादी अर्थ-शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत तर्कों को मानने से इंकार कर दिया तथा इसके फलस्वरूप उन्हें भारत को कृषि सबंधी वच्चे माल के उत्पादक देश में बदलने की नीति के विकल्प के रूप में डच ईस्ट इंडीज की सांस्कृतिक प्रणाली को आदर्श मानने की एक विचित्र भूल करनी पड़ी।⁶⁶ वे यह देखना भूल गए कि ईस्ट इंडीज के बागानों पर पूर्ण विदेशी नियंत्रण और स्वामित्व ने इंडोनेशिया के लोगों के उद्योगों का न केवल अवमूल्यन कर दिया था प्रत्युत स्वदेशी पूँजीपतिवर्ग के विकास को अवरुद्ध करके वहाँ की जनता की स्थिति भारतीयों की स्थिति से बदतर कर दी थी।

प्रासंगिक रूप में कुछ भारतीय लेखकों ने स्थिति के इस पक्ष पर भी ध्यान दिया और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि भारतीय आयातों का बहुत बड़ा भाग या तो भारत में रहने वाले विदेशियों की अथवा थोड़े बहुत अंगरेजनुमा स्वदेशी लोगों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के काम आता है अथवा विदेशी उद्यमों और रेलवे के काम आता है अथवा सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के काम आता है।⁶⁷ सबसाधारण द्वारा उपभोग में लाया जाने वाला आयात मात्रा में स्वल्प था और उसका मूल्य प्रति व्यक्ति कुछ पैसे ही बैठता था।⁶⁸

उनमें से कुछ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपने फालतू माल का जिसकी

लाभप्रद रूप से देश में खपत नहीं हो सकती, निर्यात नहीं करता, प्रत्युत निकासी के दबाव के अंतर्गत उसे गेहूँ, चावल, कपास, जूट तथा तिलहन का निर्यात करना पड़ता था, और यह स्थिति देश को भयंकर रूप से खाद्यान्न में वंचित कर रही थी। बदले में उसे सुविधा और विलास की बहुत सारी वस्तुएँ लेनी पड़ती हैं, जिनके बिना आमानी से निर्वाह किया जा सकता है।⁶⁶ बगवासी ने इस दृष्टिकोण को 6 जुलाई 1889 के अंक में अत्यंत सशक्त ढंग में इस प्रकार प्रकट किया

हमें अपने चेहरे की दमक को बढ़ाने के लिए पाउडर और घुघराले बालों की चमक बढ़ाने के लिए सुगंधित क्रीम की आवश्यकता नहीं है। हम अपने लोगों को आकर्षक सुगंध, घाँड़ियों और छाँड़ियों से मोहित करने की कोई इच्छा नहीं है। 'हम रेशमी और ऊनी वस्त्रों में चमकना नहीं चाहते।' हम आपकी शेरी और शैपेन में अपनी पापी ग्यास नहीं बुझाना चाहते। 'हम आपके वस्त्रों द्वारा अपनी लज्जा ढकना नहीं चाहते। यदि भारतीय जूलाहों की जाति का समूल नाश हो जाए तो हम उस स्थिति में वृक्षों की छाले भी ओढ़ लेंगे और यदि वृक्ष की छाले भी उपलब्ध न हों तो हम नंगे ही रह लेंगे परन्तु आपके वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपसे केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने ही हाथ पर छोड़ दीजिए और जीवित तो रहने दीजिए।

राष्ट्रवादियों ने विदेशियों द्वारा तथा स्वयं देशवासियों द्वारा संचालित व्यापार के बीच आधारभूत अंतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने उस स्थिति पर जोर प्रकट किया कि भारत का व्यापार अधिकारण विदेशी तथा बर्तमानकी व्यापारियों के हाथ में था जो जी० बी० जाशी के अनुसार उसके लाभों का बहुत बड़ा, 90 प्रतिशत भाग हड़प जाते थे तथा इस देश में बाहर न जाते थे।⁶⁷ सारे व्यापार तंत्र के अतिरिक्त हमारे सारे वाणिज्य का सम्पूर्ण संचालन विदेशी नियंत्रण और निदेशन के अधीन था। रेल, जहाजरानी, बैंक बीमा कंपनियाँ यहाँ तक कि एक सीमा में सामान की गाव से समुद्र तट पर पहुँचने की आंतरिक गतिविधि सभी कुछ विदेशी प्रयत्नों के ही अधीन था।⁶⁸ जी० बी० जाशी महोदय के अनुसार भारतीय व्यापार पर विदेशी नियंत्रण के फलस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष लगभग 26 करोड़ रुपयों की हानि उठानी पड़ रही थी। यह राशि गृहप्रभारों की उस कुल राशि से अधिक थी जिसकी हम प्रायः शिकायत किया करते हैं।⁶⁹ कुछ नेताओं ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया कि सारी हानि को पूर्ण रूप से न सही आंशिक रूप से रोकना तो भारतीयों के अपने हाथ में है ही। विदेशी व्यापार के प्रति उपेक्षा बरतने के लिए स्वदेशी व्यापारियों की प्रताड़ना करते हुए तथा उन्हें प्रबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि उन्हें विदेश व्यापार के लाभ के साथ साथ उसके समुचित भार को भी वहन करना चाहिए।⁷⁰ जाशी की टिप्पणी थी कि निरमदेह हमें इस कार्य में न तो तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और न ही पूँजी की विशाल राशि की पुनरपि यह अततः हमारा अपना ही तो कार्य है।⁷¹ इसके अतिरिक्त बंबई के खोजा और पारसी इस क्षेत्र में अग्रदूत बनकर चीन और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों में पहले से ही कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। उनका उदाहरण निम्नित रूप से अनुकरणीय है तथा निर्यात-आयात अभिकरणों की स्वदेश में और

विदेशों में स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार बंबई, मद्रास और कलकत्ता में स्वदेशी स्वामित्व वाली कम से कम तीन पोत कंपनियों की स्थापना करनी चाहिए।⁷⁶ उत्तर-पश्चिमी प्रांतों तथा अवध के प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपत्र 'एडवोकेट' ने राष्ट्रवादी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया :

यदि हमें अपनी सम्यता से ही अपना मूल्यांकन करना है तो हमें स्वदेशी पंजी में भारतीय प्रतिभा द्वारा प्रबोधित भारतीय वाणिज्य का संचालन करना होगा। यदि संभव हो तो हमें भारतीयों के स्वामित्व वाले पोतों पर ब्रिटिश झंडा लहराने हुए व्यापार करना होगा। यह एक स्वप्न, यद्यपि कि दिवास्वप्न हो सकता है परन्तु भारतीयों की एक राष्ट्र के रूप में प्रगति के लिए इससे कम कुछ भी अपेक्षित नहीं।⁷⁷

अंत में, हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि थोड़े से राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री अप्रतिष्ठित फालतू निर्यात के उत्पादन की विवशता के फलस्वरूप भारत के विरुद्ध जान वाली व्यापार शर्तों के मित्रता को समझने में भी सफल हो गए। इस संबंध में उनका पथ प्रदर्शन दादाभाई नौरोजी द्वारा 1870 में उद्धृत जान स्टुअर्ट मिल की इस उक्ति ने किया : विदेशों को नियमित भुगतान करने वाला देश न केवल भुगतान की नई धनराशि को खोता है प्रत्युत कम लाभदायक शर्तों पर विदेशी सामग्री के बदले अपने उत्पादनों के विनिमय की बाध्यता के रूप में और भी बहुत कुछ गवाता है।⁷⁸ बहुत सारे भारतीयों ने मिल के इन वचनों को प्रतिध्वनित अथवा पुनः उल्लिखित किया। उदाहरणार्थ, 1888 में जोशीजी ने अत्यंत तीव्र स्वर में टिप्पणी की अधिक निर्यातों के रूप में इंग्लैंड को इनने बड़े वार्षिक भुगतानों की आवश्यकता हमारे निर्यातों के बहुत बड़े भाग का एक अनिवार्य चरित्र प्रदान करती है जिसमें मूल्यों में अव्यवस्था की प्रवृत्ति जन्म लेती है।⁷⁹ इसी प्रकार डी० ई० वाचा ने निर्णयात्मक स्वर में कहा : कर्जदार देश कम कीमत पर अपना उत्पादन बेचने का बाध्य होता है और इस प्रकार की परिस्थितियों में विस्तृत निर्यातों का अर्थ राष्ट्रीय संपत्ति के विस्तृत बलिदान में कम कुछ नहीं।⁸⁰ अर्थशास्त्रियों के अनिश्चित अर्थों में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 17 जुलाई 1892 के अंक में इस विषय को बड़ी विवशता में उजागर किया।

अनाजों का निर्यात

विदेश व्यापार के एक पक्ष, अनाजों के निर्यात, पर भारतीय नेताओं ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ छोटे समाचारपत्रों जैसे लोकप्रिय माध्यम में विचार प्रचार किया। राजनीतिक दृष्टि से भारत के अत्यधिक जागरूक भाग बंगाल में ही नहीं, द्रुतिगति में बढ़ते अनाजों के निर्यात के प्रमुख स्रोत, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, अवध और पंजाब में भी इस प्रश्न को अत्यधिक मुख्य स्वर प्राप्त हुआ।

माग और पूर्ति के बदलते रहने के कारण वर्ष प्रतिवर्ष अनाजों के विदेश व्यापार की मात्रा और मूल्यों में नौ विविधता है, फिर भी निम्नलिखित अंकों में उसकी सामान्य प्रवृत्ति का निदर्शन प्रस्तुत है⁸¹ :

औसत	हडरडवेट	रुपये (लाखों में)
1882-3—1891-2	48,267,117	17,82
1892-3—1901-2	42,268,345	17 89
1904-5	102,021,341	41,11

चावल प्रमुख रूप से वर्मा से, गेह और दाने भारत में निर्यातित की जाती थी। भारत ने 1869 में 275,481 हडरडवेट 1873-4 में 1,755,954 हडरडवेट, 1882-83 में 14,193,763 हडरडवेट और 1891-2 में 32,740,000 हडरडवेट गेह का निर्यात किया।¹²

अनाजों के निर्यात के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अनेक कारणों से अत्यंत आलोचनात्मक था किंतु प्रमुख कारण यही था कि ये निर्यात ही देश में अनाजों की दुर्लभता अकाल की स्थितियों और यहां तक कि दरिद्रता के प्रमुख कारणों में अन्तर्गम्य थे।¹³ उदाहरणार्थ, 1891 में जिस वर्ष अकाल नहीं पड़ा था, लखनऊ के *व्यंग्यकुशल* राष्ट्रवादी उर्दू साप्ताहिक अवधपत्र ने मर्मवध्वी टिप्पणी की :

इस समय देश में निर्यात किया जाने वाला अनाज वास्तव में अनाज नष्टकर अगल-गगल देशवासियों का जीवन-रक्क है। अनाज की वागिया अनाज में भरी वागिया न होकर वस्तुतः देश के लोगों में भरी बोगिया है, जिन्हें इंग्लैंड के मुसभ्य नरपिशाच उन्मुक्त व्यं पार की तलवार में मारकर अपना भोजन बनाएंगे।¹⁴

उत्तर भारत में हिंदी के प्रमुख पत्र 'भारत जीवन' ने अपन 19 जनवरी 1900 के अंक में चेतावनी दी : 'यदि ये निर्यात न राखे गए तो समय आने पर भारत बजर भूमि बन जाएगा।'¹⁵

राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि अनाज का निर्यात भारत की निर्धनता और दुर्भिक्षा का कारण था क्योंकि भारत केवल अपने फालतू अनाज का ही निर्यात नहीं करता था प्रत्युत अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्धारित भंडार में से ही यह निर्यात करता था। अनाजों के इस व्यापार का संभव बनाने के लिए भारतीयों को आधा भूखा रहना पड़ता था।¹⁶ हितवादों ने अपन 25 जनवरी 1891 के अंक में लिखा था कि विदेशी भारतीयों के मुंह का ग्राम छीन रहे हैं और भारतीयों को कृषक जनता का विदेशियों का पेट भरने के लिए अपने परिवार को भूखा मारना पड़ रहा है।¹⁷ इसी प्रकार आर० सी० दत्त ने वन देकर कहा कि अनाज व्यापार के मुसकराने चेहरे के भीतर निहित तथ्य यह है कि कृषि उत्पादक देश अपने घर-परिवार और गांव को भूखा-नगा रखकर उन्हें मृत्यु के कगार पर ला रहा है।¹⁸ यह बात इस तथ्य में भी सिद्ध होती थी कि बड़े बड़े अकालों में भी अनाज का निर्यात यथावत तीव्र गति में हो रहा था।¹⁹ अकाल के वर्षों में निर्यात कम कर दिया गया था, ऐसा भारतीयों के अनुभव में था परंतु इस सबंध में भारतीयों का कथन यह था कि सामान्य वर्षों के निर्यात से पहले ही वास्तविक हानि तो पहुंचाई जा चुकी थी क्योंकि अनाज का फालतू अथः सुरक्षित भंडार जो अकाल के वर्षों में कृच्छ्रता की स्थिति को बदलने में सहायक सिद्ध होता, निर्यात द्वारा पहले ही खपाया जा चुका था।²⁰ भारत जैसे देशों में जो ऋतु की विषमताओं के प्रायः ही शिकार रहते हैं, फालतू अनाज का अनुमान तो खान्दानों के घाटे के वर्षों की न्यूनता की पूर्ति की व्यवस्था

के उपरांत ही लगाना चाहिए,⁹⁰ यह भारतीयों का तर्क था।

यदि भारतीय जनता के पास वास्तव में फालतू अनाज नहीं है तो वे उत्पादन का विक्रय और निर्यात क्यों करते हैं? वे अपने उत्पादन को दुर्दिन के लिए सुरक्षित क्यों नहीं रखते? इस सबका पूर्वनिर्दिष्ट उत्तर एक ही था कि भारत का समग्र व्यापार विवशता की स्थिति में तथा अस्वाभाविक था। सरकार को तथा साहूकार को नियत अवधि में और नकद रूप में बढ़े हुए भूराजस्व अथवा मालाग को चुकाने की आवश्यकता। किसान को अपना अनाज बेचने को विवश कर देती थी। इसके साथ फालतू निर्यात बनाए रखने के साथ जुड़ी हुई मंडी की समस्या दश को विदेशी बाजारों में ही अपना अनाज बेचने को बाध्य करती थी।⁹¹

अनाज का निर्यात एक अन्य दृष्टि से भी हानिप्रद था। इसमें लोगों की सर्वथा मूल आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य ऊँचे चढ़ जाते थे और इसके अपरिहार्य परिणाम थे भुखमरी और मृत्यु।⁹² कांग्रेस के 1891 के नगपुर अधिवेशन में लाला मुरलीधर ने कहा : बीस वर्ष पूर्व गेहूँ एक रुपए का डेढ़ मन और दूसरा अनाज एक रुपए का दो मन बिकता था। इसका कारण यह था कि उस समय हमारे अनाज का विदेशों में निर्यात नहीं होता था। अब यह छः गुना महंगा हो गया है और उसी अनुपात में निर्धनों के लिए अपना पेट भरना छः गुना कठिन हो गया है।⁹³

इस चिंतन के फलस्वरूप राष्ट्रीय नृत्व के एक बहुत बड़े वर्ग ने अनाजों के स्वतंत्र तथा असीमित निर्यात पर सरकार से कुछ प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की।⁹⁴ अन्य कुछ ने तो अनाजों के निर्यात पर ऊँचे निर्यात शुल्क के आधान की वकालत की।⁹⁵ कुछ और लोगों ने तो यहां तक मांग की कि अनाजों के निर्यात पर ही पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।⁹⁶ 1896-98 के अकाल के वर्षों में तो इस मांग के समर्थन में स्वर विशेष रूप से ही मुखरित हो उठा।⁹⁷ साथ ही कुछ नेताओं ने इस तथ्य को अनुभव किया कि सरकार अकाल के दिनों में भी अनाज के निर्यातों को रोकने अथवा प्रतिबन्धित करने की दिशा में कोई पग नहीं उठाती। अतएव उन्होंने यह तर्क देना प्रारंभ किया कि सरकार की नीति ही इंग्लैंड के लोगों के लिए मस्ती खाद्यमामग्री जुटाने की दृष्टि से अनाजों के निर्यातों को किसी भी मूल्य पर बढ़ाने की ही है।⁹⁸ इस प्रबल निर्यात विरोधी वातावरण के युग में अकाल के अनिरीकृत वर्षों में भी अनाज के निर्यात के समर्थक समाचारपत्र मुट्ठीभर ही थे।⁹⁹

आशा के विपरीत न होने हुए भी यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि अनाजों के व्यापार में सलग्न भारतीय व्यापारियों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण से विपरीत था। उन्होंने तो इस व्यापार के विस्तार का समर्थन किया तथा चावल पर लगे निर्यात शुल्क का तीव्र विरोध किया। उदाहरणार्थ इपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य, कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी दुर्गाचरण लाहा ने चावल पर शुल्क के आधान को आपत्तिजनक बताया और दावा किया कि इसके हटा देने से जनता का अच्छा बाजार मिलने तथा अपने उत्पादनों का अच्छा मूल्य मिलने के रूप में भारी लाभ होगा।¹⁰⁰ इसी प्रकार बंगाल वाणिज्य सदन के सचिव ने 8 अप्रैल 1889 में सदन के वार्षिक सम्मेलन को

संबोधित करते हुए इस देश में चावल के निर्यात पर लगाए गए ऊँचे शुल्को के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रकट किया।¹⁰¹

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार की भूमिका के मूल्यांकन में अपने समय में काफी आगे बढ़े हुए थे। उन्होंने मात्र अंतर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन के लाभों के प्रचलित सिद्धांत को नकारते हुए इसे अपने आप में लक्ष्य अथवा अपने आप में ही अच्छाई मानने से इकार कर दिया। भले ही इस विषय पर उनकी टिप्पणियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य पक्षों पर प्रस्तुत टिप्पणियों के समान विस्तृत नहीं थीं¹⁰² फिर भी उन्होंने भारत के विदेश व्यापार के केंद्रीय स्वरूप को उजागर किया तथा उसे लोकहित पर उसके गामान्य प्रभाव के सदृश में ही देखा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, भारतीय प्रवक्ताओं ने विदेश व्यापार के गुण-दोषों का निर्णय एकांततः राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उद्योग तथा आजीविका के साथ उसके संबन्ध तथा उनपर उसके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में ही किया। इसी कारण से उन्होंने मूल रूप अथवा सिद्धांत रूप में विदेश व्यापार की उपेक्षा नहीं की और न ही सब प्रकार के विदेश व्यापार को हानिप्रद माना। वे स्वाभाविक अर्थान देश के उद्योग, देश के हित तथा देश की आवश्यकताओं पर आधारित विदेश व्यापार के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने तो केवल अव्यावहारिक, औपनिवेशिक स्वरूप तथा बाध्य प्रकृति के भारतीय विदेश व्यापार के विरुद्ध ही आपत्ति की। वे चाहते थे कि औद्योगिक आवश्यकता को ही विदेश व्यापार की भीमा के स्वरूप तथा दिशा के निर्धारण का आधार बनाना चाहिए न कि विदेश व्यापार की आवश्यकता को यह महत्व देना चाहिए। जी० एम० अय्यर ने 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में इस दृष्टिकोण को अत्यंत स्पष्टता से इस प्रकार प्रस्तुत किया

भारत के व्यापार को स्वाभाविक आधार देना ही निकट भविष्य में भारत के पूर्ण आर्थिक विध्वंस की चेतावनी देने वाली विपत्ति से उसके बचाव का एकमात्र उपाय है।¹⁰³ स्वाभाविक आधार प्रधानतः यह है कि प्रथम, स्वदेशी उद्योगों के उत्पादन का विस्तृत और असीम बाजार सभरण देश की विशाल जनसंख्या के लिए सुरक्षित कर लिया जाए और फिर फालतू बचे हुए सामान को विदेशों में निर्यात किया जाए और विनिमय में वे पदार्थ मंगाए जाए जो भारत में पैदा अथवा निर्मित नहीं किए जा सकते।

इसी दृष्टिकोण की त्कालत इससे पूर्व रानाडे महोदय इन शब्दों में कर चुके थे :

हमें प्रत्येक स्थिति में सुसंगठित सहयोग द्वारा विदेशियों से प्रतियोगिता करना सीखना है। अपनी आवश्यकतानुसार कच्चा माल विदेश से मंगाना है, यहाँ उसे पक्के माल का रूप देना है और अपने कच्चे माल के निर्यात की जगह हमें उसी मात्रा में भार में कम, किंतु अधिक कीमती ऐसे माल का निर्यात करना है जो कलात्मक ढंग से ढले हुए हैं, और हमारे औद्योगिक वर्ग को व्यवसाय प्रदान करते हैं।¹⁰⁴

इस प्रकार भारतीय नेताओं की दृष्टि में, उद्योग प्रधान रूप में तथा व्यापार गौण रूप

मे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक-शक्ति था। तदनुसार उन्होंने भारत के प्राचीन विदेश व्यापार की प्रशंसा की तथा उसे उदाहरण बनाकर उसके अनुकरण का सगर्व उद्घोष किया।¹⁰⁶ उन्होंने मशीनो और कच्चे माल के आयात और पक्के माल के निर्यात का समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक स्वीकार किया कि नैयार मालों का आयात भी किया जा सकता है, यदि उम आयात की वृद्धि से भारत मंपन्न हो न कि ह्हासोन्मुख और उमसे देश के आर्थिक विकास में प्रगति हो न कि अधोगति। उन्होंने वस्तुतः भारत में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को लागू कराने के लिए इस प्रकार की वृद्धि का प्रयोग ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, ब्रिटिश पूँजीपतियों और ब्रिटिश कर्मचारियों के आगे लुकमे के रूप में किया। समकालीन समीक्षापत्र 'ब्रिटिश जनरल' में 1887 में लिखे एक लेख में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम तो भारत के ब्रिटिश सामग्री अथवा उत्पादनों के दुर्भाग्यग्रस्त क्रेता रूप पर विलाप करते हुए भावपूर्ण शब्दों में एक सभावना की ओर निर्देश किया

यदि ब्रिटिश भारत ने प्रति व्यक्ति केवल एक पौंड स्टर्लिंग लिया, तो इंग्लैंड अकेले भारत को इतना अधिक निर्यात करेगा, जितना वह इस समय सारे विश्व को निर्यात करता है (213,000,000 पौंड)। यह रकम ब्रिटिश उद्योगों और उत्पादनों के लिए कितना कार्य जुटाएगी।...यदि भारत अधिकता में ब्रिटिश उत्पादनों को खपाने में सफल होता है तो इंग्लैंड को और अखिल विश्व को भी कितना लाभ होगा।

और उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत करने हुए कहा : 'यह सब तभी होगा जब ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता में स्वाभाविक आर्थिक स्थितियों में विवशित होने की अनुमति दी जाएगी।' ¹⁰⁷ लगभग चौदह वर्षों के उपरांत फिलासफीकल मस्थान ग्लामगो में भाषण करते हुए आर० सी० दन्त ने अपने श्रोताओं को इसी प्रकार का पंगमर्ग दिया :

हमारे और आपके द्विज घनिष्ठतापूर्वक परस्पर जुड़े हैं, विराधी नहीं। यदि हमारे उत्पादनों का उद्धार होता है और हमारा भारत अपनी अती की औद्योगिक समृद्धि को एक वास्तु प्राप्त करता है तो भारत की नीम करोड़ जनता आपके उत्पादनों की बहुत बड़ी खरीदार होगी। भारत का समृद्ध बनाने में ही आपका भारत के साथ व्यापार बद्ध भवता है।¹⁰⁸

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नेताओं ने समानता तथा पारस्परिक हितों पर आधारित विदेश व्यापार का ही पक्ष लिया। उनकी यह निश्चित धारणा थी कि व्यापार के विकास का आधार राष्ट्रीय मपदा में वृद्धि है न कि राष्ट्रीय मपदा में वृद्धि का आधार व्यापार का विकास।

अतः देश के विदेश व्यापार के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण की समीक्षा से प्राप्त एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ध्यान दिलाना अनुपयुक्त न होगा। यह स्पष्ट है कि व्यापार के क्षेत्र में भी भारतीय नेता व्यापार के हितों की पुष्टि न करते हुए औद्योगिक हितों के पूर्ण पक्षधर थे। विकासशील विदेश व्यापार अतः भारतीय मही के उद्घाटन और प्रसार में उत्प्रेरक ही था और इस रूप में घरेलू वाणिज्य का प्रोत्साहक था। ऐसा ही प्रभाव हस्तकलाओं और कृषि के बीच के संबंधविच्छेद के रूप में भी स्पष्ट था। फलतः विदेश व्यापार का सहारा पाकर स्वदेशी उद्योगों के विनाश पर बहुत सारे स्वदेशी

व्यापारिक बुर्जुआ प्रतिष्ठान अस्तित्व में आ गए, फूलने-फलने तथा बहुमुखी विकास करने लगे।¹⁰⁸ परंतु प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने विदेश व्यापार के बिचौलियों के पनपते वर्ग के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने भारतीय बाजार के खुलने, उपभोग सामग्री के विदेशी माल तथा कृषि संबंधी कच्चे माल में परिचार के बढ़ने के फलस्वरूप बुर्जुआ व्यापारियों के लाभ उठाने के प्रयत्न पर भी उनका पक्ष नहीं लिया। इसके विपरीत वह उन लोगों का सही सही प्रतिनिधित्व करते थे जिनकी भारत के औद्योगिक भविष्य में गहरी रुचि थी। स्पष्टतः वे वैचारिक दृष्टि से अथवा किसी अन्य रूप में पनपते बुर्जुआ व्यापारियों से संबंधित नहीं थे, अन्य बातों के अतिरिक्त अनाजों के व्यापार के प्रति उनके दृष्टिकोण से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है। अनाज निर्यात करने वाले प्रमुख प्रदेशों, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध में जहां न्यूनाधिक रूप में आधुनिक उद्योगों का अभाव था और जहां विकासशील पूँजीपति अधिकांशतः व्यापारी थे और पर्याप्त सीमा तक अनाजों के निर्यातों पर निर्भर थे, इन निर्यातों के प्रति विरोध काफी गहरा था। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि देश के औद्योगिक रूप में पिछड़े भागों में भी बुर्जुआ व्यापारियों का उभरते राष्ट्रीय नेतृत्व पर कोई नियंत्रण नहीं था।

संदर्भ

1. 19वीं शताब्दी की प्रवाधि में भारत के विदेश व्यापार के विकास के निम्नत विवरण के लिए देखिए I, दुर्गाप्रसाद, मम ग्रामपेक्ट्स ऑफ इंडियन फारेन ट्रेड-1757-1893 (लंदन 1932). परिमल राय. इंडियाज फारेन ट्रेड मिस 1870 (लंदन 1934) और इंपीरियल मजेटियर ऑफ इंडिया खंड III (1908).
2. इंपीरियल मजेटियर, खंड III (1908) पृ० 268 1813 में व्यापार का मूल्य केवल 25 लाख पौंड आका गया था (वही. पृ० 260) ये सारे आक भारत के समुद्र द्वारा हुए व्यापार में ही संबंधित हैं परंतु सीमा पार के व्यापार पर इस व्यापार के औरव और प्राबल्य को देखते हुए इन आक को न्यूनाधिक रूप से भारत के विदेश व्यापार के सूचक आक के रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है.
3. देखिए अध्याय 1. उदाहरणार्थ : जान स्ट्रुवे : इंडिया (1903), पृ० 186.
4. नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 599-603. सी० पी० ए०, पृ० 164 पर दत्त : स्पीचेज II, पृ० 82-3. बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 603 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 352, 354.
5. नोरोजी : एसेज, पृ० 114; भोलानाथ चंद्र, एम एम खंड II (1873) पृ० 85, खंड III (1874), पृ० 310-1. इंडियन स्पेक्टर, 18 मई (आर० एन० पी० बब, 24 मई 1884) मराठा 25 मई 1884. हिंदू 16 जनवरी 1885. बगबासी, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 9 फरवरी 1889) रानाडे : एसेज, पृ० 184. तिलक, रामगोपाल. पूर्वोद्धत, पृ० 145 पर उद्धृत. ए० बी० पी०, 11 जनवरी 1896. दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 127 ई० एच० II, पृ० 348, 535-6. मधोलकर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 43 नदी : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 112. बाबा : सी० पी० ए०, पृ० 602. गोखले : स्पीचेज, पृ० 52 और जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 352, 357.

6. भोलानाथ चट्ट द्वारा उद्धृत, एम एम, खंड II (1873), पृ० 85.
7. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 696. इससे पूर्व उन्होंने चेतावनी दी थी कि झको के विस्तृत जोड़ इसके प्रवर्तन के वास्तविक चरित्र के संबंध में ननुष्य को हतप्रभ ही कर देते हैं. (पृ० 680) और देखिए . जी० एम० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स पृ० 188.
8. दत्त . ई० एच० II, पृ० 536
9. हिंदू, 21 अप्रैल 1884, 16 जनवरी 1885. मराठा 25 मई 1884, बगबासी, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 9 फरवरी 1889) नौरोजी स्पेचेज, पृ० 323, सी० पी० ए० पृ० 164 पर मधोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 43, दत्त ई० एच० II, पृ० 127, 348, 534, 536, जी० वी० जोशी ने कहा : क्या यह असामान्य स्थितियों का ऋण उत्पादन नहीं है (पूर्वोद्धृत, पृ० 617)
10. देखिए अध्याय II
11. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 641 और देखिए जी० एम० अय्यर : ई० ए० पृ० 131
12. आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक इकानामिक हिस्टरी आफ इंडिया, खंड II में विशेष रूप से इस प्रक्रिया का सुनिश्चित लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है जिसके कारण यह स्थिति और उसके साथ जुड़े परिणाम अस्तित्व में आए. विशेषतः देखिए पृ० 101, 105, 108, 161-4, 345-8 529-32 दूसरों के लिए देखिए, हिंदू, 21 अप्रैल 1884, रानाडे एसेज पृ० 99-101, 183-4, जोशी पूर्वोद्धृत पृ० 620-3 641 एव आगे रामगोपाल पूर्वोद्धृत, पृ० 145 पर उद्धृत तिलक, मधोलकर पूर्वोद्धृत, पृ० 41 जी० एम० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 126. गोखले : स्पेचेज, पृ० 52 और देखिए ऊपर अध्याय II
13. देखिए : अध्याय I.
14. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 651 (तथा पृ० 622-3, 652, 680), और रानाडे एसेज, पृ० 103 (और पृ० 103 एव आगे और 119) तथा देखिए, दत्त ई० एच० II, पृ० 348 सुधीरक, 1 अगस्त, केमरी, 2 अगस्त (आर० एन० पी० बब 6 अगस्त 1898 ने जापान में भारतीय व्यापार की हानि के विरुद्ध विरोध प्रकट किया अध्याय 7 भाग भी देख
15. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 652 रानाडे एसेज, पृ० 13 एव आगे दत्त ई० एच० II, पृ० 531-2. दत्त ने विशेष रूप से मशीनों और मिल-सामग्री के आयात के घटने पर शोक प्रकट किया
16. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 611 दत्त ई० एच० II, पृ० 348, 535-6 जी० एम० अय्यर ई० ए० 352 और अन्य त्रिनका यथाचित स्थान पर बाद में निर्देश किया जाएगा
17. कृतिपय महानुभावों ने आंशिक रूप से यह स्वीकार किया था कि विदेश व्यापार के कुछ लाभ भी हो सकते हैं रानाडे का यह दृष्टिकोण था कि (विदेश व्यापार में) वृद्धि को अच्छाई तो माना जा सकता है परंतु यह खालिस अच्छाई नहीं. (एसेज, पृ० 184) तथा देखिए, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 622 और 624 तथा मयानी, सी० पी० ए०, पृ० 346
18. मराठा, 25 मई 1884 दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 127. ई० एच० I, पृ० 226, ई० एच० II, पृ० 132, 163 तथा आगे
19. मराठा, 25 मई 1884
20. इपीरियल गजेटियर (1908) खंड III, पृ० 298 से गृहीत आयातों में सरकारी भंडारों और कोषों की भी परिगणना है
21. वस्तुन यथार्थ रूप से अनर्घस्त राशियों के संबंध में भारतीय नेताओं में मतभेद था. देखिए भोलानाथ चट्ट : एम एम, खंड II (1873), पृ० 89 इंडियन स्पेक्टेटोर 18 मई (आर०

- एन० पी० बंब, 24 मई 1884). मराठा 25 मई 1884. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 321 और पावर्टी पृ० 569-70. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 636-8, 683; मधोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 40. नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 112; दत्त : ई० एच० II, पृ० 528-9. भारतीय नेताओं ने यह भी चेखा कि यदि पूंजी के आयात और सरकारी ऋण न होते, जिनके कारण एक बड़ी सीमा तक आयातों के मूल्य में वृद्धि हो गई है और निर्यातों की अधिकता क्षीण हो गई है तो आयात निर्यात के मध्य की खाई और भी अधिक गहरी होती. यह तथ्य 1857 से पूर्व के कतिपय वर्षों की अवधि में भारतीय व्यापार में आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता की सामान्य प्रवृत्ति के अपवाद का ही सूचक है, इन वर्षों में निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक थे इसके कारण थे : सरकार द्वारा भारी ऋण लेना और रेलों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का आयात. देखिए : जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 638. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 599. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 336, 553
22. नौरोजी : एसेज, पृ० 113 और पृ० 112-5.
23. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 141.
24. वही, पृ० 569 और देखिए पृ० 568-74
25. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 618, 637 683. राय . पावर्टी, पृ० 6; लालमोहन घोष, सी० पी० ए० पृ० 753 मधोलकर . पूर्वोद्धृत, पृ० 41, नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 112-3. बाबा . सी० पी० ए०, पृ० 143 दत्त इंग्लैंड एंड इंडिया, पृ० 143 ई० एच० II, पृ० 348, 528. जी० एस० अय्यर . ई० ए०, पृ० 336
26. इंडियन स्केट्टर, 18 मई (आर० एन० पी० बंब; 24 मई 1884) मराठा, 25 मई 1884. हिंदू, 16 जनवरी 1883 दत्त . इंग्लैंड एंड इंडिया, पृ० 145. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 683. बाबा : राय० आई० एन० सी०-1898, पृ० 101-2, नदी पूर्वोद्धृत, पृ० 113 जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 188 और ई० ए०, पृ० 353. यदि अमरीका के विदेशी ऋणों के सम्मान-पूर्वक भुगतान का प्रयोजन होता तो इसमें मराठा आपत्ति न करता.
27. समय, 30 जून (आर० एन० पी० बंग० 5 जुलाई 1884) एल० एम० घोष : सी० पी० ए०, पृ० 753 राय० पावर्टी, पृ० 6. गोखले : वेलवी कमीशन, खंड III, पृष्ठ 18240. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 618, 637-8, 683 नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 113 दत्त . इंग्लैंड एंड इंडिया, पृ० 143. ई० एच० II, पृ० 127 और जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 353. 1862 से 1888 तक की अवधि के गृह-प्रभारों की रकमों की अधिक निर्यात की रकमों से तुलना करते हुए जोशी महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'वे लगभग एक दूसरे के सतुलन में ही थीं' (पूर्वोद्धृत, पृ० 637-8) और एल० एम० घोष : पूर्वोद्धृत स्थल
28. समय, 30 जून (आर० एन० पी० बंग०, 5 जुलाई 1884) जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 638, 683, 695. राय : पावर्टी, पृ० 6. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 323. नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 113. दत्त : ई० एच० II, पृ० 536. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 270-1.
29. भोलानाथ चंद्र, एम० एम०, खंड III (1874), पृ० 346. नौरोजी : एसेज, पृ० 115-6. स्पीचेज, पृ० 323. समय, 30 जून (आर० एन० पी० बंग०, 5 जुलाई 1884). न्यू इंडिया, 19 अक्टूबर 1901. दत्त : ई० एच० II, पृ० 163, 343-4, 348, 528-9, 536.
30. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 113.
31. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 323 तथा पावर्टी, पृ० 182, 569.

32. भोलानाथ चंद्र : एम० एम० खंड II, पृ० 89-90 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 639. राय : पावर्टी, पृ० 6-7. मघोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 41, 46. दत्त : ई० एच० II, पृ० 127, 159, 528, 536. न्यू इंडिया, 16 सितंबर 1901. इंडियन पीपुल, 28 जुलाई 1903 और एल० एम० घोष : सी० पी० ए०, पृ० 750, 753 और देखिए, ए० बी० पी० 6 फरवरी 1880, 17 जुलाई 1892.
33. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 639. वस्तुतः निकासी की कुल राशि निर्यातों की दृष्टिगोचर अधिकता से बढ़चढ़कर थी क्योंकि जैसा हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं निर्यातों की वास्तविक अधिकता दृष्टिगोचर से कहीं भिन्न थी. और देखिए, नीरोजी : पावर्टी, पृ० 569 और जी० एस० अय्यर . ई० ए०, पृ० 336 .
34. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 641 तथा पृ० 683.
35. दत्त : ई० एच० II, पृ० 127 और देखिए उनकी स्पीचेज II, पृ० 40.
36. दत्त : ई० एच० II, पृ० 348-9, 528.
37. ई० एच० I, पृ० 48-9, 69. ई० एच० II, पृ० 125-7.
38. केंजवादी यह विचार, कि यदि ब्रिटेन जर्मनी से क्षतिपूर्तियां उगाहना चाहता है तो या तो वह अनिवार्य रूप से जर्मनी का सामान खरीदे अथवा अपने देशवासियों को जर्मनी जाकर वहां की मदिरा पीने की अनुमति दे, झंततः मौलिक नहीं था.
39. भोलानाथ चंद्र, एम० एम०, खंड II (1873), पृ० 90. नीरोजी : एसेज, पृ० 114 स्पीचेज, पृ० 315. इंडियन स्पेक्टेटर, 18 मई (आर० एन० पी० बंब; 24 मई 1884), मराठा, 25 मई 1884. हिंदू, 16 जनवरी 1885. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 683 राय : पावर्टी, पृ० 6-7. मघोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 46-7. ए० बी० पी० 11, जनवरी 1896. दत्त : ई० एच० II, पृ० 127. एल० एम० घोष : सी० पी० ए०, पृ० 752 जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 357-8 तथा देखिए आगे अध्याय XIII 'दि ट्रेन'.
40. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 640-1.
41. वही, पृ० 681.
42. मराठा, 25 मई 1884. हिंदू, 16 जनवरी 1885. समय, 30 जून (आर० एन० पी० बण०, 5 जुलाई 1884). हिंदू राजिका, 28 जनवरी (वही, 7 फरवरी 1885). जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 680-1, 696. रानाडे एसेज, पृ० 183, 185. राय : पावर्टी, पृ० 93-4. दत्त : ई० एच० II, पृ० 101, 344-5. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 355, 357. जे० ए० वाडिया : रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 176
43. बी० डी० बसु में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 52.
44. एम० एम०, खंड II (1873), पृ० 90.
45. दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 127. गोखले : स्पीचेज, पृ० 51. (तथा देखिए गोखले : रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 166) जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 357.
46. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 788-9
47. रानाडे : एसेज, पृ० 184-5. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 643, 650 दत्त : ई० एच० I, पृ० 293 6. ई० एच० II, पृ० 105. स्पीच II, पृ० 120-1. गोखले : स्पीचेज, पृ० 51-2. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 355.
48. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 644-5. रानाडे : एसेज, पृ० 185.
49. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 680.

50. भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड II (1873), पृ० 115. मराठा, 25 मई 1884 हिंदू, 16 जनवरी 1885. समय, 22 जून (आर० एन० पी० बंग०, 27 जून 1885) जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 611, 643, 650-1, 683, 696. रानाडे : एसेज, पृ० 183, 185 राय : पावर्टी, पृ० 93-6. दत्त : ई० एच० I, पृ० VIII 276 ई० एच० II, पृ० 103, 345, 531. गोखले : स्पीचेज, पृ० 52. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 355. हितवादी, 16 दिसंबर (आर० एन० पी० बंग०, 31 दिसंबर 1904) और अध्याय II पीछे हा, राष्ट्रवादियों ने यह अभिस्वीकार किया कि इस शोचनीय स्थिति के लिए आयात एकमात्र उत्तरदायी तत्व नहीं था और वस्तुतः यह देश पर विदेशी सत्ता के विभिन्न प्रभावों से ही उत्पन्न दुष्परिणाम थे.
51. जोशी : पूर्वोद्धृत, क्रमशः पृ० 682, 611, 651 तथा 645. और रानाडे : एसेज, पृ० 184, दत्त : ई० एच० II, पृ० 350. जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 125. अखबारे आम, 18 फरवरी (आर० एन० पी०, पी० 21 फरवरी 1891) दैनिक-ओ-समाचार चंद्रिका, 18 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग, 22 अक्तूबर 1892)
52. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 653 और राय : पावर्टी, पृ० 95-6. दत्त : ई० एच० II, पृ० 345, 350.
53. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 85.
54. मधोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 43 और देखिए एन० के० आर० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०-1901, पृ० 138.
55. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 645-7. मधोलकर ने 50 से 60 करोड़ रुपयों की रकम का उल्लेख करते हुए स्पष्टतः जोशी की गणना पर ही विश्वास किया.
56. वही, पृ० 682 और 651 क्रमशः
57. भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड II (1873), पृ० 86
58. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 654 बाचा : रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101-2. जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स. पृ० 191.
59. इंडियन स्पेक्टेटोर ने 18 मई 1884 के अंक में लिखा : 'भारतीय खेतिहर तो केवल विदेशी निर्यातक का पावचक्की उद्योगवाला दास था' (आर० एन० पी० बंग०, 24 मई 1884) और देखिए, हिंदुस्तानी, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 21 अप्रैल 1892). बाचा : नेलवी आयोग, खंड III, प्रश्न 17509-10, 17516, 17524, सी० पी० ए०, पृ० 601, राय : इंडियन फैमिस, पृ० 63. जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 192. दि वायसराय आन दि इकानामिक कमीशन आफ इंडिया, एच० आर०, मई 1901, पृ० 352 और जून 1901, पृ० 445, रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 101. ई० ए०, पृ० 225. दत्त : ई० एच० II, पृ० 348-9.
60. बाचा : सी० पी० ए०, पृ० 601 और बाचा : नेलवी आयोग, खंड III, प्रश्न 17525-7, 17529. राय : इंडियन फैमिस, पृ० 62-3 जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 225.
61. मराठा, 16 नवंबर 1902.
62. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 658 दत्त : ई० एच० II, पृ० 350.
63. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 658. राय : इंडियन फैमिस, पृ० 62-3. जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 192, ई० ए०, पृ० 223-6.
64. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 657.
65. वही, भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड II (1873), पृ० 86. नीरोजी : स्पीचेज, पृ० 596. मधोलकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 42. बाचा : सी० पी० ए०, पृ० 603. न्यू इंडिया, 19 अगस्त 1901. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 353.

- 66 रानाडे : एसेज, पृ० 65-97 उन्होंने लिखा सांस्कृतिक पद्धति ने नीदरलैंड्स, ईस्ट इंडिया को उच्चतम स्तर की भौतिक समृद्धि पाने में सहायता की है (पृ० 79) तथा यह स्थिति उपयुक्त नहीं थी क्योंकि उत्पादित सामग्री के ब्रिटिश भारत से निर्यातित कच्चे माल का तैयार माल से अनुपात चार के मुकाबले एक था वहां नीदरलैंड्स इंडिया में यह एक के मुकाबले चार था (पृ० 85) यहां यह उल्लेखनीय है कि रानाडे तक ने एक दृष्टि, विदेशी पूँजी की अपेक्षा भारतीय पूँजी प्रयोग, से सांस्कृतिक प्रणाली का उल्लेखन किया था (पृ० 92-3)
- 67 मराठा, 25 मई 1884 राय पावर्टी, पृ० 15-16 वाचा, सी० पी० ए०, 603 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 353-55 तुलनीय, इपीरियल गजेटियर, खंड III, पृ० 278 विदेश व्यापार के लिए भारत में बाजार अत्यंत सीमित है और उपर्युक्त आयातों का एक सारवान भाग भारत में बढ़ते यूरोपीय लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के ही काम आता था
- 68 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 355 (तथा पृ० 12) और वाचा सी० पी० ए०, पृ० 603, गोखले स्पीच, पृ० 16
- 69 हिंदू 21 अप्रैल 1884, बगबासी, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 9 फरवरी 1889), ताजुल अखबार, 4 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 10 जनवरी 1801), राय पावर्टी, पृ० 13-4, 35 दत्त ई० एच० II, पृ० 348-9, 534, 536 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 85
- 70 आर० एन० पी० बग०, 13 जुलाई 1889
- 71 भोलानाथ चंद्र एम एम, खंड II (1873), पृ० 82, 85-9 खंड III (1874), पृ० 310-11 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 611, 622, 624-5, 666 784 788 रानाडे एसेज पृ० 66, 185 6 हिंदुस्तानी 16 सितंबर (आर० एन० पी० एन०, 24 सितंबर 1801) पंजा अखबार, 27 अक्टूबर (आर० एन० पी० पी०, 10 नवंबर 1894) नीरोजी स्पीच, पृ० 341 राय पावर्टी पृ० 321-3, 326 भारत जीवन, 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 13 जुलाई 1898) मधोलकर पूर्वोद्धृत, पृ० 46 नमीने आगरा, 15 मई (आर० एन० पी० एन०, 18 मई 1901) न्यू इंडिया, 19 अगस्त 1901 एडवोकेट, 10 जुलाई (आर० एन०, पी० एन०, 19 जुलाई 1902). दत्त ई० एच० II, पृ० 536
- 72 भोलानाथ चंद्र एम एम, खंड II (1873), पृ० 88-9 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 631-3, 666, 783, 787 रानाडे . एसेज, पृ० 185-6 मधोलकर पूर्वोद्धृत पृ० 41 नीरोजी स्पीच, पृ० 341
- 73 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 66
- 74 बही, पृ० 625 और पृ० 633, 666 हिंदुस्तानी, 16 सितंबर (आर० एन० पी० एन०, 24 सितंबर 1891) भारत जीवन, 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 23 जुलाई 1898)
- 75 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 634
- 76 बही, पृ० 806-7
- 77 एडवोकेट, 19 जून (आर० एन० पी० एन०, 21 जून 1902)
- 78 नीरोजी एसेज, पृ० 101 पर उद्धृत
- 79 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 641
- 80 वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 105 और देखिए, राय पावर्टी, पृ० 36 नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 125 जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 357-8
- 81 इपीरियल गजेटियर (1908) खंड III, पृ० 284

82. दुर्गाप्रसाद : पूर्वोद्धृत, 224.
83. आफताब-ए-पञ्जाब, 9 मई (आर० एन० पी० एन०, 19 मई 1883). समय, 27 अक्तूबर, सोम प्रकाश, 27 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग० 1 नवंबर 1884), ढाका प्रकाश, 2 नवंबर (वही, 8 नवंबर 1884) किस्सा-ए अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 1888) रोझना ए पञ्जाब, 21 जून (वही, 2 फरवरी 1889), बगबानी, 2 फरवरी. 6 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 9 फरवरी, 13 जुलाई 1889) नवविभाकर साधारणी, 27 मई (वही, 27 मई 1889); हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 30 अप्रैल 1891) हिंदी प्रदीप, मार्च; न्याय सुधा 13 मई, कानपुर गजट, 15 मई, नैरग, 11 मई (वही, 21 मई 1891), भारत जीवन, 15 फरवरी (वही, 18 फरवरी 1892), आर० एन० पी० पी० 10, 24 जनवरी, 21 फरवरी, 21 28 मार्च, 4, 11, 18, 25 अप्रैल, 2, 23 मई, 19 दिसंबर 1891, 28 जनवरी, 21 फरवरी, 11 मार्च, 22, 29 अप्रैल 1893, 20 जुलाई 1895, 26 मार्च, 28 मई, 4 जून 30 जुलाई 1898, 28 अक्तूबर 1899, 30 जून 1900, मे उद्धृत पञ्जाब के लगभग सभी पत्र सम्मिलित हैं : दैनिक-ओ-समाचार चद्रिका, 22 जून (आर० एन० पी० बंग०, 30 जून 1891). हितवादी, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 1 अगस्त 1891) बर्दवान संजीवनी, 28 जुलाई (वही, 8 अगस्त 1891) बगाली, 23 जनवरी 1892 बगनिवासी, 22 नवंबर (आर० एन० पी० बंग, 23 नवंबर 1895) भारत जीवन, 18 मई, मंजुमने हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 26 मई 1897), हिंदुस्तान, 13 अक्तूबर (वही, 14 अक्तूबर 1896); रहबर, 16 फरवरी (वही 24 फरवरी 1897), नजमउल हिंद, 18 अप्रैल; दबदबा-ए-केसरी, 16 अप्रैल (वही, 20 अप्रैल और 27 अप्रैल 1898 क्रमशः) हिंदुस्तान, 20 मई हिंदुस्तानी, 18 मई (वही, 25 मई 1898). काशी वैभव, 26 मई; अवध अखबार, 25 मई, (वही, 1 जून 1898); भारत जीवन, 27 जून, सुदेश प्रचर्क, जून (वही, 6 जुलाई 1898). भारत जीवन, 7 अगस्त, 2 अक्तूबर (वही, 16 अगस्त, 11 अक्तूबर 1899) नदी : पूर्वोद्धृत पृ० 113 जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 189. ई ए, पृ० 278-9 285 नसीमे आगरा, 15 मई, रोजनामचा ए केसरी 15 मई (आर० एन० पी० एन०, 18 मई 1901), इंडियन पीपल (24 जुलाई 1903) दत्त : ई० एच० II, पृ० 127 (यादटिप्पणी)
84. अवध पत्र, 21 मई (आर० एन० पी० एन०, 28 मई 1891).
85. आर० एन० पी० एन०, 30 जनवरी 1900.
86. बगवासी, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 9 फरवरी 1889) दैनिक-ओ-समाचार चद्रिका, 22 जून (वही, 30 जून 1891) नदी : पूर्वोद्धृत, पृ० 113 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 85, 110
87. आर० एन० पी० बंग०, 1 अगस्त 1891.
88. दत्त : ई० एच० II, पृ० 349 और पृ० 536.
89. दैनिक-ओ-समाचार चद्रिका, 22 जून 1891, 4 सितंबर 1895 (आर० एन० पी० बंग०, 30 जून 1891 और 7 सितंबर 1895). हितवादी, 25 जुलाई (वही, 1 अगस्त 1891). बर्दवान संजीवनी, 28 जुलाई (वही, 8 अगस्त 1891), भारत जीवन, 18 मई; मंजुमने ए हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 26 मई 1896). भारत जीवन, 2 अक्तूबर (वही, 11 अक्तूबर 1899). बाबा : सी० पी० ए०, पृ० 585-6. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 110-11.
90. हितवादी, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 1 अगस्त 1891).
91. दत्त : ई० एच० II, पृ० 348-9, 534-6. और देखिए अध्याय 13.

92. बाबा : सी० पी० ए०, पृ० 587 तथा देखिए : जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 611, 613. किस्ता ए अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 1888); अखबार ए आम, 29 जनवरी (वही, 2 फरवरी 1889); आफताब ए पंजाब, 5 जून (वही, 15 जून 1889); हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 30 अप्रैल 1891); न्याय सुधा, 13 मई; कानपुर गजट, 15 मई; नैरंग, 11 मई (वही, 21 मई 1891); भारत जीवन, 15 फरवरी (वही, 18 फर० 1892); सिराज उल अखबार, 16 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 21 फरवरी 1891); केसर उल अखबार, 18 मार्च (वही, 21 मार्च 1891); आफताब ए पंजाब, 20 मार्च (वही, 28 मार्च 1891); इंपीरियल पेपर, 11 अप्रैल (वही, 18 अप्रैल 1891); दिल्ली पंच, 22 अप्रैल (वही, 2 मई 1891); खैरबाह ए आलम, 8 मई (वही, 23 1891); अफताब ए हिंद, 16 मई (वही, 6 जून 1891); रहबर ए हिंद, 20 जुलाई (वही, 1 अगस्त 1891); पैसा अखबार, 14 दिसंबर कोहिनूर, 12 दिसंबर (वही, 19 दिसंबर 1891). पैसा अखबार, 13 मई (वही, 28 मई 1898). अम्बाला गजट, 24 मई (वही, 8 जून 1898). हितवादी, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 1 अगस्त 1891) बंगाली, 23 जनवरी 1892. राय : पावटी, पृ० 174-5. रहबर : 16 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 24 फरवरी 1897). नजमूल हिंद, 8 अप्रैल (वही 20 अप्रैल 1898) दबदबा ए केसरी, 16 अप्रैल (वही, 27 अप्रैल 1898); हिंदुस्तानी, 18 मई, हिंदुस्तान, 20 मई (वही, 25 मई 1898); काशी बंधव, 26 मई, अवध अखबार, 25 मई (वही, 1 जून 1898). राष्ट्र-वादियों के इस दृष्टिकोण कि सामान्य मूल्यवृद्धि जनहित में न होकर उनके लिए हानिप्रद है, की समीक्षा उमर की गई है.
93. लाला मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 21.
94. आफताब ए पंजाब, 9 मई (आर० एन० पी० पी० एन०, 19 मई 1883); अखबार ए आम, 29 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 2 फरवरी 1889). आफताब ए पंजाब, 5 जून (वही, 15 जून 1889); पैसा अखबार, 14 दिसंबर (वही, 19 दिसंबर 1891); भारत जीवन, 15 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 18 फरवरी 1892), सिंह सहाय, 11 जनवरी (वही, 21 जनवरी 1893), ताज उल अखबार, 8 अप्रैल (वही, 22 अप्रैल 1893); भारत जीवन, 19 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 30 जनवरी 1900). राय : इंडियन फॉर्मिस, पृ० 64. बंगाली, 28 अप्रैल 1901.
95. नवविभाकर साधारणी, 27 मई (आर० एन० पी० बग०, 1 जून 1889); हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 20 अप्रैल 1891); न्याय सुधा, 13 मई. कानपुर गजट, 15 मई. नैरंग, 11 मई (वही, 21 मई 1891). रहबर ए हिंद, 20 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 1 अगस्त 1891). पैसा अखबार, 13 मई, 20 जुलाई (वही, 28 मई, 30 जुलाई 1898). सदा ए हिंद, 16 अक्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 1899). हिंदी हिंदुस्तान, 24 मई (आर० एन० पी० एन०, 1 जून 1901). ए० बी० पी०, 9 जुलाई 1901. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 111-2, 290.
96. केसे. ए. अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 1888). रोजाना ए पंजाब, 28 जनवरी (वही, 2 फरवरी 1889). दोस्त ए हिंद, 3 अप्रैल (वही, 11 अप्रैल 1891) आफताब ए पंजाब, 20 मार्च (वही, 28 मार्च 1891). दिल्ली पंच, 22 अप्रैल (वही, 2 मई 1891). कोहिनूर, 4 फरवरी, 8, 22 अप्रैल (वही, 21 फरवरी, 22, 29 अप्रैल 1893). पैसा अखबार, 27 फरवरी (वही, 11 मार्च 1893) दैनिक-जो-समाचार चंद्रिका, 12 मई (आर० एन० पी० बग०, 14 मई 1892). और 4 सितंबर (वही, 7 सितंबर 1895).

97. ताज उल अखबार, 6 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 20 जुलाई 1895); पैसा अखबार, 20 मार्च, 20 जुलाई (वही, 10 अप्रैल, 30 जुलाई 1897) भबाला गजट 24 मई (वही, 4 जून 1898) सिविल एंड मिलट्री न्यूज, 18 अक्टूबर, ताज उल अखबार, 14 अक्टूबर (वही, 28 अक्टूबर 1899) ए कारेमपेडेट इन मियालकोट पेपर, 1 अप्रैल (वही, 7 अप्रैल 1900) हमदर्द ए हिंद, 16 जून, (वही, 30 जून 1900) अजुमन ए हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 26 मई 1896), जमाना, 17 सितंबर अनीसे हिंद, 16 सित० (वही, 23 सित० 1896) हिंदुस्तान, 13 अक्टू० (वही, 14 अक्टू० 1896) हितवादी, 13 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 21 नवंबर 1896), सजीवनी, 26 दिसंबर (वही, 2 जनवरी 1897) 13 जनवरी के सप्ताह के सभी उडिया पत्र (आर० एन० पी० बग०, 6 फरवरी 1897). ए० बी० पी०, 22 जनवरी 1897 ज्ञान प्रकाश, 26 मई, बंबई समाचार, 28 मई (आर० एन० पी० बब०, 28 मई 1898), भारत जीवन, 3 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 5 जनवरी 1898), जमायुल उल्लाम, 18 सितंबर (वही, 9 अक्टूबर 1900)
98. नेटिव ओपीनियन, 25 मई 1884 नवविभाकर माघारणी, 27 मई (आर० एन० पी० बग०, 1 जून 1889) पैसा अखबार, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 15 अप्रैल 1893). भारत जीवन, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 17 अप्रैल 1900) जी० एस० अय्यर : ई ए पू० 115-7.
99. मराठा 24 फरवरी 1884 विक्टोरिया पेपर, 16 दिसंबर (आर० एन० पी० पी०, 23 दिस० 1893), 8 नवंबर (वही, 17 नवंबर 1900)
100. एल० सी० पी०, 1882, खंड XXI कलकत्ता के अग्रेज व्यापारियों ने स्वभावतः ही इस दृष्टिकोण का समर्थन किया (ए० बी० इग्लिस का भाषण, वही, पृ० 300). डी० सी० साहा ने 1889 में इस मांग को दुहराया (एल० सी० पी०, 1880, खंड XXVIII पृ० 141)
101. बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन का 1888 का प्रतिवेदन, पृ० 5
102. आंशिक रूप से यह इस तथ्य के कारण था कि अर्थशास्त्रियों को छोड़कर भारतीय नेताओं ने जिन विशिष्ट आर्थिक विषयों पर तथा विदेश व्यापार पर सामान्य चर्चा की, वे वस्तुतः अत्यंत व्यापक विषय थे और उन्हें आसानी से संघर्ष का विषय नहीं बनाया जा सकता था उदाहरणार्थ वर्षों तक कांग्रेस के असंख्य प्रस्तावों में विदेश व्यापार का उल्लेख नहीं हुआ इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार के संबंध राष्ट्रवादी मत की स्वल्पता इस प्रश्न पर अपने आप में उनकी शक्ति के अभाव की ही सूचक है.
103. जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 11901, पृ० 126.
104. रानाडे . एसेज, पृ० 118 तथा देखिए, नोरोजी : सी० पी० ए०, पृ० 164. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 666-7. वाचा . रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 105 दत्त : स्पीचेज II, पृ० 127.
105. उदाहरणार्थ देखिए, भोलानाथ चट्ट का निबन्ध, आर० सी० दत्त : राइटिंग्स ऐंड स्पीचेज; जी० एस० अय्यर : सम इकानामिक आस्पेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया.
106. नोरोजी . स्पीचेज, क्रमशः पृ० 601, 603 और 604 तथा देखिए, नोरोजी : वही, पृ० 115-6, 190, 503 सी० पी० ए०, पृ० 164
107. दत्त : स्पीचेज II, पृ० 82-3 और देखिए ई० एच० II, पृ० 344, 617.
108. के० एस० शेल्सकर : दि प्राब्लम आफ इंडिया (सदन, 1940) पृ० 151-3, 166-7.

अध्याय 5

रेलों की भूमिका

रेलों के निर्माण द्वारा देश का विकास ही वह उपाय है जिसके द्वारा कृषि पर निर्भर विशाल जनसंख्या की हालत में अत्यंत सुनिश्चित रूप में निरंतर सुदृढ़ सुधार लाया जा सकता है।

—लाइ एनगिन

भारतीय जनता अनुभव करती है कि यह निर्माण कार्य मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी तथा धनी वर्गों के हितों की दृष्टि से ही किया जाता है और यह उन्हें हमारे साधनों के और अधिक शोषण में महायता देता है।

—गोपालकृष्ण गोखले

रेलों के निर्माण का भारतीय जनता के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। रेलों की स्थापना से पूर्व अंगरेज यथार्थ में न भारतीय जीवन में प्रवेश पा सके थे, न भारत को विकासशील विश्वमंडी के साथ जोड़ सके थे और न ही भारत का पूंजीवादी विकास पथ की दिशा पर डाल सके थे। वस्तुतः देश के विदेशी शासकों ने समय बीतते बीतते रेलों के निर्माण को देश के सभी आर्थिक रोगों की रामबाण औषधि के रूप में या और अन्य सभी योजनाओं से उसे प्राथमिकता देते हुए उसके विकास पर शक्ति तथा तीव्रता से बल दिया।

निस्संदेह भारतीय रेलों के निर्माण का इतिहास एक सर्वविदित तथ्य है, फिर भी देश में रेलों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले विविध प्रश्नों पर प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण को सम्यक रूप से समझने के लिए इस विषय का संक्षिप्त विवेचन अनुचित न होगा।

संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा

ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम 1831-2 में मद्रास में ही रेल के निर्माण की योजना बनाई गई। परंतु यह रेलगाड़ी अपनी गति के लिए पशुओं पर निर्भर थी। भारत के लिए सर्वप्रथम भाप रेल गाड़ियों की योजना 1843 में इंग्लैंड में ही तैयार की गई। ईस्ट

इंडिया कंपनी के निदेशक-मंडल ने इस योजना के मंचालन के बारे में उत्सुकता नहीं दिखाई क्योंकि उसकी दृष्टि में भारत में इस योजना की असफलता पूर्वसिद्ध थी परंतु वह भारत के साथ व्यापाररत इंग्लैंड के वाणिज्य सदनों, धनकुबेरों तथा रेलपथ के उन्नायकों तथा लंकाशायर के वस्त्र उत्पादकों के अपने देश में ही पड़ने वाले प्रबल आर्थिक और राजनीतिक दबाव को दीर्घ काल तक सहन न कर सका।¹² भारत में कंपनी के अपने ही गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग ने शांतिपूर्वक यह प्रतिवेदित किया कि भारत के सीधे स्थल-मार्ग रेलपथों के निर्माण के लिए उल्लेखनीय सुविधाएं जुटाते हैं और रेलपथों का निर्माण वाणिज्य के लिए, सरकार के लिए और देश पर सैनिक नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा।¹³ ज्यों ही भारत में रेलों के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली त्यों ही कंपनी के निदेशक मंडल और रेलवे के उन्नायकों में भारतीय रेल के निर्माण में लगने वाली निजी धनराशि के न्यूनतम लाभांश अथवा प्रतिलाभ की शासकीय गारंटी के प्रश्न पर छोटा सा विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद का निर्णय भी उन्नायकों के पक्ष में गया और 1849 में भारत राज्य सचिव ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे कंपनी के साथ प्रथम रेलवे इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों की स्वीकृति की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं :

1. निजी कंपनियां भारत में रेलों का निर्माण और मंचालन करेंगी।
2. निजी कंपनियों द्वारा जुटाई पूंजी पर 99 वर्ष की अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पांच प्रतिशत प्रतिभूत वार्षिक मूद का भुगतान करेगी।
3. ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी कंपनियों को आवश्यकतानुसार 99 वर्ष के पट्टे पर बिना मूल्य के भूमि देने का दायित्व होगा।
4. इन सुविधाओं के प्रतिपादन में कंपनी ने रेलवे के स्वर्चों और मंचालन का नियंत्रण अपने हाथ में रखा।
5. रेलों को डाक बिना प्रभारों के और सैनिकों तथा सैनिक भंडारों को छटी दरों पर ले जाना होगा।
6. जब तक प्रतिभूति के रूप में उगाही अग्रिम राशियों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक प्रतिभूति पांच प्रतिशत वार्षिक व्याज की राशि में अधिक होने वाले अतिरिक्त लाभ को ईस्ट इंडिया कंपनी और रेलवे कंपनियां आपस में बांट लेंगी। अग्रिम राशियों के चुक जाने के उपरांत सारा लाभ रेलवे कंपनियों को मिलेगा।
7. 99 वर्षों के उपरांत रेल कंपनियां बिना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के रेलों सरकार को सौंप देंगी। सरकार केवल मशीनों, संयंत्रों तथा रेलगाड़ी के डिब्बों का मूल्य चुकाएगी।
8. ईस्ट इंडिया कंपनी 99 वर्षों से पूर्व, प्रथम पच्चीस अथवा प्रथम पचास वर्षों के उपरांत पूंजीगत सामान्य हिस्सों और सहभागों का पूरा मूल्य चुकाने पर रेलवे को खरीद सकेगी।
9. उपर्युक्त अनुबंध के अनुरूप रेलवे कंपनियां किसी भी समय छः मास की चेतावनी देने पर रेलवे व्यवसाय को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप सकेंगी। और उसके उपरांत

निवेशित मूल पूजी की वसूली की माग कर सकेंगी।

ये प्रारम्भिक अनुबन्ध अगली दो शताब्दियों में हस्ताक्षरित सभी परवर्ती समझौतों के लिए आदर्श रूप बन गए। परन्तु इस समय तक रेल के निर्माण में सबधित सर्वोत्तम नीति, गति तथा सर्वोत्तम उपायों के विषय में विवाद किसी भी रूप में समाप्त नहीं हो पाया था। कुछ वर्ष तक और इस विवाद में उग्रता तथा क्षुब्धता बनी रही। फिर इंग्लैंड में समाविष्ट प्रतिभूत कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश पूँजी के साथ दून निर्माण में इसका अस्थायी रूप से हल हो गया। लार्ड डलहौजी ने 1853 में लिखे अपने प्रसिद्ध तथा सर्वांगपूर्ण लेख में इस नीति का स्पष्ट प्रकाशन किया। इस लेख में उन्होंने निर्देश किया कि यदि ब्रिटिश पूँजी के निवेश क्षेत्र की गभाव्यता के मद्देन में तथा मेनाओं की गतिविधि और युद्धकाल में द्रुतगति के लिए रेलों में अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से भारत के प्रान्तीयता के साधनों का एक बार वैज्ञानिक विकास किया जाए तो भारत ब्रिटिश उत्पादकों के माल को खपाने की मंडी के रूप में और कृषि सबध की वच्चे माल के मभरणकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।¹ उन्होंने प्रथम पग के रूप में चार मुख्य चौमुखे रेल-मार्गों की पद्धति का सुझाव दिया। इन रेलमार्गों के अतर्गत अनेक प्रेजिडेसियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और प्रत्येक प्रेजिडेसी का अंतरंग प्राकृतिक पतन से जुड़ा हो। चौमुखे रेलमार्ग को देश के कृषिउत्पादनों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस आधार के रूप में ही लिया गया।

1969 की समझौते तक जब इस नीति में परिवर्तन किया गया, प्रतिभूत कंपनियों द्वारा 4255 मील लंबे रेलपथों का निर्माण किया जा चुका था और उम अवधि में प्रतिभूत व्याज की दर साढ़े चार में पांच प्रतिशत रही।

1869 में पूर्व रेलों के निर्माण के मूल्य बहुत अधिक और अनाभरारी रहे। प्रारम्भ में ही प्रतिभूति के फलस्वरूप सरकार द्वारा कंपनियों को ऊँचे भुगतान भगत पड़े। लार्ड डलहौजी ने जहाँ प्रतिमील रेलपथ के निर्माण का औसत व्यय 8000 पाँउ होता था, वहाँ बेमोल दी गई भूमि के मूल्य के अतिरिक्त ही वास्तविक व्यय लगभग 18000 पाँउ प्रति मील आया,² इस अधिक व्यय के अनेक बहुमुखी कारण थे। कार्य का प्रारम्भिक स्वरूप, कुशल श्रमिकों का अभाव स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी का अभाव अनुभवहीनता, चौड़े रेलपथों का चुनाव निर्माण का अनावश्यक रूप में ऊँचा स्तर अनावश्यक दोहरी पटरियाँ आदि परन्तु ऊँचे व्ययों के लिए प्रमुख रूप में उत्तरदायी तत्व था, अत्यधिक प्रतिभूति पद्धति जिनमें कंपनियों के लिए रेलपथों के निर्माण और मालान में मिन-व्यय की प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन का कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा था, दमन उल्टे कंपनियों को लगभग अनावश्यक व्ययों के लिए ही प्रोत्साहित किया क्योंकि जितना ऊँचा पूँजीगत व्यय होगा उतनी ही अधिक सुरक्षित और प्रतिभूत व्याज की वसूली होगी।

भारत के एक भूतपूर्व विन मद्रम्य डब्ल्यू० एन० मैसी ने 1872 में अपने साक्ष्य में कहा 'रेलपथों पर व्यय की जाने वाली सारी धनराशि अगर रेल पूँजीपतियों में आती थी और जब तक उसे भारत के राजस्व में से पांच प्रतिशत व्याज की प्रतिभूति प्राप्त थी, तब तक उसकी बला से, चाहे उधार दी गई धनराशि हुगली में फँकी जाए अथवा ईट-मारा

बनाने के काम में ली जाए।⁶ इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप जहां उचित व्यय पर मूद की रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त आय होने की संभावना थी, वहां वास्तविक व्यय पर प्रतिभूत मूद के भुगतान के लिए ही आय अपर्याप्त रही और सरकार को स्वयं ही घाटा पूरा करना पड़ा।⁷ इस नियमित और बढ़ते हुए घाटे ने राज्य के राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित किया⁸ और इसका अपरिहार्य परिणाम यह निकला कि रेलपथों के निर्माण की गति को मंद कर देना पड़ा। गवर्नर जनरल जान लारेंस ने जनवरी 1869 में लिखे अपने विस्तृत और सुबद्ध लेख में यह सुझाव दिया कि वर्तमान व्यवस्था को जिसके अंतर्गत सारा लाभ कंपनियों को मिलता है और साग घाटा सरकार को उठाना पड़ता है,⁹ समान कर देना चाहिए। प्रतिभूति के लौटा लेने के फलस्वरूप यदि निजी उद्यम भविष्य में रुपया लगाने को अग्रसर नहीं होते तो सरकार प्रतिभूति दर की अपेक्षा अथवा मीधे राजस्वों से रुपया लेने की अपेक्षा स्वयं ही मूद की मस्ती दर पर ऋण लेकर रेलों का निर्माण तथा संचालन करे। भारत-सचिव ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और 1870-80 की अवधि में स्वयं सरकार ने जितने व्यय में ही रेलों का निर्माण किया। कुल 8,494 मील लंबे रेलपथों में से 1880 तक लगभग 2493 मील रेलपथ का निर्माण सरकारी अभिकरणों ने ही किया।

यद्यपि राज्य द्वारा संचालित रेल व्यवस्था प्रतिभूत रेल व्यवस्था की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत मस्ती और अधिक सफल थी तथापि प्रधान रूप से निर्माण की गति को तीव्रता देने में उसकी असफलता के कारण उसपर शीघ्र ही प्रहार किए जाने लगे।¹⁰ लक्ष्यमिद्धि में राज्य के राजस्व अपर्याप्त मिद्ध हुए। 1880 के अकाल आयोग के सुझाव के अनुसार अकालों में सुरक्षित रहने के लिए देश को 20,000 मील लंबे रेलपथ की आवश्यकता थी।¹¹ अकाल आयोग द्वारा अनुशंसित रेलपथों के निर्माण में द्रुतगति की प्राप्ति के लिए वर्तमान नीति में प्रत्यावर्तन की सर्वप्रथम लार्ड रिपन के मन्तव्य में स्वयं भारत सरकार द्वारा ही जबर्दस्त वकालत की गई। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए 1884 में एक मसदोय प्रवर सीमित नियुक्त की गई। उसने रेलों के निर्माण के द्रुतविकास और उसके लिए दोनों, राज्य तथा निजी, अभिकरणों से लाभ उठाने की सिफारिश की। इस उद्देश्य की प्राप्ति में निजी उद्यम स्वतः साहसपूर्वक आगे नहीं आ रहे थे अतः सरकार को एक बार पुनः प्रतिभूति व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। हां, यह बात अवश्य है कि इस बार शर्तें उतनी दुःसह नहीं थीं। राज्य अभिकरण का भी साथ साथ उपयोग चलता रहा। इसके उपरान्त तो रेलपथों का विस्तार ऐसी तीव्र गति पकड़ गया जिसे कुछ लोगों के अनुसार चरम गति कहा जा सकता है। 30 जून 1905 तक 359 करोड़ रुपये (अथवा 240,000,000 पौंड) में निर्मित लगभग 28054 मील रेलपथों का यातायात के लिए उद्घाटन हो गया था।

अंत में 1905 तक भारतीय रेलपथ विकास के संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से प्राप्त उसके प्रमुख चार पक्षों को रेखांकित करना अनुचित न होगा :

(क) सभी प्रकार की व्यावहारिकता की दृष्टि से भारतीय रेलपथों के निर्माण में भारतीय पूंजी की भूमिका नगण्य ही थी। इस कार्य की सिद्धि में ब्रिटिश पूंजी का ही

योगदान महत्वपूर्ण है। रेलपथों के निर्माण कार्य के लिए ब्रिटेन से भारत आने वाली पूँजी इतनी अधिक थी कि उसे 19वीं शताब्दी के विदेशी निवेश की सबसे बड़ी एकाकी इकाई कहा जा सकता है।¹²

- (ख) भारतीय रेलपथों के संबंध में घाटे के खतरे को उठाने को तैयार वास्तविक निजी उद्यम का लगभग अभाव ही था क्योंकि इनके उन्नायक और रुपया लगाने वाले इस उद्यम की सामान्य आशंकाओं को ही भेलने के लिए तैयार नहीं थे। वे या तो सरकारी प्रतिभूति मिलने पर ही कार्य संचालन को प्राथमिकता देते थे अथवा रेलपथों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों में धन के निवेश के पक्ष में थे।
- (ग) शताब्दी के अंत तक तो भारतीय रेलें अपने पर निवेशित पूँजी पर देय व्याज को ही चुकाने के योग्य नहीं थी। 1900 तक, जब उन्होंने प्रथम बार शुद्ध लाभ कमाया, उस समय तक सरकार को प्रतिभूत व्याज राशि के भगतान के लिए 76 करोड़ रुपयों का भारी बोझ उठाना पड़ा।
- (घ) ममीक्षाधीन अवधि के अंतिम वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सरकार के लिए आर्थिक कठिनाइयों और जनता के लिए अकाल और प्लेग जैसे रोगों के बावजूद रेलपथों का निर्माण पर्याप्त तीव्र गति से हुआ। जहाँ 1850-1891 की अवधि में 17308 मील लंबे रेलपथों का निर्माण हुआ, वहाँ 1892-1905 की अपेक्षाकृत स्वल्प अवधि में 10746 मील लंबे रेलपथों का निर्माण हुआ। जंक के निर्देशानुसार ग्रेट ब्रिटेन तक में रेलपथों का विकास इस तीव्र गति में नहीं हुआ था और फ्रांस ने जिन रेलपथों को अपने यहाँ खपाया उनके निर्माण की गति भारत की अपेक्षा मंद थी।¹³

रेल विस्तार की गति: राष्ट्रवादी दृष्टिकोण

ज्यों ही कुछ वर्षों में रेल के निर्माण कार्य ने वेग पकड़ा त्योंही भारतीय मत के प्रवक्ताओं ने रेलपथों के विस्तार, संगठनात्मक तथा वित्तीय व्यवस्था पर अपने विचार और दृष्टिकोण के निर्धारण और प्रकाशन की आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने रेल के निर्माण की गति विषयक अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया और उसकी आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं किया।

भारतीय नेताओं ने न तो विशुद्ध सैद्धांतिक आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया और न ही रेलों के गुण-दोषों पर उनके शुद्ध रूप में विचारविमर्श किया। उनका दृष्टिकोण प्रमुखतया वर्तमान रेलों के, भारतीयों के हितों पर और देश के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले, प्रभाव की जानकारी के संदर्भ में ही निर्धारित था। जी० वी० जोशी महोदय ने अपने लेख, 'दि इकानामिक रिजल्ट्स आफ़ फ्री ट्रेड ऐंड रेलवे ऐक्सटेंशन' में इस तथ्य का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका यह लेख पूना सार्वजनिक सभा के अक्टूबर 1884 के जनरल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने भारत के रेलपथों के असीमित प्रसार की मांग के संबंध में लोकमत को अभिव्यक्ति देने का दावा करते हुए लिखा :

जो सज्जन इसकी पूर्व प्रदर्शित बुगइयो को तथा भविष्य में और अधिक संपीडक बुराइयो की चेतावनी को भली प्रकार और पूर्ण रूप से मिट्ट मानते हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उन मिट्टातों पर शांत चित्त में विचारविमर्श करें जिनके आधार पर एक पक्षीय विकास की वकालत की जा रही है। वे सज्जन इस संबंध में देश की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में सम्मानित दुष्परिणामों के मंदर्भ में स्थिति की समीक्षा करें।¹⁵ इस संबंध में राज्य के विगत कार्य के देश की आर्थिकता और आय-व्यय स्थिति पर पड़े प्रभावों पर गभीर विचार किए बिना इस प्रश्न का उत्तर देना संगत नहीं होगा।¹⁶

रेलों का आर्थिक प्रभाव

ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार देश पर वर्तमान रेलों का प्रभाव पूर्णतः सुखद ही पड़ा है।¹⁷ प्रारंभ में ही रेलों के द्रुत विकास की वकालत करने हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने लोकोपकार की अपील की और घोषणा की कि रेलों से देश की दरिद्रता और दुर्भिक्ष के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। 1844 में भारत में रेलों के अग्रदूतों में प्रमुख ज्ञान चैपमैन ने निम्नलिखित टिप्पणी में भारतीय रेलों के उद्देश्य का समर्थन प्रस्तुत किया - 'राजमार्गों का अभाव दरिद्रता का अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट कारण है और रेलें भारतीयों को दरिद्रता से समृद्धि की ओर लाने का साधन हैं।'¹⁸ 1884 की मसौदीय प्रवर समिति ने इस तर्क पर रेलों के द्रुत विस्तार का समर्थन किया कि इससे देश को दुर्भिक्षों से रक्षण मिलेगा, बाहरी और भीतरी व्यापार को गति मिलेगी, उपजाऊ प्रदेश और कोयले की खानें खुलेगी और कुल मिलाकर जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।¹⁹ 1896 में गवर्नर जनरल लार्ड एलगिन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि रेलों का निर्माण कृषि पर निर्भर भारत की बहुमूल्य जनता की भौतिक स्थिति में एक निश्चित और निरंतर सुधार का साधन है।²⁰ उसने आशा प्रकट की कि भारत की महान रेल व्यवस्था को देश की जनता की भौतिक संपन्नता, सामाजिक प्रगति और राजनीतिक शांति का एक अत्यंत सशक्त अभिकरण बनाया जा सकता है।²¹

दूसरी ओर भारतीय नेताओं का निष्कर्ष सर्वथा विपरीत था। हां, उन्होंने रेलवे के वास्तविक और संभव निम्नलिखित प्रधान लाभों को दृष्टिगोचर अवश्य किया : सस्ती और द्रुत परिवहन की व्यवस्था, राष्ट्रीय मद्भाव और संगठन में प्रगति, नई मंडी का उद्घाटन, आजीविका के नवीन साधनों की सृष्टि, स्वदेश तथा विदेश व्यापार को प्रोत्साहन, दुर्भिक्षों का निरोध, कृषि फसलों के उत्पादन में गतिशीलता, उद्योगीकरण की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव, इंजिनियरिंग उद्योगों और कर्मशालाओं को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन और सामान्य रूप से देश के उद्यम का क्षेत्रविस्तार।²² परंतु उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के समान संभव और यथार्थ के अंतर को विवृत नहीं होने दिया। यह सत्य है कि रेल के प्रारंभिक वर्षों में और विरल रूप से कालांतर में भी कुछ भारतीय नेता रेलों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों से चूंधिया गए थे तथा रेलों के द्रुत विकास की मांग में ब्रिटिश नेताओं का हृदय से साथ देने लगे थे।²³ किंतु, जब उन्होंने वास्तविक लाभों की यथार्थ

परीक्षा की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ लाभों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था और कुछ रेलों के निर्माण से होने वाली हानियों के परिणामों से ही नामशेष हो गए थे।

1883 में दादाभाई नौरोजी ने शिकायत की कि भारत का दुर्भाग्य यह है कि अन्य प्रत्येक देश को रेलों से मिलने वाले लाभ इसे उपलब्ध नहीं। 1888 में जोशी महोदय ने टिप्पणी की कि राष्ट्र की औद्योगिक गतिविधि के विविध विकास के लिए रेलवे का अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ है। उन्होंने भारत जैसे देश में सामान्य गति से स्वस्थ भौतिक विकास की दिशा में बाधक बनने की रेनवे की प्रवृत्ति की निंदा की। 1897 में डी० ई० वाचा ने वेल्बी आयोग के समक्ष कहा : 'रेलवे से अर्थव्यवस्था तथा प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से जनता को कुछ हानियाँ ही पहुँची है।' 1898 में जी० एस० अय्यर ने बलपूर्वक कहा कि वर्तमान रेलवे नीति देश के लिए 'बहुमुखी रोग' सिद्ध हुई है। आर० सी० दत्त का विश्वास था कि कुल मिलाकर रेलवे के आर्थिक प्रभाव लाभप्रद नहीं थे। तिलक महोदय ने तो इनके विकास के समय ही अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहा था : रेल, तार और सड़क जैसे साधनों की भारत के लिए कोई उपयोगिता नहीं। वे तो एक प्रकार से 'दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने' के समान हैं। यहां तक कि जस्टिस रानडे का भी यही मत था कि रेलों ने भले ही और कितने लाभ पहुँचाएँ हों परंतु उन्होंने राष्ट्र की प्रगति को पंगु बनाने वाली निर्धनता रूपी विशेष दुर्बलता का कोई प्रतिकार नहीं किया।²¹ बहुत सारे भारतीय समाचारपत्रों ने इसी प्रकार के परंतु अत्यधिक उग्र समीक्षापरक विचार प्रकट किए। उदाहरणार्थ, 30 अप्रैल 1884 के अंक में महचर ने तीव्रता से लिखा : 'लौहपथों के विस्तार का अर्थ लौहबधन' है। 31 मई, 1891 के अंक में दैनिक-ओ-ममाचार चद्रिका ने घोषणा की कि 'रेलें देश को दरिद्रता के गर्त में धकेल रही हैं।' 29 जून 1903 के अंक में 'मदोवृत्त' ने अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए लिखा : 'रेलें देश के लिए 'वरदान के स्थान पर अभिशाप' ही सिद्ध हुई हैं। इन्दु प्रकाश ने अभियोग लगाते हुए लिखा : रेलों ने भारतीय समृद्धि को क्षति पहुँचाई है।'²²

राष्ट्रवादियों ने रेलों का घातक प्रभाव सर्वप्रथम औद्योगिक गतिविधि को पहुँची क्षति के रूप में ही देखा : भारतीय बड़े उद्योग के रूप में समकालीन औद्योगिक क्रांति के अभाव में परिवहन क्रांति ने भारत के वर्तमान भारवाहन उद्योग को विलुप्त कर दिया था। इंग्लैंड के सस्ते मशीनी उत्पादनों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री को प्रभावित करके इन उद्योगों का गला ही घोट दिया। भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बदले रेलों ने तो उसे गढ़े में ही धकेल दिया। भारत का धीरे धीरे ग्रामीकरण होता गया और वह धीरे धीरे ब्रिटेन की अन्न उगाने वाली बस्ती में बदल गया। 1884 में जी० वी० जोशी ने लार्ड डलहौजी और उसके उत्तराधिकारियों की उस रेलनीति पर शोक प्रकट किया जिसने आश्चर्यजनक रूप से थोड़े ही समय में देशी उद्योगों का सफाया कर दिया था और देश को दिवालियेपन और विनाश के कगार पर खड़े करके उसे चरम पतन की ओर उन्मुख कर दिया था।²³ जस्टिस रानडे भी वर्तमान रेलनीति

की निंदा में पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा : 'रेलों ने अनेक क्षेत्रों में भारत की यूरोप के साथ निराशाजनक प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी है और यूरोप के सामान को परिवहन की सुविधाएं इस हद तक जुटाई हैं जो किसी भी अन्य माधन में मभव नहीं थी। कुछ प्रमुख नगरों को छोड़कर रेलों ने स्थानीय देशी उद्योगों को नष्टभ्रष्ट ही कर दिया है और एकमात्र अवशिष्ट माधन—ऋषि पर लोगों का निर्भरता बढ़ा है—उन्हें पहले में भी अधिक अमहाय बना दिया है।' ¹¹ जी० एम्० अथर ने पूर्णतः जस्विता के साथ उद्योग किया इस देश में रेलपथ के प्रत्येक अतिरिक्त मील का निर्माण देश के किसी न किसी उद्योग के कफन में एक नया कीन है। ¹² और इसी ने जस्विता के साथ उन्होंने लिखा : रेलों को भारतीय जनता को उन्ने दुर्भाग्यग्रस्त बनाने वाली निर्धनता के फैलाने के लिए उत्तर देना ही पड़ेगा। ¹³ इसी प्रकार के विचार अन्य लोकनेताओं तथा भारतीय समाचारपत्रों ने भी प्रकट किए। ¹⁴

जी० वी० जोशी ने और गहराई में अनुभव किया कि वस्तुतः रेलों पर प्रतिभूत व्याज के सहायरी व्यय विदेश व्यापारी के लिए एक प्रकार के सहायक का ही कार्य करते थे। उन्होंने विराध प्रकट करने हुए कहा : इस प्रकार का भारत का विदेशी व्यापारी अथवा उसके देशवासियों से अनुग्रह राशि देने के रूप में उसे स्वदेशी उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता की सुविधा प्रदान करने के लिए विनियमित किया जा रहा है। ¹⁵ विदेशियों के साथ पहले में ही प्रतियोगिता में असमान भारतीय व्यापारी का इस विधि से तो और भी अधिक पगु बनाया जा रहा है।

कुछ भारतीय नेताओं का कथन था कि रेलपथ का निर्माण स्वदेशी उद्योगों के विनाश का एक अपरिहार्य प्रतिपाद नहीं है। इस औद्योगिक और परिवहन क्रांति का यह परिणाम अन्य देशों में नहीं हुआ है। रेलों ने सभी देशों में नए प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की प्रतिष्ठा चाहे की हो परन्तु भारत के विषय में इस दुःखद स्थिति का कारण यह है कि वहाँ रेलों ने उत्पादक गतिविधियों की रक्तवाहक धमनियों में रक्त संचार का कार्य नहीं किया क्योंकि उनका प्रदान उद्देश्य उन्ने इस कोयलाखानों में काम करने वालों, इस्पात और मशीनों निर्माण कार्य में मानव लाभों को काम जुटाना था न कि भारत में। स्वभावतः आन्तरिक मशीनों के विस्तार के सार आभे ब्रिटिश उत्पादकों को ही उपलब्ध हुए, भारतीय उत्पादकों को नहीं। ¹⁶ इसमें रेलों का विनाश भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और क्रमिक रूप से समझने करने हुए नहीं हुआ परन्तु घातक दुःप्रभावों की उपेक्षा करने हुए इस भारत पर आरोप दिया गया। इसपर क्षुब्ध होकर जी० एम्० अथर ने पूछा : 'क्या विनाश की प्रक्रिया का मद और क्रमिक नहीं बनाया जा सकता जिससे लोगों को सास लेने का समय तो प्राप्त हो सके।' ¹⁷

हा, नई पद्धति के कुछ एक उद्योगों, विशेषतः बागान उद्योगों, को रेलवे से संपन्नता अवश्य मिली परन्तु उसके अधिकांश लाभ भी विदेशी उद्योगियों ने डकार लिए। इस प्रकार का आर्थिक विकास निश्चित रूप से विदेशी पूँजी द्वारा देश का शोषण हो था। ¹⁸

रेलों का दूसरा हानिप्रद परिणाम था देश से धन की निकासी में बढ़ोतरी। भारतीय नेताओं का कथन था कि भारत की विचित्र राजनीतिक स्थिति के कारण रेलपथों का

निर्माण विदेशी पूंजी से किया गया है और उनका प्रशासन भी बहुत से विदेशी कर्मचारियों के हाथ में है। इसके फलस्वरूप भारत द्वारा ब्याजों और लाभों के, आयातित सामान के, यूरोपीय कर्मचारियों की सेवाओं के और इंग्लैंड में प्रबंध व्यवस्था पर होने वाले व्ययों के भुगतान के रूप में धन की विपुल राशि इंग्लैंड को भेजनी पड़ती है। ब्याजों के भुगतान की राशि भले रेल व्यय का एक स्वल्प भाग थी परंतु विदेशी धन से रेलों का निर्माण करने वाले सभी देशों को यह राशि सामान्य रूप से ही चुकानी पड़ रही थी। राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र अन्यान्य देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव नितान्त और स्पष्ट रूप से भिन्न था।³ धन की बढ़ती हुई निकासी ने रेलों के अन्यान्य लाभों को सर्वथा नष्ट भले ही न किया हो परंतु उन्हें बुधला अवश्य कर दिया था। यही कारण था कि दादाभाई नौरोजी ने 1876 में विस्मित होते हुए कहा था : यहाँ रेलों तथा दूसरे लोक कार्यों की व्यवस्था तो होनी चाहिए परंतु उनका स्वाभाविक लाभ हमें पहुंचना चाहिए अन्यथा एक भूखे व्यक्ति के सामने बढ़िया खाने के आनंद की चर्चा करना व्यर्थ है।³¹ जी० एम० अय्यर ने टिप्पणी करते हुए कहा : स्वतंत्र भारत रेल द्वारा प्रदत्त अन्य लाभों के बदले इस धन की निकासी को भी सहन कर लेता परंतु भारत को तो पहले से ही अन्यान्य मदों में लगभग तीन करोड़ पाँच विदेशों को देना पड़ता है। अतएव भारत रेलों द्वारा की जा रही धन की अतिरिक्त निकासी को किसी भी प्रकार सहन करने की स्थिति में नहीं है।³⁵

राष्ट्रवादियों द्वारा रेलों की एक अन्य कटु समीक्षा का कारण यह था कि रेलें अनाज के निर्यात को सुविधाजनक बनाकर देश में सामान्य काल में भी अनाज की अपर्याप्तता की स्थिति उत्पन्न कर रही थी तथा देश को अपने सामान्य अतिरिक्त अनाज में शून्य करके उसे प्रायः आने वाले दुर्भिक्षों का ग्रासण शिकार बना रही थी।³⁶ इस धारणा ने इतना अधिक व्यापक रूप ले लिया कि अंततः लांडे कर्जन को 1901-02 के वित्त प्रतिवेदन के समापन भाषण में इसका उत्तर देने को विवश होना पड़ा। उसने इन तर्कों को प्रथम स्तर का और सर्वथा निराधार एक भ्रम बताते हुए इस तथ्य को सर्वथा नकार दिया कि रेलों से अनाज के निर्यात में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है अथवा इस प्रकार की वृद्धि में रेलें किसी प्रकार से कारणभूत हैं। उनके विचारानुसार तो यह भी सत्य नहीं था कि भारत के कुल उत्पादन के एक बहुत बड़े भाग का निर्यात किया जाता था। उसका कथन था कि सत्य इसके विपरीत है। रेलों ने फालतू अन्न क्षेत्र से अभावग्रस्त क्षेत्र में अन्न पहुंचाने की, विदेशी बाजारों से अन्न के आयात को संभव बनाने की तथा इस प्रकार से दुर्भिक्षों की प्रचंडता को मंद करने की सामर्थ्य जुटाई है।³⁷ इस कथन के विरुद्ध भारतीयों ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की, रेलों के प्रधान समर्थकों ने ही यह दावा करना छोड़ दिया है कि रेलें दुर्भिक्षों को रोकने में समर्थ हैं। उनका कथन था कि आबातों तथा आंतरिक पुनर्वितरण रेलों के द्वारा दुर्भिक्षों की तीव्रता को मंद करने के दावे को भी 19वीं शती में पड़े तो दुर्भिक्षों के अनुभव ने झुठलाकर रख दिया है।³⁸ जी० एस० अय्यर ने तर्क दिया कि इन दुर्भिक्षों के समय बर्मा के सिबाय किसी भी अन्य देश से अनाज का आयात नहीं किया गया। इतना ही नहीं प्रत्युत उस अकाल की अवधि में भी अनाज के द्रुत निर्यातों द्वारा

क्षुद्र आतंरिक संभरण को और भी मंद कर दिया गया।³⁹ समस्या को एक अन्य दृष्टिकोण से परखते हुए 'बंगाली' ने 28 अप्रैल 1901 के अंक में तर्क प्रस्तुत किया : 'रेलों ने बाणिज्य फसलों के निर्यात को उत्तेजित करके अप्रत्यक्ष रूप से देश के खाद्य संभरण को क्षतिग्रस्त किया है क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषक खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों उपजाने लगे हैं।'।

राष्ट्रवादी नेताओं ने इस ओर भी निर्देश किया कि भारतीय रेलें व्यापारिक दृष्टि से भी सफल नहीं थी क्योंकि वे पिछली एक लंबी अवधि से विशेषतः 19वीं शताब्दी के अंत तक आत्मनिर्भर ही नहीं थी और घाटे की पूर्ति विदेशी निवेशकों के बदले भारतीय सरकार के रूप में भारतीय जनता द्वारा ही की जाती थी। उन्होंने बार बार और जोर देकर कहा कि भारतीय जनता की धीरे-धीरे दरिद्रता के संदर्भ में इन घाटों की बोझ असह्य रूप में भारी था और किसी भी रूप में रेलों से प्राप्त लाभों के समकक्ष नहीं था।⁴⁰ डी० ई० वाचा महोदय ने 1901 में कांग्रेस के सभापतीय अभिभाषण में रेलों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में प्रश्न उठाया कि 'क्या भारत जैसे किसी भी दरिद्रतम देश के लिए इन वार्षिक घाटों की विलासिता का जुटा पाना संभव है?'⁴¹

कुछेक भारतीय नेताओं ने यह भी देखा कि प्रचलित रेल नीति ने जहाँ सामान के आयात-निर्यात को निरंतर प्रोत्साहन दिया है, वहाँ देश के आतंरिक व्यापार और उद्योग के विकास के प्रति उपेक्षा ही नहीं दिखाई प्रत्युत उसपर प्रहार भी किया है।⁴² जी० एस० अय्यर महोदय 1898 में 'रेलें व्यापार का जीवन हैं, नारे की साख्यकी जाच करते हुए इस परिणाम पर पहुँचे कि 1891-2 से 1896-7 की अवधि में रेलों तथा नौकाओं द्वारा एक प्रात से दूसरे प्रात में ढोए गए माल की कुल मात्रा, पत्तनों के लिए ढोए गए सामान को छोड़कर, प्रतिवर्ष 130,451,000, से 167,65,640 मन के बीच थी; जबकि इसी अवधि में पत्तनों के लिए ढोए गए व्यापारिक माल की मात्रा 165,105,000 से 185,199,000 मन के बीच थी।⁴³ उन्होंने एक अन्य स्थान पर कहा कि यदि प्रशासन का उद्देश्य आतंरिक उद्योग का विकास करना होता तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही परिवहन साधनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता।⁴⁴ 1888 में आयात-निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली दर नीति की प्रवृत्ति पर जी० बी० जोशी ने अत्यंत विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि से गहरे विचार प्रकट किए। उन्होंने इस तथ्य की ओर देखा और इसकी तीखी आलोचना की कि भारतीय रेलपथों पर सामान ढुलाई की दर बहुत ही नीची है, यहाँ तक कि इंग्लैंड के दरों से और कितने ही अन्य यूरोपीय देशों के रेलों की दरों से नीची है। यही कारण है कि उससे सेवा प्रभार तथा व्याजों का भुगतान ही नहीं जुट पाता और प्रतिभूत प्रणाली के अंतर्गत सारा घाटा राजस्व से पूरा करना पड़ता है। उन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा, 'नीची दरों के कारण किए जाने वाले भुगतान विदेशी व्यापार के संवर्धन के लिए ही चालू रखे जा रहे हैं और यह वस्तुतः राज्य द्वारा विदेश को उसके व्यापार पर दिए जाने वाला उपहार ही है।' ⁴⁵ इन कुछेक कुशल निरीक्षकों को छोड़कर अन्य भारतीय नेताओं ने रेल समस्या के इस पक्ष की कुल मिलाकर उपेक्षा ही की। ⁴⁶ इसका एक प्रधान कारण यह था कि भारतीय उद्योग अभी रेलों की दर नीति को चुनौती देने में पर्याप्त सशक्त नहीं था। इसके अतिरिक्त

उनका विकास अधिकांश पत्तन नगरों में हो रहा था, जहां वे पत्तनों के हक में रेल दरों से सामान्य रूप से लाभान्वित हो सकते थे। इस प्रकार न तो राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी भी वर्ग ने किसी भी स्थिति में सामान्य दुलाई की दरों को सामान्य रूप से और विदेशों के निर्धारित किए जाने वाले कच्चे माल की दुलाई की दरों को विशेष रूप से घटाने का आग्रह किया और न ही देश के विकासशील व्यवसायी उद्यमी वर्ग ने इस प्रकार की कोई मांग प्रस्तुत की।⁴⁷

भारतीय नेताओं के अनुसार यदि सरकार ने उद्यम के क्षेत्र में एक सर्वथा नए उद्योग के रूप में आविर्भूत रेल उद्योग को समुचित समय पर भारतीयों द्वारा अपने हाथ में संभालने के लिए तथा प्रशासन में उन्हें अधिकाधिक भागीदार बनाने के लिए समुचित प्रबंध किए होते तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकृत करने वाले तथा पूंजी के भार से दबाने वाले रेल उद्योग के घूमिल चित्र में भी आशा की एक रजत किरण दिखाई देती, परंतु उनका यह स्पष्ट अनुभव था कि रेलों के निर्माण को प्रोत्साहन देने समय यह विचार विदेशी शासकों के मस्तिष्क में ही नहीं था। इसके विपरीत राज्य और रेल-कंपनियों दोनों ने भारतीयों को ऊंचे पदों और तकनीकी स्थानों से कोसों दूर रखा। इसी का परिणाम था कि आज सरकार के निरंतर पच्चीस वर्षों के दिशा निर्देशन के उपरांत भी देशवासी रेलपथ के निर्माण कार्य को अथवा रेल प्रबंध को संभालने में उतने ही अयोग्य थे, जितने उस समय थे जब लार्ड डलहौजी ने पहली बार भारत को रेलपथों के जाल में ढकने की योजना को स्वीकृति दी थी।⁴⁸

जी० बी० जोशी और जी० एम० अय्यर महानुभावों के अनुसार रेलों का एक राजनीतिक प्रभाव भी था जो अत्यंत घातक मिद्ध हो सकता था। जोशीजी के अनुसार राष्ट्र के हितों के लिए सर्वथा हानिकारक जमाखोरो का एक प्रबल विदेशी कुलीन तन्त्र अस्तित्व में आ रहा था। अय्यर महोदय के अनुसार : विदेशी रेल कंपनियां तो भारतीयों के हितों को आघात पहुंचाने वाले तथा पहले में ही अत्यधिक शक्तिशाली विदेशियों के निहित स्वार्थों में और अधिक वृद्धि ही करेंगी।⁴⁹

उस युग के किसी भी महत्वपूर्ण भारतीय विचारक की दृष्टि में न आग, हुग, रेलों के प्रभाव के कुछ पक्षों का यहां अध्ययन रोचक होगा। प्रथम, कृषि में व्यावसायिक क्रांति अर्थात् नकद उपजों की ज़ेतमीमा में विस्तार तथा स्थानीय उपजों में विशिष्टीकरण पर जो कदाचित् पूर्णतया न सही, आंशिक रूप से अवश्य ही रेलों की ही देन थी, किसी विचारक ने टिप्पणी नहीं की। दूसरे, यद्यपि कभी-कभी मूल्यों की समानता के तथ्य को अभिलिखित किया गया⁵⁰ तथापि रेलों द्वारा सारे देश में मूल्यों की समानता की कल्पना के अर्थशास्त्रीय महत्व को भी भुला ही दिया गया। अन्तिम, रेलों द्वारा भारतीय व्यापार और पूंजी के भारत के ग्रामों में पहुंचने के लिए जुटाए गए अवसरों की ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया और इसलिए इस क्रिमी ने अनुकूल विकास के रूप में स्वीकार नहीं किया।

यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जैसा कि अभियोग लगाया गया है सामाजिक रुढ़िवादिता के साथ साथ स्थिर, अप्रगतिशील अर्थव्यवस्था के आदर्श की दृष्टि से रेलों

और रेलों के भारत पर प्रभाव की भारतीय नेताओं द्वारा आलोचना नहीं की गई।⁵² रेलों के सभी भारतीय आलोचक न केवल आधुनिक उद्योगों के प्रबल पक्षधर थे प्रत्युत उनमें से अधिकांश प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। यह हम पूर्ववर्ती अध्याय में पहले ही दिखा चुके हैं कि लोकप्रिय समाचारपत्रों तक में जहाँ थोड़ी-बहुत रूढ़िवादिता छाई हुई थी वर्तमान समाजव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करने वाली के रूप में, रेलों की मामूली सी ही आलोचना की गई।⁵³

वस्तुतः भारतीय नेता रेलों के विरुद्ध कदापि न थे। वे तो उस विशेष समय में उसकी संचालन पद्धति के ही विरोधी थे।⁵⁴ भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलों के वास्तविक प्रभाव की जाच करने पर उन्हें यह विदित हुआ कि अधिकारियों द्वारा पहले से दिलाई गई आशाओं और अपेक्षाओं के विरुद्ध रेलें, पूर्ण वरदान नहीं थीं और भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलन पर उनका प्रभाव निषेधात्मक था। वे भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान पिछड़पन को जारी रखने वाली और उसे बढ़ाने वाली ही थी। रेलों से जो कुछ भी लाभ उपलब्ध हुए थे, वे मारे के मारे विदेशी व्यापारियों ने ही हड़प लिए थे। अतएव उनका यह निष्कर्ष था कि रेलें, जो मशकत सम्पृद्धिप्रद हो सकती थी, इस समय एक संकट बनी हुई थी। भारत के विकास पर पड़ने वाले आर्थिक भार के अनुरूप वे कदापि वांछनीय नहीं थी और जैसाकि हम आगे चलकर दिखाएंगे, भारतीय नेताओं की उस समय निश्चित धारणा थी कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना ही उद्देश्य है तो इन आर्थिक माधनो का रेलों के बदले और कहीं अच्छी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है।

ब्रिटिश उद्देश्य

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के इस निष्कर्ष से यह प्रासंगिक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी और लेखक रेलों के द्रुत निर्माण के लिए इतना अधिक दबाव क्यों डाल रहे हैं? भारत के शामक विरोध 1884 के उपरान्त और लार्ड एलगिन और लार्ड कर्जन की वायसरायी की अवधि में इस कार्य के लिए असाधारण रुचि और उत्साह क्यों दिखा रहे हैं? अथवा प्रश्न को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि रेलों का उद्देश्य किसके हितों की सेवा करना है? ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत यह विश्लेषण सहजता से भारतीयों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा था कि रेलपथों का निर्माण लोकसेवा के उद्देश्य से प्रेरित है। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता था कि उनके गासक भारतीयों के हितसाधन की भावना से ही इस कार्य में प्रवृत्त हुए हैं अथवा रेल निर्माण के पीछे भारत के आर्थिक विकास की सच्ची प्रेरणा ही काम कर रही है। वे इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि किन्हीं मामलों में रेलों के प्रति उत्साह अज्ञान और यूरोप की स्थितियों के साथ भारत की स्थितियों की गलत तुलना का परिणाम हो सकता है।⁵⁵ उनका निश्चित मत था कि ब्रिटेन के उद्देश्य वास्तव में ही कुल मिलाकर अत्यंत निम्नस्तर के कलुषित और स्वार्थपूर्ण थे। ये प्रयोजन अपने तात्त्विक रूप में उन ब्रिटिश व्यापारियों, उत्पादकों और निवेशकों के हितों की पूर्ति करते हैं जिनके निरंतर दबाव के अनर्गत भारतीय राजस्व के व्यय और खतरे के मूल्य पर

रेलों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है। रेलपथों का जाल बिछाने का वास्तविक उद्देश्य ब्रिटिश उद्यम तो भारत के प्राकृतिक साधनों के शोषण में सहायता देना ही है।¹⁵

भारतीयों के अनुसार भारत में रेल निर्माण को गतिशील बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण भारत के शासकों की यह इच्छा थी कि भारत के आचलिक प्रांतों में एक विस्तृत और वास्तव में अब तक न दोही गई एक ऐसी मही खोली जाए जो एक ओर ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादनों को खपाए और दूसरी ओर ब्रिटेन की भूखी मशीनों और प्राणियों के लिए क्रमशः कच्चे माल और खाद्यान्नों के निर्यातों की मुविधाएँ जुटाए। इस प्रकार भारत को ब्रिटेन में लिए कच्चे माल का मंभरण करने वाले कृषि उपनिवेशक के रूप में परिवर्तित करना ही भारत के शासकों की इच्छा थी।¹⁶

सरकारी रेल नीति के प्रवर्तन में विदेशी व्यापार की आधारभूत भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बहुत से भारतीय विचारकों ने इस नीति की संरचना में उनकी अपनी दृष्टि में उत्तरदायी अन्य अनेक दवावों और प्रयोजनों की भी चर्चा की। उनमें से एक इंग्लैंड के उष्ण उद्योग के सामान की, रेलवे भंडारों, लोहे की पटरियों, टंजिन, डिब्बे और दमरी मशीनें तथा सयंत्र के निर्यातों के द्वारा निकासी की व्यवस्था की आवश्यकता थी।¹⁷ रेलों के अग्रगण्य अंगरेजों को, निदेशक से लेकर टिकट वसूलने वाले तक के रूप में लाभप्रद नौकरियों की मुविधाएँ भी जुटाती थी।¹⁸ कुछ भारतीय नेना सही तौर पर यह समझने में भी सफल हो गए, यह समझ उनकी समकालीन आर्थिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ की परिचायक है, कि राज्य के स्वामित्व वाली तथा कंपनी के स्वामित्व वाली दोनों रेलें फालतू ब्रिटिश पूँजी के सुरक्षित और लाभप्रद निवेश के स्रोत का कार्य करने का उद्देश्य लिए हुए हैं और इस दिशा में प्रवृत्त भी हैं। इस संबंध में कुछ विचारकों की इस समझ की भी मूलक मिलती है कि रेलें भारत पर विदेशी शासकों के राजनीतिक प्रभुत्व को मुदृढ़ बनाने का ही आधार थी।

सरकारी नीति के उद्देश्यों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण को जी० एस० अय्यर महोदय ने 1898 में बड़ी सफलतापूर्वक संक्षेपतः निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया :

इंग्लैंड के निवेशक, कंपनी के उन्नायक, धनकुबेर, लोहाधिपति, कोयला स्वामी, रेलवे इंजीनियर और निदेशक तथा इन सबसे बढचढकर अपनी पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की इच्छा रखने वाले सेवानिवृत्त एंग्लो भारतीय कर्मचारी, सबके सब भारत में रेलों के निर्माण को द्रुतगति देने में रुचि रखते हैं। वे यूरोपीय व्यापारी भी जिनके हाथ में भारत का सारा विदेश व्यापार है और जिनका व्यापार अब पूरे के तट-वर्ती नगरों तक सीमित न रहकर भारत के ग्राम प्रांतों में फैलने जा रहा है, समान रूप में भारतभूमि में रेलों के जाल के प्रसार के लिए उत्सुक हैं।¹⁹

बहुत सारे भारतीयों ने अनुभव किया कि यह सारी दुःखद स्थिति अत्यंत क्षोभप्रद है। जानी थी जब भारतीयों के हितों की बलि चढ़ाकर रेलों के सारे लाभ इंग्लैंड उठाता था और उनके भार को भारत उठाता था।²⁰ इससे यह विचित्र प्रक्रिया देखने में आई कि 'वैतुक दायित्व' के नाम पर ब्रिटिश शासक उस देश की सहायता कर रहे थे जिसे कम से

कम भारत की महान दुर्भाग्यग्रस्त निर्भरता को भी शक्तिहीन करने के मूल्य पर, उसकी आवश्यकता कदापि नहीं थी।⁶⁴

भारतीय कसौटी

भारत सरकार की रेल नीति को ब्रिटेन की आवश्यकताओं में प्रेरित सिद्ध करने के उपरांत कुछ भारतीय नेताओं ने रेल विकास की गति और इस महत् कार्य की प्राथमिकता के निर्धारण के लिए अपनी एक कसौटी निश्चित की आवश्यकता अनुभव की। इस समस्या पर उनका विचारविमर्श न केवल उनकी परिवहन नीति पर और उनके विचारानुरूप देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, प्रत्युत स्वयं उनके दृष्टिकोण के आर्थिक विकास की रूपरेखा को भी उजागर करता है।

सर्वप्रथम, उनका सर्वथा उपयुक्त और सुदृढ़ तर्क था कि रेलों को भारत की वर्तमान विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान के सदृश में ही देखना चाहिए।⁶⁵

द्वितीय, उनका मतव्य था कि परिवहन और उद्योग में उद्योग का महत्त्व प्राथमिक और परिवहन का महत्त्व गौण है क्योंकि किसी भी उपयुक्त रूप से देखें तो आर्थिक विकास का आधार उद्योगीकरण है। जी० वी० जोगी ने 1884 में लिखा औद्योगिक प्रगति अतत आवश्यक रूप में उत्पादन वृद्धि पर निर्भर है न कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुविधाओं की वृद्धि पर। वस्तुतः उद्योगों का एक सामान्य समन्वय... राष्ट्र की समृद्धि का जीवन रक्त है।⁶⁶ इसी तथ्य की सबल पुष्टि में बंबई के नेटिव ओपीनियन ने 25 मई 1884 के एक मनेज प्रवक्ता समिति की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखा

हमारी वित्त संपत्ति में भारत में रेल प्रसार के विषय से संबंधित वर्तमान समिति की अपेक्षा विभिन्न उद्योगों के प्रारंभ की योजना की परिकल्पना के लिए एक आयोग की स्थापना अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगी।... इस दिशा में विकास का अर्थ हमारे साधनों का समुचित रूप में विकास नहीं है।

जी० एन० अग्रर ने भी इस विषय पर बल देकर कहा

सरकारी राजस्व धन-संपत्ति के उत्पादन के सवर्धन पर खर्च न होकर केवल सामान को एक स्थान में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। यह एक स्पष्ट बात है कि जो थोड़ी सी संपत्ति पहले से ही किंचितमान है उसको इधर-उधर करने की अपेक्षा नई संपत्ति के उत्पादन का लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है।⁶⁷

इसके अतिरिक्त रेलों की अपने आप में उपयोगिता देश की उत्पादन शक्ति पर निर्भर है,⁶⁸ अर्थात् राष्ट्रीय आर्थिकता और उद्योग द्वारा उनके उपयोग की क्षमता पर आश्रित है। जब तक रेलें राष्ट्रीय उद्योगों के अपेक्षाकृत अच्छे संगठन के लिए लाभप्रद अन्य अधिक महत्वपूर्ण साधनों को साथ नहीं ले पाती तब तक वे अकेले उस देश की प्रबल शक्ति में योग नहीं दे सकती, जो अकेले ही उनकी व्यापक महत्ता की सुदृढ़ आधारशिला की व्यवस्था करता है।⁶⁹ जब और ज्यों ही देश का उद्योगीकरण हो जाएगा तब अधिकाधिक रेलें भी बनाई जा सकेंगी। परंतु इस समय जबकि देश कृषिप्रधान है, तेज गति से

रेलपथों का निर्माण सर्वथा निरर्थक ही है।⁷⁰ इसके विपरीत यदि रेलों के साथ साथ भारत के उद्योग और व्यापार का विकास होता तो रेलों का विकास स्वस्थ और लाभप्रद भी होता और जन समर्थन का अधिकारी बनता।⁷¹ उदाहरणार्थ 30 अप्रैल 1884 के अदालत के संहार ने लिखा

पहले से बने रेलों के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात को पाना आवश्यक है परन्तु यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि देश के निजी उद्योगों का विकास नहीं होता।...

पहले इस देश में कपड़े की मिलें, लोहे की ढलाई के कारखाने और इस प्रकार अन्य औद्योगिक प्रयत्नों की स्थापना होने दी जाए, तब देखिए रेलें कच्चे माल और पक्के उत्पादनों के वाहन व्यवसाय को किस प्रकार लाभप्रद बनाती हैं।⁷²

परन्तु पर्याप्त विश्वास के साथ आशा किए जाने पर भी वास्तव में ऐसा कुछ न हुआ।⁷³ भारतीयों ने सोचा कि रेलें अपने आप न तो उद्योगों को जन्म दे सकती हैं और न ही देश की आर्थिकता के विकास को जन्म दे सकती हैं।⁷⁴ इसके लिए तो कुछ और परिस्थितियाँ भी अपेक्षित थीं। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने यह देखा कि उनका अनुभव अमरीका के अनुभव से सर्वथा भिन्न रहा है। वहाँ तो औद्योगिक क्रांति को आगे ले जाने में रेलें सहायक रही हैं।⁷⁵ इसके विपरीत भारत में रेलों ने औद्योगिक आंदोलन का उदात्त बनाने में भारत के प्राकृतिक साधनों के शोषण तथा विदेशी व्यापार और उद्यम को प्राप्ति देने में सहायता दी है। वाणिज्य की शक्ति ने औद्योगिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक क्रांति का ही प्रवर्तन किया है।⁷⁶ रेलों ने यहाँ तो सामान्य पथों पर स्वस्थ भौतिक प्रगति का अवरोध करके तथा राष्ट्रीय गतिविधि को उसके अपने ही केंद्र में अस्तव्यस्त करके आधुनिक उद्योग के विकास में बाधा पहुँचाई है।⁷⁷

इस सबका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि द्रुत औद्योगिक विकास के बिना रेलों के विकास की चर्चा एक प्रकार से पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थी अथवा जी० वी० जोशी के शब्दों में 'इस देश में देश के आर्थिक साधनों के बाहर अमरीका की गति पर रेलों को आगे बढ़ाने की मुस्पष्ट नीति यदि अपने साथ अपेक्षाकृत अधिक महत्व के अन्य आर्थिक उपायों को नहीं अपनाती तो राष्ट्र की दरिद्रता के रूप में ही उभरती अतः होगी।'⁷⁸

अनिम, भारतीय नेताओं ने बताया कि भारत के साधन अत्यंत सीमित हैं और उनमें अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में कार्य नहीं किया जा सकता, और क्षुद्र साधनों के कारण अनेक क्षेत्रों में हमें चनाब करना है। भारतीय लोकनायकों के मन में मदह का लेश भी नहीं था कि औद्योगिक पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था का विषम पाप है और उद्योग को परिवर्द्धन पर प्रमुखता अवश्य ही मिलनी चाहिए।⁷⁹ उन्होंने इसलिए सरकार से फिनहॉल रेलों को दी जाने वाली राजकीय सहायता को अधिक उत्पादक प्रयासों, उद्योग और मिर्चाई की ओर दिशा परिवर्तन की मांग की।⁸⁰

उन्होंने औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ रेलों के सुसंगत समन्वयन के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिसंधानों को भी प्रस्तुत किया। वे चाहते थे कि रेलों के निर्माण की गति तथा कार्यक्षेत्र के निर्णय में उन अभिसंधानों को समुचित महत्व दिया जाए। इस प्रकार

का निर्धारक और सीमक तत्व था भारतीय वित्त की बिपन्न अवस्था और करदाता पर पहले से ही भारी बोझ। व्यापक दृष्टि से उनका मंतव्य था कि रेलों के निर्माण में अपनाई जा रही द्रुतगति की दर के औचित्य को मिट्ट करने के लिए न तो भारत पर्याप्त धन-संपन्न था, न उसके साधन पर्याप्त विस्तृत थे और न ही उसके वित्त पर्याप्त समृद्ध थे।⁸¹ उनके विश्वासानुसार दूसरी विचारणीय बात यह है कि रेल निर्माण को प्रधानतया उपलब्ध स्वदेशी पूँजी पर ही निर्भर रखना चाहिए।⁸² रेलों के विस्तार कार्य के लिए स्टर्लिंग ऋण में और अधिक वृद्धि किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे केवल भारत में धन की निकासी में ही वृद्धि होगी।⁸³

भारतीय नेताओं के अनुसार वर्तमान स्थिति में शोचनीय तथा सतर्कता की अपेक्षा करने वाला एक अन्य तत्व यह था कि अधिकतर प्रारंभिक रेलों की पटरियों के लिए भारत को अनुबंधित और निश्चित एक शिलिंग दस पेंस के लिए एक रुपया विनिमय दर पर प्रतिभूत व्याजों के मुग़तान के लिए इंग्लैंड को रुपया भेजने में विनिमय पर होने वाला भारी घाटा था तथा रेलों पर लिए गए ऋणों पर व्याज के पौंडों में मुग़तान के लिए राज्य रेलवे ने लंदन के वित्त बजार में उस समय अनुबंध किया था जब पौंड के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत निरंतर घट रही थी।⁸⁴

बहुत सारे भारतीयों का यह भी मत था कि नई रेल लाइनों की स्वीकृति से पूर्व यह सम्यक रूप से देखभाल कर निश्चित कर लेना चाहिए कि वे आर्थिक रूप से कहा तक लाभप्रद हो सकती हैं।⁸⁵ उनकी यह युक्तियुक्त धारणा थी कि बहुत सारे रेलपथ आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हैं। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर ब्रिटिश पूँजीपति प्रतिभूति बिना पाए ही क्या नहीं इन रेलपथों के निर्माण को हाथ में लेते? ⁸⁶

कुछेक का तो यहाँ तक मत था कि रेलों की कितनी ही विशेषताएँ क्यों न हो आर्थिक राजनीतिक, सैनिक तथा अकाल सुरक्षा आदि उद्देश्यों के लिए आवश्यक जितने रेलपथ बनने थे, पहले ही बन चुके हैं। अब तो सरकार को अपना सारा ध्यान सष्ट के पुनर्निर्माण के अन्यान्य क्षेत्रों की ओर देना चाहिए। नए रेलपथों के निर्माण में तो तभी हाथ लगाना चाहिए जब उपर्युक्त सभी दूररे पक्ष अनुकूल हों।⁸⁷

भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय वित्त की स्थिति, स्वदेशी पूँजी की अप्राप्यता, वर्तमान और निर्माणाधीन रेलों का लाभप्रद न होना, भारतीय उद्योग के साथ रेलों के समन्वय की आवश्यकता और साथ ही विविध आर्थिक पक्षों और शक्तियों के बदलते सहसंबंधों के कारण रेलपथों के कुछ विस्तार की अपरिहार्यता की समझ इन सभी पक्षों पर सामूहिक रूप से विचार करने के उपरान्त 1884 के⁸⁸ पश्चात् यह अनुभव करने लगे कि यद्यपि रेलों के द्रुत विकास की अथवा उनके अधाधुन विकास की आवश्यकता तो नहीं है फिर भी आवश्यकता के अनुरूप उचित समय पर रेलें बनाई जा सकती हैं परंतु इस दिशा में सरकारी तौर पर जिस गति की बकालत की जाती है उसकी अपेक्षा अत्यधिक मंद गति ही अपनाने की आवश्यकता है।⁸⁹ कइयों ने तो इसमें यह बात भी जोड़ी कि सरकार रेलपथों के और अधिक विस्तार का दायित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से लोक वित्तों पर न डाले।⁹⁰ सभी भावी पथों का निर्माण विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से हो

अर्थात् राज्य को स्वयं न तो किसी प्रकार से भागीदार बनना चाहिए और न ही राज्य के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति दी जानी चाहिए। निजी कंपनियों को स्वयं ही खतरा उठाकर यह कार्य करना चाहिए।⁹¹

इस संदर्भ में 1898 में फोर्लर आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हुए आर० सी दत्त महोदय ने एक अद्भुत सुझाव दिया कि 'नई रेलों की स्वीकृति से पूर्व लोक प्रतिनिधियों से परामर्श कर लेना चाहिए।' एक अन्य स्थल पर उन्होंने जोर देकर कहा 'रेल नीति के संबंध में सरकार लोकहितों की बलि चढ़ा रही है, इसका कारण यह है कि प्रभावशाली वर्गों के मुकाबले बेचारी जनता को अपना मत अभिव्यक्त करने तथा उसे मनवाने का सांविधानिक अधिकार ही प्राप्त नहीं है।'⁹²

संगठन का स्वरूप

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने रेलों के निर्माण की गति के संबंध में विस्तृत विवेचन के अतिरिक्त रेलों के संगठन के स्वरूप पर भी ध्यान दिया, परंतु उन्होंने इस संबंध में समझा के केवल एक पक्ष अर्थात् रेलों के निर्माण और प्रबंध के लिए उपयुक्त अभिकरण की ओर ही ध्यान दिया। इस संबंध में यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय नेता विशेषतः 1884 के उपरांत, रेलों के द्रुत विस्तार के विरुद्ध थे, अतः उनका मारा क्रोध इसी एक पक्ष पर केंद्रित रहा। फलतः रेल निर्माण के अन्यान्य पक्षों पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति विरल तथा विकीर्ण ही रही। सभी प्रश्नों का उत्तर वे यह कहकर देते थे कि हमें रेलों की कोई आवश्यकता नहीं।

लार्ड रिपन के वायसराय काल में उस समय भारतीय जनता की दृष्टि से रेल के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष राज्य अभिकरण के और निजी कंपनियों के सापेक्ष लाभों का प्रश्न सामयिक विवेचन का विषय बन गया, जब वायसराय के वित्त सदस्य इवेनिन वैरिंग ने 1881 में निजी निर्माण के पक्ष में सरकारी एकाधिकार के आंशिक परित्याग, अर्थात् सरकारी सहायता के बिना अथवा किसी भी स्थिति में इस प्रकार की न्यूनतम सहायता की बकालत की। बाद में 1883 में भारत सरकार ने योजना बनाई कि उत्पादक रेल पथ निजी कंपनियों की पट्टे पर दे दिए जाएं और सामान्य मिट्टात के रूप में सरकार व्यावसायिक दृष्टि से अलाभप्रद होने के कारण से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से निजी कंपनियों द्वारा न किए जा सकने वाले रेलपथों का निर्माणकार्य ही करे।⁹³ परवर्ती वर्षों में इस नीति पर व्यापक रूप से अमल किया गया और उत्तराधिकारी राज्यसचिवों, गवर्नर जनरलों तथा राबर्टसन जैसे रेल अधिकारियों द्वारा इसका अनुमोदन और प्रगमन किया गया।

दूसरी ओर रेलों के विकास से संबंधित तथा सभी भारतीयों को समान रूप में मान्य प्रश्न या प्रतिभूति प्रश्न से भारत को पहुंचने वाली हानि। उनकी दृष्टि में इससे राष्ट्रीय वित्तों पर असह्य भार पड़ता था, अतः भविष्य में इसे जारी न रखने की प्रबल और अपरिहार्य आवश्यकता थी।⁹⁴ भारतीयों के मत में इस प्रतिभूति का अत्यंत आपत्तिजनक पक्ष यह था कि इससे कंपनी को अविवेकपूर्ण और परिणामहीन फिजूल खर्च के लिए

प्रोत्साहन मिलता था। कंपनी के पास मितव्ययी होने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं थी क्योंकि वह जितना भी व्यय कर ले, सरकार उसपर प्रतिभूत व्याज राशि देने को प्रस्तुत थी। उल्लेखनीय यह है कि यह उस समय था जबकि व्याज राशि से अधिक उपार्जन की कोई सभावना ही नहीं थी।⁹⁵ जुलाई 1881 में पूना की 'सार्वजनिक सभा' पत्रिका में अज्ञातनाम लेखक के प्रकाशित एक लेख, 'पालियामेंटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक वर्क्स' में जस्टिस रानाडे ने रेल प्रतिभूति के विरुद्ध भारतीय चिंतन को बड़े ही रोचक और सक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया

व्याज की प्रतिभूति निर्धारित दर बहुत ऊँची होने के कारण (इंग्लैंड में पूंजी पर मिलने वाले लाभों से बहुत ही ऊँची) यह पाया गया है कि कंपनियाँ रेलों के निर्माण में अथवा निर्माण के उपरान्त उनके प्रबंध में पर्याप्त रूप से मितव्ययी नहीं हैं। उनका दृष्टि वस्तुतः इसी में था कि वे यथामभव व्यय की राशि का अंक ऊँचा रखें क्योंकि जितना अधिक धन वे लगा पाएंगी, उतनी अधिक ही प्रतिभूति व्याजराशि को पाने की वे अधिकारी होगी।⁹⁶

जब एक बार रेलों की प्रतिभूति प्रथा को समाप्त कर दिया गया और यह तथ्य भी स्वीकार कर लिया गया कि कुछ नवीन रेलपथों का निर्माण अपरिहार्य था, तो प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि निर्माण के लिए क्या विकल्प व्यवस्था अपनाई जाए। राष्ट्रवादी इस विषय में एकमत नहीं थे। एक वर्ग की मान्यता थी कि कर्दनाओं पर और अधिक भार न डालने की दृष्टि से सरकार को रेलपथों पर जनकोशों का व्यय नहीं करना चाहिए तथा नए निर्माण का सारा क्षेत्र वास्तविक अप्रतिभूत निजी उद्यम पर छोड़ देना चाहिए।⁹⁷ दूसरा, और कदाचित अधिक मुखर तथा दूसरे पक्ष से भी मबधित वर्ग जिसके घनगत जी० बी० जोशी तथा अन्य महानुभाव सम्मिलित थे। निजी स्वामित्व का विरोधी तथा सरकारी उद्यम का समर्थक था। दूसरे वर्ग के पक्षधरों द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत कारणों की समीक्षा में पूर्व हम यहां यह बताना चाहेंगे कि प्रथम मत के पक्षधरों ने भी उन्हीं कारणों के आधार पर यह मांग की थी कि सरकार को उपयुक्त समय पर कंपनियों के साथ किए गए समझौतों और निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रतिभूत रेलों को खरीदने के अधिकार अपने हाथ में रखने चाहिए।⁹⁸ इसके अतिरिक्त वे सरकार द्वारा निमित्त अथवा अधिकृत रेलों के संचालन के लिए कंपनियों को पट्टे पर दिए जाने के विरुद्ध थे।⁹⁹

राज्य रेलपद्धति के पक्षधर नेताओं का विश्वास था कि इस समय वास्तविक चुनाव यथार्थ निजी उद्यम तथा सरकारी उद्यम का न होकर सरकारी उद्यम और प्रतिभूत कंपनियों को पुरानी प्रथा का है और इन दोनों में सरकारी उद्यम निश्चित रूप से अधिक अच्छा और अधिक मितव्ययी था।¹⁰⁰ उनका तर्क था कि विदेशियों की निजी कंपनियों से देश के सामान्य हितों के संरक्षण के लिए पूर्ण दायित्व तथा उद्देश्य की समग्र एकता से कार्य करने की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती क्योंकि कभी कभी तो लोकहितों के लिए निजी हितों की बलि ही चढ़ानी पड़ती है।¹⁰¹ उनकी मान्यता थी कि वित्तीय दृष्टि से प्रतिभूत रेलप्रथा की अपेक्षा राज्य रेलों से अधिक लाभ थे क्योंकि सरकार को अच्छी साख के कारण अधिक ऋण मिल सकते थे। सरकार सदैव व्याज की कम दर पर ऋण लेने में समर्थ थी और

अतीत में कहीं भी सूद की दर इतनी ऊंची नहीं रही जितनी कि 5 प्रतिशत प्रतिभूत।¹⁰² इसके अतिरिक्त ऋण ली गई पूँजी पर ब्याज चुकाने के उपरांत राज्य रेल के अवशिष्ट लाभ भी देश में ही रहेंगे न कि निजी उद्यमियों के हाथ में पड़कर विदेशों को भेजे जाएंगे।¹⁰³ 3 फरवरी 1884 के अंक में मराठा ने तो सुभाव दिया कि राज्य ऋणों पर ब्याज और 5 प्रतिशत प्रतिभूत ब्याज के अंतर का उपयोग मूल ऋण को चुकाने में करने पर लाभराशि और ब्याज राशि दोनों को देश में ही रखा जा सकता था।¹⁰⁴

जी० बी० जोशी महोदय के अनुसार राज्य रेल व्यवस्था केवल निषेधात्मक रूप में ही सही, राजनीतिक दृष्टि से लाभप्रद थी। 'यह भारतीयों हितों के विरोधी सशक्त विदेशी निहित स्वार्थों के विकास को अवरुद्ध करेगी'¹⁰⁵ बंगला साप्ताहिक 'सहचर' ने अपने 30 अप्रैल 1884 के अंक में भारतीय रेलवे पर एक विस्तृत समीक्षात्मक लेख के अंत में इस दृष्टिकोण को अत्यंत जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया :

क्या इन तथ्यों की दृष्टि में यह उचित है कि असंख्य रेलपथों का निर्माण किया जाए और जनता को रेल कंपनियों के हाथ में दास बनने के लिए विवश किया जाए ? क्या सरकार भारत को दूसरा मिस्र बनाना चाहती है ? इसके बाद केवल सरकार को रेलों का निर्माण करना चाहिए।¹⁰⁶

इस वर्ग के भारतीय नेताओं की निजी उद्यम के विरुद्ध गंभीरतम आपत्ति यह थी कि उसका चरित्र विदेशी था और वह इसके फलस्वरूप लाभों का निर्यात करता था। उनमें से बहुतों ने बार बार बल देकर कहा कि यदि विशुद्ध भारतीय कंपनी बनाई जाए तो निजी उद्यम का बांछनीय रूप से स्वागत होगा।¹⁰⁷ सचमुच ही इस पक्ष के नेताओं ने तथा प्रथम विचारधारा के समर्थक अनेकानेक नेताओं ने रेल-निर्माण के सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भारतीय पूँजी और उद्यम के विनियोजन के पक्ष में अपना स्वर मुखरित किया।¹⁰⁸ उदाहरणार्थ 'मराठा' ने 14 जनवरी 1883 के अंक में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें मांग की गई थी कि अब सरकार की नीति भारत में स्वदेशी प्रबोध, स्वदेशी पूँजी, भ्रष्ट और श्रम साधनों से रेलों के निर्माण की होनी चाहिए। 7 दिसंबर 1902 के अंक में पत्र ने मांग की कि यदि रेलों का निर्माण अवश्य करना ही है तो वह यथासंभव भारतीय पूँजी से ही करना चाहिए। रेलों में स्वदेशी पूँजी के लगभग शून्य निवेश पर दुःख प्रकट करते हुए, समाचारपत्रों ने भारतीय जनता, विशेष रूप से पूँजीपतियों को रेलों के निर्माण के लिए निजी कंपनियां चालू करने के हेतु धन जुटाने को प्रबोधित किया।¹⁰⁹ उन्होंने सरकार पर भारतीय पूँजी को आकृष्ट न करने का अभियोग लगाते हुए उससे भारतीय कंपनियों के प्रति भारतीय पूँजी लगाने के लिए विशेष व्यवहार करने का अनुरोध किया।¹¹⁰ यह अत्यंत रोचक तथ्य है कि 'हिंदू' ने जहां अपने 10 अगस्त 1887 के अंक में प्रतिभूति प्रथा को व्यर्थ बताते हुए उसकी निंदा की, वहां 3 अगस्त 1887 के अंक में भारतीय उद्यमियों के लिए प्रतिभूति की मांग करने में सकोच नहीं किया। कुछ नेताओं ने यह भी अनुमोदन किया कि विशुद्ध भारतीय पूँजी के सामर्थ्य के अनुरूप ही रेलपथों के निर्माण की गति को मंद बनाना चाहिए।¹¹¹

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि सर्वोत्कृष्ट इच्छाओं के बावजूद

भारत में रेल निर्माण के लिए पर्याप्त पूंजीगत विशाल साधनों वाली निजी कंपनियों की स्थापना संभव नहीं थी, अतः उन्होंने राज्य एकाधिकार व्यवस्था का ही समर्थन किया।¹¹² अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 5 मार्च 1885 के अंक में लिखा 'भारत जैसे देश में, जहाँ के लोग इतने अधिक निर्धन हैं, इतने अधिक अनुत्साही हैं कि वे अपनी पूंजी से रेलों का प्रबंध नहीं सभाल सकते, विदेशियों द्वारा देश को निर्धन बनाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि सरकार स्वयं व्यापारी की भूमिका निभाए तथा लाभों का अर्जन करे।' सरकार द्वारा रेलों के निर्माण और संचालन में एक महत्वपूर्ण सभ्य आपत्ति यह थी कि उससे अत्यधिक केंद्रीकरण तथा अनियंत्रित अफसरशाही आ जाती है। इस बुराई का जी० वी० जोशी द्वारा सुझाया हुआ उपचार था रेल प्रबंधों का विकेंद्रीकरण तथा विभिन्न प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों के हाथ में रेलों के प्रारंभ तथा प्रबंध के अधिकार सौंपना।¹¹³ 'मराठा' ने 3 फरवरी 1884 के अंक में रेलों के संचालन के लिए लोक-मर्मितियों और न्यासों के संगठन का परामर्श दिया। 'हिंदुस्तान रिव्यू' और 'कायस्थ समाचार' पत्रों ने अपने अपने मई 1903 के अंक में सुझाव दिया कि सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति के रूप में रेल प्रबंध के लिए एक रेल न्यास (रेलवे ट्रस्ट) बनाया जाना चाहिए।

रेलें बनाम सिचाई

इस समय भारतीय नेताओं के सिचाई के प्रति दृष्टिकोण पर विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि इस समय रेलों और सिचाई का पारस्परिक संबंध स्पष्ट नहीं है परंतु विवक्षितकाल की अवधि में दोनों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध था।¹¹⁴ भारतीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों दोनों ने रेलों और सिचाई को परस्पर विरोधी तत्व के रूप में ग्रहण किया। दोनों ने भारत में पड़ने वाला अकाली की अत्यंत उपयोगी औषधि के रूप में अपने अपने पक्ष (रेल तथा सिचाई) को प्रस्तुत किया तथा राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के अपने पक्ष में विनिधान के लिए मुकाबला किया।

1902-03 के अंत तक छोटे-बड़े सिचाई कार्यों पर सरकारी राजस्व का कुल व्यय लगभग 43 करोड़ रुपए था जबकि इसके विरुद्ध राज्य का और कंपनियों का रेलों पर प्रतिभूत कुल व्यय 30 जून 1905 तक 359 करोड़ रुपए था।¹¹⁵ इस तथ्य पर भारतीय नेताओं ने उचित ध्यान दिया और इसकी आलोचना की, फिर चाहे इस संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन दौर में शुरू हुआ था। परंतु उसने प्रचंड रूप 1897 के भयंकर अकाल की अवधि में और उसके पश्चात् ही धारण किया। आमतौर पर भारतीय नेताओं ने सिचाई के मूल्य पर रेलों के प्रति अनुचित पक्षपात के लिए सरकार की भर्त्सना की। उनकी यह स्पष्ट घोषणा थी कि इसे चहेती के रूप में लेते हुए सिचाई के साथ सौतेली मां वाला बर्ताव किया जा रहा था। 1898 में आर० एम० ग्यानी ने वायसरॉय की विधान परिषद में यह प्रश्न उठाया और शिकायत की कि जबकि रेलों पर सरकारी अनुग्रह के रूप में बहुत खर्च होता है, वहां अकालों से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा देने वाली सिचाई नहरों पर केवल 75 लाख रुपए की अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्दों में रेलों पर व्यय किए जाने

वाली राशि का लगभग तेरहवा भाग प्रतिवर्ष सिंचाई पर खर्च किया जाता है।¹¹⁷ इस विषय पर आर० सी० दत्त सरकार के तीव्रतम आलोचक थे। 1903 में उन्होंने लिखा कि जब हम रेलों से सिंचाई कार्य के विषय की ओर आते हैं तो एक ओर हमें मूल्यतापूर्ण फिजूलखर्ची मिलती है और दूसरी ओर उतनी ही मूल्यतापूर्ण कजूसी।¹¹⁸ इसी प्रकार की समालोचना अन्य अनेक समकालीन जन नेताओं और पत्रकारों ने भी की।¹¹⁹

सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के विरुद्ध भारतीय नेताओं का तर्क था कि वास्तविक जनहित की दृष्टि में : अधिक रेलों की अपेक्षा सिंचाई कार्यों की ही अधिक उपयोगिता है। 'मराठा' ने अपने 17 फरवरी 1884 के अंक में बल देते हुए कहा कि जहाँ वाणिज्य सदन का हित इसी में है कि वह रेलों के भंडे के नीचे ही अर्थात् रेलों के निम्न संघर्ष करे, वहाँ हमारा हित इसी में है कि हम नहरों के लिए संघर्ष करें। केसर ए हिंद ने 23 अगस्त 1903 के अंक में चालू एक सवा एक करोड़ रुपये की तुच्छ राशि के स्थान पर चार पाँच करोड़ रुपये की राशि सिंचाई कार्यों पर खर्च करने की वकालत करते हुए भारतीय दृष्टिकोण को इन शब्दों में प्रखर अभिव्यक्ति दी

निस्संदेह यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि नए रेल निर्माण पर भारत सरकार को प्रतिवर्ष पाँच-छ करोड़ की न्यूनतम राशि खर्च करनी पड़ती है और इस स्थिति में वह सिंचाई कार्यों के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं जुटा सकती। इस तर्क को स्वीकार करते हुए हमारा कथन यह है कि अब समय की मांग यह है कि रेलों के निर्माण की गति भद्र स्तर पर लानी चाहिए। अतः हमने वर्तमान भयंकर अकालों की अवधि में जो महंगा अनुभव प्राप्त किया है, और अनेक लाखों मनुष्यों और कृषि पशुओं का जो भयंकर विनाश हुआ है, क्या सरकार इन सबको देखते हुए भी स्वार्थी वाणिज्य सदन को प्रसन्न करने के लिए उन लाखों स्वदेशी लोगों के हितों की जो आज भी पूरे-पूरे माल अपर्याप्त भोजन पर जीवन निर्वाह का विवश हैं अपेक्षा करते हुए रेल निर्माण के द्रुतविकास की नीति को अपनाएंगी और सिंचाई की योजना की परिधि को संकुचित करेंगी। जबकि यह निश्चित है कि उसमें ही देश के सारे असुरक्षित क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है।¹²¹

कुछ भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि भारतीय कृषि की आवश्यकताओं और स्थिति की सभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त थीं।¹²² उन्होंने सिंचाई की बहुमुखी सुविधाएं जुटाने के लिए ब्रिटिश एवं शासकीय और राजाओं की भरपूर प्रशंसा की।¹²³ उन्होंने सिंचाई के द्रुत और व्यापक विकास की मांग की क्योंकि उनकी दृष्टि में इन सुविधाओं में ही भारत की व्यावहारिक मुक्ति निहित थी।¹²⁴

भारतीय नेताओं ने रेलों की अपेक्षा सिंचाई को महत्व क्यों दिया? इसका कारण यह है कि अधिकांश भारतीयों की दृष्टि में रेलों की अपेक्षा सिंचाई अकालों को रोकने के लिए अधिक प्रभावशाली तथा विश्वमनीय उपचार था।¹²⁵ रेलें केवल उपशमक थीं और इस प्रकार वे जहाँ अकाल के अत्यंत घृणित प्रभाव को मंद कर सकती थी वहाँ सिंचाई कष्ट की जड़ तक जाती थी और इस प्रकार अकालों को रोक सकती थी। रेलें देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न की उपलब्ध मात्रा के समान वितरण में अधिक कुछ नहीं कर

सकती थी; दूसरी ओर सिचाई अपने आप में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि कर सकती थी।¹²⁶ जैसा हम पहले ही दिखा चुके हैं, भारतीय नेताओं का वास्तव में यह विश्वास था कि सामान्य वर्षों में रेलों ने खाद्यान्नों के निर्यात की सुविधा जुटाकर इनकी कमी को अकाल में बदला है।

भारतीयों द्वारा सिचाई के पक्ष में प्रस्तुत एक अन्य तर्क था उसकी लाभप्रदता। उन्होंने यह निर्देश किया कि सिचाई कार्य आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है, वे 6 से 9 प्रतिशत लाभ उगाहते हैं, जबकि रेलें लगातार घाटा ही दिखाती आ रही हैं।¹²⁷ कुछ भारतीय नेताओं ने सिचाई नहरों का मस्ते परिवहन साधन के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना का भी निर्देश किया।¹²⁸

यह भी एक रोचक तथ्य है कि कुछ भारतीय नेता यह देखने-समझने में भी सफल हुए कि सिचाई पर खर्च होने वाली पूंजी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर भी जुटाती है क्योंकि बहुत-सा पैसा कुओं और नहरों आदि की खुदाई पर खर्च होता है, जबकि रेलों पर खर्च होने वाली अधिकांश पूंजी से संबंधित सामग्री का मभरण करने वाले विदेशी देशों को ही लाभ पहुंचता है।¹²⁹ एक महानुभाव तो और गहराई से उस समय विशेष में भारत के आर्थिक विकास की अवस्था में सिचाई और रेलों के तुलनात्मक गुणों को अत्यंत कुशलता से महसूसीत करने में सफल हो गए। नटिव ओपीनियन ने 9 सितंबर 1883 के अंक में लिखा 'द्वारा विश्वास है कि नहरें हमारी राजस्व व्ययन पद्धति में तथा हमारे साधनों के शैशव विकास में भारी गहनों के रूप वाली रेलों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त मिद्ध होती है। नहरे घरती की उत्पादक शक्ति को बढ़ाकर हमारे राजस्व में वृद्धि करेंगी और हमें हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी जुटाएगी।

यदि सिचाई का पक्ष इतना ही सजीव और मगक्त था तो फिर भारत सरकार ने नहरों के विकास की उपेक्षा क्यों की? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में कुछ भारतीय नेताओं को इस विषय में एक बार पुनः देश के शासकों के उद्देश्य का वेदनाजनक पुनर्मूल्यांकन करने को बाध्य होना पड़ा। 20वीं शती के प्रारंभ में उन्होंने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि सिचाई की उपेक्षा ब्रिटिश व्यापारियों, उत्पादकों और निवेशकों के हितों की सुरक्षा तथा मेवा के लिए भारतीयों के हितों की बलि चढ़ाने की विदेशी शासकों की स्वायत्तपूर्ण और गहरी ब्रिटिश प्रवृत्ति का ही परिणाम थी। इस मत को कई बार तो अत्यंत सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी गई। आर० सी० दत्त ने 1901 में लिखा : 'जैसीकि आशा थी भारत के साथ ब्रिटेन के व्यापार की सुविधापूर्ण बनाने वाली रेलों को ही प्राथमिकता दी गई है न कि भारतीय कृषि को लाभ पहुंचाने वाली सिचाई को'¹³⁰ 23 अगस्त 1903 के अंक में कैसर ए हिन्द ने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि तथा स्पष्टता से लिखा :

भारत सरकार का विनाशमूलक पग तो यही देखने को मिलता है। हम यह कहने का साहस कर सकते हैं कि सरकार स्वदेशी और ऋणग्रस्त कृषकों के उद्धार की चिन्ता की अपेक्षा वाणिज्य सदन तथा विदेशी व्यापारियों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक और अपरिमित अनुराग रखती है। सरकार कितना ही कपट क्यों न करे, मुट्ठी-भर विदेशी स्वार्थियों के हितों पर बहुसंख्यक जनता के हितों की बलि चढ़ाने की

अनुमति देता सरकार के प्रशासन का एक एक शोचमुच ही सचनीय पक्ष है ¹³¹
सामान्यतः नरमपथी 'इन्दु प्रकाश' ने अपने 30 नवंबर 1904 के अंक में लिखा .

भारत जैसे विशुद्ध कृषिप्रधान देश में नहरों के महत्व को अतिरजित करने की सभा-
बना ही दिखाई नहीं देती परंतु दुःख तो यह है कि देश का प्रशासन लोकहितो को
गौरव ही नहीं देता । अंगरेजी व्यापारियों को इस देश में मंडी के विस्तार के लिए
रेलें चाहिए और यह सरकार उनके लाभार्थ रेलें जुटा रही है । ¹³²

प्रारंभ में भारतीय आंदोलन का प्रशासन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, उसने इसे
अनदेखा कर दिया । ¹³³ उदाहरणार्थ 1901-2 के बजट भाषण में लार्ड कर्जन ने इस
समस्या का विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि सिंचाई से अकालो-
न्मुख सूखाग्रस्त जिलों की सुरक्षा अथवा वहां के विपन्न लोगों की सहायता की अपेक्षा
नहीं की जा सकती । वायसराय का तो इसके विपरीत यहां तक कहना था कि इससे तो
समस्या के और अधिक विषम हो जाने की संभावना है क्योंकि उनकी मान्यता थी कि
वस्तुतः मरुस्थल के उपजाऊ बनने के साथ ही जन्मदर भी बढ़ जाती है और इस रूप में
उपज बढ़ने के साथ साथ खाने वाले मुख भी बढ़ते हैं । कुल मिलाकर उनका मत था कि
सिंचाई का क्षेत्र सीमित है क्योंकि 4 000,000 एकड़ भूमि में अधिक भूमि की भविष्य में
सिंचाई नहीं की जा सकती । उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि सत्य यह है कि अकाल व विद्रुह
सुरक्षण के रूप में जितना संभव था और जितना शीघ्रता से अपेक्षित था उसमें संपन्न
मारा सिंचाई कार्य पहले ही संपन्न किया जा चुका है । जनता द्वारा अभी कभी समर्थित
सिंचाई कार्यों के संबंध में अनिश्चित विस्तार की अब कोई संभावना ही नहीं है । ¹³⁴ परंतु
ऊपर से अंतिम निर्णय के रूप में दिखाई देने वाली यह घोषणा स्थिर रूप में तब तक नहीं,
सरकार अन्तर्लोकमत का दावा का अनुभव करने लगी । उसका स्पष्ट प्रमाण लार्ड
कर्जन का अगले वर्ष का बजट भाषण है जिसमें उन्होंने वकालत की 'अच्छी तरह चले
हुए घोड़े को चाबुक मारना ठीक नहीं है । इस सरकार की अपेक्षा कोई भी पहले की भारत
सरकार सिंचाई को प्रोत्साहन देने के महत्व को सर्वाधिक प्रधानता का रूप नहीं दे सकती ।'
उन्होंने आलोचकों में अपनी दृष्टियों की पूर्ण सच्चाई पर विश्वास करने का अनुरोध
किया ¹³⁵ अपनी दृष्टियों की सच्चाई के प्रमाण में उसने सिंचाई के प्रयत्न की सामूहिक
समीक्षा और अतर्हित संभावनाओं की परीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी ।
डी० ई० वाचा ने सत्य ही स्वीकृति में विनोद के लिए सरकार की भर्त्सना का अवसर
हाथ में नहीं जाने दिया । 1901 में कांग्रेस के महापती श्रीभाषण में उन्होंने अपना
मत प्रकट करते हुए कहा 'यह तो स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि सरकार प्रबुद्ध लोकमत के
मुकाबले पिछड़ी रही है ।' ¹³⁶

सिंचाई आयोग ने अप्रैल 1903 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने 20
वर्षों के भीतर 65 लाख एकड़ धरती पर सिंचाई करने के लिए 44 करोड़ रुपये की
अतिरिक्त राशि खर्च करने की सिफारिश की । ¹³⁷ लार्ड कर्जन ने आयोग द्वारा प्रकल्पित
कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की . 'यह मानवीय साधनों और शक्तियों की
चरम सीमा का कार्यक्रम है और यह निजी उत्साह या सरकार की संगठित शक्ति का

प्रतीक है।¹³⁹ भारतीयों की आयोग के अनुमोदन के प्रति प्रतिक्रिया अनुकूल ही थी।¹³⁹ आलोचना का एकमात्र पक्ष यह था कि यह सब कुछ तुच्छ है। वस्तुतः आयोग को अत्यधिक ऊंची राशि और थोड़े समय में ही कार्य निपटाने के कार्यक्रम का अनुमोदन करना चाहिए।¹⁴⁰

निष्कर्ष

रेलो के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के गहरे विश्लेषण में यह तथ्य एक बार पुन स्पष्ट हो जाता है कि समीक्षाधीन अवधि के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का आर्थिक चिंतन गहरा था। उन्होंने रेलों की भूमिका को अमूर्त रूप में न देखकर समग्र आर्थिक विकास के व्यापक सदर्भ में ही देखा।

रेलो ही वर्तमान नीति के अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस नीति का निर्धारण भारतीय जनता के हितों के सदर्भ में नहीं हुआ था। यह तो उल्टे भारतीय जनता की आवश्यकताओं की बहुत दूर तक उपेक्षा ही करती थी। वस्तुतः प्रमुख रूप से ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में ही यह नीति निर्धारित की गई थी। उन्होंने यह भी देखा कि रेलें भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वे पिछड़े देश में रेल विभाग के और विकसित महानगरीय देश में उदीयमान वित्त यकिन क यह स्रवध और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली राजनीतिम जटिलताओं का भी उजागर करने में समर्थ सिद्ध हुए।

५ रेलों में औद्योगिक और कृषि स्रवधी वृद्धि के रूप में परिगणित आर्थिक विकास गणितीय बनावट में राष्ट्रिय आर्थिक हितों की सेवा की अपेक्षा रखते थे। उनके मत में उपयुक्त रेल नीति वह है जो भारतीय उद्योग को उन्नत बनाए और उपयुक्त लोक कार्य नीति वह है जो मिर्चाई और कृषि को प्राथमिकता दे।¹⁴¹ उनकी इच्छा थी कि रेल नीति भारतीय वित्त साधनों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उचित महत्व दे।

अतः में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीयों ने रेल नीति के स्वरूप को इस प्रकार लक्षित किया कि वह व्यापार की आवश्यकताओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अधीन बनाए। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करना ही न कि व्यापक आयात को उन्नत करना, अधिक खानान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना हो न कि उनके व्यापक निर्यात को। इस प्रकार उनके मन की रेल नीति एक बार पुन विकासशील उस व्यापारी पूँजी के हित की समर्थक नहीं थी, जिसने रेलें देश के अचलों में पैर फैलाने और अधिकार जमाने में सहायता प्राप्त कर रही थी और इस कारण जो निश्चित रूप में ही रेलों के द्रुतविकास की समर्थक बन रही थी। उदाहरणार्थ 1888 में बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन ने वायसराय लार्ड लंस डोन को भेजी शिकायत में देश और विदेश के व्यापार के हितों में रेलों और सहायक सड़कों के द्रुतविकास की वकालत की। इससे पूर्व सदन ने रेल सम्मेलन को एक आवेदनपत्र भेजा था जिसमें उस समय प्रचलित रेल दरो के विशेषतः निर्यात के लिए निर्धारित वस्तुओं, खाद्यान्न बीज और पटसन आदि, पर ऊँची रेल दरो क घटाने की वाञ्छनीयता पर बल दिया था।¹⁴² इन प्रकार 1899 में लार्ड कर्जन

को प्रस्तुत मानपत्र में सदन ने इस तथ्य की निंदा की कि भारत में केवल 21,000 मील लंबे रेलपथ हैं और इसके फलस्वरूप दूर अंचल-प्रांतों में कितने ही विस्तृत प्रदेश हैं जिनका किसी भी वाणिज्य केंद्र से सीधा संपर्क नहीं है। मानपत्र के अंत में यह लिखा गया था : हम लोग, जो देश के व्यापार में गहरी रुचि रखते हैं, श्रीमान महोदय के रेल विकास के आश्वासन का अत्यधिक स्वागत करेंगे।¹¹³ भारतीय नेताओं के रेलों के द्रुत विकास के विरोध में प्रस्तुत कारण और उद्देश्य तथा रेल विकास की उनके मनोनूकूल दिशा आदि के विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यापारिक हितों की अपेक्षा औद्योगिक हित ही उनकी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण थे।

संदर्भ

1. यह भाग मुख्य रूप से, इन्ग्रियल थानर इनवेस्टमेंट इन एपायर (फिलाडेलफिया, 1950) होरेस बैल : रेलवे पालिमी इन इंडिया (लंदन, 1897), जैक्स, पूर्वोद्धृत, 'दि इंपीरियल मजेटियर आफ इंडिया, पृष्ठ III, पूर्वोद्धृत; एन सान्याल : डिवेलपमेंट आफ इंडियन रेलवेज (कलकत्ता, 1930) और आर० डी० तिवारी . रेलवेज इन माडर्न इंडिया (बंबई 1941) पर आधारित है.
2. इस दबाव के कारण, प्रकृति और सीमा तथा प्रयोग की विधियां विस्तार के साथ थानर द्वारा उनके पूर्वोद्धृत ग्रंथ में निरूपित की गई है.
3. वही, पृ० 63.
4. डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर . दि मारक्विम आफ डलहौजी (आक्सफोर्ड, 1895), पृ० 192-4 जिस, पूर्वोद्धृत, पृ० 212.
5. अमरीका में कुछ रेलपथों के निर्माण का व्यय भूमि के मूल्य को मिलाकर केवल 2000 स्टलिन पाँच प्रति मील था. बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 183
6. जिस में उद्धृत : पूर्वोद्धृत, पृ० 221-2 एक अन्य विल सदस्य रिटायर्ड आनरेरी एस० लेड्ज ने 1861 में सरकारी तौर पर एक लेख में यही सवाल उठाया (उद्धृत, एच० एम० जगतिआनी दि रोल आफ दि स्टेट इन प्रोविजन आफ रेलवेज (लंदन 1924), पृ० 981 राज्य सचिव को मार्च 1869 में प्रेषित अपनी डाक में भारत सरकार ने भी विशेष रूप से रेलपथों के निर्माण के इस पक्ष की उच्च समालोचना की. उद्धृत, बैल : पूर्वोद्धृत, पृ० 98.
7. इंपीरियल मजेटियर, खंड III, पृ० 468.
8. 28 मार्च 1869 के संश्लेषण में भारत सरकार ने निर्देश किया कि इस समय भारतीय रेलों की औसत आय केवल तीन प्रतिशत है. इसका परिणाम यह हो रहा है. कि अवशिष्ट प्रतिभूत ब्याज का भुगतान भारत सरकार को ही करना पड़ा रहा है. (उद्धृत, बैल : पूर्वोद्धृत, पृ० 97). 1858-9 से 1869-70 की अवधि में प्रतिभूत सूद की राशि का कुल भार (आव से अतिरिक्त, सरकार द्वारा देय) लगभग 140 लाख पाँच था जबकि यह राशि 1868-9 में 650 लाख पाँच थी. (तिवारी : पूर्वोद्धृत, पृ० 56).
9. बैल में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 94.
10. इस संबंध में सामान्य निर्धारित व्यवस्था यह थी कि राज्य कोष पर रेलवे का सारा भार

राजस्व से प्रत्यक्ष व्ययों के रूप में अथवा रेलवे के ऋणों की सेवाओं के रूप में एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यह सीमा सदैव बढ़ाई अवश्य जाती थी परंतु निर्धारित सीमा का पालन भी अनिवार्यतः किया जाता था।

11. ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति भारतीय विदेश व्यापार के वर्तमान आयातों से असंतुष्ट थे और वे भारतीय मर्च को आंतरिक रूप से और पूरे तौर पर हथियाने के लिए तथा विशेष रूप से ब्रिटेन के लिए भारत से दूरतम प्रांतों से कच्चा माल लाने के लिए अपेक्षाकृत अच्छी परिबद्ध सुविधा के लिए चिन्ता रहे थे। वस्तुतः भारत का समुचित आर्थिक शोषण पर्याप्त आधुनिक सहायक सुविधाओं की मांग करता था। प्रतिभूत रेलवे में निवेश को सुरक्षित मानने वाले निवेशकों की ओर से भी नए सिरे से दबाव पड़ रहा था।
12. थार्नर : पूर्वोद्धृत, पृ० VIII
13. जेक्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 227. इपीरियल गजेटियर (पृ० 414) के अनुसार भारत रूस से बर्गमोल में प्रतिमील रेलवे लाइन के मुताबिक आगे था और जनसंख्या के हिसाब से प्रतिमील जापान से।
14. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 685. इंडियन स्पेक्टेटर ने 17 फरवरी 1884 के अंक में और जी० एस० अय्यर, ने 1898 में 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 182 में तथा 1903 में 'ई ए' पृ० 267 में इसी प्रकार के विचार प्रकट किए।
15. देगिंग, ने- पूर्वोद्धृत पृ० 244-5 और इपीरियल गजेटियर, खंड III, पृ० 365.
16. थार्नर में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ० 9
17. सान्याल : पूर्वोद्धृत, पृ० 146 में उद्धृत चेसनी ने 1894 में अपनी 'इंडियन पालिटी' पुस्तक में दावा किया कि रेलमार्गों के वर्तमान विकास ने दुश्मनों से भारत की रक्षा की है।
18. आई० सी० पी० 1896 खंड XXXV, पृ० 345 और देखिए, कर्जन : स्पीचेज II, पृ० 280.
19. नोरोजी : पावर्टी, पृ० 193 एसेज, पृ० 122-3, 132 एस० एन० बैंजर्जी स्पीचेज I, पृ० 179; सी० पी० ए०, पृ० 270: इंडियन स्पेक्टेटर, 4 सित० (आर० एन० पी० बंब; 10 सित० 1881) 17 फरवरी 1884; मराठा, 24 फरवरी, 2 मार्च 1884, इंदु प्रकाश, 21 अप्रैल 1884. सोम प्रकाश, 16 जून (आर० एन० पी० बंग०, 21 जून 1884) हिंदू, 9 जनवरी 1885, 12 मई 1902 डब्ल्यू० सी० बैंजर्जी सी० पी० ए०, पृ० 4, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 671, रानाडे : एसेज, पृ० 87, बगवामी, 5 मई (आर० एन० पी० बंग० 12 मई 1894) बाबा : स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 22 जी० एस० अय्यर विलबी आयोग, खंड III प्रश्न 18963, 18984 इंडियन पालिटिक्स, पृ० 182, 191 पर. दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 130. स्पीचेज I, पृ० 98, 100-101. स्पीचेज II, पृ० 76. बगवामी, 27 अप्रैल 1901; एम० के पटेल, रिप० आई० एन० सी०, 1902, पृ० 141.
20. 1853 में हाऊस आफ कामस को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत स्मारक में लोक कर्म को उपयोगी बनाने की व्यवस्था न करने वाले तथा देश के साधनों के विकास की तथा वाणिज्य और उत्पादन में वृद्धि की ओर उपज में उन्नति की संवर्धना न करने वाले 1833 के चार्टर ऐक्ट की आलोचना की गई थी। (भोलानाथ शर्मा : राजा दिगम्बर मिश्र, खंड I, पृ० 74 पर उद्धृत) रामगोपाल घोष, द्वारकानाथ टैगोर तथा बंबई के व्यापारियों के प्रारंभिक रेलवे उद्यम को दिए गए प्रोत्साहन के लिए देखिए, थार्नर : पूर्वोद्धृत, पृ० 51, 77, 97; दादाभाई नोरोजी ने इन्हें भारत जैसे देश की ज्वलंत आवश्यकताओं में संचार का एक सस्ता साधन बताया और कहा कि ये एक प्रकार सर्वरोगनाशक औषधि हैं और इन्हीं पर भारत की आर्थिक भूमिति निर्भर

है। उनका विश्वास था कि पिछले पचास वर्षों के प्रशासन में रेलपथों और नहरों का निर्माण ही एकमात्र अथवा प्रधान शुभ कार्य था। इसके लिए सरकार का दावा सही है और उसे इसका भारी श्रेय मिलना ही चाहिए। भारतीय जनता सचमुच अंगरेज जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है (एसेज, पृ० 123, 126 और पृ० 103, 106, 108, 128) तथा देखिए, इंडियन स्पॉन्टेटर, 4 सितंबर (आर० एन० पी० बंब; 10 सितंबर 1881) जामे जमशेद, 10 जनवरी (वही, 15 जनवरी 1881); बाबे क्रोनिकल, 9 जनवरी (वही) और 20 मार्च (वही, 27 मार्च 1881) और 16 दिस० (वही, 22 दिसंबर 1883); हिंदुस्तानी, 2 मार्च (आर० एन० पी० पी० एन०, 5 मार्च 1884) हिंदू, 9 जनवरी 1885. मराठा ने 24 फरवरी 1884 के अंक में लिखा : 'रेलवे के और अधिक प्रसार के बिना भारत के सदा विकासशील राष्ट्रों की पंक्ति में खड़े होने की आशा नहीं की जा सकती।' 1884 के वर्ष में यह समर्थन बिखरता दिखाई देता है, इसका कारण कदाचित् 1884 की प्रवर समिति के प्रतिवेदन और कार्यवाही पर विचार विमर्श का फल था अथवा भारतीय उद्योग रूचि के उदय का परिणाम था जो इस समय व्यापार रूचि पर प्रभुत्व पाने लगी थी।

21. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 193 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 701 और 671; वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट : पृ० 22. जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 188 पर; दत्त : स्पीचेज II पृ० 44. रामगोपाल : पूर्वोद्धृत, पृ० 145 पर उद्धृत, रानाडे : एसेज, पृ० 97 क्रमशः.
22. क्रमशः आर० एन० पी० बंग०, 10 मई 1884, वही, 31 मई 1891. आर० एन० पी० बंब; 4 जुलाई 1903 और वही, 3 दिसंबर 1904.
23. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 676-7 और पृ० 687.
24. रानाडे : एसेज, पृ० 86, 90 क्रमशः.
25. 22 मई 1901 को मद्रास प्रांतीय परिषद में अभिभाषण, स्टेट्समैन, 31 मई 1901 में उद्धृत.
26. जी० एम० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 193 तथा देखिए, उनकी ई ए, पृ० 262, 271.
27. इंडियन स्पॉन्टेटर, 19 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंब, 25 अक्तू० 1884) हिंदू, 23 जनवरी 1885; बगवासी, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 30 अप्रैल 1887) आयरनप्रियान, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 1895); दत्त : इग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 81 स्वेदस-मिन्नन्, 9 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 15 अगस्त 1899); बंगाली, 27 अप्रैल 1901. गोखले : स्पीचेज, पृ० 21. रिप० आई० एन० सी०—1904, पृ० 165. वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 624 एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी०—1902, पृ० 141.
28. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 687-8 और पृ० 675, 684, 693 और देखिए, जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 193.
29. नेटिव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बंब, 15 सित० 1883) शिलिलेखा, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्तूबर 1897).
30. जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, 193.
31. गोखले : विमर्श कमीशन, खंड III प्रश्न 18140-1. 18155-60. वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 22.
32. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 193-5; इंदु प्रकाश, 13 दिसंबर (आर० एन० पी० बंब, 18 दिसंबर 1875); ए०, बी० पी०, 18 अगस्त 1881; मराठा, 3 फरवरी 1884, 7 दिसंबर 1902;

- इंडियन स्पेक्ट्रेटर, 17 फरवरी 1884; युनाइटेड इंडिया, 11 अगस्त (बी० ओ० आई, 31 अगस्त 1884) जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 695, हिंदू, 23 जनवरी 1885, 29 अक्टूबर 1897; एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 270; बगबासी, 25 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 2 मई 1896), वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 23. तिलक, रामबोपाल : पूर्वोद्धृत, पृ० 145 पर उद्धृत. दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 143. ई एच II, पृ० 605; स्वदेशमित्र, 30 अक्टू० (आर० एन० पी० एम० 30 नवंबर 1897); केसरी, 19 नवंबर (आर० एन० पी० बंब, 23 नवंबर 1901); मोदवृत्त, 29 जून (वही, 4 जुलाई 1903); जी० एस० अय्यर : विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 19564, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 190-2 पर; और ई ए, पृ० 267-70.
33. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 193-5. जी० एम० अय्यर : ई ए, पृ० 268, 270. इंडियन पालिटिक्स, पृ० 190 पर.
34. नौरोजी . पावर्टी, पृ० 195 और देखिए, जी० एम० अय्यर : ई ए, पृ० 268.
35. जी० एम० अय्यर : विलबी आयोग, खंड III प्रश्न 19636, 19640-1, 19644. इंडियन पालिटिक्स, पृ० 190. इसी तथ्य की पुष्टि में उन्होंने 1903 में थानेर को उद्धृत किया : रेलवे उत्तम है, मिर्चाई अच्छी है, परंतु धन की निकासी क्षेत्र खोलने और उसे समातार विस्तृत बनाने की क्षतिपूर्ति के रूप में पड़ली अच्छी है और न ही दूसरी इस निकासी ने भारत के हृदयरक्त को चूम लिया है और उसके जीवन रक्त की प्रमुख, आधारभूत औद्योगिक शक्ति को क्षीण कर दिया है. (इक्व्यू० टी० थानेर वेस्ट मिस्टर रिज्यू 1880 ई ए. पृ० 287 पर उद्धृत).
36. बगबासी, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 30 अप्रैल 1887) और 5 मई (वही, 12 मई 1894), हितवादी, 25 जुलाई (वही, 1 अगस्त 1891), ए० बी० पी०, 20 सितंबर 1891; आर्यजनप्रियान, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 1895), दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 6 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 9 जनवरी 1897); बंगाली, 27 अप्रैल 1901; नेटिव ओपीनियन, 8 मई (आर० एन० पी० बंब०; 11 मई 1901); एन० के० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०, 1901. पृ० 138, मोद वृत्त, 29 जून (वही, 4 जुलाई 1903); सूर्योदय प्रकाशिका, 18 मई (आर० एन० पी० एम०, 21 मई 1904); जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 110-11, 276 बगबासी ने 6 जुलाई 1889 के घक में रेलवे के विस्तार के समर्थकों को लालची श्वेत गिद्ध कहकर उनकी भत्सना की (आर० एन० पी० बंग०, 13 जुलाई 1889) इस तथ्य की पुष्टि में वाचा ने 1889 के अकाल आयोग के प्रतिवेदन से चन्द्रिका स० 536 को उद्धृत किया जो इस प्रकार थी : यह सही है कि रेलें सूखे के वर्षों में अकालग्रस्त होने की आशंकावाले प्रदेशों में अनाज लाती हैं परंतु साथ ही अधिक उपज के वर्षों में उन प्रदेशों को अनाज के भंडार से वंचित भी करती हैं. (सी० पी० ए०, पृ० 577).
37. कर्जन : स्पीचेज II, पृ० 277-9.
38. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 276-86, बगबासी, 5 मई (आर० एन० पी० बंग०, 12 मई 1894); दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 6 जनवरी (वही, 9 जनवरी 1897) बंगाली, 27 अप्रैल 1901, एन० के० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०—1901 पृ० 138.
39. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 278
40. एस० एन० बैनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 179 इसी में पृ० 178 पर उद्धृत कलकत्ता में 2 मार्च 1878 को जनसम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव, 'पार्लियामेंटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक वर्क्स' :

- जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (सं० 1 खंड IV), पृ० 8; रास्त मुफ्तार, 5 जून (आर० एन० पी० बग, 11 जून 1881) जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 218, 687. ट्रिब्यून, 25 अप्रैल (बी० ओ० आई०, 15 मई 1884); नव विभाकर, 24 मई (आर० एन० पी० बग०, 29 मार्च 1884), डाका प्रकाश, 30 मार्च, बगबासी, 29 मार्च (वही, 5 अप्रैल 1884); बर्बवान सजीवनी, 22 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884), सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 1884); भारत मिहिर, 13 मई (वही, 24 मई 1884), दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 31 मई (वही, 6 जून 1891); लोकोपकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 15 सितंबर 1897), केसरी, 19 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 23 नवंबर, 1901), गोखले . स्पीचेज, पृ० 1194. विलबी कमिशन, खंड III प्रश्न 18399, 18406, वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 20, 22-3, जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 578-9; दत्त : ई एच I, पृ० 212 और स्पीचेज II, पृ० 44, 76-7, ई एच II, पृ० 605 एन० के० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 138.
41. वाचा . सी० पी० ए०, पृ० 580.
 42. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 270-1.
 43. जी० एस० अय्यर . इंडियन पालिटिक्स, पृ० 188.
 44. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 260.
 45. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 630-1. 2 फरवरी 1889 के घक मे बगबासी ने भी निर्देश किया कि ब्रिटेन ने भी भारी निर्यातों के लिए रेल दरे घटा दी हैं
 46. 1916-18 के भारतीय उद्योग आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट दर नीति परवर्ती वर्षों मे भारतीय राजनीति की ज्वलत समस्या बन गई थी (देखिए, प्रतिवेदन, अध्याय XIX) और अन्य असह्य अधिकृत विद्वानों तथा लेखकों की पुस्तकें परवर्ती वर्षों मे जी० एस० अय्यर तथा जी० बी० जोशी द्वारा निर्दिष्ट पथ पर रेलों की दर नीति की समालोचना रेलवे पर लिखने वाले भारतीयों की सामान्य शैली बन गई.
 47. देखिए, रेलवे सम्मेलन मे 3 सितंबर 1888 को बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन द्वारा अपने 1888 के प्रतिवेदन मे प्रस्तुत स्मरण-पत्र
 48. जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 688
 49. वही, पृ० 689 और वही, पृ० 801-02. जी० एम० अय्यर . इंडियन पालिटिक्स, पृ० 191 ई ए, पृ० 266
 50. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 689 और जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 265 और महेश्वर, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 10 मई 1884) साथ ही जोशी और अय्यर ने निर्देश किया . यह विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व था जिमने ऋण ली हुई धनराशि से रेल-पथों का निर्माण किया, ये ही अपने आप मे रोग थे जबकि स्वतंत्र देशों मे रेलें असह्य लाभों की जनक सिद्ध हो रही हैं. जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 670-1, 684, 689; जी० एस अय्यर इंडियन पालिटिक्स, पृ० 189-90 और ई० ए०, पृ० 261, 268, 270.
 51. जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 191-2 और ई ए, पृ० 262, 271. दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 130. एन० के० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०-1901, पृ० 138.
 52. इसका सुझाव वेरा आस्टे द्वारा उनकी पुस्तक . 'दि इकोनामिक डिवलपमेंट आफ इंडिया' पृ० 145 मे दिया गया है.
 53. इस प्रकार की आलोचना का अकेला उदाहरण मुझे 'बगबासी' के 5 मई 1894 के निम्न अवतरण

में मिला है, रेलों ने वर्ष व्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचाया है क्योंकि रेलों के डिब्बों में सभी वर्गों के लोगों को बेंचों पर समान रूप से और समान स्तर पर बैठना पड़ता है. (आर० एन० पी० बग०, 12 मई 1894).

54. उदाहरणार्थ, 1883 में दादाभाई नौरोजी ने लिखा : अतएव सोक कर्मों के संबंध में वास्तविक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हे रोकने की विधि सोचने का नहीं प्रत्युत उनसे जनता के सामान्वित होने की विधि सोचने का है. इंग्लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महान कार्य भारत में इन लोक कर्मों का विकास है परन्तु साथ ही देखना यह भी है कि वे यहां के लोगों के लिए लाभदायक हों, हानिप्रद न हों; ऐसा न हो कि उनसे भारतीय दास बन जाएं और दूसरे लोग उनको हड़प जाएं. (पावर्टी, पृ० 196).
55. जी० एस० अय्यर : ई० ए० पृ० 272 और दत्त : ई एच II, पृ० 174 और 545.
56. राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के मत के लिए देखिए, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 674-6, 684, 687-8, 693; जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 186 और ई० ए०, पृ० 272-3. गोखले : स्पेचेज, पृ० 21, 1157, 1194 और विलवो कमीशन, खंड III प्रश्न 18150, 18407, 18410-14; पी० ए० चार्ल्स : आई० सी० पी०-1900 खंड XXXIX पृ० 144; श्रीराम : आई० सी० पी०-1904 खंड XLIII पृ० 510; दत्त : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 53. ई एच I, पृ० 312. ई एच II, पृ० 174, 357, 546. स्पेचेज II, पृ० 37, 44, 60, 77. फॉर्मिस ऐंड लेड ऐमेसमेंट इन इंडिया (ल० 1900) (इसे आगे निर्देश के लिए 'फॉर्मिस इन इंडिया' से संकेतिक किया जाएगा) पृ० 305. समाचारपत्रों के लिए देखिए, नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 1883); बंगाली, 3 मई 1884. रास्त गुप्तार, 2 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 8 मार्च 1884) हिंदू, 18 अप्रैल 1884 न्याय मुद्रा, 7 मई (आर० एन० पी० पी० एन०, 12 मई 1884); नवविभाकर, 21 अप्रैल, बर्दवान सजीवनी, 22 अप्रैल; साधारणी, 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884); समाचार चंद्रिका, सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 1884); सहचर, 30 अप्रैल (वही, 10 मई 1884); भारत मिहिर, 24 मई (वही, 31 मई 1884); 25 जनवरी बगबासी, 9 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1887); रहबर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 30 जनवरी 1895) लोकोपकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 15 सितंबर 1897); शशिलेखा, 26 अप्रैल (वही, 30 अप्रैल 1898); जनानुकूलन, 13 मई (वही, 13 जून 1903) केसर ए हिंद, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 29 अगस्त 1903); इंदर प्रकाश, 30 नवंबर (वही, 3 दिसंबर 1904); डेली हितवादी, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 15 अप्रैल 1905) भले ही स्थान का अभाव अधिक उदाहरणों को उद्धृत करने की अनुमति न दे फिर भी यह दिखाने के लिए कि किस प्रबलता से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था हम दो तीन उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लोभ का तो सवरण नहीं कर पाते :

जी० बी० जोशी

भारत में न केवल भ्रमरेजी राज्य को प्रत्युत भ्रमरेजी वाणिज्य व्यवसाय को भी सुदृढ़ करना लाई डलहौजी का एक स्वप्न था और इस गहरी महत्वाकांक्षा के लिए भारत के स्थाई हितों को गौण रूप दे दिया गया था. इंग्लैंड में उन्मुक्त व्यापार सिद्धांत के समकालीन उदय ने और इस सिद्धांत के अनुयायियों द्वारा लब्ध प्रसिद्धि ने चंगुल में फंसाने वाली और नितांत स्वाभंगपूर्ण इस नीति के लिए आध्यात्मिक आधार का कार्य किया. ब्रिटेन राष्ट्र द्वारा भारत की कीमत संकाशायर के

उत्पादन को पोषित करने और बढ़ाने के लिए उत्पन्न करने वाले कृषि सबघी कच्चे माल के परिमाण के निर्यात की क्षमता के सदर्थ में ही आकी गई भारत को अपनी सारी शक्तियाँ कच्चे माल का निर्यात बढ़ाने में ही लगानो पड़ी नहरो, रेलो, सडको और सुघरे सचार साधनो को हर कीमत पर अधिकाधिक विकसित किया गया ताकि भारत से इंग्लैंड को कच्चे माल के निर्यातो और इंग्लैंड से वहा के पक्के उत्पादनो के भारत मे आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके तुलनात्मक रूप से इस सारी प्रक्रिया मे भारत की अपनी जरूरतो की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया भारतीय साधनो का सहोजन तो सभी प्रकार के सदेहो मे और किसी भी त्याग के मूल्य पर पूरा करना ही था (पूर्वोद्धृत पृ० 674-5)

जी० एस० अग्रयर

ब्रिटिश पूजीपति और राजनीतिज्ञ के मुह मे बईमानो का स्वर ही निकलता है, यह स्मरणीय है कि रेलपथो के निर्माण का प्रत्येक मोल अनेक घररेजो का इतना अधिक लाभ सर्वाधित करना है कि प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय अधिकारियो पर प्रतिवर्ष नए कार्य को हाथ मे लेने का निरतर दबाव डालने से कभी नहीं रुकते (ई० ए०, पृ० 2/2 3)

गोपालकृष्ण गोखल

भारतीय लोग यह अनुभव करते हैं कि यह निर्माण कार्य प्रधान रूप से ब्रिटिश व्यापारीवर्ग तथा धनिक समुदाय के हितो के लिए ही किया जा रहा है और यह हमारे ससाधनो के और अधिक शोषण मे ही सहायक है. (स्पीचेज, पृ० 1194)

पी० ए० चारलू

रेलो का प्रयोजन वास्तविक रूप से उद्यम का, वाणिज्य का, उत्पादन का, रेल सचया का और महत्वाकांक्षी इजीनियरो का प्रयोजन है इन सबक प्रतिनिधि निश्चित रूप से इस सबध मे अपना प्रबुध स्वर ऊचा करने मे तथा अपनी सुसंस्कृत, सशक्त प्रतिभा का उपयोग करने मे सगठित है (एल० सी० पी० 1900, खंड XXXIX, पृ० 144)

नवविभाकर, 21 अप्रैल 1884

रेलो की आवश्यकता ब्रिटिश व्यापारियो के लिए है... घररेज व्यापारी ही इंग्लैंड के शासक हैं, समद उनके नियंत्रण मे है, मंत्री उनके सेवक हैं ब्रिटिश व्यापारियो के लिए अनुकूल और प्रसन्नतादायक नीति ही उस राष्ट्र की सर्वोत्तम नीति है (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884)

- 57 नवविभाकर, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 6 अक्तू० 1883); साधारणी, 20 अप्रैल, नवविभाकर, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884) ममय, 12 मई (वही, 17 मई 1884) भारत मिहिर, 13 मई (वही, 24 मई 1884), बंगाली, 3 मई 1884; हिंदू, 23 जनवरी 1884, बगबासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 16 अप्रैल 1887), जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 670, 675-6, 689, जी० एस० अग्रयर इंडियन पालिटिक्स, पृ० 181, दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 24 अप्रैल 1897), दस्त ई एष II, पृ० 174, 546 और स्पीचेज I, पृ० 98, हनु प्रकाश, 30 नवंबर, (आर० एन० पी० बग०,

- 3 दिसंबर 1904), डेली हितवादी, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 15 अप्रैल 1905)
- 58 सहचर, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 10 मई 1884), समय, 12 मई (वही, 17 मई 1884); बगानी, 3 मई 1884, याज्ञदा परस्त, 15 जून (आर० एन० पी० बग०, 21 जून 1884), केसरी, 9 सितंबर (वही, 13 सितंबर 1890) जोशी - पूर्वोद्धृत, पृ० 685, दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 24 अप्रैल 1897), जी० एस० अय्यर - इंडियन पार्लिटिक्स, पृ० 181, दत्त स्पीचेज I, पृ० 98
- 59 नवाविभाकर, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884); बगबासी, 5 मई (वही, 12 मई 1894), दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 21 अप्रैल (वही, 24 अप्रैल 1897), स्वदेशमित्रन, 30 अक्तू० (आर० एन० पी० एम०, 30 नव० 1897) दत्त स्पीचेज I, पृ० 98. जी० एम० अय्यर - ई० ए०, पृ० 263
- 60 समय, 12 मई (आर० एन० पी० बग०, 17 मई 1884), बगबासी, 9 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1887), केसरी, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बग०, 9 सितंबर 1890); दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 24 अप्रैल 1897) जी० एस० अय्यर - इंडियन पार्लिटिक्स पृ० 181.
- 61 जाशी पूर्वोद्धृत, पृ० 674 और नवाविभाकर, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 6 अक्तूबर 1883)
- 62 जी० एम० अय्यर - इंडियन पार्लिटिक्स, पृ० 181
- 63 जाशी पूर्वोद्धृत, पृ० 675 688, 693, नवाविभाकर, 24 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 29 मार्च 1884), बगबासी, 29 मार्च, ठाका प्रकाश, 30 मार्च (वही, 5 अप्रैल 1884); साधारणी, नवाविभाकर 21 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884), सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 1884), मुंशदाबाद पत्रिका, 30 अप्रैल (वही, 10 मई 1884), रास्त गुप्तार, 25 मई (आर० एन० पी० बग०, 31 मई 1884), रहबर, 8 सितंबर (आर० एन० पी० एम०, 14 सितंबर 1892), लोकप्रकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 15 सितंबर 1897), जी० एस० अय्यर - ई० ए०, पृ० 272, दत्त स्पीचेज I, पृ० 102, ई एच II, पृ० 174, गोखले स्पीचेज, पृ० 1194 यह अत्यंत उत्सुकतावर्धक तथ्य है कि रेल आधिक्यता के कदाचित अपने युग के सर्वाधिक मर्मज्ञ विचारक फ्राइड क्लार्क ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा 'रेलो के प्रवर्तन का वास्तविक लक्ष्य यह है कि हिंदुस्तानी इनका निर्माण करे ताकि इंग्लैंड के लोग इनके लाभ का बड़ा भ्रम पाने में इनसे ममर्ष हो सके उद्धृत, जिक्स में पूर्वोद्धृत, पृ० 226 और देखिए, बेल पूर्वोद्धृत, पृ० 254-5
- 64 जोशी पूर्वोद्धृत, 675
- 65 जी० एम० अय्यर ने 1903 में लिखा श्री राबर्टसन ने अपने मारे विस्तृत प्रतिवेदन में कही भी भारत की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में नहीं रखा. वस्तुतः विदेशी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की एक विशिष्ट अवस्था हो गई है और वह यह मांग करती है कि भारत की समृद्धि की समस्या के समाधान के लिए अन्य देशों के ज्ञान और अनुभव को उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रत्युत अधिक सक्षम विरोधी हितों से निरंतर घिरी हुई उसकी अपनी आवश्यकताओं को ही समझने की आवश्यकता है (ई० ए०, पृ० 266-67 और पृ० 261, 263) तथा देखिए, जी० एस० अय्यर : इंडियन पार्लिटिक्स, पृ० 182, 192 3 और पाद टिप्पणी, 194 और आगे बाद-भाई नौरोजी ने एक भिन्न रूप में ही सही, यही दृष्टिकोण व्यक्त किया 'लोक कर्मों के सबंध में

- वास्तविक समस्या उन्हें समाप्त करने की नहीं प्रत्युत यह देखने की है कि उनसे देश के जन साधारण को पूरे लाभ किस प्रकार प्राप्त कराए जाए (पावर्टी, पृ० 196).
66. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 696 और 676 क्रमश और भी सरकार विदेशी व्यापारियों को व्याज के बकाया भुगतानों के रूप में उपहार अर्पित करने के स्थान पर इस चार करोड़ की राशि को देश में ही औद्योगिक संगठन की स्थापना में अथवा स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देकर उसी दिशा में उसे प्रोत्साहन देने में अथवा यहां की जनता की ही जेबों में सी गुना बढ़कर रहने के लिए देश के अन्याय उपयोगी कार्यों में व्यय करती तो सचमुच यह बहुत ही अच्छा होता (पृ० 688) और देखिए, पृ० 671, 689
67. जी० एस० अय्यर : ई० ए, पृ० 271 और इंडियन पालिटिक्स, पृ० 182, 188. डी० ई० वाचा ने भी राष्ट्रीय कांग्रेस के 1901 में हुए सत्रहवें अधिवेशन में सभापतीय अभिभाषण में यह दावा किया : 'यह अब स्वीकार कर लिया गया है कि रेलों केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्नों के शीघ्र वितरण का साधन मात्र हैं परंतु वे देश की संपदा में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं करती' उन्होंने इस बात की शिकायत की कि केंद्रीय अधिकारियों के इस भ्रम को तोड़ने में अनेक वर्ष लग गए (सी पी ए, पृ० 577) और देखिए, गनाडे एसेज, पृ० 88 और हिंदू, 23 जून 1885
68. 'ए वानिंग वायस ऐज रिगाइंड्स रेलवेज इन इंडिया' (भारतीय रेलों के प्रति चेतावनी का स्वर) इंदु प्रकाश 21 अप्रैल 1884
69. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 671
70. सहचर, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 10 मई 1884) जी० एस० अय्यर . ई० ए०, पृ० 261
71. जी० डी० जोशी ने 1884 में लिखा यदि परिवहन की इन सुविधाओं के साथ साथ राज्य देश में विविध प्रकार के औद्योगिक जीवन के लिए समृद्ध आर्थिक स्थिति जुटाने की भी व्यवस्था करता केवल तभी परिवहन के लाभों को राष्ट्र के काम लाया जा सकता था (पूर्वोद्धृत, पृ० 696) और अक्वोदय, 24 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 मार्च 1884), आयंजन-प्रियान्, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 1895) विस्तारपत्रिका, 15 मई वही, 21 मई 1904)
72. आर० एन० पी० बग०, 10 मई 1884
73. यहा तक कि 1873 में मार्क्स ने भी भविष्यवाणी की थी जब एक बार लोहा और बायलावाले किसी देश के संचलन में मशीनें प्रचलित हो गईं तो उन्हें उनके निर्माण कार्य से हटाना सरल नहीं होता एक विशाल देश में भी रेल जाल कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि रेल संचलन के लिए तात्कालिक और सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित औद्योगिक प्रक्रियाएं लागू नहीं की जाती और उनमें से रेलों से तात्कालिक रूप से न जुड़ा हुई औद्योगिक शाखाओं की मशीनों के प्रयोग का विकास भी आवश्यक रूप से वाछनीय है अतः रेल प्रणाली भारत में वास्तव में ही आधुनिक उद्योग को अग्रगति देने वाली होगी (आन कलॉर्नमनिंगम, पृ० 79) परंतु कार्य इस रूप में नहीं हुआ 19वीं शताब्दी की अवधि में रेलों का सारा निर्माण इंग्लैंड में बने सामान से ही किया गया रेलों अपने निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित सामान को तैयार करने के लिए भारत में किसी सशक्त उद्योग को जन्म देने में असमर्थ रही (जिम्स : पूर्वोद्धृत पृ० 227) अतः एक सतर्क भारतीय विचारक ने यह भी अनुभव किया और रेलों के

विस्तार के सदर्भ में भारत में लोहा उद्योग को प्रोत्साहन न देने के लिए सरकार की आलोचना की नेटिव ओपीनियन ने अपने 20 दिसंबर 1885 के अंक में लिखा यह आश्चर्य का विषय है कि कोयला झोंदो में लोहे की बड़ी बड़ी परतें मिली हैं हमारी सरकार इनका उपयोग पटरियों बनाने और पुलों के शहतीर बनाने के बदले विदेशी बाजारों से उनकी खरीद कर रही है। विदेशी लोहे पर खर्च की गई धनराशि का यदि भारत में उपयोग किया जाता तो हम न केवल अपेक्षाकृत सस्ता और बढ़िया लोहे का उत्पादन कर सकते बल्कि नए उद्योग का प्रारंभ भी कर सकते थे क्या सरकार समस्या के इस पक्ष पर ध्यान देगी और दूसरों को इस दिशा में पूंजी लगाने को प्रेरित करने के लिए स्वयं पहल करेगी ?' समीक्षाधीन काल में राष्ट्रीय नेताओं की रेल भंडारों के लिए सरकार द्वारा भारतीय कर्मों से खरीद और उनसे अप्राप्यता की स्थिति में उनके उत्पादकों से खरीद की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक मांग थी (अध्याय 3 ऊपर) भारतीय इस्पात उद्योग की स्थापना 20वीं शताब्दी में की जा सकी जबकि रेलों के निर्माण का बहुत काफी कार्य पहले ही किया जा चुका था वस्तुतः भारतीय इस्पात उद्योग का उदय रेलों की तात्कालिक और सामयिक मांगों की पूर्ति के सदर्भ में ही नहीं हुआ था, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उद्योगीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मद थी और विदेशी पूंजी के कठोर नियंत्रण में थी

- 74 दादाभाई नौरोजी ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो यह कहते हैं कि क्योंकि रेलों ने नई मंडी खोले हैं और देश के उत्पादन अवश्य बढ़ने चाहिए उन्होंने यह दोहराया पदार्थों की मांग श्रम की मांग नहीं है और निवेश के लिए पूंजी के अभाव में बड़ी मात्रा में उद्योगों का विस्तार नहीं किया जा सकता (पावर्टी, पृ० ५६)
- 75 जोशी ने निर्देश किया अमरीका में उन्मुक्त व्यापार नहीं है और संरक्षण नियम सर्वोच्च हैं वहां रेल सरकारों प्रतिष्ठान नहीं, वे निजी उद्यमों द्वारा अपने ही दायित्व पर बनाई गई हैं। अमरीका में रेल भौतिक समृद्धि का एक भाग है वहां सारे देश में कृषि उत्पादन, वाणिज्य-समृद्धि आदि अन्य पक्षों का भी साथ साथ और समुचित रूप से विकास किया जा रहा है दूसरी ओर, 'हमारी स्थिति विचित्र रूप से अमरीका जैसी नहीं है... (यहां) रेलों के विकास का राष्ट्र की समृद्धि के तत्वा की सामान्य वृद्धि के साथ कोई संबंध ही नहीं' (पूर्वोद्धृत, पृ० 670-1)
- 76 ऊपर देखिए
- 77 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 671 और 696
- 78 ए वॉनिंग वायस एंड रिगाड्स रेलवेज इन इंडिया (भारत में रेलों के सबंध में चेतावनी का स्वर), इन्दु प्रकाश, 20 अप्रैल 1884 और जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 671 क्रमशः आर० सी० दत्त ने भी टिप्पणी की - 'रेला की व्यवस्था देश की तात्कालिक आवश्यकताओं से कही आगे है' (ई एच II, पृ० 450)
- 79 हिंदू, 23 जनवरी 1885 रानाडे एसेज, पृ० 88, 91-2, 97 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 671.
- 80 उद्योग के लिए देखिए जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 688 याजदा परस्त, 15 जून (आर० एन० पी० बब, 21 जून 1884); नेटिव ओपीनियन, 20 दिसंबर 1885; रानाडे : एसेज, पृ० 87-9, जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 264, 272. रेलों के सिंचाई से सबंध की चर्चा आगे पृथक रूप से की गई है. इसी प्रकार गोखले ने 1897 में विलंबी आयोग के सामने घोषणा की 'हमें उनके और रेल-पथों की आवश्यकता नहीं हम तो इस समय पहले शिक्षा पर व्यय करना चाहते हैं और तदुपरांत

रेलों पर आप एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे अन्य दिशाएँ उपेक्षित हो रही हैं। यह ठीक है कि ये सभी रेलें अनुपयोगी नहीं हैं परंतु प्रश्न यह है कि हमारे लिए कौन सी उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक महत्व की है' (विलबी आयोग, खंड III प्रश्न 18409 और देखिए प्रश्न 18400)।

81. एस० एन० बैनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 170-81 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 55, 671 इंडियन स्पेंडेंटर, 24 फरवरी 1884; नेटिव ओपीनियन, 24 फरवरी 1884; इन्दु प्रकाश, 21 अप्रैल 1884, बंगाली . 3 मई और 9 अगस्त 1884; ट्रिब्यून, 1 मार्च (बी० ओ० आई०, 15 मार्च 1884); बिहार हेराल्ड, 22 और 29 अप्रैल (वही, 15 मई 1884), भ्रूणोदय 24 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 8 मार्च 1884); रास्त गुप्तार, 2 मार्च (वही); बगवामी, 29 मार्च और ढाका प्रकाश, 30 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 5 अप्रैल 1884), सहचर, 23 अप्रैल (वही, 3 मई 1884); भारत मिहिर, 13 मई (वही, 24 मई 1884); हिंदू, 6 अप्रैल 1889 जी० एम० अथर : विलबी आयोग खंड III, प्रश्न 19609, और इंडियन पालिटिक्स, पृ० 182, 194, गोखले : स्पीचेज, पृ० 1194, और विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18399, 18406, दत्त . इंडियन पालिटिक्स, 52-3; फैमिस इन इंडिया, पृ० 82, 305 और ई एच II, पृ० 174. 359-60, 546, 548. आर० सी० दत्त ने लिखा 'जब इंग्लैंड की जनता की प्रति व्यक्ति आय 42 पौंड के मुकाबले भारतीय जनता की प्रतिव्यक्ति आय 2 पौंड है तो हम यूरोप भ्रमण की विलासिता के मजे लेने की बात सोच ही कैसे सकते हैं' (ई एच II, पृ० 548)
82. आगे देखिए.
83. इंडियन स्पेंडेंटर, 2 मार्च 1884, इन्दु प्रकाश, 21 अप्रैल 1884. ट्रिब्यून, 25 अप्रैल (बी० ओ० आई०, 15 मई 1884), युनाइटेड इंडिया, 11 अगस्त (वही, 31 अगस्त 1884), हिंदू, 29 अक्टूबर 1897, मराठा, 7 दिसंबर 1902, दत्त . फैमिस इन इंडिया, पृ० 305
84. इन्दु प्रकाश, 21 अप्रैल 1884 हिंदू 18 अप्रैल 1884; बगवामी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 16 अप्रैल 1887); वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 20, जी० एम० अथर इंडियन पालिटिक्स पृ० 188, 193, एम० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 270 मास्टर गाज़ियन के 5 नवंबर 1898 के अंक में (इंडिया के 11 नवंबर 1898 के अंक में) दत्त का पत्र; रेलों का रुपया बेजने में निम्न विनिमय दर के प्रभाव से भारत को होने वाले वास्तविक घाटे की समीक्षा के लिए देखिए, बेल - पूर्वोद्धृत, पृ० 243-4 चिमने . पूर्वोद्धृत, पृ० 312 और सान्याल पूर्वोद्धृत, पृ० 44, 120-1
85. एस० एन० बैनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 180, 189-90; इंडियन स्पेंडेंटर, 24 फरवरी 1884, इन्दु प्रकाश, 21 अप्रैल 1884. इंडियन नेशन, 21 अप्रैल (बी० ओ० आई०, 15 मई 1884), बिहार हेराल्ड, 22 अप्रैल और 29 अप्रैल (वही); जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 687 गोखले : स्पीचेज, पृ० 1194, दत्त : स्पीचेज I, पृ० 102. सायानी : एल० सी० पी०-1898, खंड XXXVII, पृ० 534
86. एस० एन० बैनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 190. ट्रिब्यून, 22 मार्च (बी० ओ० आई०, 15 अप्रैल 1884), इंडियन इको, 25 अप्रैल (वही, 15 मई 1884), बगवामी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 16 अप्रैल 1887); गोखले : स्पीचेज, पृ० 1193-4 और विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18390.
87. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 684; रानाडे : एसेज, पृ० 88. गोखले : स्पीचेज, पृ० 1194. जी० एस०

- अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 182. उनका 1898 में मुद्रा आयोग के समक्ष साक्ष्य, स्पीचेज I, पृ० 98, 100 ई एच II, पृ० 358-9, 370, 546-8
88. जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, इस वर्ष तक इस सबब में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विभक्त था 1884 में अथवा उसके उपरांत ही सभी प्रमुख राष्ट्रवादी सभाचारपत्रों, हिंदू, मराठा, इंडियन स्पेंडटेर ने अपना सारा ध्यान रेलों के प्रश्न पर ही केंद्रित किया
89. 1884 के उपरांत रेलों के प्रति यह विशिष्ट दृष्टिकोण लगभग सभी राष्ट्रीय विचारों में अंत-प्रविष्ट हो गया था, अधिकांशतः यह अस्पष्ट था पर कभी कभी स्पष्ट रूप भी ग्रहण कर लेता था, यह तथ्य पूर्वनिर्दिष्ट विवरण को देखने से स्वतः मिट्ट हो जाएगा इस दृष्टिकोण की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए देखिए इंडियन स्पेंडटेर, 17 फरवरी 1884, ट्रिब्यून, 1 मार्च (वी० ओ० आई०, 15 मार्च 1884), बिहार हेराल्ड, 22 और 29 अप्रैल (वही, 15 मई 1884), बगबासी, 29 मार्च और सोमप्रकाश, 30 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 1884); नवविभाकर, 21 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884), सहचर, 30 अप्रैल (वही 10 मई 1884), बगबासी 9 और 23 अप्रैल (वही, 16 और 30 अप्रैल 1884 क्रमशः), पंजाब अखबार, 29 दिसम्बर 1894 (आर० एन० पी० पी०, 5 जनवरी 1895), जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 684-5, वाचा विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 17503-04, 17546, 17613, 17616-8, गोखले (वही, प्रश्न 18147, 18392, जी० एस० अय्यर . वही, प्रश्न 18605, 18624-6 18630, 18963, 19011, 19560-1, 19564 इंडियन पालिटिक्स, पृ० 181-2, पंजाब अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 28 अगस्त 1897), हिंदू, 29 अक्टूबर 1897, मायाजी एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 534 दत्त स्पीचेज I. पृ० 101-2 स्पीचेज II, पृ० 31 केमर ए हिन्द, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 1903)
90. दत्त इंडियन पालिटिक्स पृ० 52 पोछे 81 पाद टिप्पणी में उद्धृत अनेक मतों में यह दृष्टिकोण भी अस्पष्ट है
91. दत्त . इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 143 स्पीचेज II, पृ० 31. फॉर्मिड इन इंडिया, पृ० 82, 305 और ई एच II, पृ० XVII. 1778, 375, 547-8, जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 264 जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 687-8. श्रीराम एल० सी० पी०-1904, खंड XLIII पृ० 510.
92. दत्त . स्पीचेज I, पृ० 102 और इंडियन पालिटिक्स पृ० 53 और देखिए, दत्त इंडियन पालिटिक्स, पृ० 52 और ई एच II, पृ० 174, 177, 358 1884 में जी० वी० जोशी ने शिकायत की कि प्रवर समिति ने विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए स्वदेशी अभिव्यक्ति को गौरव नहीं दिया (पूर्वोद्धृत, पृ० 669) तथा जी० के० गोखले ने विलबी आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में इस बात पर बल दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी रेलों के विस्तार की वकालत नहीं की है (विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18415-6)
93. बेल : पूर्वोद्धृत, पृ० 31 और 37.
94. एस० एन० बेंजर्जी . स्पीचेज I, पृ० 189, मराठा, 3 फरवरी 1884; बंगाल पब्लिक ओपीनियन, 24 अप्रैल (वी० ओ० आई०, 15 मई 1884), भारत मिहिर, 13 मई (आर० एन० पी० बग०, 24 मई 1884), सहचर, 9 अप्रैल (वही, 19 अप्रैल 1890), गुजरात दर्पण, 23 मई (आर० एन० पी० बब, 25 मई 1889), गोखले : स्पीचेज, पृ० 1193-4; जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 264-5 दत्त ने 'इस प्रथा को कलुषित' बताया, ई एच II, पृ० 546.
95. नौरोजी : एसेज, पृ० 108-09. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 691; मराठा, 3 फरवरी 1884, बर्दवान

संजीवनी, 22 अप्रैल, सहृदय, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 3 मई 1884), हिंदू, 10 अगस्त 1887. दत्त ने पार्लटन, मंसे और लाई सारेंस जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के वक्तव्यों को इसे प्रमाणित करने के लिए पुनरुद्धृत किया और कहा . रेलपथों के निर्माण में अपव्यय हुआ है, यात्रियों के सुख की उपेक्षा की गई है. यह कदाचित किसी भी देश के रेल उद्यम के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है (ई एच II, पृ० 353) और देखिए गोखले . विलंबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18392

- 96 1868 में ही दादाभाई नौरोजी ने इस प्रथा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे : 'युद्धों समझ नहीं आता कि प्रतिभूति प्राप्त निजी उद्यम का क्या अर्थ है, यह कौंसा उद्यम है जिसके खतरे और भार तो सरकार के दायित्व ही और कंपनी केवल लाभ की ही भागीदार बने (जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, खंड III 1869. स० 1, पृ० 13). उत्तर-पश्चिमी प्रांतों से निकलने वाली उर्दू पत्रिका 'रहब' ने प्रतिभूति रेलों को : 'भारतीय करदाताओं की बलि चढ़ाकर अंगरेज पूंजीपतियों को धनी बनाने का एक ढंग बताया' 8 सितंबर (आर० एन० पी० एन०, 14 सितंबर 1892) और देखिए, बगवासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 16 अप्रैल 1887)
97. पाद टिप्पणी 91, पीछे और 'इंडियन स्पेक्टेटर', 13 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 19 फरवरी 1881), बर्बई समाचार, 2 अप्रैल (वही, 2 अप्रैल 1881), नवविभाकर, 21 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 26 जुलाई 1884), बंगाली, 9 अगस्त 1884 हमारा विचार है कि इस स्थिति का वास्तविक कारण यह था कि उन्हें आशा थी कि प्रतिभूति के अभाव में निजी उद्यमों की सर्वजन विदित इनकारी से व्यवहार में नए रेलपथों का निर्माण हो ही नहीं पाएगा.
- 98 गोखले : स्पेचेज, पृ० 1194. दत्त . ई एच II, पृ० 549. 1886 में जोशी ने इस माग का एक दूसरा विश्लेषण प्रस्तुत किया पूर्वोद्धृत, पृ० 107-11 और देखिए, वाचा . रिप० आई० एन० सी०-1898, पृ० 103
- 99 जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 265 और एच० आर० मई 1903, पृ० 469.
100. नौरोजी : एसेज, पृ० 109 नौरोजी मसानी द्वारा पूर्वोद्धृत, पृ० 115-6 पर उद्धृत जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 108, 688, 693, इंडियन स्पेक्टेटर, 23 जन० (आर० एन० पी० बब०, 29 जनवरी 1881), रास्त गुफ्तार, 26 मार्च और बाबे क्रानिकल, 26 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1882), नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बंग०, 30 जून 1883), मराठा, 3 फरवरी, 2 मार्च और 20 जुलाई 1884, नेटिव ओपीनियन, 24 फरवरी 1884, सहृदय, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 10 मई 1884) और 18 सितंबर (वही, 28 सितंबर 1889), केसरी, 2 सितंबर (आर० एन० पी० बब०, 6 सितंबर 1884), ए० बी० पी०, 5 मार्च 1885, एच आर, मई 1903, पृ० 469.
101. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 693 और मराठा, 20 जुलाई 1884 क्रमशः और जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 263, 265.
102. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 693, केसरी, 2 सितंबर (आर० एन० पी० बब०, 6 सित० 1884).
103. जोशी . पूर्वोद्धृत पृ० 693 केसरी, पूर्वोक्त स्थल रास्त गुफ्तार, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 1 अप्रैल 1882); ए० बी० पी०, 5 मार्च 1885; वाचा : स्पेचेज, परिशिष्ट, पृ० 23, सहृदय ने तो 18 सितंबर 1889 के अंक में यहाँ तक सुझाव दिया कि रेलों के राजस्व से कुछ एक लाख करोड़ को हटाना अथवा कम करना संभव होगा. (आर० एन० पी० बंग०, 28 सितंबर 1889); जी० एस० अय्यर ने राज्य द्वारा निजी कर्पानियों को पट्टे पर देने की नीति के विरोध में यही तर्क प्रस्तुत किया. (ई ए, पृ० 265).

104. जी० बी० जोशी ने 1886 में इस योजना का समर्थन किया जिसके अंतर्गत वर्तमान प्रतिभूत राशियों को सरकारी खाते में सामान्य रेल ऋणों के रूप में बदलने और पुष्ट करने का सुझाव था। उन्होंने साथ ही यह टिप्पणी की कि लाभों के बड़े बड़े भागों के अतिरिक्त प्रतिभूत कंपनियों की अपेक्षा एकमात्र सरकारी ऋण पत्रों को प्राथमिकता देने से ही हमें प्रत्येक वर्ष 816,000 पाँड का विशुद्ध लाभ हो सकता है। (पूर्वोद्धृत, पृ० 107-11)
105. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 693.
106. आर० एन० पी० बंग०, 10 मई 1884. उसी आधार पर जी० एस० अय्यर ने राज्य पथो पर निजी कंपनियों पर प्राप्ति की। 1903 में उन्होंने लिखा कि वे तो पहले ही पर्याप्त सशक्त हैं और प्रायः स्वदेशी जनता के विरुद्ध पढ़ने वाले विदेशी निहित स्वार्थों से और भी वृद्धि करेंगे। (ई ए, पृ० 265).
107. रास्त गुप्तार, 26 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 1 अप्रैल 1882); नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बंग०, 30 जून 1883); केसरी, 2 सितंबर (आर० एन० पी० बंग०, 6 सितंबर 1884); मराठा, 20 जुलाई 1884. ए० बी० पी०, 5 मार्च 1885
108. इंडियन स्पेक्टेटर, 4 सितंबर 1881 : प्रत्येक स्थिति में यहूदी धनपतियों (सकेत राय चाइल्ड की ओर है) को लाने की अपेक्षा स्वयं भारतीयों को ही उपयोगी लोक कार्यों में प्रत्यक्ष रुचि लेनी चाहिए। यहूदियों का तो एकमात्र उद्देश्य सट्टा बाजार के लेन-देन के लाभों पर एकाधिकार करना है (आर० एन० पी० बंग०, 10 सितंबर 1881) और रानाबे. रीय्यू आफ फोसेट्स व्ही एसेज आन इंडियन फाइनांस, (जे० पी० एस० एस०, खंड III, सख्या 1 जुलाई 1880) पृ० 80 और पार्लियामेन्टरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक वर्क्स : जे० पी० एस० एस०, खंड IV स० I (जुलाई 1881) पृ० 15; रास्त गुप्तार और गुजराती, 11 सितंबर (वही, 17 सितंबर 1881): ए० बी० पी०, 18 अगस्त 1881; आर्यजन प्रिया, 1 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 1895); जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 193 4 और ई ए, पृ० 268; वाचा : विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 17536-7, 17546 गोखले : वही, प्रश्न 18147. पैसा अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 28 अगस्त 1897).
109. इंडियन स्पेक्टेटर, 5 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 11 अगस्त 1883); मराठा, 14 जनवरी 1883; हिंदू, 10 सितंबर 1889 सहचर, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 13 अप्रैल 1895); भारत जीवन, 30 मई (आर० एन० पी० एन०, 8 जून 1898).
110. मराठा, 14 जनवरी 1883; नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बंग०, 30 जून 1883); हिंदू, 3 अगस्त 1887 और 20 सितंबर 1889; मराठा, 7 दिसंबर 1902.
111. सहचर, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 3 मई 1884); वाचा : विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 17546 जी० एस० अय्यर : वही, प्रश्न 19564-7. इंडियन पालिटिक्स, पृ० 194
112. रास्त गुप्तार, 26 मार्च और बाबे अनिकल, 26 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 1 अप्रैल 1882); केसरी, 2 सितंबर (वही, 6 सितंबर 1884) मराठा, 20 जुलाई, 10 अगस्त 1884.
113. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 694. उन्होंने लोकहित के बड़े कार्यों के पबंध में लोगों को सबधित करने की नीति की भी बकालत की। (वही, पृ० 826).
114. पृ० 270.
115. तुलनीय : 1901-02 के बजट भाषण में लार्ड कर्जन ने कहा कि भारत में रेलों के साथ साथ हम सबैव सिंचाई के विषय पर भी विचार करते हैं। (स्पीचेज II, पृ० 281).

116. दि इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड III, पृ० 332 और 375-6.
117. एल० सी० पी०-1898 खंड XXXVII, पृ० 534.
118. दत्त : ई एच II, पृ० 550 तथा देखिए उनकी ई एच I, पृ० 312. ई एच II, पृ० 360, 362. स्पीचेज II, पृ० 45, 77-8
119. केसरी, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब, 13 मितंबर 1890) और 19 नव० (वही, 23 नवंबर 1901); हिंदुस्तान, 5 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०, 13 अक्तू० 1897) पी० ए० चारलू, एल० सी० पी०-1900 खंड XXXIX, पृ० 144 और एल० सी० पी० 1901 खंड XL पृ० 280. श्रीराम, एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII, पृ० 510 वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 576, 580; एस० एम० पटेल : रिप० आई० एन० सी०-1902, पृ० 229. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 26. कैसर ए हिन्द और गुजराती, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 1903); डेली हितवादी, 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 15 अप्रैल 1905)
120. वाचा : स्पीचेज, पृ० 25 लगभग तथा वाचा विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 17612-9.
121. आर० एन० पी० बब०, 29 अगस्त 1903. भारतीय मत को भी विस्तार से जानने के लिए देखिए : जामे जमशेद, 19 अगस्त (आर० एन० पी० बब; 26 अगस्त 1876); जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 678; नेटिव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब, 15 सितंबर 1883); इंडियन स्पेक्टेटर, 27 दिसंबर 1891. नेटिव ओपीनियन, 10 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 16 जन० 1892); लोकोपकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 15 सितंबर 1897); हिंदू, 29 अक्तूबर 1897 और 12 मई 1902; मायानी : एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII, पृ० 534; पैसा अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 28 अगस्त 1897); एन० के० आर० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०, 1901 पृ० 138-9; शशिलेखा, 27 मिनबर और स्वदेशमित्र, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम० 5 अक्तूबर, 1901); जनानुकूलन, 13 मई (वही, 13 जून 1903); किन्तना पत्रिका, 15 मई (वही, 21 मई 1904); गुजराती, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 1903); दत्त : ई एच II, पृ० 178, 270, 545 और स्पीचेज II, पृ० 31, 49, 60.
122. नेटिव ओपीनियन, 9 सित० (आर० एन० पी० बब, 15 मित०, 1883); जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 336, 856, 857, 866-7. दत्त : ई एच II, पृ० 171 और स्पीचेज I, पृ० 7.
123. रानाडे : पार्लियामेंटरी कमेटी आफ इंडियन पब्लिक वर्क्स : जे० पी० पी० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) पृ० 11. नेटिव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब, 15 सित० 1883); इन्डु प्रकाश, 30 नवंबर (वही, 30 दिसंबर 1904); दत्त : स्पीचेज II, पृ० 60-78.
124. ए० बी० पी० 14 नवंबर 1901; और भी, जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 336; वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 25 और सी० पी० ए०, पृ० 575, मायानी : एल० सी० पी०, 1897 खंड XXXVI पृ० 190; पी० ए० चारलू : एल० सी० पी० 1900 खंड XXXIX पृ० 144 और एल० सी० पी० 1903 खंड XLII पृ० 144-5; दत्त : फैमिस इन इंडिया, पृ० 82, स्पीचेज II, पृ० 60-1; श्रीराम : एल० सी० पी०-1904. खंड XLIII पृ० 510; बांबे क्रानिकल, 27 मार्च (आर० एन० पी० बब, 2 अप्रैल 1881); बांबे समाचार, 9 सित० और सांका वर्तमान 9 सित० (वही, 10 सितंबर 1904); हिंदू, 12 मई 1902.
125. बांबे समाचार, 28 जन० (आर० एन० पी० बब०, 28 जन० 1882); जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 697, शशिलेखा, 1 अक्तू० (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्तूबर 1897); स्वदेशमित्र,

- 30 अक्तूबर (वही, 30 नवंबर 1897); पी० ए० चार्ल्स : एल० सी० पी० 1901, खंड XL, पृ० 280; एन० के० ग्राह० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 138-9; वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 576-7, दत्त : ई एच II, पृ० 178, 366-7 और स्पीचेज II, पृ० 40, 60, 78. सायानी . एल० सी० पी०-1998, खंड XXXVII पृ० 534
126. 1898 में जी० एस० अय्यर ने लिखा वे (रेलें) मपदा का उत्पादन नहीं कर सकती, वे तो केवल उसके विनरण में सहायक हो सकती हैं. इसके विपरीत मिचार्ड कायं इस समय केवल एक फसल उगाने वाले किसान को दो फसलें उगाने के योग्य बना सकते हैं. (इंडियन पालिटिक्स, पृ० 182). 1901 में ग्राह० सी० दत्त ने अग्रजों की एक सभा में कहा : रेलें भारत के अन्न-सम्भरण में एक दाने तक की वृद्धि नहीं करती जबकि मिचार्ड कायं अन्न के उत्पादन को दुगना कर देने हैं, फसलों को बचाते हैं और अफाल रोकते हैं. (स्पीचेज II, पृ० 77) और भी इंडियन स्पेक्टेटर, 27 दिसंबर 1891, वाचा . स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 25 तथा सी० पी० ए०, पृ० 577; सायानी . एल० सी० पी० 1897 खंड XXXVI पृ० 189, हिंदू 12 मई 1902; दत्त : ई एच II, पृ० 174, 360, इन्दु प्रकाश, 30 नवंबर (आर० एन० पी० बब, 3 दिसंबर 1904)
127. नेटिव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब०, 15 सितंबर 1883), जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 697, मा० पी० एल० सी० पी० 1898, खंड XXXVII पृ० 534, कर्णाटक पत्रिका, 17 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 31 अक्तू० 1898), वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 578, 580, गुजराती, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 1903), जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 267; दत्त : ई एच II, पृ० 173-4. हा यह अवश्य है कि यह एकमात्र कसौटी नहीं थी मिचार्ड कायों के अकालनिरोधक होने के कारण अलापप्रद होने पर भी उनका निर्माण करना ही चाहिए. देखिए रानाडे पालियामेटरि कमेटी आन इंडियन पब्लिक वर्क्स जे० पी० एम० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) पृ० 26 और दत्त : ई एच II, पृ० 369, 573 और स्पीचेज II, पृ० 78. इन सब में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय भारतीय लेखकों ने बड़े परिमाण के सामग्रिक मिचार्ड कायों की आलोचना की और उन्होंने उनके स्थान पर छोटे पैमाने के कम खर्चवाले कुओं और तालाबों जैसे सिचार्ड कायों का समर्थन किया. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 867-8, वाचा स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 25, बगबासी 5 मई (आर० एन० पी० बब०, 12 मई 1894).
128. रानाडे : पालियामेटरि कमेटी आन इंडियन पब्लिक वर्क्स-जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881, पृ० 16, 25, 27, नेटिव ओपीनियन, 9 सित० (आर० एन० पी० बब, 15 सितंबर 1883); मल्लिकार्जुन, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्तूबर 1897); दत्त : ई एच II, पृ० 178, 366-7.
129. नेटिव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बब०, 15 सितंबर 1883); सायानी : एस० सी० पी० 1897, खंड XXXVI; मल्लिकार्जुन, 1 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्तूबर 1897).
130. दत्त : ई एच I, पृ० 312 और ई एच II, पृ० 545-6 और स्पीचेज II, पृ० 31, 60, 77.
131. आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त, 1903.
132. वही, 3 दिसंबर 1904 और देखिए, पी० ए० चार्ल्स : एल० सी० पी० 1900, खंड XXXIX पृ० 144; श्रीराम : एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII पृ० 510; केसरी .9 सितंबर (आर०

- एन० पी० बब, 13 सितंबर 1890), दैनिक हितवादी, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 15 अप्रैल 1905)
- 133 1877 में साइंस मैगज़ीन ने घोषित किया हमें सिंचाई को अकालों के व्यापक उपचार के रूप में नहीं देखना चाहिए (जान मरडोच फौमिन फौटस एंड फौलेसीस पर उद्धृत, पृ० 9) 1878 में पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी ने बड़े पैमाने पर सिंचाई योजना को रद्द कर दिया—दत्त ई एच I, पृ० 369 कुछ विशिष्ट सरकारी हलकों में आत्मसंतुष्टि थी कि रेलों के द्रुत प्रसार से अकाल की समस्या का समाधान हो गया था उदाहरण के लिए देखिए—चेसनी पूर्वोद्धृत, पृ० 343-4, 1896 व 1901 के बीच पड़े अकालों ने अवश्य ही इस आत्मसंतुष्टि को भग किया
- 134 कर्जन स्पीचेज I, पृ० 319 20
- 135 कर्जन स्पीचेज II पृ० 282
- 136 बाबा सी० पी० ए०, पृ० 577 8 आर सी दत्त ने सिंचाई के मामले में भारतीय आलोचना को सर्वथा सही बताते हुए कहा यदि इस आलोचना का भारत सरकार पर प्रभाव पड़ता तो भारत आने वाले अकालों से समय पर ही सुरक्षित हो जाता (स्पीचेज II, पृ० 60) और भी पृ० 31, 61, 78 और ई एच II, पृ० 370
- 137 इंपीरियल गेजेटियर (1908) खंड III, पृ० 353
- 138 कर्जन स्पीचेज IV, पृ० 101
- 139 मराठा, 23 अगस्त 1903 हिंदू, 20 अगस्त 1903, वायस आफ इंडिया, 22 अगस्त 1903, साप्ताहिक वर्तमान, 20 अगस्त (आर० एन० पी० बब 22 अगस्त 1903), कैमर ए हिंद, और गुजराती 23 अगस्त (वही, 23 अगस्त 1903), मद्रास स्टैंडर्ड्स 20 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 3 अक्टूबर 1903), दत्त ई एच II, पृ० 551-3
- 140 मराठा, 23 अगस्त 1903, कैमर ए हिंद, 23 अगस्त और गुजराती, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 23 अगस्त 1903)
- 141 यही कारण है कि रेलों का पुनर्जन्म की भूमिका उनकी कल्पना को पकड़ न सकी जैसा कि बाद में बुकनान ने भी कहा उन्होंने इसपर विचार किया है कि रेलें उत्पादन के लिए लंबी अवधि के लिए लाभप्रद होने की अपेक्षा हानिप्रद ही हैं—(पूर्वोद्धृत, पृ० 191-2) सचांग साघनो के प्रति आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के फलस्वरूप कृषि की भी क्षति हो रही है
- 142 बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन का 1888 का प्रतिवेदन, पृ० 62 और 58-9
- 143 वही, 1899, पृ० 4-5

अध्याय 6

शुल्क पद्धति

भारतीय हित यह अनिवार्य अपेक्षा करते हैं कि सैद्धांतिक रूप में एकदम गलत, व्यावहारिक परिणाम के रूप में अत्यंत क्षतिकारक तथा लागू होने पर आत्मविनाशक करों को नत्काल ही समाप्त लेना चाहिए।

—लाइ सैलिसबरी

जहां अगरेज उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता के संदेह का लेश भी है वहां ऐसे सिद्धांत और ऐसी नीतियां निर्धारित की गई हैं जिससे भारत के शिष्ट उद्योगों का जन्म से ही गला घुट जाए।

—फिरोजशाह मेहता

1880-1905 की अवधि से भारतीय नेताओं द्वारा चर्चित एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक विषय था, शुल्क पद्धति। इस विषय को भारतीयों ने जो महत्व प्रदान किया, उसका कारण औद्योगिक विकास तथा निर्धनता की समस्या के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। उनके विचार में निर्धनता की समस्या का उन्मूलन उद्योगीकरण की द्रुतगति पर निर्भर था। यह प्रक्रिया कपास और चीनी पर शुल्क संबंधी सरकारी नीति की प्रतिक्रिया और सैद्धांतिक स्तर पर उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत के प्रत्युत्तर पर आधारित थी। द्वितीय पक्ष का विवेचन तो भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्थापरक एक परवर्ती अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में हम केवल प्रथम पक्ष पर ही विचार विमर्श प्रस्तुत करेंगे।

कपास आयात शुल्क की समाप्ति, 1878-82

भारत के प्रशासन के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के हस्तांतरण के समय सूत और सूती लच्छियों पर 3½ प्रतिशत तथा सूती टुकड़ों सहित अन्य ब्रिटिश सामान पर तीन प्रतिशत शुल्क था। अन्य बाहरी देशों से आने वाले सामान पर इसका दुगुना शुल्क था। 1857 के विद्रोह से उद्भूत वित्तीय कठिनाइयों ने भारत सरकार को 1859 में सूत और सूती लच्छियों पर 5 प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाने को विवश कर दिया। आगामी वर्षों में सूत और लच्छियों पर शुल्क दस प्रति-

शत कर दिया गया। परन्तु ब्रिटिश व्यापारियों और कपास उत्पादकों के दबाव से शुल्क सुधार और कटौती की प्रक्रिया, विशेषतः सूती उत्पादनों पर, शीघ्र ही अस्तित्व में आ गई (1861 में सूती गुच्छियों और धागों पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और 1862 में घटाकर 3½ प्रतिशत कर दिया गया। 1862 में सूती टुकड़ों के सामान पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। 1864 में सामान्य आयात शुल्क घटाकर 6½ प्रतिशत और 1875 में 5 प्रतिशत कर दिया गया। इन सारे वर्षों में आयात शुल्क विशुद्ध रूप से राजस्व के उद्देश्यों से ही थोपे गए। इनके पीछे सुरक्षा की इच्छा का लेश मात्र भी नहीं था।

इतने पर भी 1874 के आसपास कपास शुल्क, जो निर्यात शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय में मुकाबले कुल राजस्व का आधा भाग बनता था, लंकाशायर के कपास उत्पादकों की कटु आलोचना का विषय बन गया।² 1874 में माचेस्टर के वाणिज्य सदन ने राज्य सचिव को एक विज्ञापन दिया, जिसमें शिकायत की गई थी कि कपास उत्पादन का संरक्षित व्यापार भारत में भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के लिए अलाभप्रद बनता जा रहा था। उन्होंने साथही सूती उत्पादनों पर आयात शुल्कों के हटाने की मांग की परन्तु नवंबर 1874 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि शुल्क संरक्षक थे। हा, उन्मुक्त व्यापार के लक्ष्य को नए रूढ़िवादी भारत सचिव लार्ड सेलिसबरी ने बड़ी प्रबलता के साथ समर्थन दिया और भारत सरकार से सूती सामान पर आयात शुल्कों के हटाने की आवश्यकता पर बराबर और बार बार बल दिया।³ उसने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर शुल्क का हटाना अत्यावश्यक था। उसने सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया कि संरक्षण कर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वीकृत उन्मुक्त व्यापार की सामान्य नीति के विरुद्ध थे। दूसरे, वे भारत में निर्यात को प्रतिबाधित करके ब्रिटिश उत्पादकों को हानि पहुंचाते थे। तीसरे, करों की वृद्धि में भारतीयों के जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से वे उनके हितों के विरुद्ध थे। अंतिम, वे पनपते भारतीय उद्योग के मजबूत हितों के विरुद्ध थे। उन्हीं के कारण वह कृत्रिम उत्तेजना के अंतर्गत कच्ची नींव पर विकसित हो रहा था। इन सबसे बढ़ चढ़कर उसने टिप्पणी की कि राजनीतिक कारण भी कपास करों के शीघ्र हटाने में समान रूप से आज्ञापरक थे। वास्तव में इस संबंध में उसके द्वारा प्रदर्शित सूक्ष्म चिंतन के कारण हम उसके मंतव्य को मूल रूप में विस्तार से पुनरुद्घृत करने के मोह का संवरण नहीं कर पाते :

अंगरेजों के हाथ से निकल कर क्रमशः भारतीयों के हाथ में आने की संभावना वाला भारतीय व्यापार जहां अंगरेजों के लिए कटु भावनाओं को जन्म देगा, वही भारतीयों के लिए अप्रत्याशित सुरक्षा की सफलता मिलने से उनमें तीव्र उत्सुकता उत्पन्न करेगा। अंगरेज उत्पादक बढ़ती हुई उत्कठा के साथ अपने लिए हानिकारक करों के हटाने के लिए दबाव डालेंगे और इसके लिए जितनी ही वे जल्दबाजी करेंगे, उतना ही अधिक भारतीयों को उसके महत्व का पता चलेगा... इस स्थिति में भी कुछ क्षोभ अभिव्यक्त होगा और भारतीयों के दावों की उपेक्षा करके अंगरेजी हितों को प्राथमिकता देने की नीति को इसका कारण माननेवाले

व्यक्तियों द्वारा और भी अधिक क्षोभ अभिव्यक्त किया जाएगा। यदि इस संबंध में कार्यवाही में विलंब हुआ तो क्रोध की मात्रा व्यापक रूप में उभर कर ऊपर आ जाएगी और यदि बहुत अधिक विलंब हुआ तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर सार्वजनिक खतरा बन जाएगा।⁴

जहां तक लार्ड सैलिसबरी का संबंध था, उसने 31 मई 1876 के संप्रेषण में इस सारे मतभेद को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार सुलझाया। उसने समग्र प्रश्न की पुनः परीक्षा करने के उपरांत घोषित किया कि भारतीय हितों की अनिवार्य अपेक्षा इन करों को हटाने की है। भारतीयों के अनुसार ये कर सैद्धांतिक रूप में एकदम गलत, व्यावहारिक प्रभाव के रूप में घातक तथा प्रवर्तन में आत्मघाती हैं। कपास पर कर हटाने के विरुद्ध एकमात्र तर्क राजकोष पर पड़ने वाला हानिप्रद प्रभाव था। इस संबंध में उसका कथन था कि जहां भारत सरकार इस निर्देश को क्रियान्वित करने में विवेक का परिचय दे, उसे भारतीय करदाता को प्रत्येक प्रकार के करों में गहृत देते समय इन करों के हटाने की ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत सरकार और वायसराय लार्ड नार्थब्रुक ने राज्य सचिव के सुझाव को महत्व नहीं दिया और कपास करों को इस आधार पर हटाना अस्वीकार कर दिया कि वे व्यावहारिक रूप में संरक्षक नहीं थे। परंतु विरोधियों का मुह बंद करने के लिए सरकार ने लंबे रेशोवाली रुई के आयात पर पाच प्रतिशत कर लगाने का निश्चय किया।

हां, कपास आयात करों का भाग्य उस समय पूरी तरह निश्चित हो गया जब 1875 में लार्ड नार्थब्रुक का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और लार्ड लिटन को उसके स्थान पर वायसराय तथा जान स्ट्रैची को वित्त सदस्य नियुक्त किया गया। ये दोनों राज्य सचिव की इच्छाओं का पालन करने को अत्यंत उत्सुक थे।⁵ उस समय (11 जुलाई 1877 में) हाउस आफ कॉमंस ने इस विषय का एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत में आयातित सूती उत्पादनों पर इस समय लागू कर अपने स्वरूप में संरक्षक होने के कारण सुदृढ़ वाणिज्य नीति के विरुद्ध है और ज्यों ही वित्तीय स्थिति अनुकूल हो त्यों ही यथाशीघ्र इन्हें हटा देना चाहिए।⁶ हा, अफगान युद्ध, अकालों की प्रवृत्ति तथा चादी के अवमूल्यन से उत्पन्न वित्तीय कठिनाई ने लार्ड लिटन और उसके विन मंत्री के उत्साह को किसी सीमा तक दबा दिया। फिर भी 1878 में कुछ अपेक्षाकृत मोटे प्रकार के सूती सामान पर करों में और 1879 में सिवाय 30 रेशोवाले सूत के, अन्य सभी प्रकार के सूती सामान पर कर हटा दिए गए। इसके उपरांत अवसर आया जब 1882 में बजट में 30 लाख पौंड का लाभ दिखाया गया और अधिकांश अन्य वस्तुओं पर करों के साथ कपास पर कर पूर्ण रूप से हटा दिए गए। केवल नमक, शराब, तरल पदार्थों, शस्त्रों तथा गोला-बारूद आदि पर विशेष कर रहने दिए गए।

अगले बारह वर्षों तक भारत में वास्तव में किसी प्रकार के सीमा शुल्क नहीं थे और वह किसी भी अन्य देश की अपेक्षा उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अधिक निकटता से अपना रहा था। यहां तक कि ब्रिटेन के पतन भी भारत के पतनों के समान स्वतंत्र नहीं थे। इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप उत्पादित आयात में वृद्धि हो रही थी।

इन आयातों का मूल्य 1878-9 से 1881-2 में 18 प्रतिशत, 1878-9 से 1884-5 में 45 प्रतिशत बढ़ गया। इन वर्षों में मूल्यों में निरंतर ह्रास हो रहा था अतः इस प्रकार भारत के आयात की परिमाणगत वृद्धि बहुत अधिक थी। निस्संदेह यह सब कुछ अन्य अनेक तत्वों और शक्तियों का भी परिणाम था परंतु निर्विवाद रूप में आंशिक रूप से यह आयात कर्ग के हटाने का फल ही था।⁷

कपास आयात शुल्क की समाप्ति का राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध

कपास आयात कर्गों के निवर्तन के आंदोलन के प्रारंभ में ही भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने एक मन न इतने अधिक रोष और उत्तेजना के साथ उनका विरोध किया कि आक्रमण के प्रमुख निशाने सर जान स्ट्रेची को बाद में वर्षों तक यह शिकायत बनी रही कि भारतीय लोकप्रिय धारणा राजकीय सुधारों के प्रश्न के संबंध में बाधक और नासमझ थी।⁸

1874 में जब माचेस्टर वाणिज्य सदन ने भारत में कपास कर्गों के हटाने की मांग की और राज्य सचिव ने इस मांग को भारत सरकार के पास भेजा तो बंगाल का 'सहचर' इसके विरुद्ध अत्यंत प्रचंडता से बग्स पड़ा।⁹ जनवरी 1875 में इसी प्रकार का विरोध ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा ने किया।¹⁰ सामाचारपत्रों ने भी 1875 में लंबे रेडोवाली कपास पर 5 प्रतिशत कर लगाकर और सूती वस्त्रों पर आयात कर घटाकर कपास शुल्क के आलोचकों को चुप कराने की सरकारी नीति की तीखी आलोचना की।¹¹ अगले वर्ष लार्ड सैलिमवरी द्वारा माचेस्टर वाणिज्य सदन को क्रमशः कपास कर घटाने के आश्वासन की समाचारपत्रों ने निंदा की।¹²

मार्च 1875 में कुछ मोटे सूती वस्त्रों पर कर हटाने की बहुत सारे समाचारपत्रों ने उग्र भर्त्सना की।¹³ और 1879 में भूरी कपास के सभी प्रकार के सामान पर करों की छूट का परिणाम समाचारपत्रों तथा लोक नेताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी निंदा के रूप में ही दृष्टिगोचर हुआ।¹⁴ क्रोध में जलने हुए मुरेन्द्रनाथ वैनर्जी ने प्रश्न किया: 'क्या अभी बलिदान की और आवश्यकता थी, क्या अभी देशवासियों के हितों का और अधिक प्रबल विनाश अपेक्षित था?'¹⁵ इसी प्रकार सहचर ने 23 मार्च 1879 के अंक में कठोर भाषा में इस कृत्य के लिए लार्ड लिटन की निंदा की। उसने लिखा: 'वास्तव में हम लार्ड लिटन के चरित्र का जितना अधिक अध्ययन करते हैं, उतनी अधिक हम उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है।' पत्र ने लार्ड लिटन की कर हटाने की कहानी को 'मानसिक दुर्बलता' बताया और आश्चर्य प्रकट किया: 'हमारी शोचनीय दशा के समय अपनी जाति के प्रति उसके द्वारा दिखाए गए पक्षपात के उदाहरण को हम कभी नहीं भूल सकेंगे।' ¹⁶

1880-1 में कपास पर अवशिष्ट कुल करों के निवर्तन की बातचीत के समय भारतीय समाचारपत्र और जन सभाएं एक बार पुनः भड़क उठीं। लार्ड हार्टिगटन द्वारा भारतीय बजट पर भाषण करते हुए की गई इस टिप्पणी ने आग में घी का काम किया कि कपास कर को हटाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का कोई भी अवसर खोया नहीं जाएगा और इससे राष्ट्रवादियों का विरोध और तीखा हो उठा।¹⁸ अंत में जब 1882 में

मेजर बेयरिंग ने कपास कर के पूर्णनिवर्तन की घोषणा की तो भारतीय लोकमत ने एकमत से इस कार्यवाही से असहमति प्रकट की।¹⁹ कुछ आलोचकों ने तो अपेक्षाकृत कठोर भाषा में अपने को अभिव्यक्त किया। अमृत बाजार पत्रिका ने 6 अप्रैल 1882 के अंक में लिखा : आयात कर का निवर्तन एक पाप है और हम फिर बार-बार कहते हैं कि इसे न्यायोचित सिद्ध करने की कोई भी चेष्टा अपने आपको घोर पातक के शिखर पर पहुँचाने की चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगी। फिर भी कुल मिलाकर बेयरिंग की कार्यवाही के विरुद्ध राष्ट्रीय ममीक्षा अपेक्षाकृत हलकी ही थी। इसका आशिक कारण यह था कि इसकी पूर्व मूचना दी जा चुकी थी। उसका त्वचा विदारण किया जा चुका था और तार-तार करके उसकी आलोचना भी की जा चुकी थी और इसके अतिरिक्त यह किसी भी रूप में वस्तुतः भारतीय कपड़ा उद्योग को प्रभावित ही नहीं करता था क्योंकि इसका संबंध बढ़िया स्तर के सूती सामान से था और उस समय भारतीय मिलें उल्लेखनीय परिमाण में बढ़िया सूती सामान का उत्पादन ही नहीं कर रही थी। भारतीय मयन आक्रमण का एक अन्य प्रमुख कारण कदाचित् लार्ड रिपन और मेजर बेयरिंग की भारतीय जनता में व्यापक लोकप्रियता और भारतीयों की उन महानुभावों को राजनीतिक दृष्टि से परेशान न करने की उत्सुकता थी।²⁰

कपास कर के निवर्तन का विरोध करते हुए भारतीय नेताओं ने अपने विरोधियों द्वारा प्रस्तुत इस प्रमुख आधार का कि ये कर भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करते हैं खंडन किया। एक ओर उनका कथन था कि कपास कर अपने स्वरूप में ही उद्योग के सर्वथा संरक्षक नहीं थे क्योंकि भारत अधिकांश आयात किये जाने वाले उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्रों का उत्पादन ही नहीं करता था। भारतीय मिलें तो मोटे कपड़े के उत्पादन में विशेष निपुण हैं और उस मोटे कपड़े का आयात नहीं होता था। भारतीय मिलों को मोटे कपड़े के आयात की कुछ प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिन्हें कपास करों के निवर्तन से दुर्बल नहीं किया जा सकता।²¹ दूसरी ओर उनका सुदृढ़ मत था कि विशुद्ध राजस्व के उद्देश्यों की दृष्टि से करों की बड़ी आवश्यकता थी, वस्तुतः भारतीय वित्तों के स्वरूप की दृष्टि में तो ये कर आवश्यक ही थे।²² उसका तर्क था कि कपास करों के समान अदुःखप्रद तथा हानिकारक अन्य कोई राजस्व का स्रोत ही नहीं था। भारत के वित्तों की स्थिति के निराशाजनक और अव्यवस्थित होने के कारण उनका भय था कि कपास करों के निवर्तन से हुए घाटे की पूर्ति जनता से और अधिक ऋण लेने और धनौने किस्म के कराधान उपाय से ही की जाएगी और वस्तुतः की जा रही थी।²³ कुछ भारतीयों ने टिप्पणी की कि नमक कर तथा अनुज्ञप्ति करके अधिनियम ग्रंथ में रहने पर कपास करों को हटाना सर्वथा अन्यायपूर्ण था।²⁴ यह भी पर्याप्त आश्चर्यजनक है कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने जिस सास में कपास करों के स्वरूप को असंरक्षक माना था, उसी सास में उन करों के निवर्तन को भारतीय वस्त्र उद्योग पर हानिप्रद प्रभाव डालने वाला भी कह दिया।²⁵ इस प्रकार से उन्होंने निहितार्थ द्वारा इन करों के संरक्षक स्वरूप को अस्वीकार किया अन्यथा और किसी भी रूप में उनके निवर्तन से भारतीय उद्योग को वास्तव में होने वाली क्षति सिद्ध नहीं की जा सकती थी। कुछ ने तो खुले तौर पर मान

लिया कि आयात कर संरक्षक थे और उम रूप में सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसा हम आगे के अध्याय में दिखाएंगे, लगभग सभी भारतीय नेताओं ने अध्ययन काल में उद्योगीकरण के उन्नयन के लिए संरक्षण के महत्व और उपयोग की वफा दान की।

राजनीतिक अर्थ

प्रारम्भिक राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा संघर्ष के हेतु लिए गए थोड़े से सार्वजनिक विषयों में से एक था, कपास आयात करों के निवर्तन का विरोध। वर्षों तक संगठित रूप में बुद्धिमत्तापूर्वक तथा सतर्क होकर इसका अनुसरण किया गया परन्तु संघर्ष का अंतिम परिणाम उन्हें कुठित करने वाला ही निम्न था। पग-पग पर उनके दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई, उसे ठुकराया गया और अंत में कपास आयात कर पूर्ण रूप में हटा दिए गए। इसका परिणाम शासकों के प्रति कटु प्रवृत्ति तथा शत्रुता की भावना के विकास और प्रसार के रूप में ही सामने आया। बहुत सारे उदीयमान भागनीय नेता शनैः शनैः शासकों की सद्भावना में मदद करने लगे और समुचित राजनीतिक निष्कर्ष निकालने लगे।

स्पष्ट रूप से देश के हितों के विरुद्ध दिखाई देने वाली नीति के प्रवर्तन ने राष्ट्रवादियों को यह पूछने और इस मन में इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने पर विवश कर दिया कि यह नीति क्यों लागू की जा रही है? उनके अनुसार सरकार की कर नीति का मुख्य आधार न तो भारतीय जनता का हितचिन्तन था और न ही उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत का वास्तविक परिपालन। वस्तुतः इस सबके विपरीत भारतीय वस्त्र उद्योग में द्रुतविकास से लकाशायर के उत्पादकों के हृदय में भड़कती हुई ईर्ष्या ही इसका कारण थी। वे यह भी विश्वास करने लगे कि इंग्लैंड के दोनों राजनीतिक दल लकाशायर में राजनीतिक समर्थन पाने के इच्छुक थे अतः इंग्लैंड में दलगत राजनीति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कपास करों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप में हटाने के रूप में शक्तिशाली लकाशायर के हितों के आगे भारतीयों के हितों की बलि चढ़ानी पड़ रही थी।⁴⁶ उदाहरणार्थ, 15 दिसंबर 1875 को बोध सुधारक ने अपने, 'माचेस्टर के स्वार्थी व्यापारी और उनके कर्तव्यबद्ध सेवक भारत राज्य सचिव' शीर्षक संपादकीय में यही दृष्टिकोण प्रकट किया।⁴⁷

यहां तक कि जुलाई 1881 को जस्टिस रानाडे को यह कहना पड़ा कि अनुदार राजनीतिज्ञों ने अपने कार्यालय में उन्मुक्त व्यापार के नाम पर भारत के हितों की बलि चढ़ाई है और माचेस्टर को प्रसन्न करने के लिए 250,000 पौंड भारतीय राजस्व की राशि उसकी सेवा में भेंट की है।⁴⁸ इसी प्रकार 1880 में पटना की एक जन सभा में पूना सार्वजनिक सभा के रुढ़िवादी अध्यक्ष राव बहादुर के. एल. नुलकर ने क्रुद्ध होकर टिप्पणी की

इस बात को समझने के लिए कि इंग्लैंड में बैठकर भारत के भाग्य पर नियंत्रण रखने वाले अपनी नियुक्ति की अवधि को लंबा करने के लिए तथा अपने कोष की सुरक्षा के लिए किस प्रकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें केवल इस बात पर विचार करना है कि माचेस्टर का अनुग्रह पाने के लिए ही अभी हाल ही

मे कपास आयात करों से प्राप्त होने वाले हमारे राजस्व की बलि चढाई गई है।¹⁰ बंगाली ने 11 मार्च 1882 के अंक में न केवल ग्लैडसन की उदारवादी सरकार की अवशिष्ट कपास आयात करों के हटाने की कार्यवाही की ही निंदा की, प्रत्युत उसके इस कार्य को करने के दमो डग की भी भर्त्सना की। उसने लिखा 'करो को हटाने का निर्णय सर्वथा निराधार है, इसमें कपट और बनावट की गंध आती है। यह हमें रोष दिलाने वाली गलती को व्यापार उत्कर्ष बताने की बहानेबाजी है।

जहा ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीयों के तर्कों की ओर उनके प्रचंड विरोध की उपेक्षा करना ही ठीक समझा¹⁰, वहा भारतीय नेता कपास करों के निवर्तन पर लबी खिच गई मुठभेड़ के राजनीतिक निहितार्थ की गहराई में उतरने लगे। इससे पूर्व उनके चिंतन का जो डग था और बहुत सारे मामलों में आगामी वर्षों में भी जो चिंतन पद्धति उन्हें अपनाती थी वह यह थी कि अब तक वे अपने सभी प्रकार के कुप्रशासनों का दायित्व भारत में स्थित अंग्रेज अधिकारियों के कंधों पर डालते थे क्योंकि भारतीय नेता इन अधिकारियों को शैतान समझकर उनसे घृणा करते थे और यह मानते थे कि ये लोग अपने स्वार्थ के कारण दयालु रानी, लोकतंत्रीय संसद और स्वतंत्रता प्रेमी अंगरेजों के उदार आदेशों को लागू करने में असफल रहे हैं परंतु अब शीघ्र ही जनता को कपास करो पर मतभेद में सत्य आने लगा कि इस विषय में नौकरशाही ने जहा न्यूनाधिक रूप से भारतीयों का पक्ष लिया था, वहा ब्रिटिश सरकार और संसद न शैतान की भूमिका निभाई थी।¹¹ इसने बहुत सारे भारतीयों को इस विषय की परीक्षा करने और कदाचित् प्रथम बार इस व्यापक स्तर पर अपने शासकों की सद्भावना और भारत में ब्रिटिश शासन के वास्तविक लक्ष्य और प्रयोजन पर विचार करने को विवश कर दिया। इस चिंतन के फलस्वरूप वे इस दुःखद निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत पर अंगरेजों के शासन का प्रधान उद्देश्य भारतीयों के हितों की अपेक्षा ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों का हित-साधन ही था।

1875 में 'बेलगाव समाचार' ने अपना मत अभिव्यक्त किया कि राज्य सचिव द्वारा माचेस्टर वाणिज्य सदन को दिए गए आश्वासन कि अंगरेजी वस्त्रों पर आयात कर हटा दिए जाएंगे, ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति का ही एक प्रमाण है। सरकार जो भी काम करती है, डोग तो भारत के हित का करती है पर वास्तव में वे सब होते शासक जाति के हित में ही हैं।¹² भोलानाथ चंद्र समस्या का निर्भीक और विस्तृत विश्लेषण करनेवाले कदाचित् प्रथम भारतीय महानुभाव थे। उन्होंने 1876 में लिखते हुए प्रारंभ में ही यह स्वीकार किया कि इस सारे मतभेद में विचारणीय विषय, आयात कर, अपने आप में इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे; क्योंकि सत्य यह है कि आयात कर भले ही हटा दिए जाएं भारत का वस्त्र उद्योग तो फिर भी अपनी प्राकृतिक अनुकूल स्थितियों के कारण फले फूलेगा। राष्ट्र द्वारा विचारणीय विषय तो यह है कि देश में उसके अपने हितों के अनुकूल शासन चलना है अथवा इंग्लैंड के हितों के अनुकूल। उन्हें यह अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भारतीयों ने जो महत्वाकांक्षाएं सजो रखी थी कि अब उनके लिए सौभाग्य के सूर्य का उदय होने वाला है, उसका उत्तर सर्वथा और पूर्णतः नकारात्मक ही था।

1858 का वचन भूगतृष्णा ही सिद्ध हुआ था और यह विश्वास कि एक व्यापारी कंपनी के हाथ से ताज के हाथ में प्रशासन के हस्तांतरण से प्रशासन की प्रकृति और उसके उद्देश्यों में परिवर्तन आ जाएगा, बालू की भीत पर टिका सिद्ध हुआ है। उन्होंने लिखा :

सुधार, और एक सुव्यवस्थित शासन और नई भूमिका के स्थान पर निश्चयात्मक रूप से पिछड़ापन ही मिला है। वही जाति की अपनी जाति के प्रति सहानुभूति दिखाई देती हैं। वही भारतीयों के हितों की अनुरूपता में इंग्लैंड के हितों की निरंतर स्पष्ट स्वीकृति है, वही लूट-खसोट और छीना भपटी की भावना है और भारत को 1776 में विद्यार्थी की अवस्था में रखने का जो संकल्प था, वही 1876 में भी विद्यमान है।³³

भोलानाथ चंद्र ने व्याख्यान दिया कि मचमुच लोगों को माचेस्टर की विजय में अमूल्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इससे नग्न रूप से पता चलता है कि सारा भारत मिलाकर भी कपास की कटाई-बुनाई में माचेस्टर के समकक्ष नहीं है।³⁴ तीन वर्षों के उपरांत एस० एन० वैनर्जी ने आलंकारिक रूप से देशवासियों के आगे प्रश्न उपस्थित करते हुए उनसे पूछा : यदि हमारी अपनी सरकार होती तो क्या वह सरकार लोकमत का इस प्रकार सर्वथा निरादर करती हुई और देशवासियों के हितों की पूर्ण उपेक्षा करती हुई ऐसा काम करने का साहस करती ?³⁵ इसी कठोर सत्य की अभिव्यक्ति मगठा ने 18 सितंबर 1881 के अंक में निम्न टिप्पणी करते समय की कि भारत का स्थान साम्राज्य में समानता का न होकर एक विजित राष्ट्र का था। उसने इस बात पर विशेष बल दिया कि माचेस्टर के हितों के लिए भारत के हितों का बलिदान तो प्रत्येक विजित राष्ट्र द्वारा विजेता राष्ट्र को बिना शिकायत किए चुकाए जाने वाले दंड का ही रूप था। मगठा ने यह संकेत किया कि वस्तुतः दुख का मूल कारण विदेशी शासकों का अमुक अथवा अमुक कृत्य न होकर देश की यथार्थ मौलिक राजनीतिक स्थिति ही थी।

लार्ड रिपन ने 1882 में कपास करों का निवर्तन भारतीयों के सामान्य हित में होने के निश्चित मतव्य का पुनः समर्थन किया। उसने साथ ही इस बात का भी दावा किया कि वह भारतीयों के लाभ के लिए भारत के हित में ही भारत पर शासन का इच्छुक है।³⁶ 'बंगाली' ने 11 मार्च 1882 में अंक में तुरंत उत्तर दिया : 'भारत के लिए ही भारत पर शासन की चर्चा अपने आप में मुंदर हो सकती है परंतु हमारे शासक यह नहीं भूल सकते... कि वे अंगरेज हैं और उन्हें अवश्यमेव एक निश्चित परिमाण में प्रत्येक मूल्य पर अंगरेजों को लाभान्वित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार ही सरकार चलानी चाहिए।' अमृत बाजार पत्रिका ने एक बार फिर अपने 6 अप्रैल 1882 के अंक में भारत की राजनीतिक दासता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उसका उपचार इस प्रकार में सुझाया : 'ब्रिटिश यूरोप के अपने संबंधी देशों को उन्मुक्त व्यापार का वरदान 'दान नहीं कर सकता और अपने उपनिवेशों में भी यह उदारता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वे अपने शासक आप हैं।' 'परंतु भारत एक असहाय देश है, उसके संपूर्ण दुर्बल और शक्तिहीन है।' ³⁷ बहुत वर्षों के बाद कपास करों के निवर्तन की चर्चा करते हुए आर० सी० दत्त ने लिखा : भारत में ब्रिटिश प्रशासकों ने बंबई के शिशु कपास उद्योग को ईर्ष्या से न देखकर उसके प्रति

संतोष ही प्रकट किया परंतु भारतीय प्रशासन के संबंध में तो वे बेचारे ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश मतदाता के ही दाम थे।¹⁸

इस समालोचना का एक समाहित तत्व यह था कि भारत सरकार को ब्रिटिश व्यापारियों के नियंत्रण में मुक्त कराया जाए ताकि भारत के अनुकूल कर नीति अपनाई जा सके। सहचर के 22 मार्च 1882 के अंक में निर्दिष्ट सरकारी कोष को नियंत्रित करने की शक्ति भारतीयों को हस्तांतरित करने की मांग भी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत की गई।¹⁹ चार वर्षों के उपरांत इसी पत्र ने आग्रह किया कि यदि भारतीय आयात करों को पुनः लागू करना चाहते हैं तो उन्हें अंगरेजी उपनिवेशों, कनाडा और आस्ट्रेलिया द्वारा किए गए संघर्ष के समान स्वशासन के लिए संघर्ष का पथ ही अपनाना चाहिए। इसी प्रकार 17 जनवरी 1886 के अंक में मराठा ने घोर निराशा के साथ लिखा कि एक व्यापारी देश के विदेशी शासन में आयात करों के दोबारा बहाल होने की आशा हम कभी नहीं कर सकते।¹⁹

भारतीय नेताओं को इस समय अपने आप सूझा कि भारतीय उद्योग पर कपास करों के निवर्तन से होने वाले हानिप्रद प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने का एक अन्य उपाय था, विदेशी वस्त्रों को न खरीद कर स्वदेशी को अपनाने के रूप में स्वेच्छा से अपने उद्योग को संरक्षण प्रदान कर। स्वदेशी का एक बहुत बड़ा गुण यह था कि राजनीतिक दमन की स्थिति में भी इसे अपनाना संभव था। हमें यहां स्वदेशी के प्रचार के राष्ट्रवादी प्रयत्नों की समीक्षा के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम पहले ही इसी पुस्तक के तृतीय अध्याय में इसका विवेचन कर चुके हैं।

आयात करों का पुनः आरोपण

1882 में आयात करों के पूर्ण निवर्तन के समय लार्ड रिपन ने यह पवित्र आशा प्रकट की कि अब इस कार्यवाही में भारत और इंग्लैंड की जनता में वर्गों से विद्यमान इस प्रश्न से संबंधित अप्रिय मतभेद समाप्त हो जाएंगे।²¹ परंतु भारत के पक्ष में बोलने का दावा करने वाले कामल न हो पाए और बाद में उन्होंने वर्षों तक, वस्तुतः तब तक, जब तक कि राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा, कपास करों के निवर्तन को राष्ट्रीय कटु समालोचना के प्रहार का प्रिय लक्ष्य बनाए ही रखा। ऊपर परीक्षित सभी पक्षों पर आग्रहपूर्वक कह चुकने के उपरांत राष्ट्रीय नेता दोहराते थे, 'कपास करों का परित्याग 'राष्ट्रीय अन्याय का एक उदाहरण है', एक घटिया किस्म का विश्वासघात है, और भारतीय हितों को ब्रिटेन के हितों के अधीन करने का एक प्रमाण और उदाहरण है।²² इसके अतिरिक्त स्वल्पतम उत्तेजना के अवसर पर और प्रायः वित्तीय संकट की प्रत्येक घड़ी में नमक कर तथा आय कर जैसे अन्य करों को लगाने के समय अथवा अकाल अनुदान को समाप्त करने और राज्य सरकारों की निर्दिष्ट राशि में कटौती करने जैसे लोकहित के खर्चों में छंटनी के समय वे प्रायः इस सबके बदले कपास पर आयात कर पुनः लगाने की मांग प्रस्तुत करते थे।²³

एक लंबे और कटु संघर्ष के बाद भारतीयों को प्राप्त कर नीति संबंधी विजय मिली

तो किंतु वह अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। विनिमय की घटती दर, रेलों के द्रुत गति से निर्माण तथा भारी पड़ते हुए सैन्य व्यय ने भारत सरकार के वित्तीय साधनों पर निरंतर इतना अधिक दबाव डाला कि सरकार नए करों का सहारा लिए बिना वांछित वित्तीय संतुलन लाने में सफल ही नहीं हो सकती थी। अंततः 1894 में 3½ करोड़ घाटे का सामना करते समय नए कराधान का मामला बहुत गंभीर हो गया। निराशा की स्थिति में राजस्व के नए स्रोत को खोजते हुए सरकार ने 1892 की भारतीय मुद्रा समिति द्वारा दी गई मलाह पर अमल करने का निश्चय किया। समिति की राय थी कि आयात करों के भारत में विरोध की कम से कम संभावना थी। फलतः मार्च 1894 में सभी आयातों पर सामान्य रूप से पांच प्रतिशत कर की व्यवस्था वाला नया कर अधिनियम लागू किया गया। राज्यसचिव के आदेश से लंकाशायर के हितों को ध्यान में रखते हुए सूती वस्त्रों, सूत और धागे को इस नए अधिनियम की क्षेत्र सीमा से मुक्त रखा गया।¹⁴

इस नए अधिनियम के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की समीक्षा हमने आगे एक पृथक भाग में प्रस्तुत की है। यहां हम केवल नए कर अधिनियम की क्षेत्र सीमा से सूती सामान को पृथक रखने के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के विवेचन तक ही अपने को सीमित रखेंगे। इस पृथक्करण ने देश में विरोध का एक तूफान सा खड़ा कर दिया। विधान परिषद में भारतीय सदस्यों ने कर अधिनियम की क्षेत्र सीमा से सूती सामान को बाहर रखने के रूप में बड़े गलत काम के लिए उम बिल का प्रचंड विरोध किया।¹⁵ अनेक सार्वजनिक संस्थाओं ने स्मारपत्रों और विज्ञापनों के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया। देश के विभिन्न भागों में इसके विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए जन सभाओं का आयोजन किया गया।¹⁶ समाचारपत्रों ने तो कपाम करों की रक्षा के लिए कगार कस ली।¹⁷

राष्ट्रवादियों का कथन था कि सूती सामान विशेषतः उत्कृष्ट कोटि के सूती सामान पर आयात शुल्क को विशुद्ध रूप से वित्तीय स्वरूप का होना उचित था न कि संरक्षक स्वरूप का; क्योंकि व्यावहारिक रूप से भारतीय मंडी में अधिकांश आयातित अंगरेजी सामान में और भारतीय मिलों द्वारा उत्पादित सामान में किसी प्रकार की प्रतियोगिता ही नहीं थी।¹⁸ अधिकांश का तो विश्वास था कि किसी भी रूप में भारत जैसे पिछड़े देश में उसके उद्योगों को सुरक्षित संचालन और उन्नयन के लिए संरक्षक शुल्कों के आधान में कोई गलती नहीं।¹⁹

आयात शुल्क से सूती सामान की छूट को भारतीय नेताओं ने निस्संकोच रूप से इंग्लैंड के शासक दल और मंचेस्टर के हितों के लिए भारतीय हितों के बलिदान का एक अन्य दृष्टांत बताया। अत्यंत संयमी 'पूना सार्वजनिक सभा' तक को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि भारतीयों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकना कठिन है कि यह छूट स्वार्थी और निरर्थक चीख पुकार करने वाली अंगरेजी व्यापारियों की एक संस्था के लिए रियायत है।²⁰ वस्तुतः बहुत सारे भारतीय नेताओं ने तो इस दुर्घटना से विदेशी शासकों की उपर्युक्त राजनीतियों के संबंध में मूल्यवान पाठ ही सीखा। एडवोकेट ने अपने 30 मार्च 1894 के अंक में टिप्पणी की: लंबे और क्रोधपूर्ण विवादों के फलस्वरूप लागू किए गए अधिनियम के प्रवर्तन ने भारत में विदेशी शासकों के गुप्त इरादों पर भयावह प्रकाश डाला

है।⁵¹ प्राप्त निष्कर्ष की मृदु अभिव्यक्ति यह भी कि भारत की अंगरेजी सरकार भारत के लोगों के हितों की अपेक्षा अपने देश के हितों की अधिक फिक्र करती है।⁵² 18 मार्च 1894 को पूना में हुई एक जनमभा में स्वीकृत प्रार्थनापत्र में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रार्थियों ने इस टिप्पणी के उपरान्त कि सारी दुर्बोध नीति कगरे में कपास शुल्क को मुक्त करके सुस्पष्ट कर दी गई है, अपने विचार प्रकट करते हुए कहा 'अब यह पता चल गया है कि क्यों सरकार भारत के खनिज और उत्पादन स्रोतों के विकास में उसकी सहायता के लिए उंगली नहीं हिलायेगी। यह लकाशायर गुट से निकलने वाले आदेश की आज्ञाकारिता है। भारत के अनुकूल औद्योगिक विकास की राष्ट्रीय नीति के बजाय, जिससे सरकार प्रयत्न-पूर्वक कतराती है, यहाँ तो केवल विदेशी उत्पादकों के लिए ही अनुकूल औद्योगिक विकास नीति अपनाई जा रही है।'⁵³ 'दैनिक औ समाचार चद्रिका' ने उस समय इस भावना को बड़ी तीखी भाषा में प्रकट किया, जब उसने महिमामयी महारानी की सरकार को व्यंग्य-पूर्वक यह सलाह दी कि वह स्पष्ट भाषा में यह घोषणा क्यों नहीं कर देती कि भारत न्यूनाधिक रूप में केवल इंग्लैंड द्वारा लूटने के लिए निर्धारित प्रदेश है इसके अनिश्चित और कुछ नहीं।⁵⁴ वगबासी ने अपने 17 मार्च 1894 के अंक में प्रकाशित, 'दि मास्क हैज फालन आफ' शीर्षक लेख में अपनी सामान्य जागरूकता के साथ राष्ट्रीय भावना का संक्षेप में इस प्रकार उद्घाटन किया

कपास शुल्क के प्रश्न के मदर्म में भारत में विदेशी अंगरेजी प्रशासन के चेहरे से नकाब हट गई है। देश के उच्च अधिकारी, नहीं नहीं, मारा सरकारी तंत्र जो आज तक यह शेखी बघारता रहा है, इंग्लैंड के प्रमुख समानाग्रपत्र जो डींगें हाकते रहे हैं कि हम भारतीयों के कल्याण के लिए और भारतीयों के हित में भारत पर शासन करते हैं, वह सब खोखला सिद्ध हो चुका है। उन्हें अब यह लज्जाजनक आत्मम्बीकृति करनी ही पड़ेगी कि भारत का प्रशासन इंग्लैंड के व्यापारियों के हित के लिए ही है।⁵⁵

यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि सरकारी नीति के उत्तर में 22 मार्च 1894 के 'हिंदू पत्र' ने और 18 मार्च 1894 के 'अरुणोदय' ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे नए कर अधिनियम से सूती सामान को मुक्त रखने के अपने शासकों के उद्देश्य को विदेशी सूती उत्पादकों को न खरीदने के अपने दृढ़ संकल्प द्वारा धूल में मिला दें।⁵⁶

1894 और 1896 के कर और कपास शुल्क अधिनियम

आयात करों से सूती सामान को दी गई छूट के प्रति विरोध इतना उग्र था कि लार्ड एलगिन को भारतीय आलोचकों को संतुष्ट करने की आवश्यकता अनुभव हुई और उसने घोषणा की कि यह आवश्यक रूप से अंतिम प्रबंध नहीं है।⁵⁷ यह प्रबंध वास्तव में अल्पकालिक सिद्ध हुआ। एक बार फिर वित्तीय आवश्यकताओं ने भारत सरकार को दिसंबर 1894 में नए कराधान के लिए विवश कर दिया। इस समय सूती कपड़ों और सूती धागों पर 5 प्रतिशत आयात कर लगा दिया गया परंतु इसके साथ ही भारतीय बिजली करधों से उत्पादित 20 नंबर अथवा उससे ऊंचे नंबरवाले सूत पर प्रतिशोधपरक 5 प्रतिशत

उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। यह उत्पादन शुल्क, किसी भी देश के आर्थिक इतिहास में अविद्यमान चुगीकर, राजस्व के प्रयोजन में नहीं थोपा गया था प्रत्युत नए आयात करों से भारतीय उद्योग को किसी प्रकार में लकाशायर के हितों के विरुद्ध संरक्षण मिलने की संभावना के तत्त्व को निर्मूल करने के लिए ही थोपा गया था। वास्तविकता यह है कि यह शुल्क लगाने से पूर्व स्वयं भारत सरकार इस कदम के औचित्य से महमत नहीं थी। 1878 में मेजर जान स्ट्रेची ने सीमा शुल्क को 'महंगा, दुःखदायी, और अमुविधाजनक' और 'अधिकांश स्थितियों में भारत में अव्यावहारिक' होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। यद्वा तक कि 1894 में वित्त मन्त्रि जेम्स वेस्टलैंड ने भारत मन्त्रि बोर्ड में प्रेषण में इस तथ्य की ओर निर्देश किया, 94 प्रतिशत भारतीय उत्पादन तो माचेस्टर के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता की सीमा क्षेत्र के ही बिलकुल बाहर है क्योंकि वे तो मोटे स्तर के वस्त्र (24 नंबर और इससे अधिक ऊँचे) का उत्पादन करते हैं और माचेस्टर भारत के समान इस स्तर के वस्त्रों को मसने में बेचने का दम नहीं कर सकता। उसने सलाह दी कि यदि यह दुःखदायक शुल्क लगाना ही है तो इसे 24 नं० के ऊपर के स्तर के सूती धागों पर लगाना चाहिए। परंतु राज्य मन्त्रि का आदेश था जिसमें विवश होकर सरकार को 20 नंबर में ऊँचे स्तर के सूत पर उत्पादन शुल्क लगाना पड़ा। इस प्रकार भारतीय मिलों के कुछ उत्पादन का 20 प्रतिशत इस शुल्क के क्षेत्राधिकार में आ गया। कपास शुल्क बिल पर भाषण करते हुए जेम्स वेस्टलैंड ने क्षमा प्रार्थना करते हुए स्वीकार किया कि सरकार ने अपनी ओर में इसकी विशेषताओं के आधार पर उसका अनुमान नहीं किया प्रत्युत राज्यमन्त्रि में प्राप्त निर्देशों के कारण ही इसे लागू करना पड़ा है।⁶¹

जैसी आशा की जाती थी, भारतीय राष्ट्रवादियों ने कपास के उत्पादनों पर आयात शुल्कों की वहाली का स्वागत ही किया और इसे लोकप्रिय दृष्टि की स्वीकृति का संकेत बनाया।⁶² इस संबंध में हम दृष्टान्त रूप में डी० ई० वाचा महोदय को उद्धृत करते हैं जिन्होंने अभिस्वीकार करत हुए कहा 'सरकार ने सचमुच जनता की आवश्यकताओं को स्वर दिया है और उदारतापूर्वक उसके सच्चे हितों की वकालत की है'।⁶³ इस प्रकार की प्रशंसा सामान्य नहीं थी और आयात शुल्क की अल्पता की आलोचना भी साथ साथ होने लगी थी। उदाहरणार्थ मराठा ने 16 दिसंबर 1894 के अंक में सरकार की इस कार्यवाही के लिए उसका समर्थन करते हुए यह टिप्पणी जोड़ दी : 'सरकार ने यह तभी किया है, जब इस विषय में उसके लिए और कोई विकल्प नहीं रह गया और दिवालियापन निश्चिंत ही था। इसके अतिरिक्त पत्र ने यह भी अनुभव किया कि शुल्क और अधिक ऊँचा अर्थात् 10 अथवा 15 प्रतिशत होता। इसमें पृथक् भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने निश्चिंत रूप से कपास उत्पादन शुल्क की निंदा की। उनके अनुसार यह शुल्क अनुचित, अशिष्ट तथा भारतीय जनता के हितों के विपरीत थे।⁶⁴

ब्रिटिश उत्पादक निश्चय ही 1894 के राजकर संबंधी प्रबंध में संतुष्ट नहीं थे। उनकी धारणा थी कि 20 नंबर से नीचे नंबरवाले सूत को सीमाशुल्क से मिली छूट भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षण जुटा रही थी। लकाशायर मोटे कपड़े के उत्पादन में भारत के साथ प्रतियोगिता कर सकता था और करता था परंतु उसके मार्ग की कठिनाई

यह थी कि उत्पादित वस्तुओं पर लगे कर के मुकाबले सूत पर उत्पादन शुल्क व्यवहार में अधिक हलका था और बर्मा में भारत के निर्यातों को अनुचित रूप से समर्थन मिल रहा था।⁶⁶ अंततः, फरवरी 1896 में भारत सरकार को राज्य सचिव के माध्यम से डाले गए दबाव के आगे झुकना पड़ा और दो नए कानून बनाने पड़े जिनके अंतर्गत कपास के सूत पर आयात शुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों को हटा दिया गया और साथ ही उसी समय बुने सामान पर आयात कर 5 प्रतिशत से घटाकर 3½ प्रतिशत कर दिए गए और उमी समय भारतीय मिलों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के बुने सामान पर 3½ प्रतिशत अनुरूप उत्पादन शुल्क थोप दिया गया। इस नए विधान का परिणाम यह निकला कि एक ओर आयातित सामान से मिलने वाली 51½ लाख रुपये की राशि अथवा 37 प्रतिशत राशि हाथ में निकल गई और दूसरी ओर भारतीय सामान पर करों में 300 प्रतिशत अथवा 11 लाख रुपयों की वृद्धि हो गई है।⁶⁷

नाममात्र संरक्षण को हटाने के लिए मोटे कपड़े तक पर कराधान की क्रिया ने भारतीय लोकमत पर विस्फोटक प्रभाव डाला। भारतीय लोकमत ने भारतीय उद्योग और भारतीय जनता के हितों के बलिदान के विरुद्ध क्रोध में उफनते हुए तीखे प्रहार किए।⁶⁸ उदाहरणार्थ, 9 फरवरी 1896 के अंक में गरजते हुए मगठा ने लिखा - 'इस देश के प्रशासन के ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी महोदया के पास हस्तांतरित होने से पहले लंकाशायर के पक्ष में दोबारा लगाए जाने वाले कपास शुल्क जैसे अति नीच और अन्यायपूर्ण पापकर्म करने का माहस किसी ने भी नहीं किया'। इसी प्रकार 'समय' ने 31 दिसंबर 1896 के अंक में तीखे प्रहार करते हुए लिखा : 'इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि अंगरेज किस प्रकार अपने स्वार्थों में अंधे हो गए हैं। अपने देशवासियों के हितों की उन्हे इतनी चिंता है कि इसके लिए दूसरों के हितों को क्षति पहुंचाने में भी मकोच नहीं करते - वे तो छुरा निकाल कर दूसरों का गला काटने को तैयार हैं।'⁶⁹

कपास पर लगे उत्पादन शुल्क ने आगामी अनेक वर्षों तक राष्ट्रवादियों को उत्तेजित किए रखा। 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नीखी भाषा में निबद्ध एक प्रस्ताव में उत्पादन शुल्क की निंदा की और इसके निरसन की माग की। यह प्रार्थना 1904 में दोहराई गई।⁷⁰ डी० ई० वाचा ने 1902 में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि जब तक सरकार इस अनुचित शुल्क को हटा नहीं लेती, कांग्रेस इसके विरुद्ध आंदोलन पर आंदोलन करती ही रहेगी।⁷¹ आर० सी० दत्त ने अपने लेखों, पुस्तकों और असंख्य भाषणों में इस पर विस्तृत विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि : 'यह राज कर संबंधी अन्याय के एक प्रमाण के तौर पर 1896 का अधिनियम आधुनिक काल में अपना उदाहरण आप ही था। उन्होंने आगे कहा - अत्यंत सुसम्भ्य सरकारें विदेशी सामान पर निषेधक शुल्क लगाकर गृहउद्योगों की रक्षा करती हैं, उन्मुक्त व्यापार की समग्रतः और पूर्णतः समर्थक सरकारें भी आयातित सामान पर राजस्व के प्रयोजन से साधारण सा सीमाशुल्क लगाती हुई अपने घरेलू उत्पादनों पर शुल्क नहीं लगाती हैं।'⁷² जी० के० खोसले ने लेजिस्लेटिव कौमिल में अपने भाषणों में उत्पादन शुल्क के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अनुभूत विक्षोभ को बार बार मुखरित किया।⁷³ एन० जी० चंद्रावरकर तथा

सुरेंद्रनाथ बैंनर्जी ने कांग्रेस के सभापति पद में उत्पादन शुल्क के निवर्तन की मांग को उठाया¹ और समाचारपत्रों ने भी अपने कालमों में इस विषय को सजीव बनाए रखा।²

1894-6 के वित्तीय परिवर्तनों पर राष्ट्रवादियों का आक्रमण निम्नलिखित तर्कों पर आधारित था।

भारतीय नेता निश्चित थे कि कपास पर लगे उत्पादन शुल्क भारत के आद्योगिक विकास को विलंबित और प्रतिबंधित करने वाले थे।³ वे इस बात से विशेष रूप से भयभीत थे कि उत्पादन शुल्क भारतीय वस्त्र उद्योग के महीन विस्म के मूल की कटार के मार्ग में बाधक बनेगा और इसी विशेष दिशा में इस उद्योग के अधिक विस्तार की संभावनाएं थीं।⁴ कुछ नेताओं ने यह आशंका भी प्रकट की कि उत्पादन शुल्क भारत के वस्त्र निर्यातों को बुरी तरह से झटका देगा और उसके फलस्वरूप जापान जैसे उसके प्रतिद्वंद्वी एशियाई देशों को अपने उत्पादन से भारत के उत्पादनों को प्रतियोगिता में गिरा देने में समर्थ बनाएगा।⁵ वस्तुतः यह भय निराधार था क्योंकि 1894 और 1896 दोनों अधिनियमों में निर्यात के लिए निर्धारित उत्पादनों पर शुल्क की पूरी छूट की व्यवस्था थी। इन नेताओं ने मभवत या तो अधिनियम की धाराओं को गलत समझा अथवा कदाचित् उनका यह विश्वास था कि औद्योगिक उत्पादनक्षमता की सामान्य दुर्बलता तथा लाभ का ढाँचा परोक्ष रूप में विदेशी प्रतिद्वंद्वियों में प्रतियोगिता में भारत की सामर्थ्य का प्रतिकूल रूप में ही प्रभावित करेगा।

भारतीय नेताओं ने 1896 के कपास उत्पादन शुल्क अधिनियम पर इस तर्क में और अधिक प्रहार किया कि इसमें जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग को कठिनाता का अनुभव होगा क्योंकि यह वर्ग मोटा कपड़ा खरीदता है और उसपर अब कर लगा दिया गया है।⁶ कुछ महानुभावों ने इस तथ्य को भी सामने रखा कि विदेशी वस्त्रों के आयात कर में जो 1½ प्रतिशत की छूट इस राज्य वर के साथ जोड़ दी गई है, उसका लाभ भारतीय जनता के अपेक्षाकृत धनी वर्ग को ही होगा क्योंकि वे ही प्रधान रूप से विदेशी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि धनिकों को भारमुक्त करने के लिए बंचारे गरीबों पर कराधान कर दिया गया है।⁷ बंगाली ने अपने 8 फरवरी 1896 के अंक में पूछा: 'सरकार की निर्धन जनता के प्रति वह सहानुभूति कहा चली गई है जिसकी वह शोषी बघारती रही है?'

उनका दूसरा तर्क यह था कि भारतीय उद्योग और जनता की समृद्धि पर इसके हानिप्रद प्रभाव के अतिरिक्त तथाकथित प्रयोजनों की दृष्टि से भी यह उत्पादन शुल्क अनावश्यक, अतः अनुचित था। इस तर्क के समर्थन में उनकी सर्वप्रथम युक्ति यह थी कि स्पष्टतया वित्तीय उत्पादकता का इसको लागू करने के कारणों में कोई स्थान नहीं, क्योंकि इसकी वसूली से होने वाली आय वसूली पर होने वाले व्यय के बराबर भी नहीं हो पाएगी। अतः किसी भी रूप में यह आय पर्याप्त नहीं कहला सकती। डी० ई० बाचा ने इस संबंध में एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया। उस समय सरकार को उत्पादन शुल्क के संग्रह से 17 लाख रुपयों की वसूली हुई थी जो राजस्व का एक तुच्छ अंग था जबकि उसने मिल मालिकों के लाभों को दुर्भाग्यवस्तु कर दिया था, यहाँ तक कि उनके 50 प्रतिशत

लाभ इस शुल्क से दुष्प्रभावित हो गए थे। अपने उपर्युक्त कथन के उपपरिणाम में वाचा महोदय ने कहा कि यह कहना बिलकुल गलत है कि मिलमालिक शुल्क से होने वाली हानि की उपभोक्ताओं से पूर्ति कर सकते थे अथवा कर रहे थे।⁸² यह भी एक पर्याप्त रोचक सत्य है कि इस विवाद में वाचा महोदय ने इस कल्पना को जिसे राष्ट्रवादियों ने इसमें पूर्व स्पष्ट तर्क के रूप में प्रस्तुत किया था कि इस उत्पादन शुल्क के थोपने से उपभोक्ता पर ही सारा भार पड़ेगा—मानने से इनकार कर दिया।⁸³ द्वितीय, भारतीय नेताओं ने इस तर्क को भी ठुकरा दिया कि आयात करों के संरक्षी स्वरूप को अपक्षपाती बनाने के लिए तथा इस प्रकार भारत और ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार को बनाए रखने के लिए उत्पादन शुल्क की अपेक्षा थी। उन्होंने पूर्ववत् दृढ़तापूर्वक कहा था कि आयात शुल्क स्थानीय उद्योग के लिए सभी व्यावहारिक दृष्टियों में किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं जुटाते क्योंकि भारतीय मंडी में भारत और ब्रिटेन के सूती उत्पादनों में प्रतियोगिता का क्षेत्र अत्यधिक ही संकीर्ण था। ब्रिटेन भारत को थोड़े से ही मोटे कपड़े का निर्यात करता था और इधर भारत उल्लेखनीय मात्रा में बढ़िया भूरे सामान का उत्पादन नहीं करता था जो भारत में ब्रिटेन के निर्यात का एक बहुत बड़ा भाग था।⁸⁴ इस तर्क के पथ पर बहुत सारे भारतीयों ने मांग की कि यदि उत्पादन शुल्क अवश्य ही लगाना है तो उसे 20 नंबर और उसमें ऊंचे सूत पर न लगाकर 24 नंबर और उससे ऊंचे सूत पर ही लगाना चाहिए।⁸⁵ इस संबंध में फजल भाई विश्राम ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक संशोधन प्रस्तुत किया जिसे उपस्थित सातों भारतीय सदस्यों का समर्थन मिला।⁸⁶ बाद में जब ब्रिटिश उत्पादकों ने शिकायत करते हुए और रियायतों की इस आधार पर चिल्लाहट की कि 20 नंबर के नीचे के भारतीय सूत को दी गई छूट ने उन्मुक्त व्यापार के विरुद्ध मुद्दे खड़ा रखा है तो भारतीय नेताओं ने उनकी मान्यता का बड़ी तीव्रता से निषेध किया।⁸⁷ कुछ ने तो यहां तक कि सुझाव दिया कि यदि भारत सरकार ब्रिटिश उत्पादकों को प्रसन्न ही करना चाहती है तो उत्पादन शुल्क को बढ़ाने के बदले 20 नंबर तक के अंगरेजी सूत को आयात कर से मुक्त कर दे।⁸⁸

उत्पादन शुल्क के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का प्रचंड विरोध और उसकी सार्वजनिक भर्त्सना प्रधान रूप से उसके दुष्परिणामों के विश्लेषण अथवा उसकी निरर्थकता के परिज्ञान से उत्पन्न नहीं थे, प्रत्युत उत्पादन शुल्क थोपने के मूल कारणों का उनका सही ज्ञान तथा यह विश्वास ही इसका कारण था कि इस संदर्भ में यह कर न गलत था, न अयथास्थान था और न ही मिथ्या विचारित साधन था, क्योंकि इस सबके विपरीत इसके प्रस्तावकों का जायरूप प्रयोजन भारत के पनपते वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंचाना था ताकि मांचेस्टर के फिलस्तीनियों को सांत्वना दी जा सके जो इस रूप में प्रतिद्वंद्वी के विकास को प्रतिबाधित करने की आशा रखते थे। 1894 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस तथ्य को बड़ी ही प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया। उमने उत्पादन शुल्क को लंकाशायर के हितों पर भारतीय हितों की बलि चढ़ाना मानने के अपने दृढ़ विश्वास को अभिलिखित किया।⁸⁹ बंगाली ने अपने 8 फरवरी 1896 के अंक में तीखे व्यंग्यात्मक स्वर में टिप्पणी की: 'भारतीय जनता तो भारत सरकार को सत्ता में नहीं रख सकती... मांचेस्टर कर सकता

है और करता है '...पहले सत्ता फिर कर्त्तव्य'।

और अधिक गहराई से विचार करने पर कुछ भारतीय नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस उत्पादन शुल्क के पीछे तो भारतीय औद्योगिक विकास को ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकताओं और आदेशों के अधीन करने के सिद्धांत और नीति काम कर रहे हैं। इस भावना को सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए फिरोजशाह मेहता ने कौंसिल चेबर में घोषणा की : 'वह सिद्धांत और वह नीति यह है कि यदि कहीं अंगरेजी उत्पादनों के साथ भारतीय उत्पादनों की प्रतियोगिता के सदेह का लेशमात्र भी दिखाई देता हो तो भारतीय उद्योग का उसके जनमते ही गला घोट देना चाहिए।'⁹¹ अपने समय के कदाचित् सर्वाधिक कोमल प्रकृति के लोक नेता एन० जी० चंद्रावरकर भी 1900 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने सभापतीय भाषण में यह टिप्पणी करने को विवश हो गए कि वर्तमान नीति में किसी भारतीय उद्योग को यूरोप की प्रतियोगिता में विकसित नहीं होने दिया जाएगा।⁹² खासिम-उल-अखबार ने अपने 24 दिसंबर 1894 के अंक में टिप्पणी की कि आज तक अंगरेज भारतीय उद्योग को सहायता देने का फरेब करते आ रहे थे परंतु अब इस तथ्य ने उनके चेहरे का नकाब उतार दिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी वास्तविक इच्छा इसके दमन की ही है।⁹³ मराठा ने 17 मार्च 1895 के अंक में भारत में ब्रिटेन की मूल आर्थिक नीति के संबंध में तो और अधिक मर्मघाती टिप्पणी की। उसने लिखा : यह अकेली घटना यह प्रकट कर देती है कि इंग्लैंड के मशीन उत्पादकों की इच्छा है कि भारत कृषिप्रधान देश ही बना रहे अथवा हम भारतीय इंग्लैंड के लिए सदा कच्चे माल के उत्पादक बने रहें और इंग्लैंड सदैव हमारे लिए पक्के माल का निर्माता-उत्पादक बना रहे।

राजनीतिक प्रभाव

उत्पादक शुल्क और कर के प्रश्न के अध्ययन के आधार पर बहुत मारे विचारशील भारतीय नेताओं ने भारत में ब्रिटिश राज्य के लाभप्रद चरित्र और वास्तव में तो उसके लक्ष्यों और प्रयोजनों को चुनौती देते हुए अधिक व्यापक अनुमान लगाए। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कर सबंधी दुर्घटना को प्राप्त महान ऐतिहासिक महत्व का प्रधान आधार समस्या का यही पक्ष है। साथ ही भारत में राष्ट्रीय भावना को पनपाने में कपास उत्पादन शुल्क तथा विभिन्न कर सशोधनों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उससे राष्ट्रीय भावना विदेशी शासन के नैतिक आधार के प्रति सदेह पर ही केंद्रित हो गई अथवा दूसरे शब्दों में भारतीय जनता और उसके नेताओं के मन में इस शासन के नैतिक आधारों के विषय में ही शंका उत्पन्न हो गयी।⁹⁴

बहुसंख्यक भारतीयों ने 1894 और 1896 की अवधि में चुगीकर तथा उत्पादन शुल्कों की कहानी से यह प्रमुख परिणाम निकाला कि भारत का शासन भारतीयों के हित में न होकर सामान्यतः ब्रिटिश जनता के और विशेषतः ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हित में ही है। भारत के हितों का ब्रिटेन के हितों के साथ टकराव की स्थिति में भारतीयों को ही हानि उठानी पड़ेगी।⁹⁵ इस भावना को केमरी के 28 फरवरी 1896 के अंक में तिलक ने बड़े ही कड़वेपन में इस प्रकार प्रकट किया : भारत को निश्चित

रूप से केवल यूरोपीयों के भरण-पोषण के लिए सुरक्षित एक विस्तृत अन्न क्षेत्र के रूप में ही लिया जाता है।⁹⁶ इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 29 जनवरी 1896 के अंक में निर्मम टिप्पणी करते हुए लिखा : 'यह स्पष्ट है कि भारत अंगरेजों की संपत्ति है।' बहुत सारे अन्य भारतीयों ने समान स्पष्टता परंतु अपेक्षाकृत कम क्रोध के साथ अपने विचार प्रकट किए। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष पी० आनन्द चारनू ने 1896 में लैंजिस्लेटिव कौंसिल में कपास शुल्क बिल पर दिए गए अपने भाषण में इस प्रश्न से संबंधित समग्र राष्ट्रीय चिंतनधारा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया : 'जहां भारत ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ हाथों में विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित है, वहां अंगरेजों के हितों के साथ भारतीय हितों के टकराव के मामलों में वह असुरक्षित है और जहां (जैसा एक तमिल उक्ति में कहा गया है) यहाँ तो भेड़ ही फमल को खाने लगी है।'⁹⁷

इस प्रकार भारतीय नेतृत्व के एक विशाल वर्ग का भारत में ब्रिटिश शासन के नैतिक आदर्शों पर से तथा विदेशी शासकों के गला फाड़कर प्रचारित परोपकारी उद्देश्यों पर से विश्वास ही उठ गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति के समग्रतः अनुकूल होते हुए भी इस अनुभव ने भी किसी राजनीतिक माग को विधायी तीव्र गति प्रदान नहीं की और अनेक भारतीय नेता इस अवसर का अपने पक्ष में लाभ उठाने में चूक गए। फिर भी कुछ नेताओं ने राजनीतिक सुधार की अपनी प्रिय मागों को आगे बढ़ाने में इस अवसर का उपयोग किया। यह दूसरी बात है कि उनकी मागें ही अत्यधिक हलकी थी, विशेषतः नेताओं के राजनीतिक और आर्थिक ज्ञान के संदर्भ में देखने पर तो वे बहुत ही हलकी दिखाई देती हैं। इस संबंध में श्रीगणेश करने का श्रेय मदनमोहन मालवीय को है जिन्होंने 1894 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान परिषद के सुधार संबंधी अधिवेशन में अपने भाषण में इस दिशा में नेतृत्व किया। मालवीय जी ने देखा कि सुधरी हुई विधान परिषद भारतीयों के हितों की सुरक्षा में असफल रही है। इंपीरियल लैंजिस्लेटिव कौंसिल के सरकारी सदस्य 1894 के भारतीय कर अधिनियम पर अपनी रुचि के अनुसार मतदान नहीं कर सके हैं और कौंसिल का प्रयोग राज्य सचिव के आदेश पर केवल मोहर लगाने के रूप में ही किया गया है। अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जहाँ तक भारतीयों के सच्चे और वास्तविक हितों का संबंध है, सुधरी लैंजिस्लेटिव कौंसिल धोखे के अतिरिक्त और कुछ नहीं।⁹⁸ इस तथ्य की, कि गैरसरकारी सदस्यों ने प्रायः ही भारत के हित का ही समर्थन किया है, जानकारी के संदर्भ में उन्होंने माग की कि कौंसिल में गैरसरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और कौंसिल को देशवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ और अधिक शक्ति प्रदान की जाए।⁹⁹ 'मराठा' ने तो इससे भी और आगे बढ़कर अपने 16 दिसंबर 1894 के अंक में यह माग की कि इंपीरियल लैंजिस्लेटिव कौंसिल के बहुसंख्यक सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए और शाही बजट मतदान द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए। अन्य बहुत सारे लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार भारत के हितों की सुरक्षा में समर्थ नहीं है।¹⁰⁰ कङ्ग्रेस ने तो सरकार से कहा कि वह खुले तौर पर भारत सचिव के पक्ष में अपनी शक्तियों का त्याग कर दे अथवा लैंजिस्लेटिव कौंसिल को ही समाप्त कर

दे ताकि वह इस समय गुप्त रूप से प्रयुक्त की जाने वाली अग्नी शक्ति को खुलकर काम में ला सकें।¹⁰¹

थोड़े से, विरल उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें स्वशासन तक की मांग की गई। इस संबंध में यह क्रांतिकारी विचार इस प्रकार प्रकट किया गया कि भारत तब तक राज करो के संबंध में न्याय प्राप्त नहीं कर सकता अथवा उद्योगीकरण की नीति को कार्य रूप नहीं दे सकता, जब तक कि वह ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्ति नहीं पा लेता तथा आत्मशासित देश नहीं बन जाता। यह मत खुले तौर पर बगनिवासी ने अपने 9 फरवरी 1896 के अंक में इस प्रकार प्रकट किया। इंग्लैंड प्रधान रूप से एक उत्पादक और व्यापारी देश है। जब तक इस देश पर अंगरेज लोगो का शासन है, तब तक भारत के सपूतों को व्यापार और उत्पादन में उनकी क्रूरता को सहन करना ही पड़ेगा।¹⁰² 1896 के उत्पादन शुल्क और कर छूट की चर्चा करते हुए 1898 में आर० सी० दत्त ने उपर्युक्त दृष्टिकोण से मिलते-जुलते अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए।

जब तक भारत की जनता को सरकार की सहायता करने का, अपने राष्ट्रीय राजस्वों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का साविधानिक अधिकार मिल नहीं जाता तब तक भारतीय जनता का इंग्लैंड के ब्रिटिश मतदाताओं के आदेश से काम करने वाली भारत की बरतानवी सरकार द्वारा जानबूझकर और खुल्लमखुल्ला भारतीयों के हितों की बलि चढ़ाने का अपमानित करने वाला दृश्य बार बार देखने को मिलेगा।¹⁰³ उत्पादन शुल्क ने गोखले तक को इतना क्षुब्ध कर दिया कि उन्हें यह टिप्पणी करना पड़ी कि इस शुल्क से यह स्पष्ट हो गया है कि जान स्टुअर्ट मिल ने एक देश के लोगों पर अन्य देश के लोगों की सरकार के संबंध में जो कहा है वह सही है।¹⁰⁴

परंतु देश की राजनीतिक मुक्ति का मघर्ष अभी भविष्य के गर्भ में ही निहित था। उस समय तो कार्यसूची में था, राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना, इस प्रवृत्ति को पुष्ट करना तथा राजनीतिक आंदोलन और मघर्षों के लिए भारतीय जनता को प्रशिक्षित करना। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इनमें से प्रवृत्ति, बुद्धिमत्ता और सफलता के साथ पहला काम ही संपन्न किया गया। दूसरा कार्य करो के मामलों में मारे देश के चापे चापे में जागृत राष्ट्रीय भावना के प्रचार के साथ ही निष्पन्न हो गया। उस पीढ़ी के नेताओं में अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञों में सबसे चतुर लोकमान्य तिलक ने इस संबंध में कर के विषय पर आंदोलन के महत्व को पूर्ण रूप से अभिस्वीकार किया। राष्ट्रीय एकता का आह्वान करने में उनके समाचारपत्र 'मराठा' ने अपने 9 फरवरी 1896 के अंक में लिखा

युवा भारत के कट्टर अंगरेज शत्रु सदैव गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। आइए, हम इस भयंकर मकड़ की घड़ी में एक हो जाए। आइए, हम सारे भारतीय, हिंदू, मुसलमान, पारसी और भारत में रहने वाले अंगरेज, एक सामान्य उद्देश्य बना लें। यह समय सदेह और सकोच का नहीं। राष्ट्रीय हित में सभी निजी मतभेद भुला देने चाहिए और मूल निवासियों तथा आगल भारतीयों को समान शत्रु का सामना करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।¹⁰⁵

उत्पादन शुल्क की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, ब्रिटिश नीति के अन्य पक्षों के प्रति राष्ट्रीय प्रति-

क्रिया से अपने को उच्चतर स्तर की गुणात्मकता में पृथक् करती है। सत्य यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रथम बार ही आर्थिक अथवा उससे भिन्न कारणों से तीसरा कार्य संपन्न किया। यद्यपि यह छोटे पैमाने पर और कदाचित् देश के केवल एक ही भाग अर्थात् बर्म्स प्रेमीडेंसी में किया गया था यह कोरे आंदोलन के स्तर में उठकर वास्तविक कार्यवाही के क्षेत्र में पहुँच गया। इसी समय पर और कपास उत्पादन शुल्क के प्रश्न को लेकर विदेशी मामान का बहिष्कार उल्लेखनीय परिमाण में कार्य रूप में परिणत होता दिखाई दिया।¹⁰⁶ विदेशी मामान के बहिष्कार की घोषणा राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने स्वदेशी उद्योग की महायत्ता के एकमात्र उपलब्ध साधन के रूप में की थी क्योंकि उनके अनुसार ब्रिटेन की न्यायप्रियता और दयालुता पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता था। देश के अनेक भागों में जनमभाए की गड़ और उनमें स्वदेशी के प्रयोग की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र में एक छोटे स्तर के स्वदेशी अभियान का मचालन किया गया। राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से, छोटे स्तर पर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का यह अभियान उत्पादन शुल्क के विरुद्ध किए गए राजनीतिक आंदोलन से कम महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें लोगों के स्वतः प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का एक नया उद्गार हो गया। यह अपन दुखों की निवृत्ति के लिए शासकों के आगे गिड़गिड़ाने और उनकी कृपा पर निर्भर रहने के बदले अपनी सहायता प्राप्त करने की भावना का प्रतिनिधित्व करता था।¹⁰⁷ सरकार की शुल्क नीति में उत्पन्न होने वाली प्रारम्भिक स्वदेशी भावना भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना को जन्म देने में, शहरी लोगों की बहुमूल्या को राष्ट्रीय राजनीति के झुंडे के नीचे सर्गाठित होने में बीज डालने की भूमिका निभाई।

1899 का चीनी आयात शुल्क

भारतीय नेताओं को राज कर नीति का व्याकुल करने वाला एक और पक्ष यूरोप में अनुग्रह के रूप में आने वाली चीनी पर उसी मात्रा में थोपा गया आयात शुल्क था। यह सचमुच एक जटिल विषय था और यह भारतीय नेताओं की आर्थिक पकड़ की गहराई, आर्थिक राष्ट्रवाद की और राजनीतिक कौशल की कसौटी बन गया। समीक्षाधीन अवधि में यह आंदोलन भारतीय नेताओं के बीच गहरे मतभेद के कुछ कारणों में से एक था।

19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत चीनी का निर्यातक देश रहा था, किंतु इसके बाद जल्दी ही वह अधिकांश रूप में ब्रिटिश उपनिवेश मारिशस से बढ़िया चीनी आयात करने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की अवधि में जर्मनी और आस्ट्रिया से वहाँ की सरकारों द्वारा अपनाई गई राज्य अनुग्रह निर्यात पद्धति के फलस्वरूप चुकंदर चीनी के आयात में अपरिमित वृद्धि हो गई। मस्ती होने के कारण 1898 तक चुकंदर चीनी के मारिशस के आयात पर और साथ साथ देश में उत्पादित चीनी पर छा जाने का सकट उपस्थित हो गया। भारत सरकार ने इस प्रवाह को रोकने के लिए 20 मार्च 1899 को 1894 के भारतीय कर अधिनियम में संशोधन किया। इसके अंतर्गत सरकार ने राज्य अनुग्रहों की मात्रा में अनुग्रह पोषित चीनी पर सम करने वाले आयात करों के आधान का

अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्मुक्त व्यापार की स्पष्ट स्वीकृति नीति से दिखाई देने वाले साहसिक परिवर्तन का प्रधान कारण सरकार ने यह बताया कि सरकार भारत के महान उद्योग और उस पर निर्भर गन्ने की उपज के कृत्रिम रूप से उत्तेजित प्रतियोगिता के हाथों और अधिक क्षय तथा विनाश को रोकने को उत्सुक है। यह आरोप लगाया गया कि पहले ही बहुत अधिक क्षति हो चुकी है। भारत में रिफाइनरी व्यापक और अबाधित रूप से बढ़ होती जा रही है और गन्ने की उपज का क्षेत्र गिमतकर 13 प्रतिशत रह गया है। सरकार ने यह भी दावा किया कि अनुग्रह पोषित चीनी न केवल भारत में देश के आधुनिक कारखानों में उत्पादित और शोधित चीनी में प्रतियोगिता करती है प्रत्युत देश की अशोधित अथवा अधूरेपन से शोधित चीनी से भी प्रतियोगिता करती है।¹⁰⁸ इसके साथ ही सरकार ने इस तथ्य को मानने से एकदम इकार कर दिया कि इसके पीछे मारिशस के किसानों और उत्पादकों के हितों की सुरक्षा जैसे शाही चिन्ता के किसी विषय ने सरकार के इस निर्णय पर पहुँचने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने तो यह मत प्रकट किया कि इसके विपरीत सत्य यह है कि भारतीय उद्योग के और भारतीय कृषि के हित ही समग्रतः पथ प्रदर्शक शक्ति रही है।¹⁰⁹

यद्यपि लार्ड कर्जन ने अपने इस कदम के देश में प्रबलतम समर्थन का खुला दावा किया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि केवल आयात व्यापारियों, बंबई और कराची के यूरोपीय वाणिज्य सदनों द्वारा ही असहमति दिखाई गई है,¹¹⁰ तथापि वास्तविकता कुछ और ही थी। भारतीय राष्ट्रीय नेता कभी भी, यहाँ तक कि प्रारम्भ में भी, इस मत करने वाले आयात कर के समर्थन में एकमत नहीं थे। समय की गति के साथ तो राष्ट्रीय विरोध और वेग पकड़ता गया। इसके अनिरीकृत जैसाकि हम आगे देखेंगे, किसी भी स्थिति में भारतीय समर्थन बिना शर्त और सरकारी क्षेत्रों द्वारा यह पग उठाते हुए किए गए प्रचार की भावना के अनुरूप नहीं रहा।

भारत सरकार की कार्यवाही के समर्थक और आलोचक, कम से कम प्रारम्भ में तो बराबर सन्तुलित नहीं थे। अधिनियम के सशोधन के समय और उससे पूर्व समर्थकों ने आलोचकों को पीछे छोड़ दिया था। समर्थकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वर जस्टिस एम० जी० रानाडे का था, जिनके शब्द तब भी बहुत सारे भारतीयों की दृष्टि में आर्थिक मामलों में कानून की सी प्रामाणिकता लिए हुए थे और जिनके विचार मई और जून 1899 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित तीन लेखों में अभिव्यक्त हुए थे।¹¹¹ दूसरे सक्रिय समर्थक थे पी० आनन्द चारलू और आर० सी० दत्त। चारलू महोदय ने इपीरियल लैजिस्लेटिव कौमिल में अपने पद से सरकार को प्रबल और मुखर समर्थन दिया।¹¹² लगभग सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्र, उदाहरणार्थ दि अमृत बाजार पत्रिका, दि बंगाली, दि हिन्दू, दि मराठा, दि इन्दु प्रकाश, दि एंडबोकेट और दि ट्रिब्यून समर्थक पक्ष में ही थे।¹¹³ बन्तुत सार्वजनिक रूप से अनुग्रह पोषित चुकदर चीनी के विरुद्ध स्वर मुखरित करने वाला और सरकार से सरक्षक कार्यवाही की माग करने वाला दि अमृत बाजार पत्रिका देश का प्रथम समाचारपत्र था।¹¹⁴

राष्ट्रवादियों के एक छोटे परंतु मुखरित वर्ग ने प्रबलता और कठोरता के साथ इस

शुल्क का विरोध किया। इस वर्ग के नेता के रूप में पृथ्वीश चन्द्र राय का नाम लिया जाता है। राय महोदय इंडियन एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य थे और कलकत्ता की स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटी के सहायक सचिव थे। उन्होंने 1895 में 'पावर्टी प्रॉब्लम आफ इंडिया' पुस्तक लिखकर अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्धि पाई थी और इस समय उन्होंने चीनी कर पर एक लेख भी पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया था।¹¹⁵ इन दोनों वर्गों के बीच अकेले परंतु सशक्त व्यक्तित्व वाले फिरोजशाह मेहता थे। उन्होंने इस मामले में जल्दीबाजी करना उचित न समझा। डीपीरियल नैजिस्लेटिव कौंसिल में सरकारी बिल पर विवाद के समय उन्होंने यह मुझाव दिया कि इस मामले में किसी एक पक्ष में निर्णय करने से पूर्व और अधिक तथ्यों की जानकारी की, और अधिक विस्तृत पूछताछ की तथा और अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता है।¹¹⁶

इन दोनों वर्गों द्वारा अपनाई गई स्थिति और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के विस्तृत विवेचन से पूर्व हम इस प्रश्न में संबंधित दो अन्य पक्षों की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहेंगे। प्रथम, भारतीय नेताओं के मन में 1891 और 1896 में हुए कर विरोधी सघर्षों की याद अभी ताजा ही थी। सभी नेताओं ने सम करने वाले चीनी शुल्क को भी पहले के उन सघर्षों में मीखे पाठ और सघर्षों की अवधि में उठाए पगों के ही परिप्रेक्ष्य में देखा। हा, इन शिक्षाओं के उद्घोष के समय अवश्य अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। द्वितीय, नेताओं में न केवल शुल्क के औचित्य के संबंध में प्रत्युत इंग्लैंड और भारत में इस चीनी शुल्क के आधार पर उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत के तथाकथित अतिक्रमण को लेकर उठे कटु मतभेदों के सदर्भ में भी मतभेद प्रचलित रहे। हा, हम, इस पृथ्वी मन-भेद में प्रत्यक्ष रूप में संबंधित नहीं हैं।

चीनी शुल्क के विरोधियों ने अपने पक्ष को निम्नलिखित तर्कों का आधार दिया। प्रथम, इसकी आवश्यकता का आधार ही मिथ्या उपपत्ति है। उनका तर्क था कि यूरोपीय चीनी की भागत की अशोधित अथवा अर्धशोधित चीनी में किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता ही नहीं है। भागत अधिकांशतः इस प्रकार की ही (अशोधित तथा अर्धशोधित) चीनी का उत्पादन करना है। जब तक भारत की देशी चीनी की बिक्री पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना, तब तक भागत के असली चीनी उद्योग को अथवा उस पर निर्भर करने के उत्पादन को किसी प्रकार का कोई खतरा ही नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि इन वर्षों में करने के उत्पादन क्षेत्र में सकोच हुआ है, परंतु उनके अनुसार इसका कारण प्रधान रूप से अकाल की स्थितियों का चलते रहना तथा मानसून का असफल होना था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की सिद्धांत 1896 में भी हो चुकी थी, दूसरे शब्दों में बड़ी मात्रा में अनुग्रह पोषित चीनी के आयात का जारी करने से पूर्व भी यह स्थिति रही है। फिर भी इन आलोचकों ने यह स्वीकार किया कि देशी शोधित चीनी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता के हाथों क्षति पहुंची है परंतु इस संबंध में उनके सतोष का विषय यह था कि देश को समग्र रूप में देखने पर यह कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं मानी जा सकती थी। उनका कथन था कि कुल मिलाकर केवल 6 बड़े कारखाने बंगाल में, 2 नार्थ वेस्ट प्रांत और अवध में, 1 पंजाब में और 5 मद्रास में थे। इनके द्वारा शोधित चीनी के उत्पादन की कुल मात्रा

लगभग 800,000 क्विंटल अर्थात् देश की कुल खपत का पांचवा भाग था। यदि ये सारे कारखाने बंद भी हो जाएं तो इनमें लगे अधिक से अधिक चार-पांच हजार श्रमिक ही तो बेकार होंगे। इसके साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि भारत की शोधित चीनी की शत्रु एकमात्र चुकंदर चीनी ही नहीं थी प्रत्युत भारत के चीनी साफ करने के कारखानों के विनाश में मारिशस की चीनी का भी बराबर महत्वपूर्ण योगदान था क्योंकि यूरोप की चीनी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देने पर भी भारत में उत्पादित चीनी मारिशस में उत्पादित चीनी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यदि यह सत्य न होता तो जर्मनी और आस्ट्रिया की चीनी के भारत में प्रवेश में पूर्व ही 1883-90 की अवधि में अकेले बंगाल में 89 चीनी कारखाने बंद न हो गए होते।¹¹⁷ 'प्रतिवासी' ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी भी रूप में इस समय भारत में आधुनिक चीनी उद्योग के विकास की कोई संभावना ही नहीं है।¹¹⁸ दूसरी ओर चीनी शुल्क के समर्थकों ने तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि देश में सर्वत्र चीनी शोधक कारखाने उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और अशोधित चीनी का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इन दोनों स्थितियों के फलस्वरूप गन्ने और ताड़ वृक्षों के उत्पादन के क्षेत्र का शोचनीय रूप से ह्रास हो गया है और भविष्य में और अधिक भयंकर ह्रास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।¹¹⁹ यह सब अकाल का दुष्परिणाम न होकर विदेशी प्रतियोगिता के कारण उद्योग के अलाभप्रद हो जाने का ही कुफल है।¹²⁰ अतएव उन्होंने मम करने वाले चीनी शुल्क को स्वदेशी उद्योग के आंशिक संरक्षक तथा कृपालु उद्धारक के रूप में ही देखा। उनका दृढ़ मन था कि यह शुल्क शोधित चीनी के उत्पादन के ह्रास और मंदी को प्रतिबाधित करेगा, ग्रामीण चीनी उद्योग के जीवन को नया प्राण देगा, गन्ने के उत्पादन को विस्तार देगा तथा हजारों कर्मचारियों को आजीविका के नए अवसर जुटाएगा।¹²¹ जस्टिस रानाडे चीनी शुल्क के आलोचकों से इस पक्ष पर सहमत थे कि इस समय कदाचित्त भारत में शोधक-उद्योग अधिक विकसित नहीं था और उसके फलस्वरूप होने वाला औद्योगिक घाटा भी अधिक नहीं था परंतु उनका कथन था कि यह दृष्टिकोण सर्वथा अदूरदर्शितापूर्ण ही था। वास्तविक स्वतंत्रता तो यह था कि इस सारे उद्योग का भविष्य ही विपत्तिग्रस्त बनाया जा रहा है।¹²²

चीनी शुल्क के समर्थकों और विरोधियों के मध्य मतभेद का एक अन्य विषय उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव था। आलोचकों की मान्यता थी कि चीनी निर्यातक देशों द्वारा दिए गए अनुग्रह से चीनी सस्ती होती है और उससे उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में लाभ पहुंचता है। क्योंकि सम करने वाला शुल्क किसी भी रूप में स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन नहीं जुटा पाएगा और क्योंकि स्थानीय उद्योग देश की शोधित चीनी की मांग की आंशिक पूर्ति ही कर पाएगा अतः चीनी का आयात फिर भी जारी रखना पड़ेगा। केवल अंतर यह होगा कि शुल्क के आधान से आस्ट्रिया और जर्मनी से सस्ती चीनी के आयात के बदले प्रधान रूप से ऊँचे दाम पर मारिशस से ही चीनी का आयात किया जाएगा। इस प्रकार यह शुल्क उपभोक्ताओं पर ही अतिरिक्त कर का रूप होगा।¹²³

आलोचकों के आलोचकों अर्थात् समर्थकों ने इस तथ्य को तो अस्वीकार नहीं किया

कि अनुग्रह, पोषित चीनी मस्ती थी परंतु उनका कथन यह था कि वह सम करने वाले शुल्क के विरुद्ध उपयुक्त तर्क तभी माना जा सकता है यदि भारतीय उद्योग का भविष्य इससे प्रभावित न होता हो। इस प्रकार उन्होंने यह दिखाकर कि यूरोपीय चीनी से भारतीय चीनी उद्योग को क्षति पहुंच रही है समीक्षकों के तर्कों को कुशलता से खंडित कर दिया उन्होंने चेतावनी दी कि सहायता प्राप्त सस्ती चीनी कालांतर में उपभोक्ताओं को फंसाने के वास्तविक जाल का रूप ले सकती है। चूंकि चीनी को कृत्रिम साधनों से सस्ता बनाने के राज्य अनुग्रह का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी उद्योगों को नष्ट करना ही था। एक बार यदि देशी उद्योग इतना अधिक विनष्ट हो गया कि उसका पुनरुद्धार ही संभव न रहा तो यूरोपीय बाजार पर छा जाएंगे और मनमानी कीमत वसूल करेंगे।¹⁴ इसके अतिरिक्त शुल्क के समर्थकों ने अधिकतम सख्या का अधिकतम हित के उपयोगितावादी सिद्धांत की अपील करके चतुरतापूर्वक समर्थन का तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने निर्देश किया कि आयातित तथा शोधित चीनी की कीमत में भारत का निर्यात वर्ग तो प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह तो केवल अशोधित स्थानीय उत्पादन का ही प्रयोग करता है। इस चीनी का प्रयोग तो केवल मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ही करता है और इन वर्गों को पर्याप्त मात्रा में समझा देना चाहिए कि वे निर्यात वर्ग के लिए त्याग करें। उन्हें सम करने वाले कर से होने वाली मूल्यवृद्धि का अपना निर्यात भाइयों की सहायता के लिए परीक्षा कराधान का एक रूप ही समझना चाहिए।¹⁵

यहां एक बार फिर उल्लेखनीय है कि इन भारतीय नेताओं ने 'उद्योग सर्वप्रथम' इस निर्देशक वाक्य का अनुसरण किया। बल ही वे नेता पश्चिमी रंग में रंगे मध्य वर्ग तथा भारत के उदीयमान मध्य वर्ग के बीच में थे और इसी वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे तथापि वे सब के सब देश के उद्योगीकरण के लिए उपभोक्ता के रूप में अपने हितों का बलिदान करने को उद्यत थे। यहां यह निर्देश करना भी अनुचित न होगा कि आलोचकों को भी इस त्याग पर कदाचित् कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी आपत्ति तो इस बात पर थी कि जब इस आर्थिक त्याग का कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलना तो सारा त्याग निरर्थक ही है।

आलोचकों को तो चीनी शुल्क अधिनियम को प्रस्तुत करने में सरकार की नीयत में भी संदेह था। उन्होंने अनुभव किया कि इस बिल के प्रस्तावित करते समय सरकार सचमुच भारतीय हितों की चिंता में परेशान नहीं थी। उनकी यह चिन्ता चिल्लाहट भूठी है कि भारतीय चीनी खतरे में है। अंगरेज प्रवक्ताओं द्वारा भारतीय किसानों और उत्पादकों के प्रति दिखाई जा रही सहानुभूति मक्कारी उससे भी कुछ घटिया वस्तु है। उनके विचार में सरकारी साधन का वास्तविक उद्देश्य भारतीयों से जिनके साथ प्रतियोगिता करना और जिन्हें पराजित करना अन्यथा संभव नहीं था बाजार छोड़कर वेस्ट इंडीज और मॉरिशस के किसानों और उत्पादकों की सहायता करना था। शासकों की सच्ची निष्कपटता का प्रदर्शन इस तथ्य में होगा कि वह सभी प्रकार के चीनी आयातों पर इस सरल कर को लगाने के लिए सहमत हो जाए। आलोचकों ने घोषणा की कि इस पग का सभी स्वागत करेंगे। यदि सचमुच ही सरकार भारतीय उद्योग को बचाना चाहती है तो वर्तमान उपाय पूर्णतः अपर्याप्त है क्योंकि इससे भारतीय चीनी को उसके अत्यंत भयंकर प्रतिद्वंद्वी,

मारिशस की चीनी, से रक्षा नहीं हो पाती।¹²⁶ राय ने लिखा : आखिर हमारे लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि जर्मनी और आस्ट्रिया के स्थान पर मारिशस चीनी भेजता है। वस्तुतः मारिशस ही हमारी आवश्यकता की बढ़िया चीनी का बहुत बड़ा भाग हमारे पास भेजता है और वही हमारी चीनी उद्योग की हत्या कर रहा है।¹²⁷ यदि सरकार ईमानदारी से भारत के चीनी उद्योग के उद्धार और प्रोत्साहन की इच्छुक है तो उसे केवल मारिशस की चीनी पर ही प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए प्रत्युत उसके साथ ही साथ स्वदेशी उद्योग को सीधी सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए तथा गन्ने के उत्पादन में और चीनी उत्पादन के तरीकों में सुधार के प्रयत्न करने चाहिए।¹²⁸

चीनी शुल्क लगाने के पीछे सरकार के निहित आशय का मूल्यांकन करते समय अधिकांश समर्थकों की प्रतिक्रिया मई 1899 में इस विषय पर ज्यू बुक के प्रकाशन काल तक सरकार के पक्ष में ही थी।¹²⁹ इस पुस्तक ने प्रकाशित होते ही लोगों के गले के नीचे एक कटु सत्य उतारा। चीनी शुल्क लगाने के समय बहुत सारे समाचारपत्रों और व्यक्तियों का विश्वास था कि यह शुल्क भारत के हित में ही लगाया जा रहा है।¹³⁰ यहाँ तक कि एक प्रकार का हर्षोल्लास था कि भारत के उद्योग के पुनरुद्धार के लिए लाई कर्जन के रूप में आर्थिक उद्धारक का अवतार हुआ है।¹³¹ परन्तु इस हर्षातिरेक की स्थिति दो महीने भी नहीं बनी रह सकी जब 'ब्लू बुक' ने आलोचकों के बुरे से बुरे संदेहों की पुष्टि कर दी।¹³² इस पुस्तक ने समर्थकों तक को यह मानने के लिए सहमत कर लिया कि यह शुल्क एकांतिक रूप से अथवा सिद्धांत रूप से भारत के किसानों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नहीं लगाया गया था, प्रत्युत मारिशस और वेस्ट इंडीज के ही किसानों और उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए था।¹³³ यहाँ तक कि जस्टिस रानाडे को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि नीति में यह परिवर्तन वेस्ट इंडीज के चीनी उद्योग के विनाश के फलस्वरूप हुआ है।¹³⁴ सरकार के इस पग के अत्यधिक उत्साही समर्थक पी० आनंद चारलू को 1901 में यह स्वीकार करना पड़ा कि इस कानून को पारित करते समय जिस भय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गई थी, कि यह अधिनियम कुछ उपनिवेशों के लाभों के लिए है वह भय सर्वथा निराधार प्रतीत नहीं होता।¹³⁵ इसने चीनी शुल्क अधिनियम के बहुत से रक्षकों को यह मानने को विवश कर दिया कि इसके प्रति उनका उत्साह मंद पड़ गया है।¹³⁶ इन पर भी वे इस अधिनियम की निंदा करने को तैयार न हुए। इस संबंध में वे आलोचकों से फिर अलग हो गए और उन्होंने यह कहना जारी रखा कि यह उपाय भारतीय चीनी उद्योग की कुछ समय के उपरांत अवश्य रक्षा करेगा अतः भारतीयों को इसके समर्थन से कतराना नहीं चाहिए।¹³⁷ और मारिशस के किसानों के साथ सामान्य उद्देश्य लेकर चलना चाहिए।¹³⁸ उनका कथन था कि यदि इस शुल्क से भारतीय चीनी के दो प्रतिद्वंद्वियों में एक को हानि पहुँचती है तो यह भी एक विधेयक के लाभ ही है।¹³⁹ इसके अतिरिक्त इससे भारतीय चीनी उद्योग को सांस लेने का समय भी तो मिलेगा।¹⁴⁰

भारतीय नेताओं का यह वर्ग दूसरे वर्ग की इस मान्यता से समान रूप से सहमत था कि केवल सम करने वाले कर के आधान से ही भारतीय चीनी उद्योग के संरक्षण और उन्नयन में सफलता नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शीघ्रता

से ही कुछ अन्य कदम भी उठाने पड़ेंगे। सुझाए गए कदमों में एक था, भारतीय चीनी उद्योग के संरक्षण क्षेत्र का विस्तार, इस विस्तार सीमा के अंतर्गत मारिशस की चीनी भी समाविष्ट थी।¹⁴¹ दूसरा कदम था स्वदेशी उद्योग के लिए विशिष्ट और सक्रिय सुविधाएं जुटाना।¹⁴² मजेदार बात यह है कि इन विशिष्ट सुविधाओं की मांग करने हुए जस्टिस रानाडे इस सीमा तक बढ़ गए कि राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रिय सिद्धांत मद्यपान की प्रवृत्ति पर पाबंदी अथवा उसे अनुत्साहित करने पर ही आक्रमण करने लगे। उनका कथन था कि चीनी उत्पादन के उपजात उत्पादन के रूप में रम बाहरी बचतों में एक थी। जब तक चीनी शोधकों का स्पर्श के अवशिष्ट से मुक्ति पाने की और कारखानों के निकट ही शराब भट्ठी पद्धति के अंतर्गत बेचने की अनुमति नहीं दी जानी तब तक कोई भी चीनी का कारखाना ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता। उन्होंने शिकायत की कि उत्पादन शुल्क पर सरकारी एकाधिकार होने के कारण यह सुविधा भारतीय उत्पादकों को उपलब्ध नहीं थी। अतएव उन्होंने मांग की कि मदिरा शुल्क के हिनो को चीनी उद्योग की आवश्यकता के अधीन कर देना चाहिए और चीनी शोधकों को रम के उत्पादन की तथा बढ़िया किस्म की मदिरा पीने के इच्छुकों को बेचने को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।¹⁴³ रानाडे के इस तर्क को एक अन्य मद्दर्भ में स्वयं उनके द्वारा तथा राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा गला फाड़-फाड़कर जनता की शराब बेचन पर प्रतिबंध लगाने की मांग में तुलना करके ही देखना चाहिए।¹⁴⁴ स्पष्ट है कि यही रानाडे का उद्योगप्रेमी स्वरूप, समाजसुधारक अथवा नैतिकतावादी स्वरूप में अधिक मशकत मिद्ध हुआ और वह मदिरा पर स नियंत्रण के हटाने की वकालत करने लगे।

सरकारी कार्यवाही के सबंध में निदकों और समर्थकों में मतभेद चलते रहे। परवर्ती घटनाओं ने यह मिद्ध कर दिया कि विरोधियों का मन सभी दृष्टियों से लगभग सही था। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि चीनी शुल्क अधिनियम पर ब्ल्यू-बुक के प्रकाशन के उपरांत अधिकांश भारतीय इस अधिनियम के लागू करने में निहित उद्देश्यों पर सदेह करने लग गए थे। अधिक बुरी बात यह हुई कि कालांतर में यह अधिनियम अनुग्रह पोषित चीनी के आयातों को रोकने में असमर्थ रहा।¹⁴⁵ इससे भी अधिक बुरी बात यह हुई कि जब इन आयातों को रोका गया तो भारतीय बाजार में उसका स्थान देशी चीनी के बदले मारिशस और जावा से चीनी के बढ़ते आयात ने ले लिया।¹⁴⁶ वस्तुतः आलोचकों द्वारा सरकारी उपाय के विरुद्ध प्रकट किए गए विवादों को कुछ वर्षों के उपरांत स्वयं सरकारी अधिकारियों ने खूने आम अभिस्वीकार किया। उदाहरणार्थ 1902 में लार्ड कर्जन ने यह मान लिया कि इस समय भारत की कच्ची चीनी तथा शोधित आयातित चीनी में किसी प्रकार की वास्तविक अथवा गंभीर प्रतियोगिता नहीं है। अपनी पहले की स्थिति से हटते हुए उन्होंने घोषणा की

जहां तक मैं जान पाया हूँ, पिछले कई वर्षों से गन्ने की फसल का क्षेत्र लगभग स्थिर ही रहा है और यदि देश के किसी भाग में इसकी सीमा में संकोच आया भी है तो इसका कारण न तो विदेशी चीनी से प्रतियोगिता है और न ही भारतीय चीनी शोधकों की बाजार की पूर्ति में असफलता है। इसका कारण वस्तुतः देश के विभिन्न

भागों में उत्पन्न अकाल की स्थिति है और उसने तो प्रत्येक प्रकार के ही कृषि उत्पादन को समान रूप से ही प्रभावित किया है।¹⁴⁷

चीनी शुल्क के भारतीय समर्थकों के पास अपने पक्ष की पुष्टि में यदि केवल ऊपर विवेचित तर्क ही थे तो हमारा उससे यह निष्कर्ष निकालना अकारण न होगा कि इस विषय में उनका आर्थिक विश्लेषण और विवेक सतही तथा जीवन के तथ्यों से विच्छिन्न था, परंतु उनके आर्थिक चिंतन और दृष्टिकोण की गहराई और सूक्ष्मता के प्रति उपर्युक्त निष्कर्ष अन्यायपूर्ण तथा भ्रातिमूलक होगा। हमारे विचार में इस विषय में अब तक परीक्षित तत्वों की अपेक्षा कुछ अन्य तत्वों से ही वे सरकार के समर्थन के लिए प्रेरित थे। इस तत्व को कभी तो उन्होंने स्पष्ट कहा और कभी कभी विवशतावश चालाकी से उन्हें इस अभिव्यक्ति देने में सावधानी बरतनी पड़ी। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि चीनी शुल्क अधिनियम देश के राज कर सबंधी नियमों में एक नया मोड़ होने के कारण एक महत्वपूर्ण युग का सूचक था।¹⁴⁸ उन्हें यह एक स्वर्णिम अवसर प्रतीत हुआ और उन्होंने उत्प्रेरणापूर्वक इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार के उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर प्रहार किया तथा सरकार से संरक्षण सिद्धांत मनवाने की चेष्टा की। इन नेताओं का विचार था कि जब सरकार एक बार किसी भी कारण से, किसी भी हालत में तथा किन्हीं भी विवशताओं से घिरकर अनुकूल न सिद्ध होने पर, उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत से हट गई तो उस स्थिति में सरकार के लिए संरक्षण नीति के विस्तार के लिए उनके तर्कों और दबाव की अपेक्षा करना भव्य नहीं होगा। उनका विचार था कि चीनी शुल्क अधिनियम से जुड़े हुए अन्य उन उद्योगों को भी राज्य संरक्षण देने की मांग की जा सकेगी जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होगी भले ही उनमें ब्रिटिश प्रतियोगियों का सम्बन्ध क्यों न हो।¹⁴⁹ यदि बी० जी० काले पर विश्वास किया जाए, विश्वास न करने का हमारे पास कोई कारण भी नहीं, उन्होंने रानाडे के पत्रों के संग्रह की भूमिका में इस विषय में यहाँ तक लिखा है कि इस अधिनियम के पक्ष में स्फूर्ति से शस्त्र उठाते समय जस्टिस रानाडे के मन में यह विचार ब्रह्म स्पष्ट और प्रबल रूप में था, काले का कथन है कि इस समय करने वाले शुल्क ने तो रानाडे को एक सुविधाजनक आधार जुटाया, जिस पर स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत के विरुद्ध उन्होंने अपनी आलोचना का प्रासाद खड़ा किया। रानाडे ने यह अनुभव किया कि यह शुल्क तो शुरुआत है और उन्होंने चाहा कि इसके द्वारा अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर की गई चोट को और गहरा किया जाए ताकि भारत के स्वदेशी उद्योग के यथाक्रम विकास को दृष्टि में रखकर ही देश की अर्थनीति निर्धारित की जाए।¹⁵⁰

चीनी शुल्क अधिनियम, 1902

जैसा कि हमने अभी अभी देखा है 1899 के चीनी शुल्क अधिनियम को चुकंदर चीनी का आयात रोकने में कोई सफलता नहीं मिली। द्वितीय, चीनी उत्पादकों ने शीघ्र ही उत्पादन संघ बनाकर अपने निर्यात को परोक्ष आर्थिक सहायता देनी आरंभ कर दी। भारत सरकार ने इसका प्रत्युत्तर जून 1902 में समय करने वाले अतिरिक्त शुल्क लगाने के रूप में दिया।¹⁵¹ चीनी शुल्क संशोधन अधिनियम को चीनी शुल्क अधिनियम के समान राष्ट्र-

वादियों का समर्थन न मिल सका। इसके विपरीत पहले के अधिनियम के विरोधियों के तर्कों को ही अब इस नए अधिनियम के संदर्भ में व्यापक मान्यता मिली। यद्यपि अब भी लार्ड कर्जन ने यही घोषणा की कि इस बिल में लोकहित के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है ¹⁵² तथापि भारतीय नेताओं ने इसपर अब पुष्प वर्षा के बदले ओले ही बरसाए। बहुसंख्या में ही नेताओं ने यह स्पष्ट घोषणा की कि सरकार इंग्लैंड के खेतिहरों और चानी उत्पादकों के हित में ही सब कुछ कर रही है। वस्तुतः इस चीनी शुल्क से वे लोग भारतीय उत्पादकों में चीनी के अधिक दाम वसूल कर सकेंगे और साथ ही भारतीय चीनी उद्योग को ध्वस्त कर सकेंगे। ¹⁵³ इसके अतिरिक्त कइयो ने यह भी अनुभव किया कि सरकार की कार्यवाही के पीछे बढ़िया चीनी के यूरोपीय उत्पादकों के कल्याण की चिंता भी कदाचित्त कार्य कर रही है। ¹⁵⁴ अपवाद रूप में चीनी शुल्क के अधिनियम का समर्थन करने वाला प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र 'वंगबासी' ही था, जिसने इस अधिनियम का समर्थन इस आधार पर किया कि पहले अधिनियम के लागू होने के प्रथम वर्ष की अवधि में भारतीय उत्पादक वस्तुतः लाभान्वित ही हुए हैं। यूरोपीयों के लिए भारत में चीनी कारखाने लगाने के प्रोत्साहन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा गन्ने और शीरे की मांग बढ़ेगी और हो सकती है कि यूरोपीयों के प्रयास कालांतर में भारतीय उद्योग-पतियों के लिए अनुकरणीय बन जाएं। ¹⁵⁵

सरकारी नीति के विकल्प के रूप में कुछ भारतीय नेताओं ने पुनः ब्रिटिश उपनिवेशों से आने वाली चीनी सहित सभी देशों की विदेशी चीनी पर सरक्षक शुल्क लगाने की योजना प्रस्तुत की। ¹⁵⁶ कुछ ने तो यहां तक कह डाला कि यदि सरक्षक शुल्क लगाना संभव नहीं तो फिर उपहार-पोषित चीनी पर मम करने वाले शुल्क को हटा ही देना चाहिए। ¹⁵⁷

विभिन्न प्रकार के प्रश्न

यहां कर नीति के कुछ अन्य छोटे-मोटे पक्षों, जिनपर भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए थे, और ब्रिटिश करनीति के एक पक्ष को भी देख लेना उपयुक्त होगा जिसमें लोगों को गहरी रुचि हो गई थी।

भारतीय नेताओं द्वारा सूती वस्त्रों और चीनी पर लगे आयात शुल्कों के संबंध में अपनाई गई नीति के नितात विरुद्ध ही अब उनका दृष्टिकोण उन बहुत सारी वस्तुओं पर आयात करों के संबंध में उजागर हुआ जो विदेशी उत्पादन से प्रतियोगिता नहीं करती थी और उल्टे स्वदेशी उद्योगों और कृषि के विकास में सहायक थी। उनके इस दृष्टिकोण का आधार उद्योगीकरण की प्रक्रिया पर और उपभोक्ता के हितों पर अंततः पड़ने वाला उनका प्रभाव था। इस संबंध में मिट्टी के तेल पर सर्वप्रथम 1888 में लगाए गए और फिर 1894 में बढ़ाए गए कर के संबंध में आलोचना का स्वर पर्याप्त मुखर था। सरकार ने इस कर को सर्वथा निरापद माना था क्योंकि इससे कोई भी ब्रिटिश उद्योग प्रभावित नहीं था। ¹⁵⁸ परंतु भारतीय नेताओं के आक्षेप का आधार यह था कि मिट्टी का तेल भारतीय उद्योगों को प्रभावित नहीं करता था परंतु अपने घर में रोशनी के लिए इसका

प्रयोग करने वाले निर्धन वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ता था और इस पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती थी।¹⁵⁹

मार्च 1894 में जब कोयला, लौह धातुओं, रंगों, कच्चे औद्योगिक सामान तथा अन्य औद्योगिक मंडारों पर कराधान की योजना वाले 'इंडियन टेरिफ बिल' को पेश किया गया तो भारतीय नेताओं ने पूर्वपिक्षा अधिक तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट की। उन्होंने उद्योगों पर परोक्ष कराधान के माध्यम से औद्योगिक विकास को क्षति पहुंचाने की सरकारी नीति की जोरदार निंदा की।¹⁶⁰

19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में चांदी की चढ़रें एक छोटी सी मद थी जिसका भारत से इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने एक तो उसपर 30 से 35 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगा दिया और दूसरे उसे बोभिल ठप्पा-पद्धति का शिकार बना दिया।¹⁶¹ 1882 के पश्चात् भारतीय नेता इस राज्य कर के विरुद्ध तीव्र विरोध प्रकट करते रहे।¹⁶² 1889 में यह विरोध उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चांदी की चढ़रों पर शुल्क हटाने की तथा ऐच्छिक रूप से ठप्पा अंकित करने की पद्धति की मांग की।¹⁶³ इसका अभीष्ट प्रभाव पड़ा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लेने वाले चार्ल्स ब्राडलाफ ने यह प्रश्न संसद में उठाया और 1890 में शुल्क हटा दिया गया।

भारतीय नेताओं ने इन छोटी छोटी बातों को भी इनना महत्व केवल इसलिए दिया ताकि ब्रिटिश के स्वतंत्र उद्योग के मिद्वान का खोखलापन दिखाया जा सके। इंग्लैंड में चांदी चढ़र शुल्क हटाने की मांग करने हुए उन्होंने बार बार यह प्रश्न पूछा। जब भारत में 1882 में उन्मुक्त व्यापार के मिद्वान के पालन के बहाने में कपास शुल्क हटाया गया था तो चांदी चढ़रशुल्क अभी क्यों बनाया गया जा रहा है और इंग्लैंड भारत द्वारा निर्दिष्ट अच्छे उदाहरण का प्रत्यावर्तन क्यों नहीं कर सकता? इंग्लैंड की शुल्क हटाने से इनकारी केवल भारत के शासकों की स्वार्थपरता और उनके दोहरे व्यवहार को ही प्रकट करती है, यह उन्होंने घोषित किया।¹⁶⁴ 21 फरवरी 1884 के अंक में ज्ञान प्रकाश ने लिखा: 'इससे बढ़कर भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि इंग्लैंड उन्मुक्त व्यापार के प्रचार के संबंध में इस कड़ावत को चरितार्थ कर रहा है कि कोई दूसरे को तो फलसफा मिलाए और खुद वेवकूफों जैसी हकतें करे।'¹⁶⁵ इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने 27 मई 1884 के अंक में क्रुद्ध होकर कहा: 'इसे वे उन्मुक्त व्यापार कहते हैं... हम तो इसे धोखा ही कहेंगे न कि उन्मुक्त व्यापार।' मगठा ने 3 जून 1888 के अंक में टिप्पणी की कि 'इंग्लैंड की उन्मुक्त व्यापार की नीति मक्कारी और धोखा-धड़ी है—इंग्लैंड की सारी स्वार्थपरता की नीति नंगी हो गई है और व्यापार के संबंध में इंग्लैंड की व्यापारिक स्वतंत्रता की शैली बकवास साबित हुई है।'

भारतीय नेताओं ने चांदी चढ़र शुल्क हटाने के पक्ष में कुछ और तर्क भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि भारत में लगाए कपास करों के विपरीत चांदी की चढ़रों पर इंग्लैंड में लगाए शुल्क भी विशुद्ध रूप से संरक्षक-साधन के रूप में ही थे क्योंकि इनसे होने वाली वार्षिक आय कुछ हजार पाँडों की तुच्छ राशि ही है।¹⁶⁶ उनका तर्क था कि इन करों के

हटने से भारतीय कारीगरी और व्यापार को सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त चांदी की चदरों के निर्यात से भारतीय चांदी को निकामी की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे भारत के रूपये पर दबाव को कम करने और उसके अवमूल्यन को रोकने में सहायता मिलेगी।¹⁶⁸

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न कर-साधनों के प्रति भागीय राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण के उपर्युक्त अध्ययन के बाद कर नीति के चार प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं : प्रथम, अघाघुध न सही, यह विवेकपूर्ण ढंग से भारतीय उद्योग को मरक्षण प्रदान करने की सुस्पष्ट नीति है। द्वितीय, भारतीय नेताओं के आधुनिक उद्योग के प्रति प्रबल और पूर्ण लगाव का यह एक अन्य निदर्शन है। एक बार पुनः व्यापार के हितों की अपेक्षा उद्योग के हितों को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही भारतीय नेताओं ने जानबूझकर विदेशी वस्त्रों और शोधित चीनी के उपभोक्ता मध्यवर्गीय समाज के रूप में अपने हितों को देश के उद्योगीकरण के व्यापक हितों के अधीन ही कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने भारतीय उपभोक्तों के हितों की अपेक्षा भारतीय उत्पादकों के हितों को अधिक महत्व दिया। यह रोचक तथ्य है कि जब कभी उनके विचार में भारतीय उद्योग पर कोई आच नहीं आती थी, जैसा कि पेट्रोलियम और किन्ही किन्ही के मत में चीनी के बारे में, तब भारतीय नेता निस्संकोच और अबाध रूप से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा में अग्रसर होते थे। तृतीय, वे इस धारणा पर पूर्ण विश्वास करने लगे थे और इसी पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक आचरण भी किया और इसी का प्रचार-प्रसार भी किया कि भारत सरकार की कर नीति भारतीय उद्योग के विकास को क्षतिग्रस्त कर रही है। इसके पीछे विदेशी शासकों का उद्देश्य कदाचित् ब्रिटिश उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करना है। भारत सरकार ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादित माल की खपत के लिए भारत में यथासंभव मंडी बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है और इसी के संदर्भ में भारत के ग्रामों की आर्थिक स्वायत्तता और स्वदेशी कलाकौशल का द्रुतगति से विनाश किया जा रहा है। चतुर्थ, सरकार की कर नीति ने राष्ट्रीय भावना को न केवल जगाया प्रत्युत राजनीतिक वास्तविकता को अधिक स्पष्टता से देखना भी सिखाया। इसने नेताओं को भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को फूँकने, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने तथा उनमें पनपती राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने, सारे देश के विभिन्न भागों के लोगों को इकट्ठा होने यहां तक कि उन्हें राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन की कला सिखाने का अवसर जुटाया। वस्तुतः समीक्षाधीन अवधि में करनीति उन विषयों में से एक थी, जिन्हें भारतीयों में सरकार विरोधी भावनाएं तथा संघर्षशील राष्ट्रवाद को जगाने का श्रेय प्राप्त है।

संदर्भ

1. संपूर्ण समीक्षाधीन अवधि में भारतीय कर नीति के इतिहास के लिए देखिए, सी० जे० हैमिल्टन : दि ट्रेड रिलेशंस ब्रिटिश इंग्लैंड ऐंड इंडिया (1600-1806), (कलकत्ता 1919) प्रमथनाथ बैनर्जी . फिस्कल पालिसी इन इंडिया (कलकत्ता 1922) सी० एन० वकील फाइनेशल डेवलपमेंट इन माडर्न इंडिया (बंबई 1924) अध्याय 15 और दत्त . ई एच II
2. दि इपीरियल गजेटियर (1908) खंड IV, पृ० 262
3. राज्य सचिव के संप्रेषण देखिए (सेपरेट रेवेन्यू) स० 6, 15 जुलाई 1875 और उसका संप्रेषण (लेजिस्लेटिव) 11 नवंबर 1875, (स० 53) और 31 मई 1876 (स० 25)
4. राज्य सचिव की डाक, 15 जुलाई 1875 पूर्वोक्त स्थल 11 नवंबर 1875 की अपनी डाक में उसने दोबारा बल देते हुए लिखा सूती सामान पर कर दो उत्पादक वर्गों को, जिनपर ताज की संपन्नता और वैभव निर्भर है, एक दूसरे के प्रतियोगी ही नहीं बनाते प्रत्युत राजनीतिक विद्वेषी भी बनाते हैं यदि इस कार्य को स्थागित कर दिया जाए तो यह वर्तमान में प्रतियोगिता रत वर्गों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और कटु बने हितों में मतभेद का विषय बन जाएगा पूर्वोक्त स्थल
5. लिटन के दृष्टिकोण के लिए देखिए, लेडी बंट्टी बेलफोर दि हिस्ट्री आफ़ लांड लिटिज्स ऐंडमिनिस्ट्रेशन 1876 टु 1880 (लंदन 1899) पृ० 462, 477 स्ट्रैची के लिए देखिए, उसका 1877 का वित्तीय वक्तव्य
स्ट्रैची ने अपने दृष्टिकोण को निम्नलिखित अधिक सुस्पष्ट शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्ति दी मैं इस संबंध में भारतीय और अंगरेजी हितों में किमी प्रकार के मतभेद में विश्वास नहीं करता ... यदि ऐसा किया जाता तो स्थिति भिन्न होती—मैं इस प्रकार की कल्पना में विश्वास नहीं रखना मैं इस मोके पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ 'हमें कहा जाता है कि भारत सरकार का कर्तव्य केवल भारत के हितों की चिन्ता करना है और यदि हममें लबाशायर के हित को आघात पहुँचता है तो हमें इसमें कुछ लेना देना नहीं परंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस सिद्धांत को अस्वीकार करता हूँ भारत में अपन जीवन का अधिक समय व्यतीत करने से और भारत सरकार के सदस्य बनने का अर्थ यह नहीं कि अंगरेज ही नहीं रहा माचेस्टर के हित, जिनपर मुख्य लोग नाक निकोड़ते हैं, न केवल कपास के उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध बुद्धिमान और महान लोगों के हित हैं, प्रत्युत लाखों अंगरेजों के भी हित हैं मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जहां मानवता के नाने, मैं आशा करता हूँ और अनुभव करता हूँ कि इस देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, वहां मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि मेरी कल्पना में अपन देश के प्रति कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं,' तथा देखिए उनका 1878 और 1879 के वित्तीय भाषण
6. लांड सैलिसबरी ने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हुए यह निर्देश किया कि 5 और मिलें अपना कार्य आरंभ करने जा रही हैं तथा 1878 के अंत तक 1,231,284 पूनियाँ का भारत में नियोजन हो सकेगा (1878 के वित्तीय भाषण का परिशिष्ट बी).
7. जे० स्ट्रैची इंडिया (1903) पृ० 181-2 तथा बयरिंग फाइनेशियल स्टेटमेंट्स 1883 कड़िकाएँ 75-78, परिमल राय पूर्वोक्त, पृ० 50 और जोशी पूर्वोक्त, पृ० 628-9 हैमिल्टन ने विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कर के निवर्तन से न तो कपास के फुटकर सामान के आयात व्यापार को ही पसंदने की अपेक्षा अधिक द्रुतगति मिली है और न ही भारत के द्रुतगति से बढ़ते

कपास उद्योग के विस्तार में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हुई है (पूर्वोद्धृत, पृ० 247).

- 8 स्ट्रैची · इंडिया (1903) पृ० 178
- 9 17 दिसंबर 1874 के एक में नेटिव ओपीनियन द्वारा पुनरुद्धृत : ए० बी० पी० का एक विदेशी सस्करण, तथा देखिए आर० एन० पी० बग०, 2, 9 जनवरी, 6, 27 फरवरी 1875 में उद्धृत समाचारपत्र
- 10 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंबई शाखा की प्रबंध समिति का 15 जनवरी 1875 का शायन, जरनल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, खंड IX 1875
- 11 देखिए, आर० एन० पी० बब, 14, 21, 28 अगस्त 4, 11 मिन० 1875, आर० एन० पी० बग०, 14, 21, 28 अगस्त 1875, आर० एन० पी० एन०, 28 अगस्त 1875 आर० एन० पी० एम०, मितबर-अक्तूबर 1875
- 12 देखिए, आर० एन० पी० बब, 4, 11, 18, 25 मार्च, 1, 8 अप्रैल 1876, आर० एन० पी० बग०, 18, 25 मार्च, 15, 22, 29 अप्रैल 1876, परवर्ती विरोध के लिए देखिए भोलानाथ चट्ट एम० एम० खंड V जनवरी-जून 1876, पृ० 3, 58 63, याजदा परस्त, 1 अप्रैल, बंबई समाचार, 31 मार्च (आर० एन० पी० बब, 7 अप्रैल 1877); इंदु प्रकाश, 23 अप्रैल (वही, 28 अप्रैल, 1877); एजुकेशन गजट 20 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 28 जुलाई 1877); सहचर 23 जुलै 'रते 4 अगस्त 1877)
- 13 देखिए, आर० एन० पी० बब०, 23, 30 मार्च, 6, 13 अप्रैल 1878 और देखिए, आर० एन० पी० बब, 11, 18 जनवरी 8, 15, 22 फरवरी 1, 15 मार्च 1879, आर० एन० पी० बग० 22 फरवरी, 1 मार्च 1879 आर० एन० पी० एन०, 22 फरवरी 1 मार्च 1879 बह्य पब्लिक ओपीनियन, 13 फरवरी 1879
- 14 देखिए आर० एन० पी० बब, 22, 29 मार्च, 5, 26 अप्रैल, 10 मई 1879, आर० पी० एन० बग०, 22, 29 मार्च, 5, 12 अप्रैल 1879, आर० एन० पी० पी० एन०, 5, 12 अप्रैल 1979 3 मई 1879 को पार्लियामेंट के सामने भारत सरकार की कार्यवाही के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए एक जन सभा हुई इंदु प्रकाश, 5 मई (आर० एन० पी० बब, 10 मई 1879 इसी प्रकार की एक सभा का आयोजन कलकत्ता में 27 मार्च 1879 को किया गया. इसमें लगभग 300 लोग सम्मिलित हुए (बागल, पूर्वोद्धृत, पृ० 41) और देखिए, एस० एन० बॅनर्जी स्पीचेज I, पृ० 201 03 के टी० तैलंग . सिलेक्ट राइटिंज ऐंड स्पीचेज (बंबई 1916) पृ० 185-6 लालमोहन घोष . स्पीचेज आफ लालमोहन घोष आशुतोष बॅनर्जी द्वारा संपादित (कलकत्ता 1883 और 1884) भाग 1 पृ० 9
15. एस० एन० बॅनर्जी स्पीचेज I, पृ० 202
- 16 आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 1879
17. भारत मिहिर, 19 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 28 फरवरी 1880); बंगाली · 29 जनवरी 1881 : ए० बी० पी० 24 फरवरी 1881, आर० एन० पी० बग०, 1, 8, 15 जनवरी, 19 फरवरी 5 मार्च 1881 में उल्लिखित समाचारपत्र, आर० एन० पी० बब, 29 जनवरी 5, 26 फरवरी 1881; 16 मई 1880 को पूना में पूना मार्चजनिक सभा द्वारा आयोजित एक जनसभा, जे० पी० एस० एस०, खंड III, सख्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 9 (और देखिए, पृ० 3)
18. मराठा, 28 अगस्त, 18 सितंबर 1881; नेटिव ओपीनियन, 28 अगस्त, 4 सितंबर, 18 सितंबर 1881 और आर० एन० पी० बब, 3, 10 24 सितंबर 1881 और आर० एन० पी० बग०,

24, 31 दिसंबर 1881 में उल्लिखित समाचारपत्र

- 19 ए० बी० पी०, 16, 23, 30 मार्च, 6 अप्रैल 1882, बंगाली, 11 मार्च 1882; मराठा, 26 मार्च 1882; नेटिव ओपीनियन, 12 मार्च 1882, आर० एन० पी० बब, 11, 18 मार्च, 1 अप्रैल 1882, आर० एन० पी० बग०, 25 मार्च, 1 अप्रैल 1882, आर० एन० पी० पी० एन०, 22, 29 मार्च, 5, 12 अप्रैल 1882 में उल्लिखित समाचारपत्र यहाँ तक कि परम प्रतापी महाराज जतीन्द्र मोहन टैगोर ने चैबर कौंसिल की अपनी सीट से कपास आयात के निर्वर्तन की निंदा की (एल० सी० पी० 1882 खड XXI पृ० 304)
- 20 यह शासन पहले ही देशी भाषा प्रेस कानून तथा स्वशासन के विस्तार को वापस ले चुका है अपराध प्रक्रिया संहिता सुधार बिल दूर की कोड़ी था भारतीय नेताओं को अब भी किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा धर्रेजों से उदारवादिया और उपवादियों पर दृढ़ विश्वास था
21. उदाहरणार्थ देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा का स्मरणपत्र जनरल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खड IX (1875) पृ० 99 भालानाथ चद्र एम० एम० खड V (जनवरी जून 1876) पृ० 51, 58-9 आर० एन० पी० बब, 22 29 मार्च, 5, 12, 26 अप्रैल, 3 मई 1879 में उल्लिखित समाचारपत्र, तैलग राइटिंग्ज, पृ० 186 एल० एम० घोष स्पीचेज, खड I, पृ० 9 एम० एन० बेंनर्जी स्पीचेज I, पृ० 202 वायसरायल्टी आफ लार्ड लिटन . जे० पी० एस० एस०, खड III, स० 1 (जुलाई 1880) पृ० 68-9, मराठा, 26 मार्च 1882 सर जान स्ट्रूची ने निम्नलिखित आश्चर्योत्पादक परंतु उदघाटक शब्दों में भारतीय दुष्टिकोण को उलटे रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया भारत में करो की सूची में शामिल अथवा शामिल किया जा सकने वाला प्रत्येक उत्पादन या तो भारत में उत्पादित होता है या किया जा सकता है, अतः यह निष्कर्ष है कि कपास आयात शुल्क वास्तव में घयवा मामध्य से सरक्षक हैं (ब्रिटीश प्रतिवेदन 1878, कड़िका 55)
- 22 उदाहरण के लिए देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा का अनुस्मारक, पूर्वोक्त स्थल; भालानाथ चद्र पूर्वोक्त स्थल तैलग राइटिंग्ज, पृ० 185 एम० एन० बेंनर्जी स्पीचेज I, पृ० 200-02 वायसरायल्टी आफ लार्ड लिटन पूर्वोक्त स्थल तथा बहुत सारे समाचारपत्र, पीछे पाद टिप्पणी 13-14 में उद्धृत
23. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा का अनुस्मारक, पूर्वोक्त स्थल, सहचर 23 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 4 अगस्त 1877) एल० एम० घोष स्पीचेज, भाग I, पृ० 193, 200-02 रानाडे जे० पी० एस० एम० खड IV सख्या I (जुलाई 1881) पृ० 50 बहुत वर्षों के उपरांत आर० सी० दल ने व्यक्ति होकर कहा उस समय यह कर हटाए गए हैं, जबकि दक्षिणी भारत अभी 1877 के मद्रास प्रकाल में समल नहीं पाया, जबकि उत्तरी भारत अभी 1877 के अकाल से सतप्त है, जबकि भूराजस्वों में करों की अभी अभी बढ़ोतरी की गई है, जबकि विशेष करो की उगाही से बनाया गया 'अकाल बीमा कोष' अदृश्य हो गया है और जबकि अफगानिस्तान के सकट और विशाल खच्चों ने वैज्ञानिक जिज्ञासा का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया है (ई एच II, पृ० 416)
24. बंबई समाचार जावे जमशेद और अखबारे सौदागर, 21 मार्च (आर० एन० पी० बब, 23 मार्च 1878); इंडियन स्पेक्टेटर, 28 अगस्त (वहो, 3 सितंबर 1881); बंगाली, 11 मार्च 1882; इंडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन गुजरात मित्र, 12 मार्च (आर० एन० पी० बब, 18 मार्च 1882); वस्तुतः 1882 में जितने भी समाचारपत्रों ने आयात करों के निर्वर्तन पर टिप्पणी की, इस तथ्य को प्रस्तुत किया.

25. आर० एन० पी० बंब, 7, 21, 28 अप्रैल 1877 और 22, 29 मार्च, 5 अप्रैल 1879 में उल्लिखित समाचारपत्र; भारत मिहिर, 29 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 5 अप्रैल 1879); हिंदी प्रदीप, अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, 12 अप्रैल 1879), मिरात उष हिंद, 15 फरवरी (वही, 19 फरवरी 1880); बर्दवान संजीवनी, 3 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 14 जनवरी 1882); सहचर, 29 मार्च (वही, 8 अप्रैल 1882).
26. सहचर : 17 दिसंबर ए० बी० पी० के विदेशी संस्करण में, बेलगांव समाचार, 2 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 6 मार्च 1875); आंध्रभाषासंजीवनी तिथि रहित (आर० एन० पी० एम०, सितंबर-अक्तूबर 1875); सदादर्श, 23 अगस्त (आर० एन० पी० पी० एन०, 28 अगस्त 1875); आर० एन० पी० बंग०, 2, 9 जनवरी 6, 27 फरवरी, 13 मार्च 14, 21, 28 अगस्त 1875 और आर० एन० पी० बंब, 14, 21, 28 अगस्त, 4, 11 सितंबर 1875; 4, 11, 25 मार्च 1, 8 अप्रैल 1876; आर० एन० पी० बंग०, 18 मार्च, 15, 22 अप्रैल 1876, 21, 28 जुलाई, 4, 18 अगस्त 1877, आर० एन० पी० बंब, 23 मार्च 1878 में उल्लिखित समाचारपत्र. भोसानाच चंद्र : एम० एम०, खंड V (जनवरी-जून 1876) पृ० 48, 58-63; ए० एम० घोष : जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खंड XIII भाग 2 पृ० 65 और स्पीचेज, भाग 1 पृ० 9; ए० एन० बंनर्जी : स्पीचेज I, पृ० 220, आर० एन० पी० बंब, 22, 29 मार्च, 5, 19, 26 अप्रैल 1879; आर० एन० पी० बंग०, 22 फरवरी, 22, 29 मार्च, 5, 12 अप्रैल 1879 आर० एन० पी० पी० एन०, 5, 12 अप्रैल 1879 में उल्लिखित समाचारपत्र 'दि द्रोक्न 'लेज ऐंड इट्स कांसिक्वेंसिज' जे० पी० ए० ए०, खंड III, मध्या 1 (जुलाई 1879) पृ० 44; वायसरायल्टी आफ लार्ड लिटन : जे० पी० ए० ए०, खंड III मध्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 34, 63, 68; मिरात-उल-हिंद, 15 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 19 फरवरी 1880); सहचर : 20 दिसंबर 1880 (आर० एन० पी० बंग०, 1 जनवरी 1881); माधारणी, 2 जनवरी (वही, 8 जनवरी 1881); सुलभ समाचार, 8 जनवरी (वही, 15 जनवरी 1881); आनन्द बाजार पत्रिका, 21 फरवरी (वही, 5 मार्च 1881); केसरी : 20 सितंबर (आर० एन० पी० बंब, 24 सितंबर 1881); मराठा, 18 सितंबर 1881; 26 मार्च 1882; ए० बी० पी० 16 मार्च 1882; आर० एन० पी० बंब, 18, 25 मार्च, 1, 8 अप्रैल 1882, आर० एन० पी० बंग०, 24, 31 दिसंबर 1881, 7 जनवरी, 25 मार्च, 1 अप्रैल 1882; आर० एन० पी० पी० एन०, 22, 29 मार्च 1882 में उल्लिखित समाचारपत्र
27. आर० एन० पी० बंब, 25 दिसंबर 1875.
28. रानाडे : 'रिब्यू आफ फ्री ट्रेड ऐंड इग्निस कामस', अगस्तस मोनैग्रियन द्वारा, जे० पी० ए० ए०, खंड IV मध्या 1, पृ० 50. यह समीक्षा अज्ञातनाम प्रकाशित हुई. हमारे पास जी० ए० मानकर द्वारा जस्टिस रानाडे को इसका लेखक मानने का प्रमाण उपलब्ध है (मानकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 214-5, खंड I).
29. जे० पी० ए० ए०, खंड III, मध्या 1 (जुलाई 1880), पृ० 11.
30. उनके दृष्टिकोण का सोदाहरण विश्लेषण जान स्ट्रुची की अगली टिप्पणी में किया गया है : 'भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर लकावाय का पक्षपात करने का अभियोग मूर्खतापूर्ण आरोप है जिसका उत्तर देने की न अपेक्षा थी और न है. (इंडिया, 1903 पृ० 178) तथा देखिए : स्ट्रुची : फाइनेशनल स्टेटमेंट्स, कठिका 77. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उसी समय उच्च ब्रिटिश

अधिकारियों ने राष्ट्रीय आपत्तियों की सम्यक जानकारी तो प्राप्त की परन्तु उन्हें स्थिति के परंपरागत रूप में लेते हुए टाल दिया।

31. तुलनीय, बकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 408-24.
32. 1 मार्च (आर० एन० पी० ब०, 6 मार्च 1875). इसी प्रकार 23 अगस्त 1875 के घन मे 'सदादर्श' को लंबे रेशोवाली कपास पर आयात कर लगाने पर विचार करते समय यह टिप्पणी करने को विवश होना पड़ा : यह देखने के पश्चात कौन इनकार करेगा कि हमारे शासकों को यह वास्तविक चिंता उत्तेजित कर रही है कि भारत का एक बहुत बड़े उत्पादक देश के रूप में ही विकास हो ? (आर० एन० पी० पी० एन०, 28 अगस्त 1875) और देखिए साधारणी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० ब०, 11 सितंबर 1875).
33. भोलानाथ चट्ट : एम० एम०, खंड V (जनवरी-जून 1876) पृ० 58-60 अतएव उन्होंने कहा कि स्वामिभक्ति के लिए यवराज के भारत पधारने का कोई महत्व नहीं, इंग्लैंड की शासिका महारानी का भारत की सम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण करना व्यर्थ है वस्तुतः देवता नहीं पत्न्यत पिशाच ही सच्चे अर्थों में शासक शक्ति हैं. मावेस्टर ही सच्चे अर्थों में भारत के भाग्य का निर्णायक है (वही, पृ० 63).
34. वही, पृ० 62 तथा देखिए साधारणी, 23 मार्च (आर० एन० पी० ब०, 29 मार्च 1879)
35. एम० एन० बैनर्जी स्पीचेज I, पृ० 202
36. एन० सी० पी०, 1882 खंड XXI पृ० 328-9.
37. और देखिए, महचर : 29 मार्च (आर० एन० पी० ब०, 8 अप्रैल 1882)
38. दत्त : ई० एच० II, पृ० 339
39. आर० एन० पी० ब०, 1 अप्रैल 1882 तथा ममय, 15 मार्च (वही, 20 मार्च 1886)
40. सहचर 13 जन० (वही, 23 जन० 1886).
41. एन० सी० पी० 1882 खंड XXI, पृ० 328.
42. उदाहरण के लिए देखिए बी० ओ० आई०, 15 अप्रैल 1884; बंगाली, 22 मार्च 1884, एम० ए० स्वामी नाथ अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1885, पृ० 69; केमरी, 24 जनवरी, बोध सुधावर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० ब०, 28 जनवरी 1888); दत्त : ई० एच० II, पृ० VIII, 120, 339-41, 401-02, 411, 416, 518, 537. स्पीचेज II पृ० 126.
43. उदाहरणार्थ देखिए, आई० एन० सी० 1885, 1887 और 1889 के क्रमशः प्रस्ताव VI, VI और III. केमरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० ब०, 7 अप्रैल 1883), जे० य० याज्ञिक, रिप० आई० एन० सी०, 1885, पृ० 66, एस० ए० स्वामीनाथ अय्यर वही, पृ० 69, बंगाली, 9 जनवरी 1886; आर० एन० पी० ब०, 2, 9, 16, 23, 30 जनवरी, 6 फरवरी 18, 25 सितंबर, 29 अक्टूबर 1886; आर० एन० पी० ब०, 18 सितंबर 1886 में उल्लिखित समाचार-पत्र ट्रिब्यून, 18 सितंबर, इंडियन स्पेक्टेटर, 19 सितंबर, बिहार हेराल्ड और इंडियन मिरर, 21 सितंबर, पीपुल्स फ्रेंड, 25 सितंबर, ज्ञान प्रकाश, 30 सितंबर (बी० ओ० आई०, खंड IV सख्या 10, अक्टूबर 1886); हिंदूजनसंस्कारिणी, सख्या 3 (आर० एन० पी० एम० अक्टूबर 1886); जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 100-01, 142, 160, माडलिक, पूर्वोद्धृत, पृ० 651, 659-60, एस० एस० बैनर्जी : स्पीचेज III पृ० 8. शुभ प्रसाद मेन : रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 132; मराठा, 29 जनवरी 1888, बंगाली, 28 जनवरी 1888, ए० बी० पी० 26 जनवरी 1888, बी० ओ० आई०, फरवरी और मार्च 1888 में उल्लिखित समाचारपत्र, आर० एन० पी० ब०, 28 जनवरी,

- 4 फरवरी 1888, आर० एन० पी० बग०, 28 जनवरी, 4 फरवरी 1888, आर० एन० पी० एम, 31 जनवरी, 29 फरवरी 1888; आर० एन० पी० पी० एन० 31 जनवरी, 7, 14 फरवरी 1888; नोरोजी सी० पी० ए०, पृ० 177; ज्ञान प्रकाश और सुधारक 19 फरवरी, मुबोध पत्रिका, 18 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 24 फरवरी 1894).
44. भारत सरकार तो नए कर अधिनियम में सूती सामान को सम्मिलित करने के लिए श्रव्य उत्पन्न दिखाई देती थी परंतु महारानी की सरकार के आदेश से उसे अपने निश्चय को रह कराना पड़ा देखिए, भारतीय कर अधिनियम पर मार्च 1849 में वित्त सदस्य का भाषण, एल० सी० पी०, 1894, खंड XXXIII, और देखिए, वकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 426 पी० बैनर्जी : फिस्कल पालिसी इन इंडिया, पृ० 89-90
45. देखिए, एल० सी० पी०-1894 खंड XXXIII पृ० 155
46. पूना सार्वजनिक सभा का स्मरणपत्र, दिनांक 6 मार्च 1894, जे० पी० एम० एम०, खंड XVI म० 4 (अप्रैल 1894), इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, दिनांक 8 मार्च 1894 रिपोर्ट ऑफ दि इंडियन एसोसिएशन फ्रॉम 1892-3 टु 1895-6 बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा 2 मार्च 1894 को विरोध स्वरूप भेजा गया तार, पी० पी० (हाउस आफ कामस), 1895, खंड 72 स० 202; बंबई के 2 नवंबर 1894 को हुए सातवें प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय अभिभाषण, जे० पी० एम० एम०, खंड XXXII सध्या 3 (जनवरी 1895) पृ० 5-6 18 मार्च 1894 का पूना में हुए सम्मेलन में प्रस्तुत याचिका के लिए देखिए मराठा, 18 मार्च 1894, 20 मार्च 1894, को मद्रास में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के लिए देखिए, मराठा, 25 मार्च 1894 कलकत्ता में 8 मार्च, बंबई में 14 मार्च, अमृतसर में 7 मार्च और लखनऊ में 9 मार्च 1894 को हुए जन-सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों के लिए देखिए, पी० पी० (हाउस आफ कामस) 1895, खंड 72 सध्या 202.
47. ए० बी० पी०, 3 मार्च 1894; मराठा, 4 मार्च 1894; बंगाली, 10, 17 मार्च 1894, इंदु प्रकाश, 12 मार्च 1894; इंडियन स्पेक्टेटर, 11 मार्च 1894, एडवोकेट, 9 मार्च (आई० एम० बी० ओ० आई०, 25 मार्च 1894); ट्रिब्यून, 14 मार्च (वही, 15 मार्च 1894), आर० एन० पी० बब, 10 मार्च, आर० एन० पी० बग०, 10, 17, 31 मार्च 1894, आर० एन० पी० एम०, 15, 31 मार्च 1894, आर० एन० पी० एन०, 14, 21, 28 मार्च 1894, आर० एन० पी० पी०, 7, 21 अगस्त 1894 में उल्लिखित समाचारपत्र
48. पूना सार्वजनिक सभा का स्मरणपत्र 1894, पूर्वोक्त स्थल; इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, पूर्वोक्त स्थल; बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का विरोध, पूर्वोक्त स्थल; जी० आर० एम० चित्तनवीम, एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII, पृ० 157. रास बिहारो घोष : स्पीचेज, पृ० 151-2.
49. रास बिहारी घोष : स्पीचेज, पृ० 150 आगे चौदहवें अध्याय में राष्ट्रवादियों की कर नीति के इस पक्ष की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है.
50. पूना सार्वजनिक सभा का 1894 का स्मरणपत्र, पूर्वोक्त स्थल तथा पीछे सदर्थ 45-6 में उद्धृत सगण्य सभी भारतीय नेता.
51. आई० एम० बी० ओ० आई०, 29 अप्रैल 1894
52. ज्ञान प्रकाश, 5 मार्च (आर० एन० पी० बब, 10 मार्च 1894)
53. बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने धीमे स्वर में और अप्रत्यक्ष ढंग से राजनीतिक धमकी भी दी और इन प्राथियों ने तो अपने शासकों से राजनीतिक नैतिकता की अपेक्षा करते हुए उन्हें यहां

तक चेतावनी दे दी कि उनके इस पत्र से महारानी की आज्ञाकारी भारतीय जनता की बकसारी को एक ऐसा बहुरा घबका सनेवा जिसकी क्षतिपूर्ति कभी हो ही नहीं सकेगी. (देखिए, मराठा, 18 मार्च 1894).

54. 11 मार्च (आर० एन० पी० बब० 17 मार्च 1894).
55. आर० एन० पी० बब०, 31 मार्च 1894. इसी प्रकार बंगाली ने 17 मार्च 1894 के प्रक में घोषणा की कि 'भारतीयों का हंगलैंड के न्याय से विश्वास डग गया है'.
56. आर० एन० पी० बब०, 24 मार्च 1894.
57. एल० सी० पी०, खंड XXXIII पृ० 46.
58. वेस्टलैंड, वही, पृ० 382, 384.
59. वित्तीय प्रतिवेदन, 1878 कठिका 55
60. बकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 427-9 में उद्धृत और देखिए : वेस्टलैंड एल० सी० पी०—1894, खंड XXXIII पृ० 383-4.
61. बकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 427, 429. हैमिल्टन—पूर्वोद्धृत, पृ० 248-51.
62. एल० सी० पी०—1894, खंड XXXIII, पृ० 381-2
63. मराठा, 16 दिसंबर 1894; इंडियन स्पेक्टेटर, 23 दिसंबर 1894; हदुप्रकाश, 24 दिसंबर 1894: ए० बी० पी०, 22 दिस० 1894; बंगाली, 22 दिस० 1894; हिंदू, 27 दिस० 1894; कैंसर-ए-हिंदू, 16 दिस०, सुबोध प्रकाश, 19 दिस०, सुबोध पत्रिका, 16 दिस०, देशी मित्र, 20 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 22 दिस० 1894); स्वदेशमित्रन, 21 दिस० 1894, खासिम-उल-अखबार, 24 दिस० 1894 तथा अन्य भारतीय समाचारपत्र. (आर० एन० पी० एम०, 15 जनवरी 1895) मद्रास स्टैंडर्ड, 24 दिस० 1894 (आई० एस० बी० ओ० आई०, 13 जनवरी 1895) हिंदुस्तानी, 26 दिस० 1894 (आर० एन० पी० एन०, 2 जनवरी 1895); एस० एन० बैनर्जी . सी० पी० ए. पृ० 259-61 जोशी . पूर्वोद्धृत, 191-2 केवल एक प्रधान समाचारपत्र 'एडवोकेट' ने कपास पर आयात शुल्क के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति की कि इससे हम प्रकार की वस्तुओं के ड्राम बढ़ जाएंगे और इसका परिणाम उत्पादन शुल्क लगाना हो सकता है। इसके स्थान पर पत्र का सुझाव था कि माचेस्टर के उपवादी तत्त्वों से सबध जोड़ना चाहिए
64. वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 31.
65. आई० एन० सी० 1894 का प्रस्ताव I, वाचा . रिप० आई० एन० सी०—1894; पृ० 31-2; मराठा, 16 दिसंबर 1894, ए० बी० पी०, 22, 29 दिसंबर 1894, बंगाली, 22 दिसंबर 1894; हिंदू, 27 दिस० 1894; इंडियन स्पेक्टेटर, 23 दिसंबर 1894 हदु प्रकाश, 24, 31 दिस० 1894; आर० एन० पी० बब०, 22 दिस० 1894, 5 जनवरी 1895, आर० एन० पी० बग०, 22, 29 दिसंबर 1894, 5, 12 जनवरी 1895, आर० एन० पी० एम०, 15 जनवरी, 1895, आर० एन० पी० एन०, 9, 16, 23 जन० 1895, आर० एन० पी०, 12 जनवरी, 9 फरवरी 1895 में उल्लिखित समाचारपत्र यहाँ यह निर्देश करना उचित है कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने उस समय भी जब सीमा शुल्क के लगाने की समावनाओं पर विचार किया जा रहा था, इसका प्रबल विरोध किया था इस सबध में देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर, 1 जुलाई 1894. हिंदू, 11 जुलाई 1894. गुजराती, 1 जुलाई, सुधारक, 2 जुलाई (आर० एन० पी० बब०, 7 जुलाई 1894); केमरी, 24 जुलाई (वही, 28 जुलाई 1894); ट्रिब्यून, 18 जुलाई, एडवोकेट, 20 जुलाई

(आई० एस० बी० ओ० आई०, 26 अगस्त 1894)

- 66 हैमिल्टन, पूर्वोद्धृत, पृ० 252-3 दत्त ई एच II पृ० 539-40. वकील पूर्वोद्धृत, पृ० 430-2
- 67 वकील पूर्वोद्धृत, पृ० 433
- 68 मराठा, 26 जनवरी, 9 फरवरी 1896, ए० बी० पी० 29 जन० 1896, बगाली 1, 8 फरवरी 1896; हिंदू, 27 जनवरी 1896, इंडियन स्पेक्टेटर, 26 जनवरी 1896; मद्रास स्टैंडर्ड, 27 जनवरी, इंडियन नेशन, 27 जनवरी (आई० एस० बी० ओ० आई०, 15 मार्च 1896); एडिनोकेट, 28 जनवरी, ट्रिब्यून, 29 जन०, इंडियन मिरर, 30 जनवरी (वही, 22 मार्च 1896), बिहार हेराल्ड, 8 फरवरी (वही, 5 अप्रैल 1896), आर० एन० पी० वब 25 जन०, 1 फरवरी 1896, आर० एन० पी० बग०, 1, 8, 15 फरवरी 1896, ए० एन० पी० एम० 15, 29 फरवरी 1896 आर० एन० पी० एन०, 5, 12, 19 फरवरी 1896, आर० एन० पी० पी०, 8, 15, 22 फरवरी 1896. मे उल्लिखित समाचारपत्र बर्बई प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन की ओर से 27 जनवरी 1896 को भेजा गया तार इंडियन टैरिफ एक्ट 1896 और काटन ड्यूटी ऐक्ट 1896 से संबंधित 1896 क बागजात-नो 8078 (हाउस आफ बामस) पृ० 163 28 जनवरी 1896 में बर्बई की एक जनसभा में पारित प्रस्ताव, वही पृ० 166 29 जनवरी 1896 का अध्यक्ष, पूना मावजिनिक सभा द्वारा प्रेषित तार, वही, पृ० 171 2 फरवरी 1896 में मद्रास में हुई जनसभा द्वारा अभिव्यक्त की गयी वही पृ० 192 7 फरवरी 1896 को बोरमाद, जिला केरा बर्बई में हुई जनसभा द्वारा अभिव्यक्त विरोध, वही पृ० 193 विधान परिषद में बी० आर० भुसकुटे, पी आनन्द चारलू और मोहिनी मोहन राय के सरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध भाषण (एल० सी० पी०-1896 खड XXXV पृ० 66-7, 78-87, 92-95)
- 69 आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896.
- 70 क्रमश प्रस्ताव XVI और प्रस्ताव VIII.
- 71 रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 143
- 72 दत्त ई एच II पृ० 543 और वही, पृ० 597, 612 स्पीचेज II पृ० 45-6 80, 126-7
- 73 गोखले स्पीचेज, पृ० 10, 41-2 और 77 अपने 1903 के बजट भाषण में उन्होंने आर० सी० दत्त को प्रतिध्वनित किया उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया गृह उद्योग पर सरकारी कराधान की विदेश प्रतियोगियों के लाभ को समर्थ बनाने वाली ऐसी व्यवस्था किसी भी अन्य दश में सम्भव नहीं थी बल्कि वही वृद्धि की सरकार विनाश के कगार पर खड़ी हुई गिरने की स्थिति में हो क्यों न हो, (वही, पृ० 42) और देखिए, श्रीराम—एल० सी० पी०—1903, खड VIII पृ० 104-5
- 74 सी० पी० ए०, क्रमश पृ० 527 और 696
- 75 उदाहरणार्थ, मराठा, 10 मई 1896 नेटिव ओपीनियन, 1 अप्रैल, केसरी, 31 मार्च (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 1903) इंडियन पोपुल, 19 जनवरी 1905
- 76 आई० एन० सी० 1894 का प्रस्ताव I, हिंदू, 11 जुलाई 1894, ट्रिब्यून, 18 जुलाई (आई० एस० बी० ओ० आई०, 26 अगस्त 1894), बाचा, रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 32, मराठा, 16 दिस० 1894, ए० बी० पी०, 29 दिस० 1894, हनु प्रकाश, 24 दिस० 1894; बगबासी, 22 दिसबर, सजीवनी, 22 दिस०, दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 24 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 29 दिस० 1894), मद्रास स्टैंडर्ड, 24 दिस० 1894 ट्रिब्यून, 26 दिसबर 1894 (आई० एस० बी० ओ० आई०, 13 जनवरी 1895), ज्ञान प्रकाश 27 दिस० 1894 बिहार

- हेराल्ड, 29 दिस० 1894 इंडियन मिरर, 30 दिस० 1894 (वही, 20 जनवरी 1895); हिंदुस्तान, 4 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 9 जनवरी 1895); रहबर, 8 जनवरी (वही, 16 जन० 1895), पैसा अखबार, 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी 1895); पी० ए० बारलू, एल० सी० पी०, 1896 खंड XXXV, पृ० 83-4 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 91 पादटिप्पणी; एडवोकेट, 28 जनवरी (आई० एस० बी० ओ० आई०, 22 मार्च, 1896), समय, 31 जनवरी, बगबासी, 1 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896), कर्नाटक प्रकाशिका, 3 फरवरी, केरल पत्रिका, 8 फरवरी, कासिम उल अखबार, 3 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 15 फरवरी 1896) कुछ वर्षों के उपरांत आर० सी० दत्त ने पुष्टि की कि सीमा शुल्क क पारणामस्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग का मार्ग शताब्दी के अंतिम वर्षों में अवरुद्ध हो गया था (ई एच II, पृ० 541) तथा देखिए, वही, पृ० IX और उसकी स्पीचेज II, पृ० 46, 80, 127 1904 में गोखले ने भी इसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किया था देखिए, स्पीचेज, पृ० 77 और देखिए, श्रीराम एल० सी० पी०, खंड LII पृ० 104 05 और इंडियन पीपुल, 19 जनवरी 1905
- 77 बाचा रिप० आई० एन० सी०—1894 पृ० 32, ए० बी० पी०, 29 दिसंबर 1894, बगबासी, 22 दिसंबर (आर० एन० पी० बग०, 29 दिस० 1894), ज्ञान प्रकाश, 27 दिसंबर 1894, बिहार हेराल्ड, 29 दिसंबर 1894 (आई० एस० बी० ओ० आई०, 20 जनवरी 1895)
- 78 हिंदू, 11 जुलाई 1894, ट्रिब्यून, 18 जुलाई (आई० एस० बी० ओ० आई०, 26 अगस्त 1894), बाचा रिप० आई० एन० सी०—1894 पृ० 32, स्पीचेज, पृ० 432 ए० एल० मुदालियर वही, पृ० 33, पैसा अखबार 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी 1895), बी० एन० आप्टे, रिप० आई० एन० सी०—1895, पृ० 160, बारू मिहिर 3 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 15 फरवरी 1896) दन स्पीचेज II पृ० 46, 80 एस० एन० बैनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 694
- 79 मगठा, 26 जनवरी 1896, हिंदू, 27 जन० 1896 इंडियन स्पेक्टेटर, 26 जन० 1896, बंगाली, 1 फरवरी 1896 इंडियन नेशन, 27 जनवरी एडवोकेट, 28 जनवरी इंडियन मिरर, 30 जनवरी (आई० एम० बी० ओ० आई०, 22 मार्च 1896), बिहार हेराल्ड, 8 फरवरी (वही, 5 अप्रैल 1896) 1 फरवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह के बर्बर के प्राय सभी समाचारपत्र, आर० एन० पी० बग, 1 फरवरी 1896, समय, 31 जनवरी सजीवनी, 1 फरवरी, (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896), कर्नाटक प्रकाशिका, 3 फरवरी और केरल पत्रिका, 1 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 15 फरवरी 1896), हिंदुस्तानी, 29 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 5 फरवरी, 1896), पूना मावंबर्निक सभा के अध्यक्ष का तार, पी० पी० (एच० आफ० सी०), सी 8078 आफ 1896 पृ० 171, बोरमाद, जिला केरा, बर्बर में हुई जन-सभा द्वारा अभिव्यक्त विरोध, वही, पृ० 193 पी० ए० बारलू, एल० सी० पी०—1896 खंड XXXV पृ० 86 आई० एन० सी०—1902 का प्रस्ताव XVI गोखले, स्पीचेज, पृ० 10 77.
- 80 बंगाली, 8 फरवरी 1896, समय, 31 जनवरी सजीवनी, 1 फरवरी, दर्भंग, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896), आर्यजनप्रियान, 1 फर० (आर० एन० पी० एम०, 15 फरवरी 1896), बर्बर प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के प्रधान का तार पी० पी० (हाउस आफ कामस) 1896 सी 8078 पृ० 163 बर्बर की जनसभा में पारित प्रस्ताव, वही, पृ० 166
81. बाचा रिप० आई० एन० सी०—1894 पृ० 31, मगठा, 16 दिस० 1894 बैनिक औ समाचार

चन्द्रिका, 19 दिसंबर (आर० एन० पी० बग०, 22 दिसंबर 1894), सजीवनी, 22 दिसंबर (वही, 29 दिसंबर 1894 (आई० एस० बी० ओ० आई०, 13 जनवरी 1895), ज्ञान प्रकाश, 27 दिस० 1894, बिहार हेराल्ड, 29 दिस० 1894 इंडियन मिरर, 30 दिस० 1894 (वही, 20 जनवरी 1895). इस तथ्य पर विशेष बल नहीं दिया गया जैसाकि वित्त सदस्य ने स्वयं लैजिस्लेटिव काँग्रेस में कहा 'हमन इसमें मिलने वाले राजस्व के वर्तमान साधन के रूप में इसका प्रस्ताव नहीं किया है' (एल० सी० पी० 1894, खंड XXXIII पृ० 384) इसके अतिरिक्त भारतीय नानाओं को यह मध्य स्वतः माफ़ी के रूप में प्रतीत हुआ 1904 में वित्त सदस्य की इस टिप्पणी कि, 'आयात शुल्क से कबन 20½ लाख रुपये के राजस्व की ही प्राप्ति होती है' पर गोखले ने निरस्तराभ्युक्त बड़ा उत्तर दिया यदि मेरे माननीय मित्र गचमुच यह विश्वास करने हैं कि सीमा शुल्क इग्निए नगाए गए हैं कि इनसे राजस्व को आय होती है, जिन्हे सरकार नहीं छोड़ सकती तो कदाचित् भारत में जयवा इंग्लैंड में ऐसा मोचने वाले वे अकेले व्यक्ति होंगे (स्पीचज, पृ० 78) तथा श्रीराम, एल० सी० पी०—1903 खंड XLII पृ० 104-05.

- 82 वाचा, रिप० आई० एन० सी०—1902 पृ० 142-3
- 83 1904 में इस स्थापना की गोखले ने उस समय स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जब उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया कि, 'अब इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह शुल्क वास्तव में ही उपभोक्ताओं द्वारा, उपभोक्ताओं में अतिप्राय अधिराश निर्धन समुदायों, द्वारा ही चुकाया जाता है' (स्पीचज, पृ० 77) इग्नमे पूर्व 1902 में उस समय वे और भी अधिक सतर्क थे जब उन्होंने कहा था कि भारत का एक भाग अनन्त गरीबों के ऊपर ही पड़ता है (वही, पृ० 10).
- 84 हिंदू, 11 जुलाई 1894, ट्रिब्यून, 18 जुलाई (आई० एम० बी० ओ० आई०, 26 अगस्त 1894), वाचा रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 32, हनु प्रकाश, 31 दिसंबर 1894, ट्रिब्यून, 26 दिस० 1894 (आई० एम० बी० ओ० आई०, 13 जन० 1895), ज्ञान प्रकाश, 27 दिस० 1894, बिहार हेराल्ड, 29 दिस० 1894, इंडियन मिरर, 30 दिस० 1894 (वही, 20 जन० 1895) वाचा, स्पीचज, पृ० 430 और रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 157-8 दत्त; ई एच II, पृ० 540 गोखले स्पीचज, पृ० 412.
- 85 आई० एन० सी० 1894 का प्रस्ताव I, ए० एम० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 33, मराठा, 16 दिस० 1894, इंडियन स्पेक्टेटर, 30 दिस० 1894, दिनपदी, 28 दिस० 1894 (आर० एन० पी० बग०, 5 जनवरी 1895) केसर-ए-हिंदू, 30 दिसंबर 1894 (आर० एन० पी० बग० 5 जनवरी 1895) ताज उल अखबार, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बी०, 12 जनवरी 1895), पैमा अखबार, 26 जनवरी (वही, 9 फरवरी 1895)
- 86 एल० सी० पी०, 1894 खंड XXXIII पृ० 402-03 420, 450
- 87 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव 'XXI' एस० एन० बैंनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 259-61. वाचा रिप० आई० एन० सी०—1895 पृ० 157-8, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी०—1896 खंड XXXV पृ० 80, 82.
- 88 वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 158 एस० एन० बैंनर्जी . सी० पी० ए०, पृ० 295, पी० ए० चारलू पूर्वोक्त स्थल, पृ० 80
- 89 उदाहरणार्थ, दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 5 फरवरी 1896 के प्रक में लिखा . हमारे कुछ समकालीन इतने आशावादी हैं कि वे यह विश्वास सहज में ही कर लेते हैं कि यह विरोध .. भविष्य में फल लाएगा—अपनी सरकार को होश में लाएगा वस्तुतः यह सोचना एक गलती

है कि अपनी सरकार होश में नहीं। उदार अथवा अनुदार ब्रिटिश सरकार के पास इतनी अधिक अकल (होश) है कि वह उसे दूसरों को दे सकती है। वह जानबूझकर लकाशायर को प्रसन्न करने के लिए भारत के प्रति बड़ा भारी अन्याय कर रही है परंतु प्रश्न यह है कि सरकार कर ही क्या सकती है ? उदार हो अथवा अनुदार, लकाशायर के मतो की उपेक्षा तो कोई भी दल नहीं कर सकता (आर एन० पी० बग०, 9 फरवरी 1896)

90. प्रस्ताव I, तथा बाचा : रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 31-3 पी० ए० चार्ल्स एल० सी० पी० 1896, खंड XXXV, पृ० 81, मालवीय स्पीचेज, पृ० 37-8 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 192, गोखले . स्पीचेज, पृ० 5, 41 एस० एन० बैंनर्जी—सी० पी० ए० पृ० 694, दत्त, ई एच II, पृ० IX, 531, 534, स्पीचेज II, पृ० 126 पीछे 65 और 68 सदस्यों में उल्लिखित प्रायः सभी समाचारपत्र
- 91 पी० मेहता . स्पीचेज, पृ० 390 इसी प्रकार बगबासी ने अपने 9 फरवरी 1896 के भ्रक में लिखा भारतीयों को अब समझ आ गई है कि सरकार भारतीयों को उस उद्योग को ज़िम्मे भ्रगरेजों की रचि है अथवा जिसमें उनके हितों के भारतीयों के हितों के साथ टकराव की संभावना है, के सफलतापूर्वक संचालन की अनुमति कभी नहीं देगी (आर० एन० पी० बग०, 15 फरवरी 1896)
- 92 सी० पी० ए० में, पृ० 527
- 93 आर० एन० पी० एम०, 15 जनवरी 1895 इसी प्रकार 30 दिसंबर 1894 के भ्रक में 'अरुणोदय' ने यह विश्वास प्रकट किया कि कपास आयात शुल्क के अधिनियम को पारित करके सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह भारतीय मिलों का विकास और उनकी समृद्धि नहीं चाहती (आर० एन० पी० बब, 5 जनवरी 1895), वस्तुतः नेटिव प्रेम के बर्बई सवाददाता ने लिखा इस सप्ताह के अन्य अनेक भारतीय समाचारपत्रों ने कपास शुल्क बिल के पास होने पर अपनी अस्वीकृति सरकार की भारत में औद्योगिक प्रवृत्ति के हितों के प्रति उदासीनता से जन्मी अपने दिल की भड़ास और निराशा को प्रकट करने वाली भाषा प्रकट में की है (वही)
- 94 उदाहरणार्थ 2 फरवरी 1896 के भ्रक में दर्शक ने सरकार को चेतावनी दी इस पथभ्रष्ट नीति के निरंतर अनुसरण से भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के न्याय और सच्चाई पर से विश्वास उठने लगा है इससे पूर्व 1894 में रासबिहारी घोष शासन को सचेत कर चुके थे कि चुगो कर के द्वारा छल-कपट करने से इंग्लैंड की न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रमिद्धि, जो किसी भी मूल्य पर रक्षणीय और स्पर्धा योग्य है, दाव पर है इंग्लैंड ने इतने दीर्घकाल में आज तक तीरो-तलवार से भी अधिक सशक्त जो प्रभाव अपनी प्रजा पर डाला है, जिसके कारण प्रजा इस विशाल साम्राज्य की कफावार है, उस प्रभाव के विनष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है (स्पीचेज, पृ० 152-3) केवल भारतीयों ने खतरे की चेतावनी नहीं दी थी, जनरल जी० चिसनी ने भी बराबर जोर देकर 1894 में भविष्यवाणी की थी कि यदि समुचित पग उठाने में देर की गई तो भारत सरकार की सम्भावनाओं और चरित्र को ऐसी क्षति पहुँचेगी जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं और होंगे (पूर्वोद्धृत, पृ० 347) तथा देखिए, पृ० 290 इसी प्रकार 1894 में कपास के आयात पर शुल्क की छूट का विरोध करने वाले इंडियन काँसिल के छ सदस्यों में से एक सर ए० ऐरबुथनार ने अपने असहमति भाषण में चेतावनी दी 'ब्रिटिश राज्य के नाम से जाने जाने वाले जटिल यत्न के लिए यह निश्चित है कि भारत के हितों में और ग्रेट ब्रिटेन के हितों में आवश्यक दृढ़ बंधन हो। ऐसा कोई पग नहीं उठाना चाहिए जिससे महामामयी महारानी की भारतीय प्रजा में असंतोष उत्पन्न होता हो अथवा जिससे ब्रिटिश शासन पर उनके विश्वास को

घबका लगता हो ऐसा कोई भी पग राज्य के हित का विरोधी ही माना जाएगा (बकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 427)

- 95 मूल पाठ मे उद्धृत लेखको के अतिरिक्त देखिए, 'स्वदेशमित्रन, 21 दिसंबर 1894 कर्णाटक प्रकाशिका, 14 जनवरी 1895 (आर० एन० पी० एम०, 15 जनवरी 1895) सजीवनी, 22 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 29 दिस० 1894), बगाली, 22 दिस० 1894, बार० एन० पी० एन०, 23 जनवरी 1895, ताज उल अखबार, 5 जनवरी (आर० एन० पी०, 12 जनवरी 1895), इंडियन स्पेक्टेटर, 26 जून 1896, समय, 31 जनवरी, दर्शक, 2 फरवरी, सजीवनी, 1 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896), बर्बई के लगभग सभी समाचारपत्र विशेषतः नेटिव ओपीनियन, 26 जनवरी, इंदु प्रकाश, 27 जनवरी और गुजराती, 26 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 1 फरवरी 1896), स्वदेशमित्रन, 11 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 1896), बगाली 8 फरवरी 1896, वाचा, स्पीचेज, पृ० 431, दत्त, स्पीचेज II पृ० 127, बावे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन का स्मरणपत्र, पी० पी० (हाउस आफ कामस) 1896 सी 8078 पृ० 163 तथा वही, पृ० 193
- 96 आर० एन० पी० बब, 1 फरवरी 1896 दस सप्ताह बाद 11 फरवरी 1896 के अंक मे केसरी ने फिर लिखा गत सोमवार से पहले अनुचित बपास शुल्क स्वीकृत करके भारत सरकार ने सारे ससार के सामने यह गलत कर दिया है कि वे इस देश के लोगों के हितों के लिए भारत पर शासन नहीं करते प्रत्युत इस शासन का उद्देश्य थोड़े से अंगरेज व्यापारियों के हितों की ही रक्षा करना है
- 97 एल० सी० पी०—1896 खंड XXXV पृ० 85
- 98 मानवीय, स्पीचेज, पृ० 345 तथा केसरी, 11 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 15 फरवरी 1896), दैनिक औ समाचार चन्द्रिका (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896), दत्त : ई एच II पृ० 542-3
- 99 मालवीय स्पीचेज, पृ० 37-8
- 100 वही पृ० 26 और वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1894, पृ० 33 दैनिक औ समाचार चन्द्रिका ने 5 फरवरी 1896 के अंक मे घोषणा की कि ब्रिटिश मन्त्रिमंडल लकाशायर का दास है और यहाँ की सरकार ब्रिटिश मन्त्रिमंडल की दास है (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1896) अरुणोदय ने पहले ही 30 दिसंबर 1894 के अंक मे घोषणा की थी - माचेस्टर के उत्पादक ही हमारे असली शासक हैं और भारत राज्य मन्त्रि का वचन ही असल मे हमारे लिए कानून है (आर० एन० पी० बब 5 जनवरी 1895) इस परवर्ती दृष्टिकोण को 'भारत जीवन' ने 10 फरवरी के अंक मे (आर० एन० पी० एन, 12 फरवरी 1896), अखबार-ए-आम ने 14 फरवरी के अंक मे (आर० एन० पी० पी० 22 फरवरी 1896), और स्वदेशमित्रन ने 11 फरवरी के अंक मे (आर० एन० पी० एम, 29 फरवरी 1896) मे प्रतिध्वनित किया।
101. वाचा, रिप० आई० एन० सी०—1894 पृ० 33 इंदु प्रकाश, 31 दिसंबर 1894. और सुबोध पत्रिका 30 दिसंबर 1894 (आर० एन० पी० बब, 5 जनवरी 1895)
- 102 आर० एन० पी० बग०, 15 फरवरी 1896
- 103 दत्त इंडियन पालिटिक्स, पृ० 53 इसी प्रकार 3 फरवरी 1896 के अंक मे कर्णाटक पत्रिका ने यह राय प्रकट की आवश्यकता यह है कि भारत मे भारतीयों की ही सरकार हो. लोगों को और अधिक विस्तृत कौंसिल को पाने की चेष्टा करनी चाहिए और साथ ही देखना चाहिए कि

- देश की जनता की भावना के सच्चे प्रतिनिधि ही उनके सदस्य हों। (आर० एन० पी० एम०, 15 फरवरी 1896)
104. गोखले, स्पीचेज, पृ० 41 इसी प्रकार 1901 में आर० सी० दत्त ने टीका की यह तो किसी भी जाति की सहज प्रवृत्ति में नहीं है कि वह दूसरी जाति के हितों के लिए अपनी जाति के हितों की उपेक्षा करे (स्पीचेज II, पृ० 113)
105. इस दिशा में राष्ट्रीय प्रयास की जाच कुछ वर्षों के बाद लावट फ्रेजर ने की और उसमें इस सबंध में जो शब्द कहे, उनमें लोकमान्य की टिप्पणियाँ ही प्रतिबिम्बित होती हैं 'यह एक ऐसा विषय है, जिसपर मुझे विश्वास है कि इस समय सारा भारत समर्पित है सभी समुदाय, हिंदू, मुसलमान, बफादार, अराजकतावादी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, चुप्पी माधे कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग और अशिक्षित गैरसरकारी यूरोपीय सबके सब यही चाहते हैं कि भारतीय ऋण पद्धति का निपटारा भारत के हित में ही होना चाहिए इस समय उनके विचार में इंग्लैंड के हितों का ही प्राथमिकता दी जा रही है (पूर्वोद्धृत, पृ० 339-40)
106. 1896 के बहिष्कार आंदोलन के विस्तृत विवरण के लिए देखिए, पीछे अध्याय 3
107. तिलक महोदय ने यह स्पष्ट दिखाया कि दखिण, मराठा, 9 फरवरी 1896 इसमें लक्ष्मीधर व वस्त्रों के बहिष्कार के सबंध में लिखा गया है : ब्रिटेन के व्यापारियों को हमें अपनी आशा नहीं कर सकते भारत के लिए एक ही उपाय बचा है, उसे अपनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए
108. भारत सरकार का प्रेषण, संख्या 27 (वित्त, दिनांक 26 जनवरी 1899, कर्जन स्पीचेज I, पृ० 62, 64, 65, और वेस्टमैन, एन० सी० पी० 1899, खंड XXXVIII पृ० 175, 129)
109. कर्जन स्पीचेज I, पृ० 62 उसमें आगे कहा 'हम अपनी ही ओर से अपनी स्वयं की मांगों का सामर्थ्य का अपनी स्वयं की पटल का इस्तेमाल कर रहे हैं यह बात अलग है कि हमें भारत में अधिकारी प्रतियोगिता से मुक्त करना है' उनके विचारों में जेम्स वेस्टमैन और अधिर बल देकर कहा यदि हमारा विधान विशुद्ध रूप में भारतीयता पर आधारित है और केवल इस देश की ही रक्षा करता है और बहुसंख्यक देशांतरवासियों की आजीविका के माध्यमों की रक्षा में सहायता करता है तो मेरा विचार है कि मैं इस तथ्य को इस बिल के अनिवार्य समर्थक कारण के रूप में कौमिल के सामने रख सकता हूँ (एन० सी० पी०—1899 खंड XXXVIII पृ० 173-4)
110. कर्जन स्पीचेज I, पृ० 61-2
111. एम० जी० रानाडे 'प्ली फार प्रोटेक्शन-इंडियन शुगर इंडस्ट्री' शीर्षक से एम० जी० रानाडे ने तीन लेख टाइम्स आफ इंडिया में जून 1899 के लिए लिखे थे, इनकी भूमिका वी० जी० काले द्वारा लिखी गई थी (बबर्दी, निधि रहित)
112. पी० ए० चार्ल्स एन० सी० पी०—1899 खंड XXXVIII पृ० 134, 175-9 और दत्त द्वारा 'माचेस्टर गाजियन' तथा 'टाइम्स' का भेजे गए और 'इंडिया' (31 मार्च 1899) में पुनः प्रकाशित पत्र
113. ए० बी० पी० 8, 22, 24 मार्च 1899, बंगाली, 18 मार्च 1899, हिंदू, 18, 21 मार्च 1899, मराठा, 26 मार्च 1899, इंडियन स्पेक्टर, 26 मार्च 1899; एडवोकेट 14 मार्च, मद्रास स्टैंडर्ड, 17 मार्च (आई० एस० वी० ओ० आई०, 26 मार्च 1899), इंडियन मिरर, 23 मार्च (वही,

2 अप्रैल 1899), सत्य विजय, 23 मार्च, कैसर-ए-हिंद, 19 मार्च (आर० एन० पी० बब, 25 मार्च 1899), दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 22 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 25 मार्च 1899) समय, 24 मार्च, हितवादी, 24 मार्च, बगवासी, 25 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1899); 'उडिया और नवसवाद, 29 मार्च, मवादरदुका, 16 मार्च, उल्कलदीपिका (तिथि रहित) (वही 17 जून 1899), गिविल एंड मिलिट्री न्यूज, 15 मार्च अखबार ए आम, 14 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 18 मार्च 1899) तथा जी० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० पी०—1899 खड XXXVIII पृ० 174-5

- 114 22 अगस्त 1898 को ही उसने यह माग की और तीन महीन बाद 18 नवंबर का उमन सरकार से तत्काल अनुग्रह पोषित चीनी पर गम करने वाले शुल्क नगान को कहा कुछ दिन पूर्व 14 नवंबर 1898 को सही स्थिति पर आने के लिए उसने लागा का एकजुट होकर विदेशी चीनी की खपत बढ़ कर देने का परामश दिया और सलाह दी कि यदि लोगों में यह प्रचारित किया जा सके कि विदेशी चीनी में गर्दी घृणोत्पादक बस्तुओं का प्रयोग होता है ना लोगों का अपन पक्ष में लाया जा सकता है 'हिंदुस्तान' ने भी 20 नवंबर व अग्रे में इस प्रकार का गमबंन दिया (आर० एन० पी० ए०, 22 नवंबर 1898) और 'भारत जीवन' 28 नवंबर वही, 6 दिसंबर 1898)
- 115 पी० सी० राय दि इंडियन शुगर इयूटी (1 मई 1899 कलकत्ता), इस विषय में लिखन वाले और पत्र थे प्रतिवासी, 17 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 22 अप्रैल 1899), गुजराती, 19, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 25 मार्च, 1 अप्रैल 1899), हितचक्र, 23 मार्च (वही 25 मार्च 1899) इगक पत्रवान शास्त्री इस छोटे से वर्ग में अनेक समाचारपत्र सम्मिलित हो गए आगे दिखान
- 116 पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 5/3 मेहता महादय की अनिश्चित स्थिति के कारण एक ओर तो लाई वर्जन को वाद विवाद में हस्तक्षेप करने हुए यह कहना पड़ा कि 'यद्यपि माननीय श्री मेहता ने विषय से सम्बंधित पक्ष की विस्तृत आलोचना की है परंतु मेरा विश्वास है कि उन्होंने इस बिल को अस्वीकार नहीं किया व प्रस्तुत साधन के सामान्य सिद्धांत को स्वीकृति देने का प्रस्तुत है, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है, (स्पाचज, I पृ० 61) और दूसरी ओर डी० ई० वाचा न 1906 में उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा समादरणीय पी० एम० मेहता पर्याप्त दूरदर्शी होन के कारण महान और सफल विचारक है उन्होंने शुल्क लगाने के पक्ष में प्रस्तुत तर्कों के विरुद्ध बड़ी ही समर्थ और तेज आवाज उठाई है (स्पीचज, पृ० 173)
117. राय, इंडियन शुगर इयूटीज, पृ० 5-7, 12, 17-20, गुजराती, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 1 अप्रैल 1899) राय महोदय के अनुसार ऐसा एक अन्य पक्ष था, बंगाल की चीनी के इंग्लैंड, अमरीका और यूरोप के निर्यात में कमी पी० मेहता ने भी इसी प्रकार के तथ्य को वाणी दी यह सत्य है कि देश में कतिपय चीनी मिलों में काम ठप्प हो गया है परंतु जो तथ्य हमारे सामने रखे गए हैं, उससे मुझे यह पूरा विश्वास नहीं होता कि इसका एकमात्र अथवा प्रमुख कारण आवश्यक रूप से अनुग्रह पोषित चीनी का आयात ही है (स्पीचेज, पृ० 573)
118. 17 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 22 अप्रैल 1899)
119. रानाडे : प्ली फार प्रोटेक्सन, पृ० 5, 7-9, 13, भारत जीवन, 27 मार्च, (आर० एन० पी० एन०, 27 मार्च 1899); अखबार ए आम, 14 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 18 मार्च 1899), पी० ए० चारमू : एल० सी० पी०, खड XXXVIII पृ० 176; जी० आर० एम० चितनवीस :

वही, पृ० 175

- 120 रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 10 12, 13
- 121 दत्त, इंडिया 11 मार्च 1899, ए० बी० पी०, 22 मार्च 1899, हिंदू, 18 मार्च 1899, दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 22 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 25 मार्च 1899), हितवादी, 24 मार्च (वही 1 अप्रैल 1899); भारत जीवन, 27 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 28 मार्च 1899); हिंदुस्तान, 14 अप्रैल (वही 19 अप्रैल 1899)
- 122 रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 6
123. राय, इंडियन शूगर इयूटीज, पृ० 6, 7, गुजरात, 19, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 25 मार्च, 1 अप्रैल 1899), प्रतिवासी 17 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 22 अप्रैल 1899).
124. रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 3, ए० बी० पी०, 18 नवंबर 1898, 22 मार्च 1899, पी० ए० चारलू एल० सी० पी०-1899, खंड XXXVIII पृ० 176, समय, 24 मार्च (आर० एन० पी० बग० 1 अप्रैल 1899)
- 125 पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 1899, खंड XXXVIII पृ० 127 तथा दत्त, इंडिया 31 मार्च 1899; हिंदू 21 मार्च 1899, हिंदुस्तान, 14 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 19 अप्रैल 1899), भारत जीवन, 1 मई (वही, 3 मई 1899)
- 126 राय इंडियन शूगर इयूटीज, पृ० 2-4, 6-7, 24 तथा गुजराती 19 मार्च (आर० एन० पी० बब, 25 मार्च 1899), 14 मई (वही, 20 मई 1899)
- 127 राय, इंडियन शूगर इयूटीज, पृ० 12
- 128 वही, पृ० 22-3
- 129 1899 की पी० पी० (हाउस आफ कामस) खंड-66, सी-9287 ब्यू बूक ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि भारत सरकार ने अपने संप्रेषण में दृढतापूर्वक स्वीकार किया कि आयातित चीनी ने सापेक्षिक दृष्टि से भारत के गन्ना उत्पादक को प्रभावित नहीं किया अतः सरकार ने चीनी पर मम करने वाले शुल्क को लगाने से इनकार कर दिया इसपर राज्य सचिव ने दो बार, एक बार अपने 25 अगस्त 1898 के संप्रेषण में और दूसरी बार 26 जनवरी 1899 के संप्रेषण में मारिशस के किसानों से प्राप्त आवदनपत्र भेज जिनमें अनुग्रह पोषित चीनी के विरुद्ध भारत में सरक्षक साधन बरतने की मांग की गई थी साथ ही सचिव ने भारत सरकार पर जड़े शिष्ट ढंग से दबाव डाला कि वह इस मांग को स्वीकार कर ले
- 130 ए० बी० पी०, 24 मार्च 1899 यह बहुत लोगों का दृष्टिकोण प्रतीत होता है यह दूसरी बात है कि नेटिव प्रेस के बहुत मारे सवाददाताओं ने दुर्भाग्यवश इंडियन प्रेस के साप्ताहिक सार-संक्षेपों में इस दृष्टिकोण के उल्लेख को आवश्यक नहीं समझा उनका मतव्य कदाचित यह था कि सरकार की कार्यवाही के समर्थन में ही उपर्युक्त दृष्टिकोण समाविष्ट है सरकारी कार्यवाही के अन्यथा विरोधी 'गुजराती' ने अपने 14 मई 1899 के अंक में भारतीय प्रेस में सरकारी ह्रादो का जिस विश्वास के साथ वर्णन किया था, उसका पूरा ही उल्लेख किया (आर० एन० पी० बब, 20 मई 1899) बाबा ने भी 1906 में इस धारणा पर अपने विचार प्रकट किए (स्वीचेज, पृ० 173)
- 131 बाबा स्वीचेज, पृ० 173 'समय' के 24 मार्च (आर० एन० पी० बग०, अप्रैल 1899) के निम्न-लिखित अवतरण में यह भावना चित्रित है साईं कर्जन ने इस बिल को पास करने के रूप में भारतीय जनता के प्रति जो उच्चाश्रयता और सहानुभूति तथा इससे भी बढ़कर कर्तव्य परायणता

का परिचय दिया है, उससे प्रत्येक भारतीय घर में उनके प्रति आदर की भावना दृढ़ होगी, और देखिए, भारत जीवन, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 4 अप्रैल 1899)।

132. गुजराती ने अपने 14 मई 1899 के धक में लिखा कि भारत सरकार और भारत सचिव के बीच हुए सारे पत्र व्यवहार से स्पष्ट होता है कि कुशल चैबरलेन (उपनिवेश राज्य सचिव) ने अपने नकली शस्त्रों से विजय प्राप्त की है और उसने सचमुच ही सारी भारतीय जनता के छोटे से बड़े तक सभी व्यक्तियों को मूख बनाया है (आर० एन० पी० वब, 20 मई 1899)
133. ए० बी० पी०, 1 जून 1899 हिंदू, 12 मई 1899 (हालार्कि यह द्विविधाग्रस्त था), ट्रिब्यून, 30 मई, इंडियन मिरर, 12 मई, मद्रास स्टैंडर्ड, 11 मई (आई० एस० बी० ओ० आई०, 21 मई 1899), सजीवनी, 11 मई (आर० एन० पी० वग०, 20 मई 1899), सत्य विजय, 17 मई, केसरी 16 मई हितैच्छु 18 मई (आर० एन० पी० वब, 20 मई 1899)
134. रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 2
135. एल० सी० पी०, 1901 खंड XL पृ० 281 तथा दत्त ई एच II, पृ० 523
136. ए० बी० पी०, 20 मई 1899, इंडियन मिरर, 12 मई, मद्रास स्टैंडर्ड, 11 मई (आई० एम० बी० ओ० आई०, 21 मई 1899)
137. ए० बी० पी०, 20 मई और 1 जून 1899, हिंदू, 21 मई 1899, मद्रास स्टैंडर्ड, 11 मई (आई० एस० बी० ओ० आई० 21 मई 1899), गूढवाकेट, 19 मई (वही, 28 मई 1899)
138. रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 6
139. ए० बी० पी०, 20 मई 1899
140. रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 6
141. ए० बी० पी०, 20 मई 1899, सजीवनी, 11 मई (आर० एन० पी० वग० 20 मई 1899)
142. रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 6
143. वही, पृ० 17-21
144. देखिए आगे अध्याय 11
145. ज० एफ० फिनले एल० सी० पी०-1002, खंड XLI पृ० 216 कर्जन स्पीचेज III, पृ० 20, दत्त ई एच II, पृ० 523
146. लोवाट फ्रेजर पूर्वोद्धत, पृ० 342, परिमल राय पूर्वोद्धत, पृ० 84
147. कर्जन स्पीचेज III, पृ० 5 तथा देखिए इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1906) खंड III, पृ० 288-90
148. पी० ए० चारलू एल० सी० पी०-1699 खंड XXVIII पृ० 134
149. वही, पृ० 178-9, मराठा, 26 मार्च, 2 अप्रैल 1899, हिंदू 16, 21 मार्च, 12 मई 1899, बंगाली, 18 मार्च 1899, इंडियन मिरर, 23 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई०, 2 अप्रैल 1899), सत्य विजय, 17 मई (आर० एन० पी० वब, 20 मई 1899), बगबासी, 25 मार्च, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 1, 8 अप्रैल 1899), उडिया और नवसबाद 29 मार्च (वही, 17 जून 1899); 21 अप्रैल 1902 के न्यू इंडिया में विपिनचंद्र पाल ने स्पष्टता से स्वीकार किया कि उन्होंने 1899 में यह जानते हुए कि यह चीनी आयात शुल्क भारतीयों के हितों में न होकर ब्रिटिश पूंजीपतियों और मारिशस के हितों के लिए ही सुरक्षापरक है, उसका समर्थन इसलिए किया था कि इसे मैंने एक नए सिद्धांत के रूप में देखा था, यह सड़े-गले स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत से स्वस्थ निवर्तन था भारत सरकार के मन में भी इसे लागू करते समय यही भावना

काम कर रही थी। जेम्स बेस्टलैंड ने घोषित किया था ' मैं अपनी राज करनीति में एक संबंध बनाए अध्याय का उद्घाटन करने जा रहा हूँ ' (एल० सी० पी०-1899 खंड XXXVIII पृ० 124) इस बिल का समर्थन करते हुए लार्ड कर्जन औद्योगिक रूप से पिछड़े देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के सदर्भ में सरसक मित्रता का शानदार ढंग से बचाव करते हुए प्रतीत होते हैं (स्पीचेज I, पृ० 63-4)

- 150 रानाडे की प्ली फार प्रोटेक्शन मे बी० जी० काले की भूमिका पृ० IV और V.
- 151 जे० एफ० फिनले एल० सी० पी० 1902 गड XLI पृ० 215-7 कब्रन, स्पीचेज III, पृ० 1-2
- 152 कर्जन : स्पीचेज III, पृ० 6
- 153 ए० बी० पी०, 25, 26 अप्रैल 1902, न्यू इंडिया, 21 अप्रैल, 12 जून 1902, मराठा, 15 जून 1902 कैमर ए हिंद, 1 जून, कैमरी, 3 जून, द्रु प्रकाश, 2 जून (आर० एन० पी० बग 7 जून 1902), वायम आफ इंडिया, 21 जून 1902, प्रतिवासी, 26 मई (आर० एन० पी० बग०, 31 मई 1902), हितवादी, 30 मई (वही, 7 जून 1902) सजीवनी, 12 जून, इंडियन मिरर, 8 जून (वही, 21 जून 1902), पावर ऐंड गार्मिन, 1 जून (बी० आ० आई०, 28 जून 1902)
- 154 न्यू इंडिया, 12 जून 1902, कैमर ए हिंद (आर० एन० पी० बग, 14 जून 1902), प्रतिवासी, 26 मई (आर० एन० पी० बग०, 31 मई 1902), हितवादी, 30 मई (वही, 7 जून 1902)
- 155 14 जून (आर० एन० पी० बग०, 21 जून 1902) ट्रिब्यून न भी 27 मई 1902 के प्रक मे बिल का विरोध करने से इनकार कर दिया (बी० आ० आई०, 28 जून 1902)
- 156 मराठा, 25 मई, 8 जून 1902, ए० बा० पी० 21 अप्रैल 1902, वेसरो, 3 जून, द्रु प्रकाश, 2 जून (आर० एन० पी० बग, 7 जून 1902), माध ही कैमरी ने अपने पाठकों का चेनावनी दी कि 'माचेस्टर के लिए भारतीय चीनी उद्योग को पगु बनाने वाली सरकार मे भारतीय उद्योगों के प्रोत्साहन की आशा करना समुद्र के खारे पानी से चीनी निकालन की चष्टा करना है'
- 157 न्यू इंडिया 21 अप्रैल 1902 सजीवनी, 12 जून (आर० एन० पी० बग०, 21 जून 1902)
- 158 स्ट्रैची इंडिया (1903) पृ० 182
- 159 बंगाली, 4 फरवरी 1888, इंडियन मिरर, 3 फरवरी, गुजरात मित्र, 5 फरवरी द्रु प्रकाश, 5 फरवरी (बी० आ० आई०, मार्च 1888), बावे समाचार, 11 फरवरी, गुजरान गजट 9 फरवरी, रास्त गुफ्तार, 5 फरवरी तथा अन्य अनेक समाचारपत्र (आर० एन० पी० बग, 11 फरवरी 1888), समय, 3 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 11 फरवरी 1888), हिंदुस्तान, 12 फरवरी, वृत्तधारा, 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 14 फरवरी 1888), पूना सार्वजनिक मभा का स्मरणपत्र, दिनांक 6 मार्च 1894, जे० पी० एस० एस०, खंड XVI स० 4 (अप्रैल 1894) पृ० 137, इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, दिनांक 8 मार्च 1894, रिपोट आफ दि इंडियन एसोसिएशन फार 1892-3 टु 1895-6, पृ० 43, सुप्रीम लॉजिस्टिक कौंसिल को बर्बई प्रेसीडेंसी का विरोध पी० पी० (हाउस आफ कामस) 1895 परचा 202, द्रु प्रकाश, 12 मार्च 1894, इंडियन स्पेक्टेटर, 11 मार्च 1894, कैमर ए हिंद, 4 मार्च, ज्ञान प्रकाश, 5 मार्च, सुधारक, 5 मार्च, गुजराती, 4 मार्च (आर० एन० पी० बग, 10 मार्च, 1894), आजाद, 9 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 14 मार्च 1894), कर्णाटक प्रकाशिका, 12 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 15 मार्च 1894); स्वदेशमित्र, 16 मार्च, मनोरमा, 19 मार्च, केरल पत्रिका, 17 मार्च, क्षामिम उस अखबार, 15 मार्च (वही, 31 मार्च 1894); जी० आर० एम० चितनवीस एल०

सी० पी० 1894, खंड XXXIII पृ० 155 ए० बी० पी०, 22 दिस० 1894.

160. पूना एवेंजनिक् सभा का स्मरणपत्र, दिनांक 6 मार्च 1894—पूर्वोक्त स्थल, पृ० 138, जे० यू० याज्ञिक का मातृवं बंबई प्रांतीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण; जे० पी० एम० एस०, खंड XVII स० 3 (जनवरी 1895); इंडियन एमोसिएशन का ज्ञापन, 8 मार्च 1894, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 43; सुप्रीम लेजिस्लेटिव कोमिल को बंबई प्रेसीडेसी का विरोध, पूर्वोक्त स्थल, मराठा, 4 मार्च 1894; बंगाली, 10 मार्च 1894, एडवाकट, 9 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई०, 15 अप्रैल 1894), ददु प्रकाश, 12 मार्च 1894 कंसर ए हिंद, 4 मार्च, ज्ञान प्रकाश, 5 मार्च, सुधारक, 5 मार्च (गुजराती, 4 मार्च (आर० एन० पी० बब, 10 मार्च 1894); जी० आर० एम० निनन्चीम, एल० सी० पी० 1894, खंड XXXIII पृ० 155 यह भी दिलचस्प बात है कि मराठा ने 25 जगून 1881 के अधि में भारतीय उद्योगों के हित में मराणा पर आयात शुल्क हटाने का माग था
161. पी० पी० (टाउम आक कामस), 1894 खंड 50 परचा 347 1894 खंड 62 परचा 112, 1887. 1. 1 पृ० 404
162. नाव समाचार, 31 मार्च (आर० एन० पी० बब, 1 अप्रैल 1882), ददु प्रकाश, 10 दिस०, नाव समाचार 14 दिस० (वही, 15 दिस० 1883), लोकमित्र, 16 दिस०, नाव क्रान्तिकल, 16 दिस०, गुजराती, 16 दिस० (वही, 22 दिसंबर 1883), ज्ञान प्रकाश, 21 फरवरी, (वही, 11 फरवरी 1884) मराठा, 13 जनवरी 1884, हिंदुस्तान 8, 9 जून (आर० एन० पी० पी०, 12 जून 1884), तथा पोल 164 मदम म उद्धृत समाचारपत्र और नतामण
163. प्रस्ताव VIII प्रस्ताव प्रस्तुत करने हुए सी० पी० बाबा ने इन कमे को अशिष्ट और मध्ययुगीन बिन इ अवशेष' के रूप में निरूपित किया रिप० आई० एन० सी० 1889, पृ० 56). इससे पूर्व मराठा ने 3 जून 1888 के अधि में भारतीय वस्तुओं के प्रमाणीकरण का अशिष्ट पद्धति को तीव्र भर्त्सना का 'इंडियन स्पेक्टर' ने भी 3 जून 1888 के अधि में इन शुल्कों को 'बंबई राजकर' तथा 'राजकराय अनुन' बताया
164. नाव समाचार, 31 मार्च (आर० एन० पी० बब, 1 अप्रैल 1882), रास्त गुफ्तार, 2 अप्रैल, हितचक्र, 6 अप्रैल गुजराती, 2 अप्रैल (वही, 8 अप्रैल 1882); ज्ञान प्रकाश, 24 अप्रैल (वही, 29 अप्रैल 1882, ए० बी० पी०, 22 फरवरी 1883, सजीवनी, 29 मार्च (आर० एन० पी० बब, 5 अप्रैल 1884), मार सुधारनाथ, 5 मई (वही, 10 मई 1884), समय, 12 मई (वही, 17 मई 1884), साधारणी, 15 जून (वही, 21 जून 1884); मराठा, 13 जनवरी 1884, 3 जून 1888, जे० यू० याज्ञिक, रिप० आई० एन० सी०, 1885, पृ० 66; बी० ओ० आई०, जुलाई 1888, ददु प्रकाश, 4 जून 1888; बंगाली, 9 जून 1888, हिंदू, 11 जून 1888; इंडियन स्पेक्टर, 3 जून, सुबोध पत्रिका, 3 जून, नेटिव ओपीनियन, 3 जून, इंडियन नेशन, 4 जून, ट्रिब्यून, 6 जून, बिहार हेराल्ड, 9 जून, मदुरा मेल, 16 जून (बी० ओ० आई०, जुलाई 1888); नसीमे आगरा, 30 मई, भारतवर्ष, 1 जून (आर० एन० पी० एन०, 5 जून 1889), सुबोध सिंधु, 5 जून (वही, 12 जून 1889); रणछोड़ लाल छोटेला, रिप० आई० एन० सी०, 1889, पृ० 56 तथा देखिए बी० ओ० आई० जून 1889.
165. आर० एन० पी० बब, 23 फरवरी 1884.
166. ए० बी० पी०, 22 फरवरी 1883, बी० ओ० आई०, जुलाई 1888, ददु प्रकाश, 4 जून 1888; बंगाली, 9 जून 1888; मराठा, 3 जून 1888; इंडियन स्पेक्टर, 3 जून, सुबोध पत्रिका, 3 जून,

मेटिब जोपीनियन, 3 जून, इंडियन नेक्जट, 4 जून, ट्रिब्यून, 6 जून, मद्रास मेल, 11 जून (बी० ओ० आई०, मुंबई 1888), गुजरात दर्पण, 21 अप्रैल, बिहार हेराल्ड, 27 अप्रैल, गुजराती, 28 अप्रैल, हनु प्रकाश, 29 अप्रैल, ट्रिब्यून, 15 मई (बी० ओ० आई०, जून 1889).

167 मराठा, 23 जनवरी 1884; बाबा : रिप० आई० एन० सी० 1889, पृ० 56.

168 मराठा, 13 जनवरी 1884, रिप० आई० एन० सी० 1889, पृ० 56. आई० एन० सी० 1889 का प्रस्ताव VIII.

अध्याय 7

मुद्रा और विनिमय

भारत में लोकमत निर्णायक उपायों को आनाने के लिए सर्वथा परिपक्व है और चादी के सिक्कों की ढलाई पर रोक को सामान्यतया स्वीकृति ही मिलेगी।

—भारत सरकार का 1892 में सप्रेषण

इंग्लैंड के निर्धनों की बचनों को इस प्रकार प्रभावित करने वाले किसी सुभाव पर एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यदि ऐसी योजना यूरोप के इटली जैसे निर्धन देश में लागू की जाती तो वहां प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता में विद्रोह भड़क उठता।

—आर. सी. दत्त.

समीक्षाधीन अवधि में भारत सरकार की अर्थनीति से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मत-भेद वाला विषय था 'मुद्रा परिवर्तन'। 1893 में चादी के सिक्कों की टकसाल बंद होने तथा सिक्कों की खुली ढलाई करने पर यह विषय अस्तित्व में आया था। आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में निर्दयतापूर्वक अनावश्यक रूप से मुद्रा और विनिमय को परस्पर संबद्ध कर दिया गया। वस्तुतः मुद्रा मन्त्रालय परिवर्तन रुपये के मुद्रापरक कार्य संपन्न करने में किसी प्रकार की अमफलता अपर्याप्तता अथवा व्यर्थता से प्रभावित नहीं था, प्रत्युत इसका कारण पौड-स्टर्लिंग के संदर्भ में उसके विनिमय मूल्य में आया हुआ ह्रास था। भारत सरकार ने केवल इसी एक रोग का उपचार करने की चेष्टा की, उसने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर मुद्रा परिवर्तन के संभावित प्रभावों की पूर्ण रूप से उपेक्षा ही कर दी।

मुद्रा अपने आप में सचमुच एक व्यापक विषय है, इतना अधिक व्यापक कि उसका समग्र विवेचन संभव ही नहीं। विनिमय भी एक विषम विषय है। सौभाग्य से हमारा संबंध यहां इन दोनों विषयों की समग्रता से नहीं है। हमारा संबंध तो देश के विदेश व्यापार, उद्योग, वित्त और समाज कल्याण पर भारतीय मुद्रा और विनिमय के परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव से है। यह प्रभाव ही भारत सरकार और राष्ट्रीय नेताओं के बीच मत-

भेद का विषय बन गया और इसने ही भारतीय समाज के नेतावर्ग में प्रचंड राष्ट्र भावना तथा विद्रोही प्रवृत्ति को जन्म दिया। फलतः इस अध्याय में हमारी चर्चा का विषय दो परस्पर संबंधित विषयों मुद्रा और विनिमय के इस विशेष प्रभाव तक ही सीमित है।

सरकारी मुद्रानीति

19वीं शताब्दी के अंतिम चरण की अवधि में भारत सरकार की मुद्रा नीति का उपयुक्त और विस्तृत विवेचन 1893 की इंडियन करेसी कमेटी के प्रतिवेदन में 1898 की इंडियन करेसी कमेटी के प्रतिवेदन में तथा इस विषय पर लिखित अन्य अनेक श्रेष्ठ ग्रंथों में किया गया है।¹ अतः यहां समीक्षाधीन अवधि में भारतीय मुद्रा और विनिमय के क्षेत्र में घटित घटनाओं और परिवर्तनों का अल्पतम संक्षिप्त विवरण देना ही पर्याप्त होगा।

1835 के 17वें अधिनियम के अनुसार भारतीय मुद्रा को रजत मान पर लाया गया और 1870 के सिक्का ढलाई अधिनियम के अनुसार सरकार को यह आदेश दिया गया कि विनिमय के निजी खाते में चांदी की धातु के विनिमय में ही रूपांतरण होगा। इसने भारतीय मुद्रा का 'स्वाभाविकता' पदान की। दूसरे शब्दों में रूपये का मूल्य बाजार में चांदी के मूल्य के सदर्थ में और उसका विनिमय मूल्य स्वर्ण मान वाले देशों में चांदी में उपलब्ध होने वाले स्वर्ण के सदर्थ में ही निर्धारित किया जाता था। चांदी का मूल्य 1873 तक न्यूनतम रूप में स्थिर ही रहा अतः इस अवधि में रूपये का मूल्य 1873 के अधिनियम के आसपास ही स्थिर रहा। परंतु 1873 में जब सारे विश्व में कुछ कारणों से चांदी का सबंध भारत में नहीं, अतः उनकी यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। चांदी में पाए जाने वाले मोन के मूल्य में ह्रास आने लगा तो स्थिति में भारी परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। इसके फलस्वरूप जिस रूपये को चांदी के विनिमय के लिए स्वतंत्रता में रखा गया था, स्वर्ण पर आश्रित मुद्राओं के सदर्थ में उस चांदी के रूपये के मूल्य में ह्रास आने लगा। दूसरे शब्दों में स्वर्ण मान वाले देशों के साथ भारत का विनिमय (इंग्लैंड उस समय स्वर्ण मान वाला देश था) गिरने लगा। इस प्रकार जहां 1873 में भारतीय रूपये का मूल्य लगभग 2 शिलिंग था, वहां उसका विनिमय मूल्य 1893-94 में 14 5/4 पैसे रह गया।

भारतीय विनिमय के ऐतिहासिक पतन को अनेक स्रोतों में मर्मभेदी प्रहार सहन करने पड़े। सर्वप्रथम भारतीय विदेश व्यापार विशेषतः आयात व्यापार को बुरी तरह से बाधित और पीड़ित करने के लिए इसकी भर्त्सना की गई। विदेश व्यापार में सफल व्यापारियों ने अनुभव किया कि रूपये के स्टैबिलिटी मूल्य को लग रहे भयंकर झटके इंग्लैंड और भारत के व्यापार संबंधों पर विशेष हानिकारक प्रभाव डाल रहे थे। इसके अतिरिक्त उनकी शिकायत यह थी कि विनिमय की अनिश्चितता ने विदेश व्यापार को जुए और सट्टेबाजी का स्वरूप प्रदान कर दिया था।² पतनशील विनिमय के विरुद्ध दूसरा अभियोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त अगरेज सिविल और मार्लेट्स अफसरों ने लगाया और बाद में उन्होंने उस अभियोग को सुदृढ़ता से उभारा। उनकी शिकायत यह थी कि उन्हें वेतन तो मिलता है रूपयों में जबकि उन्हें अपने वेतन का एक बहुत बड़ा भाग अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए स्टैबिलिटी के रूप में व्यय करना

होता है। इससे उन्हें अवांछित हानि होती है और क्लेशदायक आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इसका कारण यह था कि उन्हें उसी सख्या में विनिमय में पौंड लेने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सख्या में रुपये अपने घरों को भेजने पड़ते थे।¹ रुपये के स्टैलिंग मूल्य में गिरावट के साथ एक प्रधान पाप यह जुड़ गया कि इसमें ब्रिटिश पूँजी का भारत में प्रवाह निरुत्साहित और मंदगति हो गया। पूँजी के व्याज और लाभ के साथ साथ स्वयं पूँजी के स्वर्ण मूल्य के ह्रास अथवा कम से कम अनिश्चितता ने इस प्रवाह को विलंबित कर दिया। यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश पूँजी के अंतःप्रवाह पर इस प्रतिवध ने, विशेष रूप से देश में त्वरित आवश्यकता वाले प्रतिबंधों ने रेलों के विस्तार में बाधा पहुंचाई।⁴

गिरते विनिमय से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपत्ति भारत सरकार की थी, जिसके वित्त मंचमुच ही इसके कारण विग्न हो गए थे। इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति सर्वथा विचित्र थी। जहाँ सरकार राजस्व की वसूली चांदी के रूपों में करती थी, वहाँ उसे अपने गृह व्यय का इंग्लैंड में भुगतान सोने में करना पड़ता था। 1873-98 की अवधि में चांदी की स्वर्ण क्रय शक्ति अबाध रूप में घटती गई। भारत सरकार को अपने स्टैलिंग दायित्व के भुगतान के लिए प्रतिवर्ष अधिक से अधिक सख्या में रुपये चुकाने पड़े। अधिक शोचनीय बात यह थी कि दायित्व और अधिक बढ़ते गए। इस प्रकार विनिमय में भयंकर पाटा हुआ। दूसरे शब्दों में भारत सरकार को किसी भी वर्ष विशेष में जितने रुपये का भुगतान करना पड़ा और विनिमय की दर के मृदाजनक रूप से 2 शिलिंग प्रति रुपया रहने पर जितने रुपये का भुगतान करना पड़ता, उन दोनों के मध्य का अंतर भारत सरकार से विनिमय में होने वाला घाटा ही था। उदाहरणार्थ, 1894-5 में गृह प्रभारों के भुगतान के लिए 15.77 करोड़ स्टैलिंग पौंड के बदले 28.9 करोड़ रुपये चुकाने पड़े। यदि विनिमय दर 1872-3 वाली ही बनी रहती, तो स्टैलिंग पौंड की उसी राशि के विनिमय के लिए 16.6 करोड़ रुपये चुकाने पड़ते। इस प्रकार 12.3 करोड़ रुपये के अंतरवानी ग्रांथ का विनिमय से होने वाला घाटा ही कहा जाएगा। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उस वर्ष घाटे की रकम भारत सरकार द्वारा उगाहे गए कुल भू राजस्व के आधे भाग में भी अधिक थी।⁵

विनिमय में गिरावट से 1875-98 की अवधि में होने वाला घाटा 154 करोड़ रुपये के लगभग था। 1894 में घाटे की राशि नरम शिखर पर पहुंच गई।⁶ इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को प्रतिवर्ष छठनी तक का सहारा लेना पड़ा। प्रथम साधन तो अव्यावहारिक मिथ्य हुआ। वस्तुतः इस अवधि में सरकार ने, सर्व उल्लेखनीय गति से बढ़ता गया। इस प्रकार से सरकार को व्यापक रूप से अलोकप्रिय साधनों अथवा करों, नमक कर, आय कर, भू राजस्व में वृद्धि, का सहारा लेने पर विवश होना पड़ा। परंतु भारत जैसे निर्धन कृषिप्रधान देश में इसे वृद्धि का क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से सीमित था। किसानों पर किसी प्रकार के अनुचित करभार के साथ अत्यंत गंभीर स्थिति का राजनीतिक खतरा भी जुड़ा हुआ था। विशेषतः इसका भय यह था कि इसे देश पर अधिकार जमाने वाले विदेशी शासन का दुष्प्रभाव समझा जागा और माना जाएगा कि वह देश के बाहर बड़े हुए स्वयं की पूर्ति के लिए ही यह सब कुछ करता है।⁷

इसके अतिरिक्त विनिमय में अचानक उतार-चढ़ाव का परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार को बहुत बड़ी सीमा में वित्तीय अनिश्चितता और कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसका वित्तीय हिसाब और व्यवस्थाएँ अस्त-व्यस्त हो गईं और उसका बजट 'विनिमय की दृष्टि से एक जुम्मा सरीखा' सिद्ध हुआ।⁸ इस प्रकार रुपये के स्वर्ण मूल्य में गिरावट ने लगभग शताब्दी के एक चरण (चतुर्थांश) तक भारतीय धनकुबेरो की नींद हराम रखी। वे अत्यंत व्याकुल होकर बजट के सतुलन के लिए उपाय और साधन ढूँढ़ने लगे। उनके विचार में सरकार के सामने दो ही मार्ग थे। या तो वह विनिमय में गिरावट को रोकें अथवा अतिरिक्त करों का अलोकप्रिय मार्ग ग्रहण करें। उनकी निश्चित धारणा थी कि इन दो मार्गों को छोड़कर कोई अन्य मार्ग नहीं था।⁹

निराश होकर भारत सरकार ने विनिमय में गिरावट रोकने के लिए उपयोगी साधनों की खोज प्रारंभ की। वर्षों तक वह अंतर्राष्ट्रीय दो धातुओबाले इकरारनामे पर भारी आशा मँजोए रही। भारत सरकार का विचार था कि यह सोने और चादी का मापेक्ष मूल्य निर्धारित करेगा परन्तु जब इस इकरारनामे का उपसहार होते होते मारी आशाएँ टूट गईं, 1892 के ब्रुमेल्स सम्मेलन की अमफलता नवीनतम अमफलता थी—तब सरकार अपने मुद्रा मान को चादी के स्थान पर सोने पर आधारित करने की योजना पर विचार करने लगी। इस योजना को अपनाने के लिए व्यापारीवर्ग ने भी, जो वाणिज्य मंडल और नवनिर्मित भारतीय मुद्रा समिति के रूप में संगठित था, इस समय सरकार पर दबाव डाला।¹⁰ मारे के मारे मुद्रा सबधी प्रश्न को तथा भारत सरकार की योजना को उस समय लार्ड चांसलर लार्ड हर्शल की अध्यक्षता में बनी समिति को सौंप दिया गया। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 26 जून 1893 को 1893 के अधिनियम सं० 8 को लागू किया, इसके अनुसार निम्नी स्थां में चादी के अप्रतिबाधित सिक्कों को ढालने वाली टकमाल को बंद कर दिया। सरकार ने यह अधिसूचना जारी की जिसके अंतर्गत रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस निर्धारित किया गया और कहा गया कि इसी दर पर सरकारी करों के भुगतान के लिए जनता में सोने के सिक्के, चादी के सिक्के, पौंड और आधे पौंड लिए जाएंगे तथा विनिमय में रुपये अथवा नोटों की आपूर्ति की जाएगी। सं सारे उपाय देश में स्वर्ण मान को अपरिहार्य रूप में लागू करने के पथ में प्रथम पग ही थे।

1893 की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य रुपये की प्रचलित मात्रा को घटाकर उसके स्वर्ण मूल्य को 1 शिलिंग 4 पेंस तक बढ़ाना था। इस प्रकार रुपया चादी में त्रिच्छिन्न हो गया तथा उसमें निहित चादी के मूल्य में उसका मूल्य बढ़ गया। यह रुपये का प्राकृतिक और यथार्थ स्थिति को छोड़ कर एक नकली और बड़े मूल्यवाली स्थिति को ग्रहण करना था। इसका परिणाम यह निकला कि रुपये की क्रयशक्ति बढ़ गई अथवा दूसरे शब्दों में आंतरिक मुद्रा के संकुचन के फलस्वरूप आंतरिक कीमते गिर गईं।

संक्रमण काल की अवधि, जिसमें रुपये का मूल्य और अधिक गिरता गया और 1894 में यह 4 शिलिंग 3 पेंस तक पहुँच गया, के पश्चात् सरकार की मुद्रानीति को वाञ्छित उद्देश्यों में सफलता मिली और रुपये का मूल्य धीरे-धीरे बढ़ने लगा। यहाँ तक कि जब 1898-9 की अवधि में चादी का मूल्य घट रहा था, रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस के

लगभग था। इस समय भारत सरकार ने सोचा कि 1893 की नीति के तर्क पर आधारित निष्कर्ष निकालने का उपयुक्त समय आ गया है। अतः सारे प्रश्न पर विचार के लिए उसने सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक अन्य समिति की नियुक्ति की। समिति ने स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्णमान की स्थापना की सिफारिश की तथा आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य अनेक उपाय सुझाए। फलतः 1899 में (अधिनियम सं० XXII द्वारा) रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 4 पेंस निश्चित किया गया और इस समय इसी दर पर अशरफी और आधी अशरफी के सिक्कों को भी कानूनी सिक्के की मान्यता दे दी गई। अतः रुपया नाममात्र का सिक्का बन गया हालांकि यह असीमित सरकारी सिक्का बना रहा। भारतीय मुद्रा के क्षेत्र में इस परवर्ती विकास से हमारा कोई संबंध नहीं अतः हम इस विवरण को यहीं समाप्त करते हैं। इस संबंध में केवल दो रोचक बातों का उल्लेख आवश्यक समझते हैं। प्रथम, भारत में जो यथार्थ में छाया रहा, वह स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्णमान नहीं था प्रत्युत उसे 'स्वर्ण विनिमय मान' ही कहा जाता है।¹¹ द्वितीय, भारत के वित्तीय इतिहास में विनिमय की स्थिरता के तथा लाभ बजट के नए युग का प्रारंभ होने लगा था परंतु यह न तो एकसाल बंद होने का परिणाम था और न रुपये की अत्यधिकता की सापेक्ष निवृत्ति का। वस्तुतः रुपये का टंकन तो थोड़े ही समय के बाद उल्लेखनीय परिमाण में होने लगा था।¹² तभी तो जे० एम० कॅस ने टिप्पणी की कि सरकार उद्देशजनक वेग से सिक्के बनाने में जुटी है।¹³ और भारतीय नेता शीघ्र ही रुपये की बहुलता की शिकायत करने लगे है।¹⁴ सत्य यह था कि रुपये का स्वर्ण मूल्य स्थिर बना रहा और यह सब एकाततः प्रशासनिक उपायों का परिणाम था और इन उपायों को सरकार ने किसी विवशता अथवा अनिवार्यता के कारण नहीं अपनाया था।¹⁵

भारतीय नेतृत्व की प्रारंभिक प्रतिक्रिया

रुपये के निरंतर गिरते स्वर्णमूल्य से उत्पन्न समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया में निरंतरता न थी और उसकी अभिव्यक्ति और मंदगति से हुई। बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं ने विनिमय में गिरावट की आलोचना की और इसे भारी दुर्भाग्य बताया, विशेषतः इसलिए क्योंकि विनिमय में होने वाले घाटे के फलस्वरूप नए कर लगाए गए थे।¹⁶ यह बात अवश्य है कि बहुत सारे नेता तो बहुत समय तक इस प्रश्न की समग्र जटिलता को ही न समझ पाए और न ही उसका विस्तृत विश्लेषण कर पाए। हां, इस सामान्य तंद्रा के कुछ एक राष्ट्रवादी अपवाद भी थे।¹⁷ परवर्ती आलोचकों के दृष्टिकोण के साथ इन अपवाद वाले नेताओं के दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप से ही प्रस्तुत किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नेता अपने युग से आगे बढ़े हुए ही थे। परंतु प्रारंभिक वर्षों में, 1892 तक की इस विषय की गतिविधि को संक्षेप में कहना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि अधिकांश भारतीय नेताओं की अत्यंत अस्पष्ट टिप्पणियां केवल निम्नलिखित सुझाव देने तक ही सीमित रहीं : (क) गृह-प्रभारों में कटौती,¹⁸ (ख) स्वर्ण दायित्व का रजत दायित्व में रूपांतरण,¹⁹ (ग) अंतर्राष्ट्रीय द्विघातु प्रणाली का अपनाना।²⁰ थोड़े से नेताओं ने तो यहां तक भी सुझाव दिया कि सोने की

मुद्रा जारी की जाए।¹² और निजी सट्टेबाजों के लिए स्वतंत्र टकन बंद कर देना चाहिए।¹³ जस्टिस रानाडे ने व्यावहारिक नीति की वकालत की और घोषणा की कि मुद्रा में हेरफेर का विरोध इसे विस्वागृह्य मानकर किया जाए क्योंकि इसमें चांदी के मूल्य का ह्रास और विनिमय दर में वृद्धि होती है।¹⁴

राष्ट्रवादियों द्वारा मुद्रा परिवर्तन का विरोध

1892 के आम पास जब ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों ने आंदोलन जारी कर मुद्रा और विनियम के प्रश्न को अपने समय का ज्वलन प्रश्न बना दिया तो उसके सबंध में भारतीय नेताओं की उदासीनता भी जानी रही। भारतीय नेताओं ने इसके पूरे महत्व को स्वीकार किया। इसकी पुष्टि 1892 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भारतीय राष्ट्रीयतावाद के मुख्य प्रवक्ता टी. टी. काका की उस विषय पर दिए 'उनका अपना विषय' कहा जा सकता है, निम्नोक्त मृदु स्वीकृति में होती है: 'हमारे जैम विशिष्ट स्थितिवाले देश का निकट भविष्य में अधिक उद्धार पूर्णरूप से मुद्रा प्रश्न के सही समाधान में ही निहित है।'¹⁵

इस स्थिति में भारतीय नेताओं ने रुपये के नीचे तथा घटत हुए स्वर्ण मूल्य के बचाव और संघर्ष का दृष्टिकोण ही अपनाया। यहाँ तक कि वे 1893 और 1899 के मुद्रा अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी निम्न विनियम की प्रशंसा करते रहे और उसके लिए दबाव डालते रहे। वस्तुतः मुद्रा प्रश्न पर 1893 के मुद्रा अधिनियम अपना लिए जाने के पहले और बाद में वर्षों तक राष्ट्रीय नीति की उल्लेखनीय निरंतरता के कारण इस पुस्तक में इस विषय का एक पृथक विषय के रूप में ही एक ही स्थान पर समग्र विवेचन किया गया है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रारंभिक पक्ष यह विश्वास था कि इस विषय का केन्द्र विनियम की स्थिरता न होकर सोने में विनियमित होने वाले रुपये का अनुपात था। भारतीय नेताओं का विचार था कि विनियम की ऊँची दर की वकालत करने वाले विविध पक्ष अपने स्वार्थों के कारण ही ऐसा करते थे। सरकार विनियम में गिरावट के फलस्वरूप स्टैबिलिटी के मुगलान में होने वाले घाटे की उपेक्षा करना चाहती थी ताकि सरकारी कर्मचारी इंग्लैंड में अपनी अधिकाधिक धनराशि भेज सकें और यूरोपीय मामान के आयातकर्ता आयात कर सकें, अन्यथा उन्हें भारतीय उत्पादनों में प्रतियोगिता के लिए बाध्य किया जा रहा था और इस प्रकार उन्हें अपेक्षाकृत कम मात्रा में लाभ अर्जन करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। इन्हीं कारणों से वे लोग स्वार्थपूर्ण तथा निरर्थक आंदोलन चला रहे थे।¹⁶ भारतीय नेताओं ने दृढ़तापूर्वक कहा कि देश के हितों के साथ विदेशी व्यापारियों, विदेशी पूँजी और विदेशी कर्मचारियों के हितों को न तो रखा जाना चाहिए और न ही रखा जा सकता है। भारत के संबंध में यद्यपि इस देश की जनता के और इस देश की सरकार के हित परस्पर संबंधित नहीं हैं परंतु संक्षेपतः वास्तविक यह है कि भारतीय जनता के हितों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इस प्रश्न पर किसी भी प्रकार से विचार करते समय भारतीयों के हितों को ही प्राथमिक कसौटी मानना चाहिए।¹⁷ राष्ट्रवादी नेताओं

ने इसी मित्रता को व्यवहार में लाने हुए रुपये की कृत्रिम मूल्यवृद्धि करने के लिए रजत मान का परित्याग करके टकसालों को बढ़ करने तथा स्वर्णमान को अपनाने के लिए दंडियन बरमी एसोसिएशन द्वारा संचालित तथा भारत सरकार द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित आदान-का विरोध किया।²⁷ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1892 के अधिवेशन में भी टकसाल आंदोलन का मृदु भाषा में निवृद्ध प्रस्ताव में विरोध किया गया।²⁸ मज्जेदार बात यह है कि भारत में सरकारी अधिकारियों ने उपहास के रूप में अथवा जाने अनजाने रूप में मुद्रा प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की और उसका गलत अर्थ लिया। उन्होंने 21 जून 1892 में भारत राज्य सचिव को यह प्रतिवेदित किया कि भारतीय जनमत निम्नलिखित उपायों की स्वीकार करने की स्थिति में है और चांदी के सिक्के बनाने की गमायत को जनता सामान्यतः स्वीकार करेगी।²⁹

सरकारी अधिकारियों ने भारतीय जनमत सबधी मिथ्या ज्ञान उस समय उघड़ गया जब 1893 में भारतीय टकसालों को बढ़ाने की राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने न्यूनाधिक रूप में एक स्वर में इस पक्ष का विरोध किया और इसे भारतीय जनता के विशेष उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल बताकर उसकी भर्त्सना की।³⁰ बाद में उगी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार की कार्यवाही की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया।³¹ प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने 1893 के करेसी ऐक्ट की इन शर्तों में भर्त्सना की 'अपेरे में गहरी छलांग' और 'एक भारी अक्षम्य भूल'।³² जब सरकार ने रुपये का मूल्य 1 गिलिंग 4 पेंस निर्धारित करते हुए स्वर्णमान की व्यवस्था की योजना बनाई तो इस '1893 के अपराध की 1898 में पुनरावृत्ति'³³ बताते हुए वाचा ने सरकार की भर्त्सना सांजानिक रूप से की।³⁴ दादाभाई नौरोजी ने टकसाल बढ़ करने की निंदा इन शब्दों में की: 'यह एक अवैध, असम्माननीय और निरकुश कृत्य है।' उन्होंने स्वर्णमान के परित्याग की मांग की।³⁵ आर० सी० दत्त ने भी कृत्रिम रूप से रुपये के मूल्य बढ़ाने के सरकार के प्रयत्नों की निंदा 'अप्राकृतिक, निराशाजनक और भयकर' कहकर की।³⁶ उन्होंने सरकार को स्वर्णमान लागू करने के विरुद्ध चेतावनी दी।³⁷ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक बार फिर विनिमय से हुए घाटे की पूर्ति के लिए महंगी कीमत पर मुद्रा में तबदीली करने अथवा आंतरिक मुद्रा के समेटने जैसे कृत्रिम उपाय अपनाने के प्रति अपनी असहमति प्रकट की।³⁸ डी० ई० वाचा ने पूर्ववत् बड़ी ही उग्रता से यह विचार प्रकट किया कि सामान्य रूप से सर्वसाधारण द्वारा तथा विशेष रूप से बैंकों और व्यापारीवर्ग द्वारा उस दिन से भोगे हुए और भोगे जा रहे दुखों के कारणरूप सभी आर्थिक बुराईयों की जड़ 1893 का करेसी ऐक्ट है।³⁹ उल्टे नौरोजी, दत्त तथा अन्य भारतीय नेताओं ने दबाव डाला कि टकसालें खोल दी जाएं और रुपये को चांदी के धातु मूल्य तक नीचे जाने दिया जाए।⁴⁰ भारतीय नेताओं ने फाउलर कमेटी में भारतीय हितों के संरक्षक एक भी प्रतिनिधि को सम्मिलित न करने का बहुत ही बुरा माना।⁴¹ इस कमेटी की सिफारिशों की तथा उनके फलस्वरूप प्रस्तुत 1899 के करेसी ऐक्ट की भारतीय नेताओं ने पुनः आलोचना की परंतु अब की बार पहले जैसा उत्साह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसका कारण कदाचित्त यह था कि इस समय तक मुद्रा क्रांति एक व्यवस्थित तथ्य

बन चुकी थी।⁴² फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परवर्ती अनेक वर्षों में इस प्रश्न को महत्व देती रही। अपने 17वें अधिवेशन में कांग्रेस ने नकली तौर पर रुपये की 30 प्रतिशत कीमत बढ़ाने वाले 1893 के करेंसी कानून के प्रति अपने विरोध की दोबारा पुष्टि की।⁴³ 18वें अधिवेशन में पुनः इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया।⁴⁴ असंख्य जननेता वर्षों तक रुपये की नकली मूल्यवृद्धि और लोकहित पर उसके दुष्प्रभाव की आलोचना करते रहे।⁴⁵

भारत सरकार की मुद्रानीति की राष्ट्रवादी अस्वीकृति के तीन मुख्य आधार थे : 1. ह्यासोन्मुख रुपये का लाभकारी चरित्र, 2. मुद्रा के सरकार अथवा जनता की आर्थिक कठिनाइयों के मूल कारण होने के प्रमाण का अभाव, 3. जनता की आर्थिक स्थिति पर रुपये के बढ़ते मूल्य का हानिकारक प्रभाव। इन आधारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि इनसे समीक्षाधीन अवधि में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के आर्थिक दृष्टिकोण संबंधी मौलिक सिद्धांतों पर भली प्रकार प्रकाश पड़ता है।

निम्न विनिमय के लाभ

बहुत सारे भारतीय नेताओं का यह विश्वास था कि 1873 से भारत के व्यापार और उद्योग ने जो प्रगति की है, उसमें गिरते रुपये वाले रजत मान ने भारतीय ग्रथव्यवस्था की आवश्यकताओं की संतोषजनक रूप से पूर्ति की है और इस प्रकार भारत द्वारा अपनाया जा सकने वाला यह कदाचित् सर्वोत्तम मुद्रा मान था।⁴⁶ उनके अनुसार निम्न विनिमय की मुख्य उपयोगिता थी, विनिमय में गिरावट की सीमा तक अत्यधिक महंगे बन गए आयातों से भारतीय उत्पादनों, विशेषतः सूती वस्त्रों को परीक्षा संरक्षण देने के रूप में प्रोत्साहन जुटाना। 'भराठा' ने अपने 25 सितंबर 1892 के अंक में लिखा 'विनिमय कटौती सभी प्रकार के अंगरेजी सामान पर आयात शुल्क के रूप में काम करती है। यहाँ विनिमय ने फिर वही काम किया है जो करने से सरकार निरंतर इनकार करती रही है।'⁴⁷ हिंदू तो 4 सितंबर 1889 के अंक में यह देख पाने में सफल हो गया कि निम्न विनिमय के कारण ही भारत इंग्लैंड के सूती वस्त्र उत्पादकों से चीन और जापान के बाजार हथियाने में सफल हो सका है।⁴⁸ पी० सी० राय ने इस स्थिति में एक और उपयोगिता देखी। उन्होंने कहा कि निम्न विनिमय ने अंगरेजी पूँजी के लिए भारत को एक अनाकर्षक प्रदेश बनाकर भारतीय पूँजीपतियों के लिए उद्यम के अवसर उत्पन्न किए हैं।⁴⁹

यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि राष्ट्रवादियों ने चांदी के रुपये के समर्थन में स्वीकृत तर्कों को उसी समय आगे नहीं बढ़ाया। वह तर्क यह था कि विनिमय की निम्न दर विदेश के बाजारों में मूल्य को नीचे गिराकर निर्यात को प्रोत्साहन देती है। वास्तव में कुछ भारतीय नेताओं ने (आर० सी० दत्त को छोड़ कर जिन्होंने थोड़ी बहुत अस्पष्टता के साथ यह स्वीकार किया कि चांदी के अवमूल्यन से भारत के विदेश व्यापार को हानि की अपेक्षा लाभ ही पहुँचा है⁵⁰) सर्वथा अस्वीकार कर दिया कि रुपये के अवमूल्यन ने भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन दिया है।⁵¹ जो भी हो, उनमें सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, उनके विदेश

व्यापार विरोधी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप यह नकारने की थी कि कच्चे सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देना एक अच्छी बात है।⁵² इससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि भारतीय नेताओं को अवमूल्यित रुपये की रक्षा के लिए न तो मुख्य रूप से व्यापारीवर्ग के प्रति सहानुभूति थी और न ही विदेशी व्यापार में रुचि थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसान को रुपये के अवमूल्यन से अपने उत्पादनों से अधिक रुपये के मिलने के रूप में कोई लाभ पहुंचा है। उन्होंने निर्देश किया कि वस्तुतः बहुत सारे कृषि उत्पादनों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बहुत सारे उत्पादनों के मूल्य तो घट ही गए हैं।⁵¹

भारतीय वित्त में विनिमय की भूमिका

मुद्रा परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय नेताओं की आपत्ति का दूसरा आधार उनकी यह धारणा थी कि रुपये की स्वर्ण मूल्य में गिरावट भारत सरकार की आर्थिक कठिनाइयों का मूल कारण नहीं। उन्होंने विनिमय से भारत के कोष को होने वाले घाटे को देखा ही नहीं, अपितु उसके प्रति चिंता भी प्रकट की क्योंकि आखिरकार इस घाटे का भार बेचारे भारतीय करदाता के कंधे पर ही तो पड़ना था। उन्होंने इसकी पूर्ण समाप्ति की इच्छा की।⁵³ उदाहरणार्थ 1886 में दादाभाई नौरोजी ने विनिमय में होने वाले घाटे को ब्रिटिश भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय जनता पर दुःखद भार बताया। उन्होंने लिखा 'दुर्भाग्यग्रस्त निर्धन भारतीय को गृह प्रभारों के लिए 14 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन को 7 शिलिंग प्रति रुपया की दर से बेचने के बदले 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से बेचने से रुपये के विनिमय में आई गिरावट में हुए घाटे को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपये के मूल्य का और उत्पादन बेचना पड़ता है।'⁵⁴ भारतीय नेताओं और सरकार के मध्य समझौते का क्षेत्र इस जगह खत्म हो गया, क्योंकि उनमें इस बुराई के लिए उत्तरदायी तत्वों और उनके उपचार की प्रकृति के बारे में मतभेद था। भारतीय नेता यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह विनिमय का घाटा रुपये के स्वर्ण मूल्य में गिरावट का परिणाम है। उनका कथन था कि रोग का स्रोत कहीं अन्यत्र है। भारतीय नेताओं में मुद्रा प्रश्न के इस पक्ष में उल्लेखनीय एकता तथा सुसंगति थी। रोग की यथार्थ प्रकृति की पहचान और प्रयोज्य उपचार ने उनकी समग्र मुद्रानीति में विशिष्ट स्थिति बनाए रखी। रोग की पहचान को सार रूप में निम्न विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है :

इस सारी समस्या की जड़ विनिमय की दर न होकर भारत के इंग्लैंड के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। सरकार के विनिमय संबंधी घाटे के लिए निम्न विनिमय के बदले गृह प्रभार ही उत्तरदायी है। यदि भारत से इंग्लैंड में स्वर्ण के रूप में अनिवार्य धन न भेजा जाता तो रुपये के स्वर्ण मूल्य में गिरावट से संभवतः भारत सरकार के वित्त ग्रथवा भारत के लोग प्रभावित ही न होते। दूसरी ओर जब तक गृह प्रभार बने हुए हैं, केवल मुद्रा परिवर्तन से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा।⁵⁵

इस संबंध में अनेक भारतीय प्रवक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी भौद्रिक सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया जिसके अनुसार—मुद्रा पद्धति इस विधि से प्रवर्तित

होती है कि किसी देश के भुगतानों का संतुलन अपने आप ही तुल्य स्थिति की ओर चला जाता है।⁵⁷ उन्होंने आवृत्तिपूर्वक बल देकर कहा कि गृह प्रभारों के भुगतान से होने वाले घाटे को छोड़ कर विनिमय की गिरावट अपने आप में भारत के विदेश व्यापार को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि कीमतों के उतार-चढ़ाव द्वारा विदेश व्यापार विनिमय की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आपको स्वतः ही व्यवस्थित कर लेगा।⁵⁸ कुछ अन्य भारतीय नेताओं ने भी निर्देश किया कि एक लंबे समय तक निरंतर विदेशों को अनिवार्य भुगतान की आवश्यकता ने सरकार को किसी भी मूल्य पर पौड खरीदने के लिए विवश न रखा है। उसी का अप्रतिहार्य दुष्प्रभाव चादी के मूल्य में ह्रास ग उत्पन्न विनिमय की दृष्टि है।⁵⁹ भारतीय रुपये के गत मान में हटने पर इस तर्क को बहुत बल मिला। 1899 में वाचा ने ब्रिड्ज के मिल मालिकों को बताया कि विनिमय के विशेष का कारण विदेशों में किए जाने वाले भुगतानों के फलस्वरूप भारत के विदेश व्यापार के संतुलन में आई अव्यवस्था है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ग्रामना मत प्रकट किया आपसी मुद्रा सोने की हो अथवा चादी की, रुई की अथवा गेहूँ को; जब तक यह प्रभार वृद्ध और बढ़ते ही रहेंगे तब तक यह तथाकथित विनिमय कठिनाई बनी ही रहेगी।⁶⁰ वस्तुतः समस्या तो गृह प्रभारों की ही है।⁶¹ उन्होंने तथा उनके साथ जी० एम० अर्थर महोरन ने भी यह अनुभव लिया कि 1872 तक और यहां तक कि उसके बाद भी इन गृह प्रभारों के दबाव पर ध्यान इंगलैंड में नहीं गया क्योंकि इस अवधि में रेलों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए बहुत बड़ी बड़ी रकमों के ऋण लिए गए हैं।⁶²

राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अधिकांशियों के इस दृष्टिकोण की तीव्र भर्त्सना की कि विनिमय से होने वाला घाटा उनके नियंत्रण से बाहर था और इसका उपाय या तो करो में वृद्धि द्वारा इसे सहन करना था, अथवा रुपये का मूल्य बढ़ाकर इसे निष्पन्न करना था, उनके अनुसार उसका एक अन्य उपाय भी था और उसका पता रोग की जाच-पड़ताल से लग जाता है। प्रथम, उनका कथन था सरकार को विनिमय से होने वाले घाटे का मूल कारण यदि विनिमय में गिरावट नहीं तो स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रा पद्धति मध्यम परिवर्तन में स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार होने वाला नहीं।⁶³ द्वितीय, क्योंकि मूल रूप से गृह प्रभारों का ही है अब इस रोग का प्रभावी इलाज भारत के स्टैलिग दायित्वों में निरंतर वृद्धि करने वाली वर्तमान नीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाना ही है। अतएव प्रमुख एकमात्र स्वाभाविक और उपयुक्त उपचार है गृह प्रभारों की समाप्ति अथवा उनमें कटौती अथवा इंग्लैंड की संपत्ति की निकासी की समाप्ति या कटौती अथवा कम से कम स्टैलिग के बड़े भाग का दायित्व रुपये की देनदारी में परिवर्तन ताकि उतनी रकम के बराबर भुगतान के लिए काफी कम रुपये देने पड़ें। यह भारतीय कोष भंडारों के लिए एक बहुत बड़ी मुक्ति होगी।⁶⁴ इस उद्देश्य की प्राप्ति के निश्चिततम उपायों में भारतीय नेताओं के विचार में एक था, देश का प्रणामन देश के मपूतों द्वारा ही पूर्ण योग्यता के साथ चलाया जाना, क्योंकि उस स्थिति में उनके वेतन और पेंशन राशि का भुगतान सोने में नहीं करना पड़ेगा।⁶⁵ दूसरा सुझाया हुआ उपाय यह था कि देश के भीतर ही सरकारी भंडारों के अपेक्षाकृत अधिक

बड़ी संख्या में अंश खरीदना।⁶⁵ एक अन्य उपाय यह भी था कि इंग्लैंड भारत सरकार के इंग्लैंड में होने वाले व्यय के उचित अंश का भुगतान करे।⁶⁶ वस्तुतः कुछ नेताओं ने तो रुपये के मूल्य में ह्रास का और विनिमय में घाटे का स्वागत ही किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि यह स्थिति घन की निकासी की समस्या की आग सरकार का और भारतीय जनता का ध्यान खींचेगी और जनता सरकार को गद्दी पग उठाने के लिए विवश कर देगी।⁶⁷ बंगाली ने 3 सितंबर 1892 के अंक में इस दृष्टिकोण का अत्यंत स्पष्टता से विश्लेषण किया :

यदि वर्तमान स्थिति और अधिक समय तक चलती गयी तो इसके कारण भारतीयों के लिए अत्यंत लाभप्रद परिवर्तन अवश्य होंगे। गृह प्रभागों को घटाना आवश्यक है और आवश्यकता की वस्तुओं को देश में ही पाने का प्रयत्न करना चाहिए।... यदि भारतीय बाजार में सरकार ही खरीदार बन जाए तो भारतीय व्यापार को कितना प्रबल प्रोत्साहन मिलेगा।... (यह) भारतीय उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि विनिमय में गिरावट अंगरेजों की बहुत बड़ी संख्या का अपने देश में ही रहने और भारत में हाथियाई हुई नौकरियों को भारतीयों के लिए ही छूटने से उद्धार करेगी।⁶⁸

भारतीय नेताओं ने इस बात से इनकार किया कि रुपये की मूल्यवृद्धि का प्रयोजन बड़े हुए कराधान और आर्थिक सकट में भारत को मुक्ति दिलाना है। उनका तर्क था कि यदि गृह प्रभागों में भारी कटौती न भी की जाए और विनिमय में होने वाला घाटा भी चलता रहे तो भी इनकी पूर्ति बिना किसी प्रकार के नए कराधान के वर्तमान आर्थिक संसाधनों से तथा उनमें होने वाली सामान्य बढ़ोतरी से ही की जा सकती है।⁶⁹ उनकी धारणा थी कि निस्संदेह विनिमय एक पीडाजनक तत्व है परंतु इसे भारतीय वित्त का कृत्रिम समाधान नहीं मानना चाहिए। भारतीय वित्तों के असंतुलन का दायित्व प्रमुख रूप से विनिमय के घाटे पर न देकर सरकार के मिविल और मिलिट्री के खर्चों के विषम विकास पर ही देना चाहिए, क्योंकि इनके ही कारण भारत की स्टैलिग देनदारी में बढ़ोतरी होती है।⁷⁰ अतः स्थिति का सही उपचार मुद्रा पद्धति में परिवर्तन न होकर खर्चों, विशेषतः मिलिट्री के खर्चों, में कटौती करना है।⁷¹ डी० ई० वाचा ने तो विशेष रूप से दृढ़तापूर्वक इस धारणा का समर्थन किया और आकांक्षी सहायता से सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 1884-85 से लेकर इस अवधि तक मिलिट्री के खर्चों ने सारे नए कर हजम कर लिए हैं और यदि मिलिट्री के इन व्ययों में कटौती कर दी जाए तो भारत विनिमय की बैसाखी के बिना ही अपने पांव पर खड़ा होने योग्य बन जाएगा।⁷²

कुछ भारतीय नेताओं का एक अन्य सुझाव था कि यदि वर्तमान सभी स्थितियों को अपरिवर्तनीय ही मान लिया जाए तो भी विनिमय की कठिनाता का सामना भारत में उत्पादित न की जाने वाली अथवा भारत की बहुसंख्या के काम में न आने वाली अथवा देश के विकास से संबंध न रखने वाली विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर थोड़े से आयात शुल्क को लगा कर किया जा सकता है।⁷³ यह विवरण कपास शुल्कों के सर्वथा अनुरूप था।⁷⁴

प्रत्येक स्थिति में भारतीय नेताओं ने इस कथन पर तीव्र आपत्ति की कि टकमालों के बंद करने से अथवा रुपये की मूल्यवृद्धि में सरकार भारतीय जनता को नए कराधान की आवश्यकता की ममाप्ति के रूप में किसी प्रकार का कोई सुख दे सकती है। उनका विचार था कि यह तर्क आर्थिक तथ्यों के साथ छल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मुद्रा में परिवर्तन में संभवतः किसी प्रकार की अभीष्ट सिद्धि नहीं होगी। इसके विपरीत 1893 और 1898 के मुद्रा कानूनों में भारतीय जनता को रुपये के बढ़ते मूल्य की सीमा तक भार रूप और अनिश्चित प्रकृति वाले परोक्ष करों का और अधिक शिकार बनाया गया है⁷⁵ क्योंकि अब पुराने कर भी कृत्रिम रूप में बढ़े हुए मूल्य वाले रुपयों के रूप में उगाहे जा रहे हैं।⁷⁶ दादाभाई नौरोजी ने 1898 में लिखा 'टकमाल बंद करने से और उसके साथ रुपये के इस समय 11 पैसे के लगभग यथार्थ स्वर्ण मूल्य को 16 पैसे के झूठे स्वर्ण मूल्य में बदलना भारतीय करदाताओं पर कुल मिलाकर गुप्त रूप में करों में 45 प्रतिशत की विगुह वृद्धि का भार डालना है।'⁷⁷

भारतीय नेताओं के मत में सरकार के मुद्रा संबंधी प्रश्न को हल करने के दृग से उसकी चालाक राजनीतिक छल-रूपट की नीति का पता चलता है जिसके तहत भोली-भाली तथा भटकी हुई भारतीय जनता पर, जो कर भार में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष वृद्धि से विक्षुब्ध हो उठती, गुप्त तथा परोक्ष कराधान के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की गई है।⁷⁸ इसके विपरीत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने तो करों में प्रत्यक्ष और परोक्ष वृद्धि रूप दोनों बुराईयों में प्रत्यक्ष वृद्धि को अपेक्षाकृत छोटी बुराई मानते हुए उसका ही समर्थन किया, क्योंकि उनके विचार में इसमें बेचारे करदाता को देश के करों में प्रचलन रूप में अपार बढ़ोतरी के स्थान पर केवल विनिमय में प्राकृतिक गिरावट में हुए घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त करों का ही भुगतान करना पड़ता।⁷⁹

बाद में जब 1901 के बाद लाभ का बजट आना प्रारंभ हो गया तो राष्ट्रवादी नेताओं ने एक बार फिर यह दावा किया कि ये लाभ 1893 और 1898 में थोपे गए मुद्रा विधान के अंतर्गत परोक्ष कराधान के ही परिणाम हैं।⁸⁰ साथ ही उन्होंने अभिस्वीकार किया कि मुद्रा नीति में पीछे हटना व्यावहारिक राजनीति की सीमा के अंतर्गत दिखाई नहीं देता। नेताओं की माग थी कि इन अधिशेषों का उपयोग मुद्रा विधान के आघात से पीड़ित बेचारे करदाता को करों में छूट के रूप में ही करना चाहिए।⁸¹ इस संबंध में जी० के० गोखले ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा कि यदि :

रुपये के विनिमय मूल्य में वृद्धि से देश के कराधान में किसी प्रकार की परोक्षवृद्धि की असंभव संभावना को नकारा जा सकता है, तब भारत सरकार के मार्ग में कौन सी बाधा है कि वह रुपये का मूल्य और अधिक ऊंचा 1 शिलिंग 6 पैसे यथवा 1 शिलिंग 9 पैसे अथवा 2 शिलिंग नहीं कर देती ? उस स्थिति में तो लाभ इस समय के लाभ से भी बढ चढकर होगा। जब लार्ड जार्ज हैमल्टन यह मानते हैं कि इस कृत्रिम वृद्धि में किसी भारतीय को कोई हानि नहीं हुई तो फिर सरकार इस आश्चर्यजनक सरल और सीधे उपाय से अपने संसाधनों में वृद्धि क्यों नहीं करती ?⁸²

कुछ अधिक सचेत राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार रुपये की मूल्यवृद्धि से देश द्वारा

इंग्लैंड को भेजे जाने वाले धन की बचत अथवा धन की निकासी में न्यूनता का दावा सर्वथा असंगत, 'कोरी कल्पित कथा तथा दुर्भाग्यपूर्ण भ्रांति', था।¹³ उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि एकपक्षीय तथा कृत्रिम रूप से रुपये के स्वर्ण मूल्य में वृद्धि से भारत को इंग्लैंड को दिए जाने वाले सोने के भुगतानों में एक पैसे की भी बचत नहीं हो सकती। गृह प्रभारों की पूर्ति विदेशों में भारतीय सामग्री को भेजकर की जा रही है। उस निर्यातित सामग्री की मात्रा विदेशी बाजार में उसके सोने के मूल्य के परिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित की जाती है न कि भारत में उनके रुपये के मूल्य के परिप्रेक्ष्य में। अभी अभी वर्तमान में ही सभी पदार्थों के स्वर्णमूल्य में गिरावट के कारण भारत को अपने उत्पादनों को अधिक मात्रा में भेजने के लिए विवश होना पड़ा है। जब तक इन पदार्थों के स्वर्णमूल्य में वृद्धि नहीं होती, तब तक भारत सरकार भले ही नए कर लगाकर उत्पादन जुटाए अथवा पुराने पदार्थों की क्रयशक्ति में वृद्धि करे; प्रत्येक स्थिति में भारत को उतनी मात्रा में ही अपने उत्पादनों का निर्यात करना पड़ेगा जितना वह अब तक करता आ रहा है।¹⁴ दादा भाई नौरोजी का तो यहां तक मत था कि यदि भारत ने स्वर्णमान को भी अपनाया होता तो विनिमय से होने वाले घाटे को टाला नहीं जा सकता था।¹⁵ उनकी धारणा थी कि वास्तव में भारत की स्थिति स्वर्ण प्रयोग करने वाले और स्वर्ण में ऋण का भुगतान करने वाले ऋणी देश की ही थी।¹⁶ दादाभाई ने आगे कहा कि 'परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि विनिमय में घाटे का देश पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। घाटा तो था ही परंतु यह स्वर्ण मूल्य में वृद्धि का ही परिणाम था। भारत की मुद्रा में परिवर्तन में इस घाटे को कम नहीं किया जा सकता।' केवल स्वर्ण के मूल्य में परिवर्तन से ही भारत को बचाया जा सकता है अथवा उसके घाटे को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।¹⁷ करेंसी कमेटी के सामने बयान देते हुए 1893 में दादाभाई ने राष्ट्रवादी स्थिति को अत्यंत मारगर्भित ढंग में अभिव्यक्ति दी। सर थामस फारर के इस प्रश्न के उत्तर में कि एक ओर आप मानते हैं कि भारत विनिमय में गिरावट से विपन्न है और साथ ही दूसरी ओर कहते हैं कि विनिमय में बढ़ोतरी से भारत को कोई लाभ नहीं होगा? दादाभाई ने उत्तर दिया।

अरे, नहीं, मैंने यह बिलकुल नहीं कहा। अरे, नहीं, यह मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो कहा है कि भारत को स्वर्ण मूल्य के अनुसार ही लाभ-हानि होगी। यदि स्वर्ण मूल्य में गिरावट आती है जिसका अर्थ है विनिमय में बढ़ोतरी तो अन्य स्थितियों के पूर्ववत् होने पर भारत को अपने उत्पादन कम परिमाण में भेजने होंगे। यदि स्वर्ण के मूल्य में और अधिक ऊंची वृद्धि होती है, दूसरे शब्दों में यदि विनिमय में और अधिक गिरावट आती है तो भारत को अपने उत्पादन और अधिक मात्रा में भेजने पड़ेंगे।¹⁸

कुछ भारतीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि रुपये की मूल्यवृद्धि से भारत में धन की निकासी बढ़ जाएगी क्योंकि इससे स्टर्लिंग के दायित्व खाते में कोई निवृत्ति तो नहीं मिलेगी, चांदी के रूप में लोक ऋण बढ़ जाएंगे। इनमें से अधिकांश ऋण रुपये के मूल्य वृद्धि की सीमा तक इंग्लैंड में थे।¹⁹ इसी प्रकार उन्होंने यह भी निर्देश किया कि सरकारी उपायों का भी प्रभाव यह होगा कि भारत के प्रशासन का व्यय बढ़ जाएगा क्योंकि

यूरोपीय अथवा भारतीय सरकारी वरमंचागियों को बढ़े हुए रूपों में वेतनों का मुगतान करना पड़ेगा। इसका अर्थ होगा कि कोटि कोटि मपदा उत्पादको तथा भारत को ममृद्ध बनाने वाले श्रमिकों के श्रम में अर्जित संपत्ति उनके हाथ में छीन कर भक्षकों के हाथ में सौंपना।⁹⁰

डी० ई० वाचा ने एक अन्य परोक्ष परंतु हानिप्रद प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया, भारत स्वर्णमानवाने देशों के साथ नकारात्मक व्यापार-मतुलन रख सकता था क्योंकि चीन तथा अन्य रजन प्रयोजना देशों के साथ उमका नकारात्मक व्यापार मतुलन था। नया मुद्रा अधिनियम दूर के पूर्वी देशों में भारत के निर्यात को घटाकर इंग्लैंड को भेजी जाने वाली रकम को भेजने का काम अधिभ कठिन बना देगा।⁹¹

रुपये की मूल्यवृद्धि के हानिप्रद प्रभाव

भारतीय नेताओं ने भारत सरकार के मुद्रा अधिनियम की स्वार्थता को गिद्ध करने के अनिरीकित उसके द्वारा भारतीय जनता विशेषतः उत्पादक वर्ग के आर्थिक हितों को पट्टुचाई जा रही वास्तविक अथवा मर्भावन निश्चित हानि की ओर ध्यान दिलाया।

सर्वप्रथम, उन्होंने दावा किया कि रुपये की मूल्यवृद्धि भारत के देशी उत्पादकों के प्रति पक्षपातपूर्ण रही है।⁹² उन्होंने तो मत था कि मुद्रा में परिवर्तन ने देश के विदेश व्यापार पर घातक प्रभाव डालकर देश पर व्यापारिक अनुपयोगिता थोप दी है।⁹³ व्यापार के सबंध में उनकी चिंता प्रायः दिखावटी ही थी। वास्तव में वे उद्योग में ही घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। वे रुपये की मूल्यवृद्धि के कुन मिलाकर भारत के विदेश व्यापार पर अथवा यदा तक कि निर्यात व्यापार की समग्रता पर उनके दुष्प्रभाव में वास्तव में ही चिंतित नहीं थे। उनके प्राध के भड़कने का मुख्य कारण यह था कि भारत में चीन और जापान को किए जा रहे मूल्य के निर्यात का भविष्य दुर्दशाग्रस्त हो गया था क्योंकि भारत की इन दोनों देशों के उत्पादकों से प्रतियोगिता थी और उन दोनों देशों ने या तो रजन मान अपनाए रखा था अथवा चादी और साने के बीच विनिमय का निम्न अनुपात बनाए रखा था। इसके फलस्वरूप इन देशों के उत्पादकों ने मूल्य के मदर्भ में भारतीय उत्पादकों को पिछाड़ दिया।⁹⁴ मक्षेपत भारतीय नेता व्यापक रूप से सूती वस्त्र उद्योग के भविष्य के प्रति ही अधिक चिंतित थे जिस पर उम समय तक पूर्वी व्यापार सशक्त रूप से छा गया था।⁹⁵ उन्होंने शीघ्र ही उच्च स्वर में आर्त क्रंदन करने हुए, कहना प्रारंभ कर दिया कि रुपये की मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पंगु और अस्तव्यस्त हो गया है।⁹⁶ उदाहरणार्थ, जी० के० गोखले ने 1902 में यह आगेप लगाया कि सरकार के मुद्रा कानून के फलस्वरूप भारत के सूती वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर भयकर मदी आई है।⁹⁷ और ग्रम्बालाल शंकरलाल देसाई ने 1904 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूचित किया कि पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ विनिमय में गिरावट (वृद्धि) के कारण बर्बई की बीस मिलों का दिवाला पिट गया है।⁹⁸ इस सबंध में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 18वें अधिवेशन में स्वयं एक सूती कपड़ा मिल के मालिक श्री० डी० ठाकरसी ने अत्यंत सरलता और सक्षेप से प्रस्तुत किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा :

‘वर्तमान में हुए मुद्रा परिवर्तन के कारण देश के कताई उद्योग को पिछले कई वर्षों से भयंकर संकट की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है।’ उन्होंने अपनी धारणा को प्रकट करते हुए कहा: ‘रुपये की मूल्यवृद्धि ने रजत प्रयोक्ता चीन के साथ विनिमय में गंभीर वृद्धि ला दी है और इसमें भारतीय उद्योग को चीन के बाजार में हानि पहुँची है। इसके विपरीत जापानी वस्त्र उद्योग को जिसे किसी भी देश प्रकार की बाधा या शिफार नहीं होना पड़ा — परोक्ष रूप से लाभ ही पहुँचा है। फलतः जापान चीन की एक निहार् में अधिक माग की पूर्ति करने में समर्थ हो गया है।’ उन्होंने दुखित स्वर में कहा ‘मुझे इसमें कुछ भी विस्मय नहीं होगा, यदि एक दिन जापान भारी बाजार पर उसी प्रकार कब्जा जमा लेगा, जिस प्रकार वही भारत का था।’ हमारे प्रतियोगियों का इस पूर्व में 20 रुपये प्रति गाँठ का उपहार ही है जिनके हमारे क्लार्क-बुनार्ड उद्योग का आर्थिक दृष्टि में विनाश के कारण पर लाल झंडा कर दिया है।’¹⁰⁰

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण सही था अथवा नहीं इसकी जांच में न पड़ते हुए हम उनका ही कहना चाहते हैं कि व्यापार का मूल व्यापार की अत्यंत सीधे दृष्टि में देश के उनका विनिमय तथा निर्यात पर न अदम्य रूप से विदेश व्यापार को पड़ती हानि अथवा सरकारी मुद्रा नीति के विदेश व्यापार का पड़ने वाला लाभ पर आधारित था। उसकी समीक्षा उसे स्वयं अप्रामाणिक ही सिद्ध करती है। एक बार यह स्वीकार करने पर, जैसा उनके बहुत बार समीक्षकों ने किया है कि रुपय की मूल्यवृद्धि से (भले ही कितना आंशिक रूप से) भारत के चीन और जापान का हानि वार मूल के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है¹⁰¹ ना भारतीय पक्ष भारी हा जाता है। वस्तु भारतीय राष्ट्रवादी नेता स्वयं ही अपना एकपक्षीय मान्यता पर कि भूत उद्योग में गिरावट एकानतः मुद्रा परिवर्तन का परिणाम थी पुनर्विचार करने लग। उदाहरणार्थ डी० ई० वाचा ने 1901 में स्वीकार किया कि गिरावट लाने में अन्यान्य कारण जैसे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि, अकुशल प्रबंध व्यवस्था, लेग, अकाल का भी यादा बहुत योगदान है। उन्होंने पुनः इस बात को दोहराया कि सरकार की मुद्रा नीति के विरुद्ध शिकायत करने वालों द्वारा अनिर्जित रूप में प्रस्तुत हानियों की सीमा तक संभवतः न मही परंतु वह निश्चित रूप में हानिप्रद अवश्य रही है।¹⁰²

भारतीय नेताओं ने वस्त्र उद्योग के संबंध में प्रस्तुत आधारों के सदृश ही निम्न विनिमय की आवश्यकता रखने वाले चाय तथा अन्य बागान उद्योगों की भी उन्हीं आधारों पर बकालत की।¹⁰³ वे इन उद्योगों से संबंधित संघर्ष के प्रति विशेष उत्साही नहीं थे। उन्होंने कागड़ा की तराई में चाय बागान मालिक कैप्टन ए० बैनन जैसे कुछ अंग्रेज चाय बागान मालिकों का समर्थन पाने के लिए ही इस विषय को उठाया था।¹⁰⁴

यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि मुद्रा समस्या के दोनों राष्ट्रवादी विशेषज्ञों, दादाभाई नौरोजी और डी० ई० वाचा, ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह मुद्रा प्रश्न पर विचार करते समय विदेश व्यापार की आवश्यकताओं पर ही केवल ध्यान देती है और मुद्रा की कठोरता की अपेक्षा उसकी अधिकता चाहने वाले अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक व्यापार की आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है।¹⁰⁵

1893 और 1898 के मुद्रा परिवर्तनों पर राष्ट्रीय आलोचना का दूसरा आधार कृषकों पर पड़ने वाला उनका घातक प्रभाव था। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इन परिवर्तनों से उस बेचारे को कमरतोड़ बोझ उठाना पड़ेगा।¹⁰⁵ सरकार की इस मुद्रानीति से वह बेचारा निम्नलिखित रूप से बुरी तरह से प्रभावित होगा :

प्रथम, निर्धन कृषकों और निर्धन श्रमिकों की अकाल तथा अन्य दैवी संकटों को सहन करने के प्रमुख साधन रूप बचतें प्रमुख रूप से चांदी के गहनों के रूप में ही मिलती हैं। चांदी की उपभोग वस्तु के रूप में उसकी कीमत में गिरावट रुपये के रजनमूल्य में गिरावट के स्तर तक सहसा ही उन बचतों के मूल्य को घटा देगी।¹⁰⁶ आर० सी० दत्त ने भारत के गरीब आदमी की बचतों के एक तिहाई भाग को हड़पने की सरकार की चेष्टा पर टिप्पणी की :

गरीब आदमी की बचत को इस बुरे ढंग से प्रभावित करने वाली कोई भी योजना एक पल के लिए भी इंग्लैंड में वहां के लोगों द्वारा सहन नहीं की जा सकती और यह मानना भी संभव है कि यदि ऐसी योजना इटली जैसे निर्धन औपनिवेशिक देश में लागू की जाती तो प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक क्रांति की आग भड़क उठती।¹⁰⁷

1902 में जी० के० गोखले ने बताया कि चांदी धातु के मूल्य में उस समय भी गिरावट आई है जबकि उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया।¹⁰⁸ इस संबंध में 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'मराठा' ने सरकार को यह भारी भूल सुधारने के लिए निम्नलिखित रोचक सुझाव दिए : प्रथम, सरकार टकमालों के बन्द होने में पहले की चालू कीमत पर लोगों से सारी चांदी खरीद ले और सोने में उस मूल्य का मुग्तान करे।¹⁰⁹ द्वितीय, किमान और साथ ही साथ अन्य गरीब हिंदुस्तानी सामान्य रूप से कर्ज में डूबे हुए हैं। रुपये की कीमत बढ़ाने का अर्थ हुआ उन बेचारों के ऋण में बढ़ोतरी करना अथवा आर० सी० दत्त के शब्दों में : 'दरिद्र वर्ग की विपन्नता पर पलने वाले समृद्धवर्ग के लाभों में और राशि जोड़ना तथा गरीब और कर्जदार की गर्दन को जकड़े चक्की के पाट को और अधिक भारी बनाना है।'¹¹⁰ तृतीय, किसान को कृत्रिम रूप से ऊंची कीमतवाले रूप्यों में अपना भूराजस्व चुकाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि किसान को अब निर्धारित लगान को चुकाने के लिए अपेक्षित उतनी संख्या के रूप्यों में अपना भूराजस्व चुकाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि किसान को अब निर्धारित लगान को चुकाने के लिए अपेक्षित उतनी संख्या के लिए रूप्यों की प्राप्ति के लिए पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में अपने उत्पादन को बेचना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में रुपये की मूल्य वृद्धि से करों पर पड़ने वाला गुप्त भार अधिकांशतः बेचारे किसान को ही उठाना पड़ेगा।¹¹¹ इसी तर्क के आधार पर भारतीय नेताओं ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि जहां भी भूमि का किराया नकदी चुकाना पड़ता है, वहां उसमें भी वृद्धि हो गई।¹¹²

यदि कृषकों और उद्योगपतियों को सरकार की मुद्रा नीति के फलस्वरूप हानि उठानी पड़ रही है तो फिर इसका लाभ किसे हो रहा है ? भारतीय नेताओं का निश्चित मत था कि इस विशेष सन्दर्भ में न केवल नए कर थोपने की विवशता से अथवा अपने स्वार्थों में

कटौती की आवश्यकता से बचने के लिए प्रत्युत भारत में रहने वाले विविध यूरोपीय वर्गों और समुदायों की सहायता के लिए संक्षेपतः ब्रिटेन के लाभ के लिए सरकार ने भारतीयों के हितों की वलि चढ़ाई।¹¹³ उनके अनुसार रुपये की मूल्य वृद्धि के विविध परिणामों में प्रथम था सरकारी कर्मचारियों के विशेषतः भारत के लिए भार रूप ब्रिटिश कर्मचारियों की सेना, के वतनो में अनुपाजित वृद्धि।¹¹⁴ द्वितीय, विदेशी व्यापारियों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है ताकि मुट्ठी भर अंगरेज समार के किसी भी सम्य देश में व्यापारियों द्वारा भेजे जाने वाले सामान्य खतरो में मुक्त होकर शांत और स्थिर चित्त में अपना स्वर्णिम व्यापार चला सकें।¹¹⁵ तृतीय, नए मुद्रा कानून के अंतर्गत उद्देश्यो में एक था भारत में विदेशी पृजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।¹¹⁶

टकमाल बढ़ होने में किमानो को हानि पहुंचने का राष्ट्रवादियों का तर्क इस अनुमान पर, जिसे सरकार ने भी समान रूप में स्वीकार किया था, आधारित था कि उसके परिणाम-स्वरूप रुपये की कमी रुपये की क्रयशक्ति को बढ़ा देगी। परंतु थोड़े में वर्षों, 1893-1899 की मध्यावधि, का छोड़कर यह मौलिक अनुमान विशेषतः अनाज के मामले में सत्य न सिद्ध हुआ। जैसी राष्ट्रवादियों ने भविष्यवाणी की थी, टकमालो के बढ़ होते ही तत्काल उत्पादन सामग्री और कु... अंग्रेजी रुच्चे सामान के मूल्य तो गिर गए परंतु अनाज के मूल्य में केवल 1894-1895 और 1899 के वर्षों में 1893 के स्तर तक उल्लेखनीय गिरावट आई।¹¹⁷ इस स्थिति के जिम्मेदार विभिन्न कारणों में यह तो हमारा कोई सबंध नहीं, फिर भी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने जिस ढंग में अपने स्वीकृत मन के गलत सिद्ध होने पर जो कुछ भी किया, उसे समझना उचित ही होगा।

मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट की स्वीकृति के विरुद्ध आर० सी० दत्त का प्रत्युत्तर 1898 में इस तथ्य का पोषक था कि कम से कम खाद्यान्नों की कीमतें सचमुच ही गिर गई थी और इससे कृषकों का चिंतित होना स्वाभाविक था।¹¹⁸ दूसरी ओर 1902 में जी० के गोखले ने एकदम स्वीकार किया कि सामान्य मूल्य अपने को नए रुपये के सदर्थ में शीघ्रता से ढाल नहीं पाए हैं। उनके मत में व्यवस्थित होने में इस ढील के लिए उत्तरदायी कारण गैरआर्थिक थे, जैसे, भारत जैसे पिछड़े देश में परंपरा की शक्ति, 1896-1901 की अवधि में व्यापक रूप में अकाल की स्थिति का बने रहना, तथा अन्य विभिन्न बाह्य परिस्थितियां। उन्हें अपने मन में पूरा विश्वास था कि ये तत्व बहुत देर तक बने नहीं रह सकते और रुपये के मूल्य में कृत्रिम वृद्धि के अनुरूप ही शीघ्र अथवा देर में मूल्यों में सामान्य गिरावट आएगी।¹¹⁹ डी० ई० वाचा के अनुसार मूल्यों की गिरावट को रोकने वाला एक विशेष और वास्तविक कारण 1901 में 14 करोड़ रुपयों के नए सिक्के जारी करना था। उन्होंने 1901 में टिप्पणी की कि सरकार के इस पग ने न केवल रुपये की अतिशयता की धारणा के भ्रम का पर्दाफाश कर दिया है प्रत्युत देश में धन के अभाव को भी कम किया है।¹²⁰ थोड़ी अप्रासंगिकता के साथ यहां हम यह कह सकते हैं कि कम से कम एक राष्ट्रवादी पर्यवेक्षक बंगाली अपने 28 जून 1898 के अंक में 'प्राप्त सफलता का कोई मुकाबला नहीं,' इस कहावत की उपेक्षा करने में और इस तथ्य को खोज निकालने में सफल हो गया कि स्टर्लिंग के सदर्थ

में रुपये की सुधरी स्थिति यह प्रमाणित नहीं करती कि टकसालों का बंद करना एक उचित नीति थी तथा न ही यह सिद्ध होता है कि रुपये की सुधरी विनिमय स्थिति में इस नीति का कोई योगदान है। वस्तुतः यह सुधार तो बाजार से कौंसिल बिल को लौटा लेने का और राज्य सचिव के निरंतर ऋण लेने का परिणाम था। 1893 के अधिनियम के प्राकृतिक प्रवर्तन से ये बातें सर्वथा भिन्न थी।¹²¹

राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण को सर्वाधिक सुदृढ़ समर्थन दादाभाई नौरोजी से मिला। उनकी सफाई का मुख्य आधार देखने में ही सरल था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि मूल्य गिरें या बढ़ें, वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं। उन्होंने निर्देश किया कि मूल्यों के उतार-चढ़ाव तो कई तत्वों का सम्मिलित प्रभाव होता है, अतः मूल्य के संदर्भ में किसी एक तत्व को महत्व देना अथवा उसे उत्तरदायी ठहराना सर्वथा भ्रम है। सही आर्थिक विश्लेषण के लिए टकसालों के बद होने के वास्तविक तथा पूर्ण प्रभाव को अन्य पक्षों से अलग करके उसकी अपनी ही समग्रता में उसकी जांच करनी चाहिए। समस्या को इस ढंग से देखते हुए नौरोजी का निश्चित मत था कि इस मान्यता का कि रुपये के सोने और चांदीगत मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप किसान को सरकार को राजस्व की अपेक्षाकृत ऊंची रकम चुकानी पड़ती है, वस्तुओं के वास्तविक यत्कचित मूल्य के संदर्भ में एक नितात स्वतंत्र रूप था। यदि किन्हीं अन्य तत्वों के प्रवर्तन में वस्तुओं के वास्तविक मूल्य में गिरावट नहीं आती तो इसका अर्थ केवल यह है कि मुद्रा परिवर्तन यदि न होता और अन्य तत्वों का प्रवर्तन जारी रहता तो वस्तुओं के मूल्य और अधिक बढ़ जाते तथा किसान को उसी मात्रा में लाभ होता। इस प्रकार सरकार ने टकसालों को बंद करने के कपटपूर्ण उपाय द्वारा किसान को अन्य लाभप्रद तत्वों के लाभों से वंचित कर दिया है। उन्होंने अपनी इस चिंतन पद्धति को एक अन्य रूप में भी अभिव्यक्ति दी। उनके अनुसार पुराने रुपये और नए रुपये के रजतमूल्य में अंतर आ गया है पुराने रुपये का मूल्य 184 ग्रेन चांदी था और नए का मूल्य 269 ग्रेन हो गया है, इससे विशिष्ट बाजार में और विशिष्ट समय में वास्तविक मूल्य स्तर में सर्वथा भिन्न चांदी के इन दो भिन्न परिमाणों से नियंत्रित उपभोग वस्तुओं के मूल्य के मध्य एक अंतर तो मदा बना रहेगा और रुपये की मूल्य वृद्धि में किसी भी घड़ी में मूल्य में आने वाला अंतर किसान को होने वाला घाटा ही कहलाएगा।¹²²

राजनीतिक आशय

राष्ट्रवादियों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण का कि भारत सरकार की मौद्रिक कठिनाइयों का मूल कारण गृह प्रभार थे, एक उपपरिणाम यह विश्वास था कि यदि भारत राजनीतिक दृष्टि में स्वतंत्र होता तो मुद्रा समस्या उत्पन्न ही न होती।¹²³ अब, जब समस्या उत्पन्न हो गई है; इससे निपटने के लिए सरकार को भारतीय जनता और उसके प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए।¹²⁴

जब राष्ट्रीय विरोध के बावजूद 1893 में निजी और पार गिके डालने के लिए टकसालों बढ़ कर दी गईं और बाद में भारत में स्वर्णमान को लागू करने की कार्यवाही की

गई तो बहुत सारे भारतीयों ने यह असंतोषजनक निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में भारत का शासन भारतीयों के हित में नहीं है बल्कि किसी अन्य के हित साधन के उद्देश्य के लिए है। इस तथ्य को 'मराठा' ने अपने 12 मार्च 1893 के अंक में इस प्रकार वाणी दी : सिद्धांततः वर्तमान सरकार अफसरों की, अफसरों के लिए और अफसरों द्वारा संचालित है।¹²⁵ 1898 में आर० सी० दत्त ने शोकविह्वल होकर कहा : 'भारत सरकार की कार्य-वाही से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश का कार्य भारत सरकार के लिए और विदेशी व्यापारियों के लिए सुविधा जुटाना ही है। ऐसा दिखाई देता है कि इस देश की अपनी प्रसन्नता का तो जैसे कोई महत्व ही नहीं और इस देश के प्रतिनिधियों का मत तो जैसे बेकार ही है।' ¹²⁶ दादाभाई नौरोजी ने भी 1898 में इंडियन करेंसी कमेटी को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में इसी तथ्य को इसी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया :

सत्य यह प्रतीत होता है कि भारत एक उस लावारिस शरीर के समान है जिसे कोई भी अनाड़ी अपनी बैज्ञानिक शोध के लिए चीर-फाड़ सकता है, किसी भी प्रकार के अशिष्ट, क्रूर तथा अविवेकपूर्ण प्रयोग उसपर कर सकता है। उस शरीर पर क्या बीतती है, इसकी क्या चिंता ? भारत हमारा क्रीत दास है, इसे कुछ भी अदा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 'सरकार यहां तो करदाताओं के साथ ऐसी क्रीडाओं का साहस ही नहीं कर सकती। भारत में तो सरकार केवल विदेशी (सरकारी तथा गैरसरकारी) हितों की ही सर्वप्रथम चिंता करती है और बाद में ही प्रजा के हितों पर ध्यान देती है। जहां तक विदेशी हितों का संबंध है, वहां तो सरकार प्रजा की कदापि कोई चिंता ही नहीं करती।'¹²⁷

वस्तुतः मुद्रा रोग के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा निरूपित लक्षण और उनके अनुरूप सुझाए गए उपचार में गहरे राजनीतिक आशय निहित थे। गृह प्रभारों को समाप्त करने अथवा कम से कम उनमें भारी कटौती करने और सैनिक व्यय घटाने की सलाह देना एक प्रकार से विदेशी शासकों को अधिकार त्याग के पथ पर आरूढ़ होने की बात कहना था। हा, इसमें संदेह नहीं कि कुल मिलाकर भारतीय नेताओं ने सरकार की मुद्रा नीति को जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। विनिमय की क्षतिपूर्ति के भत्ते के प्रति उनके दृष्टिकोण के अध्ययन से यह तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता

मुद्रा सुधार के विषय से भी अधिक प्रमुख दूसरा गौण विषय विनिमय क्षतिपूर्ति के भत्ते का था जिसने भारतीयों के क्रोध और शत्रुता को भड़का कर चरम सीमा तक पहुंचा दिया तथा भारतीय राष्ट्रवाद की आग भड़का दी। विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता वह भत्ता था जिसे भारत सरकार ने 1893 में रथाई रूप से भागत में न रहने वाले, यूरोपीय और यूरोपीय-एशियाई अधिकारियों को इंग्लैंड भेजी जाने वाली धनराशि में रुपये के स्वर्ण मूल्य में आई गिरावट से होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए देना स्वीकार किया था। यह भत्ता इस परिमाण तक स्वीकार किया गया था कि एक अधिकारी 1 शिलिंग 6 पेंस प्रति

रुपये की रियायती विनिमय दर पर 1000 पौंड प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक अपना आधा वेतन यूरोप को भेज सकता था। इंग्लैंड को धन भेजा गया है अथवा नहीं, यह देखे बिना ही यह भत्ता दे दिया जाता था।¹²⁸ इससे इन सरकारी अधिकारियों के वेतन में वास्तविक वृद्धि हो गई। इस बढ़े हुए धन की राशि 1893-98 की अवधि में लगभग 5 करोड़ रुपये थी। 1895-6 में जब यह अधिकतम सीमा तक पहुँच गई, तब यह रकम लगभग 1.33 करोड़ रुपये थी।¹²⁹

जब ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रारंभ में विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की मांग रखी तो भारतीय नेताओं ने उसका तीव्र विरोध किया। बाद में जब सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया तो सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ जो बाद में वर्षों तक चला रहा। इस भत्ते की निंदा करते समय राष्ट्रवादियों ने बड़ी ही कठोर और चुभती भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों के विरुद्ध घृणा की भावना को भड़काया। इस कार्यवाही से उत्पन्न देशवासियों की घृणा के स्वरूप, परिमाण, यहाँ तक कि उसके स्तर को, अपनी नरमी के लिए विख्यात नेताओं द्वारा प्रदर्शित निर्भीकता को 'कैमरे हिट' के 27 अगस्त 1893 के अंक की टिप्पणी के निम्नलिखित अवतरण में बड़े ही मुदर रूप में प्रदर्शित किया गया है।

जब कभी निष्पक्ष इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत की अवधि के ब्रिटिश प्रशासन के व्यवहार पर अनवरत निर्णय को अभिलिखित करेगा तो उसके किसी भी भाग में विदेशी घामको की, प्राचीन अथवा आधुनिक काल के इतिहास में अनुपलब्ध, फिजूल-खर्ची के रूप में सहानुभूतिहीनता के लिए और शासनतंत्र की व्यवस्था हेतु इस महान देश के अमहाय और बेजबान लोगों पर कमरतोड़ तथा निर्दयतापूर्ण बोझ डालने में बरती जाने वाली बेहिसाब क्रूरता के लिए अति कठोर निंदा के अतिरिक्त और क्या होगा? हेस्टिंग्स स लंसडौन के दिनों तक भारत सरकार की वित्तीय भूलों और निर्दय लूट की एक दुःखद और विशाल सूची रही है परंतु उनकी बुद्धि में कदाचित् यह सूची न अधिक भारी होगी और न ही अधिक विस्तृत। उन्होंने पिछले अन्यायों और पिछली गलतियों के ढेर को वर्तमान के अपेक्षाकृत अधिक बड़े अन्यायों और गलतियों से पीछे धकेल दिया है। यह असम्मानप्रद तथा अशोभन कार्य लांड लंसडौन के लिए ही सुरक्षित था और कौन कहेगा कि उसने निर्लज्जतापूर्ण घृष्टता और विवेकहीन उत्तरदायित्व से अपना कार्य नहीं किया। ऐसा अनुमान है कि इस साहम और उत्तरदायित्व के लिए तो उन्हें ब्रिटिश अभिजातवर्ग में उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित करने के रूप में पुरस्कृत ही किया जाएगा। लंसडौन की उच्च पदवी ने परमादरणीया महारानी की भारतीय प्रजा के लाखों लोगों का बहुत ही अहित किया है। इसमें संदेह नहीं कि महारानी महोदया उसकी लांडेसिंग को और अधिक उन्नत करेंगी और इसमें संदेह नहीं कि उसे ड्यूक के पद से अलंकृत करेंगी। संशोधित मुद्रा अधिनियम तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते के लेखक होने के नाते उसके सम्मान असम्मान की कौन शिकायत करेगा। इस अधिनियम तथा भत्ते के द्वारा विदेशी कर-भक्षी दैत्यों के लिए भूखों मरते भारतीय करदाताओं के मूल्य पर गुलछरें उड़ाना

संभव हो गया है। इस प्रकार लार्ड लेंसडोन ने अपनी शासन सत्ता को स्मरणीय बना दिया है। उसने लार्ड लिटन द्वारा प्रारंभ किए गए और लार्ड डफरिन द्वारा जारी रखे गए अवर्णनीय लालच के क्षेत्रीय तथा वित्तीय चक्र के प्रवर्तन को पूरा कर दिया है। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि देश के प्रशासन द्वारा गलती, अन्याय, लूट और छीना भपटी के दिन दहाड़े किए जाने वाले कार्यों पर हम क्रोध से जल रहे हैं। हम यह देखने के इच्छुक हैं कि इन गैरईसाई काम करने वालों के साथ न्याय हो। इस विषय पर और अधिक कहने की हममें हिम्मत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नंगा लूटपाट का काम सर्वथा अदृष्टपूर्व ही है। कोई जनता की थोड़ी सी भलाई करने वाली सरकार ऐसे काम से शर्मिदा हो उठती। परंतु यह मानना गायब गलत नहीं कि ब्रिटिश सरकार ईसाई तथा ईमानदार सरकार है अतः उसे एक के आनंद के लिए दूसरे को लूटने-खसूटने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है।¹³⁰

अन्य समाचारपत्रों ने भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति को इन शब्दों में वर्णित किया : 'लूट', 'क्रूर कृत्य', 'डाका'।¹³¹ कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा ने इस कार्यवाही के विरुद्ध भारत सरकार के पास विरोधपत्र भेजे।¹³² 1893 में हुए अपने अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस भत्ते का विरुद्ध तीव्र विरोध अभिलिखित किया।¹³³ फलतः अगले 10 वर्षों तक कांग्रेस के कार्यक्रमों में, जारी भत्ते को समाप्त करने की मांग के प्रस्ताव पाम होते रहे।¹³⁴ सरकार की इस कार्यवाही की निंदा में सभी सार्वजनिक नेता एकजुट हो गए। उदाहरणार्थ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस कार्यवाही को 'एक पाप कृत्य और पाप में भी निकृष्ट कृत्य' तथा 'परले दरजे का लज्जाजनक कृत्य' बतलाया। उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि ऐसी कार्यवाही करने वाली सरकार को भी क्या सम्य, ईसाई तथा सही आचरण करने वाली सरकार कहा जा सकता है? ¹³⁵ दादाभाई नौरोजी ने इस कार्यवाही को 'निर्धन भारत में हृदयहीन, मनमानी और क्रूर छीना भपटी' कहा और इसे शाइलाक के दुष्कृत्य से भी बुरा बताया क्योंकि उसने शर्त के अनुसार मास का पौंड मागा था परंतु यह सरकार तो भारतीयों का खून भी साथ ही चूस रही है।¹³⁶

भारतीय नेताओं ने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते के अन्याय को बड़ी तत्परता और गहरी रुचि के साथ इसलिए अनुभव किया कि भारत सरकार के बजट पर यह अतिरिक्त भार उस समय लादा गया था जब पहले ही वह जटिल कठिनाइयों में परेशान थी, नई परेशानियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी और देश पर नए करों के लगाने का खतरा उपस्थित हो गया था जो सीमा शुल्कों के रूप में शीघ्र ही सामने आया।¹³⁷ वस्तुतः भारतीय नेताओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि नए कर विनिमय मुआवजा भत्ते की ही प्रत्यक्ष उपज थे और ये कर सरकारी अधिकारियों के हित में ही लगाए जा रहे थे। भारतीय नेताओं के अनुसार यह कार्यवाही सचमुच सुबह से शाम तक मरने पिसने वाले और इतने पर भी पूरा भोजन न पा सकने वाले तथा अतिरिक्त करों का भार उठाने में सर्वथा असमर्थ भारतीयों की कमाई पर पलने वाले उन यूरोपीय अधिकारियों की सहायता करना था जो कुछ कम पर भी निर्बाह कर सकते थे।¹³⁸ 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को

संबोधित करते हुए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस समस्या का चित्रमय विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, 'उच्च वेतनभोगी सरकारी अधिकारियों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त मास-मदिरा जुटाने के लिए अब अभावग्रस्त भारतीय को अपने गेहूं, चावल और नमक की मात्रा को परिमित करना पड़ेगा।'¹³⁰ एक अन्य अत्यंत क्रुद्ध समीक्षक नार्थवैस्ट प्राविस और अवध के जमी उल उलुम ने लिखा 'भारत तो इन अधिकारियों के लिए वेतन ही कठिनाता से जुटा पाता है जबकि ये डाकू इसमें भी अधिक कुछ और की माग करते हैं।'^{131-A}

राष्ट्रीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता न केवल भार-रूप था प्रत्युत अनुचित और अनावश्यक भी था। उन्होंने बल देकर कहा सर्वप्रथम तो रुपये के स्वर्णमूल्य में गिरावट से भारत स्थित यूरोपीय अधिकारियों को वास्तव में कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं पहुंची क्योंकि इंग्लैंड में भेजी जाने वाली रकम का घाटा वहां उपभोग वस्तुओं के स्वर्ण मूल्य में गिरावट आ जाने से पूरा हो गया है अथवा दूसरे शब्दों में दादाभाई नौरोजी ने इसे 1886 में इस प्रकार स्पष्ट किया 'यद्यपि यूरोपीय अधिकारियों को इंग्लैंड भेजे गए रुपयों से पहले की अपेक्षा थोड़ा सोना मिलता है परंतु उस सोने की क्रयशक्ति पूर्वापेक्षा अधिक है।'¹³² द्वितीय, भारतीय नेताओं के अनुसार भारत स्थित सरकारी अधिकारियों के वेतन बहुत ही ऊंचे थे, विशेषतः इंग्लैंड और भारत के मध्य संचार साधनों और सुविधाओं में आए परिवर्तनों के संदर्भ में तो विनिमय में आई गिरावट के बावजूद वे बहुत ही ऊंचे थे।¹⁴¹ तृतीय, कर्मचारियों को यह रियायत पाने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि वे तो केवल रुपयों में ही वेतन पाने के लिए अनुबंधित थे। अतः विनिमय के अनुपात को बीच में घसीटना सर्वथा अनुपयुक्त है। जब रुपये का मूल्य अतीत में ऊंचा था और भविष्य में जिसके 2 शिलिंग तक बढ़ जाने की संभावना थी, इन कर्मचारियों ने अनुबंधित वेतन लेने से न तो भूतकाल में इनकार किया और न भविष्य में ही वे इनकार करेंगे।¹⁴² इसके साथ ही गोखले महोदय ने टिप्पणी की : सरकार रेल कंपनियों को अब भी 5 प्रतिशत की दर से सूद का भुगतान कर रही है जबकि अब वह 2½ प्रतिशत की दर में ऋण ले सकती है। उनका स्पष्ट कथन था : यदि वर्तमान अनुबंधों को भारत के बजट के पक्ष में नहीं छोड़ा जा सकता तो उन्हें उसके विपक्ष में क्यों छोड़ा जाए।¹⁴³

भारतीय नेताओं का यह भी निश्चित मत था कि इस भत्ते के निर्णय में वस्तुतः सरकार न्यायप्रिय तथा निष्पक्ष ही नहीं रह सकी है।¹⁴⁴ प्रथम, यह भत्ता वेतन के आधे भाग (चाहे विदेश भेजा गया हो अथवा नहीं) पर न देकर वास्तविक रूप से भेजी गई रकम पर ही देना चाहिए था। द्वितीय, यह भत्ता केवल उन्हीं अधिकारियों को देना चाहिए था जिनके सेवा में आ जाने के उपरांत रुपये के मूल्य में गिरावट आई है न कि उन लोगों को जिन्होंने जानबूझकर रुपयों में वेतन लेना स्वीकार किया है।¹⁴⁵ तृतीय, भारत सरकार ने अपने संबंधियों को उनकी शिक्षा के लिए विदेशों में रुपया भेजने वाले भारतीय अधिकारियों को इस भत्ते के देने से इनकार करके रंगभेद की नीति अपनाई है।¹⁴⁶

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस सारे कांड से राजनीतिक परिणामों पर पहुंचने में

चूक नहीं की विशेषतः भारत में ब्रिटिश शासन के प्रयोजन को उन्होंने शीघ्र ही जान लिया। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी रक्षा के स्वीकृत दायित्व को नहीं निभाया है।¹¹⁷ उन्होंने शिकायत की कि जहा सरकार ने भारत की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकताओं, सफाई, गमाज सुधार और प्रशासनिक सुधार, को आर्थिक तर्ग के आधार पर पूरा नहीं किया है, वहां उसने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति के रूप में भारतीय वित्तों पर अनुचित और अनावश्यक भार डालने में जरा भी सकोच नहीं किया।¹¹⁸ 22 अगस्त 1893 में अमृत वात्रा पत्रिका ने क्रुद्ध होकर लिखा 'दिनो में लोगों की जान बचाने के लिए तो पैसा नहीं था, परंतु भारतीय किसान के भाग्य पर पहले में माटे हो रहे, भयंकर रूप में उच्च वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को और अधिक मोटा करने के लिए पैसा है?' जी० के० गोखले ने भी इसी प्रकार की शिकायत की।

जनता की शिक्षा पर नगण्य और शोचनीय सरकारी खर्च में पिछले पांच साल में इस आधार पर वृद्धि नहीं हुई कि सरकार के पास खर्च करने के लिए और अधिक पैसा है ही नहीं और इधर सरकार ने कलम की एक चोट से ही शिक्षा पर होने वाले सारे खर्च से भी अधिक बड़ी धनराशि यूरोपीय अधिकारियों को भेंट कर दी है।¹¹⁹ भारतीय नेताओं ने इस बात की भी शिकायत की कि जहां उच्च वेतनभोगी ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन में परीक्ष वृद्धि हो गई है, वहां सरकारी कार्यालयों में क्लर्क अथवा प्रबंध अधिकारियों के रूप में नियुक्त भारतीयों के वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई।¹²⁰

इस सबने इस तथ्य की पुष्टि कर दी कि भारत पर एकातल इंग्लैंड के हितों की दृष्टि से शासन किया जा रहा था। वस्तुतः इस विषय पर चिंतन ने पर्याप्त सीमा तक कटुता उत्पन्न की। सामान्यतया आशावादी दादाभाई नोरोजी ने निराश होकर लिखा कि 'परंतु, देखा यह गया है कि जब यूरोपीय हितों की बात सामने आती है तो कानून और दिल, दोनों हवा हो जाते हैं और वस्तुतः मात्र निरंकुशता और शक्ति ही कानून और तर्क रह जाते हैं।'¹²¹ सुरेंद्रनाथ बैंजर्जी ने कटु व्यंग्य करते हुए टिप्पणी की :

यह विनिमय प्रस्ताव एक मूर्तिमान सिद्धांत है जिसका भारत सरकार निरंतर अनुसरण करती रही है। वह सिद्धांत क्या है? हम इस धरती के सपूत हैं, हम इस धरती के दास हैं - लकड़ी काटने वाले, पानी खींचने वाले सेवक हैं। हमारा अस्तित्व तो इस नौकरशाही रूपी भगवान की सेवा के लिए ही है।¹²²

'गुजरात दर्पण' ने 31 अगस्त 1893 के अंक में अपने क्रोध और कुठा को निम्नलिखित शब्दों में वाणी दी

हमारे देश की जनता के तथाकथित संरक्षकों की स्मृति से भी भगवान बचाए जिन्होंने इस देश के तीस करोड़ लोगों को, जिनकी वे पैत्रिक स्नेह के साथ रक्षा का दावा करते हैं, वास्तव में नरक में धकेल दिया है। जब हमें यह ध्यान आता है कि हमारा देश विनाश के गर्त में धकेला जा रहा है तो हमारे लिए संयम संभव नहीं हो पाता। इस देश में बतखों की सेना में राजहंस इसलिए भेजे गए हैं कि इस देश के वासियों की रक्षा करें, उन्हें सुसभ्य बनाएं, उन्हें सुधारें, उन पर शासन करें, उन पर पाव की ठोकर

मारें तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मौत के घाट उतारे। भगवान, हमे हमारे इन दोस्तों से बचाओ।¹⁵³

बहुत सारे अन्य भारतीय नेताओं ने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते द्वारा प्रदर्शित ब्रिटिश शासन की प्रकृति तथा भारत में ब्रिटिश कर्मचारियों की भूमिका पर इसी प्रकार की तीखी, आलोचनापरक टिप्पणियाँ की।¹⁵⁴

निष्कर्ष

पूर्वगामी समीक्षा से यह निष्कर्ष पुष्ट होता है कि भारतीय नेताओं ने रुपये के गिरते विनिमय के प्रति अपने दृष्टिकोण को निर्धारित करने में एक ओर स्पष्टतः विकासशील सूती वस्त्र उद्योग के और कृषकों के हितों को प्राथमिकता दी और दूसरी ओर कुछ अन्य वर्गों और समुदायों के हितों की उपेक्षा ही नहीं, उनका विरोध तक किया।

एक ऐसा समुदाय वेतनभोगी भारतीयों का था जिनमें अधिकांश सरकार द्वारा नियुक्त थे। इनमें अपेक्षाकृत उच्च वेतनभोगी बड़े पैमाने पर आयातित सामान के उपभोक्ता थे, वे एक निश्चित आय ही प्राप्त करने थे, टुकमालों के बदलने के फलस्वरूप भारत में मूल्यों में आई गिरावट से यह वर्ग लाभ में था। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इनके हितों का विरोध प्रच्छन्न और मौन ही नहीं था प्रत्युत कभी कभी पत्यक्ष और स्पष्ट रूप भी ग्रहण करता था।¹⁵⁵ इसी प्रकार रुपये की मूल्यवृद्धि से ऋणकर्ता साहूकार भी स्पष्टतः लाभ में था। राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ भी सूदखोर के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात न दिखाया प्रत्युत भारत सरकार की मुद्रानीति के विरुद्ध सूदखोर के मुद्रापत्रनिर्गमन से लाभान्वित होने की सभावना का एक प्रमुख तर्क के रूप में ही प्रयोग किया। ऋणकर्ताओं तथा वेतनभोगी कर्मचारियों पर पड़े करोंसी लैजिस्लेशन प्रभाव के प्रति राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण डी०ई० वाचा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नवम अधिवेशन में किए गए भाषण के निम्नलिखित अवतरण में अपने मक्षिप्त रूप में इस प्रकार है 'कठार धम करने वाले श्रमिकों तथा करो के भार से दबे-किसानों को इसलिए दरिद्र बनाया जा रहा है ताकि उनके मूल्य पर सरकारी कर्मचारी और सूदखोर मोटे हो सकें।'¹⁵⁶ इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक वेतनभोगी मजदूरों, जिनकी मजदूरी का मूल्यवृद्धि की दशा में पिछड़ जाना और दूसरी ओर मूल्यों में गिरावट आने पर लाभ में आ जाना स्वाभाविक था- के हितों की भी उगी कारण में कोई चिंता नहीं की। यह भी कम आश्चर्यप्रद नहीं कि स्वयं भारतीय नेताओं ने एक भिन्न सदर्भ में ही सही, निर्धन श्रमिकों, कृषकों के और मूल्य के बीच मह संबंध को उच्च स्तर से स्वीकार किया और उस पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया।¹⁵⁷ हा, मुद्रा समस्याओं पर विचार करते समय यह विषय उनकी गणनाओं में छूट गया।¹⁵⁸

मुद्रानीति के निर्धारण में राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित और यहाँ तक कि विरोध का शिकार व्यापारी वर्ग विशेषतः मामूरी के आयात व्यापार में मलग्न व्यापारी वर्ग था। निम्नलिखित तथ्यों में इस कथन की सुस्पष्ट और समुचित पुष्टि हो जाती है :

(क) प्रथम, जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, भारतीय नेताओं ने देश के लिए सही मुद्रानीति के प्रश्न पर निर्णय लेने हुए विदेश व्यापार की समृद्धि को एक

विचारणीय विषय नहीं बनाया।¹⁵⁹

(ख) द्वितीय, भारतीय नेताओं द्वारा अभिशंसित मुद्रानीति विदेश व्यापार में संलग्न व्यापारियों के बहुत बड़े समुदाय तथा उनके प्रवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मांग के विपरीत थी। उदाहरणार्थ, 1892 में बंगाल के राष्ट्रीय वाणिज्य सदन की पाचवीं वार्षिक बैठक में अध्यक्षीय भाषण करते हुए रायबहादुर धनपतिसिंह ने निम्नलिखित चेतावनी दी : 'बर्तमान विनिमय दर व्यापार पर घातक प्रहार है और यदि रजत मूल्य में वृद्धि के तत्काल उपाय न किए गए तो वह दिन दूर नहीं जब व्यापार का वेड़ा गंका हो जाएगा और कलकत्ता की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियां बंद होने पर विवश हो जाएगी।'¹⁶⁰ जब 1892 में इंडियन करेंसी एंमोसिएशन ने टकसाल बंद करने और स्वर्णमान अपनाने का प्रबल आंदोलन प्रारंभ किया तो भारतीय व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समुदाय सक्रिय समर्थक के रूप में इस आंदोलन में सम्मिलित हो गया।¹⁶¹ जून 1892 में कराची के 77 प्रमुख व्यापारियों ने और अक्टूबर 1892 में बंबई के 674 व्यापारियों ने सरकार को मानपत्र दिया, जिसमें रुपये के मूल्य को स्थिर करने का अनुरोध किया गया था और इसके लिए तर्क यह दिया गया था कि रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव से उनके मुश्किल व्यापार के न्यायोचित लेन-देन में विषुद्ध रूप से अनिश्चितता और जुगबुजी की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।¹⁶² बंबई के अग्रणी व्यापारी तथा महाजन सर शापुरजी भरूचा ने टक्मालों के बंद होने के उपाय की तथा रुपये के स्वर्णमान अपनाने की प्रबल वकालत की। उनके मतव्य का आधार था कि रुपये के गिरते मूल्य ने भारत के विदेश व्यापार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया है तथा विदेशी पत्तों के भारत में प्रवाह का बाधा पहुंचाई है।¹⁶³ इसी प्रकार 1898 में बंगाल के प्रतिष्ठित व्यापारी जयगोविन्द ला ने सरकार पर विनिमय की व्यावहारिक स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाला।¹⁶⁴

(ग) अतः, कुछ भारतीय नेता तो विदेश व्यापार में संलग्न व्यापारियों (जिनमें से अधिकांश सभी प्रकार से विदेशी ही थे) के प्रति सार्वजनिक रूप से शत्रुता प्रकट करने लगे और उन्हें परामर्श देने लगे कि उन्हें अवसर के अनुकूल बदलना चाहिए, बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं।¹⁶⁵ दादाभाई नौरोजी के निम्नलिखित आवेगपूर्ण शब्दों में इस विरोध की अभिव्यक्ति स्पष्ट है :

सबसे ऊपर स्वर्ण मुद्रा के लिए मधर्ग करता हुआ व्यापारी बैठा हुआ है जो यह चाहता है कि किमानों की बलि चढ़ाकर उसे उसके व्यापारिक खतरो में बचाया जाए। व्यापार के लाभ तो इस व्यापारी की अपनी ही जेबों में जाएं और व्यापारिक उथल-पुथल के खतरे बेचारा किमान उठाए। गरीबी में जकड़ा किसान इन खाते पीते व्यापारियों को बचाए। भगवान, भारत की रक्षा करो।¹⁶⁶

विदेश व्यापार में संलग्न व्यापारियों और उनकी मांगों के प्रति तथा सूती कपड़ा उत्पादकों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक रोचक अंतर स्पष्ट रूप में मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का मुद्रानीति के प्रति न केवल दृष्टिकोण ही प्रत्युत उस दृष्टिकोण के निर्धारक कारण भी बंबई के सूती वस्त्र मिलमालिकों द्वारा प्रस्तुत कारणों से मिलते जुलते हैं। यह तथ्य बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन के 1893, 1898, 1899, 1900 और 1901 के

प्रतिवेदनों के तथा 'इंडिया' के 1 दिसंबर 1893 के अंक में प्रकाशित जे० एन० टाटा के लंबे साक्षात्कार के अध्ययन से उजागर हो जाता है। सचमुच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूती उत्पादकों को अपना मंच सौंप दिया था ताकि वे भारतीय लोकमत के समक्ष अपने उद्योग के मामले की ठीक वकालत कर सकें। इसी सुविधा के कारण जे० ए० वाडिया, विट्ठलदास, डी० ठाकरसी, सोराबजी कडका और अबालाल शंकरलाल देमाई आदि सूती वस्त्र उद्योग के महारथी कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित हुए।¹⁶⁷

वस्तुतः हमारे विचार में रुपये के अवमूल्यन में भारतीय राष्ट्रवादी नानाओं की वफादारी को एकात्मता नहीं, व्यापक रूप से तो अवश्य ही स्वदेशी पृथी के आत्मकरण द्वारा देश के उद्योगीकरण के प्रति उनकी समग्र तथा एकनिष्ठ भक्ति के मद्देन में ही देखना चाहिए। यह ठीक है कि रुपये की संभावित मूल्य वृद्धि के किमानों पर पड़ने वाला हानिप्रद फलितार्थों के संबंध में उनकी समीक्षा कदाचित् उनके द्वारा विपणन दावा के अनुरूप नहीं सही फिर भी कुछ औचित्य लिए हुई अवश्य थी।¹⁶⁸ यह भी सही है कि 1893 और 1899 के करंसी लैजिस्लेशन द्वारा सरकार के विनिमय घाटे के कारणभूत गृह प्रभारों को हटाया नहीं गया था केवल उन्हें जनता के कंधों पर डाल दिया गया था। इस घाटे की निरंतरता प्रत्यक्ष रूप में सरकार को लोकव्ययों और गृह प्रभारों में कटौती के अत्यावश्यक पग उठाने को विवश कर सकती थी। हमें इसमें सन्देह नहीं है कि अतः यह देश के वस्त्र उद्योग को होने वाली स्पष्ट और वास्तविक हानि थी जिसमें भारतीय नेता चिंतित हुए और इस प्रश्न पर एक कठोर दृष्टिकोण अपनाया और सरकार की मुक्तियों को अनमुना कर दिया। निस्संकोच, देश के सूती वस्त्र उद्योग को होने वाला घाटा भारी था। उस समय यह उद्योग अपने उत्पादनों की खपत के लिए अधिकांश रूप में ईस्ट एंगिया के बाजार पर निर्भर था।¹⁶⁹ उदाहरणार्थ, 1895-6 में भारतीय मिलों द्वारा निर्मित 430 472,000 पौंड सूत में से 185,493,000 पौंड का निर्यात किया गया। इसका अधिकांश चीन को भेजा गया।¹⁷⁰ वस्तुतः 1875 के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग के द्रुतविक्रम वा रहस्य, भारतीय सूती वस्त्र की विकास से तीव्रतर गति के साथ निर्यातों में वृद्धि में ही निहित है।¹⁷¹ इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि निम्न विनिमय दर ने भारत में और रजतमान प्रयोक्ता विदेशी देशों में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिए संरक्षक का कार्य ही किया।¹⁷² निम्नस्वदेह इस उद्योग का परवर्ती इतिहास यह बताता है कि परंपरागत सस्ते श्रम और कच्चे माल की उपलब्धि की सुविधा के कारण इसकी प्रगति की प्रवृत्ति अबाधित रही परंतु यह तथ्य वास्तविकता को झुठला नहीं सकता कि इस समय विशेष में भारत की मुद्रानीति के फलस्वरूप भारतीयों द्वारा संचालित देश के प्रमुख आधुनिक उद्योग के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ था। इस तथ्य को मुद्रानीति के सरकारी समर्थकों तक ने स्वीकार किया है।¹⁷³ वस्तुतः विन सदस्य डेविड बाखूर द्वारा 1893 में कठिनाइयों को हल करने के लिए सुझाए गए निम्नलिखित उपाय से भारतीय नेता महमत ही थे :

इन आपत्तियों का उत्तर यह है कि स्वर्णमान अपनाने के प्रश्न का किसी एक पक्ष अथवा थोड़े पक्षों को लेकर निर्णय नहीं करना चाहिए प्रत्युत इस विषय से संबंधित

सभी स्थितियों की सतर्क परीक्षा के उपरांत तथा लाभ की संतुलित स्थिति को देख-कर ही निर्णय करना चाहिए और फिर तदनुसार उस पर आचरण करना चाहिए।¹⁷⁴ इस प्रश्न के प्रति सरकारी और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच भारी अंतर की उल्लेख यह थी कि उन दोनों के लिए लाभ की संतुलित स्थिति भिन्न दिशाओं में पड़ती थी। जहां सरकारी दृष्टिकोण यह था कि यदि रजतमान प्रयोक्ता देशों के साथ हमारे व्यापार को भारी क्षति पहुंचेगी तो स्वर्णमान प्रयोक्ता देशों के साथ हमारे व्यापार को उम्मीद अनुपात में भारी लाभ मिलना है; और प्रथम (रजतमान) की अपेक्षा दूसरी गांवा (स्वर्णमान) अधिक व्यापक और अधिक महत्वपूर्ण है।¹⁷⁵ राष्ट्रवादियों का विचार था कि रजतमान प्रयोक्ता देशों के साथ व्यापार मात्रा में थोड़ा होना पर भी गुणात्मकता की दृष्टि में स्वर्णमान प्रयोक्ता देशों के साथ व्यापार की तुलना में बड़ी बढ़ चढ़ कर था। अतः राष्ट्रवादी नेता देशी सूती वस्त्र उद्योग की समृद्धि के लिए स्वर्णमान का त्याग के लिए महर्प प्रस्तुत थे। वस्तुतः उनके विचार में सूती वस्त्र उद्योग देश के श्रमलाबद्ध आद्योगिक विकास की एक कड़ी था।

तथ्यात्मक वास्तविकता यह है कि भारतीय राष्ट्रीय नेता देश के औद्योगिक विकास के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने अपने शत्रु का भी गले लगाने को तैयार हो गए। यह शत्रु था 'निकासी'। यह स्पष्ट था कि विनिमय दर में गिरावट का परिणाम व्यापार की शर्तों अथवा आयातों के बढ़ने विनिमयाभूत होने वाले निर्यातों की दुर्दशा थी क्योंकि कम से कम अतर्गम काल में अथवा जब तक देश में और विदेशों में मूल्य नई विनिमय-दर पर टिक नहीं पाते, तब तक तो यह दुर्दशा अवश्यभावी थी। आयातों के मूल्यों के यंत्रीकरण से उनकी सापेक्ष वृद्धि के विरुद्ध भारतीय उत्पादनों को वास्तविक और संरक्षण का निर्दिष्ट तर्क यह स्पष्ट सूचित करता था कि व्यापार की शर्तों पर दुष्प्रभाव पड़ा है और यह तब तक बना रहेगा जब तक विनिमय में गिरावट बनी रहेगी। जैसा हम 'विदेश व्यापार' अध्याय में दिखा चुके हैं, भारतीय नेता एक अन्य सदर्भ में भारत के विदेश व्यापार की गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त चिंतित थे। यद्यपि गिरता विनिमय कदाचित् अधिक महंगा और अत्यंत अशोभनीय लग था तथापि भारतीय नेता विकासशील भारतीय उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए इस अतिरिक्त निकासी को सहन करने को उद्यत हो गए।

इससे भारतीय नेताओं की मुद्रानीति से संबंधित एक अन्य पक्ष उजागर होता है। उन्हें समस्या का विशेष रूप से भारतीय पक्ष देखने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक दृष्टि से भारत पराधीन देश था।¹⁷⁶ और उसका अपने वित्तों पर अथवा शुल्क नीति पर कोई नियंत्रण नहीं था। वर्तमान संदर्भ में राजनीतिक पराधीनता का दोहरा अर्थ था। प्रथम, इसका अर्थ था कि भारत को अपने उद्योगों को शुल्क संरक्षण देने का अधिकार नहीं था। द्वितीय, उसे गृह प्रभार देने ही पड़ते थे। भारतीय नेताओं ने निम्न विनिमय को इस दोहरी बुराई के निवारण के लिए एकमात्र उपलब्ध उपाय माना क्योंकि यह एक ओर भारतीय उद्योग के लिए संरक्षक जुटाता और दूसरी ओर निकट अथवा दूर भविष्य में यह सरकार को इस बात पर विवश कर देता कि वह गृह प्रभारों

को घटाए, इस रूप में कि सर्वप्रथम, सरकार भारत में ही भंडारों की खरीद करे और अधिक से अधिक भारतीयों की ही सेवाओं में नियुक्ति करे। कुल मिलाकर निम्न विनियम ने गृह प्रभारों की समस्या को उजागर किया। यह दोनों रूपों में महंगा उपचार था और सामान्य स्थिति में इसे अपनाने का परामर्श ही न दिया जाता, परंतु भारतीय नेताओं ने कदाचित् अनुभव किया कि भारत जैसे एक असामान्य स्थितिवाले देश के लिए यही एकमात्र उपलब्ध उपचार था।

संदर्भ

1. उदाहरणार्थ हमने भारतीय मुद्रा इतिहास के सक्षिप्त विवरण के लिए निम्नलिखित ग्रंथों का आश्रय लिया है : जे० एस० कोयाजी . दि इंडियन करेसी सिस्टम, 1835-1926 (मद्रास 1930); एच० एल० चाबलानी : स्टडीज इन इंडिया करेसी ऐंड एक्साचेज (बंबई 1931), सी० एन० वकील तथा एस० के० मुराजन : करेसी ऐंड प्राइसेस इन इंडिया (बंबई 1927), डी० के० मल्होत्रा : हिस्टरी ऐंड प्राब्लम्स आफ इंडियन करेसी—1835-1945 (लाहौर, 1945 तृतीय संस्करण); जे० एम० कोस : इंडियन करेसी ऐंड फाइनेंस, (लंदन 1913, 1924 में पुन. मुद्रित); परिमल राय : पूर्वोद्धृत.
2. इंग्लैंड और भारत के कुछ लोगों ने सोचा कि विनियम की गिरती दर 1873 के परवर्ती 20 वर्षों की अवधि में भारत के विदेश व्यापार के द्रुतविकास, लगभग दुगना करने के लिए उत्तरदायी है परंतु इस धारणा पर किसी भी स्थिति में विश्वास न किया गया था और न ही विश्वास किया जाता है व्यापारी वर्ग को इस बात का यकीन था कि गिरती विनियम दर का उसके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा देखिए, दि रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेसी कमेटी—1893, कड़िका, 25-6 और फाइनेंशियल स्टेट्समेन्ट—1886-87, कड़िका-2 और 1891-2 (कड़िका 36)
3. विभिन्न सेवाओं, नागरिक, घर्मोपदेश, नौसेना तथा म्यूल सेना, में लगे यूरोपीय अधिकारियों के शिफ्टमंडल द्वारा 31 जनवरी 1893 को गवर्नर जनरल तथा इंडियन करेसी कमेटी को प्रस्तुत प्रतिवेदन. माध्य के विवरण तथा परिशिष्ट-1893, सी-7060 II अनुमानतः 1 से एन्क्लोचर 39.
4. भारत के तीन उत्तराधिकारी वायसरायों ने इस विषय पर बल दिया : लैंसडौन, स्पीचेज, खंड II पृ० 621, एलगिन, स्पीचेज, पृ० 489, कर्जन : स्पीचेज खंड II, पृ० 276 तथा देखिए, रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेसी कमेटी 1893, कड़िका 28.
5. इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 195
6. वकील और मुराजन . पूर्वोद्धृत, पृ० 40.
7. भारत राज्य सचिव का खजाना को लिखा गया पत्र, दिनांक 26 जनवरी 1886. भारत राज्य सचिव की ओर से भारत सरकार को संप्रेषण के साथ सलग्न. स० 6 दिनांक 28 जनवरी 1886 तथा देखिए, रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेसी कमेटी 1893 कड़िका, 34.
8. उदाहरणार्थ देखिए, फाइनेंशियल स्टेट्समेन्ट्स 1883-4 (कड़िका 136), 1886-7 (कड़िका 1, 2, 123) और 1893-4 (कड़िका 28, 30, 31).
9. लैंसडौन, एल० सी० पी० 1893 खंड XXXII पृ० 282-3.
10. जी० डब्ल्यू० फारेस्ट : ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मारबिक्स आफ लैंसडौन ऐंड वायसराय ऐंड गवर्नर

जनरल आफ इंडिया, 1888-1894, पृ० 35-6 इंडियन करेसी एसोसिएशन के विस्तृत दृष्टिकोण के लिए देखिए, प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग आफ दि इंडियन करेसी एसोसिएशन, 13 जुलाई 1892, और लैंसडौन, स्पीचेज, खंड II पृ० 518-20. भारतीय व्यापारियों की धारणा के लिए देखिए, बंगाल नेशनल चैंबर आफ कामर्स के पाचवे वापिक अधिवेशन में मंडल के अध्यक्ष का भाषण ए० बी० पी०-29 मई 1892 और एस० बी० भारुचा . स्पीचेज आन इंडियन इकानामिक्स (बंबई तिथिरहित) पृ० 2-9.

- 11 'सुवर्ण विनिमय मान का अस्तित्व देश में उस समय तक कहा जा सकता है, जबकि उसका प्रचलन उल्लेखनीय परिमाण में न हो, जब स्थानीय मुद्रा स्वर्ण में आवश्यक रूप में बदलने के योग्य न हो और जब केवल सरकार अथवा सामान्य बैंक ही विदेशों में रुपये के प्रेषण की व्यवस्था स्थानीय मुद्रा के सर्द्ध में सोने के न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर करते हों विदेशों में उल्लेखनीय परिमाण में सुरक्षित भंडार इन धन प्रेषणों की आवश्यक व्यवस्था करते हों' (केन्स पूर्वोद्धृत, पृ० 30-1)
- 12 प्रथम विश्वयुद्ध तक इन वर्षों में बड़े पैमाने पर टकन हुआ : 1899, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1911 और 1912 इन वर्षों में टकित रुपये का विशुद्ध परिमाण क्रमशः इस प्रकार था : 16.9 करोड़, 11.1 करोड़, 7.8 करोड़, 16.9 करोड़, 23.4 करोड़, 15.7 करोड़, 12.4 करोड़ और 16.3 करोड़. (बकील और मुगाजन-पूर्वोद्धृत पृ० 408)
- 13 केन्स पूर्वोद्धृत, पृ० 133, उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा वे (भारत सरकार) अपनी नीति इस प्रकार की बनाते हैं जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक समुदाय न उमी वढती भूख के साथ मुद्रा का उपभोग किया, जिस प्रकार कुछ समुदाय बीयर का उपभोग करते हैं — (पृ० 134).
- 14 उदाहरण के लिए देखिए, 1908-09 के बजट पर गोखले का भाषण, स्पीचेज, पृ० 177-80
- 15 केन्स पूर्वोद्धृत, पृ० 6.
- 16 एस० एन० बैंडर्जी स्पीचेज I, पृ० 198, इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब 12 अगस्त 1876); बाबे समाचार 5 मई 1879 और 9 नवंबर 1880 (वही, 10 मई 1879 और 13 नव० 1880 क्रमशः), बंगाली, 11 जून 1881, ब्रह्मा पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881; हिंदू, 10 अप्रैल 1885, मराठा, 23 मई 1886, रीस ऐंड रैयन, 29 मई, लिबरल, 30 मई (बी० ओ० आई० जून 1886); इंडियन स्पेक्टेटर, 18 जुलाई (वही, अगस्त 1886); भारतवासी, 23 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जनवरी 1886); समय, 8 मार्च (वही, 13 मार्च 1886); साधारणी, 4 अप्रैल (वही, 10 अप्रैल 1886), सहचर, 9 जून, नवविभाकर, 14 जून (वही, 19 जून 1886), नोरोजी : एसेज, पृ० 374, हिंदुस्तान, 22 जून (आर० एन० पी० पी० एन०, 26 जून 1888). यह आश्चर्यजनक है कि जी० बी० जोशी चांदी के सोने का क्रय करने मूल्य में निरावट से असंतुष्ट नहीं थे. उनका बिचार था कि शीघ्र ही मांग और पूर्ति का नियम सतुलन ला देगा और कदाचित्त चांदी के पक्ष में ऊंचे मूल्य की प्रवृत्ति ही ला देगा. (पूर्वोद्धृत, पृ० 118, 128-9).
- 17 बंगाली, 11 जून 1881; ब्रह्मा पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881, नोरोजी . एसेज, पृ० 514-20; इंडियन स्पेक्टेटर, 18 जुलाई (बी० ओ० आई० अगस्त 1886).
- 18 इंडियन स्पेक्टेटर, 17 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 23 जनवरी 1886); मराठा, 4 अप्रैल 1886, इंडियन स्पेक्टेटर 18 जुलाई (बी० ओ० आई०, अगस्त 1886), हिंदू, 8, 11, 15 जून, 4 सितंबर 1886. अगस्त 1886 के 'बायस आफ इंडिया' के अनुसार उस समय के भारतीय समाचारपत्र इस पर सामान्य रूप से एकमत थे

19. इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बग, 12 अगस्त 1876); इडियन स्पेक्टेटर, 17 जनवरी (वही, 23 जनवरी 1886), समय, 17 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 22 मार्च 1884); इडियन स्पेक्टेटर, 18 जुलाई (बी० ओ० आई०, अगस्त 1886); समय, 22 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 23 अक्तू० 1886). जी० बी० जोशी इस सबंध में फिर अपवाद रूप में उन्होंने रूपों के ऋण के स्थान पर स्टलिंग ऋण की नौका पकड़ने का परामर्श दिया क्योंकि स्टलिंग की ब्याज दर कम थी. उनका विश्वास था कि विनियम की गिरावट के लिए अपेक्षाकृत सस्ते धन के लाभ को निष्प्रभावित करना लगभग असंभव ही होगा (पूर्वोद्धृत, पृ० 118, 128)
20. बाबे समाचार, 3 दिसंबर 1880, 31 मार्च 1882 (आर० एन० पी० बग, 4 दिसंबर 1880, 1 अप्रैल 1882 कमल); बंगाली, 11 जून 1881; ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881. नवविभाकर, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 10 अप्रैल 1886); सहचर, 9 जून (वही, 19 जून 1886).
21. इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बग, 12 अगस्त 1876); न्याय प्रकाश, 6 दिस० (वही, 11 दिस० 1880); नवविभाकर, 12 अप्रैल, (आर० एन० पी० बग०, 22 मई 1886), हिंदुस्तान, 22 जून (आर० एन० पी० पी० एन०, 22 जून 1888); सहचर, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 18 अप्रैल 1891)
22. इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बग, 12 अगस्त 1876), ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881; मराठा, 16 मार्च 1884
23. 'मिस्टर फासेट के 'एसेज आन इडियन फाइनांस', जे० पी० एस० एच०, खंड III मक्या 1 (जुलाई 1880) पृ० 80.
24. वाचा : स्पीचेज, पृ० 375
25. वाचा . स्पीचेज, पृ० 379. मराठा, 4 सितंबर 1892; ज्ञान प्रकाश, 1 सितंबर, हिवेच्छ 1 मित० (आर० एन० पी० बग, 3 सितंबर 1892), गुजरात दर्पण, 22 सितंबर (वही, 24 सितंबर 1892), वृत्तान्त पत्रिका, 13 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्तूबर 1892); हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 1892). रहबर, 8 जुलाई (वही, 27 जुलाई 1892)
26. एम० एच० वकील दि करेमी प्राब्लम इन इडिया ऐंड सर डेविड बारबर, दि ऐंग्लो इडियन ऐंड दि रूपी (बंबई 1892), पृ० 2 (एक भारतीय लेखक द्वारा मुद्रा समस्या का कदाचित यह प्रथम विस्तृत समीक्षात्मक विश्लेषण था); मराठा, 4 सितंबर 1892; गुजरात दर्पण, 22 सितंबर (आर० एन० पी० बग, 24 सित० 1892); आर० सी० दत्त . इडियन पालिटिक्स, पृ० 51-2
27. मराठा, 4 सितंबर 1892, 12 मार्च 1893; ए० बी० पी०, 31 जुलाई 1892, 8 फरवरी 1893; बंगाली, 4 फरवरी 1893, एम० एच० वकील पूर्वोद्धृत, पृ० 2. वाचा स्पीचेज पृ० 376-8, 387-90, नौरोजी, 1893 की करेमी कमेटी में नौरोजी का बक्तव्य; पावर्टी, पृ० 560 तथा हाउस आफ बामस में दिया गया भाषण ह्माडं : चतुर्थ माला, खंड IX कालम 655-7; बंदवान सजीवनी, 14 जून (आर० एन० पी० बग०, 25 जून 1892), दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 13 जुलाई (वही, 16 जुलाई 1892), ज्ञान प्रकाश, 1 सित० (आर० एन० पी० बग, 3 सितंबर 1892), गुजरात दर्पण, 22 सितंबर (वही, 22 सितंबर 1892); बाबे समाचार, 28 अक्तूबर (वही, 29 अक्तूबर 1892) एडवोकेट, 10 जन (बी० ओ० आई०, 19 जन 1892), वृत्तान्त पत्रिका, 12 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 15 अक्तूबर 1892), हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 1892) रहबर 8 जुलाई (वही 27 जुलाई 1892), बंगाली के 18 फरवरी

- 1893 के धक में प्रस्तुत इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1892 में हाउस आफ कॉमंस को दिया गया ज्ञापन बगनिवासी, 17 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 25 फरवरी 1893); बगबासी, 18, 25 फरवरी (वही, 25 फरवरी, 4 मार्च 1893); हिमालय 10 मार्च (आर० एन० पी० पी० 18 मार्च 1893) आफताबे पंजाब, 29 मई (वही, 10 जून 1899). यही दृष्टिकोण नौरोजी 1896 में पहले ही अपने निबंधों में प्रस्तुत कर चुके हैं, एसेज, पृ० 518 और आने हिंदू ने भी 4 मिन० 1889 के धक में यही विचार प्रकट किया था
- 28 प्रस्ताव IV
- 29 भारत सरकार का भारत राज्य मन्त्रि को संप्रेषण, मध्या 160, तिथि 21 जून 1892. लार्ड एलगिन द्वारा सरकारी मुद्राधोनी के जनसमर्थन का पक्का दावा भी बराबर झूठे आधारों पर किया गया स्प्रीचेज, पृ० 51 और लार्ड कर्जन स्प्रीचेज I, पृ० 118 हाल में परसीवल स्पीयर ने भी यह गलत धारणा व्यक्त की कि (कांग्रेस के) वाणिज्य से संबंधित पश्चिमी भारतीय सदस्यों ने रुपये के विनिमय मूल्य में गिरावट को रोक न पाने के लिए सरकार की आलोचना की है ' ' इंडिया, ए माइन्स हिस्टरी (एन आर्बर, 1961 पृ० 312)
- 30 ए० बी० पी०, 29 जून, 5, 6 जुलाई 1893, बगाली, 1 जुलाई 1893, मराठा, 2 जुलाई 1893 इन्दु प्रकाश, 3 जुलाई 1893, हिंदू, 10 अगस्त, 12 मिनबर 1893, गुजराती, 2 जुलाई, बाबे समाचार, 3 अं० 1 जुलाई कैमरे हिंद, 2 जुलाई, 9 जुलाई, 20 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 8, 15, 22 जुलाई 1893 कमज), आम जन प्रियान, 8 जुलाई, केरल पत्रिका, 8 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, 15 जुलाई 1893 वृत्तान्त पत्रिका, 7 मिन० (वही, 15 मिनबर 1893) हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893), द्विवादी, 29 जन, दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 2, 5 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 8 जुलाई 1893), बगबासी, 8 जुलाई वही, 15 जुलाई 1893), हिमालय, 14 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 29 जुलाई 1893), बाहेनूर, 29 जुलाई, ताज उल अखबार, 29 जुलाई (वही, 12 अगस्त 1893 अपवाद रूप केवल सचर, 28 जून (आर० एन० पी० बग०, 8 जुलाई 1893), बग निवामी, 7 जुलाई (वही, 15 जुलाई 1893), हिंदुस्तान, 8 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893) के
- 31 आई० एन० मी०-1893 का प्रस्ताव XIV इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले और बदले में स्वर्धमान को समर्थन देने वाले एकमात्र प्रतिनिधि हिंदुस्तान समाचारपत्र के मालिक राजा रामपाल सिंह थे (रिप० आई० एन० मी०-1893, पृ० 133)
- 32 रिप० आई० एन० मी० 1893, पृ० 128, 130-1
- 33 वाचा रिप० आई० एन० मी०-1898, पृ० 98
- 34 कैमरे हिंद, 8 मई, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 मई, ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब, 14 मई 1898), कैमरे हिंद, 15 मई, गुजराती, 15 मई (वही, 21 मई 1898), तोहफा ए हिंद, 13 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 23 मार्च 1898), हिंदी प्रदीप मई और जन (वही, 11 जुलाई 1898) इसका अपवाद था — श्रवणार ए आम, 24 जन (आर० एन० पी० पी०, 9 जुलाई 1898).
- 35 नौरोजी पावर्टी पृ० 532, 545 और 'इंडिया' 20 मई 1898, पृ० 317 और 8 जुलाई 1898 पृ० 11
- 36 आर० मी० दल का 1894 सी करेसी कमेटी ने समक्ष माध्य दल स्प्रीचेज I पृ० 93
- 37 वही, पृ० 76, 82 91 3, 104 तथा 'इंडिया' म 11 नर० 1893 को पुन मुद्रित, मास्टर गार्जियन का निम्ने उनके पत्र

38. आई० एन० सी०, 1898 का प्रस्ताव XIII तथा देखिए, 1898 के कांग्रेस अध्यक्ष ए० एम० बोस की टिप्पणिया, सी० पी० ए०, पृ० 424-5
39. वाचा रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 98 तथा 99
40. नौरोजी के 27 मई 1898 'इंडिया', मे संपादक के नाम नौरोजी का पत्र, और पावर्टी, पृ० 530, 544, दत्त . स्पीचेज I पृ० 103-4 कंसरे हिंद, 15 मई (आर० एन० पी० बब, 21 मई 1898). बाद मे वाचा ने यही माग दोहराई, रिप० आई० एन० सी०, 1899 पृ० 61; और जे० ए० वाडिया दि आर्टिफिशल कंसेरी ऐंड दि कामर्स आफ इंडिया (बंबई 1902) पृ० 127
41. समिति मे केवल ऐंग्लो-इंडियन-सरकारी और गैरसरकारी ब्रिटिश पंजीपति व्यावसायिक और बैंक के हितो का प्रतिनिधित्व था और कौन गवाह होगा ? वही ऐंग्लो इंडियन सरकार और गैरसरकारी बर्ग, ब्रिटिश पंजीपतिवर्ग, व्यापारीवर्ग और बैंको से सर्वाधत वर्ग' (नौरोजी का 'इंडिया' के संपादक को पत्र, 27 मई 1898 और देखिए, केसरे हिंद, 8 मई (आर० एन० पी० बब, 8 मई 1898), गुजराती, 15 मई (वही, 21 मई 1898) आई० एन० सी०-1898 का प्रस्ताव XIII
42. हिंदू, 12 जुलाई 1890, इंडियन स्पेक्टेटर, 16 जुलाई 1899; गुजराती, 16 जुलाई, केसरे-हिंद, 16 जुलाई, (आर० एन० पी० बब, 22 जुलाई 1899), आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV. दत्त . सी० पी० ए०, पृ० 490, वाचा रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 56-61
43. राष्ट्रीय कांग्रेस 1901 का प्रस्ताव XVII.
44. आई० एन० सी० 1902 का प्रस्ताव VI तथा देखिए, आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII
45. ए० एम० बोस . सी० पी० ए० पृ० 424-5; वाचा . सी० पी० ए०, पृ० 610-1, जे० एस० अय्यर 'दि वायसराय आन दि इकोनामिक कंडीशन आफ इंडिया' एच० आर०, जून 1901, पृ० 44 और ई० ए० पृ० 43, गोखले स्पीचेज, पृ० 10-11, 14, 76-7, एम० एन० बैनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 685, जे० एम० वाडिया पूर्वोद्धृत, पृ० 95 और आगे, रिप० आई० एन० सी०, 1901 पृ० 175-7, बी० डी० ठकरसे . रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 98-9, बंगाली, 19 फरवरी 1903 फिरोजशाह मेहता ने 1900 मे जोर दते हुए यहां तक कहा : टकसालो के बद होने से वर्तमान अकाल द्वारा उत्पन्न गरीबी के दुख को सहन करने की भारतीयो की शक्ति नष्ट हो गई है इस प्रकार से टकसालो के घत ने परोक्ष रूप से गरीबी बढ़ाई है। (स्पीचेज, पृ० 604)
46. ए० बी० पी०, 1 अप्रैल 1886, हिंदू, 4 सितंबर 1889, एम० एच० वकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 2, 21-2 ज्ञान प्रकाश, 1 सित० (आर० एन० पी० बब, 3 सित० 1892); गुजरात दर्पण, 22 सितंबर (वही, 24 सित० 1892); ए० बी० पी०, 17 जुलाई 1892; बंगाली 3 सितंबर 1892, मराठा, 25 सितंबर 1892, हिंदू, 22 अगस्त 1893, वाचा, स्पीचेज, पृ० 389; वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 56; दत्त ई एच II, पृ० 578 वाचा ने 1898 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बताया कि वर्तमान मुद्रा संस्था उपयुक्त थी. 'यह वह मुद्रा थी जिसके विरुद्ध कभी किसी ने लिकायत नहीं की यह वह मुद्रा थी जो सभी प्रौढ विवेचकों की राय मे भारत के लोगों के लिए सर्वथा अनुकूल और सुविधाजनक थी तथा उनकी प्रौढिक प्रगति के लिए हर प्रकार से लाभप्रद थी' (रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 100).
47. नाहीर के 'रफीक-हिंद' ने अपने 22 फरवरी 1893 के धक में लिखा 'धार्मिक प्रवृत्तिवाले एक

व्यक्ति की यह मान्यता है कि जिस प्रकार सरकार भारतीयों के मरने आयात शुल्क में छूट देकर इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना चाहती थी, उसी प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जन्मदाता प्रभु ने उस साधन को निष्फल करने के लिए विनिमय का मवाल प्रस्तुत किया है (आर० एन० पी० पी०, 11 मार्च 1893) तथा ए० बी० पी०, 17 जुलाई, 11 सितंबर 1892; ज्ञान प्रकाश, 1 सितंबर (आर० एन० पी० बग०, 3 सित० 1892), गुजरात दपण, 22 सितंबर (वही, 24 सितंबर 1892), बगवामी, 25 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 मार्च 1893), हिंदू, 5 जुलाई 1895, राय पावर्टी, पृ० 129-30 आर० सी० दत्त का भी मत था कि निम्न विनिमय भारत के उद्योगों के अनुकूल था (ई एच II, पृ० 584). वस्तुतः 13 फरवरी 1879 में ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन ने अपना मत प्रकट किया था कि लकाशायर के भारत में निर्यात में ह्रास का वास्तविक कारण विनिमय में गिरावट थी इसके मुकाबले कपास शुल्क के हटाने से मिला लाभ नगण्य ही था

- 48 ज० ए० वाडिया ने भी एक निम्न सदर्थ में 1901 में इसी तत्व की ओर संकेत किया
- 49 राय पावर्टी, पृ० 129-31
- 50 दत्त ई एच II, पृ० 578 तथा देखिए, पश्चिमी भारत की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का 1892 में प्रस्तुत स्मरणपत्र इंडियन बरेमी कमेटी (साध्य की कार्यवाही और परिशिष्ट) 1893 परि० III पृ० 338
- 51 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 626-7, 640 नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 322, नवविभाकर साधारणी, 9 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 14 अगस्त 1886)
- 52 नौरोजी स्पीचेज, पृ० 322 3, हिंदू 10 अप्रैल 1885, गुजरात दपण, 22 सितंबर (आर० एन० पी० बग०, 24 सित० 1892), दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 18 अक्टूबर (आर० एन० पी० बग०, 22 अक्टूबर 1892) बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101-02 बगवामी ने 1893 के बरेमी ऐक्ट में एकमात्र अच्छाई यह देखी कि इससे अनाज का निर्यात घट जाएगा (आर० एन० पी० बग० 2 सितंबर 1893) तथा दोस्ते हिंद, 4 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 19 अगस्त 1893)
- 53 जोशी . पूर्वोद्धृत, पृ० 626-7, नवविभाकर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 30 जनवरी 1886), नवविभाकर साधारणी, 9 अगस्त (वही, 14 अगस्त 1886), मराठा, 9 अक्टूबर 1892; बाबा रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101-02
- 54 बगवामी, 11 जून 1881, 3 सितंबर 1892, ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1891, नौरोजी एसेज, पृ० 514-5 सी० बी० ए०, पृ० 177, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 640, मराठा, 4 सितंबर, 9 अक्टूबर, 4 दिस० 1892, 12 मार्च 1893, राय पावर्टी पृ० 333; हिंदू, 5 और 8 जुलाई 1895, बाबा, स्पीचेज, पृ० 379-80 रिप० आई० एन० सी०, 1899, पृ० 101-02
- 55 नौरोजी एसेज, पृ० 515-6 तथा पृ० 374
- 56 आई० एन० सी० क्रमश 1898 और 1899 का प्रस्ताव XIII और IV, नौरोजी, एसेज, पृ० 514-7, पावर्टी, पृ० 543-4, 560, 562; एम० एच० बकील पूर्वोद्धृत, पृ० 31; बाबा, स्पीचेज, पृ० 381-2, परिशिष्ट, पृ० 12; रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 97-105; दत्त, स्पीचेज I, पृ० 93, ई एच II, पृ० 578, 585-7; बर्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का स्मरणपत्र, दिनांक 27 अगस्त 1886 सेकंड एनुअल रिपोर्ट आफ दि बर्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1886-7, पृ० 41-2; ए० बी० पी०, 1 अप्रैल 1886, 27 मार्च, 17 जुलाई 1892, 9 अप्रैल 1893,

- 13 फरवरी 1894, 29 सित० 1898; मराठा, 31 जुलाई, 9 अक्तू०, 4 दिस० 1892, 12 मार्च 1893; बंगाली, 4 फरवरी 1893, 28 जून 1898, हिंदू, 10 अप्रैल 1885, 8, 15 जून 1886 22 अगस्त 1893, 5, 8 जुलाई 1895; इंडियन स्पेक्टेटर, 18 जुलाई (बी० ओ० आई० अगस्त 1886); बिहार हेराल्ड, 18 फरवरी (बही, 18 मार्च 1894) पैसा अखबार, 6 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 16 जुलाई 1898) एम० एन० बैंनर्जी ने 1879 और 1881 में ही (यद्यपि बोझा अस्पष्ट रूप से) यह विश्लेषण प्रस्तुत किया था देखिए, एस० एन० बैंनर्जी स्पीचेज I, पृ० 198 और बंगाली, 11 जून 1881. अपने तर्कों की पुष्टि म दादाभाई नौरोजी ने 1898 में इंडियन करेंसी कमेटी को भेजे गए प्रतिवेदन में राज्य सचिव द्वारा 26 जनवरी 1886 को कोषागार को लिखा पत्र उद्धृत किया 'यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार को इस्लैंड को स्वर्ण मुद्रा के रूप में जो अनिवार्य भुगतान करने पड़ते हैं, उनके फलस्वरूप ही रुपये के विनिमय मूल्य में आई गिरावट से सरकारी वित्त प्रभावित हो रहे हैं' (पावर्टी, पृ० 543)
57. लायब ए० मिट्जलर, 'दि थ्योरी आफ इटरनेशनल ट्रेड', ए सर्वे आफ वाटंपररी इकोनामिक्स, हाबर्ड एस० एलिस द्वारा संपादित (फिलिपाइन, 1948) पृ० 221
58. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 529, 531, 554-55, एसेज, पृ० 512, 516-7 और 'इंडिया' 20 मई 1888, पृ० 317; ए० बी० पी०, 1 अप्रैल 1886 10 जुलाई 1892, हिंदू 11 जून 1889, 5 जुलाई 1895 इस सचब में अमृत बाजार पत्रिका ने 17 जुलाई 1892 के ग्रक में बड़ा ही साफ-सुथरा तथ्य प्रस्तुत किया उसने लिखा रुपये के अवमूल्यन का परिणाम मामान्यतया निर्यात में वृद्धि होती और उसके फलस्वरूप चादी के आयात बढ़ जाते इसका परिणाम यह होता कि भारत में चादी के मूल्य और ऊंचे बढ़ जाते ताकि चादी के मूल्य में भारत में और बाहर के देशों में समान रूप से अवमूल्यन हो जाता परंतु यहा यह आर्थिक तथ्य और श्रुतना विच्छिन्न हो गई है इसका कारण यह है कि धन की निकासी न भारत के आंतरिक आयात व निर्यात लिया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के निर्यातों के मूल्य गिर गए हैं और इससे देश को हालि पहुँची है
59. एम० एन० बैंनर्जी स्पीचेज I पृ०, 198 ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881 वाचा, स्पीचेज, पृ० 381; ए० बी० पी०, 8 फरवरी 1893
60. बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन 1898 की रपट, पृ० 90.
61. वाचा : स्पीचेज, पृ० 381; जी० एस० डायर, ई ए, पृ० 357
62. नौरोजी : एसेज, पृ० 517, और पावर्टी, पृ० 543-4; मराठा, 31 जुलाई 1892, बंगाली, 28 जून 1898 कैसरे हिंद, 15 मई (आर० एन० पी० नव, 21 मई 1898)
63. वाचा . रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 101-02 तथा नौरोजी, एसेज, पृ० 516-7 और पावर्टी, पृ० 545-6, 576 बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का स्मरणपत्र, तिथि 27 अगस्त 1886, पूर्वोक्त स्थल; वाचा, रिप० आई० एन० सी०-1892, पृ० 84 और रिप० आई० एन० सी०-1898, पृ० 101-04, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 93, 97-8 इंडिया, 11 नवंबर, 4 दिस० 1898, पृ० 262, ई एच II, पृ० 582, 585, ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 1881, मराठा, 31 जुलाई, 28 अगस्त, 4 सितंबर और 9 अक्तू० 1892 तथा 12 मार्च 1893 ए० बी० पी०, 27 मार्च 1892, 8 फरवरी 1893, 13 फरवरी, 10 मार्च 1894, 29 सित० 1898, हिंदू 21 मई 1894, 8 जुलाई 1895, इंडियन एसोसिएशन की हाउस आफ कामस को याचिका, 25 फरवरी 1893 के बंगाली में, इंडियन स्पेक्टेटर, 18 जुलाई (बी० ओ० आई०, अगस्त 1886 पृ० 392),

- हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 1892), बिहार हेराल्ड, 18 फरवरी (बी० बी० आई०, 18 मार्च 1894 पृ० 216), ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब, 14 मई 1898), कंसरे-हिंद, 15 मई (वही, 21 मई 1898)
- 64 दत्त स्पीचेज I, पृ० 93 तथा नौरोजी, पावर्टी, पृ० 545, 575-6, बाबा रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 104, हिंदुस्तानी, 24 अगस्त 1892, 8 फरवरी 1893 (आर० एन० पी० एन०, 31 अगस्त 1892, 15 फरवरी 1893 क्रमशः) 1893 में इंडियन एसोसिएशन की हाउस आफ कामस को याचिका 25 फरवरी 1893 के बंगाली में, ए० बी० पी० 13 फरवरी 1894, ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब, 14 मई 1898), कंसरे हिंद, 16 जुलाई (वही, 22 जुलाई 1899) दत्त, इंडिया, 11 नवंबर 1898 पृ० 262
- 65 ज्ञान प्रकाश, 1 सितंबर, हिंदुस्तानी, 1 सित० (आर० एन० पी० बब, 3 सितंबर 1892); 1893 में इंडियन एसोसिएशन का हाउस आफ कामस को ज्ञापन, 25 फरवरी 1893 के बंगाली में, ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब, 14 मई 1898), नोहफ ए हिंद, 13 मार्च (आर० एन० पी० एन, 23 मार्च 1898)
- 66 आई० एन० सी०-1898 का प्रस्ताव XIII नौरोजी पावर्टी, पृ० 575
- 67 अमृत बाजार पत्रिका में 17 जुलाई 1892 के एक मलिका विनिमय की कठिनाई एक प्राकृतिक चेष्टा है भारत को प्राकृतिक स्वस्थ स्थिति में लाना भले ही कठिन हो, यह संपत्ति की अप्राकृतिक निकासी के, प्रति विरोध है जिसका नकार भारत को बनाया जा रहा है तथा देखिए, ए० बी० पी० 1 अप्रैल 1886 हिंदुस्तानी, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 31 अगस्त 1892) बंगाली, 4 फरवरी 1893, नौरोजी सी० पी० ए०, पृ० 177
- 68 ए० बी० पी० 17 जुलाई 1892, बंगाली, 3 सितंबर 1892
- 69 बाबा स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 31, 42 ए० पी० ए० पृ० 617, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 71-5, 103 ई एच II, पृ० 578
- 70 ए० बी० पी० 9 अप्रैल 1893, 15 मार्च 1894, कंसरे हिंद, इंडियन स्पेक्टर, 11 मार्च, इंदु प्रकाश, 12 मार्च (आर० एन० पी० बब, 17 मार्च 1894), पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 445-6, पावर्टी, पृ० 281-2, ए० एन० बैंडर्जी सी० पी० ए०, पृ० 243-5, बाबा, स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 6, 16-19 रिप० आई० एन० सी०-1892 पृ० 84, रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101-02 सी० पी० ए०, पृ० 617 नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 128-30, दत्त स्पीचेज I पृ० 103 ई एच II, पृ० 583 तथा आई० एन० सी०-1895 का प्रस्ताव III
- 71 हिंदुस्तानी, 1 सित० (आर० एन० पी० बब, 3 सित० 1892), इंडियन एसोसिएशन का हाउस आफ कामस को 1893 में प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 25 फरवरी 1893 के एक में प्रकाशित, ए० बी० पी०, 9 अप्रैल 1893, 29 सितंबर 1898, बंगाली, 1 जुलाई 1893, बिहार हेराल्ड, 18 फरवरी (बी० बी० आई०, 18 मार्च 1894) नौरोजी पावर्टी, पृ० 539-40, 544, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 93, 103, 104 कंसरे हिंद, 15 मई 1898, 16 जुलाई 1899 (आर० एन० पी० बब, 21 मई 1898, 22 जुलाई 1899 क्रमशः)
- 72 बाबा रिप० आई० एन० सी०, 1898 पृ० 102-04 तथा रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 132-3 स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 9, 31, 41 43 सी० पी० ए०-पृ० 617
73. 1893 में हाउस आफ कामस को इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 25 फरवरी 1893 के एक में प्रकाशित

74. नौरोजी : सी० पी० ए०, पृ० 177.
75. आई० एन० सी०-1893 का प्रस्ताव XIV तथा आई० एन० सी०-1901 का प्रस्ताव XVII.
76. एम० एच० बकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 4, 19; मराठा, 9 अक्तूबर 1892, 2 जुलाई 1893. कंसरे हिंद, 9 जुलाई (भार० एन० पी० बब, 15 जुलाई 1893); ए० बी० पी० 29 सितंबर 1898; बाबा : स्पीचेज, पृ० 389-90, सी० पी० ए०, पृ० 611, 614; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 362, 574-5, 604; जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०-1898, पृ० 106-07, एच० भार०, जून 1901, पृ० 441, ई ए पृ० 120-1. रिप० आई० एन० सी०-1904, पृ० 175; दत्त, स्पीचेज I, पृ० 70, 76-7; ई एच II, पृ० 458, 579-80, 596, 598; इंडिया, 11 नव० 1898; जे० ए० बाडिया, पूर्वोद्धृत, पृ० 95, 129; गोखले, स्पीचेज, पृ० 14, 75-77; बी० डी० ठाकरसी, रिप० आई० एन० सी०-1902 पृ० 99; केसरी, 31 मार्च (भार० एन० पी० बब; 4 अप्रैल 1903). बस्तुतः 1893 की मुद्रा समिति ने इस तर्क की सार्थकता को स्वीकार किया था और लिखा था : हम यह मानकर चल रहे हैं कि वर्तमान अनुपात अथवा अनुपात कर का कुछ अंतर बना रहेगा; ऐसा मानने के मुताबिक रुपये के मूल्यों के वर्तमान स्तर में एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आएगा.
77. नौरोजी, पावर्टी, 531 तथा वही, पृ० 529, 533-6, 545, 561-2; इंडिया, 20 मई 1898, पृ० 317 और इंडिया, 8 जुलाई 1898, पृ० 11.
78. नौरोजी पावर्टी, पृ० 535, 537, 543, 557-8; ए० बी० पी०, 29 सित० 1898; जे० ए० बाडिया, रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 176. जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 100 और रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 175, और ई ए पृ० 10; दत्त, ई एच II, पृ० 585-6 तुलनीय रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेंसी कमेटी, 1893 कंडिका 112.
79. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 545 तथा एम० एच० बकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 5-6; मराठा, 9 अक्तूबर 1892.
80. बाबा : सी० पी० ए०, पृ० 610.
81. आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII, दत्त : ई एच II, पृ० 596, गोखले, स्पीचेज पृ० 75, 77. रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 164-5, 168; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 604; जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 41-3.
82. गोखले, स्पीचेज, पृ० 76. 1902 के कांग्रेस अधिवेशन में इसी प्रकार का प्रश्न बी० डी० ठाकरसी ने उठाया (रिप० आई० एन० सी०-1902, पृ० 99).
83. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 530
84. एम० एच० बकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 19; नौरोजी, पावर्टी, पृ० 529, 531, 560-2, सी० पी० ए०, पृ० 176, इंडिया, 20 मई 1898, पृ० 317; मराठा, 4 सितंबर, 9 अक्तू० 1892; बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 610. स्पीचेज, पृ० 382, जे० ए० बाडिया : पूर्वोद्धृत, पृ० 65, बी० डी० ठाकरसी, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 99; जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 175.
85. इंडियन करेंसी कमेटी, मिनट्स आफ एविडेंस ऐंड एपेंडिक्स-1893 सी- 7060 II, प्रश्न 2353-4.
86. वही, प्रश्न 2371
87. वही, प्रश्न 2355-9.
88. वही, प्रश्न 2391.

89. मराठा, 9 अक्तूबर 1892; एम० एच० बकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 4; नौरोजी, पावर्टी, पृ० 536; दत्त, स्पीचेज I, पृ० 88-90, इंडिया, 11 नवंबर 1898, पृ० 262, ई एच II, पृ० 581.
90. वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 614. मराठा, 9 अक्तूबर 1892. वाचा, स्पीचेज, पृ० 390. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 561-3, एम० एच० बकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 4-7
91. वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 131.
92. आई० एन० सी०, 1899 का प्रस्ताव IV तथा आई० एन० सी० 1893 और 1899 के प्रस्ताव क्रमशः XIV और XVII.
93. 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामंस में प्रस्तुत याचिका बंगाली के 18 फरवरी 1893 में प्रकाशित. बंगबासी, 26 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 2 सितंबर 1893); इंडियन स्वेक्टेडर, 8 मई 1898 कैंसरे हिंदू, 15 मई (आर० एन० पी० बग, 21 मई 1898); आई० एन० सी० 1898 का प्रस्ताव XIII वाचा ने शिकायत की कि भारत का व्यापार भी सामान्यतः अस्त-व्यस्त हो गया है (रिप० आई० एन० सी०-1893, पृ० 131).
94. 'बर्बई समाचार', 27 जून, 3, 4 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 1 जुलाई, 8 जुलाई 1893); जामे जमशेद, 27, 29 जून, 1 जुलाई (वही, 1 जुलाई 1893), कैंसरे हिंदू, 2 जुलाई, इंडु प्रकाश, 3 जुलाई (वही, 8 जुलाई 1893), गुजरात दर्पण, 12 अक्तूबर (वही, 14 अक्तूबर 1893), 1393 न इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामंस को प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 18 फरवरी 1893 के क्रम में प्रकाशित ए० बी० पी०, 23 जुलाई 1893, मराठा, 2 जुलाई 1893; हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893), दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 2 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 8 जुलाई 1893), बंगबासी, 26 अगस्त (वही, 2 सितंबर 1893), बंगाली, 3 फरवरी 1894 28 जून 1898, वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1893 पृ० 130 सी० पी० ए०, पृ० 612, राय, पावर्टी, पृ० 11 जे० यू० याज्ञिक प्रेसिडेंशियल ऐंड्रेस ऐट दि सैवथ प्राविशन काफम (सातवें प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण) जे० पी० एम० एस०, जनवरी 1895 (खंड VIII सं० 3) पृ० 5, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 91, जे० ए० वाडिया रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 177.
95. वाचा ने निर्देश किया कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के अधिकांश का उपभोग चीन और जापान द्वारा किया जाता है (रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 130)
96. पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 362, बर्बई समाचार, 4 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 8 जुलाई 1893), हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893), बंगाली, 3 फरवरी 1894, 28 जून 1898, राय, पावर्टी पृ० 11; याज्ञिक, अध्यक्षीय भाषण, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 4, वाचा : रिप० आई० एन० सी०-1893, पृ० 130-1 रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 98, सी० पी० ए०, पृ० 612-4
97. गोखले : स्पीचेज, पृ० 10 तथा देखिए पृ० 11.
98. रिप० आई० एन० सी०-1904 पृ० 174.
99. रिप० आई० एन० सी०-1902, पृ० 99 अहमदाबाद के एक अन्य मिल-अधिकर्ता सोराबजी कड़ाका ने उनका समर्थन करते हुए बड़तापूर्वक कहा कि मुद्रा कानून ने देश के कारखाना उद्योग की अक्षरशः हत्या की है (वही, पृ० 101).
100. देखिए, परिमल राय : पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 177-208. राय तथा कुछ दूसरों जैसे एलमिन (स्पीचेज, पृ० 489-90) और कर्जन (स्पीचेज III, पृ० 135), ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि

भारत का 80 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक व्यापार स्वर्णमान वाले देशों के साथ था और रुपये के स्वर्णमान से स्थिर सबंध होने पर भारत को लाभ पहुंचना निश्चित था। जैसा हम बार बार दोहरा चुके हैं, भारतीय नेता तो समग्र विदेश व्यापार की चिंता अथवा उससे सबंध ही नहीं रखते थे, उन्होंने तो अपने दृष्टिकोण को एक सीमित क्षेत्र तक ही संकुचित कर लिया जिसके अनुसार उनके प्रयत्नों का प्रत्यक्ष सबंध देश के उद्योगीकरण से ही था

101. बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 613-4 तथा देखिए मराठा, 12 जुलाई 1903
102. 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत जापन बंगाली के 18 फरवरी 1893 के अंक में प्रकाशित, बंगाली, 3 फरवरी 1894, आई० एन० सी०-1901 का प्रस्ताव XVII, बाबा, सी० पी० ए० पृ० 612
103. कांग्रेस के आठवें अधिवेशन में कैप्टन बैनन ने मुद्रा प्रस्ताव का ममर्शन किया (रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 64).
104. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 562, बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 100-01
105. मराठा, 4 सितंबर 1892, और 2 जुलाई 1893, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आफ वेस्टर्न इंडिया द्वारा 1892 में प्रस्तुत स्मरणपत्र, पूर्वोक्त स्थल, नवई समाचार 27 जून (आर० एन० पी० बब, 1 जुलाई 1893), बाबा रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101-02, आर० पी० करदीकर, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 132-3, नौरोजी, इंडिया, 20 मई 1898, पृ० 317, दत्त, इंडिया, 11 नवंबर 1898, पृ० 261-2, सी० पी० ए०, पृ० 490, पी० ए० चारनू, एल० सी० पी० 1898 खंड XXXIV पृ० 502-03 आई० एन० सी० 1899 और 1901 के प्रस्ताव IV और XVII, क्रमशः, मोखले, स्पीचेज, पृ० 14-5 75, 111, एम० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 685, बी० डी० ठाकरसी, रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 98 बंगाली, 10 फरवरी 1903
106. 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस का प्रस्तुत याचिका बंगाली के 18 फरवरी 1893 के अंक में प्रकाशित, मराठा, 2 जुलाई 1893, ए० बी० पी०, 5, 6 जुलाई 1893, 19 सितंबर 1898, हितवादी, 29 जून, दैनिक जो समाचार चन्द्रिका, 5 जुलाई (आर० एन० पी० बब०, 8 जुलाई 1893); हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893); तोहफा ए हिंद, 13 मार्च, (वही, 23 मार्च 1898), हिंदी प्रदीप, मई-जून (वही, 13 जुलाई 1898), प्रखवारे नाम के 17, 24 अगस्त के अंकों में एक पत्र (आर० एन० पी० पी०, 11 सितंबर 1897); पैंसा बख्शवार, 30 अप्रैल, 2 मई (वही, 14 मई 1898), इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब, 14 अक्टू० 1899); दत्त, स्पीचेज I, पृ० 85-8 इंडिया, 11 नवंबर 1898, पृ० 261, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 52, सी० पी० ए०, पृ० 490, हिंदू, 12 जुलाई 1899, आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV, बाबा : सी० पी० ए०, पृ० 615; जी० एस० अय्यर दि बायसराय आन दि इकोनामिक कडीशन आफ इंडिया, एच० आर० जून 1901, पृ० 441; मोखले, स्पीचेज, पृ० 14, 111 रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 163-4. ए० एस० देसाई रिप० आई० एन० सी०, 1904, पृ० 174.
107. दत्त . स्पीचेज I, पृ० 86.
108. मोखले : स्पीचेज, पृ० 14
109. ए० बी० पी०, 19 सित० 1898 तथा वही, 6 जुलाई 1893; मराठा, 2 जुलाई 1893.
110. स्पीचेज I, पृ० 81 तथा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आफ वेस्टर्न इंडिया का स्मरणपत्र, पूर्वोक्त

स्थल; इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1893 में हाउस आफ कामंस को प्रस्तुत याचिका; बंगाली के 18 फरवरी 1893 के प्रक में प्रकाशित; मराठा, 12 मार्च 1893; हिंदू, 28 जून 1893, 12 जुलाई 1899, ए० बी० पी०, 26 जुलाई 1893, नौरोजी पावर्टी, पृ० 531-2; दत्त : स्पीचेज I, पृ० 81-5, इंडिया 11 नवंबर 1898, पृ० 261-2 सी० पी० ए०, पृ० 490; जी० एस० मय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 107 एच० आर०, जून 1901, पृ० 441; आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव IV, वाचा स्पीचेज, पृ० 390, रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 60-1, सी० पी० ए०, पृ० 614, गोखले, स्पीचेज, पृ० 14, 111; ए० एस० देसाई, रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 174

111 नौरोजी, एमज, पृ० 520, इंडिया, 20 मई 1898 पृ० 317, 8 जुलाई 1898 पृ० 11, 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामंस को प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 18 फरवरी 1893 के प्रक में प्रकाशित, मराठा, 12 मार्च, 2 जुलाई 1893; ए० बी० पी०, 23 जुलाई 1893, 19, 20 सितंबर 1898, कैसरे हिंद, 9 जुलाई (आर० एन० पी० बब०, 15 जुलाई 1893), हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893); बगवासी, 8 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 15 जुलाई 1893) आर० पी० करदीकर, रिप० आई० एन० सी०-1893 पृ० 132-3, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 77-9, 85, बगवासी, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 5 फरवरी 1898), सी० पी० ए० मय्यर रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 107, हिंदू, 12 जुलाई 1899; आई० एन० सी०-1899 का प्रस्ताव IV, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 60 सी० पी० ए०, पृ० 614, स्पीचेज, पृ० 389, गोखले, स्पीचेज, पृ० 14, 75, 111, बी० डी० ठाकरसी, रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 174

112 वाचा, स्पीचेज पृ० 389, 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामंस को प्रस्तुत याचिका बंगाली के 18 फरवरी 1893 के प्रक में प्रकाशित, ए० बी० पी०, 23 जुलाई 1893, हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 11 जुलाई 1893); दत्त, स्पीचेज I, पृ० 80. इंडिया, 11 नवंबर 1898, पृ० 261, आई० एन० सी०-1899 का प्रस्ताव IV.

113 बर्बर समाचार, 27 जून (आर० एन० पी० बब०, 1 जुलाई 1893), मराठा, 2 जुलाई 1893, रहवर, 8 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 27 जुलाई 1892), हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (बही, 11 जुलाई 1893). हिमालय, 14 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 29 जुलाई 1893) नौरोजी, पावर्टी, पृ० 534, इंडिया 20 मई 1898, पृ० 317. हिंदी प्रदीप, मई, जून (आर० एन० पी० एन०, 13 जुलाई 1898), वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101. हिंदू, 12 जुलाई 1899, बंगाली, 19 फरवरी 1903.

114. जी० एस० मय्यर, ई ए, पृ० 121 तथा एम० एच० बकील पूर्वोद्धृत, पृ० 6-7, वाचा, स्पीचेज, पृ० 390, रिप० आई० एन० सी०-1893, पृ० 130, रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 101 रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 56, हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 1892); 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामंस को प्रस्तुत याचिका; बंगाली के 25 फरवरी 1893 के प्रक में प्रकाशित, ए० बी० पी०, 29 जून 1893; मराठा, 2 जुलाई 1893. आर्यजनप्रियन, 8 जुलाई, केरल पत्रिका, 8 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, 15 जुलाई 1893); नौरोजी, पावर्टी, पृ० 534, 561 इंडिया, 20 मई 1898, पृ० 317; जे० ए० वाडिया, पूर्वोद्धृत, पृ० 96 दत्त, स्पीचेज I, पृ० 89-90.

115 कैसरे हिंद, 27 अगस्त (आर० एन० पी० बब०, 2 सितंबर 1893) तथा नौरोजी, पावर्टी,

- पृ० 534, 547, 561; बंगबासी, 8 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 15 जुलाई 1893); दत्त, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 52; जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी०-1898 पृ० 107, ई ए, पृ० 120, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 56, बंगाली, 19 फरवरी 1903.
116. जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 120-1 हिंदू, 12 जुलाई 1899. वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 58-9; बंगाली, 19 फरवरी, 1903.
117. वकील और मुराजिन : पूर्वोद्धृत, पृ० 321-3 और परिमल राय : पूर्वोद्धृत, पृ० 203
118. दत्त : स्पीचेज I, पृ० 79-80, 89-90.
119. गोखले : स्पीचेज, पृ० 14 तथा पृ० 75 कुछ वर्षों के उपरांत 1908 में गोखले ने इस समस्या पर विस्तार से विचार किया : सच कहा जाए तो सरकार के मुद्रा कानून से रुपये की नकली वृद्धि का परिणाम तभी निकलेगा जब नए आधार पर वस्तुएं व्यवस्थित हो जाएंगी, तब देश में कीमतों में सामान्य गिरावट आएगी. चांदी के सिक्के गढ़ने वाली टंकालों के बंद होने के बाद के प्रथम कई वर्षों में उसका परिणाम अकाली की निरंतरता से अभाव की स्थिति की व्यापकता से और कदाचित्त जोड़े हुए रुपये के परिचलन से नकारात्मक हो गया है इसके अतिरिक्त सारे विश्व में उपभोग वस्तुओं के स्वर्ण मूल्य में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति ने भी निस्संदेह भारत में मूल्यवृद्धि में सहायता दी है. 'हमारे सिक्का विशेषज्ञ ने परीक्षा करके इस समस्या पर कुछ प्रकाश डाला है. विशेषज्ञ मिस्टर हरोसन के अनुसार 1898 से पहले बने रुपये का भंडार 130 करोड़ के लगभग का है. इस दस वर्ष की अवधि में सरकार ने विशुद्ध रूप में इस भंडार में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की है. मेरा विचार है कि देश की मुद्रा के इतने आकस्मिक प्रसार का परिणाम मूल्यों में सामान्य वृद्धि ही है' (स्पीचेज, पृ० 177-9)
120. वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 615-6
121. यदि हम फोर्लर कमिशन द्वारा (भले ही) सकोचपूर्वक अभिव्यक्त विरोधी मान्यता को देखें तो यह अकालप्रौढ़ता वस्तुतः बिस्मयजनक ही लगती है. देखिए, इंडियन करेंसी कमिटी-1898 का प्रतिवेदन, कड़िका 58. बंगाली द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण को बालातर में जे० एम० केंसन पुष्ट किया (पूर्वोद्धृत पृ० 6) एक अन्य भारतीय लेखक रणछोड़ लाल छोटेलाल ने जो हालांकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता नहीं थे (वह अहमदाबाद की एक मिल के स्वामी थे और बंबई विधानपरिषद के सदस्य थे), 1894 में सरकार में अपने आप रुपये गढ़ने की अपील इस आधार पर की कि जब एक बार भारत रजतमान से हट गया तो रुपये मुद्रा का संकेत गलत बनकर रह जाता है. उस स्थिति में भारत और इंग्लैंड के बीच विनिमय दर की ऊच-नीच पर रुपये की अधिकता और अभाव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता अतः इंग्लैंड के लिए भारत के व्यापार सतुलन पर निर्भरता की दृष्टि से कोई चिंता की बात नहीं इसके विपरीत इन स्थितियों में रुपये की कमी उद्योगों और कृषि को और उसके फलस्वरूप देश के निर्यात को क्षति पहुंचाती हुई रुपये के मूल्य को और भी नीचे की ओर से जाएगी (सेटर्स जान करेंसी, बंबई 1895).
122. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 532-4 और 'इंडिया' 8 जुलाई 1898, पृ० 10-11.
123. नोरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 177. पावर्टी, पृ० 560. इंडियन करेंसी कमिटी, साध्य की कार्य-वाही और परिशिष्ट—1893 सी०-7060 II, प्रश्न 2346-7; बंगाली 11 जून, 1881, हिंदू, 22 अगस्त 1893.
124. आई० एन० सी० 1892 का प्रस्ताव IV, दत्त, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 51-2, स्पीचेज I, पृ० 91.

125. 1893 के मुद्रा अधिनियम के कानून बन जाने पर 'मराठा' ने 2 जुलाई 1893 के प्रंक में पुनः बल-पूर्वक कहा कि इस देश की जनता के हितों पर ध्यान दिए बिना ही बिल पास कर दिया गया है। विश्व के किसी भी देश में मुद्रा संबंधी यह द्रुत परिवर्तन और वह भी इतनी आसानी से सांगु करना कदाचित् असंभव ही होता।
126. दत्त, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 52 तथा देखिए, उनकी स्पीचेज I, पृ० 86.
127. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 542 और 547.
128. होम (पब्लिक) नव० 1893 प्राग 315 (ए) कड़िका-1.
129. फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1896-7 कड़िका-104; वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 33.
130. आर० एन० पी० बब, 2 सितंबर 1893.
131. ए० बी० पी०, 22 अगस्त 1893, हिंदू, 25 अगस्त 1893, 18 अप्रैल 1894, 16 जून 1899; बंगाली, 18 नवंबर 1893, 10 फरवरी, 10 मार्च, 7 अप्रैल 1894, मराठा, 27 अगस्त 1893, 21 जनवरी 1894, इंडियन स्पेक्टेटर, 27 अगस्त 1893, इंदु प्रकाश. 25 सितंबर 1893, आर० एन० पी० बब, 2 सितंबर, 30 सित० 1893 में उद्धृत समाचारपत्र, आर० एन० पी० बग०; 2, 9, 23 सितंबर 1893 तथा आर० एन० पी० एम०, 15 सित० 1893 में उद्धृत समाचारपत्र.
132. रिपोर्ट आफ दि इंडियन एमोमिशन 1829-3 से 1895-6, पृ० 34, और जे० पी० एम० एस०, जनवरी 1894 (खंड XVI सं० 3) पृ० 60
133. आई० एन० सी० 1893 का प्रस्ताव XV
134. प्रस्ताव XVI (1894), XVI (1895), XI (1896), IV (1897), XX (1898), XIV (1899), X (1900), XIX (1901), XIX (1902), और XIII (1903).
135. रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 133-5.
136. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 344 और पृ० 143, 462 सी० पी० ए०, पृ० 176. देखिए, ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 143; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 200, 219; वाचा, स्पीचेज-परिशिष्ट, पृ० 17, 31; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1190; दत्त, ई एच II, पृ० 578
137. आई० एन० सी० के 1893 और 1894 के प्रस्ताव क्रमशः XV और XVI, 1893 में इंडियन एसोमिशन द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35 1893 में पूना सार्वजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1894 (खंड XVI सं० 3), पृ० 60, इंडियन स्पेक्टेटर, 27 अगस्त 1893, मराठा, 27 अगस्त 1893, कैमरे हिंद, 2 जून (आर० एन० पी० बब; 8 जून 1895); वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 17, 30, एम० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 262, 701-02, ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 140-1
138. जी० बी० जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 200 तथा देखिए, वही, पृ० 199, 219; नोरोजी, एसेज, पृ० 517, स्पीचेज, पृ० 144; गुजरात दर्पण, 31 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 2 सितंबर 1893), पूना सार्वजनिक सभा द्वारा 1893 में प्रस्तुत स्मरणपत्र—पूर्वोक्त स्थल, पृ० 63-4, ए० बी० पी०, 22 अगस्त 1893; बंगाली, 81 नवंबर 1893; स्वदेशमित्र, 25 अगस्त आर० एन० पी० एम० 15 सितंबर 1893), वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 129, ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी०—1895, पृ० 143; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1190; जमी उल उलुम, 28 मई

(आर० एन० पी० एन०, 2 जून 1897); जी० एस० अय्यर, विलबी आयोग, खंड III, प्र० 19027.

139. रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 135. 1895 के कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल से आए एक अन्य प्रतिनिधि 'गुरेज चंद्र राय' ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए (रिप० आई० एन० सी०—1895, पृ० 145).

139-A. 28 मई 1897 (आर० एन० पी० एन०, 2 जून 1897).

140. नौरोजी, एसेज, पृ० 516. एम० एच० वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 12, 31-2, मराठा, 25 सितंबर 1892, 12 फरवरी 1893; गुजरात दर्पण, 22 सितंबर (आर० एन० पी० बंब, 24 सित० 1892); 1893 में प्रस्तुत इंडियन एसोसिएशन की याचिका, बंगाली, के 25 फरवरी 1893 के अंक में प्रकाशित, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 137 स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 17, 30. कैसरे हिंद, 2 जून (आर० एन० पी० बंब, 8 जून 1895). एम० एच० वकील (पृ० 32-6). कैसरे हिंद का विचार था कि यदि मावधानी से हिमाचल लगाया जाए तो वदाचित्त सभानों अधिकारी लाभ में ही रहे हैं.

141. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1190 तथा जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 219, ए० बी० पी०, 27 मार्च 1892, 11 फरवरी और 22 अगस्त 1893, मराठा, 25 सित० 1892; 1893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका, बंगाली के 25 फरवरी 1893 के अंक में प्रकाशित, पी० एस० एम० का स्मरणपत्र, जे० पी० एम० एम०, जनवरी 1894 (खंड XVI स० 3) पृ० 64; गुजरात दर्पण, 31 अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 2 सित० 1903), हिन्दवादी 25 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 2 सित० 1893), वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 130, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 30; एम० एन० बैंतर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 263, पी० सी० राय, वही, पृ० 145, ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 141 जी० एस० अय्यर; विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 19027, जमी उल उल्म, 28 मई (आर० एन० पी० एन०, 2 जून 1893). अंगरेज अधिकारियों द्वारा अपनाए गए रख से यह टांटकाण कितना भिन्न था, इन अधिकारियों की दुष्प्रवृत्ति के सजीव तथा मंचित रूप को निर्मूलनिष्ठन म म कमी एक के द्वारा देखा जा सकता है. जनरल चिमनो न 1894 में अपनी 'इंडियन पोलिट्री' (पृ० 336-9) में लिखा यदि मनुष्य केवल चावल पर जीवित रहता और मादा मा रूपाडा पहु-नता तो रुपये की गिरावट के घाटे को वह सह सकता था परिणाम यह है कि भारत के वनिष्ट मिलिट्री अथवा मिनि कर्मचारियों को रुपये के मूल्य में गिरावट के फलस्वरूप निर्धनता तथा अभाव का जीवन बिताना पड़ता है (पृ० 337-8) उसने चेतावनी दी कि यदि बिनिमय को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जाता तो अंगरेज अधिकारी बहुत सारे प्रलाभनों का मोह न छोड़ पाएंगे

142. नौरोजी, एसेज, पृ० 517; स्पीचेज, पृ० 143, 462; मराठा, 25 सित० 1892, इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, 29 सित० 1893, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 34; एस० एन० बैंतर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 134. एस० ऐड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 47, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1190; वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 30; जी० एस० अय्यर, विलबी आयोग, खंड III, प्रश्न 18638.

143. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1190.

144. ज्ञान प्रकाश, 31 अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 2 सित० 1893); 29 सितंबर 1893 का

- इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 37. 1893 का पू० सा० स० का स्मरणपत्र, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1894 (खंड XVI, सं० 3) पृ० 65; बंगाली 10 फरवरी 1894; नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 143, एस० एन० बैनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 134. सी० पी० ए०, पृ० 262 और एस० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट पृ० 47-8; ए० सी० मजूमदार : रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 143; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1192; हिंदू, 27 मार्च 1899.
145. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1192, तथा एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 262 एस० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट, पृ० 48; ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 143.
146. इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, 29 सितंबर 1893, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 37. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 144; एस० एन० बैनर्जी, एस० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट, पृ० 47-8; दत्त, इंग्लैंड ऐंड इंडिया पृ० 165.
147. एस० एन० बैनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 134.
148. इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, 29 सितंबर 1893, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35; बंगाली, 13 नव० 1893; हितवादी, 25 अगस्त, सोम प्रकाश, 28 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 1893); सहचर, 30 अगस्त (वही, 9 सित० 1893); समय, 15 सितंबर (वही, 25 सितंबर 1893); एस० एन० बैनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 135 एस० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट, पृ० 48; ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी०-1895 पृ०, 141. ए० सी० पी० नायडू, वही, पृ० 143
149. स्पीचेज, पृ० 1192
150. ज्ञान प्रकाश, 31 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 1893); अखबारे आम, 30 सितंबर (आर० एन० पी० पी०, 14 अक्तूबर 1893); एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 263, दत्त . इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 165 और ई एच II, पृ० 578
151. स्पीचेज, पृ० 462.
152. उन्होंने आगे कहा : बंबई के महान व्यक्तियों, पंजाब के महान व्यक्तियों, उत्तरी भारत के महान व्यक्तियों, बंगाल के महान व्यक्तियों ! आओ, हम एकजुट हो जाए, आओ, हम मुदूढ़ पग उठाए आओ, हम निश्चय करें कि तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक इन अन्याय के देवों को सीधे रास्ते पर नहीं ला देते और तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि उनकी आंखों से भ्रम के इस आवरण को हटा नहीं देंगे जिसे बनाए रखने की वे व्यर्थ चेष्टा करते हैं कि यह देश उनका है, हमारा नहीं (रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 135).
153. आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 1893
154. ए० बी० पी०, 22 अगस्त 1893; मराठा, 27 अगस्त 1893; गुजराती, 27 अगस्त, (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 1893); बंगवासी, 26 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 1893); बंगाली, 18 नवंबर 1893; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1192; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 200. दत्त, इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 165.
155. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 562; जे० ए० वाडिया, पूर्वोद्धृत, पृ० 96; दत्त, स्पीचेज I, पृ० 90 तथा देखिए, पीछे पाठ टिप्पणी 90
156. रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 128.
157. देखिए : अध्याय 1 और अध्याय 4.
158. स्वर्ण विनिमय के पक्षधर एस० बी० धरूचा ने निम्न विनिमय के समर्थकों की उनकी असंगति के

- लिए भर्त्सना की उन्होंने व्यय करते हुए टिप्पणी की . चरखा-मिलो के ये दलाल रुपये को रजत मूल्य 6 पैसे तक लाने की इच्छा क्यों करते हैं ? यह तो मजदूरों को ठगना है .. क्या इन लोगों को सभ्य प्राणी कहा जा सकता है, जो एक ओर मजदूरों को लूटने पर भ्रामादा हैं और दूसरी ओर किसानों के हितों की बकालत करते हैं (स्पीचेज, आन इंडियन इकोनामिक्स, पृ० 26)
- 159 बंगाल का 'सहचर' एकमात्र अपवाद था जिसने स्वर्णमान का निरंतर समर्थन किया और निम्न तथा घटते बढ़ते विनिमय का विरोध किया. उसने व्यापारियों और विदेश व्यापार की सफलता को अपना सैद्धान्तिक विषय बनाया उदाहरणार्थ देखिए : 15 जून 1892 का श्रक (भार० एन० पी० बग०, 22 जुलाई 1892, 28 जून 1893 (वही, 8 जुलाई 1893), 21 फरवरी 1894 (वही, 3 मार्च 1894) अखबारों आम, 24 जून (भार० एन० पी० पी०, 9 जुलाई 1898).
- 160 ए० बी० पी०, 29 मई 1892 दुर्भाग्यवश मुझे सदन की 1893, 1894 की रपट प्राप्त नहीं हो सकी परंतु 1897-8 की रपट से सदन के चिंतन की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है. इस रपट में विनिमय की अनिश्चितता पर चिंता प्रकट की गई और बाजार में पर्याप्त धन की और इस विनिमय के अनुपात को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी
161. पेपर्स रिसेटिंग टु चेंसेस इन इंडियन करेंसी सिस्टम (भारत सरकार, 1893), पृ० 60-4, 84-90
- 162 वही, पृ० 25-7, 73-4 तथा देखिए, वही, पृ० 89-90
- 163 एम० बी० भरूचा, पूर्वोद्धृत, पृ० 2-9, 11-5, 22-32
- 164 ग्ल० मी० पी०, 1898, खंड XXXVII, पृ० 513
165. मराठा, 25 सितंबर 1892 तथा बंगाली, 19 फरवरी 1903
- 166 नौरोजी, पाबर्टी, पृ० 561 तथा पृ० 547 इंडियन करेंसी कमेटी (1893) द्वारा जाच के समय भी उन्होंने इसी प्रकार के विचार प्रकट किए इंडियन करेंसी कमेटी साक्ष्य की कार्यवाही तथा परिशिष्ट, सी-7060 II, प्रश्न 2393-7 इसी प्रकार जे० ए० बाबिया ने 1901 में स्पष्ट रूप में कहा कि वे किसानों के प्रति निरंतर अत्याचार की अपेक्षा व्यापारियों पर पड़ने वाले अस्पाई चाटे को ही ठीक समझेंगे (पूर्वोद्धृत, पृ० 126) तथा मराठा, 4 सितंबर 1892
167. देखिए, रिप० आई० एन० मी०, 1901, 1902 और 1904
- 168 1898 में करेंसी कमेटी के मसल प्रश्न किए जाने पर भार० सी० दत्त को यह स्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ा था देखिए, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 76-89
- 169 वकील और बोम, पूर्वोद्धृत, पृ० 128 परिमल राय, पूर्वोद्धृत, पृ० 179, 193-4.
- 170 स्टेटिस्टिकल ऐम्ब्रैड्ड टु ब्रिटिश इंडिया फ्राम 1891-92 टु 1900-01 सारणी 129 और 200 हमने 1895-6 वर्ष का लिया है क्योंकि स्टेटिस्टिकल एम्ब्रैड्ड में उपलब्ध होने वाली साक्ष्यिका का यह प्रथम वर्ष है
- 171 इंडियन करेंसी कमेटी, साक्ष्य की कार्यवाही और परिशिष्ट, 1893 सी-7060 II परिशिष्ट II पृ० 244, और गाडगिल, पूर्वोद्धृत, पृ० 71-2
172. चादी और रुपये के अवमूल्यन की अवधि में जहां पूर्व के दूर देशों में भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात कई गुना बढ़ गए, वहां इंग्लैंड के सूती वस्त्रों के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई (इंडियन करेंसी कमेटी; साक्ष्य की कार्यवाही और परिशिष्ट 1893, सी-7060 II परिशिष्ट II पृ० 244).

173. डी० बारबूर, एल० सी० पी० 1893 खड XXXII, पृ० 274-5; वेस्टलैंड, एल० सी० पी० 1894 खड XXXIII, पृ० 181
- 174 एल० सी० पी०, 1893 खड XXXII, पृ० 27५.
175. वही
- 176 दादाभाई नौरोजी ने इसे 'शासन की विदेशीयता' कहा (इंडियन कंग्रेस कमटी, साक्ष्य की कार्य-वाही और परिशिष्ट 1893 सी-706 II, प्रश्न 2346)

अध्याय 8

श्रमिक वर्ग का उदय

इस पतपते उद्योग के दम तोड़ने की अपेक्षा इसके मजदूर श्रमिकों की अपेक्षाकृत ऊँची मृत्यु दर ही हमें रुचिकर है। '...एक बार हमारे उत्पादकों को भली प्रकार व्यवस्थित हो जाने दीजिए। उनके उपरगत हम अपने श्रमिकों की सुरक्षा अपने आप कर लेंगे।

— अमृत बाजार पत्रिका, 25 मिनबर, 1875.

हम इन अभागे वर्गों की निर्धनता, गंदगी और निम्न स्थिति को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमारा मन कठोर हो गया है। हमारा और हमारे शासकों की आत्मा उनकी दशा देखकर उद्भिन्न ही नहीं होती। वस्तुतः उनकी यह दुर्दशा शताब्दियों में राज्य और समाज के उच्च वर्गों द्वारा किए जा रहे उनके निरस्कार और दमन का ही फल है।

— जी० मुन्सन अथर

आधुनिक उद्योगों, खानों, परिवहन और वागान के विकास ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज में औद्योगिक श्रमिकवर्ग के रूप में एक सर्वथा नवीन वर्ग का जन्म दिया। 1880-81 तक इसका आकार माध्याम्य था। उस वर्ष सूती कपड़ा मिलों में 47,955 पटमन मिलों में 35,235 और कोयला खानों में 11,969 कर्मचारी कार्यरत थे। 1905-06 तक इस नए वर्ग का स्वनम रूप में उल्लेखनीय विस्तार हो गया था। उस वर्ष सूती कपड़ा मिलों में 212,720, पटमन मिलों में 144,879 और कोयला खानों में 89,995 कर्मचारी नियुक्त थे। इस प्रकार अकेले यत्रशासन में मजदूर आधुनिक कारखानों में ही 700 000 कर्मचारी नियुक्त थे।¹

आधुनिक औद्योगिकता और उसके साथ जुड़ी पूँजीपति व्यवस्था के आने के साथ ही वे सब बुराईयाँ आ पहुँची जिन्होंने पहले अंगरेज श्रमिकों की पीढ़ियों का जीवन विकृत किया था। आधुनिक उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों, पुरुष, स्त्री और बच्चों की प्रारंभिक पीढ़ियों को भी आधुनिक मनुष्य को ज्ञात क्रूर तथा घृणित शोषण का शिकार बनना पड़ा था। भारत में फैक्टरी के जीवन का निकृष्टतम पक्ष यह था कि कर्मचारी को कारखानों में बहुत अधिक घंटे काम करना पड़ता था क्योंकि कारखानों में काम करने के समय की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं थी। आरंभ में एक औसतन बारहमासी कारखाने में शीत ऋतु

मे दिन भर अर्थात् 11½ घंटे प्रतिदिन अथवा 80½ घंटे प्रति सप्ताह काम होता था और ग्रीष्म ऋतु में 14 घंटे प्रतिदिन अथवा 98 घंटे प्रति सप्ताह काम चलता था।¹ लगभग 1887 के बाद जब कारखानों में बिजली की रोशनी प्रचलित हो गई तो बेचारे शरीरगर्भों के प्रतिदिन काम के घंटे बढ़कर विभिन्न इलाकों में 12½ से 16 के बीच हो गए। इन सब में सबसे अधिक दुःप्रभावित कलकत्ता के पटसन कारखानों के बुनकर थे, जिन बेचारों को 15-16 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था।² इतने अधिक घंटे काम करने के अनिश्चित बेचारे श्रमिकों को मिल में आने और वहां से घर जाने में ही दो-तीन घंटे लग जाते थे, इस तथ्य को ध्यान में रखने पर उन गरीबों की शारीरिक दुर्दशा का सही अनुमान लगाया जा सकता है।

एक अन्य बात यह है कि काम के इन लंबे घंटों की थकावट और बोरियत को दूर करने के लिए अवकाश काल की कोई नियमित और उपयोगी प्रणाली नहीं थी। कुछ मिलमालिक अवकाश की व्यवस्था करते थे परन्तु यह समय 15-30 मिनट का होने के कारण सर्वथा अपर्याप्त होता था। अन्य कारखानों तो छुट्टी करते ही नहीं थे। वे तो यह आशा करते थे कि कर्मचारी गाना खाने समेत भी मशीनों की चौकसी करें।³ नियमित विश्राम अथवा अवकाश तो इनकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे वे बेचारे निरंतर थकान निवृत्ति पा सकते। 1885 के बाबे फॅक्टरी लेबर कमीशन ने टिप्पणी की कि भारत के कारखानों में सारे वर्ष में दी जाने वाली छुट्टियाँ औसतन पंद्रह हैं जबकि इंग्लैंड में 10 अवकाश के अनिश्चित 52 रविवारों का पूरा छुट्टी और 52 शनिवारों की आधी छुट्टी रहती है। इस प्रकार कुल मिलाकर वहां 88 दिनों का अवकाश रहता है।⁴ इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों की शारीरिक शक्ति पूर्णतः क्षीण हो गई। वे बेचारे कभी कभी मशीनों में हटते ही और अपने माथियों के कारखाने के दरवाजे में बाहर निकल पाने में पड़ते ही फंस पा गहरी नींद में जाते थे।⁵

उसमें भी बदतर बात यह थी कि 1891 तक महिलाओं को भी पुरुषों के समान उतने ही लंबे घंटों तक काम करता पड़ता था जबकि उनके लिए काम के लिए 11 घंटे का अधिकतम समय निश्चित किया गया था। प्रारंभिक भारतीय कारखानों में काम करने वाले बच्चों के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। 1881 तक बच्चों को भी उतने अधिक घंटों तक काम करना पड़ता था, जितने घंटे वयस्क व्यक्ति काम करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि वे बेचारे थकावट से चूर चूर होकर मशीनों के बीच गिर जाते थे।⁶ 1881 के फॅक्टरी ऐक्ट ने बच्चों के लिए काम के घंटों की अधिकतम सीमा 9 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की और बच्चे की न्यूनतम परिभाषा 7 और 12 वर्ष के बीच की आयु में की। फिर भी बहुत सारे कारखानों में बच्चे वयस्कों के समान लंबे घंटों तक काम करते रहे।⁷ 1891 के फॅक्टरी ऐक्ट ने बच्चों के काम के घंटों में और अधिक कटौती करके उनकी अधिकतम सीमा 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की और बच्चे की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा भी 7-12 के स्थान पर क्रमशः 9-14 तक बढ़ा दी। परन्तु व्यवहार में इन दोनों प्रावधानों का प्रायः उल्लंघन किया जाता था।⁸

रूई पीजने-दबाने जैसे छोटों और मौसमी कारखानों की स्थिति तो आरंभ से ही

हृदयद्रावक तथा भयावह थी। 1885 के बाबे फैक्टरी लेबर कमीशन ने निर्देश किया कि स्नानदेश के पिजन और संपीडन कार्य में अधिकांशतः स्त्रियाँ और बच्चे ही लगे हुए थे और उनके काम के घंटे सामान्य रूप से सवेरे 4 अथवा 5 बजे से सायं 7, 8 अथवा 9 बजे तक होते थे और जब काम का दबाव बढ़ जाता था तो उन्हें 8-8 दिनों तक निरंतर दिन-रात तब तक काम करते रहना पड़ता था जब तक कि उनके हाथ थककर और स्वास्थ्य बिगड़ कर काम करने से इनकार नहीं कर देते थे।¹⁰ यह तथ्य प्रस्तुत एक साक्ष्य के लंबे अवतरण में उद्धृत है, जिसमें इन उद्योगों में प्रचलित स्थितियों का दुःखद वर्णन किया गया है और साथ ही एक और भारी अभावों की दुःखद कथा पर तथा दूमरी और क्रूर लोभवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है।¹¹ एक गवाहने स्वीकार किया कि उसने अपनी आँखों से देखा है कि ऊँघती हुए मजदूर महिलाएं यंत्र की तरह बिनौले यंत्र में रुई दिए जा रही हैं। एक मिनट वे मजदूर महिलाएं छाती में चिपके बच्चे को स्तन चुसवाती हैं और दूसरे ही मिनट मशीन में रुई डालने लगती है।¹²

यह स्थिति इस रूप में तो और भी अधिक असह्य थी, इतने अधिक अमानवीय और कमरतोड़ लंबे घंटों की मेहनत से मिलने वाली मजदूरी तुच्छ और किसी भी मानदंड से पूर्णतः अपर्याप्त थी। इस अवधि के अधिकांश वर्षों में बंबई के कपड़ा कारखानों में काम करने वाले पुरुषों और स्त्रियों को मिलने वाला मासिक वेतन सात रुपये से बीस रुपये के बीच था।¹³ रुई पीजने और संपीडन करने वाले छोटे कारखानों में लगभग 18 घंटे के दैनिक श्रम का पारिश्रमिक 3-4 आने था।¹⁴ इसके अतिरिक्त, और यह तथ्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, उद्योगों के विकास के और श्रम की उत्पादकता वृद्धि के बावजूद श्रमिकों के वास्तविक वेतन में कोई अंतर नहीं आया।¹⁵ श्रमिकों के वेतन में उस समय भी कोई वृद्धि नहीं की गई जब उद्योग अतिशय संपन्न स्थिति में थे, इतने अधिक संपन्न कि कई एक कारखाने तो चार वर्षों में ही अपनी लागत पूजी चुकाने में समर्थ हो गए थे।¹⁶

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने, सामान्य रूप से भारतीय जनता के दुर्भाग्य से द्रवित आधुनिक औद्योगिक पूँजीवाद की बहुमुखी बुराइयों के प्रति तथा समाज के नाप पनपते इस वर्ग के शोषण तथा विषम आर्थिक कष्टों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया? यह प्रश्न एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके साथ दो विरोधी हित जुड़े हुए हैं और वे दोनों आंशिक रूप से भारतीय होने के कारण राष्ट्रीय हैं। यह एक व्यापक परिमाण में निर्धनता का प्रत्यक्ष निदर्शन था जो पर्याप्त सीमा तक स्वयं भारतीयों के ही एक वर्ग की लोभ लालसा की उपज थी। उदीयमान राष्ट्रीय नेताओं की श्रम नीति के विस्तृत विश्लेषण से पूर्व तीन महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम, 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नेताओं की किसी स्वतंत्र श्रमनीति का विकास नहीं हुआ था, वह अधिकांशतः भारत सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थितियों के नियमन अथवा सुधार के लिए किए गए प्रयत्नों की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रकट होती थी। द्वितीय, नेताओं के दृष्टिकोण के विश्लेषण के लिए कुछेक नेताओं में श्रम समस्याओं के प्रति विचार-अभिव्यक्ति का अभाव इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीधी व खुली टिप्पणी। अंतिम, अधिकांश रूप में आंशिक अथवा पूर्णतः भारतीय पूँजीपतियों के स्वामित्ववाले आधुनिक

कारखानों में नियुक्त श्रमिकों के प्रति तथा पूर्णरूपेण विदेशी स्वामित्ववाले बागान और रेलों में लगे श्रमिकों के प्रति भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूप से भेदभावपूर्ण था ।

फैक्टरी ऐक्ट और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, 1881

यह सचमुच आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारत में पूंजीनिष्ठ औद्योगिकता की बुराईयों की उग्रता को ज्ञान करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने का प्रथम प्रयास इंग्लैंड की ओर से ही हुआ । इंग्लैंड के परोपकार और सेवा व्रतधारियों तथा वस्त्र उत्पादकों ने एकजुट होकर भारतीय कारखानों में नियुक्त स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण की कानूनी मांग की ।¹ समद सदस्यो तथा माचेस्टर वाणिज्य मंडल जैसी लोक सस्थाओं द्वारा अपने तौर पर लगातार प्रताड़ित भारत राज्य सचिव की प्रेरणा तथा उनके अंतिम निर्देश से बर्बट सरकार ने 25 मार्च 1875 को बर्बट की फैक्ट्रिया के मजदूरों के कार्य की स्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए तथा उनमें सुधार के उपायों को सुझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की ।² आयोग किसी सर्वसम्मति निष्कर्ष पर न पहुंच सका और इसके प्रतिवेदन पर केवल अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य डा० बननी ने हस्ताक्षर किए । इस आयोग के प्रतिवेदन में इस भाव दर्शाया गया था कि साधारण कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत एक वयस्क श्रमिक के लिए एक दिन में 12 घंटे कार्यकाल की व्यवस्था हो, इसमें एक घंटे का विश्राम अवकाश भी सम्मिलित है । मज्दा में एक दिन के अवकाश की व्यवस्था हो । 8 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर पाबंदी हो और बच्चों के (8 से 14 वर्ष तक की आयु के) कार्यकाल की सीमा 8 घंटे प्रतिदिन हो ।³ आयोग के अन्य सार सदस्यों ने, जिसमें 6 पर्याप्त आश्चर्यजनक रूप से कपास उद्योग पूंजी निवेशक थे, कारखानों के मजदूरों में किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप का विरोध किया ।⁴ बर्बट सरकार के हाथ में इस विषय में आगे कोई भी कार्यवाही न करने का बहाना आ गया । सरकार की मुक्ति थी कि आयोग ने सरकारी हस्तक्षेप के लिए कोई समुचित आधार नहीं प्रदाया और वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी हस्तक्षेप से बर्बट के पनपते उद्योगों का लाभ के स्थान पर हानि होने की ही संभावना अधिक है ।⁵

भारत में फैक्टरी कानून बनाने की चिल्लाहट ने अब इंग्लैंड में तेजी पकड़ ली ।⁶ इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय श्रमिक परोपकारियों की गतिविधियों ने इस मांग को और अधिक बल मिला । इन भारतीय श्रमिक परोपकारियों में सोराबजी गापुरजी बंगाली अग्रगण्य थे । इन्द्रेण फैक्टरी कानून के लिए बिल का प्रारूप फैक्टरी में काम करने वाले वयस्क पुरुषों के प्रतिदिन के कार्यकाल की सीमा 11 घंटे, स्त्रियों के प्रतिदिन के कार्यकाल सीमा 10 घंटे, और बच्चों के प्रतिदिन कार्यकाल की सीमा 9 घंटे का निर्धारण करने वाला, इन घंटों में एक घंटे का अवकाश भी सम्मिलित था, तैय्य करके आंदोलन को बड़ा भारी बल दिया ।⁷ अस्तु भारत सरकार ने उन्हें बर्बट विधान परिषद में इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति ही नहीं दी । 'फैक्टरी कानून के समर्थक अन्य स्थानीय लोक परोपकारियों में था पूना का परोपकारी समाचारपत्र जानोदय ।⁸ उसी समय हल्की

फुल्की हलचल स्वयं श्रमिक वर्ग में भी उभरती दिखाई दी। उदाहरणार्थ, राघव सखाराम ने, जो स्वयं एक श्रमिक था और डी० चमनलाल के अनुसार प्रथम श्रमिक नेता के रूप में उदित हुआ था, फैक्टरी कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया तथा उसने 578 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक जापान सरकार को भेजा ज़िम्मे काम के दिन 9 घंटे करने और सप्ताह में एक दिन के अवकाश की व्यवस्था की मांग की गई थी। 'बाद में बालाजी रामचंद्र फाकड़ ने 634 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य जापान प्रस्तुत किया था।'⁶

भारत और इंग्लैंड में आंदोलन के फलस्वरूप और उसी समय भारत में प्रजीपति हितों द्वारा किए गए प्रबल विरोध को देखते हुए, भारत सरकार ने 7 नवंबर 1879 को भारत के गवर्नर जनरल की परिपद में एक नग्न प्रकृति का बिल प्रस्तुत किया। बहुत सारे परिवर्तनों द्वारा शक्ति क्षीण किए जाने के उपरांत यह बिल 'इंडियन फैक्टरी ऐक्ट—1881' से रूप में कानून बन गया। कानून का प्रमुख संबंध श्रमिक बच्चों की समस्या से था। इसके अनुसार बच्चों को श्रमिक रूप में रखने की न्यूनतम आयु सात वर्ष की निर्धारित की गई थी और 7-12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे प्रतिदिन में अधिक समय वायं करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें प्रतिदिन इन 9 घंटों से अलग एक घंटे का अवकाश देने की तथा महीने में चार दिनों के अवकाश देने की इस कानून में व्यवस्था थी। एक्ट में खतरनाक मशीनों के लिए समुचित बाड़ा बनाने और संबंधित स्थानीय सरकार को दुर्घटनाओं की शीघ्र ही रपट करने की भी व्यवस्था थी। ये मांगी जाने केवल उन कारखानों पर लागू होती थी जो मशीनी शक्ति का प्रयोग करते थे, सी अथवा इससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करते थे और वर्ष में चार महीनों में अधिक समय तक चालू रहते थे। नील के कारखानों, चाय और काफी बागानों को विशेष रूप से इस कानून की सीमा में बाहर रखा गया था।⁷ इसके अतिरिक्त पुरुषों और महिलाओं के काम के घंटों का भी नियमित नहीं किया गया था।

इस प्रकार 1881 का इंडियन फैक्टरी ऐक्ट सर्वथा प्रारंभिक और सभी व्यावहारिक दृष्टियों में साधारण ही था। इस तथा को स्वयं सरकार ने अनेक शब्दों में स्वीकार किया। रयानापल्ल सचिव ने स्थानीय सरकारों को एक परिपत्र जारी करते हुए लिखा 'इस ऐक्ट को बनाने समय मिलमालिकों के, व्यापारिक संगठनों के तथा अन्य मर्यादों के प्रतिनिधित्व को बड़ी ही सावधानी से महत्व देते हुए उसका ध्यान रखा गया है। इस उद्देश्य को लगातार ध्यान में रखकर इसमें अधिक हलका कानून बनाना संभव ही नहीं था।'⁸

फैक्टरी कानून बनाने के लिए प्रारंभिक संधर्ष के प्रति और उसके फलस्वरूप 1881 का इंडियन फैक्टरी ऐक्ट बन जाने के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया लगभग पूर्ण रूप से बर्बाद प्रात तक ही सीमित थी। इसे अनुचित भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इस विषय में जुड़ा सारा मतभेद प्रमुख रूप से बर्बाद की कपड़ा मिलों से ही संबंधित था तथा कुल मिलाकर कारखानों के कर्मचारियों की कार्यस्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों की उपेक्षा करने वाला अथवा विरोधी था। उदाहरणार्थ यह उल्लेखनीय है कि बर्बाद प्रात के अधिकांश राष्ट्रवादी नेता, दादाभाई नौरोजी, एम० जी० रानाडे,

के० टी० तेलंग और फिरोजशाह मेहता, तथा अन्य प्रांतों के राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय अस्तित्व में आ रहे निम्नस्तरीय श्रमिक वर्ग के संबंध में अपने विचार प्रकट नहीं किए। बंबई के अग्रणी जननेता वी० एन० मांडलिक ने, जो 1875 के बांबे फैक्टरी कमीशन के एक सदस्य भी थे, श्रमिकों के हित में कानून बनाने के विरुद्ध बहुमत के साथ अपना मत दिया। यदि बंबई के 'मराठा' और 'इंदु प्रकाश' और बंगाल के 'बंगाली' और 'अमृत बाजार पत्रिका' संपादकीय टिप्पणियों को उनके निजी विचार माना जाए अथवा इस प्रकार की टिप्पणियों के अभाव को ही उनके विचार के रूप में देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन पत्रों के ये संपादक क्रमशः बंबई के युवक नेता तिलक अगरकर और चंदावरकर तथा बंगाल के एम० एन० बैनर्जी तथा घोष बंधु, एस० के० घोष तथा मोतीलाल घोष, श्रमिकों के हितों के प्रति उदासीन ही नहीं थे अपितु विरोधी थे।

जहां तक भारतीय समाचारपत्रों का संबंध है, केवल थोड़े से ही, मही गिनती के तौर पर बंबई के केवल चार, समाचारपत्रों ने ही श्रमिक हितों का समर्थन किया। इन पत्रों ने 1874 के ब्रिटिश फैक्टरी ऐक्ट के समानांतर इंडियन ऐक्ट बनाने की वकालत की। 'अखबार सौदागर' ने 24 नवंबर 1874 के अंक में लिखा : मिलमालिक निधन श्रमिकों की निर्भयता का दुरुपयोग करते हैं और उनसे निर्दयतापूर्वक काम लेते हैं। श्रमिकों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए और उनके काम के घंटे प्रातः 7 बजे से सायं 5½ बजे तक होने चाहिए।¹²⁹ 'लोकमित्र' ने 29 दिसंबर 1878 के अंक में निम्नलिखित ही उमकी स्वार्थाघता के लिए निंदा की और सरकार में श्रम के घंटों में समुचित कटौती करने का अनुरोध किया।¹³⁰ रास्त गोप्तार ने 29 दिसंबर 1878 के अंक में और 19 जनवरी के अंक में एस० एम० बंगाली के बिल के प्रारूप को पूर्ण समर्थन दिया।¹³¹ इस पत्र ने 7 दिसंबर 1879 के तथा 7 नवंबर 1880 के अंकों में, 7 नवंबर 1880 के इंडियन स्पेक्टेटर के अंक और 22 मार्च 1881 के अखबार सौदागर के अंक के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत फैक्टरी बिल का समर्थन किया।¹³² परन्तु दया और मानवता के भावों में ही द्रवित इन थोड़े से समाचारपत्रों में भी थोड़े समय के बाद शीघ्र इस क्षेत्र को छोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी। 1879 में ही लोकमित्र लेकर कानून का विरोधी बन बैठा।¹³³ इंडियन स्पेक्टेटर 7 नवंबर 1880 के अंक में पहले ही इन शब्दों में विरोध प्रकट कर चुका था : 'वयस्क श्रम के मामले में अनुचित हस्तक्षेप' मिलों की आतंरिक आर्थिकता में अनुचित हस्तक्षेप।¹³⁴ यहां तक कि अगले वर्ष सरकारी बिल का समर्थन करते करते यह पत्र विरोधी खेमे में चला गया।¹³⁵ 'अखबार सौदागर' भी फैक्टरी कानून के समर्थन में कभी कभी भटक जाता था।¹³⁶ केवल 'रास्त गोप्तार' अतः तक श्रमिकों के उद्देश्य के प्रति सच्चा और ईमानदार बना रहा।¹³⁷ बंगाल के केवल एक समाचारपत्र 'सोमप्रकाश' ने 1881 के फैक्टरी ऐक्ट बनने का समर्थन किया।¹³⁸ सार्वजनिक समस्याओं में पूना सार्वजनिक सभा अकेला सगठन था, जिसने साप्ताहिक अवकाश लागू करने की तथा वयस्कों के काम के घंटे सीमित करने की वकालत की। यह दूसरी बात है कि इस सरथा ने भी 1879 के बिल के प्रारूप की उस समय आलोचना की।¹³⁹

इसके विपरीत दूसरी ओर भारतीय समाचारपत्रों की प्रबल बहुसंख्या ने किसी भी

फैक्टरी कानून की आवश्यकता को बड़ी ही प्रचंडता से नकार दिया और कानून की पुस्तक में इस विषय पर अवाञ्छनीय किसी कानून को सम्मिलित करने की चेष्टा का चिल्लाकर विरोध किया तथा उसकी भर्त्सना की। 1875 में जामे जमशेद, 'बर्बई समाचार' और 'अरुणोदय' ने बाबे फैक्टरी कमीशन की नियुक्ति का इस आधार पर विरोध किया कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी।¹⁰ जब ए० ए० बंगाली ने 1878 में फैक्टरी बिल का प्रारूप सामने रखा तो बर्बई तथा अन्य प्रांत के राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों ने उस पत्र में अमूर्तमति प्रकट की।¹¹ ब्राह्मो समाज के जर्नालिकारी और सुधारक वर्ग के प्रवक्ता जगल के 'ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन' पत्र ने भी 27 फरवरी 1879 को यही दृष्टिकोण प्रकट किया कि कारखाना मंचारियों के लिए मरकत कानून की आवश्यकता ही नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका ने अपन 16 मार्च 1880 तक अनेक अनेक सामान्य उग्रता से बंगाली के प्रयासों की खिल्ली उड़ाई।

नवंबर 1879 में विधान परिषद में सरकारी फैक्टरी बिल के प्रस्तुत होने का, तदनुसार उस पर प्रवर समिति और परिषद के विचार-विमर्श का और उसके फलस्वरूप 1881 में फैक्टरी ऐक्ट के कानूनी रूप लेने का भारतीय प्रेम ने चौख चिल्लाहट द्वारा अपनी अमूर्तमति दिखाकर विरोध ही किया। चोटी के राष्ट्रवादी तथा समाजसुधार के समर्थक पत्रों 'उद प्रकाश' (22 मार्च 1880, 21 मार्च 1881 और 4 अगस्त 1884), 'गुजराती' (28 नवंबर 1880 और 27 मार्च 1881), 'उडियन' 'स्पेक्टेटर' (20 मार्च 1881) 'नटिव ओपीनियन' (27 मार्च और 19 जून 1881) और ज्ञान प्रकाश (30 जून 1881) ने इसके प्रति विरोध प्रकट किया।¹² गुना मार्चंजन गंगा की सामान्यतः मयमी त्रैमासिक पत्रिका ने, जो उस समय बर्बई के दशभक्तों की अभिव्यक्ति का मन बनी हुई थी, प्रापणा की 'फैक्टरी श्रम को नियमित करने के लिए कानूनी कार्यवाही का लक्ष्य मात्र भी औचित्य नहीं।'¹³ उस समय बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित 'मराठा' ने 13 मार्च 1881 के अंक में इस कानून के विरुद्ध प्रचंड विरोध प्रकट किया। बंगाल के दो अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'बंगाली', ने ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन के समान इस कानून की भर्त्सना की।¹⁴ इलाहाबाद के 'हिंदी प्रदीप' ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए।¹⁵ कुल मिलाकर बर्बई और बंगाल के अग्रगण्य अग्रणी समाचारपत्र इस बिल और उसके अनिम रूप 1881 के उडियन फैक्टरी ऐक्ट, के विरुद्ध सामूहिक राग अलापने में उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हो गए।¹⁶

उस समय के आलोचकों ने फैक्टरी कानून के विरुद्ध ऐसे-ऐसे मंत्रेदार और अनाखे तर्क प्रस्तुत किए कि जो अपने निष्कर्ष में आज के पाठक को सुनने में यदि जगली और घृणित नहीं तो भड़े अवश्य प्रतीत होंगे। उदाहरणार्थ, फैक्टरी कानून की अनावश्यकता को मिट्ट करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत एक तर्क था : 'श्रम श्रमिकों की ओर से न तो कोई मांग पेश की गई है और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त है। इन आलोचकों के अनुसार श्रमिक तो नितान्त स्वेच्छा में ही लंबे समय तक कार्य करने को सहमत हैं।'¹⁷ अमृत बाजार पत्रिका ने 12 नवंबर 1880 के अंक में इस दृष्टिकोण को मक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया : 'यदि श्रमिकों पर कारखानों में भारी अत्याचार

होता है तो वे और कहीं नौकरी क्यों नहीं ढूँढ लेने ? वे नौकरी से हटाए जान में उग्र क्यों है ? अतः यह स्पष्ट है कि 'जुलूम' होने पर भी वे नौकरी में बने रहना चाहते हैं।' इससे पूर्व इस पत्र में 16 जनवरी 1880 के अंक में लोकोपकारको की अकारण परतु सर्वथा उपयुक्त सलाह यह दी कि वे सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डालने के बदले श्रमिकों के पास जाएँ और उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करें।

इस सबंध में प्रस्तुत दूसरा तर्क यह था कि फैक्ट्रियाँ काम करने वाले श्रमिकों, स्त्रियाँ और बच्चों का किसी प्रकार की बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। नग किए जाने की बात तो दूर रही, वस्तुतः उन्हें अपने स्वामित्व में मजदूर बनना ही मिलता है।¹ यह बात जोर देकर रखी गई कि वे दरिद्र और दुखी न होकर नृत्ता मर दण्डित में संपन्न और स्वस्थ हों।² यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन आवाजों द्वारा उठाया गया कि फैक्टरी का काम श्रम मापेक्ष नहीं क्योंकि कारखाने का श्रम श्रम शोभन पर्वति का हान के कारण भारतीय श्रमिकों में अधिक नाकामि है जो कि एक प्रति पण विशेष र्गित ग्वन है। भारत के शासक पर सदैव इस उपाय पर श्रम शोभन सवधा अनुपयुक्त समस्याओं की शायन की गलती करने का आग्रह लगाया जाता है। भारतीय सामाजिक संगठन के व्यावहारिक सूक्ष्म ज्ञान के अभाव की प्रशंसा करते हैं उन समीक्षकों का कथन था कि यदि विदेशी शासन बदले में दश की शरद्वता का ही ज्ञान में ग्वन तथा भारतीय समाज और भारतीय श्रमिकों की वास्तविक आवश्यकताओं का ज्ञान का प्रयत्न करने का उद्देश्य है कि उनके अंगों की रक्षा और श्रम शोभन मुक्ति पान की अपेक्षा अधिक ज्वरन और महत्वपूर्ण उनकी समस्या ज्ञाना के अभाव और उस अराजक की खरीदन के सामना के अभाव की ही थी।³ श्रम शानन के समीक्षकों के अनुसार भारत में जातिगत विविध के अन्यान्य क्षेत्रों में लग श्रमिकों की अपेक्षा कारखानों में श्रम श्रमिकों की दशा निश्चित रूप में बेहतर थी।⁴

बच्चों के सबंध में यह बात विशेष रूप से सत्य थी क्योंकि उन्हें कारखानों की अपेक्षा बागान में अथवा शायद अन्यत्र स्थानों पर अधिक लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था।⁵ नरिव आगनिपन ने तो अपने 29 दिसंबर 1878 के अंक में यह तर्क लिख डाला कि 'एक ज्ञान वाले बच्चों की अपेक्षा कारखानों में काम करने वाले बच्चों का स्वास्थ्य अधिक अच्छा है।' ⁶ पूना सार्वजनिक सभा के जर्नल के जुलाई 1881 के अंक में फैक्टरी लॉजस्मन 'उन इंडिया' के अज्ञातनाम लेखक ने इसमें भी आगे बढ़कर यह लिखा 'कारखानों में काम करने वालों ने अपने काम को कभी भारी कष्टदायक तथा थकाने वाला नहीं समझा।'⁷ लेखक महोदय ने आगे लिखा : 'फैक्टरी कानून 12 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों को नौकरी से हटा दिया जाएगा क्योंकि मालिक उन्हें नौकरी में रखकर इस फैक्टरी के अवांछनीय दुःखदायी हस्तक्षेप को क्यों पसंद करेंगे।'⁸ इस कारण से अथवा फैक्टरी ऐक्ट में निहित व्यवस्था के पालन से मिला जुना अनिवार्य परिणाम यह होगा कि जिन भाग्यशाली बच्चों की नौकरी जारी भी रखी जाएगी उनके वेतन में भी कटौती कर दी जाएगी। इसके फलस्वरूप पहले से ही अभावग्रस्त श्रमिक परिवारों को अपने उन बच्चों को रोटी के टुकड़े से वंचित करना पड़ेगा तथा वे बच्चे अपने

माता-पिता पर भाररूप हो जाएंगे।⁵⁸ जहां तक बच्चों का संबंध था, इन भ्रालोचकों के अनुसार इस ऐकट का निकृष्टतम परिणाम यह होगा कि बाल अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाएगी क्योंकि फैक्टरी की नौकरी से हटाए हुए लड़के या तो भीख मागने पर, या उधार मागने पर या चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे।⁵⁷

फैक्टरी कानून के विरुद्ध राष्ट्रवादियों की प्रबलतम आपत्ति का आधार यह विश्वास था कि यह कानून लंकाशायर के कारखानों के मुकाबले भारत के पनपते सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन व्यय में वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसकी प्रतियोगिक सामर्थ्य में ह्रास करके इस उद्योग के विकास को बाधित करेगा।⁵⁹ कुछ राष्ट्रवादियों ने तो इसे विनाश के दैत्य का दरजा दे डाला। 13 मार्च 1881 के अंक में 'मगठा' ने विलाप करते हुए लिखा : 'भारत का शिशु उद्योग डूब गया है।' कुछ एक भारतीय नेताओं ने तो खुले तौर पर दृढ़ता से यह स्वीकार किया कि औद्योगिक विकास की बड़ी भारी आवश्यकता दृष्टिगोचर करते हुए कारखानों के मजदूरों के हितों का बलिदान भी करना पड़े तो उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 2 मिनबर 1875 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा : 'इस पनपते उद्योग का गला घोटने की अपेक्षा कारखाने के कर्मचारियों की अपेक्षाकृत बड़ी हुई मृत्यु दर ही वाछनीय है।' जब एक बार हमारे उत्पादन व्यवस्थित हो जाएंगे तो हम इन श्रमिकों की सुरक्षा का उपाय भी ढूँढ लेंगे।⁶⁰ इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण में भी यह कानून हानिप्रद है क्योंकि इसका परिणाम मोने का अडा देने वाली मुर्गियों को मारना होगा। सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर लगी किसी भी प्रकार की पाबंदी का बदले में यह फल होगा कि स्वयं कर्मचारियों की आय के और उनकी आजीविका के माधन प्रभावित होंगे।⁶⁰

कई एक भारतीय लेखकों ने श्रान्तिपूर्वक चल रहे निजी औद्योगिक उद्यम में खनरे से भरे हुए राज्य के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति पर आपत्ति की।⁶¹ उनके अनुसार उपयुक्त ढंग यह था कि स्वामी और सेवकों के झगड़ों को आपसी सौहार्द में ही सुलभन दिया जाए।⁶² भारतीय नेताओं ने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि सरकार किसी भी स्थिति में इस संबंध में कानून बनाने पर तुली हुई है तो यह कानून सारे ब्रिटिश भारत में लागू होना चाहिए ताकि बंबई प्रांत के भारतीयों के स्वामित्ववाले उद्योगों के विरुद्ध अन्यत्र प्रांतों के अगरेजों के स्वामित्ववाले उद्योगों को किसी प्रकार का लाभ न पहुंच सक और दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।⁶³ इसी प्रकार यूरोपियों के स्वामित्ववाले चाय और काफी बागान, नील के कारखानों तथा इंग्लैंड को कच्चे माल के निर्यात का सबर्धन करने वाले, कपास पीजने और धुनने वाले छोटे कारखानों को इस कानून की सीमा में बाहर रखने पर भी आपत्ति की गई। यह भेदभाव उस स्थिति में और भी अधिक अरुचिकर था जबकि रुई पीजने-धुनने वाले छोटे कारखानों में तथा चाय और नील के क्षेत्र में काम करने वालों की स्थिति बंबई के आधुनिक कपड़ा मिलों की कर्मचारियों की स्थिति से अधिक विषम थी। फलतः यह कहा गया कि लोकमेवा पर तुली हुई सरकार को सहायता की अपेक्षा रखने वाले भारतीय उद्योगों की सावधानी के साथ देखभाल करनी चाहिए।⁶⁴

इस स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर भारत सरकार फैक्टरी ऐक्ट को कानून का रूप देने के लिए इतनी उत्प्रेरणा क्यों थी? जितने भी भारतीय लेखकों ने व्यावहारिक रूप से इस विषय पर कुछ चर्चा की है, उन सबका एक यही उत्तर था कि भारत सरकार लवाशायर के ईर्ष्यालु रईमों के, अनुचित होने के बावजूद, प्रबल और असह्य दबाव के अंतर्गत ही यह सब कुछ कर रही है। लवाशायर के ये ईर्ष्यालु रईम लोकहित और उदारता के छद्मवेष में भारतीय वर्गों को महंगा बनाकर भारतीय प्रतियोगियों को पगु बनाना चाहते हैं।¹⁴ प्रमाण के रूप में, इंडियन स्पेक्टेटर न ऐस्ट के अंतिम रूप में कानून का रूप ग्रहण करने के समाचार पर अपन 20 मार्च 1881 के अंक में व्यंग्यात्मक रूप से बार्नर्ट दत्त द्वारा लिखा: 'माचेस्टर के जनानों द्वारा प्रेरित कुछ अदूरदर्शी उत्साहियों की चीन्हा-पुकार और लोकापकार का दम भरने वाली सार्वजनिक भर्त्सनाओं को मूर्छाग्रस्त सरकार द्वारा रोक पाना संभव नहीं हुआ है।'¹⁵ ब्राह्मा पत्रिक ओपीनियन ने 24 मार्च 1881 के अंक में बड़ा ही नीन्हा और स्पष्ट निर्णय इन शब्दों में दिया 'माचेस्टर ने भारत के मनी वस्त्र हथौड़े पर स्पष्टपूर्ण विजय प्राप्त कर ली।'

प्रथम इंडियन फैक्टरी ऐक्ट के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी घटनाओं से कुछ भारतीय विचारकों ने स्पष्ट निष्कर्ष निकालने में दूर नहीं की। कटु स्वर वाली अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 17 मार्च 1881 के अंक में लिखा 'भारत क्या है? माचेस्टर की कपाम उत्पादक मर्णाति ही तो है। भारतीय रगत क्या है? माचेस्टर के उपयोग के लिए रक्त उगाने हेतु बनाई गई जानवरों की एक फिल्म ही तो।' पुना के राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी के पक्कता 'मराठा' ने अपने 13 मार्च 1881 के अंक में क्रोध होकर लिखा 'हम स्पष्ट प्रकट होता है कि उनके अधिक दीर्घकाल में हम पर किस लिए शासन किया जा रहा है अर्थात् भारत पर भारत के हित में शासन नहीं किया जा रहा प्रत्युत इंग्लैंड के हितों के लिए इस देश पर शासन किया जा रहा है। भारतीयों को यह समझ लेना चाहिए कि वे विजित राष्ट्र हैं और उन पर विजित राष्ट्र पर किए जाने वाले शासन के अनिर्गुण और किसी भी रूप में शासन नहीं किया जा रहा।' इस पत्र ने भारतीयों से अनुग्रह किया कि सरकार का जापान देना छोड़िय तथा अपना उद्धार स्वयं आप कीजिए। इस पत्र की राय में आत्मचेष्टा का एक प्रभावशाली पग था, बहिष्कार। अतः इस पत्र ने भारतीयों से अपील की कि आइए हम संगठित हो जाएं, हम दृढ़ निश्चय करें कि हम माचेस्टर के वस्त्र धारण नहीं करेंगे। यदि हम यह सब कर लें तो सरकार के मकड़ों फैक्टरी कानून हमारे उद्योगों का बाल भी काट नहीं कर सकते। हा, यह दूसरी बात है कि सरकार स्वयं ही हमारे उद्योगों को बंद करने का साहसिक पग उठा ले।

इस माचेस्टर के व्यापारियों को भारत में आपास न लेने दे।¹⁶

1891 का फैक्टरी ऐक्ट और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

मिन के सम्चारियों की सुरक्षा के लिए बने 1881 के इंडियन फैक्टरी ऐक्ट की अपर्याप्तता ने इसके पाम होने के तुरंत बाद ही उसमें संशोधन के लिए आंदोलन को और अधिक भड़काया। स्पष्ट कारणों से लोकोपकारी महानुभाव तो कानून को व्यवस्थाओं से नितांत

असंतुष्ट थे ही, फिर यह ऐक्ट लंकाशायर के उत्पादकों को भी संतुष्ट न कर पाया क्योंकि वे भारत में बढ़ते हुए सूती वस्त्र उत्पादन तथा भारत में ब्रिटिश वस्त्र के निरंतर गिरते आयात के कारण घबराए हुए थे।

1882 में बंबई सरकार ने अंगरेजी कारखानों के इन्स्पेक्टर मीडे किंग को बंबई प्रांत में कारखानों की कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किया। उसने कारखानों में बहुत सारी गलत बातों को प्रचलित पाया और वर्तमान कानून को अपर्याप्त घोषित किया।⁶⁹ उसने स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए। 23 मई 1884 को बंबई सरकार ने सुझावों की व्यावहारिकता के अध्ययन के लिए और गमसन विषय पर पूर्ण विचार के लिए एक अन्य आयोग की नियुक्ति की। आयुक्तों ने, जिनमें चार मिल-मालिकों के प्रतिनिधि थे,— मूल कानून में मशोधन की सिफारिश की। उन्होंने निम्न-लिखित व्यवस्थाएँ जोड़ने का सुझाव दिया बच्चों के और स्त्रियों के काम के घंटों की अधिकतम सीमा क्रमशः 9½ और 11½ घंटे निर्धारित हों। उन्हें महीने में चार दिनों का अवकाश मिले। बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 9 और 14 वर्षों तक बढ़ाई जाए।⁷⁰ भारत सरकार को आयोग का प्रतिवेदन कार्यवाही करने के लिए भेजा गया परंतु वह वर्तमान कानून में सामान्य मशोधन में सहमत नहीं थी अतः उसने उस समय इस मसूदा में आगे और कोई भी कार्यवाही नहीं की।⁷¹

परंतु मामला यही रुक नहीं गया। एक बार फिर इंग्लैंड में एक तीव्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसकी मांग थी कि भारत में कठोर इंग्लिश फैक्टरी कानून लागू किया जाए। संसद सदस्यों ने बार-बार हाउस आफ कामंस में और उसके बाहर इस विषय को दोहराया। वाणिज्य मंडल को यह तथ्य जानकर भारी निराशा हुई थी कि भारत में कपास कर हटाने पर भी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। अतः उन्होंने राज्य सचिव में अनवरत रूप में मांग की और उसके बदले में राज्य सचिव ने भारत सरकार पर इस मसूदा में कार्यवाही करने के लिए निरंतर दबाव डाला।⁷²

इस समय इस स्थिति में एक नया तत्व देखने में आया। उस समय न्याय और अधिकार के स्थान पर उपकार और मानवता की दृष्टि दते हुए नितान्त दबे स्वर में श्रमिक धीरे-धीरे स्वयं ही अपनी मांगें पेश करने लगे। इसके साथ ही उन मांगों का रूप सरकार में आगे आने और श्रमिकों की सहायता करने की विनीत विनितियों का था। मजदूरों द्वारा अथवा मजदूरों की ओर से संचालित आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत एन० एम० लोखंडे थे। उन्होंने 1880 में 'दीन बंधु' नाम से एक ऐंग्लो-मराठी साप्ताहिक पत्र चलाया और कारखानों के कर्मचारियों के हितों को ही उस पत्र का उद्देश्य बना दिया।⁷³ उन्होंने नवंबर 1884 में बंबई के कपड़ा कारखानों के कर्मचारियों के दो सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें कर्मचारियों ने सर्वसम्मति में निम्नलिखित मांगों के प्रस्ताव स्वीकार किए : सभी कारखानों के कर्मचारियों के लिए रविवार का अवकाश रहना चाहिए। सभी कर्मचारियों के काम के घंटों की सीमा प्रातः 6½ बजे से सूर्यास्त तक रहनी चाहिए। दोपहर को आधे घंटे के अवकाश की व्यवस्था रहनी चाहिए। पिछले महीने के श्रम का उपाजित

चेतन अगले महीने की 15 तारीख को मिल जाना चाहिए। औद्योगिक दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। इन मांगों को 5500 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन में सम्मिलित किया गया था और उस ज्ञापन को उस समय अपने को श्रमिक संघ के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले लोखडे ने अक्टूबर 1884 में बंबई फैक्टरी आयोग को भेजा था।⁷⁴ परवर्ती मात वर्षों में लोखडे तथा अन्य महानुभाव सम्मेलनों और ज्ञापनों के द्वारा श्रमिकों की मांगों पर कानून बनाने के लिए सरकार पर बराबर दबाव डालते रहे।⁷⁵ लोखडे के प्रयास को भारत में प्रबल श्रम आंदोलन का प्रारंभिक रूप मानना भ्रान्तिमूलक होगा क्योंकि वास्तव में यह आंदोलन कदापि न था।⁷⁶ जैसा कि उनकी पत्रिका के शीर्षक के शब्दार्थ में ही घोषित है, लोखडे महोदय श्रमिकों के मज्ठक नेता नहीं थे, वह तो केवल श्रमिकों के हितेच्छु मित्र थे।⁷⁷ अतः लोखडे को न तो क्रांतिकारी नेता माना गया और न ही उन्हें किसी प्रकार सरकार द्वारा दंडित किया गया। जबकि नील उद्योग में संबंधित आंदोलन के आयोजकों तथा मजदूरों को दंडित किया गया था, उन्हें 1890 के फैक्टरी कमीशन का स्थानीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया।

इस संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब कभी भारत में फैक्टरी कानून जारी करने के लिए इंग्लैंड में आंदोलन छिड़ा, भारतीय और ब्रिटिश उत्पादकों ने भारत में राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध तत्काल प्रबल जवाबी आंदोलन छोट दिया। उनके द्वारा प्रस्थापित तर्क था भारतीय श्रमिकों को किसी प्रकार के कानूनी संरक्षण की अपेक्षा नहीं। किसी भी प्रकार के नए कानून में देश के शिशु उद्योगों के क्षतिग्रस्त होने की ही संभावना है। अतः इस प्रकार के नाजुक मामले में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।⁷⁸

इस ओर से एक दबाव और उस ओर से दूसरे दबाव में आकुल-व्याकुल भारत सरकार ने अंततः 1881 के फैक्टरी ऐक्ट में संशोधन के लिए 31 जनवरी 1890 में लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक बिल पेश किया।⁷⁹ संशोधन की व्यवस्थाएँ इंडियन फैक्टरी कानून को इंग्लिश फैक्टरी कानूनों के समक्ष बनाने में पर्याप्त नहीं थी। इस अंतर ने एक बार पुनः इंग्लैंड के दबाव डालने वाले वर्गों को असंतुष्ट कर दिया और वे अधिक संशक्त प्रावधानों के लिए पुनः मघपरेत हो गए।⁸⁰ मार्च 1890 में बर्लिन में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के निर्णयों में उनके आंदोलन को और प्रोत्साहन मिला।⁸¹ फलतः राज्य मंचित ने, जिन्होंने पहले बिल के प्रारूप को स्वीकृति दी थी, अब अपेक्षाकृत अधिक कठोर पग उठाने के लिए और एक अन्य आयोग को नियुक्त करने के लिए दबाव डाला।⁸² भारत सरकार ने बंबई बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध के कारखानों में नियुक्त श्रमिकों की स्थितियों की जाच-पड़ताल के लिए सितंबर 1890 में एक अन्य आयोग की नियुक्ति की।

कमीशन की सिफारिशें इस प्रकार थी एक महिला श्रमिकों के दैनिक कार्यकाल की सीमा 11 घंटे निर्धारित की जाए। बच्चों के काम के समय की सीमा घटा कर 6½ घंटे प्रतिदिन कर दी जाए। सभी कर्मचारियों के लिए, इनमें वयस्क पुरुषों को भी सम्मिलित किया गया था, एक दिन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की जाए। सभी

बयस्कों को 12 और 1 के बीच आधे घंटे का अवकाश दिया जाए। एम० एम० बंगाली को छोड़कर अन्य सदस्यों की सिफारिश थी कि स्त्रियों के काम के घंटों को निर्धारित सीमा में छूट दे देनी चाहिए यदि यह स्वयं महिलाओं के हितों के लिए आवश्यक हो। इस कमीशन ने बयस्क पुरुष के काम करने के घंटों के संबंध में हस्तक्षेप करने में उनकार कर दिया।⁸³

जहां भारतीय उद्योगपतियों ने कमीशन के विचार विमर्श पर सताए पत्र किया और आगा प्रकट की कि यह श्रमिकों के मामलों में कानून विपर्यय यह अंश हस्तक्षेप होगा,⁸⁴ वहां इंग्लैंड के आंदोलनकारी और भारत सचिव अभी असंतुष्ट थे और उन्होंने और अधिक परिवर्तनों के लिए दबाव डाला।⁸⁵ उनके विचार में कमीशन की सिफारिशें कारखाना कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में बहुत ही कम थी।⁸⁶

आयोग की सिफारिशों और भारत सरकार तथा भारत सचिव के मध्य हुए पत्र व्यवहार की रोशनी में बिल की व्यवस्थाओं के प्रावधानों का नया रूप दिया गया और इसे इंडियन फैक्टरी (संगोधन) अधिनियम 1891 का नाम देकर 19 मार्च 1891 को पास कर दिया गया। यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता था जहाँ बिजली का प्रयोग करते थे, पचास अथवा उसमें अधिक मख्या म धूम्रपान को नियुक्त करने थे तथा वर्ष में एक सौ बीस अथवा उसमें भी अधिक दिन काम करते थे। उसमें प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में एक दिन के पूर्ण अवकाश की तथा प्रतिदिन दोपहर का आधे घंटे का अवकाश की व्यवस्था थी। महिलाओं के प्रतिदिन के काम के घंटे 11 निर्धारित थे उनमें, विश्राम के लिए 1½ घंटे का अवकाश भी जुटा हुआ था, बंगाल के सिपटो में चलन वाले कारखानों को छोड़कर अन्य महिलाओं का रात में काम करने की अनुमति नहीं थी। बच्चों की न्यूनतम आयु भीमा 9 और अधिकतम 14 निर्धारित की गई। शिशु भी एक दिन उनके काम के घंटों की सीमा 7 निर्धारित कर दी गई। स्थानीय सरकारों का सफाई और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिमानों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया।⁸⁷

यह यही उल्लेखनीय है कि एक बार फिर छोट और मांसमी कारखाने जिनमें स्थिति अत्यंत गंभीर थी, कानून के हाथ में बच गए। इसके साथ ही लोहापारियों की सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 11 घंटे प्रतिदिन कार्य भीमा की मांग, दुधदनाओं में क्षतिपूर्ति की मांग तथा बीमारी की हालत में डाक्टरों सहायता की मांग भी स्वीकार नहीं हुई।⁸⁸ इसके अतिरिक्त कारखानों के निरीक्षण की पद्धति भी दोगुनी बनी गयी इसके फलस्वरूप फैक्टरी ऐक्ट की व्यवस्थाओं का नियमित रूप में उल्लेख होता रहा।⁸⁹

1891 के फैक्टरी अधिनियम की व्यवस्थाओं में फिर भी लकाशायर का पंजीपति प्रमत्त नहीं हुए। आगामी वर्षों में उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा, जिसमें बड़ी के पटमन उत्पादक भी सम्मिलित हो गए।⁹⁰ 1891 के पश्चात तो इंग्लैंड में भारत सरकार के पक्ष की समर्थक शक्तियां भी अपना रूप दिखाने लगी।⁹¹ इसका कारण कदाचित प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष रूप में भारत के औद्योगिक उद्यमों में निवेशित भारी पूंजीवालों अथवा पूंजी के निवेश की योजना में सलग्न लोगों की बढ़ती हुई प्रबलता थी। भारत में अगले कुछ वर्षों में इस दिशा में लोकोपकारियों का प्रयास कमजोर होता दिखाई दिया

जनवरी मितवर 1905 में 'टाइम्स आफ इंडिया' ने इस प्रश्न को फिर उठाया।¹⁴

यम कानून में सर्वाधिक विविध विषयों के संबंध में राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया अफ़रागत मालिकों के अनुकूल थी और उसमें श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का अभाव था। राष्ट्रवादियों द्वारा श्रम कानून की किसी भी आवश्यकता को नकारा गया और कारखानों के आंतरिक मामलों में कानूनी हस्तक्षेप की व्यवस्था करने के सरकारी और निजी व्यक्तियों के प्रयत्नों पर आपत्ति की गई।¹⁵ मगटा के 26 अक्टूबर 1890 के अंक में इस दृष्टिकोण की सामान्य प्रवृत्ति का संक्षिप्त और सम्यक् विवेचन एक स्तम्भ लेखक ने इस प्रकार किया इलाहाबाद के समाचारपत्र के वक्तव्य में पर्याप्त सत्य है कि आवश्यकता में अधिक अच्छे और कठोर विनियमों में बड़े ब्रिटिश श्रमिकों के समान भारतीय श्रमिक के हाथ-पाव बंध जाने पर जो स्थिति होती वर्तमान परिस्थितियों में उनकी स्थिति उसमें तो अच्छी ही है।

यह राष्ट्रवादी समीक्षकों ने 1890 के फैक्टरी कमीशन की सिफारिशों का स्वागत प्रमुखतः इस आधार पर किया कि वे परिमित, व्यापक तथा समुपयुक्त थी। अथवा दूसरे शब्दों में वे सिफारिशें उद्योग और उद्योगशक्तियों के हितों को दुष्टभावित नहीं करती थी तथा नितान्त हानिरहित थी।¹⁶ यही कारण है कि राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने 1890 के बिल के प्रारूप की तथा 1892 के ऐक्ट की पहल में तो सर्वथा आलोचना की ही नहीं और यदि की भी तो मात्र चलताऊ।¹⁷ इसके साथ ही मालिक लोग पहले से ही विचार की बहुत सारी व्यवस्थाओं तथा ऐक्ट को स्वीकार कर चुके थे। अतः कानून का यह अंग मात्र माचेस्टर की पराजय के रूप में ग्रहण किया गया।¹⁸ उनका एकमात्र भय यह था कि उत्पादकों पर अपेक्षाकृत अधिक कठोर कानून थोपने की दिशा में यह उद्देश्य रचित कानून एक शुरुआत का काम न दे।¹⁹ इसके साथ ही राष्ट्रवादियों के इस वर्ग का यह दृढ़ मत था कि कारखानों का श्रमिक किसी दुख पीड़ा का शिकार नहीं है और वह सुख तथा मनोप का जीवन व्यतीत कर रहा है। वस्तुतः हिंदू ने 17 मई 1889 के अंक में यहाँ तक लिखा कारखानों के कर्मचारियों की तमाकथित कठिनाइयों की कहानी मन-गढ़त है।²⁰ नेटिव ओपीनियन ने 15 मई 1890 के अंक में इसी भावना को दार्शनिक रंग दे वाला 'इसमें सदेह नहीं कि बंगाल और बंबई प्रांतों के कारखानों के कर्मचारियों की स्थिति इंग्लैंड के कारखानों के कर्मचारियों की स्थिति से बेहतर है, इस आधार पर नहीं कि उनके वेतन ऊँचे हैं प्रत्युत इस आधार पर कि अपेक्षाकृत उनकी आदतें सरल हैं, उनकी आवश्यकताएँ कम हैं, उनका भोजन सस्ता है और उन्हें कठोर सर्दियोंवाले वातावरण से बचाव के लिए महंगे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है।²¹ बंबई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, बंबई के ग्रांट मैडिकल कालेज के प्रोफेसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई के अग्रगण्य नेता के० एन० बहादुरजी एम० डी० (नंदन) ने 1891 में लिखे एक वैज्ञानिक लेख में निष्कर्ष रूप से कहा कि भारतीय कारखानों के श्रमिकों का शारीरिक दशा पूर्णतः संतोष-प्रद है। उनके स्वास्थ्य और शरीर में किसी प्रकार के ह्रास अथवा क्षीणता के कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते। महिला श्रमिक तो विशेष रूप से स्वस्थ तथा पुष्ट हैं। उन्होंने किसी प्रकार के प्रतिबंधनशील फैक्टरी कानून लागू करने का विरोध किया, यहाँ तक कि

उन रुई पीजने-धुनने-कातने के कारखानों में भी नहीं, जिनके बारे में उन्होंने दबी जबान से स्वीकार किया कि वहाँ काम कभी कभी कठोर होता था।¹⁰⁰

राष्ट्रवादी नेताओं का यह वर्ग तो विशेष रूप से ही वयस्क पुरुष श्रमिकों के काम के घंटों को सीमित करने के विरुद्ध था। इस वर्ग ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि भारतीय श्रमिक काम से दबे हुए हैं अथवा उन्हें अधिक लंबे और कठोर घंटों तक काम करना पड़ता है। इन नेताओं के अनुसार सतही तौर पर जो दिखाई देता है, व्यवहार में वास्तविक सत्य वह नहीं है। मराठा ने 20 दिसंबर 1888 के अंक में लिखा कि विचारणीय तथ्य यह है कि भारतीय श्रमिक का मौज-मजे से काम करने का एक अपना ढंग है। आप उसे घंटों लगातार काम पर लगाए रखिए फिर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि वह अपने को काम में दबा अनुभव नहीं कर रहा। वह बीच बीच में काम छोड़कर बाहर जाने और आराम करने का अवसर निकाल ही लेगा।¹⁰¹ 18 जनवरी 1889 के 'सुलभ समाचार' और 'कुशदाह' पत्रों के अनुसार तो भारतीय कारखानों के काम के घंटे उष्णकटिबंधीय देश के अनुकूल है और विदेशी माथी की अपेक्षा अधिक तटस्थ श्रमशील और सहनशील भारतीय श्रमिक की प्रकृति के भी सर्वथा अनुकूल है।¹⁰² इसके अनिरिक्त जोर देकर यह कहा गया कि काम के अपेक्षाकृत थोड़े घंटे स्वयं श्रमिकों के ही हित में नहीं होंगे क्योंकि इसे घपाने का अर्थ उनके वेतन को नीचे लाना होगा।¹⁰³

एक दिन के माप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था का बहुत ही कम विरोध हुआ। इसका प्रमुख कारण, जैसा कि पहले बता चुके हैं, यह था कि मालिक लोग पहले ही जून 1890 में इसे मान्यता दे चुके थे।¹⁰⁴

महिला श्रमिकों की नियुक्ति संबंधी व्यवस्था के विरुद्ध राष्ट्रवादियों की आपर्ण सचमुच अत्यंत आश्चर्यजनक थी। समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा 'एज आफ कानसेंट बिल' की आयु के प्रबल तथा उत्साही समर्थक 'इंदु प्रकाश' ने इस संबंध में इस प्रकार अपना विचार प्रकट किया - 'यह दुख की बात है कि सरकार ने भारतीय कारखानों में महिलाओं की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना उपयुक्त समझा। नई व्यवस्था के अनुसार उन्हें रात को काम देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा अनुमत काम के 11 घंटों में उन्हें एक बहुत लंबे समय तक विश्राम के लिए अनिवार्य रूप से अवकाश की व्यवस्था की गई है।'¹⁰⁵ अधिक रूढ़िवादी 'मराठा' भी इन समाज सुधारकों से पीछे नहीं रहा। उसने अपना मत प्रकट करते हुए 7 दिसंबर 1890 को लिखा 'आयुक्तों ने अपने प्रतिवेदन में यह कही भी नहीं लिखा कि काम के अप्रतिवाधित घंटों के कारण भारतीय कारखानों में काम करने वाली महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है अतः हमारे विचार में सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।' बाद में जब मार्च 1892 में यह समाचार मिला कि अहमदाबाद में महिला श्रमिकों की छटनी की जा रही है तो राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने यह मांग की कि फैक्टरी ऐक्ट की महिलाओं के काम के घंटों को सीमित करने वाली धारा को महिलाओं के हित की दृष्टि में स्थगित कर देना चाहिए।¹⁰⁶ परंतु उनमें से किसी एक भी समाचारपत्र ने मालिकों को इस स्वार्थपूर्ण कार्यवाही को करने में निवृत्त होने के लिए

उनकी आलोचना करने अथवा उन्हें सलाह देने के रूप में एक शब्द भी नहीं लिखा।

इसी प्रकार कारखानों में नियुक्त किए जाने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु बढ़ाने और उनके काम के घटे घटाने की व्यवस्थाओं का भी विरोध इस आधार पर किया गया कि इसका परिणाम निर्धन श्रमिकों की पारिवारिक आय में कटौती होगा।¹⁰⁹ 'मुग्धि ओ पतावा' ने 10 अप्रैल 1891 के अंक में शोकाकुल भाषा में लिखा कि इस व्यवस्था के पश्चात् स्वस्थ लड़की-लड़के अपने विकलांग माता पिता की सहायता नहीं कर पाएंगे।¹⁰⁸ एक बहुत पुराना तर्क, काम न करने वाले बच्चे अपराधी बन जाते हैं, भी इस समय पुन दोहराया गया। भारत में समाज सुधार में अग्रणी हिंदू ने 16 मिनबर 1891 के अंक में लिखा हमारी कल की आशाएँ, श्रमिक बच्चे, या तो अपने माता-पिता की सहायता के लिए श्रमार्थ में मग्न रहेंगे, अथवा अपने खाली समय में पुर्लिस और अपराध शाखा के अधिकाधिकारियों के लिए नए नए आविष्कार करेंगे। कारखाने तो अधिकांशतः उन बच्चा को नम्रानप्रद मार्ग में बचाने हैं।¹¹¹

राष्ट्रवादी नेताओं के उस वर्ग की यह निर्दिष्ट धारणा थी कि नए फैक्टरी कानून का अंतिम परिणाम श्रमिकों की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा प्रत्युत इसमें भारत में विकासशील वस्त्र उद्योग का विनाश हो जाएगा।¹¹⁰ यह भी एक मजे की बात है कि कांग्रेस के मंच में श्रमिक पक्ष की बात केवल एक बार उस समय उठाई गई जब 1895 में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुरेन्द्रनाथ बैंतर्मी ने काम के घटो पर प्रतिबन्ध लगाने वान और उत्पादन व्यय में वृद्धि करने वान फैक्टरी कानून के प्रयोग के विरुद्ध चलावनी दी। उन्होंने यह भी निर्देश किया कि यहाँ तक कि इंग्लैंड के अनिर्गन्त जापान भी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का प्रबल प्रतिद्वंद्वी है।¹¹¹ इसमें अतिरिक्त राष्ट्रवादियों ने अनभव किया कि यदि भारतीय उद्योग पशु हो गया तो उसमें श्रमिक ही सबसे अधिक घाट में रहेंगे क्योंकि वे बेचारे आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन ग्राहेंगे। 10 जनवरी 1900 के अंक में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने इस दृष्टिकोण का संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया ऋपापूर्वक, निरपेक्ष भाव से श्रमिकों के काम के घटे घटाने और उन्हें एक दिन का मासार्थिक अवकाश देने की वकालत करने वाले परोपकारी लोग क्या मिलो के बद हो जाने पर इन श्रमिकों का अपनी जेब से पालन-पोषण करेंगे? भारत की आवश्यकता है अनाज की पर्याप्तता और उसके लिए भारतीय कुछ भी करेंगे। 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करना भी अधिक नहीं है।¹¹²

1881 के फैक्टरी कानून के समान ही 1891 में फैक्टरी कानून के लिए आंदोलन की राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकृति के पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा था कि यह सब कुचले हुए भारतीय श्रमिकों की शुभकामना की भावना से प्रेरित न होकर लकाशायर की अपने प्रतिद्वंद्वी भारत का गला घोटने की भावना से ही प्रेरित था।¹¹³ बंगाली ने अपने 27 अप्रैल, 1889 के अंक में इसे सचित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा कि वस्तुतः लकाशायर के उत्पादक और परोपकारी लोग भारत के प्रति ठीक उसी प्रकार की हितकामना की भावना रखते हैं जैसी एक जंगली पशु में अपने शिकार के प्रति होती है। वस्तुतः श्रम कानून उस नीति की परंपरा में है जिसके अंतर्गत पहले ही कपास पर

सीमा शुल्क को हटाकर भारत पर मुक्त व्यापार थोपा गया था।¹¹⁴

हा, कई एक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने कारखाना कर्मचारियों की मांगों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया तथा उन्होंने मिलमालिकों से उन मांगों से अपेक्षाकृत अधिक उचित मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस दिशा में एक समय फैक्टरी कानून के तीव्र समीक्षक 'मराठा' ने नेतृत्व दिया। 'मराठा' तथा इस समय के कुछ अन्य समाचारपत्रों के इस डावाडोल व्यवहार का विश्लेषण सामान्यतः उन पत्रों के संपादकों अथवा मालिकों के परिवर्तन में निहित है।¹¹⁵ इन 'असहमत' राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित श्रमिकों की एक मांग थी, उनके काम के घंटों में कटौती।¹¹⁶ यहाँ हमें 9 अथवा 8½ घंटे के कार्य दिवस रखने के क्रांतिकारी सुझाव देखने को मिलते हैं।¹¹⁷ और इस क्रांतिकारी सुझाव का कम से कम एक रूप में तो वर्ग संघर्ष की जानकारी पर और राज्य के लोक हितकारी दायित्व पर आधृत क्रांतिकारी दार्शनिक विचारधारा द्वारा समर्थन किया गया। इस प्रकार मराठा ने 1 जुलाई 1888 के अंक में निम्नलिखित संपादकीय टिप्पणी लिखी 'अपने कर्मचारियों अथवा नौकरों से यथासंभव अधिकतम काम लेना तो मालिकों की स्वभावगत प्रवृत्ति है। गरीब नौकरों का भी पैसा पाने के लिए मालिकों की इच्छा के अनुसार स्वास रहने तक जीतोड़ परिश्रम करने पर तैयार होना संभव है। अतः राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। कारखानों में नियुक्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, एक दिन का साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन काम के समय में कम से कम विश्राम के लिए आधे घंटे का अंतराल, डाक्टरों की देखभाल, कारखानों के निकट रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण, वेतन का साप्ताहिक अथवा कम से कम मासिक भुगतान आदि इन राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित कुछ अन्य मांगें थी।¹¹⁸

भारतीय खान अधिनियम, 1901

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक खान उद्योगों में काम को नियमित करने वाला कोई कानून नहीं था। उस समय जहाँ तक नौकरी की मात्रा का संबंध था, खान उद्योगों में कोयला खानों की प्रमुखता थी। 1900-01 में कोयला खानों में 6 टन कोयले का उत्पादन हुआ और 89,248 व्यक्ति नियुक्त थे।¹¹⁹ कोयला खानों का विशेष पक्ष यह था कि भूमिस्थ खानों में महिलाओं और बच्चों का भी व्यापक रूप में नियुक्त किया जाता था।¹²⁰ इसका अतिरिक्त कोयला खानों में साथ साथ सभी खानों के कर्मचारियों की दशा अत्यंत खराब, वस्तुतः शोचनीय और दयनीय, थी।¹²¹ खान उद्योगों में उद्वेगजनक गंदगी का अतिरिक्त उचित सावधानियों के अभाव के कारण दुर्घटनाओं की संभावना थी। इतने पर भी इन कोयला खानों के श्रमिकों की दुर्भाग्यग्रस्त दशा की ओर सरकार का ध्यान पहले इसलिए नहीं गया कि एक तो भारतीय कोयला खान उद्योग की विदेश से किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं थी। दूसरे, इसके अधिकांश पर विदेशियों का स्वामित्व था।¹²² इस क्षेत्र में गिने चुने कुछ भारतीय व्यवसाय संघ भी थे परंतु उनकी गतिविधि छोटी और साधारण कोयला खानों तक ही सीमित थी।¹²³

अनन 1899 में भारत सरकार ने लैबरनेटिव कौंसिल में इंडियन माइंस बिल पेश

किया जो अतः मे '1901 के इंडियन माइम ऐक्ट' के रूप में सामने आया। यह कानून अत्यंत कोमल था, इसने बेमन से ही, खानों के निरीक्षण को और महिलाओं तथा बच्चों की नियुक्ति को नियमित करने का प्रयत्न किया।¹²⁴

प्रयोजन विशेष से निर्मित अविनियम की व्यवस्थाएँ यद्यपि इस सीमित और कठिन कार्य की पूर्णतः पूर्णतः अपथात् थी तथापि इस पर विचार अभिव्यक्त करने वाले सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया। उनके विरोध के आधार लगभग वही थे जो फैक्टरी कानून के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए थे। एक बार फिर खानों जैसे शिशु उद्योग के लिए किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता को नकारा गया और खान में काम करने वालों की स्थिति को सुतापप्रद घोषित किया गया।¹²⁵ यह कम विस्मय की बात नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उसमें योग दिया। उसने 1901 में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें खान बिल में श्रमिका की नियुक्ति पर प्रतिबंधों से संबंधित व्यवस्थाओं को हटाने का सुझाव दिया गया था।¹²⁶ इस प्रस्ताव के प्रस्तावित भूषेन्द्रनाथ बसु ने यह अवश्य स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव वगलान खान मालिका के मध्य की गार्हत्या पर ही पाठित किया जा रहा है। उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि उन्होंने महिलाओं द्वारा बच्चा का भ्रूणभ में अपने साथ ले जाना ही मनाही करने वाली व्यवस्था का विरोध किया और धापणा की कि 14 वर्ष में अधिक आयुवान का बच्चा मानना ज्यादाती है क्योंकि इस आयु में तो भारतीय महिला मा बग जाती है। उन्होंने निरीक्षकों की नियुक्ति का भी उस आधार पर विरोध किया कि वे खान मालिका के लिए आनर वन जाएंगे।¹²⁷

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा 1891 के इंडियन फैक्टरी ऐक्ट के संबंध में अभिव्यक्त तर्कों का भ्रूणभ में श्रमियों और बच्चा की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंधों के संबंध में भी उपयोग किया।¹²⁸ 4 और 10 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को भ्रूणभ में ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाली 1899 के बिल की धाराओं पर राष्ट्रवादियों ने इस आधार पर आक्रमण किया कि उसमें परंपरागत पारिवारिक संबंध छिन्न भिन्न हो जाएंगे।¹²⁹ एक प्रिमा पिया तक यह प्रस्तुत किया गया कि श्रमिकों ने उस प्रकार के कानून की चला कभी प्रकट ही नहीं थी।¹³⁰ 'हितवादी' ने तो उनसे 24 मार्च 1899 के अक मे निखा खान समचारी सरकार की गिन मांगी उदारता का स्वागत नहीं कर सकता। वह इस उदारता पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ जाता है महाराज आपकी दान्तालता के लिए धन्यवाद। मुझे तो आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, आप अपना निरीक्षक वापस बुला लीजिए।¹³¹

बहुत मार राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं ने योग्य प्राशिक्षित व्यक्तिता का ही गहन प्रबंधक नियुक्त किए जा सकने की व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उन्होंने बिलकुल ठीक ही निर्देश किया कि किसी उपयुक्त खान स्कूल के अभाव में योग्य प्रशिक्षित भारतीय प्रबंधक उपलब्ध ही नहीं है और भारतीयों के स्वामित्ववाली अधिकांश छोटी छोटी खान कंपनियों का बड़ी बड़ी यूरोपीयों के स्वामित्ववाली कंपनियों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इस स्थिति में वे उच्च वेतनभोगी प्रबंधकों को नियुक्त करने का भार उठा ही नहीं सकती हैं।¹³² इस संबंध में उनकी मांग थी कि देश में एक खान स्कूल खोला जाए¹³³ और जब

तक यह नहीं हो जाता, तब तक कानून की इस धारा को अस्थाई रूप से स्थगित रखा जाए।¹³⁴

भारतीय नेताओं ने पहले की ही तरह यह भय प्रकट किया कि खान कानून खान उद्योग के विशेषतः भारतीयों के स्वामित्ववाले भाग के विकास को नुकसान पहुंचाएगा।¹³⁵ उन्होंने खुले तौर पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि इसकी सरचना इंग्लैंड के कोयला उद्योग की सहायता के लिए की गई है।¹³⁶ सत्य यह है कि इस मामले में इस दोष के लिए कोई ठोस आधार नहीं था।

राष्ट्रवादी नीति का आधार

अब तक हमने श्रमिकों के पक्ष में कानूनी हस्तक्षेप के सदर्भ में भारतीय कारखानों और खान उद्योगों में नियुक्त श्रमिकों की बढ़ती समस्याओं के किसी न किसी पक्ष पर अपने विचार प्रकट करने वाले भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के बहुत बड़े वर्ग के विरोधी रुख की समीक्षा की है। इसके साथ ही हमने यह भी देखा है कि श्रमिकों की साधारण मांगों के प्रति भी थोड़े से राष्ट्रवादियों ने ही अपना समयन प्रकट किया है। हमने यह देखा कि यह विरोध न तो प्रचंड था और न ही व्यापक। लकाशायर की भूमिका का उल्लेख आने पर ही उग्रता और व्यापकता आ जाती थी। अन्यथा यह विरोध एक प्रकार में उन्माहरहित ही था। इसी प्रकार श्रमिकों की मांगों के प्रति समर्थन भी टूटे दिल में था और परिणाम-स्वरूप महत्वशून्य था। इन दोनों तथ्यों की दृष्टि भारत सरकार की गतिविधियों की मालिकों के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति से तथा भारत सरकार द्वारा लाए गए बिलों अथवा कानूनों की मालिकों की दृष्टि में साधारण प्रवृत्ति से हो जाती है। बंबई मिलमालिक संघ के 1891 के वर्ष के प्रतिवेदन से इस तथ्य का समर्थन होता है। 1891 के फैक्टरी ऐक्ट को उद्धृत करते हुए प्रतिवेदन में कहा गया है 'ये परिवर्तन संघ के सदस्यों द्वारा पहले से ही समर्थित दृष्टिकोणों के बाहर नहीं जाते। अतः बिल पर विचार विमर्श करते समय किसी प्रकार का शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं।'¹³⁷ मुभाए गए अथवा कानून का रूप दिए गए अधिकांश उपायों की मालिकों द्वारा स्वीकृति के तथ्य को समकालीन कई समाचारपत्रों ने भी अनुभव किया।¹³⁸ 1885 के बांबे फैक्टरी कमीशन के जांच परिणामों के, 1890 के फैक्टरी कमीशन की गिफारिशों के और 1890 के फैक्टरी अधिनियम के मालिकों द्वारा किए गए अधिकृत समर्थन में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया विरोध मालिकों के प्रति वफादारी का एक विचित्र रूप है।¹³⁹

भारतीय नेताओं द्वारा प्रस्तावित अथवा वास्तविक श्रम कानून का जो समर्थन अथवा विरोध हुआ उससे बढ़कर अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कारखानों तथा खानों के कर्मचारियों के अत्यंत दलित वर्ग के प्रति इन नेताओं में सक्रिय सहानुभूति का लगभग पूर्ण अभाव था। राष्ट्रवादी आर्थिक चिन्तन के समर्थक किसी भी महानुभाव ने इस विषय में लगभग कुछ भी नहीं कहा। भारतीय राजनीति में न्यायमूर्ति के रूप में विख्यात तथा समाजसुधारकों में अग्रगण्य गान्धे श्रमिक वर्ग के दुभाग्य पर पूर्णतः मौन थे।¹⁴⁰ भारतीयों

की निर्धनता पर द्रवित होने वाले बीमल हृदय दादाभाई नौरोजी ने भी कारखाना श्रमिकों के जीवन के निम्न स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी विश्वकोशीय बुद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक श्रेणी व। माधवार विवेचन करने वाले जी० वी० जोशी ने भी श्रमिक आर्थिकता की ओर ध्यान नहीं दिया। आर० सी० दन ने अपने अतिविस्तृत महत्वपूर्ण ग्रंथ इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया' में अथवा अपने अनक सार्वजनिक भाषणों में तथा असंख्य लेखों में कारखानों के श्रमिकों के संबंध में एक शब्द भी नहीं लिखा या कहा। 19 वीं शताब्दी के जन नरु 'हिंदू' के संपादक जी० मुत्रमनिया अथवा तो न्यनाधिक रूप से कारखानों के श्रमिकों के हितों के विरुद्ध ही थे। जी० के० गोखले ने आगे प्रसिद्ध सार्वजनिक अथवा सभादीय भाषणों में इन श्रमिकों की कठिनाइयों पर कुछ भी नहीं कहा।¹¹¹ सुरेन्द्रनाथ वेनर्जी के भाषणों में श्रमिक समस्या का एकमात्र उल्लेख उनकी कारखानों व श्रमिकों के दुख-कष्टों के प्रति नितान्त सहानुभूति-हीनता का ही प्रकट करना है।¹¹² इसके अतिरिक्त उनके द्वारा संपादित वंशाही सामान्यतया फैक्टरी कानून का विरोधी था। अखिल भारतीय कांग्रेस में भी कारखाना श्रमिकों की दुर्दशा में संबंधित वर्ग प्रस्ताव पास नहीं किया। वस्तुतः खान बानून में संबंधित कांग्रेस द्वारा पारित 'जाय प्रस्ताव' श्रमिक विरोधी ही था। अधिकांश प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्र अमृत बाजार पत्रिका हिंदू मगरा, वंगरी, टुडू प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, नेटिव ओपीनियन, एडवाइजर, इत्यादि श्रमिकों के संबंध में या तो मौन रहे अथवा उन्होंने शत्रुतापूर्ण बर्ताव किया। सामान्य स्थिति में राष्ट्रवादी नेताओं के इस पूर्ण मौन भाव की वजह से बिना उपेक्षा ही की जाती परन्तु उस अवधि में जबकि श्रमिकों की स्थिति मनुष्य शास्त्रीय और हृदयविदारक थी तथा उस समय ही उनकी दुर्भाग्यग्रस्त स्थिति अपने गंभीर स्वरूप में प्रकट हुई। 1881-1891 की मध्य की अवधि की एक सार्वजनिक जनता समस्या थी, लाक-नेताओं का मौन यदि हमें समझ में नहीं आता अर्थपूर्ण अवश्य है। जंग बागी की बहुत जरूरत होती है तथा मौन स्वतः सुगम हो उठता है। यदि और कुछ नहीं तो कारखानों और खानों में हाइड्रोड्राम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा तथा वंगला के अग्रणी ब्रह्म-समाजियों, बंबई और मद्रास के मुत्तायों, गुना के पगारियादियों और लाहौर के आर्य-समाजियों के मन में काय ही उत्पन्न भवता। उस दशासीनता का विश्लेषण जस्टिस गनाडे के लेखों में एक विरल वाक्य में मिल जाता है। उन्होंने अपने निबंध 'दिरआंग-नाउजेशन आफ रिसल क्रेडिट इन इंडिया', में लिखा कि भारत में फैक्टरी कानून यद्यपि अपनी प्रणाली तथा प्रभाव में उपयोगी है तथापि भारत में यह मानवीयता के मागर में एक बृद्ध के समान है।¹¹³ परन्तु हमारा विश्वास है भारतीय नेताओं के दृष्टिकोण की सम्भव व्याख्या यह है कि भारतीय नेताओं का ही उद्योगीकरण के उद्यम के प्रति समग्र और अविभाजित समर्थन का भाव या जिम्मेदार उत्पादन की योगित कारखाना पद्धति के प्रचलन में उत्पन्न हो रही कुशाग्र के प्रति सर्वथा अंधा बना दिया था। उन्होंने जनता की बढ़ती हुई सामान्य दृष्टि का, राजीविका के, गांधीवादी शीर्षक हो रहे साधनों के और पृथ्वी पर आभार का अर्थ दसा के निगमों का एकमात्र उपाय देश के उद्योगीकरण के रूप में देखा और उससे द्रुत विकास का निर्माण करने की फिक्र की। परन्तु इस

सबसे उन्हें निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता। उनकी इस उपेक्षा का कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने फैक्टरी कानून की प्रत्येक चेष्टा के पीछे या तो मांचेस्टर का हाथ देखा, जो बहुत ही खूले तौर पर नजर नहीं आता था अथवा विदेशी प्रतियोगिता के खतरे को देखा। उन्होंने विकासशील श्रमिक वर्ग की वस्तुगत आवश्यकताओं और हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार वे औद्योगिक पूँजीपति वर्ग के मुखिया बन गए अथवा कम से कम उनके हाथ में खेलते रहे। इसके अतिरिक्त यहाँ तक कि औद्योगिकता की समस्या को भी उन्होंने पूर्णतः और समग्रत मानिकों की आख में ही देखा। भारतीय उद्योगों की प्रतियोगी स्थिति विदेशी प्रतियोगिता में सुधार का भारतीय मानिकों द्वारा कल्पना दृष्टि तथा अधिकांश भारतीय नेताओं द्वारा समर्थित उपाय था, उत्पादन व्यय को बनाए रखना और इसके लिए अपनाए जाने वाले साधन थे, थोड़ा वेतन और काम के लंबे घंटे आदि अथवा संक्षेप में श्रमिकों से कमरतोड़ काम लेना। वस्तुतः भारतीय नेताओं ने अनकहे और परोक्षरूप से लंकाशायर के इस आरोप को स्वीकार ही कर लिया कि श्रमिकों का अत्यधिक शोषण भारतीय उद्योग को परोक्ष संरक्षण दे रहा था। भारतीय नेताओं को न तो यह सूझा कि लाभार्थ को घटाने में भारतीय उद्योग की प्रतियोगी स्थिति सुधर सकती है और न ही यह सूझा कि श्रमिकों को प्रोत्साहन देने में अथवा अन्य किसी इस प्रकार के उपायों को अपनाने में औद्योगिक उत्पादकता सुधर सकती है।¹¹⁴ वस्तुतः इस अवधि में भारतीय श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि इतनी द्रुत थी और भारतीय कारखानों को होने वाले लाभ इतने ऊँचे थे¹¹⁵ कि अंगरेज प्रतिद्वन्द्वियों के साथ भारतीय उद्योग की प्रतियोगी स्थिति को थोड़ी सी सीमा में भी दुर्बल बनाए बिना ही श्रमिकों की स्थिति में आमानी से सुधार किया जा सकता था। परंतु कालावधि में तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने आधुनिक उद्योग के हितों के रूप में समग्रत पूँजीपतियों के हितों पर ही ध्यान दिया।

निस्संदेह हम यह नहीं कहना चाहते कि उस विशिष्ट ऐतिहासिक पड़ी में और तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में भारतीय नेता कोई ऐसा पग उठाते अथवा उन्हें उठाना चाहिए था जो भारतीय समाज के उभरने दो नए वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष पनपाता। अन्य किसी प्रयोजन में न सही, राजनीतिक उद्देश्य से तो निश्चित ही देश की राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति के संघर्ष के लिए सभी देशवासियों को संगठित करना न केवल लाभप्रद प्रत्युत आवश्यक भी था। यह एक स्वतः मिथ्य सत्य है कि उस समय भारतीयों द्वारा अपनाया गया आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था और किन्हीं भी अन्य आघातों पर लोगों को विभाजित करना कदापि वांछनीय नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने इस मिथ्या की प्रस्थापना की कि कांग्रेस, सभी देशवासियों के समान रूप से प्रत्यक्ष हित के विषयों तक ही अपने को सीमित रखे और समाजसुधारों की व्यवस्था तथा अन्य वर्गीय प्रश्नों को वर्गीय सरथाओं के लिए छोड़ दे।¹¹⁶ परंतु राष्ट्रीय मंगठन के भीतर ही भीतर मतभेद, हितों में संघर्ष तथा यहाँ तक कि विवाद उठ सकते थे और उठे भी। उन विवादों को हटाने और सुलझाने में ही राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किए गए प्रयत्नों में उनका पक्षपात उभरा। मानिकों और श्रमिकों के

बीच विवाद खड़े होने पर राष्ट्रवादी नेताओं ने दोनों विवादाधीन दलों में आपनी जैन-देन के आधार पर दोनों में समझौते का कोई भी नुस्खा नहीं बनाया। वे या तो मौन रहे जिसका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक मशकत पक्ष की स्थिति का स्वीकृति के रूप में समर्थन था अथवा उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय हितों की वकालत की जिसका स्पष्ट अर्थ कारखानों और खानों के श्रमिकों के हितों की पूर्ण उपेक्षा था। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति अर्थात् भारतीय उद्योग के विकास और उनकी संपन्नता का दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग के हितों की बलि चढ़ा दी गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं ने श्रमिक हितों के विरुद्ध अन्याय विषयों में अभिशाप माने जाने वाले ब्रिटिश पूँजीपतियों और नौकरशाही के साथ सामान्य उद्देश्य अपनाने में भी संकोच नहीं किया।

1882 का बागान श्रम और अंतर्देशीय उत्खवास अधिनियम

जहाँ तक ब्रिटिश स्वामित्ववाले बागानों में नियुक्त भारतीय श्रमिकों का संबंध था, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण ठीक विपरीत था। नेताओं की स्थिति में यह पूरी की पूरी तब्दीली चाय बागान में नियुक्त, सामान्यतः असम कुली कहे जाने वाले हजारों श्रमिकों के कार्य और जीवन के प्रति अपनाए गए उनके दृष्टिकोण में जितनी स्पष्ट है, उतनी अन्यत्र नहीं। बागान श्रमिकों की दुर्दशा की ओर भारतीय नेताओं ने हार्दिक महानुभूति और पूरी तत्परता के साथ ध्यान दिया। उन्होंने क्रूर विदेशी पूँजीपतियों की भत्सना की। असुरक्षित और बेजबान श्रमिकों के दुर्भाग्य पर आसू बहाए और उत्सुकतापूर्वक उनके मामले की वकालत की। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रीय भावना का अच्छा प्रदर्शन किया तथा सामूहिक राष्ट्रीय अपमान के तथा क्षत विक्षत राष्ट्रीय गर्व के सुप्त भावों को जगाने के लिए, तथा असंख्य हृदयों में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाने के लिए कुलियों द्वारा अनुभूत दुर्भाग्य और लज्जाजनक अवहेलनाओं का सही उपयोग किया। स्थिति में यह प्रत्यावर्तन पूरी सावधानी से उठाया गया पण था क्योंकि इस मामले में मालिक विदेशी थे। 1891 में कांग्रेस के सभापति पी० आनंद चारलु ने 1901 में लैजिस्लेटिव कौंसिल में असम लेबर ऐंड इमिग्रेशन बिल पर अपने भाषण में इस दृष्टिकोण को बड़े ही विशद और संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रकट किया है :

यदि मालिक और नौकर एक ही राष्ट्र के आवश्यक अंग हों तो कदाचित् इस प्रकार के कानून के लिए आग्रह की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में भेदभाव का अवकाश थोड़ा होता है और पारस्परिक भ्रातृत्व की भावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। परंतु जहाँ इस प्रकार के पारस्परिक सद्भाव का और सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान का वातावरण न हो, इतना ही नहीं प्रत्युत स्थिति सर्वथा विपरीत हो, वहाँ एकपक्षीय प्रमादजन्य अन्यायपूर्ण प्रवृत्तियों के निवारण के लिए तथा सामयिक समझौतों के लिए इस प्रकार के कानून की एक प्रकार से अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है।¹⁴⁷

राष्ट्रीय नेताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व यह था कि असम के चाय बागान में श्रमिक इकरारनामे द्वारा अनुबंधित थे और कार्य की स्थिति सर्वथा अहितकर थी।

चाय उद्योग का भारत में वास्तविक प्रारंभ 1851 में कहा जा सकता है। इसके उपरान्त इसने तीव्र गति से विकास किया। हमारे अध्ययन की अवधि में अधिकांश चाय बागान असम में स्थित थे। 1903 में इस उद्योग में 479,000 स्थाई और 93,000 अस्थायी श्रमिक कार्यरत थे।¹⁴⁸ असम की जनसंख्या विरल होने के कारण और चाय बागान के प्रायः निर्जन पहाड़ी ढलानों पर अवस्थित होने के कारण बंगाल तथा अन्यान्य प्रांतों में अत्यधिक आवश्यकता के अनुरूप विपुल संख्या में लोगों को मंगाना पड़ता था परंतु प्रति-वर्ष हजारों श्रमिकों को अपने घरों में बहुत दूर अस्वस्थ वातावरणवाली तथा विविध रोगों से दूषित धरती पर लाना आर्थिक और अन्यान्य प्रलोभनों की व्यवस्था की अपेक्षा करना था और असम के चाय बागान के मालिक यह सब करने को प्रस्तुत नहीं थे। उनके बदले उन्होंने छल-कपट और जोर-जबरदस्ती का मार्ग ग्रहण किया। उन्होंने सरकार को दंडनीय कानून पास करके इस अपवित्र पाप कर्म में उनकी सहायता और सेवा करने के लिए मना लिया।¹⁴⁹ बस यही से असम के चाय बागान श्रमिकों के दुखों और दुर्भाग्य की कहानी आरंभ होती है। उन्हें यह जानकर घोर दुख हुआ कि विदेशी पूँजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास का परिणाम यह निकल रहा है कि उनकी आजीविका के नए माधनों की सृष्टि उन्हें परंपरागत ग्रामीण दरिद्रता की अवस्था से निकाल कर ज्वालामुखी के अनुबंधित रूप में शोषण और दुर्भाग्य की स्थिति में डाल रही है।

बंगाल के 1863 के और 1865, 1870 और 1873 में संशोधित 'ट्रांगपोर्टिंग ब्राफ नेटिव लेबरर्स ऐक्ट' (संख्या 3) की व्यवस्थाओं के अंतर्गत असम के चाय बागान के लिए श्रमिकों की भरती वर्षों तक अधिकांश ठेकेदारों द्वारा की जाती रही। यद्यपि कानून में अनुबंधित श्रमिकों के संरक्षण की अपेक्षा की गई थी क्योंकि इसमें लागूकर्ता भरती की व्यवस्था थी परंतु 1865 में यथा संशोधित अधिनियम में वास्तव में मालिकों को ही लाभ पहुंचा। इसने श्रमिकों के न केवल काम छोड़ने प्रत्युत काम करने में सुस्ती को भी दंडनीय अपराध बना दिया और साथ ही साथ मालिकों को नियुक्तिवाले क्षेत्र के जिले की सीमाओं के अंतर्गत भगाते नौकरों को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया। नौकरों को सीधे और मकरे मार्ग पर चलते रहने के लिए मालिकों ने पहले से बने अधिनियम अर्थात् 1859 के अधिनियम संख्या XIII का भी उपयोग किया जिसके अनुसार काम करने के आश्रय प्राप्त पर अग्रिम रूपों के लिए किसी श्रमिक द्वारा अनुबंध भंग, काम करने में इनकार के लिए मनुहार करना, शारीरिक रूप से दंडनीय अपराध और अर्थदंड का विषय था। मालिकों ने भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम XLV) की धारा 490 और 492 का भी उपयोग किया जिसके अनुसार यदि श्रमिक को मालिक के स्वर्ण पर कार्यस्थल पर लाया जाता है और वह मफर के बीच में अथवा कार्य के स्थान पर पहुंच कर अनुबंध तोड़ता है तो उस स्थिति में वह दंडनीय अपराध का भागी बन जाता है।

चाय बागानों की अधिक और अधिक कर्मचारियों की भूख का मिटाने में चालू

कानूनों के अपर्याप्त मिद्ध हो जाने पर भारत सरकार ने 1881 में अखिल भारतीय स्तर पर सारे प्रश्न की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। कमीशन ने प्रतिवेदन में कहा कि वर्तमान कानूनों में श्रमिकों की सुरती और कामचोरी को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि इन कानूनों से अनुबध का पालन कराना ही कठिन हो रहा है और बागान के मरदारों ने श्रमिकों की भरती पर अनावश्यक पावदिया लगा रखी है।¹⁵⁰ इन सिफारिशों के अनुसार ही 1882 का 'उनलड एमिग्रेशन ऐक्ट' पास किया गया जिसने पूर्व-वर्ती सभी कानूनों को पीछे छोट दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि उसने 1859 के अधिनियम XIII को रद्द नहीं किया। 1882 के एम अधिनियम ने भरती करने वाले अभिर्ताओं का कानूनी मान्यता दे दी और अनुबध लेखन को अत्यंत सख्त बना दिया। इसने प्रथम तीन वर्षों में पुरुषों और स्त्रियों का न्यूनतम मासिक वेतन क्रमशः 5 रुपये और 4 रुपये तथा चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 6 रुपये और 5 रुपये निर्धारित किया। इसमें मालिक का दत्ताधिकारी के निवास स्थान में पांच मील की सीमा के भीतर जहां मास्टर टैट न हो, एक ठेका अनुबधित भगाड़े व मंचारी को गिरफ्तारी के आदेशपत्र के बिना न गिरफ्तार करने का अधिकार देने की व्यवस्था थी।¹⁵¹

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं विशेषतः बंगालियों ने असम के कुलियों की सचमुच शोचनीय स्थिति और सरकार के अनुबधिन श्रम पद्धति का कानूनी मान्यता और समर्थन देने के प्रयास के विरुद्ध अपनी नीखी प्रतिक्रिया प्रकट की। उस पद्धति के दोषों पर बंगाली आदि भाषाओं के समाचारपत्र पढ़ने से ही, 1870 में लिखते आ रहे थे। इसके साथ ही असम के श्रमिकों के साथ किए जाने वाले निंदनीय व्यवहार की लोमहर्षक कहानियां लिखकर ये पत्र पाठकों के हृदय में मुक्त राष्ट्रीयता को जगा रहे थे।¹⁵² लगभग 1880 के आसपास ब्रह्म समाज के साधारण प्रचारक रामकुमार विशाखन ने 'कुली कहानी' नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें असम के कुलियों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला गया था। पुस्तक शीघ्र ही लोकप्रिय बन गई।¹⁵³

जब 1881 में इंडियन एमिग्रेशन बिल प्रस्तुत किया गया और 1882 में पारित किया गया, उस समय भारतीय समाचारपत्रों ने कुली को बागान मालिक का गुलाम बनाने के लिए तथा उसे पूर्णतः मालिक की दया पर छोड़ने के लिए बड़े ही आवेशपूर्वक भर्त्सना की।¹⁵⁴ उदाहरण के लिए 17 दिसंबर 1881 के अंक में 'बंगाली' ने लिखा कि इस बिल के द्वारा मानवीय स्वतंत्रता के पवित्र अधिकार का उल्लंघन होता है। पत्र ने घोषणा की कि यह कानून अपनी मूल प्रकृति में दाम कानून कहा जा सकता है। ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन ने अपने 29 दिसंबर 1881 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि कुली की स्थिति चल संपत्ति से किसी भी रूप में बेहतर नहीं है और यह कानून उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार करता है। दूर प्रदेश बर्बई में 'इंडियन स्पेक्टैटर' ने इस कानून की निंदा करते हुए लिखा कि इस कानून में बंगाल के दुखी कुली को कानूनी तौर पर गुलाम बनाने से कम कुछ भी तो नहीं। इस पत्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा, 'आज तक कभी श्रम को पूर्णतः पूजा की दयादृष्टि का अधीन नहीं बनाया गया।'¹⁵⁵ बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों की उदीयमान पीढ़ी के प्रवक्ता भारतीय सघ (इंडियन एसोसिएशन) ने भारत सरकार

को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें बिल की कुछ धाराओं, विशेषतः धारा संख्या 170 और 172 की आलोचना की गई। ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि इस प्रकार से विवश करने के बदले माग और पूर्ति के सिद्धांत को काम करने दिया जाए।¹⁵⁶ अधिकांश आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून एकमतः बागान मालिकों के हितों के लिए और उनके दबाव में ही बनाया जा रहा है।¹⁵⁷

अगले कुछ वर्षों में कानून के अमल में आने पर आलोचकों के गंभीरतम भय तथा उनकी अत्यंत अंधकारमय भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुईं। अगले दस वर्षों में राष्ट्रीय नेताओं ने इस कानून की निरंतर और तीखी आलोचना की तथा असम के चाय बागान के श्रमिकों की दयनीय दशा पर देश भर में आंसू बहाए। सारे देश भर में 'एमिग्रेशन ऐक्ट' की प्रसिद्धि 'दास कानून' के रूप में ही हुई।¹⁵⁸ भारतीय समाचारपत्रों द्वारा प्रायः प्रकाशित प्रलोभन देने, गुप्त रूप से भागने, पीडा देने, बलात्कार और यहां तक कि हत्या करने आदि की लोमहर्षक कहानियां सुन सुनकर भारत के लोगों के और विशेषकर बंगाल के लोगों के हृदय बहुत ही व्याकुल हो गए थे।

चाय बागान के श्रमिकों के भाग्य में सदैव गहरी रुचि लेने वाली इंडियन एसोसिएशन ने 1886 में एक बार पुनः इस विषय को उठाया। उस समय इस संस्था ने अपने सहायक सचिव द्वारकानाथ गागुली को मौके पर जाच पड़ताल के लिए प्रतिनियुक्त किया। गागुली महोदय ने 'बंगाली' और 'संजीवनी' के पृष्ठों में श्रमिकों की लगभग गुलामी की स्थिति और उन्हें सताने की गुप्त तथा मर्मांतक कथाओं के रूप में अपने अनुभवों का वर्णन किया।¹⁵⁹ यह संस्था असम के कुलियों की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए वायसराय से पहले ही 1886 में अनुरोध कर चुकी थी। अब संस्था ने अपने सहायक सचिव के अनुभवों और न्यायालयों द्वारा दिए गए कितने ही निर्णयों को उद्धृत करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन 5 मई 1888 को भारत सरकार के पास भेजा।¹⁶⁰ परवर्ती वर्षों में एसोसिएशन इस मामले में रुचि लेती रही और भारत में तथा इंग्लैंड में संबंधित अधिकारियों के पास ज्ञापन भेजती रही।¹⁶¹

समय के साथ साथ असम के कुलियों के मामले को श्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस में इस प्रश्न को उठाने के प्रारंभिक प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। 1887 की मद्रास कांग्रेस में जब बंगाल के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के नेताओं से असम के कुलियों के प्रति अमानवीय व्यवहार को कानूनी मान्यता देने वाले ऐक्ट की निंदा करने का अनुरोध किया तो उनकी प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि किसी आदेश विशेष के किसी विषय पर अखिल भारतीय कांग्रेस में विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता।¹⁶² अगले वर्ष इलाहाबाद के अधिवेशन में किया गया प्रयास पुनः निरर्थक सिद्ध हुआ।¹⁶³ परंतु यह लोकप्रिय भावना सारे ही देश में क्रमशः बढ़ा ही व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही थी अतः रुढ़िवादी कांग्रेसी नेताओं को देर मबेर इसके आगे झुकना ही पड़ा। कांग्रेस ने 1896 में 'उत्प्रवास अधिनियम' हटाने की वकालत करते हुए इस विषय का एक प्रस्ताव पारित करके चाय बागान के श्रमिकों के साथ संबंध जोड़ लिया।¹⁶⁴ प्रस्ताव के प्रस्तावित जोगेंद्रचंद्र घोष और समर्थक विपिनचंद्र पाल, दोनों

ने चाय बागान में व्याप्त लगभग गुलामी जैसी दुर्दशा की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया।¹⁶⁵ कांग्रेस के आगामी चार अधिवेशनों में प्रस्ताव के महत्व को दोहराया गया।¹⁶⁶

इस अवधि में 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अनुभवों से ही कुंठित बंगाल के नेताओं ने 25 अक्टूबर 1888 को प्रथम बंगाल प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य असम के कुलियों के प्रश्न पर उग्र विचार प्रकट करना था। प्रांतीय सम्मेलन अत्यंत सफल हुआ और मंयोजकों ने इसे वार्षिक आयोजन का रूप दे दिया। इसने मदैव ग्राम के कुलियों की समस्याओं के प्रति उत्कट और सक्रिय रुचि दिखाई।¹⁶⁷

आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' के माध्यम से इस भारतीय चाय उद्योग पर अमिट कलंक बताते हुए उसकी सामान्य निंदा में अपना सशक्त स्वर मुखरित किया तथा अर्धदासता की इस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की।¹⁶⁸

हा, यह अवश्य है कि एमिग्रेशन ऐक्ट तथा चाय बागों में व्याप्त भयंकर दुर्व्यवहारों के विरुद्ध आंदोलन में प्रमुख भूमिका राष्ट्रवादी प्रेम ने ही निभाई। भारतीय समाचारपत्रों ने कुलियों के साथ पूर्ण महानुभूति तथा समान मुदृढ़ता दिखाते हुए वर्षों तक उनकी दुर्दशा के विरुद्ध अपनी प्रक्रिया में अपने ज्ञान के शब्दकोश का पूरा प्रयोग करते हुए तथा अपने क्रोध और दुःख को अभिव्यक्ति देते हुए विरोध प्रकट किया। उदाहरणार्थ, इंडियन एम्प्लोयमेंट ने 1888 में भारत सरकार को जो ज्ञापन दिया, देश भर के सभी समाचारपत्रों ने उसका पूर्ण रूप में समर्थन किया।¹⁶⁹ इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस विषय में विशेष रुचि लेने वाले पत्र थे, मुर्रेडनाथ बैनर्जी द्वारा संपादित 'बंगाली' और कृष्णकुमार मित्र द्वारा संपादित 'सजीवनी'।¹⁷⁰

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों तथा लेखकों ने भरती और परिवहन व्यवस्था को अपने प्रहार का विशेष लक्ष्य बनाया। उन्होंने विस्तार में इस बात का विवरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार कानून का उल्लंघन करके अशिक्षित और भोले भाले मनुष्यों को बलपूर्वक विवश किया जा रहा है और उनका अपहरण किया जा रहा है तथा किस प्रकार घूर्त और सिद्धांतहीन भरती करने वालों द्वारा झूठी आशाओं और कपटपूर्ण प्रतिज्ञाओं द्वारा उन्हें छलकर और फुसलाकर उनकी स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा है।¹⁷¹ राष्ट्रवादियों की शिकायत थी कि एक बार जब कुली चाय बाग में पहुंच जाता था तो मालिक उससे घिनौना व्यवहार करता था और उसे बहुत ही भयंकर रूप से सताया जाता था।¹⁷² उसे बलपूर्वक और गैरकानूनी ढंग से बागों में रखा जाता था और यदि वह बचाव का उपाय करता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और दंडविधान के अंतर्गत उसे दंड दिया जाता था।¹⁷³ द्वारकानाथ गांगुली ने 1886 में प्रतिवेदन किया कि उन्होंने सचमुच काल-कोठारियों में असहमत श्रमिकों को गैरकानूनी ढंग से बंद करके रखे हुए देखा है। उन्होंने यह भी पाया कि चाय बागों में शारीरिक यंत्रणा एक सामान्य प्रवृत्ति है।¹⁷⁴ बहुत से भारतीय लोकनेताओं ने कुलियों के प्रति हृदयद्रावक दुर्व्यवहार की कठुण कथाओं का वर्णन किया।¹⁷⁵ राष्ट्रवादी समाचारपत्रों तथा संस्थाओं ने भी महिलाओं के साथ

बलात्कार और पुरुषों की हत्याओं की कहानियां जनता में प्रचारित की। उन्होंने कुलियों अथवा कुलियों के शुभचिंतकों द्वारा न्यायालयों में मालिकों के बिरुद्ध मामला ले जाने पर न्यायालयों द्वारा मालिकों के पक्ष में विशुद्ध रूप से और अधिकांशतः न्याय का गला घोटने की कहानियां भी प्रकाशित की।¹⁷⁶

भारतीय नेताओं का तर्कसंगत कथन था कि चाय बागों में मृत्यु की ऊंची दर सचमुच वहां की वास्तविक स्थिति का सूचक तत्व है।¹⁷⁷ उनकी एक शिकायत यह थी कि काम की स्थितियों और प्रकृति के अरुचिकर होने पर भी चाय बागान के श्रमिकों का वेतन बहुत कम था।¹⁷⁸ उन्होंने घोषित किया कि दंडनीय कानून बनाने का मुख्य प्रयोजन वस्तुतः कुलियों का वेतन कम रखना और इन नीचे वेतनो पर कुलियों को काम करने के लिए विवश करना था। यह निश्चित है कि मामान्यत वे इतने कम वेतन पर कार्य करने को प्रस्तुत नहीं होते। इस प्रकार दूसरे शब्दों में इस कानून का उद्देश्य कुलियों को ठगना था।¹⁷⁹ कुछ भारतीयों ने यह भी निर्देश किया कि भारत में अथवा असम में श्रमिकों की कमी वास्तविक समस्या नहीं थी। ऊंचे वेतनो में आवश्यकता के अनुरूप श्रमिक उपलब्ध हो सकते थे।¹⁸⁰ राष्ट्रवादियों ने इस मान्यता का जोरदार खंडन किया कि भोल-भाले श्रमिकों में काम में जी चुराने की जन्मजात प्रवृत्ति है। वह अपनी धरती पर भगवा मर जाता है परंतु दूसरी धरती पर जाकर जीने के लिए भी कठोर श्रम नहीं करना। इस प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए ही दंडनीय कानूनों की अपेक्षा है। राष्ट्रवादियों के अनुसार सत्य यह था कि यूरोपीय उपनिवेशवादी भारतीयों से अपने दामों के रूप में काम लेना चाहते हैं और यदि भारतीय काम करने में इनकार करते हैं तो उन्हें मुम्त और निकम्मा कहकर गालिया दी जाती है, उन्हें 'श्रम की महता' से अपगृहित बनाया जाता है तथा अनेक साधनों के प्रयोग द्वारा उन्हें काम करने के लिए विवश किया जाता है।¹⁸¹

भारतीय नेताओं ने यह निश्चयपूर्वक कहा कि वस्तुतः असम में कुली श्रम की मांगी पद्धति दासता के रूप में भिन्न नहीं थी क्योंकि वहां भारतीय कुली का जीवन प्राचीन काल के दासों अथवा आधुनिक काल के हज़ारी दामों के जीवन से किसी भी रूप में बेहतर नहीं था।¹⁸² इस संबंध में बी० सी० पाल ने बताया कि 1880 के आमपास के वर्षों में बंगाल की शिक्षित जनता 'अंकल टाम्स कैबिन' पुस्तक की किस प्रकार प्रशंसा करती थी और फिर तत्काल असम के चाय बागान के कुलियों की दशा की तुलना अमरीका के हन्शियों की मुक्ति से पूर्व की दशा के साथ करती थी।¹⁸³ इसी लेखक ने वर्षोपरांत 'न्यू इंडिया' के 26 अगस्त 1901 के अंक में लिखा : 'दंडनीय श्रमपद्धति दासता का संशोधित तथा आधुनिक रूप है।'

विचारणीय यह है कि इस गुप्त संसाधन के विकास से और उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से कुल मिलकर देश को क्या लाभ हुआ तथा आजीविका और नौकरी के रूप में श्रमिक को क्या प्राप्त हुआ ? कुछ भारतीय लेखकों ने समस्या के इस पक्ष की ओर भी ध्यान दिया। उनमें से सर्वाधिक संयत लेखकों ने इन लाभों को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए भी विचार प्रकट किया कि महारानी महादया की दरिद्रतम, अत्यंत निरीह और सर्वथा असहाय प्रजा के बहुत बड़े वर्ग के जीवन और स्वतंत्रता की बलि

चढाकर इन लाभों की उपलब्धि वाछनीय नहीं थी।¹⁸⁴ अन्य, अपेक्षाकृत अधिक उग्र तथा क्षुब्ध वर्ग ने तो अनुभव किया कि इस प्रकार का आर्थिक विकास सर्वथा अवाछनीय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कुलियों को दामो के रूप में बेचने की शोचनीय प्रथा को बनाए रखने के बदले चाय उद्योग का नष्ट-भ्रष्ट होना तथा असम का जंगली पशुओं का निवास बनना ही पसंद करेंगे।¹⁸⁵

उपाय

यह शोचनीय स्थिति अधिक समय तक नहीं चलने दी जा सकती थी, यहाँ तक कि अन्यथा भी यह स्थिति एक नये समय तक जारी नहीं रह सकती थी। 1887 में ही सजीवनी ने चेतावनी की घटी बजा दी

भारत के अगरेज शासकों ! ... यह भय हर दमन बढ़ रहा। अगरेज व्यापारियों ! ... धन के लोभ में मानव पर किए जा रहे अत्याचार की आग में अपनी आखें बन्द मत करो। क्योंकि, इस तरह की स्थिति का लंबे समय तक चलना असंभव है। तुम्हारे जैसे अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों को भगवान ईश्वर ने दबोचा और दबाया है। अपनी यह उन्मादी प्रकृति को छाड़ दो क्योंकि तुम्हें निश्चित रूप में अपनी करनी का हिसाब देना पड़ेगा। इस दश में अपनी इस पैशाचिक प्रथा के प्रत्येक चिह्न को मिटाने की चेष्टा करो।¹⁸⁶

भारतीय नेताओं ने इस मस्यौदा में सर्वप्रथम उपाय के रूप में इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार कुलियों की वास्तविक स्थिति का, 1859 के श्रमिक अनुबन्ध भगधिनियम (वर्कमेन ब्रीच ग्राफ कांटेक्ट ऐक्ट) के प्रवर्तन के यातनाप्रद प्रभावों को, और 1882 के अतर्दशीय उत्प्रवाम अधिनियम (उनलैट एमिग्रेशन ऐक्ट) के प्रवर्तन के दुष्परिणामों को अनुभव करे और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार पर जाच पडताल करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की नियुक्ति हेतु दबाव डाला।¹⁸⁷ द्वितीय, उनका मुभाव यह था कि शक्तिशाली और समृद्ध बागान मालिकों के मुकाबले श्रमिक निरीह तथा असहाय हैं, अतः इस तथ्य को देखते हुए सरकार को स्वयं उन्हें यातनाओं से मुक्ति दिलाने के उपाय करने चाहिए।¹⁸⁸ इस प्रकार का एक उपाय यह होना चाहिए कि अपने श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले चाय बागान के प्रबन्धकों को तत्काल और तदनु रूप समुचित दंड दिया जाए।¹⁸⁹ परंतु भारतीयों की सर्वाधिक सर्वमान्य और लोकप्रिय मांग दंडनीय कानूनों के निवर्तन की¹⁹⁰ और स्वतंत्र उत्प्रवाम को लागू करने की थी ताकि चाय बागान को भारत के बहुत बड़े श्रम बाजार से मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धांत के आधार पर श्रमिक मिल सकें।¹⁹¹

भारतीय नेता सरकार से असम के कुलियों को इस दुर्भाग्य से मुक्त करने की अनुनय विनय करते समय यह तथ्य नहीं भूले कि एक विदेशी सरकार द्वारा यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध कोई पग उठाए जाने की संभावना नहीं थी।¹⁹² इस विवेक एवं सतर्कता के कारण ही असम कुलियों के प्रगाढ़ मित्र 'सजीवनी' ने अपनी सहायता आप ही करने का आह्वान किया। इस पत्र ने 14 अगस्त 1886 के संपादकीय में भारतीयों की पर्दानगी को

ललकारते हुए लिखा कि यदि उनकी संपूर्ण शक्ति और साहस नष्ट नहीं हो गए तो उन्हें देश में क्रोध की ऐसी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित करनी चाहिए कि उसमें कुली ऐकट जलकर राख हो जाए।¹⁹³ इस पत्र ने भारतीयों से कुलियों को अथवा कुली बनने के इच्छुकों को कानूनी तथा अन्य इस प्रकार की सहायता देने के लिए तथा मालिकों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया।¹⁹⁴ इस पत्र के एक संवाददाता ने यह सुझाव दिया कि शिक्षित भारतीयों को चाय पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह चाय पीना गरीब, प्रपीडित कुलियों का खून पीने के अतिरिक्त और कुछ नहीं।¹⁹⁵ आश्चर्यजनक न होने पर भी यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि उस समय भारत में किसी ने भी चाय बागान के श्रमिकों को श्रमिक संघ बनाने आदि के रूप में अपनी सहायता आप करने का सुझाव नहीं दिया। हा, कुलियों ने स्वयं ही आक्रमण और भगड़े-फसाद के रूप में आत्मसहायता का मार्ग अपनाया¹⁹⁶ परंतु राष्ट्रीय नेताओं से उन्हें समुचित दिशानिर्देशन नहीं मिला।

असम श्रम और उत्थवास अधिनियम, 1901

भारतीयों द्वारा निरंतर आंदोलन तथा असम के उदार तथा साहसी मुख्य आयुक्त हैनरी काटन के सतत प्रयासों के फलस्वरूप जब भारत सरकार ने इस विषय पर नए कानून बनाने का निश्चय किया तो उस समय बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में चाय बागान के श्रमिकों का प्रश्न पुनः एक बार भारतीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गया। 13 अक्टूबर 1899 को विधानपरिषद में 'असम श्रम और उत्थवास बिल' लाया गया और 8 मार्च 1901 में इसे कानून का रूप दे दिया गया। जहां एक ओर इस नए बिल ने चाहे बेमन में ही सही, भरती की पद्धति को सुधारने का प्रयत्न किया¹⁹⁷ वहां दूसरी ओर कुल मिला कर पहले की तरह ही विषम दुर्व्यवहार चलते रहने से इसका प्रयोजन ही असफल हो गया था।¹⁹⁸ इसके एक प्रावधान ने, जो मारे अधिनियम के प्रयोजन और प्रभाव के अपेक्षाकृत व्यापक मंदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं थी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बन गई। 1899 में अपने मूल रूप में प्रस्तावित बिल में 1882 के अधिनियम के अंतर्गत अनुबंधित श्रमिकों के निश्चित न्यूनतम वेतन में एक रुपया प्रति मास की वृद्धि की व्यवस्था थी। बाद में इस व्यवस्था में प्रवर समिति ने इस प्रकार से सुधार किया कि प्रथम वर्ष में पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिक का मासिक वेतन क्रमशः 5 और 4 रुपये, द्वितीय और तृतीय वर्ष में क्रमशः 5½ और 4½ रुपये और चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 6 और 5 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम और चतुर्थ वर्ष में श्रमिकों के वेतन उतने ही बने रहे, जितने पहले के अधिनियम में निर्धारित थे।¹⁹⁹ यद्यपि राष्ट्रवादियों ने इस बिल को इसके मूल रूप में बागानमालिकों के हितों की सुरक्षा में गढ़ा हुआ तथा बलपूर्वक श्रम को जारी रखने वाला एक साधन मात्र माना²⁰⁰ और इस वेतनवृद्धि को बहुत थोड़ा माना तथापि इन असहाय प्राणियों को इस विलंबित न्याय का एक अंश देने वाली इस धारा का समर्थन भी किया।²⁰¹

सरकार द्वारा चाय बागानमालिकों की ओर से जे० बकिंघम द्वारा अधिनियम की

वेतनवालीधाराओं के प्रवर्तन को दो वर्षों तक स्थगित रखने के सुझाव की संशोधन के रूप में स्वीकृति ने एक बार फिर आग म घी का काम किया।¹⁹² वस्तुतः लार्ड कर्जन ने पहले ही विवाद में हस्तक्षेप करते हुए बागानमालिकों को इस प्रकार की रियायत मागने का निमंत्रण प्रत्यक्ष रूप में दे दिया था।¹⁹³ असम के मुख्यायुक्त ने जब इस संशोधन का इस आधार पर विरोध किया कि इसमें तो कुलियों के लिए पहले ही अपर्याप्त और अभी अभी विजित रियायत का कोई अर्थ ही नहीं रह पाएगा तो वायमराय ने इस लोकप्रिय मुख्यायुक्त की सार्वजनिक रूप से अवमानना और¹⁹⁴ भर्त्सना की। इस बात ने कोढ़ में खजली का काम किया।¹⁹⁵ विदेशी बागानमालिकों के सामने लार्ड कर्जन द्वारा हथियार डाल दिए जाने के विरुद्ध सारे भारतीय समाचारपत्र और लोकनेता एकजुट होकर खड़े हो गए।¹⁹⁶ उन्होंने स्पष्ट देखा कि भारतीय लोगों के मूल्य पर यूरोपीय पूजीपतियों के हितों की सावधानी के साथ रक्षा करने का यह एक अन्य निदनीय निदर्शन था।¹⁹⁷ 'वगाली' ने 10 मार्च 1891 के अंक में लिखा 'भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय पूजीपतियों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाना है चाहे इसके लिए न्याय और मानवता का गला ही क्यों न घोटना पड़े। राष्ट्रवादियों ने भारत सरकार की निंदा करने हुए कुलियों के हितों की वकालत करने में उनकी न्यायप्रियता तथा वीरता के लिए हेनरी काटन की भरपूर प्रशंसा की।'¹⁹⁸

मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 1903

1903 में जब मद्रास सरकार ने 'मद्रास बागान श्रम अधिनियम' को कानून का रूप दिया तो राष्ट्रवादियों की विदेशी सरकार के विरुद्ध क्षोभ की और बागान श्रमिकों के प्रति महानुभूति की भावना एक बार फिर भड़क उठी। प्रमुख रूप से 1901 के 'असम श्रम और उत्प्रवास अधिनियम' पर आधारित मद्रास अधिनियम में भी भाग जाने वालों के लिए गिरफ्तारी और सजा की तथा अनुपस्थित रहने वालों और सुस्ती बरतने वालों अर्थात् काम में जी चुगने वालों के लिए अर्थदंड और जेल की व्यवस्था थी। भारतीय नेताओं ने असम अधिनियम के समान मद्रास अधिनियम को भी वैशाचिक, ईश्वरविरोधी, अमानवीय, घृणित तथा अन्यायपूर्ण बताकर उसकी भर्त्सना की तथा कुलियों की स्वतंत्रता नष्ट करने के लिए और दक्षिणी क्षेत्र के बागान में दासता को कानूनी रूप देने के लिए उसकी आलोचना की।¹⁹⁹ उन्होंने सरकार पर बागानमालिकों और विदेशी पूजीपतियों को सदा उपकृत करने को प्रस्तुत रहने के लिए उनके हाथ में एक खिलौना बनने का आरोप लगाया।²⁰⁰

व्यापक संबंध

बागान श्रमिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श 'उभरे कुछ संबंधित व्यापक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर भी कई भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने गहरा विचार किया और उन प्रश्नों तथा सरकार के बागानश्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक संबंध सिद्ध करने का प्रयास किया। प्रथम, भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,

भारतीय समाचारपत्रों तथा विधानपरिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध की उपेक्षा करके बागानमालिकों के अनुकूल कानून बनाने की सरकार की तत्परता से यही निष्कर्ष निकाला कि यह सरकार भारतीय लोकमत को कोई महत्व ही नहीं देती।²¹¹ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि संशोधित विधानपरिषद पूर्णतः अनुपयोगी सिद्ध हुई है और सरकार ने भारतीय सदस्यों की इच्छाओं की अवहेलना की है।²¹² जी० एम० अय्यर को इस स्थिति में यह मत प्रकट करना पड़ा कि 'आज की भारतीय पद्धति से अधिक हास्यजनक कानूनी पद्धति कहीं भी पहले नहीं रही।' ²¹³ वस्तुतः विदेशी शासकों की न्यायप्रियता तथा प्रगतिशीलता पर कोमल और उदार चिन्तनवालों तक का विश्वास हिल गया। 'मद्रास बागान थर्म अधिनियम' के कानून बनने पर लोगो के विश्वास भंग को 'कैसरे हिंद' ने अपने 8 मार्च 1903 के अंक में सुंदर अभिव्यक्ति दी है :

यदि ये निष्पक्ष विधायक हैं तो हम उनके लिए किसी कटु विशेषण का प्रयोग न करते हुए पूछने हैं कि जिन बेजबान और बेसहारा लोगो के वे पिता के समान रक्षक बनते हैं, उन्हें वे क्यों एक अत्यंत स्वार्थी वर्ग के ही आदेश से दाम बना देते हैं ? इस बात से कौन इनकार करेगा कि न केवल ब्रिटिश नीतियों के प्रत्युत्तर ब्रिटिश सदाचार के विनाश का भी यह एक अन्य सुदृढ़ प्रमाण है। निम्नोद्देश मारे विनाश ब्रिटिश राज्य में चारों ओर विनाश के अपशकुन और संकेत दिखाई दे रहे हैं जो परिणाम में सुखद नहीं कहे जा सकते। भगवान ही ब्रिटिश राज्य को भावी विपत्तियों में बचाए।²¹⁴

'कैसरी' ने भी 10 मार्च 1903 के अंक में इस समय समस्या को विद्वद्वापी पैमाने पर आर्थिक साम्राज्यवाद के विमर्शन परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया। यह निम्नोद्देश के उपरान्त कि आज के भयंकर प्रतियोगिता के युग में यूरोपीय राष्ट्र भौतिक समृद्धि के लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं और सभ्यता का वरदान लाने के बहाने अपने अधीनस्थ अश्विक-सित राष्ट्रों के वस्तुगत और खनिज पदार्थगत साधनों का शोषण कर रहे हैं, इस पत्र ने शिकायत के स्वर में लिखा कि यूरोपीय व्यापार के उद्देश्य में अथवा उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य में जहां कहीं भी जाते हैं, उन देशों की जनता को ये लोग दाम बनाकर ही उसमें काम लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में काफिरों के प्रति और असम में चायबागान कुलियों के प्रति इनका व्यवहार इसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण है। निष्कर्ष रूप में इस पत्र ने इस विचारधारा पर दुख प्रकट करते हुए लिखा कि मनुष्यों का एक वर्ग तो धन में खेले और उसके शोष बंधुओं को उस वर्ग के ऐशो आराम के लिए खटने पर विवश किया जाए।²¹⁵

कुछ भारतीय नेता बागान श्रमिकों की समस्या को श्रमिकों और पूँजीपतियों के बीच संबंधों की व्यापक समस्या के अंश के रूप में देखने को प्रेरित हुए। इन नेताओं ने श्रमिकों का ही पक्ष लिया। उदाहरणार्थ, जी० एम० अय्यर का विचार था कि वस्तुतः भारत सरकार की बागान श्रमिकों के प्रति नीति का तथ्य इस सत्य में निहित है कि वह चाय उद्योग में केवल पूँजीपतियों के हितों को ही जुड़ा समझती है।²¹⁶ आर० सी० दत्त का भी अनुभव था कि भारत सरकार पर पूँजीपतियों का प्रभाव इतना प्रबल और प्रचंड

था कि चाहने पर भी श्रमिका के लिए कुछ करना उमक लिए सम्भव नहीं था ।¹⁷ 'सजीवनी' पत्र भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि असम का सघर्ष मूल रूप से श्रमिकों और पूँजीपतियों के बीच का विवाद है ।¹⁸ इस नई जानकारी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उमके मतत्व का विपिनचंद्र पाल ने 1901 में अपने भाषण में बड़े ही मद्दग ढग में प्रस्तुत किया । तब उनके भाषण के एक लक्ष अंग का उमकी मद्दचा व भाव उमकी नवीनता के कारण देना चाहेंगे

अत्यन्त महोदय ! यह प्रश्न एक बहुत ही पुराना प्रश्न है श्रमिका और पूँजीपतियों के मध्य सघर्ष का विश्वव्यापी प्रश्न है । सर्ववर्षाभिमान पात्र की शक्ति न पूँजीपति शक्तियों पहन ही पयाप्त बलशाली है और वे एतदम संगठित भी हैं । उनका संगठन स्वन उसीलिए नहीं कि श्रमिका का उनका उपयोग पुरस्कार न मिल सके प्रत्युत उमलिए भी है कि कानूनी व्यायातया द्वारा भत्तमना प्राप्त तथा उच्च व्यायालय द्वारा दंडप्राप्त लागा की संरक्षण दिया जा सके । जब यह सब हा रहा है तो क्या श्रम की शक्तियों का संगठित नहीं होना चाहिए ? अ यक्ष महोदय ! आप, राजा मराजाओं अथवा बड़े रिमागा के प्रतिनिधि हैं । हम सब उम दण में श्रमिका की ही स्थिति में हैं और इस सब पाग पूँजीपतियों की स्थिति में हैं ।¹⁹

असम श्रम और उत्प्रवास बिल पर पी० आनंद चारन के भाषणा में यह दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट परंतु सामारित व्यावहारिकता के साथ देखा जा सकता है । एक ओर उनका नर्क था कि मात्गी व्यवसायो तथा सुदृढ़ पूँजीपतियों की सफरता के लिए समान रूप में नन्तरदायी तथा महत्वपूर्ण तब में सहायक श्रमिका के एक बहुत बड़े वर्ग के दाव की संपत्ता नहीं करनी चाहिए दूसरी ओर उन्होंने वक्तावत की कि मार्गिकों और श्रमिका के बीच भागतक भार उठा सकता है जबकि श्रमिकों का वतनवृष्टिक जभाव में जीता ही नहीं है । मार्गिकों के लिए इसका अर्थ पेशा आगम में साधारण सी समी है परंतु श्रमिकों के लिए इसका अर्थ जीवन की अनिवाय आवश्यकताओं का भयकर रूप से अभाव है । "

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मन में बागान श्रमिकों के प्रति महानुभूति की भावना इसलिए उभरी क्योंकि इस उद्यम में विदेशी पूँजीपति सलग्न थे परंतु यही महानुभूति भारतीयों के स्वामित्ववाले उद्यमों में नियुक्त श्रमिकों के प्रति भारतीय नेताओं में नहीं दिखाई । इसका स्पष्ट रूप नाटकीय ढग से उम समय प्रकट हुआ जब 8 मार्च 1901 को असम श्रम और उत्प्रवास अधिनियम पारित हो जाने के बिलकूल सही नीग पर दो ही सप्ताहों के उपरान्त विधानपरिषद में 'इंडियन माइम बिल' विवाद और कानूनी रूप ग्रहण करने के लिए पेश हुआ तो जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, सारे के सारे भारतीय समाचारपत्रों और परिषद के भारतीय सदस्यों ने खाना में काम करने वाले बच्चा और महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए अत्यंत ही साधारण व्यवस्थाओंवाले उस बिल का विरोध किया । श्रमिका के प्रति यह दोमुहो नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यवहार में भी स्पष्ट रूप में देखी गई, जिसने एक ओर 1900 में सरकार को श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाली व्यवस्थाओं को 'इंडियन माइम बिल' से हटाने का

उपदेश दिया और दूसरी ओर इसके केवल एक वर्ष उपरांत ही असम कुलियों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया।²²¹

इस तरह के विरोधासपूर्ण रवैये का एक और नाटकीय उदाहरण 3 मार्च 1903 के हिंदू के संपादकीय में मिला। जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, 'हिंदू' बागान-मालिकों के हितों में लाए जाने वाले सभी कानूनों का प्रबलतम निंदक और विरोधी रहा है। उसने उन सभी कानूनों को 'दास बनाने वाले कानून' कहकर उनकी भत्सना की। इस पत्र ने 'मद्रास प्लांटर्स बिल' के विरुद्ध लगातार निंदा का स्वर मुखरित किया था। 3 मार्च 1903 के संपादकीय में भी उसने यही विरोध प्रकट किया। परंतु इसी संपादकीय में उसने आश्चर्यजनक ढंग में यह मांग प्रस्तुत की कि इस प्रकार का कानून श्रमिकों को नियुक्त करने वाले उन सभी मालिकों के लिए समान रूप से बनाना चाहिए 'जिन्हें श्रमिकों को पाने में ही न केवल कठिनाता का अनुभव होता है प्रत्युत उन्हें अनुबंध को निभाने के लिए श्रमिकों को विवश करने में कठिनाई का अनुभव होता है'। उसके अनुसार ऐसे कानून की दक्षिण भारत के भूमिपतियों को विशेष आवश्यकता है। ये भूमिपति तो 'पेनल लेबर ला' (दंडनीय थम कानून) को अत्यंत लाभप्रद और उपयोगी पाएंगे। अपने तर्क की पुष्टि में 'हिंदू' ने राष्ट्रवाद के नाम पर आग्रह किया : भारतीय कुलियों के संबंध में वर्गीय कानून की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वे यूरופियों के दास बनाए जा सकते हैं तो उन्हें भारतीय जमींदारों के दास बनाने में कोई अनौचित्य नहीं होना चाहिए। भारतीय कुलियों को एक वर्गविशेष का ही दास नहीं बनाना चाहिए। इस तर्क पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। 'हिंदू' द्वारा निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत मांग में उसकी अचेत विडंबना का तथा इस प्रश्न के बारे में उसकी पाखंडपूर्ण पवित्रता का पता चलता है।

जिस प्रकार अनुचित रूप से पर्वतीय प्रदेशों में कुलियों को चाय बागानमालिकों की दया पर उनके हाथों में सौंपने को उचित नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार भारतीय जमींदारों के हाथों में दंडनीय अपराध के अंतर्गत कुलियों को सौंपने में इनकार करने को किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। हिंदू द्वारा इस प्रकार का व्यवहार अपनाना सर्वथा अविश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि इससे दो महीने बाद ही तमिल पत्र-कारिता के अग्रदूत एक अन्य राष्ट्रवादी समाचारपत्र 'स्वदेशमित्र' ने इसी प्रकार की मांग पेश की।²²²

जी. आई. पी. रेलवे सिगनलवालों की हड़ताल

भारतीयों से इतर स्वामित्व वाले उद्यमों में नियुक्त श्रमिकों के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण की रोचक विडंबना 1899 में हुई जी० आई० पी० की हड़ताल के संदर्भ में देखने को मिलती है। जब रेल कंपनियों के प्रबंधक मंडल ने वेतनों में कटौती न करने, उन्नतियों को व्यवस्थित रूप देने, कार्य के घंटे सीमित करने तथा नियमित अवकाश की व्यवस्था करने की मांगें अस्वीकृत कर दीं तो 1899 में ही मई के प्रथम सप्ताह में 800 सिगनल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी।²²³ समाचारपत्रों की सूचना के अनुसार हड़ताल ने रेलवे को बुरी तरह से प्रभावित किया। आमतौर पर माल की आवाजाही

कम अथवा स्थगित कर दी गई। यात्रियों के यातायात में भी गाड़ियों की लंबी लंबी और बार बार की देर तथा भारी अव्यवस्था में बाधा पहुंची।²²⁴ भारतीय श्रमिकों के किसी वर्ग द्वारा की गई यह प्रथम सुनियोजित हड़ताल थी।²²⁵ सिगनलवालों का एक नियमित मंगठन था जिसका मुख्यालय शोलापुर में था और उनके पास कानूनी सलाह देने वाला भी किराण पर ली गई एक व्यापार संस्था थी। इस हड़ताल के पीछे दो वर्ष तक लंबा आंदोलन चलता रहा और प्रबंधकों को मागपत्र और अंतिम चेतावनी आदि पेश किए जाते रहे।²²⁶

रैलवे कर्मचारियों की यह संगठित कार्यवाही, इसे केउन शिक्षित वर्गवालों द्वारा की गई मानने पर भी, देश की उस समय की परिस्थितियों में श्रमिक कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा कानून के रूप में अब तक उठाए गए किसी भी पग की अपेक्षा एक प्रकार से अधिक क्रांतिकारी पग था। इस पत्र का पूजीपतियों के लिए तात्कालिक मामलों और संबंधित दलों से आगे जाकर विशेष अर्थ था।²²⁷ कारखाना कर्मचारियों के प्रति राष्ट्रवादियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखते हुए इन सिगनलवालों के प्रति नताओं के व्यवहार में खुले विरोध की नहीं तो तटस्थता की अथवा अधिक से अधिक दबे अनुमोदन की तो अपेक्षा की ही न। गती थी। परंतु वस्तुतः एक को छोड़कर बंबई के प्रमुख समाचारपत्रों ने बड़े जोर खगोज के साथ हड़ताल का समर्थन किया।²²⁸ इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि बहुत सारे दूरस्थ राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हितवादी', 'हिंदू', 'हिंदुस्तानी' के कालमों में सहानुभूति की लय गूंजनी रही। हा, हड़तालियों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाने वाले और महीनों तक अपने कालमों द्वारा आंदोलन छेड़ने वाले दो ही समाचारपत्र थे, बालगंगाधर तिलक के संपादकत्व में निकलने वाले 'मराठा' और 'केमरी'।

सभी भारतीय समाचारपत्रों ने यह मत व्यक्त किया कि वर्षों में इन सिगनलवालों को थोड़ी नज़रबंदी दी जा रही है, अधिक और कठोर काम लिया जा रहा है और उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अतः उनका हड़ताल पर जाना सर्वथा न्यायसंगत ही है। उनकी मांगें न्यायसंगत, सही और उचित हैं। मचमुच वे मांगें संपर्क और सहानुभूति के योग्य हैं। इसके अतिरिक्त इस हड़ताल का औचित्य इससे भी सिद्ध है कि प्रबंधकों द्वारा सिगनलवालों की वाम्तावक शिकायतों को दूर करने की प्रार्थना को लगातार ठुकरा कर इन बेचाराओं को हड़ताल का मार्ग ग्रहण करने को विवश कर दिया गया है।²²⁹

कई समाचारपत्र केवल सहानुभूति में भी बहुत आगे बढ़े, वे हड़तालियों के प्रबल और मुखर प्रशंसक बन गए। उन्होंने श्रमिकों द्वारा हड़ताल के दिनों में प्रदर्शित दृढ़ता तथा एकता के लिए उनकी भरपूर प्रशंसा की।²³⁰ 'मराठा' ने 28 मई 1899 के अंक में सिगनलमैनो के लिए हड़ताल का स्थाई महत्व बताया और कहा कि इस हड़ताल ने एकता और आत्मत्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अन्य लोगों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार 7 जून 1899 के अंक में 'हितवादी' ने भारतीय लोगों को झुकझोरे हुए लिखा कि वे प्रबंधकमंडल से अलग अलग रूप से समझौता करने से इनकार करके नैतिकता के उच्च स्तर कायम करने वाले सिगनलमैनो का अनुसरण करें।²³¹ इन समाचारपत्रों

ने हड़तालियों से नौकरी छूट जाने पर भी डटे रहने का निरंतर अनुरोध किया और हड़ताल छोड़कर काम पर जाने वालों को गद्दार कहकर उनकी निंदा की।³²

भारतीय समाचारपत्रों ने रेलवे के प्रबंधकमंडल द्वारा कर्मचारियों के प्रति किए जा रहे व्यवहार, दृष्टिकोण तथा कार्यवाही आदि की तीव्र निंदा की।³³ उन्होंने सार्वजनिक उपयोगिता के विभागों में अनुशासन के तर्कों को प्रबंधकों का वाक्छल कहकर ठुकरा दिया तथा जनता को हो रही असुविधा का सारा दायित्व प्रबंधकों पर डाल दिया।³⁴ उन्होंने रेल कंपनियों पर हड़तालियों की न्यायसंगत शिकायतें दूर करके तथा विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ को सोपने की हड़तालियों द्वारा पहले से ही महमति प्राप्त बात मानकर हड़तालियों से समझौता करने के लिए दबाव डाला।³⁵

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने सरकार से विवाद में हस्तक्षेप करने और प्रबंधक मंडल को सिगनलमैनों की उचित मांगें मानने के लिए विवश करने का अनुरोध किया।³⁶ उनका उपयुक्त तर्क यह था कि मानवता के दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो भी सरकार हस्तक्षेप करने के लिए कर्तव्यबद्ध है क्योंकि जी० आई० पी० रेलवे प्रतिभूत मस्या है और इस प्रकार हड़ताल के कारण होने वाली हानि सरकार को और अनंत करदाता को ही भुगतनी पड़ेगी।³⁷ मराठा ने 28 मई 1899 के एक लेख में लिखा कि अपने ही लोगों को जिनके प्रति हमारी गहरी महानुभूति है, निराश और पराजित करने के लिए अपेक्षित दाम हमसे ही मांगना कहा का न्याय है।³⁸ राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने यह भी लिखा कि सरकार का हड़ताल में हस्तक्षेप करना नैतिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है क्योंकि रेलवे जनोपयोगी मस्या है, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था अथवा कुप्रबंध से न केवल व्यापार, जन मुख और सुविधाओं को हानि पहुँचती है प्रत्युत यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।³⁹ समाचारपत्रों ने यह अनुभव किया और देखा कि सरकार न केवल हस्तक्षेप करने से इनकार करती है अथवा तटस्थ रहती है प्रत्युत प्रबंधकों को समर्थन तथा सक्रिय सहायता भी दे रही है, सरकार के इस आचरण की समाचारपत्रों ने तीव्र भर्त्सना की।³⁹

सिगनलमैनों के प्रति व्यापक सार्वजनिक महानुभूति शाब्दिक प्रदर्शन तक सीमित न रहकर उसमें आगे निकल गई। समाचारपत्रों ने जनता और जन समस्याओं से हड़ताली सिगनलमैनों की सहायता के लिए पैम जुटान का अनुरोध किया।⁴⁰ बहुत से लोग अपने आप सहायता के लिए आगे आए। उनकी सहायताार्थ कोष संग्रह के लिए बंबई प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों, अहमदाबाद, अमरावती, धुलिया और नागपुर में सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया।⁴¹ बंबई में 19 मई को गण्यमान्य भारतीय नागरिकों और प्रतिष्ठित व्यापारियों की एक बैठक किरोझाह एम० मेहता के भवन में हुई, इसमें हड़तालियों के उपयोग के लिए एक कोष जारी करने का संकल्प किया गया। तत्काल मौके पर 2500 रुपये की राशि इकट्ठी हो गई और अगले ही दिन 2500 रु० और देने का वचन दिया गया।⁴² इस कोष के लिए बंगाल में मुरेदनाथ टैगोर ने और बंगाली मार्क्सवादी भारत की संपादिका मुथ्री घोषाल ने भी धन जुटाया।⁴³ हड़ताल के असफल होने तथा लगभग 700 सिगनलमैनों के हटाए जाने पर बंबई में उनके लिए एक सार्वजनिक कोष

भारी किया गया। रिमा राधागक्षाम एक जी० ई० बाचा थे।¹⁴ 'मराठा' ने अपने 16 जुलाई 1899 के अंक में उन प्रयत्नों का समर्थन तथा गणहत्या की। कनकना के 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 4 जुलाई 1899 के अंक में जमींदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने नौकरों को बर्खास्त किया गया सिंगनरों की नौकरी देने का अनुरोध किया।¹⁵

भारतीय नेताओं के उग्र रूप से हत्या का समर्थन दर्शाएँ। मराठों की कुजी मजदूरों ने उनके राष्ट्रवाद में निर्दिष्ट है। हत्या की सिंगनर भारतीय थे जबकि उन्हें निष्पक्ष करने का भी स्वतंत्र रूपी का स्वामित्व और प्रशासन अंगरेजों के हाथ में था, यही अकेला तथ्य दोनों के मध्य में विवाद को भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य पक्षों की ओर तथा राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए प्रयास था। इसी मामले में तो विवाद के बारे में यह विशिष्ट जानकारी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया तथा उसे स्पष्ट अभिव्यक्ति दी गई। 'मराठा' ने शिवायत ही कि वे स्वतंत्र सिंगनरों की जीवन निवाह के लिए उपयुक्त वेतन देने में उत्सर्जन इनकार कर रही है क्योंकि वे भारतीय हैं। उसने 21 मई 1899 के अंक में अपक्षान्त गार्डन में किया

मैनर ने उदाहरित यह अनुभव किया कि जाने गुलामों का प्राचीन जीवन रहने के लिए अनेक वर्षों की आवश्यकता रही और उनका उसे दे दिया जाएगा यदि वे जीवन रहें और गरीब जाटों की गन्ना का भार खत्म करता रहे। मराठाने जाना कि मराठा समाज में अनेक लोग हैं जो वे ही वेचारा गरीब जाटों निभा रहा है और उसका जीवन तथा गन्तरीय तथा राष्ट्रीय, देश का उस प्रकार गोपण कर रहा है कि गरीबों का यह स्वयंसेवक जाना है। और इन पंजीन बहाने वाले काले गुलामों को गण अनेक (मार्ग के) लाभ की इच्छा में चढ़ने के लिए दत्ता है।

'अमृत बाजार पत्रिका' ने भी विचार में उस मारे विचार को भारतीय भेदभाव की भावना कागज पर ली थी। 12 जून 1899 के अंक में उस मारने अपने महादकीय मे लिखा 'बर्बर मराठा' यह उस अक्षेमिता प्रतीति में बन गये नही है कि उम्मेद रेनवे कंपनी को सहायता दी है और निगम द्वारा काम किया है। उसका उद्देश्य कारण यह है कि सिंगनर सिंगनरी हैं जबकि अपनी वे प्रबलक शासक जानें के है। 14 मई के अंक में गुनगावों ने और 16 मई के अंक में काम प्रमोद ने उस मंत्र में स्मरण कराया कि दो वर्ष पूर्व जब उसी रेनवे कंपनी के यूरोपीय गार्डन हड़ताल की थी, उस समय रेल कंपनी और सरकार दोनों ने सबथा भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था और वस्तुतः उनकी मांग मान ली गई थी।¹⁶ मराठा ने 16 जुलाई 1899 के अंक में निष्कर्ष में लिखा कि वास्तव में सिंगनर राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वे तो 'अपनी और अपने समाज ही मान-पतिष्ठा की रक्षा के उद्देश्य से ही प्रेरित है।'

भारतीय नेतृत्व का सिंगनरों की हड़ताल के प्रति दृष्टिकोण का राष्ट्रवादी अभिप्रेरण एक भिन्न सदस्य में पता चलता है। 1897-98 में बंबई की कपडा मिलों में कितनी ही हड़तालें हुई थी।¹⁷ प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्रों में से किसी ने भी उधर ध्यान नहीं दिया था और न ही उनका समर्थन किया था। जिस 'अमृत बाजार पत्रिका' ने बला फाड़कर सिंगनरों की वेतनवृद्धि के लिए की गई हड़ताल का समर्थन किया था, उसी ने

कुछ महीनों के ही उपरांत बंबई की कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के विरुद्ध की गई हड़ताल का विरोध करने में संकोच नहीं किया। 10 जनवरी 1900 के अंक में इस पत्र ने बकालत करते हुए लिखा कि मालिक इससे अधिक देने की सामर्थ्य ही नहीं रखते और उन्हें इस विषय में बाध्य करने की चेष्टा का अर्थ होगा भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना और इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि अंत में श्रमिक को भी 'भूखों मरना पड़ेगा'।

नए दृष्टिकोण का प्रारंभ

भारतीय श्रमिक वर्ग के उदय तथा श्रम और पूजी में संघर्ष का धीरे-धीरे उदय होने से भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मन में इस नए वर्ग की सामाजिक भूमिका के संबंध में नए विचार तथा इसके अधिकारों और दायित्वों के प्रति नए दृष्टिकोण ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। यहां यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि ये नए विचार कुछ ही भारतीय नेताओं तक सीमित थे। इन विचारों ने सभी को समान रूप से समान परिमाण में प्रभावित नहीं किया था। यह काफी आश्चर्यजनक है कि इस नए दृष्टिकोण का विवेचन सर्वप्रथम मार्च 1899 में 'बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन' की बैठक में उस समय किया गया जब स्वयं एक मिल मालिक डी० ई० वाचा ने यह विचार प्रस्तुत किया कि वस्त्र उद्योग का उत्पादन व्यय दो तरीकों से घटाया जा सकता है : प्रथम, प्रयोग की जाने वाली कच्ची कपास के स्तर को सुधार कर और द्वितीय, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति सुधार कर। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि काम के लंबे घंटों, थोड़े वेतन तथा जनता के खाद्य पदार्थों पर करोने से सदैव औद्योगिक विकास को पंगु ही बनाया है। दूसरी ओर काम के अपेक्षाकृत कम घंटे, अपेक्षाकृत उच्च वेतन, सस्ते खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और आवास सुविधा आदि ने निश्चित रूप से ही विकास को पुष्ट और सशक्त बनाया है।¹¹⁸ वाचा महाशय ने अपनी इस सलाह को अप्रैल 1905 में फिर दोहराया और उन्होंने दस घंटों के कार्य दिवस की बकालत की, उन्होंने मिलमालिकों को चेतावनी दी कि वे सोने का अडा देने वाली मूर्तों की हत्या करने की नीति पर चलने से और अपने लोभ-लालच से बाज आएंगे। उन्होंने चुनौती के स्वर में कहा कि श्रमिकों का प्रश्न भविष्य में मिलमालिक के लिए एक जटिल समस्या का रूप ग्रहण करने जा रहा है। अतः मिलमालिकों की अपनी भलाई इसी में है कि श्रमिकों की ओर से सरकार अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने से पूर्व स्वयं वे (मिलमालिक) ही इस समस्या को सुलझाना प्रारंभ कर दें।¹¹⁹

भारतीय रंगमंच पर उभरते हुए श्रमिक वर्ग के महत्व को उस समय पहचानने वाले बिपिनचंद्र पाल दूसरे नेता थे। दुर्भाग्यवश उनके इस अवधि (1901-05) के अधिकांश लेख नष्ट हो गए हैं अथवा कम से कम मुझे तो उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 1901 में उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साप्ताहिक पत्र 'न्यू इंडिया' की दो बार प्रतियां इस शताब्दी के सार्वजनिक पुस्तकालयों में मिल पाई हैं। इसके अध्ययन से यह प्रकट हो जाता है कि पाल महोदय निश्चित रूप से श्रम समस्या पर प्रगतिशील

ढंग से सोच रहे थे। 9 सितंबर 1901 के 'न्यू इंडिया' के संपादकीय में उन्होंने लिखा : देश की वर्तमान आर्थिक समस्या के अंतर्गत नीम लाख मुदूढ़ श्रमिकों की स्थिति का गंभीरतम महत्व है। आधुनिक स्थितियों में काम करने वाले इसी वर्ग से जनता की नई आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति संभव है अतः इस वर्ग के हित अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनकी उन्नति की ओर ध्यान देना ही चाहिए। कानून बना कर श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के सरकार के प्रयत्न की मर्यादना करते हुए पाल ने अनुभव किया कि पूँजी-पतियों के मारी प्रभाव के कारण सरकार कुछ नहीं कर सकती है। 'न्यू इंडिया' के 14 अप्रैल 1902 के अंक के एक अन्य संपादकीय में उन्होंने दुर्घटनाओं की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने का कानून बनाने की वकालत की।

'हिंदुस्तान रिव्यू' तथा 'कायस्थ समाचार' के 10 अगस्त 1901 के अंकों में प्रकाशित 'अवर लेबर प्राब्लम' लेख में तथा 1903 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'इकोनामिक आम-पैक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में श्रमिक प्रश्न पर व्यवस्थित रूप में विचार करने वाले जी० मुन्नमनिया अग्रणी थे। इस प्रश्न को ऊपर से नीचे तक श्रमिकों की अनुकूलता की दृष्टि से देखने की चेष्टा करने वाले प्रथम भारतीय नेता भी यही थे।²⁵⁰ उन्होंने विचारपूर्वक देखा कि जिस प्रकार पश्चिम में श्रमिक समस्या पहले ही उभर चुकी है, उसी प्रकार भारत में वह उमरनी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछले वर्षों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में आमनीर पर होने वाली हड़तालें हैं।²⁵¹ उनकी राय में स्थिति का मूलभूत पक्ष था, 'श्रमिक वर्ग की आर्थिक दशा', जिसकी विशेषता है दरिद्रता और दुर्भाग्य।²⁵² उनके अज्ञान और शिक्षा के अभाव ने उनकी स्थिति का और भी अधिक शोचनीय बना दिया है, जहाँ कहीं शिक्षितों और चतुर योग्य व्यक्तियों के साथ उनके हितों का संघर्ष होता है, वही शिक्षित और गतिशाली मालिक सदैव इन असहायों और अशिक्षितों को मूर्ख बनाते हैं।²⁵³ उन्होंने मविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह स्थिति बहुत देर तक चलने वाली नहीं। वह दिन शीघ्र आएगा जब भारतीय श्रमिक जाग उठेंगे, राजनीतिक अधिकारों, संगठित होने का अधिकार तथा अपेक्षाकृत ऊँचे वेतन का अधिकार की मांग ही नहीं करेंगे प्रत्युत उन्हें पाने में विजयी होंगे।²⁵⁴

उसी समय जी० एस० ग्रय्यर ने आधुनिक कर्मचारियों के हित-कल्याण की उपेक्षा करने के लिए भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, असंख्य राजनैतिक संस्थाओं तथा सम्मेलनों की भर्त्सना की।²⁵⁵ इन संस्थाओं पर उपेक्षा के लिए बरसते हुए उन्होंने कहा :

हम इन अभागे वर्गों की दरिद्रता, दुर्भाग्य और असम्मान को देखने के ऐसे आदी हो गए हैं कि अब हमें न तो उद्वेग होता है और न ही उनकी स्थिति को देखकर हमारे शासकों की तथा हमारी अपनी आत्मा विद्रोह करती है। वस्तुतः यह सब शताब्दियों से समाज के उच्च वर्ग द्वारा किए जा रहे निम्न वर्ग के शोषण और दमन का ही परिणाम है।²⁵⁶

इस संदर्भ में उन्होंने ताटस्थ सिद्धांत को एकदम अस्वीकार कर दिया। उनके विचार में इस मामले में प्रतियोगिता के सिद्धांत के प्रयोग की कोई व्यावहारिकता नहीं थी क्योंकि यह प्रतियोगिता सर्वथा असमान थी। कहने को तो श्रमिक स्वतंत्र थे परंतु वास्तव

में वे बेचारे अपनी दैनिक अनिवार्य आवश्यकताओं के दाग ही थे। उनके सामने तो दो ही विकल्प थे : भूखो मरना अथवा किसी भी मूल्य पर अपने श्रम को बेचना।⁵⁷ वस्तुतः प्रतियोगिता का अथवा पूर्ति और माग का यह नियम सर्वथा क्रूर था, जिसके अतंगत धनी अधिक धनी और गरीब और अधिक गरीब बनना है। इस मिथ्या ने तो भारतीय श्रमिक को विवशता की स्थिति पर ता खड़ा किया है।⁵⁸ फिर इस ताटस्थ मिथ्या का विकल्प क्या था ? जी० एस० अय्यर की मान्यता थी कि मालिकों के मन में अपन असहाय, दरिद्र कर्मचारियों के प्रति उदारता और दयालुता की महत्त भावना को पतमाना चाहिए, परन्तु उन्हें अपने मुक्ताव की व्यावहारिकता में सदेह था क्योंकि इस प्रकार की भावना का विकास अनिश्चित तथा अनिर्णीत था और उसका प्रवर्तन मनोचञ्चल तथा अस्थिर था। इससे एक ही मार्ग शेष रहा। राज्य ही एक मात्र ऐसा अभिकरण था जो अग्र-उत्पादन के रूप में स्वतंत्र रहने जाने वाले इस दुर्बल वर्ग को अमोम और वस्तुतः अमान्य प्रतिस्पर्धा से बचाने का दायित्व ले सकता है, निभा सकता है और जिस यह दायित्व उठाना और निभाना ही चाहिए।⁵⁹

जी० एस० अय्यर ने साथ ही साथ यह भी अनुभव किया कि मालिकों द्वारा अपने अधिकार दबाए जाने के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए श्रमिकों को अवश्यमेव एकजुट होना चाहिए तथा अपने संगठन बनाने चाहिए।⁶⁰ इस समय यदि एक श्रमिक अपने मालिक के किसी दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में नौकरी छोड़ता है तो उसका श्रमिक कम वेतन पर ही कार्य करने को सहर्ष तैयार हो जाता है। श्रमिकों में एकता न होने के कारण 'ऐसा करने वाले श्रमिक का उसके समुदाय द्वारा किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता'। इसके विपरीत दूसरे देशों में श्रमिक वेतन का सामान्य स्तर से नीचे गिरा सहन ही नहीं कर सकते। इसके स्थान पर तो वे काम ही बदल देते हैं।⁶¹ वस्तुतः उन्होंने अनुभव किया कि जब अंगरेज श्रमिकों ने संगठित होना सीखा, और 1824 में संगठित होने के अधिकार को प्राप्त कर लिया तभी उनकी प्रगति प्रारम्भ हुई, परिणामी सभ्यता में श्रमिक वर्ग को इनके सशक्त तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का कारण मात्र उनका संगठित होना है।⁶² उन्होंने श्रमिकों को सध में संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए मालिकों से सघर्ष करने के लिए कहा।⁶³ उन्होंने जनता में भी इस बात की अपील की कि अपने को संगठित करने के काम में जनता मजदूरों को हर तरह की सहायता दे।⁶⁴

जी० एस० अय्यर अपनी पूर्वनिर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण पुस्तक में कृषि श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने वाले प्रथम और एकमात्र राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक पूरे अध्याय में इसी विषय का विवेचन किया। कृषि श्रमिकों की अत्यन्त विषम दुर्दशा पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने श्रमिकों के हितों के लिए धानक जमींदारों के दबाव के आगे झुकने के विरुद्ध सरकार को चेतावनी दी।⁶⁵

श्रमिक समस्या के प्रति जागरूकता दिखाने वाले दूसरे भारतीय लेखक 'डान' के संपादक सतीशचंद्र मुखर्जी थे। इस विषय पर उनके विचार अगस्त 1898 के 'डान' में प्रकाशित लेखों, 'आम्बेकट्ठ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन इंग्लैंड एंड इंडिया' तथा 'डान'

के मार्च, अप्रैल, मई और जून 1100 के अंकों में प्रकाशित, 'दि इंडियन इकोनामिक प्राइवलेस' में देखे जा सकते हैं। पश्चिम की औद्योगिक प्रणाली की संचालन विधि की जानकारी मुकर्जी ने अपने समकालीन किसी भी अन्य भारतीय की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। इसके अतिरिक्त उनका दावा था कि वे विशुद्ध रूप से प्रधानतया किसानों और श्रमिकों की हितकामना से ही प्रेरित थे।¹⁶⁶ परन्तु उनके श्रमिक समस्या के विश्लेषण को एक अन्य कारण से भी महत्ता प्राप्त है। यह उन छोटे मोटे बुर्जुआओं, बुद्धिजीवियों, व्यावसायिकों, क्लर्कों तथा कर्मचारियों के उदीयमान वर्गों की प्रथम संयुक्त छवि थी जो पूँजीपतियों के विकासशील वर्ग के विरुद्ध तो थे परन्तु वे अभी तक नए मजदूर वर्ग के साथ अपने को जोड़ नहीं पाए थे। यह एक सत्याग की बात नहीं है कि यह सबान सर्व-प्रथम बंगाल में उठा जहाँ शिक्षित कर्मचारियों और व्यावसायिकों का वर्ग उठ खड़ा हुआ था और स्वदेशी पूँजीपति बहुत कम थे।

मुकर्जी प्रस्तावना रूप में यह मान कर चले कि भारतीय आर्थिक संसाधनों का पूरा पूरा विकास करना ही होगा।¹⁶⁷ परन्तु उनका तर्क था कि यही पर्याप्त नहीं होगा। इस स्थिति में एक उपयुक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ कि साधनों का विकास कौन करेगा और उन पर नियंत्रण कौन रखेगा।¹⁶⁸ ब्रिटिश उद्योगों के विकास के इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत करने हुए उन्होंने कहा कि अब तक तो उद्योगीकरण के सारे लाभ पूँजीपतियों को मिलने लगे हैं। आधुनिक उद्योग के आगमन और विकास की परिणामगत स्थिति यही रही है :

श्रमिकवर्ग जो पिछली कई शताब्दियों तक बड़े बड़े जमींदारों के आधिपत्य की बुराईयों का शिकार रहता था, वह अब समान रूप से अत्याचारी पूँजीपतियों के हाथों में पड़ गया है। यद्यपि वे कहने को (राजनीतिक दृष्टि से) मुक्त हैं परन्तु वस्तुतः आर्थिक दृष्टि में वे अपने पूँजीपति मानिकों के पूर्वापेक्षा अधिक ही अधीन हैं।¹⁶⁹

मुकर्जी ने फ्रेडरिक एंगल्स की प्रसिद्ध पुस्तक, 'वर्किंग क्लासेज इन इंग्लैंड इन 1844' से तथ्य उद्धृत करते हुए ब्रिटिश श्रमिकों की दरिद्रता और निकृष्ट स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया।¹⁷⁰ उन्होंने मित्र किया कि आधुनिक कानून भी उन बुराईयों को मिटाने में असफल रहा था क्योंकि उन बुराईयों की जड़ जितनी प्रतीत होती है उससे कहीं गहरी थी।¹⁷¹ फलतः यदि पश्चिम की औद्योगिक पद्धति को ही भारत में लागू किया गया है तो इसका एक और अनिवार्य परिणाम है, छोटे से अल्पमतीय सुगठित पूँजीपतिवर्ग का उदय, यह वर्ग विदेशी हो अथवा स्वदेशी। इस वर्ग की शक्ति और प्रभाव का अर्थ जनता की सुख-समृद्धि में उन्नति कदापि नहीं।¹⁷² दूसरी ओर श्रमिकवर्ग एकमात्र मशीन बनकर रह जाएगा। वे श्रमिक दूसरों के लिए कमरतोड़ काम करने वाले बन जाएंगे। उनका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा और वे असहाय बन जाएंगे और उस स्थिति में अपने मालिकों के अधीन हो जाएंगे।¹⁷³ इस दुर्दशा से बचने के लिए श्रमिकों को एकजुट होकर विशाल पैमाने पर श्रमिक संघों का संगठन करना पड़ेगा। उन्हें सुगठित पूँजीपतीय शक्तियों के विरुद्ध श्रमिक कल्याण संघों की व्यवस्था के रूप में अपनी सहायता आप

करने का मार्ग ग्रहण करना होगा। यही मार्ग उन्हें 'शांति और व्यवस्था' के लिए एक धमकी और सचमुच ही 'स्थाई रूप से राजनीतिक और सामाजिक खतरा' बना देगा।²⁷⁴

मुखर्जी ने अनुभव किया कि पूंजीपतीय औद्योगिकता का यह द्विमुखी परिणाम समाज को निश्चित रूप से एक गहरी विडंबना में डाल देगा। श्रमसंघों के अस्तित्व से जहां समाज की स्थिरता को खतरा सिद्ध होगा, वहां इनका अभाव इससे भी भयंकर खतरा उत्पन्न करेगा। भली प्रकार संगठित पूंजीपतिवर्ग के अबाध विकास का अंतिम परिणाम होगा, औद्योगिक भ्रष्टादासता।²⁷⁵ यह भयंकर स्थिति लोगों को रकने और विश्लेषण करने के लिए विवश करेगी कि क्या इस स्थिति, जिसमें निश्चित रूप से अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई में मिलाने वाली सभी दूषित विचारों और प्रवृत्तियों वाली संस्थाएं शामिल हैं, के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे भारत की औद्योगिक समस्याओं का समाधान ढूँढा जा सके।²⁷⁶

मुखर्जी द्वारा समस्या का सुझाया उपाय द्विमुखी था, प्रथम नैतिक तथा द्वितीय भौतिक। सारे आर्थिक जीवन को इस प्रकार पुनर्गठित करना चाहिए कि प्रतियोगिता का सिद्धांत नैतिक सिद्धांत पर आधारित हो जाए और वह नैतिकता की महत्ता स्वीकार करे।²⁷⁷ आर्थिक समस्या को व्यापक नैतिक जीवन से संबद्ध रूप में ग्रहण करना चाहिए।²⁷⁸ वस्तुतः समाज की इस नई व्यवस्था में भौतिक संपन्नता को प्रोत्साहन तो दिया जाएगा परंतु जनता इस भौतिक संपन्नता को अनिवार्यतः प्रथम स्थान कदापि नहीं देगी। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विकास ही उन्नति का स्वरूप बन जाएगा।²⁷⁹ भौतिक स्तर पर आधुनिक पूंजीपतीय औद्योगिकता के दोषों का यथासंभव निवारण प्रथम तो स्वयं औद्योगिक संगठनों द्वारा ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पारिवारिक संघ के रूप में उत्पादन-प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी जिसका आधार यह होगा कि कर्मचारी, कारीगर और कृषक सब एक ही परिवार के अंग माने जाएंगे और समान लाभान्वित के अधिकारी होंगे। ये पारिवारिक संघ व्ययमाध्य मशीनों और पूंजी की विपुल राशि की अपेक्षा रखने वाले बड़े पैमाने के पूंजीगत उद्यमों, इंजीनियरी योजनाएं, खानें, रासायनिक तथा धातु शोधन उद्योग, की स्थापना करेंगे। इन उद्योगों के सफल प्रवर्तन से व्यक्तिगत तथा सामूहिक संस्कृति के विकास में किसी प्रकार की बाधा के बदले सहायता ही मिलेगी।²⁸⁰ मुखर्जी ने दावा किया कि आर्थिक संगठन की यह व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली श्रमिकों के स्वाभिमानी और स्वतंत्र वर्ग को जन्म देगी। इस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिक के एक एक दिन के श्रम का विशेष महत्व होगा।²⁸¹ अपनी पद्धति के नैतिक और आर्थिक तत्वों को जोड़ते हुए मुखर्जी ने 1900 में प्रधान रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों के निजी गठन पर आधारित सामूहिक समाज की संस्थापना की सिफारिश इन शब्दों में की:

मेरा विचार यह है कि राष्ट्रीय विकास का कार्य इस रूप में संपन्न किया जा सकता है कि कार्य और गतिविधि के आध्यात्मिक, बुद्धिजीवी, सैनिक, व्यापारिक, तथा बेतन-भोगी सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के समक्ष एक उच्च सांस्कृतिक आदर्श हो। सामाजिक संगठन में सभी के लिए एक सर्वसम्मत निजी और सम्मानित स्थान हो। सभी इस प्रकार पारस्परिक समन्वय और सहयोग से कार्य करें जिससे बिना किसी भेद-

भाव के सारे भारतीय समाज की समान रूप से आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो।¹⁸²

संदर्भ

1. थियोडोर मोरिसन : दि इकोनामिक ट्रांजिशन इन इंडिया (लंदन, 1916), पृ० 174-75.
2. रिपोर्ट आफ दि बांबे फैक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885, पृ० 5.
3. आर० के० दास : फैक्टरी लेबर इन इंडिया (बलिन, 1923), पृ० 56. बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 307-08 भारतीय कारखानों के काम के लंबे घंटों ने इंडिवादी समाचारपत्र 'टाइम्स आफ इंडिया' को भी इतना उत्तेजित किया कि उसने अपने 16 सितंबर 1905 के ग्रंथ में इस कृत्य की इन लब्धों में निंदा की : मालिक श्रमिकों को सवेरे से शाम तक काम करने को विवश कर रहे हैं। नोच मालिक अपने लाभों की अतृप्त तृष्णा के लिए बेचारे श्रमिकों का जीवन रक्त पी रहे हैं—अहमद मुस्तार की पुस्तक 'फैक्टरी लेबर इन इंडिया', मद्रास, 1930 में पृ० 31 पर उद्धृत.
4. बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 312
5. रिपोर्ट आफ दि लार्जे फैक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885, पृ० 8
6. फैक्टरी इंसपेक्टर की रपट—1888. बुकानन . पूर्वोद्धृत, पृ० 310.
7. मारक्विम आफ सैलिसबरी का बांबे सरकार को सप्रेषण, ए० जी० क्लो : इंडियन फैक्टरी सैजिस्लेशन . ए हिस्टोरिकल सर्वे (कलकत्ता, 1926) (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ लेबर की एक रेडियो वार्ता, स० 37) में उद्धृत, पृ० 2.
8. दास : फैक्टरी लेबर इन इंडिया, पृ० 59.
9. दास : फैक्टरी लेबर इन इंडिया, पृ० 59-60. बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 308, 311. क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 29-30
10. रिपोर्ट, पृ० 10.
11. वही, पृ० 13.
12. वही, पृ० 12 तथा देखिए, वही, पृ० 11-3.
13. दास . फैक्टरी लेबर इन इंडिया, पृ० 139 बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 329.
14. रिपोर्ट आफ दि बांबे फैक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885, पृ० 12-3.
15. बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 332 और 349-51; दास : फैक्टरी लेबर इन इंडिया, पृ० 145-6, 152-3. बाडिया और मर्चेंट ने 'ए शार्ट हिस्टरी आफ लेबर कंडीशंस ऐंड दि एंपायर (लेबर कंडीशंस) (लंदन 1942) से एक तालिका प्रस्तुत की है जिसमें यह दिखाया गया है कि 1880-1919 तक भारतीय कारखानों के श्रमिकों के वास्तविक वेतन में निरंतर गिरावट आई है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम विश्वयुद्ध तक की अवधि में धन-वेतनों में वृद्धि की प्रवृत्ति में पर्याप्त एकरूपता रही है, इसके विपरीत दूसरी ओर वास्तविक वेतनों में ह्रास की प्रवृत्ति के दखन होते हैं (पूर्वोद्धृत, पृ० 372).
16. जैम्स ऑस, फैक्टरी इंसपेक्टर की रिपोर्ट. क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 17.
17. देखिए, दास : फैक्टरी सैजिस्लेशन इन इंडिया (बलिन 1923), पृ० 5-11.

18. जे० सी० किड : ए हिस्टरी आफ फेक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया (कलकत्ता 1920) पृ० 4-5
क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 4-5,
19. किड : पूर्वोद्धृत, पृ० 9. क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 4
20. दास : फेक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 15; किड : पूर्वोद्धृत, पृ० 5
21. दास : फेक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 16 सरकार ने हमारे बदले एक अन्य स्थिति ग्रहण की कि स्वयं पीड़ितों द्वारा अपने आप अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा मिनमालिज़ा द्वारा किए गए किसी अत्याचार के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत ही नहीं मिली है। (क्लो द्वारा उद्धृत : पूर्वोद्धृत, पृ० 6)
22. दास : फेक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 18-20
23. वही, पृ० 16-7.
24. उदाहरणार्थ इसका 15 जनवरी 1880 व। प्रक देखिए (आर० एन० पी० बंग०, 17 जनवरी 1880).
25. डी० चमनलाल : कुली (लाहौर 1932) खंड II पृ० 78 और क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 9.
26. क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 11.
27. 1881 के ऐक्ट की सख्या, 15.
28. किड—पूर्वोद्धृत, पृ० 21 पर उद्धृत.
29. आर० एन० पी० बंग०, 28 नवंबर 1874
30. वही, 4 जनवरी 1879
31. वही, 4 जनवरी 1879 तथा 25 जनवरी 1879 क्रमश.
32. वही, 13 दिसंबर 1879, 13 नवंबर 1880, 2 अप्रैल 1881 क्रमश
33. 26 जनवरी (वही, 1 फरवरी 1879) और 23 नवंबर (वही, 29 नवंबर 1879)
34. वही, 13 नवंबर 1880.
35. वही, 26 मार्च 1881
36. वही, 22 नवंबर 1879.
37. इसका कारण कदाचिन् यह तथ्य था कि एम० एस० बंगाली उनके स्वामियों में एक थे
38. 28 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 2 अप्रैल 1881).
39. क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 9.
40. आर० एन० पी० बंग०, 27 मार्च, 22 मई, 2 अक्टूबर 1875 तथा देखिए, ए० बी० पी०, 2 सित० 1875. बी० बी० मजूमदार द्वारा पूर्वोद्धृत, पृ० 353 पर उद्धृत.
41. नेटिव ओपीनियन, 29 दिसंबर 1878, 19 जनवरी 1879; गुजरात मित्र, 29 दिसंबर 1878, 12 जनवरी 1879, जामे जमसेद, 8 जनवरी 1879; जलगांव समाचार, 19 जनवरी 1879, बर्हई समाचार, 23 जनवरी 1879; खानदेश वंश, 13 जनवरी 1879; याज्ञदान परस्त, 26 जनवरी 1879; बरुणोदय, 26 जनवरी 1879; लोकमित्र, 26 जनवरी 1879; और सत्य सदन, 15 फरवरी 1879 (देखिए आर० एन० पी० बंग०, सप्ताहात, 4, 11, 18 और 25 जनवरी तथा 1, 15, 22 फरवरी 1879); 'बकीन ए हिंदुस्तान', 28 दिस०, 1878 (आर० एन० पी० पी० एन० 4 जनवरी 1879); बख्तबारे बाम, 8 जनवरी (वही, 11 जन० 1879); नसीमे आधरा 30 जनवरी (वही, 1 फरवरी 1879); भारत मिहिर, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 8 फरवरी 1879); सहृदय, 10 मार्च (वही, 15 मार्च 1879).

- 42 देखिए, आर० एन० पी० ब० के संबंधित ग्रंथ.
- 43 फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, ज० पी० एस०, जुलाई 1881 खंड IV स० 1, पृ० 39
44. 17 मार्च, 26 मार्च और 24 मार्च 1881 त्रमण
- 45 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 8 जनवरी 1880)
- 46 बंबई के लिए देखिए, जाम जमशेद, 28 नव० 1879 और 14 मार्च 1881, बंबई समाचार 8 दिसंबर 1879 और 22 दिस० 1880, लिटिल, 11 दिस० 1879, सूर्यप्रकाश, 13 दिस० 1879 और 19 मार्च 1881, जमशेर बहादुर, 11 दिस० 1879, सूर्योदय, 29 नव० 1880, बांबे क्रान्तिक, 14 मार्च 1881, यात्रादान परस्त, 13 मार्च 1881 खानदेश वैभव, 18 मार्च 1881, गुजरात मित, 20 मार्च 1881, गंगा लहरी, 2^र मार्च 1881, शुभसूचक, 25 मार्च 1881, शिवाजी, 25 मार्च 1881, न्याय प्रकाश, 28 मार्च 1881 आर्यावर्त तथा नासिक वृत्त, 9 अप्रैल 1881 (देखिए आर० एन० पी० ब० के संबंधित ग्रंथ) बंगाल के लिए देखिए, सहचर 14 मार्च (आर० एन० पी० ब० 26 मार्च 1881), नवविभाकर 21 मार्च, साधारणी 27 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881), भारत मिहिर, 29 मार्च (वही, 9 अप्रैल 1881), आनंद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1881)
- 47 गॉटव आर्पाइनियन, 19 जनवरी (आर० एन० पी० ब०, 25 जनवरी 1879), गंगा लहरी, 25 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881), बंगाली, 26 मार्च 1881, और दि फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया पूर्वाक्त स्थल, पृ० 489 मजेदार बात यह है कि यह तर्क उभर ममय बिना किसी हवकिचाहट या परेशानी के ताक पर रख दिया गया जब राष्ट्रवादी नेताओं ने बागान मजदूरों अथवा किसानों का मामला उठाया उम समय उन्होंने अचानक इन मूक प्राणियों की बाणी की भूमिका अपना ली
- 48 जाम जमशेद, 25 मार्च (आर० एन० पी० ब०, 27 मार्च 1875), गुजराती, 28 नवंबर (वही, 4 दिस० 1880), सहचर, 14 मार्च (आर० एन० पी० ब० 26 मार्च 1881), दि बाह्यो पब्लिक ओपीनियन ने 27 फरवरी 1879 के धक में लिखा कर्मचारियों और मालिकों के आपसी संबंध पूर्णतः स्वस्थ हैं। कर्मचारियों से कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं लिया जाता। उनके वतन निश्चित हैं और वे पूर्ण उदारता के साथ तथा नियत समय पर दिए जाते हैं इसके लिए अंगरेजी और देशी कारखान सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। कतिपय अपवादों को छोड़कर सभी कारखान प्रायः ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हैं जब कोई कर्मचारी कारखाने में बीमार पड़ जाता है तो मालिक उसके स्वास्थ्य की भलीभांति देखभाल करते हैं
- 49 बंबई समाचार, 2 मई (आर० एन० पी० ब०, 3 मई 1879), और 2 दिसंबर (वही 4 दिस० 1880), जामे जमशेद, 28 नवंबर (वही, 29 नव० 1879), सहचर, 14 मार्च (आर० एन० पी० ब०, 26 मार्च 1881)
- 50 'फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 49
51. जामे जमशेद, 17 मई (आर० एन० पी० ब०, 22 मई 1875), फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35-6 और 41, ए० बी० पी० 17 मार्च 1881
- 52 गुजरात मित, 12 जन० (आर० एन० पी० ब०, 18 जन० 1879), 'फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 37, 40 और 49 इनमें से परवर्ती में निम्नलिखित अवतरण प्रकाशित हुआ था : 'इस कथन में कोई अतिरजना नहीं कि जहां तक नियमानुसार कारखानों में काम

करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सामान्य रूप-आकार का संबंध है, वे पहले की किसी भी स्थिति से अथवा अन्य किसी भी प्रकार की नौकरी में होने पर संभावित स्थिति से अपेक्षाकृत अच्छे ही हैं। . . . अन्य व्यापारों में कार्यरत बच्चों की अपेक्षा कारखानों में काम करने वाले बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, पहनने को बढ़िया कपड़ा मिलता है, अतः वे अधिक स्वस्थ और दृष्ट-शुष्ट दिखाई देते हैं (पृ० 49)।

53. आर० एन० पी० बंब०, 4 जनवरी 1879.
54. पृ० 47 तथा देखिए 19 जून का नेटिव ओपीनियन तथा अरुणोदय (आर० एन० पी० बंब०, 25 जून 1881); ज्ञान-प्रकाश, 30 जून (वही, 2 जुलाई 1881)
55. पूर्वोक्त स्थल, पृ० 44-7. लेखक ने विचार प्रकट करते हुए आगे लिखा : हमें समझ नहीं आता कि मालिक बेचारों को अपनी रक्षा के लिए उपाय करने के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है. (पृ० 47).
56. वही, पृ० 47-8 तथा लोकमित्र, 23 नवंबर (आर० एन० पी० बंब०, 29 नवंबर 1879); हितेच्छु, 11 दिस० (वही, 20 दिसंबर 1879); 19 जून का नेटिव ओपीनियन तथा अरुणोदय (वही, 25 जून 1881); ज्ञान प्रकाश, 30 जून (वही, 2 जुलाई 1881).
57. 'फैक्टरी लैब्रिस्मेशन इन इंडिया' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 48, 19 जून का नेटिव ओपीनियन और अरुणोदय (आर० एन० पी० बंब०, 25 जुलाई 1881); ज्ञान प्रकाश, 30 जून (वही, 2 जुलाई 1881).
58. नेटिव ओपीनियन, 29 दिस० 1878 (आर० एन० पी० बंब०, 4 जनवरी 1879); लोकमित्र, 26 जन० (वही, 1 फरवरी 1879); अखबारे सौदागर, 19 नव० (वही, 22 नवंबर 1879); बांबे क्रानिकल, 14 मार्च, याजदान परम्त, 13 मार्च, जामे जमशेद, 14 मार्च, सूर्य प्रकाश, 19 मार्च (वही, 26 मार्च 1881); न्याय प्रकाश, 28 मार्च, गुजराती, 27 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881), अखबारे आम, 8 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 11 जनवरी 1879), नमीमे-आगरा, 30 जनवरी (वही, 1 फरवरी 1879); हिंदी प्रदीप, जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 8 जनवरी 1880); ए० बी० पी०, 17 मार्च 1881; 'फैक्टरी लैब्रिस्मेशन इन इंडिया'—पूर्वोक्त स्थल, पृ० 40; नवविभाकर, 21 मार्च (आर० एन० पी० बंब०, 2 अप्रैल 1881); भारत मिहिर, 29 मार्च (वही, 9 अप्रैल 1881); आनंद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1881).
59. बी० बी० मजूमदार : पूर्वोक्त, पृ० 353 पर पादटिप्पणी. इसी प्रकार 8 जनवरी 1879 के प्रंक में अखबारे आम ने दृढ़ता से स्वीकार किया कि यदि श्रमिकों से अधिक काम भी लिया जाता है तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आखिर देश को लाभ ही तो होता है। इस पक्ष ने लिखा है कि युद्धकाल में एक सिपाही को न केवल अधिक कार्य करना पड़ता है प्रत्युत मरना भी पड़ता है. भारत का उद्योगीकरण युद्ध से कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इसी में देश का उद्धार निहित है
60. नेटिव ओपीनियन, 29 दिस० 1878 (आर० एन० पी० बंब०, 4 जनवरी 1879); ए० बी० पी०, 12 नवंबर 1880; गुजरात मित्र, 20 मार्च, (आर० एन० पी० बंब०, 26 मार्च 1881); गंगा सहरी, 25 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881); 'फैक्टरी लैब्रिस्मेशन इन इंडिया'—पूर्वोक्त स्थल, पृ० 31 और 40; साधारणी, 27 मार्च (आर० एन० पी० बंब०, 2 अप्रैल 1881); भारत मिहिर, 29 मार्च (वही, 9 अप्रैल 1881); आनंद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1881).

61. फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 31 गंगा लहरी, शुभसूचक और शिवाजी, 25 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 2 अप्रैल 1881); दि ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियम, 27 फरवरी 1879; ए० बी० पी०, 16 जनवरी, 1880
62. बगाली, 26 मार्च 1881
63. पूना सार्वजनिक सभा का स्मरणपत्र, एल० सी० पी० 1881 खंड XX पृ० 100 पर उद्धृत तथा रास्त गुप्तार, 7 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 13 दिसंबर 1879). रास्त गुप्तार तो इस कानून को सेना पर भी लागू करना चाहता था
64. 'फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35-6 तथा मोमप्रकाश, 28 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 2 अप्रैल 1881).
65. जामे जमशेद, 25 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 27 मार्च 1875), बर्बर्ड समाचार, 18 मई (वही, 22 मई 1875), अरुणोदय, 26 सितंबर (वही, 2 अक्तूबर 1875), गुजरात मित्र, 12 जनवरी (वही, 18 जनवरी 1879), नेटिव ओपीनियम, 19 जनवरी (वही, 25 जनवरी 1879), अरुणोदय, 26 जनवरी (वही, 1 फरवरी 1879), खानदेश वैभव 13 जनवरी वही 15 फरवरी 1879), सत्य सदन, 15 फरवरी (वही, 22 फरवरी 1879), हितेच्छ, 11 दिसंबर और सूर्य प्रकाश, 13 दिसंबर (वही, 20 दिसंबर 1879); बर्बर्ड समाचार 9 दिसंबर (वही, 13 दिसंबर 1879) इंदु प्रकाश, 22 मार्च (वही, 27 मार्च 1880), ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियम 27 फरवरी 1879, ए० बी० पी०, 16 जनवरी और 19 मार्च 1880. अखबारे आम, 8 जनवरी (आर० एन० पी० ए० एन०, 11 जनवरी 1879), नसीमे आगरा, 30 जनवरी (वही, 1 फरवरी 1879) भारत मित्र, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 8 फरवरी 1879); सहचर, 10 मार्च (वही, 15 मार्च 1879), हिंदी प्रदीप, जनवरी (आर० एन० पी० ए० एन०, 8 जनवरी 1880); गुजरात मित्र, 20 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 26 मार्च 1881), नेटिव ओपीनियम, 27 मार्च, गंगा लहरी, 25 मार्च न्यायप्रकाश, 28 मार्च, गुजराती, 27 मार्च, शुभसूचक, 25 मार्च और शिवाजी, 25 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881); मराठा, 13 मार्च 1881, ए० बी० पी० 17 मार्च 1881, बगाली, 26 मार्च 1881, 'फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया' पूर्वोक्त स्थल पृ० 30 और 43, सहचर, 14 मार्च (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च 1881), नवविभाकर, 21 मार्च, साधारणी, 27 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881); आनंद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, 16 अप्रैल 1881).
66. आर० एन० पी० बब०, 26 मार्च 1881.
67. 'मराठा' तो कुछ एक मर्त्या अकालप्रोढ़ सुझाव देने की सीमा तक चला गया. 'जनता को जागरूक बनाने की चेष्टा किए बिना राजनीतिक अधिकारों के लिए किसी प्रकार के संघर्ष का कोई भी फल नहीं निकलेगा. आइए भोलीभाली अनजान जनता को समझाए कि नॉचेस्टर कितनी प्रबलता से अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुटा है. भारत के अबोध लोगों को सरकार की गतिविधियों से परिचित कराइए. उन्हें बताइए कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए. हमें विश्वास है कि हमारे प्रयत्नों को अवश्य सफलता मिलेगी.
68. नेटिव ओपीनियम ने भी 26 मार्च 1891 के श्रक में इसी प्रकार की अपील की थी (आई० एस० वी० ओ० आई० 19 अप्रैल 1891, पृ० 316). यह अपील इंडियन फैंक्टरी, (संशोधन) ऐक्ट, 1891 के पास होने के समय की गई थी.
69. दास : फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया; पृ० 31-2. क्लो : पूर्वोद्धृत, पृ० 13.

- 70 रिपोर्टें आफ दि फैंक्टरी लेबर कमीशन आफ 1885 पृ० 10-15 उद्घाटन यह भी मिफारिश की थी कि वष में 6 महीने में कम समय तक काम करने वाले कारखाना में मंत्रियों और बच्चों को 16 घंटे प्रतिदिन को नौकरी मिलनी चाहिए और उन्हें दो घंटे का अवकाश मिलना चाहिए यह मिफारिश कमीशन की मानवीय मन प्रवृत्ति का सर्वात्मता का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि श्रमिकों के पक्षधर किंग्स्टन ग्राफ्टब्रिगेडो, 113 व साप्ताहिक 'दीन' 14 न 25 जनवरी 1885 के अंक में कमीशन की मिफारिशों की निंदा की और दिया जमी जमी प्रकाशित रिपोर्टें यह स्पष्ट करती है कि कमिशनर वे लोग हैं जिन्होंने मिलमानिरो के हितों की ही रक्षा की है यदि सरकार ने कमीशन की मिफारिशों में अनुरूप कोई कार्यवाही की तो श्रमिकों का उदास भारी अहित होगा (आर० एन० पी० बब०, 31 जनवरी 1885)
- 71 दाम फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 37
- 72 वही, अध्याय 3 और किड पूर्वोद्धृत, पृ० 37
- 73 आर० एन० पी० बब० न 9 अक्टूबर 1880 के बाद के अंक में इसे आगे मूल रूप में सम्मिलित किया इसका प्रथम अंक सन्वत् 3 अक्टूबर 1880 को प्रकाशित हुआ आर० क० दाम और उनके परिवर्तनों लेखकों ने इस समाचारपत्र का 1880 वर्ष में अम गलत लिखा है उदाहरणार्थ देखिए फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 62, मुन्नार पूर्वोद्धृत पृ० 96 और एम० डी पुणेकर ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया (बंबई 1948) पृ० 59
- 74 रिपोर्टें आफ दि बाबे फैंक्टरी लैबर कमीशन 1885, पृ० 230।
- 75 रिपोर्टें आफ दि इंडियन फैंक्टरी लेबर कमीशन 1890 पृ० 15-20 दाम फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 13, किड पूर्वोद्धृत पृ० 51-2
- 76 रिपोर्टें आफ दि वकिंग आफ दि फैंक्टरी ऐक्ट इन बाबे फार दि दाय० 1885 में इस संबंध में निम्नलिखित अवतरण है उद्धृत क कारखाना श्रमिकों का कोई मुनाफा श्रमिकों से नहीं है यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यद्यपि पिछले फैंक्टरी कमीशन में काम करने वाले श्रमिकों एम० लोखंड अपन जापना 1885 के श्रमिकों से वा प्रमाण बनाता है परंतु उस सच का एक सगठित दल के रूप में कोई प्रतिपक्ष है और न ही सदस्यों का कोई सूची है न कोई कोष है और न ही कोई नियमावली है मंत्र विचार में जो भी श्रमिकों लायर्ड के पास आता है वह उस स्वेच्छा से परामर्श देता है (पृ० 15) मुन्नार द्वारा उद्धृत पूर्वोद्धृत पृ० 8 फैंक्टरी इंसपेक्टर की 1892 की रिपोर्ट के अनुसार सच एक ऐसा तत्व था जो किमो भा रूप में कम से कम वर्तमान में तो स्वामी और मजदूरों के आपसी संबंध का किमा रूप में प्रभावित नहीं कर सकता था (बुकानन पूर्वोद्धृत, पृ० 421 उद्धृत)
77. दीनबधु का अर्थ है 'गरीबों का दास्त' इसके अनिर्गुण वह कदाचित् सोराबजी एस० बंगाली के अभिन्न मित्र थे
- 78 देखिए, दाम फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, अध्याय 3 किड पूर्वोद्धृत, अध्याय 3
- 79 इस बिल के प्रारूप में मंत्रियों के लिए एक दिन में 11 घंटे कार्य करने की सीमा निर्धारित करने की तथा महीने में मंत्रियों और बच्चों के लिए चार अवकाश दिनों के निर्धारण की व्यवस्था की वयस्क श्रमिकों में सबधित किमी प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं था, दाम फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 48-9
- 80 किड पूर्वोद्धृत, पृ० 48-49, दाम फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 49-50
- 81 किड पूर्वोद्धृत, पृ० 48-49, दाम फैंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 50-60.

- [illegible]

- (वही, 13 दिस० 1890), गुजराती, 7 दिस० (वही), मराठा, 14 दिसबर 1890, समय, 12^१ दिसबर (आर० एन० पी० बग०, 20 दिसबर 1890)
- 95 1890 के बिल और 1891 के ऐक्ट पर समाचारपत्रों की टिप्पणियों में कमी का एक अन्य कारण यह था कि समाचारपत्र पहले ही एज आफ कानसेंट बिल (सहमति बिल) में व्यस्त थे
- 96 जामे जमशेद, 8 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 4 मार्च 1891) तथा इंदु प्रकाश 11 अप्रैल 1891, मराठा, 5 अप्रैल 1891, सुरभि ओ पताका, 10 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 18 अप्रैल 1891), सहचर, 9 सितंबर (वही, 19 सितंबर 1891)
- 97 मराठा, 16 फरवरी 1890 और 5 अप्रैल 1891, सुरभि ओ पताका, 13 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 22 फरवरी 1890), दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 5 मार्च (वही, 8 मार्च 1890), के० एल० नुलकर, एल० सी० पी० 1891 खड XXX, पृ० 177, 179
- 98 हिंदू ने 10 दिसंबर 1890 के घक में अपेक्षाकृत और अधिक आशा प्रकट की उसके संपादक ने यह कहते हुए कि—'श्रमिकों की स्थिति अच्छी है और वे काफी प्रसन्न हैं, लिखा कि उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार उनके पारिश्रमिक बढ़ गए हैं, किस अच्छी प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है और कितना सुखद भविष्य उनके सामने है सहचर, 11 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 21 मार्च 1891)
- 99 आर० एन० पी० बग०, 17 मई 1890 तथा सहचर, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बग०, 19 सितंबर 1891) यह द्रष्टव्य है कि सरकारी प्रवक्ताओं ने भारत में निर्धनता की स्थिति को नकारने के लिए आय और आवश्यकताओं की सापेक्षिकता का तर्क पेश किया तो राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अवैज्ञानिक, 'क्रूर तथा हृदयहीन' बताकर अस्वीकृत कर दिया देखिए अध्याय 1
- 100 दाम फंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 90-1 तथा हिंदुस्तान, 1 जून (आर० एन० पी० एन० 5 जून 1889¹)
- 101 मराठा, 1 जन 1884, गुजरात दर्पण, 30 मई (आर० एन० पी० बग०, 1 जून 1889), भारत जीवन, 1 दिसंबर (आर० एन० पी० एन०, 9 दिस० 1890), दाम के फंक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 90 पर उद्धृत के० एन० बहादुरजी; सहचर, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बग०, 19 सितंबर 1891)
- 102 आर० एन० पी० बग०, 26 जनवरी 1889
- 103 हिंदू, 17 मई 1889, समय, 28 दिसंबर 1888 (आर० एन० पी० बग०, 5 जनवरी 1889), मुखम समाचार और कुशदाह, 18 जन (वही 26 जनवरी, 1889), मराठा, 14 दिस० 1890, समय, 14 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 22 फरवरी 1890), नेटिव ओपीनियन, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1890)
104. कतिपय समाचारपत्रों ने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया परंतु केवल जून 1890 से पहले तक ही देखिए, समय, 24 मई (आर० एन० पी० बग०, 1 जन 1889), हिंदुस्तान, 22 मई (आर० एन० पी० एन०, 29 मई 1889), और 23 अप्रैल (वही, 28 अप्रैल 1890), भारत जीवन, 1 दिस० (वही, 9 दिस० 1890), नेटिव ओपीनियन, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 1890), इस सदर्भ में 22 फरवरी 1889 के घक में हिंदुस्तान ने इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि इस कदम से मिलमालिक अपने लाभ के सप्तमास से बर्चित हो आएंगे यह भी मजेदार बात है कि उस समय हिंदुस्तान का संपादक कोई और नहीं मदनमोहन मालवीय थे और मालिक थे राजा रामपालसिंह जो उन दिनों कांग्रेस के मंच के एक प्रबल

साहसी ब्रह्मा थे. देखिए : रि इडिबन नेबन बिलडर्स (मद्रास, तिथि-रहित, तृतीय संस्करण) भाग 1 पृ० 146.

105. 6 अप्रैल 1891. इस बात का श्रेय उसे अवश्य मिलना चाहिए कि इस विचित्र रविवे का प्रयोजन भी उसने उसी बंधादकीय में स्पष्ट कर दिया है...परंतु श्रमिकों के हितों से अलग हटकर ... यह पूछना उपयुक्त होगा कि क्या सरकार पर पूंजीपतियों, इस प्रकार के कानून से बिनके उत्पादक उद्यम बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं, के हितों की देखभाल का दायित्व नहीं है. स्पष्ट है कि हिंदु प्रकाश के लिए उदीयमान औद्योगिक पूंजीवाद की शक्तियों के विरोध की अपेक्षा हिंदू रुढ़िवादिता को क्षीण करने वाली शक्तियों का विरोध करना सरल ही था.
106. मराठा, 13 मार्च 1892; संजीवनी, 5 दिसंबर (आर० एन० पी० बंग०, 12 दिसंबर 1891); नेटिव ओपीनियन, 10 मार्च, गुजरात दर्पण, 10 मार्च, बंबई समाचार, 7 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 12 मार्च 1892) और देखिए, बंगबासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 16 (अप्रैल 1892).
107. हिंदुस्तान, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 28 अप्रैल 1890); भारत जीवन, 1 दिसंबर (वही, 9 दिसंबर 1890); मराठा, 7 दिस० 1890. हिंदू, 16 मित० 1891.
108. आर० एन० पी० बंग०, 18 अप्रैल 1891.
109. और देखिए, बंबई समाचार, 4 दिसंबर (आर० एन० पी० बंग०; 6 दिसंबर 1890)
110. ए० बी० पी० मराठी 1889; हिंदू, 17 मई 1889, कोहेनूर, 28 मई (आर० एन० पी० पी०, 8 जून 1889); समय, 14 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 22 फरवरी 1890); भारत जीवन, 1 दिसम्बर (आर० एन० पी० एन०), 9 दिसम्बर 1890) दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 5 मार्च (वही, 8 मार्च 1890), मुराशि ओ पताका, 10 अप्रैल (वही, 18 अप्रैल 1890); सहचर, 9 सितंबर (वही, 19 सितंबर 1891); इंदु प्रकाश, 11 अप्रैल 1891.
111. सी० बी० ए०, पृ० 264-5. बैनर्जी ने बंगाल के विदेशी स्वामित्ववाले पटसन उद्योग को भी अपने संरक्षण में लिला ओ हुंडी के प्रहार का शिकार था
112. और देखिए, मराठा, 23 दिसंबर 1888; समय, 28 दिसंबर (आर० एन० पी० बंग०, 5 जनवरी 1889); मुराशि ओ पताका, 10 अप्रैल (वही, 18 अप्रैल 1891); गम क्वारे हिंद, 21 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 28 मार्च 1891)
113. मराठा, 23 दिस० 1888; ए० बी० पी० 8 फरवरी 1889; हिंदू, 14 और 17 मई 1889 और 10 दिस० 1890; ज्ञान प्रकाश, 16 मई और ट्रिब्यून, 22 मई (बी० ओ० आई०, जून 1889); सुलभ समाचार और कुलदाह, 18 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 26 जनवरी 1889); मुराशि ओ पताका, 31 जनवरी (वही, 9 फरवरी 1889); सहचर, 7 फरवरी (वही, 16 फरवरी 1889); प्रतिकार, 7 जून (वही, 15 जून 1889); हिंदी प्रदीप (आर० एन० पी० एन० 26 जून 1889); गुजरात दर्पण, 30 मई और मिबाजी, 24 मई (आर० एन० पी० बंग०, 1 जून 1889); कोहेनूर, 28 मई (आर० एन० पी० पी०, 8 जून 1889); संजीवनी, 8 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 15 फरवरी 1890); समय, 14 फरवरी (वही, 22 फरवरी 1890); दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 5 मार्च (वही, 8 मार्च 1890); कासिम जल अखबार, 10 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 28 फरवरी 1890); भारत जीवन, 1 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 9 दिस० 1890); ट्रिब्यून, 11 मार्च (आई० एस० बी० ओ० आई०, 29 मार्च 1891 पृ० 257); नेटिव ओपीनियन, 26 मार्च (वही, 19 अप्रैल 1891 पृ० 316); सहचर, 11 मार्च (आर० एन० पी०

- बग, 21 मार्च 1891), गम ह्वारे हिंद, 21 मार्च और 20 जून (आर० एन० पी० पी०, 28 मार्च और 4 जुलाई 1891) के एन० नुनकर, एल० सी० पी० 1891 खड XXX पृ० 177; बगदामी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 16 अप्रैल 1892) एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 2645
- 114 नैजिस्मटिव सोमिन भ फेस्टा विन पर विचार प्रकट करते हुए के० एन० नुलार न मानवतावाद को एक मात्र निर्देशक तत्त्व मानने वाले इंग्लैंड के परांपराग्रियों के सन्नयन में व्यग्न करत हुए हुए है 'उनका कदाचित्त यह विश्वास है कि वे अपनी निरपेक्षता का पर्याप्त प्रमाण भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं अस्तु ये ही वे लोग थे जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व कपाम पर सीमा शुल्क हटवान में सफलता प्राप्त की थी और इससे हुए घाट को पूरा करने के लिए सरकार पर नमक कर में वृद्धि के लिए दबाव डाला था भारतीय जनता इन महानुभावों के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकती वह तो इन निरपेक्ष मित्रों से क्षमा चाहती है और इनमें साधारणता हीन के बदले जगली रहना हो अति पसंद करती है क्योंकि इसमें उसे सस्ता नमक और थोड़ा बहुत वस्त्र तो उपलब्ध ही मकेंगे एन० सी० पी० 1891 खड XXX पृ० 1778 तथा बगानी, 27 अप्रैल 1889 और हिंदू, 17 मई 1889
- 115 उदाहरणार्थ 1884 मराठा के मपादक महाराष्ट्र के क्रानिकारी सामाजिक और राजनीतिक विचारक जी० जी० आगरकर थे 1881 में इसका सपादक और स्वामी बदन गण अक्तूबर 1888 तक अगरकर इस पत्र के लिए लिखते रहे सितंबर 1891 में गण और परिवर्तन आया
- 116 इंडिया स्पेक्टेटर, 3 अगस्त (आर० एन० पी० बब०, 9 अगस्त 1884), मराठा, 6 अक्तूबर 1884 और 1 जुलाई 1889, गुजराती, 9 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 15 नवंबर 1890)
- 117 इंडियन स्पेक्टेटर 4 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 10 नवंबर 1883), मराठा, 12 अक्तूबर 1890
- 118 इंडियन स्पेक्टेटर, 4 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 10 नवंबर 1883) सुबोध पत्रिका 29 सितंबर बंग० ओ० आइ० अक्तूबर 1994), मराठा, 5 अक्तूबर 1884 7 दिसंबर 1888, 15 सितंबर 1889, 16 मार्च 1890 और 12 अक्तूबर 1890, गुजराती 9 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 15 नवंबर 1890)
119. मोरिमन पूर्वोद्धृत, पृ० 175
- 120 बुकानन . पूर्वोद्धृत, पृ० 272
- 121 वही, पृ० 303, 307, 322 तथा देखिए, कर्जन, स्पेक्टेज II, पृ० 257-8
- 122 बुकानन पूर्वोद्धृत, पृ० 265, 267
- 123 वही, पृ० 263
- 124 दि इंडियन मास एस ऐक्ट—1901 (1901 की ऐक्ट की संख्या VIII) में भारत सरकार द्वारा खाना के प्रधान इम्पैक्टर को और राज्य सरकार द्वारा दूसरे इम्पैक्टरों को नियुक्ति की व्यवस्था की प्रधान इम्पैक्टर को सुरक्षा और स्वास्थ्य को दृष्टि से स्थिति के अन्वय अथवा अनुपयुक्त होने पर खानों में बच्चों और स्त्रियों की नियुक्ति को रोकने का अधिकार दिया गया इम्पैक्टरों का यह दायित्व था कि वे खानों में उपयुक्त रोजनदानों तथा सफाई के अन्य ऐसे साधनों की व्यवस्था कराएँ 12 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया था अधिनियम में खान प्रबंधकों के कर्तव्यों और योग्यताओं से संबंधित नियमों के बनाने की भी व्यवस्था थी
- 125 हितवादी, 24 मार्च (आर० एन० पी० बग० 1 अप्रैल 1899) समय, 6 अप्रैल (वही, 14 अप्रैल 1900), हिंदु प्रकाश, 22 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 24 मार्च 1900), हिंदुस्तान, 24 फरवरी

- (आर० एन० पी० एन०, 27 फरवरी, 1900), एडवाकेट, 18 जनवरी (वही, 26 जनवरी 1901), बंगाली, 6 दिसम्बर 1900 और 19 जनवरी, 1901, ए० बी० पी०, 16 मार्च 1901; हि०, 26 मार्च 1901, श्री राम, एन० सी० पी०—1901 खंड XL पृ० 207
- 126 प्रस्ताव सं० XXXLV तथा हितावादी, 24 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 1 अप्रैल 1799); ए० बी० पी०, 16 मार्च 1901
- 127 श्री एन० बंग, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 102-04.
- 128 मार्च 4 अर्थात् (आर० एन० पी० बंग०, 14 जुलाई 1894), हितावादी, 24 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1899), समय, 6 अप्रैल (वर्ग, 14 अप्रैल 1900); बंगाली, 6 दिसम्बर 1900, बी० एन० बंग रिप० आई० एन० सी०, 1900 पृ० 104, ए० बी० पी०, 16 मार्च 1901
- 129 समय, 6 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 14 अप्रैल 1900), श्रीराम, एन० सी० पी० 1901 खंड XI, पृ० 207
- 130 द्रु प्रसाद, 22 मार्च (आर० एन० पी० बंग 24 मार्च 1900), बी० एन० बंग, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 103, हितावादी, 11 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 19 जनवरी 1901)
- 131 आर० एन० पी० बंग०, 1 अप्रैल 1899 बंगाली न ता 20 अप्रैल 1902 के श्रक में यह श्रम प्रकट किया गया कि मजदूर मजदूर श्रमिक कथम के उग्र स्वर का ही नोट कर देगा, मिस्टर प्रेसिडेंट मैम हितावादी श्री जिनकी मजदूरी प्रस्ताव करत हुए अघाते नहीं
- 132 बंगाली 6 दिसम्बर 1900 ए० बी० पी० 16 मार्च 1901; श्रीराम, एन० सी० पी० 1901 खंड XI पृ० 208, श्री एन० बंग रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 104
- 133 बंगाली 6 दिसम्बर 1900, आई० एन० सी०—1900 का प्रस्ताव सं० XXXIV तथा आई० एन० पी० 1901 का प्रस्ताव सं० XVIII
- 134 ए० बी० पी० 1901 का प्रस्ताव XXXIV, बी० एन० बंग, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 104
- 135 द्रु प्रसाद, 22 मार्च (आर० एन० पी० बंग 24 मार्च 1900), बंगाली 6 दिसम्बर 1900 और 19 जनवरी 1901, ए० बी० पी०, 16 मार्च 1901, श्रीराम, एन० सी० पी०—1901 खंड XI पृ० 208, बी० एन० बंग रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 104
- 136 हितावादी, 24 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 1 अप्रैल 1899); द्रु प्रसाद, 22 मार्च (आर० एन० पी० बंग, 24 मार्च 1900 एडवाकेट 18 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 26 जनवरी 1901), हि० 26 मार्च 1901, बंगाली, 12 जन० 1901 हितावादी 11 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 19 जनवरी 1901), समय, 19 जनवरी (वही, 26 जनवरी 1901, बी० एन० बंग रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 103 इससे पूर्व 1894 में 4 जुलाई के श्रक में 18 जनवरी तक उड़ी मजदूर परिषद्वादी की हितावादी खान कानून बोधने के काम बड़ा कर मजदूर इच्छाओं की श्रम मजदूर का न्याय विचारण है उसने बंगाल के साथ लिखा कि यह जातिविक्रम उदारता कोरी 'मजदूर' है (आर० एन० पी० बंग०, 14 जुलाई 1894)
- 137 रिपोर्ट आफ दि मिलऑनस एसोसिएशन फार 1891, पृ० 8 साथ के बायिक अधिवेशन के साथ के एक महत्वपूर्ण मध्यम मार्त वास्तव ने आपण के समय अधिक यथार्थ तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत किया 'इसे मताप का विषय हो समझना चाहिए कि 1884 के फैक्टरी अधिनियम द्वारा की गई सिफारिशों मग की उन सिफारिशों के अनुकूल हैं जिन पर समय सच कर इस भवन में चर्चा की

जाती रही... मेरा विचार है कि हम मिल अधिकारियों के लिए इस मस्यौदा (1891 का फंक्चरी ऐक्ट) शिकायत करने की कोई बात नहीं इससे विपरीत हमें तो यह पग उठाने के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए (वही, पृ० 211) तथा दण्डिण, 'न० एल० माथी' एल० सी० पी० 1891 खड XXX पृ० 162) मेरे निचार में सरकार न शरता और साथ ही साथ विवक के साथ युद्ध लड़ा है

- 138 बंबई समाचार, 3 और 5 फरवरी (आर० एन० पी० बव, 8 फरवरी 1891, मराठा 22 जून 1890, जामे जमशेद, 8 मार्च (आर० एन० पी० बव, 14 मार्च 1891)
- 139 हिंदी मुहावरें, 'मुहूर्त मुस्त और गंगा नुस्त' का नाव ही यहाँ अधि उपयुक्त है
- 140 अपनी पुस्तक 'गानाड प्राफिट आफ लिबरल इडिया में टी० जी० बर्वे लिखत है कि गानाडे राज्य के हस्तक्षेप को इस रूप में चार्त किया कि जिससे आसानी प्रयोग का पथ दृष्ट रूप में नियमित हो जाए कि थोड़ी सा परिश्रम न गानाई 77 (पृ० 114) परतु हम गानाडे के भारतीय अर्थशास्त्र पर लिखे निबन्धों में अथवा उनके अन्य विमो प्रसिद्ध ग्रन्थ में एक प्रकार का कोई उद्धरण ढूँढ पान में असफल रहे है दुर्भाग्यवश बर्वे ने सदर्थ निर्देश नहीं दिया दूसरी ओर बंगाली अवताप दन की धारणा है गानाड न समग्र लेखन में वर्गीक प्रविधाय की आवश्यकता के संबंध में, नद लोगो के हातासपजीक वद्वित हो जान के दुष्प्रभाव के संबंध में, श्रमिक संधी की आवश्यकता के संबंध में अथवा मिल मालिका के विरुद्ध श्रमिकों के हितों के संरक्षक प्रभावी उपायों के संबंध में किसी उद्धरण का ढूँढना निराशरता ही है 12 वैश्वशाब्द आफ गानाड इकानामिक इंडियन जनरल आफ इकानामिक जनवरी 1942 खड XXII स० 3 पृ० 262-3
- 141 इसके विररीत उन्ही 1911 में 1911 के इंडियन फंक्चरी बिल को व्याख्या, जिसमें 1911 का खाना में वर्णन श्रमिक के काम के घटा का प्रतिदिन बारह तक गमित करने का विधान था, के विरुद्ध मतदान किया
- 142 सी० पी० ए०, 2643
- 143 गानाड एमेज, पृ० 60
- 144 वाडिया और मर्चेंट पूर्वाद्धन, पृ० 173
- 145 1867 में फंक्चरी इम्पेक्टर जम्म जान न स्पष्ट दो ही बंबई उम्त्र उद्योग अन्तर्गत मसूदा है और बर्ही कारखानों ने चार वर्षों में ही अपनी लागत पूँजी वापस चुकता कर दी है (कल्ले पूर्वाद्धन, पृ० 17 पर उद्धृत) 1905-06 में भारतीय वस्त्र उद्योग का औसत विणद लाभ 227 लाख रुपये था जबकि दन दो वर्षों में वनन के रूप में वार्षिक भुगतान की राशि थी बवल 209 लाख रुपये एस० डी० महता दि इंडियन काउन ट्रेडिंग टाउन इस्ट्री (बर्बर् 1953) पृ० 103
- 146 सी० पी० ए० पृ० 12
- 147 एल० सी० पी०, 1901 खड XI पृ० 132
- 148 इनीग्रियन गजेटियर आफ इडिया (1908) खड III पृ० 56-7
- 149 तुलनीय कर्तन स्पेचर II पृ० 238-9) असम में श्रम व्यवस्था अनिवार्यत इतरागनामे के दण की थी जिसके धनगत श्रमिकों को निश्चित वर्षों का अनुबंध करके भ्रमम जाना होता था यदि श्रमिक अनुबंध की पूर्ति नहीं करते थे तो सरकार दंड विधान के प्रवर्तन की योजना द्वारा वागान मालिकों की सहायता करती थी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इतरागनामा पद्धति एक बार असम पद्धति श्रमिकों को पूर्णत मालिकों के अधीन और उनकी दया पर निर्भर बना देती थी

1901 में असम नेबर ऐंड एमिग्रेशन बिल पर भाषण करते हुए विधि सदस्य टी रेलिफ न इस तथ्य को बड़ी ही मुस्पष्ट अभिव्यक्ति इस प्रकार से दी 'इम बिल द्वारा मान्यता प्राप्त श्रम अनबध एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार, बिना लाग लपेट के कहा जाए तो कोई व्यक्ति यह जानने से पहले ही कि वह क्या कर रहा है, असम में काम करने को प्रतिबद्ध हो जाना है फिर वह अपने चार वर्ष के अनबध से जकड़ा रहता है जिसमें मुनाबिक अनुबधित समय तक काम न करने पर दंड और जेल की धमकी दी जाती है इस तरह की दशाओं का मालिक जोर नोकर की किसी सामान्य कानून में कोई अवकाश नहीं हमने दूढ़े ब्रिटिश भारत के कानून का हिस्सा असम के बागान मालिकों के अनुरोध पर और उनके ही हित में बना दिया है साथ यह है कि इस बिल के पोछे प्रेरक शक्ति बागानमालिकों के हित हैं न कि बचारे कुलियाँ क (एन० सी० पी०, 1901, खंड XL, पृ० 133)

- 150 दास हिस्टरी आफ इंडियन नेबर लैजिस्लेशन, पृ० 17
- 151 1882 का रनलेड एमिग्रेशन ऐक्ट, 1882 (1882 का एक्ट सं० 1) भरता कि ठिकान पर अनुबंध करने से इनकार करने पर एक महीने तक की जेल को मजदूरी या सखती थी श्रमिकों का मांगने के लिए पुमलान अथवा भागे हुएों का शरण देने का दंड था एक मंसा का बागवास अथवा 200 रु० का अर्थदंड अथवा दोनों
- 152 बिपिनचंद्र पाल मेमोरीज आफ मास्टर लाइफ एंड टाइम्स, खंड 1 (जनरता 1937) पृ० 246 (इमसे श्राग सदर्थ के लिए मेमोरीज से संकेनित किया जाएगा)
- 153 वही, खंड II (कलकत्ता 1891) पृ० 53, 70 सी० बागान हिस्टरी आफ दि इंडियन एसासिएशन 1876-1951 (कलकत्ता 1951) पृ० 53 102
- 154 दखिण आर० एन० पी० रज 6 अगस्त 10 17 मितबर 24 31 दि०बर 1891 14 21, 28 जनवरी, 18 फरवरी 1892 माहम, 4 फरवरी (आर० एन० पी० एन 14 फरवरी 1892)
- 155 15 जनवरी (आर० एन० पी० बब 21 जनवरी 1887)
- 156 बंगाली, 14 जनवरी 1892
- 157 मिमरियल आफ दि ईंडियन एसासिएशन बहा तथा पाए 154 की पादनिष्पत्ति में उद्धृत बहूत सार राष्ट्रवादी समाचारपत्र 17 दिगंबर 1891 में रज की न टिप्पणी को निर्याद भारत को अपनी सरकार यानी तो ऐसा कानून अभी पास न किया जाता
- 158 दन इम्लैंड एंड इंडिया, 131 ई एच II पृ० 352 तथा दखिण, सी० आई० चिन्तामणि इंडिया ऐंड नाइजरलैंड, एच० आर०, अप्रैल 1901, पृ० 213
- 159 बागान पूर्वोद्धृत, पृ० 103
- 160 वही, पृ० 104 उद्धृत पुस्तक में परिशिष्ट ई के अंतर्गत जापान पुनरुद्धृत है
- 161 1892 3 से 1895-6 तक की रिपोर्ट्स आफ दि इंडियन एसासिएशन पृ० 21 82 8, 92
- 162 बी० सी० पात मेमोरीज, खंड II पृ० 54 5
- 163 वही इस द्वितीय प्रयास का पाल द्वारा प्रस्तुत विवरण गलत है इसका कारण स्पष्टतः वझावस्था में याददाश्त कमजोर हो जाना ही था मही लेख-जोड़े के लिए दखिण, रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 158-62
- 164 कलकत्ता में हुए 12वें अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव XV
- 165 रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 165-9 प्रस्ताव पर बोलते हुए आर० के० सरकार न घोषणा

- की कि 'देश के किसी भी कानून में इससे अधिक बर्बर व्यवस्थाएँ मिलना संभव नहीं' (वही, पृ० 169)
- 166 1897, 1898, 1899, 1900 और 1901 के प्रस्ताव क्रमशः IV, XX, XIV, X तथा XIII.
- 167 बागल पूर्वोद्धृत, पृ० 105-07.
- 168 खंड II पृ० 352, 522 तथा देखिए, इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 131
- 169 बंगाली, 12 मई 1888; बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए, आर० एन० पी० बंग०, 26 मई, 2, 9, 16 और 23 जून 1888; वायस आफ इंडिया, जुलाई 1888 (खंड VI, स० 7), इंडियन स्पेक्टेटर, 3 जून (वही); आफताबे हिंद, 15 जून (आर० एन० पी० पी०, 23 जून 1888); इपीरियल पेपर, 23 जून (वही, 7 जुलाई 1888)
- 170 विशेष रूप से देखिए, उनके 1886 के ग्रक जब प्रेस ने 'कुली' अधिनियम के विषय एक संयुक्त अभियान छेड़ दिया था 'सजीवनी' के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रकाशित ग्रको में इस विषय पर सुंदर और प्रामाणिक लेखमाला उपलब्ध है
171. ए० बी० पी०, 19 अगस्त 1886, सजीवनी 20 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 27 अगस्त 1887), 1888 का मेमोरियल आफ दि इंडियन एमोमिएशन बागल पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट ई, पीछे 169 पार्श्वटिप्पणी में उल्लिखित समाचारपत्र ए० बी० पी० 24 मई 1888, हिंदू, 30 मई 1888, इंदु प्रकाश 11 जून 1888, नेटिव ओपीनियन, 3 जून 1888, ए० एम० बीमजी, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 160, रहबर, 14 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 18 फरवरी 1892), 1893 में इंडियन एमोमिएशन द्वारा राज्य मंचिव को प्रस्तुत विरोधपत्र 1892-3 से 1895-6 तक के वर्षों की रिपोर्टें आफ दि इंडियन एमोमिएशन प० 82 जे० सी० घोष, रिप० आई० एन० पी० 1896 पृ० 165-6, द न इंग्लैंड ऐंड इंडिया पृ० 131 और ई० एच० II, पृ० 352 उद्धरणार्थ ज० सी० घोष ने 1896 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बताया 'मैंने गरीब आदमी और औरों को मोत में भी बदतर भाग्य में वचन के लिए जहाज में ब्रह्मपुत्र के गहरे पानी में छलांग लगान देखा है, उसी कांग्रेस के समान आर० ब० सरकार ने विवरण देने हुए न अंग्रेजों और अंग्रेजों के जाने पर एक पीछे सी खूनी छाड़ दी गई है और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि देश के दुर्गम घन प्रदेशों में इनके अंतर्गत के पड़ारियों के आनंद से भी बरत है रिप० आई० एन० सी० 1896, पृ० 165 और 170 क्रमशः
- 172 पक्षाधी 4 जून (आर० एन० पी० बंग०, 7 जून 1884), रहबर, 4 जून (वही, 14 जून 1884) सजीवनी, 22 नवंबर (वही, 29 नवंबर 1884) पत्रिका, 25 सित० और नवविभाकर, 78 गिन० (वही, 3 अक्टूबर 1885), दि रिपोर्ट आफ नेटिव प्रम फार बंगाल 1886; मोम प्रकाश 19 जुलाई और आनंद वात्रा पत्रिका, 19 जुलाई (वही, 24 जुलाई 1886), सजीवनी, 7 अगस्त (वही, 14 अगस्त 1886), भारत मित्र 19 अगस्त (वही, 28 अगस्त 1886), रहबर, नवंबर और दिसंबर की 'सजीवनी' (वही अक्टू० नव० और दिस० 1886), ए० बी० पी०, 19 अगस्त 1886; हिंदू, 24 जून 1887, मराठा, 12 फरवरी और 27 मई 1888, 1888 का इंडियन एमोमिएशन का आपन, प्रकाशित स्थान: पीछे 169 की पार्श्वटिप्पणी में उल्लिखित समाचारपत्र ए० बी० पी०, 24 मई 1888 वायस आफ इंडिया, जुलाई 1888 (खंड VI स० 7) इंडियन स्पेक्टेटर, दिहालून 23 मई 1888 (वही), रहबर, 14 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 18 फरवरी 1892), बंगाली, 4 फरवरी 1893, द न ई एच II, पृ० 522, कैसरे हिंद, 8 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 14 मार्च 1903), जे० एम० ग्रय्यर ई ए, पृ० 195

173. ए० बा० पी०, 24 मई 1888; इंडियन एसोसिएशन का 1888 का जापन, पूर्वोक्त स्थल; दल . इन्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 131. ई एच II, पृ० 352.
174. बगल : पूर्वोक्त, पृ० 103 तथा इंडियन एसोसिएशन का 1888 का जापन, पूर्वोक्त स्थल.
175. जे० सी० घोष ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में एकत्रित प्रतिनिधियों का एक घटना बताई जहाँ बड़ी संख्या में औरतो और मरदो पर सामूहिक रूप से कांडे वरसाए गए चीफ कामशनर की 1887 की श्रमिकों के श्रम में उत्पन्न सबंधी रिपोर्ट का उद्धृत करत हुए उन्होंने एक घटना का विवरण दिया कि किस प्रकार मैनजर के घर के बगड़े के एक खम्भे के साथ मित्रता को बाध दिया गया, उनके कपड़े कमर तक उठा दिए गए और उनके नये चूतड़ों पर चमड़े के जालूक से पिटाई की गई. (रिप० आई० एन० सी०-1896, पृ० 167)
- 176 रिपोर्ट आन आ दि नेटिव प्रेस, बगल-1886, सोम प्रकाश, 19 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 24 जुलाई 1886); ए० बी० पी०, 24 मई और 19 जुलाई 1888; मराठा, 12 फरवरी, 27 मई 1888; ट्रिब्यून, 23 मई (बी० ओ० आई०, जुलाई 1888), इंडियन एसोसिएशन का जापन, पूर्वोक्त स्थल; जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी०-1896 पृ० 167, दल . ई एच II, पृ० 352; कंसरे हिंद, 8 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 14 मार्च 1903)
- 177 इंडियन एसोसिएशन 1888 का जापन, पूर्वोक्त स्थल; ट्रिब्यून, 23 मई (बी० ओ० आई०, जुलाई 1888); बगली, 4 फरवरी 1893: जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी०-1896, पृ० 167; जी० एम० अय्यर . ई ए, पृ० 185 तुलनीय कर्जन स्पीचिंग I पृ० 243 श्रम म स्वतंत्र श्रमिकों को अपेक्षा अनुबंधित श्रमिकों की मृत्यु दर भयंकर रूप से ऊँची थी
178. इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1893 में राज्य सचिव का प्रेषित याचिका . रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन फार 1892-3 टु 1895-6, पृ० 82, बगानी, 21 जनवरी 1893. जे० सी० घोष, रिप० आई० एन० सी०-1896 पृ० 167; सी० वाई० चित्तामणि : इंडिया ऐंड लाब कर्जन, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 243; जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 180-5
- 179 जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी०-1896 पृ० 167 तथा बी० सी० पाल . वही, पृ० 168; बगली, 4 फरवरी 1893; हितवादी, 23 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 31 मार्च 1900), इंडियन एसोसिएशन ने 10 मार्च 1893 के जापन में उल्लेख किया कि यदि कुलियाँ को अस्वास्थ्य के कारण-सूचक कामों में काम करना पड़ता है अथवा यदि उन्हें अपने घरों से बहुत दूर जाना पड़ता है तो उन्हें अपेक्षाकृत त्याग के अनुरूप ही उपयुक्त वेतन मिलना चाहिए (रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892-3 टु 1895-6, पृ० 22)
180. जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी०-1896 पृ० 167; हितवादी, 23 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 31 मार्च 1900); जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 182
181. केसरी, 10 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 14 मार्च 1903) और देखिए, जे० सी० घोष . रिप० आई० एन० सी०-1896 पृ० 165 जी० एम० अय्यर ई ए पृ० 181
- 182 सोम प्रकाश, 19 जुलाई; आनंद बाजार पत्रिका, 19 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 24 जुलाई 1886); ए० बी० पी०, 19 मई 1886, सजीवनी, 20 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 27 अगस्त 1887); प्रतिकार, 26 मई (वही, 2 जून 1888), परिदर्शक 11 जून (वही, 23 जून 1888), ए० बी० पी०, 24 मई 1888, मराठा, 27 मई 1888, हिंदू, 30 मई 1888; 1888 का इंडियन एसोसिएशन का जापन, पूर्वोक्त स्थल, बी० सी० पाल : रिप० आई० एन० सी०-1888, पृ० 159; बंगाली, 4 जून 1892; रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892-3 टु 1895-6,

- पृ० 22-7, जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 1896, पृ० 167; केसरी, 19 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 1901) केसरे हिंदू, 8 मार्च (वही, 14 मार्च 1903); दत्त : ई एच II, पृ० 352.
183. बी० मी० पाल : मेमोरीज, खंड II पृ० 54.
184. बंगाली, 11 मार्च 1893; ए० बी० पी०, 28 फरवरी 1901; दत्त : ई एच II पृ० 351-2.
185. मजीबनी 19 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 26 नव० 1887) तथा ए० बी० पी०, 19 जुलाई 1888
186. 20 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 27 अगस्त 1887).
187. मई 1888 का इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल; बांगल : पूर्वोद्धृत, पृ० 105-06; बी० सी० पाल : रिप० आई० एन० सी० 1888, पृ० 158, 162; ए० बी० पी०, 19 अगस्त 1886, बंगाली, 12 मई 1888, मराठा, 27 मई 1888; हिंदू, 30 मई 1888; नेटिव ओपीनियन, 3 जून 1888, हदु प्रकाश, 11 जून 1888; वायस आफ इंडिया, जुलाई 1888 (खंड VI, स० 7); ट्रिब्यून 23 मई और इंडियन रीप्रेसेंटेटर, 3 जून (वही). बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए, आर० एन० पी० बंग०, 26 मई, 2, 9, 23 जून 1888; इंडियन एसोसिएशन का 1893 का ज्ञापन, रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892-3 टु 1895-6 पृ० 83-8.
188. मजीबनी, 29 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 29 नव० 1884); मराठा, 27 मई 1888; ए० बी० पी० 24 मई 1888
189. इंडियन एसोसिएशन का 1893 में दिया गया ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 23-7; बंगाली, 11 मार्च 1893.
190. हिंदू, 30 मई 1888; बंगाली, 5 दिसंबर 1891; इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1893 में प्रस्तुत ज्ञापन रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892-3 टु 1895-6, पृ० 21. इंडियन एसोसिएशन द्वारा 1896 में प्रस्तुत ज्ञापन, वही, पृ० 92; बंगाली, 6 जून और 15 अगस्त 1896; आई० एन० सी०, 1896, 1897; 1898, 1899, 1900 और 1901 के प्रस्ताव संख्या XV, IV, XX, XIV, X और XIII क्रमशः हिंदू, 3, 8, नव० 1899; न्यू इंडिया, 26 अगस्त 1901; सी० वाट्सन चिनामणि : इंडिया ऐंड लाईव कर्जेन, एच० आर० अप्रैल 1901, पृ० 244 जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी०-1901, पृ० 166; दत्त : ई एच II, पृ० 352.
191. दत्त : ई एच II पृ० 352 तथा 1893 का इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, पृ० 22. बंगाली, 15 अगस्त 1896; हितवादी, 23 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 31 मार्च 1900); ए० बी० पी०, 26 फरवरी 1901; हिंदू, 13 मार्च 1901.
192. मजीबनी, 28 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 4 मितंबर 1886); भारत मिहिर, 2 सितंबर (वही, 11 मितंबर 1886); सी० वाट्सन चिनामणि : इंडिया ऐंड लाईव कर्जेन, एच० आर०, अप्रैल 1901, पृ० 244 दत्त : ई एच I, पृ० XII ई एच II, पृ० 352, 522.
193. आर० एन० पी० बंग०, 21 अगस्त 1886
194. 28 अगस्त (वही, 4 मितंबर 1886) तथा भारत मिहिर, 2 सितंबर (वही, 11 सितंबर 1886)
195. 3 दिसंबर, (वही, 10 दिसंबर 1887).
196. देखिए, दास : प्लांटेशन लेबर इन इंडिया (कलकत्ता 1931) पृ० 34, 94-5.
197. अमम लेबर ऐंड एमिग्रेशन ऐक्ट—1901 (1901 का ऐक्ट नं० VI), अध्याय I-VII. विशेष रूप से धारा 3 देखिए, जिसमें स्थानीय सरकारों को किसी भी अथ वित्तों में अथवा उसके किसी

भाग में उत्पन्नवासियों की धरती पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया था दंडनीय कानून न्यायाधिकार रूप में अपरिबर्तित हो रहा देखिए अधिनियम का अध्याय IX.

- 198 दाम हिस्टरी आफ इंडियन लेबर लैजिस्लेशन, पृ० 23 और चमनलाल . पूर्वोद्धृत, खंड II, पृ० 6-7 चालू दुःखवहारी के प्रति श्रमिकों के असंतोष की अभिव्यक्ति 1903 में बड़े पैमाने पर श्रमिकों के चाय बागानों में हुए उपद्रवों के रूप में हुई देखिए, दास . प्लाटेशन लेबर इन इंडिया, पृ० 34
- 199 रजनी स्पीचेज II, पृ० 245
- 200 हिंदू, 3 नवंबर 1899, ए० बी० पी०, 26, 28 फरवरी 1901, कमरी, 19 मार्च (आर० एन० पी० बंग, 23 मार्च 1901), हिन्दावादा, 15 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 1901); बंगाली, 19 मार्च 1901
- 201 सजीवनी, 2 नव० (आर० एन० पी० बंग०, 11 नवंबर 1899), बंगवासी, 11 नव० (वही, 15 नवंबर 1899), आर० एन० पी० बंग०, 9 मार्च 1901 में उल्लिखित बंगाल के समाचारपत्र; सजीवनी, 28 फरवरी, हिन्दावादी, 1 मार्च, इंडियन मिरर, 1, 2, मार्च 1901 (वही, 9 मार्च 1901), बंगाली 17, 27, 24 फरवरी 1901, ए० बी० पी०, 26, 28 फरवरी 1901, हिंदू, 13 मार्च 1901, मद्रास स्टैंडर्ड, 10 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 16 मार्च 1901), एडवोकेट, 1 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 2 मार्च 1901), श्रीराम, एन० सी० पी०-1901, खंड XL पृ० 86, ए० आनंद चारलु, वही, पृ० 131-2 जब के० बकिंधम ने परिषद में प्रथम तीन वर्षों में पूर्वा और म्रियो के वनन क्रमशः 5 और 4 रुपये तथा चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 6 और 5 रुपये निर्धारित करने का सशोधन पत्र किया तो परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने उसके विरुद्ध मतदान किया (वही, पृ० 146)
- 202 एल० सी० पी०-1901 खंड XL पृ० 147
- 203 रजनी स्पीचेज II, पृ० 236
- 204 वही पृ० 245-7 तथा देखिए पृ० 234-5
- 205 एन० सी० पी०-1901 खंड XL पृ० 150
- 206 बंगाली, 10 मार्च और 19 मार्च 1901, हिंदू, 13 मार्च 1901, ए० बी० पी० 11 मार्च 1901, बंगाल के समाचारपत्रों के लिए देखिए, आर० एन० पी० बंग० 16, 23, 30 मार्च 1901; मद्रास स्टैंडर्ड, 10 मार्च और स्वदेशमित्र 11 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 16 मार्च 1901); इंदु प्रकाश, 28 मार्च (आर० एन० पी० बंग, 30 मार्च 1901), अवध टाइम्स, 7 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 9 मार्च 1901), दत्त : ई एच I, पृ० XIV और ई एच II, पृ० 522, आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव XIII, पी० आनंद चारलु श्रीराम तथा बिपिन कृष्ण बोस ने सर हेनरी कोटन के स्वर के साथ स्वर मिलाया और बकिंधम के सशोधन के विरुद्ध मत दिया. एल० सी० पी०-1901 खंड XL पृ० 158
- 207 मगठा, 17 मार्च 1901 तथा इंडियन मिरर, 10 मार्च, प्रतिवासी, 11 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 16 मार्च 1901), बंगवासी, 16 मार्च, वसुमती, 21 मार्च (वही, 23 मार्च 1901), प्रभाती, 20 मार्च (वही, 30 मार्च 1901); दत्त : ई एच I, पृ० 14-15 ई एच II, पृ० 352 और 522 दत्त ने एक अन्य उदाहरण देकर सरकार के मजदूरों के प्रति और बागान मालिकों के प्रति व्यवहार में अंतर दिखाया कि जब 1903 में बागानमालिकों ने उस निर्धारित चाय पर कर लगाने की मांग की, जिसकी आय का उपयोग भारत में चाय की खपत पर होना था तब भारत

- सरकार ने अपने सम्मान को ताक पर रखकर इस मांग को स्वीकार कर दिया और मित्र कर दिया कि वह चाय बागानमालिकों की चाय बेचने वाली एजेंट हो है (ई एच II, पृ० 522-3)
208. ए० बी० पी०, 11 मार्च 1901; बंगाल के गमाचारपत्रों के लिए देखिए, आर० एन० पी० बंग०, 16, 23, 30 मार्च 1901, केमरी, 19 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 1901), ज० सी० घोष रिप० आई० एन० सी०-1901 पृ० 165
209. बंगाली, 15 फरवरी 1903; हिंदू, 28 फरवरी, 2, 3, मार्च 1903, दटियन पीपुल, 13 मार्च 1903; युनाइटेड इंडिया, 3 मार्च (बी० ओ० आई०, 21 मार्च 1903), टी थन रिप्यू फरवरी 1903; आर० एन० पी० एम०, 7 फरवरी, 7, 14 मार्च 1903 और आर० एन० पी० बंग०, 14 मार्च 1903 में उल्लिखित मद्राम और बर्मी के लगभग सभी महत्वपूर्ण गमाचारपत्र जो ए० अय्यर : ई ए, पृ० 183 मद्राम विधान परिषद में मद्राम बागान यम विन का जायराण भारतीय सदस्यों द्वारा तीव्र विरोध किया गया था देखिए प्रार्थीटिम आफ मद्राम नैजिस्मेटय कौंसिल-1902, खंड XXX पृ० 211-6 और 1903 के लिए, खंड X\XI पृ० 93-7
210. बंगाली, 15 फरवरी 1903; हिंदू 3 मार्च 1903, इंडियन पीपुल, 13 मार्च 1903; युनाइटेड इंडिया, 3 मार्च (बी० ओ० आई० 21 मार्च 1903), स्वदेशमित्र, 5 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 7 फरवरी 1903), कैमरे हिंदू, 8 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 14 मार्च 1903)
211. सुधारक, 9 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 14 मार्च 1903). इनके बंदने जो ए० अय्यर ने अनुभव किया कि सरकार ने सार्वजनिक मगठन के रूप में एकमात्र बाणिज्य मदत और निजी व्यक्तियों के रूप में इस सदन के शीर्षस्थ प्रतिनिधियों से ही परामर्श किया था (ई ए, पृ० 184).
212. केमरी, 10 मार्च, सुधारक, 9 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 14 मार्च 1903), जी० ए० अय्यर ई ए, पृ० 183-5
213. जी० ए० अय्यर ई ए, पृ० 185
214. आर० एन० पी० बंग०, 14 मार्च 1903.
215. वही
216. जी० ए० अय्यर : ई ए, पृ० 180 और 'अवर लेवर प्राइम', एन० आर०, अगस्त 1901, पृ० 117-8.
217. दत्त ई एच I, पृ० XIV-XV, पृ० 352, 522
218. 14 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 1901)
219. रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 168
220. एल० सी० पी०, 1901 खंड XL, पृ० 131 और 153
221. आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव XIII और आई० एन० सी०-1900 का प्रस्ताव XXIV.
222. 25 मई (आर० एन० पी० एम०, 30 मई 1903)
223. मराठा, 7, 21 मई 1899.
224. मराठा, 14 मई 1899, सुधारक, 15 मई (आर० एन० पी० बंग०, 20 मई 1899)
225. जहां तक हमारी जानकारी है, भारत में श्रम आंदोलन के इतिहास लेखकों ने इस तथ्य की पूर्ण उपेक्षा की है यह आश्चर्य का विषय है कि वे इस हड़ताल तक का उल्लेख नहीं करते इससे पूर्ववर्ती इसी रेलवे के ऐंग्लो-इंडियन गाड़ों की हड़ताल का वर्णन किया जाता है परंतु उस हड़ताल में भारतीय श्रमिकों का योगदान तो माना ही नहीं जा सकता वस्तुतः 1899 से पूर्व बर्मी और कलकत्ता की कितनी ही कपड़ा मिलों में हड़तालें हुईं वे तात्कालिक तथा असंगठित, अधिक

से अधिक अर्धसंगठित थी.

- 226 बेमरी, 16 मई (आर० एन० पी० वब, 20 मई 1899).
- 227 14 मई 1899 के केमरी हिंदू ने यह स्पष्ट देखा था, उसने यह निर्देश किया कि यदि यह सफल हुआ तो यह अन्य दो श्रमियों के लिए अनिवार्य उदाहरण सिद्ध होगा. (आर० एन० पी० वब, 30 मई 1899)
- 228 केमरी हिंदू अपवाद था शीर्षस्थ गमबंधा में हे, मराठा, केमरी, इंडियन स्पेक्टेटर, इंदु प्रकाश, सुधारक, नेटिव ओपीनियन, ज्ञान प्रकाश, सुबाध पत्रिका और मोद वृत्त
- 229 मराठा, 7, 14, 21, 28 मई, 4 जून, 16 जुलाई 1899 बंबई के समाचारपत्रों के लिए देखिए, आर० एन० पी० वब, 13, 20 मई 1899, ए० बी० पी०, 24 मई 1899, हितवादी; 26 मई (आर० एन० पी० वब०, 3 जून 1899), हिंदू, 8 मई 1899, वृत्तांत पत्रिका, 17 मई (आर० एन० पी० वब० 31 मई 1899), हिंदुस्तानी 17 मई (आर० एन० पी० वब० 31 मई 1899); जामे उल उलूम, 7 जून जम्मात अखबार, 10 जून हिंदुस्तानी, 7 जून (वही, 14 जून 1899), गहना ए हिंदू, 24 जून और 1 जुलाई (वही, 5 जून 1899), अमृत बाजार पत्रिका ने तो यमगता ना सामान्याकरण तक कर दिया ये हड़तालें बुचले हुए लोगों के जीने का अधिकार मागने के प्रयत्न हैं - तब बड़ी, बड़ा बड़ा हड़ताल होता है, समझ लीजिए कि बड़ा शिकायती की दृष्टि से श्रमिक प्रयत्नता और व्यापकता है कि उसने हड़तालियों को अपने अन्तर्दाताओं के विरोध में मागता है कि वे उन विषयों पर दिया है (24 मई 1899)
- 230 बेमरी, 16, 30 मई (आर० एन० पी० वब, 27 मई, 3 जून 1899); नेटिव ओपीनियन, 25 मई (वही, 27 मई 1899); ए० बी० पी०, 2 जून 1899, हिंदुस्तानी, 17, 31 मई (आर० एन० पी० वब० 31 मई, 7 जून 1899), मराठा, 28 मई 1899
- 231 आर० एन० पी० वब०, 14 जून 1899
- 232 केसरी, 23 मई, नेटिव ओपीनियन, 25 मई (आर० एन० पी० वब०, 27 मई 1899), केसरी, 30 मई (वही, 3 जून 1899)
- 233 मराठा, 7, 14, 21 मई, 1899, नेटिव ओपीनियन, 11 मई श्री सयाजी विजय, 6 मई, ज्ञान प्रकाश, 11 मई (आर० एन० पी० वब०, 13 मई 1899); इंदु प्रकाश, 18 मई; सुधारक, 15 मई, नेटिव ओपीनियन 18 मई, केमरी 16 मई, गुजराती, 14 मई (वही, 20 मई 1899); नेटिव ओपीनियन, 25 मई (वही, 27 मई 1899); पैमा अखबार, 17 जून (आर० एन० पी० वब०, 1 जुलाई 1899), हिंदुस्तानी, 17 मई (आर० एन० पी० वब०, 31 मई 1899)
- 234 मराठा, 21 मई 1899, बेमरी, 16 मई (आर० एन० पी० वब 20 मई 1899)
- 235 मराठा, 14 मई 1899; इंदु प्रकाश, 18 मई, इंडियन स्पेक्टेटर, 14 मई, सुबाध पत्रिका, 14 मई, नेटिव ओपीनियन, 18 मई, गुजराती, 14 मई (आर० एन० पी० वब०, 20 मई 1899). 14 मई 1899 के इंडियन स्पेक्टेटर ने सारे मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया : अच्छा हो या बुरा, हमें अब इस देश में बड़ी बड़ी सस्थाओं के रूप में श्रमिकों को संगठित करना है हम इसे छोड़ नहीं सकते. श्रमिकों को संगठित करके यह सिद्ध करना है कि उनमें कितनी शक्ति है. श्रम और पूँजी के बीच शत्रुता की भावना के विकास को रोकने का उपाय यह है कि श्रमिकों और पूँजीपतियों को समय समय पर उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए सात्वनाप्रद योजनाएं अपनानी चाहिए (वही)
- 236 मराठा, 7 मई 1899; सुधारक, 15 मई, केसरी, 16 मई, इंदु प्रकाश, 18 मई, जामे जमशेद,

- 16 मई (आर० एन० पी० बब०, 20 मई 1899), नेटिव ओपीनियन, 25 मई, केसरी, 23 मई (वही, 27 मई 1899); वृत्तान्त पत्रिका, 17 मई (आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1899); अखबारे आम, 9 जून (आर० एन० पी० पी०, 24 जून 1899).
237. मराठा, 14, 21, 28 मई, 4 जून 1899, सुधारक, 25 मई (आर० एन० पी० बब०, 27 मई 1899); केसरी, 30 मई (वही, 3 जून 1899) 24 मई 1899 के 'बर्बई समाचार' न रपट दी कि कितने ही शीर्षस्थ व्यक्ति फिरोजशाह एम० मेहता के भवन पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इसी प्रकार के मत प्रकट किए हैं वही, 27 जून 1899
238. मराठा, 14, 21, 28 मई, इंदु प्रकाश, 18 मई, सुधारक, 15 मई, नेटिव ओपीनियन, 18 मई, केसरी, 16 मई (आर० एन० पी० बब०, 20 मई 1899); नेटिव ओपीनियन, 25 मई (वही, 27 मई 1899).
239. मराठा, 28 मई 1899, ए० बी० पी०, 15 मई 1899; मोद वृत्त, 20 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह का और गुजराती, 14 मई (आर० एन० पी० बब०, 20 मई 1899), केसरी, 30 मई (वही, 3 जून 1899), अल्मोड़ा अखबार, 10 जून (आर० एन० पी० एन०, 14 जून 1899)
240. मराठा, 28 मई, 16 जुलाई 1899; नेटिव ओपीनियन, 18 मई, केसरी, 16 मई, गुजराती, 14 मई (आर० एन० पी० बब०, 20 मई 1899), खानदेश वैभव, 19 मई, मुद्रांन, 20 मई, सुधारक, 22 मई (वही, 27 मई 1899), केसरी, 30 मई (वही, 3 जून 1899), हिंदुस्तानी, 31 मई (आर० एन० पी० एन०, 7 जून 1899)
241. केसरी, 23 मई (आर० एन० पी० बब०, 27 मई, 1899); मराठा, 4 जून 1899 अहमदाबाद के 'जगदादश' ने अहमदाबाद के जन सम्मेलन की रपट देते हुए लिखा कि एक प्रतिष्ठित प्रमुख नागरिक ने दोह-मनमाड लाइन पर काम करने वाले मिगनलरो के दा मास तक जीवन निर्वाह का सारा भार उठाने का जिम्मा लिया है. (आर० एन० पी० बब०, 27 मई 1899)
242. 'बर्बई समाचार', 24 मई, नेटिव ओपीनियन, 25 मई (आर० एन० पी० बब०, 27 मई 1899)
243. ए० बी० पी०, 17 जून 1899
244. इंदु प्रकाश, 27 जून (आर० एन० पी० बब०, 29 जुलाई 1899)
245. और हिंदुस्तानी, 2 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 9 अगस्त 1899).
246. आर० एन० पी० बब०, 20 मई 1899, और हिंदुस्तानी, 7 जून (आर० एन० पी० एन० 14 जून 1899).
247. मुस्तार : पूर्वोद्धृत, पृ० 87; बुकानन : पूर्वोद्धृत, पृ० 422
248. वाचा . स्पीचेज, पृ० 435-7.
249. वही, पृ० 445
250. परंतु उनका यह श्रमपक्षीय दृष्टिकोण स्पष्टतः 19वीं शताब्दी की समाप्ति पर ही बना क्योंकि 'हिंदू' के संपादक के उत्तरदायित्व को उन्होंने 1900 में ही छोड़ा, उस समय तक तो उनका व्यवहार निरंतर मालिकों के पक्ष में और कर्मचारियों के विरुद्ध था.
251. जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 177-8 और 'अवर सेबर प्राम्लम' एच० आर०, अगस्त 1901 पृ० 116.
252. ई ए, पृ० 175 तथा पृ० 185 और 188 और 'अवर सेबर प्राम्लम' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 118.
253. अवर सेबर प्राम्लम, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 119 तथा ई ए, पृ० 178
254. अवर सेबर प्राम्लम, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 120.

255. ई ए, पृ० 175
256. वही, पृ० 228-9
257. वही, पृ० 227.
258. वही, पृ० 230
259. वही, पृ० 227.
260. वही, पृ० 218-9.
261. वही, पृ० 232
262. वही, पृ० 221.
263. वही, पृ० 219 इस सबध मे उन्होंने यह भी निर्देश किया कि किसी विशिष्ट मामले मे कानून का किमी रूप मे उत्लघन हुआ है, इसके निणायक श्रमिक ही हो सकते हैं. (वही)
264. वही
265. वही, पृ० 208
266. 'दि इंडियन इकोनामिक प्रब्लम' लेख के प्रारभ मे ही उन्होंने घोषणा की कि मैं अधिक प्रत्यक्ष देखता हूँ महान श्रमिक वर्ग की प्रसन्नता और कल्याण को न कि भावी पूँजीपतिवर्ग के कल्याण को यह पूँजीपतिवर्ग तो श्रमिकों को दबाएगा मेरी दृष्टि मे तो किसानों और कारीगरों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए इनके मूल्य पर उपलब्ध किसी भी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय गौरव का मेरा दृष्टि मे कोई मूल्य नहीं (ज्ञान, खंड III पृ० 233).
267. वही, पृ० 236
268. वही, पृष्ठ 229
269. वही, खंड II पृष्ठ 179-80, और खंड III पृष्ठ 229
270. वही, खंड III पृष्ठ 263
271. वही, खंड II पृष्ठ 182
272. वही, खंड III पृष्ठ 231 और पृष्ठ 269. मुखर्जी ने यह भी निर्देश किया कि भारतीय श्रमिक का शोषण करने मे विदेशी और स्वदेशी पूँजीपति कोई भेदभाव नहीं बरतेगे. यह दूसरी बात है कि विदेशी पूँजीपति धन की निकासी की दृष्टि से भारतीय पूँजीपति की अपेक्षा अधिक भयंकर और अवांछनीय है (वही, पृ० 233).
273. वही, पृष्ठ 269 यह उल्लेखनीय है कि सहानुभूति की मोटी खुराक देते हुए घृणा नहीं तो भर्त्सना को अभिव्यक्ति गरीबों और प्रचुर रूप मे की गई इस विचार को किसी भी रूप में बी० सी० पाल के आधुनिक औद्योगिक श्रमिकों का भविष्य प्रगतिशील मानने वाले विचार को भिन्न रूप मे देखा जा सकता है.
274. वही, पृष्ठ 229, 231, 269.
275. वही, पृष्ठ 232 मुखर्जी ने तो और आगे बढ़कर यहां तक कहा कि जहाँ तक पश्चिमी औद्योगिक पद्धति अपनाए जाने का प्रश्न है श्रमिक सचों के संगठन की चिंता एक प्रकार से श्रमिकों के हित की चिंता करने वालों का दायित्व है (वही, पृ० 229).
276. वही, खंड II पृ० 183.
277. वही, खंड III पृ० 226 तथा पृ० 230.
278. वही, पृ० 232.
279. वही, पृ० 264-5. उनके विचार में भारत विशेष रूप से इस प्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त क्षेत्र

या क्योंकि यह देश में सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि में उच्च जीवन का महत्व देने वाला देश है न कि उच्च जीवन स्तर को (बही, पृष्ठ 291)

280. वही, पृष्ठ 264, 269

281. वही, पृष्ठ 266, 269

282. वही, पृष्ठ 265-6

अध्याय 9

कृषि का विकास : एक

जमींदारों के हितों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ कांग्रेस का आंदोलन (सरकार को विवश करने की नीति लिए हुए), खेतिहरों पर ही, अधिकांशतया खर्च किए जाने वाले जमींदारों पर लगे करों की उनसे वसूली के परित्याग का पक्षधर है।

जे० डी० रीस

भारत की आत्मा रूप किसान के ऊपर मड़गने लगा जड़ना और उदामीनता के बादलों को हटाने पर ही देश का उद्धार किया जा सकता है। हमें अवश्यमेव उन बादलों को हटाना होगा और उमके लिए हमें अपने आपको किसान के साथ जोड़ना होगा और यह अनुभव करना होगा कि किसान हमारा है और हम किसान के हैं।

बान गगाधर तिलक

कदाचित् भूमि संबंधी समस्या 19वीं शताब्दी के समाप्ति काल में भारत के लिए सिग्दद बनने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी। मेतीबाड़ी भारतीयों का प्रमुख आर्थिक आधार थी। लगभग 80 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर थे। 19वीं शताब्दी की अवधि में ब्रिटिश सर्वोच्चता के प्राथमिक प्रभाव के अतर्गत देश के निरंतर ग्रामीकरण ने, भारतीयों की कृषि पर परंपरागत निर्भरता का, और अधिक बढ़ा दिया था। फलतः आर० सी० दत्त के शब्दों में स्थिति यह हो गई थी कि मेतीबाड़ी के फलने-फूलने का अर्थ था भारतीयों की खुशहाली और फसलों के बिक्री जाने का अर्थ था देश में अकाल की स्थिति।¹

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई थी और यहां के खेतिहर बहुत गरीब थे। भारत में उस समय तक ज्ञात अकालों में सर्वाधिक भयंकर 1876-8 के भयंकर अकाल तथा 1896-1901 तक देश को अपनी जक में रखने वाले भीषण अकालों ने यह तथ्य नाटकीय ढंग से उजागर कर दिया। खेतिहरों की निराशापूर्ण स्थिति का एक अन्य संकेत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पनपता असंतोष था जिसकी अभिव्यक्ति बंगाल में 1873 को पबना दंगों में, 1875 में दक्षिण के खेतिहरों के दंगों में, बंबई में 1878-9 के फडके के विद्रोह में तथा 1894 में असम कृषि दंगों में देखने को मिली। भयंकर

विनाशकारी अकालों तथा कृषक असंतोष ने सरकार तथा भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का ध्यान भारतीय किसानों की समस्याओं और निर्धनता की ओर खींचा।

भारतीय नेताओं के कृषि संबंधी विभिन्न पक्षों के प्रति दृष्टिकोण का, सरकार की कृषि संबंधी नीतियों का तथा खेतिहरों की दृष्टि का कारणों का विवेचन निम्नलिखित पांच शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। 1. भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य 2. कृषक और भूमिपति 3. कृषक और साहूकार 4. पूँजीवादी खेतीवादी 5. कृषि और उद्योग।

भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य

अनेकानेक ऐतिहासिक तत्वों के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में भूमि की पट्टेदारी और भूराजस्व प्रणालियों का मिला जुला रूप विकसित हुआ। यहाँ मक्षेप में भी इन दोनों पद्धतियों की समीक्षा करना संभव नहीं अतः हमें यहाँ केवल अपेक्षित मात्र-मक्षेपों से ही संतोष करना पड़ेगा। निम्नलिखित इनसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता; हाँ, उचित अनुमान अवश्य ही जाएगा। बंगाल में और उत्तरी मद्रास में जमींदारों ने स्थाई बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत धरती अपने कब्जे में कर रखी थी। इस पद्धति के अनुसार वे सरकार को स्थाई तौर पर निर्धारित राजस्व का भुगतान करते थे। उत्तरी भारत में जमींदारों अथवा ग्राम समुदायों ने धरती पर कब्जा कर रखा था और वे भूमि कर चुकाते थे। यह कर समय-समय पर राजस्व के नए समझौतों के अनुसार बदला जाता था। बंबई और मद्रास में प्रचलित रयतवादी पद्धति के अंतर्गत धरती पर किसान मालिकों का ही कब्जा था जो सीधे राज्य सरकार को कर चुकाते थे। प्रत्येक पृथक ज़ोन पर पृथक पृथक तौर पर राजस्व कृता जाता था और प्रत्येक नए समझौते में इसे नियमित रूप में बदला जाता था।¹ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में समय और स्थान के अनुसार राजस्व की मात्रा निर्धारण का सिद्धांत बदलता रहता था परन्तु 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्थाई बंदोबस्त में न आए देश के सभी भागों में न्यूनतम रूप से कम से कम सिद्धांत रूप में ही, एकरूपता का आधार अपनाया गया। इसका सामान्य आधार अथवा नियम यह था कि जमींदारों और ग्राम समुदायों के कब्जों की जोतों पर वास्तविक अथवा अनुमानित प्रतिशोधक विराण का आधा भाग तथा रयतवादी में आर्थिक विराण का, अथवा निवल (नेट) सर्पित से प्राप्त अथवा निवल उत्पादन पूँजी का आधा भाग² सरकार द्वारा भूराजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।³ व्यवहार में इस सिद्धांत पर कठोरता से अमल नहीं किया गया, चालू राजस्व का कृता जाना जाने रहने, धरती की उत्पादकता को तन्व-मीने, लोगों की सामान्य आर्थिक स्थिति और भूमि के त्रय मूल्य आदि अन्य तत्वों पर भी समुचित ध्यान दिया जाता रहा।⁴ चालू करों में वृद्धि का आधार विशुद्ध रूप से केवल उपज की ओर यह एक अनिश्चित ढंग था। इस वृद्धि के पीछे अनेक अन्य विचारणीय विषय भी जुड़े रहते थे।⁵

समीक्षाधीन अवधि में भूराजस्व सरकारों आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था। 1881-2 में सरकार की कुल निदध राजस्व 46.86 करोड़ में से भूराजस्व की वसूली 19.67 करोड़ थी। 1901-02 में सरकार की कुल वसूली 60.79 करोड़ में भूराजस्व का

योगदान 21.99 करोड़ था।⁷ जैसा कि ये अंक सूचित करते हैं, इन वर्षों में भूराजस्व की वसूली में क्रमिक वृद्धि हो रही थी।⁸ इसके लिए सरकारी विश्लेषण यह था कि यह वृद्धि 'मुख्य रूप से कृषि भूमि के विस्तार तथा मूल्यों में वृद्धि का परिणाम' थी।⁹

राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय कृषि संबंधी समस्याओं में कर निर्धारण पद्धति तथा भूराजस्व की मात्रा को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने भारत सरकार की भूराजस्व नीति का किसानों के दुर्भाग्य और दरिद्रता का तथा कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण घोषित किया। सतीशचंद्रन अवधि के प्रारंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा सरकारी नीति पर शोषणोपेक्षा की शुरुआत भारतीय कृषि समस्याओं पर 'अग्रनव आफ दि पूना सार्वजनिक सभा' में प्रकाशित जस्टिस रानाडे की लेखमाला ने तथा।¹⁰ दस प्रकार 1879 में 'एंग्लो-रियन प्रॉब्लम ऐंड इट्स सोल्यूशन' शीर्षक अपने लेख में जस्टिस रानाडे ने एक कटु मन्त्र का उल्लेख किया - 'यदि राजस्व विभाग की कार्यवाहियों ने देश को कगाल बना दिया है'।¹¹ 1881 में प्रकाशित अपने लेख 'लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल वेल्फेयर' में उन्होंने अपना मत अभिव्यक्त किया कि जब तक वर्तमान कर निर्धारण पद्धति के अंतर्गत भूराजस्व के दबाव का तब नहीं किया जाता, तब तक कृषि में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं प्रयत्न नहीं लाभकर परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारी भौतिक समृद्धि के विनाश के मार्ग में भूमि पर अकारि अधिकार तथा अपनी ही मरजी में भूमि के उत्पादन में वृद्धि का अधिकार दालो मुख्य बाधाएँ हैं।¹²

सरकार की भूराजस्व नीति के विरुद्ध अन्य कई भारतीय नेताओं ने भी यथामस्य विचार प्रकट किए। 1891 में नागपुर में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रसंग की चर्चा करने तथा निर्णायक स्वर में घोषणा की कि भूराजस्व प्रशासन की अविवेकपूर्ण पद्धति देश में दरिद्रता और भयभीतों की व्यापकता के कई कारणों में से एक था। दस सुधार के चलते देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि का सुधार न केवल असंभव हो गया है प्रत्युत उस कृषि का क्रमिक ह्रास भी निश्चित हो गया है।¹³ 1888 में 1901 तक की अवधि में एक भी वर्ष ऐसा नहीं बीता जबकि भूराजस्व प्रशासन के विरोध में किसी पक्ष पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित न किया हो। बीसवीं शताब्दी के शुरू होने की और देश के विनाशकारी अकालों के पंजे में फसने की आशंका भी दत्त ने राष्ट्रवादियों की भूमि पर संबंधी आलोचना को एक तीव्र आदान-प्रदान का रूप दे दिया। अपनी लेखमाला और भाषणों के जो वाद में ओपेन लेटर्स टु नार्ड कर्जन, नाम में छपे, तथा भूमि राजस्व की ही व्यापक विवेचना करने वाले, 'इकोनॉमिक हिस्टरी आफ इंडिया', ग्रंथ के (दो खंडों में) प्रकाशन के माध्यम से दत्त ने बार-बार भूराजस्व प्रणाली पर कृषि को पगुवाना था, भारतीयों को दरिद्र बनाने का तथा अकालों के परिणाम और प्रभाव को गहरा करने का अभियोग लगाया।¹⁴ दत्त को अपन इस धर्मगुरु में जी० बी० जोशी से मूल्यवान समर्थन मिला। जोशी ने 1900-01 में 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'जे' नाम से प्रकाशित पत्रमाला में बंबई के भूराजस्व प्रशासन पर चोट की।¹⁵ गुजरात में भूमिकर निर्धारण की प्रभावी निंदा करने वाले गोकुलदास के० पारीख ने भी दत्त को समर्थन दिया।¹⁶ बहुत सारे अन्य लोक नेताओं तथा समाचारपत्रों ने भूराजस्व प्रशासन को ही कृषि के ह्रास का

तथा कृषकों की दरिद्रता का मूल कारण ठहर गया।¹⁷ उस समय में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह आलोचना अधिकांशतया बंबई, मद्रास और केंद्रीय प्रांतों से भूमिगत निवारण पद्धति तक ही सीमित थी। म्यांमार् बंदोबस्तवाज वगैरह में यह पद्धति स्पष्टतया शिफायत का कारण नहीं बन सकती थी। प्रमुखतया 'मद्रासपुर कानून' के लागू होना के कारण उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, अवध तथा पंजाब में सरकारी मात्रा बुना मिलान ससोपप्रद समझी जाती थी।¹⁸

वस्तुतः भूराजस्व नीति उन विषयों में सामक्य थी जिम पर राष्ट्रीय नेताओं का मार्ग का सारा वर्ग और सारी की सारी विचारधारा सुदृढापूर्वक सुगठित थी। भूराजस्व सबंधी सरकारी नीति की राष्ट्रवादियों द्वारा समीक्षा का व्यापक ज्ञान आरंभ १९०० दशक के लेखों से होता है। अतः हम इस अध्ययन में उनके कुछ पक्षों की परीक्षा करेंगे। इस मद्रास में देश में व्यापक परिमाण में हुई समीक्षा के विवरण का संक्षेप, हम यहाँ केवल राष्ट्रवादियों द्वारा की गई समीक्षा की मक्षिण रूपरेखा ही प्रस्तुत करेंगे।

बुराइयाँ

भारतीय न्याया के अनुसार भारतीय भूराजस्व पद्धति का प्रथम बड़ा भागी दांपत्य था कि कर निवारण अन्यत्र व आगनापूर्वक ऊँची दर पर आ और उस ज्ञान या प्रत्यक्ष बंदोबस्त में धर्मिहर के भुगतान की उच्चतम मापदंड सीमा तक निरंतर उन और पर प्रत्यापना जाता था। उस प्रकार यह राजस्व वास्तव में बहुत अधिक ज्ञान के रूप में प्रदान जाता था तथा धर्मिहर वर्ग का निधन बनाना एवं कुल देता था।¹⁹ बंदोबस्त दांपत्य था कि देश के बहुत भागों में भूराजस्व की वास्तविक मान आधे निबल सिंग ज्ञान या प्रत्यापना उपर की अपेक्षा बहुत ऊँची है। सरकार ने इस अपनी माग की आतम सीमा के रूप में स्वीकार किया है और यह प्रायः सकल (ग्राम) उपज की सीमा प्रतिजन न जाना जाती है।²⁰ बंबई और मद्रास में कभी कभी कर निवारण की मात्रा उनकी ऊँची होती कि सारा का सारा आर्थिक क्रिया इसी में निपट जाता था।²¹ उसके निवारित धर्मिहर जमीनों केवल गुजारेवाली तथा अनाभप्रद ज़ोना के सबंध में सरकार माग धर्मिहर का वतन और उसकी पूँजी के लाभ का ही हडप लेती थी। जस्टिस रानाड ने 1879 में इस स्थिति का विवरण इस प्रकार किया

खराब भूमिवाले सभी खेतों में जुलाई के दाम तथा शिमान के खेतन इस सीमा तक पहुँच जाते हैं कि सारी फसल में उनकी पूर्ति ही मुश्किल से हो पाती है। उस एसी धरती में कोई लाभ नहीं मिलता है। वह अपने खेत में श्रम करने के बदले केवल रोटी कमा पाता है। अतः इस प्रकार के खेतों पर कोई आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती। शिमान बेचारा जो भी लगान चुकाता है, वह या तो ऋण लेकर चुकाता है अथवा किसी अन्य साधन से प्राप्त आय से चुकाता है। भूमि में प्राप्त आय में यह सम्भव नहीं है।²²

इस भारी लगान का कभी कभी परिणाम यह निकलता है कि उस खेत में स्थित निजी संपत्ति का राज्य द्वारा बलपूर्वक अधिग्रहण कर लिया जाता है और बेचारा शिमान

वास्तव में राज्य का खेत जोतने वाला दास बन कर रह जाता है।²³

राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने सभी लेखों और भाषणों में आकड़ों सहित प्रमाण उद्धृत किए। कई एक भारतीय नेताओं ने इस ओर भी निर्देश किया कि भुगतान न कर पाने वाले खेतिहरों पर लगान का भुगतान करने के लिए अनुचित और भारी दबाव डालना, धरती के लगान की उगाही के लिए बड़ी संख्या में उनके जोतों का बिक जाना, जोतों को मजबूरी में मस्ते दामों पर बेचना व रेहन रखना आदि मामले धरती के लगान की ऊंची दर के ही सूचक प्रमाण हैं।²⁴ इनके प्रतिरिक्त देश में अकाल, भुखमरी और मौत की बढ़ती संख्या भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है।²⁵ राष्ट्रवादियों ने सारे देश में धरती के निरंतर बढ़ते दामों तथा किरायों में निरंतर हो रही बढ़ोतरी को लगान के निम्नस्तरीय होने का प्रमाण और परिणाम मानने में सर्वथा इकार कर दिया। इसके विपरीत उनका तर्क यह था कि यह तो देश की बढ़ती जनसंख्या के उद्योगों में खपत न पाने में बेचारे खेतिहरों में धरती को पाने के लिए बढ़ती हुई प्रतियोगिता का तथा देश के बढ़ते हुए ग्रामीकरण का ही दुष्प्रभाव था।²⁶ उन्होंने यह भी निर्देश किया कि पूँजीनिवेश के निकायों की कमी से भी इस वृद्धि को समझने में सहायता ली जा सकती है।²⁷ वस्तुतः बंदोबस्त अधिकारियों के विरुद्ध निजी सुधारों पर कर न लगाने की सरकारी प्रतिभूति खेतिहरों द्वारा किए गए सुधारों को बरकरार रखने के लिए नहीं करती। यह प्रायः या तो परोक्ष रूप से धरती के पुनर्वर्गीकरण के वेश में किया जाता है अथवा सरकार द्वारा किए गए सुधारों से हुए सुधार कहकर किसानों को बहकाया जाता है अथवा निजी सुधारों के फलस्वरूप तथा अशत प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से हुई आय को 'अनुपाजित आय' घोषित करके किया जाता है।²⁸

राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार धरती की लगान पद्धति का एक दूसरा महत्वपूर्ण दोष यह था कि आर्थिक मशोषणों के फलस्वरूप सरकार की धरती में भाग अनिश्चित और अपने प्रभाव में उतार-चढ़ाववाली थी। इसके साथ ही बढ़ोतरी के कोई निश्चित अथवा विशिष्ट नियम नहीं थे। यह लगान अज्ञात, अस्पष्ट, अनिश्चित, भ्रामक और अवांछित, अस्थिर और अपर्याप्त आधारों पर बढ़ाया जा सकता था और बढ़ाया जाता था। निश्चित बेचारा इन आधारों को न तो समझता था और न ही समझ सकता था। राजस्व अधिकारियों को दोबारा बंदावस्त के समय अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति का रोतासाह् दुरुपयोग करने का अवसर मिल जाता था। मजेदार बात यह थी कि उन अधिकारियों पर किसी प्रकार का न्यायिक अथवा विभागीय प्रतिबन्ध नहीं था।²⁹

तृतीय, भारतीय नेताओं ने भूराजस्व पद्धति की कठोरता की भी निंदा की। उन्होंने घोषित किया कि धरती का लगान सस्ती के माध्यम, दृढ़तापूर्वक तथा कसकर वसूला जाता था। इसके उगाड़ने का ढग और समय असुविधाजनक, दुःखदायक तथा भारतीय कृषि की परिस्थितियों के प्रतिकूल था।³⁰ उनका कथन था कि सरकार फसलों के बिगड़ जाने और अकालों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देती। इस प्रकार के प्राकृतिक संकट के काल में जब बेचारा किसान आर्थिक दृष्टि से भारी कष्ट भोग रहा होता है, उस समय भी उसे अपने हिस्से का सरकारी लगान चुकाने को कहा जाता है।³¹

कुछ भारतीयों ने विभिन्न प्रदेशों और वर्गों में भूमि लगान के भार की स्थिति के

प्रश्न पर भी विचार किया और अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्न प्रांतों में इस बोझ का रूप भिन्न भिन्न था। बंगाल का योगदान अपने हिस्से की तुलना में बहुत कम था।³² इसके अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा किसान को काफी अधिक भार उठाना पड़ता था।³³ कई नेताओं ने तो स्पष्ट अनुभव किया कि ब्रिटिश भारत में प्रचलित भूमि लगान पद्धति में जो भी दोष वर्तमान हैं, उनका कारण भारत सरकार द्वारा रिकार्डियन सिद्धांत में विश्वास और उसका अनुसरण करने में है और इसके साथ यह धारणा काम कर रही थी कि भारत में राज्य ही वास्तविक रूप से भूमिपति अथवा भू-स्वामी था। फलतः सरकारी भूराजस्व नीति के पीछे विद्यमान मान्यता पर प्रहार का अभियान चलाया। इस प्रहार का विवेचन 'इंडियन पोलिटिकल इकोनमी' अध्याय में आगे किया गया है। भारतीय नेताओं के अनुसार भूराजस्व पद्धति के कृषि पर पड़ने वाले घातक और क्षतिकारक प्रभाव निम्नलिखित थे :

प्रथम, ऊंचे परिमाण में भूमि लगान किसान की संभावित वचन का एक बहुत बड़ा भाग हड़प कर ग्रामों को धनशून्य बना देता है, भूमि को धन निवेश से वंचित कर देता है और सामान्य रूप से कृषि संबंधी सुधारों पर होने वाला खर्च रोक देता है।³⁴ द्वितीय, भारी लगान देहातों में माधनहीनता बढ़ाकर अकालों की व्यापकता और विस्तार बढ़ा देता है। किसान अच्छे वर्षों में बुड़ी फसलवाले वर्षों के लिए कुछ नहीं बचा पाना फलतः वह आसानी से अकाल और मृत्यु का शिकार बन जाता है। यह उसकी वचन शक्ति का अभाव ही था जो मूल्य को अकाल का रूप दे देती थी।³⁵ आजीविका वांछी जोतों पर तो भारी और उंचे लगान सामान्य वर्षों में भी भुखमरी की स्थिति ला देते हैं।³⁶ तृतीय, लगानों में निरंतर संशोधन, अल्पकालीन बंदोबस्त, लगान वृद्धि के अनिश्चित आधार, प्रत्येक व्यक्ति के भूभाग का नया मूल्यांकन और उसके फलस्वरूप जोतने वाले के सुधारों पर नए लगान लगाना आदि, ये सब किरायों का आधार अनिश्चित बना देते हैं। अनिश्चित किरायों के साथ जुड़े ऊंचे लगान, किसान के सारे बचत के लक्ष्य को, तथा उसकी धरती के स्थाई सुधार की तथा कृषि संबंधी उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते हैं। किरायों की अमरक्षितता तथा लगानों में ऊंची बढ़ोतरी किसान को असमंजस में डाल देते हैं कि वह कठोर श्रम करे कि आराम का जीवन बिताए, क्योंकि उसे तो यह भी विश्वास नहीं होता कि वह अपने कठोर श्रम का फल भी पाएगा कि नहीं। भूराजस्व पद्धति के साथ जुड़ी हुई यही असुविधाजनक स्थिति थी जिसने भारतीय किसान को आलसी, फिजूलखर्च बना दिया था। देहातों में उद्यम और उत्साह की भावना के अभाव के लिए यही उत्तरदायी है। इसका परिणाम यह निकला है कि कृषि में गतिहीनता तथा ह्रास आ गया है और भारतीय ग्रामों में निर्धनता का साम्राज्य स्थापित हो गया है।³⁷ भारतीय नेताओं ने इस धारणा का बड़ी तीव्रता तथा उग्रता के साथ खंडन किया कि भारतीय किसान का शक्तिहीन, अकर्मण्य तथा अदूरदर्शी स्वभाव और चरित्र ही उसकी आर्थिक कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी था, उसकी ये तथाकथित चरित्रगत विशेषताएं तो काफी हद तक वस्तुतः भूराजस्व पद्धति का ही परिणाम थीं अन्यथा भारतीय कृषक तो स्वभाव से ही मितव्यी, परिश्रमी तथा दूरदर्शी है।³⁸ चतुर्थ, भूराजस्व का ऊंचा

परिमाण और उसके साथ जुड़ी अनिश्चितता भूमि पर निजी पूँजी के निवेश को बाधित ही नहीं प्रत्युत असंभव बना देती है और इस प्रकार भूमि मुधारों को और पूँजीनिष्ठ कृषि के विकास को नकार देती है।³⁹ पंचम, सरकारी लगानों में वृद्ध बड़े बड़े जमींदारों और बड़ी बड़ी ज़ोतों के मालिकों को किराया बढ़ाने का बहाना जुटा देती है और वे वास्तविक से भी बहुत अधिक किराया बढ़ा देते हैं जिसके फलस्वरूप वास्तविक जमीन जोतने वालों पर भारी बोझ पड़ता है।⁴⁰ आर० सी० दत्त ने बताया कि जहाँ ज़ोतों पर लगान किराए के एक भाग के रूप में होता था, वहाँ लगान कर्मचारी उन जमींदारों पर, जो सामान्यतया किराया बढ़ाने के प्रति उदार हो सकते थे, किराया बढ़ाने के लिए ज़ोर देते थे ताकि सरकार अधिक लगान लगा सके।⁴¹ छोटे कृषि उत्पादकों में ऊँचे परिमाण में किसी प्रकार की बढ़ोतरी न होने पर, लगान की ऊँची दर और उसके साथ संबद्ध भूमि लगान पद्धति की कठोरता तथा उग्रता धरती को बचाने के लिए इच्छुक और लगान की मांग की पूर्ति में असमर्थ बेचारे परेशान किसानों को निर्दयतापूर्वक माफ़कार के ऋण पत्रों में डाल देती है जहाँ एक बार फँसा वह गरीब कभी मुक्त नहीं हो पाता।⁴² भूमि के लगानों के संग्रह की कठोरता और अमूर्तिविधा से भी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विवश होना पड़ना था और ग़ज़ार में एकदम उपज का तूफ़ान सा आ जाता था, जिसमें दित्तों के विरुद्ध मूल्यों में नरती गिरावट आ जाती थी जो उन बेचारे किसानों के लिए हानिकारक थी।⁴³

बृहत् भारतीय नेताओं ने भूमि लगान की समस्या को घन की निकासी के साथ ही जोड़ा और कहा कि ऊँचे लगान के दोष उस स्थिति में और भी तीव्र हो जाते हैं जब टा लगान की राशि का भूमि को उपजाऊ बनाने में उपयोग न करके उसके बहुत बड़े भाग को देश में बाहर निकासी की जाती है।⁴⁴

उपचार

राष्ट्रवादीयों द्वारा की गई भूराजस्व प्रशासन की आलोचना के उपर्युक्त सक्षिप्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय नेताओं का विश्वास था कि कृषिसंबंधी सभी समस्याओं और दोषों की आधारभूत भूराजस्व पद्धति में उपयुक्त सुधार किए बिना किसी भी समस्या का समाधान असंभव है। उनके इस दृष्टिकोण को जस्टिस रानाडे के शब्दों में निम्ननिम्नित रूप में सक्षिप्त रूप में रखा जा सकता है

उनकी (खेतिहरों की) एक ही मांग है कि उन्हें, सामाजिक स्तर पर अपने को बेहतर बनाने के निरर्थक मर्ष में उनकी शक्तियों को नष्ट करने वाले उनकी योग्यताओं का अंगु करन वाले अत्यंत कष्टदायक तथा असह्य भार रूप, लगान के बंदोबस्तों से मुक्त किया जाए। इस भारी दबाव को थोड़ा हलका कीजिए, गतिविधि तथा लचीली शक्ति को भीतर से ही उमड़ने दीजिए, उनकी रवत ही भौतिक संपन्नता की आरंभ होगी और इससे उनके सारे पुराने घाव भर जाएंगे ...।⁴⁵

परंतु अब प्रश्न यह था कि इस भारी भार को हलका बनाया किरा प्रकार जाए ? राष्ट्रवादीयों का उत्तर यह था कि भारतीय भूराजस्व पद्धति के अनिवार्य दोषपूर्ण तत्व ये थे कि एक ओर काश्तकारी असुरक्षित थी, दूसरी ओर लगान की खाई बड़ी गहरी थी और

तीसरी ओर लगान वृद्धि अनिश्चित आधार लिए हुए थी। उपचार में केंद्रीय उपाय ये हो सकते थे कि काश्तकारी को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भूमि जोतने वाले अपने को स्वतन्त्र मालिक समझें ही नहीं, प्रत्युत यथार्थ में वास्तविक और स्वतंत्र रूप से मालिक बन भी जाएं। जैसा कि जस्टिस रानाडे ने बार बार बल दिया, भारत में तो संपत्ति के जादू की ही आवश्यकता थी।¹⁴ 1890 में इस विषय पर लिखते हुए, जी० बी० जोशी ने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति दी :

स्वत्वाधिकार एक ऐसी प्रभावी और मानव को गतिशील बनाने वाली शक्ति है जिसमें विश्व भर में सुधारों को स्वतः प्रेरणा और गति मिलती है। तथाकथित आलमियो, परोपकारियों और ससार को मिथ्या मानने वाले वेदान्तियों के इस देश में भी स्वत्वाधिकार का प्रभाव स्वतः मान्य है। वस्तुतः मानव प्रकृति का और मानव श्रम का नियम भारत, फ्रांस अथवा नार्वे कहीं भी, बदला नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को आप एक काली चट्टान का ही सुरक्षित स्वामित्व दे दीजिए, वह उस पथ-गिरी धरती को लहलहाते बाग में बदल देगा, किसान की वतमान उपेक्षावृत्ति को बदलने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ साधन हमें दिखाई नहीं देता कि उसकी रुचि उत्पन्न करने के लिए उसकी जोत का उसे सुरक्षित अधिकार दिया जाए तथा उसे अपने श्रम का फल पाने का पूरा आश्वासन दिया जाए।¹⁷

भागीय नेताओं द्वारा सुभाए गए उपचारमूलक साधनों को आर० सी० दत्त ने 1900 में लार्ड कर्जन को लिखे अपने पांचवें और अंतिम ओपेन लेटर टु कर्जन में बड़ी सफाई के साथ मंजिस्त्र रूप दिया।¹⁸ उन्होंने लार्ड कर्जन के भूमि प्रस्ताव के द्वितीय प्रत्युत्तर 'सेकंड रिप्लाइ टु लार्ड कर्जनस लैंड रिजान्यूशन' में इसे तत्त्व रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया : एक कृषिप्रधान देश की मपन्नता और प्रसन्नता व्यापक रूप में भूमि लगान पर कुछ स्पष्ट, निश्चित, ममक आने वाली तथा व्यावहारिक सीमा लगाने पर ही निर्भर करती है...।¹⁹ सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनों का विवेचन निम्नलिखित रूप में है

भूमि लगान का भार इस स्तर तक कम किया जाना चाहिए, जिसमें किसान के पास आजीविका के लिए समुचित बचत रह जाए, खराब मौसमों के लिए व्यवस्था संभव हो सके, तथा पृथी के निवेश द्वारा भूमिसुधार किया जा सके। दोबारा बंदोबस्त करने समय भी लगान वृद्धि पर इस प्रकार से एक सीमा निर्धारण करनी चाहिए, जिससे किसान इस विश्वास के साथ स्वेच्छापूर्वक सुधार कर सके कि उसे उसके श्रम और त्याग का फल अवश्य मिलेगा।²⁰ कुछ भारतीय नेताओं का यह भी कथन था कि भारत की अपनी स्थितियों में भूमि लगान के निर्धारण का उचित मानक आधार यह होगा कि निम्न उपज का, अथवा किराए से आय का, अथवा आर्थिक किराए का आधा भाग उगाहना होगा। इसमें शर्त यह होगी कि इसका हिसाब सही सही और ईमानदारी से किया जाए। इस आधार पर लगाया गया लगान होगा तो कष्टदायक और अमुविधाजनक ही परंतु भारतीय स्थिति में इसे उचित माना जा सकता है।²¹ भारत सरकार की भूमि लगान नीति के विरुद्ध युद्ध की तीव्रता में आर० सी० दत्त ने कुल उत्पादन के 1/5 भाग के अधिकतम तक लगान सीमा निर्धारित करने का अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की।²² मजेदार बात यह

हैं कि जस्टिस रानाडे ने 1879 में दक्षिणी प्रदेशों के लिए लगान की अधिकतम सीमा कुल उपज का 1/6 भाग निर्धारित करने की सिफारिश की थी।⁵³ इस संदर्भ में जी० बी० जोशी का क्रांतिकारी सुभाव यह था कि अलाभप्रद जोतों पर लगान लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनमें किसी प्रकार की अतिरिक्त उपज नहीं होती जिससे किराए अथवा लगान का भुगतान किया जा सके। ऐसे मामलों में सरकार की मांग किसान की अपने ही लिए सर्वथा अपर्याप्त उपज से कटौती का रूप ले लेती है। इस प्रकार सरकार गरीब किसान की पट्टे से ही निम्नस्तरीय तथा स्वल्प खाद्यपूर्ति का एक बड़ा अंश हड़प लेती है।⁵⁴

द्वितीय, देश के अस्थाई बंदोबस्तवाले भागों में सरकार लगानों के स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था करे। कृषि के संदर्भ में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक रूप में समर्थित राष्ट्रीय मांगों में एक थी और इसका विवेचन आगे एक पृथक् भाग में किया गया है। राष्ट्रवादियों का सुभाव था कि जब तक इन क्षेत्रों में स्थाई बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक सरकार दोबारा होने वाले बंदोबस्त के समय मनमानी बढ़ोतरी से किसान को मरक्षण दे। सरकार यह काम इस प्रकार कर सकती है कि वह लगान वृद्धि के लिए स्पष्ट तथा सुनिश्चित आधारों, सीमाओं और व्यवस्थाओं का निर्देश इस रूप में कर दे कि जिसमें एक ओर किसान, जो सबको भली प्रकार जान और समझ ले तथा दूसरी ओर बंदोबस्त अधिकारी अपनी मर्जी से उनका उल्लंघन अथवा उनमें परिवर्तन न कर सकें,⁵⁵ किसानों द्वारा किए गए सुधारों पर लगान न लगाने के सिद्धांत का सावधानी से पालन कराए,⁵⁶ बंदोबस्त शब्द को व्यापक रूप दे⁵⁷ तथा दीवानी और अन्यान्य न्यायालयों में लगान वृद्धि को न्याय का विषय बनाए जा सकने की व्यवस्था करे।⁵⁸

तृतीय, राजस्व पद्धति को और अधिक लचीला बनाना चाहिए और उगाही के ढंग को सुधारा और अधिक आसान बनाया जाना चाहिए।⁵⁹ यह कार्य लगान को विभिन्न किस्तों में बांटने की ओर उन किस्तों को सुविधानुसार तयियों पर चुकाने की व्यवस्था करके किया जा सकता है।⁶⁰ इसके अतिरिक्त बर्षों और अकाल के वर्षों में प्रणामनिक कार्य के रूप में मात्र स्थगन नहीं प्रत्युत सिद्धान्त रूप में रियायत, व्यापक और उदार छूटें देकर भी लगान पद्धति सुधारी जा सकती है ताकि विघ्न किसान अकाल के बाद के वर्षों में फिर अपने आपको सभाल सकें।⁶¹ इस संदर्भ में सामान्य भारतीय नेताओं का लगान का किस्तों में भुगतान के सिद्धांत को अथवा अन्य किसी इस प्रकार के सशोधित ढंग को पर्याप्त समर्थन मिला।⁶² परंतु उन्होंने इस सुभाव को मानने के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाला क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि वर्तमान व्यवहार से यह एक क्रांतिकारी प्रत्यावर्तन था अतः सरकार द्वारा इसे स्वीकार करना संभव नहीं था।⁶³

राष्ट्रवादियों की भूराजस्व पद्धति से संबंधित नीति का एक रोचक पक्ष यह था कि उन्होंने राजस्व प्रशासन संबंधी मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए किसानों को मगठित करने का कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया। इस सुस्ती अथवा उपेक्षा का कदाचित्त एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद 1896 में लोकमान्य तिलक द्वारा अकाल पीड़ित महापट्ट में अर्थार्थ रूप में कर न देने के आंदोलन को चलाने का प्रयास था। 1896 के अकाल की अवधि में सरकार द्वारा कर बसूली में स्थगन अथवा रियायत देने से इनकार किए जा-

पर उत्तेजित तिलक ने चालू 'अकाल सहायता कोड' के अंतर्गत अपने अधिकार मांगने के लिए लोगों को सुशिक्षित और संगठित करने का बीड़ा उठाया। 'केसरी' पुस्तिकाओं, जन-सभाओं, प्रचार दीरों तथा अभी अभी अपने नियंत्रण में आई 'पूना सार्वजनिक सभा' के अभिकरणों के माध्यम से तिलक दक्षिण के किसानों को यह समझाने में जुट गए कि अकाल की अवधि में उनके बचाव और सहायता के लिए कानूनी व्यवस्था थी, सरकार उनके जीवन की रक्षा के लिए नैतिक रूप में बाध्य थी। सरकारी अधिकारी अकाल संहिता के अंतर्गत उनकी सहायता के लिए कर्तव्यबद्ध थे। उस संहिता का पालन करने के लिए किसान भाई सरकारी अधिकारियों पर दृढ़तापूर्वक और उच्च स्वर से दबाव डालें, करों के भुगतान करने की स्थिति में न होने पर भुगतान करने से इनकार करने पर किसान भाई न केवल कानूनी दृष्टि में बिल्कुल न्याय पर होंगे प्रत्युत वस्तुतः वे कानून पालन कराने में सहायक भी सिद्ध होंगे।¹⁵⁴ यह लगान-मनाही आंदोलन के एक प्रारंभिक रूप से अलग कुछ न था।¹⁵⁵ तिलक के सरकार विरोधी न होने के दृढ़ कथनों के बावजूद सरकार ने स्थिति को भली प्रकार समझ लिया था और उसने पूना सार्वजनिक सभा के अभिकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की, सभा के विरुद्ध और अंत में स्वयं लोकमान्य के विरुद्ध कठोर पग उठाया।¹⁵⁶ तिलक पर 1897 में राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने और उन्हें 18 महीने कारावास का दंड दिए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1896 की शीत ऋतु में दक्षिण के किसानों में उसके आंदोलन की क्रांतिकारी शक्तियों को दूरदर्शी ब्रिटिश अधिकारी न केवल भाप गए थे प्रत्युत उसके प्रति सावधान भी हो गए थे। इसके साथ ही स्वयं तिलक ने भी अपने इस कार्य के गहरे राजनीतिक परिणाम निकाले तथा उससे उपयुक्त सबक लिया। जब अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व का अनुसरण न किया और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अकालपीड़ितों की सहायता के लिए प्रभावी पग उठाने में पिछड़ गई तो लोकमान्य ने कांग्रेस की उसके निकम्मेपन के लिए भर्त्सना की तथा केसरी के 12 जनवरी 1897 के अंक में लिखा :

पिछले बारह वर्षों से हम गना फाड़फाड़कर इस इच्छा से चिल्लाते आ रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने परंतु अब तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और हमारी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। हमारे शासक हमारे वक्तव्यों पर विश्वास नहीं करते अथवा विश्वास न करने का दावा करते हैं। आइए, अब हम सुदृढ़ सांविधानिक उपायों से सरकार को अपनी शिकायतें सुनने के लिए विवश कर दें। हम अशिक्षित ग्रामीणों को यथासंभव सर्वोत्तम राजनीतिक शिक्षा दें। उनके साथ समता के स्तर पर व्यवहार करें। उन्हें उनके अधिकार बताएं तथा उन्हें सलाह दें कि सांविधानिक तरीकों से वे अधिकार कैसे पाए जाते हैं। तभी, केवल तभी सरकार इस बात को समझेगी कि कांग्रेस के तिरस्कार का अर्थ भारत राष्ट्र का तिरस्कार है। तभी कांग्रेसी नेताओं के प्रयास सफल होंगे। इस महान अनुष्ठान के लिए योग्य और दृढ़ निश्चयवाले व्यक्तियों के एक विशाल दल की अपेक्षा है, जिनके लिए राजनीति अवकाश और मनोरंजन का साधन न होकर

कठोरतम नियमितता और पूर्णतम योग्यता के साथ निभाया जाने वाला प्रतिदिन का कर्तव्य हो।⁶⁷

भारत जैम देश में खेतिहरो की ऐतिहासिक, राजनीतिक भूमिका के प्रति भी उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया। उन्होंने घोषणा की :

भारत की आत्मा रूप किसान पर मड़गते सुम्नी और बेपरवाही के बादलों को हटाए बिना देश की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें इन बादलों को अवश्यमेव हटाना होगा और उसके लिए किसानों के साथ अपने को पूर्णरूप में जोड़ना होगा। हम यह समझ लेंगे कि किसान हमारा है और हम किसान के हैं।⁶⁸

भूराजस्व का स्थाई बंदोबस्त

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा भूराजस्व कम करने की मांग तथा राजस्व में वृद्धि और उसके व्यय की मिन्नतों में सुधार की बकालत मूल उपाय न होकर शासक औपधि ही थे। उनके विचार में जिस अंश तक राजस्व समस्या और किसान की साधनहीनता और दरिद्रता का जन्म राजस्व प्रणाली के फलस्वरूप होता है, उस अंश तक उनका वास्तविक और व्यापक समाधान भूमि पर सरकारी मांग के स्थाई बंदोबस्त में ही निहित था। जब किसान को यह मानना पड़ा कि वह बंदोबस्त कर्मचारी के चंगुल में सदा के लिए मुक्त है तभी वह धरती को अपनी ओर सुरक्षित मानेगा और तभी संपत्ति का जादू देश में अपना चमत्कार दिखाएगा। तभी किसान में धरती के लिए पूजा बचाने और धरती में विनियोजित करने की, धरती को सुधारन की तथा अधुनातन वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग का उन्माद और प्रवृत्ति पनपेगी।

गणेशाधीन अर्वाचन के प्रारंभ में भूराजस्व के स्थाई बंदोबस्त के मामले पर जस्टिस रानाडे ने कृषि समस्या पर लिखे अपने लगभग सभी निबंधों में बड़े विश्वासपूर्वक बहस की।⁶⁹ 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करने हुए इस मांग को अपनी मांग बना लिया :

कि विभागाधीन स्थाई बंदोबस्त के विषय को एक बार फिर हाथ में लिया जाए और उस पर इस रूप में व्यावहारिक कार्यवाही की जाए कि देश के सभी बसे हुए और भली प्रकार जोते गए भूभागों पर किसी भी मूल्य पर बिना और अधिक विलंब किए सरकारी भूमि लगान को स्थायित्व और निश्चितता दी जाए।⁷⁰

उल्लेखनीय यह है कि कांग्रेस का इसके उपरांत वास्तव में शायद ही कोई अधिवेशन हुआ हां जिसमें इस मांग को दोहराया न गया हो।⁷¹ लगभग सभी अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में जिनमें आर० सी० दत्त भी सम्मिलित थे।⁷² तथा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों ने इस मांग के लिए आंदोलन किया।⁷³

यह राष्ट्रवादी मांग काफी अस्पष्ट रही है क्योंकि भारतीय इतिहास और भारतीय अर्थशास्त्र के बहुत सारे विद्वानों तथा भारतीय नेतृत्व के विभिन्न आलोचकों ने इस मांग को बंगाल के 1793 के स्थाई बंदोबस्त के समकक्ष माना और यह धारणा प्रकट की कि इस मांग के माध्यम से तत्कालीन भारतीय नेता रयतबाड़ी क्षेत्रों में बंगाल की जमींदारी

प्रथा लाना चाहते थे। इस मान्यता को अंगीकार करते हुए उनमें से कितनों ने व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से भारतीय नेताओं पर विशेषाधिकार संपन्न जमींदारों के प्रवक्ता होने तथा अधिकारहीन और कुचले हुए कृषकों के हितों की उपेक्षा ही नहीं प्रत्युत उनका विरोध करने का आरोप लगाया। राजस्व के स्थाई बंदोबस्त की निरंतर वकालत करने के कारण आर० सी० दत्त को तो जमींदारों का पिटू होने की उपाधि दी गई। वस्तुतः आर० सी० दत्त तथा अन्य नेताओं पर राजस्व के स्थाई बंदोबस्त के संबंध में लगाए गए आरोप सर्वथा निराधार थे। विषय के इस पक्ष का विस्तृत विवेचन अनुचित न होगा।

निस्संदेह, इस भ्रम की जड़ें बहुत पुरानी थीं, यहां तक कि उस युग के भारतीय नेताओं के मन में भी यह भ्रांति व्याप्त थी, परंतु परवर्ती लेखकों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व भारत सरकार की भूमि लगान नीति के संबंध में 1902 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कर्जन ने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करते समय जानबूझकर ऐसी विधि अपनाई जिससे वह सरकारी भूराजस्व नीति के समीक्षकों के विरुद्ध भारतीयों के मन में भ्रम का बीज बोकर बहस में विजय प्राप्त कर सके। कुछ भी हो उसने पहले उस प्रसिद्ध प्रस्ताव में राजस्व के स्थाई बंदोबस्त को बंगाल के 1793 के स्थाई बंदोबस्त के साथ जोड़ा और उसके पश्चात पराङ्मुख होकर कहा कि भारत सरकार के वर्तमान विरोधियों, पूर्ववर्ती विचार परंपरा के प्रतिनिधियों ने इससे पहले ही सारे भारतवर्ष में स्थाई बंदोबस्त की वकालत की है।¹⁶ उसने आगे चलकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि स्थाई बंदोबस्त बंगाल का अकाल से नहीं बचा सका है। यह विश्वास करने का भी कोई आधार नहीं कि बंगाल का किसान भारत के अन्यान्य प्रांतों के किसान की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। स्थाई बंदोबस्त होने के कारण जमींदार का किराएदार बना हुआ बंगाल का किसान वास्तव में सुखी नहीं है अपितु विपरीत स्थिति यह है कि वह किराए में दबा पड़ा है, कंगाल है और दलित पीड़ित है। जमींदारी प्रथा के अभाव से उत्पन्न सहानुभूतिशून्य अभिकर्ताओं द्वारा प्रदेश का प्रबंध संचालन, जमींदार और किराएदार के बीच विकृत संबंध और बिचौलियों का बहुमुखी हस्तक्षेप आदि बुराईयां बढ़ती जा रही हैं। अंतिम सत्य यह है कि यदि इन सबके बावजूद बंगाल का किसान सुरक्षित और संपन्न है तो इसका कारण स्थाई बंदोबस्त न होकर सरकार द्वारा उसकी रक्षा के लिए पारित काश्तकारी कानून हैं।¹⁶ इस प्रकार कर्जन ने डंके की चोट पर कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी सभ्य देश के लोक आदर्श के रूप में सहायक होने के अनुभव से शून्य कृषि 'किराया पद्धति के प्रस्ताव का जानबूझकर समर्थन नहीं कर सकती...'।¹⁷ बस, यही कथन का आधार बन गया। कर्जन ने जानबूझकर अथवा अनजाने सरकार विरोधियों की स्थाई बंदोबस्त की मांग को बंगाल में प्रचलित कृषि किराया पद्धति के साथ जोड़ दिया। उसने आलोचकों पर परोक्ष रूप से और बड़ी ही सफाई तथा चतुरता से जमींदार समर्थक होने का बिल्ला लगाने की भी चेष्टा की। उसने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकार की स्थिति को सुधारने और सुरक्षित करने के सरकारी प्रयत्नों में सहयोग न देने के लिए उन नेताओं पर ताने कसे और उन्हें आड़े हाथों लिया।¹⁸

इम संबंध में कर्जन द्वारा प्रदर्शित मार्ग का परवर्ती अनेक लेखकों ने अनुसरण किया और समय बीतने के साथ भ्रमजाल और कसता गया। इसी क्रम में जे० डी० रीस ने 1908 में लिखा कि जमींदारों के हितों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा कांग्रेस का आंदोलन सरकार को उन कगो की वसूली बंद करने के लिए विवश करने पर तुला हुआ है जो सरकार वटे वड़े जमींदारों से उगाहती है और बड़े पैमाने पर छोटे छोटे किसानों पर खर्च करती है।⁷⁹ भारत में कर्जन के प्रशासन के भाग जीवनीकार लोवेट फ्रेजर ने 1911 में अपने लेख में आर० सी० दत्त पर अभियोग लगाते हुए लिखा कि 'वह प्रमुख रूप से समृद्ध वर्ग के हितों की ही देखभाल कर रहे है।' फ्रेजर ने राष्ट्रवादियों की गतिविधियों पर साफ तौर पर लिखा 'अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन का एक विचित्र पहलू यह है कि अत्यंत दरिद्र वर्ग का सरकार के सिवाय अन्य कोई प्रवक्ता और सरक्षक ही नहीं है।'⁸⁰ 1921 में प्रकाशित के० टी० शाह के 'मिक्स्टी इयर्स आफ इंडियन फाइनांस' के निम्नलिखित अवतरण स फ्रेजर की राष्ट्रवादियों की स्थिति के प्रति गलत धारणा के अत्यंत भ्रष्ट रूप को दर्शा जा सकता है।

यदि स्वर्गीय श्री आर० सी० दत्त के लेखों को इस संबंध में गत शताब्दी के लोकमत का सूचक स्वीकार कर लिया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि बंगाल के स्थाई बदाबस्त को दूगरे प्रांतों में लागू करने को भारतीय लोकनानाओं की व्यापक स्वीकृति प्राप्त थी और इसका उद्देश्य अंगरेजी ढंग के जमींदारों के हाथ में पूरे तौर पर जमीन का अधिपत्य सौंपना था।⁸¹

अतीत में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण के सबंध में तीन अन्य प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों, पी० जे० थामस, पी० एम० लोकनानाथन तथा बी० आर० मिश्र ने भी गलतफहमी पैदा की।⁸² भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो भारतीय इतिहासकारों, पनसी छाया घोष तथा बी० बी० मिश्र ने काफी हाल में और मभवन उमरे लिए उनके पास कोई कारण न था इसी गलती को दहराया है। टाक्टरेट की उपाधि के लिए लिखे अपने शोध प्रबंध, 'दि डेवलपमेंट आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1892-1909', में श्रीमती घोष ने कांग्रेस की स्थाई बदाबस्त की मांग को बंगाल टाइप के स्थाई बदाबस्त का विस्तार मान लिया है।⁸³ श्रीमती घोष ने तो यहां तक लिख डाला है कि 1899 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद में भाषण देने हुए आर० सी० दत्त ने सरकार से भारत के दूसरे भागों में बंगाल पद्धति को लागू करने की प्रार्थना की थी।⁸⁴ बी० बी० मिश्र अपने हाल के ग्रंथ, 'दि इंडियन मिडल क्लासेज देयर ग्रेथ इन माडर्न टाइम्स' में लिखते हैं कि कांग्रेस ने 1888 में सरकार पर देश के सभी भागों में बंगाल के ढंग के स्थाई बदाबस्त को, जिनमें काश्तकारी को बहुत दुख पहुंचाया था और इस प्रकार जो सर्वथा अनुपयोगी था, यह हम पहले ही दिखा चुके हैं, लागू करने के लिए दबाव डाला था।⁸⁵ इस सुदृढ़ मान्यता की स्थापना पुस्तक के 'मिडल क्लास अपोजीशन टु टेनेट राइट्स' शीर्षक उप-विभाग में की गई है। इसमें लेखक का तर्क है कि 1880 के वर्षों में लैजिस्लेटिव कौंसिल के विस्तार के लिए सरकार की आनाकानी का एक कारण यह भय था कि उनका विस्तार और भारतीयकरण काश्तकारी में सुधार जैसे प्रगतिवादी कानूनों के मार्ग में आड़े आएगा।

भारत सरकार के मन में यह भय न केवल कौंसिल के भारतीय सदस्यों की काशनकार विरोधी भूमिका से उत्पन्न हुआ प्रत्युत शिक्षित वर्गों के राजनीतिक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्वारा उठाई गई मांगों की प्रकृति से भी उत्पन्न हुआ।¹⁹⁶ हालांकि एक अन्य लेखक परसिवल स्पीयर यह स्वीकार करत हुआ भी कि पश्चिम तथा दक्षिण प्रदेशों के कांग्रेसी सदस्यों को जमींदारों से कोई विशेष सरोकार नहीं था, दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि बंगाली सदस्य सामान्यतया जमींदारों से संबंधित थे और उन्होंने सारे भारत में स्थाई बंदोबस्त लागू न करने में उत्पन्न अनेक कुराड़ियों के लिए सरकार को दोषी ठहराया था।¹⁹⁷

वास्तव में, समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में उनकी समाप्ति तक भारतीय स्वाधीनतावादी नेताओं के प्रबल बहुमत ने जमीन पर स्थाई बंदोबस्त की सरकारी मांग और बगान के स्थाई बंदोबस्त के बीच अंतर की स्पष्ट जानकारी थी। उन्होंने यथामभव स्पष्ट तथा निष्पक्ष भाषा में और बार बार इस तथ्य को उजागर किया कि स्थाई बंदोबस्त की चर्चा का अर्थ देश के अन्यान्य भागों में बगान पद्धति के दोहराने की मांग अथवा 1793 में जमींदारी लगान के विस्तार की मांग कदापि नहीं था, उसका अभिप्राय केवल भूमि के लगान की मांग की निरंतरता को स्थिर करने की मांग थी। उन्हें यह ज्ञान था कि उन्हें गलत समझा जा सकता है और उनके मतव्यक्त गलत और निराशाजनक माना जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहते में कोई गलती नहीं किया कि जमींदारी तथा रियासती पट्टे के सार्वभौमिक गुण-दोषों के संबंध में उनके निजी विचार कुछ भी कम नहीं परंतु स्थाई बंदोबस्त की मांग करने समय उनका न पट्टेदारी प्रथा में कोई वास्ता न और न ही लगान वसूली में। उन्हें तो एकमात्र लगान की विविधता अथवा पट्टेदारी प्रथा के अंतर्गत कराधान के सिद्धान्तों में ही प्रयोजन था।

स्थान की कमी के कारण यहां भारतीय नेताओं द्वारा इस संबंध में दिए गए सभी विश्लेषण सर्वथा स्पष्ट तथा पूर्ण रूप में उद्धृत करना संभव नहीं आ। अध्ययनकर्ता की सारी अवधि में फैले हुए कुछ उद्धरण नीचे पुनः उद्धृत किए जा रहे हैं। बगान ने इस संबंध में सर्वाधिक बदनाम नेताओं के अवतरणों पर बल दिया गया है। 1879 में एक प्रमुख बंगाली नेता, उल्लेखनीय है कि अपनी पीढ़ी के कदाचित् सर्वप्रमुख नेता, लामोहन घोष ने लिखा :

मेरे विचार में बंगाल में प्रचलित पद्धति के सर्वाधिक रूप निरंतरतावादी बंदोबस्त को सारे देश में व्यापक रूप देने में बड़का देश के लिए अन्य कोई बरदान नहीं हो सकता। हम तो चाहेंगे कि स्वयं कृषक वर्ग अपने आप ही बंदोबस्त की कार्यवाही करे न कि यह कार्य बंगाल के जमींदारों जैसे बिचौलियों के द्वारा किया जाए। हम तो भारत में स्विट्जरलैंड तथा यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों में प्रचलित पद्धति जैसी ही कोई पद्धति चाहते हैं।¹⁹⁸

1880 में जस्टिस रानाडे ने कहा : 'भूमि द्वारा उत्पादित अनाज के अनुरूप निर्धारित स्थाई रेंटतबाड़ी बंदोबस्त... इस कृषि समस्या का एकमात्र समाधान बन सकता है।'¹⁹⁹ चार वर्षों के बाद उन्होंने यह अधिकृत घोषणा की :

यहां हम यह कहना चाहेंगे कि समय समय पर इस पत्र में तथा अन्यान्य पत्रों में प्रकाशित हमारे विचारों को प्रायः गलत समझा गया है। हमने रयतबाड़ी पट्टेदारों को नष्ट करने की मांग कभी नहीं की अथवा इसके माध्यम जमींदारी बंदोबस्त की व्यवस्था के लिए कभी नहीं सोचा। रयतबाड़ी प्रथा तो इस प्रांत में चिरकाल से प्रचलित है और यह एकमात्र पद्धति है जो हमारे ग्रामीण समाज की लोकतंत्रीय व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल है। हमने तो इस प्रांत में किसानों की जोतों पर लगान के स्थाई निर्धारण के लिए आंदोलन किया है।⁹⁰

इदु प्रकाश ने स्थाई बंदोबस्त की वकालत करने हुए 7 मार्च 1881 के अंक में दृढ़तापूर्वक लिखा :

भारत के इस प्रांत के किसी भी वर्ग ने जमींदारी लागू करने की वकालत नहीं की और यदि इदु प्रकाश ने बंगाल की कृषिमबंधी संपन्ना की जय जयकार की है तो इसके श्रेय बंगाल में लगान के स्थाई निर्धारण का ही है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम जमींदारों द्वारा किसानों को अप्रसन्न करना चाहते हैं। हमारी स्थिति को इस रूप में देखना इस सारे प्रश्न को समझने में शोचनीय रूप से अपने अज्ञान का ही प्रदर्शन करना है।⁹¹

मगठा ने 17 फरवरी 1884 के अंक में इस प्रश्न पर जिम गण्टटा और दो टूक निर्णयात्मकता के साथ प्रकाश डाला, वह सचमुच ही विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथा उल्लेखनीय है

यदि स्थाई बंदोबस्त उचित है तो सरकार को कुछ त्याग अवश्य करना पड़ेगा। उसे ब्रिचैनियो अथवा जमींदारों पर निर्भर न रहकर किसानों के पाम जाना होगा। सरकार उद्योगों और शिल्पों को प्रोत्साहन देने के बदले बेचारे किसानों को जमींदारों की दया पर ही निर्भर रहने को विवश कर गये है। बंगाल की जमींदारी अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में खुदकास्त कृषि नहीं है। खुदकास्तवाली पद्धति ही स्थाई रयतबाड़ी पद्धति होगी। यह वह पद्धति है जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं।⁹²

1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्थाई बंदोबस्त के संबंध में प्रस्तावित प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शेख राजा हुसैन खा ने स्पष्ट उद्घोष किया कि वह सरकारी मांग की स्थिरता तथा निश्चितता चाहते हैं कि आवश्यक रूप से बंगाल में प्रचलित पद्धति जैसी किसी स्थाई बंदोबस्त की पद्धति। उन्होंने बल देकर कहा कि सारे देश में जमीन की पट्टेदारी विविधता लिए हुए है, उसके अनुसार प्रत्येक स्थान पर स्थाई बंदोबस्त का रूप भी भिन्न भिन्न होगा।⁹³ हिंदू ने भी 13 सितंबर 1889 के अंक में इस बात से इनकार किया कि राष्ट्रवादियों की मांग जमींदारी पद्धति लागू करने की है। उसने दावा किया कि स्थाई बंदोबस्त का कोई भी समझदार समर्थक इस पद्धति का पक्षधर कतई नहीं है। 2 जनवरी 1891 के अंक में तो हिंदू इस बार और भी अधिक स्पष्ट तथा सबल प्रवक्ता था :

स्थाई बंदोबस्त की वकालत करने वाले आज के नेता जमींदारों के किसी बड़े वर्ग

की सृष्टि नहीं करना चाहते। वे तो धरती की उपज में सरकार के भाग को उन लोगों द्वारा हड़प लेना नहीं देखना चाहते जो न श्रम करते हैं और न कष्ट उठाते हैं। वे तो एक ऐसी पद्धति चाहते हैं जिसमें बंगाल की पद्धति के दोषों का अभाव हो और इस प्रकार किसान को सभी लाभ प्राप्त हों।

अपने समय के बंगाल के उच्चतम नेता मुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा संपादित 'बंगाली' पत्र ने न केवल जोतने वालों की सलाह से ही स्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया प्रत्युत उसने 1793 के बंदोबस्त की निंदा भी की। उसने 28 जून 1890 के अगले अंक में लिखा कि जमींदारी-पट्टेदारी का परिणाम यह हुआ कि जमींदारों और अमली खेतिहरों के बीच विचौलियों की एक लंबी शृंखला अस्तित्व में आ गई है। उसने घोषित किया :

हम स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, परंतु इस संबंध में हम यह कहना चाहते हैं कि देश के लिए यह परम सौभाग्य होता यदि यह सीधा किसानों से किया जाता। लार्ड कार्नवालिस द्वारा जमींदारों के परिप्रेष्य में इस विषय को देखना एक भारी और दुखद गलती है... देश के किसी भाग में भी नए सिरे से इस समय 1793 के बंदोबस्त के विस्तार की किसी भी योजना के विरुद्ध हमें अवश्य अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। धरती के बंदोबस्त का राज्य द्वारा अपनाया जाने वाला सही सिद्धांत यह होना चाहिए कि धरती को रखने वाले, जोतने वाले और सुधारने वाले श्रमिक को श्रम का फल पाने में किसी प्रकार की अमुविधा, परेशानी तथा बेचैनी न हो और उसे भूस्वामी के रूप में राज्य को केवल निश्चित और उचित किराए का ही भुगतान करना पड़े।⁹⁴

1893 के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्थाई बंदोबस्त के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप में कहा कि वह जमींदारों के लिए नहीं प्रत्युत किसानों के लिए ही बोल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव में सरकारी लगान के अथवा बंदोबस्त के कूतने के किसी उपाय का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसमें तो केवल भूमि लगान की मांग को नियमित और निश्चित करने का कहा गया है।⁹⁵ एक अन्य मराठी नेता वी० आर० नातू ने 1894 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इसी तथ्य को दोहराया तथा विदेशियों को यह भ्रान्त धारणा बनाने में बचने के लिए सावधान किया कि देश की बहुमह्य स्थाई बंदोबस्त के रूप में बंगाल में प्रचलित पद्धति चाहती है।⁹⁶ 1901 में लिखी अपनी पुस्तिका, दि इंडियन फॉर्मिस में पी० सी० राय ने बंगाल के जमींदारों की सभी प्रकार से भर्त्सना करने के उपरान्त मांग की कि अवश्यभावी स्थाई बंदोबस्त भविष्य में सीधे राज्य और खेतिहर के बीच होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के विचौलियों, जमींदारों, तान्त्रिकों तथा मालगुजारों को बीच में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने सरकार और जनता में अपील की कि वे दमन का ऐसा दुस्वक्र कदापि न चलने दें जो बेचाहे किसानों के लिए दबाव अथवा मृत्यु का फंदा बन जाए।⁹⁷ लार्ड कर्जन द्वारा 1902 के प्रस्ताव में प्रस्तुत भारतीयों की मांग का गलत विश्लेषण जी० सुब्रह्मण्य अय्यर की आंखों से छिप न सका। उन्होंने फरवरी 1892 में प्रकाशित अपने एक लेख, 'लार्ड कर्जन रिजाल्यूशन आन लैंड रेवेन्यू' में प्रखर स्वर में लिखा कि प्रस्ताव ने यह

अनुमान लगाने में गलती की है कि :

भूराजस्व नीति के आलोचक... स्थाई बंदोबस्त की मांग के रूप में जमींदारी पद्धति की भी मांग कर रहे हैं। श्री दत्त तथा दूसरों ने अपने को राज्य और किसान के बीच जमींदारों, बिचौलियों की सृष्टि की वकालत करने वाले समझे जाने के विरुद्ध बचाव की बार बार चेष्टा की है। उनकी योजना थी स्थाई बंदोबस्त सीधे सरकार और किसान के बीच हो... स्थाई बंदोबस्त के लिए जमींदार पद्धति कोई आवश्यक पक्ष नहीं और हमारा सुझाव है कि सीधा बंदोबस्त सरकार और किसानों के बीच होना चाहिए। दुख देनेवाला यह जमींदारों का तत्त्व तो वर्तमान विवेचन के अंतर्गत आता ही नहीं।⁹⁸

अंतिम रूप में हम यह दिखाना चाहेंगे कि आर० सी० दत्त इस तथ्य को निरंतर अपनी आंखों के सामने रखने वाले तथा भली प्रकार इसे समझने वाले किसी भी अन्य भारतीय नेता से किसी भी प्रकार पीछे नहीं थे कि बंगाल की जमींदाराना पट्टेदारी में तथा भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त में बड़ा भारी अंतर था। 1874 में ही एक युवक अधिकारी के रूप में उन्होंने बंगाल के स्थाई बंदोबस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कार्नवालिस की 'जबरदस्त गलती' कहा।⁹⁹ इसके साथ यह भी दर्शनीय है कि सरकारी अधिकारी के रूप में जमींदारों और उनके स्थाई बंदोबस्त के लिए स्थाई धृणा के कारण उन्हें जमींदारों से सदैव अपयश और तिरस्कार ही मिला।¹⁰⁰

इसमें संदेह नहीं कि समय के बीतने के साथ साथ बंगाल के स्थाई बंदोबस्त के प्रति उनकी अरुचि नम पड़ती गई और यहां तक कि बाद में एक प्रकार से मर्यादित प्रशंसा के रूप में बदल गई, फिर भी उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि देश के अन्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की चर्चा करना निरर्थक ही नहीं, गलत भी था। इस प्रकार 1897 में उन्होंने कहा कि यदि पन्ध्रके प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो उससे संबंधित सभी प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।¹⁰¹ 1899 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जम अधिवेशन में पी० सी० घोष ने 'देश के अन्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की मांग' महसूस की, दत्त महोदय ने इस मांग को आगे तो नहीं ही बढ़ाया साथ ही खुले तौर पर इस बात की घोषणा की कि वे भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न पद्धतियों, बंगाल की जमींदारी पद्धति, अवध की ताल्लुकेदारी पद्धति, उत्तर-पश्चिम की महलवाड़ी पद्धति, मध्य भारत की मालगुजारी पद्धति और दक्षिण भारत की रयतवाड़ी पद्धति के गुणों का विवेचन ही नहीं करना चाहते। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट भाषा में जोर देकर कहा : किसान किस पद्धति अथवा बंदोबस्त के अंतर्गत रह रहा है, इसकी चिंता करना बेकार है। उसे केवल अपनी भूमि की उपज का उचित भाग मिलने का विश्वास होना चाहिए... इसी में उसकी रक्षा है और इसी में देश की रक्षा है।¹⁰² लार्ड कर्जन को लिखे अपने चतुर्थ पत्र में उन्होंने इस मामले में अपनी स्थिति एकदम साफ कर दी :

देश के अन्यान्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की मांग मैं इस समय नहीं करता। आपको लिखे अपने प्रथम तीन पत्रों में मैंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। भारत के

प्रत्येक प्रांत में अपनी भूमि पद्धति है, जिसके अंतर्गत वहां के लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं।¹⁰⁷ श्री मन्महोदय। मैंने तो केवल यह मांग की है कि जिन भी पद्धति के अंतर्गत किसान रहता आ रहा है उसमें उसे संरक्षण प्रदान किया जाए।¹⁰⁸

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं ने और विशेषतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थाई बंदोबस्त की मांग करते समय सदैव भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त शब्द का तथा भूमि पर सरकारी मांग की स्थिरता और स्थायित्व शब्द का ही प्रयोग किया। इस रूप में उन्होंने इस सबंध में सदेह के लिए कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा कि उनकी वास्तविक इच्छा क्या थी।¹⁰⁹ इसी प्रकार अतीत में सरकारी क्षेत्रों में इस प्रश्न पर हुए विवाद के इतिहास में उनका व्यवहार 9 जुलाई 1862 और 24 मार्च 1865 में राज्य सचिव को संप्रेषित अपने पत्रों में उनके विशेष उल्लेख और इन संप्रेषणों को पूरे तौर पर लागू करने से भारतीयों के पूर्णतया संतुष्ट होने के उनके उद्धोष इस तथ्य को उजागर करते हैं कि स्थाई बंदोबस्त की मांग करते समय उनके मन में बंगाल की जमींदारी पद्धति बंदोबस्त नहीं थी। इसमें विपरीत वे धरती पर सरकारी मांग को स्थाई रूप से सीमित करना चाहते थे।¹¹⁰ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की विभिन्न लगान पद्धतियों के विकास का ऐतिहासिक विवरण करते हुए आर० सी० दत्त ने रैयतवाड़ी पद्धति में न केवल पट्टेदारी अथवा किसानों के स्वतंत्राधिकार में प्रत्युत भूमि के अस्थायी लगान निर्धारण के रूप में भी अनेक भयंकर दोष देखे क्योंकि रैयतवाड़ी पद्धति के व्यवस्थापक थामस मोनरो ने रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान के स्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था, दत्त महोदय ने उनकी पंशमा की।¹¹¹

स्थायी बंदोबस्त की मांग के अन्तर्गत राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण के सबंध में यदि अन्य प्रमाण अपेक्षित हैं तो वह समझौते और यथार्थवादिता की भावना में उनकी इस योजना की स्वीकृति और सहमति में देखे जा सकते हैं। जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था की मांग की गई कि लगान का एक स्थाई बंदोबस्त होगा जिसमें भूमि लगान को निरंतरता का रूप देने हुए निश्चित किया जाएगा परन्तु उसके मूल्यों में परिवर्तन की सीमा तक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।¹¹² इस सदर्भ में राष्ट्रवादी नेताओं ने लाड रिपन द्वारा सुझाए गए समझौते का समर्थन किया।¹¹³ अक्टूबर 1882 और मई 1883 के संप्रेषणों में यह कहा गया कि जब तक भूमि का कोई नया खेपण नहीं किया जाएगा तथा लगान को ऊंचा नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि (क) बात का क्षेत्र बढ़ नहीं जाता, (ख) कीमते बढ़ नहीं जाती, (ग) राज्य के लोग द्वारा किए गए सुधारों के फलस्वरूप उपज बढ़ नहीं जाती।¹¹⁴ इसके अतिरिक्त दस अप्रैल को कि लगान के स्थाई बंदोबस्त से उन क्षेत्रों में जहां बड़े बड़े जोतने योग्य भाग जाते नहीं गए हैं, जमीन के मालिकों को अनुपाजित आय की अपरिमित राशि मिलने योग्यी दूर करने के लिए भारतीय नेताओं ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए यह मांग की कि सरकार अपनी इस मांग को अपने ही मापदंड में पहले से ही पूर्णतया विवक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित रखे।¹¹⁵ इन सब बातों पर विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि सशोधित राष्ट्रवादी मांग के अंतर्गत भूमि लगान की राशि को मूल्यों के साथ जोड़ दिया जाए तो वास्तविक मांग से पट्टेदारी

पद्धति का नहीं प्रत्युत कर निर्धारण के मिद्वान का ही मंकेन मिलता है।

अब रोचक प्रश्न यह उठता है कि उपर्युक्त तथ्यों के मंदर्भ में जब राष्ट्रवादियों की स्थाई बंदोबस्त की माग के संबंध में स्थिति नितान्त स्पष्ट और निश्चित थी तब फिर यह मतिभ्रम कैसे उत्पन्न हो गया ? इसके उत्तर में हमारे हम कथन में कुछ हद तक सत्य है कि कम से कम आधिकारिक रूप से तो सही, यह घण्टा जानबूझकर पैदा किया गया था ताकि भूमि लगान पद्धति पर राष्ट्रवादियों के प्रहार का कोई श्रेय न मिल सके। राष्ट्रवादियों की स्थिति को जानबूझकर गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया ताकि भारतीयों द्वारा उठाए गए प्रमुख विषयों पर वे विशेषतया भूमि पर भारी लगान में इंग्लैंड और भारत की जनता का ध्यान हटाया जा सके। यह प्रसंगीकरण नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे एक भ्रष्ट तथा पाखण्डपूर्ण प्रवृत्ति काम कर रही थी जिसके अंतर्गत इंग्लैंड का संपूर्ण व्यवस्था, उपाधिकारी महानुभाव, वशानुशा लांडे, आर्याग्न काश्तकार की सहायता तथा रक्षा के किसी भी प्रयास का विरोध करने वाले तथा अपनी नीति प्रतिक्रिया प्रकट करने वाले आयरलैंड के बड़े बड़े भूमंडला के स्वामी, मालिक, टारी पार्टी के पथप्रदर्शक, इंग्लैंड में भूमि के राष्ट्रीयकरण के विरोधी तथा विभव में सर्वोच्च वेतनभोगी मिडिल क्लास के सदस्य आदि के सब भारतीय विमानों के उद्धारक बन गए और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं पर जमींदारों के पिछड़े होने का आरोप लगाने लगे। वस्तुतः स्थिति की यह विवक्षा भारतीयों में छिपी नहीं थी। उदाहरणार्थ वर्जन के इस दृढ़ मन का कि स्थाई बंदोबस्त किसी भी मध्य देश में संभव नहीं होता है, खंडन करने हुए आर० सी० दत्त ने 1902 में टिपणी की। इंग्लैंड के वे जमींदार जो 1798 के पिट्स ऐक्ट के अंतर्गत हुए स्थाई बंदोबस्त के लाभ का उपभाग कर रहे हैं और उन्हें गौरव दे रहे हैं, भारत आने पर यह शिक्षा ग्रहण करने हैं कि जो उनके लिए अच्छा है वह भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है।¹¹⁰ ए

हा, यह अवश्य है कि यह व्यापक गलतफहमी केवल तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का ही परिणाम नहीं थी। वस्तुतः कुछ भारतीय नेताओं की भूमि नीति के कुछ पक्षों और लगान के स्थाई बंदोबस्त पर तर्क प्रस्तुत करने में उनका ढंग कुछ इस प्रकार का अवश्य था कि उससे कभी कभार इस ओर ध्यान देने वाले का भ्रान्ति अवश्य हो सकती थी। प्रथम, कर्मा कभी भारतीय नेताओं ने और विशेषतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ववर्ती कुछ वर्षों में अपनी माग प्रस्तुत करने हुए केवल 'स्थाई बंदोबस्त' शब्दों का प्रयोग किया। वे 'भूमि लगान' शब्द जोड़ना भूल गए।¹¹¹ वस्तुतः यह शेष भाषा संबंधी भूल अथवा आलस्य के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी और जिसने भी कांग्रेस के पूर्ववर्ती प्रस्तावों को और अनेकानेक राष्ट्रवादियों के इस विषय पर लेखों और जनभाषणों को, जिनमें से कुछ को हम पहले ही ऊपर उद्धृत कर चुके हैं, ध्यान से पढ़ा है, वह इन शब्दों के छूट जाने में भटक नहीं सकता।

द्वितीय, यह कदाचित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, भूमि लगान के स्थाई बंदोबस्त के बहुत से समर्थकों ने विशेषतः आर० सी० दत्त ने बंगाल के किसानों की स्थिति का रंगीन चित्र खींचा और बंगाल को ही स्थाई बंदोबस्त की व्यावहारिक उपलब्धियों के आदर्श

के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बंगाल के किसानों को अकाल से विशेष कष्ट नहीं पहुँचा; इसका कारण उनके अनुसार यह था कि स्थाई बंदोबस्त ने उसे इस योग्य बना दिया है कि वह अकालों के विरुद्ध उच्च स्तर पर आर्थिक प्रतिरोध अपना सके। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का किसान देश के अन्य भाग के किसानों की अपेक्षा भौतिक साधनों की दृष्टि से अधिक संपन्न है।¹¹⁵ इस भावना को कभी कभी आर० सी० दत्त महोदय बहुत ही अतिरंजित रूप दे देते थे और इस सीमा तक कह डालते थे कि स्थाई बंदोबस्त ने बंगाल की जनता को समृद्ध और सुखी बना दिया है।¹¹³ दत्त बार बार यह भी घोषित करते रहे कि बंगाल के जमींदार उचित तथा न्यायमंगल किराया वसूल करते हैं और इस किराए की रकम कुल उपज के 1/5 भाग से अधिक नहीं होती।¹¹⁴ बंगाल के तथा देश के अन्यान्य भागों के बहुत सारे और नेता भी थे जिन्होंने बंगाल के किसानों को जमींदारी की कृपा का पात्र बनाने वाले बंगाल के स्थाई बंदोबस्त की आलोचना की। उदाहरणार्थ पी० सी० राय ने बंगाल बंदोबस्त की निम्न शब्दों में निंदा की :

जनता के एक अत्यंत सीमित और निपट स्वार्थी वर्ग जो जमींदार वर्ग कहलाता है के सिवाय इस पद्धति ने न तो राज्य को और न ही किसानों को कोई लाभ पहुंचाया है।... बंगाल के किसान अत्यंत शोचनीय अवस्था में हैं और भारत के किसी भी प्रदेश के कृषि क्षेत्रों से बेहतर अवस्था में नहीं है।... यदि बंगाल का किसान थोड़ा बहुत खाता-पीता और समृद्ध दिखाई देता है तो इसमें जमींदारों का कोई भी सहयोग नहीं, यह तो उसका अपना श्रम है। बंगाल का औसत जमींदार विशेषतः अपने कार्य से अनुपस्थित रहने वाला, उतना ही क्रूर और अत्याचारी है जितने कि बनिया, साहूकार तथा महाजन आदि विभिन्न नामों वाले किसान के शत्रु हृदयहीन हैं।¹¹⁵

यहां यह उल्लेखनीय है कि आर० सी० दत्त ने स्वयं कभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि 1793 के स्थाई बंदोबस्त ने बंगाल के किसान को समृद्ध बनाया है। उन्होंने तो सदैव उसके लाभों को 1859 और 1885 के पट्टेदारी कानूनों के लाभों से जोड़ने की ओर ध्यान दिया। उनकी दृष्टि में 1793 का विनियम तथा 1859 और 1885 के कानून परस्पर सहयोगी हो नहीं प्रत्युत एक ही पहलू के दो पक्ष थे। कानूनों के इन दोनों वर्गों के सम्मिलित प्रवर्तन से ही बंगाल के किसान की स्थिति सुधर सकी थी तथा भारत के अन्य प्रांतों के किसानों की अपेक्षा अच्छी बन सकी थी। जिम तरह उन्होंने 1793 के स्थाई बंदोबस्त की प्रशंसा की उमी तरह, उमी ऊँचे स्वर में, उम ढग से और उसी उत्साह से उन्होंने 1859 और 1885 के अधिनियमों का स्वागत किया।¹¹⁶ जब कर्जन ने 1902 के प्रस्ताव में अनुदारतापूर्वक उनपर तथा अन्य नेताओं पर अपने काश्तकारों पर जमींदारी की मांग के सीमा निर्धारण की आवश्यकता पर नमुचित ध्यान न देने का आरोप लगाया¹¹⁷, तो दत्त को आघात पहुँचा और उन्होंने मृदुता के साथ कर्जन को उत्तर दिया कि उन्होंने सदैव इसे अभिस्वीकार ही नहीं किया कि 'बंगाल के रेंट ऐक्ट' ने स्थाई बंदोबस्त द्वारा किए अच्छे कार्य को पूर्णता तक पहुँचाया है प्रत्युत 1885 के 'रेट

ऐक्य' की रूपरेखा तैयार करने में भी पर्याप्त योगदान दिया है।¹¹⁸ दत्त को इस समय वास्तव में यह भी कहना चाहिए था कि उन्होंने 1874 में ही जमींदारों और किसानों के बीच स्थाई बंदोबस्त के लिए दबाव डाला था, उन्हें इस बात की भी वकालत करनी चाहिए थी कि विस्तृत सर्वेक्षण के उत्तम संग्रह प्राप्त किए जाने वाले किराए की दर सावधानी से निर्दिष्ट कर इसे सदा के लिए स्थिर घोषित कर दिया जाए।¹¹⁹

तृतीय, अधिकांश भारतीय नेताओं ने जमींदारी की पट्टेदारी के उन्मूलन की मांग नहीं की। उनकी दृष्टि में जहां तक किसानों के हितों का संबंध था, जमींदारी पट्टेदारी और रयतवाड़ी पट्टेदारी के बीच कोई अंतर नहीं था। उनके इस उपेक्षा भाव का अर्थ जमींदारी के प्रति उनका अनुराग कदापि नहीं था अपितु उन्हें यही विश्वास था कि जहां तक जमींदारी प्रथा के दोषों का संबंध था, दोनों वास्तव में जमींदारी पद्धति के दो भिन्न भिन्न रूप थे — एक निजी जमींदारी का रूप था और दूसरा राजकीय जमींदारी का। जहां प्रथम में किराए का निर्धारण निजी स्वामी करते थे वहां दूसरे में सरकार आगे बढ़कर इस काम को सम्पन्न करती थी। व्यवहार में किसान के लिए इन दोनों में चुनाव की कोई बात ही नहीं थी।¹²⁰ आर० सी० दत्त का इस विषय में कथन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रयतवाड़ी पद्धति का संगठन किसान को जमींदारी के चंगुल से बचाने के लिए नहीं, अपितु विधायकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को हथियाने और अपने राजस्व को अधिकतम उद्धान ही दृष्टि में ही किया है।¹²¹ कंपनी जमींदारों के लाभों के प्रति ईर्ष्यान्वित रही है और किसानों के हितों के प्रति उत्सुक नहीं रही। इस पद्धति के अनर्गत कंपनी का किसानों पर इतना अधिक कष्ट नियंत्रण हो गया है जितना किसी दामोदर स्वामी का अपने दामोदर पर होता है, जो उनकी जीवन की आवश्यकता के लिए अपेक्षित में अनिश्चित और सब कुछ छीन लेता है।¹²² कट्टर नेताओं ने तो यह भी कहा कि जमींदारी प्रथा रयतवाड़ी प्रथा से दो बारों में तो बेहतर ही है। प्रथम, जहां सरकार किसानों का धरती के अनुचित लगान बढ़ाने तथा अन्य इस प्रकार के दूसरे दबावों से बचाने के लिए जमींदार के विरुद्ध कानून बना सकती है और बनाती है, वहां भूराजस्व को बढ़ाने की अपनी शक्तियों पर, तथा अन्य कई प्रकार से किसान के साथ संबंधों को कटु बनाने की प्रक्रियाओं पर कानूनी अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने से इनकार करती है। यदि एक बार लगान का स्थाई बंदोबस्त स्वीकार कर लिया जाए तो जमींदारों अथवा अन्य बड़े बड़े मालिकों के किराया बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाकर किसानों तक इसके लाभों का विस्तार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह कार्य तो सरकार अब भी सम्मानपूर्वक कर सकती है। जमींदारों को किराया बढ़ाने की अनुमति देने, प्रोत्साहन देने यहां तक कि कभी कभी विवश करने की वर्तमान नीति को छोड़कर उसके स्थान पर सरकार एक आदर्श प्रस्तुत कर सकती है।¹²³ कुछ भारतीय नेताओं के अनुसार रयतवाड़ी पट्टेदारी से जमींदारी को बेहतर बनाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष निकासी का था। उनका तर्क था कि जमींदारी पद्धति में यदि किसान को ऊंचा किराया देना पड़ता है तो इसमें एक अच्छाई तो है कि यह किराया भारतीय मालिक को जाता है जो उस धन को भारत में ही खर्च करता है। इसके विपरीत विदेशी बरिश्च

वाली सरकार को दिए जाने वाले किराए की देश के बाहर निकासी हो जाती है।¹²⁴

चतुर्थ, कुछ गलतफहमी इस तथ्य से भी उत्पन्न हुई कि कुछ भारतीय नेता इस बात से व्याकुल थे कि जिस ढंग से अपनी प्रतिभा के उपयोग के अभाव में भारतीय लोगो का सारा सामाजिक जीवन समान रूप में निम्न स्तर पर पहुँच गया था, उस समय इन नेताओं ने उत्सुकता के साथ यह अनुभव किया कि जमींदार उच्च वर्ग से संबंध रखता है जिसे सामाजिक स्तर और बौद्धिक उत्कर्ष को किसी रूप में बनाए रखने में सफलता मिली है अतः वह संपूर्ण भारतीय जनता को अधिकारपूर्ण तथा गवार्ह अस्तित्व में पहुँचाने से बचाने में सहायक और उद्धारक मित्र हो सकता है।¹²⁵ इसके अतिरिक्त भारतीय नेताओं के एक वर्ग का यह भी विश्वास था कि लोगो को नेताओं और विचारियों की आवश्यकता है और जमींदार अच्छे विचारों का मित्र हो सकते हैं तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक नेता हैं।¹²⁶ इस संबंध में अमृत बाजार पत्रिका द्वारा 20 जनवरी 1871 के अंक में 1793 के स्थाई वदोबस्त की रक्षा में प्रस्तुत लक्ष्य संपादकीय विद्वेषण का अध्ययन रोचक होगा। यह उद्धरण दर्शनीय है क्योंकि इसमें बंगाल के नेताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग के और महान भारत के ही राष्ट्रवादी नेताओं की वैचारिक प्रक्रिया की सूक्ष्म दृष्टि देखने को मिलती है। यह बात और है कि इस उद्धरण का संबंध अध्ययन-काल से दस वर्ष पूर्व में है, फिर भी यह अवतरण ध्यान देने योग्य है।

यह सर्वविदित और विश्वमान्य सत्य है कि वर्ग के रूप में जमींदार देशवासियों के सद्भावहार के पात्र नहीं। उनकी एक बहन बड़ी मर्यादा अनुत्पादितता निराम्यो, दुर्बलो, अज्ञानियो, शोषको और स्वाधिया की है। हम यह भी भली प्रकार जानते हैं कि वे ओद्योग और धर्तनापूर्ण वार्थों में प्रतिवर्ष बृद्धि धनराशि, जिसपर वास्तव में किसानों का ही नैतिक अधिकार है, हस्तगत है। हम यह भी जानते हैं कि इन जमींदारों में कुछ के विनाश से ही लाभा किसानों का अर्थदायता के स्थान से मुक्ति मिलेगी। हम यह सब जानते हैं और जमींदार की अपेक्षा किसानों से ही अधिक प्यार और उसका ही अधिक आदर करते हैं। उनके पर भी हम जमींदारों का समर्थन करते हैं। यह हमारी जरूर आवश्यकता है। निस्संदेह यह कुर है, परंतु है हमारी आवश्यकता ही।

संपादकीय में आगे कहा गया है कि यह आवश्यकता का रूप में है, प्रथम, जनता के आंदोलन के लिए भारतीयों का पैसा चाहिए और वह पैसा केवल जमींदारों के पास है, व्यापारी तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। मद्रास में कहा जमींदार नहीं हैं, धन और दानियों के अभाव में वहाँ जन आंदोलनों को गहरा धक्का लगा है। द्वितीय, अंगरेजों ने पहले ही संपत्ति उत्पादन के सभी साधनों, व्यापार, उद्योग तथा लाभ नियुक्तियों को हथिया रखा है। भूमि ही बची हुई है। यदि जमींदारों को हटा दिया जाए तो संपदा के इस स्रोत पर भी अंगरेज अधिकार जमा लेंगे और इससे किसानों को लाभ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः जमींदारों को ही चलाने देना चाहिए जो किसानों के श्रम के फल को हथियाने के कारण बुरे अवस्था हैं परंतु यूरोपीयों से अधिक बुरे तो नहीं। संपादकीय ने इस विषय का विस्तृत विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

जमींदारों की कीमत पर किसानों की समृद्धि ठीक उसी प्रकार सदैव उचित है जिस प्रकार किसानों और जमींदारों की कीमत पर यूरोपीयों की समृद्धि अनुचित परन्तु हम इस बात का कोई भरोसा नहीं कि सरकार किसानों के हित में ही बंदोबस्त को नष्ट करना चाहती है। इसके विपरीत हमें तो यह आशंका है कि धरती पर बढ़ाया हुआ लगान हमारे लाभ के लिए नहीं प्रत्युत अंगरेज जाति के लाभ पर ही खर्च होगा।

समाश्रयी ने इस माहमिअ घोषणा के साथ यह निष्कर्ष निकाला 'पहले हमें अपने देश के वित्तों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और हम दिन और दिमाग से बंदोबस्त का विरोध करेंगे परन्तु इस समय तो हम उसका समर्थन करने का ही विवश हैं।'

उपर्युक्त सभी तथ्यों से यह अत्यंत सार्थक सिद्ध होता है कि बहुत सारे भारतीय नेता जमींदारी और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के प्रश्न की उपेक्षा करना चाहते थे परन्तु इन पक्षों से यह स्पष्ट धुरनाया नहीं जा सकता कि रथार्थ बंदोबस्त की मांग करते समय भारतीय नेता जमींदारी पट्टेदारी के नाश करने का पड़्यत्र नहीं कर रहे थे।

संदर्भ

1. दत्त, स्पीकेर II पृ. 30
2. दत्त, स्पीकेर II पृ. 37
3. 'बल (बल)' उपर्युक्त मूल्य तथा श्रमिका व वेतन और लाभ की औसत दर पर कृषि में वित्त-व्यय (बल) का लाभ आदि की मापन के उपरान्त उत्पादन के अनमानित व्यय का अंतर निबल (नर) प्राप्त प्रयोज्यता का ही
4. दत्त, स्पीकेर II पृ. 35 इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV, पृ. 217
5. इंपीरियल गजटियर आफ इंडिया (1905) खंड IV, पृ. 222-3
6. वित्त मंत्रालय कोमिशन द्वारा 1884 में सामान्य रूप से सरकार द्वारा करबुद्धि के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत का प्रस्तुत सक्षप इस प्रकार से है पहला, मूल्यांकन करते समय जमींदार अथवा किराएदार द्वारा किए गए सभी प्रकार के सुधारों पर छूट दी जाती थी दूसरा, पहले से ही वर्गीकृत धरती के पुन वर्गीकरण की अथवा पुन मूल्यांकन की अनुमति किसी भी रूप में नहीं दी जाती थी तीसरा, चालू मूल्यों को ही सशोधन का आधार माना जाता था तथा किसी प्रकार का परिवर्तन केवल सावधानी से निर्धारित दो या तीन आधारों पर ही किया जाता था ये आधार थे, भारत सरकार जात को स्थिर कर सकती थी, नियंत्रित कर सकती थी तथा उसमें बढ़ोतरी कर सकती थी बुद्धि का आधार राज्य द्वारा किए गए सुधारों से उपज में बुद्धि और मूल्यों में बुद्धि थी वित्त सदस्य (फाइनेंस मेबर) ने इस बात का संकेत दिया कि नियम कठोर नहीं थे और उनकी प्रयोगशीलता का विचार प्रत्येक मामले में पृथक पृथक रूप से ही सावधानी के साथ लिया जाता था (फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1884-5, कड़िका 75) कुछ का कहना था कि वास्तविक कर निर्धारण तो और भी अधिक व्यावहारिक था देखिए, बी०एच० बोडेन वावेस ;

- 'ए शाट एमाउट आफ दि लैंड रैवेन्यू ऐंड इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया' (आक्सफोर्ड, 1894), पृ० 48
- 7 इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV, पृ० 201
- 8 1856-7 और 1901-2 की अवधि में भूराजस्व संग्रहण 58.6 प्रतिशत बढ़ गया दूसरी सगणना 1888-9 और 1905-6 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए ग्रंथों से की गई है
- 9 इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1909) खंड IV पृ० 239, और देंट्रिग, स्ट्रैची - इंडिया (1903) पृ० 125
- 10 मनकर पूर्वोद्धृत, में इन लेखों के साथ गनाडे का नाम जुड़ा हुआ है, पृ० 213-6
- 11 जे० पी० एस० एस०, जलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 2 और देखिए, पृ० 19, 21
- 12 वही अक्टू० 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 53, और देखिए वही, पृ० 55, 57-8 'दि इन्डियन ऐग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ बिल', वही, अक्टूबर 1879 (खंड I, स० 2), 'दि ला आफ रैंड सल इन ब्रिटिश इंडिया', वही अक्टूबर 1880 (खंड II स० 2), 'सेटुल प्राविमेज लैंड रैवेन्यू ऐंड टैनेमी बिल्स', वही, अप्रैल 1881 (खंड II, स० 4), 'गैमिनिपेशन आफ सॉर्स इन एसिया, वही, अक्टूबर 1882 (खंड V, स० 2), 'प्रिण्पियल लैंड नॉजिस्वेशन ऐंड दि बगान टैनेसी बिल, वही, अक्टूबर 1883 (खंड VI, स० 2) 'प्रिण्पियल रिफार्म्स इन दि रिमैग्नेट आफ लैंड एससमेट्स', वही, जनवरी 1884 (खंड VI, स० 3) और 'प्राइमरी एंड वॉरिन्स अगस्ट दि न्यू रिजार्चर ऑ दि लैंड एससमेट पालिसी वही, अप्रैल 1884 (खंड VI सख्या 4)
- 13 प्रस्ताव III
- 14 दन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन की भूराजस्व नीति पर लगाए गए आगलों के लिए विशेष रूप से दर्शाए गए हैं पृ० 79, 182-90, 194, 231-245, 362, 372-3, और 'आपन नेटस ऑ लाई रजेंन' (गाड रजेंन का नाम खुल पत्र 1900 में निश्चित) (इसे आगे मद्रभ के लिए 'आपन नेटस से संकेतिन किया जाएगा) परबर्ती कान के लिए विशेष रूप से देखिए, दन इन्डियन एंड इंडिया' पृ० 134, सी० पी० ए०, पृ० 481-90, सी० पी० ए०, पृ० 27, 40-159-60, आपन नेटस, स्पांचेज II पृ० 30, 38, ई एच II, पृ० XIII फॉर्मिस एंड लैंड एससमेट इन इंडिया (दन 1900, पृ० XIX-XII)
- 15 जागी पूर्वोद्धृत में पुन मुद्रित, पृ० 392-574 उन्होंने इसी प्रकार के विचार 1884 में (पृ० 696) तथा 1890 में अपने निबंध, 'त्रि दकोनामिक सिन्थ्युएशन इन इंडिया एग्रीकल्चर' (देखिए विशेषतया पृ० 672, 886-904-05) में भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए थे
- 16 देखिए, नर्टमन एंड कंपनी (मद्रास 1902) द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक 'लैंड प्राब्लम्स इन इंडिया' में एक लेख 'दि बावे लैंड रैवेन्यू सिस्टम', मई 1900 में बंबई में हुए प्रांतीय सम्मेलन में दिए गए उनके अध्यक्षीय भाषण के उद्धरण, जो बंगाली के 22 मई 1900 के ग्रंथ में पुन मुद्रित हुए थे और डिगबी पूर्वोद्धृत, पृ० 624-8 और रिप० आई० एन० सी०—1902, पृ० 81 एवं आगे
- 17 पूना सार्वजनिक सभा के सचिव का पत्र, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1879 (खंड I, सख्या 3), पृ० 37-43, बाचा, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 22, सी० पी० ए०, पृ० 561, 574-5, राय, पावर्टी पृ० 180-1 इंडियन फॉर्मिस पृ० 50, पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 607, जी बेंकटरमन, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 131, ए० नदी इंडियन पार्लियामेंट, पृ० 130, जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खंड III, प्रश्न 18716, रिप० आई० एन० सी०—1901, पृ० 87,

बारहवें बंबई प्रांतीय सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव, मराठा, 16 नव० 1902; गोखले, स्पीचेज, पृ० 80-82, 110-2, 1017; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 743, 757, एल० ए० जी० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1903, पृ० 52, आर० एन० मधोलकर, दि इकोनामिक कडीशन इन इंडिया, एच० आर०, अगस्त 1904 समाचारपत्रों में उदाहरण रूप में देखिए, इंदु प्रकाश, 25 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब०, 30 अक्टूबर 1880), मराठा, 31 जुलाई 1881, 1 जनवरी 1882; ए० बी० पी०, 5 अक्टूबर 1882, 18 मार्च 1901, हिंदू, 18 जनवरी, 5 सितंबर 1884, 4 जून 1900; इंडियन स्पेक्टेटर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब०, 13 जनवरी 1883), (इंडियन स्पेक्टेटर ने अपने 8 मार्च 1884 के प्रक में टिप्पणी की कि भूमि पुत्रों के साथ ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने सभी प्रकार के संबंधों में लुटेरों की भूमिका ही निभाई है); स्वदेशमित्र, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 1885), स्वदेशमित्र, 13 नवंबर (वही, 30 नवंबर 1889), हिंदुस्तान, 3 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 10 मार्च 1891); बंगाली, 13 फरवरी 1892; स्वदेशमित्र, 17 मार्च, 28 अप्रैल, 12 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 15 दिस० 1900 क्रमशः); केमरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 29 दिस० 1900), न्यू इंडिया, 19 मई 1902

18. उदाहरण के लिए देखिए, दत्त, ओपेन नेटर्स, पृ० 71, 74-5
19. उदाहरण के लिए देखिए, पूना सार्वजनिक सभा के सचिव का एक पत्र, जे० पी० एम० एम०, जनवरी 1881 (खंड III, स० 1) पृ० 37-9, रानाडे, 'एंग्लो-इंडियन प्रॉब्लम ऐंड इट्स सोल्यूशन', जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 5-9; 'लैंड ला रिकॉम एंड एंग्लो-इंडियन बैंक्स', जे० पी० एम० एम० अक्टूबर 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 37, 54, 16 मई 1880 को पूना सार्वजनिक सभा द्वारा आयोजित पूना की एक सार्वजनिक सभा में स्वीकृत याचिका, जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1880 (खंड III, स० 1) पृ० 5; 'एंग्लो फार स्पानिफिकन आफ इंडिया', जे० पी० एम० एम०, जनवरी 1885 (खंड VII स० 3) पृ० 7-15, तैलंग, स्पीचेज, पृ० 16, आई० एन० सी०-1896, 1897, 1901, 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XII, IX, VIII(a), III, III, III, राय, पावर्टी, पृ० 180-1, 184-9, जोशी : पूर्वोद्धृत पृ० 334, 392, 536 (विशेष रूप से देखिए, पृ० 452-3, 457-61, 466-81, 494-5, 508-10) 890-902, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 450, ए० नदी. इंडियन पोलिटिक्स पृ० 130-3, पी० पी० पिल्लई, रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 99; तिलक, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 132, दत्त, स्पीचेज I पृ० 21, 40, 180, सी० पी० ए०, पृ० 480-9, ओपेन नेटर्स, पृ० 18-9 तथा पांच पत्र, स्पीचेज II पृ० 30, 57, 179-80; ई० एच० I पृ० IX, पाद टिप्पणी 370, ई० एच० II पृ० XIII, 483, 490-1, 496-7, 535; दसवें बंबई प्रांतीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव (प्रस्तोता : तिलक), मराठा, 27 मई 1900, जी० के० पारिख, 10वें बंबई प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, बंगाली, 22 मई 1900 (नया डिग्री, पूर्वोद्धृत, पृ० 624-8); प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर्स आफ बांबे, 1901 खंड XXXIX पृ० 22-36; 'लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया', पृ० 124-34, रिप० आई० एन० सी० 1903, पृ० 59, बी० आर० नाबियार, रिप० आई० एन० सी०-1900 पृ० 101; बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 561, 564; स्पीचेज, पृ० 436; गोखले, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर्स आफ बाबा, 1900, खंड XXXVIII, वही, पृ० 92-3, वही, 1901, खंड XXXIX, पृ० 244; स्पीचेज, पृ० 80-2, 110-12, आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 86-7;

- जी० एस० अय्यर, वही, पृ० 93, ई ए, पृ० 48, डी० ए० खरे का तेरहवें बर्बर प्रांतीय सम्मेलन में अष्टाक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 1903, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 757-9 समाचारपत्रों के लिए देखिए, उदाहरणार्थ, इंदु प्रकाश, 25 अक्तू० और 29 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 30 अक्तूबर और 4 दिस० 1880 क्रमशः) मराठा, 1 जनवरी 1882, इंडियन स्पेक्टेटर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब०, 13 जनवरी 1883), हिंदू, 18 जनवरी, 7 फरवरी, 5 सितंबर 1884, 4 जून 1900, स्वदेशमित्र, 27 जुलाई आर० एन० पी० एम०, अगस्त 1885), 13 नव० (वही, 30 नव० 1889), स्वदेशमित्र, 1 मई, शांतिगंगा, 15 मई (वही, 31 मई 1896); तमिल प्रतिनिधि, 10 अक्तू० (वही, 31 अक्तू० 1900), स्वदेशमित्र, 12 दिस० (वही, 15 दिस० 1900), 4 अगस्त के पैमा अखबार में मद्रास आलम 11 पत्र (आर० एन० पी० पी०, 18 अगस्त 1900), कसरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 29 दिस० 1900), 12 मार्च (वही, 16 मार्च 1901); ए० बी० पी०, 17, 23 जनवरी, 18 मार्च 1901, न्यू इंडिया, 19 मई 1902
20. रानाडे, जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 11 और अक्तूबर 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 55, ए० एन० एफ० स्पेक्टेटर आफ इंडिया जनवरी 1882 (खंड VII, स० 3), पृ० 16, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 890-1, दन सी० पी० ए०, पृ० 185, कैमिल इन इंडिया, पृ० XI ओपेन स्टेट्स, पृ० 17-39 पाद टिप्पणी 51 स्पेक्टेटर II पृ० 73 179-80 ई० एच० II पृ० XIII, 94, 306, 320 459, 469, 702, ए० एम० अय्यर, ई० ए०, पृ० 47 तथा आगे
21. दत्त, स्पीचेज II पृ० 57, 74, 177, 202 ई० एच० I पृ० X 1879-80, ए० एन० II पृ० 335, 492, 499, जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 50-1
22. जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 9 और देखा, स्पेक्टेटर आफ इंडिया सवकमेटी आफ पूना सार्वजनिक सभा पूना 1873 पृ० 32, 33 फिलिप फॉर्सेट्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 1875 खंड XXXVIII पृ० 21 ए० ए०, इंडियन पार्लियामेंट, पृ० 111, 132, जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 376, 479-80, 481, 491-900, अय्यर, पार्लियामेंट आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 1900, खंड XXXVIII, पृ० 94, जी० ए० पारिख, लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया, पृ० 147 दन, ई० एच० II, पृ० 493 पाद टिप्पणी, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 50, 79-80 और देखा ए० पी० पी०, 18 अक्तूबर 1900 और 12 फरवरी 1902; पी० पी० गिल्बर्ट, रिप० आई० एन० मा० 1903 पृ० 60 रानाडे ने भी बकालत की कि राजस्व अधिकारियों को इस नथ्य को ध्यान में रखते हुए तब तक बोरी बहुत छुट देने हुए चलना चाहिए कि धरती को निरंतर बढ़ती हुई आबादी का पालन पोषण करना पड़ता है जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 3
23. पूना सार्वजनिक सभा के सचिव का पत्र; जे० पी० एम० एम०, जनवरी 1879 (खंड I, स० 3), पृ० 37; रानाडे, जे० पी० एम० एम०, अक्तूबर 1881 (खंड IV, स० 2), पृ० 54, 56-7, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 347, 869, 904-05, डी० ए० खरे, रिप० आई० एन० सी० 1893, पृ० 117; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 625-6; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 568
24. रानाडे, जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 7-8, राय, पावर्टी, पृ० 186-7; जी० के० पारिख, लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया, पृ० 124-34, तथा डिग्वी पूर्वोद्धृत, में उद्धृत, पृ० 625; दत्त, स्पीचेज I, पृ० 22; 'सर फिलिप फॉर्सेट्स' मिनट्स आन दि सम्बेन्ट आफ ए

परमानेंट सेटलमेंट फार बंगाल, बिहार ऐंड उड़ीसा विद ए प्रिफेस बाइ आर० सी० दत्त, (कलकत्ता 1901) पृ० XII, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 758, 760-1. पी० पी० पिल्लई, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 61

- 25 दत्त, स्पीचेज I, पृ० 22, स्पीचेज II, पृ० 170, ए० बी० पी०, 18 अक्टू० 1900 और 12 फरवरी 1902
- 26 तैलंग, स्पीचेज, पृ० 17, जोशी, पूर्वाद्धृत, पृ० 654, 658, 900, जी० के० पारिख, डिगबी, पूर्वाद्धृत, पृ० 627 उद्धृत, जोर रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 82, गोखले, प्रोसीडिंस आफ दि कोसिल आफ दि गवर्नर आफ बांग 1901, खंड XXXIX, पृ० 244 और देखिए, बी० ए० श्वर बा तैलंग बर्बई प्रांतीय सम्मेलन म अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 1903
- 27 तैलंग बर्बई प्रांतीय सम्मेलन म डॉ० ए० ग्रे ने अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 1903.
- 28 माई 11, स्पीचेज, पृ० 511 पूना मार्गदर्शक समा के मंचिख रे पत्र जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1879 (खंड I, म० 3) और जुलाई 1886 (खंड IX, म० 1) पृ० 2-5, रानाडे, जे० ए० एन० एम० जलाई 1879 (खंड II, म० 1, पृ० 3, जनवरी 1884 (खंड VI, म० 3) पृ० 4, 9, तैलंग, स्पीचेज पृ० 10-1, जोशी, पूर्वाद्धृत, पृ० 497, 902-04; मराठा, 25 जुलाई 1884 पत्रा पाठ पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 117; जी० वेंकटरमन, रिप० माइ० एन० सी० 1895, पृ० 132, पाठ मेहता, स्पीचेज, पृ० 450, जी० के० पारिख, डिगबी, पूर्वाद्धृत, पृ० 627 पर, एन० एम० नैरिया, रिप० आई० एन० सी० 1903, पृ० 64, दत्त, इ० ए० II पृ० 457, 461
- 29 पूना मार्गदर्शक समा के मंचिख रे पत्र, जे० पी० एम० एन०, जनवरी 1879 (खंड I, म० 3) पृ० 3, रानाडे, मा० ए० एन० एम०, जलाई 1879 (खंड II, म० 1), पृ० 3, जनवरी 1884 (खंड VI, म० 3), पृ० 5 आशा पूर्वाद्धृत, पृ० 417, आर० एन० मधालकर, रिप० आई० एन० सी० 190, पृ० 48-9 पी० मन्ना पूर्वाद्धृत, पृ० 606, दन ओपेन लेटर्स, पृ० 47, 52, स्पीचेज II पृ० 39 186, 187, ई० एन० सी० II पृ० IX-XI, 152, 169, 171, 370, पाद-टिप्पणा 350, 382 ई० एन० II, पृ० XII-XIII 335, 491-2, 499, 505, 515-6, जी० के० पारिख डिगबी, पूर्वाद्धृत पृ० 626-8 पर, रिप० आई० एन० सी० 1903, पृ० 56-7, वाचा, सी० पा० ए०, पृ० 564 मन्ना एन० मधालकर, 'दि इकोनामिक कंडीशन आफ इंडिया' एच० आर० जगन्नाथ 1904, पृ० 259
- 30 रानाडे, जे० पी० एम० एम०, जलाई 1879 (खंड II, म० 1) पृ० 9; नेटिव ओपीनियन, 7 नवंबर (आर० एन० पी० बब०, 13 नवंबर 1880), गुजोध पत्रिका, 14 नव०, खानदेश वैभव, 12 नव०, लार्मिज, 14 नव० (वही, 20 नव० 1880); ज्ञान प्रकाश, 13 दिस० (वही, 18 दिस० 1880), भूगोदय, 20 दिस०, कल्पतरु, 19 दिस० (वही, 25 दिसंबर 1880); नव विभाकर, 6 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 11 नव० 1882), इंडियन स्पेक्टेटर, 7 जन० (आर० एन० पी० बब०, 13 जन० 1881); अखबार आम 12 दिस० (आर० एन० पी० पी० एन०, 19 दिस० 1883), हिंदू, 5 सित० 1884; वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 22 तथा सी० पी० ए०, पृ० 561; पी० पी० पिल्लई, रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 98-100; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 394-5, 451, 575-6, 622; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 364; आर० एन० मधालकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 39; एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 509-10, जोशी, पूर्वाद्धृत, पृ० 453; जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी०,

- 1901, पृ० 92-3, ई० ए०, पृ० 52-4; राय, इंडियन फैमिस, पृ० 58; न्यू इंडिया, 19 मई 1902; डी० ए० खरे का 13वें बर्बई प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, मगठा, 26 अग्रेन 1903, ए० ए० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 759- दत्त, ई० ए० 11, पृ० 487
31. 16 मई 1880 को पूना में हुई सार्वजनिक सभा में स्वीकृत याचिका, जे० पी० ए० ए०, जुलाई 1880 (खंड III, स० 1), पृ० 5-6, पी० मेरुता, स्पीचेज, पृ० 575, 671, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 404-05, 408-10, 415, 418, 508-10, गोखले, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1900, खंड XXXVIII, पृ० 88-92 और स्पीचेज, पृ० 6, जी० वे० पारिख, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1900, खंड XXXVIII, पृ० 118 और आगे, वही, 1901 खंड XXXIX, पृ० 236-7, आर० ए० मधोलकर, रिप० आई० ए० सी० 1901, पृ० 87, जी० ए० अय्यर, ई० ए०, पृ० 52, ए० ए० घाण, सी० पी० ए०, पृ० 760.
32. इंडियन स्पेक्टेटर, 11 और 18 मितंबर (आर० ए० पी० बब० 17 और 24 मितंबर 1881), जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 466
33. रानाडे, जे० पी० ए० ए०, अक्तूबर 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 57, नीराजी, स्पीचेज, पृ० 177, जी० ए० अय्यर, ई० ए०, पृ० 80, और आगे अध्याय 11
34. रानाडे, जे० पी० ए० ए०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1), पृ० 19, और वही, अक्तूबर 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 56-7, राय, पावर्टी, पृ० 180-4, 187-8, जी० ए० अय्यर, विलबी आयोग, खंड III प्रश्न 18737, जी० के० पारिख, इंगवी, पूर्वोद्धृत, पृ० 628 पर, दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 69, ई० ए० I, पृ० XI स्पीचेज II, पृ० 75
35. पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 607, दत्त, स्पीचेज I, पृ० 22, 37, 40, 180, सी० पी० ए० म, पृ० 480-1, 485, 487, ओपेन लेटर्स, पृ० 18-9 स्पीचेज II पृ० 57, ई० ए० I, पृ० XI, 94, 171, केमरी, 25 दिम० (आर० ए० पी० बब०, 29 दिम० 1900), आर० ए० मधोलकर, रिप० आई० ए० सी० 1904, पृ० 259
36. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 480, 497, जी० ए० अय्यर, ई० ए०, पृ० 50
37. पूना सार्वजनिक सभा के सचिव का पत्र, जे० पी० ए० ए०, जनवरी 1879 (खंड-I, स० 3), पृ० 43; रानाडे, जे० पी० ए० ए०, जनवरी 1884 (खंड I, स० 3, पृ० 5-6, हुयंस रान, रिप० आई० ए० सी० 1888, पृ० 176; ए० ए० अय्यर, रिप० आई० ए० सी० 1889, पृ० 50; हंडु प्रकाश, 28 जुलाई 1890; आर० ए० मधोलकर, रिप० आई० ए० सी० 1890, पृ० 48; जे० राम, वही, पृ० 52; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 696-7, 824, 969-71, 886 तथा आगे, 894, 904-05, डी० ए० खरे, रिप० आई० ए० सी० 1893 पृ० 117, ए० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 521-2; जी० ए० अय्यर, विलबी आयोग, खंड I, प्रश्न 18737, दत्त ओपेन लेटर्स, पृ० 52; स्पीचेज II, पृ० 30, 39, 41, 75, 105, 184, 186, 188, 198; लैंड प्रॉब्लम्स आफ इंडिया, पृ० 17-8; ई० ए० I, पृ० XI, 94 171, ई० ए० II, पृ० XII, 467, 501, 516.
38. रानाडे, जे० पी० ए० ए०, अक्तू० 1881 (खंड IV, स० 2), पृ० 55, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 347, 453, 870-1, 904-05, अखबारे आम, 21 जुलाई (आर० ए० पी० पी० 30 जुलाई 1898); ए० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 521; दत्त, सी० पी० ए०, पृ० 478, 480, स्पीचेज II, पृ० 91 तथा आगे, ई० ए० II, पृ० XIII.

39. रानाडे, जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 2) पृ० 48, 57, ज्ञान प्रकाश, 8 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 10 फरवरी 1883); बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1889, पृ० 49, जे० एन० बोस, रिप० आई० एन० सी० 1890, पृ० 50, आई० एन० सी० 1891 और 92 के प्रस्ताव प्रमाण III और IX, डी० ए० खरे, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 117, आर० एन० मधोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 45, स्वदेशमित्र, 17 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 1900), एल० ए० जी० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1903, पृ० 55 रानाडे ने 1879 में ही निर्देश किया था कि कृषि में इस समय जितनी भी पूँजी नियोजित है वह सारी की सारी व्यक्तिगत तथा अनुत्पादक उद्देश्य लिए हुए है अतः उसकी प्रकृति मृदन्त्रों पूँजी की है न कि निवेश पूँजी की ज० पी० एम० एम०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 167
40. बंगाली 21 श्रवतूबर 1882, जी० एम० खरपडे, रिप० गा० एन० सी० 1893, पृ० 118
41. दत्त, ई० एच० II, पृ० 269, 306, 463, 480-3
42. इंदु प्रकाश, 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब०, 30 अक्तू० 1880), मुन्नेष पत्रिका, 14 नव० (वही 20 नव० 1880), इंदु प्रकाश, 5 सित० (वही, 10 सित० 1881), दि वायसरायल्टी आफ लाज निटन ज० पी० एम० एम०, जुलाई 1880 (खंड III, स० 1), पृ० 61, रानाडे, ज० पी० एम० एम० जन० 1881 (खंड III स० 3) पृ० 18 और अक्तू० 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 7, अष्टावारे राम, 12 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 19 दिस० 1883), हिंदू, 18 जन० 1884, पी० पी० रिचर्ड, रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 98, पी० मेहता, स्पार्च, पृ० 150 575 105, 622 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव X, आर० एन० मजिस्टर इंडियन पालिटिक्स पृ० 39, ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 131 2 दत्त सी० पी० एम०, पृ० 450 स्पीचर्ज II पृ० 57 8 193-4 ई० एच० II, पृ० 467, 516, जी० के० पार्थिव का दमव बढे प्रांतों सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, बंगाली, 1900, दसवे बढे प्रांतों सम्मेलन में निरुद्ध द्वारा प्रस्तुत और सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव, मराठा, 27 मई 1900, राय इंडियन फॉर्मिस, पृ० 50, 59, जाशी पूर्वाद्धित, पृ० 410, 414 421, 426, 435, गांधील, स्पीचर्ज, पृ० 57, 1017, वाचा गो० पी० ए०, पृ० 561-2, 585 न्यू इंडिया, 19 मई 1902 तथा दमिन्ना, अध्याय 10 अंग
43. गांधिले, प्रामोडिडम आफ दि कांसिल आफ दि गवर्नर आफ बाब 1901, खंड XXXIX, पृ० 247, जी० एम० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1901, पृ० 92 3, दत्त, ई० एच० II, पृ० 487 तथा देखिए अध्याय 4 का 72 मध्या की पादटिप्पणी
44. दक्षिण आगे अध्याय 12 और 13
45. जे० पी० एम० एम०, अक्तूबर 1881 (खंड IV, स० 2), पृ० 58 और देखिए, रानाडे, जे० पी० एम० एम० जनवरी 1884 (खंड VI, स० 3) पृ० 4, वाचा, सी० पी० ए० पृ० 574-5
46. रानाडे जे० पी० एम० एम०, अक्तू० 1881 (खंड IV, स० 2) पृ० 57, एसेज, पृ० 256-7
47. जोशी, पूर्वाद्धित, पृ० 870 और देखिए, पृ० 347
48. दत्त ओपेन लेटर, पृ० 79-80 तथा देखिए, वही, पृ० 81-3, फॉर्मिस इन इंडिया पृ० XIV-XVI
49. उन्होंने तो जोर देकर कहा कि भारत में भूमि समस्या का कभी समाधान नहीं हो पाएगा और भारत में से तब तक नहीं बँटेगा जब तक यह नहीं किया जाता

50. नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 173, 176, रानाडे, जे० पी० एस० एस०, अक्टू० 1879 (खंड II, स० 2) पृ० 66, जन० 1881 (खंड III स० 3), पृ० 17 और अक्टू० 1881 (खंड IV, स० 2), पृ० 42, 45-6, एल० एम० घोष, स्पीचेज, पृ० 28, मराठा, 31 जुलाई 1881, स्वदेशमित्र 8 मई, शशिलेखा, 15 मई आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1896), आई० एन० सी०, 1890 और 1902 के प्रस्ताव क्रमशः XIII तथा III, जो० एस० अयर विलबी आयोग, खंड 3, प्रश्न 18643-4, दत्त, स्पीचेज I पृ० 23, 26, 37, 40, भी० पी० ए०, पृ० 486, ओपेन लेटर्स, पृ० 53, स्पीचेज II पृ० 17-8, 41, 59, 87, 200, 202, ई० एच० II पृ० 528, 606-07; स्वदेशमित्र, 17 मार्च (आर० एन० पी० एम० 31 मार्च 1900), ए० बी० बी०, 21 अप्रैल, 4 जून, 18 अक्टू० 1900, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 364-5, 457, 497, 513, एम० एम० मालवीय, रिप० आई० एन० सी०, 1900 पृ० 99, वाचा, सी० पी० ए० पृ० 601, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 691, 698-699, मार वे वर्ड प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव, मराठा, 10 नव० 1902, तरहने बबई प्रांतीय सम्मेलन में मिलर का भाषण, मराठा, 10 मई 1903, एल० ए० जो० अयर, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 523, गायन, स्पीचेज, पृ० 77, 80, 83 192 तथा देखिए आगे पाद टिप्पणी 55 55
51. रानाडे, जे० पी० एम० एस० अक्टू० 1884 (खंड VI, पृ० 4), पृ० 55 और देखिए, रानाडे, वही, जुलाई 1879 (खंड II स० 1) पृ० 11-3, दत्त आपन लेटर्स पृ० 41 53, 63, 89, 82-3 कैमिशन इन इंडिया पृ० XVI स्पीचेज II पृ० 18 75, 104, 177-8 20, ई० एच० I पृ० 396, ई० एच० II, पृ० X, XII, 471, 485, 495 501-02 517 617 मराठा, 3 मई 1903
52. दत्त, भी० पी० ए०, पृ० 423 आपन लेटर्स, पृ० 41-2, 53, 65 82-3 मार वे वर्ड प्रांतीय सम्मेलन की विवक्षित प्रकट करने हुए कहा कि उन्होंने मकान उपज के 1/5 भाग को सरकार को अधिकतम सीमा निर्मा के लिए जान पर न बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था न कि प्रस्ताव लगान के सामान्य गणक के रूप में यह प्रस्ताव रखा था अधिकतम लगान पर इस प्रकार की रोक की आवश्यकता उस समय उपज हुई जब राजस्व अधिकारियों द्वारा उपज के आधे भाग पर संगठित लगान कभी कभी कुल उपज के 1/5 भाग से अधिक रकतता या और कभी कभी तो मकान उपज के 1/3 से भी अधिक जाता था ओपेन लेटर्स पृ० 39 पाद टिप्पणी 47 पाद टिप्पणी, 53 पाद टिप्पणी, 65 पाद टिप्पणी, स्पीचेज II पृ० 178-9, ई० एच० II पृ० 512-3 यह समझ है कि दत्त इस ढंग से अपनी उम गलती पर परदा डालने की चेष्टा कर रहे थे जो मतभेद की तीव्रता में उनमें हा गई थी और कर्जन ने राष्ट्रवादियों की समालोचना को नकारने के लिए त्रिमका बड़ी बुद्धिमत्ता से उपयोग किया था
53. जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1) पृ० 13
54. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 480-1
55. एल० एम० घोष, स्पीचेज, पृ० 28, आई० एन० सी० 1895, 1896 और 1901 और 1903 के प्रस्ताव क्रमशः XIV, XIII, III और III पूना सार्वजनिक सभा की ओर से 9 नवंबर 1895 को साईं एलगिन के स्वागत में किया गया भाषण जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1896 (खंड XVIII स० 3), पृ० 11; सी० शंकरन नायर सी० पी० ए०, पृ० 385; दत्त, स्पीचेज I पृ० 40, 181, ओपेन लेटर्स पृ० 48-9, स्पीचेज II पृ० 41, 49, 75, 104, 180-1, 186-7, 190, 198-202, लैंड प्रॉब्लम आफ इंडिया, पृ० 25-6, ई० एच० I पृ० XIV, ई०

56 तेलंग, स्वीचेज, पृ० 4, 6-7, 20, रानाडे, जे० पी० एम० एस० जनवरी 1884 (खंड VI स० 3), पृ० 8-11 और वही, अप्रैल 1884 (खंड VI स० 4), पृ० 48-9, मराठा, 30 मार्च 1884, 25 जुलाई 1886, ज्ञान प्रकाश, 3 अप्रैल, इंदु प्रकाश 31 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 5 अप्रैल 1884), दंडियन स्पेक्टेटर, 20 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884), इंदु प्रकाश, 12 जुलाई (वही, 17 जुलाई 1886), पूना मार्चजैनिक सभा के सचिवों के पत्र, दिनांक 4 जून 1884, ज० पी० एम० एस०, जुलाई 1886, खंड IX, ग० 1), पृ० 3, 5-6, जाशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 824, दत्त, ई० एच० II पृ० 465-7.

57 एन० एम० घाप, स्वीचेज, पृ० 28, एम० एम० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1869, पृ० 50, आई० एन० सी० 1894 1896, 1898, 1901 और 1903 के प्रस्ताव समग्र II (बी), XVII, VI, III और III, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 407, दत्त, ओपन लटम पृ० 53, 65-6, 7, 83 एन० एन० ईनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 698-9

58 श्री नारायणराव पृ० 335, 622-4, दत्त, आर० लटम पृ० 4) 54, 50, रैमिन दत्त ईशिता, पृ० XVI स्पावर्क II पृ० 12, 4 5 एन० II पृ० 16, 7, 612, आई० एन० सी० 1902, 1903 और 1904 का प्रस्ताव क्रमशः III, III (ए) III (बी), डी० 70 और वा परहब बर्डी प्रान्तिय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अर्ध 1903

59 आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव स० X, एन० एन० नवावकर पृ० 10 ए० पृ० 520

60 नारायण, पण्डित। आर० ई० कोमिल आर० दि० गजनर। एक बच्चे 1901, खंड XXXIX पृ० 24 31 एन० एन० एन० आई० एन० सी० 1901 पृ० 93 और 30 ए० पृ० 54-5

61 1877 और 1878 का प्रस्ताव रंजीत रावराव मनाजीराव स्तरपर मांग उठाई गई और दंडियन रानाडे ए० पी० एम० एस० जनवरी 1884 (खंड II स० 2), पृ० 66, ए० पी० एम० एम० रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 11 100 मराठा, 17 जन० 1897, जी० के० पारिख, प्रामोदस्य आर० दि० कोमिल आर० दि० नवनेर आर० बाबू 1900 खंड XXXVIII पृ० 118 और आर० जाशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 404 413 4, 420, 511, 555-8, हिंदू० 19 अगस्त 1902 दत्त, मानज II पृ० 53, जी० एम० अय्यर, ई० ए० पृ० 55-7 आखिले स्वीचेज, पृ० 82 3

62 रानाडे, जे० पी० एम० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1), पृ० 10 13-4, श्रीर अप्रैल 1884 (खंड II स० 4) पृ० 55, बर्डी समाचार, 22 नव० (आर० एन० पी० बंब, 27 नव० 1890), पूना मार्चजैनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र, जे० पी० एम० एस० जुलाई 1881 खंड IV स० 1), पृ० 7, ए० बी० पी०, 26 जून 1884, और 19 जून 1892, मराठा का एक स्तम्भ लेखक, 7 फरवरी 1892, राय, इंडियन फॉर्मिस, पृ० 58 दत्त, ई० एच० II, पृ० 493 पाद टिप्पणी आर० एम० सयानी, एल० सी० पी० 1897 खंड XXXVI पृ० 191

63 रानाडे, जे० पी० एम० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1), पृ० 13-4; दत्त, ई० एच० II पृ० 493 पादटिप्पणी

64 केसरी, 15 और दिस० (आर० एन० पी० बंब, 19 और 26 दिस० 1896); आर० एन० पी० बंब, 2, 9, 16, 23 और 30 जनवरी और 6, 13 और 27 फरवरी 1897 में यथाप्रतिवेक्षित विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट, मराठा 3, 10, 17 जनवरी 1897; रामगोपास

पूर्वोद्धृत, पृ० 122-30, तहमकर, पूर्वोद्धृत, पृ० 69-73, प्रधान और भागवत, पूर्वोद्धृत, पृ० 100-03, सास मेटोग्रियल्स फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, (बंबई), खंड II पृ IX, 196, 638

- 65 उदाहरणार्थ, 15 दिसंबर 1896 के भूक के कसारी का लेख 'अशिक्षित विमान को यह पटाने की आवश्यकता है 14: उसके अधिकार क्या है और उन्हें वह किस प्रकार प्राप्त कर सकता है' उन्होंने यह घोषणा की कि नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे हिंसा जनता को समझाएं कि यदि उनकी फसल जराब हो गई है तो उन्हें लगान चुकाने की आवश्यकता नहीं है (आर० एन० पी० बब०, 19 दिस० 1896), उन्होंने इसी छक में लिखा 'यदि लोग गोली 11 1' ग वरक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का दृढ़ निश्चय कर ले तो नेतागण उनका युद्ध में साहाय्य करने के लिए बर्तव्यबद्ध होंगे (प्रधान तथा भागवत, पूर्वोद्धृत, पृ० 102) तथा दक्षिण रामगोपाल, पूर्वोद्धृत, पृ० 125-1, और तहमकर, पूर्वोद्धृत, पृ० 71
- 66 रामगोपाल, पूर्वोद्धृत, पृ० 126-9
- 67 वही, उद्धृत, पृ० 129-30
- 68 तहमकर—पूर्वोद्धृत, पृ० 63 पर उद्धृत
- 69 जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1877 (खंड II स० 1), पृ० 14-20 और अक्टू० 1881 (खंड IV स० II), पृ० 54-8 एमेज, पृ० 256-7 रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 143, इस प्रकार 1881 में स्टार्डर निर्धारण की कालन करने हुए रहा 'सरकार के पास अशिक्षित एकमात्र विकल्प, जिसके माध्यम से उपकरणों का सुधार महत्वहीन हो जाता है' का अनुपात-वर्धन में अन्य उपकरणों के प्रभाव की चर्चा करने हुए उन्होंने शाकायुक्त होकर रहा भारी गणना की समूची की आमान मुविधाया ने इसे विस्पृति की नींद में सुला दिया है और यह मानने लगे हैं कि राटो के टुकड़े के लिए परेशान लाखों किसान वैधानिक कानूनों के रूप में पत्थर के टुकड़ों के उग्रहण से मनुष्य हो जायेंगे वस्तुतः गहरे घावों की ओर गहरा वर्तमान की पड़ती में नव जीवन रक्त और शक्ति का संचार किए बिना किरायों की गतही खाई का पाटने वाल कानूना से कोई लाभ नहीं होगा।' जे० पी० एम० एम०, अक्टूबर (खंड IV, स० 2) पृ० 54 और 57 ब्रह्मण
- 70 प्रस्ताव V II 1888 में प्रस्ताव पारित कराने के प्रयत्न की अमफलता के लिए दक्षिण रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 163-4 174-8
- 71 1890 का प्रस्ताव VI 1891 का III, 1892 का IX, 1893 का X और XI, 1894 का II, 1896 का XII, 1897 का VII, 1898 का VI, 1900 का XXIII, 1901 का III, 1902 का III, 1903 का III और 1904 का III
- 72 एल० एम० घाय, स्पेचिज, पृ० 5; पूना मार्बेजनिज सभा के सचिव का पत्र, जे० पी० एम० एम० जनवरी 1879 (खंड I स० 3) पृ० 43, 16 मई 1880 को पूना में हुई एक सार्वजनिक सभा में स्वीकृत याचिका, जे० पी० एम० एम० जुलाई, 1880 (खंड III स० 1) पृ० 8-9, पूना मार्बेजनिज सभा का स्मरणपत्र दिनांक 2 मार्च, 1881 जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1881 (खंड IV, स० 1), पृ० 8-9, शेख राजा हुसैन खा, मुशी शेख हुसैन खा और राजा रामपालसिंह, आई० एन० सी० 1888 पृ० 1756, बी० एन० सेन रिप० आई० एन० सी० 1889, पृ० 48-9, एस० सुबह्मण्य अय्यर वही, पृ० 50-1, आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 49, और इंडियन पालिटिक्स पृ० 45-6, बी० जी० तिलक, रिप० आई० एन० सी०

1893 पृ० 114 और रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 133, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 362-3, 811, 824-5, एम० आर० मयानी, एल० सी० पी०—1897, खड-XXXVI म० 191 और सी० पी० ए० पृ० 36६, जी० आर० एम० चित्तनवीम, एल० सी० पी० 1898 खड X XVII पृ० 481, पी० ए० चार्ल्स, बही, पृ० 502 और एल० सी० पी० 1900, खड XXXIX पृ० 146, पी० महता, स्पीचेज, पृ० 60 07 एम० एम० मानवीय, रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 91 3 और रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 99 एम० एन० बैनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 75 6, गाखले, स्पीचेज पृ० 24 112 जी० एम० ज्ययर एच० आर०, फरवरी 1902 पृ० 149 51, बारहव और बारहव बर्द प्रांतीय मम्मलना के प्रस्ताव, मराठा 16 नवंबर 1902 और मई 1903 क्रमश

- 73 भूराजस्व व स्थाई निर्धारण की मांग आर० सी० दत्त के भूमि मसम्या पर लिख गए लगभग गभो लेखों में उपलब्ध है उदाहरणार्थ देखिए, इंग्लैंड ए० इंडिया पृ० 51 133 5 फैंमिस इन इंडिया', पृ० XII, स्पीचेज I पृ० 1९-24, 158 1९0-1 २० एच० II पृ० X XI
- 74 ज्ञान प्रकाश 6 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 8 फरवरी 1९79) अरुणादय, 27 अप्रैल (बही, 3 मई 1879), शिवाजी, 8 अगस्त (बही 10 अगस्त 1879) सुबाध पत्रिका, 1 अगस्त (बही, अगस्त 1880 इंदु प्रकाश 7 मार्च (वर्ष 12 मार्च 1९८1), अरुणादय 30 अक्तूबर (बही, ६ नवंबर 1९०१ १4 मार्च 1900 3 फरवरी 1९01, ज्ञान प्रकाश 8 फरवरी (आर० एन० पी० बब० 10 फरवरी 1883) मासप्रकाश 8 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 13 जनवरी 1883), नाटव ओपीनियन, 1 अप्रैल 1883 हिंदू 27 फरवरी 18९4, 13 मित० 1889 2 जून० 1891, नसीम आगरा 23 अग० ' ' एन० पी० पी० एन० अगस्त 1884), स्वदेशमित्र, 27 जुलाई (आर० एन० पी० ए० अगस्त 18९5), वगाना, 28 जून 1890, इंदु प्रकाश, 28 जून 1890 हिंदुस्तान, 3 मार्च आर० एन० पी० एन० 10 मार्च 1९९1) हिंदुस्तानी अक्तू० (आर० एन० पी० एन० 1९ अक्तू० 1891), हिंदुस्तानी, 8 नवंबर (बही 1९ नवंबर 1893), विक्टोरिया पेपर, 2० अक्तू० (आर० एन० पी० पी०, 4 नवंबर 1893, पेंसा अखबार, 13 अक्तू० (बही 20 अक्तू० 1894), केरल पत्रिका, 26 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 31 जन० 1895), मियालकोट पेपर, 8 अक्तू०, पेंसा अखबार, 7 अक्तू० (आर० एन० पी० पी०, 28 अक्तू० 1899), स्वदेशमित्र 18 मार्च और 21 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च और 31 अगस्त 1900 क्रमश)
- 75 लैंड रेंजेन्यू पालिसी आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, (कलकत्ता, 1902) कठिका 5
- 76 बही, कठिका 5 और 6
- 77 बही, कठिका 6
- 78 बही, कठिका 9
- 79 रीस, पूर्वोद्धृत, पृ० 63 यह काफी उन्नतजनक है कि ए० ओर तो रीस ने लगान के स्थाई बंदोबस्त सबंधी कांग्रेस के आंदोलन को अनिर्धार समर्थक नाम दे डाला दूसरी ओर उसी प्रस्ताव के तीन ही पृष्ठों के उपरान्त प्रत्येक जमींदार के निजी स्वामित्व के स्थाई बंदोबस्त की बहालत प्रारंभ कर दी रीस की मान्यता थी कि यह स्थाई बंदोबस्त बंगाल के स्थाई बंदोबस्त से भिन्न होगा (बही, पृ० 66-9) इससे स्पष्ट है कि उसे यह मान्य था कि स्थाई बंदोबस्त शब्द के विपरीत रूप से दो भिन्न अर्थ हो सकते थे
- 80 लोबेट फेजर पूर्वोद्धृत, पृ० 154-5

- 81 शाहू : सिकसटी इयर्स आफ इंडियन फॉर्मिस, पृ० 196 और देखिए, पृ० 200.
- 82 थामस, पूर्वोद्धृत, पृ० 123, लोचनाथन, दि इकोनामिक्स आफ गोखले', इंडियन जरनल आफ इकोनामिक्स, जनवरी 1842, खंड XXII स० 3 पृ० 228, बी० आर० मिश्र : लैंड रैवेन्यू पालिसी इन दि यूनाइटेड प्राविसेज (वनारम 1942) पृ 3/-39 हा लोचनाथन ने गोखले को स्थाई बदोबस्त का समर्थन करने के दोष से मुक्त कर दिया
- 83 पी० सी० घोष 'दि डेवलपमेंट आफ इंडियन नेशनल काप्रेम, 1892-1909' (रनरत्ता, 1960) पृ० 41-3
- 84 वही, पृ० 44 यह एक भारी आश्चर्य का विषय है, जैसाकि बाद में दियाया जाएगा, भाषण में कोई ऐसा अवतरण ही न था, जिसकी इस उम्र से व्याख्या की जा सके
- 85 बी० बी० मिश्रा 'दि इंडियन मिडिल क्लासेज' देयर गॉय इन माउन टाइम्स (जून 1961), पृ० 350 यह भी एव तथ्यो है कि जिस वर्ष यह प्रस्ताव भन ही मिश्रा ने अमिप्राय के अनुकूल नहीं, पारित हुआ, वह वर्ष 1889 न हाकर 1889 या 1898 में ता यह मामला तामस की विभिन्न स्थाई समितियों के सदस्यों के पास उनकी राय जानने के लिए ही भेजा गया था (देखिए प्रस्ताव XIV)
- 86 वही, पृ० 343-40
- 87 पी० सी० गोर : दाइरा एंडरंड्स टिप्परी (ए एन० एन० नार, यू एम० ए० 1961) पृ० 312 इसी प्रकार एन० एन० मिश्र लिखते हैं जहां पर भूमिधारा त्यों का बंध है, तामस की नीति अमिकाशत उनकी पक्ष में थी तामस स्थाई बदोबस्त के विचार की समर्थन था, जो किसानों और जमींदारों के बीच बहुत अधिक और रिया तया राज्य के लिए प्रयुक्त हो तम उपयोगी था तामस की इस नीति का क्या जायज करने एन लाई एलमिन तामस का ही उजागर किया कि बगान के अमादार बडे ही शांतागरी के और उम प्राप्त के तयको और वक्ताओं के साथ उनके तामागिक संबंध थे' पा तामस एंड पा'तमात्र जा दि रिट्रिज इन इंडिया, 1895 1898 (बर्त 1963)-पृ० 21-
- 88 एल० एम० तामस स्मिन्त्र पृ० 5
- 89 रानाडे, एमेज, पृ० 327
- 90 जे० सी० एम० एम० जनवरी 1874 (खंड VI स० 3) पृ० 19-20.
- 91 आर० एन० पी० बर०, 12 मार्च 1881
- 92 और देखिए मगटा, 22 अगस्त 1836 और बगान पब्लिक प्रातीनयन (बी० ओ० आई०, 31 जनवरी 1884)
- 93 रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 175 1889 के काप्रेम के अधिवेशन में स्थाई बदोबस्त के प्रस्ताव के प्रस्तोता बी० एन० सेन ने इस पक्ष पर बल दिया था रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 48-9) इसी प्रकार 1890 के काप्रेम के अधिवेशन में ताननीनाय बोग ने विश्वास दिलाया कि सारे बर्बई और मद्रास में हम किसानों के स्वत्वाधिकार बाना स्थाई बदोबस्त ही देखना चाहते हैं (रिप० आई० एन० सी० 1890, पृ० 51-2)
- 94 और देखें एम० एन० वैनर्गो, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 75-6
- 95 रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 14 उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सरकार देश के विभिन्न भागों में प्रचलित स्थिति के अनुरूप जमींदारों अथवा ग्रामों के मालिक अथवा किसानों के साथ बातचीत कर सकती है

- 96 रिप० आई० एन० सी० 1894, पृ० 38 और देखिए पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 606-07; पी० ए० चार्ल्स, एन० सी० पी० 1900 खर्च XXXIX पृ० 147
97. राय . इंडियन फैमिस, पृ० 56 7.
98. एच० आर० फरबरी 1902, पृ० 149-51, और देखिए, गोखले स्पीचेज, पृ 24
99. दत्त पीजटरी इन बंगाल (कलकत्ता, 1874) पृ० 46 और आगे
- 100 बगबागी, 10 अगस्त (आर० एन० पी० ब्र०, 17 अगस्त 1895)
- 101 दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 134
- 102 गी० पी० ए०, पृ० 486 पी० गी० घोष का मुमराह करने वाली बात कदाचित् आर० सी० दत्त की भारा के दूसरे भागों में बंगाल प्रशासन के विस्तार की भाग थी, परन्तु दत्त विस्तार की मांग कर रहे थे न कि जमींदारी पट्टेदारी की, वह उस पद्धति की मांग कर रहे थे जिसमें कुल उपज का 1/3 भाग ही किसान के रूप में बचाना होता है उनके विचार का पूरा वाक्य इस प्रकार है 'बंगाल नियम का भारत के दूसरे भागों में विस्तार किया दूसरे प्रांतों में कुल उपज के 1/6 भाग ही किसान में बचाने दिया जाने चाहिये धरती के विस्तार की अधिकतम सीमा निर्धारित कीजिए, तब देश में निश्चय ही अन्न की आवश्यकता को पूरा करने में सुविधा होगी' (वही, पृ० 481).
- 103 दत्त आपन लेटर्स पृ० 65 और देखिए, वही, पृ० 74 स्पीचेज II, पृ० 17-8, ई० एच० II, पृ० X;
- 104 उदाहरणार्थ देखिए पूना मराठा जन सभा के मंत्रिद्वय का पत्र, जे० पी० एस० एस० जनवरी 1879 (खंड I स० 3) ए० 43 गाजाडे, जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 1, कमज पृ० 256; 16 मई 1880 की पूना की जन सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एस०, मई 1880, (खंड III स० 1) पृ० 9, जन प्रकाश, 8 फरवरी (आर० एन० पी० ब्र० 10) फरवरी 1881, आई० एन० सी० 1880, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1897 और 1900 के प्रस्ताव क्रमशः XIV, VII, VI, III, IX, X, XIV, VII और XXIII, गी० एन० मेन, रिप० आई० एन० सी० 1839 पृ० 48, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 363, 811, 854-5 आर० एन० मधोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 45-6, पी० ए० चार्ल्स, एन० सी० पी०, 1898, पृ० XXXVII, पृ० 502 और वही, 1900, खंड XXXIX, पृ० 146, सी० जकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 384-5 दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 51, 134-5 स्पीचेज II पृ० 168 गोखले, स्पीचेज, पृ० 24
- 105 गानाड, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1879 (खंड II स० 1), पृ० 14-15, 16 मई 1880 की पूना में हुई जन सभा में स्वीकृत याचिका, जे० पी० एस० एस० जुलाई 1880 (खंड III, स० 3, पृ० 9, रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 48-9, आई० एन० सी० 1889, 1893, 1894, 1898, 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव VI, XI, II, III, III, और VI (बी) क्रमशः, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 364 811, दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 91-2 स्पीचेज I पृ० 19-20 स्पीचेज II पृ० 40-1, 172-3, फैमिस इन इंडिया, पृ० XII, ई एच II पृ० X-XI, 273-291; आर० एन० मधोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 45, गोखले, स्पीचेज, पृ० 25.
106. दत्त, ई० एच० I पृ० 123-5, 135-40, 152, 168 और देखिए, दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 49-50 ओपेन लेटर्स, पृ० 31, ई० एच० II पृ० 77-8 दत्त ने एलिफिस्टन के रयतबाड़ी पद्धति के प्रबल समर्थक होने पर भी ग्राम समुदायों और ग्राम पंचायतों आदि के बचाने की चेष्टा के लिए उसकी प्रशंसा की (ई० एच० I, पृ० 352-55)
107. 16 मई 1880 की पूना में हुई जन सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एस० जुलाई 1880

- (खंड III स० 1), पृ० 8-9; रानाडे, एसेज, पृ० 327, जे० पी० एस० एस०, अक्टूबर 1881 (खंड IV स० 2) पृ० 56, वही, जनवरी 1884 (खंड VI स० 3) पृ० 21 वही, अप्रैल 1884. (खंड VI स० 4) पृ० 55; शेष राजा हुसैन खा, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 175; आर० एन० मधोलकर, रिप० एन० सी० 1890 पृ० 49, के० जी० देशपांडे, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 33 आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव II (बी), पी० ए० चारलु, एल० सी० पी० 1900 खंड XXXIX पृ० 146; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 607, दत्त, स्पीचेज I पृ० 181-12, ओपेन लेटर्स पृ० 48, 66, 79, फॉर्मिस इन इंडिया पृ० XV, स्पीचेज II पृ० 187-8, ई० एच० II पृ० 514, गोखले, प्रोसीडिंग्स आफ दि कांसिल आफ दि गवर्नर आफ बावे 190 खंड XXXIX पृ० 245 एल० ए० जी० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 56.
108. दत्त, ई० एच० II पृ० 503-04, एस० गोपाल, दि वायसरॉयल्टी आफ लाहॉर रिपन (नदन, 1953), पृ० 189.
109. रानाडे, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1884 (खंड VI स० 3), पृ० 4-11; साधारणो, 23 नव०, सजीवनी, 22 नव०, समाचार चंद्रिका, 24 नव० (आर० एन० पी० वग० 29 नव० 1884); ग्रामवर्त प्रकाशिका, 29 नव० (वही, 6 दिस० 1884), प्रतिकार, 12 दिस० (वही, 20 दिस० 1884), आई० एन० सी० 1893, 1894, 1898 और 1899 के प्रस्ताव क्रमशः XI, II, VI और II (बी) आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 159, रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 87, पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 607; दत्त, स्पीचेज I पृ० 158-60, ओपेन लेटर्स, पृ० 35, 41, 43-4, 79, फॉर्मिस इन इंडिया, पृ० XIII, XV, स्पीचेज II पृ० 9, ई० एच० I पृ० XI-XII, 503-04
- 110 आई० एन० सी० 1889, 1890, 1902 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः VII, VI, III और III (बी) दत्त, स्पीचेज I पृ० 181 2, ई० एच० पृ० 151 गोखले, स्पीचेज, पृ० 24, आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 87
- 110-ए दत्त, स्पीचेज II, पृ० 173 तथा देखिए, गोखले, स्पीचेज, पृ० 25
- 111 आई० एन० सी० 1896, 1901, 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XIII, III, III, III और III
112. रानाडे, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 17 8, इंदु प्रकाश, 10 मार्च (आई० एन० पी० वग०, 15 मार्च 1879), शिवाजी, 8 अगस्त (वही, 16 अगस्त 1879), इंदु प्रकाश, 7 मार्च (वही, 12 मार्च 1881), पूना सांख्यिक समा का स्मरणपत्र, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV, स० 1), पृ० 8; ए० बी० पी०, 5 अक्टूबर 1882, 28 नव० 1889, 27 मार्च 1900, बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1889 पृ० 48, जे० एन० बोस, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 51, ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 33-4, मासवीय, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 90, दत्त, इम्पेंड एंड इंडिया, पृ० 13, 134; स्पीचेज I, पृ० 15-18, 180-1, सी० पी० ए०, पृ० 481; ओपेन लेटर्स, पृ० 59 60, 64-5, स्पीचेज II, पृ० 4 5, 40, 169, ई० एच० I, पृ० 94-6, ई० एच० II, पृ० X 461, 509 और जे० एन० गुप्ता की लाइफ एंड वर्क आफ आर० सी० दत्त (नदन 1911) पुस्तक पृ० 333-4 पर उद्धृत एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 698, एल० एम० मोघ, सी० पी० ए०, पृ० 759.

- 113 दत्त फ्रामिस मिनिट्स, पृ० IV तथा देखिए, स्पीचेज I, पृ० 18, ओपेन सेटर्स, पृ० 64 ई० एच II, पृ० 94-5
- 114 दत्त, सी० पी० ए०, पृ० 484 ओपेन नेट्स, पृ० 22, 61-4, फॉर्मिस इन इंडिया पृ० IX, 106 07, ई० एच० II, 461 इस संबंध में दत्त के विवेचन में स्पष्ट मिलती यह है कि वह यह देखने में चूक गए कि बंगाल में वास्तविक किसानों और जमींदारों के मध्य विच्छेदिए थे जमींदारों के पास तो काबिज किसानों की ओर से 1/5 भाग से अधिक नहीं पहुँचता था जबकि वास्तव में किसानों के बारे में शायद अपनी कुल उपज के प्रतिशत का बहुत बड़ा भाग देना पड़ता था और मजबूत ही यह सब कुछ रेंजबाइडी में भी हो रहा था
- 115 राय इंडियन फॉर्मिस, पृ० 55-6 और देखिए, एम० एन० बैनर्जी, स्पीचेज II, 12-3, इंडियन स्पेक्टर, 25 मितवर (आर० एन० पी० बब० । अक्टूबर 1881), ग्रामवर्त प्रकाशिका, 16 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 1 मार्च 1884), मराठा, 17 फरवरी 1884, बंगाली, 28 जून 1890 और आगे देखिए, बंगाल रेंट बिल की धारा जैसा पहले निर्देश किया जा चुका है, एम० नवयवक के रूप में दत्त ने स्वयं 1874 में अमहाय किसानों का दमन करने और उन्हें दरिद्र बनाने की अमीदारों की अनुमति देने वाले 1793 के म्याई बंदोबस्त की निंदा की थी। देखिए, 'गोजेटरी आफ बंगाल', पृ० X, 46 और आगे 1888 में जी० बी० जोशी ने बंगाल में ऊँच रिगाए लागू होने की निंदा लगातार की थी पूर्वोद्धृत, पृ० 884
- 116 दत्त इंग्लैंड एंड इंडिया पृ० 90-1, 116, स्पीचेज I, पृ० 146 180, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 55 सी० पी० ए०, पृ० 481 ओपन नेट्स पृ० 189 59, 61 65, 78 फॉर्मिस मिनिट्स पृ० VII VIII रीविज II, पृ० 45 10, ई० एच० II, पृ० 263 4 437, 460-1
- 117 नैट रेंज यू पाणिनी आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया 1902, कड़िका-9
- 118 दत्त स्पीचेज II, पृ० 170
- 119 दत्त गोजेटरी आफ बंगाल, पृ० 82 इस वायव्याही के नैतिक उद्देश्य की चर्चा दत्त ने निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की है और फिर पट्टे जमींदार है 'यही, जो किराया बढ़ाने के लिए किसानों का परेशान करता है ' यही, जो स्वयं महला के शहर में अपने आरामदेह घर में चुपचाप बैठा रहता है और उमर मजदूरों के साथ तब खेतों में श्रम करते हैं और रात भर जागृत रहते हैं व जल का अपनी दाढ़ी में, मावन के बरसने पानी और पीछे की सख्त कपानों की गर्मी में गुरु ग्राममानों की नीच काम करने हैं वे जमीन जोतते हैं और फसल काटते हैं पौधे लगाने हैं और फल बीजते हैं उन्हें इमाना परेशान किया जाता है कि वे अपने अधिक श्रम के फल में भाग पर निर्भर बढ़ता भाग का पूरा करने से इनकार करते हैं जमींदारों के पास किसानों को तब करने की शक्ति कहाँ से आता है ? क्या एक निकम्मे आदमी को किसी महान्ता गरीब की परेशान करने का नैतिक अधिकार प्राप्त है ? इस कार्य का समर्थन करने वाली आचारसंहिता मजबूत ही विचित्र होगी (पृ० 87)
- 120 उनका दृष्टिकोण का तर्क अध्यापनया असद्विध था हा, यह कभी कभी स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता था प्रमाण रूप में देखिए, सी० जे० ओ० डोमिल की समीक्षा 'दि रूइन आफ इंडियन प्राविंस जे० पी० एस० एम०, जनवरी 1881 (खंड III, सं० 3) पृ० 38, श्रुत प्रकाश, 7 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 12 मार्च 1881), हिंदू 14 अप्रैल 1884, जोशी, पूर्वोद्धृत, 885, दत्त इंग्लैंड एंड इंडिया, पृ० 130, ए० बी० पी०, 28 जुलाई 1904
- 121 दत्त ई० एच० I, पृ० 128, 232-3 190, 362, 365 दत्त ने कपनी के एक डायरेक्टर हेनरी

सेंट बान टक्कर की पुस्तक से निम्नलिखित अवतरण को उद्धृत किया : इसे न ही छुपाया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है कि इस रैयतवादी पद्धति का उद्देश्य किराए के रूप में भिसने वाले सरकारी राजस्व की अधिकारिक प्राप्ति है.

122. वही, पृ० 362.
123. रानाडे एसेज, पृ० 29-30, 327, सी० जे० ओ० डोनिल की समीक्षा 'रूड्न आफ इंडियन प्राविस' जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1881 (खंड III, स० 3); एस० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1886, पृ० 62, एच० ए० रहीम, रिप० आई० एन० सी० 1890, पृ० 55, जी० सी० सिंह, रिप० आई० एन० सी० 1893 पृ० 115-6, केरल पत्रिका 26 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 31 जनवरी 1895), मालवीय, स्पीचेज, पृ० 266-8, दत्त इग्लैंड एंड इंडिया, पृ० 13, स्पीचेज I पृ० 15 सी० पी० ए०, पृ० 482, ओपेन लेटर्स, पृ० 59, 74-6, 78, और देखिए पीछे 40-1 पाद टिप्पणी. उदाहरणार्थ, आर० सी० दत्त न विभिन्न प्रांतों के किराया-कानूनों को पूरा समर्थन दिया और किसानों की सुरक्षा के लिए इससे भी कोई बड़ा माघन अपनाने की वकालत की. देखिए फरवरी 1899 को अवधि में पायनियर की लिखे पत्र, तथा 14 सित० 1900 को ऐंटनी मॅकडानल को निम्ना पत्र, जे० एन० गुप्ता 'पूर्वोद्धृत, पृ० 349 पर स्पीचेज II, पृ० 178, और ई० एच० II, पृ० 268-71, 458-60 467.
124. एम० एन० बैनर्जी, स्पीचेज II, पृ० 10-11, हिंदू, 14 अप्रैल 1884, ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1883, 3 फरवरी 1901, दत्त, ई० एच० I, पृ० 96, 133 और जे० एन० गुप्ता 'पूर्वोद्धृत, पृ० 334 पर; और देखिए, ए० बी० पी०, 25 जन० 1902 यहा यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्र-वादियों ने सरकारी तक को बड़ी ही सफाई से मोड़ दिया कि जमींदारी पद्धति के अंतर्गत जहा किराए का लाभ खून चूसने वाले जमींदारवर्ग को मिलता है. बहा रैयतवादी में यह खून चूसने वाली संस्था सरकार है.
125. रानाडे, एसेज, पृ० 287, 290; दत्त, ई० एच० I, पृ० 131-2 ई० एच० II, पृ० 43.
126. रानाडे, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1879 (खंड II, स० 1) पृ० 2, 17-18, एसेज, पृ० 239-42; पूना सार्वजनिक सभा का स्मरणपत्र, जे० पी० एस० एम०, जुलाई 1881 (खंड IV, स० 1) पृ० 9; ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 28 अक्तूबर 1880; ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1883, मराठा, 27 जुलाई 1890, इंदु प्रकाश, 28 जुलाई 1890; बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1890, पृ० 50; ए० बी० पी०, 20 फरवरी 1899, दत्त, ई० एच० I, पृ० 132, दत्त, ई० एच० II, पृ० 52, 58, 86, 88-9, 264, 267 दत्त ने अपने ग्रंथ 'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया' के द्वितीय खंड में टिप्पणी की कि ग्राम समुदायों और बिचौलिया जमींदारों के अभाव में पंजाब में व्यापारी सराफ और रकम उधार देने वाले आदि के रूप में एक नया वर्ग अस्तित्व में आ गया है जो किसी भी देश के कुलीनतंत्र का निष्कृष्टतम रूप है (ई० एच० II, पृ० 89-90).

अध्याय 10

कृषि का विकास : दो

जमींदारों को इस स्थिति में रखना चाहिए कि वे काश्तकारों का दमन न कर सकें। साथ ही काश्तकारों को भी भूस्वामियों को अपमानित और निरस्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सामाजिक शिष्टाचार का निर्वाह इस रूप में हो कि भूमिपति काश्तकार से प्रेम करें और काश्तकार भूमिपतियों का आदर करें।

अमृत बाजार पत्रिका, 8 जनवरी, 1885

समाज के एक वर्ग को कठोर श्रम और दासता के बंधन में जकड़ने वाली तथा दूसरे वर्ग को शारीरिक श्रम से सर्वथा छूट, मुख-चैन और पूर्ण अवकाश की सुविधा जुटाने वाली प्रवृत्तियों के प्रमुख कारण कुछ भी क्यों न रहे हों...परंतु अब यह नितान्त स्पष्ट है कि आधुनिक सभ्यता की प्रवृत्तियाँ तथा समता की पनपनी भावना इन दोनों वर्गों में असमान और अन्यायपूर्ण संबंधों को दीर्घकाल तक बने नहीं रहने देंगी। देर मवेर समाज की पुनर्व्यवस्था होना निश्चित है, और अच्छा गही है कि हम बिना किसी प्रहार की शिकायत किए और बुडबुड़ाए उस समय के स्वागत के लिए तैयार रहे।'

भराठा, 21 अक्टूबर, 1893

यदि अंगरेजों के दमन को चिंगारी की संज्ञा दी जाए तो राजाओं और जमींदारों के दमन को शोले की संज्ञा देनी पड़ेगी।

बंगनिवासी, 30 अक्टूबर, 1891

किसान और जमींदार

भूमि जोतने वाले की उपज पर केवल कर कर्मचारी का ही अधिकार नहीं था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, मध्य भारत के प्रांतों में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा अवध और बंबई तथा पंजाब के छोटे से भागों के जमींदारी क्षेत्रों में भूमि जोतने वाला काश्तकार था जो जमींदार को किराया चुकाता था, उससे से ही जमींदार सरकार को लगान का भुगतान करता था। इसके साथ ही साथ इन सभी इलाकों में किराया लेने वाले

जमींदार और किराया चुकाने वाले तथा असल में ही जमीन जोतने वाले किसानों के बीच बिचौलियों की संख्या निरंतर कई गुना बढ़ती जा रही थी। इधर रयतवाड़ी इलाकों में भी धीरे धीरे खुदकाशन की प्रणाली विच्छिन्न तथा विलुप्त होती जा रही थी। मालिक किसान धीरे धीरे अपनी धरती ऋणदाता, व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग के हाथों बेचते जा रहे थे। व्यापारी लोग भूमि के मालिक तो बन जाते थे पर धरती जोतने नहीं थे। वे उन पुराने किसान मालिकों को धरती पर बने नए रहने दते थे परन्तु अब उनकी स्थिति दरिद्र व असहाय किराएदार किसान की हो जाती थी। देश के देशान्तों में निरंतर बढ़ते हुए किरायों तथा धरती का खानी कराने की घटनाओं ने विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी और किसी न किसी रूप में किसानों और जमींदारों के पारस्परिक संबंधों के प्रश्न को देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या बना दिया था। अतः सरकार किराए के कमरनाट भारत में दबे किसानों को कुछ राहत देने के लिए तथा विभिन्न प्रांतों में वास्तविक और किराए संबंधी कानूनों की श्रृंखला बनाने के लिए विवश हो गई। यहाँ यह उन्मुखनीय है कि सरकार ने रयतवाड़ी इलाकों में मनमर्जी पर रण वास्तविकता की समस्या की पूर्ण रूप से ही उपेक्षा कर दी।

यह काफी आश्चर्यजनक बात है कि इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी नेताओं की नीति न केवल अनिश्चित थी प्रत्युत इस पर उन्होंने विशेष ध्यान भी नहीं दिया। इन नेताओं ने न तो किसान और जमींदारों के बीच के प्रश्न को प्रमुख आर्थिक समस्या माना और न ही किसानों के लक्ष्यों को सामान्य राजनीतिक आंदोलन में जोड़ा। राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किसानों की समस्याओं की उपेक्षा का परिमाण को इस तथ्य में नापा जा सकता है 'समीक्षाधीन अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके संबंध में वास्तव में ही कुछ भी नहीं रहा' परन्तु इस समय देश के सामने आने वाली आर्थिक यथार्थताओं से उत्तरोत्तर भ्रमन वाले राजनीति में सक्रिय और सजीव भाग लेने वाले नेताओं में तो इन समस्याओं का आख्य मूढ़ने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन नेताओं ने इन समस्याओं को दो रूप में लिया : सामान्य और विशिष्ट। सामान्य रूप के अंतर्गत इन नेताओं ने किसानों का अस्पष्ट रूप में ही पक्ष लेंते हुए छिटपुट टिप्पणियों की तथा सामान्य उपचार सुभाष। और विशिष्ट रूप के अंतर्गत उन्होंने सरकार द्वारा पारित विभिन्न वास्तविक और किराया संबंधी अधिनियमों पर अपने मत प्रकट किए। यहाँ उन्हें रोग विशेष के लिए निश्चित उपचार सुभाना था अथवा अपना स्पष्ट मत प्रकट करना था। अतः उन्हें बुद्धि और पर ही किसानों अथवा जमींदारों के समर्थक के रूप में आना पड़ा।

सामान्य रूप के अंतर्गत राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने जमींदारी-इलाकों में किसानों के प्रति मानवीय चिंता प्रकट की तथा जमींदारों द्वारा किसानों के सामान्य दमन कमर-तोड़ किरायों की वसूली और किसान की बेदखली के प्रति विरोध प्रकट किया।¹ यह विरोध कभी कभी तीखी भाषा में भी होता था। उदाहरणार्थ, शक्तिशाली जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की आलोचना करने हुए बंगाली ने अपने 9 दिसंबर 1882 के अंक में लिखा : 'किसी भी प्रकार का अत्याचार निंदनीय है। अत्याचारी भले ही गोरा हो अथवा काला आदमी, दमन करने वाला भले ही भारत में जन्मा और पला हो अथवा दूर

पश्चिम से आया हो, सर्वथा और समान रूप में घृणा का पात्र है।³ दस हजार व्यक्तियों के खून पसीने की बमार्ड पर एक व्यक्ति को जीवन की सभी सुख-सुविधाएं तथा बिना-मिताएं जूटाने वाली लगान सशस्त्र पद्धति को अमान्य ठहराते हुए 'भोम प्रभाश' ने 24 जुलाई, 1882 के अंक में व्यंग्यपूर्वक पूछा - 'एक के श्रम का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना और गुलदर्रे उठाना कहा का न्याय है?' उसने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि 'भूमय की गति के साथ जमींदार उत्तरोत्तर जितना अधिक शक्तिशाली हुआ है, किसान उत्तरोत्तर उतना ही अधिक दीन-हीन हुआ है।'⁴ 14 जन, 1884 के अंक में 'बंगवासी' ने गांव के जमींदार को सभी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन करने वाला तथा बंगाल का सबसे बड़ा उत्पत्ती बताया।⁵ 'बंगनिवासी' ने 30 अक्टूबर, 1891 में जमींदारों, उनके गुमास्तों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसानों के अमानवीय और अकथनीय दमन की निंदा करते हुए एक लंबा और क्रोधपूर्ण संपादकीय प्रकाशित किया। उसने इस संबंध में शिक्षित लोगों की जवर्म्मण्यता तथा उपेक्षा वृत्ति की आलोचना करते हुए लिखा

यदि हमारे अपने ही देशवासी (जमींदार और उनके दलाल) माधारण मा अधि-
कार पाते इतना भारी अत्याचार और दमन कर सके हों तो अमीम शक्तियों में
संपन्न विद्वान् जिला-तीस के अत्याय के विरुद्ध चीखा-निन्लाहट करना इतना तक
उचित है? यदि अंगरेजों द्वारा किए गए दमन को चिगाही कहा जाए तो इन
जमींदारों और राजाओं द्वारा किए जा रहे दमन को धक्कने हुए घोले की मजा दी
जानी चाहिए।⁶

उत्तरी पश्चिमी प्रांत और जवय में उत्तरी भारत के कांग्रेस के मुस्लिम समर्थकों में अग्रणी मज्जाद हुसैन द्वारा संपादित प्रमुख हाम्य-व्यंग्य प्रधान पत्र 'अबन पत्र' के 18 जनवरी 1894 के अंक में एक कार्टून प्रकाशित हुआ। इसमें अधनंगे बदन और लंग पैरों दो किसान एक जमींदार को पालकी में उठाए हुए चित्रित किए गए थे। बड़ी तोड़वाले जमींदार ने चमकीले गहने और 'स्टार आफ इंडिया' का तमगा पहन रखा था। कार्टून का शीर्षक 'गा. अकाल का कारण'। उन दोनों में एक किसान दूसरे साथी में कह रहा था : 'भाई इसका बाभू तो हमारा दम तोड़ देगा, क्यों न इस पाजी को फेंक दिया जाए?'⁷ मालाबार में निकलने वाली, के० पी० करुणाकर मेनन द्वारा संपादित, 'केरल पत्रिका' ने अपने 21 मार्च 1896 के अंक में बार-बार होने वाले मोपला बलवों के लिए, जमींदारों द्वारा किए गए अमहनीय दमन से उत्पन्न गरीबी को उत्तरदायी बताया और अत्याचारी जमींदारों को सभी वर्गों और समुदायों के किसानों का समान रूप में क्रूरतापूर्वक दमन करने वाला घोषित किया।⁸ 4 जुलाई 1896 के अंक में 'केरल पत्रिका' ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने जमींदारों का दमन न रोका तो न केवल मोपलों के बलवे नहीं रुक पाएंगे प्रत्युत नायर लोग भी विद्रोह पर उतर आएंगे।⁹

कुछ एक भारतीय जननेताओं ने 1870 के आसपास जमींदारी प्रथा की निंदा की। जमींदारों पर सशक्त प्रहार बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने बंगदर्शन के अंतर्गत 'समय' लेख में किया।¹⁰ युवक नेता आर० सी० दत्त ने चटर्जी महोदय का अनुसरण किया।¹¹ 17 फरवरी 1884 को 'मराठा' ने अपने एक लंबे लेख में जमींदारी पद्धति पर तीखा प्रहार

किया। जैसा कि हम आगे विवेचन करेंगे, बंगाल किराया बिल पर मनभेद के समय अनेक भारतीय मस्याओं और राष्ट्रवादी नेताओं ने किमान ममर्थक दृष्टिबोध अपनाया। बाद में पृथ्वीशचंद्र राय ने अपने दो लेखों, 1895 में प्रकाशित 'पावर्टी प्रान्त्वंग इन इंडिया' और 1901 में प्रकाशित 'दि काजेज आफ रेंटियन फॉर्मस' में जमींदारी प्रणाली और जमींदारों के दमन को ही लोगों की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी माना।¹¹ जी० बी० जोशी ने जमींदारी की विस्तृत आलोचना की। उन्होंने 1890 में प्रकाशित अपने निबंध 'इकोनामिक सिच्युएशन इन इंडिया' में जमींदारी और रेंतवादी दोनों क्षेत्रों की बुराइयों की तफसील में आलोचना की। उन्होंने लिखा कि गारे देश में काश्तकार द्वारा आगे धरती को किराए पर देने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विचौलियों और मनमग्नी में रखे काश्तकारों की सख्या कई गुना बढ़ गई है। एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और दूसरी ओर गैरकृषि उद्योग में बराबर ह्रास होने में किसानों में धरती के पान के लिए होड़ और प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस स्थिति का दुष्परिणाम करते हुए जमींदारों ने किसानों को गगनचुंबी किंया देने के लिए नाथ्य कर दिया है। उन ऊंचे किरायों और काश्तकारी की अमरुक्षा का दुष्परिणाम यह निकला है कि असली हल जोतने वाले किसान का धरती को मुभारने का निश्चयात्मक उत्साह ही नष्ट हो गया है।¹² जोशी जी के निबंध का संक्षेप इस प्रकार है

किमान की स्थिति यह है कि वह किननी भी समझदारी में काम कर ले, कृषि उद्योग अथवा उपज में उसे कुछ मिलता मिलाना नहीं है और यदि वह अपने काम की उपेक्षा करता है तो उसका कुछ बिगड़ना नहीं। उसे किसी प्रकार की कोई आजा नहीं है। अपने कट्टे की कुछ एकड़ धरती को बचाने के लिए वह भूख मरने को बजाय मुहमाया ऊंचा किंया चुकाना है। अपनी सहायता आप करने का उद्देश्य ही इस स्थिति का अंग नहीं और न ही इस स्थिति में स्वतः कठोर श्रम की प्रेरणा की अपेक्षा की जा सकती है।¹³

1894 में प्रकाशित अपने निबंध 'नोट्स आन ऐग्रीकलचर इन बाबे' में जोशी ने जमींदारी और स्वैच्छिक काश्तकारी के विकास पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने दुखपूर्वक कहा कि आंशिक रूप से उपकाश्तकारी के व्यापक व्यवहार के कारण और आंशिक रूप से श्रम प्रतृता से मुक्ति न मिलने के फलस्वरूप बंबई प्रांत में समुचित काश्तकारी अधिकार अथवा काश्तकारी कानून नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई है। इस प्रकार काश्तकारी अधिकारों तथा अवीनस्न काश्तकारों की बेदखली अथवा किराया वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है।¹⁴

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने काश्तकारों को संरक्षण देने के निश्चयात्मक उपाय भी सुझाए। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय था किरायों में अनुचित वृद्धि के, भारी लगानों के, बेदखली के तथा काश्तकारों के अधिकारों के हनन के विरुद्ध काश्तकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना तथा कब्जे के अन्यान्य अधिकारों को विस्तृत तथा सुदृढ़ रूप देना।¹⁵ यह एक रोचक तथ्य है कि सरकार द्वारा अपनाए गए काश्तकारी कानून का जी० बी० जोशी, आर० सी० दत्त तथा जस्टिस रानाडे तीनों मुख्य अर्थशास्त्रियों ने

समर्थन किया तथा काश्तकारी अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के पक्ष में प्रबल तर्क दिए।¹⁷ जोशी ने अधिकारियों में बंबई के नितान असुरक्षित उपकाश्तकारोंवाले रयतवाडी डलाके में भी कानूनी संरक्षण के विस्तार का अनुरोध किया।¹⁸

यह स्वाभाविक ही था कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन की व्यापक मांग तो नही की गई परंतु यह कम महत्वपूर्ण नहीं कि यह मांग क्यों उठाई गई। इस प्रकार 2 अक्टूबर 1881 के अंक में इंडियन स्पेक्टेटर ने सरकार से सारी जमींदारी खरीदने और फिर सीधे किसानों में समझौता करने का अनुरोध किया।¹⁹ 24 जुलाई 1882 के अंक में 'सोम प्रकाश' ने सरकार को इस सरकार के आदर्श उदाहरण का अनुसरण करने का उपदेश दिया और कहा कि सरकार जमींदारी प्रथा समाप्त कर दे। जमींदारों का तीन वर्षों में दान वाले लाभ रु बराबर का वन उगकी जमीन के मूल्य के रूप में देकर उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए। यह धन आधा सरकार जुटाए और आधा ही व्यवस्था किसान करें।²⁰ कभी कभी भारतीय नेता मांग के प्रति टालमटोल काम लेने के लिए जमींदारी प्रणाली को एक मिश्रित तथ्य मानकर जमींदार और पट्टेदार के मांग-प्यास में समझौता भी बरताने लगते थे।²¹

12 जन, 1880 के अंक में बंगाली नवगणक म्याई वंदोबस्त की एक और मजेदार आलोचना प्रकाशित हुई। बंगाली पत्रों ने इस स्वयंसेवा के आलोचकों के आलोचकों की आलोचना की। बंगाल में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिशीलता का निमित्त श्रमवाद है। जमींदारी ही वह पूँजी के निश्चित लाभ के निवेश का प्रभावशाली अवधिमान प्रणाली है। यही कारण है कि पूँजी निवेश की प्रवृत्ति उद्योगों द्वारा जमींदारों की ओर हो रही है। दो वर्ष पश्चात् 28 जनवरी 1882 के अंक में बंगाली नवगणक ने अपना आलोचनात्मक आशय व्यक्त करते हुए अपना मत प्रकट किया कि जमींदारी प्रणाली का प्रत्यक्ष बंगाली श्रमिकों के आर्थिक और व्यापारिक स्तर का उन्मुखनीय अंतर स्पष्ट करता है।

उत्तर विपरीत सामान्य आशय पर जमींदारों अथवा अन्य बड़े बड़े भूखंडों के स्वामियों ने हिता के भारतीय नेताओं द्वारा समर्थन के उदाहरण बहुत ही कम थे। बंगाल में बंगाली नवगणक के समर्थन की अपनी पहली नीति में हटते हुए 19 मार्च 1887 के अंक में भारतीय पत्रों ने बंगाल में किसान संगठनों को नोडों के उपाय करने का और किसानों का उत्पन्न किराये के भुगतान की अनिवार्यता से परिचित कराने का अनुरोध किया। 20 फरवरी 1899 के अंक में अमृत बाजार पत्रिका ने भी दावा किया कि अंगरेजी राज्य की अवस्था, कृषि संबंधित लोगों के विप्लवों तथा अनेक अन्याय बुराईयों से सुरक्षा जमींदारों के अधिकारों और सुविधाओं को बनाए रखने पर ही निर्भर है कि उनके विनाश में। एक वर्ष पश्चात् इसी पत्रिका ने अपने 12 जनवरी 1900 के अंक में सरकार से अनुरोध किया कि वह या तो जमींदारों के प्रति अपनी कठोरता की नीति में मृदुता लाए या उन्हें किसानों से किराया वसूल करने की सुविधाएं जुटाए। 'केसरी' ने 18 अक्टूबर 1881 के अंक में शिकायत की कि देश के दूसरे भाग में, बंबई के सतारा तथा अन्य दूसरे जिलों में किसानों से जमीन के निर्धारण लगानों की वसूली करने में हिसाबदारों को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने उनकी आवश्यक तथा अपेक्षित

सहायता नहीं की।¹³ 27 जुलाई 1890 के अंक में 'मराठा' ने बिलाप करने का निम्नलिखित देश में जमींदारों और भूस्वामियों की दुर्दशा के उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं। उसने सरकार की क्रमशः जमींदारों के अधिकारों के उन्मूलन की प्रवृत्ति की शिकायत की। उसने जमींदारों को और कुछ नहीं तो अपने को जीवित रखने के लिए परम्परा सन्निहित होने का परामर्श दिया। उसने दक्षिण के जमींदारों को तो विशेष रूप से ही अपना एक संघ बनाने की सलाह दी। 9 दिसंबर 1900 के अंक में इस पत्र ने सरकार से लगान वसूली में इनामदारों की सहायता करने का अनुरोध किया। यद्यपि इस बात को महाना अनुचित न होगा कि जमींदारों की सम्पत्ति और उनके अधिकारों की रक्षा की। अर्थात् कि पीछे यह भावना काम कर रही थी कि दलित भारतीय जनता का सत्तन नान्व नहीं जमींदार वर्ग ही कर सकता था।¹⁴

जैसा हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं कि जमींदार और किसानों के मध्य राष्ट्रवादियों के सामान्य विचार अत्यन्त मृदु है। वस्तुतः राष्ट्रवादी नेताओं ने किसानों के अधिकारों के बचाव के लिए जमींदारों के अधिकारों के बचाव के लिए भी काम किया। सरकार द्वारा 1880-1905 की अवधि में स्वीकृत कानूनों के प्रति उनके दृष्टिकोण के अध्ययन में भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। 1885 के बंगाल काश्तकारी कानून को छोड़कर इन नेताओं ने किसी भी अन्य काश्तकारी कानून में कोई गहरी या पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई।

1885 का बंगाल टेनेसी ऐक्ट

1793 के स्थाई बंदोबस्त ने किसानों को जमींदारों की दया पर ही छोड़ दिया था। 60 वर्षों में भी ऊपर समय बीत जाने के बाद सरकार का बंगाल के किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान गया। 1859 के लगान अधिनियम (अधिनियम संख्या 10) के अनुसार 12 वर्षों में ऊपर एक ही भूभाग के पट्टेदार किसानों को मौरूमि हक मिलाने का। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि इसके अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट और उचित आधाराओं को छोड़कर अन्य किसी भी रूप में लगान नहीं बढ़ाया जा सकता था। यह अधिनियम तथा 1869 का मशोघित अधिनियम जमींदारों और किसानों के मध्य पतपते तनाव को दूर न कर सके। जमींदारों ने किसानों को निकालने लगान में बराबर परिवर्तन करते रहने, बलपूर्वक उन्हें तग करने, अवैध रूप में उनकी कुर्की करने और उन्हें बेदखल करने आदि गंदे तरीके जारी रखे। उन्होंने किसी न किसी तरीके से किसानों को मौरूमि हक पाने में वचित करने में तथा लगान बढ़ाने में सफलता पाने के मार्ग निकाल ही लिए। एक ओर जमींदार पूर्ववत् धूर्तता करते रहे और दूसरी ओर यह शिकायत करते रहे कि 1859 और 1869 के कानूनों के अंतर्गत उनके लिए बालू लगान की वसूली अत्यंत कठिन हो गई है यहां तक कि सर्वथा उपयुक्त कारणों में भी लगान में वृद्धि तो लगभग असंभव हो ही गई है।¹⁵ फलतः 1872-76 में बंगाल में कृषकों और जमींदारों के बीच अनेक संघर्ष हुए और जमींदार विरोधी विप्लव हुए। ऐसा लगने लगा कि स्थिति किसी समय भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है।¹⁶ बिहार में

तो किसानों की स्थिति बंगाल के किसानों में भी अधिक खराब थी और किसानों के जमींदारों के साथ संबंध अत्यंत द्वेषपूर्ण थे।⁹ 1876 व. परवर्ती वर्षों में बंगाल सरकार और भारत सरकार ने स्थानीय बोरोवस्त के लक्ष्यवादी ढांचे का स्थिरता देने की दृष्टि से तथा स्वयं ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर राजनीतिक खतरों का आधार सिद्ध होने वाली प्रचलित कृषि क्रांति में राज्य सत्ता बचाने के लिए इस प्रश्न का कानूनसम्मत रूप देने के बराबर प्रयत्न किए। उस रोग का सीधा सादा और साफ उलाज यह था कि जमींदारों और किसानों के मध्यों को मुदत आधार दिया जाए, परन्तु इस उलाज को कार्य रूप देने के संबंध में अधिकांशियों के मन में अनेक शकाएँ, साच-विचार और तर्क-वितर्क थे। इस दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों के सर्वमान्य उद्देश्य थे बड़े हुए किसानों के लिए अधि-भाग अधिकारों का विस्तार करना, सुरक्षा के अधिभाग का विस्तार करना, अधिभागी अथवा दूसरे सभी प्रकार के किसानों का निर्धारित स्थिरता न मही, अनुचित रूप में लगान बढ़ाने में जमींदारों को रोक कर सुरक्षा प्रदान करना। इनके साथ ही लगान वसूली की मर्यादित मर्यादा, जुटाए गए जमीन की बड़ी हुई उपज में बड़े मूल्य के भाग के अनुरूप लगान बढ़ाने की प्रतिभूत जुटाए गए जमीन और उनका श्रमोत्पन्न पट्टेधारियों को उनके जिनो की सुरक्षा का आश्वासन देना और साथ ही साथ कृषि मजदूरी भगदों के उठने पर उन्हें दत्तगति और न्यायपूर्ण इस में निपटाने के लिए नियमा और व्यवस्थाओं का निर्धारण करना।⁹ परन्तु इन सभी सुधारों को तकर चलने वाले जमींदारों को व्यथित किए बिना कारगरों को सन्तुष्ट करने वाले वास्तविकी कानून का बनाना कठिन ही नहीं; अतः श्रमभव कार्य सिद्ध हुआ। 1878 में लगान कानून आयाग ने बंगाल में इस समस्या की जाच-पड़ताल की। आयोग ने 1880 में सरकारी और गैरसरकारी विस्तृत विचारों पर आधुन अपना प्रतिवेदन और कानून का प्रारूप प्रस्तुत किया।¹⁰ अगले वर्ष लगान कानून कमिशन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर आधुन होते हुए भी कितने ही जरूरी विषयों में उससे भिन्नता लिए हुए बिल का एक प्रारूप भारत सरकार के पास भेजा गया।¹¹ भारत सरकार ने इंग्लैंड के अधिकांशियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करने और अपना मत स्थिर करने में लगभग दो वर्ष लगा दिए। अंत में 1883 में उसने डीपीरयल लैजिस्लेटिव कौंसिल में इस विषय पर एक बिल पेश किया। इस बिल के साथ जुड़े हुए पांच महत्वपूर्ण मुद्दा थे (1) उन सभी किसानों को मौरूसी हक देना, जो एक ही गांव में अथवा जागीर में 12 सालों से धरती जोत रहे हैं। भले ही इस अवधि में भिन्न भिन्न कालों में उसके पास धरती के खंड भिन्न भिन्न क्यों न रहे हों। इसके साथ ही किसानों के मौरूसी हकों के नकारने को प्रमाणित करने का भार भी जमींदार पर ही डाला गया था, (2) मौरूसी हक को उत्तराधिकार का विषय बनाना और आसानी से हस्तांतरित किया जाने वाला हक बनाना, हालांकि जमींदार हकशुफा कह सकता था। मौरूसी किसानों को बेरोकटोक जमीन आगे लगान पर देने का अधिकार प्रदान करना, (3) लगान वृद्धि के संबंध में यह व्यवस्था करना कि किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली लगान की राशि उसकी कुल उपज का 1/5 भाग से अधिक न हो तथा दस वर्षों की अवधि के अंतराल से पूर्व लगान किसी भी रूप में दुगुना न किया जा सके। गैरमौरूसी किसान द्वारा चुकाए

जाने वाले लगान की राशि का उसकी कुल उपज के 5/16 भाग में अधिक का न होना। (4) गैरमौरूसी किसानों के जोत से हटाए जाने पर उसे मुआवजे का हक होना, तथा (5) लगान के मुकदमों की मरल और सक्षिप्त सुनवाई के साथ उनके शीघ्र निपटाए जाने की व्यवस्था के रूप में जमींदारों की प्रमुख शिकायत को दूर करना। इसके अतिरिक्त अदालत के माध्यम से फसल की बिक्री और कुर्की की व्यवस्था की गई। इन सभी महत्वपूर्ण धाराओं के लागू होने की निश्चितता के लिए दीवानी अदालतों के तथा कार्यकारी अधिकरण के हस्तक्षेप की भी इस बिल में व्यवस्था थी।¹¹

1883 के काश्तकारी बिल पर जमींदारों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। इस प्रकार मध्यम वर्गीय सरकार ने जमींदारों को शांत और सतुष्ट करने वाले परिवर्तनों का मुआवजा के लिए प्रबल समिति नियुक्त की। इस समिति में जमींदारों के दो महत्वपूर्ण प्रवक्ता क्रिस्तोदास पाल (उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर प्यारमोहन मुर्गर्जी को रखा गया) तथा महाराजा दरभंगा सम्मिलित थे।¹² इस समिति ने बिल का इस रूप में संशोधन किया कि उसका कृषक समर्थक आधार ही नामशेष हो गया। संशोधित बिल ने मार्च 1885 में कानून का रूप ले लिया। 1885 के काश्तकारी कानून में मौरूसी हक की प्राप्ति को संकुचित बना दिया गया। अब इस अधिकार को केवल उसी गांव में धरती जोतने तक सीमित कर दिया गया। पहले के 1883 के बिल में निहित 'उसी जमीन' में धारा को छोड़ दिया गया। 1883 के ही बिल द्वारा किसानों को हस्तान्तरण करने की दी गई पूर्ण शक्ति को भी इस बिल में छीन लिया। मौरूसी और गैरमौरूसी किसानों पर लगान बढ़ाने की सीमाएं भी हटा दी गईं। गैरमौरूसी किसानों का वेदगल करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था वाली धारा का भी इस बिल में हटा दिया गया। इस प्रकार 1883 के बिल की किसानों को लाभ पहुंचाने की संभावनावाली तीनों धाराओं को तो छोड़ ही दिया गया और मौरूसी अधिकार प्राप्ति में संबंधित धारा का हलका बना दिया गया। विरोधी दिशा में बिल का एकमात्र संशोधन इस रूप में था कि मौरूसी हक वाले किसान के लगान की वृद्धि को घटा दिया गया था। यह वृद्धि कचहरी के बाहर आपसी अनुबंध द्वारा 6 आने प्रति रुपये का बढ़ने का आन प्रति रुपये कर दी गई थी। 1885 का काश्तकारी अधिनियम मौरूसी किसानों के अधीनस्थ मुजारों का कोई संरक्षण नहीं दे सका था।¹³ अधिनियम के प्रथमको का दावा था कि यद्यपि इसमें जमींदारों को सुविधाएं जुटाने की व्यवस्था है तथापि जिस ढंग से अधिनियम को अंतिम रूप में निर्धारित किया गया है, उसमें किसान के अधिकारों को, अधिकृत भूमि पर उसके स्वामित्व को, एकपक्षीय स्वत्वापहरण के विरुद्ध उसके हितों की सुरक्षा को वास्तविक रूप में सुदृढ़ता प्रदान की गई है।¹⁴ उनकी राय में इस अधिनियम की निर्दोषता का सर्वोत्तम प्रमाण सैद्धांतिक रूप से इससे संबद्ध सभी प्रमुख वर्गों द्वारा शांतिपूर्वक इसकी स्वीकृति थी।¹⁵ दूसरों के विचार में 1883 में फ्लारेंस नाइटगेल द्वारा अभिव्यक्त भय, कि जमींदार अपने वर्ग को सुविधाएं पहुंचाने वाले बिल पास करा लेंगे और किसानों को मिलने वाली सुविधाएं छीन ली जाएंगी,¹⁶ सत्य सिद्ध हुआ है।¹⁷

जैसी आशा की जाती थी, जमींदार किसी भी ऐसे काश्तकारी कानून के पूर्णतः

विरोधी थे जिसमें किसानों को मौलगी हक देने की तथा धरती का हस्तान्तरण करने की शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था हो और लगान बढ़ाने के तथा किसानों का वेदखल करने के अधिकारों पर नियंत्रण हो व्यवस्था हो। उनका दावा था कि इस प्रकार का कोई कानून बनाना उनके स्वतंत्राधिकारों पर छापा मारना, उनके यश, सम्मान और निहित अधिकारों का धूमिल करना तथा 1793 की संधि का उल्लंघन करना होगा। उनकी यह भी धारणा थी कि अधिकारियों द्वारा विचारित कानून का रूप स्वयं किसानों के लिए हानिप्रद सिद्ध होगा क्योंकि इसका परिणाम निर्गुण मुसद्मेवाजी तथा उपपट्टेशजी होगा।

दमरी और इंडियन एसोसिएशन, बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों व उदीयमान नेता मुरेद्रनाथ बैनर्जी तथा बंगाल के बहुसंख्यक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने किसानों के समर्थन का पक्ष लिया। उन्होंने किसानों और जमींदारों के मध्य के संबंधों में सरकार के हस्तक्षेप करने के अधिकार को न्यायोचित ठहराया। किसानों के पक्ष में उस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा यह मानते हुए भी कि ये बिल किसानों की रक्षा की दृष्टि से अधिक मार्थर नहीं है, 1880-1883 की अवधि में पेश किए गए सभी वास्तविक बिलों के प्रारूपों को सामान्य स्वीकृति दी और इन बिलों के विरुद्ध जमींदारों द्वारा किए जा रहे युद्धों का विरोध किया।¹³ बंगाल के राष्ट्रवादी नवाजा का अपेक्षाकृत अधिक युवा और अधिक प्रगतिशील वर्ग तो सरकारी कानूनों के प्रति कोरे समर्थन को प्रकट करने में आगे बढ़ गया। उनमें से बहुतों ने बड़ी ही प्रवृत्तता के साथ किसानों के उद्देश्य का अनुमोदन किया और बंगाल के शिक्षित लोगों, राजनीतिक सम्प्रदायों और नेताओं से किसानों के हितों को वाणी देने तथा जमींदारों द्वारा संचालित शक्तिशाली आंदोलन का विरोध करने का अनुरोध किया। उदाहरणार्थ, 18 दिसम्बर 1880 के अफ मे बंगाली ने लिखा :

हमारे अपने सगठन है जा देश के लाचार किसानों के हितों की देखभाल तथा सुरक्षा का दम भरते है। हमें तो समझ ही नहीं आता कि आज के समाज देशभक्ति के व्यापार तथा वर्तव्य पालन का अपेक्षाकृत कोई और श्रेष्ठ अवसर अगले पचास वर्षों में कभी आएगा भी कि नहीं। मचमुच ही समय आ गया है कि ये सगठन अपनी उपयोगिता का प्रमाण दे तथा अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करे।¹⁴ बंगाल की बेबस कृषक जनता देश के लाखों निरीह लोग इतना भी तो नहीं जानते कि उनके चारों ओर हो क्या रहा है। यह उनके मित्रों का काम है कि वे उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दे, उनकी अगुआई करे तथा उनकी ओर से काम करें। आइंडर और बोधे प्रदर्शन का समय अब बीत गया है। अब तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हृदय से उत्साही हो, किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हों और उनके भाग्य को सवारने को उत्सुक हों। ऐसे व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिलों में जाएं। किसान के समर्थन में जनसभाएं करें और उसके पक्ष में प्रदर्शनों का आयोजन करें। अभावग्रस्त भोपडीवासी निम्नस्तरीय किसान की सेवा करने वाला अपने व्यापक रूप में देश की सेवा ही करता है।¹⁵

वस्तुतः बंगाली ने तो 3 जनवरी 1880 के अंक में किसानों का एक अंग होने का दावा किया। इंडियन एसोसिएशन ने आगे बढ़कर किसानों की आवश्यकताओं और शिकायतों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के पवित्र कर्तव्य के निर्वाह की प्रतिज्ञा की।¹⁴ इंडियन एसोसिएशन तथा अन्य कतिपय महानुभावों, द्वारिबानाथ गागुली, कृष्णकुमार मिश्र और रंगलाल मुखर्जी आदि ने व्यक्तिगत रूप से किसानों को अपनी मांगों के लिए अपने आप आंदोलन करने के लिए संगठित करने का बीड़ा उठाया। संगठन के अधिकारी तथा अन्य किसानों में सहानुभूति रखने वाले बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और उन्होंने 1880, 1881 और 1885 में असह्य किसान प्रदर्शनों तथा किसान जनसभाओं का आयोजन किया। कुछ सभाओं में तो दस में बीस हजार तक किसान सम्मिलित हुए और इन सभाओं में सुरेन्द्रनाथ बैंजर्जी, आनन्दमोहन बोस तथा द्वारिकानाथ गागुली जैसे वक्ताओं ने भाषण दिए।¹⁵ अनेक स्थानों पर लगान संघों तथा किसान संघों की स्थापना भी हुई।¹⁶ वस्तुतः इंडियन एसोसिएशन ने इन संघों का उपयोग देशान्त में अपनी शाखाओं के ज्ञान बिछाने और राजनीतिक गतिविधि का विस्तार करने के लिए ही किया।¹⁴

1883 के बंगाल टेनेसी बिल को देश के अन्य भागों के गण्यमान्य नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ। विशेषतः बाल गंगाधर तिलक अथवा जी० जी० आगरवाल द्वारा बिल के समर्थन में लिखित तथा 1883 में मराठा में प्रकाशित मंपादकीय लख मचमुच विस्तृत रूप में उद्धृत करने योग्य है क्योंकि इनमें राष्ट्रीय नेताओं के उच्च पदाधिकारियों के कृषि संबंधी क्रांतिकारी दृष्टिकोण के प्रारंभिक लक्षण देखने को मिलते हैं। 14 अक्टूबर 1883 के अंक के मंपादकीय ने गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता तथा मानवता के प्रति छलकते प्रेम के सहानुभाव के रूप में बिल की प्रशंसा करने हुए घोषित किया कि भौतिक सुख सुविधाओं के समान विनय का यह एक छोटा सा प्रारंभ है जो प्रगतिशील समाज में एक न एक दिन अवश्य पूरा होगा। सरकार में अपने व्यापक कार्य पर मुद्द बने रहने का अनुरोध करते हुए मंपादकीय ने सलाह दी कि उस श्रेष्ठ कार्य के विरुद्ध निहित स्वार्थी वर्ग चिन्ताएँ परंतु दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता इसी में है कि शक्ति, संपत्ति और संरक्षकता के हाथ में जाने वाले लोगों द्वारा अपनाए गए धमकी भरे व्यवहार की उपेक्षा की जाए, उसके आगे झुकना न जाए। मंपादकीय में यह निर्देश दिया गया कि यदि जमींदारों के पास मृष्टि के प्रारंभ काल में स्वत्वाधिकार होते तो भी समय की गति के साथ उनमें संशोधन करना ही पड़ता। इसके अनिश्चित सरकार जमींदारों के निहित हितों को बनाए रखने के लिए तब तक बाध्य है जब तक वे लोकहित के मार्ग में आड़े नहीं आते। जब समाज कल्याण के लिए खतरा उपस्थित हो तो इन अधिकारों में संशोधन एक तकाजा बन जाता है। जब उपयुक्त समय आ जाए, परिस्थितियाँ अनुकूल हो तब परिवर्तन तो समाज में अपना मार्ग आप ही बनाएगा तथा समाज पर अपने को बलपूर्वक ही थोपेगा, भले ही समाज के कुछ सदस्य उसे न चाहें। जमींदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर 'मराठा' ने 21 अक्टूबर 1883 के अंक के मंपादकीय में दिया। जमींदारों की इस धारणा का कि काश्तकारी कानून के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, उत्तर देते हुए मंपादकीय ने टिप्पणी की कि प्रत्यक्ष और तात्कालिक क्षतिग्रस्त व्यक्ति कभी

यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके अधिकारों को छीनने का उपयुक्त समय आया है अथवा कभी आएगा। सारे विश्व में खतिहरों के दुर्भाग्य पर रुदन करने हुए मंपादकीय में लेखक ने लिखा।

प्रमुख कारण कुछ भी हो, चाहे खेत में बरीयता हो अथवा न्यायालय में प्रीयता हो, उसमें समाज के एक वर्ग पर कमरतोड़ कठोर श्रम और दानता लाद दी है तथा इसमें वर्ग को पूर्ण आराम तथा शारीरिक श्रम में मुक्ति का वरदान दे दिया है परन्तु अब यह पूर्ण रूप में नितान्त स्पष्ट हो गया है कि आधुनिक सभ्यता तथा समता की पतनी भावना उन दोनों वर्गों के मध्य अग्रमान और न्यायपूर्ण संबंधों को लंबे समय तक बने नहीं रहने देगी। समाज की पुनर्स्थापना का दिन या देश मंच पर आना निश्चित है। अच्छा हो कि हम बुटबुटाने अथवा गिरावा भिक्वाण करने के बदले उस दिन के स्वागत के लिए ही अपने आप को तैयार कर लें।

लेखक ने घोषणा की कि यदि उस पर छोड़ दिया जाए तो वह अधिक शक्तिशाली साधन प्रस्तुत कर सकता है जिसके अनुसार जमींदार किसानों को राहत दी जा सके को विवश हो जाएंगे। 18 नवंबर 1883 के अंक में 'भगठा' न पुनः अत्युच्च नित्यता का स्वर अपनाया और घोषणा की कि बिल सत्रार्थी गये मतभेद के विषय में विचारणीय विषय यह है कि क्या हम सुस्त, आलसी और सुप्तगोंगे का एक ऐसा वर्ग बनाए रखना चाहते हैं जो दूसरे आदमियों के श्रम के फल से तो डकारें मारें, इसमें वे श्रम में अजित धन पर गुलछरें उड़ाए परन्तु इस बात की तरफ भी चिन्ता न कर दें कि जिस श्रम पर वह चलता है, मर्दों से छिड़कर तथा खाद्य पदार्थों के अभाव में भूखे मरते हैं। 6 जनवरी 1884 के अंक में उसने जमींदारों को चेतावनी देना शुरू किया कि जमींदारों के पास पैसा है और उस पैसे के फलस्वरूप उनके पास प्रभाव और शक्ति है, इसके विपरीत दूसरी ओर किसान निस्संदेह निर्धन, दुर्बल और अवाकफ परन्तु किसान सदैव इस रूप में नहीं बना रहेगा यदि जमींदार समय पर नहीं चेते तो जब कभी भी किन्तु एक बहुत बुरा जोर का झटका उन्हें अवश्य लगेगा और वह झटका जमींदारों को बिलकुल झुल कर रख देगा।¹⁵ 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने भी अपने 25 मार्च 1883 के अंक में बिल पर इसी प्रकार के जमींदार विरोधी और किसान समर्थक विचार प्रकट किए।¹⁶ 25 मार्च तथा 1 अप्रैल 1883 के अंकों में 'नेटिव ओपीनियन' ने भी बिल पर इसी प्रकार की धारणा व्यक्त की।¹⁷ बंगाल के बाहर के भी कितने ही पत्रों ने बिल का समर्थन किया।¹⁸ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि जस्टिस रानाडे ने बंगाल टेनेसी ऐक्ट का इस पुस्तक के एक अलग भाग में आगे विवेचित आधारों पर विरोध किया तथापि उन्होंने किसानों की पूर्ण सहायता के लिए उपचार स्वरूप कानून की तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ण रूप में अभिस्वीकार ही नहीं किया प्रत्युत 1793 के विनियम होने पर भी इस कानून को बनाने के सरकारी पक्ष को न्यायोचित घोषित किया।¹⁹ यहाँ यह भी बनाना उचित होगा कि सरकारी अधिकारी के रूप में आर० सी० दत्त ने बंगाल में किसान अधिकारों को लागू करने के एंशले ईडन के प्रस्तावों का पूर्ण रूप से समर्थन किया।²⁰

बंगाल और बिहार में राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने जमींदारों का पक्ष लिया तथा

1881 और 1883 के काश्तकारी बिलों का विरोध किया। कई मामलों में यह विरोध खुले तौर पर ही किया गया।⁵¹ 'अमृत बाजार पत्रिका' और उसके बंगाली प्रतिरूप 'आनंद बाजार पत्रिका' ने सामान्यतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाया परंतु उनके विरोध के आधार भिन्न थे। उन्होंने पितृवादी तर्क प्रस्तुत किया जो परिणाम में जमींदारों के पक्ष में जाता था। उदाहरणार्थ उनका एक तर्क था कि किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप से जमींदारों और किसानों के मध्य मैत्री और सौहार्द के संबंधों को धक्का पहुंचेगा। 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 8 जनवरी 1885 के अंक में बड़े सकोच और हिचकिचाहट के साथ इस तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया :

जमींदार और किसान से संबंधित विषय पर हमारा सिद्धांत पक्ष यह है कि किमानों के जोत संबंधी अधिकारों की स्पष्ट और संतोषप्रद परिभाषागत व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उन्हें छोटी भूपट्टी के प्रयामों के विरुद्ध बचाया जा सके परंतु इसके साथ ही दोनों को परस्पर सामाजिक सद्भाव और महानुभूति से बांधने वाले तथा समय की कमौटी पर खरे मिद्ध हुए बंधनों को निर्ममतापूर्वक टूटने नहीं देना चाहिए। मक्षेप में जमींदारों को इस स्थिति में रखा जाए कि वे किसानों से सत्ता न सकें परंतु इसके साथ ही किसानों को भी जमींदारों को नकारने के लिए और सामाजिक परंपराओं में उनके महत्व को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जमींदार अपना हित किसान से स्नेह करने में और किमान अपना हित जमींदार का आदर करने में अनुभव करें।⁵²

कभी कभी तो उन्होंने यह अनुभव किया कि बंगाल के जमींदारों पर प्रहार एक प्रकार से देश में एकमात्र अवशिष्ट संपन्न और नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्ग पर ही आक्रमण था।⁵³ परंतु उनके विरोध का प्रमुख आधार उनका यह विश्वास था कि प्रस्तावित उपायों में जमींदार और किमान के बीच के बिचौलियों, मध्यवर्ती किसान तथा मानिक, के हितों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी।⁵⁴

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब जमींदारों ने अलबर्ट बिल के विरुद्ध विप्लवावादी आंदोलन चलाने वाले बंगाल के अंगरेजों से अपने पक्ष में समर्थन की मांग की तो अमृत बाजार पत्रिका तक ने तथा अन्य जमींदार समर्थक राष्ट्रवादी पत्रों ने जमींदार विरोधी पत्रों का साथ दिया और जमींदारों की इस कार्यवाही की निंदा करते हुए उसे देश के प्रति विश्वासघात, वचन भंग, दुष्चापन तथा निर्लज्ज व्यवहार बताया।⁵⁵

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों और तत्कालीन नेताओं द्वारा प्रस्तावित काश्तकारी बिल के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की भिन्नता का आधार उनकी सहानुभूति के पात्र जमींदार, बिचौलिया अथवा किमान की भिन्नता थी।

जमींदार समर्थक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने मौरूसी अधिकारों के विस्तार संबंधी व्यवस्था⁵⁶ का मौरूसी हक के हस्तांतरण की व्यवस्था का,⁵⁷ लगान की वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था का⁵⁸ तथा गैरमौरूसी किसानों को बेदखल करने पर उन्हें क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था⁵⁹ का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि यदि लगान पर सीमा ही लगानी है तो उसकी अपेक्षाकृत अधिकतम ऊंची सीमा निर्धारित करनी चाहिए।⁶⁰

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों के एक समूह ने सोच समझकर ही ताल्लुकेदार जेतदार जैसे बिचौलियों के हितों की बकालत की। उदाहरणार्थ, 'अमृत बाजार पत्रिका' ने खुले आम बिचौलियों के हितों का समर्थन किया तथा उन्हें बंगाली समाज का आधार और भविष्य बताया।⁶⁰ ए. आनंद बाजार पत्रिका का तर्क था कि सरकार जो प्रस्तावित अधिकार सभी किसानों को देना चाहती है, यदि वे अधिकार बिचौलियों को दिए जाएं तो उनका अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है क्योंकि ये बिचौलिये पट्टेदार उल्लेखनीय रूप से उन सभी दोषों से मुक्त हैं जो किसानों और जमींदारों में प्रायः पाए जाते हैं। ये लोग जमींदारों में अपेक्षाकृत अच्छे हैं और वे जमींदारों और किसानों की अपेक्षा धरती में प्रत्यक्ष और गहरी रुचि लेते हैं। ये एक माध्यम किसान की अपेक्षा अधिक समृद्ध और सुशिक्षित हैं अतः भूमि सुधार और वैज्ञानिक साधनों के उपयोग में अधिक सक्षम हैं। साथ ही, ये लोग जमींदारों के दमन का रोकने में भी पर्याप्त समर्थ और शक्ति संपन्न हैं। इसके अतिरिक्त ये किसानों में अपना प्रत्यक्ष संबंध भी बनाए रखते हैं। इन्हें किसानों के साथ संबंध के लिए चपरासियों, नायबों और दिवानों आदि का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।⁶¹ जब एक बार इस समाचारपत्र को यह विश्वास हो गया कि यह बिल इन बिचौलियों पट्टेदारों के हितों में द्विज जाता है तो उसने 1883 के काश्तकारी बिल का विरोध किया।⁶² इस पत्र ने यह भी देखा कि ये बिचौलिये सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बंगाल के एक महत्वपूर्ण वर्ग में सम्बन्धित थे। बहुत से मध्यवर्गीय बंगाली, छात्र, वकील, क्लर्क, डाक तथा पुलिस अधिकारी, इसी बिचौलिये वर्ग में सम्बन्ध रखते थे और यह वर्ग स्वशासन के आंदोलन का आधार था।⁶³ बंगाली ने 17 मार्च 1883 के अंक में बंगाली समाज की गीठ की हड्डी बने इन बिचौलियों के हितों की सुरक्षा करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने का समर्थन किया। इस पत्र ने इस समर्थन के साथ यह भी सकेत किया कि यह कार्य काश्तकारी बिल द्वारा पहले ही किया जा चुका है। वगवासी, नवविभाकर, भारत मित्र, तथा माधारणी आदि ने भी बिचौलियों को अधिकार देने के पक्ष का समर्थन किया।⁶⁴

किसानों के पक्ष के समर्थक भारतीय नेताओं ने काश्तकारी बिल की काश्तकारों के अधिकारों को विस्तृत करने वाली धाराओं का अनुमोदन किया, इन अधिकारों को और सुदृढ़ बनाने की बकालत की तथा किसानों के हित के विरोधी दिखाई देने वाले तत्वों की आलोचना की। प्रथम, उन्होंने व्यापक और स्थाई आधार पर मौरूसी हक देने वाली व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया।⁶⁵ उन्होंने इस दिशा में और अधिक बड़ी सुविधाओं की मांग की।⁶⁶ द्वितीय, उन्होंने मौरूसी हक को हस्तांतरित किया जा सकने वाला बनाने तथा उसे उत्तराधिकार का रूप देने का पूरा पूरा समर्थन किया।⁶⁷ तृतीय, उन्होंने जमींदार के लगान बढ़ाने के अधिकार पर प्रस्तावित प्रतिबंध का स्वागत किया।⁶⁸ कइयों का तो विचार था कि प्रतिबंध वांछनीय रूप में नहीं है और अधिकतम निर्धारित सीमा भी बहुत ऊंची है।⁶⁹ कुछ ने मांग की कि जब भूमि के सुधार में जमींदार का कोई योगदान ही नहीं है तो उसे लगान बढ़ाने की अनुमति क्यों दी जाए।⁷⁰ कुछ ने तो जमींदार और किसान के मध्य स्थाई रूप से लगान के निर्धारण की मांग की।⁷¹ चतुर्थ, गैरमौरूसी हकवाले किसानों

को जमींदारों द्वारा बेदखल करने पर किसानों को जमींदारों द्वारा क्षतिपूर्ति की प्रस्तावित व्यवस्था का भी उन नेताओं ने अनुमोदन किया।⁷² कुछ नेताओं ने यह प्रस्ताव किया कि जमीनों के लगान और इसकी वृद्धि के संबन्ध में मौरूसी और गैरमौरूसी हकवाले किसानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।⁷³ पंचम, किसानों में लगान के आसान तरीकों से वसूली की सुविधाएं जमींदारों को प्रदान की जानी चाहिए।⁷⁴ जमींदारों को फसल की कुर्तियों का अधिकार दिए रखने का यह अभिप्राय होगा कि वे किसानों का दमन करते रहेगे।⁷⁵

राष्ट्रवादी नेताओं के इस वर्ग ने 1883 के टेनेसी बिल के एक विशिष्ट पक्ष के प्रति कि इससे उपकाशनकारी के प्रसार के निवारण में कोई सहायता नहीं मिलती है तथा इससे मौरूसी हक प्राप्त किसानों के अधीनस्थ काश्तकारों के हितों को सुरक्षा नहीं मिलती है, ऐसा तीखा आलोचनात्मक और लगभग आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया कि बंगाल के ग्रामों में कालांतर में घटित घटनाओं के मदर्भ में इस आलोचना को एक अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया है।⁷⁶ अतः उसकी हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

इन नेताओं ने निर्देश किया कि 1883 के बिल के विभिन्न प्रावधानों, मौरूसी हक को व्यापक बनाने, मौरूसी हक को हस्तान्तरण का विषय बनाने तथा किसानों को जमीन को आगे लगान पर देने का अधिकार देने का परिणाम यह निकलेगा कि बिचौलिया वर्ग बड़े पैमाने पर उभर कर अस्तित्व में आ जाएगा जो जमींदार की अपेक्षा किसानों का अधिक दमन करे और उनमें बहुत ऊँचे लगान वसूल करे। इस प्रकार असली धरती जगतने वालों की बहुत बड़ी समस्या तो अधिकारहीन और सर्वथा असहाय तथा अधीनस्थ किसान बनकर रह जाएगी।⁷⁷ इस सबका कारण उनके विचार में यह था कि इस बिल में न तो धरती के असली जोतने वालों के समुचित सुरक्षण की कोई व्यवस्था थी और न ही 'किसान' शब्द का उपयुक्त विश्लेषण किया गया था। ग्राम उनकी मांग थी कि इस नए वर्ग के विकास को अवश्यमेव रोकना चाहिए। परन्तु यह कार्य कैसे हो? इस मद्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जमींदार मौरूसी हक के हस्तान्तरण के विरुद्ध इस आधार पर थे कि उनके अनुसार इसके परिणामस्वरूप जमीन मूदखोर बिचौलियों के हाथों में पड़ जाएगी। नेताओं के जिम वर्ग के विचारों का हम यहां विश्लेषण कर रहे हैं वह बिचौलियों के विरुद्ध इसलिए था कि यह वर्ग जमींदारों के नहीं परन्तु किसानों के हितों के प्रतिकूल था। अतः उन्होंने जमींदारों द्वारा अपनाई गई स्थिति को मानने से इनकार कर दिया और इसके विपरीत मौरूसी हक के हस्तान्तरण का इस आधार पर समर्थन किया कि इससे किसानों को महायता मिलेगी। इसके साथ ही इसके परिणामस्वरूप बिचौलियों के विकास की संभावना को निर्मूल करने तथा उपकाशनकारी को निरुत्साहित करने के लिए उन्होंने कुछ अन्य उपचार भी सुझाए जो किसानों के अनुकूल और जमींदारों, बिचौलियों तथा मूदखोरों के प्रतिकूल थे। सर्वाधिक व्यापक लोकप्रिय उपचार था कि मौरूसी हक असली खेत जोतने वालों को मिलना चाहिए। नाम के लिए जमीन के स्वामी को नहीं। इसके साथ ही उनका कथन था कि जब कभी जितने समय के लिए मौरूसी

हक प्राप्त किसान अपनी सारी धरती को अथवा उसके कुछ भाग को लगान पर चढ़ाता है, उतनी अवधि के लिए उसे अपने मौरूसी हक से वंचित कर देना चाहिए और उसके बदले असली जोतने वाले उपकाशतकार को ही यह अधिकार मिल जाना चाहिए।⁷⁶ 10 नवंबर 1883 के अंक में सजीवनी ने और 12 नवंबर 1883 के अंक में नवविभाकर ने उपकाशतकारी पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने की माग की।⁷⁹ नवविभाकर ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्वक स्वयं हल जोतनेवाले किसान की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की, 'क्या यह कानून बनाना ठीक नहीं होगा कि जो स्वयं अपने हाथों अथवा नौकरों के माध्यम से हल नहीं जोतता, जोत के हानि-नाभो का प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं बनता, किसान कहलाने का हकदार नहीं है और इसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मौरूसी हक प्राप्त नहीं कर सकता।' 13 मार्च 1883 के अंक में 'बंगाली' ने जमीन की जोतो की सीमा निधारित करने वाले आज के प्रस्ताव के महत्व का पूर्वाभास करते हुए सिफारिश की कि किसी भी काशतकार को समुचित और नियमित रूप से जोतने के लिए अपेक्षित माधनो की उपलब्ध पर्याप्तता से अधिक धरती रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अंतिम, कुछ कृषक समर्थक समाचारपत्रों ने प्रस्ताव रखा कि मौरूसी हकदार किसान द्वारा और गैरमौरूसी हकदार किसान द्वारा चुकाए जाने वाले लगान का अंतर इतना थोड़ा हो कि कोई भी मौरूसी हकदार किसान अपनी धरती को किराए, पट्टे पर देने में किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति की सम्भावना ही न देखे।⁸⁰

1884 की प्रवर समिति और भारत सरकार द्वारा 1883 के काशतकारी बिल के तीन प्रमुख सिद्धान्तों पट्टे की स्थिरता, न्यायसंगत लगान तथा स्वतंत्र रूप में बिक्री का अधिकार, में कतरव्योत किए जाने की किमानममर्थक गण्ट्रवादी नेताओं ने इन परिवर्तनों के विरुद्ध रोषपूर्ण आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों के हितों के साथ विश्वासघात करने के लिए और जमींदारों के हितों के अनुरूप बिल में संशोधन करने के लिए विशेषतः मौरूसी हक प्राप्त करने संबंधी, प्रस्तावित करने संबंधी धाराओं को पानी में डालने तथा लगान वृद्धि को सीमित करने वाली और बेदखली की हालत में क्षतिपूर्ति करने वाली व्यवस्थाओं को छोड़ने के लिए सरकार की आलोचना की।⁸¹ कुछ लोगों का विरोध तो इस सीमा तक पहुंच गया कि वे संशोधित बिल को स्थगित करने की ही माग करने लगे क्योंकि उनका विचार था कि किसानों के दृष्टिकोण से यह बिल न केवल असंतोषजनक प्रत्युत उनके हितों के प्रतिकूल भी था।⁸² अंत में किसानों के पक्षधर, जो इस बिल के आलोचक थे, केवल इसी विश्वास से इसका समर्थन करने लगे कि कुछ भी न होने से तो कुछ होना अच्छा है।⁸³ इसके अतिरिक्त बहुतों ने यह अवश्य अनुभव किया होगा जैसा 'साधारणी' ने अपने 5 जुलाई 1885 के अंक में लिखा 'यद्यपि काशतकारी अधिनियम संतोषप्रद नहीं है तथापि इसके अंतर्गत प्रमुख सिद्धान्त कृषकों के अनुकूल है अतः यह अधिनियम इस रूप में किसानों के अन्यान्य हितों तथा अधिकारों के आंदोलन के लिए आधारशिला का कार्य करेगा।⁸⁴ यहाँ यह उल्लेखनीय है जो संभवतः आश्चर्यजनक ही है कि वस्तुतः हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि से संबंधित 1885 के परिवर्ती बीस वर्षों की अवधि में बंगाल में इस संबंध में कोई आंदोलन नहीं हुआ। साथ ही यह निष्कर्ष

निकालना भी बिलकुल सही होगा कि भारत सरकार बंगाल और बिहार के जमींदारों के आगे उनके द्वारा डाले गए दबाव के कारण झुकी न कि इस कारण कि किसानों के पक्ष में अपेक्षित समर्थन तथा बंगाल के उभरते बहुसंख्यक राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध का अभाव था। वस्तुतः राष्ट्रवादियों का एक वर्ग सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील और अधिक दूरदर्शी था। जब बहुत सारे सरकारी अधिकारी उपकास्तकारी को देहाती बेरोजगारों का एक सुरक्षित सहारा अथवा अधिक से अधिक एक अपरिहार्य रोग मानते थे, इन नेताओं ने उपकास्तकारी को रोकने के लिए और मजदूर किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया।⁸⁵

पट्टेदारी संबंधी कानून, 1880-1905

1881 के उत्तर-पश्चिमी प्रांतीय लगान अधिनियम (नार्थ-वेस्टर्न प्राविसेज रेंट ऐक्ट) पर राष्ट्रवादियों की कोई भी टिप्पणी उपलब्ध नहीं।⁸⁶ 'जरनल आफ दि पूना सार्वजनिक सभा' में अप्रैल 1881 में बिना नाम से प्रकाशित एक लेख में 1883 में कानून का रूप ग्रहण करने वाले मध्य प्रदेशीय प्रांतों के कास्तकारी बिल की तीखी आलोचना की गई।⁸⁷ लेखक ने बिल की उन व्यवस्थाओं पर आपत्ति की जिनके अंतर्गत मालगुजारों के लगान बढ़ाने की शक्तियों को सीमित किया गया था, विशेषतः सरकार अपने राजस्व की मांगों पर इस प्रकार की कोई सीमा लगाने के पक्ष में नहीं थी, लगान वसूली में किसानों को कष्ट देने पर तथा उन्हें बेदखल करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेखक ने उन व्यवस्थाओं की भी निंदा की जिनका संबंध गैरमौरूसी किसान को बेदखल करने पर भूमिमुधार की क्षतिपूर्ति करना था तथा मौरूसी हकों को व्यापक रूप देना था।⁸⁸ लेखक ने सैद्धांतिक रूप में यह मान लिया था कि जमींदारों और किसानों के संबंध किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नियमित नहीं किए जा सकते, इन्हें तो किसी प्रतियोगिता पर छोड़ देना पड़ेगा।⁸⁹ व्यायमुध्दा ने भी जमींदारों के दृष्टिकोण से सेंट्रल प्राविमेज टेनेंसी बिल की आलोचना की।⁹⁰ दूसरी ओर बंगाली ने बिल का समर्थन तो किया परंतु यह अनुभव किया कि किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में बिल पर्याप्त नहीं है।⁹¹ जब सरकार ने बाद में 1883 के सी० पी० टेनेंसी ऐक्ट को थोड़ा और अधिक किसानों के अनुकूल बनाने की इच्छा से उसमें परिवर्तन का प्रयत्न किया तो 'मराठा' ने अपने 29 सितंबर 1889 के अंक में जमींदारों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का सरकार की नीति के प्रति विरोध किया।

राष्ट्रवादी नेताओं ने 1886 के अवध रेंट ऐक्ट पर तथा पंजाब कास्तकारी अधिनियम पर अपने विचार प्रकट नहीं किए।

1885 के बंगाल टेनेंसी ऐक्ट में संशोधन का बिल 1897 में पेश किया गया और 1898 में पारित किया गया। इससे उल्लेखीन रूप से ही बंगाल में नाममात्र का मतभेद उभरा। 'ढाका प्रकाश' और 'बंगबासी' ने इस बिल के प्रति जमींदार समर्थक दृष्टिकोण अपनाया⁹² तो 'बंगाली' और 'हितवादी' किसान समर्थक ही बने रहे।⁹³ बंगाल विधान परिषद में मुरेंद्रनाथ बैनर्जी और कालीचरण बैनर्जी ने अपने विचार में किसानों के हितों

के विरुद्ध जाने वाले बिल के पक्षों के विरुद्ध भाषण दिया।⁹⁴ एन० एन० सेन ने इन दोनों महानुभावों के साथ बिल के संशोधन तक का प्रयास किया ताकि किसानों के अधिकारों को और अधिक दृढ़तापूर्वक सुरक्षित किया जा सके।⁹⁵

16 अप्रैल 1884 के अंक में 'हिंदू' ने और 15 फरवरी 1888 के अंक में 'स्वदेशमित्र' ने 1880 के दशक में मद्रास के जमींदारीवाले इलाकों में किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों को अनावश्यक घोषित किया।⁹⁶ 'हिंदू' ने अपने 27, 28 और 30 मई और 23 जून 1898 के अंकों में 1898 के मद्रान टेनेसी बिल का अनुमोदन किया। 'हिंदू' ने यह अवश्य अनुभव किया कि बिल की व्यवस्थाएं किसानों के हितों का पर्याप्त सीमा तक संरक्षण नहीं करतीं। उसकी इच्छा थी कि सभी किसानों को सदा के लिए मौरूसी हक दे देने चाहिए क्योंकि जमीन के वास्तविक मालिक वे ही थे न कि जमींदार। मद्रास विधान परिषद में राष्ट्रवादी सदस्यों ने दुर्लभ स्थिति इस्तिथार की।⁹⁷

मालाबार के जमींदारों द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों की बेदखली रोकने के उद्देश्य से 24 जनवरी 1890 को 'मालाबार कंपनसेशन फार टेनेंट्स इंप्रूवमेंट बिल' (किसानों की स्थिति में सुधार के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने वाला मालाबार का बिल) प्रस्तुत किया गया। मालाबार की प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रिका 'केरल पत्रिका' इस विषय पर चालू कानूनों के विरुद्ध वर्षों से शिकायत करती आ रही थी, बार बार होने वाले मोपला विद्रोहों के लिए जमींदारों द्वारा उत्पन्न गरीबी को उत्तरदायी बताती आ रही थी तथा मालाबार के किसानों को धर्ती पर किसी न किसी प्रकार के मौरूसी हक देने की मांग करती आ रही थी।⁹⁸ उसने 'केरल संचारी' और 'केरल चंद्रिका' आदि पत्रिकाओं के साथ इस बिल का बड़ी ही तत्परता और सक्रियता से समर्थन किया।⁹⁹ दूसरी ओर 'हिंदू' और 'मनोरमा' ने बिल का विरोध किया।¹⁰⁰ मद्रास विधान परिषद के राष्ट्रवादी सदस्यों, सी० विजयराघवाचारी, जी० वेंकटरमन और पी० रत्नसभापति पिन्लई ने भी बिल का विरोध किया।¹⁰¹ सी० विजयराघवाचारी की एक आपत्ति यह थी कि बिल में केवल मालाबार के 'करनोमदार' पट्टेदारों के संरक्षण की व्यवस्था थी, जबकि ये लोग वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के साहूकार थे और किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे। बिल में वास्तविक किसान की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही न थी। उन्होंने घोषणा की कि यही बात है कि इस बिल का समर्थन नंबूदरी जमींदारों और असली हल जोतने वालों के बीच के नायर बिचौलियों द्वारा ही किया जा रहा है।¹⁰²

जमींदारों के दृष्टिकोण से 'तोहफा ए हिंदू', 'नसीमे आगरा', 'अनीसे हिंदू' और 'प्रयाग समाचार' ने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लगान अधिनियम में संशोधन के प्रयत्नों का विरोध किया। 'अवध पंच' ने किसानों की दृष्टि से समर्थन किया। 'हिंदुस्तानी' ने जमींदारों के लक्ष्य के प्रति अपना झुकाव दिखाते हुए भी बीच की स्थिति अपनाए रखी।¹⁰³ 'इंडियन डेली मेल' ने अपने 25 अक्टूबर 1901 के अंक में 1901 के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लगान बिल को पूर्ण समर्थन दिया।¹⁰⁴ परंतु कुल मिलाकर प्रांत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जमींदार समर्थक दृष्टिकोण ही अपनाया। उन्होंने जमींदारों की मांग पूर्ति की दृष्टि से बिल के संशोधन के लिए दबाव डाला तथा बाद में पर्याप्त परिमाण में उद्देश्य की पूर्ति न

होने पर अधिनियम की आलोचना की।¹⁰⁸

1898 और 1904 की अवधि में बंबई सरकार ने रत्नगिरि जिले में खेतों और उनके किसानों के मध्य के संबंधों के जटिल प्रश्न पर कानून बनाने का एक प्रयास किया। इस संबंध में उत्पन्न मतभेद की स्थिति में बंबई के राष्ट्रवादी नेताओं ने निश्चित रूप से खेत समर्थक दृष्टिकोण ही अपनाया।¹⁰⁹

किसान और साहूकार

ग्रामीण भारत की तीसरी मुसीबत ये गांव के साहूकार अथवा कर्ज देने वाले बनिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ग्रामीण कर्जदारी इतनी तेजी से बढ़ गई कि वह ग्रामीण क्षेत्र की विषमता समस्या बन गई। ग्रामीण ऋणदाता साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली, आसमान को छूने वाली ब्याज की दर ने दो प्रमुख रोगों को जन्म दिया : ब्याज के भुगतान किसान की आय का बहुत बड़ा भाग हड़प जाते थे और किसान की प्रायः ही ऋण की वापसी में असमर्थता के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि हल न चलाने वाले ऋणदाता साहूकारों के हाथ में चली जाती थी। इस प्रकार पुराना किसान साहूकार की मरजी पर पट्टेदार बन गया था और इसका अवश्यभावी परिणाम यह निकला कि कृषि और कृषक दोनों की हानत पहले से अधिक बिगड़ गई।¹⁰⁷

ग्रामीण कर्जदारी की समस्या के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का रवैया प्रायः कुछ जटिल, बहुमुखी और उभयपक्षी और कभी कभी विपरीत था। जहा ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने साहूकार और उसके ब्याज की ऊंची दरों को किसान की निर्धनता और कर्जदारी के प्रमुख कारणों में से एक माना,¹⁰⁸ वहा भारतीय नेताओं का विश्वास था कि ऋणदाता साहूकार खेतिहरों की गरीबी और ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण न होकर गौण कारण ही था। इस मवध में उनकी आशंका यह थी कि साहूकार को ही इस अपराध का प्रमुख और एकमात्र कारण बनाना किसान की गरीबी और ऋणग्रस्तता के वास्तविक और मूल कारणों से ध्यान हटाने जैसा था।¹⁰⁹ उनकी धारणा थी कि इस प्रश्न को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि किसान को साहूकार के पास आना ही क्यों पड़ता है ? साहूकार के पाम रुपया उधार लेने के लिए जाना किसान के लिए कोई खुशी अथवा फायदे की बात तो है नहीं।¹¹⁰

उनके अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्तता में चौकानेवाली वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक भारतीय किसान की निर्धनता भी थी। भारतीय किसान को अपनी घरती से पर्याप्त आजीविका नहीं मिल पाती थी फलतः वह अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए, विशेषतः तंगी के दिनों में, ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेने को बाध्य था। इस प्रकार किसान के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह भूखों मरे या साहूकार की शरण में जाए।¹¹¹ उनके विचार में ऋणग्रस्तता का दूसरा कारण था, लगान की ऊंची दर के साथ साथ निश्चित तथा कठोर भूराजस्वपद्धति। उन्होंने घोषित किया कि अधिकांशतया किसान सरकार के लगान का भुगतान करने के लिए ही ऋण लेते थे। 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 12 जून 1884 के अंक में लिखा : 'खून चूसने वाला ऋणकर्ता साहूकार सरकारी भूराजस्व

पद्धति की ही उपज है। साहूकार का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार लगान से दबे किसान को संकट के समय में भी लगानों में किसी प्रकार की राहत नहीं देती थी।¹¹² कुछ भारतीय नेताओं ने तो ग्रामीण कर्जदारी का सारा दोष जटिल और अत्यंत विस्तृत कानून प्रणाली पर डाला जो व्यवहार में साहूकार की सहायता करती थी और उसे किसान से उसकी भूमि का कब्जा हथियाने में प्रोत्साहित करती थी और इस प्रकार साहूकारी की सारी बुराइयों को तीव्रता प्रदान करती थी।¹¹³ बहुत सारे नेताओं ने इस सरकारी धारणा का जोरदार और दृढ़ता से खंडन किया कि किसान विवाह, मृत्यु तथा अन्य इस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक समारोहों के लिए अनावश्यक रूप से ऋण लेता है अथवा दूसरे शब्दों में किसान की ऋणग्रस्तता का कारण उसकी फिजूलखर्ची है।¹¹⁴

इस प्रकार राष्ट्रवादियों द्वारा ग्रामीण कर्जदारी के विश्लेषित कारणों के पीछे उनका यह विश्वास था कि यह ब्रिटिश प्रशासनिक पद्धति की ही देन है और ऋणदाता साहूकार तो ब्रिटिश अर्थनीतियों का एक उपकरणमात्र है। इस विश्वास को किन्हीं मामलों में अत्यंत स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्त भी किया गया। उदाहरणार्थ 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 2 जनवरी 1901 के अंक में दृढ़तापूर्वक कहा कि इस देश में कम से कम मारवाड़ी उद्यमी तो ब्रिटिश शासन की ही उपज थे। 'केसरी' ने 18 फरवरी 1902 के अंक में टिप्पणी की।

निरसंदेह ऋणदाता साहूकारों की संख्या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बढ़ी है परंतु इसका कारण ब्रिटिश शासन द्वारा स्वदेशी उद्योगों की हत्या है। जब राष्ट्रीय उद्योग नामशेष हो गए हैं, जब प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपये की इंग्लैंड को निर्यात कर दी जाती है तब यह क्या आश्चर्य का विषय है कि भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा एक दूसरे को खाने के सिवाय उनके लिए और कोई वैकल्पिक मार्ग ही नहीं रह गया है। ब्रिटिश सरकार न केवल यह परिवर्तन लाई है अपितु उसने कानूनी साधनों से इसे निरंतर बनाए रखने का प्रयत्न भी किया है।¹¹⁵

बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने किसान की दरिद्रता के प्रमुख कारण देहाती कर्जदारी तथा साहूकारों को मानने की सरकारी धारणा में असहमत होते हुए भी साहूकारी से उत्पन्न बुराइयों को तत्परतापूर्वक स्वीकार किया, ग्राम के साहूकारों द्वारा बसूले जाने वाले ऊंची दर के ब्याज की निंदा की तथा किसान को लूटने के लिए बनिए द्वारा अपनाए जाने वाले अवैध और घृणित हथकड़ों की भत्सना की तथा साहूकारी को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसे किसानों की गरीबी का एक गौण कारण ही घोषित किया। उन्होंने प्रायः 'खून चूसने वाले' के रूप में विख्यात और ज्ञात साहूकार के पजों से किसान को बचाने की मांग की।¹¹⁶ उदाहरणार्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1899 के अधिवेशन में पंजाब के प्रतिनिधि लाला मुरलीधर ने कर्ज देने वाले साहूकारों के रेखाचित्र निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया :

साहूकार मनुष्य और पशु का विचित्र समन्वित रूप है। जो लोग आत्मा के पुनर्जन्म तथा पुनः शरीर धारण करने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वे मेरी इस धारणा से एकदम सहमत होंगे कि साहूकार के पास शेर के पंजे हैं, लोमड़ी का दिमाग है और

बकरे का दिल है।...वह पैसे को हड़पने वाला, घृणित जोक है, मैं तो कहूँगा कि यह वह व्यक्ति है जो गरीब खेतिहर का खून घूसता है।¹¹⁷

कुछ भारतीयों ने कृषि भूमि के गैर खेतिहर वर्गों के पास हस्तांतरण होने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की तथा उसकी निंदा की।¹¹⁸

इसके साथ ही साथ सारे भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में तथा ऋण लेने के वैकल्पिक साधनों के अभाव की स्थिति में साहूकार ग्रामीण भारत की आर्थिक आवश्यकता था, क्योंकि उसके बिना किसान के लिए कृषि कार्यों का संचालन लगान की माग का शीघ्रता से भुगतान आर्थिक कठिनाता के समय अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करना कठिन हो जाएगा। अतः उनका विचार था कि साहूकार को दबाना नहीं चाहिए प्रत्युत उसे सुधारना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए।¹¹⁹ निस्संदेह उस समय की परिस्थितियों में यह चिंतनधारा अपने में सार्थक तथा सुदृढ़ थी।¹²⁰ नेताओं में से कुछ लोग इस तर्क को बहुत आगे ले गए और कभी कभी साहूकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए खुले आम बोलने लगे।¹²¹

साहूकारों के साथ किसानों के संबंधों के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण को कदाचित्त समय समय पर साहूकारों के शोषण तथा अपदस्थ करने के प्रयत्नों में किसानों को बचाने के लिए और इन प्रयत्नों के परिणाम में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए उत्पन्न होने वाले खतरो को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपनाए गए उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में ही भली प्रकार समझा जा सकता है।

दकन खेतिहर सहायता अधिनियम, 1879

अधिकारियों द्वारा उठाया गया साहूकार विरोधी प्रथम महत्वपूर्ण चरण 1879 का दक्षिण के कृषिकों की सहायता का अधिनियम था। इसका उद्देश्य 1875 के गंभीर उपद्रवों के रूप में दक्षिण बंबई के खेतिहरों द्वारा अभिव्यक्त असंतोष को दूर करना था। यह कार्य साहूकारी को दबाने, साहूकारों की गलत और कपटपूर्ण प्रवृत्तियों को रोकने, कानूनी कार्यवाही को सरल रूप देने तथा ग्रामीण ऋणों को नीचे लाने से किया जा सकता था। दक्षिण के चार जिलों में लागू किए गए अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया कि वे प्रतिज्ञापत्रों की भावना को देखें, ऋण के इतिहास और योग्यता की जांच करें, अनुचित व्याज दरों की वसूली की अनुमति न देते हुए समुचित आधार पर वास्तव में ही देय ऋण राशि निर्धारित करें। यह अधिनियम कर्जदार की धरती को बिकने से बचाता था जब तक कि किसान ने जमीन देने का ही निश्चित रूप में लिखित इकरारनामा न कर रखा हो। इतने पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में से इस अधिनियम में किसानों को धरती लौटवाने की व्यवस्था भी थी। अधिनियम में ग्राम रजिस्ट्रार की नियुक्ति की व्यवस्था थी, जिसके आगे ऋण सबंधी सभी प्रतिज्ञापत्रों का पंजीकरण कराना पड़ता था और ऋण की रकम अधिक होने पर कर्जदार को दिवालिया घोषित

करने का प्रार्थनापत्र देना होता था। इस अधिनियम के अंतर्गत ऋण चुकता न करने पर जेल के दंड को हटा दिया गया था तथा ऋण परामर्शदाता की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1882 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और कर्जदारों को रेहन रखी गई घरती को छुड़वाने की चिंता किए बिना ही हिसाब के लिए कानून की शरण लेने की शक्ति दी गई।

इस अधिनियम को जस्टिस रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा तथा बंबई के कई समाचारपत्रों ने सक्रिय समर्थन दिया।¹²² रानाडे ने अपने दृष्टिकोण को निम्न शब्दों में संक्षिप्त रूप दिया :

इस अधिनियम का समग्र औचित्य इसी एक तथ्य में निहित है कि साधारण कानून दिवालिये और अशिक्षित किसान में तथा संपन्न और चालाक साहूकार में बुद्धि और सुविधाओं की समानता के सिद्धांत को लेकर चलता है जबकि वस्तुतः इस समानता का किसी भी रूप में अस्तित्व ही नहीं है, नकली कानून द्वारा समानता की धारणा पूर्ण रूप से ही कल्पनामूलक है और इसका बहुत ही दुरुपयोग होता रहा है। अपेक्षाकृत दुर्बल वर्ग के संरक्षण की दृष्टि से पुरानी रूढ़िवादी स्वदेशी परंपराओं की ओर लौट कर इस बुराई के उन्मूलन का समय आ गया है।¹²³

रानाडे ने अक्टूबर 1879 में 'जरनल आफ दि पूना सार्वजनिक सभा' में प्रकाशित अपने लेख, 'द्रकन ऐग्रीकलचरिस्ट बिल' में बिल की नगभग सभी महत्वपूर्ण धाराओं का समर्थन किया।

बंबई के बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने प्रमुख रूप से इस आधार पर बिल को अस्वीकृत कर दिया कि यह अनिच्छापूर्वक किया गया प्रयास है अतः यह किसानों की सुरक्षा में सफल नहीं होगा। यह साहूकार के रूप में गौण बुराई का तो उपचार करता है परंतु कठोर और दकियानूसी लगान पद्धति के रूप में प्राथमिक बुराई को छूटा तक नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि किसान के दायित्व तो यथापूर्व बने रहेंगे परंतु उसकी ऋण लेने की साख जाती रहेगी अतः उसकी और दुर्दशा होगी।¹²⁴ अधिनियम के आलोचकों के मन में कदाचित्त वही विश्वास काम कर रहा था जिसे 3 फरवरी 1884 के अंक में मराठा ने खुले तौर पर प्रकट किया : 'यह एक ऐसा साधन है जिस दुर्भाग्य के वास्तविक आधार को छिपाने के लिए अपनाया गया है।' 'सरकार द्वारा' अपने उत्तरदायित्व को साहूकार के कंधों पर फेंकने की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों का यह एक रूप है।' यहा तक कि अधिनियम का खुलकर समर्थन करने वाले रानाडे ने यह शर्त जोड़ दी कि यह बिल किसानों को राहत पहुंचाने में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जब इस कल्पना से काम लिया जाए कि भूराजस्व नीति को उदार बनाया जाएगा बिल की सफलता के लिए यह एकमात्र शर्त है।¹²⁵ उन्होंने आगे दृढ़तापूर्वक लिखा : 'नहीं तो यह कानून कोई भी उल्लेखनीय और स्थाई लाभ नहीं पहुंचा सकेगा और सभव यह भी है कि वर्तमान स्थिति को ही और अधिक विषम बना देगा क्योंकि किसान बेचारों को बढ़े हुए भूमि लगानों को चुकाने के लिए किसी तरह रुपया जुटाना पड़ेगा।¹²⁶ थोड़े से भारतीय नेताओं ने अधिनियम का विरोध भी किया। उनके विचार

मे यह साहूकार के हितों की पूर्ण उपेक्षा करता था और परिणामस्वरूप पूरी तरह बरबाद कर रहा था।¹²⁷

धरती के संक्रमण पर प्रतिबंध

1879 के उपरांत शताब्दी के अंत तक सरकार ने देहाती कर्जदारी के बढ़ते खतरे के विरुद्ध कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। परंतु धरती के किसानों के हाथ से निकल कर गैर-खेतिहर वर्गों के हाथ में जाने की गति इतनी अधिक बढ़ गई कि अधिकारी घबड़ा उठे। तब सरकार पहले से अपनाए गए प्रयत्नों की अपेक्षा और अधिक वेगवान और प्रभावी उपचार करने को विवश हो गई। इस सबंध में वर्षों तक सरकारी चिंतन इस धारणा के चारों ओर घूमना रहा कि किसानों के हाथों से धरती के गैरखेतिहर वर्गों के पास जाने के प्रमुख कारण थे, सरकारी मांग की अत्यधिक कोमलता। सरकारी कर नीति आर्थिक लगान का एक भाग लेने के बाद बहुत बड़े अनुपाजित अवशिष्ट भाग को भूस्वामियों के हाथ में छोड़ देती थी और इससे खून चूसने वाले लगान वसूलने वाले वर्ग के बने रहने में सहायता मिलती थी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भूस्वामियों को धरती बेचने अथवा रेहन रखने के रूप में धरती को हस्तान्तरित करने की अबाधित शक्ति दी गई थी। भारतीय किसानों की फिजूलखर्ची की आदत थी। वह एक ओर अपनी इस प्रकृति के कारण और दूसरी ओर भूमि के संक्रमण की शक्ति में संपन्न होने के कारण अधिकतम रकबा उधार लेता था।¹²⁸ अतः यह विश्वास बनाया गया कि जितना उच्च कराधान होगा किसानों के लिए वह उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। यदि ब्रिटिश प्रशासन को ने राजनीतिक दृष्टि में अपने प्रस्ताव को लागू करना असंभव अनुभव न किया होता तो अवश्य ही उन्होंने गैर-खेतिहर जमींदारों को लाभरहित बनाने के लिए भूमि लगान में वृद्धि के प्रस्ताव को रखने की उन्मुक्तता अवश्य दिखाई होती।¹²⁹ अधिकारियों द्वारा विकल्प रूप में अवशिष्ट दूसरा उपाय था, अनुद्धिमान और अदूरदर्शी किसानों के लिए घातक मित्र हो रहे भूमि हस्तान्तरण के उपहार रूप अधिकार को उनके हाथों में छीन लेना, धरती बेचने की उम्मीद शक्ति पर प्रतिबंध लगाना तथा इस प्रकार उम्मीद मात्र को सीमित करने हुए बने पैमाने पर ऋण लेने की उसकी शक्ति और प्रलोभन को दूर करना।¹³⁰

नई नीति का प्रथम प्रमुख साकार रूप 1900 का पंजाब एक्टिनेशन ऐक्ट था। अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी किसान द्वारा डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना और परिभाषित खेतिहर के सिवाय किसी अन्य को स्थाई रूप से भूमि के स्वामित्व परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गैरखेतिहरों को भूमि के स्वामित्व की कई रूपों में अस्थाई स्वीकृति अधिकतम बीस वर्षों की अवधि के लिए निश्चित की गई। इस अवधि के उपरांत, बिना किसी प्रकार की बाधा के धरती मूल स्वामी के अधिकार में मानी जाने की व्यवस्था की गई तथा किसी आदेश अथवा आज्ञापति के परिपालन के लिए कृषि भूमि को न बेचे जा सकने की व्यवस्था की गई।¹³¹ इससे स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान को चालू ऋणग्रस्तता से मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि पंजाब के कृषक वर्ग के एक बाहरी व्यक्ति के रूप में साहूकार द्वारा किए जा रहे संपत्तिहण से और इस

रूप से शायद निरंतर बढ़ रहे राजनीतिक खतरे के रोग से बचाने के लिए तथा भविष्य में उसे न बढ़ने देने के लिए बनाया गया था।¹³² यही कारण है कि भूमि के खेतिहर वर्गों में हस्तांतरण की पूरी इजाजत थी और वास्तव में भूमि के संक्रमण को पूर्णरूप से रोकने की जगह इसे कम किया गया और नियमित बनाया गया। हां, यह आशा अवश्य की गई थी कि इससे किमान की थोड़ी सी आवश्यकता होते ही साहकार के पास भागे जाने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य पर परीक्ष रूप से दबाव अवश्य पड़ेगा।

उस दिशा में उठाया गया अगला महत्वपूर्ण कदम 1901 में बंबई में लैंड रैवेन्यू अमेडमेंट ऐक्ट (भूराजस्व संशोधन अधिनियम) को कानून का रूप देना था। इसमें सरकार को भूमि लगान का भूगतान न करने के अपराध में सरकार द्वारा जवन किए गए खाली भूखंडों और खेतों के तथा इस्तेमाल के अधिकार में रहित नए प्रकार के ज़ोनों के बंदोबस्त करने की शक्ति दी गई थी। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कलक्टर द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के लिए तथा यथानिर्दिष्ट शर्तों पर जवन धरती देने की भी व्यवस्था थी।¹³³ इस अधिनियम में सामर्थ्य देने की व्यवस्था थी, बाधना की नहीं थी तथा जवन धरती को असंक्रमणीय बनाने की व्यवस्था थी। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि इस अधिनियम का क्षेत्र पंजाब के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ही संकीर्ण था, इसके अतिरिक्त पंजाब अधिनियम में ऐसा यह अधिनियम दो रूपों में बंटा था, प्रथम, इसके अंतर्गत जितनी भी धरती आती थी, यह अधिनियम उस पर प्रतिबंध की नहीं लगाता था प्रत्युत रेशन, वित्री आदि किसी भी रूप में धरती के इस्तेमाल पर पूर्ण निषेध लगाता था। द्वितीय, यह सरकार को सर्वेक्षण ज़ोनों पर स्थाई मौखी हक देने के बदले जवन किए गए खंडों को थोड़े समय के पट्टे पर देने का अधिकार देता था।

धरती के निजी स्वामित्व परिवर्तन की शक्ति को प्रतिबंधित करने की चेष्टाओं के प्रति राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण ग्रामीण ऋण प्रस्तुता के कारणों और निवारण के उपायों के संबंध में ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं के बीच मतभेदों को उजागर करता है। इन मतभेदों को देखते हुए यह स्वाभाविक थी कि राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अधिनियम का उसके जन्म काल में लेकर सरकार द्वारा उसे स्वीकृति देने के समय तक विरोध किया।¹³⁴

पंजाब के बाहर पंजाब भूमि संक्रमण बिल का या तो विरोध हुआ और या उसे समर्थन नहीं मिला।¹³⁵ पंजाब में भी राष्ट्रवादी पदाधिकारियों में इस बिल ने मतभेद उत्पन्न कर दिया।¹³⁶ इसने बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादियों का अजीब स्थिति में डाल दिया। उदाहरणार्थ पंजाब प्रांत के राष्ट्रवादी पत्रों में उर्दू भाषा के मुखपत्र 'खवारे आम' ने आरंभ में बड़ी ही संकोच की सी स्थिति अपनाई और अपनी प्रतिक्रिया समर्थकों और विरोधियों दोनों के विचारों को प्रकाशित करने के रूप में प्रकट की। लगभग एक वर्ष तक बीच में लुढ़कते रहने के उपरांत आखिरकार उसने अपने 7 अगस्त 1900 और 27 अक्टूबर 1900 के अंक में बिल का विरोध किया।¹³⁷ परंतु दो ही सप्ताहों के उपरांत उसने अपना रुख बदल दिया और उसने 10 नवंबर 1900 के अंक में

विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि यह अधिनियम सफल होगा और इसके संबंध में उठाई गई सभी आपत्तियां अमगत हैं।¹³⁸ किसी भी रूप में पंजाब के भीतर अथवा बाहर पंजाब एलिनेशन बिल का कठोर रोषपूर्ण अथवा दीर्घकालीन विरोध नहीं हुआ।

दूसरी ओर 'बबई भूराजस्व मशोधन बिल' में बबई प्रदेश की जनता में व्यापक रोष की लहर दौड़ गई। प्रदेश के सभी भागों में विरोध सभाएं हुईं तथा बबई प्रेजीडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा तथा दकन सभा ने इसके विरुद्ध जापन भेजे।¹³⁹ प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्र इस बिल की निंदा के लिए कटिबद्ध हो गए¹⁴⁰, और प्रमुख लोकनेता हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए।¹⁴¹ बबई लैजिस्लेटिव कौंसिल के कुछ भारतीय सदस्यों, पी० एम० मेहता, जी० के० गोखले, जी० के० पारिख, बालचंद्र कृष्ण और डी० ए० खरे ने बिल को जल्दबाजी में कानून का रूप देने के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए कौंसिल से बहिर्गमन का अभूतपूर्व कदम उठाया, यह भारतीय विधान परिषदों के इतिहास में कदाचित् प्रथम उदाहरण था।¹⁴²

भूस्वामित्व परिवर्तन विरोधी कानून के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के विरोध का आधार यह विश्वास था कि भले ही यह कानून किसानों को साहूकारों द्वारा किए जाने वाले स्वामित्वहरण में बचाने के उत्तम उद्देश्य को लेकर बनाया गया है परन्तु इससे व्यवहार में कोई लाभ तो होगा नहीं उल्टे यह किसानों के हितों के विरुद्ध ही जा सकता है। प्रथम, उनकी धारणा थी कि स्वामित्व परिवर्तन पर लगे प्रतिबंधों से किसानों की साख जड़भूल से नष्ट न होने पर भी क्षीण अवस्था हो जाएगी। क्योंकि किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए, सरकारी मांगों के भुगतान के लिए और अभाव के दिनों में परिवार के भरण-पोषण के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती ही रहती है, उस कानून का परिणाम यह होगा कि या तो वह ऋण ले ही नहीं पाएगा अथवा उसे इसके लिए बहुत ऊँची व्याज दर देनी पड़ेगी।¹⁴³ उनका यह भी दावा था कि इस प्रकार के प्रतिबंधों का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि भूमि का मूल्य घट जाएगा।¹⁴⁴ उनकी यह भी धारणा थी कि ये प्रतिबंध किसानों के स्वामित्व के अधिकारों के क्षेत्र में घुसपैठ हैं। धीरे-धीरे ये प्रतिबंध किसानों को वास्तव में ही राज्य का दाम बना देंगे।¹⁴⁵ भारतीय नेताओं ने विशेष रूप से बबई भूराजस्व मशोधन बिल पर प्रहार करते हुए अपनी इस आलोचना को उग्र स्वर दिया। उनके अनुसार जब्त की गई धरती पर समुचित समझी जाने वाली शर्तों पर और समुचित समझी जाने वाली अवधि के लिए बंदोबस्त का सरकार को अधिकार देने वाली व्यवस्थाएँ न केवल किसानों में स्वामित्व का अधिकार छीनने का उद्देश्य लिए हुए हैं प्रत्युत उसके स्थाई मौरूसी हक और निरंतर जोतने का हक भी छीनती हैं। इस प्रकार नेताओं ने इन व्यवस्थाओं को राजकीय जमींदारी अथवा भूमि के राष्ट्रीयकरण के मिथान को लागू करने का एक गुप्त षड्यंत्र बताया।¹⁴⁶ कुछ ने तो भविष्यवाणी की कि जहाँ तक किसानों का संबंध है, इन 'क्रांतिकारी' व्यवस्थाओं से विपरीत परिणाम ही प्राप्त होगा। बेचारा किसान अपने पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों को बचाने के लिए साहूकारों पर और अधिक निर्भर रहेगा

और साहूकार बदले में भविष्य में सरकार द्वारा जन्त किए जाने की आशंका से भूमि का कब्जा लेने की चेष्टा करेगा।¹⁴⁷ उनमें से कुछ ने तो निर्धन, असमर्थ और विपन्न किसानों के हाथ में भूमि विपन्न बनाए रखने की बुद्धिमत्ता को ही चुनौती दी और स्पष्ट घोषित किया कि इसका अनिवार्य परिणाम कृषि का अवपात ही तो होगा। दूसरी ओर उन्होंने धरती के स्वच्छंद हस्तांतरण की वकालत की क्योंकि उनके अनुसार इसका परिणाम यह होगा कि धरती अपेक्षाकृत अधिक योग्य और साधन संपन्न किसानों के हाथ में आ जाएगी जो कृषि उत्पादन को ऊँचे स्तर पर लाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग और पूँजी का निवेश कर सकेंगे।¹⁴⁸ इस विचारधारा का प्रधान समर्थक प्रवक्ता जस्टिस रानाडे ने 1880 में जिस स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया, उसे हम आगे एक पृथक भाग में दिखाएंगे।

धरती के स्वामित्व के परिवर्तन पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए भारतीय नेताओं ने साहूकार की हानि को विरोध का आधार कम ही माना।¹⁴⁹ यहाँ तक कि उन्होंने पूरे जोर से इस बात का खंडन किया कि इसके पीछे उनके कोई साहूकार समर्थक रूझान थे। उदाहरणार्थ, फिरोजशाह मेहता और जी० के० गोखले दोनों को तीव्रता से इस बात का खंडन करना पड़ा कि बर्बई राजस्व संशोधन बिल के विरोध के पीछे साहूकारों ने द्रिष्टो की चिंता किसी भी रूप में प्रेरक कारण थी।¹⁵⁰

भारतीय नेताओं ने व्यापक रूप में यह अनुभव किया कि स्वामित्व के परिवर्तन को प्रतिबंधित करना समस्या की मौलिक स्थितियों की भ्रात धारणा के कारण ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता पर गलत दिशा में प्रहार करना था। सारी योजना विषम भांति पर ही आधारित थी। निस्संदेह भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार किसान को भूमि की जमानत पर ऋण लेने की सुविधा जुटाता था परंतु उनका तर्क यह था कि यह अधिकार ऋण लेने का कारण नहीं था। अतः उनकी धारणा थी कि बड़े पैमाने पर भूमि के हस्तांतरण की बुराई को रोकने के लिए किसान की माख पर नहीं प्रत्युत उसके ऋण लेने के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रहार करना चाहिए। प्रथम को प्रतिबंधित करके दूसरे को बने रहने देने का अर्थ है, रोग के लक्षणों को दबाना परंतु उसके मूल कारण को बने रहने देना।¹⁵¹ इस संदर्भ में उन्होंने इस कथन का कि भारतीय किसान स्वभाव से अदूरदर्शी है अतः वह ऋणसुलभता की अधिकतम सीमा तक सदैव ऋण लेता ही रहता है अथवा लेता रहेगा बार बार और लगातार खंडन किया।¹⁵² उन्होंने इस तर्क को बेहूदा बताया कि धरती पर सरकारी मांग के हलकेपन के एरोक्ष परिणामस्वरूप अनुपाजित फालतू आय के कारण धरती पर साहूकारी का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है।¹⁵³ उन्होंने शिकायत की कि जहाँ सरकार किसी भी बाहरी साधन को अपनाने के लिए सहमत है, वहाँ अपने द्वारा वसूले जाने वाले धरती के ऊँचे और कठोर लगानों को, जो वास्तव में किसान की ऋणग्रस्तता के सही कारण हैं, हटाने के लिए सहमत नहीं क्योंकि इससे उसके अपने वित्तीय हित प्रभावित होते हैं।¹⁵⁴ डान पत्रिका के दिसंबर 1899 के अंक में प्रकाशित 'दि इकोनामिक सिचुएशन इन इंडिया' लेख में सतीशचंद्र मुखर्जी ने इस विषय में उल्लेखनीय गहरी पैठ और पैनी दृष्टि का परिचय दिया। ब्रिटिश प्रशासन में भारत में भूमिस्वामित्व में परिवर्तन के

अधिकार के स्रोत की खोज करते हुए उन्होंने निर्देश किया कि कठोर वित्तीय पद्धति लागू करने पर भारत सरकार के लिए किसान को भूमि बेचने अथवा रेहन रखने के रूप में स्वामित्व में परिवर्तन का अधिकार अनुपूरक पग के रूप में ही देना पड़ा अन्यथा लगान की द्रुत वसूली संभव ही न हो पाती। स्वामित्व परिवर्तन के अधिकार में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करना होगा और उसके साथ वित्तीय पद्धति में, जिसके सदस्य में इन अधिकारों का देना एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी, प्रभावी संशोधन करना ही नहीं प्रत्युत उसे खत्म करना होगा।¹⁵⁵

बहुत सारे भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि स्वामित्व परिवर्तन, निषेधक कानूनी उपायों की वास्तविक प्रभावशालीता के संदर्भ में दृष्टिगोचर परिणाम के अनुरूप सिद्ध नहीं हो रहा था क्योंकि यह उपाय ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सतही पक्ष से ही सबध रखता था। यह उपाय अधिक से अधिक रोग के प्रभाव को कम ही कर सकता था परन्तु वास्तविक समस्या का न तो यह विश्लेषण कर पाता था और न ही समाधान।¹⁵⁶

वैकल्पिक उपचार

ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के प्रति भारतीय नेताओं का मूल दृष्टिकोण यह था कि अपेक्षाकृत अधिक असंदिग्ध उपायों के रूप में केवल साहूकार विरोधी उपायों पर ही अधिक बल नहीं देना चाहिए प्रत्युत देखना यह चाहिए कि ये कौन से कारण हैं जिनसे विवश होकर किसान को साहूकार और ऋणदाता के चंगुल में फसना पड़ता है। ग्रामीण ऋण के अपेक्षाकृत अच्छे अभिकरण (एजेंसिया) खोलने से ही किसान को साहूकार से छुटकारा मिलना संभव है। 'मगठा' ने इस दृष्टिकोण को अपने 8 अक्टूबर 1899 के एक में स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त किया

जब तक रुपया ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहेगी, मेनिहर और ऋणदाता साहूकार एक दूसरे के निकट आते ही रहेंगे और भूस्वामित्व परिवर्तन निषेधक कानूनों के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वस्तुतः सरकार जितना कर सकती है उसे उतना अवश्य करना चाहिए। या तो वह ऋणग्रस्तता के वास्तविक कारण लगान में कुछ कटौती करके ऋणग्रस्तता को, आंशिक रूप में ही सही, कुछ कम करे अथवा किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उन्हें शैतान और क्रूर प्राइवेट ऋणदाता साहूकारों के पंजों से छुड़ाने के लिए स्वयं ऋणदाता के रूप में कार्य करे।¹⁵⁷

इसी प्रकार गोपालकृष्ण गोखले ने बंबई मूँल्लिगान संशोधन बिल पर भाषण करते समय सरकार को चुनौती दी कि वह एक छोटा सा इलाका छोट ले। वहाँ के किसानों के सारे ऋण साहूकारों से लेकर अपने हाथ में कर ले और किसानों की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि बैंक चालू करे और फिर किसान से भूस्वामित्व परिवर्तन का अधिकार छीने। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि समस्या को सही ढंग से सुलझाने का यही एकमात्र सही उपाय होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हमारे बहुत सारे देशवासी सरकार की इस नीति का समर्थन करेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि मूल समस्या यह है

कि जब तक उसके चालू ऋणों को कम नहीं किया जाता और उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक किसान को किसी प्रकार की राहत ही नहीं मिल सकती। कानून तत्र के संचालन मात्र में किसान की स्थिति में सुधार की आशा करना निरर्थक है।¹¹⁸ संक्षेप में उपशमक उपचारों के साथ साथ रोग की निवृत्ति के लिए स्थाई और मौलिक औषधियों को भी आवश्यक रूप में ग्रहण करना चाहिए।¹¹⁹

भारतीय नेताओं ने ग्रामीण दरिद्रता को निर्मूल करने के लिए उपचार के रूप में भ्रम, उद्योग तथा फालतू पूँजी के नए अवसर जुटाने¹²⁰ तथा भूमि लगान को शिथिल बनाने के सुझाव देने¹²¹ के साथ साथ किसानों के लिए साख की मरग और मन्ती व्यवस्था जुटाने पर बल दिया। उन्होंने इस सबंध में तब प्रस्तुत किया कि जहाँ किसान को ऋणदाता माहूँकार की लूट से बचाना आवश्यक था वहाँ उसके लिए ब्याज की नीची दर पर आवश्यक निर्धन के ऋण लेने की सुविधाओं की व्यवस्था करना भी आवश्यक था। साख की वैकल्पिक व्यवस्था जुटाए बिना माहूँकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाना किसान का वर्तमान में भी अधिक बुरी शर्तों पर माहूँकार की दया पर छोड़ने के समान होगा। अतः हमारे अध्ययन के अंतर्गत सारी अवधि में व दश में कृषि बैंकों का जाल बिछाने के लिए आंदोलन करते रहे।¹²² जब भारत सरकार ने कृषि बैंक और ऋण समितियों की उन्नति की व्यवस्था के लिए कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बिल (माहूँकारी साख समिति बिल) पेश किया तो इन नेताओं ने उसका प्रसन्न मन में पूर्ण समर्थन किया।¹²³ इस सदर्भ में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण तत्व उनका यह दृढ़ विश्वास था कि सरकार कृषि बैंकों के उन्नयन का कार्य अपने ही हाथ में ले, इस कार्य को निजी उद्यमियों के हाथ में न छोड़े।¹²⁴ जस्टिस रानाडे, जी० बी० जोशी और जी० के० गोखले ने भी यही मत प्रकट किया कि सिर में पैर तक कर्ज में डूबे किसानों के पुगने ऋणों को इकट्ठा करके बंधाव नष्ट किए जान पर ही किसान कृषि बैंकों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।¹²⁵

पूँजीनिष्ठ खेती

भूमि विषयक सबंधों के वर्तमान ढाँचे के अंतर्गत जमींदार और साहूँकार के अत्याचारों से किसान को सुरक्षित करने के सरकार और भारतीय नेताओं के प्रयत्नों और उपायों से उसकी स्थिति का सामान्य रूप में ही सुधारना संभव था, प्रशास, रूस, और फ्रांस में भूमि सबंधी कानूनों से सबंधित और अनुभवप्राप्त रानाडे ने भूमि सबंधों को सबंध नए आधारों पर स्थिर करने की नीति पेश की।¹²⁶ किसानों के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति थी। राज्य, जमींदार और साहूँकार के दमन से किसान को बचाने की विभिन्न सरकारी चेष्टाओं का उन्होंने न केवल समर्थन किया था प्रत्युत अपनी ओर से इस सबंध में सुझाव भी रखे थे। वह सरकारी साधनों की भावना और दिशा से सहमत नहीं थे। उनका विश्वास था कि इनसे न तो कृषक वर्ग के उस रूप में वर्तमान कष्ट दूर होंगे और न ही उस वर्ग पर लगे प्रतिबंध उस रूप में दूर होंगे जिस रूप में प्रशास के कानून ने 19वीं शताब्दी के

पूर्वार्ध में वहाँ के किसानों की दशा में सफलतापूर्वक सुधार किया है। उन्होंने निर्देश किया कि भारतीय काश्तकारी कानून के अंतर्गत किसान और जमींदार दोनों का कृषि संबंधों की पुरानी व्यवस्था के बंधनों में बंधा रहना जारी रहेगा। इस प्रकार का कानून तो कर्तव्यों और अधिकारों की वर्तमान जटिलताओं में वृद्धि करने का काम ही करेगा, जमींदार वर्ग को केवल लगान के रूप में अनुग्रह राशि (पेंशन) खाने वाला बनाने के और किसान को जमीन के पूर्ण स्वत्वाधिकारी के रूप में राज्य की ओर अधिक से अधिक देखने के लिए विवश करेगा। दोनों को अपनी स्थिति को सही प्रकार से समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। एक वर्ग के हित में वर्तमान अधिकारों को सतही तौर पर दुहा जा रहा है, हालाँकि इसे 'शीघ्र सुधार' व 'क्रांतिकारी' सुधार का नाम दिया जा रहा है। इस प्रकार की नीति का परिणाम यह होगा कि भगड़ालू भागीदारों में भूमि पर स्वामित्व और हितों का पूर्ववत् पृथक् और विभाजित रूप बना रहेगा और किसी भी प्रकार का वास्तविक सुधार नहीं हो पाएगा।¹⁶⁷ इसी प्रकार किसान को कर्जदार साहूकार की लूट से बचाने के लिए भूमि संक्रमण को अवैध बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति करते हुए रानाडे ने अपना मत प्रकट किया : वास्तविक संपत्ति के इच्छित तथा अनिच्छित सभी प्रकार के हस्त-ंतरणों पर प्रतिबंध लगाने में स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। इससे तो केवल वर्तमान गरीबी की जड़ें मजबूत होंगी और वर्तमान असहाय अवस्था और अधिक विषम बन जाएगी।¹⁶⁸

रानाडे ने चालू भूमि संबंधों के स्थान पर निजी और स्वतंत्र संपत्ति के आधार पर नए भूमि संबंध स्थापित करने का आह्वान किया।¹⁶⁹ संरक्षित पट्टेदारी के स्थान पर उन्होंने किमान को स्वतंत्र तथा उन्मुक्त बनाने का सुझाव दिया ताकि उसके निजी अस्तित्व की स्थापना हो सके। इस प्रकार का स्वतंत्र किमान दबाया नहीं जा सकेगा, वह स्वामित्व के पूर्ण अधिकार का उपभोग करेगा। संपत्ति के जादू से सम्मोहित वह अपनी धरती पर कठोर श्रम करेगा।¹⁷⁰ इसके साथ ही उदका यह विश्वास था कि छोटे छोटे किसानों में बंटी हुई कृषि, भारतीय परिस्थितियों में न तो म्याई और प्रगतिशील बन सकेगी और न ही सभी वर्गों की सर्वोत्तम शक्तियों का सदुपयोग या उन्नत तकनीक और लोक कर्मों का समुचित उपयोग कर सकेगी। उन्होंने लिखा कि जमीन जोतने वालों का जमीन से पूर्णतः अलगव एक राष्ट्रीय रोग है और सारे देश में छोटे छोटे किसानों के स्तर का बहुत नीचे गिरना भी किसी रूप में कम गंभीर रोग नहीं।¹⁷¹ उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा : कृषि के समुचित और सन्तुलित विकास के लिए बड़े पैमाने के पूंजीनिष्ठ किसानों का होना आवश्यक है। ऐसे संपन्न किसान भारतीय जमींदारों के समान नहीं प्रत्युत बरतानवी जमींदारों तथा जर्मन जमींदारों के आदर्श पर धरती के पूरे तौर पर मालिक होंगे। 1879 में उन्होंने आशा प्रकट की कि एक बार धरती को कृत्रिम प्रतिबंधों से मुक्त की जाए, समरुद्ध और मितव्ययी वर्ग धरती पर अधिकार करने में सफल हो ही जाएगा। सारे देश में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आ जाएगा, जिसका उद्देश्य धरती के अधिकांश साधनों का और सरकार द्वारा निमित्त लोक कार्यों का उपयोग करना होगा¹⁷² थोड़ा आगे उन्होंने ये रोचक टिप्पणियाँ की :

भारत जैसे पुराने और पिछड़े हुए सभी देशों में शक्ति के सभी तत्वों पर एकाधिकार करने वाला एक अल्पसंख्यक वर्ग सदैव मिलता है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इस वर्ग के लोग सदैव अग्रणी रहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास प्रतिभा, संपत्ति, मितव्ययी प्रकृति, ज्ञान और सयोजनशक्ति होती है जबकि बहुसंख्यक वर्ग के लोग अशिक्षित, अदूरदर्शी, बेसमर्थ, फिज़ूलखर्च और साधनहीन होते हैं, इन दोनों वर्गों में किसी भी राजनीतिक चातुरी से सतुलन नहीं रखा जा सकता। प्रतिभा और संपत्ति के प्रति शक्ति का आकर्षण निश्चित है। अतः कंगाली में फंसे किसानों को भूमि का स्वामी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना सर्वथा निरर्थक है। यह तो धरती और पूँजी के स्वाभाविक ऐक्य को भंग करना है।¹⁷⁶

1883 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा करते हुए रानाडे ने खमार भूमि अथवा जमींदारों के निजी अधिकार की भूमि को कम करने की और किसानों के अधीनस्थ धरती में बढ़ोतरी करने की प्रवृत्ति की आलोचना की।¹⁷⁷ उन्होंने इस बिल की व्यवस्थाओं का प्रशा की भूमि कानून व्यवस्थाओं से अंतर दिखाते हुए प्रशा के कानून की इस आधार पर प्रशंसा की कि उसमें पुराने जमींदारों को अपनी भूसंपत्ति के एक भाग को अपने अधीन अधिकार में ही बड़े पैमाने के पूँजीनिष्ठ खेतों में बदलने की अनुमति थी।¹⁷⁸ इसी प्रकार सरकार का नीति की आलोचना के अन्यान्य कारणों के साथ एक महत्वपूर्ण कारण उनका यह विश्वास था कि इससे बड़े पैमाने की पूँजीनिष्ठ कृषि के विकास में रुकावट पैदा होती है।¹⁷⁹ इसी प्रकार उनके भूमि के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का विरोध का प्रमुख आधार उनका यह भय था कि इन प्रतिबंधों से देश की भूमिगत संपत्ति के केंद्रित होने की अपरिहार्य प्रवृत्ति रुक जाएगी।¹⁷⁷

अतएव रानाडे ने भारत में कृषि संबंधों में भावी विकास को साथ साथ जीवित रहने वाले दो कृषि संबंधित वर्गों को जन्म देकर उन पर आधारित करने की वकालत की : (क) व्यापक क्षुद्र कृषक वर्ग, जो राज्य के अथवा जमींदारों के किसी भी प्रकार के भार से पूर्णतया मुक्त होगा। उसे स्थाई और निम्न दर पर निर्धारित भूराजस्व की प्रतिभूति प्राप्त होगी और उसके लिए कृषि बैंकों के द्वारा सस्ती दर और आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था होगी। (ख) पूँजीपति किसानों का बड़ा वर्ग, जो किसी भी काश्तकारी कानून से अप्रभावित होगा अर्थात् उसके पास धरती का पूर्ण और एकात्मक स्वत्वाधिकार होगा। यह वर्ग इस स्थिति में होगा कि अपेक्षित पूँजी का निवेश तथा अधुनातन वैज्ञानिक कृषि संबंधी तकनीक का उपयोग कर सके। प्रशा में इस संबंध में उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित जमींदार और किसान दोनों वर्गों के संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकारवाली स्वाभिमित्य पद्धति के अनुकरण और स्वीकरण की अपील की।¹⁷⁸ उन्होंने बताया कि प्रशा में 1860 में 15 प्रतिशत भूमि पर राज्य अथवा चर्च का अधिकार था, 44 प्रतिशत पर बड़े बड़े जमींदारों का अधिकार था, 35 प्रतिशत पर किसानों का स्वत्वाधिकार था और 5 प्रतिशत पर छोटे छोटे मालिकों का अधिकार था। इस प्रकार समर्थन के स्वर में उन्होंने कहा कि वहाँ भूमि समृद्ध जमींदार और भारमुक्त निर्धन में बराबर बंटी हुई है। सामंती अर्धदास ने वहाँ भारमुक्त स्वत्वाधिकारी का और जागीरदार लार्ड ने अपनी संपत्ति के

अबाध स्वामी का रूप ले लिया है।¹⁷⁹ प्रशा के आदर्श को भारत पर लागू करते हुए जस्टिस रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुँचे।

यदि इस देश को अपनी शक्ति और समृद्धि के आधार के रूप में स्वाभिमानी व स्वतंत्र भूधरो की गहनी आवश्यकता है तो भूमि पर स्वामित्व प्राप्त व्यक्तियों के प्रकाश और नेतृत्व की भी आवश्यकता किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं। 'ऊपर के दस हजार लोगो द्वारा बड़े बड़े भूभागवाली जागीरो पर अधिकार करना और बड़ी सख्या में छोटे छोटे खेतियार किसानो द्वारा छोटे छोटे भूभागो पर अधिकार रखना, इस प्रकार बड़े और छोटे खेतो पर खेती' देश की उन्नति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए ग्रामीण समाज को यह मिश्रित रचना एक आवश्यकता है।¹⁸⁰

रानाडे ने पृजीनिष्ठ हिंस्र और जमींदार वर्ग के अस्तित्व में आने के साधनों और उपायों पर भी विचार किया। उन्होंने आशा प्रकट की कि कुछ एक मितव्ययी स्वतंत्र किसान धीरे धीरे अपनी स्थिति में विस्तार करेंगे और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे।¹⁸¹ उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि धनिक वर्ग के बहुत सारे लोग भूमि की ओर आकृष्ट होंगे, बेपरवाह और निकम्मे किसानों से भूमि खरीदेंगे तथा इस प्रकार पृजीपति जमींदार की भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे।¹⁸² स्पष्टतया यह उपचार रीयतबाड़ी उलाके पर ही लागू होगा। बंगाल के जमींदारी क्षेत्र के संबंध में रानाडे ने प्रशा के भूमि सुधारों के अनुकरण का सुझाव दिया। उनका इस संबंध में सर्वप्रथम सुझाव यह था कि कृषि में संबंधित सारे क्षेत्र में सभी प्रकार के सुधार समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक सवरो पर किसी प्रकार की हिंस्र गड़बड़ डाले बिना अथवा क्रांति का भटका अनुभव किए बिना तथा अतर्बर्गीय संघर्षों को जन्म दिए बिना ही किए जाने चाहिए।¹⁸³ बंगाल काश्तकारी कानून के प्रति उनके विरोध के कारणों में उनकी एक यह आशका थी कि इस बिल का अनिवार्य परिणाम वर्ग संघर्ष होगा।¹⁸⁴ वह जमींदारों के वर्तमान अधिकारों के एवतरफा छीने जाने के भी विरुद्ध थे और बंगाल बिल में, उनके अनुसार यह भावना निहित थी।¹⁸⁵ इसके साथ ही उनकी यह भी मान्यता थी कि छीने गए अधिकारों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।¹⁸⁶ इस संबंध में रानाडे की अपनी योजना किसानों और जमींदारों दोनों को धरती के स्वामित्व का समान अधिकार देकर दोनों में सौहार्द और सौमनस्य की भावना उत्पन्न करता था। उनका प्रस्ताव था कि किसान को भूमि का पूर्ण स्वत्वाधिकार दे देना चाहिए परंतु केवल उतने ही भाग का, जितना उसकी पट्टेदारी के अंतर्गत आता है। इस स्वामित्व को खरीदने के मूल्य के रूप में उसे अवशिष्ट धरती पर जमींदार के पक्ष में अपने सभी दाव छोड़ने होंगे। इस प्रकार उसकी पट्टेदारीवाले भूभाग पर उसका पूर्ण स्वत्वाधिकार होगा और शेष भाग पर जमींदार का पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा। यदि जमींदार का फिर भी कुछ बकाया निकलता है तो उसकी पूर्ति किसान कुछ एक वर्षों तक किराया प्रभारों के नकद भुगतान द्वारा करेगा।¹⁸⁷ संक्षेप में जमींदारी अधिकारों को खोने के लिए जमींदारों को क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए तथा उन्हें पट्टेदारी के अंतर्गत भूमि का कुछ भाग अपनी जोत के लिए रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निष्क्रिय लगान बसूलने वाले जमींदार सोत्साह पूँजी निवेशक उद्यमी किसान

और जमींदार का रूप ले लेंगे। रानाडे ने अपनी योजना को और अधिक स्पष्ट रूप देते हुए ये प्रस्ताव सामने रखे कि बंगाल में 2 3 मौलूमी हकवाले भूभाग पर और 1/2 गैर-मौलूमी हकवाले भूभाग पर किसानों को एकाधिकार दे देना चाहिए और 1,3 मौलूमी भूभाग और 1/2 गैरमौलूमी भूभाग जमींदारों को उनकी निजी भूमि के रूप में सौंप देना चाहिए क्योंकि रानाडे का विश्वास था कि इस विभाजन में जमींदार की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। अतः उनका इस संबंध में आगे और मुझाव यह था कि अधिकारों और दायित्वों के मनुलन को व्यवस्थित रखने के लिए किसानों को व्यापक समेत कर मूल्य के भुगतान के लिए घटी हुई ज़ोतों पर भी तीस अथवा चालीस वर्षों तक पुनः लगान का भुगतान करने रहना चाहिए। सरकार एकदम एकाधिकार पाने के लिए चुकाया जाने वाला अपिम रकबा किसानों को ऋण रूप में दे सकती है। यह ऋण राशि उनके अनुसार 340 करोड़ रुपये देंगेगी।¹⁹⁹ इस प्रकार रानाडे की आशा थी कि निहित अधिकारों का बिना किसी प्रकार में उल्लंघन किए बंगाल में किसानों की एक अथवा दो पीढ़ियों में मुक्ति सुलभ हो जाएगी।¹⁸⁹ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र किसान और पंजीनिष्ठ जमींदार के बारे में रानाडे की सारी की सारी योजना जमींदारों के पक्ष में थी। उनके द्वारा प्रस्तावित सुधारों से स्वतंत्र कृषकों के विकास का इतनी सहायता नहीं मिलती थी जितनी लगान वसूलने वाले जमींदारों के पूंजीपति जमींदार के रूप में विकास का प्रगति मिलती थी। उनका स्वतंत्र स्वामित्व का मित्रता भी कृषकों में भूमि विवरण की अपेक्षा जमींदारों को भूमि सौंपने पर आधारित था। वास्तविकता यह थी कि उनकी भूमि सुधार की यह योजना किसानों के हितों के इतनी अधिक प्रतिकूल थी कि उसका अनुमान ही नहीं किया जा सकता था। उनके अनुसार मर्यादित अथवा असुरक्षित पट्टेदार किसान अपनी वर्तमान स्थिति के बदले भूमि के स्वतंत्र स्वतंत्र अधिकारी की नई उपाधि ग्रहण करना चाहेगा।

कुछ भारतीय नेताओं ने भारतीय कृषि के विकास के लिए पूँजी और श्रम के मेल की मांग करते समय रानाडे की भारतीय कृषि के संस्थागत पुनर्गठन की प्राथमिक योजना का अस्पष्ट समर्थन ही किया।¹⁹⁰ इस योजना को व्यापक और स्पष्ट समर्थन विरल ही मिला। ऐसा 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन में देवराव विनायक का भाषण ऐसा ही एक विरल समर्थन था जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि पर केवल उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जो उसमें सुधार कर सकें कि गरीब तथा अभावग्रस्त किसानों का। उनका दावा था कि वास्तव में संपन्न लोगों के एक छोटे वर्ग, मध्यवर्ती वर्ग, की सृष्टि द्वारा देश की कृषि संपदा बढ़ाई जा सकती है।¹⁹¹ इस योजना के विरुद्ध, 'डॉन' के संपादक सतीशचंद्र मुखर्जी का स्पष्ट मत था कि पूँजीनिष्ठ कृषि देश के लिए हानिप्रद और अवांछनीय है। एक ओर यह बेकारी को जन्म देती है और दूसरी ओर इससे किसानों के आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है।^{191-A}

कृषि और उद्योग

कुछ एक भारतीय नेताओं ने कृषि विकास की समस्या को और किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार को भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक संदर्भ में देखा और इस निष्कर्ष पर पहुँचे

कि कृषि की प्रगति देश के उद्योगों के साथ और द्रुतविकास के साथ बड़ी घनिष्ठता से संबंधित है। जब तक देश के ग्रामीण की प्रवृत्ति को शीघ्रता से रोका नहीं जाता देश की कृषि समस्या के समाधान की दिशा में किया जाने वाला कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता।

इस दृष्टिकोण के प्रारंभिक प्रस्तावक के रूप में रानाडे ने 1881 में तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय कृषि में व्याप्त रोग का मूल कारण राजनीतिक पद्धति के गहरे अन्तर्गत में निहित है अतः बाहरी उपचार अथवा चमड़ी पर मर्हम पट्टी करने का कोई लाभ नहीं होगा। स्थिति के उपचार के लिए किसी भी अन्य वस्तु में बहचदकर अपेक्षित यह है कि कृषि पर राज्य के भार को कम किया जाए और श्रम, उद्योग और फालतू पूँजी के लिए नए मार्ग खोलकर धरती पर आबादी का भार घटाया जाए।¹⁹ बाद में 1892 में रानाडे ने 'भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर दिए गए अपने भाषण में इस मित्रता का प्रतिपादन किया कि कृषि पर सदा के लिए निर्माण रहने वाले देश का निर्धन रहना तथा अपेक्षाकृत और अधिक निर्धन बनते जाना निश्चित है क्योंकि कृषि तो ह्रासमान प्रतिफल नियम (ला आफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स) की अवांछनीय स्थिति के अंतर्गत संचालित होती है और भारत में तो वर्षा की अनिश्चितता का एक और दुर्गुण इसके साथ जुड़ा है।²⁰ मराठा ने 1881-84 की अवधि में अपनी संपादकीय माला में कृषि प्रगति और औद्योगिक प्रगति के घनिष्ठ रूप से अन्योन्याश्रित होने पर बार बार जोर दिया। उदाहरणार्थ, 4 सितंबर 1881 के अंक में उसने लिखा :

कृषि संबंधी श्रम बाजार में कृषक श्रमिकों का आधिक्य है और जब तक यह आधिक्य कृषि में हटाया नहीं जाता और कहीं दूसरे स्थान पर खपाया नहीं जाता तब तक कृषकों की दीन-हीन दशा में सुधार के लिए उपचार रूप में किए गए किसी भी प्रयास का उत्तम, लाभप्रद और स्थायी परिणाम नहीं निकलेगा। कृषि और मशीनी उद्योग का विकास साथ साथ ही होना चाहिए।

इसी प्रकार अपने 12 फरवरी 1882 के अंक में उसने तर्क प्रस्तुत किया 'केवल कानूनों में, बैंकों में यहाँ तक कि किसानों को स्थायी रूप में काश्तकारी के अधिकार देने में किसानों की हालत में तब तक कोई सुधार नहीं होगा, जब तक कि देश में विविध उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती क्योंकि एकमात्र कृषि पर निर्भर रहने वाला देश कभी संपन्न नहीं रह सकता।'²¹ नेटिव ओपीनियन ने भी अपने 25 मई 1884 के अंक में इस तर्क को दोहराया।

1895 में पी० सी० राय ने रानाडे के विचारों से सहमति प्रकट करने हुए घोषणा की कि कृषि प्रधान देश दस्तकारी और हस्तशिल्पियों के देश की अपेक्षा नदब पिछड़ा रहेगा। देश की आर्थिक कठिनाइयों का सर्वोत्तम समाधान मृतप्राय भारतीय उद्योगों का पुनरुद्धार तथा पश्चिम के आधुनिक उद्योगों को अपनाना है। इसमें कृषि में श्रम का आधिक्य कम होगा और देश संपन्न बनेगा।²²

जी० बी० जॉशी ने जमीन पा लेने की अस्वस्थ और अत्यधिक प्रतियोगिता के लिए कृषि पर बढ़ते भार को उत्तरदायी ठहराया। उनके अनुसार इस प्रतियोगिता का दुष्परि-

णाम यह हुआ है कि घरती के लगान गगनचुंबी हो गए हैं, घरती को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ा है और किसान की घरती सुधारने की आकांक्षा क्षीण हुई है।¹⁹⁶ इसके अतिरिक्त कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते भार ने बेकारी बढ़ाई है और लाखों को जबरदस्ती निकम्मा बना दिया है अथवा दूसरे शब्दों में इसने देश की आर्थिक शक्ति को विनाशात्मक रूप से बेकार कर दिया है। उनकी संगणना के अनुसार आधी से अधिक ग्रामीण जनता वास्तव में उपयुक्त काम के अभाव का शिकार थी।¹⁹⁷ अतएव उन्होंने फालतू और बेकार जनसंख्या को समुचित काम जुटाने के लिए अकृषीय उद्योगों के विकास की सिफारिश की। उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि धर्म के नए अवसरों को जुटाने के रूप में वर्तमान अस्वस्थ और असामान्य दबाव से किसान जितना ही अधिक मुक्त होगा उतनी ही अधिक उसकी कार्यस्थिति भाररहित होगी और सफलता के अधिक अच्छे अवसर उमें उपलब्ध होंगे।¹⁹⁸ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब तक भारत एकमात्र कृषि-उद्योग पर निर्भर है, हमारी आर्थिक कठिनाइयों का मूल अछूता ही रहेगा।¹⁹⁹ तिलक के केसरी ने 18 जून 1901 तथा 11 नवंबर 1902 के अंकों में इन दोनों धारणाओं की पुष्टि की।²⁰⁰

जी० मुन्नाय्य अय्यर ने भी 1903 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'सम इकोनामिक आसाईकटन आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में इसी विचारधारा को अमंदिग्ध अभिव्यक्ति दी। रूस के वित्तमंत्री एम० डी० वित्ते के इस कथन से सहृदयता प्रकट करने हुए कि जब तक कोई भी देश विगुद्ध रूप से कृषिप्रधान देश बना रहेगा, तब तक वह समय समय पर आने वाले अकालों और सामान्य दरिद्रतापरक अभावों से मुक्ति नहीं पा सकेगा, अय्यर ने आरोप लगाया कि इस संबंध में भारत की स्थिति रूस से भी बदतर है। यहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और शेष मजदूरी अथवा छोटे छोटे अनुत्पादक धंधों पर आश्रित है। उन्होंने लिखा कि जब तक देश की आर्थिक दशा की इस गंभीर अव्यवस्था का उपचार नहीं किया जाता तब तक हजारों वर्षों की अवधि में भी न यहां का किसान संपन्न बन पाएगा और न ही दूसरे वर्ग समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। निर्धनता की इस चरम सीमा का निराकरण कभी नहीं हो पाएगा। अतएव देश का उद्योगीकरण देश की संपन्नता की अनिवार्य शर्त है।²⁰¹

संदर्भ

एकमात्र अपवाद 1899 का था और वह भी पंजाब लैंड एलियेशन बिल पर प्रस्ताव के रूप में। कांग्रेस ने और बातों के साथ इस बात की भी सिफारिश की कि निजी किराया वसूली वाले जमींदारों के मामले में अनुचित रूप से किराये में बढ़ोतरी रोकने की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। (प्रस्ताव II बी) जमींदारी पर कांग्रेस की चुप्पी को ए० ओ० ह्यूम की पुस्तिका, 'हिंदुस आन ऐग्रीकल्चरल रिफार्म इन इंडिया' में की गई टिप्पणियों, तीखी भर्त्सनाओं, 'पूर्णतः भूस्वामी', 'किराया वसूली करने वाले बेकार बिचौलिया' आदि के संदर्भ में देखिए उनकी पुस्तिका 'हिंदुस

बान एंथ्रोक्लरल रिफॉर्म इन इंडिया' (कलकत्ता 1889, पृ० 3)।

- 2 'सोम प्रकाश', 14 जून (आर० एन० पी० बग०, 19 जून 1880), नवविभाकर 12 जुलाई (वही 17 जुलाई 1880), बर्दवान सजीवनी, 9 नवंबर (वही, 20 नवंबर 1880), भारत बन्धु, 26 नव० (आर० एन० पी० पी० एन०, 2 दिसंबर 1880), साधारणी, 15 मई (आर० एन० पी० बग०, 21 मई 1881), केरल मित्रन, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एम०, मई 1881), हिंदी प्रदीप अगस्त (आर० एन० पी० पी० एन०, 3 सितंबर 1881), इंडियन स्पेक्टेटर 25 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 1 अक्टू० 1881) परिदृश्य, 1 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 14 जनवरी 1882), सोम प्रकाश, 26 जून, वही, 1 जुलाई 1892, उच्चल दीपिका 15 जुलाई (वही, 22 जुलाई 1882), प्रयाग समाचार, 11 दिसंबर में प्रकाशित लेख (आर० एन० पी० पी० एन०, 14 दिस० 1882), साधारणी, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 13 जनवरी 1883), समय, 28 मई (वही 2 जुलाई 1883), सहचर, 18 जुलाई (वही, 28 जुलाई 1883), ग्रामवर्न प्रकाशिका, 22 मार्च (वही, 5 अप्रैल 1884), समय, 29 दिसंबर 1884 (वही, 3 जनवरी 1885), सहचर, 6 मई (वही 16 मई 1885), सुगंधि या पनाका 9 दिस० (वही 18 दिसंबर 1886), सजीवनी 14 जनवरी (वही, 21 जनवरी 1892), प्रवृत्ति 21 जनवरी (वही 29 जनवरी 1892), सजीवनी 11 फरवरी (वही, 15 फरवरी 1892), बगनिवासी 25 जन० (वही, 2 नवंबर 1895), चारु मिहिर 27 अप्रैल (वही 9 मई 1896), केरल पत्रिका 16 नव० और केरल सचारी 20 नवंबर (आर० एन० पी० एम०, 30 नव० 1895), केरल चंद्रिका, 20 मार्च (वही, 31 मार्च 1896) केरल सचारी, 1 जुलाई (वही 15 जुलाई 1896), हिंदुस्तान 25 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 31 अगस्त 1896) और आगे उन्निश्चित समाचारपत्र और देखिए, मराठा, 17 फरवरी 1884
- 3 बंगाली 23 जनवरी 1892 भी देखें
- 4 आर० एन० पी० बग०, 29 जुलाई 1882
- 5 वही, 21 जून 1884
- 6 वही, 7 नवंबर 1891
- 7 आर० एन० पी० एम०, 24 जनवरी 1894
- 8 आर० एन० पी० एम०, 31 मार्च 1896 तथा दक्षिण केरल पत्रिका, 1 जगहन, 12 और 20 दिसंबर (वही 15 अगस्त, 31 दिसंबर 1896)
- 9 वही 15 जुला० 1896
- 10 दन पाजटरा इन बंगाल प० 210 24
- 11 वही पृ० 46 और भाग
- 12 गाय पावर्न, पृ० 179-200, इंडियन फाइनामेन 1, 39 40, 55 57
- 13 जगता पूर्वोद्धन पृ० 870-94, 900 01 904-05
- 14 वही पृष्ठ 884
- 15 वही, पृ० 351-2 तथा पृ० 412
- 16 गम० एम० अय्यर स्पीचज एंड राइजिंग, पृ० 250 4 सोम प्रकाश, 14 जून (आर० एन० पी० बग०, 19 जून 1880) साधारणी, 23 जन० (वही, 29 जनवरी 1881), सोम प्रकाश, 14 अगस्त वही, 19 अगस्त 1882) कविवचनसूधा, 5 मार्च (आर० एन० पी० पी० एन०, 15 मार्च 1883) एम० एन० बैनर्जी स्थानत्र 11 पृ० 15, 17, केरल पत्रिका, निरिहति

- (आर० एन० पी० एम०, मार्च 1886); एच० ए० वहीम, रिप० आई० एन० सी० 1890, पृ० 55, वगनिबानी, 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 2 नवंबर 1895), केरल पत्रिका, 16 नवंबर और 14 दिसंबर (आर० एन० पी० एम०, 30 नवंबर और 31 दिसंबर 1895), केरल पत्रिका, 4 जुलाई और 1 अगस्त (वही, 15 जुलाई और 15 अगस्त 1896), हिंदुन्नाम, 25 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 31 अगस्त 1898), राय पावर्टी, पृ० 217, 273, मालवीय, स्पेन्जे, पृ० 266-8, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 98, आई० एन० सी० 1899 का प्रस्ताव II (बी०)
- 17 गनाडे एसज, पृ० 30-1, 327, जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 878-84, दन पीछ जहाय 9 में पाद टिप्पणी 116 तथा सी० पी० ए०, पृ० 482, अपेन नेटमें, पृ० 18, 74-8 में तथा ज० एन० गुप्ता पूर्वोद्धृत, पृ० 349
- 18 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 365-6
- 19 आर० एन० पी० बग०, 8 अक्तूबर 1881
- 20 आर० एन० पी० बग०, 29 जुलाई 1882 तथा देखिए सोम प्रकाश, 27 नवंबर (वही, 2 दिसंबर 1882)
- 21 बगाली 19 फरवरी 1881, सोम प्रकाश, 14 जून (आर० एन० पी० बग०, 19 जून 1880); सोम प्रकाश, 27 नवंबर (वही, 2 दिस० 1882); भारत मित्र, 22 जनवरी (वही, 2 फरवरी 1884); तथा देखिए चांगे पाद टिप्पणी 71 यहा यह उल्लेखनीय है कि किरायेदारों के स्थाई बन्दोवस्त की माग को सर्वप्रथम 1831 में राजा राममोहन राय ने ही मुखरित किया था अभिन मेन नोट्स आन बंगाल रिनेमा (कलकत्ता, द्वितीय संस्करण 1957) पृ० 12, बी० बी० मजूमदार: पूर्वोद्धृत, पृ० 67-9 सोम प्रकाश ने अपने 24 जुलाई 1882 के छक में अपने दृष्टिकोण के समर्थन में राममोहन राय का मत उद्धृत किया था (आर० एन० पी० बग०, 29 जुलाई 1882).
- 22 आर० एन० पी० बग०, 26 मार्च 1887, बगबासी, 16 दिसंबर (वही, 23 दिस० 1893).
- 23 आर० एन० पी० बग०, 22 अक्तूबर, 1881.
- 24 विवेक रूप से देखिए, मराठा, 27 जुलाई 1890 और ए० बी० पी०, 20 फरवरी 1899.
- 25 इस सवध में राष्ट्रवादी विचारधारा की मूल्यता का उपलब्ध कारण कदाचित यह हो सकता है कि विभिन्न प्रांतों के स्वदेशी पत्रों के सजाददाताओं ने इस सवध में अपेक्षित प्रतिवेदन ही न भेजे हो यहा इस तथ्य की ओर हम अवश्य निर्देश करना चाहेंगे कि हमने जितने भी राष्ट्रवादी पत्रों और पत्रिकाओं का उनकी मूल भाषा में तथा साथ ही साथ राष्ट्रवादियों के लेखों और भाषणों का अध्ययन किया है, उनसे हम इस परिणाम पर ही पहुंचे हैं कि ये सब तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं की इस विषय में वैचारिक गहराई और हबि क अभाव के ही परिचायक हैं, साथ ही यह निष्कर्ष निकालना भी गलत और अनुचित न होगा कि यदि सजाददाताओं ने व्यापक तथा प्रबल दृष्टिकोण के सवाद भेजे होते तो विषय की गंभीरता को देखते हुए पत्र-पत्रिकाओं द्वारा उनकी उपेक्षा कदापि सम्भव न होती.
- 26 सी० ई० बर्कलेट : बंगाल ग्रहर् दो सेफ्टिनेट गवर्नर (कलकत्ता 1901) खंड II, पृ० 705, 812-3; हलबर्ट, एम० सी० पी० 1883 खंड XXII, पृ० 77-8; स्ट्रैचो : इंडिया (1903) पृ० 424. जमींदारों द्वारा किसानों के दमन के लिए सरकारी रिपोर्ट के अवतरण देखिए, जिन्हें पार्वती चरण राय ने अपने ग्रंथ 'दि रेंट क्वेश्चन-इन बंगाल' (कलकत्ता 1883) पृ० 122 और जाने में पुनरुद्धृत किया है.

27. बकलैंड . पूर्वोद्धृत, खंड I, पृ० 544-8, खंड II, पृ० 631-2, 636-3
28. वही, खंड II, पृ० 702; स्ट्रैची : इंडिया (1903) पृ० 425-6
29. बकलैंड पूर्वोद्धृत, खंड II, पृ० 704-05, 813.
30. इलवर्ट . एल० सी० पी० 1883 खंड XXII पृ० 80-3
31. वही, पृष्ठ 84-8.
32. वही, पृष्ठ 100-126.
33. बकलैंड . पूर्वोद्धृत, खंड II, पृष्ठ 809.
- 33-A. वही, पृष्ठ 811-2 और 1885 का अधिनियम VIII
34. देखिए, 1885 के अधिनियम की धारा-49.
35. नाथन लाइफ आफ दि मोरक्विस आफ डफरिन गेड एवा (लंदन 190५), खंड II, पृ० ४0.
36. बकलैंड पूर्वोद्धृत, खंड II, पृ० 816.
37. जर्नल आफ इस्ट इंडिया एसोसिएशन, खंड XV सख्या 3, 1883, पृ० 191.
38. जे० एन० गुप्ता . पूर्वोद्धृत, पृ० 101-03 पर आर० सी० दत्त और ए० पी० मँकडोनल
39. 27 जून 1881 को इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रेषित ज्ञापन बागल पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट, पृ० I, II, XIV पर. 1879-80 का इंडियन एसोसिएशन का प्रतिवेदन, ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन के 25 अगस्त 1881 के अंक में उद्धृत; इंडियन एसोसिएशन का 29 अक्टूबर 1883 का विज्ञापन इंडियन एसोसिएशन का 1883 का प्रतिवेदन, पृ० 15 और आगे; एस० एन० बैनर्जी . स्पीचेज II, 6-11; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 28 अक्टूबर. 9, 16 दिसंबर 1880 19 मई, 16 जून, 18 अगस्त 1881; बंगाली, 24 जुलाई, 14, 21 अगस्त, 4 सित०, 9 अक्तू, 13 नव० 11, 18 दिस० 1880; 8, 15, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 17, 24, 31 मार्च, 7 अप्रैल, 1 नवंबर 1884; समालोचक, 27 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 1880); मोम प्रकाश, 9 अगस्त (वही, 14 अगस्त 1880); साधारणी 15 अगस्त (वही, 21 अगस्त 1880), नव विभाकर, 10 जनवरी (वही, 22 जन० 1881); परिदर्शक, 6 फर० (वही, 19 फरवरी 1881); साधारणी, 13 मार्च (वही, 26 मार्च 1881); सुधाकर, 14 मई (वही, 21 मई 1881); बंगबासी, 11 नवंबर (वही, 18 नवंबर 1882), साधारणी, 24 दिस० (वही, 30 दिस० 1882); इंडियन मिरर, 31 मार्च / वी० ओ० आई०, अप्रैल 1883); ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 9, 16, 23 अप्रैल (वही, मई 1883), और 5, 21 जुलाई (वही, जुलाई 1883); बंगबासी, 7 जुलाई, भारत मिहिर, 17 जुलाई, प्रतिनिधि, 12 जुलाई. साधारणी, 24 जून, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 14 जुलाई, सजीवनी, 7 जुलाई (वही, जुलाई 1883); साहस, 23 जुलाई, नव्यभारत, 30 जुलाई (वही, 30 अगस्त 1883); सहचर, 28 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 31 मार्च 1883); भारत बधु, 31 मार्च, प्रभाती, 3 अप्रैल (वही, 7 अप्रैल 1883); साधारणी, 15 जुलाई (वही, 28 जुलाई 1883); सजीवनी, 11 अगस्त, बंगबासी, 11 अगस्त (वही, 25 अगस्त 1883); समय, 10 सित०, आलोक, 14 सितंबर (वही, 22 सित० 1883), हार्बेशहर प्रकाशिका, 3 नवंबर (वही, 17 नव० 1883); ग्रामवर्त प्रकाशिका, 10 नव० (वही, 24 नव० 1883); बवंदान सजीवनी, 4 दिस० मन्त्रि, 7 दिस०, प्रजाबधु, 4 दिस० (वही, 8 दिसंबर 1883); भारत मिहिर, 11 दिसंबर (वही, 22 दिसंबर 1883); बंगाल पब्लिक ओपीनियन, 20 दिस० 1883 (बी० ओ० आई०, 15 जनवरी 1884), इंडियन नेशन, 7 जनवरी (वही, 31 जनवरी 1884); बंगाल पब्लिक ओपीनियन,

- 10 अप्रैल (वही, 30 अप्रैल 1884), मजीवनी, 16 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 23 फरवरी 1884), ग्रामवर्ग प्रकाशिका, 16 फरवरी, प्रतिहार, 22 फरवरी (वही, 1 मार्च 1884)
- 40 उमी प्रकार इस पत्र ने 19 फरवरी 1881 के अंक में दृढ़तापूर्वक लिखा राष्ट्र का गठन किसमें होता है ? क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कुछ सी सदस्यों में ? अथवा मुफ़्तिस्ल में मिलन वात कुछ हजार जमींदारों में ? अथवा मैकडो हजारा वनहस्तावासियों में ? राष्ट्र का भाषणी में निवास करता है - वस्तुतः बंगाल की यह गयी अल्पक जनता ही है, जिससे वास्तव में राष्ट्र का गठन होता है इसी प्रकार अन्य सबन मायनाओं के लिए दक्षिण, बंगाली, 14 अगस्त, 13 नवंबर 1880 15 जनवरी 1881, ब्राह्मण पत्रिका ओपीनियन, 9 दिसंबर 1880, 25 अगस्त 1881, एन० एन० वैनर्नी स्टीचर II, पृ० 13 20 साधारणी, 15 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 28 मार्च 1881), मजीवनी 11 अगस्त (वही 25 अगस्त 1883), बंगाल पत्रिका ओपीनियन, 20 दिसंबर 1883 गी० आ० घाट, 15 जनवरी 1884)
- 41 इंडियन एसोसिएशन का 1879-80 का वार्षिक वार्षिक विवरण 25 अगस्त 1881 के ब्राह्मण पत्रिका ओपीनियन में उद्धृत विज्ञापन के प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित गये थे एसोसिएशन ने बंगाल सरकार का 27 जन 1881 की विनियमों की कानून एक जापान मजा वाचन पूर्वोद्धृत परिशिष्ट 'ए' में उद्धृत और दूसरा जापान 29 अक्टूबर 1883 को भजा (इंडियन एसोसिएशन का 1883 का वार्षिक विवरण) पृ० 15 और आग
- 42 वाचन पूर्वोद्धृत, पृ० 50, 53 1 70 1, 90 और परिशिष्ट, पृ० 1, बंगाली, 8 जनवरी, 5, 17 फरवरी 2 अप्रैल 14 25 मई 1881, ब्राह्मण पत्रिका ओपीनियन 20 जनवरी 10 फरवरी 1881 इंडियन एसोसिएशन का पाचवा वार्षिक विवरण, 4 मार्च 1882 के बंगाली में उद्धृत, ए० बी० पी०, 25 जून 1885.
- 43 वाचन पूर्वोद्धृत, पृ० 53-54, 71, ए० बी० पी०, 25 जून 1885.
- 44 वाचन पूर्वोद्धृत, पृ० 72-3, 78 इंडियन एसोसिएशन के 1885 में पाचवा वार्षिक विवरण में इस मदर्श में बढ़ा गया इस समय एसोसिएशन बड़ी सत्रियता से ग्राम सभा के निर्माण में जुटी हुई है शक्ति के प्रदर्शन के लिए आयोजित किए जाने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों की सफलता के लिए लोगो की विपुल सम्यो के सधो की बड़ी भारी आवश्यकता है यह तथ्य अब हमारे सामने आता है कि हमारा आंदोलन थोड़े से शिक्षित बाबुओं तक सीमित है तो हमारे मन में बड़ी ही कसक पैदा होती है एसोसिएशन ने इस कसक अथवा कलक को मिटाने का सकल्प कर लिया है (उमी में उद्धृत, पृ० 90) तथा देखिए, बंगाली, 4 मार्च 1882
- 45 और देखिए, मराठा 10 अप्रैल, 7 सितंबर 1884
- 46 बी० ओ० आई०, मार्च 1883 और आर० एन० पी० बग०, 31 मार्च 1883; इंडियन स्पेक्टेटर, 24 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 30 जुलाई 1881) और 1 अप्रैल तथा 1 जुलाई (बी० ओ० आई० अप्रैल और जुलाई 1883) भी देखें
- 47 नेटिव ओपीनियन ने बाद में अपनी स्थिति बदल ली और बिल का विरोध करना प्रारंभ कर दिया देखिए, उसका दिनांक 11 नवंबर 1883 का अंक
- 48 बाबे क्रानिकल, 25 फरवरी (बी० ओ० आई०, मार्च 1883) ट्रिब्यून, 7 अप्रैल (वही, अप्रैल 1883) रास्त गोफ़तार, 4 नवंबर (वही, नव० 1883) जामेअमजेद, 20 दिसंबर 1883 बाबे क्रानिकल, 30 दिसंबर 1883 गुजराती समाचार, 1 जनवरी (वही, 15 जनवरी 1884) केसरी, 16 मार्च (वही, मार्च 1885)

49. रानाडे : एसेज, पृ० 275-7.
50. दत्त स्पीचेज II, पृ० 170 तथा जे० एन० गुप्ता : पूर्वोद्धृत, पृ० 50, 98-103.
51. उदाहरणार्थ, भारत मिहिर, 17 अगस्त, ढाका प्रकाश, 22 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 28 अगस्त 1880); भारत मिहिर, 14 सित० (वही, 25 सित० 1880); बिहार बध्, 9, 16, 23 सितंबर (वही, 2 अक्टूबर 1880); सोम प्रकाश, 3 जनवरी (वही, 8 जनवरी 1881), ढाका प्रकाश, 16 जनवरी (वही, 22 जनवरी 1881); बिहार हेराल्ड, 13 मार्च (बी० ओ० आई०, मार्च 1883), इंडियन कानिकल, 21, 28 मई, लिबरल, 3, 10 17 जून (वही, जून 1883), चारु वर्त, 2, 9 जुलाई (वही, जुलाई 1883), उत्पल दीपिका, 30 दिसंबर 1882 (आर० एन० पी० बग०, 20 जनवरी 1883), उत्कल दर्पण, 21 जनवरी (वही, 10 फरवरी 1883), चारु वर्त, 5 फरवरी (वही, 17 फरवरी 1883); सोम प्रकाश, 27 अगस्त (वही, 1 सितंबर 1883), 10 सितंबर (वही, 22 सितंबर 1883); ढाका प्रकाश, 11 नवंबर (वही, 17 नवंबर 1883); इंडियन कानिकल, 22, 29 दिसंबर 1884 (बी० ओ० आई०, जनवरी 1885); नवविभाकर, 9 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 14 मार्च 1885), बी० एन० माउन्टिक . स्पीचेज, पृ० 636 7, 640-1, 645.
52. बी० ओ० आई०, जनवरी 1885 तथा देखिए ए० बी० पी० 3 मार्च 1880, 7 दिसंबर 1882, 19 मार्च 1885, आनंद बाजार पत्रिका, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 4 मिन० 1880). 12 फरवरी (वही, 17 फरवरी 1883); तथा देखिए, कविचन मुधा, 26 मार्च (आर० एन० पी० बी० एन०, 5 अप्रैल 1883). यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1883 के पट्टेदारी टेनेमी बिल पर रानाडे के प्रहार का यह एक आधार था. रानाडे की आशंका यह थी कि इस बिल में एक वर्ग के दूसरे वर्ग के बीच हस्तक्षेप की सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है जिसका दुरुपयोग वह वर्ग-समर्थ को जन्म देने और बढ़ाने में कर सकती है (एसेज पृ० 276) तथा देखिए, पृ० 283-4
53. ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1883; आनंद बाजार पत्रिका, 20 जून (आर० एन० पी० बग०, 5 जुलाई 1883), और 21 जुलाई (वही, 26 जुलाई 1881) देखिए, शिवाजी, 8 फरवरी (बी० ओ० आई०, 15 फरवरी 1884)
54. ए० बी० पी०, 10 मार्च 1881, 21 मार्च 1884, 19 मार्च 1885; आनंद बाजार पत्रिका, 14 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 26 मार्च 1881) तिथिग्रहित (बी० ओ० आई०, फरवरी 1883) तथा आगे 61-3 पाद टिप्पणियों में उद्धृत.
55. ए० बी० पी०, 22, 29 नवंबर 1883; गान्धी पब्लिक ओपीनियन, 29 नव०, 6, 13 दिस० (बी० ओ० आई० दिस० 1883 ; बंगाली, 24 नव०, 15 दिसंबर 1883, समय, 26 नवंबर, आनंद बाजार पत्रिका 26 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 1 दिस० 1883), नवविभाकर, 3 दिसंबर (वही, 8 दिसंबर 1883); भारत मिहिर, 11 दिस० (वही, 22 दिस० 1883); इंडियन स्ट्रैटेजर, 2 दिसंबर, लिबरल, 25 नवंबर इंडियन मिरर, 27 नवंबर, 13 दिसंबर, इंडियन ह्वो, 27 नव०, भारत मिहिर, 27 नव०, नवविभाकर, 26 नवंबर (बी० ओ० आई० दिसंबर 1883), मराठा, और गुजराती मिस्र, 23 दिसंबर 1883 (वही, 15 जनवरी 1884).
56. 30 अगस्त के नवविभाकर में एक संवाददाता (आर० एन० पी० बग०, 4 सित० 1880); भारत मिहिर, 21 दिस० 1880 (वही, 1 जन० 1881); बिहार हेराल्ड 27 मार्च 3 अप्रैल (बी० ओ० आई० अप्रैल 1883); इंडियन कानिकल, 21, 28 मई (वही, मई 1883); इंडियन कानिकल 21 जन०, 4 फर०, बिहार हेराल्ड 29 जन० (वही, 15 फर० 1884); साधारणी, 7 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 13 दिस० 1884).

- 57 ढाका प्रकाश, 16 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 22 जनवरी 1881); बिहार हेराल्ड, 12 और 19 फरवरी (बी० ओ० आई०, 29 फरवरी 1884)
- 58 बिहार वधु, 9, 16, 23 मितबर (आर० एन० पी० बंग०, 2 अक्तूबर 1880); हिंदू रजिका, 8 दिस०, ढाका प्रकाश, 12 दिस० (वही, 18 दिसबर 1880); भारत मिहिर, 21 दिसबर 1880 (वही, 1 जनवरी 1881); सोम प्रकाश, 9 मार्च (वही, 14 मार्च 1885)
- 59 30 अगस्त के नवविभाकर का एक सवाददाता (आर० एन० पी० बंग०, 4 मितबर 1880); भारत मिहिर, 7 सितबर (वही, 18 मितबर 1880), उक्तल दीपिका, 23 जून (वही, 7 जुलाई 1883; बिहार हेराल्ड 8, 15 अप्रैल (बी० ओ० आई०, 30 अप्रैल 1884); साधारणी, 7 दिसबर (आर० एन० पी० बंग०, 13 दिसबर 1884)
- 60 बिहार हेराल्ड, 27 मार्च, 3 अप्रैल (बी० ओ० आई०, अप्रैल 1883), इंडियन कानिकल 30 जुलाई (वही, अगस्त 1883), बिहार हेराल्ड, 11, 18 मार्च (वही, 31 मार्च 1884).
- 60 ए. ए० बी० पी०, 3 और 10 मार्च 1881, 21, 28 फरवरी और 6 नवबर 1884 तथा 19 मार्च 1885 उगने अपने 3 मार्च 1881 के एक में यह भी निर्देश किया कि वस्तुतः बंगाल के गावों का त्रिचौनिया बाबू था जिन्होंने परीक्षा पास कर रखी थी और जो 'निश्चिन्ता, पढ़ता और गरजता' था
- 61 आनंद बाजार पत्रिका, 12, 19, 26 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 17, 24 फरवरी, 3 मार्च 1883 और ए० ओ० आई० फरवरी 1883) और 23 जुलाई (बी० ओ० आई० अगस्त, 1883).
- 62 आनंद बाजार पत्रिका, 5, 19 नवबर (आर० एन० पी० बंग०, 10, 24 नवबर 1883); 10 मार्च, 18 अगस्त, 22 मितबर (वही, 15 मार्च, 23 अगस्त, 27 मितबर 1884); 3 अगस्त (वही, 8 अगस्त, 1885)
- 63 आनंद बाजार पत्रिका, 26 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 3 मार्च 1883); 10 मार्च, 18 अगस्त (वही, 15 मार्च, 18 अगस्त 1884) तथा देखिए, नवविभाकर, 17 नवबर (वही, 22 नवबर 1884).
- 64 बंगाली 17 नवबर (आर० एन० पी० बंग०, 24 नवबर 1882), भारत मिहिर, 20 नवबर, 11 दिसबर (वही, 1, 22 दिसबर 1883), नवविभाकर 25 फरवरी, 7 नव० (वही, 1 मार्च, 22 नवबर 1884), साधारणी, 25 मई (वही, 31 मई 1884)
- 65 बंगाली, 24 जुलाई, 18 दिसबर 1880 ५ जनवरी 1881, 24, 31 मार्च, 7 अप्रैल 1883, 22, 29 नवबर 1884, इंडियन एमोसिएशन का 27 जन 1881 का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, इंडियन एमोसिएशन का 29 अक्तूबर 1883 का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, साधारणी, 24 दिस० (आर० एन० पी० बंग०, 30 दिस० 1882), मगटा, 15 अप्रैल 1883, इंडियन मिरर, 31 मार्च (बी० ओ० आई०, अप्रैल 1883), इंडियन नेशन, 22 अक्तूबर (वही नव० 1883, समय, 10 मितबर (आर० एन० पी० बंग०, 22 सितबर 1883); मजीवनी, 10 नवबर (वही, 17 नव० 1883); इंडियन नेशन, 7 जनवरी (बी० ओ० आई० 31 जनवरी 1884); ग्रामवर्त प्रकाशिका, 16 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 1 मार्च 1884). मजीवनी, 3 मई (वही, 10 मई 1884); एम० एन० वैनर्जी स्पीचेज II, पृ० 15
- 66 बंगाली, 15 जनवरी 1881, इंडियन एमोसिएशन का 2, जून 1881 का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल; इंडियन एमोसिएशन के तत्वावधान में विलिंगटन रबेयर कलकत्ता में हुई पट्टेदारों के सम्मेलन की कार्यवाही बंगाली, 2 अप्रैल 1881.

- 67 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन 6 फरवरी 1879, 16 दिसंबर 1880, बंगाली 24 जुलाई 1880 12 फरवरी 1881, 31 मार्च, 29 सितंबर 1883 22 नवंबर 1884 इंडियन एमोसिपेशन का 27 जून 1881 और 29 अक्टूबर 1883 का जापन पूर्वोक्त स्थल, इंदरान मजोरिती 2 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 13 मार्च 1880), साधारणी 24 दिसंबर (वही 30 दिसंबर 1882), भारत मिहिर, 17 जुलाई (बी० ओ० आई०, जुलाई 1883) इंडियन नेशन 22 अगस्त, 26 नवंबर (वही, नवंबर, दिसंबर 1883), इंडियन नेशन 5 फरवरी इंडियन नेशन 11 फरवरी (वही 29 फरवरी 1884) 21 फरवरी 1884 के अंक में तो बंगाली पर एक आलोचनात्मक लेख 1884 के पत्रेदारी बिल द्वारा जमींदारों को दिए गए हफ्ता के अधिकार पर भी आलोचना थी (बी० आई० 15 मार्च 1884)
- 68 एम० एन० बेंतली स्पेशल II पृ० 17, बंगाली 14, 21 अगस्त 4 25 सितंबर, 13 नवंबर 1880 29 जनवरी 5 फरवरी 1881 1 22 29 नवंबर 1884 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन 20 जनवरी, 1881 इंडियन एमोसिपेशन का 29 अक्टूबर 1883 का जापन पूर्वोक्त स्थल मार्च सुधार 17 मार्च (आर० एन० पी० बंग० 17 मार्च 1883) सप्ताह 14 जनवरी नव विभाग 19 जनवरी (वही 14 जनवरी 1885) प्रभात 10 फरवरी (वही 14 फरवरी 1884) नव पब्लिक ओपीनियन 1 अप्रैल 1883 15 अप्रैल 1883 20 अप्रैल 1884 इंडियन नेशन 7 जनवरी 24 जनवरी (आर० एन० पी० बंग० 1 जनवरी 1884)
- 69 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन 27 जनवरी और 11 अगस्त 1881 बंगाली 22 जनवरी 1881 इंडियन एमोसिपेशन का 27 जनवरी 1881 का जापन पूर्वोक्त स्थल प्रभात पर एक आलोचनात्मक लेख 23 अगस्त और 6 सितंबर (बी० ओ० आई०, सितंबर 1883) ग्रामवत प्रकाशिका 10 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 24 जनवरी 1884) प्रभात 6 फरवरी वही 14 फरवरी 1884)
- 70 इंडियन नेशन, 24 नवंबर (बी० ओ० आई० दिसंबर 1884) समय 1 22 दिसंबर (आर० एन० पी० बंग० 6 22 दिसंबर 1884)
- 71 सोम प्रकाश, 9 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 14 अगस्त 1880) बंगाली 12 फरवरी 1881, बंगाल पब्लिक ओपीनियन 10 नवंबर (बी० ओ० आई०, 31 जनवरी, 1884) ग्रामवत प्रकाशिका, 16 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 1 मार्च 1884), प्रभात 6 फरवरी (वही 14 फरवरी 1885) इंडियन एमोसिपेशन ने मांग की कि वह बार बढ़ाए गए करों पर 30 वर्ष तक की न्यूनतम अवधि के लिए स्थिर और निर्धारित माने जाएं 27 जून 1881 का जापन पूर्वोक्त स्थल) ग्रामवत प्रकाशिका ने 17 जनवरी 1885 के अंक में और समय ने 19 जनवरी 1885 के अंक में मांग की कि सरकार का हिसान से ही सीधे लगान का निपटारा करना चाहिए ताकि यह यह जनमत कर कि सचमुच वह भूमि का मालिक है और जमींदार तो केवल लगान दूर करने वाला है (आर० एन० पी० बंग० 24 जनवरी 1885)
- 72 बंगाली 7 अप्रैल 1883 12 अप्रैल, 1, 29 नवंबर 1884 मराठा 15 अप्रैल 1883, इंडियन एमोसिपेशन का 29 अक्टूबर 1883 का जापन पूर्वोक्त स्थल
- 73 इंडियन नेशन 24 नवंबर, इंडियन इको, 19 दिसंबर (बी० ओ० आई० दिसंबर 1884), समय 14 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 29 नवंबर 1884)
- 74 ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 30 जनवरी 1879, इंडियन एमोसिपेशन का 29 अक्टूबर 1883 का जापन, पूर्वोक्त स्थल, बंगाली, 1 नवंबर, 6 दिसंबर 1884
- 75 बंगाली, 24 जुलाई, 18 दिसंबर 1880 12 फरवरी 1881, 12 अप्रैल, 6 दिसंबर 1884, इंडियन

एसोसिएशन का 27 जून 1881 तथा 2) अक्टूबर 1883 का जापन, पूर्वोक्त स्थल

- 76) तुलसीय ए० मित्रा समग्र आय इंडिया 1951 ख० \ I (बंग बंगाल, सिक्किम और चट्टनगर) भाग 1 ए रिपोर्ट (दिल्ली 1951) पृ० 154 यद्यपि इन बातों (1859 और 1885 के विराये-दार (वेनेमी) कानून) का उद्देश्य किसानों का बमरनाम विराया और बदगुनी में बचाने का था तथापि व्यवहार में वे जमींदारों के तथा प्रत्यत किसानों के ही मूल्य पर ग्रामीण मध्य वर्ग और जातिदार के हित संरक्षक ही सिद्ध हुए। नाम उग मध्य वर्ग का तथा समृद्ध किसान वर्ग को पहुँचा जा पिछली शताब्दी में जमींदारों के विनाश के फलस्वरूप उभर कर अस्तित्व में आया था, यह वर्ग भूमिहीन मजदूरों का ज्ञान पर नरा पर उनकी फसल में हिस्सा बाँटता था और इस रूप में फैलता जा रहा था। यह शताब्दी में और पिछली शताब्दी में उग उग में अनुराग सरकार की गतिविधियों आवश्यकता का ज्ञान ही
- 77) बंगाली 31 मार्च 1880 तथा 1) 29 अक्टूबर 1883 29 नवंबर 1884 इंडियन एसोसिएशन का 29 अक्टूबर 1883 का जापन 1) अक्टूबर 1883 12 नवंबर 1883 ए० ए० पी० बंग 1 नवंबर 1883) मजबूती 1 नवंबर (29 नवंबर 1883) बंगाल पब्लिक ओपीनियन 1 पृ० 180 1883 आई 2) फरवरी 1884) समय 24 दिसंबर 1883 (आर० एन० पी० बंग 1 नवंबर 1884), मजबूती 2) अप्रैल (वही 26 अप्रैल 1884
- 8) इंडियन एसोसिएशन का 2) जून 1883 का जापन 1) अक्टूबर 1883, 29 सितंबर 1883 नवंबर 12 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 17 नवंबर 1883), मजबूती 17 नवंबर (वही 29 नवंबर 1883) बंगाल पब्लिक ओपीनियन 1 फरवरी (बी० ओ० आई० 29 फरवरी 1884) समय 24 दिसंबर 1883 (आर० एन० पी० बंग० 1 नवंबर 1884), 3 नवंबर (वही, 8 नवंबर 1884) 3 नवंबर 1884 के अर्थ में समय में प्रस्ताव दिया कि यह कानून बना देना चाहिए कि जिसमें उग अग्रिम का, जो स्वयं हल पर नहीं, मोहमी हक के हस्तांतरण पर निषेध घोषणा लागू हो
- 79) आर० एन० पी० बंग०, 17 नवंबर 1883
- 80) बंगाल पब्लिक ओपीनियन 7 फरवरी (बी० ओ० आई०, 29 फरवरी 1884), बंगाली, 29 नवंबर 1884 इंडियन इको 19 दिसंबर (बी० ओ० आई० दिसंबर 1884)
- 81) इंडियन एसोसिएशन का 1883 का जापन बंगाली द्वारा पुन उद्धृत, 28 फरवरी 1885 बंगाली, 21 फरवरी, 14 मार्च 1885 मराठा, 1 मार्च 1885 इंडियन नेशन, 2 अप्रैल (बी० ओ० आई० मई 1884), ग्रामवत प्रवाशिका 3 मई (आर० एन० पी० बंग०, 10 मई 1884), साधारणी, 21 सितंबर (वही, 27 सितंबर 1884), समय, 22 दिसंबर (वही, 27 दिसंबर 1884), इंडियन इको, 6 मार्च सजीवनी, 14 मार्च, साधारणी, 15 मार्च (बी० ओ० आई०, मार्च 1885); प्रभाती, 18 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 21 फरवरी 1885), प्रजाबधू, 20 फरवरी, समय, 23 फरवरी (वही, 28 फरवरी 1885), प्रतिवार, 27 फरवरी, सजीवनी, 28 फरवरी (वही, 7 मार्च 1885), साधारणी, 8 मार्च (वही, 14 मार्च 1885), साधारणी, 15 मार्च (वही, 21 मार्च 1885), सहचर, 18 मार्च (वही, 28 मार्च 1885), आनंद बाजार पत्रिका, 3 अगस्त (वही, 11 जुलाई 1885)
- 82) बंगाली, 28 फरवरी 1885, मराठा, 1 मार्च 1885 इंडियन इको, 6 मार्च, बंगाल पब्लिक ओपीनियन 19 मार्च, सुरभि, 10 मार्च समय, 16 मार्च (बी० ओ० आई०, मार्च 1885); प्रभाती, 18 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 21 फरवरी 1885), समय, 23 फरवरी (वही, 28 फरवरी

- 1885); सजीवनी, 28 फर० (वही, 7 मार्च 1885), साधारणी, 7 मार्च, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 7 मार्च (वही, 14 मार्च 1885); सजीवनी, 14 मार्च, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 14 मार्च (वही, 21 मार्च 1885), प्रतिकार, 20 मार्च (वही, 28 मार्च 1885);
83. बगाली, 14 मार्च 1885; मराठा, 15 मार्च 1885, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 मार्च, इंडियन नेशन, 16 मार्च, केसरी, 16 मार्च बगवामी 14 मार्च (वी० ओ० आई०, मार्च 1885); सजीवनी, 4 जुलाई, साधारणी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 11 जुलाई 1885).
84. आर० एन० पी० बग०, 11 जुलाई 1885
85. अफसरो के मन के लिए देखिए, पार्वती चरण राय . पूर्वोद्धृत, पृ० 216-29
86. देखिए, पीछे 25 म० पादटिप्पणी.
87. 'दि मैट्रल प्राविसेज नैड रैवेन्यू ऐंड टैनेमी बिल्स', जे० पी० एस० एस०, अप्रैल 1881 (खंड III, स० 4) हमारे पाम यह बढने के लिए कि यह लेख जमिंदार रानाडे द्वारा लिखा गया था, मनकर महोदय का प्रमाण है (मनकर पूर्वोद्धृत, खंड I, पृ० 214).
88. जे० पी० एम० एम०, अप्रैल 1881 (खंड III, स० 4) पृ० 17, 23.
89. वही, पृ० 18 तथा देखिए, पृ० 22
90. 29 नवंबर, 13 दिसंबर (आर० एन० पी० पी० एन०, 7, 21 दिस० 1882).
91. 30 सितंबर 21 अक्तूबर 1882.
92. ढाका प्रकाश, 28 मार्च, 4 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 1, 10 अप्रैल 1897), बगवामी, 8 मई (वही, 15 मई 1897).
93. बगाली, 2 अप्रैल 1898, हिनवादी, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 16 अप्रैल 1898)
94. प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ दि लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ बंगाल 1898, खंड XXX, पृ० 14-9.
95. वही, पृ० 65 और आगे
96. आर० एन० पी० एम०, 15 फरवरी 1898.
97. पी०आर०पिल्लई प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ मद्रास 1898, खंड XXVI, पृ० 147 तथा आगे, सी० जे० मूर्दलियार, वही, पृ० 163 तथा आगे; गी० विजयराघवाचारी, वही पृ० 180 तथा आगे.
98. उदाहरणार्थ देखिए, आर० एन० पी० एम०, 30 नवंबर और 31 दिसंबर 1895, 31 मार्च, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 31 दिसंबर 1896
99. केरल पत्रिका, 25 फरवरी, केरल मंचारी, 15 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 28 फरवरी 1899); केरल चंद्रिका, 2 मार्च (वही, 15 मार्च 1890)
100. हिंदू, 9 फरवरी 1899, मनोरमा, 30 जनवरी और 28 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 15 फरवरी और 31 अगस्त 1899)
101. प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ मद्रास 1899, खंड XXXVII, पृ० 22-30, 326 और आगे.
102. वही, पृ० 24-9.
103. आर० एन० पी० एन०, 26 जुलाई, 2 और 16 अगस्त, 4 और 18 अक्तूबर 1899
104. वही, 26 अक्तूबर 1901.
105. एडवोकेट, 1, 5, 15 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 2, 9, 16 मार्च 1901); अगस्त टाइम्स,

- 5 अप्रैल (वही, 6 अप्रैल 1901); एडवोकेट, 19 सितंबर, 20 अक्तूबर (वही, 21 सितंबर, 26 अक्तूबर 1901). एच० आर० नवंबर 1901 पृ० 456-7; विश्वभरनाथ, प्रोसीडिन्ग आफ दि लेजिस्लेटिव कौंसिल पार एन० डब्ल्यू० पी० एन० अवध, 1901, पृ० 65-70, श्रीराम, वही, पृ० 70-71; विश्वभरनाथ और श्रीराम, वही, पृ० 72 और आगे 'केसरी' और 'इंडियन मिग्रे' ने भी अपने अपने क्रमशः 22 अक्तूबर 1901 (आर० एन० पी० वग०, 26 अक्तूबर 1901) और 19 अक्तूबर 1901 शंक मे (आर० एन० पी० वग०, 26 अक्तूबर 1901) विल का विरोध किया
- 106 मराठा, 18 सितंबर, 25 दिसंबर 1898, 29 जनवरी, 19 फरवरी 1899; गुजराती, 15 जनवरी; मवाई वैभव, 17 जन० (आर० एन० पी० वग०, 21 जनवरी 1899); केसरी, 11 अप्रैल, 18 जुलाई (वही, 15 अप्रैल, 22 जुलाई 1899); केसरी, 20 फर० (वही, 24 फरवरी 1900); केसरी, 2 सितंबर (वही, 6 सितंबर 1902); मराठा, 27 सित०, 11 अक्तू० 1903; सुधारक, 21 सित०, मयाजी विजय, 19 सित० (आर० एन० पी० वग०, 26 सितंबर, 1903); ज्ञान प्रकाश, 1 अक्तूबर, सज वर्तमान, 30 सितंबर. सत्य शोधक, 27 सितंबर, केसरी, 29 सितंबर (वही, 3 अक्तूबर 1903); गुजराती, 14 फरवरी, केसरी, 16 फरवरी, सज वर्तमान, 17 फरवरी (वही, 3 अक्तूबर 1903); गुजराती, 14 फरवरी, केसरी, 16 फरवरी, सज वर्तमान, 17 फरवरी (वही, 20 फरवरी 1904); मराठा, 21 फरवरी 1904; डी० ए० खरे, प्रोसीडिन्ग आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1899, पृ० 20-8, वही, 1903, पृ० 186-8, वही, 1904, पृ० 21-3, एन० जी० आर० और जी० के० पारिख वही, 1899 पृ० 35.
- 107 ए० जी० ह्यूमः हिट्स आन ऐग्रीकल्चरल रिफार्म इन इंडिया (कलकत्ता, 1879) पृ० 35, एम० एम० थाबर्न-एंगीकोला रेडिविवस, एग्नियाटिक क्वाटर्ली रिव्यू, जुलाई 1901. पंजाब के चार क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता संबंधी एम० एम० थाबर्न द्वारा की गई जांच पड़ताल की रिपोर्ट के प्रकाशन, डब्ल्यू० डिग्वी, पूर्वोद्धृत, पृ० 297-304; राधाकमल मय्यर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया (लंदन 1933) पृ० 263-75, बी० एम० भाटिया : पूर्वोद्धृत, 150-5
- 108 उदाहरणार्थ देखिए, इफार्म, स्पीचेज, पृ० 240; चिमने, पूर्वोद्धृत, पृ० 395, कर्जन, स्पीचेज I पृ० 124, स्पीचेज II पृ० 166; 1901 के अकाल आयोग के अध्यक्ष अटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा 1901 में डिग्वी को लिया पत्र जो डिग्वी की गुरुतक में दिया गया है, पूर्वोद्धृत पृ० 323, जे० डी० रीम, 'फैमिन-फैक्ट्स ऐंड फैसेसिज', एग्नियाटिक क्वाटर्ली रिव्यू, जुलाई 1901, पृ० 9.
109. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 347. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 394, 770; बी० आर० नीलू. रिप० आई० एन० सी०, 1894 पृ० 38; ए० बी० पी०, 12 जून 1884, 20 मार्च 1892, 1, 2 जनवरी 1901, अखबारे आम, 6 जनवरी (आर० एन० पी० वग०, 14 जनवरी 1899); हिंदुस्तानी, 4 अक्तू० (आर० एन० पी० एन०, 11 अक्तूबर 1899), वही में 10वें प्रांतीय सम्मेलन में जी० के० पारिख का भाषण, बंगाली, 22 मई 1900, तेज बहादुर सप्रू, 'रिव्यू आफ आर० सी० दत्तस ओपन लेटर्स', एच० आर०, नव० 1900, पृ० 36, हिंदू, 14 दिसंबर 1900; स्वदेशमित्र, 12 दिसंबर (आर० एन० पी० एम० 15 दिसंबर 1900); जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 29; सी० वाई० चिंतामणि, 'इंडिया ऐंड लार्ड कर्जन, एच० आर० मई 1901 पृ० 341-2; केसरी 18 फरवरी (आर० एन० पी० वग०, 22 फरवरी 1902); एस० एस० थाबर्न के 'पंजाब इन पीस एंड वार' की समीक्षा, एच० आर०, अगस्त 1904 पृ० 196-7.
110. जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०, 1900 पृ० 29.

- 111 इंदु प्रकाश, 4 अगस्त (आर० एन० पी० ब०, 9 अगस्त 1879), मराठा, 10 अप्रैल 1881; रानाडे - 'लैंड ला रिकॉम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंस' जे० पी० एम० एस०, अक्टूबर 1881 (खंड IV खण्ड 2), पृ० 39-40; जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 350, 356, 515, 521-2; ए० बी० पी०, 20 मार्च 1892, 22 नव० 1898; राय, पावटी, पृ० 222, नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 116, 118, सिक्कानकोट पेपर, 16 नवंबर (आर० एन० पी० पी०, 25 नव० 1899); दत्त सी० पी० ए०, पृ० 478, बंगाली 21 अगस्त 1901, एन० सी० केनकर, एच० आर०, सितंबर-अक्टूबर 1901 पृ० 243, जी० एम० अय्यर ई० ए०, पृ० 13, 16, केसरी 18 फरवरी (आर० एन० पी० ब०, 22 फरवरी 1902)
- 112 और देखिए, ज्ञान प्रकाश, 5 सितंबर, बोध सुधाकर, 28 अगस्त (आर० एन० पी० ब०, 7 मिन० 1878), ज्ञान प्रकाश, 30 सित० (वही, 5 अक्तू० 1878) इंदु प्रकाश, 4, 11 अगस्त (वही, 9, 16 अगस्त 1879); इंदु प्रकाश, 25 अक्तू० (वही, 30 अक्तूबर 1880), इंदु प्रकाश, 5 सित० (वही, 10 सित० 1881), रानाडे 'दि डकन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स बिल' जे० पी० एम० एस०, अक्तू० 1879 (खंड II स० 2) पृ० 46 7 'लैंड ला रिकॉम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंस' पूर्वोक्त स्थान, पृ० 37, 55 और कलाक पूर्वोद्धृत, पृ० 27, मराठा, 24 सितंबर 1882, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्तूबर (आर० एन० पी० ब० 14 अक्तूबर 1882), ए० बी० पी०, 26 जून 1884, 20 मार्च 1892, 22 नवंबर 1898, 1, 2 जनवरी 1901, रहबर टि०, 3 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 15 जुलाई 1893), जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 345-9, 357, 408, 410 414 421, 426, 435, 443-4, 448-50, 515, 522, पी० मेहता पूर्वोद्धृत, पृ० 394 5, 450, 575, 655, बालवीय, पूर्वोद्धृत, पृ० 305-06, 312-3, आई० एन० सी०, 1895 का प्रस्ताव X आर० एन० मुधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 111, आर० पी० करांडकर, वही, पृ० 112, नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 131-2, गोखले स्पीचेज, पृ० 1016 7, जी० एम० अय्यर विलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 19024, रिप० आई० एन० सी०, 1900 पृ० 29 और ई० ए० पृ० 13, 16 7, अजबारे आम, 6 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 14 जनवरी 1892); पंजाब समाचार 18 मार्च (वही, 25 मार्च 1899), दान अक्तूबर 1899 पृ० 67, दिसंबर 1899 पृ० 136, दत्त, सी० पी० ए०, पृ० 480, स्पीचेज II पृ० 194, ई० एच० II पृ० 331, जी० के० पारिख, बंबई ने दमव प्रांतीय मम्मलन म अध्यक्षीय भाषण, बंगाली, 22 मई 1900, सी० आई० चिंतामणि, इंडिया गेड लांड कंटेन, पूर्वोक्त स्थान, पृ० 341-2, बंगाली, 21 अगस्त 190, मद्रास स्टैंडर्ड, 2 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 10 अगस्त 1901), 'रिब्यू आफ फाबनंस 'पंजाब इन दीम गेड बार' एच० आर०, अगस्त, 1904 पृ० 196, और देखिए पीछे अध्याय 9 और आगे 'भूमि स्वामित्व परिवर्तन' भाग I
- 113 एम० एम० घाष स्पीचेज, पृ० 88, रानाडे 'दि डकन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स बिल' पूर्वोक्त स्थान, पृ० 50-1, 'लैंड ला रिकॉम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंस' पूर्वोक्त स्थान, पृ० 44, पना सावर्जनिक मन्ना 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र, जे० पी० एम० एस०, जनवरी 1880 (खंड II स० 3) पृ० 106; सजीवनी, 6 अगस्त (आर० एन० पी० ब०, 13 अगस्त 1898); दान, अक्तूबर 1899 पृ० 67, दिसंबर 1899, पृ० 136-7, गोखले स्पीचेज, पृ० 1016; दत्त स्पीचेज I पृ० 13-4, 27; 'रिब्यू आफ फाबनंस—'पंजाब इन दीम गेड बार' एच० आर० अगस्त 1904 पृ० 197
- 114 उदाहरणार्थ देखिए, रानाडे, 'दि डकन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स बिल' पूर्वोक्त स्थान, पृ० 45 'लैंड

रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 55; जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 346-7, 443 4, 515, 517, 519, 536, मेहता स्पीचेज, पृ० 663 4, 810, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 308, आर० एन० मुखोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 111, नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 117, जी० एम० अय्यर ई० ए०, पृ० 13 6, दल ओपन लटर्स, पृ० 78, स्पीचेज I पृ० 27 तथा देखिए पीछे श्रृंखला 9 और आग पाठ टिप्पणी मध्या 152

115 आर० एन० पी० बब, 22 फरवरी 1902

116 उदाहरणार्थ देखिए ज्ञान प्रकाश, 30 सितंबर (आर० एन० पी० बब, 5 अक्टूबर 1878); एल० एम० बोष स्पीचेज पृ० 88, आनंद बाजार पत्रिका, 7 सितंबर (आर० एन० पी० बग० 18 सितंबर 1880), इंदु प्रकाश, 25 अक्टू० (आर० एन० पी० बब 30 अक्टूबर 1880), भारत बधु, 26 नवंबर (आर० एन० पी० पी० एन०, 2 दिस० 1880), रानाचे 'मिस्टर वडररन एंड हिज क्रिटिक्स आन ए परमानेंट जैंगलमट फार् दि इकन ब्रे० पी० एम० एम० जनवरी 1881 (खंड III म० 3) पृ० 17 'लेड ता रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 41, 50 मराठा 1 जनवरी, 12, 19 फरवरी 1882, बंगाली, 2 दिस० 1882 भारत मिहिर 28 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 9 दिस० 1882), भारत मिहिर 28 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 9 दिसंबर 1882), भारत मित्र 22 नवंबर (वही, 1 दिसंबर 1883) ए० बी० पी० 12, 26 जून 1884, मजीवनी, 19 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 26 अप्रैल 1894) हिंदू राजका, 30 अप्रैल (वही 10 मई 1894) हिंदू, 29 दिसंबर 1884 राजा रामपाल मह, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 65 6 कोहेनर, 13 15 17 अगस्त रावी 14 अगस्त, आफताब पञ्जाब, 16 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 24 अगस्त 1899) दिनवादी 25 जगदी आर० एन० पी० बग, 1 अगस्त 1891) बननिवासी 28 अगस्त (वही 5 सितंबर 1891) बंगाली, 23 जनवरी 1892, हिंदुस्तान, 26 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 28 अप्रैल 1892) तान उल खखबार 4 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 18 फरवरी 1893) गृहबारे हिंदू 3 जुलाई (वही 22 जुलाई 1893), अखबार आम, 13 अक्टूबर (वही 21 अक्तूबर 1894) रहबारे हिंदू, 14 मार्च 20 जून (वही 23 मार्च और 6 जुलाई 1895), अखबारे आम, 15 जुलाई (वही 27 जुलाई 1895) गमखबारे हिंदू 20 जुलाई (वही 3 अगस्त 1895) जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 350 61, 407-08 411 3 447 8, राय पावर्टी, पृ० 20 सहचर, 13 मार्च मजीवनी, 16 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 23 मार्च 1895), आर० एन० मुखोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 15 मिहिर रामगोपाल पूर्वोद्धृत पृ 145, मजीवनी, 19 मार्च, 6, 13, 27 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 26 मार्च, 13, 20 अगस्त 3 सितंबर 1898), आर० एम० सयानो एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 524, फोइनेस, 5 अक्टूबर, गुरुखी, 6 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब०, 6 अक्टूबर 1898); नाज उल अखबार, 21 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 4 फरवरी 1899), पैमा अखबार 1 फरवरी (वही, 18 फरवरी 1899) मियालकाट एपर, 8 अक्टू० (वही 78 अक्टूबर 1898) अल्मोडा अखबार, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 17 अप्रैल 1899), मराठा, 9 अक्टूबर 1899, बाबा स्पीचेज, पृ० 436 दत्त स्पीचज I पृ० 4, नेत्र बहादुर मधु ए० ए० नवंबर 1900 पृ० 36, 'प्रोसीडिंग्स आफ दि फर्स्ट नार्थ अररोट डिस्ट्रिक्ट काफेस हेल्थ आन 21 22 जुलाई 1900 पृ० 9 एन० जी० नदावरकर सी० पी० ए० पृ० 51, बेमरी बे 12 फरवरी 12 मार्च के मवाददाना (आर० एन० पी० बब 14 फरवरी 6 मार्च 1901) विक्ट

हूतन, 4 मई (आर० एन० पी० एम०, 4 मई 1901); इडियन मिरर, 28 सित० (आर० एन० पी० बग० 5 अक्तू० 1901); न्यू इडिया 25 नव० 1901; सी० वाई० चितामणि - इडिया ग्रेड लाई कर्जन. पूर्वोक्त स्थल, पृ० 341; पी० मेहता - स्पीचेज, पृ० 625; एम० आर० आर० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 142; सी० सी० घोष . वही, पृ० 144; गोयले : स्पीचेज, पृ० 111, 329, 1034; यामनीय . स्पीचेज, पृ० 30

117 रिप० आई० एन० सी०, 1899 पृ० 44

118 रानाडे एसेज, पृ० 297-4; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 419-20, 439, 447-8 514-21; आर० एन० मुखोन्नकर - रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 108 09, नदी, इडियन पालिटिक्स, पृ० 116-7, एम० एन० बैनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 698; बमाली, 13 फरवरी 1892, सजीवनी, 13 अगस्त (आर० एन० पी०, बब, 20 अगस्त 1898); इडियन स्पेक्टेटर, 11 दिगंबर 1898; पैना अखबार, 1 फरवरी (आर० एन० पी०, 18 फरवरी 1899); सियालकोट पेपर, 8 अक्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 1899); इंदु प्रकाश, 9 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब०, 14 अक्तूबर 1899)

119. रानाडे, 'दि डकन ऐग्रीकलचरिस्ट्स बिल' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 49-50; आनंद बाजार पत्रिका, 7 सितंबर (आर० एन० पी० बग०, 18 सितंबर 1880); ज्ञान प्रकाश, 25 मित० (आर० एन० पी० बब, 30 सितंबर 1882), इडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्तूबर, 26 नवंबर (वही 14 अक्तू०, 2 दिस० 1882); ए० बी० पी०, 25 जनवरी, 1 फरवरी 1883, 20 मार्च 1892 22 नवंबर 1898, इडियन स्पेक्टेटर, 29 जून (आर० एन० पी० बब, 5 जुलाई 1884); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 343; एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 517, प्रधान और भागवत पूर्वोद्धृत, में तिलक, पृ० 133; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 656-7, जी० के० पारिख प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ दि गवर्नर आफ बाचे, 1901, खंड, XXXIX पृ० 314; डी० ए० खरे, वही, पृ० 325-6; बाचा, सी० पी० ए०, पृ० 582; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 156

120 तुलनीय, गाडगिल, पूर्वोद्धृत, पृ० 97 तथा कर्जन, स्पीचेज II पृ० 29, सी० एम० रिवाज, एन० सी० पी० 1899, खंड XXXVIII पृ० 325-6; जी० हैमिल्टन, इडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 1901 लगभग 113

121. मराठा, 6 मार्च 1881, 7 मई 1882; अखबारे आम, 6 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 17 नवंबर 1894), और 6 जनवरी (वही, 14 जन० 1899); बिस्टोरिया पेपर, 17 जुलाई (वही, 5 अगस्त 1899); भारत मित्र, 22 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 27 जनवरी 1900); ए० बी० पी०, 1 जनवरी 1901; केमरी, 18 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 22 फरवरी, 1902)

122. रानाडे, 'दि डकन ऐग्रीकलचरिस्ट बिल', जे० पी० एम० एस० अक्तूबर 1879 (खंड II सं० 2) (यह लेख मूल रूप से लेखक के नाम के बिना प्रकाशित हुआ था और मनकर के अनुसार इसे जस्टिस रानाडे ने ही लिखा था) लेख में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इस संबंध में मनकर का विचार असाध्य रूप से सत्य सिद्ध होता है) पूना सार्वजनिक मभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र, जे० पी० एम० एम०, जनवरी 1880 (खंड II सं० 3 ; 20 जुलाई का राम्म गुप्तार और लोक-मित्र) आर० एन० पी० बब, 24 जुलाई 1879); स्वदेशमित्र, 9 अगस्त (वही, 16 अगस्त 1879), जामे जमजोद, 22 अगस्त (वही, 23 अगस्त 1879).

123 रानाडे, 'लैंड ना रिफार्म ऐंड ऐग्रीकलचरल बैरम' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 43

- 124 इंदु प्रकाश, 22 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 27 जुलाई 1878), ज्ञान प्रकाश, 30 सितंबर (वही, 5 अक्टूबर 1878), गुजरात मित्र, 29 दिसंबर 1878 (वही 4 जनवरी 1879); अरुणोदय, 27 जुलाई (वही, 2 अगस्त 1879); इंदु प्रकाश, 4 अगस्त (वही, 9 अगस्त 1879); नेटिव ओपीनियन, 10 अगस्त (वही, 16 अगस्त 1879); इंदु प्रकाश, 29 नवंबर (वही, 4 दिसंबर 1880), मुबोध पत्रिका, 5 दिसंबर (वही, 11 दिसंबर 1880), मराठा, 3 अप्रैल 1881, 3 फरवरी 1884, इंदु प्रकाश, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 8 अप्रैल 1882), मिबाजी, 22 सितंबर (आर० एन० पी० बब, 30 गिनवर 1882), इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्टूबर (वही, 14 अक्टूबर 1882), मराठा, 15 अक्टूबर 1882, जनवरी 1883 क वी० ओ० आई० मे उद्धृत समाचारपत्र
- 125 'दि डकन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स ऐक्ट,' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 44.
- 126 एसेज, पृ० 327, और 'द लेंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंकिंग,' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 42, 45-6, 49-53, पूना सार्वजनिक सभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 110-11. परवर्ती वर्षों में बहुत सारे भारतीयों ने इसी प्रकार का भय प्रकट किया तथा निर्देश किया कि बिल साहूकार और कर्जदारों में भगडा पंदा करने के लिए बनाया गया है और इसका परिणाम बहुत सारे मामलों में किसानों की घरतों के यथायथ रूप में हा साहूकारों के हाथों में चले जाने के रूप में हुआ है अत उन्होंने अधिक उदार राजस्व नीति की और किसान के ऋण के लिए नैकल्पिक माधन की व्यवस्था की वकालत की नेटिव ओपीनियन, 23 सितंबर 1888, मराठा, 4 अक्टूबर 1891, केसर हिंद, 25 अक्टूबर (वही 24 अक्टूबर 1891), गुजरात दर्पण, 29 नवंबर (वही, 5 दिसंबर 1891), जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 355, 359-60, वी० आर० नातू, 1890 आई० एन० सी०, 1894 पृ० 38; इंदु प्रकाश, 7 मई (आर० एन० पी० बब, 12 मई 1891), इंडियन स्पेक्टेटर, 13 मई (वही, 19 मई 1894), एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 509-10, 517-8, पी० महता, स्पीचेज, पृ० 304-05
- 127 मराठा, 5 जून 1881, 24 मिनवर 1882, 4 अक्टूबर 1891, इंदु प्रकाश, 21 मिनवर 1891, प्रकाशक, 4 जनवरी, काल 4 जनवरी, (आर० एन० पी० बब, 12 जनवरी 1901)
- 128 प्रमाण के रूप में देखिए, भारत सरकार का 3 जनवरी 1894 का भारत मन्त्रि को संप्रेषण, होम (पब्लिक) प्रोसीडिंग्स, जनवरी 1894, प्रोग म० 186 (ए) कडिका-28, ज० मौन्टी, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाब, 1900, खंड XXXVIII पृ० 141 और वही 1901 खंड XXXIX पृ० 179-84, जार्ज हैमिल्टन, इंडियन डिबेट्स 3 फरवरी 1901 लगभग 111-5 लैंड रेविन्यू पालिसी आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, 1902 कडिका, 29 एरिक स्टोकम: दि इंग्लिश यूटिलिटीरियम गेड इंडिया (आक्सफोर्ड 1959) पृ० 138-39, रीस. पूर्वोद्धृत, पृ० 319
- 129 ज० मौन्टी, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाब, 1900, खंड XXXVIII पृ० 141, जार्ज हैमिल्टन, इंडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 1901 लगभग 111-2, एन० एम० थाबर्न का 10 जनवरी 1902 को फैबियन सोसायटी में भाषण, स्टेट्समैन, 6 फरवरी 1902
- 130 इस दृष्टिकोण के विकास के इतिहास के लिए देखिए, सी० एम० रिवाज, एन० सी० पी० 1899, खंड XXXVIII पृ० 318-20 1857 और 1880 में सरकारी क्षेत्र में इस विषय पर मतभेद के लिए देखिए, रानाडे, एसेज, पृ० 294-324
- 131 1900 का अधिनियम XIII.

132. सी० एम० रिवाज, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 325-7; कर्जन, स्पीचेज I पृ० 124-5, स्पीचेज II पृ० 28-9, 34.
133. 1901 का बर्दई अधिनियम IV जे० एम० मोदी, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1901, खंड XXXIX पृ० 186, जोशी, पूर्वोक्त पृ० 532, 539, 545.
134. रानाडे, 'लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 32, एसेज, पृ० 325-7; आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव X ; 9 नव० 1895 को पूना सार्वजनिक सभा द्वारा लाई एलगिन को संबोधन जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1896 (खंड XVIII स० 3) पृ० 11; दत्त, सी० पी० ए० पृ० 478 और स्पीचेज II पृ० 36
135. आई० एन० सी०, 1899 का प्रस्ताव II, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्तूबर, इदु प्रकाश, 9 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब, 14 अक्तू० 1899), हिंदुस्तानी, 20 दिसंबर (आर० एन० पी० एन०, 26 दिसंबर 1899), इंडियन स्पेक्टेटर, जुलाई 1900, केसरी, 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब, 3 नव० 1900); बंगाली, 8 नवंबर 1900 7 अक्तूबर के श्रक में हिंदू ने तथा 8 अक्तूबर 1889 के श्रक में मराठा ने बिल की निंदा तो नहीं की परंतु उसे निरर्थक घोषित किया
- 136 बिल के समर्थकों के लिए देखिए, सिविल ऐंड मिलिट्री न्यूज, 4 अक्तू० (आर० एन० पी० पी०, 21 अक्तू० 1899), पैसा अखबार, 4 नवंबर (वही, 18 नवंबर 1899), रफोके हिंद, 18 नव० (वही, 25 नवंबर 1899), रफोके हिंद, 3 मार्च, 28 अप्रैल, 9 जून 8 सितंबर, 3 नवंबर (वही, क्रमश 10 मार्च, 5 मई, 30 जून, 15 सितंबर, 17 नवंबर 1900), गमकबारे हिंद, 27 जनवरी (वही, 3 फरवरी 1900) विरोधियों के लिए देखिए, ट्रिब्यून, 7 अक्तू० (आई० एम० बी० ओ० आई० 22 अक्तूबर 1899); वकील, 31 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 12 अगस्त 1899), मियालकोट पेपर 8 अक्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 1899), विक्टोरिया पेपर, 4 नवंबर (वही, 18 नवंबर 1899), पंजाब समाचार, 18 नवंबर (वही, 25 नवंबर 1899), दाते हिंद, 2 मार्च, विक्टोरिया पेपर, 5 मार्च (वही, 10 मार्च 1900); मियालकोट पेपर, 8 अप्रैल (वही, 14 अप्रैल 1900), पब्लिक गजट, 24 अक्तूबर (वही, 3 नवंबर 1900), पंजाब के दो काग्रमी नेताओं, मुरलीधर और कन्हैयालाल ने कांग्रेस अधिवेशन में बिल का विरोध किया देखिए, रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 45-7
- 137 आर० एन० पी० पी०, क्रमश 18 अगस्त और 3 नवंबर 1900
138. वही, 24 नवंबर 1900 इसी प्रकार 22 अगस्त 1900 के श्रक में विक्टोरिया पेपर भी अपनी पिछली स्थिति से पलट गया और सशोधन बिल का समर्थन करने लगा आर० एन० पी० पी०, 8 सित० 1900
139. होयलैंड . पूर्वोक्त, पृ० 71, एच० मोदी पूर्वोक्त, खंड I पृ० 424
140. मराठा, 30 जून, 7, 14 जुलाई 1901, हिंदू 31 जुलाई 1901, ए० बी० पी०, 26 अगस्त 1901; आर० एन० पी० बब, 1, 8, 22 जून 1901 में प्रतिवेदित समाचारपत्र तथा देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर 1901 के आर० एन० पी० बब
- 141 जोशी, पूर्वोक्त, पृ० 439-44, 512-54, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 641-6, 651-712; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1017-48; जी० के० पारिख, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1901, खंड XXXIX, पृ० 191-5, 312-9; डी० ए० खरे, वही, पृ० 319-28, प्रधान और भागवत पूर्वोक्त में तिलक, पृ० 132-3; बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 569-70, एन० सी० केसकर, 'दि रीसेट लैंड लैंडस्लेजान इन बांबे' एच० आर०, सितंबर-अक्तूबर 1901 पृ० 242

और आगे तथा देखिए कृत, स्पीचेज II पृ० 136, 138 और इम्प्लैन्ट में रहने वाले भारतीयों के सम्मेलन की ओर से दादाभाई नौरोजी, आर० सी० दत्त और के० हरनामसिंह द्वारा हस्तक्षरित आपन; दत्त, स्पीचेज II पृ० 141-9 में पुन उद्धृत.

- 142 प्रोसीडिंग्स आफ दि कॉन्सिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे, 1901, खंड XXXIX पृ० 367-8
- 143 पूना सार्वजनिक सभा का 6 मितबर 1879 का विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 110, आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 110 रहबर, 1 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 10 मार्च 1897), आई० एन० सी०-1899 का प्रस्ताव II, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्तूबर, इंदु प्रकाश, 9 अक्तू० (आर० एन० पी० बब, 14 अक्टूबर 1899); पैसा अखबार, 1 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 18 फरवरी 1899), नकील 31 जनार्दन, 12 अगस्त 1899), विक्टोरिया पेपर, 1 नवंबर (वही, 18 नवंबर 1899), मियालकोट पेपर 16 नवंबर (वही, 25 नवंबर 1899), इंडियन एसोसिएशन की लाहौर की उपसमिति का प्रतिवेदन, रफीके हिंद, 25 नवंबर में पुन उद्धृत वही, 9 दिसंबर 1899), केसरी, 30 अक्टूबर (आर० एन० पी० बब, 3 नवंबर 1900); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 444, 515, 544, गोखले, स्पीचज, पृ० 1032-3, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 674, 686, जी० के० पारिख पूर्वोद्धृत पृ० 192-3, पी० एन० खर पूर्वोक्त स्थल पृ० 325; मी० बाई० चिंतामणि इंडिया का लाहौर कर्जन' एच० एच० मई 1901 पृ० 340-1 मराठा, 14 जुलाई 1901, अष्टवादवाद गद्यम, कैसरे हिंद 26 मई गजराती 26 मई (आर० एन० पी० बब, 1 जून 1901) इंदु प्रकाश 20 जन (वही 2 जन 1901 मालवाय, स्पीचज पृ० 310, 317
- 144 रहबर, 1 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 10 मार्च 1897) विक्टोरिया पेपर 4 नवंबर (आर० एन० पी० पी० 18 नवंबर 1899), पत्रात्र समाचार, 4 नवंबर मयालकोट पेपर 16 नवंबर वही 18 नवंबर 1899), इंडियन एसोसिएशन का लाहौर उपसमिति का प्रतिवेदन, पूर्वोक्त स्थल इन्ने हिंद, 2 मार्च (आर० एन० पी० पी० 16 मार्च 1900), दत्त सी० पी० ए०, पृ० 477 आपन लेटर्स, पृ० 75 स्पीचेज II पृ० 14, ई० एच० II पृ० 471, 487, 494, मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 17 जाधी पूर्वोद्धृत पृ० 444, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 317
- 145 रानाडे, 'लैंड का विकास एंड एग्रोवल्चरन बेंस ज्ञाति एन०, पृ० 323, पूना सार्वजनिक सभा का लाहौर एग्जिनि बो स बोधन, 9 नवंबर 1899, पूर्वोक्त स्थल पृ० 11, आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 109-10, मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 45
- 146 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 444, 513, 515, 522, 530-1, पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 643-4, 654, 658-9, 680-5, 692-3, 697-702, 704, गोखले स्पीचेज पृ० 1018-9, 1038-9, वाचा, मी० पी० ए०, पृ० 569-70, केसरी 4, 18 जून (आर० एन० पी० बब, 8, 27 जून 1901)
- 147 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 531, 543, पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 675, 711, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1037
- 148 रानाडे, एसेज, पृ० 325-7, जी० एन० गुप्ता पूर्वोद्धृत में दत्त पृ० 168, इंडियन स्पेक्टेटर 8 जुलाई 1900, जी० के० पारिख, पूर्वोक्त स्थल पृ० 316
- 149 विक्टोरिया पेपर, 4 नवंबर (आर० एन० पी० पी०, 18 नवंबर 1899), नकील, 20 नवंबर (वही, 2 दिसंबर 1899), इंडियन एसोसिएशन लाहौर की उपसमिति का प्रतिवेदन, पूर्वोक्त स्थल,

कन्हैयालाल, रिप० आई० एन० सी०, 1899, पृ० 46; एन० सी० केलकर, 'दि रीसेंट लैंड लेजिस्लेशन इन बावे', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 247. दूसरी ओर गोखले ने शिकायत की कि बर्बई लेजिस्लेशन के तत्कालीन शिकार इससे किसी भी रूप में बुरी तरह से प्रभावित नहीं होवे (स्पीचेज, पृ० 1030, 1037-8).

- 150 उदाहरणार्थ, फिरोजशाह मेहता ने यह निर्देश करने के उपरांत कि अंगरेज अधिकारी, देशी व्यक्तियों के साथ मपकं बनाता है, वह सहानुभूतिपूर्ण होने पर भी अकेला पड़ जाता है, जिज्ञासु होने पर भी अनभिज्ञ रहता है और जीवनपर्यंत अजनबी और विदेशी ही बना रहता है, दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं और मेरे साथी ही यह कहने का दावा कर सकते हैं कि हम किसानों के विचारों और भावों को व्यक्तिगत रूप से और सही तौर पर जानते तथा उनकी जानकारी का अनुभव रखते हैं. हम ही उनके जीवन के ढंग, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं, उनके स्वभाव, उनके पूर्वग्रहों और रुचियों आदि को जानते और समझते हैं. अतः कृषकों के विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के और उनका प्रतिनिधित्व करने के सही अधिकारी हम ही हैं, न कि दूर द्वीप में रहने वाले अंगरेज और कृषक जनता से दूर तथा अलग-थलग अंगरेज अधिकारी (स्पीचेज, पृ० 670), तथा देखिए, वही, पृ० 640-1, 652, 703; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1029-30
151. एन० सी० केलकर, 'दि रीसेंट लैंड लेजिस्लेशन इन बावे', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 244 तथा आर० एन० मधालकर, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 111, मराठा, 8 अक्तूबर 1899, 30 जून, 7 जुलाई 1901, हिंदू, 7 अक्तूबर 1899; हिंदु प्रकाश, 9 अक्तू० (आर० एन० पी० बब, 14 अक्तू० 1899), इंडियन स्पेक्टेटर, 28 अक्तू० 1900; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 443, 447, 512-5, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 304, दत्त, स्पीचेज II पृ० 135-6, सी० बार्ड० चित्तामणि, 'इंडिया ऐंड लांड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 340-2; गुजराती, 2 जून (आर० एन० पी० बब, 8 जून 1901); बगानी, 21 अगस्त, 1901; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 313-4
- 152 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 448, 515-22, 544, पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 663-4, 676-7, जी० के० पारिख, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 193, 318; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 308 तथा देखिए पीछे पादटिप्पणी सं० 114
- 153 उदाहरणार्थ, जी० एस० अग्रर ने टिप्पणी की 'यदि सरकार यह समझती है कि लगान इतना कम है कि इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता जैसे विनष्टा और भारी रोग को बढ़ावा मिलता है तो सरकार के लिए रास्ता खूना है, वह लगान में इतनी अधिक वृद्धि की घोषणा कर दे कि किसान बचारे को अपनी खेती में आजोबिदा ही न मिल सके और उसे इस प्रकार सदा के लिए ऋणग्रस्तता में मूर्तिमिमन जाल' सरकार भविष्य में और अधिक नरमी बरतने के लिए, जैसा लांड वजन वृद्ध है, अपने को वचनबद्ध क्यों करती है ? (ई० ए०, पृ० 13-4) आर० सी० दत्त ने सरकार पर पुरानी परंपरा के जमींदारों की प्रवृत्तियों को दोहराने का आरोप लगाया: 'किरायेदारों का जाल नृम कि वे दूर दूर हो रहे, गरीब आदमी बद से बदतर हो जाए' (स्पीचेज II पृ० 194-5) तथा पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 656-7
- 154 डी० ए० शार० विल पर पूना सार्वजनिक सभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 110; आर० पी० कर्णिकर, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 112-3; मराठा, 8 अक्तू० 1899; हिंदू, 7 अक्तूबर 1899; पैसा प्रखबार, 7 अक्तूबर (आर० एन० पी० पी०, 28 अक्तूबर 1899); नियालकोट पेंसर, 16 नवंबर, 1 दिस० (वही, 25 नवंबर, 9 दिस० 1899); दोस्ते हिंद, 2 मार्च (वही, 10 मार्च 1900); मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 45; जोशी,

- पूर्वोद्धृत, पृ० 440, 443-4, 450; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1019, सी० वाई० चिंतामणि, 'इंडिया ऐंड लांड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 341-2, मराठा, 30 जून, 7 जुलाई 1901, इंदु प्रकाश, 20 जून (आर० एन० पी० बब, 22 जून 1901); एन० सी० केलकर, 'दि ग्रीसेंट लैंड लेजिस्लेशन इन बांबे', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 243-4; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 305-06, 312-4
- 155 सरकार द्वारा भूमि का अधिकार न पाने पर भी किसान सरकार की नकद मांग की पूर्ति आमानों में कर सकता है, इसका अनुमान अथवा ज्ञान होने पर सरकार उसे स्वामित्व का अधिकार न दे यह एक बात है तथा किसान द्वारा प्राप्त भूमि के स्वतन्त्र व्यापार के अधिकार का अपनी अबुद्धिमत्ता, हठधर्मिता और फिजूलखर्ची आदि के कारण दुर्ूपयोग करने पर सरकार द्वारा उस अधिकार का छीना जाना दूसरी बात है दूसरी स्थिति में सरकार का पग न्यायसंगत हो जाता है।
- 156 बर्नई भूराजस्व बिल पर अपने भाषण में ममीक्षा के इस रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति गणपलकृष्ण गोखले ने की उन्होंने यह घोषणा की कि यदि बिल वास्तव में साहूकारों के बुरी तरह शिकार बने हुए किसानों को किसी प्रकार की राहत दे सकता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उपाय के विरुद्ध कितना भी कुछ क्यों न कहा गया हो, उससे उन किसानों के पक्ष में तो यह लाभ ही पहुंचाएगा उन्होंने अपना यह दृढ़ मत अभिव्यक्त किया यह कहना असंभव है कि बिल इस प्रकार से कुछ भी कर सकता है (स्पीचेज, पृ० 102) तथा देखिए, वही, पृ० 25, 1022-4, 1036-40, दत्त, सी० पी० ए० पृ० 460 ओपेन लेटर्स, पृ० 78; एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० १19-२0 क्रिड 7 अक्टूबर 1899, सियाल्कोट पेपर, 16 सितंबर (आर० एन० पी० पी०, ० अक्टूबर 1900), मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी० 1899, पृ० 45, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 444, 512, 514-5, 530, 541 2, 544, सी० वाई० चिंतामणि, 'इंडिया एंड लांड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल पृ० 340 1, मराठा, 14 जुलाई 1901, कैमरे हिंद, 26 मई, गुजरातो, 26 मई (आर० एन० पी० बब, 1 जून 1901), बंगाली, 21 अगस्त 1901 तथा देखिए पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 672
- 157 और देखिए, मराठा, 30 जून 1901
- 158 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1039-40.
- 159 और देखिए, वही, पृ० 25, 1017, रानाडे 'लैंड ला रिकॉम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 48, 57 एसेज, पृ० 256-7; एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 520
- 160 रानाडे, 'लैंड ला रिकॉम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 42 तथा देखिए, मराठा, 4 सित० 1881, 1 जनवरी, 12 फरवरी 1882, 25 मई 1884 25 जनवरी 1885, प्रकाशक, 8 जनवरी, कल, 4 जन० (आर० एन० पी० बब, 12 जनवरी 1901), केसरी, 18 जून (वही, 22 जून 1901) 10, 17 नवंबर (वही, 14, 21 नवंबर 1903); जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 65-6
- 161 प्रमाण के रूप में देखिए, पूना सार्वजनिक सभा का 6 सितंबर 1879 का विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 105-06, 110-1; रानाडे, 'दि डकन ऐग्रीकल्चरलिस्ट बिल' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 49, मिस्टर वेडरबर्न ऐंड हिज फ्रिंटिस आन ए परमानेंट सेंटलमेट फार दि डकन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 17; 'लैंड ला रिकॉम एंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 42, 46, 53-7, एसेज, पृ० 256-7; मराठा, 1 जनवरी 1882, इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश अखिरहित (बी० जी० आई० जनवरी 1883), जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 355-60, आई० एन० सी० 1895 का प्रस्ताव X; आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 111; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 395, 673-4,

दत्त, सी० पी० ए०, पृ० 480 और आगे, स्पीचेज II पृ० 135-6, ई० एच० II पृ० 495; एन० पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 520; ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1898, सी० वाई० चिंतामणि, 'इंडिया ऐंड लाईफ कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 340-2, मासवीय, स्पीचेज, पृ० 313-4. तुलनीय स्मूथर मैकजी छूट की कोई पद्धति ऋणग्रस्तता को न तो समाप्त करेगी और न ही घन के रूप में बढ़ाएगी भूमिलगान को समाप्त कर देने का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा (प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे, खंड XXXIX, पृ० 353)

162. एल० एम० घोष, स्पीचेज पृ० 88, सोम प्रकाश, 31 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 5 नवंबर 1881), भारत बधु, 26 नव० (आर० एन० पी० पी० एन०, 2 दिस० 1880); 28 अप्रैल (वही, 3 मई 1882), बंगाली, 10 सित० 1881, 2 दिस० 1882, माडलिक, पूर्वोद्धृत, पृ० 131-8, रानाडे, 'लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स' पूर्वोद्धृत और एसेज, पृ० 40 65, 256, नेटिव ओपीनियन, 19 नव० (आर० एन० पी० बग०, 25 नव० 1882), सोम प्रकाश, 20 नव० (आर० एन० पी० बग०, 25 नव० 1882) भारत मिहिर, 28 नव०, मुलभ समाचार, 2 दिस० (वही, 9 दिस० 1882), बगबासी, 16 दिस० (वही, 23 दिस० 1882), भारत मित्र, 22 नव० (वही, 1 दिस० 1883), इंडियन मिरर, बाह्यो पब्लिक ओपीनियन, दि हेराल्ड (बिहार) इंडियन स्पोर्टेटर, नेटिव ओपीनियन, मराठा सभो तिथिरहित (बी० ओ० आई०, जनवरी 1883); इंडियन मिरर, 2 अगस्त, पीपुल्स फ्रेड, 4, 11, 18 अगस्त, ट्रिब्यून 11 अगस्त, इंडियन स्पोर्टेटर, 12 अगस्त इंडियन इको, 14 अगस्त, इंदु प्रकाश, 6 अगस्त (बी० ओ० आई०, अगस्त 1883), सजीवनी, 19 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884), ग्रामवर्त प्रकाशिका, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 1884), आनंद बाजार पत्रिका, 5 मई (वही, 10 मई 1884), महेश्वर 7 मई, नवविभाकर 12 मई (वही, 17 मई 1884), बगबासी, 16 अगस्त (वही, 23 अगस्त 1884), बर्बई समाचार, 26 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 1884), ज्ञान प्रकाश 15 मई (वही, 17 मई 1884), इंडियन स्पोर्टेटर, 29 जून (वही 5 जुलाई 1884), हिंदू, 29 दिस० 1884, 3 फरवरी 1888, मराठा, 25 जनवरी 1885, पंजाबी अखबार, 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 16 फरवरी 1889), हिंदुस्तान, 10 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 16 दिस० 1890), बगनिवामी 28 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 5 सित० 1891), गुजरात दर्पण, 29 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 5 दिस० 1891) आई० एन० सी० 1891, 1896, 1901 और 1902 के अंश III, XIII III, और III क्रमशः, एस० मूदलियार, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 36-7, त्रिबुस्तान, 26 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 28 अप्रैल 1892), जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 359 366 राय, पावर्टी, पृ० 222-5, सजीवनी, 26 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 2 नव० 1895), बिक्टोरियन पेपर, 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 16 फरवरी 1895), आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 158, दत्त, स्पीचेज I पृ० 14, आर० एम० सयानी, एम० सी० पी० 1897, खंड XXXVI पृ० 191, रहबर, 1 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 10 मार्च 1897), पंजाब अखबार, 23 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 10 जुलाई 1898); अखबारे आम, 25 जुलाई (वही, 6 अगस्त 1899), अल्मोडा अखबार, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 12 अप्रैल 1899), ताज उस अखबार, 21 जन० (आर० एन० पी० पी०, 4 फरवरी, 1899); बिक्टोरिया पेपर, 4 फरवरी (वही, 18 फरवरी 1899), वकील, 3 अप्रैल (वही, 29 अप्रैल 1899), नवाब एच० हर्सन, रिप० आई० एन० सी० 1899

- पृ० 49; जी० के० पारिख, 22 मई 1900 के बंगाली में उद्धृत; तेज बहादुर सप्त, एच० आर० नवंबर 1900 पृ० 36; रफीके हिंद, 16 जून (आर० एन० पी० पी०, 7 जुलाई 1900); सियाल-कोट पेपर 16 सित० (वही, 6 अक्तूबर 1900); अखबारे आम, 10 नवंबर (24 नवंबर 1900); जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 29; चित्तोड़ में 21-22 जुलाई 1900 को हुए प्रथम अरोटा सम्मेलन की कार्यवाही, पृ० 9 पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 673; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 580-4, बी० के० बोस, एल० सी० पी० 1901 खंड XL, पृ० 266-8; ए० बी० पी०, 1 जन०, 25 सित० 1901, हिंदू 23 मार्च 1901, बंगाली, 28 नवंबर 1901; न्यू इंडिया, 2 दिसंबर 1901; सी० वाई० चित्तामणि, 'इंडिया ऐंड लांड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 341; इंडियन डेली मेल, 24 नव०; हिंदुस्तानी, 27 नव० (आर० एन० पी० एम०, 30 नवंबर 1901); इंदु प्रकाश, 2 दिसंबर, कैंसरे हिंद, 1 दिसंबर, सुधारक 2 दिस० (आर० एन० पी० बब, 7 दिस० 1901); मराठा, 16 नवंबर 1902; श्रीराम, एल० सी० पी० 1903, खंड XLII, पृ० 103
- 163 ए० बी० पी०, 28, 29 अक्तू० 1903; बंगाली, 28 अक्तू० 1903; मराठा, 8 नव० 1903; आर० एन० पी० बग०, 14, 21 नवंबर 1903, आर० एन० पी० बब, 31 अक्तू०, 7, 14 नवंबर 1903, आर० एन० पी० एम०, 7, 21 नव० 1903 में उल्लिखित सभी समाचारपत्र; एडवोकेट, 1 नव० (आर० एन० पी० यू० पी०, 7 नव० 1903), ट्रिब्यून, 21 अक्तू० (आर० एन० पी० पी०, 31 अक्तूबर 1903), पैसा अखबार, 8 नव० (वही, 14 नवंबर 1903), आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव XII; गोखले, स्पीचेज, पृ० 329-30; ए० मुखोपाध्याय और श्रीराम, एल० सी० पी० 1904, खंड XLIII क्रमशः पृ० 389 और 401-02
- 164 रानाडे, एसेज, पृ० 61, 63, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 359-60, 366, हिंदू, 29 दिस० 1884, नवविभाकर, 12 मई (आर० एन० पी० बग०, 17 मई 1884), महत्तर, 14 मई (वही, 24 मई 1884), एस० मुदालियर, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 37, राय, पावर्टी, पृ० 224, इंदु प्रकाश, 2 दिस० (आर० एन० पी० बब, 7 दिस० 1901), गोखले, स्पीचेज, पृ० 332-3; मराठा, 8 नव० 1903; एच० आर०, मार्च 1904 पृ० 302-03
- 165 रानाडे, 'लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल रैंक्स', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 49-51, एसेज, पृ० 256, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 367, गोखले, स्पीचेज, पृ० 25, 112, 331-2
- 166 रानाडे के इस विषय पर विचार 1879-83 की अवधि में प्रकाशित पूना सार्वजनिक सभा के जर्नल में लिखे चार लेखों में प्रकट हुए थे. देखिए, दि ऐग्रेरियन प्रान्स्म एंड इट्स सोल्यूशन' जे० पी० एस० एस० जुलाई 1879 (खंड II स० 1), 'दि ला आफ लैंड सेल इन ब्रिटिश इंडिया' (1880), एसेज में 'लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल रैंक्स', जे० पी० एस० एस०, अक्तू० 1881 (खंड IV, स० 2) और 'प्रशियन लैंड लेजिस्लेशन ऐंड दि बंगाल टेनेसी बिल' (1883) एसेज में
167. रानाडे, एसेज, पृ० 275-81, 283, 288-9 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने बंगाल में वर्तमान बुराईयों को हटाने के लिए उपाय के रूप में कानूनी साधन की महत्ता को स्वीकार किया था.
168. वही, पृ० 326
169. इस प्रकार, बंगाल के सबंध में उन्होंने लिखा . रैंयतबाड़ी भूमि पहले ही अधिकारों की जटिलता को सीमित करने की कल्पना करती है जबकि सभी वैधानिक उपायों की प्रवृत्ति यथासंभव जोतों को अधिक से अधिक जिरायती अथवा खाम बनाने की होनी चाहिए. कानूनों का रूप ऐसा होना चाहिए कि उनके अंतर्गत भूमि का स्वामी सभी प्रकार के लाभ का तो भागी बने और हानियों

से उसका कोई सबध न हो. (वही, पृ० 278).

- 170 वही, पृ० 257, 264, 287, 289 तथा लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 56-7
171. एसेज, पृ० 287 तथा देखिए, 'एंग्लेरियन प्राबलम ऐंड इट्स सोल्यूशन', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 17
172. 'दि एंग्लेरियन प्राबलम ऐंड इट्स सोल्यूशन', पूर्वोक्त स्थल पृ० 17 उन्होंने आगे कहा 'समृद्ध बगों को इस समय भूमि में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है न उन्हें धरती से कोई पद मिल सकता है न प्रतिष्ठा और न ही वे जमींदारों के रूप में काम कर सकते हैं इस प्रकार के सपन्न बगों की अनुपस्थिति कृषि के सर्वतोमुखी विकास को अवरोध कर देती है.
- 173 वही, पृ० 18 तथा देखिए, वही, पृ० 10-1, 13-14, 19 और एसेज, पृ० 325-7
174. एसेज, पृ० 277 ९
- 175 वही, पृ० 267-70, 273-5
- 176 'दि एंग्लेरियन प्राबलम ऐंड इट्स सोल्यूशन', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 16-7
- 177 एसेज, पृ० 326-7 उन्होंने यह भी लिखा 'इस समय देश सरकार की अवस्था में है वह वर्तमान अर्धमासकी और पितृमत्तात्मक स्थितियों से गुजर रहा है वह इस समय अधिक व्यवस्थित और व्यवसायपरक स्थिति को अपना जा रहा है प्रवाह के विरुद्ध जाने वाला अथवा प्रवाह को अवरोध करने वाला कोई आर्थिक कानून वर्तमान परिस्थितियों में सफल नहीं हो सकता सभी देशों में सभी प्रकार की — भूमिगत अथवा पदार्थगत सर्पित का स्वामित्व बेमसुम अदूरदर्शी और अपने हस्तगत साधनों को सभालने और उनका सही रूप में उपयोग करने में असमर्थ लोगों के वर्ग के हाथों से निकल कर बुद्धिमान, दूरदर्शी, व्यावहारिक तथा दृढ़ निश्चयी वर्ग के हाथ में ही चला जाना चाहिए यह दूरदर्शिता का नियम है इस सबध में सरकार अधिकतम जा प्रयास कर सकती है, वह यह है कि अपरिहार्य हस्तान्तरण को सरकार नियमित रूप दे दे ताकि तात्कालिक कठिनाई दूर हो जाए (वही, पृ० 325-6) यह भी उल्लेखनीय है कि रानाडे को यह भलीभाँति ज्ञात था कि साहूकार भूमि का कब्जा ब्याज की ऊँची दर वसूलने के लिए लेता था न कि कृषि व्यवसाय में उत्पादपूर्वक प्रवृत्त होने के लिए स्वामित्व सभालना था ('लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैंक्स', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 38).
- 178 एसेज, पृ० 264, 268-9, 276 रानाडे ने बंगाल के जमींदारों को अपनी योजना के सपन्न जमींदार मानने में कोई गलती नहीं की परवर्ती भारतीय लेखकों ने आमतौर पर यह गलती की है दूसरी ओर उन्होंने देखा कि 19वीं शताब्दी में बंगाल की ओर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुघल से पूर्व प्रजा की स्थिति वास्तव में ही एक समान थी क्योंकि बंगाल के जमींदारों और प्रजा के जागीरदार (ज़ादतगिरी) दोनों में निकटतम सादृश्य था इसी सादृश्य के कारण ही उन्होंने प्रजा भूमि प्रश्न का सावधानी के साथ अध्ययन किया था तथा उसकी बकालत की थी (वही, पृ० 259).
- 179 वही, पृ० 272-4
- 180 वही, पृ० 287 तथा देखिए, पृ० 290.
181. 'दि एंग्लेरियन प्राबलम ऐंड इट्स सोल्यूशन', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 17.
- 182 वही, और एसेज, पृ० 325-7.
183. एसेज, पृ० 274-5
184. वही, पृ० 276 तथा देखिए, पृ० 283, 287, 288

- 185 उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रस्ताव केवल एक वर्ग के लाभ के लिए दूसरे वर्ग के अधिकारों को छीनता है इसे केवल समाजवादी अथवा साम्यवादी सिद्धान्तों पर ही आधारित माना जा सकता है (वही, पृ० 287) तथा दखिण, पृ० 279 80 283, 289, 291
- 186 वही, पृ० 280
- 187 वही, पृ० 284
- 188 वही पृ० 285-6
- 189 वही, पृ० 286-7
- 190 नसीम आगरा, 23 अगस्त आर० एन० पी० पी० एन०, 25 अगस्त 1884), जे० एन० बोम, रिप० आर्ट० एन० सी०, 1890 पृ० 52, आर्ट० एन० सी०—1891 और 1892 के प्रस्ताव III जोर IX हिंदुस्तानी, 8 नवंबर (आर० एन० पी० एन०, 15 नवंबर 1893), विभूदरजनी, 25 नवंबर (आर० एन० पी० एन०, 15 अप्रैल 1896) इत स्वीचज I पृ० 161 मो० शकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 385, अदशमित्रन, 17 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 31 मार्च 1900)
- 191 आर० आर्ज० एन० सी०, 1890 पृ० 53 उन्होंने यह सवाल उठाया 'क्या यह अच्छा नहीं होगा कि भाई राम ठाकुर म कुल भाया द नवन म असमय निज निगानो का जोतो का स्वामी बनान का अज्ञा अभिमान बना दिया जाए ? क्या यह स्वयं उनके अपने लिए, धरती के लिए तथा देश का उत्थन करने नहीं होगा ?'
- 191ए ज्ञान, अप्रैल 1900 पृ० 764
- 192 'लेड ना रिफार्म एड एग्जीक्यूटिव बैकम पूर्वोक्त स्थल, पृ० 42 अपनी सामान्य गहरी पकड़ के अन्तर्गत रानाद न सत्रप का दूसरा पक्ष पर भी विचार किया 'इसमें मदद नहीं कि कृषि अनुसंधानों । शी गेट प्रेरणाएं और मैं अपने आप स्वयं उद्योगों का संप्रतिन उन्हे श्री परिणाम में देश के साक्षरता का इस रूप में पजी पक्षीय विभाग द्वारा जिम्मा कि इस समय पूर्वोक्त नहीं किया जा सकता ।' (वही पृ० 53)
193. रानाद, एसेज, पृ० 256 तथा देखिए पृ० 207
- 194 तथा देखिए, मराठा, 23 जनवरी, 13 फरवरी, 17 जनवरी, 1891, 1 जनवरी 1892, 25 मई 1884
- 195 राय, पावर्टी, पृ० 97-8
- 196 भागी, पूर्वाद्धा, पृ० 350, 353, 370 2
- 197 वही, पृ० 849, 851 2
- 198 वही, पृ० 368 तथा देखिए, पृ० 852-3
- 199 वही, पृ० 642
- 200 आर० एन० पी० बब, क्रमश 22 जून 1901 और 15 नवंबर 1902 तथा देखिए, केसरी, 10, 17 नव० (आर० एन० पी० बब, 14, 21 नव० 1903); बारहवें बर्षे प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव, मराठा, 16 नवंबर 1902
201. जी० एस० अथर, ई० ए०, पृ० 64-6.

अध्याय 11

लोकवित्त : एक

सम्य प्रशासनवाला कोई ऐसा देश नहीं, जहाँ पर इतना हलका कराधान हो ।

— जान स्ट्रुच्चे

हाँ, कुछ वस्तुएँ अभी ऐसी बची हैं जिन पर कर लगाया जा सकता है ताकि अंगरेजों का विजय अभियान पूरा हो सके । गेमी अवशिष्ट वस्तुओं में उल्लेखनीय हैं भारतीय लोगों की चमड़ी और उनका वायुमंडल । — 'केसरी', 31 जनवरी 1888

न्यायप्रिय सरकार द्वारा प्रशासित प्रत्येक देश में निर्धनों की अपेक्षा धनिकों पर ही अधिक मात्रा में कर लगाना उचित समझा जाता है क्योंकि यह धनी वर्ग ही पुलिस संगठन में, न्यायिक अदालतों की स्थापना में, रेलों, तार आदि में लाभान्वित होता है परंतु जिस देश का प्रशासन उच्च वर्गों के लोगों के ही हाथ में हो वहाँ क्या वे अपने आप पर कर थोपने की मूर्खता करेंगे ? — 'स्वदेशामित्र', 18 फरवरी 1888

समीक्षाधीन अवधि में भारत सरकार की औद्योगिक और शुल्क पद्धति संबंधी नीतियाँ तथा निकासी समस्या के उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की क्रोधाग्नि का प्रज्वलित करने वाला तत्व था उसकी वित्त नीति । इस अवधि में भारतीय वित्तों के निर्धारक तत्व थे एशिया में अंगरेजी-रूसी शत्रुता के बढ़ने के फलस्वरूप भारत पर रूस के आक्रमण की आशंका से सैनिक व्ययों में भारी बढ़ोतरी, चांदी के स्वर्ण मूल्य में अवपात, रेलवे के द्रुत विकास पर होने वाला व्यय तथा इन सभी तत्वों के फलस्वरूप व्ययों में विकास द्वारा करोड़ों की बढ़ोतरी को एक आवश्यकता का रूप दिया जाना । यद्यपि कुछ एक वर्षों में भारतीय वित्त सदस्य बचत का बजट प्रस्तुत करने में सफल हो गए तथापि कुल मिलाकर ये वर्ष आर्थिक असंतुलन, कष्ट तथा करोड़ों द्वारा व्यय की राशि प्राप्त करने के प्रयत्नों की असफलता के ही वर्ष थे ।¹ यह कम हैरानी की बात नहीं कि वर्ष प्रति वर्ष सभी वित्त सदस्य पृथक पृथक रूप से भारत के वित्तों की दुर्दशा का रोना रोते रहे तथापि जब कभी

ब्रिटिश और ब्रिटिश भारतीय राजनीतिज्ञों ने भारतीय वित्तों की सामान्य चर्चा की उन्होंने सदैव अत्यंत आशावादी दृष्टिकोण प्रकट किया। इस प्रकार 1893 में अपनी पुस्तक 'इंडियन पालिटी' में जनरल चिसनी ने भारतीय वित्तों की उल्लेखनीय स्थिरता पर हर्ष प्रकट किया।¹ 1878-98 के बीच की अवधि के भारतीय विनो की समीक्षा के उपरान्त जैम्स बैस्टलैंड ने 1898-99 के वित्त विवरण में बड़े साहस के साथ दृढ़ स्वर में कहा कि मेरे द्वारा ऊपर के अंको में प्रदर्शित-विवेचित 20 वर्षों के वित्तों के अभिलेख से यह सिद्ध है कि इंग्लैंड को छोड़कर विश्व के लगभग किसी भी देश के वित्तों से इस देश के वित्त बेहतर है।² 1901 में भारत सचिव जार्ज हैमिल्टन ने भारतीय वित्तीय पद्धति की स्थिरता तथा पुनः बल प्राप्त करने की शक्ति पर आश्चर्य तथा हर्ष के भाव प्रकट किये।³

दूसरी ओर राष्ट्रवादी नेताओं ने ठीक इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। उदाहरणार्थ, 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 30 मार्च 1882 के अंक में भारतीय वित्त पद्धति के सिर से पाव तक अशक्त होने की घोषणा की। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1894 के अधिवेशन में डी० ई० वाचा ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि हमारी शिकायत के मूल कारण हमारे वित्त ही हैं और ब्रिटेन को भारत में हाथ धाना पड़ा तो उसका कारण शोचनीय वित्त ही होगा।⁴ कांग्रेस के 1895 के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुर्देनाथ बैनर्जी ने जान ब्राइट की इस मान्यता को उद्धृत करते हुए कि किसी देश के लोगो की स्थिति का निर्णय उनके वित्तों की स्थिति की समीक्षा के मद्देन में ही किया जा सकता है, घोषणा की कि इस आधार पर भारत की स्थिति की जांच करने पर वह सचमुच ही दुःखद एवं चिंतनीय है क्योंकि भारत के वित्तों की स्थिति निम्न आबर्नक घाटे एवं रेकरिंग डेफिसिट तथा निम्न बढ़ते ऋण की है।⁵ 1896 में जनवरी में प्रकाशित अपने निबंध 'दि प्रेजेंट फाउन्डेशन पोलीशन' में जी० वी० जोशी ने इस सरकारी धारणा का खंडन करते हुए कि भारतीय वित्त वित्तीय कौशल के उज्ज्वल रूप को प्रदर्शित करते हैं, निश्चित स्वर में कहा कि परिमाण और तीव्रता की दृष्टि से देश अभूतपूर्व वित्तीय संकट के कारण गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है।⁶ स्थिति की विषमता न इस तथ्य में और भी गंभीर रूप ले लिया था कि वर्तमान शोचनीय स्थिति किसी व्यक्ति अथवा प्रशासक विशेष की गलतियों और कार्यवाहियों का परिणाम नहीं थी अपितु वित्त पद्धति, देश की सारी की सारी वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था ही इसके लिए उत्तरदायी थी।⁷ इसी प्रकार इपीरिंगल लैजिस्लेटिव कौंसिल में 1902 में अपने सर्वप्रथम भाषण में जी० के० गोखले ने 1885-6 के वर्षों के भारतीय वित्तों का बड़ा ही भयावह चित्र खींचा और आरोप लगाया कि उस वर्ष से हमारे वित्तों की प्रबन्ध-व्यवस्था इस रूप में की गई है कि इस धारणा को बल मिलने लगा है कि भारतीय राजस्वों के प्रबन्ध में भारतीय हितों की अपेक्षा अन्यान्य हितों को ही प्राथमिकता दी जा रही है।⁸

भारतीय नेताओं ने भारत के वित्तों की प्रकृति और प्रबन्ध-व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी राजकोषीय नीति की विस्तृत परीक्षा की तथा वैकल्पिक नीतियां अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने विशेष रूप से सरकार के

प्रत्येक ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम की, जिसे उन्होंने जनता पर नए कर बोझने का, अनावश्यक, निरर्थक तथा अकल्याणकारी व्यय का तथा भारत और ब्रिटेन के संबंधों में अन्याय का उदाहरण समझा, परीक्षा की, निंदा की तथा उसके विरुद्ध लोकप्रिय आंदोलन चलाया। प्रत्येक इस प्रकार के उदाहरण से उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रकृति और उद्देश्यों के संबंध में समुचित निष्कर्ष निकालने की चेष्टा की।

कराधान

भारत सरकार के कुल राजस्व 1880 में 74.3 करोड़ के मुकाबले 1993 में 90.6 करोड़ और 1904 में 172.2 करोड़ तक पहुंच गए।¹⁰ परंतु जहां तक अन्य बातों के साथ राज्य रेलवे की कुल रेलवे वसूली, मिर्चाई योजनाओं की वसूली तथा अन्य रेलों के खातों की विशुद्ध वसूली को सम्मिलित करने का संबंध था, ये अक विकृत रूप लिए हुए थे। इसके अतिरिक्त खाने के एकक में परिवर्तन जैसे कुछ और तत्वों ने भी वर्षों तक वित्तीय आकड़ों की तुलनात्मकता को विकृत किया था।¹¹

लोगों पर राजस्व भार के संबंध में ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं द्वारा परस्पर विरोधी मत प्रकट किए गए। बहुत सारे ब्रिटिश लेखकों और अधिकारियों ने सारे सरकारी राजस्व को कराधान के परिमाणारूप देखने पर प्रारम्भिक आपत्ति की।¹² उदाहरणार्थ उनमें से बहुतों ने यह मिश्र करने की चेष्टा की कि भूमि पर लगान सरकारी किराया था, कर नहीं।¹³ इसी प्रकार उन्होंने अफीम में मिलने वाले राजस्व को भी लोगों पर लगने वाला कर मानने में इनकार कर दिया।¹⁴ दूसरी ओर भारतीय लेखकों ने सरकारी राजस्व के स्रोतरूप लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं का कर स्रोतों के रूप में वर्गीकरण किया। उदाहरणार्थ दादाभाई नौरोजी ने 'कर' की परिभाषा इस प्रकार से की : देश की कुल वार्षिक आय में देश की सरकार अपने प्रशासन और सार्वजनिक ऋण आदि के लिए जो रकम लेती है, वह कर है।¹⁵ शब्द के वर्तमान स्वीकृत अर्थ को ध्यान में रखते हुए भारतीय नेताओं द्वारा विवक्षित परिभाषा को अपेक्षाकृत अधिक सही मानना उचित है।

ब्रिटिश प्रशासक प्रायः इस बात को दृढ़तापूर्वक कहते रहे कि भारत पर बहुत हलके कर लगाए गए हैं और सर्वाधिक संभावना यही है कि यह विश्व भर में सर्वाधिक हलके कर चुकाने वाला देश है। प्रमाण के रूप में भूतपूर्व वित्त मन्त्रिजन जान स्ट्रैची ने बड़े विश्वास के साथ यह दावा किया : 'विश्व में सम्य प्रशासन वाला कोई भी देश भारत के समान हलके कर चुकाने वाला देश नहीं है।'¹⁶ कर्जन भी इसी प्रकार की स्थिति के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। जी० के० गोखले की इस धारणा को कि करारोपण भारतीय जनता को बहुत बुरी तरह से व्यथित कर रहे हैं, नकारते हुए कर्जन ने 1902 में तिरस्कारपूर्ण स्वर में टिप्पणी की : यदि सम्माननीय सदस्यों को किसी यूरोपीय देश में रहने के लिए भेज दिया जाए तो मुझे आशा है कि वे राजस्व पद्धति के मामलों में परिवर्तित विचारों के साथ ही शीघ्र इस देश में रहने के लिए वापस लौट आएंगे।¹⁷

ब्रिटिश अधिकारियों का इस संबंध में दृढ़ मत यह था कि कराधान की व्यावहारिक

शब्दावली में भारत में प्रतिव्यक्ति कर भार विंश्व के दूसरे देशों, विशेषतया ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति कर भार के मुकाबले बहुत ही कम था। 1860 में, तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स विन्सन ने इस अंतर को इस प्रकार से स्पष्ट किया। उनके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 5 शिलिंग कर भार था जबकि इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति कर भार की राशि 2 पौंड 3 शिलिंग थी।¹⁸ ग्यारह वर्षों के उपरांत वायसराय लार्ड मेयो ने भी यह कहते हुए कि भारत में प्रतिव्यक्ति कर भार की रकम केवल 1 शिलिंग और दस पैसे है, कराधान का हलकापन स्पष्ट करने की चेष्टा की।¹⁹ कर्मभार का यह अंक निकालने के लिए उन्होंने सरकार के कुल सभी प्राप्य राजस्वों में से भूमि लगान, अफीम शुल्क, उपहार कर तथा इस प्रकार के अन्य करों से होने वाली प्राप्तियों को अलग कर दिया था। इसी अनुमान पर विश्वास करते हुए भारत राज्यसचिव हेनरी फाउलर ने 1894 में दृढ़ स्वर में कहा : 'भारत में प्रतिव्यक्ति करभार लगभग 2 शिलिंग 6 पैसे अथवा इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति कर्मभार के मुकाबले 1/20वां भाग तथा आयरलैंड में प्रतिव्यक्ति करभार का 1/13वां भाग है।'²⁰

यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि 1880-1904 की अवधि में भारत के राजस्वों में वृद्धि को, जिसके संबंध में यह दावा किया गया था कि किसी प्रकार के वृद्धि के साधन रूप नए कर्मभार की लगाए बिना ही हुई थी, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने देश की विकासशील संपन्नता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।²¹ जनरल चिमनी ने दृढ़तापूर्वक कहा 'राजस्व की विभिन्न शाखाओं में वृद्धि देश की संपन्नता की वर्ष प्रतिवर्ष क्रमिक, निरंतर तथा संतुलित प्रगति की सूचक है।'²² 1903 में कर्जन ने गर्वोक्ति करते हुए टिप्पणी की कि हमने भौतिक संपन्नता के सूचक राजस्वों में निरंतर सुधार, व्यापक तथा बढ़ती हुई वचों और सभी परीक्षाओं में अग्रगति दिखाई है।²³ कुछ एक ब्रिटिश अधिकारियों ने तो यहां तक कहा कि 1860 के उपरांत कर्मभार वस्तुतः कम हुए हैं।²⁴

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इन सरकारी धारणाओं को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया।²⁵ उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में कराधान कमरतोड़ और अग्रग्राह्य है और देश के सामर्थ्य और माधनों का अतिक्रमण करते हैं। ये अपनी ऊंचाई के चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। वास्तव में कराधान का दमतोड़ दबाव ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभियोगपत्र का एक नियमित अंग बन गया था और इसने बहुत सारे भारतीय नेताओं को इस विषय पर कठोर, तीखी और रोषपूर्ण भाषा में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए आदोलित किया था।

1838 में हम 'यंग बंगाल' को अन्यान्य वस्तुओं के साथ साथ देश पर बड़े विशाल कराधान के विरुद्ध शिकायत करता हुआ पाते हैं।²⁶ 1871 में बावे एम्प्लिशन ने हाउस आफ कॉमंस को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि ब्रिटिश शासन के अनेक वर्षों में भारी कर भारत के दुख का कारण रहे हैं।²⁷ 1879 में सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने यह मत प्रकट किया कि 'कोई अत्यंत लापरवाह प्रेक्षक भी यह देख सकता है कि इस देश में कराधान अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। नए कराधान के रूप में और भार डालने का कोई भी प्रयास जनता के लिए असहनीय सिद्ध हो सकता है।'²⁸ इसी

प्रकार 1880 में रानाडे ने टिप्पणी की कि 'कराधान में और अधिक वृद्धि करना राजनीतिक पागलपन का परिचय देना होगा।'²⁹ 'अमृत बाजार पत्रिका' ने मत प्रकट किया कि एक सीमा होती है जिसके आगे कराधान असंभव सा हो जाना है और यह सिद्ध करने के कई प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। उसने 27 अगस्त 1885 के अंक में चेतावनी देते हुए लिखा : 'जब विवेकशून्य शासक सीमा का अतिक्रमण करते हैं तो वे विद्रोह को निमंत्रण देते हैं। यदि लोग विद्रोह करने में अत्यंत अशक्त हैं तो प्रकृति स्वयं ही हस्तक्षेप करती है तथा अपने रोष का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। भारत में इस सीमा का अतिक्रमण हुआ है, इसका प्रमाण लगातार अकालों के रूप में देखा जा सकता है।' यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भी कराधान पर बहुत तीव्र आलोचनाएँ हुईं। दादाभाई नौरोजी ने शामकों पर आरोप लगाया कि वह इस प्रकार ऊँचे और ऊँचे कर लगाए जा रहे हैं, जैसे निचुड़े हुए मत्तरे को और निचोड़ने की चेष्टा की जा रही हो। इस प्रकार ये शासक जनता के कष्टों और दुखों में वृद्धि कर रहे हैं।³⁰ इसके माथ ही निलक के 'केमरी' ने अपन 31 जनवरी 1888 के अंक में टिप्पणी की : 'भारत में कोई भी वस्तु कराधान में मुक्त नहीं, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों तक को कराधान का विषय बनाया गया है।' व्यर्थपूर्ण प्रहार करते हुए केसरी ने मुग्धता दिया : हा अभी भी कुछ एक वस्तुएँ बची हैं, जिन पर कर लगाया जा सकता है ताकि अंग्रेजों का विजय अभियान पूरा हो जाए। इन अवशिष्ट वस्तुओं में उल्लेखनीय हैं, भारतीय लोगों की चमड़ी और उनका वायुमण्डल।'³¹ 9 फरवरी 1888 के सत्यमित्र' ने चेतावनी दी कि सरकार को यह बात अपने ध्यान में 'भली प्रकार धारण कर लेनी चाहिए कि गुस्सा दिलाए जान पर एक निर्गद गाय भी हाथी का फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकती है अथवा स्वतः दुहने का रावने वाल दूध को दोहने से उपयोग खाला यदि गाय के स्तनों में फिर दूध को दोहने की चेष्टा करता है तो उस खाले को वह गाय दुलती मार सकती है।' लगभग विद्रोहान्मक स्वर में उगने घमकी देते हुए लिखा : 'भामी की रानी, निजाम-उन-मुल्क, चिमनाजी अप्पा, बाजीराव तात्या टोपे और अन्यान्य श्रेष्ठ वीर यादवा यद्यपि इतिहास के पात्र बन गए हैं तथापि उनकी तलवार आज भी विश्व के सामने घम रही है तथा हमारी वीरता का प्रमाण जूटा रही है।'³² 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बराबर इस तथ्य में सहमत और प्रभावित थे कि किसी भी नए कगधान को सहन करने की देश की शक्ति नष्टप्राय हो चुकी है।³³ वर्षों तक इसी प्रकार की विरोधी भावनाएँ और इसी प्रकार के मत बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा प्रकट किए जाते रहे।³⁴

भारतीय नेताओं की एक अन्य शिकायत यह थी कि देश में कगधान अत्यन्त ऊँचा और भारी ही नहीं है प्रत्युत निरन्तर बढ़ता भी जा रहा है।³⁵ उदाहरणार्थ, जी० वी० जोशी ने 1896 में हिसाब लगाया कि रेनवे तथा अन्य व्यापारिक वसूलियों को निकाल देने पर भी कांग्रेस कगधान का भार 1883-4 और 1895-6 की अवधि में 35 प्रतिशत बढ़ा है।³⁶

भारत में कराधान की भारी ऊँचाई प्रमाणित करने के लिए भी भारतीय नेताओं ने

अन्यान्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई विधि के समान आकड़ों को ही कसौटी बनाया परंतु इस कसौटी का निर्धारण उन्होंने अपने ढंग से ही किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्वतंत्र रूप से प्रति व्यक्ति कराधान की राशि कम थी परंतु उनका तर्क यह था कि प्रति व्यक्ति आय को देखे बिना ही प्रति व्यक्ति से लिए जाने के स्वतंत्र आकड़ों में कराधान के परिमाण का निर्णय नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यहाँ प्रति व्यक्ति कराधान की राशि नहीं प्रत्युत इससे सबद्ध प्रतिव्यक्ति आय के अनुपात को देखना अधिक महत्वपूर्ण था। यदि भारत में कराधान नीचा था तो राष्ट्रीय आय उससे भी अधिक नीची थी। भारतीय नेताओं का कथन था कि इस सदर्भ में देखे जाने वाले पर भारत में कराधान सचमुच ही अत्यंत भारी और दबाने वाला मिद्ध होता है। दादाभाई नौरोजी इस तर्कपद्धति के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने 1871 में पूर्वी भारत के वित्तों के लिए नियुक्त प्रवरसमिति को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में इस तर्क पद्धति का प्रयोग किया था। उन्होंने इस तथ्य को वाणी दी कि इंग्लैंड में प्रतिव्यक्ति कराधान का परिमाण लगभग 8 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 16 प्रतिशत के लगभग है।¹⁷ उन्होंने तथा अन्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अपना पक्ष मिद्ध करने के लिए सांख्यिकी प्रमाणा का वर्षों तक उपयोग किया। इस संबंध में यह उत्तरवर्णीय है कि उनके अंका को मगणना में प्रतिशत में भिन्नता आ जाती थी।¹⁸

कुछ भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि आय के साथ कराधान का यह औसत भी बोझ के भारीपन को मही रूप में और यथाचित ढंग में प्रस्तुत नहीं कर पाता। उनका कथन था कि कुल मिलाकर कराधान का जनता की भुगतान की क्षमता के साथ संबंधित करना चाहिए। एक निधन व्यक्ति में उसकी आय के एक निश्चित अनुपात को कर के रूप में लेना एक बात थी और एक धनी व्यक्ति में उसकी आय के उगी अनुपात को कर के रूप में लेना मवथा भिन्न बात थी क्योंकि इसमें निधन व्यक्ति के लिए ता जीवनस्तर बनाए रखने में कम और अधिक कठिनता का सामना करना पड़ेगा। चिन्तन की इस रूपरेखा की स्पष्ट और निश्चित अभिव्यक्ति दादाभाई नौरोजी के लेखा में दखने को मिली। उन्होंने राष्ट्रवादियों की स्थिति में प्रतीत होने वाले विरोधाभास के समाधान के लिए इस चिन्तन पद्धति का प्रयोग इस प्रकार में किया कि भन्ने ही यह मान लिया जाए कि प्रति व्यक्ति कराधान नीचा है फिर भी वह भारतीय लोगों के लिए कमरतोड है। उन्होंने पूर्वी भारत के वित्तों से संबंधित प्रवरसमिति को भेजे गए अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य का सम्यक् विश्लेषण इस प्रकार से किया

इस तथ्य को भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए कि एक हाथी के लिए एक टन वजन भी भारी नहीं परंतु बच्चे को कुछ एक किलो भार ही कुचलने के लिए काफी है। कराधान के प्रतिशत से आसानी के साथ भार उठा सकने अथवा उस भार से कुचले जाने को नहीं मांगा जा सकता, प्रत्युत इसे अपने के लिए उपयोग्य आधार है भुगतान के लिए आय के साधनों की प्रचुरता अथवा कृच्छता। आय के साधनों की प्रचुरता की स्थिति में भारी प्रतिशत के करो का सुविधा से भुगतान किया जा सकता है और आय के साधनों की सीमितता की स्थिति में यह भार कठिनता से ही सहन

हो पाता है अथवा थोड़ा-बहुत क्लेश उत्पन्न करता है परंतु आय के साधनों की अपर्याप्तता की स्थिति में तो यह भार अत्यधिक कष्टदायक हो जाता है।¹³ उन्होंने अपने इस सूत्रबद्ध सिद्धांत को 'पावर्टी आफ इंडिया' लेख में दोहराया और बाद में अपने असंख्य भाषणों आदि में इसका विस्तृत विवेचन किया।¹⁴ 1896 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आर० एम० सम्यानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में दादाभाई के तर्कों को दोहराया।¹⁵

दादाभाई ने जब इस चिंतनपद्धति का भारत पर प्रयोग किया तो उन्हें यह धोषणा करनी पड़ी कि भारत में कराधान का भार इंग्लैंड के कराधान के भार से दुगुना ही नहीं अपितु दुखदायक भी है क्योंकि यह गरीबों से लिया जा रहा था।¹⁶ इसी प्रकार आर० एम० सम्यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के संबंध में आय पर करों की औसत 16 प्रतिशत है और यद्यपि इंग्लैंड के संबंध में प्रचलित अनुपात के मुकाबले कहने को केवल 2½ गुना ऊंचा है तथापि वास्तव में यह परिमाण में उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक भारी है और इस प्रकार सूचक अनुपात की अपेक्षा भारत इंग्लैंड से वास्तव में ही कहीं अधिक बुरी स्थिति में है।¹⁷ के० टी० नैलिंग, मदनमोहन मालवीय, गोपालकृष्ण गोखले, आर० सी० दत्त तथा कितने ही अन्य नेताओं ने भी इसी ढंग से देश की निर्धनता और कराधान भार में सहसंबंध जोड़ा।¹⁸ 1896 में जी० वी० जोशी ने सर्वथा ठोस मिथ्या प्रस्तुत किया कि जब तक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विकास नहीं होता, वर्तमान कराधान में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने दावा किया कि कराधान बढ़ रहा है जबकि राष्ट्रीय उत्पादन का ह्रास हो रहा है।¹⁹ दादाभाई नौरोजी और मदनमोहन मालवीय ने भी थोड़े भिन्न शब्दों में इसी तर्क वाक्य को दोहराया। उन्होंने जोर देकर इस तथ्य को दोहराया कि भारतीय अपेक्षाकृत ऊंचे कर देने को भी प्रसन्नतापूर्वक उद्यत होंगे, परंतु शर्त यह है कि इनका संबंध बढ़ती राष्ट्रीय आय के साथ होना चाहिए।²⁰

अपने मन्तव्य के समर्थन के लिए भारतीय नेताओं ने इस संबंध में अंगरेज अधिकारियों के वक्तव्य प्रस्तुत किए जिनमें कहा गया था कि भारत सरकार ने मकटकाल में भारत पर किसी प्रकार के कराधान का अवकाश ही नहीं छोड़ा है। अब स्थिति यह हो गई कि भारत में आर्थिक और राजनीतिक मकटकाल बिना किसी प्रकार का नया कराधान किया ही नहीं जा सकता।²¹

बाद में जब लाभ के बजट पेश किए जाने लगे तो राष्ट्रवादियों ने उन्हें इस तथ्य के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया कि भारतीय जनता से आवश्यकता अथवा वांछनीयता से अधिक कर छेड़ें गए हैं।²² 1902 में आवर्तक बजट बचतों को अपने बजट भाषण का केंद्रीय विषय बनानेवाले गोपाल कृष्ण गोखले ने यह घोषित करते हुए भारत सरकार की वित्त नीति पर घातक प्रहार करना आरंभ किया कि ये बचने अत्यंत दुःखद रूप में और स्पष्ट ढंग से यह मिथ्या करती हैं कि देश के लोगों की स्थिति और देश के वित्तों के बीच किसी प्रकार का भी व्यावहारिक संबंध नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्यायपूर्ण ढंग से बड़े ऊंचे परिमाण में जनता पर भारी करों का दबाव निर्धारित किया

गया है और उसे बनाए रखा जा रहा है। इस प्रकार एक ओर विपन्न राष्ट्र और दूसरी ओर भरपूर कोश के प्रत्यक्ष विरोध का सुविधापूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है।⁴⁹

राष्ट्रवादी नेताओं में से कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी लोगों के विभिन्न वर्गों में कराधान के वितरण के प्रश्न पर विचार किया। 1880 के प्रारंभ में भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा कराधान के परिमाण के संबंध में विहित विस्तृत जाच-पड़ताल के निष्कर्ष के रूप में यह परिणाम सामने आया था कि भारत में कराधान का प्रमुख भार प्रधान रूप से अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों पर ही पड़ता है।⁵⁰ राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने इस परिणाम के साथ पूर्ण सहमति प्रकट की और कराधान पद्धति की उसके प्रतिगामी चरित्र के लिए मालोचना की। उनके अनुसार कराधान पद्धति का प्रतिगामी चरित्र यह था कि इसकी प्रवृत्ति धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक भार डालने की थी। 1871 में दादाभाई नौरोजी ने जनता के अन्यान्य वर्गों की अपेक्षा किसानों में अधिक कर ऐंठने के लिए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए व्यर्थपूर्वक पूछा : 'या इसका कारण यह है कि समृद्ध वर्ग आंदोलन का आश्रय ले सक्ता है और सरकार को अपनी बात मानने के लिए विवश कर सकता है, जबकि गरीब मजदूर और खेतिहर यह सब कुछ नहीं कर सकते। क्या इसी कारण से यह उचित समझा गया है कि अन्यान्य वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग को निचोड़ना आसान है?'⁵¹ जी० बी० जोशी ने अप्रैल 1888 में अपने निबंध 'दि बर्मा डेफिसिट ऐंड दि एग्रेममेंट आफ माल्ट ड्यूटीज' में इस प्रश्न की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने 'सपन्न जमींदारों और उनके धनिक मित्रों तथा चायबागान के स्वामियों को छूट देने वाली और निर्धनों पर भार डालने वाली' कर नीति अपनाने के लिए वित्त मदद की भर्त्सना की।⁵² उन्होंने कराधान पद्धति की विषमता पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पद्धति के अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासन ब्रिटिश न्याय और ब्रिटिश शांति में अधिकाधिक लाभान्वित होने वाले सपन्न व्यक्ति तो कम टैक्स देने हेतु जबकि लाखों, कम उपाजन करने वाले निर्धन लोग अधिकतम कर चुकाते हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कराधान के भार की विषमता एक वर्ग और दूसरे वर्ग के मध्य ही नहीं प्रत्युत नगरों में विभिन्न वर्गों के बीच और देहातों की साधारण जनता के बीच विद्यमान है।⁵³ इस सबंध में भावी कार्यवाही के लिए उन्होंने पथप्रदर्शक के रूप में सरकार को सलाह दी कि सर्वप्रथम वह सार्वजनिक कराधान के वितरण की विषमताओं के संशोधन और निवारण को अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करे।⁵⁴ इससे पूर्व 1886 में उन्होंने कराधान के निम्न सिद्धांत का उल्लेख किया था :

सभी वित्तीय विचार विमर्शों में व्यावहारिक वित्त विशेषज्ञ के लिए विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि सामान्य जनसंख्या पर कराधान का कुल बोझ भारी है अथवा हलका, यह तो व्यावहारिक राजनीति का एक तत्व है। अर्थशास्त्री के लिए तो विचारणीय यह है कि सार्वजनिक भार को एक साथ लेते हुए यह देखना है कि उसका विभाजन समान रूप से और निष्पक्ष रूप से हुआ है अथवा नहीं... (और) यह देखना है कि उसका भार सभी वर्गों पर न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से उनकी भुगतान क्षमता के अनुरूप पड़ता है अथवा नहीं? ⁵⁵

नमक कर में वृद्धि के बदले आय कर में बढ़ोतरी की वकालत करते हुए सुब्रह्मण्य अय्यर के स्वामित्ववाले तथा उनके द्वारा संपादित 'स्वदेश मित्र' ने अपने 18 फरवरी 1888 के अंक में जोशी जी के विचारों को इस प्रकार दोहराया :

एक न्यायसंगत सरकार द्वारा प्रशासित प्रत्येक देश में निर्धनों की अपेक्षा धनिकों पर ही अधिक परिमाण में कराधान करना उचित समझा जाएगा क्योंकि धनी लोग ही लाभान्वित होते हैं परंतु यदि किसी देश की सरकार ही उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में है तो क्या वे अपने आप पर कराधान की मूर्खता करेंगे।⁶⁰

'स्वदेशमित्र' ने अपने 25 फरवरी 1888 वाले अगले अंक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि केवल वही सरकार न्यायप्रिय सरकार कही जा सकती है जो निर्धन वर्गों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है तथा उच्च और मध्यवर्ग पर कराधान द्वारा अपने राजस्व की वसूली करती हैं।⁶¹ इसी प्रकार 18 मार्च 1888 को पूना सार्वजनिक सभा के तत्वावधान में नमक कर के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए हुए पूना के निवासियों के एक सम्मेलन ने अपने ज्ञापन में शिकायत की कि इस देश का निर्धन वर्ग पहले से ही भारी करों के बोझ से दबा हुआ है जबकि उच्च वर्ग के तथा अधिक समृद्ध लोग तुलनात्मक रूप में छूट और राहत का आनंद भोग रहे हैं।⁶² पृथ्वीश चंद्र राय भी कराधान का असमान परिमाण की आलोचना करने में पर्याप्त उग्र थे और उन्होंने इस अपेक्षाकृत बड़ा कलंक बताया। नमक कर, आय कर तथा भूमि लगान का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतः दुर्व्यवस्थित वित्तों का सारा भार बेचारे निर्धनों को ही उठाना पड़ता है।⁶³ बाद में 1903 में अपने वज्रट भाषण में गांधी ने भी यही मत प्रकट किया कि कराधान में प्रस्तावित किसी प्रकार की राहत अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों को ही मिलनी चाहिए क्योंकि अपने माधनों की अपेक्षा वे ही राजकोश में वाछनीय से बहुत अधिक भुगतान का योगदान करने हैं।⁶⁴

यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि इस काफी कुछ क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपने समय के अग्रणी भारतीय उद्योगपति जे० एन० टाटा का प्रबल समर्थन मिला। उन्होंने 1895 में 'लंदन डेली क्रानिकल' को भेजे अपने पत्र में लिखा

मैं सदैव इस मत का समर्थक रहा हूँ कि भारत में निर्धनों पर कराधान का बोझ बहुत ही भारी है और अच्छे खाते-पीते वर्ग के समृद्ध लोगों पर यह भार अत्यंत हल्का है। जिन लोगों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकारी सहायता की अपेक्षा रहनी है, इसके लिए कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता, जिन्हें सरकारी सहायता के अभाव में किसी हानि की आशंका नहीं रहती यद्वा तक कि सरकार के बदल जाने का भी जिन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, उन बेचारों को सरकारी देनदारी के भुगतान के लिए अपने भोजन तक की बलि चढ़ानी पड़ती है।⁶⁵

इस विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारकों के सभी वर्गों द्वारा दिए गए व्यापक समर्थन की चर्चा हम नमक कर और आय कर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण की समीक्षा के संदर्भ में करेंगे जहां यह दिखाया गया है कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इस मंतव्य की पुष्टि की कि यदि भारतीय लोगों पर कराधान करना ही है तो केवल

धनिकों पर कर लगाने चाहिए, निर्धनों पर नहीं।⁶²

कराधान के कारण अन्याय

भारतीयों के विचार में अत्यधिक कराधान भारत की घोर निर्धनता के ही नहीं यहाँ तक कि प्रायः निरंतर पड़ने वाले अकालों के भी तात्कालिक और प्रमुख कारणों में से एक था। इस संबंध में राष्ट्रीय विचारधारा को दादाभाई नौरोजी ने 1880 में भारतीय अकाल आयोग के प्रतिवेदन में निहित कुछ विवरणों पर ज्ञापन में स्वर दिया गया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारी कराधान लाखों की भूखमरी और मौतों के लिए उत्तरदायी थे।⁶³ भारत के अग्रगण्य राष्ट्रवादी जननेता तथा पत्रकार वर्णों तक इस दृष्टिकोण को दोहराते रहे।⁶⁴ अंततः 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपने एक मौलिक सिद्धांत के रूप में अपना लिया। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि हानि के अकालों का कारण भारतीयों की घोर दरिद्रता थी और दरिद्रता लाने के अन्यान्य कारणों में प्रमुख थे अत्यधिक कराधान तथा ऊँचे लगाने।⁶⁵

इसमें भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि कुछ भारतीय नेताओं ने और सर्वोपरि जी० वी० जोशी न उपर्युक्त तर्कों के अनिश्चित भारतीय उद्योग और भारतीय उद्यम की दृष्टि में भी उच्च कराधान ही निश करने हुए अपनी सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने घोषणा की कि ऊँचे कराधान पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करते थे और इस रूप में देश के आर्थिक विकास को यदि पूर्णतः अमभव नहीं तो बहुत अवरोध बना रहता था।

1888 में जी० वी० जोशी ने प्रथम डम वात पर ज्ञापन दिया कि राज्य द्वारा लगाए गए भारी कर मजदूरी में बढ़ोतरी और मजदूरी कोष के विकास में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करते थे।⁶⁶ बाद में 1890 में उन्होंने अपने एक विस्तृत लेख 'इकोनॉमिक सिन्यूएशन इन इंडिया' में इस तथ्य को उजागर किया कि भारत में औद्योगिक श्रमिक को पीड़ित करने वाला एक बड़े पैमाने की अपर्याप्तता थी जो अन्यान्य विषयों के साथ इस तथ्य का परिणाम थी कि भारतीयों का कुल आय में प्रथम तो बचतों का अवकाश ही कम रहता है और फिर हमारी कुल अर्जन आयों पर भारी कर लगाकर उन्हें और भी क्षीण कर दिया जाता है। उन्होंने संगणना की कि कुल राष्ट्रीय बचतों (कुल उत्पादन में से लोगों के जीवन निर्वाह पर होने वाले व्यय को घटाकर) की राशि प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपये थी, जिसमें से सरकार 50 करोड़ रुपये करों के रूप में ले लेती थी। इस प्रकार राष्ट्रीय वार्षिक बचतों का आधे से अधिक भाग न्यूनताधिक रूप में अधिकांशतः अनुत्पादक व्ययों की पूर्ति के लिए सरकारी कोश में चला जाता था। इसमें स्पष्ट है कि हमारी औद्योगिक प्रगति को पीछे की ओर धकेलने वाला इससे अधिक बड़ा आर्थिक रोग और क्या हो सकता है ?⁶⁷ गोपालकृष्ण गोखले ने 1902 में अपने प्रथम बजट भाषण में इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। गोखले ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा : 'भारतीय वित्तों पर कराधान का स्तर इतना अधिक निम्न होना चाहिए कि उससे राष्ट्रीय उद्योग की अबाधित गतिविधि और विकास के लिए यथासंभव अवकाश मिल सके।' ⁶⁸

तथ्यात्मक रूप से बहुत सारे भारतीय नेताओं ने भारत की विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से संबंधित सैद्धांतिक नियम के स्तर पर निम्न कराधान की मांग उठाई। यह मांग 'अमृत बाजार पत्रिका' के 7 फरवरी 1871 के अंक में बड़ी स्पष्टता से अभिव्यक्त की गई। उसमें इस सरल कथन को निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्ति दी गई :

लोगों पर कराधान स्वयं लोगों द्वारा लगाया ही नहीं जाता और उनका साम्राज्य के वित्तों पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। उनकी चीखोंपुकार कराधान में कटौती के लिए हो सकती है न कि वृद्धि के लिए। हमारी विनम्र सम्मति में संसदविहीन जनता के लिए कराधान में कटौती के लिए निरंतर और मुद्दू मांग करते रहना ही एकमात्र बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है।

1886 में जी० वी० जोशी ने बल देकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन की विशिष्ट स्थितियों के कारण राष्ट्र की भौतिक और नैतिक प्रगति के लिए सरकारी बोझों का यथासंभव हलका होना आवश्यक है।⁶⁹ जब 1898 के उपरांत भारतीय बजटों में निरंतर बचत होनी प्रारंभ हो गई, बहुत सारे भारतीय नेताओं ने करों में छूट की मांग की।⁷⁰ 1902 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने टिप्पणी की कि जब देश के सामान्य करदाता मूखों मरते किसान हों तो देश के शासकों का उन प्रजाजनों को कराधान में छूट देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है।⁷¹ 1905-06 के बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्न कराधान के मामले को अत्यंत स्पष्टता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया :

सभी देशों में यह वित्त का सर्वमान्य नियम है कि सरकारी करों का भार यथासंभव हलका होना चाहिए। ... यदि संपन्न यूरोपीय देशों में यह स्थिति है तो भारत में इसकी और अधिक जरूरत है क्योंकि यहां राजस्व की वसूली निर्धन और असहाय जनता से की जाती है तथा उस राजस्व के अपेक्षाकृत बड़े भाग का भुगतान जीर्ण-शीर्ण एवं नितांत अभावग्रस्त कृषक वर्ग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां भारत में मामले की विशिष्ट स्थितियों के कारण सरकारी व्ययों के एक बहुत बड़े भाग को जनता की नैतिक तथा भौतिक उन्नति से असंबद्ध अथवा अत्यंत दूर से संबद्ध कार्यों पर व्यय करना पड़ता है।⁷²

भारतीय दृष्टिकोण के कुछ पक्ष

देश पर अधिकार भार होने के विचार की लोकप्रियता में वृद्धि के लिए कई तत्व उत्तरदायी थे। सी० एन० बकील के अनुसार 1871-1901 की अवधि में कराधान का परिमाण राष्ट्रीय आय की औसत के 8-9 प्रतिशत के बीच था।⁷³ द्वितीय, आवश्यकता से ऊपर कराधान अथवा कराधान का ऊंचा स्तर विकासशील देश की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश के लिए अधिक से भी कुछ बढ़कर कठिनता उत्पन्न करता था। क्योंकि यह किसानों, दस्तकारों अथवा दूसरे शब्दों में निम्न मध्य वर्गों के सभी तत्वों से बलपूर्वक संपत्तिहरण था। यह धारणा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अवधि में स्वतः प्रमाण के

रूप में सामने आ गई। तृतीय, वर्तमान कराधान के स्तर के समर्थक तत्व के रूप में देश-नुराग अथवा सामाजिक जागरूकता की भावना नहीं थी। इसके विपरीत, जैसा हम बाद में स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, भारतीय नेताओं के मन में यह भय था कि भारत सरकार की विदेशी प्रकृति के कारण प्रशासन की न्यूनतम आवश्यकताओं से किसी प्रकार का अधिक राजस्व शाही उद्देश्यों की पूर्ति में लाया जाएगा। चतुर्थ, भारतीय नेताओं ने भूमि और नमक पर करों के तथा शराब पर उत्पादन शुल्कों के माध्यम से सरकार के भारतीय राजस्वो के उगाहने पर आपत्ति की। अंतिम, भारतीय नेताओं ने कराधान के स्तर और उसके उपयोग के ढंग को सहसंबंधित कर दिया। उन वर्षों में भारत सरकार अंततः राज्यों के कार्यों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत की संकीर्ण परिधि में काम कर रही थी और किसी बड़े पैमाने के विकास को सक्रियता से नहीं ले रही थी।

राजस्व के स्रोत

अब हम भारत सरकार के राजस्व के तत्कालीन मुख्य स्रोतों, भूमि लगान, नमक कर, अफीम और उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, और आयकर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण का विचार करेंगे।⁷⁴ वर्तमान भूमि लगान के परिमाण और उसमें किसी प्रकार की वृद्धि के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, नेताओं की तीव्रतम आलोचना तथा चुने हुए कुछ उत्पादनो पर आयात कर लगाकर कोश जुटाने की उन नेताओं द्वारा की गई जोरदार वकालत का विस्तृत विवेचन पूर्ववर्ती अध्यायों में किया जा चुका है। अगले पृष्ठों में आय कर, नमक कर, अफीम कर तथा उत्पादन शुल्क के संबंध में उनके विचार प्रस्तुत करते हुए उनका विश्लेषण किया गया है।

आय कर

हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि के प्रारंभ में ही अर्थात् 1880 में लाइसेंस कर के रूप में प्रसिद्ध आय कर का एक संशोधित रूप भारत में लगाया जाता था। इस दिशा में सर्व-प्रथम प्रारंभ 1860 में किया गया, जब प्रथम वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने व्यापार, कृषि, व्यवसाय, सरकारी तथा गैरसरकारी नौकरी से 200 रुपये प्रति वर्ष से अधिक आय पर कर लगा दिया। इस कर में निरंतर परिवर्तन किए जाते रहे हैं और अंत में 1865 में इसका परित्याग कर दिया गया, साथ में यह घोषणा की गई कि इसे देश के एक बहुत बड़े सुरक्षित कोष का काम करना था।⁷⁶ उस वर्ष के उपरांत व्यक्तिगत आय पर कर लगाने के मामले को कई बार अपनाया गया और कई बार छोड़ा गया। अंततः उसे कुछ विभिन्न रूपों में फिर ग्रहण किया गया।

1878 में भारत सरकार ने अंतिम रूप से तब तक नियमित रूप ले चुके अकालों के मुकाबले के लिए लंबी अवधि की बीमा निधि योजना के रूप में समुचित राजकोशीय व्यवस्था का दृढ़ निश्चय किया। इस निधि के लिए रकम अंशतः भूराजस्व और लगान पर उपकर लगाने से और अंशतः व्यवसायी और व्यापारी वर्गों तथा दस्तकारों पर लाइसेंस कर लगाने से उगाही जानी थी। इस कार्य के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया।

प्रातीय उपायों की ही इस विषय में सहायता ली गई। लाइसेंस कर वस्तुतः सीमित आय कर था और इसका निर्धारण प्रायः लगभग आय के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर होता था।⁷⁷ कृषि, व्यवसाय तथा वेतनो से तथा इनके अतिरिक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली आय को इस कर की क्षेत्र सीमा के बाहर रखा गया था। इस कर का परिमाण और प्रकृति सब प्रांतों में समान नहीं थी। उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध में तथा मद्रास में कर योग्य न्यूनतम आय की राशि 200 रुपये थी जबकि बंगाल, बंबई और पंजाब में यह राशि 100 रुपये थी। कर का परिमाण भी विभिन्न वर्गों (जिनके अंतर्गत करदाता विभक्त किए गए थे) के अनुसार भी भिन्न था परंतु यह किसी भी रूप में करदाता के कुल लाभ के दो प्रतिशत से अधिक अथवा 500 रुपये से अधिक नहीं था। 1879-80 में सरकार ने व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गों तक इस कर के विस्तार की अमफन चेष्टा की। 1880 में कर में छूट की सीमा 500 रु० तक बढ़ा दी गई। इस समय कर से प्राप्त होने वाली राशि 5 लाख पौंड में ऊपर थी और करदाता व्यक्ति 228,447 थे।⁷⁸

भारतीय नेताओं ने लाइसेंस कर लगाने के समय ही सामान्य रूप में उसका विरोध किया⁷⁹ और परवर्ती वर्षों में उसे हटाने की मांग करने लगे।⁸⁰ यद्यपि यह मान देते योग्य है कि उन्होंने प्रमुख रूप में लाइसेंस कर लगाने के पीछे निहित मिथ्या पर प्रहार नहीं किया। उन्होंने इसे लगाने के ढंग पर आपत्ति की, जो उनके अनुसार असमान और अन्यायपूर्ण था। इस कर के विरुद्ध उनकी सर्वप्रथम आपत्ति यह थी कि यह आय के बहुत ही निम्न स्तर तक आक्रमण करता था, अनिर्धनों की बहुत बड़ी संख्या इसमें दुर्प्रभा वित्त होती थी। कुछ का तो यह भी विचार था कि करो का बोझ निर्धनों पर अत्यधिक भारी था, जबकि समृद्ध वर्ग इसमें अपेक्षाकृत रूप में मुक्त था। उदाहरणार्थ, 14 जनवरी 1878 के अंक में 'इंदु प्रकाश' ने इस कर की न्यायोचितता पर प्रश्नात्मक स्वर में पूछा कि यह कहा का न्याय है कि यह बड़े बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों, व्यापारियों तथा वाणिज्य में लगे व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश यूरोपीय हैं की जेबों को तो हलके रूप में प्रभावित करता है जबकि छोटे छोटे व्यापारियों और दस्तकारों पर जिनमें अधिकांश भारतीय हैं, पर भारी बोझ डालता है।⁸¹ इसी प्रकार 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने 23 अक्टूबर 1881 के अंक में इस कर को वर्णसंकर राक्षस बताया जो आधा भीरु और आधा गुंडा था। समृद्धतम और अच्छी सरकार के सर्वोत्तम लाभों का आनंद उठाने वालों के पास से तो यह दुबक कर निकल जाता था और छोटे छोटे व्यापारियों का खून चूसता था।⁸² राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने इस ओर भी संकेत किया कि निर्धन लोग कर निर्धारण और समाहरण से संबंधित छोटे छोटे अधिकारियों के कुप्रशासन की प्रवृत्ति से भी बुरी तरह दुखी थे।⁸³ अतएव कुछ समाचारपत्रों ने कर सीमा बढ़ाने की मांग की।⁸⁴ यह पर्याप्त रोचक सत्य है कि 17 जनवरी 1880 के अंक में 'बंगाली' ने बड़ी तीव्रता से कर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर आपत्ति की क्योंकि इससे उन लखपति व्यापारियों के प्रति, जिन्हें इस प्रकार के किसी अपवादात्मक पक्षपात की कोई आवश्यकता नहीं थी और जो अधिकांशतः यूरोपीय ही थे, विशिष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि भारतीय समाचारपत्र इस मामले में शहरी निर्धनों की तीव्र भावनाओं

को अभिव्यक्ति दे रहे थे। उनकी इन भावनाओं को अन्यान्य रूपों में भी अभिव्यक्ति मिल रही थी।⁸⁵ प्रमाण के रूप में कलकत्ता में 1878-9 में इस कर के विरोध में भिन्नियों, नालबंदों तथा ठेकेवालों ने हड़ताल कर दी।⁸⁶ अप्रैल 1878 में सूरत में इस कर के ऊँचे निर्धारण के विरुद्ध गंभीर दंगे हुए।⁸⁷

राष्ट्रवादियों के लाइसेंस कर पर प्रहार का दूसरा आधार यह था कि उच्च वेतन-भोगी यूरोपीय तथा भारतीय सरकारी कर्मकारी और फलते-फूलते व्यवसायी अन्याय-पूर्ण ढंग से इस कर के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए थे।⁸⁸ फलतः उन्होंने इस कर के अधिकार क्षेत्र के व्यवसायी वर्गों तथा वेतनभोगी वर्गों तक विस्तार के लिए दबाव डाला।⁸⁹ पूना सार्वजनिक सभा के तत्वावधान में पूना के निवासियों के 16 मई 1880 को पूना में हुई जनसभा में स्वीकृत जापन में राष्ट्रवादियों की लाइसेंस कर के विरुद्ध समीक्षा को संक्षेप में बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राथियों ने जापन में इस तथ्य पर दृढ़तापूर्वक प्रकाश डाला कि यह कर अतिरिक्त कराधान का भार वहन करने में सर्वथा समर्थ उच्च वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य संपन्न वर्गों तक छूट देकर तथा आजी-विका और कम भुगतान के साधनों में सर्वथा विहीन अकालग्रस्त निर्धन वर्गों पर कराधान का बोझा डाला कि 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लंघन करता था।'⁹⁰

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपने युग के अग्रणी दो समाचारपत्र 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'हिंदू' ने परोक्ष कराधान के सिद्धांत का अत्यंत स्पष्ट रूप से समर्थन किया तथा इस लाइसेंस कर को न केवल समाप्त करने के लिए बल्कि इसे आय कर का परिवर्तित रूप देने के लिए सरकार पर दबाव डाला।⁹¹

1882 में मीमा शुल्क को हटा देने के उपरांत विनिमय की दर के धटने और सैनिक व्यय के बढ़ने के कारण भारत सरकार को शीघ्र ही आय के नए साधनों की खोज करनी पड़ी। साधनों की इस खोज में स्वभावतः दृष्टि लाइसेंस कर की ओर गई जो उस समय आधा करोड़ रुपये की तुच्छ राशि जुटाता था। 1886 में सरकार ने आय कर लगाया जहां तक आय की दृष्टि से निम्नतम वर्गों का संबंध था, यह कर वस्तुतः वर्तमान लाइसेंस कर का ही परिवर्धित, विस्तृत और समीकृत रूप था। नया कर व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गों पर भी लागू किया गया। 2,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि से कम आय पर इस कर की दर 4 पाई प्रति रुपया और 2,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि से ऊपर की आय पर 5 पाई प्रति रुपया निर्धारित की गई। 500 रुपये अथवा उससे कम राशि प्रतिवर्ष की आय को आय कर से मुक्त रखा गया। सैनिक अधिकारियों के मामले में छूट की सीमा 6000 रुपये प्रति वर्ष रखी गई। अन्यान्य साधनों, घरती (जिसमें चाय बागान भी सम्मिलित थे) वेतन, पेंशन, इंग्लैंड में भुगतान किए जाने वाले भ्रवकाश भत्ते, इंग्लैंड में व्यवस्थापित जहाजरानी कंपनियां, इंग्लैंड में चुकाई गई प्रतिभूतियों के ब्याजों और प्रतिभूत राशि की सीमा तक रेलों को होने वाले लाभ से प्राप्त होने वाली कुछ अन्य किस्म की आय को भी आय कर के सीमा क्षेत्र से बाहर गया था। इस कर के चालू होने के प्रथम वर्ष अर्थात् 1886-7 में लगभग 3,51,000 लोगों ने आय कर चुकाया और इससे लगभग 1.37 करोड़ रुपयों की राशि वसूल हुई। इस कुल आय की लगभग तीस प्रतिशत राशि वेतनों तथा

पेंशनो में वसूल की गई। 1902-03 में करदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 5,31,000 हो गई और लगभग 21 करोड़ रुपयों की राशि इकट्ठी हुई।⁹²

आय कर के प्रति राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण में सामान्यतया मतभेद ही था। यदि समय की पर्याप्त लची अवधि के सदर्थ में देखा जाए तो यह मतभेद और भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाता है। वस्तुतः कुछ भारतीय नेताओं ने विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न यहां तक कि परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया।

1880 में आय कर लगाने के प्रस्ताव का और 1886 में वास्तविक रूप में इस कर के आरोपण का राष्ट्रवादी पत्रों और नेताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध किया।⁹³ यह विरोध स्वयं कर की प्रकृति के विरुद्ध उसे यूरोपीयों और समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों का डर है। इतना नहीं था क्योंकि अतिरिक्त करों के किसी भी प्रस्ताव पर राष्ट्रवादियों में विश्वास का अभाव था और यह उस समय राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक प्रकार से स्थाई अभिशाप था, राष्ट्रवादियों का विरोध उस आवश्यकता की अस्वीकृति के प्रति था जिसके अंतर्गत यह कर लगाया गया था। उदाहरण के रूप में भारतीय समाचारपत्रों द्वारा अपनाई गई स्थिति की समीक्षा करते हुए 'बायस आफ इंडिया' के मपादक ने राष्ट्रवादियों के मंतव्य को इसी रूप में ग्रहण किया।⁹⁴ इसके अतिरिक्त 1882 में पढ़ने तक तो बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादियों को यह आशंका थी कि आय कर लगाने में बजट में बचत हो सकती है और इन बचतों को सरकार आयात कर हटाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।⁹⁵ 1882 के उपरांत जब सचमुच आयात कर हटा दिया गया तो भारतीय नेताओं ने इस आधार पर आय कर का विरोध किया कि राजस्व वसूली का अपेक्षाकृत अच्छा साधन आयात करों को पुनः लगाना होगा।⁹⁶ थोड़े में भारतीयों ने इस कर से प्राप्त राजस्व को सरकार द्वारा तेजी में बढ़ते सैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्रयोग करने का संदेह भी किया। ये व्यय भारतीयों के लिए क्लेश और कष्ट का कारण बने हुए थे।⁹⁷ अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय कर विरोधियों के शीर्षस्थ नेताओं ने इस कर के एक पक्ष, व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गों को इसके सीमा क्षेत्र में लाने का समर्थन किया।⁹⁸

इतना मंत्र जानने के बाद यहां यह जान लेना भी आवश्यक है कि जब आय कर के कुछ विरोधियों ने भारत के लिए प्रत्यक्ष कर के सर्वथा अनुपयुक्त होने की घोषणा की⁹⁹ अथवा उनमें से कुछ ने आय कर लगाने के स्थान पर नमक कर के विस्तार और उसमें वृद्धि की वकालत की।¹⁰⁰ तो उस समय उन्होंने यह सर्वथा स्पष्ट कर दिया कि उनका विरोध किसी भी रूप में सामान्य लोकहित की कामना से उतना प्रेरित नहीं था जिसना संकुचित वर्ग तथा निहित स्वाध्यायपूर्ण हितों में किसी भी रूप में देखा जाए, वी० एन० मॉडलिक पर्याप्त स्पष्टवक्ता दिखाई देते हैं, उन्होंने 1886 में आय कर बिल (इन्कम टैक्स बिल, 1886) पर भाषण करते हुए सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उच्च वर्गों को लाइसेंस कर के स्थान पर आय कर के अंतर्गत रख देने से इस ऐक्ट का संतुलन जाता रहा है।¹⁰¹

आय कर के इस विरोध के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जिसकी भारतीय

आय कर के इतिहास लेखकों ने न्यूनाधिक रूप से लगभग उपेक्षा ही की है, यह था कि आय कर लगाने का विरोध करने के बदले राष्ट्रवादी नेताओं में अधिक सशक्त वर्ग ने कर लगने के पूर्व, कर लगने के समय और कर लग चुकने के बाद एक प्रकार से उसका प्रागः सक्रिय और प्रबल तथा किन्हीं किन्हीं मामलों में अनिच्छा तथा अनुत्साहपूर्ण समर्थन ही किया।

‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने 1870 के बाद से आय कर का सक्रिय समर्थन किया।¹⁰² बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने 1880 में आय कर को वेतनभोगी तथा व्यवसायी वर्गों पर लागू करने के जान स्ट्रैची के प्रयास का स्वागत और समर्थन किया।¹⁰³ भारत में रहने वाले अंगरेजों के विरोध के कारण जब स्ट्रैची के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा तो ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने तीखे व्यंग्य बाण बरसाए। 5 मार्च 1880 के अंक में इस पत्र ने भारतीय आलोचकों के आय कर हटाने के प्रयास को आड़े हाथों लेते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की :

अब वेतनभोगियों और व्यवसायी वर्गों पर लगा कर हटा लिया गया है। एक निपट मूर्ख को भी यह समझने में देर नहीं लगेगी कि सर स्ट्रैची के आय कर को लगाने के क्षेत्र में निम्न २५१ घोषणा के विरुद्ध की गई चिल्लाहट कितनी निरर्थक और निराधार थी। प्रत्येक समाज में कुछ गधे अवश्य होते हैं, यदि वे न हों तो भना अपनी पीठ पर धोबी के कपड़ों का बोझ कौन उठाएगा ? परंतु इन गधों को धोबी के कपड़ों का भार उठाने पर ही लगाए रखना चाहिए। उन्हें राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व अथवा मार्गदर्शक पत्रों का संपादकत्व नहीं सभालने देना चाहिए।

परवर्ती वर्गों में ‘हिंदू’, ‘इंदु प्रकाश’ और ‘इंडियन स्पेक्टेटर’ जैसे अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों की बहुसंख्या ने चालू लाइसेंस वरके स्थान पर आय कर लगाने का अनुरोध किया।¹⁰⁴ अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में अपने प्रथम अधिवेशन में अन्यान्य वस्तुओं के साथ फिलहाल इस कर से मुक्त सरकारी और गैरसरकारी वर्गों के समुदाय पर इस कर के विस्तार के अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया।¹⁰⁵ 1886 में जब अंततः आय कर लगाया गया तब ‘अमृत बाजार पत्रिका’, ‘हिंदू’, ‘मराठा’ तथा अन्य अनेक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने उसका समर्थन किया।¹⁰⁶

1886 के उपरांत राष्ट्रवादी क्षेत्रों में आय कर को और अधिक व्यापक तथा और अधिक विस्तृत लोकप्रियता मिलने लगी, विशेष रूप से यह इस तथ्य से सिद्ध है कि यह माना जाने लगा कि इसके हटाने का परिणाम अन्य करों को लगाना होगा। यह तथ्य इस दृष्टिकोण को भी सिद्ध करता है कि कुछ भारतीय नेताओं का पूर्ववर्ती विरोध वस्तुतः अपने आप में आय कर का विरोध न होकर किसी प्रकार के नए कराधान का ही विरोध था। जब एक बार यह प्रमाणित हो गया कि नए करों का लगाना अपरिहार्य है तो राष्ट्रवादी नेताओं ने एक स्वर से आय कर हटाने की मांग का विरोध किया तथा किसी भी प्रकार के अन्य कर लगाने की अपेक्षा इस कराधान का ही पक्ष लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के तृतीय अधिवेशन में यह तथ्य उस समय नाटकीय ढंग से सामने आया जब एक प्रतिनिधि श्री० आर० चक्रवर्ती आयरनर ने छठे प्रस्ताव में संशोधन के रूप में

आय कर हटाने की माग पेश की, नत्काल 'नहीं' 'नहीं' 'संशोधन वापस लो' की ऊची ऊची आवाजें आईं, यह कहा गया कि हम अपने आपको कराधान से मुक्त नहीं करना चाहते हम इस कर के 'पक्षधर' हैं। 'बैठ जाइए' 'बकवास बंद कीजिए'। चक्रवर्ती आर्यगर को अपना संशोधन वापस लेने पर विवश होना पड़ा।¹⁰⁷ कांग्रेस के अगले अधिवेशन (1888) में मदनमोहन मालवीय ने घोषणा की कि कांग्रेस धनिकों अथवा उन लोगों पर जो कर चुकाने में समर्थ हैं, आय कर लगाने की वाछनीयता में सहमति प्रकट करती है और उसकी पुष्टि करती है।¹⁰⁸

1902 में सी० वाई० चितामणि ने तेहरवा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कर हटाने के आदोलन की बड़ी जोरदार निंदा की¹⁰⁹, साथ ही उस वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष एस० एन० बैनर्जी की भी कर हटाने की माग के प्रति सहानुभूति नहीं थी।¹¹⁰ भारत के अन्य सार्वजनिक नेताओं में से दादाभाई नौरोजी ने वायसराय की कॉमिल के सदस्य एस० एम० मलाबारी को 26 अप्रैल 1889 को लिखे पत्र द्वारा आय कर के विरुद्ध नमक कर के पक्ष में मत देने के लिए उनकी निंदा की।¹¹¹ आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया' में आय कर के न्यायसंगत और उचित होने के कारण उसकी प्रशंसा की।¹¹² 1888 में जी० वी० जोशी ने नमक कर में वृद्धि के बदले आय कर में वृद्धि और विस्तार के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किया।¹¹³ 'इंडियन एसोसिएशन' ने भी 1894 में इसी प्रकार की माग प्रस्तुत की।¹¹⁴

समाचारपत्रों में 'अमृत बानार पत्रिका' ने तो आय कर के पक्ष में जिहाद जारी रखा।¹¹⁵ इस पत्र ने 18 अप्रैल 1893 के अपने अंक में इस कर के परिमाण में वृद्धि की माग की। 28 दिसंबर 1887 के अपने अंक में हिंदू ने माग की कि आय कर को भारतीय कराधान का स्थाई स्रोत बना देना चाहिए।¹¹⁶ 15 दिसंबर 1890 के अपने अंक में सुधारक ने घोषणा की कि कर को हटाने की माग अमदिग्ध रूप से स्वार्थपूर्ण ही होगी।¹¹⁷ 'संजीवनी' ने 10 मार्च 1894 के अंक में आय कर में वृद्धि की वकालत की। उसका आधार यह था कि वर्तमान दर से वास्तव में धनिकों को छूट मिलती थी।¹¹⁸ 'बंगाली' ने भी 4 नवंबर 1902 के अंक में कर हटाने पर आपत्ति की। 29 मई 1904 के अंक में 'मराठा' ने बजट में बचत होने पर भी इस कर के बने रहने की इच्छा प्रकट की और मुझाव दिया कि इस कर से होने वाली आय का न्याय बना देना चाहिए और उस आय को शिक्षा विशेषतः औद्योगिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। बहुत सारे अन्य समाचारपत्र आय कर हटाने के विरुद्ध वर्षों तक यही स्थिति अपनाए रहे और कई मामलों में तो इसके क्षेत्र विस्तार की निरंतर वकालत करते रहे।¹¹⁹ विशेषतः 1888 में नमक कर में वृद्धि के समय बहुत अधिक संख्या में समाचारपत्रों ने इसके बदले आय कर में वृद्धि की वकालत की।¹²⁰

1886 के उपरांत आय कर के पक्ष में उत्पन्न राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचंड बहुमत के विरुद्ध केवल मुट्ठी भर भारतीय समाचारपत्रों और नेताओं ने ही उस वर्ष के बाद इस कर को हटाने की माग की। जहां तक हम निश्चित रूप से जान पाए हैं। 10 नवंबर 1890 का 'सोम प्रकाश' (बंगाल में निकलने वाला) और 11 फरवरी 1891

का 'सहचर', 'नार्थ वेस्ट प्राविसेज' तथा अवध में प्रकाशित होने वाला 'भारत जीवन' ही इस कर को हटाने की मांग कर रहे थे।¹²¹ राजनीतिक नेताओं में जी० आर० चितनवीस, महााराजा दरभंगा और आशुतोष मुखर्जी ही, जिनकी उच्च स्तर के राष्ट्रीय नेताओं में गिनती नहीं होती थी। कर का विरोध करने वालों में थे।¹²²

जहाँ तक आय कर लगाने के ढंग का संबंध है, कुछ भारतीय नेताओं ने भी मही जमींदारों और भूमिपतियों को इस कर में मुक्त करने की आलोचना की। 17 जनवरी 1880 को 'बंगाली' ने इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जमींदारों द्वारा पहले से ही मंडक शुल्क और लोककर्म शुल्क चुकाए जाने के कारण उन्हें इस कर से मुक्ति देने के औचित्य की धारणा का खंडन किया। उस पत्र ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि ये कर वस्तुतः परोक्ष रूप में किसानों द्वारा ही चुकाए जाते हैं। 7, 9, और 12 जनवरी 1886 के अंकों में 'हिंदू' ने, 25 फरवरी 1886 के अंक में 'इंडियन नेशन' ने और 18 जनवरी 1886 के अंक में 'गुजरात मित्र' ने जमींदारों को 1885 के कर के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की आलोचना की।¹²³ 1888 में जी० बी० जोशी ने जमींदारों, ताल्लुकेदारों और बागान मानियों तक आय कर के क्षेत्र विस्तार के पक्ष में तर्कों का विस्तृत विवेचन किया।¹²⁴ 9 जनवरी 1890 के अंक में 'हिंदू' ने और 18 फरवरी 1894 के अंक में 'कैसेरे हिंदू'¹²⁵ ने भी इसी प्रकार की मांग करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।

थोड़े से भारतीय नेताओं ने भारतीय आय कर में नियमित वृद्धि के नितांत अभाव की भी चर्चा की। इस कर की दृष्टि में 2000 रुपये में ऊपर की सभी प्रकार की वार्षिक आयों को इकट्ठे वर्गीकृत करने पर आपत्ति करते हुए हिंदू ने दृढ़तापूर्वक लिखा कि क्रमिक कराधान का सिद्धांत विश्व के अन्य किसी भी देश के समान ही भारत में भी सही तौर पर लागू है। अपना मत प्रकट करते हुए उसने लिखा कि उच्च वेतनभोगियों के लिए 2½ प्रतिशत कर की दर बहुत ही नीची दर है।¹²⁶ इंडियन एसोसिएशन ने 8 मार्च 1894 के जापान में सुझाव दिया कि जीवन की उपभोग सामग्री पर परोक्ष ढंग से कराधान के बदले आय कर की दर क्रमिक रूप से बढ़ा देनी चाहिए। अपेक्षाकृत उच्च वेतनों पर अपेक्षाकृत ऊँचा करारोपण करना चाहिए।¹²⁷ बहुत सारे और भारतीय नेताओं ने सुव्यवस्थित रूप से क्रमिक आय कर के लगाने की मांग की।¹²⁸

इस समय राष्ट्रवादी नेताओं के विशाल बहुमत द्वारा आय कर के समर्थन के अथवा कम से कम उसके अधिकार क्षेत्र के वेतनभोगी और व्यवसायी वर्गों तक विस्तार के आधारों का संक्षिप्त विवेचन कदाचित अनुचित न होगा। इन आधारों में प्रथम और कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह सम्भव थी कि आय कर ही एक ऐसा अकेला महत्वपूर्ण कर है जिसके द्वारा भारत में रहने वाले यूरोपीय, भले ही वे सरकारी अधिकारी हों, निजी व्यवसाय संस्थानों के कर्मचारी हों, व्यवसाय वर्ग के लोग हों अथवा व्यापारी हों, भारत सरकार के शासन-संचालन के व्यय में अपने भाग का योगदान कर सकते हैं।¹²⁹ 'अमृत बाजार पत्रिका' ने इसी भावना की अभिव्यक्ति निम्नलिखित शब्दों में की : आय कर भारत में रहने वाले शत प्रतिशत यूरोपीयों की जेबों को प्रभावित करता

है जबकि इससे हजार भारतीयों में केवल एक व्यक्ति की जेब ही प्रभावित होती है।¹³⁰ कुछ समाचारपत्रों ने तो यह दृढ़ मत अभिव्यक्त किया कि आय कर का विरोध करना यूरोपियों के हाथों खेलना है।¹³¹ राष्ट्रवादियों द्वारा आय कर को समर्थन देने का दूसरा कारण था, कराधान में सामाजिक न्याय और समता की भावना। इस अत्यंत प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति किन्हीं किन्हीं मामलों में तो सर्वथा स्पष्ट रूप में की गई। उदाहरणार्थ, 17 जनवरी 1880 के अंक में 'बंगाली' ने बल देकर कहा कि यदि भारत सरकार अपने खर्चों में कटौती न करके उन खर्चों की पूर्ति के लिए नए कर लगाने पर ही तुली हुई है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा यह होगा कि यह कर निर्धनो पर थोपने की अपेक्षा उन लोगों पर लगाए जाए जो उनका भार सहन कर सकते हैं।¹³² 5 मार्च 1880 के अंक में तो 'अमृत बाजार पत्रिका' ने और भी अधिक दृढ़ता के साथ लिखा : 'इस समय हमारे सामने विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि प्रत्यक्ष कर भारत के अनुकूल है अथवा नहीं ? इस समय तो विचारणीय यह है कि हमारे समाज के अपेक्षाकृत संपन्न सदस्यों को इस भार में अपने समुचित भाग का योगदान करना चाहिए अथवा नहीं ? यदि उन्हें अपना योगदान करना है तो प्रत्यक्ष कराधान के अतिरिक्त उन तक पहुंचने का और कोई मार्ग ही नहीं।' अगले वर्ष 'पत्रिका' ने आय कर लगाने के औचित्य की एक बार फिर वकालत की तथा दस कर के द्वारा लोगों को अत्यधिक असुविधा और कष्ट मिलने और इस कारण इसके लाभों के निर्मूल हो जाने के तर्कों के औचित्य को मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने 29 दिसंबर '1881' के अंक में लिखा : 'सर्वप्रथम, मत्स्य तो यह है कि जब बीस करोड़ लोगों को नमक कर, भूमि लगान और मुद्रांक शुल्क आदि के भुगतान में होने वाले कष्ट की निश्चिन्ता रूप में ही कोई चिन्ता नहीं की जाती तो फिर इस देश में समृद्ध वर्ग के दो लाख लोगों को होने वाली साधारण सी असुविधा की चिन्ता ही कौन करता है ?'¹³³ 19 दिसंबर 1884 के अंक में 'हिंदू' ने भी निर्देश किया : 'निर्धन लोगों को धनिकों पर कर लगाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं। निर्धनों को तो उल्टे अपने पर नमक कर, उत्पादन शुल्क और मुद्रांक शुल्क आदि लगाने के विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए।' ¹³⁴ 1888 में जी० वी० जोशी ने भी इसी दृष्टिकोण को बड़ी स्पष्टता और प्रबलता के साथ अभिव्यक्ति दी। 1886 में आय कर लगाने का अनुमोदन करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि 1886 के आय कर अधिनियम के अंतर्गत उच्च तथा उच्च मध्यम वर्गों पर डाला गया भार निर्धन वर्गों पर डाले गए भार के मुकाबले किसी भी परिमाण में, स्तर में पर्याप्त, उचित अथवा अनुरूप नहीं है। इसके विपरीत सत्य तो यह है कि कराधान के नए उपाय से लोक कराधान में समानता तथा समुचित संतुलन मिट्ट नहीं होता। '... 1886 के कराधान के उपरांत आज भी स्थिति यह बनी हुई है कि संपन्न वर्ग तो कर थोड़े परिमाण में चुकाता है जबकि जनता को अपने उचित भाग की अपेक्षा अधिक करों का भुगतान करना पड़ता है।'¹³⁵

हां, आय कर के समर्थकों ने इसके हर पहलू का अनुमोदन नहीं किया। सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी जिस ढंग से कर लगाया जा रहा था, उसकी आलोचना की। उनके अनुसार तथा सम्मानपूर्वक समझौते का निर्णय करने वाले कर

समीक्षकों के अनुसार 1886 में यथा आरोपित आय कर का निकृष्टतम पहलू छूट की निम्नतम सीमा थी। वे लोग यह सीमा कम से कम 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति वर्ष करने के पक्ष में थे। व्यापक रूप से देखें तो राष्ट्रवादियों की स्थिति यह थी कि आय कर की छूट की सीमा निम्न होने के कारण यह कर कम आयवाले उन लोगों, निम्न वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों, छोटे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दस्तकारों को बुरी तरह प्रभावित करता था क्योंकि विशेषतः संयुक्त परिवार प्रथा के संदर्भ में इन लोगों के पास करों के भुगतान की सामर्थ्य ही नहीं थी। अल्प आय वालों के प्रति कर समाहरण करने वाले प्रशासन का व्यवहार भी अमंतोषजनक था। यह विभाग उन्हें अनुचित रूप से परेशान तथा तंग करता था। इन स्वल्प आयवालों में बहुत सारे लोग कर समाहरण कार्य पर नियुक्त छोटे-मोटे सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार और क्रूरता सहन करने में सर्वथा असमर्थ थे।

कुछ राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने आय कर की लागू करने से पहले ही उसे निर्दोष बनाने के लिए उसकी छूट की ऊंची सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया।¹³⁶ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वेतनभोगी और व्यवसायी वर्गों को लाइसेंस शुल्क के सीमा क्षेत्र में लाने की सिफारिश करते हुए सुझाव दिया कि जहां तक सब वर्गों का संबंध है, उन पर न्यूनतम कर योग्य राशि की सीमा पर्याप्त मात्रा में ऊंची करनी चाहिए।¹³⁷ 1886 में आय कर लगाने के समय बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इसकी छूट की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला।¹³⁸ 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तृतीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करते हुए कर योग्य आय की सीमा न्यूनतम एक हजार रुपये निर्धारित करने की मांग की।¹³⁹ अगले वर्ष मदनमोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव को सम्माननीय निर्धन लोगों का प्रस्ताव बताया।¹⁴⁰ तथा यह कांग्रेस के अधिवेशनों में हर वर्ष पाम होता रहा।¹⁴¹ राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने वर्षों तक इस विषय पर आंदोलन का नियमित वातावरण बनाए रखा।¹⁴² भारतीय लोकनेताओं ने कांग्रेस के मंच से, विधानसभा में तथा समाचारपत्रों में इस विषय को बार बार उठाया।¹⁴³

आय कर की कार्यविधि से संबंधित राष्ट्रवादी आलोचना के औचित्य तथा व्यापकता को अधिकारियों ने भली भांति अभिस्वीकार किया और उसके फलस्वरूप 1903 में भारत सरकार ने कर योग्य आय की सीमा 1000 रुपये प्रति वर्ष कर दी।¹⁴⁴ इस सरकारी पग का राष्ट्रवादी नेताओं ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया।¹⁴⁵ बिरल अपवादों को छोड़कर आय कर के संबंध में किसी अन्य प्रकार की रियायत की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई।¹⁴⁶

राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आशय

आय कर के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध में राष्ट्रवादी नेताओं की बिपुल बहुसंख्या संकुचित वर्गगत हितों से ऊपर उठने में समर्थ हो सकी। इन नेताओं में अधिकांश स्वयं वकील और पत्रकार थे।

इनके वेतनभोगी वर्ग के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे फिर भी उनमें से बहुत बड़ी संख्या में नेताओं ने इस कर का समर्थन ही नहीं किया प्रत्युत आय कर लगाने की वकालत तक की। यहां तक कि इस कर का अपने उस रूप में विरोध करने वाले नेताओं की बहुत बड़ी संख्या ने इसका समर्थन ही नहीं किया प्रत्युत इसकी अधिकार सीमा का वेतनभोगी वर्गों तथा व्यवसायी वर्गों तक विस्तार करने की मांग की। इस प्रकार शिक्षित मध्यवर्तीय वर्गों को किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान की अधिकार सीमा के अंतर्गत लाने की वाछनीयता के बारे में राष्ट्रवादी नेताओं में प्रायः यथासंभव व्यापक एकमत था। जब एक बार आय कर अस्तित्व में आ गया तो परवर्ती वर्षों में इस हटाने के लिए इसके विरुद्ध कोई एक भी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी स्वर सुनने को नहीं मिला।

इस संदर्भ में यह अत्यंत सावधानी के साथ उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश शीर्षस्थ नेता तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचारपत्रों, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', 'मराठा', 'बंगाली', 'हितवादी', 'संजीवनी', 'इंदु प्रकाश', 'इंडियन स्पेक्टेटर' तथा 'स्वदेशमित्र' के स्वामी तथा संपादक निश्चित रूप से आय कर के निर्धारण क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और अन्यथा प्रत्यक्ष करों के बंधन से अथवा यहां तक कि अधिकांशतः परोक्ष करों के बंधन से सर्वथा मुक्त थे।¹¹⁷ इतने पर भी वे अपने आप को अपने पर कर लगाने के लिए समर्पित करने के लिए और इस रूप में आत्मक्षति के कष्ट को भुगतने के लिए सहमत थे ताकि भारत सरकार के विदेशी कर्मचारियों पर कराधान किया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का यह दृष्टिकोण एक ओर राष्ट्रीय भावनाओं के तथा देश पर विदेशी शासन के विरुद्ध शत्रुता की भावनाओं के उभरते तूफान का द्योतक है और दूसरी ओर उस समय के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सामान्य राष्ट्रीय हितों के समक्ष अपने निजी स्वार्थों को गौण बनाने की प्रवृत्ति का सूचक है।¹¹⁸

राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता के केवल उसी वर्ग के हितों की इस मामले में देखभाल की जिस वर्ग की वार्षिक आय एक हजार रुपये प्रति वर्ष से नीचे थी अथवा दूसरे शब्दों में निर्धन दुकानदारों तथा निम्नवेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों के हितों की वकालत की। इस संबंध में यह अवश्य उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं द्वारा आय कर की छूट सीमा को बढ़ाने की वकालत केवल सामाजिक न्याय और समता के आधारों पर ही उपयुक्त नहीं थी प्रत्युत छोटे छोटे दुकानदारों और निम्न स्तरीय सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पक्ष में लाने की यह एक सभी दृष्टियों से सर्वथा उपयुक्त राजनीतिक युक्ति भी थी। यहां तक कि इस मामले में नेताओं ने आय कर की छूट सीमा बढ़ाने की अपेक्षा नमक और भूमि लगान घटाने के लिए अपेक्षाकृत कठोर संघर्ष किया। सत्य यह है भारतीय नेताओं ने करों में राहत देने के मामले में मंदैव सतर्कता बरतते हुए और झुलकर किसी भी योजना की मिफारिश करते हुए ऊपर दी गई प्राथमिकताओं का ध्यान रखा।¹¹⁹ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वास्तव में भारतीय नेताओं ने आय कर के मामले में इस कर को हटाने के लिए निरंतर वकालत तथा आंदोलन कर रहे बड़े तड़े व्यापारियों और जमींदारों के हितों का यांत्रिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया।¹²⁰

नमक कर

1880 से 1905 की अवधि में नमक कर भारत सरकार की आय का एक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। नमक पर कराधान की पद्धति एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न भिन्न रूप लिए हुए थी। बंबई में इसे उत्पादन शुल्क का रूप प्राप्त था, बंगाल में प्रधान रूप से आयातित नमक पर सीमा शुल्क लगता था¹⁵¹ और मद्रास, उत्तरी भारत तथा पंजाब में सरकार द्वारा एकाधिकार के रूप में स्वतः उत्पादित नमक पर कर सरकार द्वारा वस्तुओं के निर्धारित मूल्य में सम्मिलित रहता था।

1878-79 तक नमक कर की दर भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में व्यापक रूप में भिन्न थी।¹⁵² कलकत्ता अंतर्देशीय सीमा शुल्क रेखा समाप्त करने के उपरांत जब नमक कर की दर में लगभग एकरूपता लाई गई तो उत्तरी भारत में उसे समानांतर रूप देने के लिए उसकी दर घटाकर 3 रुपये प्रति मन के स्थान पर 2 रु० 8 आने प्रति मन कर दी गई, बंगाल में भी यह दर घटाकर 3 रु० 4 आने के बदले 2 रु० 14 आने प्रति मन कर दी गई। मद्रास और बंबई में यह दर बढ़ाकर 1 रु० 13 आने के स्थान पर 2 रु० 8 आने कर दी गई। यह सुधारकारी एकीकरण सरकार के लिए लाभ-प्रद सिद्ध हुआ। 1875-77 से 1879-81 में नमक कर के राजस्व की राशि लगभग दस लाख पौंड बढ़ गई।¹⁵³ परंतु लोगों ने इस वृद्धि के पूरे परिमाण को अनुभव नहीं किया क्योंकि उस समय परिवहन सुविधाओं के समकालीन विस्तार के कारण बाजार में नमक के मूल्यों में उल्लेखनीय रूप में गिरावट आ गई थी।

1858 में पहले भी प्रमुख भारतीयों ने नमक कर की आलोचना की थी।¹⁵⁴ 1882 तक भारतीय नेता नमक कर में कटौती और उसे हटाने तक की मांग करते रहे। नमक कर के समानीकरण की प्रक्रिया 1859 में प्रारंभ हुई और उसके फलस्वरूप बंबई प्रांत में कर की दर बड़वार काफी ऊंची हो गई। अतः स्वाभाविक रूप से ही उस प्रदेश में कर के विरुद्ध तथा कर में वृद्धि के विरुद्ध आलोचना का स्वर अत्यंत मुखर था।¹⁵⁵ उदाहरणार्थ, 1880 में दादाभाई नौरोजी ने नमक कर को ब्रिटिश नाम पर एक कलक बताया।¹⁵⁶

इस समय हम इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय नेताओं के एक अन्य वर्ग ने भले ही वह अल्पमूल्यक था, नमक कर का समर्थन किया। यह बहुत स्वाभाविक था कि यह वर्ग प्रधान रूप से बंगाल में ही था जहां नमक कर में परिवर्तन नीचे की ओर जा रहे थे और जहां जमींदार सदैव किसानों के हितों के मूल्य पर अपने हितों की रक्षा के प्रति चिंतित थे। बंगाल में नमक कर के पक्षधर दो प्रारंभिक प्रतिनिधि थे, राजा दिगंबर मित्र और क्रिस्तोदास पाल।¹⁵⁷ इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 'अमृत बाजार पत्रिका' ने भी सड़क शुल्क जैसे अन्यायपूर्ण करों में वृद्धि के बदले नमक कर में वृद्धि की वकालत की।¹⁵⁸ इस अप्रत्याशित स्थिति अपनाने के लिए पत्र के संपादकों द्वारा निर्दिष्ट कारण यह था कि बंगाल में नमक कर प्रधान रूप से नमक पर आयात शुल्क था। यह नमक लिबरपूल और चेशायर से लाया जाता था अतः इस कर में वृद्धि का सारा भार विदेशियों पर ही पड़ने की संभावना थी।¹⁵⁹

1882 में भारत सरकार ने नमक कर में कटौती की। बर्मा अथवा पंजाब के सिंधु

पार के जिलों को छोड़कर सारे देश में यह कर दो रुपये प्रति मर्न कर दिया गया। इस कदम के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। मराठा और बंबई के बहुत सारे अन्य पत्रों ने और बंगाल के कुछ पत्रों ने इसका स्वागत किया और सरकार से इसे और अधिक घटाने यहां तक कि इसे समाप्त करने का ही अनुरोध किया।¹⁶⁰ दूसरी ओर 'अमृत बाजार पत्रिका' और बंगाल तथा उत्तरी भारत के कितने ही दूसरे पत्रों ने अनुभव किया कि इस कदम का स्वागत नहीं किया जा सकता क्योंकि वस्तुतः लोगों ने नमक कर को कभी दुःखप्रद नहीं माना। इसके बदले तो लाइसेंस कर के भुगतान में राहत देनी चाहिए थी।¹⁶¹

1882 और 1888 की मध्यावधि में नमक कर के विरुद्ध अनेक राष्ट्रीय स्वर मुखरित हुए। उदाहरणार्थ नमक कर विरोधी आंदोलन के संचालन में अग्रदूत होने का श्रेय प्राप्त करने वाले जी० बी० जोशी ने इन्हीं वर्षों की अवधि में नमक कर के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी किया था। 1886 में प्रकाशित अपने एक लेख 'वेज ऐंड मीज आफ मीटिंग दि ऐंडीशिनल आर्मी एक्सपेंडीचर' में उन्होंने नमक कर का और जनजीवन तथा लोकभ्रम पर उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने नमक कर में किसी भी प्रकार की वृद्धि का अत्यंत प्रखरता के साथ विरोध किया तथा किन्हीं क्षेत्रों में इस कर को सुरक्षित राजस्व मानने की नीति को घातक प्रवृत्ति बताते हुए उसकी तीव्र निंदा की। उन्होंने नमक कर को देश में स्थाई कराधान का एक अंग बनाए रखने की भर्त्सना की।¹⁶² 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन में ही एस० ए० स्वामिनाथन बम्बर तथा बी० एस० पंतुलु ने नमक कर में किसी प्रकार की वृद्धि के प्रयत्न की निंदा की तथा कांग्रेस और जनता में इस प्रकार की किसी भी अवांछनीय घटना के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया।¹⁶³ इन वर्षों की अवधि में कुछ एक अग्रगण्य समाचारपत्रों ने भी नमक कर घटाने अथवा उसे समाप्त करने की वकालत की।¹⁶⁴ दूसरी ओर 1886 में कुछ समाचारपत्रों ने आय कर लगाने के बदले नमक कर में वृद्धि की वकालत की।¹⁶⁵

1888 तक ऊपरी बर्मा पर विजय और उसके संयोजन के उत्तर-पश्चिमी सीमा में सैनिक कार्यवाही के तथा विनिमय में होने वाली निरंतर गिरावट के फलस्वरूप भारत सरकार की आर्थिक स्थिति एक बार फिर गड़बड़ हो गई थी और एक बार फिर नए करों का लगाना अनिवार्य हो गया। इस सबके परिणामस्वरूप तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स वेस्टवैड को 19 जनवरी 1888 के अपने एक कार्यकारी आदेश द्वारा नमक पर 2 रुपये प्रति मन कर के स्थान पर उसे बढ़ाकर ठाई रुपये प्रति मन कर देना पड़ा।¹⁶⁶ 1902 में नमक कर से कुल आय 9.1 करोड़ रुपये हुई जबकि 1888 में इस कर से होने वाली आय की राशि 7.6 करोड़ रुपये थी।¹⁶⁷

नमक कर में वृद्धि ने भारत में असंतोष, रोष और विरोध की सशक्त, तीव्र लहर उत्पन्न कर दी। 'मराठा', 'हिंदू', 'बंगाली' और यहां तक कि 'अमृत बाजार पत्रिका' के साथ साथ देश के बहुत सारे अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने बड़ी ही तीखी और निंदात्मक भाषा में इस पग की कठोर भर्त्सना की।¹⁶⁸ कुछ समाचारपत्रों के विरोध

का ढंग तो विद्रोह की सीमा को छूता सा लगने लगा। उदाहरणार्थ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी ने अपने 31 जनवरी 1888 के अंक में टिप्पणी करते हुए लिखा :

विश्व के किसी भूभाग में भारत के समान दुर्भाग्यग्रस्त लोग नहीं रहते। यदि विश्व के किसी भी देश के किसी व्यक्ति को उसके पापों के लिए दंड देना हो तो उसे भारत में भेज दीजिए। हमें यह सब भारत सरकार के नमक कर विषयक नवीन आदेश के संदर्भ में ही सोचने को विवश होना पड़ रहा है। वस्तुतः इस प्रकार का अमानवीय पग केवल वही उठा सकता है जिसे भारतीय जनता की सर्वथा अभावग्रस्त और दीन-हीन दशा की चिंता ही न हो।... इस समय तो उन लोगों की ही बन आ रही है जो यह मानते हैं कि तलवार के बल पर अंगरेजों ने भारत को जीता है और तलवार के बल पर उन्हें इसे अपने अधीन बनाए रखना चाहिए।... बिल्ली स्वभावतः विनम्र और भीरु होती है परंतु जब उसे आवश्यकता से अधिक दबाया जाता है तो बड़ी पलटकर इस प्रकार से भपटती है कि उसका प्रहार असह्य हो जाता है। इस समय यही संभव स्थिति हिंदू की है। यहां यह स्मरणीय है कि इस समय अंगरेज लोगो पर थोड़ा सा भी कर भार डालने में संकोच करने वाली सरकार के लिए भारत पर अपना स्थाई प्रभुत्व खोने की आशंका हो सकती है।¹⁶⁹

‘बोध समाचार ने अपने 25 जनवरी 1888 के अंक में चेतावनी देते हुए लिखा कि वर्तमान बढोतरी गहरी खाई के घसते कगार के अनिर्गुण और कुछ नहीं और इसे लागू करना जनता के रिसते घावों को हरा करना है, इसमें जनसाधारण की शांति और संतोष भंग होने की निश्चित आशंका निहित है।¹⁷⁰ महागण्ट्र मित्र ने अपने 8 मार्च 1888 के अंक में अन्यान्य वस्तुओं के साथ नमक कर में वृद्धि के विरुद्ध लोगों को भडकाते हुए एक हिंदू और एक अंगरेज के बीच एक वार्तालाप प्रकाशित किया, जिसमें हिंदू लार्ड डफरिन को कमाई की उपमा देता है। अंगरेज जब हिंदू के इस व्यवहार पर आपत्ति प्रकट करता है तो वह उत्तर में स्पष्ट शब्दों में कहता है - ‘क्या नमक कर में वृद्धि जीवन रक्त चूसना नहीं?’¹⁷¹ इसी प्रकार बंगाल के पत्र ‘प्रजावधु’ ने अपने 27 जनवरी 1888 के अंक में आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखा - ‘सचमुच भारतीयों के लिए वह घड़ी अभिशाप रूप ही थी, जब लार्ड डफरिन ने भारत भूमि पर पांव रखा।’¹⁷²

नमक कर में बढोतरी ने एक बार फिर जी० बी० जोशी को 1888 में सरकार की नमक कर नीति पर घातक प्रहार करने को उत्तेजित किया।¹⁷³ अतः इस प्रश्न को 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया और कर वृद्धि के पग को अमान्य ठहराते हुए उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित तथा अभिलिखित किया।¹⁷⁴ यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अपनी ही स्थाई समिति की इच्छाओं के विरुद्ध पारित किया। स्थाई समिति इस प्रस्ताव का पहले ही इस आधार पर विरोध कर चुकी थी कि एक बार जब वृद्धि कर ही दी गई है तो उसके तुरंत उपरांत उसे हटाने की मांग करना सर्वथा निरर्थक है।¹⁷⁵ अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि रत्नगिरि जिसे

के दो साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तथा समर्थित प्रस्ताव पर कांग्रेस के किसी भी मुख्य नेता ने कोई भी बक्तव्य नहीं दिया।¹⁷⁶

इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी सर्वसम्मत मत को छिन्न-भिन्न करते हुए थोड़े से स्वर सरकारी पग के समर्थन में भी मुखरित हुए।¹⁷⁷ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पहले से ही विरोधी राज्य के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'ट्रिब्यून' जैसे अधिकांश समाचारपत्रों के नाम इस समय इस प्रश्न पर राष्ट्रीय भावना के मुख्य स्रोत में पुनः सम्मिलित होकर उसे संयुक्त स्वर से वाणी देनेवालों की सूची के अंतर्गत नहीं था।

राष्ट्रीय नेताओं द्वारा परवर्ती वर्षों में नमक कर की तीव्र निंदा और उसमें कटौती की निरंतर मांग जारी रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस संबंध में राष्ट्रीय भावना का सम्यक प्रतिनिधित्व किया और एक के बाद दूसरे वर्ष निरंतर इस कर में तात्कालिक कटौती की मांग के प्रस्ताव पारित करती रही।¹⁷⁸ बहुत सारे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने इसी पथ का अनुसरण किया।¹⁷⁹ जी० वी० जोशी के राजनीतिक शिष्य गोपालकृष्ण गोखले ने अपने राजनीतिक विषयों में नमक कर के प्रश्न को अपनी रचि का विषय बनाया तथा अपने गुरु के कार्य को राजनीतिक मंच तथा विधानसभा के मदन से आगे बढ़ाया।¹⁸⁰ इसी प्रकार अधिकांश राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने इस कर के विरुद्ध वर्षों तक अविच्छिन्न रूप से आंदोलन चलाए रखा।¹⁸¹ इस संबंध में आर० डी० रसडन नामक एक अंगरेज व्यापारी द्वारा 'मराठा' के संपादक को लिखे और 'मराठा' के ही 21 जुलाई 1889 के अंक में प्रकाशित पत्र का विवरण भी एक पर्याप्त रोचक तथ्य प्रस्तुत करता है। यद्यपि स्पष्टतः इसमें व्यक्तिगत मत का ही प्रकाशन था तथापि इसके प्रकाशन का अर्थ निश्चित रूप से इसके संपादक तिलक के मत के थोड़ा बहुत अनुकूल होना था। इसके प्रकाशन से संपादक जेल जाने से बाल बाल बचा।¹⁸² पत्र लेखक रसडन ने भारतीय नेताओं को अनाज कानून विरोधी आंदोलन के समानुरूप नमक कर के विरुद्ध आंदोलन चलाने की सलाह दी। उन्होंने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे सरकार को बताए कि अकाल से बहुत बड़ी संख्या में होने वाली मृत्यु तो नमक कर से होने वाली हत्या ही है। यह सारी कार्यवाही घृणाजनक, लज्जाजनक तथा कलकपूर्ण है। हम इस कर को वापस लेने का अनुरोध करने हैं। यदि तुम इस कर को नहीं हटाओगे तो हम प्रयत्न करेंगे और स्थिति को इस प्रकार से अमह्य और विषम बना दें कि तुम चाहो अथवा न चाहो पर तुम्हें इस कर को शीघ्रता से हटाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी द्वारा लगभग चालीस वर्ष बाद अपनाए गए पथ का निर्देश करते हुए उसने भारतीय नेताओं को सलाह दी कि वे अपने लोगों को समझाएं कि 'वे स्वयं नमक तैयार करें ताकि उन्हें नमक कर देना ही न पड़े'... और आप नेतागण उनकी आवश्यकता के समय उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए कोष की व्यवस्था करके उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहन दे सकते हैं।'

बाद में शताब्दी के बदलते बदलते जब बजटों में बचतें होने लगीं तो भारतीय नेताओं ने इन बचतों का निम्नलिखित रूप में उपयुक्त उपयोग करने और सर्वप्रथम, नमक कर में कटौती करने के लिए संघर्ष किया।¹⁸³ मिलमालिक संघ को संबोधित करते हुए

डी० ई० वाचा ने तो यहां तक कहा कि कपास पर सीमा शुल्क हटाने से भी पहले नमक कर में कटौती करनी चाहिए।¹⁸⁴

अंततः 1903 में 8 आने प्रति मन की दर से नमक कर में कटौती की घोषणा की गई। जैसी कि आशा की जाती थी, भारतीय नेताओं ने इस घोषणा का सहर्ष स्वागत किया। हा, उस समय उन्होंने कर की इस दर को और नीचा करने की मांग पेश कर दी।¹⁸⁵ परबर्नी महीनो और वर्षों में यह मांग दोहराई गई¹⁸⁶ और जब 1905 में सरकार ने आठ आने प्रति मन की दर से और अधिक राहत देने की स्वीकृति दी तो भारतीयों ने अपनी प्रतिक्रिया सरकार को बढ़ाई देने के साथ साथ डम कर में और अधिक कटौती करने की मांग के रूप में प्रकट की।¹⁸⁷

यह उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर भारतीय नेताओं का शक्तिमपन्न तथा प्रभुत्व-प्राप्त वर्ग नमक कर के विरुद्ध सघर्ष कर रहा था, वहां दूसरी ओर एक छोटा सा अन्यमत्त प्रमुख रूप से 'अमृत बाजार पत्रिका' के नेतृत्व में नमक कर के बढ़ने आय कर में अथवा अन्यान्य करों में राहत देने के पक्ष ने अपने विचार प्रवृत्त कर रहा था।¹⁸⁸ जैसा हम पहले ही दिखा चुके हैं, थॉडेंस संग्रहाल के लिए 1888 में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपनी स्थिति बदली थी और नमक कर में वृद्धि का विरोध किया था, परन्तु 1888 के उपरांत उसने एक बार पुनः अपनी पूर्ववर्ती स्थिति अपना ली।¹⁸⁹

नमक कर पर राष्ट्रवादियों के प्रहार के कारण

राष्ट्रवादियों ने नमक कर पर अपने आक्रमण के लिए तीन में अधिक कारण प्रस्तुत किए? उन्होंने मैदांतिक आपत्ति उठानी प्रारंभ की। उनकी घोषणा के अनुसार उत्तम राजस्व और व्यापक कराधान का यह नियम ही जीवन की प्रधान आवश्यकता की वस्तु नमक निस्संदेह जीवन की एक प्रभुत्व आवश्यकता थी पर कराधान और वह भी डम असाधारण परिमाण में नहीं होना चाहिए।¹⁹⁰ इसके उपरांत उन्होंने प्रशामकों की इस धारणा के आगे प्रवर्तित लगाया कि यद्यपि एक कर में समृद्ध राजस्व की प्राप्ति होती है तथापि इसका भार लोगों को दुःखप्रद प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह जनसंख्या के विशाल भाग में बटा हुआ है।¹⁹¹ उनका अर्थ था कि इसके परिमाण को अमृत रूप में नहीं नापना चाहिए प्रत्युत भारतीय जनता की निपट दरिद्रता के सदम में और उस प्रसंग में ही उसे देखना चाहिए। यदि लोगों की आय के अत्यंत निम्न स्तर को देखा जाए तो कुछ आने प्रति व्यक्ति कर भी वारसत में ही स्पष्ट रूप से उनकी कमर तोड़ने वाला सिद्ध होगा। इस दिशा में तर्क देते हुए जी० वी० जाशी ने टिप्पणों की कि यदि अन्यान्य बातों के साथ अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों की स्थिति में निरंतर उत्तरात्तर सुधार हुआ होता जिससे उनके पास उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक सुविधा तथा अवकाश प्राप्त होता तो यह नमक कर इतना अधिक दुःखद न होता।¹⁹² 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस में नमक कर प्रस्ताव को पेश करने वाले एन० वी० बरवे ने अपनी मान्यता को सचित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा : 'इस देश में लाख लाख ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए इन अतिरिक्त आठ आने का अर्थ है वर्ष में आठ दिन बिना भोजन किए व्यतीत

करना और विशेषतः उन लोगों के लिए जिन्हें पहले ही 24 घंटों में कठिनाता से एक समय का खाना मिल पाता है।¹⁹³ कुछ राष्ट्रवादियों ने तो नमक कर के परिमाण की गणित-रूप में संगणना करके इस तर्क को बढ़-चढ़ कर समर्थन देना चाहा। उदाहरणार्थ, 1890 में प्रिगल केनेडी ने संगणना की कि पांच व्यक्तियों के परिवार की पांच रुपये प्रति मास की आय पर नमक कर 6 पाई प्रति रुपये की दर से पड़ता था जबकि निम्न स्तर पर आय कर की दर चार पाई प्रति रुपये प्रति व्यक्ति पड़ती थी।¹⁹⁴ इसी प्रकार डी० ई० वाचा ने उसी वर्ष संगणना की कि यदि प्रति व्यक्ति आय को 2 पौंड भी मान लिया जाए तो नमक कर प्रति व्यक्ति आय का 1.1 प्रतिशत था।¹⁹⁵

राष्ट्रवादियों के नमक कर विरोध का प्रधान आधार उसका दोषपूर्ण स्वरूप था जिसका उद्भव इस तथ्य से होता था कि यह कर देश के निर्धनों में अत्यंत निर्धनों को, जो न तो किसी प्रकार के कर का भुगतान करने में समर्थ थे और न ही जिनकी आय कठिनाता से भी तन और प्राण एक साथ रख पाने में समर्थ थी, बहुतों की तो आय जीवन निर्वाह के ही उपयुक्त नहीं थी,¹⁹⁶ अत्यंत भारीपन, दबाव तथा क्रूरतापूर्वक प्रभावित करता था।¹⁹⁷ यही मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार इस टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध किया। इस सदर्भ में थोड़े से भारतीय नेताओं ने राजस्व की असमानता और नमक कर की प्रतिगामी प्रकृति का भी उल्लेख किया। 1871 में इसी प्रमुख आधार पर दादाभाई नौरोजी ने नमक कर के विरुद्ध आपत्ति की। 'सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनांस' को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में दादाभाई ने निर्देश किया कि नमक कर के भार का परिमाण जितना अधिक गरीबों पर पड़ता था, अन्य धनिक वर्गों द्वारा भुगतान किए जाने वाले राजस्व के भाग का परिमाण उतना अधिक नहीं था। निर्धन कुलियों, श्रमिकों और किसानों पर नमक कर का भार उनकी साधारण 20 शिलिंग वार्षिक आय का चार प्रतिशत था, यह बनाने के उपरांत उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा : 'बीस शिलिंग प्रतिवर्ष कमाने वाले निर्धन व्यक्ति के लिए चार प्रतिशत कर भी अपेक्षाकृत धनी वर्गों की आय पर दस अथवा बीस प्रतिशत कर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।'¹⁹⁸ इसी प्रकार 1880 में 'जरनल आफ पूना सार्वजनिक सभा' प्रकाशित 'फाइनांस आफ इंडिया ग्रैंडर लार्ड लिटन' के अज्ञातनामा लेखक ने लिखा : 'यह कर अपने परिमाण में धनिकों और निर्धनों को समान रूप में प्रभावित करता है किंतु उनके साधनों के अनुरूप उन्हें प्रभावित नहीं करता। यही एक प्रबलतम कारण है कि इसे बराबर नीची दर पर ही रखा जाए जिसमें यह निर्धन जनता के लिए दुखद सिद्ध न हो।'¹⁹⁹ इसी प्रकार की भावनाएं अन्य नेताओं ने भी प्रकट की।²⁰⁰ हां, जी० बी० जोशी ने अवश्य ही इस दृष्टिकोण को 1886 में अत्यंत स्पष्टता तथा निर्व्याजना के साथ अपने लेख में प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि रकम के भुगतान में समानता एक प्रकार की झूठी समानता है। यह सच्ची समानता अर्थात् 'बलिदान की समानता' नहीं है।²⁰¹ दो वर्षों के उपरांत 1888 में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि नमक कर में वृद्धि लोक करो के निर्धनों और धनिकों में वितरण की विषमता को और गहरा करती है।²⁰²

भारतीय नेताओं द्वारा अपनाई गई दूसरी कसौटी नमक कर का नमक की सपत पर

पडने वाला प्रभाव था। इस संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मूलकाल में ब्रिटिश इंडियन प्रशासक अपनी नमक कर नीति को इस कमीटी पर परखने के लिए बराबर सहमत रहे थे।²⁰³ यहाँ तक कि 1888 में कर में बढ़ोतरी करते हुए जेम्स वेस्टलैंड ने यह आशा प्रकट की कि ढाई रुपये का भार अब नमक की खपत की बढ़ती हुई दर को किसी भी रूप में बाधित नहीं करेगा।²⁰⁴ दूसरी ओर भारतीय नेता इस तथ्य में पूर्णतया सहमत थे कि बनाए रखी जाने वाली नमक कर की ऊँची दर से और विशेषतया 1888 में की गई वृद्धि से नमक की खपत बाधित और क्षीण हुई है। बदले में इसका अर्थ हुआ लोगों के दुखों और कष्टों में भयंकर रूप से वृद्धि क्योंकि नमक एक ऐसा उपभोग्य पदार्थ था जिसकी शारीरिक स्थिति और मानव के स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य उपयोगिता थी।²⁰⁵

एक बार फिर जी० वी० जोशी ने ही राष्ट्रवादियों के पक्ष को बड़े ही मशक्त और युक्तीयुक्त ढंग से प्रस्तुत किया। सामान्य रूप में उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में तथ्यों का ही आश्रय लिया। उन्होंने पिछले 19 वर्षों के अनुभव का विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण प्रस्तुत किया।²⁰⁶ उन्होंने सिद्ध किया कि 'नमक की खपत सदैव नमक कर दरो में परिवर्तन के अनुरूप ही परिवर्तित होती रही है। नमक कर में वृद्धि से खपत घटी है और नमक कर में कटौती का परिणाम खपत में वृद्धि के रूप में सामने आया है।'²⁰⁷ उन्होंने निर्देश किया कि नमक के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप निर्धन व्यक्ति को ही अपनी खपत में कटौती करने को विवश होना पड़ता है जबकि उच्च वर्ग के संपन्न खाते-पीने लोगों पर अथवा मध्यवर्ग के लगभग खाते-पीते लोगों पर नमक कर में वृद्धि और कटौती से नमक की खपत में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत नमक कर की दर में स्वल्पतम तबदीली भी समाज के पिछड़े निर्धन वर्ग की खपत पर उल्लेखनीय परिमाण में अंतर को स्पष्ट प्रदर्शित करती है। अतः सारा समाज नमक की खपत में किसी भी प्रकार की गिरावट का समान रूप से भागीदार नहीं होना, इसका सारा भार समाज के अधिक निर्धन वर्ग को ही अकेले उठाना पड़ता है।²⁰⁸ 1896 में उन्होंने अपने लेख 'दि साल्ट ड्यूटी क्वेश्चन' में इस तर्क को पुनः दोहराया। इस लेख में उन्होंने 1888 के बाद के वर्षों में अनुभूत अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया तथा दृढ़तापूर्वक कहा कि निराशाजनक भविष्यवाणी नितांत सत्य सिद्ध हुई है। सख्यागन अंको को उद्धृत करते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि नमक की खपत 1888 के उपरांत 1888 से पूर्व की खपत के अनुरूप नहीं रही है। 1882-87 से नमक की खपत की दर औसतन 38 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, 1887-8 में 1894-5 तक यह दर 0.12 प्रतिशत हो गई। इससे भी अधिक निराशाजनक स्थिति यह थी कि इस अवधि में नमक की खपत जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप भी नहीं रही। जोशी ने गणना की कि भारत में प्रति व्यक्ति नमक की खपत जहाँ 1880-81 में 8.8 पौंड थी, और 1886-7 में बढ़कर 10.3 पौंड हो गई थी, वहाँ 1894-5 में वह फिर घटकर 9.5 पौंड हो गई। उन्होंने गणना की कि जनसंख्या के 8 करोड़ लोगों को 8 वर्ष पूर्व की खपत की आदत के मुकाबले अनुमानतः लगभग 2 से तीन पौंड प्रति व्यक्ति नमक की खपत में कटौती करने को विवश होना पड़ा। अतः उनके द्वारा निम्नलिखित अभिव्यक्त निष्कर्ष उन्हें चौंकाने वाला ही था :

भूखो मरते निधनों का रक्त चूसने वाली कर पद्धति, कितनी ही महत्वपूर्व आवश्यकता से प्रेरित क्यों न हो, सर्वथा निंदनीय तथा स्पष्टतया तिरस्करणीय है। कोई भी राजस्व कानून, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का कोई भी सिद्धांत इस प्रकार की क्रूर कर पद्धति लागू करने की स्वीकृति नहीं देता। कितनी ही बड़ी अपरिहार्य आवश्यकता क्यों न हो ? राजस्व सबधी सकटकालीन स्थिति कितनी ही विषम और अमह्य क्यों न हो ? जनसाधारण के कष्टों को इस प्रकार की निर्मम उपेक्षा को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

इस कथन के उपरांत आक्रोश और निराशा में पूर्ण लेखक ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए लिखा : 'परन्तु दुख तो यह है कि हमारा वित्तीय प्रशासन सामान्य मानवीयता की दुर्बलता से परिचित ही नहीं, उसे सघर्षशील दरिद्रता से किसी प्रकार की सहानुभूति ही नहीं।' ²⁰¹

1888 के उपरांत नमक कर विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूसरे प्रमुख नेता थे गोपालकृष्ण गोखले। उन्होंने जोशी का अनुकरण ही नहीं किया प्रत्युत सभी महत्वपूर्ण स्थितियों में उन्होंने जोशी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के साथ साथ उनके ही द्वारा उद्धृत सांख्यिकी सगणनाओं को दोहराया। इस दिशा में उनका महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने जोशी के कार्य को लोकप्रिय बनाया। ²¹⁰

नमक कर के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का दूसरा आरोप यह था कि इसमें नमक जैसी आवश्यक उपभोग्य वस्तु की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धि के कारण पशुओं और भूमि को नमक से वंचित करके कृषि को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति निहित थी। ²¹¹ इसके अतिरिक्त जी० वी० जोशी और गोपालकृष्ण गोखले ने नमक कर की इस रूप में भी निंदा की कि नमक उद्योग पर कर एक औद्योगिक कर था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार पद्धति को बढ़ावा मिलता था अतः इससे भारत की विशेषतया आवश्यक और सशक्त आर्थिक प्रगति बुरी तरह से प्रभावित होती थी। ²¹² इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नमक कर लगाने के फलस्वरूप अस्तित्व में आने वाले कतिपय विभिन्न तत्व जैसे कि नमक पर सरकार का एकाधिकार, विभिन्न प्रांतों में नमक कर का समानीकरण और कर की ऊँची दरें आदि भारत के विभिन्न प्रांतों में विशेषतया बंगाल में एक फलते-फूलते स्थानीय उद्योग को प्रतिबाधित और विनष्ट करने में तथा स्वदेशी उत्पादन को बाजार से निकाल फेंकने में उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं। ²¹³ जी० वी० जोशी ने तो इस सीमा तक आरोप लगाया कि बंगाल में उद्योगों का सामूहिक ह्रास सभी देशी उद्योगों को विदेशियों को हस्तांतरित करने की कर नीति की एक चातुरीपूर्ण रणनीति है। ²¹⁴ उन्होंने यह आशंका भी प्रकट की कि एकाधिकार की मध्यवर्ती स्थिति अपनाए बिना ही कपटपूर्ण ढंग से बंगाल की ही घातक नीति बंबई में भी अपनाई जाने लगी है। ²¹⁵

कराधान के वैकल्पिक साधन

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने धीमे स्वर में या खुले रूप में यह अभिस्वीकार किया कि बजट के घाटे ने सचमुच ही सरकार को इतनी ऊँची दर पर नमक कर बनाए रखने के

लिए बाध्य कर दिया है। इस घाटे की पूर्ति किसी न किसी रूप में होनी ही चाहिए। अतः उन्होंने अतिरिक्त राजस्व की उगाही के लिए नमक कर की अपेक्षा कम आपनि-जनक कुछ उपाय और साधन सुझाए। उनके विश्वास के अनुसार यह कार्य वास्तव में कोई बहुत कठिन कार्य नहीं था। उन्होंने प्रथम विकल्प के रूप में आयात कर पुनः लगाने की सिफारिश की।²¹⁶ कुछ नेताओं द्वारा सुझाया गया दूसरा वैकल्पिक साधन आय कर में वृद्धि थी।²¹⁷ और अब तक इसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त वर्गों को इसकी अधिकार सीमा के अंतर्गत लाने की वकालत थी।²¹⁸ कुछ नेताओं ने तो धनिकों पर और धनिकों द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादनों पर सामान्य रूप से ही कर लगाने के लिए शासन पर दबाव डाला। इन नेताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन करों की रूपरेखा क्या होगी? ²¹⁹ कुछ ने तो यह भी अनुभव किया कि 1888 में नमक कर में वृद्धि करने से पूर्व सिविल और मिलिट्री के चालू खर्चों में कटौती के परिमाण पर ध्यान दिया जाना उचित था।²²⁰ उदाहरण के रूप में बंबई प्रांत के लगभग सभी समाचारपत्रों ने यह सुझाव दिया कि यूरोपीय सरकारी अधिकारियों के वेतन में लगभग चतुर्थांश की कटौती करके उस समय बजट के घाटे को बड़े अच्छे ढंग से पूरा किया जा सकता था।²²¹

जोशी और गोखले ने निर्देश किया कि स्वयं नमक कर की प्रचलित पद्धति के अंतर्गत ही राजबापों सिद्धांत अपनाने की व्यवस्था की जाती तो अंततः इस कर में होने वाली वसूली पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई होती। यह सिद्धांत कराधान की इस सुप्रसिद्ध मान्यता पर आधारित था कि कर की दर इतनी नीची रखनी चाहिए कि जिसमें खपत को बढ़ावा मिले। इस नियम को अपनाने में नमक कर जैसा राजस्व का साधन बड़ा ही सफल सिद्ध होता। 1896 में जी० वी० जोशी ने मगणना की कि यदि 1888 के उपरान्त नमक की खपत का 1888 से पूर्व के वर्षों की दर पर बढ़ना जारी रहता तो इस खपत का परिमाण 1895-6 तक लगभग 100 लाख मन तक बढ़ जाता और राज्य को 2 रुपये प्रति मन कर की पुरानी दर पर दो करोड़ रुपये के लगभग बढ़े राजस्व की उतनी ही वसूली होती, जितनी कि कर के बढ़ाने पर खपत के गिर जाने से वास्तव में ही अब वसूली हुई है।²²² गोखले ने अपने 1902 के बजट भाषण में कराधान का यह सिद्धांत अपनाने का अनुरोध किया।²²³ अतः में उन्होंने 1903 के अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया : 'इस संबंध में' यहाँ तक कि राजस्व की दृष्टि से भी सर्वोत्तम नीति यह होनी चाहिए कि करों के परिमाण को घटा कर खपत की वृद्धि के अनुरूप कर वसूली में होने वाली वृद्धि का लाभ ग्रहण किया जाए।²²⁴

भारतीय नेता अपने द्वारा सुझाए गए कराधान के वैकल्पिक साधनों में से किसी एक को भी मानने से सरकार द्वारा इनकार किए जाने पर रुष्ट हो गए। बहुतों ने तो सरकार के ब्रिटिश उत्पादकों, ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय जनता के अपेक्षाकृत समृद्ध और प्रभावशाली वर्गों के आगे झुकने के कारण उस पर कायरता और पक्षपात का तथा इस देश के करोड़ों असहाय और बेजबान लोगों को परेशान करने का तथा उन पर भार डालने का आरोप तक लगाया। उदाहरणार्थ केमरी ने अपने 24 जनवरी 1888 के अंक में निम्नलिखित व्यंग्यात्मक टिप्पणी की :

यदि परम श्रेष्ठ बायसराय महोदय मॉर्चेस्टर से आने वाले सूती सामान पर आयात कर लगाने का निश्चय करते तो इससे माचेस्टर के व्यापारियों में व्याकुलता फैल जाती... क्या कृपालु ब्रिटिश सरकार संसद के चुनाव के समय उपयोगी सहायता देने वालों के प्रति कृतघ्न हो सकती थी? यदि आय कर में वृद्धि की जाती तो उमका भार अधिकाशनया उच्च यूरोपीय अधिकारियों और यूरोपीय व्यापारियों पर पड़ता। विनिमय की दर पहले से ही ऊंची होने के कारण यह भार उनकी कमर तोड़ने वाला होता और इससे वे विद्रोह के लिए उठ खड़े होते। क्या लार्ड डफरिन जैसा समझदार व्यक्ति इस प्रकार के विरोधी तत्वों को उभार कर अपने उज्ज्वल नाम को कलंकित करेगा? संक्षेप में लार्ड डफरिन ने इन दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर तथा नमक कर में वृद्धि के अवशिष्ट उपाय को अपना कर अपनी प्रतिभा का ही परिणय दिया है। लार्ड डफरिन को यह भली भाँति ज्ञात है कि भारत की निहत्थी और वफादार जनता जब तक भी वह जीवित है, किसी मांग के प्रति इनकार के स्वर का उच्चारण नहीं करेगी। भारतीयों को संगठनात्मक रूप से मुदृढ़ होने की भी तो आवश्यकता नहीं क्योंकि सरकार ने कृपापूर्वक उनकी सुरक्षा का दायित्व लिया हुआ है।²²⁵

इसी प्रकार 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 22 जनवरी 1888 के अंक में लिखा।

अथवा, कदाचित् सरकार लोकमत से भयभीत है क्योंकि यह निश्चित है कि धनिक वर्गों पर लगे करों में किसी प्रकार की वृद्धि के परिणामस्वरूप पचीस करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों के विरोध के रूप में सरकार को बुरा समय देखना पड़ता, जबकि बीस करोड़ लोगों के मुँह में जबान ही नहीं जिसमें नमक कर में वृद्धि के विरुद्ध उनके द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के विरोध की संभावना हो। सरकार की न्याय भावना के प्रति कुछ न कहा जा जाए, इतना तो निश्चित है कि भारत सरकार इस पीढ़ी में काफी समझदार है।²²⁶

22 जनवरी 1888 के 'मराठा', 25 जनवरी 1888 के 'हिंदू', 26 जनवरी 1888 के 'अमृत बाजार पत्रिका', 28 जनवरी 1888 के 'बंगाली' ने तथा 4 फरवरी 1888 के 'सजीवनी' ने इसी स्वर में अपना मत प्रकट किया।²²⁷ जी० बी० जोशी ने इस विषय में सरकार की कार्यवाही के पीछे निहित कारणों का समान भावना से उल्लेख किया।²²⁸ 18 मार्च 1888 के 'मराठा' ने तो यहाँ तक दावा किया कि नमक कर में जुड़ा विचारणीय प्रश्न वस्तुतः यह है कि भारत देश भारतीयों के लिए है अथवा औरों के लिए?

राजनीतिक सीख

बहुत सारे राष्ट्रवादी समीक्षकों ने विधान परिषद के दो नामजद सदस्यों, प्यारे मोहन मुकर्जी और दिनशा पेटिट के 1888 में नमक कर में वृद्धि को समर्थन देने के व्यवहार की तीव्र भर्त्सना की।²²⁹ उन्होंने इसे राष्ट्रवादियों की इस धारणा के प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया कि वर्तमान विधान परिषदें भारतीय लोकमत को न सही रूप में प्रतिबिम्बित करती हैं और न कर सकती हैं और न ही यह देश के जनसाधारण के हितों की रक्षा कर सकती

है। अतः इन विधानपरिषदों में लोकप्रिय तत्वों को सम्मिलित करके इनका सुधार करना चाहिए।²³⁰ इस निष्कर्ष को जी० बी० जोशी ने अच्छा समर्थन दिया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा कि 'नमक कर में वृद्धि सबंधी चर्चा विधान परिषद के लिए अपमानजनक है।'...और देशी सदस्यों के लिए तो यह और भी अधिक अपमानजनक है।'...इस सबसे बढ़कर तो व्यवस्था के लिए ही यह सर्वाधिक अपमानजनक है।'...²³¹ इसी प्रकार कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन में मदनमोहन मालवीय ने कहा : 'हम इस बात पर मतोष कर लेंगे कि विधान परिषद में कोई गैरमरकागी सदस्य न हो परन्तु हमारे लिए इस बात पर सतोष करना संभव नहीं कि ऐसे लोग गैरमरकागी सदस्य हैं जिनका जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं, जो जनता की वास्तविक स्थिति में सर्वथा अनजान है तथा जनता के प्रति अनिवार्यतया वाछनीय महानुभूति न दिखाकर उसके प्रति विश्वासघात करने हैं।' उन्होंने पी० एम० मुरुजी और दिनशा पेटिट को निजी आय का उपभोग करने वाले और ऊँचे वेतन पानेवाले अत्यंत सम्मानीय मज्जन बताते हुए आलंकारिक भाषा में पूछा 'मज्जनो, क्या आपको विश्वास है कि विधानपरिषद के चुनाव में यदि जनता के मत के लिए कोई अवकाश हो तो क्या जनता इन लोगों को सदस्य के रूप में भी नहीं चुनेगी?' श्रोताओं की ओर से 'नहीं', 'नहीं', 'कभी नहीं' की तुमुल ध्वनि के मध्य उन्होंने पुनः पूछा कि और यदि किसी भी प्रकार की गलती से ये लोग एक बार विधानपरिषद के सदस्य नियुक्त हो भी गए तो क्या अगले चुनाव में उन्हें अपमान और घणा के साथ ठकरा नहीं दिया जाएगा।²³²

निष्कर्ष

नमक कर के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने नमक कर में कटौती और उसका समाप्त करने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय नीति के रूप में ही अपनाया था। वस्तुतः इस मांग का नेताओं ने चालू वित्त नीति की निंदा और उसकी व्यावहारिकता के आगे प्रश्नचिन्ह लगाने के लिए उपयोग किया। इसके साथ ही साथ इस मामले में राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की निर्धन जनता के हितों को सही रूप में और तत्परतापूर्वक अभिव्यक्ति दी और इसके द्वारा उन्होंने उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में निर्धन जनता को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। वस्तुतः इस प्रयास में निर्धनों को साथ लेकर चलने के तथ्य को भारतीय नेताओं ने अत्यंत स्पष्टतापूर्वक समझ लिया था। 1890 में राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन में नमक कर में कटौती की मांग के प्रस्ताव को पेश करते हुए प्रिंगले केनेडी ने प्रतिनिधियों को निम्नलिखित अवतरण में इस प्रकार संबोधित किया :

प्रतिनिधि मित्रो ! क्या आप उन लोगों के कथन को जो आप पर यह दोष लगाते हैं कि आपका मामला निजी स्वार्थ से प्रेरित है और आपका आंदोलन मात्र कृष्ण वर्ण के शूद्रों की गौर वर्ण के ब्राह्मणों के प्रति घृणा को अंगरेजों के प्रति घृणा के रूप में परिवर्तित करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, यह कहकर गलत सिद्ध कर सकेंगे कि यदि गुलामी का यह जुआ और किसी रूप में कम दुःखदायी नहीं बनाया जा

सकता तो हम पर ही कर लगाइए, धनिकों पर कर लगाइए परंतु कृपा करके निर्धनों को तो क्षमा कर दीजिए।²³³

इसी प्रकार 1892 में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि जी० एस० खपटने ने नमक कर पर प्रस्ताव को दरिद्र नारायण की कांग्रेस से विनय के रूप में वर्णित किया।²³⁴

इसके विपरीत राष्ट्रीय नेताओं ने इस मामले में देश के धनिकों के हितों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की अन्यथा धनिक वर्गों के प्रवक्ता के रूप में वे भी इसी विश्वास से कि इससे धनिकों पर लगे आय कर जैसे अन्याय करों की समाप्ति में सहायता मिलेगी, नमक कर को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने का समर्थन ही करते।²³⁵ राष्ट्रवादियों की स्थिति और धनिक वर्गों के हितों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से तभी देखा जा सकता है यदि जमींदारों, बड़े बड़े व्यापारियों और गैरसरकारी अंगरेजों के समकालीन प्रवक्ताओं द्वारा अपनाए गए और सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्त कर समर्थक दृष्टिकोण के सदर्थ में राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण को देखा जाए। 1882 में कलकत्ता के व्यापारियों के प्रवक्ता दुर्गाचरण लाहा ने इपीरियल विधानपरिषद में नमक कर में कटौती की विचाराधीन नीति को भावनात्मक बताकर इसका विरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें अच्छा तो यह होता कि इसके बदले सरकार देश की परिस्थितियों के अनुकूल न बैठने वाले प्रत्यक्ष करों को हटा ही देती।²³⁶ विधानपरिषद में बंगाल के जमींदारों के प्रतिनिधि महाराजा जीतेन्द्र मोहन टैगोर ने लाहा के मत का पूरा पूरा समर्थन किया।²³⁷ इसी प्रकार बंगाल के जमींदारों के एक अन्य प्रवक्ता प्यारमोहन मुकर्जी ने बर्बई के व्यापारियों के प्रवक्ता दिनशा पेटिट तथा भारत में रहने वाले ब्रिटिश सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों के अनेक प्रवक्ताओं ने 1888 में नमक कर में की गई वृद्धि का पूरा पूरा समर्थन किया।²³⁸ 1887 के बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन की समिति के प्रतिवेदन में यह दावा किया गया कि आय कर की वर्तमान दर को दुगना करने की अपेक्षा नमक कर में वृद्धि कम आपत्तिजनक थी।²³⁹ सदन के 1889 के अध्यक्ष और सचिव ने तो पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ नमक कर में किसी प्रकार की कटौती का विरोध किया।²⁴⁰

उत्पाद राजस्व

राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत तथा एक अन्य परोक्ष कर उत्पादनो पर उत्पादन शुल्क के रूप में तथा मादक द्रव्यों, शराब, भाग-घतूरा और अफीम, बेचने के लिए लाइसेंस फीस के रूप में लगाया गया कर था। इस माध्यम से होने वाली कुल आय 1860-1 में 1.18 करोड़ रुपये से 1880-01 में 3.19 करोड़ तथा 1902-03 में 6.64 करोड़ रुपये हो गई।²⁴¹ हमने यहां देशी अथवा कच्ची शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व के उस पक्ष विशेष का ही यहां विवेचन प्रस्तुत किया है जो इस मद से होने वाली आय का प्रमुख भाग था।²⁴² देशी शराब पर शुल्क पद्धति देश के भिन्न भिन्न कालों में है। इन पद्धतियों को मोटे तौर पर परस्पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : (1) केंद्रीय शराब कारखाना पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादित तथा बिक्री के लिए अनुज्ञप्त प्रत्येक गैलन

शराब पर एक निश्चित शुल्क लगाया जाता था; (2) ठेका बिक्री पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादित मात्रा पर शुल्क न लगाकर कुल उत्पादन पर शुल्क लगाया जाता था और उसका भुगतान एक मुश्त नीलामी के आधार पर किया जाता था। स्पष्ट है केंद्रीय पद्धति की अपेक्षा ठेका बिक्री पद्धति में शराब की खपत पर सरकारी नियंत्रण का अवकाश काफी कम था।²⁴³ 1890 के वर्षों में शराब की न्यूनतम खपत में अधिकतम राजस्व की उगाही भारत सरकार की एक नीति थी। इसका अर्थ था शुल्क की दर को बढ़ाना तथा शराब की बिक्री के स्थानों को इस सीमा तक प्रतिबन्धित करना कि उसकी खपत न्यूनतम हो जाए। इसके साथ ही साथ गैरकानूनी शराब के उत्पादन को भी सीमित कर दिया गया।²⁴⁴ कम में कम 1890 के पश्चात् तो क्रमशः नीलामी पद्धति को हटाने जाना और केंद्रीय शराब कारखाना पद्धति का विस्तार करना सरकार की निश्चित, निर्धारित और और घोषित नीति बन गई।¹

भारतीय नेताओं ने मादक द्रव्यों की खपत और उन पर करगणान के प्रश्न को बहुत अधिक महत्व दिया। भारतीय नेता कुन मिनाकर मद्रिरा के प्रयाग के विरुद्ध थे और देश में मदिरापान की प्रवृत्ति के प्रसार के विरोधी थे। उनके विचार में मदिरापान की प्रवृत्ति एक घातक दोष तथा भयंकर उत्पात था जो नैतिकता को ध्वंस करने वाला एक प्रकार का पापमय मय था, आर्थिक दृष्टि में देश को दग्ध और शारीरिक दृष्टि से दुर्बल बनाने वाला था।²⁴⁵ कुछ नेताओं का तो यही तर्क विश्वास था कि मदिरापान की प्रवृत्ति के विनाश से श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाने से औद्योगिक प्रगति दुष्प्रभावित होगी।²⁴⁷

मदिरा की खपत में वृद्धि की निंदा करते समय भारतीय नेताओं ने यहाँ एक बार फिर 'पहली चपत सग्वार के मुह पर मारी।' उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह और उगवी आवश्यक नीति ही मदिरापान की प्रवृत्ति के प्रसार के लिए पूरी तरह उत्तरदायी थी। उन्होंने अधिकतम उत्पादन शुल्क की वसूली के लिए जानबूझकर अथवा अनजाने मदिरापान की प्रवृत्ति का प्रोत्साहित करने के लिए अथवा तत्परता के साथ उसे निरुत्साहित करने में असफल रहने के लिए सरकार की तीव्र भर्त्सना की।²⁴⁶ 1880 के वर्षों में वृत्तांत में तो सरकारी उत्पादन शुल्क नीति की आलोचना अत्यंत उग्र तथा निरंतर थी क्योंकि वही उस प्रांत में ठेका पद्धति प्रचलित थी जिस पर मदिरा को सस्ता करने का आरोप लगाया जा रहा था।²⁴⁹

भारतीय नेताओं ने यह भी दोष लगाया कि एक ओर तो सरकार सार्वजनिक रूप से तथा सिद्धांत रूप में मदिरापान की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने का दावा करती है परंतु दूसरी ओर व्यावहारिक रूप में उसकी नीति का प्रभाव सर्वथा विपरीत रूप में पड़ रहा है।²⁵⁰ प्रशासन द्वारा उत्पादन शुल्क की वसूली में वृद्धि करने वाले सरकारी अधिकारियों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करने, उन्हें उन्नति देने तथा इस वसूली में वृद्धि न कर पाने वाले अधिकारियों की निंदा करने की नीति अपनाने का वास्तविक परिणाम यह देखने में आया है कि सरकारी कर्मचारी मदिरा की खपत को बढ़ाकर उत्पादन शुल्क की वसूली में वृद्धि करने के प्रति और उत्साही बन गए हैं।²⁵¹ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस

विषय में सरकारी पक्ष के प्रवक्ता भी राष्ट्रवादियों के आरोप का प्रत्याहार करने में तथा उत्पादन राजस्व में वृद्धि का कारण उत्पादन शुल्क की ऊँची दर और उस पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रणों को सिद्ध करने में कम उत्साही तथा कम तत्पर थे।²⁵² यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि कुछ एक अन्याय्य सदर्थों में सरकारी अधिकारियों ने परोक्ष रूप में मदिरा की खपत में वृद्धि को स्वीकार तो किया परंतु इसे सरकार ने जनता की बढ़ती संपन्नता के संकेत के रूप में ही प्रस्तुत किया।²⁵³ राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रश्न के समग्र रूप के अनुरूप ही सरकारी मान्यता का खंडन किया और उसके विपरीत यह धारणा प्रस्तुत की कि मदिरापान ने पियक्कड़ों और उनके परिवारों में दुर्भाग्य, विनाश और दरिद्रता का आधिपत्य स्थापित कर दिया है।²⁵⁴

राष्ट्रवादी नेताओं का इस तथ्य के प्रति निश्चित मत था कि मदिरापान के व्यसन के विरुद्ध संघर्ष करने में शिक्षा एक अत्यंत मद प्रभाववाला शस्त्र था। इस व्यसन के प्रसार को तत्काल कम करने के लिए प्रशासकीय उपाय ही उपयोगी सिद्ध हो सकते थे।²⁵⁵ अतः उन्होंने मदिरापान के विरुद्ध लोकप्रिय आंदोलन छेड़ने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान और सारे प्रयास सरकार में जनता के नैतिक व्यवहार की श्रेष्ठता के आदर्श के समक्ष राजस्व के दृष्टिकोण को गौण बनाने और इस प्रकार मदिरापान की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने की नीति को अपनाने के लिए अनुरोध और विवश करने पर ही केंद्रित किया।²⁵⁶ उन नेताओं द्वारा मुष्गाएँ गए लगभग सभी प्रशासकीय उपायों का उद्देश्य मधुशालाओं और मदिरा बिक्री की दुकानों की संख्या घटा कर मदिरा को महंगा और मदिरा की प्राप्ति को दुर्लभ तथा कष्टमाध्य बनाना था। नेताओं द्वारा प्रचारित उपायों में जिस उपाय को सर्वाधिक व्यापक लोकप्रियता मिली, वह था स्थानीय लोकमत। उन्होंने माग की कि किसी भी स्थान पर नई मदिराशाला अथवा नई मदिरा बिक्री दुकान को खोलने के प्रश्न को निर्णय के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्थानीय नगरपालिका जैसी संस्थाओं के माध्यम से अभिव्यक्त लोकमत को निर्णायक तत्व के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए।²⁵⁷ एक अन्य लोकप्रिय माग जो अधिकांशतः बगाल तक ही सीमित रह गई वह थी ठेका प्रथा की समाप्ति।²⁵⁸ जब 1889-90 की अवधि में बगाल के अधिकांश भागों में ठेका पद्धति समाप्त कर दी गई, स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया।²⁵⁹ राष्ट्रवादियों ने मदिरा पर आयात कर और उत्पादन शुल्क बढ़ाने का समर्थन किया।²⁶⁰ कुछ ने तो सरकार में मदिरा बिक्री केंद्र बंद करने, मदिरा की परचून बिक्री की दुकानों को लाइसेंस देने में कठोरता बरतने जैसे विशुद्ध प्रशासनिक पग उठाने का अनुरोध किया।²⁶¹ यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं कि राष्ट्रवादी नेताओं में इन सभी उपायों की वकालत करते हुए नशाबंदी को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। संभवतः उनके विचार में यह उपाय व्यावहारिकता तथा संभावना के क्षेत्र से बाहर था।²⁶²

मदिरा से सबद्ध उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रति राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका दृष्टिकोण और उसके पीछे प्रेरणा विशुद्ध राष्ट्रीय ही थी। भले ही मदिरा उत्पादन शुल्क राजस्व का एक

फलता-फूलता साधन था और इसका भुगतान केवल मदिरा के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाना था जिससे देश की सामान्य जनता पर अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी राष्ट्रवादी नेताओं ने सर्वसाधारण की हितकामना की दृष्टि से इसे देखा और इस रूप में उसकी निंदा करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। इस संबंध में राष्ट्रवादियों की नीति के इस पक्ष को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मदिरा को अपेक्षाकृत अधिक महंगा करने की राष्ट्रीय नीति अपनाने पर एक ओर मदिरा का सेवन करने वाले भारतीय नेताओं का भी घाटे में रहना स्पष्ट था, दूसरी ओर मदिरा की पूर्ति में कटौती का स्वाभाविक परिणाम उत्पादन शुल्क में ह्रास था और यह मदिरापान न करने वालों के हित के सर्वथा विरुद्ध था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस मामले में वित्तीय विषयों में भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने निःस्वार्थपरता और परोपकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

विचाराधीन प्रश्न से संबंधित दो अन्य तत्व भी यहां उल्लेखनीय हैं, प्रथम, कालांतर में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रबल राजनैतिक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त मदिरा विरोधी संघर्ष के इस रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति का इस समय तक अभाव था। उच्च भारतीय नेताओं में यह भावना अवश्य उभरने लगी थी कि मदिरा विरोधी आंदोलन का जनता को राजनीतिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 17 अप्रैल 1905 में एंग्लो इंडियन टेंपरेंस एसोसिएशन के अधिवेशन में बोलते हुए दादाभाई नौरोजी ने कहा :

भारत में इन लोगों की संस्था की 300 शाखाएं थी और इसका अर्थ था कि नीचे में ऊपर तक के सभी वर्गों, धर्मों और स्थितियों के लोग परस्पर संगठित होने, एक दूसरे के प्रति भ्रातृभाव अपनाने तथा एक महान उद्देश्य के लिए कार्य करने का पाठ सीख रहे थे। '...यह संस्था भारत में मदिरापान के व्यसन को निर्मूल करने के लिए ही प्रयास शुरू करने नहीं जा रही थी, प्रत्युत समान रूप से ही महत्वपूर्ण परस्पर संगठित होने के उच्च विचारों को अपनाने के लिए भी जनसाधारण को प्रशिक्षित करने जा रही थी। यह संघ प्रवृत्ति इन लोगों के लिए सचमुच अत्यंत उपयोगी मिद्ध होगी।'²⁶³

द्वितीय, विदेशी सरकार के मदिरापान के प्रसार के लिए दोषी घोषित करने की प्रवृत्ति ने भारतीय उत्पादन शुल्क नीति को एक राष्ट्रीय रंग दिया।

अफीम से प्राप्त होने वाला राजस्व

अफीम भारत सरकार के राजस्व का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत था। 1884 तक यह बजट की द्वितीय और 1884 के उपरांत तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद मद थी। इसकी वसूली में वर्ष प्रतिवर्ष बड़े ही भयंकर रूप से उतार-चढ़ाव आता रहता था और इसके फलस्वरूप भारतीय वित्त को निश्चित रकम की वसूली में सदैव अस्थिरता और अनिश्चितता रहती थी। उदाहरणार्थ, 1880-81 में अफीम से प्राप्त होने वाली विशुद्ध रकम 8.45 करोड़ थी, 1890-91 में 5.70 करोड़ और 1900-91 में 4.97 करोड़ थी

जबकि 1897-8 में यह 2.70 करोड़ की निम्न सीमा को पहुँच गई।¹⁸⁶¹ अफीम राजस्व की वसूली बंगाल अफीम के निर्यात से जिसका उत्पादन बंगाल सरकार के अधिकार के अंतर्गत बिहार, उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध के राज्य एकाधिकार व्यवस्था के अंतर्गत होता था तथा बंबई में मालवा अफीम पर भारी निर्यात शुल्क के संग्रह से होती थी। निर्यातित अफीम का अधिकांश चीन को भेजा जाता था और उसका एक भाग उत्पादन और राजस्व पद्धति के अंतर्गत भारत में बेचा जाता था जिसकी बिक्री से प्राप्त आय उत्पादन कर के खाते में जमा की जाती थी। अफीम से प्राप्त होने वाला उत्पादन शुल्क 1870-1871 में 36 लाख था जो धीरे धीरे बढ़कर 1900-01 में 103 लाख हो गया।¹⁸⁶⁵

सारी 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और अनेकानेक लोक संस्थाओं ने नैतिकता और मानवीयता के आधारों पर चीन के साथ ब्रिटेन के अफीम के व्यापार की कटु आलोचना की। 1888 में अफीम व्यापार निरोध संघ (सोसाइटी फार दि सप्रेगन आफ दि ओपियम ट्रेड) की स्थापना के रूप में अफीम व्यापार के, सरकार द्वारा उसे दिए जा रहे संरक्षण के तथा उसके उन्नयन के विरुद्ध एक मुनियोजित आंदोलन प्रारंभ हुआ।¹⁸⁶⁶ इस आंदोलन के फलस्वरूप 10 अप्रैल 1891 को हाउम आफ कामन्स ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया गया कि भारत में अफीम में वसूल किया जाने वाला लगान अनैतिक था। इसके साथ ही भारत सरकार पर दबाव डाला गया था कि उचित रूप में औषधि के रूप में प्रयोग में आने वाली माग को छोड़ कर उसे पोस्ट की खेती और अफीम की बिक्री के लिए लाटमेंस देने बंद कर देने चाहिए। 1893 में इस प्रश्न को उसके ममग रूप में देखने और उसकी छानबीन करने के लिए एक राजकीय आयोग (रायल कमीशन) नियुक्त किया गया। कमीशन-मैन 1895 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और यथार्थ्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करने की मलाहट दी।¹⁸⁶⁷ इन सभी वर्षों में भारत सरकार ने अफीम के व्यापार को निषिद्ध और प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रस्ताव का तीव्र प्रांतवाद किया। भारत सरकार का प्रमुख तर्क यह था कि इस प्रकार के पगों से विन्तीय तथा राजनीतिक स्थितियों में दुष्प्रभावित होने की आशंका थी।¹⁸⁶⁸

अफीम व्यापार और उससे प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रति भारतीय नेताओं के दृष्टिकोण का अध्ययन रोचक है। उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहाँ उन्हें दो बातों में से एक का चुनाव करना था। प्रथम, अपना राष्ट्रीय हित, जो अनेक अन्य मामलों में उनका पर्यप्रदर्शन नत्व बना रहा था; द्वितीय, मानवीयता और परोपकार की भावना, जिसके आधार पर वे प्रायः ब्रिटिश सरकार से आर्थिक तथा राजनीतिक रियायतें देने के लिए निवेदन करते आ रहे थे।

अफीम कर के नैतिक पक्ष में अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी स्थिति के प्रतिकूल पक्ष ही ग्रहण किया। उनका यह पक्ष इस लगान के विरोधी आलोचक अंगरेजों की स्थिति के ही अधिक निकट था क्योंकि इन नेताओं ने खुले तौर पर घोषित किया कि अफीम का व्यापार और उससे उगाहा जाने वाला कर दोनों सर्वथा अनैतिक होने के कारण अत्यंत निंदनीय थे। 1870 में ही केशवचंद्र सेन ने हजारों दरिद्र चीनियों के हत्या-

अन्यायपूर्ण अफीम व्यापार को हटाने की मांग की।²⁶⁹ 1880 में दादाभाई नौरोजी ने बड़े क्षोभपूर्ण स्वर में घोषणा की कि अफीम व्यापार इंग्लैंड के मस्तक पर कलंक का टीका है और भारत के लिए इसमें भागीदार होना अभिशाप रूप है।²⁷⁰ उसी तीव्र स्वर में 7 अगस्त 1881 के अंक में 'मराठा' ने 40 करोड़ मानवों को विष देने के अभिशाप को भारतीय जनता के मत्थे मढ़ने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया।²⁷¹

दादाभाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त अफीम में प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति के संबंध में सरकारी दृष्टिकोण से असहमत थे। सरकारी दृष्टिकोण यह था कि अफीम लगान का भुगतान भारतीय जनता द्वारा नहीं प्रत्युत चीनी उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाता है।²⁷² नौरोजी और दत्त का विपरीत मत यह था कि वस्तुतः यह भारतीय जनता पर एक गुप्त कर है क्योंकि यदि अफीम व्यापार पर सरकार का एकाधिकार न होता तो अफीम कर के रूप में सरकार को होने वाले सारे के सारे लाभ भारतीय जनता को उपलब्ध होते।²⁷³

अफीम व्यापार के प्रमुख प्रश्न, अफीम व्यापार को खत्म करने पर भारतीय नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गए। जहां अधिकांश नेताओं ने इस प्रकार का पक्ष ग्रहण किया जो भारत सरकार की नीति से बहुत कुछ मिलता-जुलता था, वहां उल्लेखनीय मख्या में नेताओं ने मानवीय आधार पर अफीम व्यापार को त्यागने का भी पक्ष ग्रहण किया। प्रथम पक्षवालों का तर्क था कि कोरी भावना को आधार बना कर अफीम कर की बलि चढ़ाने की बात कहना युक्तिसंगत नहीं लगता क्योंकि अफीम में प्राप्त होने वाली राशि भारतीय वित्त का एक उल्लेखनीय अंग है और उसे छोड़ने का अर्थ होगा उसके स्थान पर अन्य नए कर लगाना। अतः उन्होंने उस समय इंग्लैंड में चलाए जा रहे अफीम विरोधी आंदोलन की तीव्र आलोचना की।²⁷⁴ इस प्रकार 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 9 जुलाई 1880 के अंक में टिप्पणी करते हुए लिखा, 'नैतिकता के दृष्टिकोण से राजस्व के इतने अच्छे स्रोत का छोड़कर उसकी पूर्ति के लिए नए करों को लगाने के रूप में पहले ही निर्धन तथा अभावग्रस्त जनता के जीवन रक्त को निचोड़ना हमारी विनम्र नैतिक सम्मति में ऊंचे स्तर की अनैतिकता होगी।'²⁷⁵ संघर्षशील माधारण ब्रह्म समाज का उच्च नैतिक मुखपत्र, 'बाह्योर्पल्लव ओपीनियन' ने 15 जुलाई 1880 के अंक में अफीम लगान के संबंध में आदर्श नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के विरुद्ध चेतावनी दी।²⁷⁶ यहाँ तक कि भारत में सामाजिक सुधारों के लिए मतत यत्नशील तथा प्रचंड प्रवक्ता 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 12 मार्च 1882 के अंक में इंग्लैंड के अफीम विरोधी आंदोलन करने वालों को 'अच्छी भावनाओं से प्रेरित परंतु अज्ञानी कट्टर लोगों का शक्तिशाली वर्ग बताया।'²⁷⁷ एक अन्य सुधारक पत्र 'हिंदू' ने अपने 3 जुलाई 1883 के अंक में घोषणा की कि वह अफीम राजस्व को हटाने की मांग का केवल इस शर्त पर समर्थन कर सकता है कि इंग्लैंड के करदाता इससे भारत सरकार को होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन दें।²⁷⁸

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने अंगरेजों के अफीम विरोधी प्रयास को दूसरे लोगों के मूल्य पर लोकोपकार के दम का रूप देते हुए उस पर तीखे व्यंग्य प्रहार किए। उनका सुझाव था कि यदि ब्रिटिश लोग चीनियों के कल्याण के प्रति सचमुच ही उत्सुक थे तो

उन्हें अपनी सरकार पर भारत सरकार को अफीम राजस्व के खोने से होने वाली क्षति-पूर्ति के लिए दबाव डालना चाहिए।²⁷⁹ यह भी पर्याप्त रोचक तथ्य है कि ब्रिटेन के अफीम विरोधी आंदोलन के जिन अग्रणियों की ईमानदारी के आगे प्रवर्धन लगाया गया और जिन्हें मूर्ख तथा कटुटार की उपाधियों से विभूषित किया गया, उनमें भारत समर्थक, राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्साही पक्षधर, ससद सदस्य डब्ल्यू एस० केन और संयुक्त स्मिथ जैसे लोग भी सम्मिलित थे।

भारतीय नेताओं के इस वर्ग ने अफीम व्यापार को प्रतिबंधित करने के विरोधी अपने पक्ष के समर्थन में कुछ और रोचक तर्क भी पेश किए। प्रथम, उनका निश्चित मत था कि चीन के दोषों में सुधार के कार्य को हाथ में लेने से पहले अधिकारियों और सुधारकों का यह नैतिक दायित्व है कि वे भारत में मदिरापान के दुर्व्यसन के विरुद्ध सघर्ष करें क्योंकि मदिरापान अफीम फूँकने की अपेक्षा किसी भी रूप में कम हानिप्रद नहीं था।²⁸⁰ द्वितीय, कुछ की तो यह मान्यता थी कि अफीम निर्यात के त्याग से संबंधित भारत सरकार का कोई भी पक्ष सर्वथा निष्फल सिद्ध होगा क्योंकि अभाव की खाई की पूर्ति प्रशा, तुर्की और मयूक्त राज्य अमरीका द्वारा अथवा अपने देश में अफीम की खेती के विस्तार तथा अफीम के उत्पादन में वृद्धि करके स्वयं चीनियों द्वारा अत्यंत तत्परता और शीघ्रता से की जाएगी। इस प्रकार लोकहित का उद्देश्य तो अपूर्ण तथा अप्राप्त ही रहेगा। हा, इसमें भारतीयों को निश्चय ही आय के एक बढ़िया स्रोत से हाथ धोना पड़ेगा।²⁸¹ यह आश्चर्यजनक तथा उत्सुकतावर्धक है कि समाचारपत्रों ने यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया कि अफीम व्यापार को निषिद्ध करने में इस व्यापार में मग्न भारतीय व्यापारी बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसके विपरीत अफीम विरोधी पत्रिका 'मजीवनी' ने अपने 23 दिसंबर 1893 के अंक में व्यापारियों पर अफीम व्यापार के समर्थन का अभियोग लगाते हुए लिखा कि उनका ऐसा करना स्वाभाविक था क्योंकि इसमें उन्हें बहुत बड़ा लाभ जो था।²⁸² अफीम विरोधी आंदोलन के विरोधी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के पीछे व्यापारिक प्रेरणा का अभाव तथा राजस्व प्रेरणा की प्रभुता से यही सिद्ध होता है कि राष्ट्रवादी नेताओं के इस वर्ग की इस नीति के निर्माण के पीछे व्यापारियों के हित की किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी।

मानवीयता के आधार पर अफीम उत्पादन को प्रतिबंधित और अफीम व्यापार को कानूनी रूप से निषिद्ध करने के समर्थक भारतीय नेताओं के दूररे वगैरे ने इस कार्यवाही से राजस्व को होने वाली क्षति की पूर्ति व्ययों में कटौती द्वारा करने का सुझाव दिया। इस संबंध में 'मराठा', 'हिंदू', 'सोम प्रकाश' और 'आनंद बाजार पत्रिका' जैसी बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति समय विशेष पर संपादकीय लिखने वाले किसी भी महानुभाव की व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तित रूप लेने वाली और इस प्रकार अस्थिर तथा ढावा-डोल रही है। 'आनंद बाजार पत्रिका' ने अपने 20 जुलाई 1880 के अंक में राष्ट्रवादियों की अफीम विरोधी भावनाओं को बड़ी ही स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ निम्नलिखित अवतरण में इस प्रकार से वाणी दी है :

क्योंकि चीन को अपनी मांग की सन्तुष्टि के लिए कहीं न कहीं से अफीम का आयात

आवश्यक रूप से करना ही है, अतः यदि भारत चीन को अफीम की पूर्ति करता है तो इसमें हानि ही क्या है ?' इस तर्क ने हमारे शासकों को नैतिकता की क्या ही बढ़िया आचार-संहिता मिखाई है ? इस प्रकार तो एक डाकू भी अपने कृत्य को आवश्यक बताकर न्यायोचित सिद्ध करेगा। एक हत्यारा भी यह कहेगा कि जिस व्यक्ति की उसने हत्या की है, उसे अंततः तो एक दिन मरना ही था, यह दूसरी बात है कि उसके हाथों से अथवा किसी अन्य कारण से ? यदि ब्रिटिश सरकार ईमानदारी से चाहे तो वह आसानी से कुल व्यय के आघे की कटौती कर सकती है और इस प्रकार सुविधापूर्वक अफीम के अनैतिक व्यापार को बंद कर सकती है।²⁸³

अफीम व्यापार के प्रबल तथा सतत विरोधी दादाभाई नौरोजी ने यद्यपि यह अभिस्वीकार किया कि बहुत सारे दूसरे राष्ट्रीय नेता इस प्रश्न पर उनके साथ नहीं थे,²⁸⁴ तथापि उन्होंने उस समय इंग्लैंड जाकर राष्ट्रवादियों के लक्ष्य का प्रचार करने के लिए अफीम पर बाद-विवाद करने की चेष्टा की और इस रूप में उन्होंने एक बार यह पुनः सिद्ध कर दिया कि उस समय कोई ऐसा सार्वजनिक विषय नहीं था जिसका प्रयोग उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए न किया हो। 1880 में अफीम व्यापार से भारत को किसी भी प्रकार के होने वाले लाभ को अस्वीकार करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस व्यापार से होने वाला लाभ तो वास्तव में खिसक कर इंग्लैंड के पास पहुँच जाता है। भारत को तो केवल चीनियों की वदुआएँ ही मिलती हैं। वस्तुतः अफीम कर तो केवल भारत की उस गम्भीर आर्थिक रुग्णता तथा वित्तीय दिवालियापन को छुपाता है जिससे देश बहुत बुरी तरह में ग्रस्त है। उनका तर्क था कि यदि अफीम का यह अभिशप्त व्यापार न होता तो भारत इंग्लैंड की माँग को पूरा करने की स्थिति में न होता। उस समय भारत का दुर्भाग्य शीघ्रता से उभर कर सतह पर आ जाता और उसका उपचार संभव हो पाता। अतः इस अफीम व्यापार ने भारत के कष्टों को और बढ़ावा दिया है।²⁸⁵ 1886 में लंदन में बुलाए गए अफीम व्यापार निरोध संघ की बैठक में दिए गए अपने भाषण में शब्द प्रतिशब्द इसी तर्क को दुहराते हुए दादाभाई नौरोजी ने संघ से अनुरोध किया कि अफीम के प्रश्न को भारत की प्रमुख समस्या दरिद्रता के संदर्भ में अपने समग्र रूप में ही देखें। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि भारत को अपने उत्पादकों को रखने और अपने भौतिक संसाधनों को विकसित करने की स्वतंत्रता दी जाए, तो भारत आसानी से इतने अधिक और पर्याप्त राजस्व जुटा सकता है कि सरकार बिना किसी संकोच अथवा मोच-विचार के अभिशप्त अफीम राजस्व को छोड़ सकती है।²⁸⁶

इस प्रकार राष्ट्रवादी नेताओं का अफीम व्यापार के प्रति दृष्टिकोण दोमुह्री भावनाओं से प्रभावित था और इस विषय में ये दोनों भावनाएँ परस्पर विरोधी मानवतावादी और निजी राष्ट्रीय हितवादी प्रवृत्तियाँ थीं। कुछ नेताओं ने इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों में एकता लाने का प्रयास किया परंतु जब उन्हें इन दोनों में एक का चुनाव करने को विवश होना पड़ा तो उन्होंने मानवतावादी प्रवृत्ति को ही अपनाया। एम० जी० रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, एस० एन० बैनर्जी और मोतीलाल, शिशिर कुमार घोष भ्रातृद्वय के साथ साथ बहुत सारे अन्य नेताओं ने नैतिकता के प्रश्न की अपेक्षा राष्ट्र

हित को ध्यान में रखते हुए अफीम व्यापार को निषिद्ध करके नए करें की संभावना की आशा का प्रकट की। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार भारतीय नेताओं ने 1877 से 1882 तक सीमा शुल्क को हटाने के लिए व्यापक और संयुक्त विरोधी आंदोलन चलाया था, अफीम व्यापार में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत वित्तीय संभावनाएं निहित होने पर भी इन नेताओं ने इस व्यापार के विरुद्ध संचालित ब्रिटिश आंदोलन के विरुद्ध उसी प्रकार के किसी व्यापक और संयुक्त विरोध का आयोजन नहीं किया।⁸⁷ इसका विश्लेषण कदाचित इस तथ्य से हो जाता है कि अफीम राजस्व के मामले में संभावित हानि केवल वित्तीय थी, उससे किसी प्रकार से औद्योगिक हित प्रभावित नहीं होते थे जबकि कपास मीमा शुल्क से वित्तीय हानि के साथ साथ औद्योगिक हितों को हानि पहुंचती थी। अतः स्पष्टतः भारतीय नेताओं का यह मतव्य था कि वित्तीय हानि के प्रति विरोध प्रकट करके उसे भले ही सहन कर लिया जाए, चाहे इससे चिन्म को संतोष न मिले और न ही सिद्धांतों के पालन की प्रसन्नता मिले, परंतु औद्योगिक हानि को तो किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके परिणाम दूरगामी होते हैं और इससे राष्ट्रीय हितों को वास्तविक और व्यापक क्षति पहुंचती है।

संदर्भ

1. इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 165-9, फाने . पूर्वोद्धृत, पृ० 12-6; पी० जे० थामस : ग्रोथ आफ फेडरल फाइनाम इन इंडिया (मद्रास, 1939) पृ० 239-54
2. चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 339.
3. कड़िका, 82
4. 16 अगस्त 1901 हसांड (चौथी सिरिज) खंड XCIX लगभग 1208 इमी प्रकार 1899 में कर्जन ने घोषणा की कि बुरी हालत में श्री बजट में 4½ करोड़ लाभ की उपस्थिति यह दिखाती है कि भारतीय वित्तों में केवल सहन शक्ति ही नहीं प्रत्युत उनमें अद्भुत सामर्थ्य का श्रोत भी प्रतीत है (स्पीचेज, I पृ० 76) तथा देखिए जी० हैमिस्टन, हसांड (चौथी सिरिज) 4 सितंबर 1895, खंड XXXVI लगभग 1702-05.
5. रिय० आई० एन० सी, 1898 पृ० 131
6. एस० एन० वैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 242 तथा देखिए उनकी, स्पीचेज III पृ० 12 जान ब्राइट के उसी अवतारण को उद्धृत करते हुए पी० सी० राय ने 1895 में दावा किया कि ब्राइट की कसौटी पर तो भारत पर ब्रिटेन का शासन स्वतः विनिश्चित, स्वतः कलकित तथा स्वतः लाजित सिद्ध होता है. (पावर्टी पृ० 276-7)
7. वही, पूर्वोद्धृत, पृ० 207.
8. वही, पृ० 229-30. जोशी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया कि भारतीय वित्तों की प्रवृत्ति व्यर्थों में संतुलन माने की है अतः भारतीय वित्त को स्वस्थ कहा जा सकता है. जोशी के अनुसार यह संतुलन वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक न होकर देश की सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति

का ही सूचक है -- यह केवल प्रशासन की क्रूर शक्ति का ही प्रदर्शन है. ...व्यावहारिक रूप से अनुत्तरदायी और स्वेच्छाचारी विभाग की विवेकहीन नीति को ताज के व्यय निर्धारित करने की अनुमति दी जा रही है इस प्रकार से व्यवस्थित व्ययों से जनता पर कराधान का स्तर निश्चित किया जा रहा है, जिसका वस्तुतः जनता की कर भुगतान की क्षमता से किसी भी प्रकार का कोई सामान्य संबंध नहीं (वही, पृ० 207).

- 9 गोखले, स्पीचेज, पृ० 21.
- 10 वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 607-08 भारत सरकार का विशुद्ध राजस्व 1881-2 में 46-86 करोड़ रुपये और 1904-05 में 65 17 करोड़ रुपये था (इपीरियल नबेटियर आफ इंडिया, 1908 खंड IV पृ० 201)
- 11 चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 32८-8, दत्त, ई० एच०, II, पृ० 37-43, वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 85-91 और थामस पूर्वोद्धृत, पृ० 120
- 12 उदाहरणार्थ देखिए, रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेसिन कमीशन, 1880 खंड II पृ० 82, फाउलर हसाई (चौथी सिरीज) 15 अगस्त 1894, खंड XXVIII लगभग 1140, और स्ट्रेंजी, इंडिया (1903), पृ० 120-1
- 13 अध्याय 14 में रैवेन्यू के अंतर्गत 'इंडियन पोलिटिकल इकोनमी' संबंधी ग्रन्थ देखिए
- 14 आगे ओपीयम रैवेन्यू पर अनुभाग देखिए.
- 15 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 60 उन्होंने साथ में यह भी कहा : 'आप इस रकम को कर राजस्व कहें अथवा अपनी रुचि का कोई अन्य नाम दें सरकार इसे किसी भी रूप में अथवा किसी भी शैली में ग्रहण करे, इतना तो निश्चित है कि यह रकम सरकार के लिए देश की आय से ही ली जाती है इस तथ्य को तो नहीं बदला जा सकता है. भारत के संबंध में सरकार यह रकम भूमि लगान के रूप में लेती है, अफ्रीम कर के रूप में अथवा किसी भी अन्य रूप में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तथ्य यह है कि सरकार देश की कुल आय में से अपने लिए इतना अधिक राजस्व ले लेती है जो अन्यथा जनता के पास ही रहता' (वही) उन्होंने अपने इस मत को दोहराते हुए थोड़े समय के उपरान्त और अधिक सशक्त अभिव्यक्ति दी राजस्व के इस भाग को राजस्व, कर, किराया, भ्रष्टाचार, बरदान, अभिजाप अथवा भ्रष्टाचार की वर्णमाला के ए से जेड तक अक्षरों के पर अन्य किसी नाम से पुकारिए, सीधी सी सच्चाई तो यह है कि देश को अपनी आय से सरकार को उसके प्रयोजनों के लिए एक निश्चित भाग देना ही पड़ता है यह भाग न तो आकाश से बरसता है और न ही देश की सरकार द्वारा किसी आदमी से उत्पन्न किया जाता है (वही, पृ० 220) तथा देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 316, परिशिष्ट, पृ० 40 और आगे वाचा, सी० पी० ए० पृ० 539 चौथी, पूर्वोद्धृत, पृ० 223.
- 16 स्ट्रेंजी, इंडिया (1894) पृ० 395 तथा देखिए चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 347
- 17 कर्जन, स्पीचेज, खंड II पृ० 452 तथा वही, खंड III पृ० 146.
- 18 थामस पूर्वोद्धृत, पृ० 77 पर.
- 19 नोरोजी की पावर्टी पृ० 58 पर उद्धृत, 1880 के अकास आयोग की संगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति पर 4 ब्रिटिश का कर भार था (रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेसिन कमीशन, 1880 भाग II पृ० 93).
20. हसाई (चौथी सिरीज) 15 अगस्त 1894, खंड XXVIII, लगभग 1140 वित्त सदस्य एडवर्ड वा के अनुसार 1904 में कर भार का परिमाण केवल 1 42 प्रति व्यक्ति था (एन० सी० पी०

1904) खंड XLIII पृ० 534). स्ट्रेची : इंडिया (1903) पृ० 120 भी देखिए.

21. देखिए, पीछे अध्याय I.
22. चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 328 तथा पृ० 331.
23. कर्जन : स्पीचेज, खंड III पृ० 148 तथा जी० हैमिल्टन, इंडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 1902 लगभग 106; ला : फाइनांसल स्टैमेंट, 1903 कंठिका 35.
24. स्ट्रेची : इंडिया (1903) पृ० 119; वैस्टलैंड, एल० सी० पी० 1895 खंड XXXIV पृ० 436.
25. उदाहरणार्थ, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी ने 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की : 'यहां तक कि प्रेम के क्षेत्र में भी कोई अपेक्षाकृत सुंदर मूर्ति सामने नहीं आती किंतु ज्यों ही छानबीन करने वाली सचं साइट का प्रकाश उस पर डाला जाता है, मारा भ्रमजाल तत्काल लुप्त हो जाता है. (सी० पी० ए० में, पृ० 702).
26. हिंदू पायनियर, विभानबिहारी मजुमदार की हिस्टरी आफ पोलिटिकल थाट फ्राम राममोहन टू दयानंद (1882-4) खंड I (कलकत्ता, 1934) पृ० 91 पर उद्धृत.
27. दत्त, ई० एच० II पृ० 385 पर उद्धृत, और देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट डी०.
28. एस० एन० बॅनर्जी, स्पीचेज I पृ० 203.
29. रिब्यू आफ फासेट्स 'थी एसेज आन इंडियन फाइनांस', जे० पी० एस० एस०, खंड III सख्या 1 (जुलाई 1880), पृ० 80 हमारे पास जी० ए० मन्नेकर का कथन प्रमाण रूप में उपलब्ध है जिनके अनुसार यह समीक्षा जस्टिस रानाडे द्वारा लिखी गई थी. (मनकर : पूर्वोद्धृत, पृ० 214).
30. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 116.
31. आर० एन० पी० बंब, 4 फरवरी 1888. उसी मनोदशा में लिखते हुए 'हिंदी प्रदीप' ने 1 जनवरी 1879 के प्रक में टिप्पणी की : हमारी सरकार के पवित्र चरण असदिग्ध रूप से अत्यंत चमत्कारी हैं, जहां जहां पड़ते हैं, वह धरती और वहां की घटिया से घटिया वस्तु राजस्व का बहुमूल्य स्रोत बन जाती है. (आर० एन० पी० पी० एम०, 11 जनवरी 1879).
32. आर० एन० पी० बंब, 11 फरवरी 1888. अपने 5 मार्च 1888 के प्रक में इसी पत्र ने व्यंग्यात्मक ढंग से सरकार को बजट का घाटा पूरा करने के लिए लोगों को लूटने और हवा, मेलों, विवाह तथा वेश्यागमन पर कर लगाने की सलाह दी (आर० एन० पी० बंब 10 मार्च 1888).
33. सी० पी० ए०, पृ० 354 पर तथा देखिए पृ० 351 और 367. दो वर्ष उपरांत सयानी ने चेतावनी दी कि वर्तमान करो में वृद्धि करना अथवा और नए करारोपण करना राजनीतिक क्षतरे का विषय बन जाएगा क्योंकि भारतीय जनता में और अधिक करों के भुगतान की सामर्थ्य नहीं है (एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 531)
34. उदाहरण के लिए देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर, 24 अक्टूबर (आर० एन० पी० बंब, 30 अक्टूबर 1880); 'रिब्यू आफ दि इंडियन साल्ट टैक्स' जे० पी० एस०, जुलाई 1881 खंड IV संख्या 1), पृ० 60; नवाबभाकर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बंब०, 12 जनवरी 1884); संजीवनी, 6 मार्च, माधारणी 7 मार्च (वही, 13 मार्च 1886); महाराष्ट्र मित्र, 9 सित० (आर० एन० पी० बंब, 18 सितंबर 1885); एस० वी० सुब्बारायडु, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 70; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 220-1, 281, हिंदू 29 अगस्त 1887 गंगाली 3 मितंबर 1887; इंडियन स्पेक्टेटर, 28 अगस्त, 11 सितंबर, ज्ञान प्रकाश, 29 अगस्त, इंडियन यूनियन, 31 अगस्त, बिहार हेराल्ड और इंडियन कानिक्ल, 3 सितंबर, मुबोध पत्रिका, 4 सितंबर, इंदु प्रकाश, 5 सितंबर, इंडियन नेशन, 5 सितंबर तथा अन्य अनेक भारतीय समाचारपत्र (वी० ओ० आई०, अक्टूबर

- 1887); बोध सुधाकर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी 1888); मराठा, 22 जनवरी 1888; हितवादी, 22 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 20 मार्च 1895); बगवानी 20 अप्रैल (बही, 27 अप्रैल 1895); राय, पावर्टी, पृ० 260 तिलक, प्रोमीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे 1895, खंड XXXIII पृ० 90-1: पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 447-8; जी० बी० जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 203, 228-9; ट्रिब्यून, 16 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 25 जनवरी 1902); एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 259, 700; गोखले, स्पीचेज, पृ० 6-7, 21 परिशिष्ट, पृ० 1169 और 1178; नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 51; नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 120, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 747, 756, दत्त, ई० एच० II पृ० 559, 603.
- 35 राय, पावर्टी, पृ० 256-8; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 221-6; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 448; सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 348; बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 611; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 700; जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18965 और ई० ए०, पृ० 38-40; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 219-291. दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 141-2, ई० एच० II पृ० 383-4; गोखले, स्पीचेज, पृ० 6.
36. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 223
37. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 182
38. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 141, 156-7, 189, 292-4, 592. परिशिष्ट पृ० 38 एसेज, पृ० 374, पावर्टी, पृ० 60-1. 221; इंडियन स्पेक्टेटर, 24 जून (आर० एन० पी० बब, 30 जून 1883); तेलंग सेलेक्टड राइटिंग ऐंड स्पीचेज (बबई 1885) (इसे आगे सदर्थ के लिए स्पीचेज से संकेतित किया जाएगा), पृ० 222; एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III पृ० 143 और सी० पी० ए०, पृ० 703, राय, पावर्टी, पृ० 259; सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 347-8; नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 110; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 756, दत्त, ई० एच० II पृ० 603-04, ए० मुखर्जी, एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII पृ० 423-4 तथा देखिए पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 447-8, 451-2; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 276, 279-80, 291-2; ज्ञान प्रकाश, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 1903)
39. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 183
- 40 उदाहरणार्थ नोरोजी, पावर्टी, पृ० 60-1, 221-2 और स्पीचेज पृ० 156 और 293-4
41. सी० पी० ए०, पृ० 348.
- 42 नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 157. भारत के व्यर्थों पर उन्होंने विलबी आयोग को बताया कि किसानों पर कराधान मात्र इस दृष्टि से दुखदायक है कि यह दुखदायक बन जाता है (स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 51) तथा पावर्टी, पृ० 221-2.
- 43 सी० पी० ए०, पृ० 348.
- 44 तेलंग, स्पीचेज, पृ० 223, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 30-1; गोखले, स्पीचेज, पृ० 15, 21; दत्त, ई० एच० II पृ० 572; राय, पावर्टी, पृ० 258-9; बाबा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 32; विश्वम्भरनाथ, एल० सी० पी०, 1897 खंड XXXVI, पृ० 182; ए० मुखर्जी, एल० सी० पी० XLIII, पृ० 424.
45. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 226 तथा देखिए, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 219 और 291.
- 46 नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 116, 316, 361, 609 परिशिष्ट, पृ० 21; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 219

- और 29। तथा देखिए, तिलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1895 खंड XXXIII पृ० 91; दत्त, स्पीचेज, II पृ० 83-4; गुजराती, 22 मार्च (आर० एन० पी० बब, 28 मार्च, 1903)।
47. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 61 स्पीचेज, पृ० 131, 528; राय, पावर्टी, पृ० 260-1, मालवीय, स्पीचेज पृ० 221, नवी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 120; दत्त, ई० एच० II पृ० 377; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 10.
48. जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 45 तथा पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 574-5, 604.
49. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1-2, 8-9 तथा पृ० 6-7, 21, 71, 74 और 101 तथा देखिए, गोखले, रिप० आई० एन० सी०, 1904 पृ० 170 और आगे; वाचा, सी० सी० ए०, पृ० 610-1 एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 700; आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII
50. रिक्स ब्यापसन, एल० सी० पी० 1882 खंड XVI, पृ० 313-4, 1880 के भारतीय अकाल आयोग के अनुसार कराधान का भार पृथक पृथक वर्गों पर प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न था, भूमि से संबंधित जमींदार वर्गों पर यह भार 273 पौंड, कृषक श्रमिकों पर 1085 पौंड व्यापारियों और अधिकारियों पर 164 पौंड और हस्तशिल्पियों पर 1 पौंड था इस सगणना के उद्देश्य के लिए आयोग को अपनी इच्छाओं के नितांत प्रतिकूल भूमि लगान को समग्र कराधान में सम्मिलित करना पड़ा (रिपोर्ट्स आफ दि इंडियन फेमीन कमीशन, 1880, खंड II पृ० 93)
51. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 177.
52. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 152 तथा देखिए, पृ० 89, 100, 142
53. बही, पृ० 164.
54. बही, पृ० 185 तथा पृ० 165.
55. बही, पृ० 91 और देखिए, पृ० 100, 149.
56. आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 1888.
57. बही.
58. जे० पी० एस० एस०, जनवरी-अप्रैल 1888 (खंड X, सख्या, 13-4) पृ० 21. इसी प्रकार 4 फरवरी 1888 के सजीवनों ने निर्देश किया कि इस देश में धनिक वर्गों पर केवल उपयुक्त एवं पर्याप्त कर नहीं लगा, इसी ही बात नहीं, बल्कि बात यह है कि वह उतना कर भी नहीं देता जितना निर्धन वर्ग देता है (आर० एन० पी० बग० 11 फरवरी 1888).
59. राय, पावर्टी, पृ० 261 और 274. बाद में 1901 में उन्होंने सिफारिश की कि गरीबों पर कराधान भार को अवश्य कम करना चाहिए, जले ही इसके लिए उन करो को भारी खाते-पीते लोगों के कंधों पर ही क्यों न ढालना पड़े (इंडियन फेमिस, पृ० 67)।
60. गोखले, स्पीचेज, पृ० 40 तथा देखिए, गोखले, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1900 खंड XXXVIII पृ० 94, सोम प्रकाश, 24 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 29 जुलाई 1882); एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 704, दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 163, केसरी, 31 मार्च (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 1903).
61. राय, पावर्टी, पृ० 274-5 पर उद्धृत.
62. प्रमाण के रूप में देखिए, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 100, 140-2, 161-6.
63. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 222
64. उदाहरणार्थ, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 185, 221, 228; राय, पावर्टी, पृ० 241; जी० एस० अय्यर,

बिलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18646; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 250-2, 281; दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 133; स्पीचेज I पृ० 27, बार० एन० मघोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 83, ज्ञान प्रकाश, 16 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 18 जनवरी 1879); बोध मुधाकर, 22 जनवरी, (बही, 29 जनवरी 1879), नवविभाकर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 12 जनवरी 1884); सजीवनी, 18 जुलाई (बही, 25 जुलाई 1885), साधारणी, 7 मार्च, सजीवनी, 6 मार्च (बही, 13 मार्च 1886), हितवादी, 13 जुलाई (बही, 21 जुलाई 1900); जी० एम० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1900 पृ० 29, ए० बी० पी० 18 मार्च 1901, एडवोकेट, 2 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 4 फरवरी 1905)

- 65 प्रस्ताव XII इस प्रकार का एक प्रस्ताव लगभग इसी भाषा में कांग्रेस ने निम्नांकित वर्षों में पारित किया, देखिए, 1897 का प्रस्ताव IX, 1901 का प्रस्ताव VIII; 1902 का प्रस्ताव III और 1904 का प्रस्ताव III
- 66 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 185.
- 67 बही, पृ० 793-5 तथा पृ० 824, 1136. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जोशी ने अपनी उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत कृषि को भी शामिल किया था
- 68 गोखले, स्पीचेज, पृ० 13 तथा देखिए, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 710
- 69 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 1
70. जी० एम० जय : ई० ए०, पृ० 42-3; गोखले, स्पीचेज, पृ० 4, 15, 21, 73, दत्त, ई० एच० II पृ० 559, 596-7, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 691, 700-02, आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII
- 71 सी० पी० ए०, पृ० 700 पर
- 72 गोखले, स्पीचेज, पृ० 101
- 73 वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 533 नियचय ही यह कामचलाऊ तखमीना था फिर भी मेरे विचार में विचाराधीन विषय के लिए यह उपयुक्त और पर्याप्त था हमारे पास बहुत सारे उच्च सरकारी प्रवक्ताओं की मान्यताएँ प्रमाण रूप में उपलब्ध हैं कि किसी भी अन्य कराधान को महन करने की भारत की क्षमता पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो चुकी थी प्रमाण रूप में देखिए, एलगिन, स्पीचेज, पृ० 490
- 74 1880 में भूमि राजस्व में 21 1 करोड़, नमक कर से 7 1 करोड़, अफीम शुल्क से 10 4 करोड़, उत्पादन शुल्क से 3 1 करोड़, सीमा शुल्क में 2 5 करोड़ और आय कर (लाइसेंस कर) से 5 करोड़ रुपये की वसूली हुई, 1904 में इन करोड़ों से प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 28 3 करोड़, 7 9 करोड़ 9 0 करोड़, 7 9 करोड़, 6 4 करोड़ और 1 8 करोड़ रुपये थी. (पी० जे० वामस : पूर्वोद्धृत, पृ० 408).
- 75 लाइसेंस कर और आयकर के संक्षिप्त इतिहास के लिए देखिए, जे० पी० नियोनी : दि इवाल्थूशन आफ दि इंडियन इनकम टैक्स (लंदन 1929), प्रमथनाथ बैनर्जी : ए हिस्ट्री आफ इंडियन टैक्सेशन (कलकत्ता, 1930), और पी० के० आर० बी० राव टैक्सेशन आफ इनकम इन इंडिया (कलकत्ता, 1931).
76. वित्त सदस्य चार्ल्स ट्रिबेसियन. पी० बैनर्जी . इंडियन टैक्सेशन, पृ० 94 पर उद्धृत.
77. जान स्ट्रैची और रिचार्ड स्ट्रैची . दि फाइनांस ऐंड पब्लिक बक्स आफ इंडिया, पृ० 197.
- 78 पी० बैनर्जी : इंडियन टैक्सेशन, पृ० 72

79. आर० एन० पी० बंब, 12, 19, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 1878, आर० एन० पी० बंग०, 12, 19, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 2, 23 मार्च 1878, आर० एन० पी० एम०, अप्रैल 1878, आर० एन० पी० पी० एन०, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी, 9, 16 मार्च, 6 अप्रैल 1878; एल० एम० घोष : स्पीचेज, पृ० 6
80. उदाहरण के रूप में देखिए, ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 1, 8 जनवरी 1880; बंगाली, 4 दिस० 1880; नवविभाकर, 1 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 6 मार्च 1880); विवेकवादिनी, स० 12 (आर० एन० पी० एम०, मार्च 1880); बर्बई समाचार, 11 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 11 दिसंबर 1880); रास्त गुफ्तार, 27 मार्च, जामे जमशेद, 1 अप्रैल (वही, 2 अप्रैल 1881); इंडियन स्पेक्टेटर, 3 अप्रैल (वही, 9 अप्रैल 1881); नेटिव ओपीनियन, 17 अप्रैल (वही, 23 अप्रैल 1881); इंडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन, 12 मार्च (वही, 18 मार्च 1882); ए० बी० पी०, 16 मार्च 1882; अखबारे आम, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, 19 अप्रैल 1882); रहबरे हिंद, 24 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1882); भारत मिहिर, 14 मार्च, सहचर, 15 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 25 मार्च 1882); द्रविडावर्तमणि, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, अप्रैल 1883); इंडियन स्पेक्टेटर, 16 मार्च (बी०ओ०आई०, 31 मार्च 1884); बंगाली, 22 मार्च 1884.
81. आर० एन० पी० बंब, 19 जनवरी 1878.
82. वही, 29 अक्तूबर 1881. और देखिए बोध सुधाकर, 9 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 12 जनवरी 1878); रास्त गुफ्तार, 13 जनवरी (वही, 19 जनवरी 1878); कवि वचन सुधा, 21 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 26 जनवरी 1878); आफताबे पंजाब, 21 फरवरी (वही, 23 फरवरी 1878); ए० बी० पी०, 10 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 10 जनवरी 1878); भारत मिहिर, 17 जनवरी, सोम प्रकाश, 21 जनवरी (वही, 26 जनवरी 1878); साधारणी, 20 जनवरी (वही, 2 फरवरी 1878); सुदेशाभिमानी, 1 मई (आर० एन० पी० एम०, मई 1878); विवेकवादिनी, स० 12 (वही, मार्च 1880); आनंद बाजार पत्रिका, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 24 अप्रैल 1880); सोम प्रकाश, 7 जून (आर० एन० पी० बंग०, 12 जून 1880); एल० एम० घोष, स्पीचेज, पृ० 6; 16 मई 1880 को पूना की सावंजनिक सभा में स्वीकृत आपन, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खंड III, स० 1) पृ० 4.
83. जुलाई से दिसंबर 1878 तक के महीनों का आर० एन० पी० बंब, ए० बी० पी०, 21 फरवरी, प्रतिकार, 22 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 2 मार्च 1878); वर्ष 1879 में बर्बई, बंगाल, पंजाब, और उत्तर पश्चिम प्रांतों तथा अवध और मद्रास के नेटिव प्रेस के प्रतिवेदन. ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 1880; बंगाली, 4 दिस० 1880; आनंद बाजार पत्रिका, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 24 अप्रैल 1880); सोम प्रकाश, 7 जून (वही, 12 जून 1880); नवविभाकर, 21 जून (वही, 26 जून 1880); इंडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्तू० (आर० एन० पी० बंब, 29 अक्तूबर 1881)
84. सहचर, 14 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 26 जनवरी 1878); बनारस अखबार, 17 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 26 जनवरी 1878); आफताबे पंजाब, 21 फरवरी (वही, 23 फरवरी 1878); ए० बी० पी०, 2 जनवरी 1880; बंगाली, 17 जनवरी 1880; हिंदू हितैषिणी, 21 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 28 फरवरी 1880); नवविभाकर, 1 मार्च (वही, 6 मार्च 1880); साधारणी, 7 मार्च (वही, 13 मार्च 1880); भारत मिहिर, 9 मार्च (वही, 20 मार्च

- 1880); इंडियन स्पेक्टेटर, 7 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 12 मार्च 1881).
85. जे० पी० नियोगी : दि इवाल्फुनन आफ दि इंडियन इनकम टैक्स, पृ० 100-03.
86. वही, पृ० 101.
87. सोसैं मैटीरियल फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रीडम मूवमेन्ट इन इंडिया, खंड I, 1818-85 (बंबई, 1957) पृ० 29-40.
88. इंदु प्रकाश, 14 जनवरी, रास्त गुप्तार, 13 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 19 जनवरी 1878); जामे जमशेद, 24 जनवरी (वही, 26 जनवरी 1878), मफीजे बोधाना, 6 फरवरी, घाफताबे पंजाब, 21 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 23 फरवरी 1878); सोम प्रकाश, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 12 जनवरी 1878); वकीले हिंदुस्तान, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, 13 अप्रैल 1878); सुदेशानिमानी, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, अप्रैल 1878); साधारणी, 16 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 13 मार्च 1878); एल० एम० घोष, स्पीचेज, पृ० 6, 19 नए कर के अधिकार क्षेत्र से सरकारी कर्मचारियों और व्यवसाय में लगे हुए लोगों को बाहर रखने संबंधी प्रावधान की भर्त्सना करने के लिए मद्रास में एक जनसभा हुई. शम्भु उल अखबार, 18 मार्च (आर० एन० पी० एम०, मार्च 1878).
89. बंगाली, 17 जनवरी, 6 मार्च 1880; ए० बी० पी०, 2 जनवरी 1880; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 1880; आर० एन० पी० बंब, 4 सितंबर 1880 में प्रतिवेदित समाचारपत्र, हिंदू हितैषिणी, 21 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 28 फरवरी 1880); नवविभाकर, 1 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 6 मार्च 1880); साधारणी, 7 मार्च (वही, 13 मार्च 1880); भारत मिहिर, 9 मार्च (वही, 20 मार्च 1880); सहचर, 15 मार्च (वही, 27 मार्च 1880); इंडियन स्पेक्टेटर, 6 मार्च, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 12 मार्च, 9 अप्रैल 1881); नेटिव ओपीनियन, 17 अप्रैल (वही, 23 अप्रैल 1881), मुबोध पत्रिका, 19 फरवरी (वही 25 फरवरी 1882); मराठा, 30 अप्रैल 1882; नेटिव ओपीनियन, 16 अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 22 अगस्त 1885); इंडियन स्पेक्टेटर, 23 अगस्त (वही, 29 अगस्त 1885); जे० यू० याज्ञिक, रिप० आई० एन० सी० 1885, पृ० 67. और देखिए, आई० एन० सी० 1885 का प्रस्ताव VI.
90. जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खंड III, सख्या 17) पृ० 4.
91. देखिए, 2 जनवरी 1880 की अमृत बाजार पत्रिका और 19 दिसंबर 1884 का हिंदू तथा देखिए, ए० बी० पी०, 3 जनवरी, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 12 जनवरी 1878); हिंदू हितैषिणी, 12 जनवरी (वही, 26 जनवरी 1878); भारत मिहिर, 21 फरवरी (वही, 2 मार्च 1878); और साधारणी, 16 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 1878); और इंडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्टूबर (आर० एन० पी० बंब, 19 अक्टूबर 1881). 10 जनवरी 1878 के अमृत बाजार पत्रिका ने टिप्पणी की कि सरकार ने आय कर नहीं लगाया है क्योंकि उसे यूरोपियों और समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों का डर है.
92. बी० के० आर० बी० राव : टैक्सेसन आफ इनकम, पृ० 292. तथा पी० बैनर्जी : इंडियन टैक्सेसन, पृ० 127; ए कालविन, एल० सी० पी० 1886 खंड XXV पृ० 21 और आगे.
93. ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 1880; 22 दिसंबर 1881; बंगाली, 24 दिस० 1881; रास्त गुप्तार, मुजरात मित्र, बांबे क्रानिकल और अरुणोदय, 11 दिस० सूर्य प्रकाश, 10 दिस०, न्याय प्रकाश, 12 दिस०, कासिदे मुंबई, 16 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 17 दिसंबर 1881); बंबई समाचार, जामे जमशेद, 20 दिस० (वही, 24 दिस० 1881); सहचर, 28 दिस० 1881

(आर० एन० पी० बंग०, 7 जनवरी 1882); परिवर्तक, 1 जनवरी (वही, 14 जनवरी 1882); नसीमे आगरा, 30 दिसंबर 1881 (आर० एन० पी० पी० एन०, 10 जनवरी 1882); सोम प्रकाश, 5 अक्तूबर, सुरभि ओ पताका 7 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग०, 10 अक्तू० 1885); सहचर, 7 अक्तू०, भारत मिहिर, 8 अक्तू०, सजीवनी, 10 अक्तू० (वही, 17 अक्तू० 1885); वायस आफ इंडिया जनवरी 1886; इंडियन मिरर, 7, 9, 15 जनवरी, ट्रिब्यून, 9 जनवरी, बिहार हेराल्ड 19 जनवरी, इंडियन नेशन, 11 जनवरी, इंडियन इको 11 जनवरी (बी० ओ० आई०, जनवरी 1886); हिंदुस्तानी 8 जन०, अखबारे ग्राम 9 जन० (बी० ओ० आई०, जन० 1886), बंगाली 9, 16, 23 जन० 1886; इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का भारत सरकार को पत्र बंगाली, 23 जनवरी 1886. बाबे प्रेसीडेसी एसोसिएशन का भारत सरकार को विरोधपत्र. रिपोर्ट आफ बाबे प्रेसीडेसी एसोसिएशन 1885-6, पृ० 205-08; बंबई समाचार और जामे जमशेद, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 9 जनवरी 1886); इंदु प्रकाश, 11 जनवरी, 10 जनवरी के गुजराती, गुजरात मित्र, रास्त गुप्तार और येजदां परस्त. हितेच्छ, 14 जनवरी, पंडित, 15 जन० (वही, 16 जन० 1886); सुरभि ओ पताका, भारत मिहिर, 31 दिस० 1885; भेरी, 1 जन० नव मेदिनी, 3 जन० ढाका प्रकाश, 3 जन० सोम प्रकाश और नवविभाकर, 4 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 9 जनवरी 1886), सहचर, 6 जनवरी, सजीवनी, 9 जन० (वही, 16 जनवरी 1886); उत्कल दीपिका, 16 जनवरी, (वही, 30 जन० 1886); कर्णाटक प्रकाशिका, तिथिरहित. हिंदू जनभूषयो, तिथिरहित केरल मित्रन, तिथिरहित. शम्स उल अखबार, 8 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, फरवरी 1886); माडलिक, स्पीचेज, पृ० 660, एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज, III पृ० 1-9.

94. वायस आफ इंडिया, जन० 1886 तथा देखिए, इंडियन मिरर, 7, 9, 15 जनवरी, इंडियन इको, 11 जनवरी (बी० ओ० आई०, जन० 1886); बंगाली, 9, 16 जन० 1887; 1886 में बंबई प्रेसीडेसी एसोसिएशन का भारत सरकार को विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल; इंडियन स्पेक्टेटर, 10 जन० (आर० एन० पी० बंब, 16 जन० 1886); आर० एन० पी० बंग०, 16 जनवरी से 6 फरवरी 1886, एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III, पृ० 3-4.
95. रास्त गुप्तार, गुजराती, गुजरात मित्र और अरुणोदय, 11 दिस०, इंदु प्रकाश, 12 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 17 दिस० 1881); बंबई समाचार और जामे जमशेद, 20 दिस० (वही, 24 दिसंबर 1881)
96. सहचर, 7 अक्तूबर, सजीवनी, 10 अक्तू० (आर० एन० पी० बंग०, 17 अक्तू० 1885); सुरभि ओ पताका, 31 दिस० 1885, नवविभाकर, 4 जनवरी (वही, 9 जन० 1887); भारत मित्र, 7 जनवरी, उचित वक्त, 8 जनवरी, बगबासी, 9 जनवरी (वही, 16 जनवरी 1886); सहचर, 13 जन०, भारत मिहिर, 14 जन० (वही, 23 जनवरी 1886); सोम प्रकाश, 1 फरवरी (वही, 6 फर० 1886); बाबे प्रेसीडेसी एसोसिएशन का 1886 में भारत सरकार को ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल माडलिक, स्पीचेज, पृ० 651-60; एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III, पृ० 8.
97. जनवरी 1886 के वायस आफ इंडिया में भारतीय समाचार पत्रों की राय का सार-संक्षेप. 1886 में बाबे प्रेसीडेसी एसोसिएशन का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III, पृ० 8.
98. ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 1880; बंगाली, 9, 16 जन० 1886; भारत सरकार को इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का पत्र, बंगाली 23 जनवरी 1886 में; ट्रिब्यून, 9 जन० (बी० ओ० आई०, जन० 1886); जनवरी 1886 के वायस आफ इंडिया में भारतीय समाचारपत्रों के

- दृष्टिकोण का सार संक्षेप; 1886 में बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के सैक्रेटरी का भारत सरकार को ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल; सहचर, 30 दिसंबर 1885, सुरभि औ पताका, 31 दिसं 1885 (आर० एन० पी० बंग०, 9 जन० 1886); संजीवनी, 9 जनवरी (वही 16 जन० 1886)
99. ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 1880; 22 दिसं 1881; पूना सार्वजनिक सभा, 1881 का ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, खंड IV, स० 1 (जुलाई 1881) पृ० 15; सहचर, 7 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग०, 17 अक्तू० 1885). ट्रिब्यून, 6 फर० (बी० ओ० आई०, फरवरी 1886); मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 665.
100. पूना सार्वजनिक सभा का 1881 का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल. नवविभाकर, 4 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 9 जनवरी 1886); सहचर, 6 जनवरी (वही, 16 जनवरी 1886); सोम प्रकाश, 1 फरवरी (वही, 6 फरवरी 1886).
101. मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 661.
102. 1870 और 1872 के लिए देखिए, बी० बी० मजूमदार : पूर्वोक्त, पृ० 382-3 तथा ए० बी० पी०, 7 फरवरी 1871.
103. ए० बी० पी०, 2 जनवरी 1880; बंगाली, 17 जनवरी 1880; आनंद बाजार पत्रिका, 30 दिस० 1879; नवविभाकर, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 10 जन० 1880); नवविभाकर, 1 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 6 मार्च 1880); साधारणी, 7 मार्च (वही, 13 मार्च 1880); भारत मित्र 9 मार्च (वही, 20 मार्च 1880); सहचर, 15 मार्च (वही, 27 मार्च 1880); तथा देखिए पीछे पादटिप्पणियां 89-90.
104. हिंदू, 19 दिस० 1884; हनु प्रकाश, 3 मार्च 1884; इंडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंब, 29 अक्तू० 1881); 18 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 24 दिसंबर 1881); 9 मार्च 1884; सुबोध पत्रिका, 11 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 17 दिस० 1881); नवविभाकर, 19 दिस० (आर० एन० पी० बंग०, 24 दिस० 1881); आनंद बाजार पत्रिका, 26 दिस० 1881 (आर० एन० पी० बंग०, 7 जनवरी 1882); साधारणी, 15 जन० (वही, 21 जन० 1882); प्रभाती, 7 अप्रैल (वही, 7 अप्रैल 1883); स्वदेशमित्र, 11 दिस० (आर० एन० पी० एम०, दिस० 1884); दैनिक, 23 नव० (आर० एन० पी० बंग०, 28 नव० 1885). 1880 से पूर्व इस प्रकार की मांग के लिए देखिए, पीछे पादटिप्पणी स० 91.
105. प्रस्ताव VI. बाद में जब सरकार ने दोबारा कर लगाने का निर्णय किया तो गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को भारतीयों के प्रगतिशील वर्ग के मत के रूप में लेते हुए अपने पक्ष की स्वीकृति के तौर पर उद्धृत किया. (एल० सी० पी० 1886 खंड XXV, पृ० 27).
106. ए० बी० पी०, 14, 28 जन०, 4, 11 फरवरी 1886; हिंदू, 7, 9, 15 जनवरी 1886 (बी० ओ० आई० जनवरी 1886); मराठा, 17 जनवरी 1886 (मराठा ने जाय कर को कराधान पद्धति के स्थाई पक्ष बनाए जाने का विरोध किया) हनु प्रकाश, 25 जनवरी 1886; सुबोध पत्रिका, 24 जन० (आर० एन० पी० बंब, 30 जन० 1886); शिवाजी, 29 जन० (वही, 6 फरवरी 1886); दैनिक, 30 दिस० 1885 (आर० एन० पी० बंग० 2 जनवरी, 1886); भारतवासी, 9 जन०, साधारणी, 10 जनवरी (वही, 16 जनवरी (1886); आनंद बाजार पत्रिका 18 जन०, (वही 23, 30 जन० 1886); सुरभि औ पताका, 28 जन० (वही, 6 फरवरी 1886); आफताबे पंजाब, 13 जनवरी (बी० ओ० आई०, जनवरी 1886); इन पत्रों में कुछ ने इससे पहले यहां तक कि कुछ ही दिन पहले जाय कर का विरोध किया था. इसी सूची में प्रकाशित बंगाल के प्रमुख समाचारपत्रों की व्यापक संख्या को देखते हुए, 1886 में बंगाल के हिंदुस्तानी भाषाई

समाचारपत्रों के प्रतिवेदन में की गई इस स्वीकृति पर आश्चर्य होता है कि आनंद नाजार पत्रिका को छोड़कर किसी एक भी स्वदेशी भाषाई पत्र ने आय कर का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन नहीं किया। होम (पब्लिक) मार्च 1888, प्राग, 404 (ए) कठिका, 56.

107. रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 135.
108. मालवीय, स्पीचेज, पृ० 505.
109. रिप० आई० एन० सी० 1902, पृ० 133
110. सी० पी० ए०, पृ० 704.
111. मसानी . पूर्वोद्धृत, पृ० 318 पर.
112. दत्त, ई० एच० II पृ० 165. समान रूप से ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि राष्ट्र की आय को दुष्प्रभावित करने वाले करो को लौटाने की माग के समय उनके द्वारा उल्लिखित कर थे : भूमि लगान, भूमि लगान पर उपकर, नमक कर, कपास उत्पादन शुल्क. उनके द्वारा हटाए जाने के लिए उल्लिखित किए गए करों में आय कर सम्मिलित नहीं था. देखिए, ई० एच० II पृ० 596-7. इसी प्रकार 1904 के बजट पर उनके भाषण. बी० के० बोस और श्रीराम ने आय कर जारी रखने के पक्ष में ही भाषण दिया. (एल० सी० पी० 1904, खंड XLIII पृ० 432 और 508 क्रमशः).
113. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 141, 161-6, 190.
114. ज्ञापन, दिनांक 8 मार्च 1894. रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892-3 से 1895-6 पृ० 43 तथा देखिए, पूना सार्वजनिक सभा का ज्ञापन, दिनांक, 23 दिस० 1890, जे० पी० एम० एस०, जन० 1891. (खंड XIII स० 3) पृ० 80.
115. 20 सित० 1891, 7-8 मार्च 1894, 23 अक्तूबर 1902.
116. और देखिए, हिंदू, 8 अप्रैल 1889, 28 मई 1890, 3 दिसंबर 1890.
117. आर० एन० पी० बंब, 20 दिस० 1890.
118. आर० एन० पी० बंग०, 17 मार्च 1894 तथा सजीवनी, 30 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 6 सित० 1890).
119. तिरंगा निशान, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1889) इंदु प्रकाश, 8 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 13 दिस० 1890); नेटिव ओपीनियन, 14 दिस० (वही, 20 दिस० 1890); मराठा, 14 दिस० 1890; बंगबासी, 30 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 6 सित० 1890); हिंदुस्तानी, 21 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 27 जन० 1891); कैसरे हिंदू, 18 फरवरी (आर० एन० पी० बंब, 24 फरवरी 1894); स्वदेशमित्र, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 15 अप्रैल 1899); जमी उल उलूम, 7 नव० (आर० एन० पी० एन०, 13 नव० 1900); भवघ समाचार, 7 नव० (वही, 8 नव० 1902); हितवादी, 31 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग०, 8 नवंबर 1902); स्वदेशमित्र, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 1904).
120. देखिए आगे 'नमक कर' सबंधी भाग.
121. आर० एन० पी० बंग०, 15 नव० 1890, वही, 21 फरवरी 1891 और आर० एन० पी० एन०, 25 नवंबर 1890 क्रमशः.
122. जी० आर० चितनवीस, एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII पृ० 246; महाराजा आफ दरभंगा, एल० सी० पी० 1897. खंड XXXVI पृ० 210; आज़ुतोव मुखर्जी, एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII पृ० 416-20.

123. बी० बी० आई०, जनवरी 1886, वही, फरवरी 1886 और मार० एन० पी० बंब, 16 जनवरी 1886 क्रमशः.
124. जोषी, पूर्वोद्धृत, पृ० 141-2, 161, 165, 190
125. मार० एन० पी० बंब, 24 फरवरी 1894.
126. हिंदू, 7, 9, 12 जनवरी (बी० बी० आई० जनवरी 1886).
127. रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 1892-3 से 1895-6 पृ० 43.
128. बगबासी, 9 जनवरी (मार० एन० पी० बंग०, 16 जनवरी 1886); कंसरे हिंदू, 18 फरवरी (मार० एन० पी० बंब, 24 फरवरी, 1894); संजीवनी, 10 मार्च (मार० एन० पी० बंग०, 17 मार्च 1894); ए० मुखर्जी, एन० सी० पी०, 1904 खंड XLIII पृ० 420-2. दुर्भाग्यवश इस मामले की मुखर्जी द्वारा की गई वकालत कर हटाने की बैकल्पिक मांग के कारण स्वतः महत्वहान हो गई. (वही, पृ० 416-20).
129. आनंद बाजार पत्रिका, 30 दिसंबर 1879 (मार० एन० पी० बंग०, 10 जनवरी 1880); अक्षबारे आय, 21 जनवरी (मार० एन० पी० पी० एन०, 31 जनवरी 1882); मराठा, 17 जनवरी 1886; ट्रिब्यून, 20 फरवरी (बी० बी० आई०, फरवरी 1886); सुबोध पत्रिका, 24 जनवरी, इंदु प्रकाश 25 जनवरी (मार० एन० पी० बंब, 30 जन० 1886); शिवाजी, 29 जन० (वही, 6 फरवरी 1886); सहृदय, 30 दिस० 1885, सुरभि ओ पताका, 31 दिस० 1885 (मार० एन० पी० बंग०, 9 जनवरी 1886) आय० दर्पण, 8 जनवरी, सजीवनी, 9 जन० आनंद बाजार पत्रिका 11 जन० (वही, 23 जनवरी 1886); साधारणी, 17 जन०, आनंद बाजार पत्रिका, 18 जन० (वही, 23 जन० 1886), हिंदू, 28 दिस० 1887, 8 अप्रैल 1889, 28 मई 1890, मराठा, 14 दिस० 1890; इंदु प्रकाश, 8 दिसंबर (मार० एन० पी० बंब, 13 दिस० 1890); नेटिव ओपीनियम, 14 दिस० (वही, 20 दिस० 1890), सजीवनी, 30 अगस्त (मार० एन० पी० बंग०, 6 सित० 1890); स्वदेशमित्र, 5 अप्रैल (मार० एन० पी० एम०, 15 अप्रैल 1899); जमी उल उलूम, 7 नवंबर (मार० एन० पी० एन०, 13 नव० 1900); अक्ष समाचार, 7 नवंबर (मार० एन० पी० एन०, 8 नवंबर 1902)
130. 29 दिसंबर 1881 तथा ए० बी० पी०, 2 जनवरी, 5 मार्च 1880, 28 जनवरी, 1886, 20 दिसंबर 1891 और 23 अक्टूबर 1902.
131. ए० बी० पी०, 29 दिस० 1881; सुबोध पत्रिका, 11 दिसंबर (मार० एन० पी० बंब, 17 दिस०, 1881); हिंदू, 3 दिस० 1890; बगबासी, 30 अगस्त (मार० एन० पी० बंग०, 6 सित० 1890); ए० बी० पी०, 20 सितंबर 1891. आफताबे पंजाब, 2 नवंबर (मार० एन० पी० पी०, 14 नव० 1891), स्वदेशमित्र, 8 अप्रैल (मार० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 1904).
132. प्रत्यक्ष कर के भारत के अनुकूल न होने की धारणा पर प्रहार करते हुए उसने आगे लिखा : जबकि हम सबों में कटौती की मांग और सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को उठाने की प्रार्थना करना समाप्त नहीं करते, यहां यह स्मरण रखना हमारे लिए कर्तव्य रूप है कि भारत में प्रत्यक्ष करों का अत्यंत क्रूर, अत्यंत घातक और अत्यंत अन्यायपूर्ण भाग वह नहीं जिसका भुगतान हम स्वयं करते हैं प्रत्युत वह है जिसका भुगतान वास्तविक हूल जोतने वाले अपने जीवन रक्त से ही करते हैं.
133. तथा देखिए, ए० बी० पी०, 2 जनवरी 1880, 14, 28 जनवरी, 4 फरवरी 1886, 20 सित० 1891. 18 अप्रैल 1893. 7, 8 मार्च 1894, 23 अक्टूबर, 1902
134. और देखिए, हिंदू, 8 अप्रैल 1889, 28 मई 1890.

135. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 164-6 तथा नवविभाकर, 5 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 10 जनवरी 1880); सुबोध पत्रिका, 11 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 17 दिस० 1881); अखबारे आम, 21 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 31 जन० 1882); इंदु प्रकाश, 8 मार्च 1884; इंडियन स्पेक्टेटर, 9 मार्च 1884 स्वदेशमित्रन, 11 दिस० (आर० एन० पी० एम०, दिस० 1884); दैनिक, 23 नवंबर (आर० एन० पी० बंग०, 28 नवंबर 1885); मराठा, 17 जन० 1886. भारतवासी, 9 जनवरी, साधारणी, 10 जनवरी (वही, 16 जनवरी 1886); सुरभि ओ पताका, 28 जन० (वही, 30 जन० 1886); रिप० आई० एन० सी० 1887 पृ० 135; तिरंगा निशान, 13 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1889); सुधारक, 15 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 20 दिस० 1890); पूना सार्वजनिक सभा का 23 दिसंबर 1896 का ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1891 (खंड XIII स० 3), पृ० 80; हिंदुस्तानी, 21 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 27 जन० 1891), आफताबे पंजाब, 2 नवंबर (आर० एन० पी० पी०, 14 नवंबर 1891); सजीवनी, 10 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 17 मार्च 1894); स्वदेशमित्रन, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 15 अप्रैल 1899); उमी उल उलूम, 7 नवंबर आर० एन० पी० एन०, 13 नवंबर 1900) अवस समाचार, 7 नवंबर (वही, 9 नवंबर 1902); हितवादी, 31 अक्तूबर, बंगाली, 4 नव० (आर० एन० पी० बंग०, 8 नवंबर 1902); स्वदेशमित्रन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 1904).
- 136 नवविभाकर, 26 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 31 जनवरी 1880); ए० बी० पी०, 29 दिस० 1881); इंडियन स्पेक्टेटर, 18 दिस० (आर० एन० पी० बंब०, 24 दिस० 1881), और 9 मार्च 1884, सजीवनी, 10 अक्तू०, सोम प्रकाश, 12 अक्तू० (आर० एन० पी० बंग०, 17 अक्तूबर 1885)
137. प्रस्ताव संख्या VI.
- 138 ए० बी० पी०, 28 जनवरी, 11 फरवरी 1886, बंगाली, 9, 23 जनवरी 1886; दैनिक, 30 दिस० 1885 (अफ० एन० पी० बंग०, 2 जनवरी 1886); बंगवासी, 9 जनवरी (वही, 16 जन० 1886); दैनिक और आनंद बाजार पत्रिका, 11 जनवरी (वही) सहचर, 13 जन०, भारत मिहिर 14 जन०, सजीवनी और भारतवासी, 16 जनवरी, साधारणी, 17 जनवरी (वही, 23 जनवरी, 1886); सुरभि ओ पताका, 28 जनवरी (वही, 6 फरवरी 1886); एस० एन० डैनर्जी, स्पीचेज III पृ० 4; इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, बंगाली के 23 जन० 1886 के प्रक में प्रकाशित बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का ज्ञापन, रिपोर्ट आफ बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1885-6 पृ० 206-07.
- 139 प्रस्ताव संख्या VI.
140. मालवीय, स्पीचेज, पृ० 504.
- 141 1888 का प्रस्ताव VIII, ; 1889 का प्रस्ताव; III (जी); 1890 का प्रस्ताव II (जी); 1891 का प्रस्ताव IV, 1892 का प्रस्ताव V (बी), 1893 का प्रस्ताव III (बी); 1894 का प्रस्ताव XVI (बी); 1895 का प्रस्ताव XXII (ए); 1896 का प्रस्ताव XIII; 1898 का प्रस्ताव XX (बी); 1899 का प्रस्ताव XIV (III बी); 1900 का प्रस्ताव X (iii बी); 1901 का प्रस्ताव III तथा XIX (i ए)
142. उदाहरणार्थ, हिंदू 8 अप्रैल 1889; बंगवासी, सजीवनी, 30 सितंबर (आर० एन० पी० बंग०, 6 सित० 1890); नेटिव ओपीनियन, 14 दिसंबर (आर० एन० पी० बंब, 20 रिप० 1890); हिंदुस्तानी, 21 जनवरी (आर० एन० पी० बंब०, 27 जनवरी 1891); ए० बी० पी०, 20

सितंबर 1891; आफ्ताबे पंजाब, 2 नवंबर (आर० एन० पी० पी०, 14 नवंबर 1891); हिंदू, 4 अप्रैल 1894, 30 नवंबर 1895, स्वदेशमित्र, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 15 अप्रैल 1899); जमी उल उलुम, 7 नवंबर (आर० एन० पी० एन०, 13 नवंबर 1900), अवध ममाचार, 7 नवंबर (वही, 8 नवंबर, 1902); ए० बी० पी०, 12 मार्च 1902; हिनवादी, 31 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 8 नव० 1902)

143. जी० पी० सेन, रिप० आई० एन० सी०, 1887 पृ० 131-2. ज० सी० घोष, वही पृ० 133; मासवीय, स्पीचेज, पृ० 505-08; राय, पावर्टी, पृ० 267-71, जी० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० पी० 1894 खड XXXVIII पृ० 246, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1896, खड XXXV पृ० 285; जी० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० पी० 1899 खड XXXVIII पृ० 234; पी० ए० चारलू, वही, पृ० 243, गोखले, स्पीचेज, पृ० 10, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1902, खड XLI. पृ० 119; श्रंगम, वही, पृ० 142-3, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 704; सी० वाई० चितामणि, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 133.
144. रियायत की घोषणा करते हुए वित्त सदस्य मर एडवर्ड ला न टिप्पणी की. 'जहां तक आय कर में छूट की सीमा को बढ़ाने की बात है, हमारा विश्वास है कि हजार रुपये से कम रकम पर कर का भुगतान अधिकांशतः साधारण व्यापारियों, व्यापारिक संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों के बलकों और पेंशनभोगियों द्वारा किया जाता है जो आय के अपने निम्न तथा साधारण माध्यमों के कारण इस कर को असाधारण भार के रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त हमारे विचार में कर निर्धारकों की जांच सभी अनुचित कार्यवाही का शिकार भी अधिकांशतः इस निम्न वर्ग को होना पड़ता है. ये कर निर्धारक कभी कभी जांच के समय अन्यायपूर्ण ढंग से बहुत ऊंचे कर निर्धारित कर देते हैं. (फाइनेशनल स्टेटमेंट, 1903-04 कड़िका 39)
145. गोखले, स्पीचेज, पृ० 38 श्रीराम, बी० के० बोम०, पी० आनंद चारलू, एल० सी० पी०, 1903 खड XLI पृ० 100, 126 7, 140-2 क्रमशः, हिंदू, 18 मार्च 1903, ए० बी० पी०, 19, 23 मार्च 1903; बगाली, 21 मार्च 1903; 28 मार्च, 4, 11 अप्रैल 1903 क० बी० आ० आई० मे, 28 मार्च के आर० एन० पी० बब, मे, 28 मार्च, 4 11 अप्रैल 1903 के आर० एन० पी० बग मे, 4, 11, 22 अप्रैल 1903 मे आर० एन० पी० पी० मे, 28 मार्च, 4, 11 अप्रैल 1903 आर० एन० पी० यू० पी० मे तथा 21 मार्च 1903 के आर० एन० पी० एम० मे उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएं आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव म०, VIII
146. प्रमाण रूप में देखिए, गोखले, स्पीचेज, पृ० 77 और आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव म०, VII.
147. राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस पक्ष पर अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मानिक ने 23 अक्तूबर 1902 को सार्वजनिक रूप से बल दिया उन्होंने निर्देश किया कि वह आय कर का तब भी समर्थन कर रहे हैं जबकि उन्हें इस कर के कारण एक बहुत बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ेगा
148. अतः भारतीय नेताओं की बड़ी संख्या वित्त सदस्य ए० कालविन की 1886 में उच्च वर्गों पर इस निंदापरक टिप्पणी से बच गई कि ये लोग जनता पर कराधान का भार ढालने के लिए तो उत्सुक हैं परंतु अपनी उगली भी छुआना नहीं चाहते. फलतः ये वर्ष विशेषतः व्यापारी और व्यवसायी लोग जिस सरकार की छत्रछाया में फलते-फूलते हैं, उस सरकार के समर्थन के लिए कर के रूप में उसके प्रति अपना कोई भी योगदान नहीं देते कालविन ने अपने मित्रों, संपादकों का करारहित उल्लेखनीय आय अर्जन करने के लिए मचाक उड़ाया तथा उनसे जनता के भार में

उनके समुपयुक्त भाग की उगाही द्वारा उच्च तथा मध्यवर्ग को कर से बचने के इस 'फलक' से मुक्त करने का वचन दिया. (एल० सी० पी० 1886 खंड-25 पृ० 11 और 18) जैसा हम दिखा चुके हैं, भारतीय पत्रकार तथा अन्यान्य राष्ट्रीय नेता इस कार्य में सरकार की सहायता करने के लिए बाधे से भी अधिक मार्ग तक आगे बढ़ने को सहमत थे. वस्तुतः जैसा कि नमककर वाले अगले भाग में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, सरकार ने ही इस संबंध में इनकार का रवैया अपनाया. दो वर्ष बाद सरकार ने इस राह पर आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया. भारतीय नेताओं के पास इस इनकार की तीव्र आलोचना का मार्ग ही बचा था. तुलनीय इफरिन मिनिट्स, एन्सलोजर टु डिस्पैच (पब्लिक) आफ गवर्मेंट आफ इंडिया, सख्या 68 दिनांक 6 नवंबर 1888.

149. उदाहरण के रूप में 8 अप्रैल 1889 के धंक में हिंदू ने निर्देश किया कि निम्न मध्य वर्ग का सालाना 500-1000 उपाजर्जन करने वाला व्यक्ति आय कर चुकाने की अच्छी स्थिति में था उस व्यक्ति की अपेक्षा जो बेचारा नमक कर का भुगतान करता है. पत्र ने इस आधार पर मांग की कि प्रत्याशित राहत देने के किसी भी प्रश्न पर इन दोनों में निर्धन व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. और देखिए एस० एन बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 703-04; और पी० ए० चार्ल्स, एल० सी० पी० 1902. खंड XLI, पृ० 119. कराधान में किसी प्रकार की राहत आय कर की अपेक्षा नमक कर और भूमि लगान के भार को हलका करने के दृष्टिकोण के लिए देखिए, ए० बी० पी०, 4 फरवरी 1886; मराठा, 14 दिस० 1890; सजीवनी, 30 अगस्त (वार० एन० पी० बंग०, 6 सित० 1890); पूना सार्वजनिक सभा का 23 दिस० 1890 को प्रेषित ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जनवरी, 1891 (खंड XIII स० 3) पृ० 80; मराठा, 29 मई 1904.
150. 1882 में इंग्लिश लैजिस्लेटिव कौंसिल में कलकत्ता के व्यापारियों के प्रतिनिधि दुर्गाचरण साहा और बंगाल के जमींदारों के प्रतिनिधि जीतेन्द्र मोहन टैगोर ने नमक कर में कटौती का विरोध किया. उन्होंने इसके बदले लाइसेंस कर को हटाने की सिफारिश की (एल० सी० पी०, 1882 खंड XXI पृ० 290-1, 304), 1889 में दुर्गाचरण साहा ने नमक कर में कटौती का विरोध किया और उनके बदले आय कर समाप्त करने का सुझाव दिया. उनके अनुसार आय कर समाप्त करने से जनता को ठोस और वास्तविक राहत मिलेगी तथा लोग इसका सचमूच ही स्वागत करेंगे. (एल० सी० पी०, 1889, खंड XXVIII पृ० 141). 1890 में बंगाल के राष्ट्रीय वाणिज्य सदन (बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स) ने सरकार के पास आय कर समाप्त करने के लिए ज्ञापन भेजा (चैम्बर की 1890 की रिपोर्ट, पृ० 23)
151. बंगाल और असम को उनकी जबरूरत का मारा नमक इन्लेड और यूरोप से मिलता था. इसका प्रमुख कारण यह था कि देशी नमक उद्योग आयातित नमक की प्रतियोगिता नहीं कर सकता था. यह आयातित नमक वस्तुतः विदेशी पोतों में पोत के भार को सतुलित करने के लिए लादा जाता था. स्थानीय नमक पर और आयातित नमक पर शुल्क लगाने के उपरांत दोनों का मूल्य बराबर हो जाता था. (पी० बैनर्जी : इंडियन टैक्सेशन, पृ० 280-6; बकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 457-8).
152. 1859 में यह दरें निम्नलिखित रूप से थी :
बंगाल में 2 र० 8 आने प्रति मन, मद्रास में 14 आने प्रति मन, बंबई में 12 आने और उत्तरी भारत में 2 रुपये प्रति मन (पी० बैनर्जी : इंडियन टैक्सेशन, पृ० 278).
153. जान और रिचर्ड स्ट्रैची : पूर्वोद्धृत, पृ० 219-32.
154. उदाहरण के रूप में देखिए, पी० बैनर्जी : इंडियन टैक्सेशन, पृ० 277. बी० बी० मजूमदार : पूर्वोद्धृत, पृ० 204, 484-5; दत्त, ई० एच० II पृ० 150-1

155. प्रमाण के रूप में देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 178. एसेज, पृ० 107; नेटिव ओपीनियन, 18 अगस्त (आर० एन० पी० बग, 24 अगस्त 1872), सत्य शोधक, 5 सितंबर जगन्मित्र, 6 सित०, ज्ञान प्रकाश, 16 सित० (वही, 18 सितंबर 1875), बर्बई समाचार, 21 सित० (वही, 25 सितंबर 1875), शुभसूचक 22 जनवरी और रास्त गुप्तार, 14 जनवरी (वही, 20 जनवरी 1877), सूर्य प्रकाश, 5 जनवरी, गुजरात मित्र, 6 जनवरी, जामे जमशेद, 10 जन० (वही, 12 जनवरी 1878); इंदु प्रकाश, 14 जनवरी रास्त गुप्तार, 13 जन० (वही, 19 जनवरी 1878); नेटिव ओपीनियन, 20 जन० (वही, 26 जन० 1878); बाबे क्रानिकल, 14 मार्च, जामे जमशेद, 17 मार्च (वही, 20 मार्च 1880), 'दि फाइनासेज आफ इंडिया ग्रैंड लाई लितन' जे० पी० एम० एस०, अप्रैल 1880 (खंड II, स० 4) पृ० 30, प्रोसीडिंग्स आफ दि समा, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खंड III स० 1), पृ० 3, 'दि वायसरायल्टी आफ लाई लितन', वही, पृ० 63, भारत मिहिर, 27 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 7 अगस्त 1880), मराठा, 15 मई 1881; 'दि इंडियन साल्ट टैक्स, ए बुक रिव्यू', जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) पृ० 59-61, इंडियन स्पेक्टेटर, 14 अगस्त (आर० एन० पी० बग, 20 अगस्त 1881); केमरी, 23 अगस्त (वही, 3 सितंबर 1881), इंडियन स्पेक्टेटर और रास्त गुप्तार, 29 जनवरी (वही, 4 फरवरी 1882), हिंदी प्रदीप, जनवरी 1879 (आर० एन० पी० पी० एन०, 11 जनवरी 1879).
- 156 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 215.
- 157 बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धृत, पृ० 314 और 317
- 158 1877 में पत्रिका द्वारा अपनाई स्थिति के लिए देखिए, वही, पृ० 383 1881 में उसके रवैये के लिए देखिए 30 जून 1881 का उसका प्रक, और देखिए, नवविभाकर, 26 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 31 जनवरी 1880); आनंद बाजार पत्रिका, 11 जुलाई (वही, 23 जुलाई 1881)
159. ए० बी० पी०, 30 जून 1881 तथा आनंद बाजार पत्रिका, 11 जुलाई 1881 पूर्वोक्त स्थल.
- 160 मराठा, 2 अप्रैल 1882, बर्बई समाचार और जामे जमशेद, 10 मार्च (आर० एन० पी० बग, 11 मार्च 1882); अरुणोदय, नेटिव ओपीनियन, रास्त गुप्तार और इंडियन स्पेक्टेटर, 12 मार्च (वही, 18 मार्च 1882), सोम प्रकाश, 13 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 18 मार्च 1882), मुलभ समाचार और बगबासी, 18 मार्च (वही, 25 मार्च 1882), साधारणी, 19 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1882).
161. ए० बी० पी०, 16 मार्च 1882, भारत मिहिर, 14 मार्च, सहचर, 15 मार्च, नवविभाकर 20 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 25 मार्च 1882), चारुवर्त और आनंद बाजार पत्रिका, 20 मार्च, बिहार बहु, 30 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1882), परिदर्शक, 26 मार्च (वही, 8 अप्रैल 1882); अखबारे आम, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, 19 अप्रैल 1882), रहबरे हिंद, 24 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1882).
- 162 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 89-100 तथा देखिए पृ० 3
- 163 रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 69 और 73.
164. मराठा, 25 जन०, 22 मार्च 1885; सिबाजी, 23 जनवरी, जामे जमशेद, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग, 31 जन० 1885), नेटिव ओपीनियन और इंडियन स्पेक्टेटर, 22 मार्च (वही, 28 मार्च 1885); हिंदू, 3 अप्रैल 1885, स्वदेशमित्र, 18 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, जनवरी 1886); बंगबासी 2 और 23 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 9 और 30 जनवरी 1886).

165. देखिए पीछे पादटिप्पणी संख्या, 100. उदाहरणार्थ ट्रिब्यून, 1 मई (बी० ओ० आई०, मई 1886).
166. एल० सी० पी० 1888 खंड XXVII, पृ० 20.
167. थामस, पूर्वोद्धृत, पृ० 498
168. मराठा, 22 और 29 जनवरी 1888; हिंदू, 25 जन० 1888; बंगाली, 28 जन० 1888; ए० बी० पी०, 26 जन० 1888; नेटिव प्रेस बंबई के रिपोर्टर ने 28 जनवरी और 4 फरवरी 1888 को समाप्त होने वाले सप्ताहों की रिपोर्टों में लिखा कि इस सप्ताह के लगभग सभी समाचारपत्रों ने नमक कर में वृद्धि के संबंध में न्यूनाधिक रूप में रोष प्रकट किया है. और देखिए, आर० एन० पी० बंब, 11 फरवरी 1888; संजीवनी, 21 जनवरी, नवविभाकर, साधारणी, 23 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 28 जन० 1888); सुरभि ओ पताका, 26 जनवरी, प्रियबंधु और समय, 27 जनवरी, बंगदासी, 28 जन०, ढाका प्रकाश, 29 जन० (वही, 4 फरवरी 1888); हिंदू रंजिका, 1 फरवरी, जगतवासी, 2 फरवरी, प्रतिकार, 3 फरवरी (वही, 11 फरवरी 1888); आर० एन० पी० एम० 31 जन०, 15, 29 फरवरी 1888 में उल्लिखित लगभग सभी समाचारपत्र. कोहेनूर, 28 जनवरी, (आर० एन० पी० पी० एन०, 31 जन० 1888); हिंदुस्तान, 1, 2, 3 फरवरी, पंजाबी अखबार, 4 फरवरी सुबोध सिंधु, 1 फर० (वही, 7 फरवरी 1888); अवध अखबार, 10 फरवरी (वही, 14 फरवरी 1888); वायस आफ इंडिया के कार्यालय में प्राप्त समाचारपत्रों द्वारा अभिव्यक्त मत को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उसके संपादक ने लिखा कि अधिकांश ने नमक कर में वृद्धि के प्रति तीव्र विरोध प्रकट किया है, बी० ओ० आई०, फरवरी 1888; नेटिव ओपी-नियन, 22 जनवरी, इंडियन नेक्शन, 23 जनवरी, इंडियन यूनियन, 25 जन०, पीपुल्स फ्रेंड्स, 28 जन० (बी० ओ० आई०, फरवरी 1888); बिहार हेराल्ड और ट्रिब्यून, 11 फरवरी (वही, मार्च 1888).
169. आर० एन० पी० बंब, 4 फरवरी 1888.
170. वही, 28 फरवरी 1888 इसी प्रकार मुदु स्वर वाले इंदु प्रकाश ने अपने 30 जनवरी 1888 के शंक में चेतानवी देते हुए लिखा : कहा जाता है कि जैसे साहें डलहौजी ने अधिवहन नीति अपना कर साहें केनिंग ने लिए विद्रोह से जूझने का वातावरण तैयार किया था, उसी प्रकार साहें डफरिन भी भारतीय जनता पर विभिन्न करों की वृद्धि द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए कदाचित्त वैसा ही वातावरण तैयार कर रहे हैं. (आर० एन० पी० बंब, 4 फरवरी 1888).
171. आर० एन० पी० बंब, 17 मार्च 1888.
172. आर० एन० पी० बंग० 4 फरवरी 1888. बंबई के 'सत्य बोधक' ने अपने 25 जनवरी 1888 के शंक में टिप्पणी की कि 'इस प्रकार की असम्य भूल करके साहें डफरिन ने भारतीय जनता की दृष्टि में अपने को घृणा का पात्र बना दिया है. (आर० एन० पी० बंब, 28 जनवरी 1888) 22 जनवरी के शंक में कुचरात मिश्र ने व्यंग्यपूर्णक लिखा कि साहें डफरिन 'इस देश से बदनाम होकर ही जाएगा. भारतीय लोग उसकी अवहेलना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें कीमतीसौध इस व्यक्ति से छुड़कारा मिले !' (वही).
173. बीबी, पूर्वोद्धृत, पृ० 137-90. सरकारी नीति के अन्वय से असंतुष्ट उन्होंने घोषणा की : वायसराय और राज्य सचिव आठे आठे रहते हैं, उनकी नीति भी बुलबुलों के समान क्षणभर के लिए दीप्त रहकर जल में तल के लिए बिनीन हो जाएगी, परंतु करोड़ों दुखी और श्लेश्वस्त भारतीयों का संत नहीं हो पाएगा. सांविधानिक रूप से उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं परंतु उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो अपने पर किए गए अन्याय और प्रत्याचार को चुपचाप सहने

कर से' (वही, पृ० 140).

174. प्रस्ताव सं० XV.
175. रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 179.
176. वही, पृ० 179-80.
177. इडियन मिरर, 22 फरवरी (बी० ओ० आई०, फरवरी 1888); सोम प्रकाश, 23 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 28 जन० 1888); बर्दवान सजीवनी, 24 जनवरी, सहचर, 25 जन० (वही, 4 फरवरी 1888).
178. 1899 का प्रस्ताव III (i), 1890 का प्रस्ताव V; 1891 का प्रस्ताव VI (ए), 1892 का V (ए), 1893 का VII (ए), 1894 का XVI (ए), 1895 का XIX, 1896 का VIII, 1897 का IV, 1898 का XX, 1899 का XIII, 1900 का X, 1901 का XIX, 1902 का XIII. पूना सार्वजनिक सभा का 23 दिस० 1890 का जापन, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1891 (खंड XIII सं० 3) पृ० 79-80. विभिन्न प्रांतीय कांग्रेसों ने भी अपने वार्षिक अधिवेशनों में इस प्रश्न पर विचार किया.
179. नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 177. स्पीचेज, पृ० 142 (उन्होंने नमक कर को किसी सभ्य देश में प्रचलित राजस्व पद्धतियों में सर्वाधिक क्रूर बताया); वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1890. पृ० 37-9, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 158; एम० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III पृ० 160; एस० एंड डब्ल्यू०, पृ० 312; रिपोर्ट आफ दि बंगाल नेशनल चैंबर आफ कामर्स 1888, पृ० 34; राय, पावर्टी, पृ० 266-7; पी० ए० चारल्ट, एल० सी० पी० 1896, खंड XXXV पृ० 84, 285; जो० बी० जोन्सो, पूर्वोद्धृत, पृ० 191-202, 1136; जो० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० पी० 1899, खंड XXXVIII पृ० 234; पी० ए० चारल्ट, वही, पृ० 243 और एल० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 118.
180. उदाहरण के रूप में देखिए, आई० एन० सी० 1890, पृ० 39 और रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 151.
181. उदाहरण के रूप में, बंगाली, 9 मार्च 1889; ओनामी अखबार, 7 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी 1889); कोहेनूर, 5 मार्च (वही, 9 मार्च 1889); मराठा, 14 दिस० 1890, 23 जन० 1891; हिंदू, 10 जन० 1891; बंगाली, 28 मार्च 1891; आर० एन० पी० बब, 28 मार्च और 4 अप्रैल 1891; पैसा अखबार, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 18 अप्रैल 1891); अखबारे आम, 16 अप्रैल (वही, 25 अप्रैल 1891).
182. रामगोपाल, पूर्वोद्धृत, पृ० 45, 47.
183. स्वदेशमित्र, 16 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 4 दिस० 1900); बंगाली, 16 अक्टूबर 1901; भारत जीवन, 17 फरवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 22 फर० 1902); गोखले, स्पीचेज, पृ० 10-3; पी० ए० चारल्ट, एल० सी० पी० 1902, खंड XLI पृ० 118-9; हितवादी, 4 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 12 अप्रैल 1902); आई० एन० सी० 1902 का प्रस्ताव XIII. स्वदेशमित्र, 17 जन० (आर० एन० पी० एम०, 17 जनवरी 1903); 1902 की कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण करते हुए एस० एन० बैनर्जी ने घोषणा की कि यदि करों में राहत देनी ही है तो विचारणीय तथ्य यह है कि कटौती के लिए किस कर को प्राथमिकता देनी चाहिए. मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि नमक कर में ही सर्वप्रथम कटौती की जानी चाहिए (सी० पी० ए०, पृ० 703).

184. बाबा, स्पीचेज, पृ० 434.
185. आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव VIII. गोखले, स्पीचेज, पृ० 38, 40-1; श्रीराम तथा पी० ए० चारनू, एल० सी० पी० 1903 खंड XLII पृ० 99-100 और 140-2; मराठा, 22 मार्च 1903; हिंदू, 18 मार्च 1903; बंगाली, 19, 21, 25 मार्च 1903; वायस आफ इंडिया, 21 मार्च 1903, मद्रास स्टैंडर्ड, 18 मार्च (बी० ओ० आई०, 28 मार्च 1903); इंदु प्रकाश, 19 मार्च, इंडियन मिरर, 20 मार्च, इंडियन सोशल रिफार्मर, 22 मार्च (वही, 4 अप्रैल 1903), एडवोकेट और न्यू इंडिया, 26 मार्च (वही, 11 अप्रैल 1903); आर० एन० पी० बंग, 21, 28 मार्च, 4 अप्रैल 1903, आर० एन० पी० बंग०, 28 मार्च, 4 अप्रैल 1903; आर० एन० पी० एम०, 21, 28 मार्च 1903; आर० एन० पी० यू० पी०, 28 मार्च, 4, 11 अप्रैल 1903; आर० एन० पी० पी०, 28 मार्च, 4, 11, 25 अप्रैल 1903 में उल्लिखित समाचारपत्र.
- 186 उदाहरण के रूप में हिंदू, 18 नव० 1903; हिंदुस्तान रिव्यू और कायस्थ समाचार, सितंबर 1902; गोखले, स्पीचेज, पृ० 77-9; आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII (बी).
187. आई० एन० सी० 1905 का प्रस्ताव VII. गोखले, स्पीचेज, पृ० 93-5; मराठा, 26 मार्च 1905; बंगाली, 28 मार्च 1905, आर० एन० पी० बंग, 25 मार्च, 1, 8 अप्रैल 1905, आर० एन० पी० बंग०, 1, 8 अप्रैल 1905, आर० एन० पी० एम०, 1, 8 अप्रैल 1905 में उल्लिखित समाचारपत्र, सिटीजन, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० यू० पी०, 8 अप्रैल 1905).
- 188 डी० पी० सर्वाधिकारी, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 43-4. उन्होंने नमक कर में कटौती को मद्रास धीरे बर्बई की (वर्गगत) मांग बताते हुए उसकी आलोचना की. दैनिक औ समाचार चंद्रिका, 20 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 24 फरवरी 1894)
- 189 ए० बी० पी०, 4 दिस० 1902, 12 जन०, 23, 24 मार्च 1903, 27 मार्च 1905 उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों में एक यह था कि नमक कर में किसी भी प्रकार की कटौती का लाभ लिबरल और चेम्बायर के नमक व्यापारियों को ही मिलेगा
190. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 213-6, 'दि इंडियन साल्ट टैंक्स' जे० पी० एम० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV नं० 1) पृ० 59-61, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 91; केसरी, 24 जनवरी (आर० एन० पी० बंग, 28 जनवरी 1888), सजीवनो, 28 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 4 फरवरी 1888), हिंदुस्तान, 1, 2, 3 फरवरी, सुबोध सिन्धु, 1 फरवरी पंजाबी अखबार, 4 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फरवरी 1888), एस० एन० बेंनर्जी, स्पीचेज III, पृ० 161 और सी० पी० ए०, पृ० 703, बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 38, पैसा अखबार, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 18 अप्रैल 1891); राय, पावर्टी, पृ० 261-2; गोखले, स्पीचेज, पृ० 13, 94, 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में इसी आपत्ति को चिन्तात्मक भाषा में प्रकट करते हुए पंजाब के लाला भुरलीशर ने नमक कर को 'मूख और व्यास पर, मानव जीवन पर कर' बताया. (रिप० आई० एन० सी०-1890 पृ० 42).
191. प्रमाण के रूप में देखिए, इयूक आफ आरमिल का 21 जनवरी 1869 का संप्रेषण, जान स्ट्रेची तथा रिचार्ड स्ट्रेची : पूर्वोद्धृत, पृ० 222-3 पर; लिटन, एल० सी० पी० 1878 खंड XVII पृ० 99-100, वेस्टलैंड, एल० सी० पी० 1888 खंड XXVII पृ० 20.
192. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 184-5.
193. रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 179. 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में यही तथ्य प्रस्तुत करते हुए मोहन चटर्जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा 'जब उच्च पद प्रतिष्ठित और विलासिता की

गोद में लोटते हुए महानुभाव कहते हैं, 'अरे गरीब आदमी, इसे महसूस नहीं करेगा' तो हमें यह बहुत दुःखदायी, बहुत निरुत्साहित करने वाला तथा बहुत हृदयद्रावक लगता है वस्तुतः हमारे पास इस मूर्खता, गनता तथा स्वार्थपरता को सही रूप में परिभाषित करने के लिए शब्द ही नहीं' (रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 46) इसी प्रकार की अन्य टिप्पणियों के लिए देखिए, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 186-7; नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 64; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 30-1; राय, पावर्टी, पृ० 265; हिंदू, 18 नवंबर 1903.

- 194 रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 36
195. वही, पृ० 37 तथा देखिए वाचा को सी० एल० पारिख . पूर्वोद्धृत, पृ० 345 पर
- 196 नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 178; एस० ए० स्वामिनाथ अय्यर रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 69; बंबई के नागरिकों के द्वारा दिनांक 18 मार्च 1888 को प्रस्तुत सार्वजनिक आपन, जे० पी० एस० एस०, जन-अप्रैल 1888 (खंड X स० 3-4) पृ० 18, बंगाली, 28 जन० 1888, इंडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन, 22 जन०, इंडियन नेशन, 23 जन०, इंडियन यूनियन, 25 जनवरी, पीपुल्स फ्रैंड, 28 जन० (वी० ओ० आई०, फरवरी 1888), बिहार हेराल्ड, ट्रिब्यून, 11 फरवरी (वही, मार्च 1888), स्वदेशमित्र, 28 जन० (आर० एन० पी० एम०, 31 जन० 1888) एन० बी० बरवे, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 179, एस० एन० बैंनर्जी और एम० तथा डब्ल्यू०, पृ० 312, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 37 और स्पीचेज, पृ० 414, जी० एस० अय्यर, बिलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18762, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 30-1, राय, पावर्टी, पृ० 265-6, पी० ए० चारनू, एल० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 118, हिंदू, 18 नवंबर 1903 नमक कर में वृद्धि से प्रभावित भारतीय जनता के दुर्भाग्य का सजीव चित्र खींचते हुए जी० के गोखले ने 1890 में घोषणा की कि इस वृद्धि ने अकाल की सीमा पर जीवन निर्वाह करने वाले निर्धन तथा अभावग्रस्त लोगों के भयंकर कष्ट, विषम दुःख, गहन बाधाओं और भारी कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया है जी० वी० जोशी ने इस विषय पर अपने विस्तृत लेख में इस तथ्य को भली प्रकार उजागर किया गोखले, रिप० आई० एन० सी०, 1890, पृ० 40; आई० एन० सी० 1895 की रिपोर्ट, पृ० 150-1, स्पीचेज, पृ० 11, 95, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 83-105, 137-90 191-202 विशेष रूप से देखिए, पृ० 3, 92, 140, 149, 167, 185-7, 195, 1136
197. 1888 का प्रस्ताव IV; 1895 का प्रस्ताव XIX, 1896 का प्रस्ताव VIII 1897 का प्रस्ताव IV, 1898 का प्रस्ताव XX (11 बी), 1899 का प्रस्ताव XIV (11 बी), 1900 का प्रस्ताव X (11 बी) 1901 का प्रस्ताव XIX (11 बी)
- 198 नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 178
- 199 जे० पी० एस० एस०, अप्रैल 1880 (खंड II स० 4) पृ० 30
- 200 सजीवनी, 28 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 4 फरवरी 1888), पूना में पारित प्रस्ताव, जे० पी० एस० एस०, जन०-अप्रैल 1888 (खंड X स० 3-4) पृ० 31; जे० मुद्दालियार, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 46; गोखले स्पीचेज, पृ० 40
201. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 91
- 202 वही, पृ० 185 तथा देखिए, पृ० 149, पृ० 188
- 203 आरगिल के ड्यूक का 1869 का संप्रेषण, जान स्ट्रेची और रिचार्ड स्ट्रेची . पूर्वोद्धृत, पृ० 222 पर फाइनाल स्टेटमेंट, 1877. दूसरी ओर दो भूतपूर्व वित्त सदस्य, ई० बेरिंग तथा ए० कालविन

अपना यह सुविचारित मत प्रकट कर चुके थे कि नमक कर में किसी प्रकार की वृद्धि का परिणाम निर्धनों पर भार में वृद्धि और नमक की क्षपत में कटौती होगी (एल० सी० पी०, 1882, खंड XXI पृ० 321-3 और एल० सी० पी० 1886, खंड XXVI पृ० 9-10)।

204. एल० सी० पी० 1888 खंड XXVII पृ० 20

205. सत्य शोधक, 5 सित० जगन्मित्र, 6 सित०, ज्ञान प्रकाश 16 सित० (आर० एन० पी० बंब, 18 सित० 1875); केसरी, 23 अगस्त (वही, 3 सित० 1881), इंडियन स्पेक्टेटर, 22 जन०, केसरी, 24 जन०, शुभ सूचक, 20 जन० (आर० एन० पी० बंब, 28 जन० 1888); बंगवासी और संजीवनी, 28 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 4 फरवरी 1888); पंजाबी अखबार, 4 फरवरी, सुबोध सिंधु, 1 फर०, हिंदुस्तान 1, 2, 3 फर० (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फर० 1888); पूना में सार्वजनिक सभा द्वारा 18 मार्च 1888 को स्वीकृत ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जन-अप्रैल 1888 (खंड X स० 3-4) पृ० 26-27; वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 37 और सी० एल० पारिख : पूर्वोद्धृत, पृ० 382 पी० केनेडी, रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 36 बंगाली, 28 मार्च 1891; पंसा अखबार, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 18 अप्रैल 1891); अखबारे आम, 16 अप्रैल (वही, 25 अप्रैल 1891); राय, पावर्टी, पृ० 264-5; ए० डी० उपाध्याय, रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 151; 1902 की कांग्रेस का प्रस्ताव सं० XIII इस विषय पर लोकप्रिय भावना के प्रदर्शनार्थ कुछ एक अवतरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं : 1890 की कांग्रेस में पी० केनेडी ने दुःखित होकर कहा : नमक की सस्ते दाम पर उपलब्ध न हो पाने के कारण इस विशाल भारत देश के लाखों-करोड़ों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की इन दिनों आयु घट गई है, उनका शरीर क्षीण हो गया है, शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ उनके मानसिक और नैतिक स्तर के विकास की सुविधाएं भी घूमिल पड़ गई हैं' (पूर्वोद्धृत), 1895 की कांग्रेस में ए० डी० उपाध्याय ने जोक प्रकट करते हुए कहा : 'आखिर हमने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है कि जिसके फलस्वरूप हमें वर्षों तक पर्याप्त नमक की अनुपलब्धि का अवांछनीय दंड दिया जा रहा है (पूर्वोद्धृत)। अपने 31 जन० 1888 के अंक में तिलक के केसरी ने लिखा : 'वायसराय महोदय की अथवा किसी अन्य महानुभाव की सलाह पर वित्त सदस्य ने नमक की पूर्ति को घटाकर उचित ही पग उठाया है। उसने अपने एक ही तौर से दो झिकार मारे हैं, एक ओर तो राजस्व की उगाही कर ली गई है और दूसरी ओर शासन के विरुद्ध अपने लेखों द्वारा निरर्थक उछलकूद मचाने वालों को क्षीणकाय बना दिया है। (आर० एन० पी० बंब, 4 फरवरी 1888)।

206. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 169-83.

207. वही, पृ० 184.

208. वही, पृ० 187-8.

209. वही, पृ० 195-8.

210. गोखले, रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 40; रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 150-1; स्पीचेस, पृ० 13, 31, 39-41, 79.

211. हिंदू, 3 अप्रैल 1885; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 90, 824; इंडियन स्पेक्टेटर, 22 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 28 जनवरी 1888); इंडियन नेशन, 23 जनवरी (सी० ओ० आई०, फरवरी 1888); हिंदू, 25 जनवरी 1888; वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 37; राय, पावर्टी पृ० 263-4; वाच उस अखबार, 27 दिसंबर 1890 (आर० एन० पी० पी०, 10 जन० 1891)।

212. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 92
213. वही, पृ० 93-9, 178-9, गोखले, स्पीचेज, पृ० 79-80
214. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 97
215. वही, पृ० 98 शुभमूचक ने अपने 22 जनवरी के धक में और रास्तगुप्तार ने अपने 14 जनवरी के धक में इस प्रकार की आशकाए प्रकट की थी (आर० एन० पी० बब, 20 जनवरी 1877)
216. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 100, 142, स्वदेशमित्रन, 18 जनवरी (आर० एन० पी०, जनवरी 1886); पीछे पादटिप्पणी सख्या 168 में निर्दिष्ट लगभग सभी समाचारपत्र आई० एन० सी०, 1889 का प्रस्ताव सख्या III (1) नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 177-8
217. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 166, 190, मराठा, 22 जन० 1888, ए० बी० पी०, 26 जन० 1888, 28 जनवरी 1888 को समाप्त होने वाले सप्ताह के बर्दई के लगभग सभी समाचारपत्र रिपोर्टर का सार सक्षेप (आर० एन० पी० बब, 28 जन० 1888), ट्रिब्यून, 11 फरवरी (बी० ओ० आई०, मार्च 1888), सजवनी, 28 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 फरवरी 1888), स्वदेशमित्रन, 28 जन०, 25 फर० (आर० एन० पी० एम०, 31 जनवरी, 29 फरवरी 1888); अमृत बोधिनी, 2 फरवरी (वही, 15 फर० 1888), हिंदुस्तान, 1, 2, 3 फरवरी, सुबोध सिधु, 1 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फरवरी 1888)
218. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 141-2, 161, 165-6, 190, कैसरे हिंद, 22 जन० (आर० एन० पी० पी० बब, 28 जन० 1888)
219. एन० बी० बरवे, रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 179, इंदु प्रकाश, 30 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी 1888), स्वदेशमित्रन, 18 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 फरवरी 1888), गोखले, रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 39-40, शशिलेखा, 27 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 31 दिस० 1895)
220. पूना निवासियों द्वारा 18 मार्च 1888 को एक सार्वजनिक सभा में स्वीकृत ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जनवरी अप्रैल 1888 (खंड X स० 3-4), पृ० 17, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 141, 189 तथा देखिए आगे अध्याय XII
221. रिपोर्टर का सार सक्षेप, आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी 1888; कैसरी, 31 जन० (आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी 1888).
222. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 199.
223. गोखले, स्पीचेज, पृ० 39
224. वही, पृ० 79
225. आर० एन० पी० बब, 28 जन० 1888.
226. आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी 1888.
227. आर० एन० पी० बग०, 11 फरवरी 1888.
228. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 139
229. मुर्जी और पेटिट द्वारा नमक कर के समर्थन के लिए देखिए, एस० सी० पी०, 1888 खंड XXVII पृ० 24 और 31. मुर्जी ने घोषणा की कि साब ही साब यह एक ऐसा साधन है जिससे सर्वसाधारण को सामान्य सतों मिल गया और जो देश के निर्धनतम व्यक्ति की जेब को भी उत्तेजनीय रूप से प्रभावित नहीं करेगा. उनकी कार्यवाही की जापोचना के लिए देखिए, 9 फरवरी 1888 का गुजरात गजट, जिसने लिखा : "कूरता की यह पराकाष्ठा है. कुछ वषा

जानो कि तुम किस तरह अधीन जनता का खून घूस रहे हो (आर० एन० पी० बब, 11 फरवरी 1888); 5 फरवरी 1888 के 'राज्यभक्त' ने भी एन० मुकजी को 'जादूगर लाई' डफरिन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतली' की सजा देते हुए टिप्पणी की कि मुकजी महोदय का स्वार्थ घृणास्पद है और यह उसके 'देशद्रोही' होने का प्रमाण है (आर० एन० पी० बब, 11 फरवरी 1888); ज्ञान प्रकाश, 9 फरवरी, श्री शिवाजी, 10 फरवरी और बबई के बहुत सारे अन्य समाचारपत्र (आर० एन० पी० बब०, 11 फरवरी 1888) वृत्त घर, 9 फरवरी, सुबोध सिन्घ, 8 फर० (आर० एन० पी० पी० एन०, 14 फरवरी, 1888), जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 143-4, 186-7, स्वदेशमित्र, 18 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 1888), डब्ल्यू० सी० बैनर्जी का लेख, बंगाली, 25 अगस्त 1888 के अंक में, मसानी पूर्वोद्धृत, पृ० 318 पर नौरोजी का कथन, बाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 38 मालवीय, स्पीचेज, पृ० 27-8, 30, एस० एन० बैनर्जी, एस० एंड डब्ल्यू०, पृ० 312 इसके बहुत समय पश्चात् 1897 में जमील उल उलुम ने अपने 28 मई के अंक में घटना का स्मरण कराते हुए अपना रोष निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया - 'नमक कर के मामले में महामहिम की अपेक्षा पदवियों के भूखे भारतीय ही वास्तव में अधिक दोषी हैं ऐसा लगता है कि यह धोखेबाजी उन्हें मा के दूध के साथ घृटी में पिलाई गई है वे देशद्रोही हैं बंगाल में एक राजा है जिन्होंने नमक कर का जोरदार समर्थन किया है ऐसे लोग जिस भी देश में उत्पन्न हुए हैं और रहते हैं, उस देश के और मानवता के नाम पर कलक रूप हैं, ऐसे लोगो को तो समुद्र में फेंक देना चाहिए जब तक ऐसे धोखेबाज इस देश में जीते हैं, देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता (आर० एन० पी० एन०, 2 जून 1897)

230 बबई के नेटिव प्रेम के सवाददाता ने अपनी साप्ताहिक टिप्पणी में लिखा कि रामन गुप्तार और सप्ताह के अन्य अनेक समाचारपत्र विधानसभाओं के वर्तमान दापपूर्ण गठन की एक बार फिर शिकायत कर रहे हैं और उन्हें वास्तविक रूप में अधिक लोक प्रतिनिधित्व का रूप देने की मांग कर रहे हैं (आर० एन० पी० बब, 11 फरवरी 1889) मगठा 18 फरवरी 1888 स्वदेश-मित्र, 18 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 1888), हिंदुस्तान, 1, 2, 3 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 7 फरवरी 1888); एम० एन० बैनर्जी, एम० एंड डब्ल्यू०, पृ० 311-2 स्पीचेज III पृ० 137, 161, बाचा रिप० आई० एन० सा०, 1890 पृ० 38; लाला मुरलीधर, वही, पृ० 42

231 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 144

232 मालवीय स्पीचेज, पृ० 26-7 और 30-1.

233 रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 36

234 रिप० आई० एन० सी०, 1892 पृ० 67 और गोखले, स्पीचेज, पृ० 79, और जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 200

235 सी० पी० जान स्ट्रेची : इंडिया (1903) पृ० 165-6 'जिन लोगों पर यह कर लगा है, उन लोगों की बहुसंख्या तो इस कर के अस्तित्व तक से परिचित नहीं जनता तो शांत और अप्रभावित रहती है अपनी आवाज सुना सकने वाले केवल अल्पसंख्यक सपन्न वर्ग ही उन बातों का, जिनका उनके अपने जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, गला फाड़कर समर्थन करते रहते हैं.' स्ट्रेची द्वारा स्थिति का अध्ययन यों तो संबंधा सही है परंतु केवल एक बात गलत है जिसका उल्लेख उसने नहीं किया, उस समय भारतीय नेता भी अपनी आवाज सुना सकने में समर्थ थे और उन्होंने नमक कर का विरोध ही नहीं किया प्रत्युत उसके विरुद्ध बहुत ही ऊचा स्वर

उठाया. इस प्रकार उन्होंने मूक जनता की भावनाओं को बाणी दी.

- 236 एल० सी० पी०, 1882 खड XXI पृ० 290-1. 1889 में उसने नमक कर में किसी प्रकार की कटौती के अपने विरोध को दोहराया और एक बार फिर उसने आय कर में राहत देने की वकालत की (एल० सी० पी० 1889 खड XXVII पृ० 141)
- 237 एल० सी० पी०, 1882 खड XXI पृ० 303-04.
- 238 एल० सी० पी०, 1888 खड XXVII पृ० 24 और आगे
- 239 रिपोर्ट आफ दि बगाल नेशनल चैंबर आफ कामर्स, 1887 पृ० 23-4 तथा देखिए, हिंदू पैट्रियाट, 23 जनवरी (बी० ओ० आई०, फरवरी 1888)
- 240 रिपोर्ट आफ दि बगाल नेशनल चैंबर आफ कामर्स, 1889 पृ० 3-4, 34-5
- 241 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खड IV, पृ० 276
- 242 कुल 6 64 करोड़ राजस्व में से 4 86 करोड़ मदिरा पर उत्पादन शुल्क से ही वसूल हुआ (वही)
- 243 यह समझने में कठिनाई नहीं होती चाहिए कि नीलामी पद्धति का सबसे बड़ा दाप यह था कि उससे मदिरा के मन्थ में भारी कटौती की सम्भावना थी एकाधिकार का एकमात्र उद्देश्य यथा-सम्भव अधिकतम लाभ कमाना था बहुत सारे मामलों में यह पाया गया कि थोड़ी मात्रा में अचो कीमतवाली मदिरा की बिक्री की अपेक्षा बड़ी मात्रा में थोड़ी कीमतवाली मदिरा की बिक्री से अधिकतम लाभ की सुरक्षित प्राप्ति हुई (वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 470)
- 244 पी० बैंजामिन. इंडियन टैक्सेशन, पृ० 482-5
- 245 वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 477
- 246 उदाहरणार्थ, मराठा, 18 फरवरी 1883, 29 मिनबर 1885, बगाली, 9 अप्रैल, 19 अप्रैल 1887; इंडियन एमोसिएशन का बगाल सरकार को प्रतिवेदन, दिनांक 15 नवंबर 1887, बगाल : पूर्वोद्धृत, परिशिष्ट डी० एस० एन० बैंजामिन ए नेशन इन मेकिंग, पृ० 93-7, दादाभाई नोरोजी के दृष्टिकोण के लिए देखिए ममानी पूर्वोद्धृत, पृ० 363, 365; आई० एन० सी०, 1888 का प्रस्ताव VII; आई० एन० सी०, 1900 का प्रस्ताव XV, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 565, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 381, मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 32, जी० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 77 9, गोखले, स्पीचेज, पृ० 16, 84 मदिरापान की प्रवृत्ति के प्रति प्रारंभिक भागतीय समालोचना के लिए देखिए, पेट्रीशन आफ दि ब्रिटिश इंडियन एमोसिएशन 1852 बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धृत, पृ० 486 पर, और केशवचंद्र सेन, लाइफ एंड वर्क' पी० एम० बगु द्वारा संपादित (कलकत्ता 1940) पृ० 209-10
- 247 आई० एन० सी० 1900 का प्रस्ताव XV एम० एन० चौधरी, रिप० आई० एन० सी० 1900, पृ० 86
- 248 लोकनताओं और सस्थाओं के लिए देखिए, इंडियन एमोसिएशन द्वारा बगाल सरकार को 15 नवंबर 1887 को प्रस्तुत ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, आई० एन० सी० 1888 का प्रस्ताव VII और आई० एन० सी० 1900 का प्रस्ताव XV, तिलक के मन को रामगोपाल ने उद्धृत किया है : पूर्वोद्धृत, पृ० 72-3, 217, तिलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ दि बांबे 1895 खड XXX पृ० 91-2, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 564-5, एस० एन० बैंजामिन ए नेशन इन मेकिंग, पृ० 381, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 381 गोखले, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौमिल आफ बांबे 1901, खड XXXIV, पृ० 249 स्पीचेज, पृ० 16, 83-4, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1888. पृ० 140, और रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 31, जी० सी० मित्रा, रिप० आई० एन०

सी० 1899 पृ० 77-9 समाचारपत्रों के लिए देखिए, समाचार चन्द्रिका, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 17 अप्रैल 1880); सुलभ समाचार, 30 अक्तूबर (वही, 6 नवंबर 1880), सोम प्रकाश, 6 दिसंबर (वही, 11 दिस० 1880), ए० बी० पी०, 24 नव० 1881, 22 नव० 1883 और 2 अप्रैल 1885, मदार मजरी, स० 4 (आर० एन० पी० एम०, फरवरी 1882), सोम प्रकाश, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 8 अप्रैल 1882), सोम प्रकाश 3 अप्रैल (वही, 5 मई 1883); भारत मिहिर, 1 मई (वही, 12 मई 1883), बगबासी, 27 अक्तूबर (वही, 3 नवंबर 1883), सशोधिनी, 7 नवंबर, (वही, 17 नव० 1883), परिदर्शक, 11 नवंबर (वही, 24 नवंबर 1883), मराठा, 17 मई और 29 सितंबर 1885, बंगाल के सभी पत्र-पत्रिकाओं ने इंडियन एसोसिएशन द्वारा 15 नवंबर 1887 को प्रस्तुत आपन का समर्थन किया देखिए, आर० एन० पी० बग०, नवंबर, दिसंबर 1887, सजीवनी, 7, 14 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 14 और 21 अप्रैल 1888), आर० एन० पी० बग०, 22 मार्च 1890, 25 अप्रैल 1891 में उल्लिखित सभी समाचारपत्र हिंदुस्तान, 17 और 18 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 24 जुलाई 1889), भारत जीवन, 1 जुलाई (वही, 9 जुलाई 1895), स्वदेशमित्र, 13 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 15 मार्च 1889), इंडियन पीपुल, 26 मई (आर० एन० पी० य० पी०, 4 जून 1904), स्वदेशमित्र, 2 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 3 दिस० 1904) राष्ट्रवादियों की कभी कभी अभिव्यक्त होने वाली हादिक भावनाओं की सुदूर अभिव्यक्ति लाला मुरलीधर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन के सदस्यों को संबोधित भाषण में निम्न अवतरण में इस प्रकार से हुई है 'जहां पूर्व ने पश्चिम की गणित, ज्योतिष तथा अन्य विज्ञानों की शिक्षा दी है वहां प्रतिदान में पश्चिम ने पूर्व को मुक्ति के बदले मदिरा के रूप में नरक-यातना दी है यहा तक कि हमारे मुस्लिम शासक भी मदिरा से घृणा करते थे और मदिरा से प्राप्त आय को अभिशाप मानते थे यह ईसाई शासकों को ही समर्पित है कि वे इसे प्यार करें, उत्तेजित हो, इसे चूमे-चाटे और इसमें लाखों करोड़ों पाँड धन कमाए क्या ऐसे मनुष्य भी समार मे हैं जो ईश्वर और परलोक पर विश्वास करने का डोग तो रचते हैं परंतु ईश्वर द्वारा उनके अधीन किए लोगों के प्रति क्रूरता, निर्दयता तथा याजनाबद्ध निर्भमता का व्यवहार करते हैं ? इस प्रकार ये लोग उम परमपिता के प्रति प्रत्येक प्रकार के पापमय और घृणित आचरण करते हैं (रिप० आई० एन० सी०, 1890, पृ० 32-3)

- 249 248 की पादटिप्पणी में उद्धृत प्रसंगों के अतिरिक्त उदाहरणार्थ देखिए, आर० एन० पी० बग०, 17 अप्रैल, 30 अक्तू०, 27 नवंबर 1880 26 फरवरी, 12 मार्च, 16, 25 जुलाई, 1 अक्टू०, 26 नवंबर, 10, 17 दिस० 1881 18, 25 फरवरी, 18 मार्च, 15 जुलाई 1882 27 अक्तू०, 10, 17 नवंबर 1883, इंडियन मिरर, 20 नव०, बंगाल पब्लिक ओपीनियन, 13 दिस० (बी० ओ० आई०, दिस० 1883), बंगाली, 10 नवंबर 1883, 9 अप्रैल और 19 नवंबर 1887, सजीवनी, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 7 मई 1887), बंगाल की प्रथम प्रांतीय परिषद का प्रस्ताव, 3 नव० 1888 के बंगाली में उद्धृत
- 250 1898 में पी० मेहता ने टिप्पणी की कि उत्पादन (एक्साइज) विभाग 'उस प्रचारक के उदाहरण का अनुकरण कर रहा है कि जो यह कहता है कि वह अच्छे सिद्धांतों और आदर्शों के प्रचार के लिए तो प्रतिबद्ध है परंतु उन सिद्धांतों पर आचरण करने के लिए किसी भी रूप में विवश नहीं है. (स्पीचेर, पृ० 564) तथा देखिए, तिलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाने, 1895, खंड XXX पृ० 92.

251. ए० बी० पी०, 22 नवंबर 1883; बाबा, रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 140; दैनिक ओ सभाचार चंद्रिका, 10 मार्च सहृषर, 12 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 22 मार्च 1890); जी० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 78-9 तथा देखिए, केशवचंद्र सेन, पूर्वोद्धृत, पृ० 210.
252. फाइनांशल स्टेटमेंट, 1888-9 कंडिका, 65 तथा भारत सरकार का संश्रेषण, संख्या 166, 25 जून 1887. उसी में उद्धृत फाइनांशल स्टेटमेंट 1891-2 कंडिका-38. 1903 में लिखते हुए जान स्ट्रेची ने बल देकर कहा : '1880 के पश्चात लगभग सभी ओर मदिरा की दुकानों की संख्या में ओर मदिरा की खपत में कमी हुई है, इसे सामान्य रूप से देखा जा सकता है.' इंडिया (1903) पृ० 170.
253. फाइनांशल स्टेटमेंट, 1884-5 कंडिका, 37; फाइनांशल स्टेटमेंट, 1889-90 कंडिका, 22; फाइनांशल स्टेटमेंट, 1891-2 कंडिका, 38; एडवर्ड ला, एल० सी० पी० 1901 खंड XL पृ० 309; फाइनांशल स्टेटमेंट 1902-03 कंडिका, 91.
254. जी० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सी०, 1899 पृ० 70; रामगोपाल : पूर्वोद्धृत, पृ० 217 पर तिलक, गोखले, स्पीचेज, पृ० 16; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 380.
255. 1904 में जी० के० गोखले ने कहा था : 'सिखा एक उपयोगी उपचार हो सकता है परंतु इसके प्रवर्तन की प्रक्रिया का मंद होना अनिवार्य है मेरे विचार में स्थानीय लोकमत को इस संबध मे वैधानिक या अन्य सी जानी चाहिए' (स्पीचेज, पृ० 85).
256. आई० एन० सी० 1888 का प्रस्ताव VII, 1889 का प्रस्ताव, IV; 1890 का प्रस्ताव IV, 1891 का प्रस्ताव VI (सी), 1892 का प्रस्ताव V (सी), 1893 का प्रस्ताव III (सी); 1894 का XVI (सी), 1895 का प्रस्ताव XXII (बी), 1896 का प्रस्ताव XI (ए) 1897 का प्रस्ताव IV (ए) 1898 का प्रस्ताव XX (ए), 1800 का प्रस्ताव XV रानाडे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स इन बांबे प्रेजिडेंसी केलाक : पूर्वोद्धृत, पृ० 45 पर; मराठा, 18 फरवरी 1883; हिंदू, 15 जुलाई 1885; बी० एन० मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 579; बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 140 और रिप० आई० एन० सी० 1890 पृ० 31; प्रधान एंड भागवत : पूर्वोद्धृत, पृ० 90 पर तिलक; गोखले, स्पीचेज, पृ० 83-5
257. ए० बी० पी०, 24 नव० 1881; नेटिव ओपीनियन; 26 अगस्त (बी० ओ० आई० सित० 1883 सं० 9 खंड-1); लिबरल, 18 नवंबर, बंगाल पब्लिक ओपीनियन, 13 दिस० (वही, दिसंबर 1883 संख्या 12 खंड I); बंगवासी, 21 मई, नवविभाकर, साधारणी, 23 मई (आर० एन० पी० बंग०, 28 मई 1887); इंडियन एसोसिएशन का 15 नवंबर 1887 का आपन, पूर्वोक्त स्थल; बंगाली, 5 और 19 नव० 1887; प्रथम प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव बंगाली के 3 नवंबर 1888 के संक में उद्धृत, ए० बी० पी०, 21 फरवरी 1889; आई० एन० सी० के 1890-1900 के प्रस्ताव, पीछे 256 संख्या पादटिप्पणी में उद्धृत. रामगोपाल : पूर्वोद्धृत, पृ० 72-3 पर तिलक; हिंदू, 27 नव० 1890; बाबा, रिप० आई० एन० सी०, 1890 पृ० 31; एस० एन० बंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 290; गोखले, स्पीचेज, पृ० 84-5.
258. देखिए पीछे पादटिप्पणी सं० 249 में प्रस्तुत संदर्भ.
259. आई० एन० सी० 1890 का प्रस्ताव सं० IV.
260. केलाक : पूर्वोद्धृत पृ० 45 पर रानाडे का दृष्टिकोण, सोम प्रकाश, 13 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 18 फरवरी 1882); मराठा, 18 फरवरी 1883; समय, 26 जन० (आर० एन० पी०

- बंग०, 31 जन० 1885); बंगबासी, 30 अप्रैल (वही, 7 मई 1887); आई० एन० सी०, 1890 का प्रस्ताव IV. तिलक, प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1896. खंड XXXIV पृ० 117. आई० एन० सी० 1990 का प्रस्ताव XV.
261. आई० एन० सी०, 1899 का प्रस्ताव IX तथा समाचार चंद्रिका, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 17 अप्रैल 1880); सुलभ समाचार, 30 अक्तू० (वही, 6 नवंबर 1880); मांडलिक, (स्पीचेज, पृ० 584; मराठा, 18 फर० 1883; समय, 26 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 31 जन० 1885); आई० एन० सी० 1890 का प्रस्ताव सं० IV. तिलक, प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ गवर्नर आफ बांबे, 1895 खंड XXXII पृ० 92; गोखले, वही-1901, खंड XXXIX पृ० 249. इस मबंध में गोखले ने एक रोचक तथ्य का निवेश किया कि 'जब तक शराब मिलने की संभावनाओं में कटौती नहीं की जाती, तब तक मदिरा जैसे पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का यथं दरिद्र उपभोक्ता की जेब को हल्का करना ही होगा. तिलक महोदय ने तो यहां तक कह डाला कि यदि लोग 'पक्के पियक्कड़ ही हैं तो फिर मदिरा के मूल्यों में वृद्धि करने में कोई तुक नहीं.
262. हमारे अध्ययन काल की अवधि में 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह माग बेमन से उस समय प्रस्तुत की जबकि उसने सरकार से 'अमरीका के प्रमुख मदिरा कानून' जैसे उपायों को अपनाने का अनुरोध किया, परंतु उसी सांस में उसने स्थानीय लोकमत और मदिरा पर अतिरिक्त कराधान की भी वकालत की (प्रस्ताव XV).
263. मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 366. 1891 में नितांत परहेज (मदिरापान न करने) करने वाले भारतीय छात्र भाव वाले सघ (इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ टोटल ऐबस्टेनस) का उद्घाटन करते हुए दादाभाई नौरोजी ने सुविचारित रूप से कहा था : 'इसका एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलने में समर्थ हुए हैं तथा सभी समुदायों को समान रूप से दुष्प्रभावित करने वाले महान प्रश्न पर सुविचारित कार्यवाही करने को प्रस्तुत हुए हैं, वही, पृ० 365-6 तथा देखिए, एस० एन० बंनर्जी . ए नेशन इन मेकिंग, पृ० 94-07.
264. इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, (1908) खंड IV पृ० 275 और वकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 603.
265. इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV, पृ० 275.
266. वकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 492.
267. इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) पृ० 245-6 अफीम के हानिप्रद प्रभाव के संबंध में कमीशन की राय थी कि भारत में अफीम के संयत प्रयोग को उसी रूप में लेना, जिस रूप में इंग्लैंड में मदिरा के संयत प्रयोग को लिया जाता है. अफीम हानिप्रद है, हानिरहित है और यहां तक कि अफीम लाभप्रद भी है, यह सब उस परिस्थिति और उस विवेक पर निर्भर है जिसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है (वही, पृ० 246).
268. ई० बेरिंग, फाइनांसल स्टेटमेंट, 1882 कंडिका, 146-73; 1893 में रेविड बारबर का अफीम के लिए नियुक्त शाही कमीशन के समक्ष साक्ष्य, वकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 49 पर तथा देखिए चिसनो, पूर्वोद्धृत, पृ० 328-30, जान स्ट्रेची, इंडिया, (1903) पृ० 155.
269. केनवचंद्र सेन पूर्वोद्धृत, पृ० 210
270. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 215 तथा देखिए, वही, पृ० 201; स्पीचेज, पृ० 142 तथा 192-3; मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 316. दादाभाई नौरोजी का भी अफीम व्यापार के संबंध में बहुत ऊंचा नैतिक आदर्श था. जब उन्होंने 1855 में व्यापारिक संस्थाओं के साथ व्यापारिक गठबंधन किया तो

उन्होंने उसी समय यह ज्ञात रखा की कि वे अफीम के व्यापार से होने वाले लाभ के भागीदार नहीं बनेंगे। बाद में उन्होंने सचमुच ही अफीम तथा मदिरा से अर्जित लाभ में से अपना घात लेने से इनकार कर दिया (नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 192 और मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 74)

271. और देखिए, रास्त गुप्तार, 12 जून (आर० एन० पी० बब, 18 जून 1870); नेटिव ओपीनियन (वही, 24 अगस्त 1872); बंगाली, 3 जुलाई 1880, 12 मार्च 1882; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 26 मई 1881; हिंदू, 5 दिस० 1884; मराठा, 22 मार्च 1885, ए० बी० पी०, 20 मई 1886, 16 फरवरी 1888; आंध्र प्रकाशिका, स० 19 (आर० एन० पी० एम०, मई 1886); बगनिवासी, 17 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 25 अप्रैल 1881); मजीवनी, 26 अगस्त (वही, 2 मित० 1893).
272. रिपोर्ट आफ दि इंडियन फॉमिन कमिशन 1880, भाग II, पृ० 89, पी० बैंजर्जी : इंडियन टैंक्सेशन, पृ० 314, तथा पीछे पादटिप्पणी सं० 268 में उद्धृत अधिकारीगण.
273. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 41 तथा मसानी पूर्वोद्धृत, पृ० 316; दत्त. ई० एच० II, पृ० 155 इसके दूसरी ओर जी० बी० जोशी ने अभिस्वीकार किया कि अफीम लगान का भुगतान विदेशी उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाता है (पूर्वोद्धृत, पृ० 222).
274. बर्बई समाचार, 29 जून (आर० एन० पी० बब, 3 जुलाई 1875), जामे जमशेद, 19 फरवरी (वही, 22 फरवरी 1879); बर्बई समाचार, 3 मई (वही, 8 मई 1881), बाबे क्रानिकल, 8 मई (वही, 14 मई 1881); आर्यावर्त, 4 जून और शिवाजी, 3 जून (वही, 11 जून 1881); बंगाली, 3 जुलाई 1880; नवविभाकर, 29 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 3 अप्रैल 1880); नेटिव ओपीनियन, 19 जून, 25 दिस० 1881; मराठा, 16 अप्रैल 1882, सुबोध पत्रिका, 22 जून (आर० एन० पी० बब, 28 जून 1882); केसरी, 2 मई (वही 6 मई 1882), नेटिव ओपीनियन, रास्त गुप्तार और बाबे क्रानिकल 7 मई (वही, 13 मई 1882); महचर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 फरवरी 1882); समय, 4 जून (वही, 9 जून 1882); साधारणी, 11 मई और नवविभाकर, 12 मई (वही, 17 मई 1884), समाचार चंद्रिका, 16 मई (वही, 24 मई 1884); आनंद बाजार पत्रिका, 2 जून (वही, 7 जून 1884); मराठा, 22 मार्च 1885; गुजरात दर्पण, 12 मई (आर० एन० पी० बब, 18 मई 1889), नेटिव ओपीनियन, 7 मई (वही, 9 मई 1891); पूना वैभव, 6 सितंबर (वही, 12 सित० 1891); ज्ञान प्रकाश, 17 नव० (वही, 19 नवंबर 1892), आफताबे पंजाब, 27 अप्रैल और ताज उल अखबार, 25 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 9 मई 1891); अखबारे आम, 18 अगस्त (वही, 29 अगस्त 1891); हिंदुस्तान, 8 मई (आर० एन० पी० एन०, 15 मई 1889); न्यायमिधु, 22 अप्रैल (वही, 30 अप्रैल 1891); सुबोध संधु, 29 अप्रैल (वही, 7 मई 1891), बंगाली, 18 अप्रैल 1891; सहचर, 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 25 अप्रैल 1891); डाका प्रकाश, 26 अप्रैल और सुरभि ओ पताका, 17 अप्रैल (वही, 2 मई 1891); सोम प्रकाश, 8 जून (वही, 13 जून 1891); हिंदू जनभूषणी, 18 मई (आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1889); वृत्त पत्रिका, 14 दिस० तथा मद्रास के अन्य पत्रों की स्वीकृति (वही, 15 दिस० 1893); ताज उल अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 19 अगस्त 1893); कोहेनूर, 9 सितंबर (वही, 23 सित० 1893) दोस्ते हिंद, 13 अक्टूबर (वही, 21 अक्टूबर 1893); पैसा अखबार, 8 दिस० (वही, 16 दिस० 1893); बिहार हेराल्ड, 18 मई (आई० एस० बी० ओ० आई०, 9 जून 1895); फोर्निक्स, 8 मई (आर० एन० पी० बब, 18 मई 1895); इंडियन स्क्वेटेर, 12 मई 1895); कर्णाटक प्रकाशिका, 30 अगस्त (आर०

एन० पी० एम०, 31 अगस्त 1897)

275. अफीम विरोधी आंदोलनकारी संगठनों और लोकोपकारियों पर चोट करते हुए पत्रिका ने अपने 20 मई 1886 के अंक में व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखा : 'वे भूल जाते हैं कि इंग्लैंड जैसे आक्रमणकारी और विजेता देश को किसी देश को बिना देने जैसी साधारण सी घटना पर बड़बड़ाना नहीं चाहिए...' इतना तो असंदिग्ध रूप से तथ्य है कि अफीम की अपेक्षा लोहा और सिक्का किसी भी देश को अधिक प्रीयता और अधिक निश्चितता से विनष्ट करने वाले साधन हैं' इसके साथ ही पत्र ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा . 'अफीम राजस्व की क्षति प्रति के लिए भारतीयों पर कर लगाने के लिए भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह इस प्रकार का कृत्य होगा कि जहर देने के स्थान पर सरकार लूट का घंथा अपनाते पर विवश होगी'. और देखिए ए० बी० पी०, 16 फरवरी 1888 और 17 अप्रैल 1891.
276. ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन ने अपने 26 मई 1881 के अंक में और अधिक दुष्टापूर्वक लिखा कि भले ही अफीम लगान के अभाव में भी बजट में किसी प्रकार का असंतुलन न आने पाए फिर भी भारत जैसा निर्धन देश अफीम राजस्व को हटाने का मामध्य नहीं रखता
277. आर० एन० पी० बंब, 18 मार्च 1882; मराठा ने अपने 22 मार्च 1885 के अंक में इन आंदोलनकारियों को 'अतिरिक्त श्रेष्ठ आदर्शवादियों के सामाजिक संगठन' की सत्ता दी.
278. हिंदू ने अपने 11 मई 1895 के अंक में और आगे लिखा . 'अफीम एक भारी बुराई हो सकती है परंतु राष्ट्रीय दिवालियापन उससे बड़ी बुराई है'
279. ए० बी० पी०, 9 जुलाई 1880 और 20 जुलाई 1886; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 15 जुलाई 1880; आनंद बाजार पत्रिका 2 जून (आर० एन० पी० बंग०, 7 जून 1884); हिंदू, 26 जनवरी 1885, 9 दिसंबर 1890, 3 जुलाई 1893; बंगाली, 18 अप्रैल 1891.
280. केलाक : पूर्वोद्धृत, पृ० 45 पर तिलक; ए० बी० पी०, 9 जुलाई 1880. 16 फरवरी 1888; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 15 जुलाई 1880; नेटिव ओपीनियन, 19 जून 1881; मराठा, 17 जुलाई 1881, 23 अप्रैल 1882, 22 मार्च 1885; 'दि इंडियन स्टार्ट टैंक्स' जे० पी० एस० एस०, खंड IV ख० 1 जुलाई 1881, पृ० 61; केसरी, 2 मई (आर० एन० पी० बंब, 6 मई 1882); साधारणी, 11 मई और नवविभाकर, 12 मई (आर० एन० पी० बंब०, 17 मई 1884); समाचार चक्रिका, 16 मई (वही, 24 मई 1884); सहृदय, 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बंब०, 25 अप्रैल 1891); सोम प्रकाश, 8 जून (वही, 13 जून 1891); सुलभ दैनिक, 15 दिस० (वही, 23 दिसंबर 1893); रहस्ये हिंदू, 28 सितंबर (आर० एन० पी० पी०, 14 अक्तू० 1893); अखबारे आम, 31 अक्तू० (वही, 4 नवंबर 1893); वृत्त पत्रिका, 14 दिसंबर तथा अन्य पत्र-पत्रिकाएं (आर० एन० पी० एम०, 15 दिस० 1893).
281. नवविभाकर, 29 मार्च (आर० एन० पी० बंब०, 8 अप्रैल 1880); नेटिव ओपीनियन, 19 जून 1881; मराठा, 16 अप्रैल 1882 और 7 दिस० 1893; केसरी, 2 मई (आर० एन० पी० बंब, 6 मई 1882); समय, 4 जून (आर० एन० पी० बंब०, 9 जून 1882); साधारणी, 11 मई (वही, 17 मई 1884); हिंदुस्तान, 8 मई (आर० एन० पी० एन०, 15 मई 1889).
282. आर० एन० पी० बंब०, 30 दिस० 1893.
283. आर० एन० पी० बंब०, 31 जुलाई 1880 मराठा ने अपने 7 अगस्त 1881 के अंक में टिप्पणी की : 'निस्संदेह चीन के साथ अफीम व्यापार बंद कर देने से भारतीय वित्तों में चौड़ी खाई पड़ जाएगी परंतु 40 करोड़ लोगों को बिना देने के आरोप तिर पर लेने की अपेक्षा इस खाई को

भरने के लिए अन्य आर्थिक उपाय सोचना तथा विभिन्न विभागों के खर्चों में कटौती करना ही अधिक उपाय है' छोड़े ही समय के उत्तरान 12 मार्च 1892 के ग्रंथ में मराठा ने मत प्रकट करते हुए लिखा : 'अफीम व्यापार जैसे यहित कार्य को निषिद्ध करने जैसे नैतिक और लाभप्रद साधन में अपने रुपये के उपयोग में किसी भी भारतीय को शिकवा-शिकायत नहीं होगी'. इसी प्रकार सजीवनी ने 26 अगस्त 1893 के ग्रंथ में दावा किया : 'पाप पूर्ण व्यापार से अजित राजस्व से कोई भी सरकार फलती-फूलती नहीं रह सकती. न्यायप्रिय भगवान द्वारा सभी पापी अवश्य दंडित किए जाएंगे. अतः सरकार के लिए उचित यही है कि वह इस पापमय व्यापार को छोड़ दें' (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 1893) और देखिए, सोम प्रकाश, 19 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 24 जुलाई 1880) इंडियन स्पेक्टर, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 13 अगस्त 1881); हिंदू, 5 दिस० 1884 और 14 अप्रैल 1891, नौरोजी, पावर्टी पृ० 215 स्पीचेज, पृ० 196 और मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 359, 362 पर; हिंदुस्तानी, 15 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 21 अप्रैल 1891); इंडियन मिरर, 15 अप्रैल और एडवोकेट, 17 अप्रैल (आई० एस० बी० ओ० आई०, 3 मई 1891); दि एटी आगियम एलायन्स मूवमेंट' जे० पी० एस० एम०, खंड XIV, स०-2 अक्टूबर 1891 पृ० 6, 16, वृत्तंत पत्रिका, 16 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1891); रहबरे हिंद, 16 और 20 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० 25 अप्रैल 1891), बगनिवामी, 17 अप्रैल और सजीवनी, 18 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 25 अप्रैल 1891); समय 24 अप्रैल (वही, 2 मई 1891).

284. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 194.

285. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 215

286. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 192-6

287. सीमा शुल्क से होने वाली शुद्ध आय 1875-6 में 2.5 करोड़ रुपये, 1877-8 में 2.4 करोड़ रुपये थी. 1882-3 में यह घटकर 1.1 करोड़ रुपये रह गई. इसका अर्थ हुआ कि कर नीति में सुधार के पांच वर्षों में 1.4 करोड़ रुपये घट गई. 1882 और 1893 की अवधि के बीच इसका निम्नतम प्राप्ति 1884-5 में 0.8 करोड़ रुपये थी. इस प्रकार कर नीति से सुधार के फलस्वरूप सीमा शुल्क में किसी भी एक अकेले वर्ष में होने वाली अधिकतम हानि दो करोड़ रुपये से कम की थी अफीम राजस्व से 1875-1898 के बीच में होने वाली शुद्ध आय 6.1 करोड़ रुपये थी देखिए, वकील : पूर्वोद्धृत, पृ० 596 और 603.

अध्याय 12

लोकवित्त : दो

सरकारी और गैरसरकारी दृष्टिकोणों में प्रमुख मतभेद का विषय है व्यय की दिशाएं ।

बालगगाधर तिलक

भयंकर बढ़ते सैनिक व्यय जैसा कोई भी अन्य विषय भारत देश का बुरी तरह से झकझोरने वाला नहीं ।

डी ई वाचा

व्यय

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने कराधान के परिमाण तथा कर निर्धारण की पद्धति की जाच-पड़ताल के साथ साथ उसके उपयोग पर भी विम्वृत विचार किया क्योंकि उनके विचार में करो मे प्राप्त कुल रकम के समान कराधान के उद्देश्यो और उनके वितरण का प्रश्न भी किसी रूप में कम विचारणीय तथा कम महत्वपूर्ण नहीं था । उन्होंने इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार किया कि कर राजस्व के लोकहित में व्यय होने वाले रूप में अथवा करदाताओं को परोक्ष रूप से कर राजस्व लौटाए जाने के संभावित रूप में तथा कर राजस्व के अनुत्पादक, निरर्थक और व्यर्थ के कार्यों में उपयोग किए जाने वाले रूप में बड़ा भारी अंतर था । इस कसौटी को आधार बनाने पर भारतीय नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत सरकार की व्यय नीति असतोषप्रद ही नहीं थी, प्रत्युत सर्वसाधारण के हितों के लिए क्षतिकारक भी थी । प्रथम, उन्होंने इस तथ्य को बड़े ही गंभीर रूप में लिया कि भारत के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग देश के भीतर खर्च न होकर देश के बाहर खर्च होता है, इस प्रकार देश में राजस्व की निकासी हो रही है । उन्होंने निर्देश किया कि इस संबंध में भारत की स्थिति ब्रिटेन जैसे स्वतंत्र देश से, जहां भले ही भारी कर लगाए गए हैं, सर्वथा भिन्न थी ।¹ इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने निकास शीर्षक अध्याय में किया है । यहां तो हमें इतना संकेत करना है कि कुछ भारतीय नेताओं ने लोकवित्तों की कुल वसूली की अपेक्षा व्यय की व्यावहारिक दिशाओं के प्रति अधिक ध्यान दिया । इस प्रकार 1800 में दादाभाई नौरोजी ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा :

‘इस समय वास्तविक प्रश्न, सभी प्रश्नों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि 60,00,00,00 पौंड या 100,000,000 पौंड कैसे प्राप्त किए जाएं। हो सकता है कि यह विषय भी आवश्यक हो परंतु अधिक आवश्यक और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जनता से उगाही रकम जनता को किस प्रकार लौटाई जाए।¹² 1887 में लिखे अपने एक पत्र में वह और भी अधिक सुस्पष्ट और मुखर थे : ‘भारत में कराधान की बुराई उसका परिमाण नहीं, यहां तक कि अकबर के समय वसूल किए जाने वाले भूमि लगान जितना इस समय वसूल किए जाने पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्व के एक भाग की देश से निकासी ही दुर्भाग्यपूर्ण बुराई है।’¹³ ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने भी अपने 22 फरवरी 1900 के अंक में इसी प्रकार की धारणा प्रकट की :

यदि करों द्वारा उगाही घनराशि इस देश में व्यय की जानी है तो इस देश के वासी ऊंचे कराधान और उनके भुगतान से भी अपने को व्यथित अनुभव नहीं करेंगे परंतु यदि 25 करोड़ रुपये के मूल्य का इस देश का उत्पादन प्रतिवर्ष इंग्लैंड को ही भेजना है जिसके बदले में इस देश को कोई लाभ नहीं मिलना है तो इस देश के वासी हलके कराधान का भुगतान करने में भी अपने को दरिद्र और असमर्थ अनुभव करेंगे।¹⁴

द्वितीय, भारतीय नेताओं ने देखा कि सरकारी खर्च की प्रकृति फिजूलखर्ची वाली है और उनका वितरण देश की आर्थिकता और जनता की परिस्थितियों और सच्ची आवश्यकताओं के अनुकूल और उनसे संबंधित नहीं है। उनका विश्वास था कि इनका और अधिक लाभप्रद तथा सार्थक उपयोग किया जा सकता था। य् तो उनका यह निष्कर्ष सामान्यतया भारतीय वित्तों के व्यय की आलोचना ही करता था परंतु कभी कभी विशेषतः इन नेताओं में अर्थशास्त्र के पंडितों द्वारा इसे भली प्रकार पकड़ा और अपने विवेक्षण का आधार बनाया गया। इस प्रकार ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने अपने 30 मार्च 1882 के अंक में यह मत प्रकट किया कि देश की वित्त व्यवस्था की किसी भी रूप में जांच करने पर प्रथम प्रश्न यह उभर कर सामने आता है कि उगाही गई घनराशि में से कितनी इस देश पर खर्च की गई है और कितनी यों ही बरबाद की जा रही है? इस पत्रिका की दृष्टि में इसका उपयुक्त उपचार था, करों की राशि का उपयोग निश्चित रूप से केवल उन्हीं के लिए किया जाना चाहिए जिनसे वह वसूल की गई है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि अंगरेजी शासन को कायम रखने का व्यय दायित्व भारत पर है, पत्रिका ने भारतीय वित्तों का सभी पक्षों, चेम्बेयर, माचेस्टर, लंदन, सिविल सर्विस, मिलिट्री सर्विस, नौकरी करने वाले तथा साहसियों की इच्छापूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने का अथवा इंग्लैंड के युद्ध अभियानों, आक्रमणों और दुष्कर्मों में सहायता देने के लिए प्रयोग किए जाने का विरोध किया। फिरोजशाह मेहता ने 1883 में देश भर में निर्मित सड़कों, पुलों, दवाखानों, स्कूलों और पुलिस चौकियों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी यह पूछा कि मौलिक प्रश्न यह है कि क्या इन सुधारों में संसाधनों का व्यय आवश्यकता से अधिक तथा गलत दिशा में नहीं हुआ है? क्या इन संसाधनों का और अधिक सार्थक तथा और अधिक लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता था? क्या देश की

वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी से इतनी भारी गलतियाँ सुधारी नहीं जा सकती थीं।⁵ 1895 में बंबई विधान परिषद में अपने प्रथम बजट भाषण में बाल गंगाधर तिलक ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि बजट के मूल्यांकन की वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिए कि पिछले 25 वर्षों में राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है और प्रांत की भौतिक संपन्नता के लिए उस राशि का कितना अंश समर्पित किया गया है।⁶ 1896 के अपने निबंध 'दि प्रेजेंट फाइनांशियल पोजीशन में' 1883-4 के वर्षों से भारतीय खर्चों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उपरांत जी० बी० जोशी ने अपना मत प्रकट किया कि यदि देश का इतना भारी अतिरिक्त घन देश के आंतरिक विकास और प्रगति के उद्देश्यों पर खर्च किया जाता तो देश के लाखों करोड़ों लोग संतोष और आनंद का उपभोग करते।⁷ दादाभाई नौरोजी ने 21 मार्च 1896 को विलबी कमीशन को लिखे अपने पत्र में इस स्थिति का अत्यंत सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।⁸

विलबी कमीशन के समक्ष और अपने प्रसिद्ध बजट भाषणों में सुस्पष्ट सिद्धांतिक रूप में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और उसके आधार पर भारतीय वित्तों के विश्लेषण करने का सारा दायित्व अकेले गोपालकृष्ण गोखले ने निभाया। 1897 में विलबी कमीशन के समक्ष तर्क करते हुए उन्होंने कहा कि खर्चों में वृद्धि, राष्ट्रीय वित्त के एक पक्ष के रूप में कोई विशेष गंभीर आपत्तिजनक नहीं। उन्होंने लोकवित्तों का सिद्धांत निर्धारित करते हुए कहा : 'इस संबंध में सभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जिस क्षेत्र में व्यय में वृद्धि हुई है, उसके उद्देश्य का स्वरूप क्या है? और लोकवित्तों के उस दिशा में किए गए खर्चों का परिणाम क्या निकला है?' उन्होंने यह स्वीकार किया कि पिछली बहुत सी दशाब्दियों से यूरोपीय देशों के व्ययों में वृद्धि हो रही है परंतु उनका कथन था कि वह वृद्धि भारत के खर्चों में हो रही वृद्धि से मौलिक रूप से बहुत भिन्न है। जहां उन देशों के बड़े खर्चों ने उन देशों की सुरक्षा और शक्ति में वृद्धि की है, उन देशवासियों के ज्ञान और संपन्नता में वृद्धि की है, वहां स्वेच्छाचारी शासकों के प्रबन्ध के दोषग्रस्त वैधानिक नियंत्रण के तथा विदेशी शासन के अंतर्निहित दोषों के अंतर्गत भारत के निरंतर बढ़ते खर्चों ने भारत में केवल हमारे संसाधन के निरंतर शोषण में वृद्धि करने में सहायता की है, हमारी भौतिक प्रगति को अवरुद्ध किया है, हमारी प्राकृतिक सुरक्षा को दुर्बल क्षीण किया है तथा हम पर अपरिभाषित तथा अनिश्चित वित्तीय दायित्वों का बोझ लाद दिया है।⁹ भारत के सार्वजनिक खर्चों तथा अन्य देशों के सार्वजनिक खर्चों के बीच एक अन्य मौलिक अंतर यह था कि जहां अन्य देशों में सार्वजनिक व्यय करदाताओं के हितों में किया जाता है, वहां इस देश में दूसरों के हितों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है और कभी कभी तो उन हितों को भारतीय हितों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के उदाहरण के रूप में यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वित्तों को ब्रिटिश सर्वोच्चता के हितों के स्थाई दावों की पूर्ति करनी पड़ती है। उन्हें ब्रिटिश प्रभुत्व के पूर्व में विस्तार के हितों की देखभाल और भारत में सिविल और मिलिट्री सेवा में संलग्न यूरोपियों के हितों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश वाणिज्य, व्यापारी तथा धनिक वर्गों के हित भारतीय करदाताओं के हितों पर हावी हो जाते हैं।¹⁰

कराधान के प्रश्न के समान भारतीय नेता प्रायः यह तर्क करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि भारत की निर्धनता और भारतीयों की कर भुगनान की अक्षमता के सदर्थ में सरकारी खर्च भारत जैसे निर्धन देश के ससाधनो और शक्ति के बाहर थे। मदनमोहन मालवीय ने 1889 में घोषणा की कि भारत की दरिद्रता के सदर्थ में खर्चों में वृद्धि न केवल अनुचित तथा अन्यायपूर्ण थी प्रत्युत निश्चित रूप से पाप कर्म भी थी। उन्होंने यह तो माना कि सरकारी खर्चों में वृद्धि अपने आप में कोई बुराई नहीं, यह वृद्धि तो वस्तुतः स्वागत योग्य होती है परंतु यह तब होता है जबकि उसका परिणाम जनता की धन-संपत्ति में वृद्धि के रूप में सामने आए। जैसे कि इंग्लैंड में था परंतु इस देश का दुर्भाग्य तो यह है कि सरकारी खर्च तो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं जबकि देशवासियों की दशा दिन प्रतिदिन बंद से बदतर होती जा रही है।¹¹ इसी तर्क को आधार बनाते हुए 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दृढ़तापूर्वक कहा, 'वित्तीय खर्चों की जाच-पड़ताल से तब तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा, जब तक उसमें भारतीयों की चालू वित्तीय मार को सहन करने की शक्ति की जाच-पड़ताल का कार्य सम्मिलित न किया जाए।'¹² 1895-6 की इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसिल में अपने भाषण में फिरोजशाह मेहता ने भी इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन किया। उन्होंने निर्देश किया कि व्ययों की आवश्यकता तो एक तुलनात्मक शब्द है। खर्च की किमी भी विशिष्ट मद के लिए कितनी ही अधिक आवश्यकता क्यों न हो, इस आवश्यकता की पूर्ति करते समय व्यय के लक्ष्य और दिशा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अतत करों का भार निर्धन किसानों को ही उठाना पड़ता है। इस कथन के उपरांत अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि लगान को वसूली केवल इसी ढंग से ही की जानी है तो जिन खर्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्व वसूल किया जाता है, अपने आप में भन्ने ही कितना उपयुक्त, उचित तथा निर्विवाद सिद्ध क्यों न कर दे उसका भुगतान देश के ससाधनो और शक्ति की सीमा के बाहर है।¹³

पिछले बहुत सारे वर्षों की अवधि में बढ़ते सरकारी खर्चों को सर्वथा अनुचित, नितात हानिप्रद, यहाँ तक कि भारत की निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक मानते हुए भारतीय नेताओं ने व्यापक स्तर पर सरकारी खर्चों में कटौती का समर्थन किया और उसके लिए आंदोलन किया। उन नेताओं ने यह घोषित किया कि भारत के आर्थिक तथा वित्तीय दोषों की निवृत्ति के लिए खर्चों में कटौती एक आवश्यक उपचार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बढ़े हुए सैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए अपने पहले ही अधिवेशन में अन्य सार्वजनिक व्ययों में कटौती करने का सुझाव दिया।¹⁴ कांग्रेस ने अपने 1887 के तृतीय अधिवेशन में वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए खर्चों में कटौती का सुझाव एक बार पुनः दिया।¹⁵ 1891 में कांग्रेस ने घोषणा की कि अनुचित रूप से बढ़े हुए सैनिक और नागरिक सेवाओं के खर्च भारत की दरिद्रता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थे और इन सरकारी खर्चों में कटौती भारत की दरिद्रता के निवारण के साधनों में एक थी।¹⁶ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकारी खर्चों और दरिद्रता के अकालों में सहस्रबध को तथा इन खर्चों में कटौती को बार बार 1892, 1896, 1897, 1899, 1901 और 1904 में दोहराया।¹⁷

1894, 1895 और 1897 में कांग्रेस ने अपने दृढ़ मत को पुनः बलपूर्वक दोहराया कि देश के दुर्दशाग्रस्त बित्तों में सुधार का एकमात्र उपचार सरकारी खर्चों में कटौती है।¹⁷ 1885 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में राष्ट्रीय सम्मेलन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए इसी प्रकार के सशक्त तर्क प्रस्तुत किए।¹⁸ 'पूना सार्वजनिक सभा ने,' 'बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन'¹⁹ 'मद्रास महाजन सभा'^{19-A} ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए 1886 में इस संबंध में सरकार को विस्तृत ज्ञापन दिए। जी० वी० जोशी ने अपने 1886-7 में प्रकाशित लेख 'ए नोट ऑन रिटेंचमेन्ट' में,²⁰ गोपालकृष्ण गोखले और डी० ई० वाचा ने विलबी कमीशन के समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्यों²¹ में तथा रमेशचंद्र दत्त²² ने 1898 में इसी मांग को मुखरित किया।

यहां यह जानना कम रोचक नहीं होगा कि दादाभाई नौरोजी ने खर्चों में कटौती के संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि उन्होंने भारत की निर्धनता के निवारण के लिए संपत्ति का उत्पादन बढ़ाने पर ही सारा बल दिया। उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाया जा सके तो भारत किसी भी व्यय की पूर्ति में समर्थ हो जाएगा।²³ अतः उन्होंने ऊंचे खर्चों को घटाने की आवश्यकता पर बल न देकर धन की निकासी को रोकने की आवश्यकता पर ही सारा बल दिया। यहां तक कि बड़े पैमाने पर यूरोपीयों को नौकरी देने की आलोचना भी उन्होंने इसी आधार पर की कि इससे देश से धन की निकासी होती है, न कि इस आधार पर कि इससे प्रशासन महंगा हो जाता है।

इस प्रकार सरकारी खर्चों के वर्तमान ऊंचे स्तर के कटु आलोचक तथा इन खर्चों में कटौती के प्रबल समर्थक होने के नाते राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकारी खर्चों के वास्तविक विकास की जांच के लिए तथा इन व्ययों को सीमित करने के ठोस तथा व्यावहारिक उपाय मुझाने के लिए सारी समस्या की छानबीन आरंभ की। वे इस तथ्य से सहमत थे कि सरकारी खर्चों की ऊंची दर के कारण अनिवार्य नहीं हैं, अतः उनका उपचार किया जा सकता है।²⁴

सरकारी खर्चों के मबध में राष्ट्रीय नेताओं के दृष्टिकोण का एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्होंने इसके विवरण के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनका मुख्य उद्देश्य व्यय मबधी मूल नीतियों तक ही सीमित था। इस प्रकार उदाहरण के रूप में 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मत अभिव्यक्त किया कि व्यय आयोग (एक्सपेंडीचर कमीशन) की जाच-पडताल का तब तक कोई उपयोग नहीं होगा जब तक कि इन व्ययों को नियमित करने वाली नीति की रूपरेखा की जाच-पडताल न की जाए।²⁵ इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी ने विलबी कमीशन को बताया कि वे विभागीय खर्चों के विवरण की जानकारी के प्रति कोई उत्सुकता नहीं रखते क्योंकि व्यय के समग्र प्रशासन को स्वाभाविक आधार पर स्थापित किए बिना इस प्रकार की जाच-पडताल केवल रोग के लक्षणों को दबाना मात्र होगा, इसका जड़ को दूर करना नहीं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता तो इस बात की है कि उन मिद्दातों की चर्चा की जाए जिनके अनुसार व्यय के सारे ढांचे का संचालन होता है।²⁶ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि गैर सरकारी लोग न

तो व्ययों के विवरण की समीक्षा कर सकते हैं और न ही व्ययों के सही आंकड़ों का गहरा अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध ही नहीं होती। उन्होंने टिप्पणी की कि वस्तुतः उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि व्यय के विवरण से संबंधित कौन से प्रश्न पूछें? अतः वे केवल नीतियों की सामान्य रूपरेखा की आलोचना कर सकते हैं।²⁷

सैनिक व्यय

1880 से 1905 तक की अवधि में भारतीय बजट में खर्चों का सबसे बड़ा भाग सेना पर होने वाले खर्चों का था। 1881-2 में सेना पर और सेना से संबंधित कार्यों पर होने वाले सामान्य खर्चों की कुल विशुद्ध राशि 17.88 करोड़ थी जो भारत सरकार के कुल व्ययों का लगभग 41.9 प्रतिशत था। 1885 के पश्चात् प्रमुखतया बर्मा युद्ध, उत्तर-पश्चिम में रूस के आगे बढ़ आने की आशंका, समय समय पर सेना के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए पगो और इस मद में लंदन में किए जाने वाले भुगतान में हुई विनिमय की हानि, आदि कारणों से यह राशि और भी अधिक बढ़ने लगी। समीक्षा-धीन अवधि में ऐसा ही होने वाले व्ययों में निरंतर और क्रमिक वृद्धि का इन आंकड़ों से देखा जा सकता है। 1886-7 में यह राशि 19.41 करोड़ अथवा बजट के कुल शुद्ध खर्चों का लगभग 42.4 प्रतिशत थी। 1891-92 में 22.57 करोड़ अथवा लगभग 45.4 प्रतिशत, 1901-02 में 23.55 करोड़ अथवा लगभग 45.2 प्रतिशत तथा 1904-05 में 30.22 करोड़ अथवा कुल शुद्ध खर्चों का 51.9 प्रतिशत थी।²⁸ इसके अतिरिक्त भारत को रायल नेवी (शाही नौ-सेना) को देश की सामान्य जलीय सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी जिसकी राशि विविधता लिए रहती थी। 1869 में जहा यह राशि 70,000 पौंड थी, वहा 1900 में 100,000 पौंड हो गई। इसके साथ ही भारत सरकार को स्थानीय रायल इंडियन मरीन का खर्च भी उठाना पड़ता था।²⁹ इसके अतिरिक्त युद्ध, विशेष अभियान तथा विशिष्ट सुरक्षा कार्य पर होने वाले विशिष्ट प्रकार के व्यय भार भी सहन करने पड़ते थे। 1876-7 और 1902-03 में सैनिक प्रक्रियाओं पर 22.2 करोड़ रुपये और विशिष्ट सुरक्षा कार्यों पर 4.5 करोड़ रुपये खर्च हुए।³⁰

भारतीय नेताओं ने सेना पर होने वाले खर्चों पर प्रबल प्रहार किए तथा इस विषय पर एकमत होकर निरंतर और नियमित रूप से अभियान चलाए रखा। वस्तुतः हमारे अध्ययन के अंतर्गत संपूर्ण अवधि में सेना संबंधी व्यय राष्ट्रीय आंदोलन के आक्रमण का सबसे प्रमुख लक्ष्य रहा है। यद्यपि इन नेताओं ने सेना संबंधी व्यय और उसके सभी अंशों, घनराशि के साथ साथ उद्देश्य और उसके उपयोग किए जाने के ढंग आदि की तीखी आलोचना की तथापि उनका ध्यान प्रमुख रूप से इस प्रश्न के आर्थिक पक्ष पर ही केंद्रित रहा। उदाहरणार्थ, कुछ आर्थिक प्रश्नों से संबद्ध पक्षों को छोड़कर इन नेताओं ने सैन्य संगठन, कार्यक्षमता की समस्याओं तथा सैनिक नीति की न्यूनाधिक रूप से उपेक्षा ही की। इस प्रवृत्ति का एकमात्र अपवाद सेना के भारतीयकरण की इच्छा थी।

संक्षेप में भारतीय नेताओं ने यह घोषणा की कि भारत के वित्तों के असंतुलन का

प्रधान कारण तथा ऊँचे कराधान के अस्तित्व का कारण मिलिट्री के ऊँचे और निरंतर बढ़ते हुए व्यय ही थे। उनकी यह निश्चित धारणा थी कि जब तक अनावश्यक सेना संबंधी खर्च इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे अथवा इतने ऊँचे बने रहेंगे तब तक भारतीय वित्तों में सुधार की कोई संभावना नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन से सैनिक व्यय में वृद्धि के प्रति विरोध प्रकट किया।³⁰ 1889 में कांग्रेस ने देश में सेना संबंधी व्ययों में वृद्धि की निरंतरता के स्थान पर उसमें कटौती की आवश्यकता पर बल दिया।³¹ 1891 में उसने अपना यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि देश की घोर दरिद्रता का कारण वर्तमान सैनिक और नागरिक प्रशासन पर होने वाली फिजूलखर्ची है। इसमें भी सैनिक प्रशासन की फिजूलखर्ची विशेष चिंतनीय है।³² परवर्ती वर्षों में कांग्रेस सेना के खर्चों में कटौती करने और उस कटौती को बनाए रखने की निरंतर और बार बार मांग करती रही। राष्ट्रवादियों की अन्य सस्थाएं भी समय समय पर इस प्रश्न को उठाती रही। 1885 में 'ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन', कलकत्ता की 'इंडियन एसोसिएशन', 'बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन', 'पूना मार्चजानिक सभा', मद्रास की 'महाजन सभा', कराची की 'सिंध सभा' तथा सूरत की 'प्रजा हितवर्धक सभा' ने संयुक्त रूप से अंगरेज मतदाताओं से 'भारत की अपील' शीर्षक से इंग्लैंड में इस्तहारो की एक सामान्य माला निकाली और उसका वितरण किया।³³ इस्तहार नंबर-9 का शीर्षक था '20 वर्षों में भारत के सैनिक व्ययों में 21 प्रतिशत की वृद्धि।' इसका अर्थ था कि जो सैनिक व्यय 1857 में 11,463,000 पाँड पर पहुँच गया था, वही 1884 में और अधिक बढ़कर 16,975,550 पाँड हो गया है, इसे आसानी से घटाकर 14 लाख पाँड किया जा सकता था।³⁴

बहुत सारे प्रमुख राष्ट्रवादी लोकनेताओं ने सैनिक खर्चों की विस्तार में और तीखे-पन के साथ चर्चा की। डी० ई० वाचा निश्चित रूप से इस प्रश्न पर प्रमुख राष्ट्रवादी प्रवक्ता थे। इस विषय पर दिए गए उनके भाषणों और लिखे गए लेखों को यदि एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए तो एक काफी बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। 1885 में उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए 1871 में सेना पर किए जा रहे खर्चों में वृद्धि की समीक्षा की तथा इस घोर पातक के लिए सरकार की भर्त्सना की।³⁵ 1891 के कांग्रेस के अधिवेशन में एक अन्य विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस समय सेना के खर्चों में कष्टदायक वृद्धि के प्रश्न के समान दुःखदायक अन्य कोई प्रश्न नहीं। सेना पर होने वाले व्ययों में वृद्धि तो देसवासियों की क्षमता को खाए जा रही है।³⁶ उन्होंने अपने इसी दृष्टिकोण को परवर्ती वर्षों में बार बार दोहराया।³⁷ जी० बी० जोशी ने प्रथम अपने 1886 में प्रकाशित निबंधों 'ए नोट आन रिट्रिचमेंट' और 'दि नेटिव इंडियन आर्मी' में देश के वित्तों पर बढ़ते हुए सैन्य व्ययों के घातक प्रभाव की जांच की।³⁸ उन्होंने 1886 में प्रकाशित अपने लेख 'दि प्रेजेंट फाइ-नांशल पोजीशन' में विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर अपना आरोप दोहराया।³⁹ अत्यधिक सैन्य व्ययों के विरुद्ध अभियान चलाए रखने वाले गोपालकृष्ण गोखले एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे।⁴⁰ अनेक अन्य राष्ट्रवादी जननेताओं ने भी बराबर जोशो खरोशे के साथ बड़े सैनिक व्ययों के विरुद्ध भाषण दिए तथा लेख लिखे।⁴¹ इसी प्रकार

राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं ने भी सैन्य व्ययों के विरुद्ध बराबर जोरदार आवाज उठाई और इन व्ययों में कटौती की मांग के लिए दबाव डाला।⁴²

भारतीय नेताओं ने मिलिट्री के खर्चों की आलोचना के लिए केवल उन खर्चों के विस्तृत आकार को ही अपना आधार नहीं बनाया प्रत्युत भारतीय संसाधनों की शून्यता पर विचार करते हुए उनके औचित्य को भी समीक्षा का आधार बनाया। उन्होंने इस मिद्धान पर बल दिया कि देश की सुरक्षा और मेना संबंधी आवश्यकताओं को मिलिट्री के खर्चों के उपयुक्त आकार के निर्धारण की एकमात्र कसौटी न मानकर देश की उन खर्चों को सहन करने की क्षमता को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।⁴³ अतएव उनका तर्क था कि इस समय देश सशस्त्र सेनाओं पर जितना व्यय कर रहा है, वह उसकी सहनशक्ति के बाहर है।⁴⁴ कुछ लोगो ने तो यह तथ्य प्रतिपादित किया कि सैन्य खर्चों का इससे बढ़कर अधिक निदनीय पक्ष क्या हो सकता है कि भारत जैसा निर्धन देश अपने वार्षिक राजस्व का जितना बड़ा भाग मना पर खर्च कर रहा है, उतना तो ब्रिटेन और जारशाही रूस को मिलाकर विश्व के अपेक्षाकृत अधिक विकसित, अधिक संपन्न और सैनिक तानाशाह देश भी नहीं कर रहे।⁴⁵ उन्होंने यह तथ्य भी प्रस्तुत किया कि सैनिक खर्चें भारत के सारे विशुद्ध भूराजस्व को हजम कर जाते हैं। उन्होंने इस तथ्य का प्रयोग इस महंगे मयस्त्र रानाओं के सैन्यनत्र को भारत द्वारा वहन करने में उसकी अक्षमता के प्रमाण के रूप में किया।⁴⁶ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सातवें अधिवेशन में डी० ई० वाचा ने टिप्पणी की कि 'दरिद्र किसानों का खून चूसा जा रहा है ताकि सैनिक करभोक्ता मजे उठा सकें, स्टार और मंडल प्राप्त कर सकें।'⁴⁷

भारतीय नेताओं के अनुसार भारत की आर्थिक क्षमता के बाहर सैन्य खर्चों का प्रत्यक्ष तथा कदाचित् निकृष्टतम दुष्परिणाम यह हो रहा था कि सरकार एक ओर तो सेना पर पानी की तरह रुपया बहा रही थी और दूसरी ओर राष्ट्र निर्माता विभागों पर बहुत कम खर्च कर रही थी। इस प्रकार देश की स्वस्थ आंतरिक प्रगति और आर्थिक विकास को धक्का लग रहा था। समस्या के इस तथ्य को प्रायः ही प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया गया। उदाहरणार्थ, डी० ई० वाचा ने 1891 में चिंतित होकर आश्चर्य प्रकट किया : 'यदि भारत का 54 करोड़ का बड़ा भारी अनावश्यक, सामान्य से अतिरिक्त और फालतू खर्चा 5 वर्षों में बचाया गया होता तो भारत न जाने कितना सुखी-संतुष्ट, कितना संपन्न तथा कितना उन्नत हो गया होता।'⁴⁸ दस वर्षों के उपरांत उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा : 'जनता के कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, देश के सभी आंतरिक सुधारों के मार्ग में प्रधान बाधा मिलिट्री के खर्चें हैं।'⁴⁹ इसी प्रकार तिलक के 'केसरी' ने अपने 15 अप्रैल 1902 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा : 'घरेलू प्रशासन के मामलों में जनता के हितों के प्रति सरकार की उपेक्षा वृत्ति का वास्तविक कारण भारत के बढ़ते हुए मिलिट्री के खर्च ही है।'⁵⁰ जी० के० गोखले ने 1903 में इस तथ्य पर कि 1885-1898 की अवधि में सरकार द्वारा जनता से अतिरिक्त राजस्व के रूप में इकट्ठी की गई 120 करोड़ रुपये की धनराशि में से लगभग 80 करोड़ रुपया सेना द्वारा हड़प लिया गया है और इस विशाल धनराशि में से सार्वजनिक शिक्षा के भाग में आधे करोड़ रुपये से भी कम रकम

आई है, शोक प्रकट करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा कि जब हमारे राजस्व निरंतर बढ़ते हुए सेना के उद्देश्यों की पूर्ति की ओर ही उन्मुख किए जा रहे हैं तब राज्य द्वारा किसी बड़े परिणाम पर जनता की भौतिक समृद्धि तथा नैतिक प्रगति से संबंधित किसी सुदृढ़ और स्थाई प्रयास की संभावना के लिए अवकाश ही नहीं।⁵¹

ऊंचा सैन्य व्यय तथा सुझाए गए उपाय

भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि ऊंचे सैन्य व्ययों की कोरी निंदा करना ही काफी नहीं है क्योंकि सरकारी अधिकारी इस तथ्य से तो इनकार ही नहीं करते कि ये खर्च ऊंचे हैं। उनका तर्क तो यह रहता है कि ये खर्च अनिवार्य है और भारत साम्राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनमें किसी प्रकार की कटौती संभव नहीं। उदाहरणार्थ 1894-5 के वित्तीय विवरण पर हुए विवाद में जनरल ब्रिक्बरी ने सैन्य व्ययों के आलोचकों को उत्तर देते हुए कहा था :

मैंने निंदा प्रस्ताव देखे हैं, मैंने आरोप पत्र देखे हैं, मैंने जोरदार वक्तव्य सुने हैं, मैंने भारत सरकार से खर्चा घटाने की अपीलें भी देखी हैं, परंतु किसी व्यक्ति ने भी इस संबंध में कोई एक भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया कि किस प्रकार उचित मात्रा में सैन्य व्ययों में कटौती की जा सकती है।⁵²

इस प्रकार लार्ड कर्जन के वायसराय काल में सैन्य व्यय उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते आसमान पर पहुंच गए इसके बावजूद उसने 1901 में घोषणा की :

मुझे इस तर्क से जरा भी क्षोभ नहीं पहुंचा कि सेना पर किया जाने वाला साग व्यय निरर्थक है और इस धन का अधिक अच्छा उपयोग देश के आर्थिक विकास की योजनाओं पर खर्च करके किया जा सकता है। मैं बड़ी प्रसन्नता से सारे राजस्व को ही विकास योजनाओं पर खर्च करने को प्रस्तुत हूं परंतु मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना की आवश्यकता है और भारत को सुरक्षित नहीं माना जा सकता।⁵³

इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नेता सैन्य व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों की जांच-पड़ताल करने और तदनुरूप उपायों को सुझाने के लिए विवश हो गए। परंतु इस महत् कार्य को हाथ में लेकर भी इन नेताओं ने इस प्रश्न के व्यापक नीति संबंधी पक्षों के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखा। उन्होंने न तो कोई व्यावहारिक सुझाव दिए और न ही सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए अपेक्षित तकनीकी प्रशासनिक विवरणों का अध्ययन किया।⁵⁴ इस दृष्टिकोण का स्पष्ट और युक्तियुक्त प्रतिपादन डी० ई० वाचा ने 1895 में उस समय किया, जब उन्होंने यह टिप्पणी की कि अधिकारी लोग सेना के खर्चों के आलोचकों से रचनात्मक सुझावों की मांग तो इस प्रकार कर रहे हैं, जैसे कि मानो इन आलोचकों के पास सारे सूक्ष्म तथा विस्तृत विवरण उपलब्ध हों और इनकी सहायता से उनके लिए सुझाव भेजना संभव है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें 'रचनात्मक' कहे जाने वाले सुझावों का भेजना संभव ही नहीं है। रचनात्मक प्रस्ताव देने के लिए जब हम अपेक्षित सामग्री ही नहीं दी जाती तो हम केवल समीक्षा ही कर सकते

हैं और इसके लिए हमें दोष नहीं दिया जा सकता।⁵⁵ विध्वंसक आलोचना का कार्य भारतीय नेताओं ने प्रभावात्मकता, सशक्तता तथा व्यापकता के साथ किया। वास्तव में जो थोड़े बहुत विधाई उपाय इन नेताओं ने सुझाए भी, वे भी मूलतः प्रभाव की दृष्टि से विध्वंसक थे।

हमारे अध्ययन की अवधि में विभिन्न युद्ध, जिनमें भारतीय सेनाओं ने भाग लिया था, तथा अनेक बड़े पैमाने के साहसिक अभियान जिन्हें भारत सरकार ने अपनाया था, ही सेना के खर्चों में वृद्धि के प्रमुख आधारभूत कारण थे। 1876-7 में 1902-03 की अवधि में ही अकेले इस खाते में जुड़न वाली अतिरिक्त खर्चों की राशि लगभग 22 करोड़ रुपए थी।⁵⁶ भारतीय नेताओं ने इन युद्धों और अभियानों में भाग लेने की निंदा की। उनके इस दृष्टिकोण का प्रमुख आधार तो आर्थिक कारण थे परंतु साथ ही उनके विरोध का आधार राजनीतिक नैतिकता भी थी और वस्तुतः उनके अनुसार इन युद्धों तथा अभियानों से भारतीयों के हितों तथा उद्देश्यों का तो सबंध ही नहीं था। इनसे ब्रिटेन के प्रादेशिक तथा व्यापारिक विस्तार के हित ही मुख्य रूप में जुड़े हुए थे। भारतीय नेताओं ने लगभग उन सभी युद्धों को सर्वथा अनावश्यक तथा ब्रिटिश लोलुपता की सृष्टि घोषित किया। भारतीय नेताओं ने इन युद्धों और अभियानों पर हुए खर्चों को इंग्लैंड और भारत के बीच वाटने के अनुचित तथा अन्यायपूर्ण ढंग की भी आलोचना की क्योंकि उनके अनुसार इन युद्धों आदि से होने वाले सार के सारे लाभ तो इंग्लैंड ने उठाए थे जबकि उन पर होने वाले खर्चों भारत के मते भुगट दिए गए थे। इन नेताओं ने प्रायः यह मांग की कि इनके सारे ही खर्चों का भुगतान ब्रिटेन को करना चाहिए। निंदित और आलोचित युद्धों और अभियानों में अधिक उल्लेखनीय थे—1878-80 का अफगान युद्ध, 1882 में मिस्र पर अभियान, 1884-5 में सूडान पर आक्रमण, 1885 में बर्मा का संयोजन, 1888 में सिक्किम पर अभियान, 1895 में चित्तल पर अभियान, 1896 में मिस्र पर अभियान और 1903-04 में तिब्बत पर अभियान।⁵⁷

राष्ट्रवादी नेताओं के मत में सेना के अनावश्यक ऊँचे खर्चों का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भारतीय सेना का अनावश्यक रूप से विस्तृत आकार था। 1885-87 में रूसी खतरे का सामना करने के लिए 10000 बर्तानवी सैनिकों की और 20000 भारतीय सैनिकों की भरती करके इस सीमा तक भारतीय सेना में वृद्धि करने को और लगभग 2,26,700 सैनिकों की सेना रखने को⁵⁸ राष्ट्रवादियों ने सर्वथा अवांछनीय, हर तरह से अनावश्यक बताया और इसीलिए उस पर होने वाले व्यय को सार्वजनिक कोषों का व्यर्थ दुरुपयोग बताकर उसका तीव्र विरोध किया।⁵⁹ आगामी वर्षों में इन नेताओं ने दृढ़तापूर्वक यह मत व्यक्त किया कि सेना देश की न्यायोचित आवश्यकताओं से बहुत अधिक बढ़ गई है अतः उसमें यथाशीघ्र कटौती की जानी चाहिए।⁶⁰ बाद में जब 1896 में सूडान में, 1899-1900 में दक्षिणी अफ्रीका में और 1900-01 में चीन में भारतीय सैनिक टुकड़ियों को ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भेजा गया तो भारतीय नेताओं ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इन मामलों में बड़ी संख्या में सैनिकों को देश से बाहर भेजा गया है और इससे देश की आंतरिक अथवा बाहरी सुरक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं

हुई। यह घटना इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि सेना में कटौती बड़ी आसानी से की जा सकती है।⁶¹ सेना की अधिकता की व्यर्थता के उप सिद्धांत के रूप में नेताओं ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जब कभी सेना की संख्या तथा उसकी क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है, उन कदमों का अंतिम निर्णय सुरक्षा से संबंधित विषयों के सदर्भ में नहीं हुआ है। सामान्य रूप में ब्रिटेन के शाही हितों की सुरक्षा और उन्नयन के विचारों को महत्व दिया जाता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1903 और 1904 के अधिवेशनों में इस विचारधारा को बड़ी स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ प्रतिपादित किया।⁶² 1896 में विलबी कमीशन को भेजे अपने एक संप्रेषण में दादाभाई नौरोजी ने असाधारण प्रखरता तथा कटुता के साथ इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में यत्न किया

वास्तव में सारी यूरोपीय (अर्थात् भारतीय) सेना ब्रिटिश सेना का अविभाज्य अंग है। ब्रिटिश सेना द्वारा भारत को एक श्रेष्ठ प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में समझा जाता है और उसी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी मूल्य पर अंगरेजों के लाभ, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए तथा उनके देशवासियों के लिए आखेट स्पल के रूप में, एक ब्रिटिश साम्राज्य तथा यूरोपीय सम्मान की सुरक्षा की दृष्टि में ही भारत का उपयोग किया जाता है। भारतीय लोगों के साथ दासों का व्यवहार किया जाता है। उन्हें मालिकों की चर्म उन्नति के लिए सारे खर्चों के भुगतान के गर्व गौरव का अनुभव करने को तो मिलता है परंतु सारे मामले में जरा भी जबान खोलने की अनुमति नहीं मिलती।⁶³

इसी प्रकार गोखले ने अपना निश्चित मत अभिव्यक्त किया कि ब्रिटिश नीति एशियाई साम्राज्यों को हड़पने की तथा यूरोपीय शक्तियों की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संसाधनों का प्रयोग करने की ही रणनीति है।⁶⁴ बहुत सारे अन्य भारतीयों ने भी इसी उग्रता से लेख लिखे तथा भाषण किए।⁶⁵

भारतीय नेताओं ने मांग की कि भारत की प्राकृतिक समीपों के बाहर के सैन्य उद्देश्यों के लिए भारतीय मशमूर सेनाओं का उपयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सेवा के लिए भारतीय राजस्वों का व्यय नहीं किया जाना चाहिए।⁶⁶ उन्होंने कहा कि शाही उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट भारतीय सेना के भाग विशेष के भरण-पोषण का, भारत में स्थित सुरक्षित ब्रिटिश सेना का और शाही युद्धों में प्रयुक्त भारतीय सेना के व्यय का सारा भार ब्रिटिश सरकार को वहन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखने से यह सब सर्वथा उपयुक्त तथा न्यायोचित ही होगा।⁶⁷ जब ब्रिटिश सरकार ने 1903 में भारतीय नेताओं द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी अफ्रीका में नियुक्त ब्रिटिश-सेना की एक टुकड़ी के भरण-पोषण के व्यय के कुछ भाग का भुगतान भारतीय राजस्व से करने की योजना की घोषणा की तब उसे सुनकर भारतीय नेता तिलमिला उठे। उन्होंने बहुत दूरस्थ प्रदेश दक्षिणी अफ्रीका में शांति स्थापित करने के लिए किए जा रहे खर्चों के भार की भारत के ऊपर डालने की चेष्टा को एक धूर्ततापूर्ण और निंदनीय योजना घोषित की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साम्राज्य के उद्देश्यों के लिए भारतीय धन को खर्च

करने का यह एक दूसरा उदाहरण था। उन्होंने अपनी भावनाएं प्रायः तीखी और कठोर भाषा में ही अभिव्यक्त की। उदाहरण के रूप में 'ग्रेडवोकेट' ने अपने 23 जुलाई 1903 के अंक में लिखा था। भारतीयों की छाती से माम के एक और बड़े टुकड़े को काटने के लिए मि० ब्रोडरिक ने अपना छुरा तेज कर लिया है।¹⁴ 'इंडियन सोशल रिफार्मर' ने 19 जुलाई 1903 के अंक में भारत को लूटने की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हुए भारतीय लोक नेताओं से कहा कि वे दस आदेशों की सी-सी-मादी शब्दावली में इस घृणित योजना की निंदा करें।¹⁵ दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट शब्दों में ग्रेटो के समान दार्शनिक भाषा में लंदन की सभा में उपस्थित लोगों से पूछा : 'वे कौन से कारण हैं और वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने हमारे शासकों के मन को इतना अधिक कलुषित कर दिया है कि उन्हें ऐसा नीच और घृणित सुझाव देना पड़ा है ?'¹⁶

भारतीय नेताओं ने यूँ तो अपना सारा ध्यान प्रायः सैन्य-व्यय के नीतिपरक पहलुओं की सामान्य समीक्षा तक ही सीमित रखा, कुछेक नेताओं ने अवश्य 1890 की अवधि में अग्रिम सीमा नीति के अगनाने के फलस्वरूप सैन्य-व्ययों में वृद्धि होने में पूर्व ही सैन्य-संगठन के पक्षों को विशेष रूप से आलोचना और समोधन का आधार बनाया।

सामान्यतः अधिकांश भारतीय नेताओं की आलोचना में केवल अस्पष्ट और थोड़े से नेताओं की अभिव्यक्ति में सुस्पष्ट प्रस्तुत किया गया। पहला आक्षेप यह था कि भारतीय सेना जहाँ एक ओर अधिक खर्चीली है वहाँ दूसरी ओर अपेक्षित रूप में कुशल नहीं है।¹⁷

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने यह सिद्ध करने के लिए तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत किए कि भारत में सेना का प्रति सैनिक मूल्य सारे विश्व से ही उच्चतम था। उन्होंने आंकड़ों से सिद्ध किया कि यूरोप में जर्मनी के कुशलतम सैन्यतंत्र से भी भारतीय सेना का व्यय अधिक ऊँचा था। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में हुए व्यय से भी यह व्यय अधिक ऊँचा था।¹⁸ उन नेताओं के विचार में भारतीय सेना के महंगेपन के लिए कई तत्व उत्तरदाई थे। उनका कहना था कि 1859 की एकीकरण योजना, अल्प-कालीन सेना पद्धति, इंग्लैंड में भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली, इंग्लैंड और भारत के मध्य ब्रिटिश सेनाओं के परिवहन की पद्धति, अनुपयोगी सेवाओं का विकास तथा ब्रिटिश सैनिकों को पेंशन देने जैसी बातों ने भारत पर व्यर्थ का गलत और अनावश्यक रूप से ज्यादा वित्तीय भार डाल दिया है इसलिए इन खर्चों को समाप्त करने की अथवा उनमें कटौती करने की आवश्यकता है।¹⁹ 1897 में विलबी कमीशन के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जी० के० गोखले ने भारतीय स्टाफ कार्पर्स सिस्टम पर कटु प्रहार किए। गोखले ने वक्ता से टिप्पणी की कि सेना में उन्नति की पद्धति सेनाओं की आवश्यकता के संदर्भ में नियमित नहीं की गई प्रत्युत अफसरों के हितों को देखते हुए ही उसका नियमन किया गया है। इसका अर्थ तो यह निकला कि सेना अधिकारियों के लिए है अधिकारी सेना के लिए नहीं हैं। वास्तव में उनके चितन का निष्कर्ष यह था कि सेना के अधिकारियों को उनके सेवा काल में तथा सेवा निवृत्ति के उपरांत आवश्यकता से बहुत अधिक वेतन दिया जाता है।²⁰

एकाध भारतीय नेताओं का तो यहां तक विश्वास था कि भारत स्थित ब्रिटिश सैनिकों के वेतन और भत्ते आदि एकदम अपव्यय थे। उदाहरणार्थ 'इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 15 अगस्त 1880 के अंक में यह निर्देश किया कि यूरोप में किसी एक सैनिक पर आने वाले व्यय की तुलना में भारत स्थित ब्रिटिश सैनिक पर व्यय पांच गुना अधिक आता है। 'पत्र' ने टिप्पणी करते हुए लिखा :

छंटाई की छुरी का चलाना नितांत आवश्यक हो गया है। निश्चित रूप से ही हम यह नहीं चाहते कि हमारे सिपाही विलासिता का जीवन बिताएं। '...हम यह तो किसी भी रूप में नहीं देखना चाहते कि वीर ब्रिटिश सैनिक घटिया वस्त्र पहनें और घटिया भोजन खाएं परंतु लोगों की आशंका यह है कि वे यदि आवश्यकता से अधिक बढ़िया वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन अवश्य आवश्यकता से अधिक बढ़िया खाते हैं। '...हमारा भी विश्वास है कि स्वदेशी सेना को मिलने वाले तुच्छ राशन की तुलना में ब्रिटिश सैनिक अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।'⁷⁵

जब इंग्लैंड में हुई वेतन-वृद्धि के समान भारत में ब्रिटिश सैनिकों के वेतन में भी 1902 में वृद्धि की गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके साथ साथ अन्यान्य नेताओं ने इस पग के विरुद्ध अपना अत्यंत सशक्त विरोध प्रकट किया।⁷⁶ यहां उल्लेखनीय है कि उस समय कुछ ने तो भारतीय सैनिकों के वेतन में वृद्धि की वकालत की⁷⁷ और जब भारत सरकार ने 1895 में भारतीय सैनिकों का वेतन 7 रुपये से बढ़ा कर 9 ६० माह कर दिया तो उनमें से बहुत सारे नेताओं ने 'हर्षवर्धक समाचार' के रूप में इस पग का स्वागत किया।⁷⁸

कुछ भारतीय नेताओं द्वारा बचत का सुझाया गया दूसरा उपाय था पृथक अध्य-क्षीय कमानों की समाप्ति, क्योंकि उनके वक्तव्य के अनुसार केंद्रीय शाही नियंत्रण के कारण सैनिक दृष्टि से उनकी सार्थकता निस्स्मर तथा नामशेष हो गई थी। उस समय तो उन्हें बनाए रखने का एकमात्र उद्देश्य बिना कार्य के ही अधिकारियों को वेतन जुटाना था।⁷⁹ भारतीय नेताओं ने लार्ड किचनर की 1904 की सेना के पुनर्विभाजन और पुनर्गठन की योजना का भी विरोध किया क्योंकि इसके साथ अतिरिक्त खर्चे जुड़े हुए थे। उन्होंने मांग की कि इस योजना का भार भारतीय राजकोष पर नहीं डालना चाहिए।⁸⁰

सैन्य विभागों के प्रश्न पर किचनर-कर्जन मतभेद⁸¹ के प्रति भारतीय नेताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग किस सीमा तक सैन्य-व्ययों में बचत के लिए कृत-संकल्प थे। इस मतभेद का, जिम पर कर्जन ने स्वयं अपने वायसराय पद के भविष्य तक को दांव पर लगा दिया था, पता जनता को 1905 में उस समय चला, जब कर्जन द्वारा बनाए गए यूनीवर्सिटी ऐक्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय में उसके द्वारा दिए गए दीक्षांत भाषण तथा बंगाल के किए गए विभाजन के कारण राष्ट्र-वादी कर्जन के प्रबल विरोधी बन गए थे। उन नेताओं के लिए अपनी घृणा के पात्र, जिसके विरुद्ध वे प्रचंड संघर्ष करते आ रहे थे, के विरोधी किचनर का समर्थन करना सहज और मानवीय कृत्य ही था। परंतु उनके द्वारा कर्जन का किया गया विरोध किसी व्यक्तिगत कारण से प्रेरित नहीं था प्रत्युत उसका मूल-आधार राष्ट्रीयतावाद ही था,

अतः उन्होंने प्रधान सेनापति की शक्तियों में वृद्धि द्वारा सैन्यव्ययों में वृद्धि की संभावना की आशंका में किचनर और भारत सचिव के विरुद्ध मर्देव कर्जन के पक्ष का समर्थन किया। हां, यह बात दूसरी है कि इन लोगों का यह समर्थन उत्साह शून्य था और कभी कभी तो उसका स्वर भी मंद रहता था।⁸²

कुछ भारतीय नेताओं के मत में भारत में सेना के ऊंचे खर्चों के लिए उत्तर-दायी एक अन्य तत्व था, भारतीय सेना में महंगी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों का अधिक अनुपात। इस कारण से तथा बहुत सारे अन्यान्य कारणों से इन नेताओं ने सेना के भारतीयकरण की मांग की।⁸³ हां, थोड़े-बहुत नेताओं ने यह अवश्य स्वीकार किया कि भारत सरकार की विदेशी प्रकृति के कारण उसके लिए भारत में एक निश्चित संख्या में ब्रिटिश सैनिकों का रखना एक प्रकार से अनिवार्य सा हो गया है परंतु उनका सुझाव यह था कि उन सैनिकों की संख्या इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितनी कि उस समय थी।⁸⁴ इसके अतिरिक्त बहुतों का तो यह भी तर्क था कि ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों की आवश्यकता विदेशी शासन को बनाए रखने के लिए है। अतः उनका सारा खर्चा ब्रिटिश वित्तों को ही उठाना चाहिए। यदि सारा नहीं तो कम से कम भारत के माथ इस खर्च का भागीदार तो बनना चाहिए।⁸⁵ उन्होंने भारतीय सैनिकों को अधिकारी बनने का अवसर देने से इनकार को भी आलोचना की तथा अनुभव किया कि यह अन्यान्य आधारों के अतिरिक्त वित्तीय आधार की दृष्टि से आपत्तिजनक है क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी भारतीय अधिकारियों की अपेक्षा अधिक महंगे पड़ते थे। अतः उन्होंने भारतीयों के लिए सेना की सेवा में उच्च पदों के द्वार खोलने का अनुरोध किया।⁸⁶ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस मांग को उठाने के पीछे वित्तीय आधार कदाचित् अपेक्षाकृत गौण कारणों में से एक था।

जी० वी० जोशी और जी० के० गोखले ने भी भारतीय सेना में किसी भी प्रकार की बालटियर पद्धति राष्ट्रीय देशरक्षक सेना तथा रिजर्व सेना के अभाव में स्थाई सेना को युद्ध के लिए निरंतर तैयार रखने की नीति की आलोचना की। उनका कथन था कि इससे अन्यान्य दुर्बलताओं के साथ देश में नपुंसकता की प्रवृत्ति पनपती है और देश के वित्तों का व्यर्थ दुरुपयोग होता है जिसके फलस्वरूप करदाता को अपने भुगतान के अनुरूप प्रतिदान नहीं मिल पाता है। उनका कथन था कि किसी देश की क्षमता का आधार सकलकाल में सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर सकना होता है। जहाँ अन्य देशों ने अपनी शांति काल की सेना में अल्पकालिक सूचना से ही अनेक समयों में अपेक्षित वृद्धि कर ली है, वहाँ भारत एक भी बटालियन के विस्तार की सामर्थ्य नहीं रखता, अकगणना की दृष्टि से खर्चों में वृद्धि के रूप में सेना में वृद्धि दिखा देना दूसरी बात है। इससे भारतीय पद्धति अकुशल और विनाशात्मक रूप से अपव्ययी तथा महंगी बन जाती है। दूसरी ओर उनका सुझाव यह था कि रिजर्व सेना की पद्धति को अपनाने से एक तो सरकार सेना की संख्या में कटौती कर सकेगी और दूसरे इससे 14 ताँ को राहत मिलेगी। उल्लेखनीय यह है कि इस सबका कुल मिलाकर देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उनसे इससे उसकी क्षमता में वृद्धि ही होगी।⁸⁷

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित दूसरा पग था, बालटियर

पद्धति की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 में ही इस माधन को अपनाने की बकालत की थी और इसके उपरांत लगभग प्रतिवर्ष उसने इस मांग को दोहराना जारी रखा।⁸⁹ इस मांग का प्रत्यक्ष प्रयोजन देश की सुरक्षा-क्षमता में वृद्धि करना था परंतु इन प्रस्तावों पर वक्तव्य देने वाले प्रायः ही इसके वित्तीय लाभों का ही गुणगान करने लग जाते थे।⁹⁰

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि किसी भी अन्य तत्व की अपेक्षा सीमा-वर्ती अभियान और उन अभियानों के लिए की जाने वाली तैयारियां ही सेना को बड़ी भारी संख्या में बनाए रखने के तथा दुस्प्रद व भारस्वरूप सैन्य व्ययों के लिए उत्तरदायी तत्व थे। क्योंकि इन अभियानों का संबंध सरकार की सीमा नीति से था अतः भारतीय नेताओं ने इस नीति की विस्तृत रूप से भर्त्सना की तथा इस नीति को छोड़ने के लिए सरकार पर दबाव डाला।⁹¹ इसके अतिरिक्त इन नेताओं ने मांग की कि यदि सरकार के लिए अग्रगामी सीमा नीति को छोड़ना संभव नहीं तो इंग्लैंड को या तो सारे का सारा अथवा उल्लेखनीय परिमाण में खर्च का भार उठाना चाहिए क्योंकि यह नीति प्रधानतया इंग्लैंड के सामाजिक लक्ष्यों व हितों के लिए अपनाई गई है तथा इंग्लैंड ही इनसे प्रमुख रूप से लाभान्वित होता है।⁹²

हम ऊपर इस बात का विवेचन कर चुके हैं कि किस प्रकार राष्ट्रवादियों ने यह मांग पेश की कि भारत के विदेशी युद्धों में भाग लेने के सारे अथवा आंशिक व्यय का, भारत स्थित ब्रिटिश सेना के भरण-पोषण के व्यय के भाग का, भारत की आवश्यकता से बढ़-चढ़ कर शाही उद्देश्यों के लिए हुए सैन्य व्ययों का, सीमावर्ती अभियानों में हुए व्यय का तथा सामान्य रूप से इस प्रकार की अग्रगामी नीति के अपनाने से होने वाले व्यय का भार ब्रिटेन को उठाना चाहिए। अपने युग के कुछ प्रमुख नेता तो एक पग और आगे बढ़कर यहां तक कहने लगे कि भारत के सामान्य मैनिक व्यय में ब्रिटिश कोष को अपना योगदान देना चाहिए। यह मांग इस अपील के साथ जुड़ी हुई थी कि भारत के समग्र प्रशासकीय व्यय में इंग्लैंड को अंशदान करना चाहिए।

इस विचित्र मांग के पीछे विद्यमान तर्क इस मांग से भी अधिक रोचक हैं तथा भारत में ब्रिटिश राज्य के उद्देश्यों के संबंध में राष्ट्रवादी नेताओं की गहरी जानकारी पर बहुत प्रकाश डालते हैं। निष्कर्ष रूप में राष्ट्रवादियों का तर्क यह था कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा में इतनी अधिक रुचि रखते हैं, जितनी कि भारत स्वयं, क्योंकि अंगरेजों को भारत पर शासन करने में महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनैतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस तर्क को प्रायः ही पर्याप्त सुस्पष्ट तथा सुदृढ़ भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 1893 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने प्रश्न किया :

ब्रिटेन के इतने गहरे, व्यापक और महान हितों के साथ साथ महत्ता और संपन्नता अनिवार्यतः पूर्वी साम्राज्य पर निर्भर है और इसके साथ अविच्छिन्न रूप से संबंध है। क्या यह उचित है, क्या यह न्यायसंगत तथा वांछनीय है कि ब्रिटेन की इस महानता, प्रतिष्ठा और समृद्धि का सारा मूल्य दरिद्र भारतीय जनता की गर्दन पर लाद

दिया जाए ? इसमें तो यही ज्ञान होना है कि मैकाले द्वारा निदनीय रूप से यथा-निर्दिष्ट इंग्लैंड और भारत के संबंध जैसे कि पारस्परिक लाभों के न होकर केवल स्वामी और दास के ही हों ।⁹²

इस भाग के लिए जीवनपर्यंत आंदोलन करने के उपरगत देश के इस महान सपूत तथा भारतीय राष्ट्रीयतावाद में मृदु प्रवृत्ति के संस्थापक महान वृद्ध नेता ने प्रत्यक्ष कटुता के साथ लिखा : भारत में यूरोपीय सैन्य-व्यय का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शक्ति पर, ब्रिटिश सम्मान पर, ब्रिटिश हितों के लिए प्रतिवर्ष चार-पाच करोड़ की अन्यायपूर्ण लूट पर रूस के संभावित आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करना है ।⁹³ इसी प्रकार 1895 में पी० सी० राय ने साहमपूर्वक पूछा : यदि रूस ने भारत को कभी जीत भी लिया (भगवान ऐसा दुर्भाग्य का दिन न दिखाएँ) तो क्या अकेले भारत की ही हानि होगी ? क्या इंग्लैंड को इससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी ? क्या इंग्लैंड की महत्तम शक्ति अत्यंत मूल्यवान बाजार उसके हाथ में नहीं छिन जाएंगे ? और इस संबंध में उन्होंने लार्ड रडोल्फ चर्चिल को उद्धृत किया : भारत के बिना तो इंग्लैंड राष्ट्र ही नहीं रह पाएगा ।⁹⁴ पूना के एम० एम० पराजपे द्वारा संपादित उग्रवादी समाचारपत्र 'कल' तो अपने 28 अगस्त 1903 के अंक में यह घोषणा करने हुए विद्रोह की सीमा के निकट ही पहुंच गया कि यदि रूस भारत पर आधिकार कर ले तो इसमें भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा । इस पत्र ने लिखा :

भारतीय किसान यथापूर्व अपने खेत जोत रहे हैं । ये खेत देश से बाहर नहीं ले जाए जा सकते । भारतीय किसान की दशा पहले ही इतनी अधिक शोचनीय है कि रूसी आक्रमण से भी वह और अधिक विषम बन ही नहीं सकती । अतः रूस के आक्रमण से सुरक्षा की चिंता तो प्रधान रूप से हमारे शामकों को ही बर्गनी चाहिए, क्योंकि इस आक्रमण से वे ही सिद्धान्त रूप में प्रभावित होंगे । उन्हें ही भारत के आधिपत्य से राख धोने पड़ेगे ।⁹⁵

भारत में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सैनिकों की नियुक्ति की मना के अपेक्षाकृत उच्च पदों से भारतीयों के बहिष्कार की, तथा रिजर्व दल बनाने की अपेक्षा स्थाई मना पर निर्भरता की आलोचना करते हुए भारतीय नेताओं में अधिक जागरूक लोग इस तथ्य में ठीक ही परिचित थे कि भारत के लोगों को निहत्था बनाने की प्रवृत्ति के साथ साथ समुक्त रूप से ही उपर्युक्त प्रवृत्तियों पर विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों के इस प्रकार के निर्णय में किसी प्रकार की भूलचूक नहीं थी । वस्तुतः उन्हें भारतीय लोगों के हृदय में अपने (अंग्रेजों के) प्रति गहरी घृणा और भय का पता था और इसी सदर्भ में उनके ये पग थे । 'मराठा' ने अपने 29 मार्च 1891 के अंक में घोषणा की कि भारत के सैन्य व्यय में हो रही वृद्धि का एकमात्र कारण यह था कि ब्रिटिश शासक अधिकाधिक अलाव-प्रिय होते जा रहे हैं और उनके प्रति जनता की घृणा बढ़ती जा रही है । इसके फलस्वरूप जनता में सताष की भावना को बलपूर्वक थोपने के लिए और उनके पारो और एक तटस्थ क्षेत्र बनाने के प्रबल प्रयास किए जा रहे हैं । पी० सी० राय ने 1885 में लिखा कि भारतीय सेना में यूरोपीय तत्वों की व्यापक वृद्धि का प्रधान कारण भारत को मात्र पशु-बल से अपने अधीन बनाए रखने की नीति है । उन्होंने टिप्पणी की कि यह आविश्वास

भावना न केवल हमारे शासकों को देश पर शस्त्रबल से शासन करने को प्रोत्साहित करती है प्रत्युत निकृष्टतम संकटकालीन स्थिति का उपयुक्त और प्रभावी सामना करने के लिए सदैव सैनिक दृष्टि से उद्यत रहने की प्रेरणा भी देती है।¹⁹⁶ 'अमृत बाजार पत्रिका' ने भी अपने 6 सितंबर 1894 के अंक में इसी भावना को प्रतिध्वनित करते हुए लिखा, भारतीय सेना के खर्चों में वृद्धि का कारण शासकों के मन में जनता के प्रति अविश्वास-भावना है। इससे पूर्व पत्रिका ने अपने 3 सितंबर 1885 के अंक में यह मत प्रकट किया था कि भारतीयों के प्रति ब्रिटेन के इस अविश्वास को मध्य एशिया में रूस की गतिविधि के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण के संदर्भ में समझा जा सकता है। इस पत्रिका ने दावा किया कि अंग्रेज रूसियों से भयभीत नहीं हैं प्रत्युत उन्हें इस बात का भय है कि रूसियों के पहुंचते ही इस देश के वासी ही उनके विरुद्ध न हो जाएं। अतः उनकी इच्छा रूसियों को भारत की सीमा से हजारों मील दूर रखने की है। 1897 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सी० शंकरन नय्यर ने तथा 1903 में अपने बजट-भाषण में जी० के० गोखले ने भी इसी प्रकार की आलोचना अपनी सामान्य मृदु अभिव्यक्ति के साथ की।¹⁹⁷ विलबी कमीशन के समक्ष जिरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस दृष्टिकोण को तीखी और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतीय सेना में दो भारतीय सैनिकों की तुलना में एक ब्रिटिश सैनिक रखने का अनुपात इस भय का परिणाम है कि भारतीय सैनिक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या यह भय सैनिकों से है? उनका उत्तर था: 'मेरा अभिप्राय भारतीय सैनिक से है। ब्रिटिश सरकार को भारतीय सैनिक से ही भय है।' अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए वे पुनः अपने मुख्य विषय की ओर लौट आए और बोले: यदि आप यह मानते हैं कि यूरोपीय सैनिकों की एक निश्चित संख्या का होना आवश्यक है तो इसका कारण यह आशंका है कि भारतीय सेना उपयुक्त ढंग में कार्य नहीं करेगी।¹⁹⁸

अविश्वास और भारी सैन्य-व्ययों की नीति के एक विकल्प के रूप में इन नेताओं ने एक नई नीति अपनाने की वकालत की जिसके अंतर्गत देश की सुरक्षा को राष्ट्रीय आधार दिया जाए। भारतीय लोगों पर विश्वास तथा भरोसा किया जाए और भारतीयों को संपन्न तथा संतुष्ट बनाया जाए।¹⁹⁹ इसी प्रकार बहुतों का सुझाव था कि रूसी आक्रमण के विरुद्ध बचाव के लिए मंहंगी अग्रगामी सीमा-सुरक्षा नीति अपनाने की अपेक्षा जनता की वफादारी तथा विश्वास को पाना अधिक बेहतर और अधिक उपयोगी वैकल्पिक नीति है। उनके अनुसार वास्तविक सीमा तो वफादार जनता का हृदय है और विदेशी आक्रमण से सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय आंतरिक सुधार और जनता का संतोष है।²⁰⁰

असैनिक व्यय

भारतीय राष्ट्रवादी नेता सैन्य व्ययों के समान असैनिक व्ययों के प्रति इतने अधिक कटु और उग्र नहीं थे। हा, बहुत सारे नेताओं ने असैनिक व्ययों में वृद्धि की आलोचना अवश्य की, परंतु उसमें अन्यान्य विषयों के विरोध में पाई जाने वाली तीव्रता और उग्रता का

प्रायः अभाव ही था। इस संबंध में उनकी प्रधान आलोचना यह थी कि विशेषतः भारत जैसे निर्धन देश के लिए यहाँ का प्रशासन बहुत अधिक महंगा था। 1897 में इस दृष्टि-कोण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने लिखा : 'एशियाई निर्धनता लिए रहने वाले भारत जैसे एशियाई देश में पश्चिमी ढंग का प्रशासन चलाना वित्तीय-राजनीतिज्ञता के प्रतिकूल ही है।'¹⁰¹

भारतीय नेताओं के अनुसार प्रशासन के महंगेपन का प्रधान कारण प्रशासन के उच्च पदों के लिए ऊँचे वेतन का ढाँचा है। वास्तव में अमेरिकी प्रशासन के विरुद्ध उनकी कदाचित् यही अकेली महत्वपूर्ण शिकायत थी। स्वभावतः अमेरिकी प्रशासन के व्ययों में कटौती के सुझाव इस पक्ष-विशेष तक ही सीमित थे।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अमेरिकी खर्चों में कटौती के लिए सुझाए गए उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय था, सभी प्रशासनिक सेवाओं, नगर, रेलवे, इंजीनियरी, मेडिकल, डाक-तार, पुलिस, लोक-कर्म, सीमा-शुल्क आदि, के वरीय पदों का और विशेषतः महान इंडियन सिविल सर्विस का भारतीयकरण इस सेवा पर व्यावहारिक दृष्टि से ब्रिटिश नागरिकों का एकाधिकार था और इसमें प्रायः स्पृहणीय वेतन-पेंशन और भत्ते आदि की व्यवस्था थी। यह विषय अपने आप में इतना अधिक विस्तृत है कि इस ग्रंथ में इसे समेटा नहीं जा सकता और साथ ही यह विषय हमारे अध्ययन-क्षेत्र की सीमा से भी बाहर है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रवादियों की मार्गों में से एक है, जिसे 1858-1905 की मध्यावधि में पनपते राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के अध्ययनों में गलत रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। फिर भी, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण की अवधि में इस मांग के राष्ट्रवादी आंदोलन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तथा समर्थित आधारफलक होने के कारण हम यहाँ इसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए भारतीय नेताओं ने सुझाव दिया कि सेवा में भारतीयों की वृद्धि जैसे प्रत्यक्ष पगों को उठाने के अतिरिक्त, आई० सी० एम० तथा अन्यान्य सेवाओं की भारत और इंग्लैंड में साथ साथ ही परीक्षा की व्यवस्था करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में वृद्धि करने जैसे कुछ एक परोक्ष प्रशासनिक पगों को भी उठाना चाहिए।

राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सामाजिक और नैतिक लाभों के अनेक और विविध आधारों पर की। वे आधार थे, राजनैतिक औचित्य, न्याय तथा विशुद्धता, 1858 में की गई 'प्रतिज्ञा' की पूर्ति, प्रशासनिक क्षमता तथा प्रशासन में बचत।¹⁰² हमारा सबंध इस विषय में केवल आर्थिक आधारों से है और इन्हीं आधारों के प्रायः पूर्वापेक्षा सर्वाधिक व्यापक प्रमुखता तथा महत्ता प्राप्त होने का विश्वास किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों की प्रशासनिक विभागों में यूरोपियों के प्रभुत्व से संबंधित आर्थिक-आलोचना दोषारी थी। एक ओर तो उन्होंने यूरोपियों की संख्या में अधिकता पर यह आरोप लगाया कि इससे देश की संपत्ति की निकासी होती है, क्योंकि यूरोपीय अधिकारियों द्वारा विपुल राशि में प्राप्त किए जाने वाले वेतनों और पेंशनों का निर्यात कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश को दरिद्रता

का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर उनका अभियोग यह था कि यूरोपियों का ऊँचे स्तर पर दी जाने वाली वेतन राशि से सरकार के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ विवेचन के लिए हमें पुनः एक बार इस प्रश्न के इन दोनों पक्षों को पृथक् करना है। हम यहाँ केवल व्यय-पक्ष का ही विवेचन करेंगे, धन की निकासी के पक्ष का हमने अगले अध्याय 'ट्रेन' में ही विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं में इन दोनों पक्षों के मद्द्ध में अपने आप श्रम विभाजन हो गया था। उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मांग को मुदद आधार दते हुए न्याय, राजनैतिक औचित्य, प्रशासनिक कुशलता तथा 1858 के शाननपत्र में निहित व्यवस्थाओं को अपनाने की अपील की। दादा भाई नौरोजी, वाचा दत्त तथा कुछ अन्य महानुभावों ने धन की निकासी पर अधिक बल दिया। 'अमृत वाजार पत्रिका', 'हिन्दू', 'कैमरी', 'मराठा', जी० वी० जोशी तथा अन्य बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने मितव्ययी प्रशासन के प्रश्न पर बल दिया। इस प्रकार ये तीनों वर्ग अपने-तकों को सर्वथा पृथक् रूप में ही प्रस्तुत नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत बार वे तीनों प्रकार के तर्कों को मिला-जुलाकर भी उपस्थित करते थे।

भारतीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय तर्क सार रूप में इस प्रकार थे। यूरोपीय ऊँची दर पर वेतन पाते हैं और कदाचित् उन्हें ऊँचा वेतन मिलते रहना निश्चित ही है। अतः उच्च पदों पर विदेशियों की व्यापकता भारतीय प्रशासन के महंगेपन का महत्वपूर्ण कारण है। इसके विपरीत दूसरी ओर क्योंकि भारतीय अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप में कम वेतन पर नियुक्त किए जा सकते हैं अतः यूरोपीय अधिकारियों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करके प्रशासनिक खर्चों को उल्लेखनीय रूप से नीचे लाया जा सकता है।^१ इस सदर्भ में आर्थिक पक्ष को कभी कभी नैतिक तथा राजनीतिक पक्षों से अलग करते हुए उस पर बल दिया जाता था। उदाहरणार्थ, 'अमृत वाजार पत्रिका' ने 18 नवम्बर 1886 के अपने अंक में खरेपन के साथ, यह खरापन इस पत्रिका की अनेक महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट विशेषताओं में से एक उल्लेखनीय विशेषता उस समय थी, जब यह दो भाइयों, शिशिर कुमार तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित किया जाता था, टिप्पणी की :

ऊँचे वेतन वाले सभी पदों से भारतीयों को दूर रखने की सरकारी कार्यवाही की अनैतिकता पर सरकार से बात करना अथवा भारतीयों को बिना किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार दिए अधीनस्थ प्रजा बनाए रखने और इस प्रकार उनमें असंतोष फैलाने की राजनैतिक गलती करने की बात सरकार से करना भेस के आगे बिन बजाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अतः तुच्छ बातों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक विषय पर ही डटा रहना चाहिए। (बल दिया गया)।

भारतीय नेताओं में अर्थशास्त्रियों ने भी समस्या के सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयत्न किया। 17 मई 1892 के संमदीय विवरण को आधार बनाते हुए उन्होंने सगणना की कि 1000 रु० अथवा उससे अधिक प्रतिमाह वेतन अथवा पेंशन पाने वाले यूरोपीयों को प्रतिवर्ष दी

जाने वाली धनराशि 14½ करोड़ रुपये बैठती है, जो भारग्न सरकार के कुल शुद्ध राजस्व का 30 प्रतिशत है।¹⁰¹

सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत तर्कों के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि जब कभी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी यूरोपीय का स्थान ग्रहण करता है तो उसे अपेक्षाकृत निम्न वेतन दिया जाना चाहिए। वस्तुतः राष्ट्रवादी मंतव्य का आधार यह पूर्वानुमान ही था, परंतु यह एक पर्याप्त रोचक आश्चर्य है कि जिस निरंतरता के साथ इस मंतव्य को ग्रहण किया गया, उम मंतव्य के तथा उस मंतव्य के प्रतिपादन के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका खुले आम प्रतिपादन अथवा प्रचार विरल ही हुआ। उसके सर्वथा विपरीत कुछ भारतीय नेताओं ने जातीय समानता के तर्क को आधार बना कर यहां तक मांग करनी प्रारंभ कर दी कि प्रशासनिक स्थानों की प्रकृति और उनके साथ जुड़े उत्तरदायित्वों के संदर्भ में ही वेतनों और सुविधाओं के निर्धारण का न्याय पथ अपनाना चाहिए, न कि उन पदों पर आरुढ़ व्यक्ति विशेषों की राष्ट्रीयता को किसी भी रूप में आधार बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि भारतीय अर्सेनिक सेवारत भारतीय व्यक्तियों को यूरोपीय व्यक्तियों के समान ही वेतन, समान अवकाश तथा समान पेंशन आदि देकर इस सेवा की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। उदाहरणार्थ 'ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन' ने अपने 11 मिनंबर 1879 के अंक में अंगरेज अर्सेनिक प्रशासकों को मिलने वाले वेतन, अवकाश और पेंशन इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्त कर्मचारियों को देने की मांग करते हुए एक नई जाति प्रथा चलाने का विरोध किया। पत्रिका के अनुसार यह प्रथा भारतीय प्रशासकों में हीन भावना की सृष्टि करेगी। इसी प्रकार सिविल सर्विस को कानूनी रूप देने की लिटन की योजना के विरुद्ध प्रतिवाद तथा उसे निवारण की चेष्टा करते हुए बंगाली ने अपने 10 जनवरी 1880 के अंक में टिप्पणी की :

भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी तो एक ऐसा विचित्र जंतु है जिसे यूरोपीय कर्मचारियों के लिए मोहक सम्मान, भविष्य तथा वेतनों आदि से कुछ लेना-देना ही नहीं। अपने यूरोपीय साथी की अपेक्षा वेतन, पेंशन, यश, पदवी आदि की दिशा में तो उसकी स्थिति नितांत भिन्न है, परंतु संसार में कोई भी सम्मानित और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति इस प्रकार के असम्मानित पद के प्रति आकृष्ट नहीं होगा और न ही इस प्रकार के स्थान को ग्रहण करने का लालच करेगा।

1886 में लोक सेवा आयोग को अपने प्रत्युत्तरों में बी० एन० मांडलिक, फिरोजशाह मेहता और बी० जी० तिलक ने, समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत, की वकालत की।¹⁰² इसके उपरांत 1898 में कांग्रेस के महापति ए० एम० बोस ने और जी० के० गोखले ने वेतनों के संबंध में भारतीय और यूरोपीयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव बरतने पर तीव्र आपत्ति की।¹⁰³ दूसरी ओर 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिंदू', 'स्वदेशमित्र', 'केसरी', तथा अन्य अनेक ने खुले आम तथा दृढ़तापूर्वक भारतीयों को कम वेतन देने की वकालत की। उनका तर्क था कि इस प्रकार के त्याग के बिना आर्थिक आधारों पर प्रशासन के भारतीयकरण का राष्ट्रवादियों का सारा मामला ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। इस

संदर्भ में 'अमृत बाजार पत्रिका' द्वारा अपनाई गई स्थिति का रवयं उसी के शब्दों में अध्ययन अपने आप में पर्याप्त रोचक है। इस पत्रिका ने नवंबर-दिसंबर 1886 की बबधि में प्रकाशित संपादकीय लेखमाला में भारतीयों को यह सुझाव स्वीकार करने की सलाह देते हुए लिखा कि जो प्रत्याक्षी भारत में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं, उन्हें नियमित वेतन का 2/3 भाग ग्रहण करने को प्रस्तुत होना चाहिए। अपने 18 नवंबर 1886 के अंक में इस पत्रिका ने लिखा : यदि हम यूरोपीय लोगों के साथ समान वेतन पाने के लिए भगड़ते हैं तो इस संबंध में सरकार द्वारा सेवाओं के भारतीयकरण के उद्देश्य को ही हम समाप्त कर देते हैं।... इस समय प्रश्न सही अथवा गलत के बीच चुनाव का नहीं। प्रत्युत हमें 'भारतीयकरण' लेना है अथवा नहीं इसके बीच चुनाव का है। अपने 9 और 16 दिसंबर के अंकों में इस तर्क को सशक्त वाणी में प्रस्तुत करते हुए इस पत्रिका ने आगे बढ़कर लिखा : सत्य यह है कि यदि भारतीय अपेक्षाकृत कम वेतन लेकर क्षमता तथा कार्यकुशलता का प्रदर्शन करेंगे तो इससे परोक्ष रूप से सरकार पर प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनों में कमी करने का दबाव पड़ेगा। कम वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारियों को सम्मान और लोक-प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ेगा, इस आपत्ति का उत्तर देते हुए पत्रिका ने जो लिखा, वह एक ओर तो अकाल-प्रौढ़ विचार है, और दूसरी ओर संपादक के मन में व्यापक रूप से उदार प्रजातांत्रिक विचारों के गहरी जड़ पकड़े होने का प्रमाण है। पत्रिका ने लिखा :

हमें यह अपने मन में भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि अधिकारियों में सम्मान की प्रवृत्ति के जन्मदाता देश के विदेशी शासक हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि अधिकारियों को इतना अधिक अनुचित रूप से आदर-सम्मान दिया जाए, जितना कि भारत में दिया जाता है। सरकार ने यह सब जानबूझकर इसलिए किया है ताकि ये अधिकारी जनता की पहुंच के बाहर हो जाएं।... निरंकुश सरकार को अपने कर्मचारियों को जनता पर निरंकुश शासन के लिए निरंकुश शक्तियां देनी ही होती हैं।... हम प्रजाजनों के मान-सम्मान तथा स्वतंत्र-चरित्र की बलि चढ़ाकर अधिकारियों को ऊपर उठाना ही सरकार की नीति है।... सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान प्राप्ति की बात करना स्पष्टतः देश-द्रोह है। हमें अपनी मारी शक्तियां कर्मचारियों को नीचे लाने में और जनता को थोड़ा ऊपर उठाने में खर्च करनी चाहिए।

इसी प्रकार 'हिंदू' ने अपने 15 जुलाई 1886 के अंक में यह आशावादी दृढ़ मत व्यक्त किया कि शिक्षित भारतीय भाड़े के टट्टू यूरोपीय द्वारा मांगे गए वेतन की अपेक्षा थोड़े वेतन पर ही अपने देश तथा अपने देशवासियों के लिए काम करना स्वीकार कर लेंगे। उसने भारतीयों से विदेशियों के समान वेतन पाने की आत्महत्या जैसी मांग को छोड़ने का अनुरोध किया।¹⁰⁷ 25 मई 1887 के अंक में इस पत्र ने फिर लिखा कि अंगरेजों को मिलने वाले जिन वेतनों को धन का अपव्यय कहकर हम उनकी निंदा करते आ रहे हैं, उन्हीं वेतनों की देशवासियों द्वारा अपने लिए मांग करना विवेकशून्य है, देशानुराग विरोधी कृत्य है।¹⁰⁸ इसी प्रकार 1886 के लोक सेवा आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में

अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने या तो कहा कि भारतीयों को यूरोपीयों को मिलने वाले वेतनों से कम वेतन मिलना चाहिए¹⁰⁹, या उन्होंने एक मिला-जुला मुझाव रखा कि एक हजार प्रतिमास के वेतन तक तो यूरोपीयों और भारतीयों के वेतन में समानता रहनी चाहिए। इस राशि से ऊपर के वेतनों में भारतीयों को कम मिलना चाहिए।¹¹⁰ 1898 में विलबी कमीशन के समक्ष अपना साक्ष्य देते सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कदाचित् अपने साथी मित्रों के कटु प्रहारों से बचने के लिए इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कहने की अपेक्षा उसे मृदु भाषा में प्रस्तुत किया। 'जहां कहीं किसी पद के लिए योग्य भारतीय उपलब्ध है, वहां उसकी नियुक्ति अवश्य ही करनी चाहिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने मुझाव दिया कि यदि किसी पद के लिए अपेक्षित योग्यताओं के मूल्य का स्थानीय बाजारी मूल्य के संदर्भ में परीक्षण किया जाए और तदनुसृत वेतन का निर्धारण किया जाए तो हममें सरकारी खर्च में उल्लेखनीय बचत हो सकती है।'¹¹¹ इसी प्रकार विलबी कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य में दादाभाई नौरोजी ने अभियोग स्वीकार किया कि भारत का प्रशासन भारतीयों के हाथ में होना चाहिए और उन भारतीयों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि योग्यता के स्तर के वही वने रहने पर स्वयं सरकार के अपने ही तख्तीने के अनुसार कम से कम 1/3 भाग की सरकारी खर्च में बचत होगी।¹¹²

सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के सिवाय भारतीय नेताओं ने उल्लेखनीय परिमाण में सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कोई अन्य ठोस मुझाव नहीं दिया। उन्होंने अमैनिक प्रशासन के खर्चों में कटौती के लिए प्रायः अस्पष्ट और सामान्य माग प्रस्तुत करने तक ही अपने को सीमित रखा। उनके द्वारा कटौती के लिए मुझाए गए उपायों में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कुछ उपाय जो 1880 की अवधि में ही मुझाए गए थे, निम्नलिखित हैं :

उनके मत में उच्च सरकारी अधिकारियों को दिए जा रहे वेतनों में कटौती करके प्रशासनिक व्ययों में वास्तविक बचत की जा सकती है। उन्होंने घोषणा की कि इकरारनामे के अंतर्गत अमैनिक प्रशासन के अधिकारियों जिनमें अधिकांश यूरोपीय हैं तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों, उदाहरणार्थ, गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नरों, भारत सरकार के तथा आयुक्तों के सचिवों के वेतन, पेंशन तथा भत्ते गगनचुंबी हैं, इनमें कटौती करने से सरकारी वित्तों को भारी लाभ हो सकता है और इस कटौती से इन वेतन भोगियों को भी कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि अतीत में इन लोगों के ऊंचे वेतनों के लिए जिस देश-निर्वासन तथा कष्टमय जीवन को न्यायसंगत बताया जाता था, और आज इंग्लैंड और भारत में यातायात-साधनों के विकास के फलस्वरूप तथा भारत में निवास की स्थितियों में सुधार आ जाने के फलस्वरूप पहले की परिस्थितियां बदल चुकी हैं।¹¹³

भारतीय नेताओं ने इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया कि कुछ ऊंचे प्रशासनिक स्थान जैसे कि राजस्व बोर्ड, राजस्व आयोग का स्थान तथा कुछ मध्य-स्तरीय अधिकारों के स्थान, निरर्थक ही नहीं प्रत्युत बिना कार्य के वेतन का भुगतान करने वाले थे;

अतः उनकी मांग थी कि इन स्थानों को समाप्त कर देना चाहिए।¹¹¹ उनमें से बहुतों ने तो इंग्लैंड में 'इडिया कौंसिल' (भारत परिषद) को ही समाप्त करने की मांग की। उनकी इस मांग के पीछे अन्य कुछ कारणों के साथ साथ परिषद का आर्थिक दृष्टि से महंगा तथा उपयोगिता की दृष्टि से सर्वथा निरर्थक होना था।¹¹⁵

इसके साथ साथ कुछ राष्ट्रवादियों ने कटौती के नाम पर निचले स्तर के निम्न वेतन वाले स्थानों को समाप्त करने की अथवा उन स्थानों के वेतनों में कटौती करने की सरकारी प्रवृत्ति का विरोध किया।¹¹⁶ उनमें से बहुतों ने तो काफी आगे बढ़कर सरकार से कभी कभी उसी जोश-खरोश के साथ, जिम जोश-खरोश के साथ वे ऊंचे वेतनों में कटौती की वकालत कर रहे थे, बहुत कम वेतन वाले अधीनस्थ प्रशासनिक तथा पुलिस-कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि की वकालत की। इस प्रकार उदाहरण के रूप में, 1895 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में मुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने विनिमय क्षति पूर्ति भत्ते की आलाचना करते हुए सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्कों और चपड़ासियों की वेतन वृद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने शिकायत की कि बेचारे अभावग्रस्त सरकारी कर्मचारी अपने वेतन में बड़ी कठिनाता सही जीवन निर्वाह कर पाते हैं। विवश होकर जीविका जुटाने के लिए उन्हें गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। वे बहुत सालों से वही वेतन प्राप्त कर रहे हैं।¹¹⁷

सरकारी खर्चों में कटौती का राष्ट्रवादी क्षेत्र में व्यापक रूप से लोकप्रियता प्राप्त एक अन्य उपाय केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का प्रतिवर्ष गर्मी के महीनों में प्रायः अप्रैल से अक्तूबर तक पर्वतीय प्रदेशों में जाना तथा वहां से वापस लौटना था। यद्यपि इस उपाय को अपनाने के फलस्वरूप रुपयों-पैसों के रूप में होने वाली बचत विशेष उल्लेखनीय नहीं थी तथापि इस उपाय को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। वस्तुतः भारतीयों ने इस मांग को मनवाने के लिए दो बार छोटे-मोटे आंदोलन किए। प्रथम, 1886-7 की अवधि में भारत सरकार द्वारा वित्त समिति की नियुक्ति ने भारतीय राजनीति में व्ययों में कटौती को एक सजीव विषय बना दिया और पुनः जब भयंकर अकाल ने देश को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने विविध आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक आधारों पर सरकारों के पर्वतगमन की निंदा की।¹¹⁸ यहाँ हमें केवल उनकी आर्थिक आपत्तियों से प्रयोजन है और वे थीं, प्रतिवर्ष पर्वतीय प्रदेशों में अल्पकालीन पड़ाव की विलासिता के लिए भारी और निरर्थक धन की व्यवस्था करनी पड़ती है और भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह सब जुटाना कठिन कार्य ही है।¹¹⁹ इस तर्क को कभी कभी तो और अधिक प्रबलता से प्रस्तुत किया गया। उदाहरणार्थ, 'बिहार हेराल्ड' ने अपने 20 जुलाई 1886 के अंक में टिप्पणी की कि पहाड़ों पर सरकारी अधिकारियों का जीवन मात्र प्रसन्नता और मीजों का जीवन है। इस पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति बेचारे करदाताओं के जीवन रक्त को बूसकर ही की जाती है।¹²⁰ कुछेक भारतीय नेताओं ने इस व्यवस्था के तात्किक दृष्टि से असंगत होने की भी चर्चा की। उनके अनुसार ब्रिटिश अधिकारियों को इस अनुमान तथा आवश्यकता के संदर्भ में ही ऊंचे वेतन दिए जाते हैं कि इन बेचारों को मैदानों की सख्त गर्मी में काम करना पड़ता है। फिर गर्मियों के महीनों में उन्हें पर्वतीय प्रदेशों में जाने के लिए

सुविधाएं जुटाने और विपुल परिमाण में धनराशि खर्च करने के पीछे क्या तुक है ?¹²¹

सरकारी खर्चों में कटौती के राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए अन्य उपाय थे, (क) सरकारी ऋणों पर व्याज की वसूली में कटौती। इसके लिए सारे ऋणों को ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूति के अंतर्गत रख देना चाहिए क्योंकि विन्-मंडी में उसकी साख भारत सरकार की माख की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट है।¹²² (ख) लोक कर्मविभाग में फिजूलखर्चों में पर्याप्त कटौती।¹²³

भारतीय नेताओं का कथन था कि खर्चों को घटाने के महत्वपूर्ण उपायों में एक था, रेल पथों के निर्माण की गति को मद करना। हम इस पुस्तक के पाचवें अध्याय में राष्ट्रवादियों की वित्तनीति के इस पक्ष का पहले ही विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर चुके हैं।

ब्रिटेन और भारत के बीच व्यय-विभाजन

भारत के वित्तों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा सुझाया गया दूसरा उपाय यह था कि ब्रिटेन भारतीय साम्राज्य को बनाए रखने के मूल्य का योगदान करते हुए वित्तीय मामलों में भारत के प्रति न्यायोचित व्यवहार करे। भारत से धन की निकामी को रोकने अथवा कम करने के साधन के रूप में भी इन नेताओं ने इस उपाय को प्रस्तुत किया, दादाभाई नौरोजी ने तो विशेष रूप से ही इस द्वितीय कारण (धन की निकामी रोकने) के लिए आंदोलन किया।¹²⁴ अंततः संमद सदस्य के नाते, उन्हें ब्रिटेन और भारत के समान हितों में खर्चों जाने वाली धनराशि के दोनों सरकारों में विभाजन की जाच-पडताल के लिए मई 1895 में शाही कमीशन (विलबी कमीशन) को नियुक्त करान में सफलता मिल गई। इससे पहले दिसंबर 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस प्रकार की जाच-पडताल करने का प्रस्ताव पारित किया था।¹²⁵

भारतीयों द्वारा ब्रिटेन और भारत में व्यय के और अधिक निष्पक्ष बंटवारे की मांग निम्नलिखित दो आधारों पर की गई। प्रथम, मकुचित आधार यह था कि ब्रिटेन के तख्मीने की मकट कालीन आवश्यकताओं के लिए भारत की बलि चढ़ा दी जाती है और वे सारे व्यय भारत के मत्थे मढ़ दिए जाते हैं, जिनका समग्रतः नहीं तो अशतः भुगतान किसी भी न्याय के अंतर्गत अनिवार्यतः ही ब्रिटिश कोष को करना चाहिए क्योंकि प्रमुख रूप से ब्रिटिश हितों में उन सारे व्ययों का विनियोजन होता है।¹²⁶ ऐसे व्यय थे, देश के भीतर और देश के बाहर लड़ी गई लड़ाइयां, जिनमें भारत ने भाग लिया है और भारतीय सेना पर हुए व्यय का भार उठाया है।¹²⁷ लंदन-स्थित 'इंडिया आफिस' (भारत-सचिवालय) का व्यय,¹²⁸ एशिया के विविध देशों में स्थित दूतावासों और जलमेना के कार्यालयों के व्यय,¹²⁹ तथा अन्य अनेक फुटकर विविध व्यय, जैसे कि 1895 में अफगान राजकुमार नसरुल्ला खा की लंदन यात्रा पर हुआ व्यय,¹³⁰ कोरोनेशन में भारतीय सेना टुकड़ी पर हुआ व्यय¹³¹ और 1902 में परशिया की खाड़ी में वायसराय के दौरे पर हुआ व्यय।¹³² द्वितीय, अधिक व्यापक, अधिक महत्वपूर्ण तथा अधिक सुदृढ़ आधार यह था कि भारत में ब्रिटिश की सर्वोच्चता के कानून और व्यवस्था के बने रहने से तथा कुशल प्रशासन से ब्रिटेन के ही व्यापार, उद्योग और पूंजी को अत्यंत लाभ पहुंचता है, ब्रिटेन के ही

नागरिकों को विपुल परिमाण में नौकरी के अवसर जट पाते हैं; अतः ब्रिटिश सरकार को इस सर्वोच्चता का मूल्य चुकाने के लिए और भारत सरकार के साधारण, सामान्य व्ययों के एक भाग का भुगतान करने के लिए महमत होना ही चाहिए।¹³³

सैन्य व्यय में योगदान करने के अतिरिक्त कुछ एक भारतीय नेताओं ने इस सबध में दो महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सुझाव रखे। प्रथम, भारत में सभी प्रकार की सेवाओं में नियुक्त यूरोपियों पर होने वाले व्यय का ब्रिटेन को अशदान ही नहीं प्रत्युत सारे के सारे व्यय का ही भुगतान करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने किसी भी रूप में स्पष्टतया और अनिवार्यतया भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही इनकी नियुक्ति की है।¹³⁴ द्वितीय, ब्रिटेन को भारत सरकार के गृह प्रभारों के तथा इंग्लैंड में हुए भारत सरकार के व्ययों के न्यायोचित भाग का योगदान करना चाहिए।¹³⁵

ब्रिटेन के भारतीय व्ययों में योगदान करने को सहमत गान का एक परोक्ष मभावित लाभ भारतीय नेताओं की दूर दृष्टि के अनुसार यह था कि इससे ब्रिटेन की समद और बहा की जनता भारतीय विन्नों के प्रति अधिक गहरी रुचि और अधिक समीक्षापरक दृष्टि अपनाएगी क्योंकि इसमें उनकी अपनी जेब ही प्रभावित होगी।¹³⁶

विलबी कमीशन ने 1900 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह कमीशन कुल भिलाकर ब्रिटेन और भारत के मध्य प्रचलित विन्तीय सबधों से सन्तुष्ट था। अतः उमने ब्रिटिश कोष में से भारतीय कोष को साधारण सी ही राहत देने की सिफारिश की। दादाभाई नौरोजी, विलियम विडरबर्न तथा डब्ल्यू० एस० वेन, जो कमीशन के सदस्य भी थे, कमीशन के बहुमत से असहमत थे तथा उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाला अपना अल्पमतीय प्रतिवेदन पृथक् रूप से ही प्रस्तुत किया।¹³⁷ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जहां विलबी कमीशन द्वारा प्रतिज्ञात ब्रिटिश अशदान को वृत्तज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया, वहां वहुत सारे अन्य सदस्यों ने कमीशन के निष्कर्षों के प्रति असंतोष प्रकट किया।¹³⁸ उनका विचार था कि यह योगदान थोड़ी असुविधाजनक प्रकृति का है और इसे भारत के प्रति किए गए न्याय की एक छोटी सी किरत ही समझना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने अल्पमतीय प्रतिवेदन का बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया।¹³⁹

कल्याणकारी कार्यों में व्यय

यद्यपि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भले ही सरकारी व्ययों में कटौती के लिए निरंतर आंदोलन किया तथापि वे मिद्वान रूप में सभी प्रकार के व्ययों में वृद्धि के विरुद्ध नहीं थे। दूसरे शब्दों में उनका दृष्टिकोण किसी भी रूप में सब प्रकार से कराधान के न्यूनतम तथा व्ययों के न्यूनतम करने के मिद्वान तक सीमित नहीं था। इसके सर्वथा विपरीत जहां उन्होंने सेना, असेनिक प्रशासन तथा रेलों पर होने वाले खर्चों को अनावश्यक, निरर्थक तथा अत्यधिक महंगे मानते हुए उनमें कटौती के लिए आंदोलन किया, वहां उन्होंने राज्य की विकासपरक तथा क्षेत्र-कल्याणकारक मानी जाने वाली गतिविधियों, जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, औद्योगिक तथा कृषि-सबध्नी उन्नति

कृषि-बंकों का विकास, सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोकप्रिय तथा कुशल पुलिस-प्रणाली तथा न्याय-प्रशासन के लिए व्ययों में वृद्धि, का न केवल स्वागत किया प्रत्युत उसके लिए अनुरोध किया और दबाव तक डाला। वास्तव में भारतीय नेताओं द्वारा बचतों की वांछित दिशाओं के अध्ययन के उपरान्त तथा उनके द्वारा बचतों की अवांछित दिशाओं की समीक्षा के उपरान्त यह रोचक तथ्य सिद्ध हो जाता है कि सरकारी खर्चों के समुचित वितरण और उसके क्षेत्र की समस्या के संबंध में राष्ट्रवादियों की समझ मचमुच ही प्रशंसनीय थी।

मामान्यीकरण के स्तर पर राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक प्रगति को द्रुतगामी बनाने के लिए सरकारी वित्तों के उपयोग की संभावनाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। उन्होंने इस संबंध में कहा कि राज्य की पुलिस और सेना के प्रयोजनों के लिए किए जा रहे व्ययों के मुकाबले भारत सरकार द्वारा जनता के प्रत्यक्ष हितों के अथवा उनके नैतिक और भौतिक विकास के कार्यों पर वास्तव में किए जाने वाले खर्च की राशि साधारण तथा तुच्छ थी। अतः उन्होंने मांग की कि सरकार को इस दिशा में अधिक खर्च करना चाहिए और जब कभी कटौती की छुरी चलानी पड़े तो उसका उपयोग राज्य के अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए किया जाना चाहिए, आवश्यक खर्चों के लिए उसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। 1886-7 के आर्थिक संकट से उभरने के लिए कटौती के उपायों की एक सूची प्रस्तुत करते हुए जी० वी० जोशी ने आवश्यक तथा उपयोगी खर्चों को समाप्त न करने की सरकार को चेतावनी दी क्योंकि इसका अनिवार्य दृग्परिणाम देश के विकास का अवमंद् अथवा पराङ्मुख होना था। उन्होंने बचत के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिस भी क्षेत्र में बचत की योजना बनाई जाए वहां यह अवश्य देखना चाहिए कि उसमें स्थाई तथा उपयोगी रूप से कुशलता तथा प्रगति पर किसी प्रकार से बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता।¹¹⁰ बाद में 1888 में उन्होंने इंडियन पोलिटिकल ऐसोसिएशन और लेखकों पर लगाए जा रहे इस अभियोग से उनका बचाव किया कि वे वास्तव में ही उपयोगी और आवश्यक खर्चों में भी कटौती चाहते हैं और दावा किया कि वे तो उल्टे तकनीकी शिक्षा, न्याय प्रशासन पर खर्चों आदि में वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि लोकमत के व्याख्याता निरंतर लंबे समय से जिस दान पर दबाव डालते आ रहे हैं, वह इस प्रकार से है :

सरकार को उन खर्चों में कटौती करनी चाहिए, जिन्हें अनुभव और विवेक ने जनता के धन का निरर्थक अनावश्यक और धूर्ततापूर्ण अपव्यय सिद्ध कर दिया है। विलासिता वाले बड़े बड़े भवन बनवाना, पर्वतीय प्रदेशों में पड़ाव डालना, समान योग्यता वाले अथवा अधिक योग्यता वाले भारतीय प्रत्याशियों के सुलभ होने पर भी महंगे यूरोपीय लोगों को नियुक्त करना सर्वथा निरर्थक व्यय है। सेना में अनावश्यक बढ़ोतरी करना तथा गृह प्रभाग में अनुचित वृद्धि करना अनावश्यक व्यय है। सीमाओं के 'वैज्ञानिक सशोधन' पर, दूसरे देशों की सीमा में 'सैनिक विनोद-विहार' पर किए जाने वाले व्यय धूर्ततापूर्ण हैं।¹¹¹

1895 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में अपने बजट-भाषण में फिरोजशाह मेहता ने

शिकायत की कि सेना और नगर प्रशासन के अत्यधिक ऊँचे व्ययों की एक बहुत बड़ी बुराई यह थी कि शिक्षा और पुलिस-सुधार जैसे अत्यंत आवश्यक प्रयोजनों के लिए भी अपेक्षित राशि सुलभ नहीं हो पाती थी।¹¹² 1895 में बंबई के बजट पर अपने सर्वप्रथम भाषण में ही बी० जी० तिलक ने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि 1870 में सरकार ने 5½ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा करने पर भी राज्य के भौतिक विकास पर कठिनाता से कुछ लाख रुपये ही खर्च किए हैं। उन्होंने निर्देश किया कि जहाँ देश को औद्योगिक, तकनीकी अथवा उदार शिक्षा, ग्रामों में सफाई, सड़कें और नहरें आदि लोकोपयोगी कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी,¹¹³ उस दिशा में खर्च न करके अतिरिक्त राजस्व की उगाही राशि को विविध प्रशमाकीय विभागों पर अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया गया है। 1896 के बजट पर बोलते हुए उन्होंने विशेष रूप में सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों के दृष्टिकोण में मतभेद का प्रमुख विषय खर्चों की दिशाएं हैं।¹¹⁴ इसी प्रकार 1897 में विलबी कमीशन के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने सुस्पष्ट रूप में यह मिफारिश की कि उत्पादक प्रकृति के अर्सेनिक व्यय अपनी पर्याप्त मात्रा में सदैव वांछनीय रहे हैं। इस कथन के उपरांत उन्होंने उत्पादक प्रकृति के व्यय का अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया। करदाता को बदले में शिक्षा, न्यायपूर्ण अधिक कुशल प्रशासन, ग्राम तथा नगरों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी सफाई, लोकहित के अन्य दूसरे कार्य—जिनसे प्रांत के संसाधनों और जनता की समृद्धि में योगदान मिलता है—जिस व्यय में हो पाते हैं, वह 'उत्पादक प्रकृति का व्यय' है।¹¹⁵

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो वर्षों से सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा के लिए, न्याय प्रशासन की व्यवस्था आदि के लिए बजट में अधिक व्यवस्था की मांग करती आ रही थी, 1897 में अपनी मांगों को अधिक व्यवस्थित रूप दिया तथा सरकार से अनुरोध किया कि सेना तथा अन्य इस प्रकार की मदों में होने वाले अनुत्पादक खर्चों को घटाकर बची राशि के बड़े भाग का जनता की प्रगति और सुख-समृद्धि के उन्नयन में सदुपयोग करना चाहिए।¹¹⁶ अतः हमें जी० के० गोखले के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सिचाई कार्यों के व्ययों में वृद्धि, पुलिस सेना में सुधार, विदेशों में औद्योगिक शिक्षा के लिए राजकीय छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, पूसा में कृषि-महाविद्यालय की स्थापना और सहकारी ऋण-समितियों को प्रोत्साहन देने जैसे प्रस्तावित सरकारी उपायों का पूर्ण समर्थन किया तथा 1904 के बजट-भाषण में उन्होंने यह निर्देश किया कि इन उपायों तथा इन जैसे लोकहित कारक उपायों के लिए विपुल धनराशि अपेक्षित है। इसके साथ उनका यह भी दृढ़ मत था कि लोक कल्याण के इन कार्यों पर बड़े हुए व्ययों की न केवल शिकायत ही नहीं की जाएगी प्रत्युत देश भर में उसके प्रति ईमानदारी से संतोष और कृतज्ञता की भावना अभिव्यक्त की जाएगी।¹¹⁷

इस संबंध में दो चुने वर्षों में कुछ अपने लोक कल्याण के विभागों पर भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों का अध्ययन भी पर्याप्त रोचक होगा¹¹⁸ :

	1885	1898
शिक्षा	1.4 करोड़	1.37 करोड़
विज्ञान-विभाग	.40 करोड़	.45 करोड़
डाक्टरी और जन-स्वास्थ्य	.69 "	1.53 "
कानून और न्याय	2.77 "	3.43 "
सिचाई	.79 "	.2 "
		(वास्तविक राजस्व)
पुलिस	2.5 "	3.8 "

लोकहित के किसी भी अन्यान्य क्षेत्र की अपेक्षा भारतीय नेता शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हुए उसके लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था चाहते थे। इसका कारण उनका यह सुप्रसिद्ध मित्रांत था कि आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीयतावाद को पुनर्जन्म देने के प्रमुख कारणों में सबसे पहला है। इस विश्वास को स्वयं वर्षों से सरकारी प्रवक्ता पनपाते तथा विकसित करते आ रहे थे। सर्वप्रथम, राष्ट्रवादी नेताओं ने शिक्षा पर सामान्य रूप से तथा उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से खर्चों में कटौती के प्रयासों का विरोध किया।¹⁴⁹ यहां यह देखना भी रुचिबर्धक होगा कि उच्च शिक्षा पर किसी प्रकार के भी प्रतिबन्ध अथवा उस पर होने वाले व्यय में किसी प्रकार की कटौती के प्रबलतम मुखर विरोधी फिरोजशाह मेहता ने सरकार द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार में किसी प्रकार की बाधा के प्रयास को नव शिक्षित भारतीयों के प्रति शासकों का ईर्ष्याभाव बताया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, प्रजाजनों को शासकों के स्तर पर उन्नत करने की बात करना अपने में बड़ा मोहक लगता है परन्तु जब प्रजा सरकार पर दबाव डालने लगती है, मानव स्वभाव की सहज दुर्बलता के कारण उस समय प्रबल प्रवृत्ति यह होती है कि प्रजा को पीछे धकेल दिया जाए।¹⁵⁰ इसी प्रकार वर्षों तक और लगभग निरन्तर ही भारतीय नेता शिक्षा पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि के लिए दबाव डालते रहे। उदाहरणार्थ, यह एक ऐसी मांग थी कि जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1888 से आगे धार्मिक मांग का रूप दे दिया था।¹⁵¹ 1893 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों और कालेजों में निर्धन छात्रों की फीस में रियायत अथवा माफी देने की मांग की।¹⁵² इसी प्रकार 1895 में उसने शिक्षा संस्थाओं में फीस बढ़ाने के राज्य द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः समर्थित प्रस्ताव का विरोध किया।¹⁵³ 1904 में कांग्रेस ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की दिशा में सरकार द्वारा पथ-प्रदर्शन करने की क्रांतिकारी मांग की।¹⁵⁴ बहुत सारे दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करने की मांग की तथा साथ ही साथ अन्य देशों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्ययों के मुकाबले तथा स्वयं भारत सरकार द्वारा सेना पर किए जाने वाले व्ययों के मुकाबले भारत में शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुच्छ-राशि की आलोचना की।¹⁵⁵

शिक्षा को और विशेषतया प्राथमिक शिक्षा को अथवा जन-साधारण को शिक्षित करने के लक्ष्य को अपने सारे जीवन का लक्ष्य बनाने वाले जी० के० गोसले के विचारों का संक्षिप्त विवेचन अनुचित न होगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में ही

इस उद्देश्य को अपनाया और 1891 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शिक्षा के लिए निर्धारित संसाधनों की स्वल्पता के लिए निंदा और शिकायत की। उन्होंने निर्देश किया कि यूरोप के सर्वाधिक पिछड़े देशों में भी शिक्षा पर किए जाने वाली व्यय की राशि उन देशों के सरकारी राजस्वों का 6.5 प्रतिशत है जबकि भारत में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात केवल एक प्रतिशत है। भारत में वास्तव में ही शिक्षा पर व्यय होने वाली राशि 20 वर्ष पूर्व खर्च होने वाली राशि से भी कम थी, जबकि उसका अनुपात 1.4 प्रतिशत था।¹⁵⁶ 1897 में विलबी कमीशन के समक्ष उन्होंने शिक्षा पर व्यय की तुच्छता को भारतीय व्यय के मस्तक पर एक बड़ा भारी कलंक बताया और कहा : ग्रेट ब्रिटेन में शिक्षा पर बढ़ते हुए व्यय के मुकाबले भारत में शिक्षा पर हो रहे व्ययों की तुलना करने पर सरकार द्वारा पवित्र कार्य की उपेक्षा करने के लिए जितने भी अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाए, थोड़ा ही है। ब्रिटेन और भारत में शिक्षा पर किए गए व्यय के अंतर को दिखाते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि सगे बेटों और सौतेले बेटों के प्रति व्यवहार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने देश में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के नितांत अभाव के लिए प्रशासन को विशेष रूप से ही आड़े हाथों लिया।¹⁵⁷ 1901 में अपने बजट-भाषण में बोन्ने लेजिस्लेटिव कौंसिल में उन्होंने अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक दोहराया।¹⁵⁸ इंग्लैरियन लेजिस्लेटिव कौंसिल में अपने प्रसिद्ध वार्षिक बजट भाषणों में गोखले ने शिक्षा के सामान्य रूप से और प्राथमिक शिक्षा के विशेष रूप से प्रसार का निरंतर तथा सशक्त शब्दों में समर्थन किया। इस प्रकार 25 वर्षों तक सर्वसाधारण की शिक्षा की योजना के लिए वकालत करने रहने के उपरांत 1903 में उन्होंने कहा : 'देश की तात्कालिक और अनिवार्य आवश्यकता है, सर्वप्रथम जनता के लिए प्राथमिक विद्यालय। शिक्षा के प्रसार के प्रति अपने अत्यधिक उत्साह के कारण वे स्वयं अपनी मान्यताओं के तथा अवशिष्ट अन्यान्य नेताओं के प्रशासन के और अधिक विकेंद्रीकरण के विश्वास के भी विपरीत चले गए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा को राज्य के विषयों की सूची से हटाकर केंद्रीय विषय बना देना चाहिए ताकि देश की सर्वोच्च सरकार जिस प्रकार और जितना ध्यान सैन्य सेवाओं तथा रेल पथ प्रसार जैसे अपनी सूची के विषयों पर देती है, उतना ही महत्व और ध्यान देश की जनता की शिक्षा पर दे सके। वस्तुतः शिक्षा के लिए गोखले के मन में इतना अनुराग था कि उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित एक अन्य सिद्धांत का भी अतिक्रमण कर दिया। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में योग्य अंग्रेजों को अध्यापक बनने के लिए आकृष्ट करने के लिए उन्हें ऊँचे-ऊँचे वेतन देने की वकालत की।'¹⁵⁹ इस संबंध में उनके द्वारा निदिष्ट सुस्पष्ट उपयोगी प्रस्ताव यह था कि जब कभी बजट में बचत हो, उसका उपयोग देश के शैक्षणिक तथा औद्योगिक हितों के संवर्द्धन में करना चाहिए।¹⁶⁰

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जहां भारतीय नेता सरकार से बहुत आगे बढ़ गए, वहां उन्होंने सरकार द्वारा उदार ऊंची शिक्षा के प्रसार को बाधित करने की दिशा में प्राथमिक शिक्षा को एक बहाने के रूप में उपयोग करने पर आपत्ति की। उसका कथन था देश की राजनैतिक,

सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उच्च शिक्षा की भी समान रूप से आवश्यकता थी और सत्य तो यह कि उसके बिना शिक्षा के अन्य दोनों क्षेत्रों में भी किसी प्रकार की प्रगति नहीं की जा सकती।¹⁶¹

भारतीय नेता शिक्षा के अतिरिक्त देश के औद्योगीकरण,¹⁶² सिंचाई¹⁶³ कृषि-विकास, ग्रामीण ऋणप्रस्तुता से मुक्ति के लिए कृषि बैंकों की स्थापना,¹⁶⁴ स्वास्थ्य तथा सफाई-सुविधाओं,¹⁶⁵ तथा प्रशासन से न्यायाधिकरण को पृथक करने¹⁶⁶ तथा पुलिस पद्धति में सुधार करने¹⁶⁷ जैसे प्रशासनिक सुधारों के लिए भी सरकारी बजट में से अधिक धन के निर्धारण के इच्छुक थे।

सरकारी अधिकारियों ने एक ही साथ दो परस्पर विरोधी मांगों, व्ययों और कराधान में कटौती करने तथा अपनी प्रिय लोक-कल्याणपरक योजनाओं पर व्ययों को बढ़ाने, के लिए प्रायः ही राष्ट्रवादी नेताओं को फटकारा। उदाहरण के रूप में 1894 में ब्रिटिश सदस्य जेम्स वेस्टलैंड ने लाहौर में क्रिसमिस के अवसर पर इकट्ठे हुए राजनीति में रुचि रखने वाले भारतीय सम्य महानुभावों (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) के मामले पर व्यंग्य-आक्षेप करते हुए पूछा : 'क्या हमें आप ही सिखाएंगे कि भारत पर किस प्रकार शासन करें ?' उन पर बरसते हुए उसने कहा कि वे एक ही साथ एक मद में खर्चों में भारी कटौती करने और दूसरी मद में खर्चों में वृद्धि करने की अपनी सलाह और बुद्धि-मत्ता को अपने पास ही रखें।¹⁶⁸

राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इस आलोचना का प्रत्युत्तर सीधा-सादा परंतु निरुत्तर करने वाला था। आवश्यकता से अत्यधिक बढ़े हुए सैन्य व्यय और प्रशासनिक व्यय में कटौती करने से एक साथ ही कराधान में कमी और लोकहित के व्ययों में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार वेस्टलैंड की फटकार का उसी तीखी और व्यंग्यपूर्ण वाणी में उत्तर देते हुए फिरोजशाह मेहता ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया कि भारतीय नेता इस प्रकार के सुझाव देने में सर्वथा तर्कबुद्धि रहित और विवेकहीन थे हालांकि वे विश्व की विशिष्टतम सेवा के सदस्यों का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। इसके उपरान्त उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यह समझना कठिन नहीं कि यदि सही दिशा में बचत की जाए तो राजस्व में कमी करना तथा अन्य दिशा में व्यय को बढ़ाना संभव है। उन्होंने कराधान और व्ययों के संबंध में राष्ट्रवादियों की समग्र स्थिति को मक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया :

यदि आप सैन्य व्यय में उचित कटौती कर सकें, यदि आप व्ययसाध्य, महंगे अभियानों को न अपनाने की नीति पर स्थिर रह सकें, यदि आप विपुल सेना और घरेलू तत्त्वमीनों में संतुलन ला सकें, यदि आप वेतनों और पेंशनों के जटिल तथा कमरतोड़ भार को हलका करने के व्यावहारिक उपाय अपना सकें तो यह अनुमान सर्वथा निर्मूल और काल्पनिक नहीं होगा कि न्याय-व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, पुलिस को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है, शिक्षा की अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ पद्धति को अपनाया जा सकता है, देश में लोक कल्याणकारी कार्यों और रेल पथों का जाल बिछाया जा सकता है, सफाई के व्यापक साधन अपनाए जा सकते

हैं, डाक तार को अपेक्षाकृत सस्ता बनाया जा सकता है, इतने पर भी थोड़ी आय वालों को कर भार में राहत दी जा सकती है, घरेली पर लगान की दर कम करके किसानों को सुख-चैन की सांस लेने का अवसर जुटाया जा सकता है और नमक कर में भी कटौती की जा सकती है।¹⁶⁹

ए० एम० बोस ने¹⁷⁰ 1898 में और जी० के० गोखले ने 1902 तथा 1905 में¹⁷¹ इसी तर्क को दोहराया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण तथा चिंतन का आधार-भूत तत्व यही था कि बढ़ते हुए सैन्य-व्यय ही देश के अन्य सभी प्रकार के आंतरिक सुधारों के मार्ग की प्रधान बाधा थे।

कुछ भारतीय नेताओं ने तो एक कदम और आगे बढ़कर यहां तक कह डाला कि यदि वर्तमान कर्गों की आय के पूर्वापेक्षा अधिक बड़े और व्यापक भाग को आंतरिक सुधारों के उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाए तो कराधान के चालू परिणाम को भी सहन किया जा सकता है।¹⁷² विविष्ट दूरदर्शी तथा प्रतिभाशाली जी० पी० जोशी महोदय ने तो उत्पादक-प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से लगाए गए अतिरिक्त कराधान तक का समर्थन देने का वचन दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों से औद्योगिक प्रयासों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से विशेष रूप से लगे नए कर्गों का भार सहर्ष उठाने का अनुरोध किया।¹⁷³ इसी प्रकार उन्होंने 1893 में व्यापक परिमाण में कृषि शिक्षा के कार्यक्रम को अपनाने की वकालत की, भले ही इसके लिए विशेष कराधान द्वारा धन की व्यवस्था क्यों न करनी पड़े।¹⁷⁴ जी० के० गोखले ने भी विलबी कमीशन के समक्ष कुछ कुछ इसी प्रकार का सुझाव रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्थानीय संस्थाओं को विशेष कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।¹⁷⁵ जी० मुन्नाय्य अय्यर ने भी कमीशन को सूचित किया कि शिक्षा के प्रसार के लिए वे कर्गों में वृद्धि करने के भी समर्थक हैं।¹⁷⁶

सरकारी कोश पर लोकप्रिय भारतीय नियंत्रण

भारत सरकार की वित्तनीति की समीक्षा करते समय भारतीय नेता कठोरतापूर्वक तथा अनिवार्य रूप से इस परिणाम पर पहुंचे कि सरकारी वित्तों पर भारतीयों के नियंत्रण की लोकप्रिय मांग सर्वथा उचित है। उनके विचार में यदि भारत में कराधान कमरतोड़ स्थिति में ऊंचा और अधिक रहे और व्यय निरर्थक तथा अनावश्यक हों तो इस सारी स्थिति के लिए स्पष्टतया उत्तरदायी कारणों में एक वर्तमान में वित्तों पर नियंत्रण रखने वाला संवैधानिक तंत्र है, जो संतोषजनक रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल रहा है। 1892 से पूर्व भारत की इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसिल का वस्तुतः ही बजट से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। 1892 के इंडियन कौंसिल अधिनियम के अधीन कौंसिल में बजट का विश्लेषण प्रस्तुत करना होता था। सदस्यों को उस पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार अवश्य था परंतु उन्हें उस पर किसी प्रकार के प्रस्ताव रखने का अथवा कौंसिल में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। भारतीय वित्तों पर सर्वोच्च नियंत्रण ब्रिटिश संसद का था। भारत सरकार संसद में विद्यमान भारत राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी थी।¹⁷⁷

राष्ट्रवादी नेताओं ने विन नियंत्रण के प्रचलित तंत्र को सर्वथा दोषपूर्ण घोषित किया। उनका कथन था कि यह तंत्र सरकार के कार्यपालक अंगों की दायपरक और कराधानपरक प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में अमफल सिद्ध हुआ है। यह तंत्र कमरतोड़ कराधान को रोकने में और देश के संसाधनों के निगर्थक, व्यर्थ, अनुचित तथा अनुपयोगी खर्चों को रोकने में नितात असफल रहा है, इसी प्रकार जी० के० गोखले ने विलवी कमीशन के समक्ष अपने माध्य में निर्देश किया कि भारतीय वित्तों की प्रबध व्यवस्था में भारतीय हितों पर भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता के हितों को, एशिया में ब्रिटिश विस्तार को, ब्रिटिश की नागरिक और सैन्य सेवाओं को तथा ब्रिटिश वाणिज्य और पूँजी को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा :

भारतीय कर-दाताओं के हितों को इन अन्य हितों के गौण बनाने की व्यापक चेष्टा ने और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि भारतीय वित्तों के न्यायोचित तथा मितव्ययी प्रशासन के लिए, संबंधानिक नियंत्रण तंत्र द्वारा उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जानी उचित है। मुझे तो यह आशंका है कि हमारे देश के समान और किसी भी देश में वित्तों की सुरक्षा की ऐसी भ्रातिपूर्ण व्यवस्था नहीं है।¹⁷⁸

भारतीय नेताओं ने दृढ़तापूर्वक यह मत प्रकट किया कि वर्तमान सविधान के अंतर्गत भारतीय कर-दाताओं के हितों की सर्वोच्च संरक्षक ब्रिटिश ममद समुचित रूप से और ईमानदारी में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल रही है। सत्र के अंतिम समय में खाली बेंचों के मामले भारत के बजट को पेश किया जाता है और बिना किसी गंभीर विवाद, चिन्तन और छानबीन के कुछ थके माद सदस्यों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दलीय स्थिति के कारण भारत सचिव का सुरक्षित और निश्चित बहुमत का विश्वास रहता है।¹⁷⁹ भारतीय नेताओं की शिकायत थी कि भारत में भी किसी प्रकार के आर्थिक नियंत्रण और सन्तुलन की व्यवस्था का अभाव था, इसके बदले स्वतन्त्र निर्मित अपव्यय पद्धति ही प्रचलित थी। भारत सरकार के वित्त विभाग को छोड़कर लगभग और सभी विभाग पूर्णतः खर्च करने वाले विभाग हैं।¹⁸⁰ इंपीरियल लैंजिस्लेटिव कौंसिल का इस संबंध में अस्तित्व अवश्य है परंतु वित्तीय मामलों में वह सर्वथा अशक्त है। इसके सदस्य केवल भाषण दे सकते हैं, वे किसी भी रूप में सरकार की निंदा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सरकार के प्रस्तावों से अपनी अमहमति तक प्रकट नहीं कर सकते। फलतः बजट पर हुए विवाद या तो निर्जीव होते हैं या अधिक से अधिक पांडित्यपूर्ण होते हैं।¹⁸¹

राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार वित्तीय नियंत्रण के चालू तंत्र के असंतोषप्रद चरित्र का मूल कारण इस तंत्र में लोकप्रिय भारतीय तत्व का नितात अभाव था। अतः 1891 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतीय लोगों की बढ़ती दरिद्रता के अन्यान्य कारणों में एक मूल और व्यापक कारण, भारतीयों के अपने ही देश के वित्तों पर नियंत्रण से तथा उनके प्रशासन में समुचित योगदान से उन्हें सर्वथा पृथक रखना था।¹⁸² इसी प्रकार 1901 में कांग्रेस के सभापतीय भाषण में डॉ० ई० वाचा ने बल देकर कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के व्ययों और कराधान पर देशवासियों को बोलने का कोई

अधिकार ही नहीं अन्यथा वे यह दिखा देते कि किस प्रकार न्यूनतम राजस्व से अधिकतम बचत और कुशलता उपलब्ध की जा सकती है।¹⁸³ आर० सी० दत्त ने अपने ग्रंथ—‘इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया इन दी विक्टोरियन एज’ में अपने लोकवित्तों के तथा बिलबी कमीशन की कार्यवाहियों के परीक्षण का निष्कर्ष इस शिकायत रूप में निकाला—भारतीय प्रशासन में इस लोकप्रिय भारतीय तत्व की अनुपस्थिति में सभी कार्यरत प्रभाव विशुद्ध रूप से भारतीय हितों से सर्वथा असंबद्ध प्रयोजनों के लिए भारतीय राजस्व की बलि चढाकर खर्चों में वृद्धि और कराधानों में वृद्धि के लिए ही निरंतर कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे।¹⁸⁴

रोग निदान में उपचार भी निहित था। इंग्लैंड में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के संबंध में सुझाए गए उपचारों में महत्वपूर्ण—ढीले-ढाले समदीय नियंत्रण को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावों बनाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में भारतीयों की सर्वाधिक मांग देश की वित्तीय स्थिति की जांच-पड़ताल करने तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवर्ष हाऊस आफ कामन्स की एक प्रवर समिति नियुक्त करने की थी।¹⁸⁵ दूसरा प्रस्ताव भारतीय मामलों की समय-समय पर संसदीय जांच-पड़ताल करने की 1858 से पूर्व की पद्धति को पुनर्जीवित करना था।¹⁸⁶ इनके अतिरिक्त 1897 में जी० के० गोखले ने सुझाव दिया कि भारतीय मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के प्रांतों को संसद में सीधा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।¹⁸⁷ इस सदर्भ में एक अन्य राष्ट्रवादी प्रस्ताव यह था कि प्रांतीय तथा इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसिलों द्वारा निर्वाचित योग्य भारतीयों को पर्याप्त संख्या में भारत सचिव की कौंसिल में प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए।¹⁸⁸

ये सारे के सारे उपचार अपनी प्रकृति में केवल उपशामक ही थे। वित्तीय रोग के उपचार के लिए भारतीय नेताओं ने एक और अधिक महत्वपूर्ण मांग पेश की। उनका कथन था कि मरकरी कोष को प्रत्यक्ष रूप में भारतीयों के प्रभावी नियंत्रण के अतर्गत लाया जाए। वित्तों को सुव्यवस्थित रूप देने का, राजस्व की वसूली में वृद्धि का और जनता के हित में तथा जनता की इच्छाओं के अनुकूल वित्तों के व्यय का यह एकमात्र सुनिश्चित उपाय था। यह मांग प्रायः सामान्य रूप में पेश की जाती थी जबकि इसने पूर्णतः क्रांतिकारी रूप लिया। इस प्रकार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए दादाभाई नौरोजी ने जोर देते हुए कहा : कराधान के साथ प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि हमारा प्रथम सुधार यह हो कि हमें स्वयं अपने पर कराधान करने की शक्ति मिले।¹⁸⁹

इसी प्रकार अपने 16 सितंबर 1886 के अंक में ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने साहसपूर्वक यह मांग की कि देश के लोगों को अपने लिए कानून बनाने की, अपने करों के निर्धारण करने की तथा अपने वित्तों को व्यवस्थित करने की अनुमति अवश्यमेव मिलनी चाहिए। पत्रिका ने बड़ी स्पष्टता से लिखा—‘भारत के लिए यह एक प्रकार का गृह-प्रशासन है और केवल इसी से भारत स्थाई रूप से इंग्लैंड से संलग्न हो सकता है। जुलाई 1902 में ‘हिंदुस्तान रिव्यू’ ने और ‘कायस्थ समाचार’ ने भी इसी प्रकार की स्वशासन की मांग अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास पूर्ण स्वर में की।¹⁹⁰ अन्य अनेक भारतीय नेताओं ने

भारतीयों को अपने वित्तों की प्रबंध व्यवस्था का अधिकार देने की मांग के पक्ष में विभिन्न स्तर के सशक्त तर्क प्रस्तुत किए।¹⁹¹

बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अवश्य अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया तथा सरकारी विन्नों के प्रबंधक पर लोकप्रिय भारतीय नियंत्रण के सुस्पष्ट और ठोस सुझाव पेश किए। उन्होंने उन व्यावहारिक प्रस्तावों में 'बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, के सिद्धांत पर अधिक बल नहीं दिया और उससे काफी कम पर समझौते के लिए अपनी सहमति प्रकट की।¹⁹² उन्होंने प्रधान रूप से वर्तमान में प्रचलित इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में इस प्रकार से सुधार की मांग की जिससे उनमें व्यापक रूप से लोकप्रिय भारतीयों के अपेक्षाकृत अधिक भाग लेने की तथा उनकी शक्तियों में अधिक वृद्धि करने की व्यवस्था हो सके। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि विधान परिषदों में सुधार की मांग अनेकानेक राजनैतिक और आर्थिक आधारों पर की गई थी। हमारा संबंध केवल वित्तीय आधारों पर की गई मांग से ही है।

1892 से पूर्व सरकारी खर्चों पर वैधानिक नियंत्रण की मांग एक प्रकार से कायरतापूर्ण तथा अस्पष्ट ढंग से पेश की गई थी। इसी प्रकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि बजटों को संशोधित तथा अधिक प्रतिनिधित्व वाली विधान परिषदों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।¹⁹³ अगले वर्ष कांग्रेस ने परिषदों के सुधार के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की और सरकार से मांग की कि बजटों सहित सभी वित्तीय मामले इन्हीं परिषदों को मौपने चाहिए तथा परिषदों को ही इनका निपटारा करना चाहिए।¹⁹⁴ 1887 में 1888 में और 1889 में इस मांग को दोहराया गया।¹⁹⁵ यहां यह उल्लेखनीय है कि 'मौपना' 'पेश करना' 'निपटाना' आदि जैसे शब्द सुझावपरक होने पर भी सर्वथा धुंधलापन लिए हुए थे। वे कम से कम प्रत्यक्ष रूप से लोकप्रिय नियंत्रण का अर्थ सूचित नहीं करते थे। विधान परिषदों के सुधार के संबंध में वित्तीय तर्क प्रस्तुत करने वाले अन्य भारतीय नेता भी प्रायः इन परिषदों के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण के परिमाण और प्रकृति के निर्देश करने में कम दुर्बल और कम अस्पष्ट नहीं थे।¹⁹⁶

1892 के उपरांत राष्ट्रवादियों की मांग ने उस समय सुस्पष्ट रूप लिया, जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल का और प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। उनमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और निर्वाचित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आशिक रूप से अपनाया गया। अब नेतागण यह मांग करने लगे कि गैर सरकारी सदस्यों को वित्तीय मामलों पर प्रस्ताव पेश करने और उस पर मतदान कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए।¹⁹⁷ कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी मांग को रखने के उपरांत बहुतों ने इस धारणा का खंडन करना आवश्यक समझा कि उनका इरादा सरकार पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का है। उन्होंने निर्देश किया कि संशोधित परिषदों में भी सुस्पष्ट रूप से निश्चित बहुमत सरकारी सदस्यों का होगा, जिसे किसी भी रूप में अल्पमत में बदलने का हम में से बहुतों का कोई भी विचार नहीं है, अतः सरकार को किसी भी मामले में मतदान में हार का सामना करने की आशंका से घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं।¹⁹⁸ इसके अतिरिक्त इन नेताओं ने भारत में कार्यपालिका के सिद्धांत,

परिषदों द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को रद्द करने की विशिष्ट और अंतिम शक्ति का इंग्लैंड के हाथ में होना, को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया।¹⁹⁹ यह पर्याप्त आश्चर्यजनक ही है कि जी० के० गोखले ने विलंबी कमीशन के समक्ष इस सीमा तक अभिस्वीकार किया कि नीति संबंधी बड़े-बड़े प्रश्नों पर विचार-विमर्श तथा उन पर निर्णय ठीक प्रकार से इंग्लैंड में ही हो सकता है।²⁰⁰ इस प्रकार भारतीय नेताओं ने अपनी शक्तिमत्ता से दूर-शामी प्रभाव वाली मांग को नपुंसक बना दिया और साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों में यह कहते हुए उसे दबाव के ढंग का रूप दे दिया कि उनके द्वारा सुभाए गए सुधारों का प्रधान प्रभाव यह नहीं होगा कि भारत में ब्रिटिश कार्यपालिका के अधिकार खंडित अथवा दुर्बल पड़ जाएंगे। इसका प्रभाव तो पूर्ण रूप से मात्र नैतिक होगा, क्योंकि जब कभी गैर सरकारी सदस्य सरकार के विरुद्ध अथवा पक्ष में मतदान करेंगे तो ब्रिटिश जनता को और अधिकारियों को भारत के लोकमत की सही स्थिति का सच्चा रूप देखने को मिल जाएगा।²⁰¹ इन नेताओं की सरकारी वित्तों पर वैधानिक नियंत्रणों के अपने ही तर्कों में संकोच शीलता कदाचित् आशिक रूप से तो कड़वी गोली को चीनी में लपेट कर प्रस्तुत करने की भावना में प्रेरित थी परंतु मुख्य रूप से एक-एक पग आगे बढ़ने के विश्वास की उपज थी।

संदर्भ

- 1 उदाहरणार्थ देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 59, 222-4 और स्पीचेज, पृ० 331, 157, 220, 294, 316, 593, परिशिष्ट, पृ० 39-43, 50-1, 181, भोलानाथ चंद्र, एम० एम०, खंड II (1873) पृ० 92; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 248, राय, पृ० पावर्टी, 251-2, 259 60, 278, दत्त, ई० एच० I, पृ० XI-XIII; ई० एच० II पृ० XIX, 613 स्पीचेज II पृ० 21, 61-2; गोखले, स्पीचेज, पृ० 15; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 759
- 2 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 200.
3. मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 316 और देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 223-4 और स्पीचेज, पृ० 142, 316, परिशिष्ट, पृ० 18-20, 41, 50, 52.
- 4 और देखिए, ए० बी० पी०, 18 जून 1885, 24 दिस० 1896, 1 जून 1900, इंडियन स्पेक्टेटर, 5 जुलाई 1885; राय, पावर्टी, पृ० 251-3; ए० नवी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 126; दत्त : फर्मिस इन इंडिया, पृ० 100-01; ई० एच० I पृ० XII वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 605.
- 5 पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 152 तथा देखिए, पृ० 350, 451, 456-8.
6. प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1895, खंड XXXIII पृ० 90.
7. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 220 तथा देखिए, पृ० 199-200.
8. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 361 और देखिए, जी० सी० अय्यर, विलंबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18567, 18917, 18963, 19048, न्यू इंडिया, 18 दिसंबर 1902.
9. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1168-9.
10. बह्नी, पृ० 1156-7 तथा देखिए पृ० 1159.

11. मालवीय, स्पीचेज, पृ० 219 तथा देखिए पृ० 276-81, 291.
- 11-ए प्रस्ताव सख्या V तथा देखिए मालवीय स्पीचेज, पृ० 279, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 124-49
12. पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 447-52. इंडियन स्पेक्टेटर ने तो इसमें भी पूर्व 1883 में अपने 24 जून के अंक में सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार को अनावश्यक रूप में बजट को सतुलित करने अर्थात् पहले आवश्यक खर्चों के लिए सबल्य कर लेने तथा पुनः उन खर्चों की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की खोज करने की चेष्टा छाड़ देनी चाहिए बजट को सतुलित करने का एकमात्र उपयुक्त ढंग यह है कि प्रथम हिमाव-ग्रात के साथ माथ बराधान की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा कर निर्धनों को किसी प्रकार का विशेष कष्ट दिए बिना मुविधा से उगाहा जा सकता है, फिर उमर अनुरूप खर्चों की व्यवस्था करनी चाहिए (आर० एन० पी० बज, 30 जून 1883) इन के अग्रा ओर ससाधना में सह सवध की व्यवस्था की माग करने वाले अन्य नेता एस० एन० बैंनर्जी, स्पीचेज, III पृ० 13, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1169, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 12, एन० पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 528-9 तथा आर० टी० नागरकर, रिप० आई० एन० सी०, 1894, पृ० 78-9, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 207-08
13. प्रस्ताव स० VI
14. प्रस्ताव स० VI
15. प्रस्ताव सख्या III
16. प्रस्ताव सख्या IX, XII, IX, XIII, VIII और III क्रमशः
17. प्रस्ताव सख्या XIV, III (II) क्रमशः
18. बंगाली, 2 जनवरी 1886 तथा देखिए, बागल पूर्वोद्धृत, पृ० 86
19. जे० पी० एस० एस०, अक्टू० 1886 और जन० 1887 (खंड IX सख्या 2 और 3) तथा बावे प्रेजीडेंसी एसोसिएशन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, क्रमशः 1885-86 पूना सार्वजनिक सभा ने इस तर्क को दोहराते हुए बड़े प्रबल तथा सशक्त ढंग से एक अन्य ज्ञापन 6 मार्च 1894 को प्रस्तुत किया जे० पी० एस० एस०, अप्रैल 1894 (खंड XVI सख्या 4)
- 19-ए रिपोर्ट आफ दि फाइनाम कमेटी 1886, खंड II पृ० 452
20. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 1-82 तथा पृ० 140-1, 189-90, 201, 222, 824-6
21. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1169 और आगे, वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 9 और आगे तथा 31-2
22. दत्त, स्पीचेज I पृ० 26, 36-7 इम्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० IX, 137, 141-2, 144-5. कैमिस इन इंडिया, पृ० XIV, XVI, XVII, ई० एच० II पृ० 612 और देखिए, एस० एन० बैंनर्जी, स्पीचेज III पृ० 13; जे० यू० याज्ञिक एस० ए० स्वामिनाथ अय्यर, बी० एस० पतुलु गुरु, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 65-72, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 443-50, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 219-21, 248-52, 276-81, 285-302, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1896 खंड XXV पृ० 286; आर० एम० स्यामी, सी० पी० ए०, पृ० 309, 351-2, एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 527 भारतीय समाचारपत्रों ने प्रत्येक उपसब्ध अवसर पर विशेषतया नए कर लगाने के बबसर पर बढ़ते सरकारी खर्चों की आलोचना की तथा उन खर्चों में कटौती का समर्थन किया.
23. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 147, 361 परिशिष्ट, पृ० 16-8 25, 48 और देखिए, पावर्टी, पृ० 200
24. उदाहरण के लिए बी० बी० जोशी द्वारा 1886-7 में दिया गया वक्तव्य देखिए, भारत सरकार

के वर्तमान खर्चों के प्रमुख कारण नीति संबंधी गलतियों की तरह या तो दूर किए जा सकते हैं या निरीक्षण की कठिनाइयों के कारण इनकी व्यावहारिक क्षति कम होती जा रही है। (पूर्वोद्धृत, पृ० 10) इस संबंध में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण और सरकारी दृष्टिकोण के अंतर को समझना दिलचस्प होगा। उदाहरणार्थ जान स्ट्रैची के कथन को देखिए : 'यह सत्य है कि अनुत्तरदायी लोगों के लिए यह दावा करना सरल है कि सरकारी खर्चों में बचत करने की बड़े पैमाने पर संभावनाएं हैं, परंतु मैं निर्भीकता के साथ चुनौती देता हूं कि प्रशासनिक आवश्यकताओं की वास्तविक जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सिद्ध करना आसान नहीं होगा कि नागरिक सेवा के लिए जितनी राशि खर्च की जा रही है, उससे कहीं अधिक की आवश्यकता है (फाइनांशल स्टेटमेंट, 1878) ई० बेरिंग ने 1883-4 के फाइनांशल स्टेटमेंट में अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा : भारत के वित्तों के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी खतरे, जिनमें युद्ध का खतरा भी शामिल है, ऐसे कारणों से नियंत्रित हैं जिन पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। (कंडिका-121)। इसी प्रकार एलगिन से 1894 में घोषणा की कि भारत सरकार के वित्तों की दुर्गति के लिए उत्तरदायी कारणों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। (स्पेचेज, पृ० 50)।

25. प्रस्ताव सं० II.
26. नौरोजी, स्पेचेज, परिशिष्ट, पृ० 6, 22-3, वही, पृ० 361, 379. परिशिष्ट, पृ० 26-30; जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी०, 1894 पृ० 76; बी० एन० सेन०, रिप० आई० एन० 1895 पृ० 61 इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए जे० मुदालियर ने कहा कि भारतीयों को हिसाब किताब ठीक रखने की ब्रिटिश क्षमता पर पूरा भरोसा है। (वही, पृ० 62)।
27. वही, परिशिष्ट, पृ० 22, 28 तथा बाबा, विलबी कमीशन, खंड III 17316
28. इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 202. मैंने गजेटियर में दी गई तालिका से ही प्रतिष्ठत की संगणना की है शंको के अन्य आकड़े निम्नलिखित लेखकों के निम्नलिखित ग्रंथों में दिए गए हैं, सी० एल० वकील, फाइनांशल डिवलपमेंट आफ माडर्न इंडिया, पृ० 547-8; के० टी० शाह - मिक्सटो ईयर्स आफ इंडियन फाइनांस, पृ० 72-3 और पी० जे० थामस : दि ग्रोथ आफ फंडरल फाईनांस इन इंडिया, पृ० 502.
- 28-ए. इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 382-3
29. वही, पृ० 187.
30. आई० एन० सी०, 1885 का प्रस्ताव L, वक्ताओं में एक बी० एस० पांतुलु गुरु ने भावोद्बोधक घोषणा की कि यदि रूस के आक्रमण की आशंका से ही सेना संबंधी व्यय बढ़ाया जाना है तो इसके फलस्वरूप कराधान में वृद्धि करनी होगी। बढ़े हुए करो को चुकाने में देश खरिद हो जाएगा, किसानों को भूमि छोड़नी पड़ेगी और सरकार को उनके पक्ष का अनुसरण करते हुए भारत देश छोड़ना पड़ेगा...यह तो रूस के आक्रमण की अपेक्षा बदतर ही होगा अतः यह औषधि रोग से बदतर ही है। (रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 73)।
31. 1890 का प्रस्ताव संख्या III (एफ) तथा प्रस्ताव II (एफ)।
32. प्रस्ताव सं० III.
33. इसके उपरान्त इसे 'इंडियन लीफलेट्स' के नाम से संकेतित किया जाएगा।
34. तथा देखिए 26 जनवरी 1886 को बढ़ हुए मिलट्री खर्चों पर भारत सचिव को दिया गया बांबे प्रेजिडेंसी एनोसिएशन का आपन, 1885-6 का बांबे प्रेजिडेंसी एनोसिएशन का प्रथम वार्षिक

- प्रतिवेदन, पृ० 209-16; 30 सितंबर 1886 को पूना सार्वजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत विरोध पत्र, जे० पी० एस० एस०, अक्टूबर 1886 और जनवरी 1887 (खंड IX सख्या 2 और 3) पृ० 1-3; और प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग हेल्ड ऐट दि फामजी कावसजी इंस्टिट्यूट ग्रंथर दि आस्प्रीस आफ दि बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन आन सैंटरडे, दि फिफटीथ जुलाई 1893, फार दि परपस आफ एडार्मिंटग पेटीशंस टु दि हाउस आफ कामंस आन सिमल्टेनिअस एक्जामिनेशंस फार दि इंडियन सिविल सर्विस ऐंड होम मिलिट्री चार्जेज.
35. रिप० आई० एन० सी०, 1885, पृ० 60
36. वही, 1891, पृ० 25
37. वही, 1892, पृ० 84, वही, 1894. पृ० 132-3; वही, 1895 पृ० 71-3; वही, 1897, पृ० 29; स्पीचेज, पृ० 396-7 और परिशिष्ट पृ० 9-11, 16. 31-2, 41-3. सी० पी० ए०, 617, 619.
38. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 7-8, 252-3.
39. वही, पृ० 216-20 तथा देखिए, पृ० 141.
40. गोखले, स्पीचेज, पृ० 26, 43-4, 88-90, 105 परिशिष्ट पृ० 1179-87.
41. उदाहरणार्थ, 1898 में मृदु स्वभाववाले आर० एम० सयानी ने इपीरियल लैंजिस्नेटिव कॉमिल के सदस्य के रूप में बोलने हुए घोषणा की कि निस्संदेह आवश्यक तथा अनुचित रूप से बढ़े हुए मैनिक व्यय यदि देश को वरबादा की ओर ले जाने वाली हमारी वित्तीय उलझनों के प्रमुखतम कारण नहीं हो तो भी प्रमुख कारणों में से एक अवश्यक है' (एन० सी० पी० 1898 खंड XXXVI पृ० 527). आर० सी० दत्त, ने 1900 में दृढ़ता पूर्वक कहा : 'भारत में सामान्य रूप से पढ़ने वाले अकालों का कारण शास्त्रास्त्रों पर तथा युद्धों पर भारी खर्च करने की दूषित नीति है जो भारत को आकुल व्याकुल करने वाली है. भारत किमी कीमत पर न तो ये खर्च सहन कर सकता है और न ही उसे सहन करने चाहिए (फैमिस इन इंडिया, पृ० XIX). बी० कृष्णास्वामी ने 1903 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भ्रूकभोरते हुए कहा : 'कोरे प्रस्तावों पर विश्वास करना छोड़िए. उन्होंने घोषणा की कि इश्तहारों और छोटी छोटी पुस्तिकाओं के द्वारा जनता के क्रोध को भड़काना होगा. प्रत्येक भोपड़ी में जाइए किसान के पास खेतों में जाइए तथा उन्हें इन अन्यायपूर्ण करों के प्रति जागरूक बनाइए (रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 121). और देखिए, एस० एन० बैनर्जी, (स्पीचेज II पृ० 73. स्पीचेज III पृ० 143; एस० ऐंड० डब्ल्यू. परिशिष्ट, पृ० 26, सी० पी० ए०, पृ० 243-6, 706-08; राय, पावर्टी, पृ० 281-3, 298; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 334 349-55, 458; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 220, 281; नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 128, 130; पी० ए०, चारलू एस० सी० पी०, 1902, खंड XLI, पृ० 113-5; श्रीराम, वही, पृ० 148 और वही 1903, खंड XLII पृ० 105; मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 454 में नोरोजी; दत्त, ई० एच० II, पृ० XVII, इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 166.
42. देखिए, उदाहरण के रूप में ज्ञान प्रकाश, 20 जन० (आर० एन पी० बंब, 1 फरवरी 1879); जिवाजी, 31 जनवरी, (वही, 8 फरवरी 1879); इंडियन स्पेक्टेटर, 15 अगस्त (वही, 21 अगस्त 1880); हिंदू, 30 अगस्त (बी० ओ० आई०, सितंबर 1883); सोम प्रकाश, 31 अगस्त (आर० एन० पी० बंग, 5 सित० 1885); संजीवनी, 20 फरवरी (वही, 27 फरवरी 1886); मराठा, 29 मार्च 1891, 13 अप्रैल 1902; हिंदुस्तान, 7 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०, 8 अक्तूबर 1891); हिंदुस्तानी, 20 अप्रैल (वही, 28 अप्रैल 1892); इंदु प्रकाश, 27 मार्च, बंबई

- समाचार, 1 अप्रैल और कैमरे हिंद, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 1 अप्रैल 1993), वगबासी, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 15 अप्रैल 1893), प्रांतकार, 21 अप्रैल (वही, 29 अप्रैल 1893), पैसा अखबार, 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी (895), ए० बी० पी०, 3 अप्रैल 1885, 27 अप्रैल 1902, इंदु प्रकाश, 25 मार्च (आर० एन० पी० बब, 30 मार्च, 1895), अवध टाइम्स, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 13 अप्रैल 1901), भारत जीवन, 17 फरवरी (वही, 22 फरवरी, 1902), ट्रिब्यून, 16 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 25 जनवरी 1902), मराठा, 13 अप्रैल 1902, केसरी, 15 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 19 अप्रैल 1902), केसरी, 21 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1903), हितवादी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 11 अप्रैल 1903), गुजराती, 17 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 23 अप्रैल 1904), इन्डियन एडवोकेट, 18 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी०, 27 अगस्त 1904), स्वदेशमित्र, 9 मई और प्रपच तारकी 13 मई, द्रविडवर्तमान, 11 मई (आर० एन० पी० एम०, 13 मई 1905), इंदु प्रकाश, 23 मार्च कैमरे हिंद, 26 मार्च, गुजराती, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 25 मार्च 1905), इंडियन मोशन रिफार्मर, 26 मार्च ओरिजेंटल रिव्यू, 29 मार्च कल 31 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1905)
43. बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं की धारणा में जबकि यह स्वतः सिद्ध तथ्य अंतर्हित था, जी० के० गोखले ने उसे सुस्पष्ट वाणी दी 'जिम प्रकार लाहें सैलिसबरी ने स्वयं एक बार निर्देश किया था सैन्य क्षमता का निर्धारण प्रत्येक देश के दो तत्वों के समुक्त विचार के सदर्भ में ही करना चाहिए प्रथम, देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं तथा द्वितीय, इस उद्देश्य के लिए उस देश द्वारा सुविधापूर्वक जुटाए जा सकने वाले साधन (स्पीचेज, पृ० 43)
44. ए० बी० पी०, 13 अगस्त, 15 अक्तूबर 1885, हिंदू 20 अगस्त, 24 सितंबर 8 अक्तूबर 1885, मराठा, 11 अक्तू० 1885, इंडियन स्पेक्टर, 27 सित०, 4 अक्तू०, इंदु प्रकाश, 28 सित० 12 अक्तू०, सुबोध पत्रिका, 23 सित०, इंडियन मिरर, 4, 6, 10 अक्तूबर इंडियन नेशन, 5 अक्तू० नेटिव ओपीनियन, 11, 18 अक्तू०, स्वदेशमित्र 28 सित० सजीवनी 3 अक्तू०, हिंदुस्तान, 11 अक्तूबर, गुजराती, 29 सितंबर, कैमरे हिंद, 11 अक्तू० (बी० ओ० आई०, अक्तूबर 1885); एडवोकेट, 23 अक्तू०, सिंध टाइम्स, 24 अक्तूबर ट्रिब्यून 31 अक्तू० बिहार हेराल्ड, 3 नवंबर (वही, नवंबर 1885), समाचार चंद्रिका, 4 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 9 जन० 1886), हिंदू, 13 फरवरी 1890, एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III पृ० 143 एस० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 26 ए० बी० पी०, 5 अप्रैल 1895, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 452 राय, पावर्टी, पृ० 304, दत्त इगलैंड एंड इंडिया, पृ० 136, अवध टाइम्स, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 13 अप्रैल 1901), बाबा, स्पीचेज, पृ० 397, बी० के० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 121, गोखले, स्पीचेज, पृ० 45 104, आई० एन० सी०, 1904 का प्रस्ताव XII
45. ए० बी० पी०, 13 अगस्त 1885, राय, पावर्टी, पृ० 286-7 गोखले, स्पीचेज, पृ० 44, 1180 हितवादी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 11 अप्रैल 1902) 1886 में जी० बी० जोशी ने प्रकाश को प्रस्तुत करते हुए यह प्रमाणित किया कि किम्वद पारिभाषिक दृष्टि से देखने पर भी यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत ने अपनी सेना पर अधिक खर्च किया है (पूर्वोद्धृत पृ० 253). 'इंडियाज अपील टु दि इन्डियन एलेक्टरेट', 1885 ने भारत के मामले को उस समय दूसरे हन से देखा किया जब उसने

- यह तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत किया कि इंग्लैंड में सेना पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय आय का 2 16 प्रतिशत या जबकि भारत में इस व्यय का अनुपात 4 25 प्रतिशत बैठता था (इंडियन लीफ़लैट्स स०-11 पूर्वोद्धृत)
- 46 इंडियन लीफ़लैट्स, स० 9 पूर्वोद्धृत, वाचा, रिप० आई० एन० सी० पृ० 60 तथा सी० पी० १०, पृ० 619, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 449, गोखले, स्पीचेज, पृ० 44, 105, केसरी 21 जुलाई (आर एन० पी० बब, 25 जुलाई 1903)
- 47 रिप० आई० एन० सी०, 1891 पृ० 25
- 48 वही
- 49 सी० पी० ए०, पृ० 619 पर
- 50 आर० एन० पी० बब, 19 अप्रैल 1902 दूसरी ओर इसने अपने 31 मार्च 1903 के प्रक में टिप्पणी की कि यदि देश को समग्रत सुरक्षित रचना है ता उसका आंतरिक विकास करना आवश्यक है (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 1903)
- 51 गाखले, स्पीचेज, पृ० 43 4 इसी प्रकार 1892 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एच० सी० मिना न करुण अभिव्यक्ति करत हुए कहा शस्त्र, लेखनी की हत्या कर रहा है, सैनिक बंदरता कला और मस्कर्ति का नष्ट करने जा रही है (रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 96) देखिए वार प्रजीडमी एसोसिएशन का 27 जनवरी का आपन, पूर्वोक्त स्थल, पी० महता स्पीचेज, पृ० 334 5, 350, 457 8 मानवीय, स्पीचज पृ० 295 जी०एस०अय्यर, विलबी कमिशन खड III पृ० 19963, आर० एम० सयानी, एल० सी० पी० 1898, खड XXXVII पृ० 527 १० एम० वाम, सी० पी० १०, पृ० 425 7, हिंदू, 26 अप्रैल 1902 गोखले, स्पीचेज, पृ० 26, 28, 109 सी० वाई० चिनामणि, 'इंडियन मिलिट्री गवर्नमेंटोचर' एच० आर०, फरवरी 1903 पृ० 233 इतिहास, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 11 अप्रैल 1903), आई० एन० सा० 1903 का प्रस्ताव VII
- 52 एन० सी० पी० 1894 खड XXXI II पृ० 273
- 53 कन्न, स्पीचेज, II पृ० 266 एक वर्ष पूर्व उमने कहा था 'भारत में साम्राज्य के राजनीतिज्ञ के दा वडे कतव्य है प्रथम यथामभव इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को अधिकाधिक सतुष्ट, प्रसन्न और समृद्ध बनाना द्वितीय, देशवासियों को तथा उनकी संपत्ति को सुरक्षित बनाना हम एक कतव्य की उपेक्षा करके दूसरे कतव्य के पालन की ओर नहीं बढ़ सकते' (स्पीचेज I पृ० 325) तथा देखिए, स्पीचेज III पृ० 404
- 54 उदाहरण के रूप में जनरल ब्रेचनबरी ने अपने पूर्वोद्धृत भाषण में घोषित किया 'भारत सरकार मितव्ययिता की दिशा में दिए गए किसी भी व्यावहारिक सुझाव का स्वागत करती है और सदा स्वागत करगी' (एल० सी० पी० 1894 खड XXXIII पृ० 274)
- 55 वाचा रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 73
- 56 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खड IV पृ० 187
- 57 इस विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए, मेरा लेख, 'इंडियन नेशनलिस्ट्स ऐंड फारेन वार्स ऐंड एक्सपोजिशन 1878-99 हिस्टोरिकल स्टडीज, स०-1, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
- 58 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खड IV पृ० 348-9
- 59 आई० एन० सी० का 1885 का प्रस्ताव V, वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 601-1

- बोली, पूर्वोद्धृत, पृ० 254. ए० बी० पी०, 13 अगस्त, 15 अक्तू० 1885; हिंदू, 20 अगस्त, 24 सित०, 8 अक्तूबर, नवंबर 1885. मराठा, 11 अक्तू० 1885. 'अक्तू०-नवंबर, 1885 के बी० ओ० आई०, मे उद्धृत पत्र, आर० एन० पी० ब०, 22 अगस्त, 5, 26 सित०, 7 नवंबर 1885, 9 जनवरी 1886 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएँ; बाबे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन का 27 जनवरी 1886 को प्रस्तुत स्मरणपत्र, रिपोर्ट आफ दि बाबे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन 1885-6, पृ० 209, 214-5, मद्रास महाजन सभा का लाहं डफरिन को संबोधित पत्र, मराठा, 7 मार्च 1886, पूना सार्वजनिक सभा द्वारा 30 सितंबर 1886 को प्रस्तुत विरोधपत्र; जे० पी० एस० एस० अक्तूबर 1886 और जनवरी 1887) खंड IX, सख्याएँ, 2-3).
- 60 आई० एन० सी० का 1891 का प्रस्ताव स० III, वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1891, पृ० 23-6, राय, पावर्टी, पृ० 304-06; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 141, 201, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 9 10, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1183, 1205 सी० शंकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 386, केसरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० ब०, 7 अप्रैल 1900); वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 617; गोखले, स्पीचेज, पृ० 26-7 हिंदू, 4 अप्रैल (बी० जो० आई०, 26 अप्रैल 1902), एच० आर०, अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 4 अक्तूबर 1901), एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 706, सी० वाई० चिंतामणि, 'इंडियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर,' एच० आर० मार्च 1903 पृ० 227 एल० एम० घोष० सी० पी० ए०, पृ० 764 दत्त, ई० एच० II, पृ० XVII
- 61 बंगाली, 23 मई 1896 ए० बी० पी०, 27 मई 1896, हिंदू, 27 मई (आई० एम० बी० ओ० आई०, 12 जुलाई 1896), आई० एन० सी०, 1899, 1901, 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव सख्या-3, 10, 7, 7(बी) और 12(सी) क्रमशः, बी० एन० बसु, रिप० आई० एन० सी०, 1899 पृ० 53, बंगाली, 29 जून 1900, दत्त, स्पीचेज II पृ० 85, एच० एस० दीक्षित, रिप०, आई० एन० सी०, 1901 पृ० 154; गोखले, (स्पीचेज, पृ० 27, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 114-5, श्रीराम, बही, पृ० 148, एम० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 706, बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी०, 1902 पृ० 105, ए० बी० पी०, 15 मार्च 1903; वाचा, स्पीचेज, पृ० 400 श्रीराम, एल० सी० पी०, 1903 खंड XI II पृ० 105; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 764, बी० एन० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1903 पृ० 121,
- 62 प्रस्ताव स० VII (ए) तथा प्रस्ताव स० XII (सी) क्रमशः
- 63 नीरोजी, स्पीचेज, पृ० 352 और देखिए, पृ० 250, 340-1, और मसानो पूर्वोद्धृत, 434-5
- 64 गोखले, स्पीचेज, पृ० 106-07 और देखिए पृ० 21, 26-7 1156, 1205
- 65 राय, पावर्टी, पृ० 287, 293 305-06 हिंदू 24 सित० और 8 अक्तू० 1885, मराठा, 11 अक्तू० 1885, अक्तू०-नवंबर 1885 के बी० ओ० आई० में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएँ पूना सार्वजनिक सभा द्वारा 30 सितंबर 1886 को प्रस्तुत विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 29, तथा सी० पी० ए०, पृ० 607, 618 स्पीचेज, पृ० 396; दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 110, 137, सी० पी० ए०, पृ० 490, स्पीचेज II पृ० 45, 85, ई० एच० II पृ० 566-7, श्रीराम, एल० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 148 और बही, 1903 खंड XLII पृ० 106, एच० आर०, अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 4 अक्तू० 1902); एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 706, 708 बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 105, ए० बी० पी०, 22 सितंबर 1903, एन० एम० समर्थ, रिप० आई० एन० सी०, 1903 पृ० 119.

बंगाली, 18 मार्च 1905.

66. देखिए ऊपर, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 155. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1163; बाबा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 33.
67. आई० एन० सी० 1899, 1901. 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव संख्या IIL, X, VII, VII (ए) और XII (सी) क्रमशः; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 158; गोखले, स्पीचेज, पृ० 27, 107, 995, 1205-07; नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 163, 250, 340-2, 350 परिशिष्ट पृ० 93. मसानो : पूर्वोद्धृत, पृ० 454 5; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 453-5, बाबा, स्पीचेज, पृ० 400-01, परिशिष्ट, पृ० 33 और सी० पी० ए०, पृ० 618-9; जी० एस० अय्यर, विलबी कमिशन, खंड खड III प्रश्न 19800; दत्त, स्पीचेज, I पृ० 34-5, स्पीचेज II पृ० 85, ई०एच० II-पृ० 566, 612; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 706. एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 765; अक्टूबर और नवंबर 1885 के बी० ओ० आई० में उद्धृत पत्र-पत्रिकाएं; पंसा अखबार, 4 मई (आर० एन० पी० पी०, 18 मई 1895); बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1899 पृ० 53; पंसा अखबार 18 जन० आर० एन० पी० पी० 21 जनवरी 18899; केसरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 7 अप्रैल 1900); बंगाली, 29 जून 1900; श्रीराम, एल० सी० पी० 1902, खड XLI पृ० 148, और वही, 1903 खड XLII पृ० 105, बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 105; ए० बी० पी०, 22 सित० 1903 बंगाली, 18 मार्च 1905; केसरी, फरवरी (आर० एन० पी० बब, 11 फर० 1905) वस्तुतः 1867 में ही दादाभाई नोरोजी ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और कदाचित् उन्होंने इस प्रश्न पर राष्ट्रवादियों के आंदोलन के लिए एक आदर्श भी जुटाया. वह आदर्श यह मांग की कि ब्रिटेन को प्रचीसीनिया अभियान में नियोजित भारतीय सेनाओं के सभी माध्यारण खर्चों का भुगतान करना चाहिए. (एसेज, पृ० 51-9).
68. आर० एन० पी० यू० पी०, 25 जुलाई 1903. तथा एडवोकेट, 30 जुलाई (बी० ओ० आई०, 22 अगस्त, 1903).
69. धार० एन० पी० बब, 25 जुलाई 1903
70. इंडिया, 7 अगस्त 1903 और देखिए हिंदू, 18, 23 जुलाई 1903; मराठा, 26 जुलाई, 29 अगस्त 1903; ए० बी० पी०, 18, 20 जुलाई 1903, बंगाली, 19, 22 जुलाई 1903; वायस आफ इंडिया 25 जुलाई 1903, आर० एन० पी० बब, 25 जुलाई 1903; उल्लिखित पत्र. आर० एन० पी० बग, 25 जुलाई, 1 अगस्त 1903, आर० एन० पी० यू० पी० 8, 15, 22 अगस्त 1903, आर० एन० पी० पी०, 1, 8, 15 22, 29 अगस्त 1903, बी० ओ० आई०, 1, 8, 15 अगस्त 1903 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएं; इंडियन रिव्यू, अगस्त 1903, पृ० 45; बाबा, स्पीचेज, पृ० 398; कैसरे हिंदू, 16 अगस्त (वही, 22 अगस्त 1903); गुजराती सभा के तत्वावधान में अहमदाबाद में हुई जनसभा प्रजाबधु, 16 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 22 अगस्त 1903).
71. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 155-6, 253-4; इंडियन सीफलैट्स सं०, 11 पृ० 2. बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 53, 61; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1181-3; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1902 खड XLI पृ० 113, 115.
72. एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज II पृ० 73. स्पीचेज III पृ० 6-7; इंडियन सीफलैट्स-सं० 11 पृ० 2; ए० बी० पी०, 13 अगस्त 1885; बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 53, 61,

स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 16; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 253; राय, पावर्टी, पृ० 285; गोखले स्पीचेज, पृ० 1183, ए० भीमजी, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 40

73. 1859 की एकीकरण योजना की आलोचना के लिए देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, 'ए स्टेटमेंट आफ इंडियन नवरेचर्स' जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV स०-1) पृ० 10, बाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1885, पृ० 53-6, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 23, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 71, रिप० आई० एन० सी०, 1897 पृ० 29 स्पीचेज, पृ० 395; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 245; गोखले, स्पीचेज, पृ० 1184, सी० वाई० चितामणि, 'इंडियन मिलिट्री एक्स्पेडीचर' एच० आर०, फरवरी 1903, पृ० 120, आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव VII (डी) अन्य पक्षों के लिए देखिए, रानाडे, 'रिथ्यू आफ फासेट्स थ्री एसेज आन इंडियन फाइनांस' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 80, इंडियन स्पेक्टेटर, 11 मई (आर० एन० पी० बब, 17 मई 1884); बाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 57-60, इंडियन लीफलेट्स, स० 9 पृ० 6-7, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 156, आई० एन० सी० 1891 का प्रस्ताव III, गोखले, स्पीचेज, पृ० 992 5, 1184, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 160, 352, बगवामी, 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 27 अप्रैल 1905)
74. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1186-7 1880 में ही जस्टिस रानाडे ने रटाफ काम्स मिस्टम ममाप्त करने की माग की थी देखिए उनका 'रिथ्यू आफ फासेट्स थ्री एसेज आन इंडियन फाइनांस' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 80 भारतीय सैनिक अधिकारियों को मिलने वाले भारी वेतन की आलोचना भी इंडियन लीफलेट्स स० 9 पृ० 6 पर की गई है
- 75 आर० एन० पी० बब, 21 अगस्त 1880 और इंडियन स्पेक्टेटर, 20 अगस्त (वही, 26 अगस्त 1882); इंडियन लीफलेट्स स० 11 पृ० 2, स्वदेशमित्र, 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 1885); ए० बी० पी०, 16 मित० 1886; ए० भीमजी, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 133-4.
- 76 आई० एन० सी० 1902 और 1903 के प्रस्ताव स० VII और VII (सी) ए० बी० पी०, 28 अप्रैल 1902; हिंदू, 24 मार्च, 15 अप्रैल, 9 जुलाई 1902, मराठा, 6 जुलाई 1902, गुजराती, 6 जुलाई, मद्रास स्टैंडर्ड, 8 जुलाई, नेटिव ओपीनियन, 9 जुलाई, इंडियन नेशन 21 जुलाई (बी० ओ० आई०, 2 अगस्त 1902); केसरी, 8 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 12 जुलाई 1902). आध प्रवाशिक 16 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 19 अप्रैल, 1902), स्वदेशमित्र, 16 जुलाई (वही, 26 जुलाई 1902), निजाम उल मुल्क, 24 मार्च (आर० एन० पी० एन०, 29 मार्च 1902); एम० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 706, बाचा, स्पीचेज, पृ० 397, ए० बी० पी०, 20 और 23 अगस्त 1903, बगाली, 22 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 29 अगस्त, 1903). शायम आफ इंडिया, 18 जुलाई, कल 17 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 18 जुलाई 1903); केसरी, 21 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1903); अहदाबाद में जनसभा, प्रजाबधु, 16 अगस्त (वही, 22 अगस्त 1903) यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि प्रजाबधु ने शिकायत की कि नगर के प्रमुख धनी, सेठ सभा में बिलकुल अनुपस्थित थे इंडियन पीपुल और अवध समाचार, 7 अगस्त (आर० एन० पी० ए० पी०, 15 अगस्त 1903); एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 763; खड्गारे आम, 16 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 25 जुलाई 1903)
77. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 239, 241, 252; सुबोध पत्रिका, 16 नवंबर जामे जमनेद, 22 नवंबर

(आर० एन० पी० बब, 22 नव० 1884); एडवोकेट, 29 जनवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 4 फर० 1905)

- 78 राय पावर्टी, पृ० 285; मराठा, 24 मार्च 1895, जी० आर० एम० चितनवीम, एन० सी० पी० 1895 खड, XXXIV पृ० 400, बगदासी, 29 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 अप्रैल 1895), सहचर, 10 अप्रैल (वही, 20 अप्रैल 1895), अखबारे आम, 28 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 6 अप्रैल 1895), शुभ सूचक, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 20 अप्रैल 1895)
- 79 इंदु प्रकाश, 28 मई (आर० एन० पी० बब, 2 जून 1883), एस० बी० सुब्बरायुडू, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 72, हिंदू, 24 जून 1885; स्वदेशमित्र, 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 1885), टिप्पून, 18 मित० (बी० ओ० आई०, अक्टू० 1886), जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 6-8, एन० जी० चंदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 529, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 15 यहा यह उल्लेखनीय है कि 1893 में पृथक प्रमोदसी सेना को समाप्त कर दिया गया था
- 80 आई० एन० सी० 1904 प्रस्ताव XII (बी), कैमरे हिंदू, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब, 31 दिस० 1904), इंडियन पीपल, 28 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी०, 3 सित० 1904), एडवोकेट, 29 जनवरी (वही 4 फरवरी 1905), गाखले स्पीचज, पृ० 102-4, इंदु प्रकाश, 23 मार्च कैमरे हिंदू, और गुजराती, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 25 मार्च 1905), इंडियन सोशल रीफार्मर, 26 मार्च, ओरियंटल रिव्यू, 29 मार्च, एल, 31 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1905), स्वदेशमित्र 9 मई प्रपंच तारकी, 13 मई द्रविडावर्तमणि, 11 मई (आर० एन० पी० एम०, 13 मई 1905)
- 81 देखिए नेव, फ्रेजर पूर्वोद्धृत, पृ० 415-53
- 82 ए० बी० पी०, 15 मई 1905, मराठा, 25 जन 1905, एच० आर०, जुलाई, 1905, पृ० 80-1; आर० एन० पी० बब 1, 8 जुलाई 1905 म, आर० एन० पी० एम०, 1, 15 जुलाई 1905 में आर० एन० पी० बग०, 1, 8, 15 जुलाई 1905 में तथा आर० एन० पी० यू० पी०, 1, 8 जुलाई 1905 में उल्लिखित पत्र-परिचय
- 83 रतार, 'रिव्यू आफ फासेट्स, 'थी एसेज, आन इंडियन' फाइनास' जे० पी० एस० एम०, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 80, हिंदुस्तान, 6 दिसंबर (आर० एन० पी० पी० एन०, 12 दिस० 1883); सहचर, 12 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 22 अगस्त, 1885), टिप्पून, 30 मई, सुबोध पत्रिका, 27 मई (बी० ओ० आई०, जून 1885), एम० ए० स्वामिनाथ अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 68, नवविभाकर, 1 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 6 फरवरी 1886), ए० भीमजी, रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 68 नवविभाकर 1 फर० (आर० एन० पी० बग०, 6 फरवरी 1886), ए० भीमजी, रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 133-4, बी० एन० दर, रिप० आई० एन० सी०, 1894, पृ० 139, राय, पावर्टी, पृ० 284; नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 75-6, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1182-3; सी० वाई चिंतामणि, 'इंडियन मिलिट्री एक्सपेंडीचर' एच० आर०, फरवरी 1903, पृ० 226-7
84. नौरोजी, (स्पीचेज, पृ० 74-5 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1 82
- 85 इस मांग का विस्तृत विवेचन आगे किया गया है
86. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो यह मांग बहुत पहले 1887 और 1888 में उठाई थी (प्रस्ताव IV और VI क्रमशः) और तब लगभग 1904 तक निरंतर इस मांग को दोहराती रही. इसके

प्रस्तावों में आर्थिक तर्कों का स्पष्ट प्रतिपादन तो नहीं है परंतु जिन लोगों ने इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और जिन महानुभावों ने इन पर वक्तव्य दिए, उन्होंने आर्थिक तर्क एवं युक्तियाँ अवश्य पेश की थीं, देखिए, ए० एम० भीमजी, रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 134, और तिलक, रिप० आई० एन० सी०, 1891 पृ० 38-9 और देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर, 22 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 28 जन०, 1882); मराठा, 14 फरवरी 1886; हिंदुस्तान, 7 अक्तू० (आर० एन० पी० एन०, 8 अक्तू० 1891); गोखले, स्पीचेज, पृ० 1185, 1187-8; केसरी, 17 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 21 जनवरी 1899).

87. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 156, 242, 246-7, 253-4; गोखले, स्पीचेज, पृ० 46-8, 90-1, 1183-5, और देखिए, राजा रामपाल सिंह, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 93. यह देखना भी मजेदार होगा कि यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही राजा राममोहन राय ने देश के प्रशासनिक ध्येयों में कटौती के उपाय के रूप में स्याई सेना के एक बहुत बड़े भाग के लिए नगर रक्षक दल की स्थापना की वकालत की थी. उन्होंने कहा था कि मानव को दुख देने वाले भूमि राजस्व आदि में वृद्धि करने के किसी भी प्रकार को ढग की अपेक्षा इससे होने वाली बचत से अधिक उपयोगी लाभ होगा (बी० बी० मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ० 70)
88. 1886 का प्रस्ताव स० XII, 1887 का प्रस्ताव स० V तथा 1888 का प्रस्ताव स० VI तथा निम्नलिखित
- 89 रामपालसिंह, रिप० आई० एन० सी०, 1886 पृ० 93; एम० बाहिद अली, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 133; तिलक, रिप० आई० एन० सी०, 1891 पृ० 38-9; गोखले, स्पीचेज, पृ० 48-9 इस दृष्टि से कि हम मांग को इस्तेमाल शिक्षित भारतीयों को अथवा बगालियों को धकेलने के लिए एक और प्रयास की तरह न किया जाए, गोखले ने प्रस्ताव रखा कि 'सरकार प्रयोग के लिए किसी विशिष्ट धेव का तथा किसी विशिष्ट जाति के किसी विशिष्ट वर्ग का चुनाव कर सकती है' (वही) तथा देखिए वही, पृ० 90-1; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 7-8, 252, हिंदू, 20 अप्रैल 1885
- 90 हम विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, मेरा लेख, 'इंडियन नेशनलिज्म ऐंड फारेन वार्स ऐंड एक्सपीडिशन, 1878-9' प्रकाशित, 'हिस्टोरिकल स्टडी', ग्रंथ 1.
91. आई एन० सी० के 1892, 1895, 1897 और 1898 के प्रस्ताव क्रमशः VII, VIII, I, II, III, और VII, पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 452-3; राय पावर्टी, पृ० 299-300; आजाद, 17 मई (आर० एन० पी० एन०, 25 मई 1895); एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 255; एस० ऐंड० डब्ल्यू०, परिशिष्ट पृ० 48; डी० जी० उपाध्ये, रिप० आई० एन० सी० 1895 पृ० 101; पी० ए० चारनू, एन० सी० पी० 1896 खंड XXXV पृ० 286; नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 344-6, 349-50, परिशिष्ट, पृ० 79, 93 तथा आगे; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 33, रिप० आई० एन० सी० 1897 पृ० 32 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1206-07; जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन खंड III प्रश्न 19800; हिंदू, 26 अगस्त 1897; रियाज उल अखबार, 12 जन० (आर० एन० पी० एन० 19 जन० 1897); हिंदुस्तानी, 13 अक्तू०, 22 दिस० (वही, 20 अक्तू०, 29 दिसंबर 1897); सहचर, 22 दिस० 1897 (आर० एन० पी० बंग०, 1 जन० 1898); सजीवनी, 12 फरवरी, (वही, 19 फरवरी 1898); जी० आर० एम० चितनवीस, एस० सी० पी० 1898, खंड XXXVII पृ० 486; आर० एम० सयानी, वही, पृ० 525-7; बंगाली, 26 मार्च 1898; गुरुजी, 26 फर०, राज्यभक्त, 1 मार्च, कैसरे हिंद, 27 फर० (आर०

- एन० पी० बंब, 5 मार्च 1898) दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पूर्वोद्धृत, 110-1 स्पीचेज I पृ० 34 5, 41, ए० एम० बोस, सी० पी० ए, पृ० 421; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी०, 1902 खंड XLI पृ० 116; एच० ए० बाडिया, रिप० आई० एम० सी० 1904 पृ० 203; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 765; केसरी, 7 फरवरी (आर० एन० पी० बंब 11 फरवरी 1903)
- 92 सी० पी० ए० पृ० 168 तथा देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 75-6, 78, 90
93. मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 456 पर.
94. राय, पावर्टी, पृ० 299 इसी प्रकार 1898 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने पूछा - 'क्या इंग्लैंड को यह पक्का विश्वास है कि यदि भारत की मुरझा नष्ट हो गई और भारत ब्रिटिश साम्राज्य से छिन गया तो वह प्रभारों के रूप में ज्ञात मूल्यवान विषयों के रूप में इंग्लैंड को मिलने वाले लाखों करोड़ों रुपये की हानि से इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को, उसके गौरव को, उसके व्यापार को, उसके विनियोजन को, उसकी पूँजी को तथा उसकी जनता को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी ?' (ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 420) और देखिए, हिंदू, 20 अगस्त 1885, 13 फरवरी 1890; सुरभि, 1 सित० (आर० एन० पी० बंब, 5 सित० 1885); पताका, 18 सित० (वही, 26 सित० 1885), तिरंगा निम्नान, 1 सितंबर (आर० एन० पी० एम०, 15 सित० 1888), ए० बी० पी०, 5 अप्रैल 1895, 27 मई 1896, आर० एम० एम० एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 527, एस० एन० बैंनर्जी, एम० ऐंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 26, 48; विलबी कमिशन, खंड III प्रश्न 19435, सी० पी० ए०, पृ० 708, केसरी, 10 जून (आर० एन० पी० बंब, 14 जून 1902); दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 140-1, 145, 166, ई० एच० II पृ० 567; गोखले, स्पीचेज, पृ० 28, 105, 1208
- 95 आर० एन० पी० बंब, 29 अगस्त 1903
- 96 राय, पावर्टी पृ० 296
97. सी० शंकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 357; गोखले, स्पीचेज, पृ० 48
- 98 नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 75-6 तुलनीय एच० एल० सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० 165-8, 206
- 99 आई० एन० सी० 1891 का प्रस्ताव IV; तिनक, रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 38-9; एस० ए० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1885, पृ० 68, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 156, 252; नौरोजी, स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 75, राय, पावर्टी, पृ० 207, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 16; गोखले, स्पीचेज, पृ० 48-9, 90-1
- 100 नौरोजी, पावर्टी, पृ० 216, सी० पी० ए, पृ० 165-6 स्पीचेज, पृ० 658-9, 664, एस० एन० बैंनर्जी, स्पीचेज, I पृ० 192, एस० ऐंड डब्ल्यू०, पृ० 422 और सी० पी० ए०, पृ० 250, ए० बी० पी०, 3 सितंबर 1885 और 19 जुलाई 1891; बगाली, 4 जून 1887, 10 अक्टू० 1897 और 1 जुलाई 1903, केसरी, 14 सितंबर (आर० एन० पी० बंब, 18 सित० 1897), ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 403; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1902 खंड XLI पृ० 115-6 अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 1 मई 1884 के प्रक में इस दृष्टिकोण का विपरीत ढंग से प्रयोग किया उसने लिखा 'यही कारण है कि भारतीय जनता रूसी सेना के भारतीय सीमाओं की ओर आगे बढ़ आने पर असीम सतोष अनुभव करती है, क्योंकि उसका विश्वास है कि रूसी जितना ही भारत की सीमा के अधिक निकट आएंगे, उतना ही उसके मालिक उसका अधिक आदर-सम्मान करेंगे'
101. इंडिया, जुलाई 1897 पृ० 202 और उदाहरणार्थ देखिए, ए० बी० पी०, 21 मई 1885, 31 मई

1888; 27 अगस्त 1886 को व्ययों की कटौती पर बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन, सेकंड एनुअल रिपोर्ट आफ दि बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1886-7; 30 सितंबर 1886 को पूना सार्वजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत विरोधपत्र, जे० पी० एस० एस० अक्टू० 1886 और जनवरी 1887 (खंड IX सं० 2 और 3); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 824-5; आई० एन० सी० 1891 और 1904 के प्रस्ताव सं० III (बी) और III क्रमशः, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 456; मानवीय, स्पीचेज, पृ० 250, 281; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 9, 31-2, सी० पी० ए०, पृ० 607-8; ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 127; 'दि इकोनामिक सिचुएशन इन इंडिया' अन्न, अक्टू० 1899 (खंड IV सं० 3) पृ० 65.

102. नैतिक और सामाजिक लाभों के लिए हम थोड़े से ही उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं. देखिए, जी० के० गोखले, स्पीचेज, पृ० 188 इंडियन पीपुल्स राइट : अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 23 दिसंबर 1886 के प्रक में अपना दृढ़ मत प्रकट करते हुए लिखा कि 'भारत के लोगों का दावा है कि भारतीय प्रशासन के सभी स्थानों पर ही उनका ही अधिकार है उनके इस दावे का आधार यह है कि इन सभी स्थानों का व्यवहार भारतीय ससाधनों द्वारा उठाया जाता है अतः भारत के नागरिक होने के नाते इन स्थानों को वे अपनी ही संपत्ति समझते हैं. इसी प्रकार 1904 के राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रस्ताव सं० I का पेश करते हुए सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी ने तर्क उपस्थित किया कि विचारणीय तत्त्व यह है कि यद्यपि देश हमारा है, धन हमारा है, भारी जनसंख्या हमारी है फिर भी हमारे भाग्य में ऊँची नियुक्तियों का केवल 14 से 17 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है, ऐसा क्यों? (रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 64). सेवाओं के भारतीयकरण का प्रचार राजनीतिक दृष्टि से इस रूप में किया गया कि यदि शिक्षित भारतीय लोगों का लाभप्रद नियुक्तियां न दी गईं तो वे राजनीतिक दृष्टि से अमंजिल अनुभव करेंगे. उदाहरण के लिए देखिए: नोरोजी, एसेज, पृ० 38, पावर्टी, पृ० 205, स्पीचेज, पृ० 507; माडलिक, स्पीचेज, पृ० 701; ए० बी० पी०, 9 जनवरी 1880; गोखले, स्पीचेज, पृ० 68-9.
103. आई० एन० सी० 1801, 1897, 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव सख्या, III, III (ii), XV, II (सी) और I (बी) क्रमशः, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 124, 184, 639, स्पीचेज, पृ० 284-6, परिशिष्ट, पृ० 5; एस० एन० बॅनर्जी, स्पीचेज I पृ० 191, सी० पी० ए० पृ० 270, एस० एंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 26-8, 32, 44, 47; 16 मई 1880 को पूना को जनसभा में स्वीकृत विरोधपत्र, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खंड III सं० 1), पृ० 7. रानाडे, 'रिब्यू आफ फारवेर्दस 'थी एसेज आन इंडियन फाइनांस', जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खंड III सं०-1), पृ० 80; पूना सार्वजनिक सभा द्वारा 2 मार्च 1881 को प्रस्तुत ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV सं०-1), पृ० 12; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 5, 6, 49, 155; बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का 27 अगस्त 1886 को प्रस्तुत स्मरणपत्र, रिपोर्ट आफ दि फाइनांस कमिटी (कसकता, 1887), खंड II पृ० 452-3; रानाडे मेमोरेंडम आफ डिस्टेंस, वही, खंड-1 पृ० 398. मालवीय, स्पीचेज, पृ० 280, 299-301, 518. गोखले, स्पीचेज, पृ० 28, 63-4, 1187-8. वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 26-7, 29, 31-2 सी० पी० ए०, पृ० 609. दत्त, ई० एच० I पृ० 413. ई० एच० II पृ० XVII, सी० पी० ए०, पृ० 491. बी० एस० जय्यर, ई० ए० पृ० 100. बिलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18764 एस० ए० स्वाभिनाथ जय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 68; माला मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी०, 1891,

- पृ० 15. जी० ए० पाटिल, रिप० आई० एन० सी०-1902 पृ० 139. नवविभाकर, 14 जून (आर० एन० पी० बग०, 19 जून 1880). अरुणोदय, 23 जन० (आर० एन० पी० बब, 29 जन० 1881), बकुल, 31 दिस०, शिवाजी, 29 दिस० 1882 (वही, 7 जन० 1883), इंडियन स्पेक्टेटर, 25 फरवरी और 24 जून (वही, मार्च और 30 जून 1883 क्रमशः). मराठा, 3 जून, 9 सितंबर 1883, अल्मोड़ा अखबार, 9 जुलाई (आर० एन० पी० पी० एन०, 14 जुलाई 1883); उचित वक्ता, 15 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 22 मार्च 1884), नवविभाकर, 1 सित० (वही, 6 सित० 1884), पताका, 10 जुलाई (वही, 18 जुलाई 1885), नेटिव ओपिनियन, 19 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 25 अप्रैल 1885); हनु प्रकाश, 25 मई (वही, 30 मई 1885); ए० बी० पी०, 21 मई 1885, 18 नवंबर, 9 और 16 दिस० 1886; बगाली, 16 जन० 1886, 14 फरवरी 1886; इंडियन स्पेक्टेटर 27 जून और 14 नव० 1886, मराठा 20 जून, हिंदू, 15 जुलाई (बी० ओ० आई०, जुलाई 1886) भारतीय प्रेस के विचारों का मासिकीय सार-संक्षेप, बी० ओ० आई०, जुलाई 1886 केसरी, 31 जन० (आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी, 1888); अखबारे आम, 21 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 28 अप्रैल 1888); ए० बी० पी०, 31 मई 1888 और 3 मार्च और 24 मई 1894; विक्टोरिया पपर, 30 नव० (आर० एन० पी० पी०, 12 दिस० 1891), आर्यजनप्रियन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1893), ज्ञानोदयम, 1 मई (वही, 15 मई 1893), बगवामी, 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 27 अप्रैल 1895), वसुमती, 5 मई (वही 14 मई 1898); केसरी, 31 मार्च (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 1903), इंडियन पोपुल, 18 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी० 27 अगस्त 1904)
104. भिन्न भिन्न लोगों का जोड़ भिन्न भिन्न था और यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उन सबने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1892 के अधिवेशन में मदनमोहन मालवीय द्वारा जुटाए गए अनुमानित और मिलते जुलते आकड़ों पर ही हिसाब लगाया था (स्पीचेज, पृ० 515-6) तथा देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 134 (उनकी अकगणना 20 करोड़ रुपये बँठती थी) परिशिष्ट पृ० 6, 89-90; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 607; दन, ई० एच० I पृ० 427 की पादटिप्पणी, स्पीचेज I पृ० 178 गोखले स्पीचेज, पृ० 1187 8 ममदीय लेखा-जोखा के लिए देखिए, इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 201
105. माबलिक, स्पीचेज, पृ० 186-7; पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 225, अन्य भारतीय नेताओं के लिए देखिए, प्रोसीडिंग्स आफ पब्लिक सर्विस कमिशन (कनकता, 1887, खंड I भाग III पृ० 18-20, 45-6, खंड II भाग II पृ० 23, खंड III भाग III पृ० 5; खंड IV भाग II पृ० 102, 325 (तिलक); खंड V भाग II, पृ० 288, 393, खंड VI, भाग II पृ० 36, 240, 273, 428, 442, 494, 504, भाग II पृ० 32, 71, 86
106. ए० एम० बोस, सी० पी० ए० पृ० 407; गोखले, स्पीचेज, पृ० 18
107. बी० ओ० आई०, जुलाई 1886.
108. और देखिए, रास्त गुप्तार, 29 जून शुभ सूचक, 13 जून (आर० एन० पी० बब, 5 जुलाई 1879); एस० ए० स्वामिनाथ अय्यर रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 68; इंडियन स्पेक्टेटर और मराठा, 20 जून (बी० ओ० आई०, जुलाई 1886), स्वदेशमित्रन तिथिरहित (आर० एन० पी० एम०, फरवरी 1887); केसरी, 31 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी 1888); आर्यजनप्रियन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1893); ए० बी० पी०, 24 मई

- 1894; बसुनती, 5 मई (आर० एन० पी० बग०, 14 मई 1898); जी० एस० बय्यर, ई० ए०, पृ० 100, दत्त, स्पीचेज I पृ० 94.
- 109 प्रोसीडिंग्स आफ पब्लिक सर्विस कमीशन (1887) खंड II भाग III पृ० 41; खंड III भाग III पृ० 7; खंड IV भाग III पृ० 147 खंड IV भाग II पृ० 214, खंड VI भाग II पृ० 386, भाग III पृ० 93.
110. वही, खंड IV भाग II पृ० 130 (नोरोजी), पृ० 145 (रानाडे), खंड V भाग II पृ० 230; खंड VI, भाग II पृ० 74.
111. एम० एन० बैनर्जी, एस० ऐड डब्ल्यू०, परिशिष्ट पृ० 47 तथा देखिए एस० एन० बैनर्जी, बिलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 19419.
112. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, 5 इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 11, 31-2, 37 भी
113. ए० बी० पी०, 27 फरवरी 1880; रानाडे, 'रिब्यू आफ फासेट्स थी एसेज आन इंडियन फाइनांस' जे० पी० एस० एम०, जुलाई 1880 (खंड III, स० 1) पृ० 80; जलवा तूर, 1 मार्च (आर० एन० पी० पी० एन, 4 मार्च 1880), भारत मिहिर, 3 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 14 अगस्त 1880), जे० पी० एस० एस० जुलाई 1881 (खंड IV स० 1) पृ० 10, बंगाली, 29 अक्तू० 1881; बकुल, 31 दिस० 1882, शिवाजी, 29 दिस० 1882 (आर० एन० पी० बग०, 6 जन० 1885), भारत मिहिर, 5 जून (आर० एन० पी० बग०, 9 जून 1883), सुरभि, 2 जून (वही, 7 जून 1884); नवविभाकर, 1 सित० (वही, 6 सित० 1884), तत्व-विवेचनी, 4 मई (आर० एन० पी० एम०, मई 1884); बंगाली, 19 जुलाई 1884, प्रजावधु, 6 फर० (आर० एन० पी० बग०, 14 फरवरी 1885), पताका, 11 सित० (वही, 19 सित० 1885); नेटिव ओपीनियन 19 अप्रैल आर० एन० पी० बग०, 25 अप्रैल 1885 इंदु प्रकाश, 25 मई, वही, 30 मई 1885); स्वदेशमित्र, 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 1885); बी० राघवाचारी, रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 44-5; जे० यू० याज्ञिक, वही, पृ० 65, एस० ए० एस० बय्यर, वही पृ० 68, एम० एन० बैनर्जी, स्पीचेज, III पृ० 15-6, 195; मराठा, 14 फर० और 18 जुलाई 1886; सिंध टाइम्स, 10 जून, बंगाली, 3 जुलाई (बी० ओ० आई०, जुलाई, 1886); सजीवनी, 9 जन० सोम प्रकाश, 11 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 16 जन० 1886), भारत मिहिर, 14 जन० (वही, 23 जन० 1886); सार सुप्रानिधि, 15 मार्च, उचित वक्ता, 13 मार्च, सोम प्रकाश और समाचार चंद्रिका, 15 मार्च (वही, 20 मार्च 1886); बंगबासी, 6 नव० (वही, 13 नव० 1886); रिपोर्ट आफ दि प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 1886-7, पृ० 44-6, 54; 30 सितंबर 1886 का पूना सार्वजनिक सभा का ज्ञापन, जे० पी० एम० एस०, अक्तू० 1886, जनवरी 1887 (खंड IX स० 2-3) पृ० 6 मद्रास महाजन सभा तथा अन्य स्थानीय सार्वजनिक सभाओं के ज्ञापन रिपोर्ट आफ दि फाइनांस कमेटी 1886 खंड II पृ० 453; स्वदेशमित्र, तिथिग्रहित (आर० एन० पी० एम० फरवरी 1887); एस० एस० बय्यर, और बी० एम० बय्यर, प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक सर्विस कमीशन, 1887 खंड V भाग II पृ० 214 और 288 क्रमशः; ए० बी० पी०, 16 सित० 1886; ट्रिब्यून, 18 सितंबर और बिहार हेराल्ड, 21 सित० (बी० ओ० आई०, अक्तू० 1886); हिंदू, 25 मई 1887; आर० एन० पी० बग०, 28 जनवरी 1888 में उल्लिखित पत्र पत्रिकाएं; केसरी, 31 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 फरवरी 1888); आजाद, 3 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 7 फरवरी 1888); हिंदुस्तान, 18 अगस्त (वही, 21 अगस्त 1889); तिरंगा निशान, 5 अक्तू० (आर० एन० पी० एम०, 31 अक्तू० 1889) नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 144, 397, परिशिष्ट पृ० 32-3; रूबर ए

हिंद, 26 फर० (आर० एन० पी० पी०, 3 मार्च 1894), राय, पावर्टी, पृ० 306, 308-10, 318, एस० के नायर, रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 74; विज्ञानर नाथ, एल० सी० पी०, 1897 खंड XXXVI पृ० 185 और वही 1898 खंड XXXVII पृ० 518-9. वस्तुतः उच्च वेतनो में कटौती की मांग एक पुरानी मांग ही थी क्योंकि 1852 में सर्वप्रथम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तथा बंगाल प्रेसीडेन्सी के मूल निवासियों की एसोसिएशन के ज्ञापन में यह मांग की गई थी (बी० बी० मजूमदार; पूर्वोद्धृत, पृ० 482 पर)

- 114 डकन स्टार, 12 मित० (आर० एन० पी० वव, 18 मित० 1880). जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1881 (खंड IV स० 1), पृ० 10, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 3-7, 64, 69, 75-7, 82, मराठा, 25 फरवरी 1883 इंदु प्रकाश, 26 मार्च, 28 मई (आर० एन० पी० वव, 31 मार्च, 2 जून 1883); जे० यू० याज्ञिक, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 65; एस० ए० अय्यर, वही, पृ० 68, हिंदू, 24 जून 1885, इंडियन प्रेस ओपीनियन वा सपादकीय सार मक्षेप, बी० जी० आई०, जुलाई 1886, मराठा, 17 जून 1886, मराठा 20 जून, इंडियन मिरर, 22 जून, 3 जुलाई, बंगाली, 3 जुलाई (बी० जी० आई०, जुलाई 1886); 27 जगन्त 1886 को बावे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन द्वारा खर्चों पर प्रस्तुत ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, 30 सितंबर 1886 को पूना सार्वजनिक सभा का विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 7, 10 मद्रास महाजन सभा तथा अन्य अनेक स्थानीय मानवजीन मस्याओ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन, रिपॉर्ट आफ दि फाइनांस कमेटी 1886, खंड II पृ० 450, 452-54, 459-65, 471-84 रानाडे, 'मेमोरेण्डम आफ डिसेंट' (अस्वीकृति में ज्ञापन) वही, खंड I पृ० 395-6, 398, 403-04, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1197-9 और देखिए, तिलक, प्रोग्रेसिव आफ दि कीमन आफ दि गवर्नर आफ दि गवर्ने, 1895, खंड XXXIII पृ० 91.
- 115 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही इस मांग को उठाया और उसके पश्चात् वर्षों तक यह मांग दादराती नो रही परन्तु उसने इसके पक्ष में किसी प्रकार के आर्थिक कारण उपस्थित नहीं किए कांग्रेस के लिए दस्तावेज 1885, 1894, 1896, 1897 और 1898 के प्रस्ताव मस्या II, IV, XI (जी), IV (एफ) और XX (एफ) क्रमशः, एस० मुदालियर, रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 278, स्वदेशमित्र, 17 अगस्त (आर० एन० पी० एम० अगस्त 1885), तिरंगा निशान, 11 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, 15 जुलाई 1898); स्वदेशमित्र, 21 जुलाई (वही, 31 जुलाई 1888), स्वदेशमित्र, 6 जून (वही, 15 जून 1900)
- 116 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाषण करते हुए ने० यू० याज्ञिक ने इस तथ्य को आलोचना की कि प्रायः विभाग अध्यक्षों द्वारा खर्चों में कटौती के लिए बनाई गई योजना दिखावटी होती है अथवा उमका पालन इधर उधर किसी क्लक को नौकरों से हटाने के रूप में अथवा किसी सरकारी मस्यान के प्यासे कर्मचारियों को पानी पिलाने वाले किसी नौकर को अथवा 8-10 रु० मासिक वेतन पाने वाले किसी चारासी को नौकरों से हटाकर किया जाता है इसके पश्चात् उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि इस प्रकार की आसू पोछने वाली नीति अपनाने से निश्चित रूप से किसी प्रकार के सतोषप्रद परिणाम की आशा नहीं की जा सकती, (रिप० आई० एन० सी० 1885 पृ० 65); जलवा तर, 1 मार्च (आर० एन० पी० पी० एन०, 4 मार्च 1880); ए० बी० पी०, 21 मई 1885, सोम प्रकाश और आनंद बाजार पत्रिका, 1 जून (आर० एन० पी० वव०, 6 जून 1885), रहबरे हिंद, 1 जून (आर० एन० पी० पी०, 15 जून 1889); सजीबनी, 21 सितंबर (आर० एन० पी० वव, 28 सितंबर 1889), तिरंगा निशान, 5 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम०, 31 अक्टूबर 1889), रहबरे हिंद, 26 फरवरी (आर० एन० पी० पी०

- 3 मार्च 1894); सजीवनी, 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 27 अप्रैल 1895); बसुमती, 5 मई (वही, 14 मई 1898).
117. एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 263-4 और स्वदेशाभिमानि, 15 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, अप्रैल 1878); आई० एन० सी० के 1891, 1892, 1893, 1894, 1901 और 1902 के क्रमशः प्रस्ताव सख्या VII (सी) V (ई) III (ई) XVI (ई) VII और X; अखबारें आम, 20 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 7 सितंबर 1895); सहचर, 10 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 20 अप्रैल 1895); बंगाली, 11 अप्रैल 1896; एस० एन० बैंनर्जी, एम० ऐंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 25, जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18963, 19710, 19719-20, 19735, 19761; हिंदुस्तानी, 14 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 20 जुलाई 1898); ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 426; गोखले, स्पीचेज, पृ० 95, 1200; विक्टोरिया पेपर, 8 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 19 जुलाई 1902) और देखिए, नीरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 15
- 118 1886 में एम० एन० बैंनर्जी ने इन कारणों को बड़े ही सुंदर ढंग से ससिप्त रूप में प्रस्तुत किया है देखिए (स्पीचेज III पृ० 10-20)
119. ए० बी० पी०, 19 नवंबर 1880 इंडियन स्पेक्टेटर, 24 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब, 30 अक्तू० 1880); बंगाली, 19 मार्च 1881, 12 मार्च 1882; मराठा, 27 मार्च 1881; सोम प्रकाश, 17 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 22 जन० 1881); ठाका प्रकाश, 20 फरवरी (वही, 26 फर० 1881); बर्दवान सजीवनी, 22 मार्च (वही, 2 अप्रैल 1881); साधारणी, 13 नव० (वही, 10 नव० 1881); चारुवार्ता, 6 मार्च (वही, मार्च 1882), सोम प्रकाश, 27 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1882); बर्दवान सजीवनी, 2 मई (वही, 13 मई 1882); अल्मोडा अखबार, 7 मई (आर० एन० पी० पी० एन०, 10 मई 1883); हिंदुस्तान, 28 मार्च (वही 2, अप्रैल 1884); बंगाली, 15 मार्च और 21 जून 1884, आर० एन० पी० बग० 31 मई, 21, 28 जून, 5, 12 19 जुलाई 1884, बी० ओ० जार्ड०, 30 जून, 15, 31 जुलाई 1884, जून, छुलाई 1886, तथा आर० एन० पी० बग०, 2, 9, 16, 23, 30 जनवरी, 3, 10, 24 जुलाई 1886 में उल्लिखित पत्र-व्यवहार, शफीके हिंद 22 मई (आर० एन० पी० पी०, 31 मई 1886); गमकवारें हिंद, 26 जून (वही, 5 जुलाई 1886), बंगाली, 10 जून 1885, बी० एस० पातुलु गुरु, रिप० आई० एन० सी०, 1885 पृ० 72 बंगाली, 3 अप्रैल, 17 जुलाई 1886, मराठा, 17 अक्तूबर 1886; एस० एन० बैंनर्जी स्पीचेज III, पृ० 6, 12-4; बाबे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन द्वारा 27 अगस्त 1886 को प्रस्तुत जापन पूर्वोक्त स्थल, मेरठ एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा के स्मरण-पत्र रिपोर्ट आफ दि फाइनाम कमेटी 1886 खंड-2 पृ० 452-3; हिंदू, 2 मई 1887; बगवत्सी, 26 फर० (आर० एन० पी० बग०, 5 मार्च 1887), रास्त गुप्तार, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब; 27 अप्रैल 1887), मुलतान उल अखबार, 15 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 15 दिस० 1887); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 155, हिंदू, 22 जून 1888, 1 जून 1891, 3 फरवरी 1892, 31 जुलाई 1893 2 अप्रैल 1894, हिंदुस्तान 5 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 10 फर० 1889); समय 10 मार्च, सजीवनी, 11 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 18 मार्च 1893); चारुवार्ता, 20 मार्च सहचर, 22 मार्च (वही, 1 अप्रैल 1883), हिंदुस्तान 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बब०, 11 अप्रैल 1876), वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, 26, ए० बी० पी० 27, 28 फरवरी 1897; मराठा, 14 मार्च 1897; सजीवनी, 13 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 20 फरवरी 1897);

24 माचं के उडिया और नवसवाद (वही, 15 मई 1897); मद्रास स्टेट्स, 11 माचं (आई० एम० बी० ओ० आई०, 21 माचं 1897); ज्ञान प्रकाश, 11 माचं, सत्य मित्र, 7 माचं काठियावाड टाइम्स, 10 माचं (आर० एन० पी० बग, 13 माचं 1897); श्री सयाजी विजय, 17 माचं, इंडिपेंडेंट, 21 माचं (वही, 27 माचं 1897); आजाद, 5 माचं, हिंदुस्तानी, 3 माचं (वही, 10 माचं 1897), प्रजुमने हिंद, 3 माचं, रफी उल अखबार 5 अप्रैल (वही, 14 अप्रैल 1897), कर्णाटक प्रकाशिका, 8 माचं (आर० एन० पी० एम०, 15 माचं 1897), शाशिलेखा, 16 माचं (वही, 31 माचं 1897); स्वदेशमित्रन, 1 अप्रैल (वही, 15 अप्रैल 1897); शाशिलेखा, 30 सित० (वही, 15 अक्टू० 1898), स्वदेशमित्रन, 14 अप्रैल (वही, 30 अप्रैल 1899); हितवादी 3 माचं (आर० एन० पी० बग०, 11 माचं 1899 (वही, 30 अप्रैल 1899) हितवादी, 3 माचं (आर० एन० पी० बग०, 11 माचं 1899); आध्र प्रकाशिका, 10 माचं (आर० एन० पी० एम०, 15 माचं 1900); दत्त इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 165

- 120 बी० ओ० आई०, जुलाई 1886
- 121 बईवान सजीवनी, 17 जून, महार, 18 जून, ममय, 23 जून (आर० एन० पी० बग०, 28 जून 1884); अवध पत्र, 29 जुलाई (आर० एन० पी० पी० एन०, 4 अगस्त 1884) ट्रिब्यून, 19 जुलाई (बी० ओ० आई०, 31 जुलाई 1884), एम० एन० बैंकर्स, स्पीचेज III, पृ० 16
- 122 नौरोजी, ए०, पृ० 170, पावर्टी, पृ० 142, 210, सी० पी० ए०, पृ० 173-4, आई० एन० सी० 1885 का प्रस्ताव सभ्या \ I जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 102-05, 111-2, 131-5, कैमरी, 31 मई (आर० एन० पी० बग, 4 जून, 1898), दत्त, ई० एच० II पृ० XVII, 612.
- 123 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 55-61, 27 अगस्त 1886 का बाबें प्रेसीडेन्सी एमोमिणशन का ज्ञापन, पूर्वोक्त मदन राय, पावर्टी पृ० 311-5 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1202
124. विशेषतः देखिए, नौरोजी पावर्टी, पृ० 149, 150 और आगे उन्होंने इस नभ्य को इन रूप में प्रस्तुत किया कि कावर्तामिया टगड और भारत के बीच वित्तीय संबंध इस प्रकार के थे जिन प्रकार के मालिन और नौकर के बीच हात है (स्पीचेज, पृ० 163, 337, 342, परिशिष्ट, पृ० 78, 93 सी० पी० ए०, पृ० 168)
- 125 प्रस्ताव V अनेक अन्य भारतीय नेताओं ने दानों देशों के बीच खर्चों के समुचित विवरण की मांग का पूर्ण समर्थन किया, उद्धरणों के लिए देखिए आगे इस मांग के विस्तृत विवरण में संबंधित विवरण, उदाहरण के रूप में देखिए, आर० एम० सायानी, सी० पी० ए०, पृ० 368; आई० एम० बी० ओ० आई०, मई, जून, जुलाई में उल्लिखित पत्र-परिचाल, गोखले बाबा, नौरोजी, एम० एन० बैंकर्स, और एम० अय्यर के विलबी कमिशन के समक्ष माध्य, दत्त : फॉर्मस इन इंडिया, पृ० XX और ई० एच० II, पृ० 213.
- 126 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1204-07, बाना, पृ० 394-5, नौरोजी, स्पीचेज पृ० 343. पावर्टी, पृ० X. एस० एन० बैंकर्स, सी० पी० ए०, पृ० 253-4, 268-9, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 361-2, दत्त, स्पीचेज, II, पृ० 46; ए० बी० पी०, 4 जून 1883.
127. देखिए, पीछे
128. नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 173, स्पीचेज, पृ० 339, पावर्टी, पृ० 607; एस० एन० बैंकर्स, सी० पी० ए०, पृ० 254. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1204-05; दत्त, स्पीचेज II पृ० 47, ई० एच० II पृ० XVI, 613; बाबा, स्पीचेज, पृ० 395; आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VII.
129. एस० एन० बैंकर्स, सी० पी० ए०, पृ० 254; बाबा, स्पीचेज, पृ० 395, परिशिष्ट, पृ० 33.

130. ए० बी० पी०, 24 जून, 15 सित० 1895; आर० एन० पी० बंब, 22, 29 जून 1895 में, आर० एन० पी० बंग०, 29 जून, 6 जुलाई 1895 में, आर० एन० पी० एन०, 4 जून, 2, 9, 16, 23, 30 जुलाई 1895 में आर० एन० पी० एम०, 30 जून, 15, 31 जुलाई 1895 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएं, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 256; नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 351; राय, पावर्टी, पृ० 338
131. ए० बी० पी०, 11 जुलाई 1902; हिंदू 18 जुलाई 1902; आर० एन० पी० बंब, 26 जुलाई 23 अगस्त 1902, आर० एन० पी० एम०, 19, 26 जुलाई 1902, आर० एन० पी० एन०, 19, 26 जुलाई, 9, 16, 23 अगस्त 1902, आर० एन० पी० बंग०, 19, 26 जुलाई 1902, और आर० एन० पी० पी०, 2 अगस्त 1902 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाएं
132. हिनवादी, 30 अक्तू० (आर० एन० पी० बंग०, 7 नव० 1903); इंडियन पीपुल, 6 नव० (आर० एन० पी० यू० पी०, 7 नव० 1903); एडवोकेट, 13 दिस०, (वही, 19 दिस० 1903)
133. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 142, सी० पी० ए० 167-8, 171, स्पीचेज, पृ० 146, 151-5, 158, 162-3, 299 330-6, 380, परिशिष्ट, पृ० 78-9, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1208; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 1897, खंड XXXVI पृ० 231; जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 19800; दत्त, ई० एच० पृ० 409 ई० एच० II पृ० XVI-XVII, 60, 613 इस मंत्र्य में इन नेताओं ने अपने शामको का स्मरण कराया कि भारतीय साम्राज्य को पाने में इन्होंने अपनी ओर से तो एक पाई भी खर्च नहीं की 1857 के विद्रोह को कुचलने के खर्च को मिलाकर भारतीय साम्राज्य को विजित करने के मारे खर्च का भार भारतीय जनता ने ही उठाया है नोरोजी, पावर्टी, पृ० IX, 210, सी० पी० ए० पृ० 170, स्पीचेज, पृ० 222, 351. परिशिष्ट, पृ० 78. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1207; दत्त, ई० एच० पृ० 399, 406, 409 स्पीचेज II पृ० 46.
134. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 142, 657, सी० पी० ए०, पृ० 167-8, स्पीचेज, पृ० 146, 150, 158-9, 337-40, परिशिष्ट, पृ० 5, 23, 43-4, 75, 79, 89-90; वाचा, स्पीचेज, पृ० 400, परिशिष्ट, पृ० 33 सी० पी० ए०, पृ० 618; एस० एन० बैनर्जी, विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 19419; जी० एस० अय्यर, वही, प्रश्न 19800.
135. इंडियन स्पेक्टेटर, 25 फरवरी (आर० एन० पी० बंब, 3 मार्च 1883); एम० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 254-5; नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 340, परिशिष्ट, पृ० 79; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 33 आई० एन० सी० 1898 का प्रस्ताव XIII (बी), दत्त, ई० एच० 11 पृ० XVI-XVII, 215, 613
136. एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 256-7, एच० ए० बाबिया, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 91, सी० शकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 386 दत्त, स्पीचेज I पृ० 35; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 618-9, स्पीचेज, पृ० 400.
137. फाइनल रिपोर्ट आफ दि रायल कमीशन आन दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्सपेंडिचर आफ इंडिया (खंड IV) (हाउस आफ कामंस) 1900 खंड 29 पृ० लगभग 131.
138. 1900 का प्रस्ताव XI
139. वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 618, स्पीचेज, पृ० 398, 400-01, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 708; ई० एच० II पृ० 557, 559; बंगाली, 24 अप्रैल 1900; मराठा और कंसरे हिंदू, 6 मई (आर० एन० पी० बंब, 12 मई 1900); हिंदुस्तानी, 25 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०.

1 मई 1900); स्वदेशमित्रन, 16 अप्रैल, (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रैल 1900)

140. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 1-2.
141. वही, पृ० 154-5.
142. पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 456-7
143. प्रोसीडिंग्स, आफ कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 1895 खंड XXXIII पृ० 90-1.
144. वही, 1896, खंड XXXIV पृ० 119; और देखिए इसी अध्याय के पृ० 2 और 3.
145. वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 31.
146. प्रस्ताव III (ii) इसी प्रकार 1904 में कांग्रेस ने मांग की कि जब तक बजट की बचतों में करदानाओं को राहत देकर सरकार के अपने खर्चों को बढ़ाने के प्रलोभन की आशंका को मर्यादित किया जाए, सरकार को चाहिए कि अपने बजट की बचतों के एक भाग को जनता को लाभान्वित करने वाले, जैसे वैज्ञानिक, कृषि संबंधी तथा औद्योगिक शिक्षा, डाक्टरों राहत की मुविधाओं में वृद्धि कार्यों में खर्च करे तथा अवशिष्ट राशि को स्थानीय तथा नगर प्रशासन मंडलों को अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित सफाई सुधार तथा दूरस्थ प्रदेशों में मच्चार साधनों के विकास कार्यों को हाथ में लेने के लिए सहायता देने में खर्च करे (प्रस्ताव VIII सी)
147. गोखले, स्पीचेज, पृ० 92; और देखिए पृ० 109. लोक कल्याण के खर्चों में वृद्धि की वकालत करने वाले कुछ और नेता थे, नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 25; एम० एन० बैनर्जी, एम० ऐंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 22-5, जी० एम० अय्यर, विलबी कमिशन खंड III प्रश्न 19002.
148. वकील, पूर्वोद्धृत, पृ० 158-67, 555-6, 566.
149. आई० एन० सी० 1891, 1892, 1893 और 1894 के प्रस्ताव संख्या VIII, XII, XV और XX क्रमश, के० टी० तैलंग, मिनिट टु दि रिपोर्ट आफ दि इंडियन एजुकेशन कमिशन, 1893 पृ० 609 और रिप० आई० एन० सी०, 1888 पृ० 152, रानाडे, 'मेमोरेडम आफ डिसेट,' रिपोर्ट आफ दि फाइनांस कमेटी, 1886, खंड पृ० 411; ए० बी० पी०, 21 मई 1885, 26 जुलाई 1888; सहचर, 2 सित०, मुरभि, 8 सितंबर (आर० एन० पी० बंग० 12 सित० 1885; चारु बार्ता, 7 सित०, पताका 11 सित० (वही 19 सित० 1885); सोमप्रकाश, 28 सित० (वही, 3 अक्तू० 1885); मुरभि ओ पताका, 10 जून (वही, 19 जून 1886); 1888 के भागन सरकार के शिक्षा बिल पर बंगाल और बंबई के समाचारपत्रों में टिप्पणियां, विभिन्न पत्रों और जुलाई, अगस्त 1888 के नेटिव प्रेसों में क्रमश उद्धृत एच० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 49; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 331-5 339-55, 502-04, 508; बी० एन० सी०, रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 87-8; डब्ल्यू० सी० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 130; गोखले, स्पीचेज, पृ० 56-7, 1193
150. पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 334 एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा के अनेक विरोधी थे कहा 'भारत में प्रत्येक महाविद्यालय को बिर्बले नाग सेने की जगह मानते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि जितने कम विद्यालय हों उतना ही अच्छा है (वही, पृ० 348)
151. आई० एन० सी० 1888 का प्रस्ताव संख्या IX और आगे.
152. प्रस्ताव संख्या XII और देखिए, तैलंग, मिनिट टु दि रिपोर्ट आफ इंडियन एजुकेशन कमिशन, 1883 पृ० 614.
153. प्रस्ताव संख्या, XX 1903 के शिक्षा सुधारों पर आपत्ति करते हुए 1903 में कांग्रेस के अध्यक्ष बाल मोहन घोष ने घोषणा की : 'हम अपने देश के अपेक्षाकृत निर्धन छात्रों के मार्ग में कठिनाइयां

उत्पन्न करना नहीं चाहते हम अपने दरिद्र देश में एटन और आक्सफोर्ड के स्तर की आभिजात्य (ठाट-बाटवासी) शिक्षापद्धति का प्रस्तावन और प्रचलन नहीं चाहते' (सी०पी०ए०, पृ० 777). और देखिए—तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 600-08

- 154 प्रस्ताव सं० 11 इसी के साथ अपने तृतीय प्रस्ताव में कांग्रेस ने देश की दरिद्रता के निवारण के उपाय के रूप में शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। लाल मोहन घोष ने अपने अध्यक्ष प्राषण में जनता की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जोरदार तर्क दिए (सी०पी०ए० पृ० 777-9). और देखिए, जी० एस० अय्यर, विलबी कमिशन, खंड III प्रश्न 19685.
155. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 222, 826, 1076, 1086-7, 1090 और आगे, तैलंग, रिप० आई० एन० सी० 1888 पृ० 152, जी० एस० अय्यर, वही, पृ० 153-4, एच० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 49-50, बी० एन० सील, रिप० आई० एन० सी० 1892 पृ० 87-95; एच० सी० मित्रा वही, पृ० 95-6; एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 290-1, एस० ऐड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 22-4; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 28-9, सी० पी० ए०, पृ० 584, 619; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 295, 359-68; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 352-3, 457-8, बी० जी० तिलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1896, खंड XXXIV, पृ० 115-9, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 777-9 समाचारपत्रों के मत के लिए देखिए, इंदु प्रकाश, 26 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 31 मार्च 1883), नव-विभाकर, 1 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 6 मार्च 1886); हितवादी 24 दिस० 1898 (आर० एन० पी० बंग० 1 जन० 1899); स्वदेशमित्र, 15 सित० (आर० एन० पी० एम०, 20 सित०, 1902); केमरी, 31 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 4 अप्रैल 1903) इन सब में एक विचित्र टिप्पणी 20 सितंबर 1896 कैमरे हिंद की थी उसने यह निर्देश किया कि 1896-7 के लिए शिक्षा पर 6,319,000 रुपये बजट के खर्च का तखमीना था तथा मदिरा में वसूल होने वाला उत्पादन शुल्क 5 करोड़ रुपये था, उसने टिप्पणी की कि 'वे भारत को पियत्रकड बनाने के लिए अत्यधिक उन्मुक्त हैं, परंतु ज्ञान के प्रकाश के व्यापक प्रसार के प्रति सर्वथा उदासीन हैं उनके पास 'आबकारी शुल्क' के 1/11 भाग से अधिक खर्च करने के लिए हृदय ही नहीं है (कि हर 100 में 23 व्यक्तियों के खर्ग तक सीख मकें ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष के बाद भी देश में मध्यता का यह कैसा मुदर प्रसार है, आर० एन० पी० बंब, 26 सित० 1896) तकनीकी शिक्षा के लिए देखे अध्याय 2
- 156 रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 51.
- 157 गोखले, स्पीचेज, पृ० 192-3, 1200
- 158 प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट के अपेक्षाकृत अधिक बड़े भाग की व्यवस्था तथा बर्बई सरकार से प्रांतीय राजस्व के एक निश्चित भ्रश के शिक्षा के लिए निर्धारण करने की वकालत करते हुए गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के लाभों का विस्तृत वर्णन किया और कहा : 'शिक्षा का अर्थ है, समाज की बहुसंख्या को बुद्धिमत्ता का स्तर प्रदान करना, सुशिक्षित श्रम के प्रति अपेक्षाकृत अधिक रुचि और उत्साह उत्पन्न करना, उचित और अनुचित में विवेक की अपेक्षाकृत अधिक योग्यता उत्पन्न करना (प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे, 1901, खंड XXXIX पृ० 250-1).
- 159 गोखले, स्पीचेज, पृ० 59-62 तथा देखिए, पृ० 25-6, 43-4, 95-6.
160. वही, पृ० 61.

161. तैलंग, मिनिट टु दि रिपोर्ट आफ दि इंडियन एजुकेशन कमीशन, 1883 पृ० 609; बंगाली, 17 अप्रैल 1886; मराठा, 1 अगस्त 1886; भारतीय समाचारपत्रों के विचारों का सम्पादकीय सार-संक्षेप, बी० ओ० आई०, अगस्त 1886; इंडियन नेशन, 2 अगस्त, इंडियन मिरर, 8 अगस्त, ट्रिब्यून, 14 अगस्त, बिहार हेराल्ड, 17 अगस्त (बी० ओ० आई० अगस्त 1880); भारत मिहिर, 8 अप्रैल, नवविभाकर, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 17 अप्रैल 1886); भारत मिहिर, 15 अप्रैल, सहचर, 14 अप्रैल (वही, 24 अप्रैल 1886); साधारणी और ढाका प्रकाश, 25 अप्रैल (वही, 1 मई 1886); सुरभि ओ पताका, 12 मई (वही, 22 मई 1886); भारतवासी, 14 सित०, नवविभाकर, साधारणी, 6 सित० (वही, 11 सित० 1886); डब्ल्यू० सी० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 130, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 334, 349-51 506-08; एच० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सी० 1891, पृ० 49-50; बी० एन० भील, रिप० आई० एन० सी० 1892, पृ० 87-90; एच० सी० मित्रा, वही, पृ० 96; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 291-2; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 628
162. देखिए अध्याय III.
163. देखिए अध्याय V.
164. देखिए अध्याय X
165. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 64; नवविभाकर, 1 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 1886); पीछे पादटिप्पणी सख्या 143 और 145; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 368-76, आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VII (सी).
166. आई० एन० सी० 1886, 1887, 1888, 1892, 1894, 1901, और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः XI, II, III, XII, IV और XIII; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 457; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 154, 222; ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 447-8; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 619; एम० एम० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 717-8.
167. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 222; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 457; ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 450-2; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 619; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 719-21; विश्वभरनाथ, एल० सी० पी० 1897, खंड XXXVI पृ० 183; गोखले, स्पीचेज, पृ० 91-2, 95. इसका निर्देश पहले ही पीछे किया जा चुका है कि भारतीय नेताओं ने पुलिस व्यवस्था में योग्यता और ईमानदारी बढ़ाने के लिए निम्न वेतनभोगी पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की वकालत की
168. एल० सी० पी० 1894, खंड XXXIII पृ० 306. इसी प्रकार एक अन्य वित्त सदस्य ई० ला ने टिप्पणी की : 'आदरणीय श्री गोखले एक ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जो खजाने के द्वार पर आकर 'दो', 'दो' की रट लगाता है. परंतु वह बड़े हुए खर्च ही नहीं चाहता प्रत्युत वर्तमान चालू करों को भी समाप्त करवाना चाहता है, (एल० सी० पी०, 1904, खंड XLIII, पृ० 539; और देखिए, कर्जन, स्पीचेज II पृ० 464.
169. नौरोजी, स्पीचेज पृ० 319-20; दत्त, ई० एच० I, पृ० 308-9, 406-9, ई० एच० II, पृ० XV-XVI, 215-20, 373-5, 604. भारतीय नेताओं ने अन्य संदर्भों में भी इस ओर संकेत किया था कि भारतीय रक्त और पैसे के मूल्य पर साम्राज्य हथियाया गया था. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 567, 640, स्पीचेज, पृ० 221-2; गोखले, स्पीचेज, पृ० 120; दत्त, ई० एच० I, पृ० 399.
170. ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 427, 448.

171. गोखले, स्पीचेज, पृ० 26-8 तथा 109 कमन्स; और देखिए टी० ई० बाचा, रिप० आई० एन० सी० 1891 पृ० 25; इडिगन एडवोकेट, 18 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी० 27 अगस्त 1904).
172. बी० जी० तिलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बावे, 1895 खंड XXXIII, पृ० 91; गोखले, स्पीचेज, पृ० 61; आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव VIII; गोखले रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 169. मराठा ने अपने 29 मई 1904 के प्रकट में आय कर समाप्त करने का विरोध किया। उसने इसके बदले यह प्रस्ताव किया कि इसकी आय के लिए एक न्यास बना दिया जाए जो इस रकम को शिक्षा पर खर्च करे। इससे पूर्व अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 3 अगस्त 1900 के प्रकट में लिखा कि धरती पर लगे ऊँचे लगानों को भी यदि कृषि सुधारों, सफाई और ग्रामीण शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता, तो हम इन लगानों को उपयोगी मान लेते।
173. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 751.
174. वही. पृ० 1088.
175. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1200.
176. विलबी कमीशन, खंड III, प्रश्न 19686
177. सी० एन० वकील, पूर्वोद्धृत, अध्याय 1.
178. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1156-7; और देखिए, वही, पृ० 21, 1159-60, नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 155; 6, स्पीचेज, पृ० 300; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 203, 207, 220-1, 229-30; एस० एन० बैनर्जी, एस० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 2-3; बाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 3-4, सी० पी० ए०, पृ० 620; जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18559; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 287-90; सी० मकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 385; दत्त, ई० एच० पृ० XV, और ई० एच० II पृ० 386-7.
179. आई० एन० सी० 1889 और 1890 के प्रस्ताव क्रमशः IX और III, पी० मेहता, सी० पी० ए०, पृ० 90; नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 107-8 सी० पी० ए०, पृ० 156; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 17-20, 46, 216-7; गोखले, स्पीचेज पृ० 1158, 1160-1, एस० एन० बैनर्जी एस० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 3; जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 1894 पृ० 77; विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18559, 18765, 18769; एच० एन० दत्त, रिप० आई० एन० सी० 1897 पृ० 44.
180. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1161; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 287; दत्त, ई० एच० I पृ० XV; ई० एच० II पृ० XVIII, 360.
181. उदाहरणार्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 20वें अधिवेशन में सी० के० अय्यर ने दावा किया कि 1892 में कौंसिल में बजट पर विचार-विमर्श करने दी गई शक्ति वास्तव में कोरी बकवास और निरा धोखा था क्योंकि इस कौंसिल में किए गए भाषणों का सरकार की नीति और प्रशासन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा : 'बजट पहले से ही तैयार रहता है, उसके सभी पक्ष पूर्वनिर्धारित रहते हैं और कौंसिल के अतिरिक्त सदस्यों को केवल अपना मत प्रकट करना होता है और इसके लिए पहले से ही लिखे गए निबन्धों को पढ़ना भर होता है। (रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 181). और देखिए, नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 154-5, स्पीचेज, पृ० 245, पावर्टी, पृ० 637-8; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 236, एस० एंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 3; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 369;

गोखले, स्पीचेज, पृ० 1158, 1161; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 3; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 50

182. प्रस्ताव III.

183 सी० पी० ए०, पृ० 620.

184. पृ० 601. उन्होंने यह भी शिकायत की कि ब्रिटेन का प्रत्येक हित और ब्रिटिश जनता का प्रत्येक वर्ग भारत सरकार पर दबाव डाल सकता है परंतु भारत की जनता अपनी ही सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है (पृ० 598) तथा देखिए उनकी ई०एच० I पृ० XV, ई० एच० 2 पृ० 387, स्पीचेज I पृ० 41, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 108; 131, 222, 245, 300, 356. पावर्टी, पृ० 638-9 सी० पी० ए०, पृ० 172-3, जोशी, पूर्वाद्धृत, पृ० 220 गोखले, स्पीचेज, पृ० 8, 1156, 1158-9, 1161, 1169, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 287 आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 357

185. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 108 आई० एन० सी० 1885, 1886 और 1897 के प्रस्ताव क्रमशः III, IV और III (i) गोखले, स्पीचेज, पृ० 1162, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 5, एस० एन० बैनर्जी, एस० एंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 3, 6; जी० एस० अय्यर, बिलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 18767, 18834, 18847

186 एस० एन० बैनर्जी, एस० एंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 5-6.

187. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1164 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस माग को व्यापक सदर्थ में दोहराया, प्रस्ताव IX (ए) तथा देखिए, इंदु प्रकाश, 4 जून (आर० एन० पी० बब०, 9 जून 1883)

188 वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 34 एस० एन० बैनर्जी, एस० एंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 5-6. जी० एस० अय्यर, बिलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 18767 आई० एन० सी० 1897 का प्रस्ताव संध्या III (1) आर० सी० दत्त ने 1903 में बिना किसी निर्धारित सिद्धांत के इस माग को उठाया (ई० एच० II, पृ० 600), तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक प्रशासनिक सुधारों के सदर्थ में इस माग को उठाया (प्रस्ताव स० IX) और देखिए, दत्त, स्पीचेज I पृ० 98

189 नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 105 भारतीय नेताओं की उदीयमान पीढ़ी के प्रथम वास्तविक अखिल भारतीय सम्मेलन के महान ऐतिहासिक महत्व के प्रति सम्यक रूपेण जागरूक दादाभाई नौरोजी ने भावी राष्ट्रवादी प्रयास के लिए एक लक्ष्य निश्चित किया मैं यहाँ यह कह सकता हूँ कि भारत की इस प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रधान कार्य जनता की उच्चतम और प्रतिष्ठित आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से और माहमपूर्वक प्रकाशित करना है हमें तत्काल अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति में सफलता मिलती है अथवा नहीं यह एक दूसरी बात है परंतु हमारे शासकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारी उच्चतम आकांक्षा कौन सी है... यदि हम स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं कि हम स्थाई समिति को सामान्य नियंत्रण क्षमता प्राप्त होने के अंतर्गत इंग्लैंड से भारत को हस्तांतरित वास्तविक सरकार लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम यह चाहते हैं कि हम पर 'कराधान का अधिकार हमारी प्रतिनिधि परिषदों को होना चाहिए हमें बता देना चाहिए कि हमारा अन्ततः लक्ष्य क्या है ?' (इस पर ब० दिया गया). (वही, पृ० 109) और देखिए, वही, पृ० 222, 300 परिशिष्ट पृ० 10, 108 और आगे, बाद में 1897 में डी० ई० वाचा को लिखित पत्र, मसानी : पूर्वाद्धृत, पृ० 379 पर.

190. आर० एन० पी० यू० पी०, 23 अगस्त 1902 इंग्लैंड में ताजपोशी के अवसर पर उपस्थित

वसतिधियों पर हुए खर्चों की देनदारी भारत पर डालने की तीव्र निंदा करते हुए और इस तथ्य पर शोक प्रकट करते हुए बड़ी ही बीरता तथा साहस के साथ उन्होंने घोषित किया : 'निर्धन भारत देश एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा है भारतीयों की दशा तब तक ऐसी बनी रहेगी जब तक इस देश के संपूत अपने अधिकारों के लिए डट नहीं जाते तथा उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए उपनिवेशियों की तरह घोरता तथा साहस का परिचय न दे, अन्यथा ब्रिटिश सरकार के हाथों वित्तीय मामलों में उदारता की कौन कहे न्याय तथा औचित्य की भी आशा नहीं की जा सकती

191. उदाहरणार्थ देखिए, सहचर, 26 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 7 फरवरी 1880), सजीवनी, 9 जून (वही, 16 जून 1883), नवविभाकर 29 मार्च (वही, 3 अप्रैल 1886); मद्रास महाजन सभा का स्थापन, रिपोर्ट आफ दि फाइनांस कमिटी 1886, खंड II पृ० 453, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 7 एमिणेंट इंडियन, पृ० 29 पर डब्ल्यू० सी० बैनर्जी, मराठा, 1 अप्रैल 1894. गुजराती, 24 मार्च (आर० एन० पी० बब, 30 मार्च 1895); जनोपकारी, 16 जून (आर० एन० पी० एम०, 30 जून 1896), हिंदुस्तान, 28 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 29 दिस० 1897), दत्त, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 51 फॉर्मिस इन इंडिया, पृ० XX, ई० एच० 1 पृ० 408 और ई० एच० II पृ० XVII-XVIII, 380-1, 387, 599-601; एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III पृ० 136, 145, 159, सी० पी० ए०, पृ० 710-1, बंगाली, 22 जुलाई 1903
192. उदाहरणार्थ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1895 के कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में बड़े निष्पक्ष शब्दों में कहा कि 'बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह आधुनिक सभ्य सरकार का तात्त्विक सिद्धांत है' कांग्रेस ने सरकार से प्रशासन में इस सिद्धांत को अपनाने की बात नहीं कही है उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यह निर्देश किया कि राजनीति एक व्यावहारिक कला है, इसमें कोई सिद्धांतों की बातें करने से काम नहीं चल सकता (सी० पी० ए०, पृ० 236-7)
193. प्रस्ताव सं० III
194. प्रस्ताव सं० IV
195. प्रस्ताव सं० II, I और II और III क्रमशः
196. उदाहरणार्थ, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए मदनमोहन मालवीय ने तर्क दिया 'हम आपसे न्याय और औचित्य के नाम पर अपने बजट पर थोड़े बहुत नियंत्रण की अनुमति की प्रार्थना करते हैं' कौंसिल में लाए जाने पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस पर कुछ कहने की स्थिति में रखने के लिए हम आपसे अनुमति विनय करते हैं (स्पीचेज, पृ० 20) और देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर, 6 मार्च, इंदु प्रकाश, 7 मार्च (आर० एन० पी० बब, 12 मार्च 1881); नेटिव ओपीनियन, 15 मार्च (वही, 19 मार्च 1881), एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज III पृ० 9, 26, 34, 38; नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 109-10, सोम प्रकाश, 24 जन० (आर० एन० पी० बग०, 29 जन० 1887)
197. एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 236 और एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट 4-6, आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 369, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 3-5; जी० एस० अय्यर, विलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 18765, 18767, 18873-4; आई० एन० सी० 1897 का प्रस्ताव III (1); सी० शंकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 386, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 292-3. आई० एन० सी०, 1904 का प्रस्ताव IX.
198. एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 236-7, एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 4-5; आर०

- एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 369, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1161; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 4; सी० शंकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 386, एच० एन० दत्त, रिप० आई० एन० सी०, 1897 पृ० 44; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 293
- 199 एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 237 एम० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृष्ठ 5, जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18767, 18875; आई० एन० सी० 1904 का प्रस्ताव स० IX तथा देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 106
- 200 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1161
- 201 वही, एस० एन० बैनर्जी, एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 5, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 293-4: एच० एन० दत्त, रिप० आई० एन० सी० 1897 पृ० 44

अध्याय 13

धन की निकासी

ब्रिटिश शासन की लोकोपकारी प्रवृत्ति की चर्चा तो केवल कल्पित कहानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों का रक्त चूसना है।

अपनी सरकार के बिना भारतीय वर्तमान आर्थिक निकामी से मुक्ति नहीं पा सकते... किसी भी प्रकार के कोई भी शासक उपाय उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र में किसी प्रकार के यात्रिक हेर-फेर अथवा सुधार से न तो भारतीयों को कोई लाभ हो सकता है और न ही होगा। दादाभाई नौरोजी

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मत में भारत की दरिद्रता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में एक था— भारत से इंग्लैंड को संपत्ति की निकासी। नेताओं के एक वर्ग के अनुसार तो यह निकासी भारत के सभी आर्थिक दोषों का प्रधान आधारभूत कारण है। वस्तुतः हमारे अध्ययन काल की अवधि में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख आधार 'निकासी सिद्धांत' अथवा यह विश्वास था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग इंग्लैंड को निर्यातित किया जा रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई समुचित आर्थिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता। अथवा दूसरे शब्दों में भारत को परोक्ष रूप से ब्रिटिश राष्ट्र को खिराज देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ वर्षों के उपरांत देश में जनता के दिलों में निकामी-मिद्धात ने इतनी अधिक व्यापक लोकप्रियता और प्रभाव जमा लिया कि कितने ही ब्रिटिश प्रवक्ताओं और लेखकों को यह सिद्ध करने के लिए प्रबल प्रयास करने को बाध्य होना पड़ा कि यह सारी की सारी कल्पना आर्थिकता की दृष्टि से निराधार तथा भ्रांतिमूलक है।

निकासी सिद्धांत के सर्वमान्य प्रमुख आचार्य दादाभाई नौरोजी थे। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन-काल की सारी ही अवधि में विरल संकल्प के साथ रात-दिन इसके लिए संघर्ष किया। इस सिद्धांत की उलझनों को सुस्पष्ट करने की चेष्टा तो थोड़े से ही नेताओं ने की परंतु इसमें विश्वास रखने और इसका प्रचार करने वालों की संख्या कम नहीं थी। दादा

भाई नोरोजी ने 1867 में अपनी मान्यता को वाणी दी और उसके उपरांत यह धीरे धीरे व्यापकता और समर्थन प्राप्त करती गई। उनके ग्रंथों—‘पावर्टी ऐंड आनब्रिटिश रूल इन इंडिया’ डिग्वी के ग्रंथ—‘प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया’ और दंत के ग्रंथ—‘इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया’ के दो खंडों के प्रकाशित होने पर तो यह मान्यता प्रचार के अपने चरम शिखर पर पहुंच गई तथा उसे राष्ट्रवादियों और लोकनेताओं में व्यापक मान्यता ही मिल गई। इस ग्रंथ में हम अपने अध्ययन के अंतर्गत अवधि में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा प्रचारित तथा मान्य ‘निकासी-सिद्धांत’ के विस्तृत विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख रूप से दादा भाई नोरोजी के भाषणों और लेखों को ही निम्नवस्तु आधार बनाकर चलेंगे।

सर्वप्रथम, 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक के समक्ष पढ़े गए अपने एक लेख—‘इंग्लैंड्स डेट टु इंडिया’¹—में इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की मपदा को उम देश में छीन रहा है। भारत में बसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश में बाहर चला जाता है, तथा इंग्लैंड के संसाधनों में जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप भारत का रक्त निरंतर निबोड़ा जा रहा है।² बर्ड के दो प्रमुख समाचारपत्रों—‘नेटिव ओपीनियन’ और ‘राम्प-गोफनार’—को उन्होंने यह दिखाने के लिए उद्धृत किया कि शिक्षित भारतीयों की उदीयमान पीढ़ी उनके विचारों की समर्थक है।³ इसके साथ ही देश में व्याप्त आर्थिक दुर्दशाओं के उपचार के रूप में उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम इंग्लैंड की जनता के लिए जो करना उचित है, वह यह है कि वह भारत से छीनी गई मंपत्ति भारत को वापस लौटा दें ताकि भारत अपने संसाधनों का विकास कर सके।⁴ दादा भाई नोरोजी ने 1870 और 1872 में लंदन की कलासमिति के समक्ष क्रमशः पढ़े गए दो लेखों—‘दि वाट्स ऐंड मीन्स आफ इंडिया’⁵ तथा ‘आन दि कामर्स आफ इंडिया’⁶—में भारत से भौतिक और नैतिक धन की निकासी संबंधी अपने दृष्टिकोण को फिर से दोहराया। हा, इस सिद्धांत के साथ कालांतर में जुड़े क्रांतिकारी आशय तथा मौलिक चिंतन का इन लेखों में अभाव ही था, इस समय धन निकासी के आर्थिक परिणामों की निंदा करते समय दादा भाई नोरोजी निकासी के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच राजनैतिक संबंध के महत्व के उत्तरदायी होने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अभिस्वीकार किया कि यदि इंग्लैंड ने भारत को अपने अधीन नया रूप ही देना है तो भारत को उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए।⁷ उन्होंने इंग्लैंड को अवश्य यह परामर्श दिया कि वह भारत के साथ न्यायोचित ढंग से आर्थिक संबंधों को स्थापित करने की चेष्टा करे,⁸ तथा देश के उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करे ताकि देश दरिद्रता के अभिशाप को भोगे बिना ही ब्रिटिश-शासन के मूल्य का भुगतान कर सके तथा देश से धन की निकासी का भार उठा सके।⁹

1871 में अपने द्वारा संगणित लगभग 120 करोड़ पाउंड प्रतिवर्ष की देश से निकासी के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा—‘मैं इसे एक शिकायत के रूप में नहीं कह रहा हूँ। आपको भारत में की गई सेवाओं का प्रतिदान तो मिलना ही चाहिए, परंतु प्रश्न तो यह है कि हमारे पास भुगतान के साधन तो होने चाहिए।’¹⁰ उन्होंने घोषणा

की कि वस्तुतः यह तो इंग्लैंड का ही कर्तव्य है कि वह हमें एक ऐसी सरकार दे, अपनी शक्ति और साख के सभी लाभ-हमें दे ताकि हम बिना भूखे मरें अथवा अकाल का शिकार बने ब्रिटिश-शासन का मूल्य चुका सकें।¹¹ उन्होंने एक बार फिर देश के उत्पादन में वृद्धि के लिए बड़े परिमाण में विदेशी पूंजी के विनियोग की सिफारिश की। इस प्रकार उन्होंने 1870 में ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वह विदेशी शासन के दरिद्रता-वर्धक प्रभावों को दूर करने के लिए बड़े परिमाण में विदेशी पूंजी का आयात करे।¹² उन्होंने आशा की कि यदि समुचित परिमाण में विदेशी पूंजी का भारत देश में आयात किया गया और उसका यथोचित रूप से विनियोग भी किया गया तो शीघ्र ही वर्तमान वित्तीय कठिनाइयाँ और असंतोष दूर हो जाएंगे।¹³

1871 में 'सिलैक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनाम' को दिए अपने प्रतिवेदन में दादा भाई नौरोजी ने एक बार फिर स्वीकार किया कि धन की निकासी विदेशी शासन का ही एक प्राकृतिक आर्थिक परिणाम था।¹⁴ उन्होंने ब्रिटिश राजनेताओं से वर्ष-प्रतिवर्ष करोड़ों पाँड के भारत से इंग्लैंड को निकासी के भार को समुचित रूप में हल्का करने के तथा भारतीय लोगों की, धन की निकासी के न्यायोचित भाग के भूगतान की समुचित और आवश्यक परिमाण तक क्षमता बढ़ाने के उपायों को दृढ़ करने का अनुरोध किया।¹⁵

1873 तक जब दादा भाई नौरोजी ने 'भारत की दरिद्रता' पर अपने प्रसिद्ध लेख का प्रथम प्रारूप तैयार किया, तो उस समय तक धन की निकासी पर उनके विचार अपेक्षाकृत अधिक सुप्रसिद्ध रूप में ज्ञात संघर्षशीलता का रूप ग्रहण करने लगे थे। 1876 तक निकासी-मिद्धान ने इनके मन में सुस्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया और उसे उन्होंने उसकी समग्रता में ईस्ट इंडिया ऐसोसिएशन की ब्रिटिश शाखा के समक्ष पढ़े अपने लेख—'पावर्टी आफ इंडिया' के संशोधित प्रारूप में अभिव्यक्त किया। इस मिद्धान के दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक और राजनैतिक पक्षों के विस्तृत विश्लेषण को तो हम अगले पृष्ठों में पेश करेंगे। यहां केवल इतना ही निर्देश करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने लेख का निष्कर्ष इन जोरदार शब्दों में निकाला :

ब्रिटिश शासन की भारत के हितों की उपेक्षा करने की और भारतीयों को इंग्लैंड के हित में दास वृत्ति से परिश्रम करने वाले बनाए रखने की अस्वाभाविक नीति के फलस्वरूप साग शासन गलत, अस्वाभाविक आत्महत्या के गढ़ में घंसेता हुआ चला जा रहा है। उन्होंने इस कथन के साथ ही चेतावनी दी कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब तक प्रकृति के ये नियम अचल हैं, तब तक प्रत्येक उल्लंघन के लिए दंड का न्याय उसी प्रकार निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार दिन के पश्चात् रात के आने का क्रम निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है।¹⁶

इस समय से दादा भाई नौरोजी ने अपने निकासी-सिद्धांत के प्रचार के लिए तथा निकासी के विरुद्ध प्रचंड और प्रबल संघर्ष चलाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार में निकासी भारत में ब्रिटिश-शासन का प्रधान आधारभूत दोष था। अपने असंख्य भाषणों में ब्रिटिश समाचार-पत्रों को लिखे पत्रों में, पत्र-पत्रिकाओं में लिखे लेखों में, अधिकारियों के साथ किए गए पत्र-व्यवहार में, सरकारी आयोगों, समितियों और निजी

संवाददाताओं के समक्ष दिए गए साक्ष्यों में—वास्तव में सार्वजनिक संचार के सभी उपलब्ध साधनों द्वारा उन्होंने इस अकेले निकासी के प्रश्न पर जनता तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने तथा केंद्रित करने का प्रयत्न किया।¹⁷ इस प्रकार के उदाहरण के रूप में उन्होंने 1880 में लिखा—इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत से इंग्लैंड को हो रहे रक्त-प्रवाह को किस प्रकार रोका जाए। इस संबंध में किसी भी उपचार की उपयुक्तता और श्रेष्ठता का आधार इस दुःखदायक प्रवाह को रोकने में उसकी क्षमता की परीक्षा ही होगी।¹⁸ 1886 में भारत में ब्रिटिश शासन के अपने समीक्षात्मक लेख का सार-संक्षेप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि सारे मामले का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान रोग तथा भारतीय व्यय के अन्याय-मग्न प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के लोकोपकार की चर्चा करना केवल काल्पनिक हाथा वास्तविकता तो यह है कि ब्रिटिश-शासन खून चूसने वाला है।¹⁹ इस प्रकार वे अपने इस निकासी-सिद्धांत को कभी कभी अखंड परंतु प्रायः साधारण भाषा में प्रस्तुत करते हुए इसकी स्वीकृति के लिए लगभग आधी शताब्दी तक निरंतर प्रयत्न करते रहे। ज्यों-ज्यों वर्ष बीतते गए त्यों-त्यों उनकी उन्नतता और शोध बढ़ता गया। भारत की जनता और भारत की संपदा के जीवनरक्त की इंग्लैंड को निक्काली जाने के लिए उनके अपने मन में उत्तरदायी ब्रिटिश नीति के लिए उन्होंने अनुचित, निरंकुश, डाकाजनी वाली, अस्वाभाविक, विध्वंसक विशेषणों का प्रयोग किया।

दादा भाई नौरोजी के लगभग साठ-ही साठ से अन्य भारतीय नेताओं ने भी निकासी की चुगई को समझा। जस्टिस रागाडे ने 1872 में पुना में भारतीय व्यापार और उद्योग पर एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने भारत में ब्रिटेन को भारत की मृत्ती और साधनों की निकासी की आलोचना की तथा यह टिप्पणी की कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय का निम्नलिखित अधिक भाग किसी न किसी रूप में ब्रिटिश द्वारा छीन लिया जाता है।²⁰ बाद में 1892 में 'भारतीय राजनैतिक आर्थिकता' पर दिए गए अपने पथ-प्रदर्शक भाषण में रागाडे ने टिप्पणी की कि उत्तराधिकार में पाए गए परंपरागत जिन दुर्वृत्तताओं ने आर्थिक विकास पर घातक प्रभाव डाला है, उन सब को विदेशी शक्ति द्वारा की जा रही भारत की संपत्ति और प्रतिभा की निकासी से माय ही सबट्र करना चाहिए।²¹ भोलानाथ चंद्र दूसरे भारतीय लेखक थे, जिन्होंने 1893 में प्रतिवर्ष और अधिक चौड़ी होती जा रही निकासी की खाई का विस्तृत विवेचन किया। उनके विचार में निकासी का प्रारंभ उस समय हुआ—जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजस्व के कुछ भाग को अपने व्यापारिक निवेश के लिए एक तरफ अलग रख दिया था परन्तु अब तो स्थिति पूर्वापेक्षा बदतर ही हो गई है। उस समय धन एक स्रोत में गड़कर जाता था परन्तु अब हजारों द्वारों से बहकर जाता है।²²

निकासी-सिद्धांत पर बल देने वाले तथा अपने लेखों और सार्वजनिक गतिविधियों के माध्यम से उसका प्रचार करने वाले दूसरे प्रमुख और महत्वपूर्ण भारतीय नेता आर० सी० दत्त थे। यद्यपि वे इस खेमे में देर से दीक्षित हुए तथापि उन्होंने लोकोक्ति के रूप में प्रचलित नवीन धर्मानुयायी का-सा उल्हास दिखाकर विलंब की क्षति पूर्ति कर दी। 27 फरवरी 1901 को इंग्लैंड में नेशनल लिबरल फंडेशन के सम्मेलन में दिए गए अपने

भाषण में उन्होंने घोषणा की कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी अन्य देश में दूढ़ने से भी नहीं मिलता। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि इंग्लैंड को प्रतिवर्ष स्वयं अपने राजस्व का आधा भाग खर्च करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अथवा रूस को भेजना पड़ता तो इंग्लैंड में वर्षों पूर्व अकाल पड़ गया होता।¹³

अपने ग्रंथ—‘इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया’ के प्रथम खंड की भूमिका में उन्होंने निर्णयात्मक स्वर में लिखा—शुद्ध राजस्वों का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उन्होंने शोक विह्वल होकर कहा—मचमुच ही भारत का उपजाऊपन, दूसरे देशों की ही संपन्न और भाग्यशाली बना रहा है।¹⁴ पुस्तक के परवर्ती भाग में उन्होंने निकासी के माथे निम्नलिखित पाप को मढ़ते हुए लिखा—‘देश के साधनों की सीमा से बढ़कर इतनी बड़ी आर्थिक निकासी विश्व के किसी समृद्धतम देश को दरिद्र बना सकती है। इसने भारत को विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व रूप में निरंतर और व्यापक रूप से पड़ने वाले घातक अकालों का देश बना दिया है।’¹⁵ इसी प्रकार ग्रंथ के दूसरे खंड की भूमिका में उन्होंने इंग्लैंड की आलोचना करते हुए लिखा कि इंग्लैंड जैसा विश्व का समृद्धतम देश विश्व के दरिद्रतम देश-भारत से वार्षिक योगदान को वसूलने की नीचता पर उतर आया है। उन्होंने जोर देकर दृढ़ स्वर में कहा कि इस योगदान के लिए भारतीयों को निरंतर अबाध रूप से अपने जीवन-रक्त का निर्यात करना पड़ता है।¹⁶

जी० वी० जोशो, पी० सी० राय, मदन मोहन मालवीय, डी० ई० वाचा, जी० के० मोखले, मी० मुत्रहृण्य ऐयर और और सुरेंद्रनाथ बेंनर्जी सहित अन्य बहुत सारे भारतीय नेता भी निकासी के प्रश्न में सर्वविध आंदोलन में सम्मिलित हो गए।¹⁷

राष्ट्रवादी ममाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका निकासी-सिद्धांत का प्रबलनम समर्थक था। 28 जुलाई 1870 में ही इस पत्रिका ने निकासी को भारत की दरिद्रता का कारण घोषित किया और कालांतर में वर्षों तक अपने इस सुदृढ़ मत को दोहराया। उदाहरणार्थ 14 अगस्त 1881 के अंक में इस पत्रिका ने शिकायत की कि भारत अनेक विभिन्न ढंगों में तथा अनेक दलों द्वारा इस प्रकार चूसा जा रहा है कि वे स्वयं अपने आप भी एक दूसरे की गतिविधियों और कार्यवाहियों में परिचित नहीं। वे यह भी नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणामस्वरूप उनका रोगी किस अत्यंत विषम तथा शोचनीय दशा में पहुंच गया है। 2 मार्च 1896 के अंक में इस पत्रिका ने अपने कथन को इस प्रकार दोहराया—इस लगातार निकासी के फलस्वरूप भारत दरिद्रता का शिकार हो गया है और इंग्लैंड संपन्न देश बन गया है। यह व्यवस्था भारत को संपत्ति की स्थिति में और भारतीयों को पशुओं की स्थिति में लाकर उनका अवमूल्यन करती है।¹⁸ अधिकांश अन्य प्रमुख भारतीय पत्रों ने भी नियमित रूप से इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए तथा भारत से संपत्ति की निकासी की निंदा की।¹⁹

कितने ही वर्षों तक सोच विचार करने के उपरांत अथवा कदाचित् संकोच के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में कलकत्ता में हुए अपने अधिवेशन में औपचारिक रूप से निकासी-सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि वर्षों से निरंतर

देश से संपत्ति की हो रही निकासी देश में अकालों के लिए और देशवासियों की निर्धनता के लिए उत्तदायी है।³⁰ परवर्ती वर्षों में कांग्रेस ने इस आरोप को अनेक बार फिर दृढ़तापूर्वक दहराया।³¹

भारतीय नेताओं ने निकासी क्लेश अतीत में भारत के शासकों और ब्रिटिश शासकों के बीच अंतर का आधार मना।³² अतीत के शासकों ने देश से थोड़ी सी संपत्ति की निकासी की। मुगल और मराठा शासकों ने अपनी प्रजा को भले ही लूटा हो, परन्तु देश की संपत्ति देश के भीतर ही बनी रही और देश के भीतर ही खर्च की गई। इससे निजी तौर पर कुछ नागरिका को कष्ट अवश्य पहुंचा होगा, उन लोगों के दबाव अवश्य अनुभव किया होगा और वे अपनी संपत्ति से वंचित भी अवश्य हुए होंगे परन्तु कुल मिलाकर देश को कोई हानि नहीं हुई। देश के एक व्यक्ति को पहुंची हानि दूसरे के लिए लाभ बन गई। दूसरी ओर ब्रिटिश देश की पूँजी को देश से ही बाहर ले गया और उसे देश के बाहर ही उसने खर्च किया।³³ इसी प्रकार पुराने शासकों के अंतर्गत कराधान का भार कितना भी भारी क्यों न रहा हो परन्तु उसके आर्थिक समघात देश की जानता के लिए इतने अधिक हानिप्रद नहीं थे, जितने कि ब्रिटिश-शासन के अंतर्गत अपेक्षाकृत नीचे कराधान के आर्थिक समघात दानिकाग्रक है। इसका कारण ब्रिटिश राज्य में राजस्व के बड़े भाग की निकासी है।³⁴ यहां तक कि जब नादिरशाह जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण किया, इस देश को लूटा और उसके तत्काल उपरांत वापस चले गए। तब भी देश को होने वाली आर्थिक हानि अस्थायी थी। ऐसे झटके निरंतर बार बार नहीं लगते थे। ये झटके अनियमित थे परन्तु ब्रिटिश शासन के मामले में निकासी सरकार की चालू व्यवस्था का ही एक अंग थी। अतः वह अबाध और निरंतर चलने वाली थी प्रत्येक वर्ष बढ़ने वाली भी थी। इस प्रकार से घाव सदा ही हरे बने रहते थे और निकासी एक रिसते नासूर की तरह थी।³⁵

निकासी की संगणना

जैसा कि हम पहले निर्देश कर चुके हैं राष्ट्रवादियों के अनुसार निकासी की मूल रूपरेखा थी भारत से इंग्लैंड को भारत की संपदा और उपभोग सामग्री का वह निर्यात, जिसके समन्वय रूप भारत को किसी प्रकार के आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक, प्रतिदान नहीं मिलते थे। इस प्रकार भारतीयों की परिभाषा के अंतर्गत निकासी अनिवार्य रूप से ही आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता थी अथवा निर्यातों का एकतरफा होना था।³⁶ वस्तुतः इस अधिकता से एक साथ ही निकासी का अस्तित्व, संपत्ति के प्रेषण का रूप तथा उसके परिमाण अथवा मात्रा के साधन आदि सिद्ध होते थे। निकासी को परिभाषित करने के पीछे भारतीय नेताओं की यह भावना थी कि इससे उनके लिए निकासी की आर्थिक रूप से दुर्जय तथा विचित्र रूप से सरल संगणना करने की व्यवस्था सुलभ हो जाती है, क्योंकि निर्यातों और आयातों के अंतर को दृष्टिगोचर करते ही निकासी की राशि सहज उपलब्ध हो जाती थी।³⁷ दादा भाई नौरोजी अवश्य एक पग और आगे बढ़ गए और उन्होंने आयातों पर निर्यातों की अधिकता के अतिरिक्त अपने विचारानुसार निर्यातों पर लाभ

के रूप में भारत को दी जाने वाली परंतु न दी गई एक अन्य विपुल राशि को लिया और इसमें निकासी का अपेक्षाकृत अधिक सही अनुमान लगाया।⁸⁷ उनके इस दृष्टिकोण के दो आधार थे। प्रथम, उनका अनुमान था कि ब्रिटेन और कई दूसरे देशों में निर्यातों पर आयातों की अधिकता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि पूँजी के सौदों तथा भारत से धन की निकासी पर होने वाले व्ययों को पृथक् कर देने पर भी निर्यातों से लाभ होता था।⁸⁸ यह तर्क वस्तुतः सर्वथा कोरी कल्पना ही था। इसका अर्थ यह हुआ कि आयातों और निर्यातों के मूल्यों के अंतर द्वारा निर्दिष्ट राशि की अपेक्षा वास्तव में ही निकासी की राशि अपने परिमाण में बहुत अधिक है। इस तर्क की प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से दादा भाई की इस धारणा पर आश्रित है कि भारतीय निर्यातों का निर्यात-पत्तन पर घोषित मूल्य लागत मूल्य रहता था न कि बिक्रेता के लाभ के साथ बिक्री का मूल्य रहता था तथा भारतीय आयातों में ब्रिटिश निर्यातकार के लाभ पहले ही सम्मिलित रहते थे।⁸⁹ अस्तु, निकासी की राशि के इस विकृत अनुमान का किसी भी मामले में बहुत सारे अन्य नताओं ने कोई उल्लेख नहीं किया। निकासी के विषय से संबंधित बहुतों ने तो व्यापार के निर्यात—संतुलन की सीधी सादी संगणनाओं तक ही अपने को सीमित रखा। यहाँ तक कि स्वयं दादा भाई नौरोजी भी भारत के विन्नीय न्याय के मामले को पेश करते हुए कभी कभी निर्यातों पर होने वाले लाभों की गणना को छोड़ने के लिए सहमत हो जाते थे।⁹⁰

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने निकामी की सही राशि की संगणना की चेष्टा की। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संगणना की विभिन्न विधियाँ अपनाए जाने के कारण प्रति व्यक्ति तथा प्रतिवर्ष आयातों और निर्यातों की खाई निरंतर चौड़ी होती जाने में प्रतिवर्ष निकासी संबंधी आंकड़े भिन्न भिन्न रूप में ही सामने आने लगे। उदीयमान राष्ट्रीय नेता वर्ग ने इन आंकड़ों को अपने हाथ में लिया तथा जन-संपर्क के प्रत्येक उपलब्ध माध्यम के द्वारा देश के कोने कोने में इनका प्रचार-प्रसार करते हुए इन्हें लोकप्रिय बनाया। जब जनता के सामने देश की संपत्ति की निकासी के सुस्पष्ट आंकड़े आए तो स्पष्टतः जनता के मन में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता ने प्रबलता तथा विश्वसनीयता का रूप ले लिया। अतः इस संबंध में कुछ-एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जो अर्थ-शास्त्री भी थे की गई संगणनाओं का अध्ययन रोचक ही होगा।⁹¹

दादा भाई की निकासी संबंधी संगणनाएं अत्यधिक जटिल थीं। इसका कारण यह था कि सभी प्रकार की संभव आपत्तियों का सामना करने के लिए तथा आलोचकों को संतुष्ट करने के लिए वे अपनी संगणना के आधारों को ही निरंतर बदलते रहे। 1867 में उनके द्वारा निकासी की संगणित राशि 80 लाख पौंड थी।⁹² 1870 में उनके आंकड़े बढ़ कर 1 करोड़ बीस लाख पौंड हो गए।⁹³ 1876 में प्रकाशित 'पावर्टी आफ इंडिया' में उन्होंने घोषणा की कि रेल पथों के व्याज को निकाल कर 1835 से लेकर निकामी की औसतन वार्षिक राशि इस प्रकार से थी⁹⁴ :

वर्ष	वार्षिक घाट (पौंड में)
1835-1839	5,347,000
1840-1844	5,930,000
1845-1849	7,760,000
1850-1854	7,458,000
1855-1859	7,730,000
1860-1864	17,300,000
1865-1869	24,600,000
1870-1872	27,400,000

1893 में उन्होंने गिनती की कि निकासी की राशि 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष में अधिक बैठती है।¹⁴ 1897 में उनके आकड़े 1883-92 की अवधि में लगभग 359 करोड़ रुपये थे, परंतु सरकारी ऋण पर वसूल किए जाने वाली रकम को निकासी न मानने के समर्थकों को सतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रभारों की राशि को निरामी की सीमा में अलग कर दिया और फिर भी देखा कि इन दस वर्षों में निकासी की राशि लगभग 288 करोड़ थी, जिसमें अनुमानतः 118 करोड़ रुपये की राशि विदेश व्यापार के लाभों से अर्जित आय थी। दादा भाई द्वारा सगणित अल्पतम राशि थी 241 करोड़ रुपये अथवा 24 करोड़ रुपये की वार्षिक निकासी।¹⁵ अतः 1905 में उन्होंने घोषणा की कि लगभग 3 करोड़ 40 लाख पौंड का अथवा 51.5 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान की प्रति वर्ष देश से निकासी हो रही है।¹⁶

जी० बी० जोशी के अनुसार 1834-1888 तक लगभग 66 करोड़ पौंड की देश से निकासी हो चुकी थी। उन्होंने यह भी निर्देश किया कि यह निकासी प्रति वर्ष बढ़ रही है और 1888 तक कुल 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है।¹⁴ 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महापति पद से भाषण करते हुए डी० ई० वाचा ने निरामी की राशि 30 से 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बताई।¹⁵ कांग्रेस के अगले ही अधिवेशन में एस० एन० बैनर्जी ने 19वीं शताब्दी के पिछले तीस वर्षों में निकासी की औसत राशि 3 करोड़ पौंड संगणित की।¹⁶ आर० सी० दत्त का अनुमान कम था। उनके अनुसार बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में निकासी की राशि लगभग 2 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष थी।¹⁷ पृथ्वीचंद्र राय द्वारा 1901 में सगणित निकासी की अत्यधिक राशि 6 से 7 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष थी।¹⁸

अपनी मान्यता के अनुसार लोगों को यह समझाने के लिए कि निकासी की राशि सचमुच ही परिणाम में विपुल है, बहुत सारे भारतीय नेताओं ने सरकारी राजस्व के अनुपात के संगणन की पद्धति को अपनाया। इस प्रकार उदाहरण के रूप में आर० सी० दत्त ने बार बार इस ओर निर्देश किया कि भारत के कुल राजस्व का लगभग आधा भाग विदेशों को निष्कासित हो जाता है।¹⁹ असल में, जैसा कि हम इस ग्रंथ के एक अध्याय में पहले ही दिखा चुके हैं कि भारत सरकार की वित्त नीति की राष्ट्रवादियों द्वारा की गई

महत्वपूर्ण आलोचना यही थी कि देश में वसूल किए गए राजस्व के एक विपुल भाग का देश के बाहर व्यय किया जा रहा है।⁵⁴

निकासी का उद्भव

भारतीय नेताओं के अनुसार व्यापार सतुलन में अधिशेष निकासी का रूप लेता था। परंतु कौन से तत्व निकासी को जन्म देने के आधारभूत कारण थे? यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1858 के उपरांत ही निकासी के विश्लेषण के समय यह प्रश्न प्रमुख रूप से उपस्थित हुआ। यद्यपि कंपनी के शासन काल में विशेषतया 1833 से पहले की अवधि में हुई संपत्ति की निकासी की राशि की तो प्रायः संगणना की गई और उसकी निंदा भी की गई तथापि इन नेताओं ने इन वर्षों की मध्यावधि में हुई निकासी के विश्लेषण की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया।⁵⁵ इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी दो कारण थे :—प्रथम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश, इसके भागीदारों को लाभों का भुगतान, इसके सरकारी ऋण तथा खुली लूट की प्रक्रिया के माध्यम से इसके अधिकारियों द्वारा निजी संपत्ति का संचय आदि भारत से शुल्क वसूलने अथवा संपत्ति लौटाने के अत्यंत स्पष्ट और महत्वपूर्ण तत्व थे। इन शुल्कों के परिमाण और इनकी आर्थिक महत्ता पर भले ही मतभेद हो, परंतु इनकी सत्ता निर्विवाद थी। द्वितीय, भारतीय नेता अगणित उच्च सरकारी और गैरसरकारी अंगरेजों के अधिकृत वक्तव्यों को उद्धृत करने और उनकी विस्तृत परीक्षा करने के चक्कर में बिना पढ़े ही निकासी के तथ्य को सिद्ध कर सकते थे।⁵⁶ वस्तुतः निकासी और उसके दुष्परिणामों के संबंध में भारत से सहानुभूति रखने वाले अंगरेजों की सख्या इतनी बढ़ी थी कि आर० सी० दत्त महोदय को आश्चर्यचकित होकर यह कहना पड़ा—‘कोई एक निंदक यह टिप्पणी कर सकता है कि भारत की ओर से तो इंग्लैंड को संपत्ति प्रवाहित होती है और वहाँ के लोग भारतीयों को कोरी सहानुभूति और स्वार्थ के रूप में बदला चुकाते हैं।’⁵⁷ इसके अतिरिक्त भारतीयों को भूतकाल की इतनी अधिक चिंता नहीं थी, जितनी कि भविष्य की। भविष्य के सुरक्षित हो जाने पर तो वे भूत को भूलने तक के लिए सहमत थे।⁵⁸

1858 के पश्चात् अथवा यहाँ तक कि 1833 के पश्चात् निकासी का प्रश्न जटिल और विवादास्पद बन गया था क्योंकि न तो भारत द्वारा उस समय इंग्लैंड को किसी प्रकार का शुल्क दिया जा रहा था और न ही भारत के अधिशेष राजस्व को इंग्लैंड के कोष में डाला जा रहा था। अतः निकासी के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के लिए यह दिखाना आवश्यक हो गया कि किस प्रकार भारत ब्रिटेन के पृथक् पृथक् नागरिकों के भुगतानों के रूप में तथा वह भी विभिन्न मार्गों से ब्रिटेन को ‘परोक्ष’ शुल्क चुका रहा था।⁵⁹ उन्हें यह भी सिद्ध करना पड़ा कि इस परोक्ष निकासी का कारण पूर्णतया भारत पर ब्रिटेन का राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व था।

भारतीय नेताओं के अनुसार निकासी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व असेनिक सेवा में, सेना में तथा रेलवे में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों, अंग्रेज वकीलों तथा अंग्रेज डाक्टरों आदि द्वारा अपनी बचतों, आय और वेतन के एक बहुत बड़े भाग का इंग्लैंड में भेजना

था तथा भारत सरकार द्वारा अंग्रेज सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों तथा अवकाश-कालीन भत्तों का इंग्लैंड में ही भुगतान करना था। दूसरे शब्दों में आंशिक रूप से भारतीय प्रशासन में, सेना में तथा रेलवे में यूरोपियों की असामान्य नियुक्ति का ही परिणाम निकासी था।⁶⁰ इस संदर्भ में यहां यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी तो दादा भाई नौरोजी ने निकासी के उद्गम के संबंध में बड़ा ही संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने विशेषतया विवादों में संलग्न होने पर निकासी के सारे ही रोग का दायित्व भारतीय प्रशासन में अंग्रेजों की अत्यधिक नियुक्ति पर डाला।⁶¹ कभी कभी तो उनकी यह संकीर्ण मनोवृत्ति मूर्खता की सीमा पर पहुंच जाती थी। उदाहरण के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि भारत की जनता की इस विषम दरिद्रता और चरम दीनता का एकमात्र कारण देश की सरकार में विदेशी कर्मचारियों की असामान्य नियुक्ति है। इसी के फलस्वरूप देश को भौतिक हानि हो रही है और देश की संपत्ति की निकासी हो रही है। उन्होंने उस समय चेतावनी देते हुए कहा—देश के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ‘‘आप केवल इसी एक बुराई को हटा दीजिए, भारत प्रत्येक रूप में सौभाग्यशाली बन जाएगा।’’⁶² ‘‘दादा भाई नौरोजी द्वारा इस संकुचित दृष्टिकोण को अपनाने का परिणाम यह निकला कि उनके निदकों को निकासी-सिद्धांत के खोखलेपन को सिद्ध करने के लिए केवल उनके वक्तव्य को ही विवेकशून्य प्रमाणित करने की आवश्यकता रह गई। कदाचित् इससे भी अधिक दुर्भाग्यजनक बात यह है कि दादा भाई के इस हास्यप्रद विश्लेषण ने बहुत सारे विचारकों को निकामी पर स्वयं उनके तथा अन्य राष्ट्रवादियों के विचारों की वास्तविक गहराई व जटिलता को समझने में पथभ्रष्ट ही किया। दादा भाई नौरोजी के निकासी पर तर्क के इस अंधकारपूर्ण पक्ष की व्याख्या किसी सीमा तक निम्नलिखित तीन पहलुओं से की जा सकती है : (1) दादा भाई नौरोजी स्वभाव से उग्रवादी थे। (2) 1870 तक सरकारी विदेशी पूजी विपुल परिमाण में नहीं थी और उससे काफी समय बाद तक निजी विदेशी पूजी की मात्रा भी उल्लेखनीय नहीं थी। उस समय भारतीयों के विश्लेषण के अनुसार यूरोपियों की नियुक्ति निश्चित रूप से ही निकासी का सर्वाधिक विस्तृत स्रोत थी। (3) 1860 की अवधि तक दादा भाई नौरोजी विदेशी पूजी के विरुद्ध नहीं थे⁶³ और यहां तक कि उन्होंने तथा अन्य भारतीय नेताओं ने इसके बाद भी कई वर्षों तक विदेशी पूजी के प्रयोग का अत्यंत सुदृढ़ता तथा प्रबलता के साथ विरोध नहीं किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि बाद में जब विदेशी पूजी भारत से संपत्ति की इंग्लैंड को निकासी का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई तो दादा भाई नौरोजी ने निकासी के इस स्रोत के विरुद्ध ऊंचे स्वर में उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया।⁶⁴

भारतीय नेताओं के अनुसार भारत से धन की निकासी का एक अन्य प्रधान और आधारभूत स्रोत भारत सरकार के गृह प्रभार अथवा भारत सरकार की ओर से भारत सचिव द्वारा इंग्लैंड में किया गया खर्च था। गृह प्रभारों के अंतर्गत भारत के सरकारी ऋणों और प्रतिभूत रेख पथों के व्याज का भुगतान भारत को संभरित सैन्य तथा अन्यान्य संसारों का मूल्य, भारत सचिवालय में भारत सचिव के कर्मचारियों पर होने

वाले खर्चों तथा भारत सरकार के यूरोपीय कर्मचारियों को पेंशनों और भत्तों को मिलाकर भारत के खाते में इंग्लैंड में भुगतान किए गए सैनिक व असैनिक व्यय आदि सम्मिलित थे।⁶⁵ गृह प्रभागों के इनमें से प्रत्येक अंग का कभी कभी भारतीय नेताओं ने पृथक्-पृथक् विवेचन किया तथा निकासी के स्रोत के रूप में इसकी निंदा की।⁶⁶

भारतीय नेताओं के अनुसार निकासी का तीसरा प्रमुख स्रोत भारत में व्यापार और उद्योग में निवेशित निजी विदेशी पूँजी पर होने वाले लाभ थे।⁶⁷

निकासी के आर्थिक प्रभाव

जैसा कि हम पूर्व निर्देश कर चुके हैं तथा जैसा कि आधुनिक इतिहास के छात्रों को सम्यक् रूप में ज्ञात है, निकासी के साथ जुड़ा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम देश की घोर दरिद्रता थी। हा, प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के इस सबंध में दृष्टिकोण थोड़ा-बहुत भिन्न रूप अवश्य लिए हुए थे। उदाहरणार्थ, दादा भाई नौरोजी ने निकामी को देश के सभी रोगों, दुखों और दरिद्रता का वास्तविक, प्रधान और यहाँ तक कि एक मात्र मूल कारण घोषित किया, तथा अन्यान्य कारणों को केवल भ्रामक बताया।⁶⁸ उन्होंने 1880 में बड़ी प्रबलता के साथ तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा :—

यह आर्थिक नियमों की क्रूर प्रक्रिया नहीं है प्रत्युत यह तो ब्रिटिश नीति की विवेक-शून्य और क्रूर कार्यवाही है। यह भारत की धन-संपत्ति को ही भारत में हड़पने का क्रूर कृत्य है और इसमें भी बढ़कर देश से इंग्लैंड को संपत्ति की क्रूर निकासी है। संक्षेपतः यह भारत का रक्त चूसने के रूप में दुखद ढंग से आर्थिक नियमों को विकृत करना और इसके फलस्वरूप भारत को विनष्ट करने का निर्मम प्रयास है।⁶⁹

इस संबंध में दादा भाई के दृष्टिकोण को अपनाने वाले केवल थोड़े से ही और राष्ट्रवादी नेता थे। इन थोड़े से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे—अमृत बाज़ार पत्रिका के संपादक-गण।⁷⁰ इन नेताओं में अधिकांश ने तो इस धारणा से कि भारतीय जनता को दरिद्र बनाने में निकामी की महत्वपूर्ण ही नहीं कदाचित् सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, सहमति के रूप में अपने विचार प्रकट करके ही संतोष कर लिया।⁷¹ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी निकासी को केवल भारत की दरिद्रता के कारणों में से एक बताया।⁷² यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने निकासी के सापेक्षिक महत्व के प्रश्न पर तथा दरिद्रता के लिए उत्तरदायी अन्यान्य विविध पक्षों पर विचार ही नहीं किया। जब उन्होंने निकासी पर विचार-विमर्श किया तो उन्होंने इसकी प्रबलता से निंदा की और जब उन्होंने अपने विश्वासानुसार भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी किसी दूसरे पक्ष पर विचार-विमर्श किया तो उन्होंने पहले जैसी ही प्रबलता से उसकी निंदा की।

लोगों को कदाचित् यह सम्यक् रूप से ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रवादी नेताओं की निकासी को देश को दरिद्र बनाने वाली मानने की अवस्था उसे देश के लिए आर्थिक दृष्टि से विध्वंसक तथा दुर्भाग्यजनक कारण मानने की धारणा के पीछे कौन-सा आर्थिक तर्क काम कर रहा था। इस दृष्टि से इस संबंध में ध्यान देने योग्य तत्त्व यह है कि भारतीय

नेताओं ने निकासी को केवल संपत्ति की हानि के रूप में ही नहीं लिया प्रत्युत उसे पूँजी की हानि भी माना। उनके द्वारा प्रतिपादित निकासी-सिद्धांत केवल धन के अथवा सामग्री के निर्यात के संकुचित विचार क्षेत्र तक सीमित नहीं था प्रत्युत वह व्यापक आर्थिक कारणों तथा विचारों पर ही आधारित था।

संपत्ति की प्रत्यक्ष हानि की अथवा राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग के स्थूल रूप से स्थानान्तरण होने की अथवा लोगों की आजीविका के साधनों में वास्तविक कमी होने की धारणा तो निकासी की परिभाषा में निहित थी। राष्ट्रवादी नेताओं में बहुत सारे अर्थ-शास्त्रियों ने व्यापक रूप में निकासी के रूप और अर्थ को जिस प्रकार समझा तथा स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में जिस प्रकार उसका प्रचार-प्रसार किया, वह यह था कि इस निकासी का देश की अर्थव्यवस्था पर भले ही अन्य कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो फिर भी इससे राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली कटौती ही अपने आप में इतना विशाल दोष है कि इसे एक भारी रोग कहा जा सकता है।⁷³

कुछ एक भारतीय नेता इस तथ्य को भी समझने में सफल हो गए कि विदेशों में राष्ट्रीय अर्थ के स्थानान्तरण में देश की आय पर और देश के भीतर रोजगार पर उसका घातक प्रभाव ही पड़ता है। उन्होंने इस तथ्य की ओर निर्देश किया कि निकासी का अर्थ राष्ट्रीय आय के कुछ निश्चित भाग का देश के बाहर विदेशों में खर्च करना मात्र ही नहीं प्रत्युत देश के भीतर ही उसके खर्च किए जाने पर उसमें आय और रोजगार में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि में कमी है। इस प्रकार 1903 में आर० सी० दत्त ने टिप्पणी की कि :

जब दश में उगाहे करो को देश में ही खर्च किया जाता है तो धन देश की जनता में परिचालित होता है, व्यापारों, उद्योगों और कृषि को परिपुष्ट करता है तथा किसी एक न एक रूप में सर्वसाधारण के पास पहुंच जाता है परंतु जब देश में वसूल किए गए करो को देश के बाहर प्रेषित कर दिया जाता है तो देश का वह धन देश के लिए सदा के लिए ही नष्ट हो जाता है। वह न तो देश के व्यापारों अथवा उद्योगों को संपन्न बनाता है और न ही किसी रूप में देश के जनसाधारण के हाथ में पहुंचता है।⁷⁴

आर० सी० दत्त सहित कुछ एक भारतीय नेताओं ने जार्ज बिगेट की निम्नलिखित सुप्रसिद्ध टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए देश के करो के देश के बाहर विदेशों में खर्च किए जाने पर उसके देश की आर्थिकता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित तथ्य को सिद्ध किया :

किसी देश से वसूल किए गए करो को उसी देश में खर्च करने तथा एक देश से वसूल किए गए करो को दूसरे देश में खर्च करने में प्रभाव की दृष्टि से एक महान अंतर है। प्रथम स्थिति में जनता में वसूल किए गए करो का विशाल भाग सरकारी सेवा में लगे लोगों को ही वापस मिल जाता है। उन लोगों द्वारा पाया गया धन खर्च किए जाने पर फिर श्रमिक वर्गों के पास पहुंच जाता है। परंतु वह स्थिति सर्वथा और पूर्णतया भिन्न होती है जबकि किसी देश से उगाहे करो को उस देश में नहीं

खर्चा जाता। इस स्थिति में उस देश को भारी और वास्तविक हानि होती है और करारोपित देश से निकाला गया धन पूर्णतया नष्ट हो जाता है। जहाँ तक राष्ट्रीय उत्पाद पर इसके प्रभावों का संबंध है, सारे का सारा धन समुद्र में फेंका गया ही सम्भूतना चाहिए।⁷⁶

इस तथ्य के आधार पर भी भारतीय नेताओं ने भारत के पुराने स्वेच्छाचारी शासकों और ब्रिटिश शासकों के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इस प्रकार 1902 में सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी ने टिप्पणी करते हुए लिखा, पुराने विजेताओं ने विजित देश को शीघ्र ही अपना देश बना लिया था तथा देश की जनता से छीनी गई संपत्ति शीघ्र देश के लोगों के पास लौट आई थी। इस प्रकार उन्होंने गृह उद्योग के स्त्रातो को प्राप्ताहित किया तथा देश की जनता की भौतिक संपन्नता में योगदान दिया।⁷⁶ अपने 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' ग्रंथ के प्रथम खंड की भूमिका में आ० सी० दत्त ने भी इस विषय पर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में प्रकाश डाला। एक भारतीय कवि के शब्दों में जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के जल को सुखाकर भाप के रूप में ग्रहण करता है और फिर उसी जल को धरती को हरा-भरा करने के लिए वर्षा के रूप में उसे वापस लौटा देता है उसी प्रकार देश शासक को देश के करोड़ों को उगाहकर देश की संपन्नता के लिए खर्च करने के रूप में उन करोड़ों देशवासियों को लौटा देना चाहिए। परंतु भारत के उगाहे गए कर भारत का संपन्न न बना कर किसी अन्य देश की ही संपन्नता में वृद्धि करते हैं—इसका विरोध करते हुए उन्होंने निश्चित स्वर में कहा कि ऐसा तो अफगान और मुगल शासकों के निकृष्टतम शासन काल में भी नहीं हुआ। दूसरी ओर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो चकाचौध उत्पन्न करने वाले महल और स्मारक बनवाए तथा साथ ही साथ जिन विलासी कार्यों में वे प्रवृत्त हुए, उन्होंने भारत के उत्पादकों और कारीगरों को प्रोत्साहन और सपोषण दिया। उन्होंने इस प्रकार अपना निश्चित मत अभिव्यक्त करते हुए कहा—बुद्धिमान शासकों के तथा सूर्व शासकों के अधीन शासन काल में एक बात समान रही है कि करोड़ों वसूल किया गया धन जनता के पास ही लौट आया है और उसने देश के व्यापार और उद्योगों को संपुष्ट बनाया है।⁷⁷

यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादियों की इस मांग—वसूल किए गए कर जनता को ही वापस लौटा देने चाहिए, ताकि उनकी जेबें भारी हो सकें।⁷⁸ अथवा उनके व्यापार और उद्योग समृद्ध बन सकें—के पीछे करोड़ों को देश ही के भीतर खर्च करने से देश की गौण आय पर उनके पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में राष्ट्रवादियों की जानकारी का परिचय प्राप्त होता है।⁷⁹

दादा भाई नौरोजी ने निकासी की परिभाषा को और अधिक विस्तृत रूप दिया तथा विदेशियों द्वारा अपने वेतनों और आयों के भारत में खर्च किए जाने वाले भाग के विरुद्ध भी शिकायत की। इस शिकायत के संबंध में उनका दावा था कि विदेशियों द्वारा किया गया उपभोग भी आंशिक रूप से भारतीय सामग्रियों और सेवाओं की हानि ही थी क्योंकि अन्यथा ये वस्तुएं उपभोग के लिए भारतीयों को ही सुलभ होती।⁸⁰

भारतीय नेताओं में अर्थशास्त्रियों ने अवश्य निकासी से होने वाली संपत्ति की हानि

की अपेक्षा पूँजी की हानि को अधिक भयकर माना, क्योंकि उन्होंने यह भली प्रकार और स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि संक्षेपतया निकासी इस रूप में हानिप्रद थी। क्योंकि यह देश को उत्पादक पूँजी से वंचित करती थी। दादा भाई नौरोजी निकासी सबंधी अपनी समीक्षा के विश्लेषण में प्रारंभ से ही इस पक्ष को सर्वोच्च स्थान देने वाले महानुभाव थे। उन्होंने निकासी पर अपनी लगभग सभी अधिकृत घोषणाओं में पूँजी की हानि वाले तत्त्व को बड़ी ही सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी जो इनके निकासी-सिद्धांत का सार थी। उल्लेखनीय यह है कि दादा भाई के निकासी-सिद्धांत के इस पक्ष को आगे चलकर समुचित महत्व प्राप्त नहीं हुआ। फलतः राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री के रूप में दादा भाई की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि तथा योगदान की न्यूनाधिक रूप में उपेक्षा ही की गई। उन्हें पक्के राष्ट्रीय नेता के और महान व्यक्ति के रूप में तो मान्यता दी गई, परंतु अर्थशास्त्र जैसे विषयों में उन्हें अनाड़ी नहीं तो अनजान अवश्य समझा गया, जा भूर्खतापूर्ण ढंग से यह विश्वास करना था कि भारत जैसे विशाल देश में कुछ एक हजार अंग्रेजों का दिया गया धन उस देश की सर्पत्ति में उल्लेखनीय वसीलाता है। निकासी सिद्धांत को समुचित रूप में समझने में कमी हमें राष्ट्रवादी नेताओं के और विशेषतः दादा भाई के निकासी से पूँजी की हानि सबंधी विचारों का विस्तृत विवरण का प्रारित करनी है।

सर्वप्रथम, यहां यह उल्लेखनीय है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता मंचेत रूप से यह विचार रखते थे और दृष्टि विचारों का व्यापक प्रचार करने थे कि निकासी प्रमुख रूप से इस प्रकार सक्षान्त-कारक है क्योंकि इसमें देश में पूँजी-मंच में बाधा उपस्थित हो रही है और वर्तमान मंचित पूँजी के विशाल भाग को विदेशी भूमि पर ले जाने के रूप में देश की प्रगति विलंबित हो रही है।

1817 के प्रारंभ में ही 'मिलेक्ट कमेटी ऑन ईस्ट इंडिया फाइनांस' को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में दादा भाई नौरोजी ने इस दृष्टिकोण को सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी 'अन्यान्य देशों द्वारा जितना भी राजस्व दशवार्षिकों में उगाहा जाता है उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में वहां की जनता से 70,000,000 पौंड वसूल किया जाता है वह सारे का सारा राजस्व देश के लोगों के पास ही लौट आता है और देश के भीतर ही रह जाता है। अतः देश की पूँजी पर आधृत देश के उत्पादन में किसी प्रकार का ह्रास नहीं आता। परंतु भारत के विदेशी राज्य द्वारा शामिल होने के कारण प्रतिवर्ष उगाहे जाने वाले 50,000,000 पौंड में से 12,000,000 पौंड तो साफतौर पर ही खुलेआम इंग्लैंड को ले जाए जाते हैं और राष्ट्रीय पूँजी अथवा दूसरे शब्दों में इस देश की उत्पादकशक्ति में निरंतर वर्ष प्रतिवर्ष गिरावट ही आती जा रही है।'⁹¹

दादा भाई नौरोजी ने अपने ग्रंथ 'पावर्टी ऑफ इंडिया' में अपनी उक्त मान्यता को लगभग ऐसे ही शब्दों में दोहराया⁹² और उन्होंने दावा किया कि निकासी न केवल वर्तमान राष्ट्रीय बचतों को नामशेष कर रही है प्रत्युत बिरंगे में मिली विद्यमान राष्ट्रीय पूँजी के भण्डार को भी रिक्त कर रही है।⁹³ अपने उक्त लेख के समीक्षकों को प्रत्युत्तर देते हुए उन्होंने सेवाओं के यूरोपीकरण की अपनी आपत्ति को बड़ी ही सुस्पष्ट भाषा में विज्ञापित किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि कृषि तथा अन्यान्य उद्योगों के संघर्षन और

प्रगति के लिए अपेक्षित जीवन रक्त की व्यवस्था के लिए देश की पूजी को बचाना अत्यावश्यक है और उसका एक मात्र उपाय भारतीयों की सेवाओं में नियुक्ति है।⁸⁴ इसी प्रकार 1887 में एम० ई० ग्राट डफ को लिखे अपने प्रत्युत्तर में दादा भाई ने शिकायत की कि वर्तमान नीति के अंतर्गत ब्रिटिश भारत अपनी तुच्छ आय से निरंतर निकासी के कारण अपनी किसी प्रकार की पूजी को रख पाने की स्थिति से वंचित किया जा रहा है।⁸⁵ 12 फरवरी 1895 को 'हाउस आफ कामन्स' में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने घोषित किया—निकामी के फलस्वरूप देश से पूजी हटा दी गई है और देशवर्षामया को पूजी को बढ़ाने से वंचित कर दिया गया है। वस्तुतः इसमें इंग्लैंड को अनिवार्यतः लाभ पहुँचा है और ब्रिटिश भारतीयों के साधन इस तरह लडखड़ा गए हैं कि वे किसी भी रूप में अपने साधनों को पुनर्जीवन नहीं दे सकते। अतः उनके लिए दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन जीने के सिवाय अन्य कोई चारा ही नहीं।⁸⁶ विलबी कमीशन के सामने जिरह के दौरान दादा भाई ने निकामी से भारत की पूजी को होने वाली हानि की ओर कमीशन का ध्यान दिलाने की पूरी-पूरी चेष्टा की तथा अपने आलोचकों को बीच में ही पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों को उपयुक्त खिराज देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है परंतु यह खिराज इस परिणाम में होना चाहिए कि जिससे भारत के पूजी-निर्माण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे।⁸⁷

दादा भाई नौरोजी ने विलबी कमीशन के अध्यक्ष के साथ जो लंबा-चौड़ा वाद-विवाद किया उसमें उन्होंने बड़ी ही मुस्पष्ट भाषा और नाटकीय शैली से निकामी के प्रश्न को प्रभावशाली ढंग से ही पूजी निर्माण तथा आय-प्रजनन के साथ जोड़ दिया। इस विषय में दादा भाई नौरोजी ने भारत जैसे अविकसित देश में निवेश वृद्धि और आय-वृद्धि के पारस्परिक संबंध में 'बड़ी ही मुख्यवस्थित तथा अकाल-प्रौढ़ सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया। आइए, हम उनके तर्कों को उसके मूल रूप⁸⁸ में सिलसिलेवार समझें।

दादा भाई ने अपने साक्ष्य के प्रारम्भिक भाग में प्रतिपादित किया कि देश की कुशल और प्रगतिशील सरकार के लिए भारत का 6400 लाख रुपये राजस्व नितांत अपर्याप्त पड़ रहा है और यह राशि इनकी कम, सरकार की उस अस्वाभाविक प्रणाली के कारण है जो लोगों को दरिद्र बना रही है तथा उन्हें सरकार को अधिक भुगतान करने में नितांत असमर्थ बना रही है। उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि विदेशी सत्ता द्वारा रक्त चूसे जाने के स्थान पर यदि भारतीयों को अपने साधनों को भारत में ही रखने दिया जाए तो भारतीय आवश्यकता पड़ने पर कर्गों के रूप में ही 20,000 लाख रुपयों का भुगतान कर सकते हैं। लार्ड विलबी दादा भाई के इस मतव्य से सहमत नहीं थे, तभी उन्होंने पूछा कि स्वतंत्र सत्ता के अधीनस्थ किए जाने पर एक निर्धन देश 2 रु० 12 आने (3 शिलिंग 8 पैसे) प्रति व्यक्ति कर के स्थान पर उससे बढ़ाकर 1 पाँड 6 शिलिंग 6 पैसे प्रति व्यक्ति कर का भुगतान किम प्रकार कर सकता है? दादा भाई का स्पष्ट उत्तर था कि अपने लाभों को अपने ही पास रखने की अनुमति प्राप्त होने पर आज का निर्धन देश कल धनी बन जाएगा। यह तर्क विलबी की समझ में न आया अथवा वह समझना ही नहीं चाहता था, अतः उसने पूछा कि क्योंकि दादा भाई यूरोपीय सिपाहियों और राजकीय

प्रशासकों पर खर्च किए जा रहे 2000 लाख रुपये पर आपत्ति करते हैं और यहाँ तक कि यदि यह रकम भारतीयों को लौटा दी जाए तो भी इसमें दो रुपये के स्तर से बढ़कर 1 पौंड 6 शिलिंग 6 पैसे प्रति व्यक्ति के स्तर तक अर्थात् 6400 लाख रुपये से बढ़कर 30,000 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कर वृद्धि में सहायता कैसे मिल सकती है ? दादा भाई द्वारा इस प्रश्न का दिया गया उत्तर इस तथ्य का उद्घाटन करना है कि उनकी दृष्टि में निकासी का अर्थ केवल संपत्ति का स्थानांतरण नहीं था। उनका उत्तर था कि देश में खींचा जाने वाला धन यदि बचा लिया जाए तो उसके आर्थिक प्रभाव ये होंगे कि इसमें देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरे शब्दों में देश का लाभ केवल 2000 लाख रुपये की वार्षिक बचतों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। विलबी इस पर भी सतर्क नहीं था और उसने और अधिक कुरेदा परंतु आप इसमें (भारत को) उम रकम (2000 लाख रुपये) से बढ़कर तो समृद्ध नहीं बना सकते ? दादा भाई का प्रत्युत्तर था—यदि यह रकम देश में ही रहने दी जाए तो आर्थिक दृष्टि में वर्तमान की अपेक्षा यह अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी प्रभाव ही डालेगी। इसका अर्थ केवल 2000 लाख रुपये की बचत ही नहीं होगी प्रत्युत यह पुनः उत्पादन की, देश में पूँजी को बढ़ाने की दिशा में बचत होगी, परंतु यहाँ विचारणीय है कि दादा भाई ने पूँजी की बढ़ातरी को एक बुद्धि की पाई वाली कहानी की तरह यात्रिक रूप में नहीं देखा जिसमें पैसा चक्रवर्ती ब्याज (या नफा) की सहायता से हर साल बढ़ता जाए। भले ही उनके वार्षिक आकड़े और सगणनाएं अस्पष्ट और कभी कभी निराधार भी हों परंतु इतना निश्चित है कि वे निवेशित आर्थिक विकास की जड़ को ही पकड़ नहीं रहे थे तथा आर्थिक विकास के आधुनिक मिट्टातो को पूर्व सूचित ही नहीं कर रहे थे प्रत्युत निवेशगुणक की धारणा की भी कदाचित् भविष्यवाणी कर रहे थे। इस पर जब विलबी ने विरोध प्रकट किया—कि यहाँ भारत में रखे गए 2000 लाख रुपये में भारत को केवल निश्चित राशि ब्याज की ही तो प्राप्ति होगी। दादा भाई ने एकदम महं तोड़ उत्तर दिया—ब्याज ही केवल सब कुछ नहीं है, इससे तो देश के माधनो का विकास होगा जिसमें आज की अपेक्षा देश की पाँच गुणा अधिक समृद्धि हो सकती है। वस्तुतः भारतीयों के रक्त के रूप में भारत की पूँजी देश से बाहर ले जाई जाती है, उसे देश में ही रहने दिया जाए और भारत के अपने साधनों का रूप लेने दिया जाए तो देश इसी से पर्याप्त संपन्न बन जाएगा। यह पूँजी देश के रक्त समान है। विलबी ने फिर भी ठीक से न समझने का ढोंग रचा⁸⁹ और टिप्पणी की—मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत इतना संपन्न देश है कि 2000 लाख रुपये यदि यहाँ लगाए जाएं तो वह एक वर्ष के भीतर ही 20000 लाख से 30000 लाख रुपया अर्जित कर सकता है। दादा भाई ने तत्काल यह उत्तर देकर विलबी की टिप्पणी को नाकारा कर दिया कि उनके द्वारा पूर्व सूचित परिणाम का अर्थ यह नहीं कि यह सब एक ही वर्ष में हो जाएगा। उनके कथन का अभिप्राय तो केवल इतना था कि यदि निकासी को रोक दिया जाए तो भारत आवश्यक करों का भुगतान यथासमय करने की स्थिति में आ जाएगा। भले ही वे कर 20000 लाख रुपये हों अथवा 30,000 लाख रुपये। इस वाद-विवाद के उपरान्त भी विलबी ने दो तीन बार पुनः यह प्रयास किया कि दादा भाई यह स्वीकार कर लें कि

2000 लाख रुपयों की छोटी सी रकम भारत के साधनों को एक बड़े परिमाण में सफल बना सकती है—यह धारणा नितान्त निर्मूल तथा मिथ्या कल्पित है परंतु दादा भाई तो अपने कथन पर डटे रहे।

जी० वी० जोशी ने भी निकासी को पूँजी की क्षति माना और इस क्षेत्र में भी उन्होंने राष्ट्रवादी चिंतन को एक नया धरातल प्रदान किया। उनका मुद्दा था कि निकासी को वार्षिक कुल राष्ट्रीय उत्पादन के एक अंश के रूप में नहीं लेना चाहिए भले ही यह भाग चाहे जितना ऊँचा और भारी क्यों न हो; प्रत्युत इसे तो वार्षिक शुद्ध कार्य-क्षम अधिशेष अथवा बचत का एक भाग समझना चाहिए। इस प्रकार 1884 में अपने लेख—‘दी इकोनामिक रिजल्ट ऑफ़ फ्री ट्रेड ऐंड रेलवे एक्सपेंशन’—में उन्होंने सगणना की कि 1882 में आयात पर निर्यात की अधिकता 23 करोड़ रुपये थी। भारत का कुल वार्षिक उत्पादन 350 करोड़ था और कुल उत्पादन 12 प्रतिशत पर सर्वाधिक अनुकूल दर से लाभ की राशि 40 करोड़ थी। अतएव राष्ट्रीय समाधानों पर निकासी का भाग राष्ट्रीय उत्पादन के लाभों का पचास प्रतिशत में अधिक था।¹⁰ छ वर्ष पश्चात् अपने लेख—‘दि इकोनामिक मिच्युएशन इन इंडिया’ में जोशी जी ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी उक्त धारणा को मीधी तर्कमय अभिव्यक्ति दी

निकासी का पूरा माप देश की कुल वार्षिक आय के साथ उसका अनुपात नहीं है यह अनुपात तो लगभग 6 प्रतिशत है। उसका वास्तविक माप देश के प्रशासन के मचालन पर होने वाले वार्षिक आवश्यक व्ययों को निकाल कर शुद्ध आय का अनुपात है और यह अनुपात लगभग एक तिहाई भाग है। शुद्ध राष्ट्रीय आय के पूरे एक तिहाई भाग का विदेशी दायित्वों के निभाने के लिए देश के बाहर चले जाना और बदले में देश को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ न पहुँचना मचमुच ही देश की भारी क्षति है और यही भारत में लघु पूँजी मचय का कारण है।¹¹

डी० ई० वाचा और जी० एम० ऐयर सहित कितने ही अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने वार्षिक निकासी के संबंध में इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। उन्होंने भी देश में पूँजी के बाहर ले जाने को देश की उल्लेखनीय और तात्त्विक क्षति बताया।¹²

द्वितीय, कुछ एक भारतीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि निकासी में उत्पन्न होने वाली पूँजी की न्यूनता का परिणाम यह निकलता है कि इसमें भारत की आर्थिक मुक्ति का आधारभूत औद्योगिक विकास प्रतिबंधित हो जाता है। वस्तुतः उनका यह अनुभव था कि भारत में आधुनिक उद्योग की मदनति का प्रमुख दायित्व निकासी पर ही था। इस प्रकार दादा भाई नौराजी ने अपने लेख—‘दि पावर्टी ऑफ़ इंडिया’ में तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण भारत की एक अत्यंत अप्रतिहार्य आवश्यकता थी परंतु व्यवहार में उद्योग उपलब्ध पूँजी की कमी के कारण सीमित था और यहाँ उन्होंने जान स्टुअर्ट मिल के इस मतव्य को उद्धृत किया—

‘उत्पादक श्रम को समर्थन और नियोजन देने वाला तत्त्व निवेशित पूँजी है न कि श्रम के उत्पादन के लिए उसके पूर्ण होने पर क्रेताओं की किसी प्रकार की माँग।’ और भारत पूँजी के अभाव से पीड़ित है जिसका एक कारण तो यह है कि इसका अधिशेष उत्पादन

स्वल्प है और इससे भी बढ़कर बात यह है कि इसके दैनिक पुनः उत्पादन की आवश्यकताओं की और यहां तक कि अधिशेष की निकासी कर दी जाती है। इसलिए देश अपनी संपदा की वृद्धि के लिए उद्योग का उपयोग ही नहीं कर पाता और इसके फलस्वरूप देश की दरिद्रता का उत्तरोत्तर विस्तार अबाधित रूप में होता जा रहा है।⁹³ 1881, में अपनी इस तर्क प्रणाली की उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की — जबकि अंग्रेज लोग भारत की मूल पूँजी का ही अपहरण कर रहे हैं तो फिर वे इस बात पर आश्चर्य क्यों प्रकट कर रहे हैं कि भारत में उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती।⁹⁴ इसी प्रकार बिलबी कमीशन के सामने जिरह में उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि भारतीयों की उद्योगों में पूँजी निवेश करने में अमहमति ही भारत के औद्योगिक विकास के अभाव का प्रधान कारण है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि तथ्य यह है कि भारतीयों के पास उपलब्ध पूँजी पर्याप्त नहीं है। इससे भारत अपने ही लाभ के लिए अपने ही ससाधनों से अपने ससाधनों का स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता। यदि प्रतिवर्ष भारत को पूँजी में वचित न किया जाए तो वह निश्चित ही अपने साधनों का विकास करने में मग्न हो जाएगा।⁹⁵ बाद में 1900 में दिए गए अपने भाषण में दादा भाई ने घोषणा की कि यहाँ तक कि भारत के पुराने उद्योगों की क्षति का दायित्व निकासी पर है। ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीयों का जीवन रक्त चूस लिया है और वे अब अपने उद्योगों के संचालन की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए उनके पास साधन ही नहीं हैं।⁹⁶

जी० बी० जोशी ने यह मत भी प्रकट किया कि भारत में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कार्यरत पूँजी की अपर्याप्तता का कारण बड़े पैमाने पर पूँजी के सग्रह का अभाव था और यह अंशतः भारत में ब्रिटेन को पूँजी की निकामी का परिणाम था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा : कोई भी देश इस निकामी को सहन करते हुए अपने औद्योगिक क्षेत्र को प्रगतिशील नहीं बना सकता।⁹⁷ इसी प्रकार डी० ई० वाचा ने भी अनुभव किया कि भारत तब तक नए उद्योगों की स्थापना के सबंध में सोच तक नहीं सकता, जब तक कि वह पूँजी की निकासी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो जाता क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है और भारत के उद्योग धनाभाव से पीड़ित है। उन्होंने अपने मतव्य की सत्यता के प्रमाण के रूप में जापान की उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति को उद्धृत किया जहाँ दम तोड़ने वाली प्रक्रियाएं... संपत्ति के राष्ट्रीय अधिशेष का वार्षिक अपहरण नहीं किया जा रहा था।⁹⁸ बिलबी कमीशन द्वारा जी० के० गोखले से जिरह के दौरान दादा भाई नौरोजी और गोखले के मध्य हुए प्रश्नोत्तरों में निकासी और औद्योगीकरण के अभाव के मध्यवर्ती संबंध के विषय में राष्ट्रवादी स्थिति को अत्यंत ही स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी गई। गोखले से यह प्रश्न किया गया कि भारतीय नए उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं करते ?

(दादा भाई) इसका क्या कारण है कि भारतीय इन उद्योगों को जैसे कि चाय उद्योग को अथवा इनमें से किसी और उद्योग को अथवा इनमें किसी उद्यम को हाथ में नहीं ले सके जबकि विदेशी आए और उन्होंने इन पर कब्जा जमा लिया। क्या इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश की पूँजी देश से बाहर ले जाई जा रही है ?

(गोखले) हा, यही कारण है।

(दादा भाई) क्या यह सभी रोगों का मूल कारण नहीं है ?

(गोखले) हा, सभी रोगों की जड़ यही है।⁹⁹

कुछ एक भारतीय नेताओं ने थोड़ा और आगे बढ़कर यह निर्देश भी किया कि जहाँ निकासी भारत की पूँजी की क्षति का एक स्रोत है, वहाँ अतीत में यह इंग्लैंड के पूँजी संग्रह का एक स्रोत सिद्ध हुई है और उसने देश के साधनों को सफल बनाया है तथा देश के द्रुत औद्योगीकरण में सहायता प्रदान की है।¹⁰⁰

इस संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई नौरोजी तथा उपर्युक्त अन्यान्य नेता कुल मिलाकर इस तथ्य से अपरिचित ही थे कि उनके द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय अधिशेष अपने आप से औद्योगिक पूँजी का रूप ग्रहण नहीं कर सकता, उसके इस रूप में परिवर्तित होने के लिए तो दो अडचनो को हटाना होगा। प्रथम, उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की कि बचत करने वाले वर्गों के अनाप-शनाप खर्चों के कारण राष्ट्रीय पूँजी का भीतर ही भीतर ह्रास होता जा रहा है। इसके साथ, बचत करने वाले वर्गों की प्रवृत्ति या तो संपत्ति के संग्रह की है अथवा, औद्योगिक, अनुत्पादक क्षेत्रों में धन के निवेश करने की है। दादा भाई ने समस्या के इस पक्ष पर ध्यान अवश्य दिया परंतु चलता सा। उन्होंने विलर्बा कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य में भारत की रियासतों के कुछ एक शासकों की धन-संग्रह की प्रवृत्ति की आलोचना की। इसी प्रकार जसाकि हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं, जी० वी० जोशी ने सरकार की भारतीय जनता से सरकारी ऋण उगाहने की प्रवृत्ति की निंदा की क्योंकि उनके अनुसार ये ऋण देश में निवेश की जाने वाली पूँजी का देश में अपहरण करते हैं। इसी प्रकार 'बंगाली' ने 25 दिसंबर 1880 के अंक में तथा 28 जनवरी 1882 के अंक में बंगाल की जमींदारी पद्धति की इसलिए आलोचना की कि इससे बंगाल की उपलब्ध पूँजी का व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हटाकर भूमि में उसका निवेश किया जा रहा है। परंतु साधारणतया भारतीय नेताओं के इस वर्ग ने पूँजी निर्माण के इस पहलू की प्राथ उपेक्षा ही की। द्वितीय इन नेताओं ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अधिशेष को औद्योगिक पूँजी के रूप में लाने से पूर्व तकनीक, पूँजी संगठन, उत्तम-कौशल आदि से संबंधित समस्याओं का निपटारा भी आवश्यक है। वस्तुतः जैसे कि हम द्वितीय और तृतीय अध्याय में अन्यान्य सदस्यों में देख चुके हैं कि बहुत सारे नेताओं ने इन समस्याओं पर ध्यान अवश्य दिया परंतु निकासी के संबंध में उन नेताओं ने इन समस्याओं को गौण स्थान ही दिया। विशेषतः दादा भाई नौरोजी ने तो इन्हें तुच्छ मानते हुए इनकी पूर्ण उपेक्षा की। उनका कदाचिन् यत्र विश्वास था कि निकासी को रोकना और उससे पूँजी का निर्माण करना ही प्रधान लक्ष्य था, और इस लक्ष्य की सिद्धि हो जाने के उपरांत ही अन्यान्य समस्याओं का सामना करना उचित है।

दादा भाई नौरोजी द्वारा निकासी के विरुद्ध लगाया गया एक अन्य आरोप यह था कि इससे विदेशी पूँजी को देश में घुसने और देश का शोषण करने की सुविधा उपलब्ध होती थी। उनके अनुसार सुविधा जुटाने का यह कार्य दो रूपों में होता था; प्रथम, निकासी भारत के अंदर पूँजी ही के संग्रह में बाधा पड़कर और इस प्रकार से आंतरिक पूँजी को

पंगु बनाकर, किसी प्रकार की स्वदेशी प्रतियोगिता की संभावना को समाप्त करके ही विदेशी पूँजीपतियों को भारत में आकर एकाधिकार जमाने तथा भारत के सभी संसाधनों का स्वेच्छापूर्वक दोहन करने की सुविधा जुटाती थी।¹⁰¹ द्वितीय, निकासी देश में निवेशित विदेशी पूँजी के संग्रह का एक प्रधान स्रोत थी क्योंकि निकासी का एक बहुत बड़ा भाग विदेशी पूँजी के रूप में फिर भारत में लाया जाता था।¹⁰² इस संबंध में दादा भाई की मान्यता थी कि यूरोपीय सेवाएं भारत में दुधारी तलवार का काम कर रही हैं। एक ओर तो वे भारतीय वेतनभोगी वर्गों के हाथों में पूँजी संग्रह करने में बाधक बन रही हैं तथा यूरोपीय अधिकारियों की बचतों के माध्यम से विदेशी पूँजी के विकास का संवर्धन कर रही है और दूसरी ओर वे ब्रिटिश पूँजीपतियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर रही है।¹⁰³

दोनों, निकासी-सिद्धांत और ऊँचे भूमि लगानों द्वारा देश के दरिद्रीकरण के सिद्धान्त के अत्यंत मुखर वकील आर० सी० दन ने भी इन दोनों सिद्धांतों में आपसी संबंध स्थापित करने की और यह दिखाने की चेष्टा की कि निकासी का भुगतान प्रमुखतया भूमि लगानों से किया जाता है अतः यह देश के कृषकों की दरिद्रता की सूचक है। इस प्रकार अपनी 'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया' के द्वितीय खंड की भूमिका में उन्होंने लिखा कि 1900 C. में गृह प्रभार कुल भूराजस्व के लगभग बराबर ही थे।¹⁰⁴ बाद में अपनी पुस्तक में उन्होंने इन दोनों के मध्य और अधिक जटिल आर्थिक संबंध सिद्ध किया। इन दोनों के वित्तीय संबंधों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा : निकासी का प्रत्यक्ष संबंध सरकारी राजस्व से है और सरकारी राजस्व में बहुत बड़ा भाग भूमि लगानों का है। आर्थिकता की दृष्टि से निकासी का रूप अनिश्चित निर्यात है। निकासी के वित्तीय और आर्थिक पक्षों का संबंध निम्नलिखित रूप से है : किसानों को भूमि के लगान अथवा राजस्व का भुगतान करने के लिए अपनी उपज के एक बहुत बड़े भाग को बेचना पड़ता है। इस उपज का निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि देश को अनेकित निर्यात अधिशेष की मृष्टि करनी पड़ती है और क्योंकि कठोर भूमि लगान पद्धति के अंतर्गत गांव से बलपूर्वक छीने गए कृषि उत्पादनों को बाजार में लाना ही पड़ता है। इस प्रकार भूमि लगान की यात्रिकता के द्वारा किसान को निकासी के लिए भुगतान करने और निकासी को माध्यम बनने वाले कृषि उत्पादनों को जुटाने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। इसका परिणाम यह है कि एक ओर तो वह बेचारा भारी और कठोर भूमि लगानों के कारण दरिद्र है और दूसरी ओर अन्न के अभाव में भूखा मरता है क्योंकि वह अपने अनाज को बेचने के लिए और देश उस अनाज को निर्यात करने के लिए विवश है। इसका कारण उस गरीब किसान पर भूमि लगान और निकासी की दोहरी मार ही है।¹⁰⁵

इससे पूर्व 1901 में उन्होंने दादा भाई नौरोजी की इस मित्रतापूर्ण आलोचना, भूमि लगानों को भारत की दरिद्रता के कारण बताकर उन पर अधिक बन देना निर्धनता के मूल कारण, निकासी से जनता का ध्यान हटाना ही था—का प्रत्युत्तर देते हुए निकासी और भूमि लगानों को परस्पर अधिक प्रत्यक्ष संबंध करने का प्रयास किया। 24 मई 1901 को लंदन में हुए भारतीयों ने एक सम्मेलन में भारत में भूमि लगानों को कोमल बनाने

की मांग का प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि वस्तुतः यह निकासी पर पहले के ही प्रस्तुत प्रस्ताव का पूरक है। उन्होंने कहा कि दादा भाई नौरोजी जहां भारतीय राजस्व के एक बहुत बड़े भाग की प्रतिवर्ष निकासी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, मैं स्वयं भी यही दिखाने को उत्सुक हूं कि राजस्व के एक बहुत बड़े भाग को वसूली देश के दरिद्रों में दरिद्रतम लोगो, भारत के किसानों, से ही की जाती है। उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि इससे प्रकट होता है कि हम दोनों (मैं और दादा भाई) दो भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं कर रहे हैं प्रत्युत एक ही प्रश्न के दो पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि हम दो विभिन्न सुधारों की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल बाहरी और भीतरी दृष्टि से सुधार की आवश्यकता को दिखाते हुए उसी एक सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा : कि आर्थिक निकासी तब तक कम नहीं होगी जब तक भूमि लगान कम नहीं होंगे, और भूमि लगान तब तक कम नहीं होंगे, जब तक धन की निकासी नहीं घटाई जाती।¹⁰⁸ इसी प्रकार 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 1 अक्टूबर 1900 के अंक में मत प्रकट किया कि भूमि पर ऊँचे लगान एक भारी रोग है और यह अकाल के प्रमुख कारण निकासी का फल है।

डी० ई० वाचा ने 1886 में निकासी के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के एक अन्य पक्ष को उजागर किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि निकासी कृषि को सभी प्रकार की उत्पादक पूँजी से वंचित कर रही है। उन्होंने बल देकर कहा कि जब तक सारी जनता के सभी लाभों की निकासी की जा रही है, तब तक धरती की उत्पादकता में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। क्योंकि यह वृद्धि तभी संभव है जब धरती पर सर्वत्र पूँजी का व्यय प्रत्येक स्थिति में निश्चित रूप में थोड़ी मात्रा में और कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में किया जाए।¹⁰⁹

बहुत सारे भारतीय नेता यह देखने में भी सफल हो गए कि संपत्ति के एकपक्षीय स्थानांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त निकासी भारत के विदेशों के साथ व्यापार संबंधों को बिगाड़ने के रूप में एक दूसरा आघात भी कर रही थी क्योंकि निकासी के साथ विनिमय अधिशेष अनिवार्य रूप से जुड़ा तत्व था और यह भारत के निर्यात की एक अनिवार्य विशेषता बन गई थी। भारत के लिए दो ही मार्ग थे या तो वह निर्यात करे या नष्ट हो जाए। फलतः भारत को विदेशी क्रेताओं को अपना माल खरीदने को प्रलोभित करने के लिए अपने माल की कीमत घटानी पड़ती थी। दूसरे शब्दों में निकासी के फलस्वरूप जिन शतों पर भारत आयात के बदले निर्यात करता था, वह इसके सर्वथा अनुकूल नहीं थीं।¹⁰⁸

यहां यह एक उल्लेखनीय रोचक तथ्य है कि राष्ट्रवादियों को निकासी की आलोचना में कुछ विशिष्ट महानुभावों का समर्थन प्राप्त हुआ। आदम स्मिथ ने 'वैलथ आफ नेशन्स' में भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों को 'भारत के लुटेरे डाकू' बताया।¹⁰⁹ इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी निकासी के लिए लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, जिनका दादा भाई नौरोजी प्रयोग किया करते थे। 1857 में मार्क्स ने लिखा : .

ये पेंशन पाने वाले (भारत सरकार के मेवा निवृत्त ब्रिटिश कर्मचारी) ऋणों पर इंग्लैंड में देय लाभ और ब्याज के रूप में भारत में प्रतिवर्ष 150 से 200 लाख डालर की राशि खींचकर उसका उपभोग करते हैं। इस विपुल राशि को वस्तुतः भारतीय जनता द्वारा परोक्ष रूप से अंग्रेज सरकार को दिया गया खिगाज ही मानना चाहिए। प्रतिवर्ष विभिन्न मेवाओं से अवकाश प्राप्त करने वाले ब्रिटिश कर्मचारी अपने साथ वेतनो में उल्लेखनीय परिमाण में बचाई गई धन राशि अपने साथ ले जाते हैं, इसे भी निश्चित रूप से भारत से धन की होने वाली निकामी में जोड़ना चाहिए।¹⁰⁸ और 1881 में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखते हुए लिखा : अंग्रेज लोग भारत से प्रतिवर्ष लगान में और रेलों, जो हिंदुओं के लिए बेकार हैं, पर लाभ के रूप में जो ले जाते हैं, मेना और अमेरिकी शासन के कर्मचारियों के लिए पेंशन, अफगानिस्तान तथा अन्यान्य युद्धों आदि के लिए जो कुछ भी वे ले जाते हैं, उसके बराबर वे कुछ भी बदले में नहीं देते और भारत के भीतर प्रतिवर्ष खर्च किए जाने वाले धन में वह सर्वथा अनिश्चित ही होता है। भारत द्वारा उदार (पूर्व) प्रतिवर्ष इंग्लैंड को भेजी जाने वाली उपभोग सामग्री के मूल्य को ही यदि देखा जाए तो यह भारत के 6 करोड़ औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय बँटती है। यह रक्त चमने की घनघोर प्रक्रिया है।¹⁰⁹

अन्त में दो अन्य आर्थिक पक्ष भी विचारणीय हैं। प्रथम, क्या निकामी का अर्थ अनुत्पादक मेवाओं पर होने वाले व्यय के रूप में सर्वांग रूप में लिया जाए अथवा व्यापक रूप में जिसमें अनर्गत गार नियात अधिशेष की रकम, भले ही वह दादा भाई नौरोजी की गणना के अनुसार 24 करोड़ रुपये मानी जाए जिसमें सरकारी ऋणों पर मूढ़ सम्मिलित नहीं है, अथवा मोरिमन की गणना के अनुसार 30 करोड़ रुपये मानी जाए, जिसका आधार निर्यात अधिशेष का परिमाण है, अथवा और कोई राशि स्वीकार की जाए, भारत की निम्न राष्ट्रीय आय के अथवा अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित विशुद्ध अधिशेष के अथवा 1881-2 में उगाहे जाने वाले सरकारी लगानों की 46.86 करोड़ रुपये की राशि के और 1901-2 में उगाहे जाने वाले लगानों की 60.79 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले पर्याप्त महत्वपूर्ण राशि थी।¹¹⁰ बी द्वितीय, आज यह व्यापक रूप में स्वीकार किया जाना है कि देश को अपने आर्थिक विकास की आधार शिना रखने के लिए अथवा आत्मनिर्भरता की स्थिति पर पहुँचने के लिए पहले उसका पूँजी आयातक देश बनना आवश्यक है अथवा दूसरे शब्दों में उसके पास आयात अधिशेष अवश्य ही होना चाहिए। अपने आर्थिक विकास की परवर्ती स्थिति में ही वह केवल निर्यात अधिशेष के द्वारा ऋणों को लौटाने की स्थिति में आ सकता है। यहाँ तक कि इसके अवसर भी थोड़े समय की परिधि में तो विरले ही होते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के पदचात की अवधि में बड़ी संख्या में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिस प्रकार प्रयत्नशील हैं उनमें एक भी देश का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जहाँ यह प्रगति निर्यात अधिशेष के साथ हो रही हो। लगभग प्रत्येक स्थिति में इन देशों का व्यापार सतुलन ऋणात्मक ही है। उदाहरण के लिए आज के भारत को ही लीजिए और यह एक सर्वथा विशिष्ट स्थिति का देश भी है, तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सारी 19वीं शताब्दी

में, केवल 1857 के विद्रोह के कुछ एक वर्षों को छोड़कर और वह भी 250 लाख डालर के साधारण परिमाण तक, यह देश विशुद्ध रूप से पूँजी का निर्यातक ही रहा है।

निकासी में कटौती

निकासी सिद्धांत के कुछ एक समर्थकों का तो विश्वास था कि जब तक निकासी जारी है भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण कभी संभव ही नहीं और यदि भारत को निकासी से एक बार मुक्ति मिल जाए तो और सब कुछ अपने प्राकृतिक रूप में ही स्वतः ठीक हो जाएगा।¹¹⁰ कुछ एक अन्य नेताओं ने थोड़ा कम कठोर दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने भारत की दरिद्रता और अकाल को निर्मूल करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ निकासी में कटौती को भी एक आवश्यक शर्त माना।¹¹¹

इस संबंध में दो अन्य बातें भी विचारणीय हैं। प्रथम, जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं, दादा भाई तक इस तथ्य से परिचित थे कि विदेशी शासन के आवश्यक उपकरण के रूप में थोड़ी बहुत निकासी का बना रहना तो सर्वथा अनिवार्य ही है। विदेशी शासन को उखाड़ फेंके बिना तो इसे सर्वथा निर्मूल किया ही नहीं जा सकता और हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि के दौरान सामान्यतया भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की कल्पना ही दादा भाई के मस्तिष्क में नहीं थी।¹¹² द्वितीय, दादा भाई और आर० सी० दत्त ने ब्रिटिश जनता को यह समझाने की पूरी चेष्टा की कि निकासी में कटौती से स्वयं उन्हें असीम लाभ पहुंचेगा क्योंकि इससे उनका भारत को निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा।¹¹³ दादा भाई ने अपने लक्ष्य में मिथि प्राप्त करने के लिए हमारे अध्ययन के अंगर्गत अवधि के दौरान ब्रिटिश जनता के विभिन्न वर्गों में उत्पन्न हो रहे तीखे राजनैतिक मतभेदों का लाभ उठाने में भी किसी प्रकार का सकोच नहीं किया। उन्होंने पहले 1893 में और फिर 1896 में ब्रिटेन के श्रमिक वर्ग से अपील करते हुए यह अभियोग लगाया कि उच्च वर्ग के थोड़े से लोग ही हैं जो इस समय भारत से सभी प्रकार के लाभ उठा रहे हैं जबकि दूसरी ओर यदि निकासी समाप्त कर दी जाए तो भारत ब्रिटिश के सामान एक इतनी बड़ी भारी मण्डी बन जाएगा कि ब्रिटेन को अपने श्रमिकों की बेकारी का शब्द ही नहीं सुनना पड़ेगा।¹¹⁴

निकासी में कटौती कैसे की जा सकती है? इस संबंध में राष्ट्रवादियों का उत्तर बड़ा ही सीधा-सादा था। निकासी के कारणों को हटा दीजिए। निकासी के कारणों की पहले ही विस्तृत समीक्षा की जा चुकी है अतः राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए उपायों के विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहां केवल राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए उपचारों का मात्र उल्लेख ही करेंगे।

इन उपचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था नगर तथा सैनिक सेवाओं का भारतीयकरण और इसके फलस्वरूप इन सेवाओं में यूरोपीय तत्वों की समुचित परिमाण में कटौती।¹¹⁵ इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं दादा भाई नौरोजी ने प्रायः ही संकीर्ण आधार देते हुए यह सुझाव दिया कि भारतीयकरण ही इस रोग की एकमात्र औषधि है। इससे निकासी सिद्धांत एक प्रकार के फूहड़ और

उपहासास्पद बनकर रह गया। यह स्थिति उस समय और भी अधिक विकृत रूप धारण कर गई जब उन्होंने यह धारणा प्रकट की कि अमैनिंक सेवाओं की एक साथ इंग्लैंड और भारत में परीक्षा तथा अप्रतिभृत और गौण सेवाओं की न्यायोचित प्रतियोगिता देश को संपन्न बनाने की पर्याप्त आवश्यक शर्तें हैं।¹¹⁶

द्वितीय, भारतीय नेताओं ने गृहप्रभारों में कटौती की मांग की।¹¹⁷ इस पग की वकालत कभी कभी तो निकासी में इसे सबधित किए बिना ही की गई। गृह प्रभागों को अनेक रूपों में घटाया जा सकता है। भारतीय नेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय था ब्रिटेन द्वारा इस भार के एक बड़े भाग को बहन करने में भागीदार बनना।¹¹⁸ कुछ एक नेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि इंग्लैंड में लिए गए सरकारी ऋणों पर भारत द्वारा देय ब्याज के भुगतान के और स्वयं सरकारी ऋणों के भार को हटाकर¹¹⁹ इन ऋणों के लिए ग्राही प्रतिभृत जुटा करके ब्याज की दर में कटौती करके,¹²⁰ सरकारी ऋण इंग्लैंड में लेने के बदले भारत में ही लेकर¹²¹ रेलपथ निर्माण की गति को कम करते हुए रेलवे ऋणों के भार को कम करके,¹²² भारत के सरकारी भंडारों के लिए स्वयं सरकारी भंडारों के लिए स्वयं भारत में ही सामान की खरीदारी करके,¹²³ अनावश्यक आयात को रोकने के लिए भारतीय उद्योगों को उन्नत करके,¹²⁴ निजी विदेशी पूँजी के बढ़ते आयात के प्रवाह को रोककर¹²⁵ गृह प्रभागों को घटाया जा सकता है। भारतीय नेताओं द्वारा निकासी को रोकने के लिए सुझाया गया महत्वपूर्ण उपचार था—इंग्लैंड और भारत में गृह प्रभागों का न्यायोचित विभाजन।¹²⁶

निकासी सिद्धांत में विश्वास न रखनेवाले कुछ भारतीय

यह एक व्यापक मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रवादियों में एक ऐसा वर्ग भी विद्यमान था जो निकासी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। इस वर्ग का नेतृत्व रानाडे के हाथ में था और वे निकासी के रूप में प्रसिद्ध धन के निर्यात को भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारण नहीं मानते थे।¹²⁷ इस धारणा का आधार, 1890 में पूना में प्रथम उद्योग सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण के लिखित रूप का एक अवतरण है। इस भाषण में रानाडे ने घोषणा की थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह सोचते हैं कि जब तक हमें इंग्लैंड को ऊँचे खिगज देने को विवश रहना पड़ेगा, जिसका अर्थ लगभग 20 करोड़ रुपये के अधिशेष निर्यात से हाथ धोना है, तब तक हम पतन के गत में गिरे पड़े रहेंगे और किसी प्रकार भी अपना उद्धार आप नहीं कर सकेंगे। यह न तो किसी रूप में उपयुक्त है और न ही यह वीरोचित स्थिति है। उन्होंने निर्देश किया कि इस निकासी का एक भाग तो भारत में निवेशित अथवा भारत के लिए ऋण में ली गई विदेशी पूँजी पर ब्याज की राशि है और हमें इस विषय में शिकायत करने के बदले धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा ऋणदाता है, जो ब्याज की इतनी नीची दर पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक अन्य भाग भारत को सभरण किए गए भंडारों के मूल्य की राशि का है, जिस भंडार के अनुरूप सामान का हम भारत में उत्पादन नहीं करते। अवशिष्ट भाग प्रशासन और सेना पर व्ययों का तथा पेंशनों के भुगतान का है।

यद्यपि इस संबंध में अवश्य शिकायत की जा सकती है कि यह सारा आवश्यक खर्च नहीं है। रानाडे ने अपने श्रोताओं को सलाह दी कि वे खिराज के प्रश्न के निरर्थक विवाद में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अथवा अपव्यय न करें। उन्हें इस प्रश्न को राजनीतिज्ञों पर ही छोड़ देना चाहिए।¹²⁸

हमारे विचार में यह अवतरण सचमुच यह सिद्ध नहीं करता कि रानाडे इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि भारत से संपत्ति की निकासी हो रही है अथवा यह आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, रानाडे 1872 के प्रारंभ में निकासी सिद्धांत का भारत में प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और औद्योगिक सम्मेलन में दिए गए उनके इस भाषण के मुश्किल से ही दो वर्षों के उपरांत 'भारतीय राजनैतिक आर्थिकता' विषय पर दिए गए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भाषण में भारत से संपत्ति और प्रतिभा की निकासी के लिए उत्तरदायी विदेशी शासन की निंदा की।¹²⁹ इसके अतिरिक्त ऊपर उद्धृत अवतरण में भी उन्होंने भारतीयों को आधुनिक उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य विशेष से बुलाए गए औद्योगिक सम्मेलन का विरोध निकासी के प्रश्न को उठाने के आधार पर किया न कि राजनीतिज्ञों को इस प्रश्न पर विचार न करने की सलाह दी। वस्तुतः 1881 में पूना सार्वजनिक सभा में, जिसके कर्ता-धर्ता और सर्वेसर्वा उस समय रानाडे ही थे, कुछ विषय प्रस्तुत किए जिन पर भारतीय विशेष रूप से क्षुब्ध थे और इन विषयों में एक विषय था—आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता के माध्यम से निकासी का प्रश्न तथा उस निकासी को रोकने के उपाय।¹³⁰ इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसके पदों के पीछे रानाडे महत्वपूर्ण और अग्रणी नेता थे और जिसके प्रस्तावों के प्रारूप तैयार करने में उनकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण थी, घोषणा की कि निकासी भारत की दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण है।¹³¹ इन सकेतों से भी बढ चढ़कर और अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणस्वरूप तथ्य यह है कि आर्थिक मामलों में उनके दोनों निकट सहयोगी और शिष्य—जी० वी० जोशी और जी० के० गोखले ने इस दृष्टिकोण की पुष्टि की कि निकासी ने औद्योगिक विकास को प्रतिबंधित किया है और देश की जनता को दरिद्र बनाया है।¹³² हा, यह कहना तो अवश्य ही गलत होगा कि जोशी और गोखले के विचार रानाडे के विचार थे परंतु यह अनुमान गलत नहीं होगा कि शिष्यों ने गंभीरता से किसी विचार का समर्थन नहीं किया होगा, जो उनके गुरु के सिद्धांतों के मूल रूप से ही विरुद्ध हो।

इस कथन में इतना जरूर सत्य है कि रानाडे तथा कितने ही और भारतीय निकासी सिद्धांत के विरुद्ध थे। रानाडे, जोशी और गोखले और भारतीय नेताओं में कदाचित् बहुत-मारे अन्य निकासी सिद्धांत को भारतीय राजनीति का अथवा राष्ट्रवादी प्रचार और आंदोलन का प्रधान विषय नहीं बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे इस प्रश्न को कुछ समय के लिए आंखों से ओझल भी करना चाहते थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है, जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय नेताओं का बहुमत, वास्तव में दादाभाई नौरोजी, 'अमृत बाजार पत्रिका' और कुछ इनेगिने लोगों को छोड़कर लगभग सभी भारतीय नेताओं के विचार में देश की दरिद्रता के गढ़ों में

धकेलने वाले मुख्य कारणों में निकासी भी केवल एक कारण ही था ।

निकासी सिद्धांत के आलोचक

राष्ट्रवादी नेताओं की आर्थिक नीतियों के वैज्ञानिक दृष्टि से खरेपन का निर्णय देना तथा उनकी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए तथा उन्हें सही सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों की समीक्षा करना कदाचित् हमारे ग्रंथ के लिए उपयुक्त नहीं होगा । निकासी के राष्ट्रवादी विरोधियों के सबंध में भी हमारा यही मत है । परन्तु इसके साथ ही निकासी सिद्धांत पर भारत में सरकारी और गैरसरकारी प्रवक्ताओं द्वारा, मलाहकारों द्वारा तथा भारत में ब्रिटिश राज्य के रक्षकों द्वारा 1880-1905 की अवधि में और उसके उपरान्त जिन उग्रता के साथ प्रहार किए गए, उसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है । इसके अतिरिक्त सरकारी पक्ष के अर्थशास्त्रियों और लेखकों की यह भी कल्पना थी कि राष्ट्रवादियों द्वारा निकासी पर किया जा रहा प्रहार उनकी पूर्ण मूर्खता और राष्ट्रवादी नेताओं के पूर्वाग्रह से नहीं तो उनकी आर्थिक अज्ञानता और संबंधित आर्थिक प्रश्नों की उपयुक्त जानकारी के अभाव से अवश्य उत्पन्न हुआ । इस सदर्भ में हम निकासी सिद्धांत पर ब्रिटिश प्रहार के प्रमुख तर्कों और राष्ट्रवादियों द्वारा दिए गए उत्तरों की समीक्षा करेंगे, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि निकासी के राष्ट्रवादी आलोचक आर्थिक वास्तविकताओं से अनभिज्ञ नहीं थे । उन्होंने तो अपने विरुद्ध बाद में लगाए जाने वाले आरोपों को पहले से ही भाप लिया था कि कदाचित् यह कहा जा सकता है कि उनके समीक्षकों ने इस विषय के प्रति पूर्ण न्याय नहीं किया और न ही किसी सूक्ष्म चिंतन का परिचय दिया । वे अपने निकासीवाद के स्वरूप निर्धारण में भले ही सही रहे हो अथवा गलत, परन्तु इतना निश्चित है कि आर्थिक मामलों में वे अनाड़ी नहीं थे और निकासी के प्रति उनका दृष्टिकोण देश की स्थिति के विस्तृत, पूर्ण और अन्तर्बद्ध तथा समन्वित आर्थिक विश्लेषण का ही एक अंग था । निकासी सिद्धांत का तुरंत ब्रिटिश द्वारा खंडन थियोडोर मोरिसन के प्रत्युत्तर परक ग्रंथ, 'दी इकोनामिक ट्रांजिशन इन इंडिया' में किया गया । यह ग्रंथ 1911 में प्रकाशित हुआ और कदाचित् यह सर्वाधिक विस्तृत और आलोचकों के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम विश्लेषण था, ¹³² आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में एल० सी० ए० नोल्स और वीरा एंस्टे ने निकासी सिद्धांत की मोरिसन द्वारा आलोचना की व्यापक रूपरेखा को ही ग्रहण किया । ¹³⁴ यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि निकासीवाद के समर्थक और विरोधी एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत थे कि भारत को अपने निर्यातों के भाग के बदले कुछ आर्थिक तुल्य-मूल्य की प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार जान स्ट्रेची ने 1878 के वित्तीय विवरण में टिप्पणी की कि इंग्लैंड के साथ भारत के संबंध और उस संबंध के वित्तीय परिणाम भारत को प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख पौंड का उत्पादन बदले में बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक दृष्टि से तुल्य मूल्य की सामग्री के प्राप्त किए ही यूरोप को भेजने को विवश होना पड़ता है । आयातों पर निर्यातों की इस अधिकता को ही अर्थशास्त्री अपनी भाषा में खिराज का नाम देते हैं । ¹³⁵ और मोरिसन ने 'निकासी' को इस प्रकार परिभाषित किया कि भारत से सामग्री अथवा

धन के निर्यातों की वह धनराशि, जिसके बदले भारत को उस वर्ष उस धन राशि के तुल्य मूल्य का किसी प्रकार का सामान प्राप्त नहीं हुआ निकासी है।¹³⁶ इस प्रकार निकासीवाद के आलोचकों और समर्थकों के मध्य मतभेद का आधार एकतरफा निर्यात अधिशेष के सही आर्थिक शब्दार्थ, उद्गम और परिणाम के संबंध में अपनी अपनी समझ है। निकासी सिद्धांत पर प्रहार का रूप इस प्रकार से था :—

प्रथम, यह कहा गया कि भारतीय आवश्यक कटौतियों का हिसाब न करके प्रायः निकासी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते कि निर्यात अधिशेष का एक भाग तो अदृश्य आयातों, जैसे कि जहाजरानी सेवाएं, आयातों और निर्यातों पर लगने वाला बीमा शुल्क तथा भारतीय छात्रों और पर्यटकों द्वारा विदेशों में किए गए खर्च आदि के खाते में चला जाता है।¹³⁷ पूंजी खाते के कार्य व्यापार भी आयातों और निर्यातों को सापेक्ष महत्व देने की झूठी प्रवृत्ति लिए हुए हैं क्योंकि पूंजी के आयात वास्तविक निर्यात अधिशेष को घटा देते हैं और पूंजी के बापसी भुगतान इन्हे अतिरंजित रूप दे देते हैं।¹³⁸ अंतिम, निर्यात अधिशेष की संगणना करते समय सोने और चांदी के भारी आयातों की भी गिनती करनी चाहिए।¹³⁹ मोरिसन ने संगणना की कि वार्षिक निकासी—जिसका अर्थ उसके अनुसार सोने और चांदी के कार्य व्यापार तथा पूंजी के आयातों को मिलाकर विशुद्ध निर्यात अवशेष था—की गति 210 लाख पौंड थी।¹⁴⁰

द्वितीय, आलोचकों का कथन था कि भारत अतिरिक्त निर्यातों के बदले पर्याप्त आर्थिक तुल्य मूल्य की सामग्री प्राप्त करता है। निकासी का सबसे बड़ा भाग ऋण लिए हुए धन पर ब्याज की राशि का था, ये ऋण भारत के आर्थिक विकास और संपन्नता के सूचक थे न कि दरिद्रता के। विदेशी पूंजी की सहायता से रेलों का निर्माण किया गया है, सिचाई को विकसित किया गया है तथा बागान और दूसरे औद्योगिक साहस के कार्य प्रारंभ तथा विकसित किए गए हैं, जिनसे भारत लाभ अर्जित कर रहा है। इस लाभ का ही एक छोटा-सा भाग ब्याज के रूप में देश के बाहर भेजा जाता है। इसके साथ साथ इन लाभों के अर्जन के अतिरिक्त यह उद्योग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। यदि मारे लाभ ही देश से बाहर भेज दिए जाएं तो भी किराए और श्रम की राशि का भुगतान तो इस देश को ही प्राप्त होगा।¹⁴¹ अतः भारतीयों को अपने पूंजीगत साधनों की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों का आभारी होना चाहिए।¹⁴² भारत को प्राप्त लाभों को और अधिक बढ़ा चढ़ा कर इस प्रकार चित्रित किया गया कि भारत को इंग्लैंड के साथ राजनैतिक संबंधों का यह लाभ होता है कि इंग्लैंड उसे विश्व की सबसे सस्ती बाजार से ऋण लेने की सुविधा जुटाता है। यदि भारत में निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी के उपलब्ध होने की कल्पना कर भी ली जाए तो उसे ऋण रूप में लेना अपेक्षाकृत अधिक मंहगा पड़ेगा।¹⁴³ मोरिसन ने घोषणा की कि वास्तव में भारत को सरकारी ऋण जिस प्रकार सस्ती दर पर मिलते हैं, उससे तो 'राजनैतिक निकासी'¹⁴⁴ की बात खत्म हो जाती है और निष्कर्ष रूप में यह कहना ही पड़ता है कि भारत ब्रिटिश राज्य से अपने संबंधों के कारण आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है।¹⁴⁵ इस संबंध में भारत की स्थिति की तुलना—यू० एस० ए०, रूस, आस्ट्रेलिया, और जापान जैसे अन्यान्य देशों

से की जा सकती है। अमेरिका को यूरोपीय देशों की कर्जदारी के कारण व्यापक निर्यात अधिशेष रखने पड़ते हैं, तो भी वह समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। वस्तुतः वह देश इसी लिए समृद्ध हो रहा है क्योंकि वह अपनी पूँजी की रिक्तता की पूर्ति विदेशी पूँजी से कर रहा है और विदेशी पूँजी की ही सहायता से अपने साधनों का विकास कर रहा है।¹⁴⁶ इसके अतिरिक्त इन देशों के उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निर्यात अधिशेष का किसी देश की राजनैतिक स्थिति से कोई संबंध ही नहीं है।¹⁴⁷ जहाँ तक भारत के अनुत्पादक ऋण का संबंध है, इस विषय में विशेष स्मरणीय और विचारणीय बात यह है कि अन्य देशों के अनुत्पादक ऋणों की तुलना में यह अत्यल्प मात्रा में है।¹⁴⁸

तृतीय, जहाँ तक सरकारी ऋणों पर व्याज को घटाकर गृह प्रभागों का, यूरोपीय कर्मचारियों द्वारा अपनी बचतों को बाहर भेजने आदि का संबंध था, आलोचक इस बात में सहमत थे कि इस विषय में भारत की स्थिति अन्य देशों में भिन्न ही नहीं प्रत्युत विचित्र थी। हा, यह बात अवश्य है कि ये गृह प्रभाग अधिक नहीं थे और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत को इसके बदले क्षति पूर्ति के रूप में परिश्रमी, निस्स्वार्थी तथा योग्य ब्रिटिश अधिकारियों की सेवाएँ और शांति तथा व्यवस्था के रूप में इतर-आर्थिक लोक-कल्याण, आधुनिक प्रशासन, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, अथवा दूसरे शब्दों में 'उत्तम सरकार' उपलब्ध थी।¹⁴⁹ उत्तम सरकार की उपलब्धि को आर्थिक स्वरूप इस प्रकार दिया जा सकता है कि इसके अभाव में भारत की औद्योगिक प्रगति संभव ही नहीं थी।¹⁵⁰ इसे और अधिक स्पष्ट रूप देना चाहे तो कहा जा सकता है कि भारत को आर्थिक विकास के सर्वथा अनुकूल एक ऐसा प्रशासन उपलब्ध हुआ है, जो उसके अपने द्वारा जुटाए जाने वाले किसी भी प्रशासन की अपेक्षा अधिक सहायक है।¹⁵¹

निकासीवाद के मित्रातवादी प्रचारक—इसमें हमारा तात्पर्य सबसे पहले दादा भाई नौरोजी से है—आलोचकों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों को पहले ही जानकर उनका उत्तर भी दे चुके थे। उनके प्रत्युत्तरों की समीक्षा के प्रारंभ में यह लिखना अनुचित न होगा कि समर्थकों ने निकासी की संगणना और परिभाषा के संबंध में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। संगणना के लिए उन्होंने अपने आयातों और निर्यातों के खाते में सोने चांदी के कार्य व्यापार को शामिल नहीं किया।¹⁵² द्वितीय, उन्होंने देखा कि पूँजी का कार्य व्यापार वास्तविक व्यापार संतुलन को भूँठा सिद्ध कर देता है। इस रूप में वस्तुतः निर्यातों की वास्तविक अधिकता विदेश-व्यापार के आकड़ों के अध्ययन मात्र से सतही तौर पर दिखाई देने वाली अधिकता से कहीं बढ़ चढ़ कर है क्योंकि आयातों में उपभोग सामग्री सम्मिलित रहती है, जिसके लिए वित्त की व्यवस्था पूँजी के आयातों के साधनों द्वारा की जाती है। भले ही पूँजी के इन आयातों की व्यवस्था सरकारी खाते से की गई हो अथवा जनता के निजी खाते से, भले ही इंग्लैंड में यह पूँजी उगाही गई हो अथवा अंग्रेजों द्वारा भारत में पुनः निवेशित की गई हो। देर-अबेर उसका भुगतान तो आखिर निर्यातों की अधिकता के रूप में करना ही पड़ता था।¹⁵³ यह कहना भी गलत होगा कि भारतीय नेता प्रत्यक्ष और परोक्ष आयातों में अंतर नहीं कर पाए अथवा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के भेद को नहीं समझ पाए। प्रमुख परोक्ष आयात

थे—इंग्लैंड अथवा भारत में की गई सेवाओं का भुगतान, जहाजरानी, बीमा और बैंक प्रभार। भारतीयों ने इन सेवाओं पर विचार ही नहीं किया प्रत्युत इन्हें प्रायः ही अपनी शिकायत का प्रमुख आधार भी बनाया। बैंक, बीमा व्यापार और भारत के भीतर ही तटवर्ती जहाजरानी स्पष्टतया भारत में विदेशी व्यापार और उद्यम के ही अंग थे और भारत में विदेशी पूँजी के निवेश के इन लाभों को राष्ट्रवादियों ने अपनी जाच-पडताल का विषय बनाया था। जहाँ तक आलोचकों के इस कथन का संबंध था कि निर्यातों की अधिकता का एक भाग तो आयातों और निर्यातों पर होने वाले जहाजी खर्च और बीमा की देनदारी का रूप था, दादा भाई ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया परंतु साथ ही यह निर्देश किया कि निर्यातों और आयातों के मूल्य की सगणना करने का सरकारी ढंग यह था कि निर्यातों की वर्तमान अधिकता के ही अंतर्गत पहले में ही इन किरावों आदि का विधान किया जा चुका है। यह कैसे हुआ—इसका विवरण उन्होंने निम्नलिखित ढंग से किया—भारतीय आयातों का मूल्य सरकारी खातों में भारतीय पत्तनों पर प्रचलित मूल्य के रूप में ही आका गया अतः उस मूल्य में तो भाड़े का व्यय और बीमा की देनदारी स्वतः सम्मिलित हो गए और दूसरी ओर निर्यातों का मूल्य भारतीय पत्तनों पर प्रचलित मूल्य के रूप में ही कूटा गया, अतः उनमें भाड़े और बीमा का व्यय—जो उसके मूल्य में सम्मिलित किया जाना था और जिसका भुगतान आयात के पत्तन पर किया जाना था—को अलग रखा गया। अतः उनके द्वारा संगणित निकासी इस विशिष्ट वक्रता से मुक्त थी।¹⁵⁴ सत्य तो यह है कि वे इसके भी आगे बढ़ गए तथा उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि यदि निर्यातों के मूल्य में मालभाड़े और बीमा की रकम को जोड़ दिया जाए तो निकासी उनकी सगणना से भी अधिक बढ़े चढ़े रूप में सामने आएगी।¹⁵⁵ आलोचकों के इस प्रमुख तर्क का कि निकासी का वास्तविक संबंध तो पंजीगत सेवाओं तथा व्यक्तिगत सेवाओं के भुगतान से है, राष्ट्रवादियों द्वारा दिया गया उत्तर उपयोगिता तथा अनिवार्यता के मौलिक सुद्ध तथा परिपक्व आधार को लिए हुए था। उनका कथन था कि यदि किसी सेवा विशेष की वास्तव में ही उपयोगिता और आवश्यकता है और उसे विदेश में रूपया खर्च करके ही पाया जा सकता है तो इस रूप में तो निकासी को सहन करना अनुचित नहीं कहा जा सकता परंतु इसके सर्वथा विपरीत यदि सेवा निरर्थक है अथवा उपयोगी होने पर भी स्वयं भारत में उपलब्ध की जा सकती है तो उस पर रूपया खर्च करने के रूप में निकासी अवश्यमेव आपत्तिजनक है।

इस धारणा का कि निकासी के प्रमुख भाग का संबंध उत्पादक सरकारी ऋणों पर ब्याज और निजी विदेशी पूँजीपति उद्यमियों के लाभों से है और ये दोनों ही भारत के आर्थिक विकास और संपन्नता के सूचक हैं, राष्ट्रवादियों ने कई तरह से उत्तर दिया। उन्होंने निर्देश किया कि अब्बल तो विदेशी पूँजी आवश्यक ही नहीं थी। इसकी आवश्यकता तो तब पड़ी है जबकि देश के शायद इस देश की पूँजी की निकासी करते रहे हैं और कर रहे हैं। इस निकासी के न होने पर तो भारत रेलपथ आदि के लिए स्वयं ही पूँजी जुटा पाता और साधारणतया अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में वास्तव में ही समर्थ होता। अतः विदेशी पूँजी ने भारतीय पूँजी का स्थान ग्रहण किया

है, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। यदि विदेशी पूँजी का देशी पूँजी की वृद्धि में वास्तविक योगदान रहता तो उसका अवश्य स्वागत किया जाता। इसके अतिरिक्त भारत में आयातित पूँजी वास्तव में भारत की अपनी ही पहले निर्यात की गई पूँजी थी। अतः भारत में वास्तविक रूप में विदेशी पूँजी का निवेश किया ही नहीं गया है।¹⁵⁸

दूसरे भारतीय नेताओं का यह निश्चित मत था कि विदेशी पूँजी वास्तव में उतनी लाभकारी कदापि नहीं थी जितना इसके ममर्थक कहते थे। रेलों भी शुद्ध वरदान नहीं हैं और उन्हें देश की आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से आगे धकेला जा रहा है।¹⁵⁷ रेलों के निर्माण के लिए उठाए गए सरकारी ऋण स्पष्टतया न तो लाभप्रद है और न ही आवश्यक। निजी विदेशी पूँजी केवल ब्याज को ही इस देश में बाहर नहीं खींच ले जाती प्रत्युत उद्यम के सभी प्रकार के लाभ भी हड़प जाती है और इसमें देश पूँजी के पुनर्निवेश के गौण लाभों में भी वंचित रह जाता है।¹⁵⁸ इसके अनिर्गुण रेलगाड़ियों ने 19वीं शताब्दी के अंत तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाया।¹⁵⁹ वेतन आदि के रूप में देश को कुछ लाभ अवश्य हुआ परंतु इन वेतनों का भी एक अंश विदेशियों को प्राप्त हुआ और यह भी निकासी का ही एक रूप है।¹⁶⁰ इससे भी बढ़कर उल्लेखनीय सत्य यह है कि विदेशी उद्यमों में कार्य की शोचनीय स्थिति को और पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाली रकम की तुच्छता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इनसे भारत को होने वाला लाभ मामूली ही है।¹⁶¹

भारतीय नेताओं ने और अधिक तर्क प्रस्तुत किए। उनका कथन था कि औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति के कारण विदेशी पूँजी स्वदेशी पूँजी के उपयोगी विनियोजन को निरुत्साहित और वंचित कर रही थी, उसके मार्ग में बाधा बन रही थी, इस रूप में वह देश के लिए हानिकारक थी।¹⁶² और कुल मिलाकर विदेशी पूँजी का उद्देश्य भारत को विकसित और संपन्न बनाना नहीं था प्रत्युत उसका दोहन, शोषण और अपहरण करना था।¹⁶³

इस प्रकार इस धारणा का कि भारत को सस्ते व्याज की दर पर ऋण उपलब्ध होने से उसे लाभ पहुंचता है, उत्तर यह था कि अब्बल तो ऋणों की सर्वथा ही कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे, उनका उपयुक्त ढंग से प्रयोग ही नहीं किया जाना। वस्तुतः वे ऋण कुछ और न होकर भारत में निष्कासित भारत की ही पूँजी थे, अतः उनकी सस्ती दर पर उपलब्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा यदि ऊंची दर पर ही सही, देश में देशवासियों से ही ऋण लिया जाता तो भुगतान देश में रहता और देश के साधनों को फलीभूत बनाता, जबकि नीची दर के विदेशी ऋण निकासी का ही कारण बनते हैं।

भारतीय नेताओं ने भारत की तुलना कुछ समय निर्यात अधिशेष रखने वाले अमेरिका से करने की सर्वथा अनुचित बनाया। इस तथ्य के अलावा कि अमेरिका आमतौर पर ऋण ली गई पूँजी पर केवल ब्याज का ही भुगतान करता है और उद्यम के सारे लाभ देश के भीतर अपने पास ही रखता है।¹⁶⁴ भारत के निर्यात अधिशेष और अमेरिका के निर्यात अधिशेष के बीच एक अन्य बहुत बड़ा और चौकाने वाला अंतर था। अमेरिका इस समय अपने निर्यात अधिशेषों के द्वारा बाहरी देशों के लिए गए ऋणों का भुगतान

कर रहा है, जिसका अर्थ यह है कि अतीत में वह निर्यात अधिशेष वाला देश था। इसके निर्यात अधिशेष इसकी आस्थगित वसूलियों से संबंधित है। परंतु भारत का मामला बिल्कुल अलग-थलग था। वह पिछले ऋणों का भुगतान नहीं कर रहा है क्योंकि भारत के निर्यात अधिशेषों की संगणना ही केवल तब की जाती है, जब उनमें आयात पूजी आयातों में सम्मिलित कर दी जाती है। इस प्रकार जहां तक भुगतान-चिट्ठे का संबंध है ऋण में ली गई धनराशि का भुगतान तो उसी समय स्वयं निर्यातों के साथ ही कर दिया जाता है। इस प्रकार एक ओर तो भारत के पास अतीत में कोई आयात अधिशेष नहीं थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात कुछ-एक वर्षों तक थे भी, तो उनका परिमाण तुच्छ था। दूसरी ओर भारत के निर्यात अधिशेषों ने भविष्य के लिए इसे दूसरे देशों पर किसी प्रकार की दायित्व प्रदान नहीं की। इसलिए कालांतर में आयात अधिशेष इसकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। फलतः भारत का निर्यात अधिशेष एक ऐसी विचित्र प्रक्रिया है—जिसकी पूजी के कार्य व्यापार का न तो कोई अतीत है और न ही कोई भविष्य। यह तो पैदा होते ही दम तोड़ने की सी स्थिति है।¹⁶⁵

इन सब तर्कों के बावजूद निकासी मिद्धात के प्रस्तावक प्रायः ही निकासी संबंधी अपनी संगणनाओं से उत्पादक सरकारी ऋणों के लागत मूल्य को शामिल न करने पर सहमत थे।¹⁶⁶ इस संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपयोगिता को आधार मानते हुए इन नेताओं ने उधार ली गई पूजी के मपन्न किए गए संचाई कार्य के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। इसी प्रकार कुछ-एक नेताओं ने तो देश के उत्पादक ससाधनों के विकास के लिए विदेशों से ऋण लेने का समर्थन किया।¹⁶⁷

भारतीय नेताओं ने एक अन्य तथ्य की ओर सकेन करते हुए कहा कि भारतीय सरकारी ऋण का एक भाग पूर्णतया राजनैतिक प्रकृति का होने के कारण निरर्थक, अनावश्यक और अपने स्वरूप में अनुत्पादक है तथा इसके बदले में तुल्य मूल्य का कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।¹⁶⁸ 1858 में लगभग 690 लाख पौंड तक पहुँचे साधारण सरकारी ऋण के उद्गम की खोज करते हुए भारतीय नेता इस परिणाम पर पहुँचे कि इसको अस्तित्व में लाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसने अपने शासन काल में ब्रिटिश द्वारा भारत को जीतने के लिए किए गए युद्धों के खर्चों की पूर्ति के लिए तथा भारत को कंपनी के लाभों का भुगतान करने के लिए इस रोग की सृष्टि की है। इसके साथ इसमें कंपनी द्वारा ताज को भारत के प्रशासन के हस्तांतरण के मूल्य के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि तथा 1857 के विद्रोह को कुचलने में खर्च की गई धनराशि भी जोड़ दी गई है। इस प्रकार 1858 के बहुत बाद भी भारत विदेशी शक्ति द्वारा विजित होने का मूल्य चुकाता आ रहा है।¹⁶⁹ भारत और इंग्लैंड के अनुचित वित्तीय संबंधों के उदाहरण हैं—1878 के अफगान युद्ध का, मिस्री युद्धों का, 1890 के बर्मा युद्ध तथा सीमांत युद्धों का खर्च भारत के मत्थे मड़ना। ताज द्वारा भारत का प्रशासन संभालने के उपरांत साधारण सरकारी ऋणों का भार उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।¹⁷⁰ अतः राष्ट्रवादी भारतीय नेताओं की दृष्टि से लगभग 1000 लाख पौंड भारतीय सहकारी ऋण का एक बहुत बड़ा भाग स्पष्टतया व्यापार-ऋण नहीं है। इसलिए

नैतिक दृष्टि से वह भारत का दायित्व नहीं। इसका ब्याज स्पष्टतया धन की निकासी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई कभी कभी ऋण के इस अंश के प्रति भी उदारता बरतने को सहमत हो जाया करते थे।¹⁷¹

जहाँ तक भंडारों का संबंध था, वे पहले से ही आयातों में सम्मिलित थे¹⁷² और इसके अतिरिक्त वे निकासी प्रकृति के ही थे, क्योंकि मूलतः वे इस रूप में अनावश्यक थे क्योंकि उनका उत्पादन देश में किया जा सकता था¹⁷³ परंतु फिर भी इन भंडारों के भुगतान के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण उदार था।¹⁷⁴

निकासी के विरोधी भारतीय नेता निकासी के जिस एक भाग को किसी भी स्थिति में क्षमा करने के लिए सर्वथा तैयार नहीं थे, वह था भारत सरकार द्वारा यूरोपीय कर्मचारियों पर किया जाने वाला व्यय। उनके विचार में सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान निकासी की जड़ था। स्पष्ट है कि भारत को निकासी के इस भाग के बदले में तुल्य मूल्य का कुछ भी तो प्राप्त नहीं होता। दूसरी ओर भारतीय नेता यह मानने को तैयार नहीं थे कि गैर आर्थिक सेवाओं के द्वारा इस मद की निकासी की क्षति-पूर्ति हो जाती है।¹⁷⁵ वस्तुतः ये सेवाएं आवश्यक ही नहीं थीं। सत्य तो यह है कि देश को इन सेवाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि स्वयं भारतीयों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक योग्यता और अधिक सस्तेपन के साथ ये सेवाएं की जा सकती हैं।¹⁷⁶ अतः इन सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान अनिवार्य रूप में थोपा गया है और वास्तव में निकासी का ही एक निश्चित रूप है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि भारतीय नेताओं ने भारतीय कारखानों में विदेशी तकनीशनों की नियुक्ति¹⁷⁷ पर कोई आपत्ति नहीं की अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति का भी विरोध नहीं किया।¹⁷⁸ इन नेताओं ने विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के लिए सक्रिय सघर्ष किया।¹⁷⁹ इन दोनों मदों में होने वाली निकासी को आवश्यक और उपयोगी माना गया। दूसरे, राष्ट्रवादियों का कथन था कि भारत सरकार द्वारा सैनिक और अमैतिक प्रशामन पर किए जाने वाले व्यय का एक बहुत बड़ा भाग भारत के हित को दृष्टि में रखकर नहीं किया जा रहा था प्रत्युत इसका उद्देश्य ब्रिटिश और उसके नागरिकों के हितों को सुरक्षित करना था।¹⁸⁰ अतः कानून और व्यवस्था के नाम पर भी किया गया व्यय स्पष्ट रूप से धन की निकासी था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने सरकारी अधिकारियों को भारत की सुरक्षा के दावे को चुनौती देते हुए प्रश्न किया कि भारत समुचित रूप से सुरक्षित कहा है जबकि स्वयं अंग्रेजों को इसे लूटने की खुली छूट मिली हुई है।¹⁸¹

कुछ एक भारतीय नेताओं ने यह भी टिप्पणी की कि यूरोपीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान को गैर आर्थिक पहलू से कितना ही न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयास क्यों न किया जाए, आर्थिक दृष्टि से तो वह निश्चित रूप से ही धन की निकासी था।¹⁸² दादा भाई ने इस संबंध में व्यंग्य प्रहार करते हुए ब्रिटिश जनता से प्रश्न किया कि क्या वे उपयोगी सेवा के तर्क पर अपने प्रशासन के उच्च पदों पर और प्रमुख स्थानों पर फ्रांसीसी युवकों जैसे विदेशियों को आरुढ़ होने की अनुमति देंगे?¹⁸³ उन्होंने इस बात का भी

निर्देश किया कि स्वयं अंग्रेजों ने 16वीं शताब्दी की अवधि में अपने देश से इटली और पाये को हो रही संपत्ति की निकासी पर तीव्र आपत्ति उठाई थी।¹⁸⁴

अंतिम, इस तर्क का कि भारत को ब्रिटिश नागरिकों की नियुक्ति से गैर आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, खंडन करते हुए भारतीय नेताओं ने लाभों के मुकाबले होने वाली गैर आर्थिक हानियों का रेखाचित्र प्रस्तुत किया। उन हानियों में प्रमुख थी - नैतिकता की हानि, बौद्धिकता की हानि, अनुभव की हानि तथा सारे राष्ट्र को बौना और नपुंसक बनाने के रूप में हानि। 1897 में विलबी कमीशन के सामने इस संबंध में भारतीयों के मामले को जी० के० गोखले ने अत्यंत ही स्पष्टता और प्रौढता के साथ प्रस्तुत किया :

विदेशी अभिकरण की प्रशासनिक मंहगाई ही एकमात्र बुराई नहीं है। इसके साथ नैतिकता की बुराई जुड़ी हुई है, जो किसी भी अन्य तत्व से अपेक्षाकृत बढ़-चढ़ कर है। वर्तमान पद्धति के अंतर्गत भारतवासियों को बौना और नपुंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हम डीन भावना से ग्रस्त होकर ही अपना सारा जीवन जिएं और इस देश का श्रेष्ठतम व्यक्ति भी इसलिए झुक जाए ताकि वर्तमान प्रशासन का अहम् मंजूर हो सके। उन्नति की प्रवृत्तियाँ, यदि मुझे इस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी जाए, ऐटन और हैरों में शिक्षा पाने वाले प्रत्येक बच्चे को यह प्रेरणा मिलती है कि वह एक दिन बड़ा होकर रूइमन, नेल्सन अथवा वॉलिंगटन बने। इसके लिए उसे प्रत्येक उपलब्ध सुविधा जुटाई जाती है, सर्वोत्तम प्रयत्न किए जाते हैं—परंतु हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन की इन सब प्रवृत्तियों में वंचित रखा जाता है। वर्तमान शासन प्रणाली में हमारे देश के लोग उन्नति के जिम चरम शिखर पर पहुँचने के योग्य हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच सकेंगे। स्वशासन देश के व्यक्ति जिस नैतिकता के उत्थान की आशा करते हैं वह हमारे लिए कभी संभव नहीं। प्रयोग में न आने के कारण हमारी प्रशासनिक क्षमता तथा सैन्य प्रतिभा भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और हम अपने ही देश में कमरबन्ड मजदूरी से आजीविका जुटाने वाले बन कर रह जाएंगे।¹⁸⁵

इस विषय में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अधीनता के कारण उत्पन्न गैर आर्थिक क्षतियों की ओर आध्यात्मिक पतन की चर्चा करते समय भारतीय नेता सचमुच ही उस समय हक्के-बक्के से अवश्य रह जाते होंगे जबकि उनके सामकें उन्हें विदेशी शासन के आर्थिक लाभों को देखने के उपदेश भाड़ते होंगे। जब इन नेताओं ने भौतिक अधिमान को स्वीकार कर लिया और विदेशी शासन द्वारा की गई आर्थिक हानियों की शिकायत की तो उन्हें गैर आर्थिक और आध्यात्मिक लाभों की ओर ध्यान देने को कहा गया। उन लोगों का उस समय आर्थिक और गैर आर्थिक मामलों को एक साथ जोड़ने और इससे संबंधित भ्रांतिक तर्कों पर आपत्ति करना उचित था। किसी भी रूप में भारतीय नेता विशेषतया 1905 के उपरांत ही विदेशी शासन के विरोध में आध्यात्मिक आकांक्षाओं और आर्थिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से मिलाकर उनका उपयोग करना सीख पाए।

निकासी सिद्धांत के विरोधियों के इस अंतिम तर्क के विरुद्ध, कि निकासी के बदले भारत को आर्थिक विकास के उपयुक्त उत्तम प्रशासन मिलता है, सारे ही भारतीय नेता

एक स्वर में भड़क उठे। राष्ट्रवादी नेताओं की आर्थिक नीतियों के समग्र विश्लेषण में यह स्पष्ट है कि जस्टिस रानाडे—जो अन्यथा निकासी पर आवश्यकता में अधिक बल देने के पक्ष में नहीं थे—सहित सभी राष्ट्रवादी नेता इस एक प्रश्न पर नमान रूप से सहमत थे कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन देश के आर्थिक विकास के हित में कदापि नहीं है। वस्तुतः उनका सारा आर्थिक आंदोलन प्रायः सभी क्षेत्रों में सरकारी नीति की घातक प्रवृत्ति से बचाने की भावना से ही प्रेरित था।

निकामी सिद्धांत के उपर्युक्त विश्लेषणों और इसके समर्थकों द्वारा इसकी पुष्टि में यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उनके हाथ में निकामी सिद्धांत एक अलग-थलग आलोचना नहीं था प्रत्युत उद्योग, रेल, विदेशी व्यापार, विदेशी पूँजी, मुद्रा और विनिमय, भूमि लगान, श्रम और कराधान तथा व्यय से संबन्धित सरकारी नीति के मूल्यांकन का एक अंग था। यह सिद्धांत भारतीय नेताओं की आर्थिक नीतियों के लक्ष्य प्रत्येक पहलू से घनिष्ठ तथा गहन रूप से जुड़ा हुआ था। वास्तव में दादा भाई नौरोजी, आर० सी० दत्त और एक लोकप्रिय स्तर पर राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों ने सभी आर्थिक प्रश्नों को उठाया और निकामी सिद्धांत का उपयोग सरकारी आर्थिक नीतियों की समग्र राष्ट्रवादी आलोचना को प्रकाश में लाने के लिए तथा भारत में ब्रिटिश राज्य की शोषक प्रवृत्ति को प्रकाश में लाने के लिए किया। मंत्र साधारण के मन में निकामी आर्थिक शोषण को मरल और सजीव रूप देने में समर्थ थी। अन्यथा शोषण के जटिल रहस्यों के समझने के लिए समय व क्षमता तो केवल अर्थशास्त्रियों के पास थी। निकासी वह विदुषी जिम पर भारतीय राष्ट्रीयतावाद की चोट पूरी ताकत से लगती थी।

राजनैतिक आशय

निकासीवाद की आर्थिक महत्ता कुछ भी क्यों न रही हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में तो इसकी वास्तविक महत्ता इसके राजनैतिक आशयों में निहित है। क्योंकि इसने बात साफ कर दी और भारतीयों को उस समय भारतीय स्थिति के प्रमुख विरोधी को समझने अर्थात् भारतीयों को अपनी स्थिति और भारतीय साम्राज्य में अंतर्विरोध को समझने के योग्य बना दिया। इस अनुभूति की प्रक्रिया को समझने के लिए उस प्रक्रिया को देखना पड़ेगा जिसके अंतर्गत निकासी सिद्धांत की रचना और प्रचार ने अंत में इस सिद्धांत के प्रवर्तक दादा भाई नौरोजी के राजनैतिक दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप दिया।

सर्वप्रथम, निकासी की मूल परिभाषा और उसके कारण ने दादा भाई नौरोजी को यह मानने से कि यह भारत के पिछड़ेपन का उपकरण और परिणाम था, इनकार करने पर तथा उसके बदले यह मानने पर विवश कर दिया कि यह भारत की राजनैतिक परिस्थितियों का कारण अथवा यथार्थतः भारत के विदेशी सत्ता द्वारा शासित होने का ही परिणाम था। अपने निबंध, 'पावर्टी आफ इंडिया' में, उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि प्रधानतया भारत पर राजनैतिक अधिकारों के कारण इंग्लैंड भारत के निर्यातों के एक बड़े भाग को रखने में समर्थ था।¹⁸⁹ 1896 में लार्ड विलबी को

लिखे अपने पत्र में उन्होंने बार बार और जोर देते हुए लिखा : हमारे लिए निकासी एक व्यापारिक मामला नहीं है। यह विदेशी सत्ता द्वारा भारत के संसाधनों के खर्चों के अस्वाभाविक प्रशासन और अस्वाभाविक प्रबंध का परिणाम है।¹⁸⁷ उन्होंने दृढ़तापूर्वक लिखा कि जहां तक इंग्लैंड में प्रभारों की देयता का संबंध है, वे भारत की किसी भी प्रकार की सहमति के बिना, अत्याचार के द्वारा बलपूर्वक ही लिए जा रहे हैं।¹⁸⁸ इस प्रश्न के समग्र राजनैतिक पक्ष ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। और उन्होंने लिखा कि लाई मैकाले ने ठीक ही फरमाया है कि कंधों पर रखे जाने वाले सभी प्रकार के जुओं में अजनबियों का जुआ सर्वाधिक भारी होता है।¹⁸⁹ बाद में 1897 में विलबी कमीशन के समक्ष जिरह के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की, भारत में ब्रिटिश राज्य का स्वाभाविक और आवश्यक दोष भारत की आर्थिक, राजनैतिक और बौद्धिक निकासी है। इसे समुद्र पार के विदेशी शासन से पृथक् किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्रशासन इस सुदृढ़ सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं रखता कि भारतीयों को अपने देश की सेवा में समुचित भाग और उनके अपने ही खर्चों में उन्हें कुछ कहने का अधिकार मिलना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ उन्होंने बड़ी ही सुस्पष्ट भाषा में निकासी के राजनीतिक कारणों की ओर इशारा किया।¹⁹⁰ निकासी सिद्धांत के अध्ययन से निकलने वाले निष्कर्षों ने भारत में ब्रिटिश राज्य के स्वरूप व प्रयोजनों के विषय में दादा भाई के विचार व दृष्टिकोण को धीरे धीरे गंगा शुरू कर दिया। अब निकासी पर विचार करते समय सामान्य रूप से ब्रिटिश राज्य को देवी वरदान बतलाने वाले दादा भाई एक दूसरी भाषा में ही बोलने लगे। धीरे धीरे और लगभग अपनी इच्छाओं के विरुद्ध वे यह अनुभव ही नहीं करने लगे पत्युत सार्वजनिक रूप से घोषित करने लगे कि ब्रिटिश राज्य को उपयोगी, दयालु और लोकहितकारी मानना मात्र एक भ्रम था। जैसाकि इसी अध्याय के प्रारंभिक भाग में हम निर्देश कर चुके हैं, दादा भाई के अनुसार, भारत में औद्योगिक विकास के अभाव का और भारतीयों की दरिद्रता का सारे का सारा ही दायित्व निकासी पर है और यह निकासी शासकों की दूषित नीति का ही परिणाम है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि निकासी को समक्ष रखकर सोचने पर ब्रिटिश राज्य के अन्य कल्पित लाभों, न्याय और व्यवस्था, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, विदेशी आक्रमण से बचाव तथा अकाल से बचाव, की भारतीय जनता के लिए कोई उपयोगिता थी। 1880 में उन्होंने अकाल से बचाव के लिए उठाए गए पगों पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा : भारत के शासक अपने लिए हम संबंध में किसी प्रकार का श्रेय लेने का कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि वस्तुतः इन अकालों के लिए वे ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। वे ही तो भारत की संपदा की निकासी कर रहे हैं जो परिणाम में भारतीयों के द्वार पर दुर्भाग्य भुखमरी और लाखों मौतें लाती है।¹⁹¹ न ही भारत ब्रिटिश शासन द्वारा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध जुटाई गई सुरक्षा से किसी भी प्रकार से लाभान्वित होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत के प्रवेश द्वार पर तो संतरी बनकर खड़े हैं और सारे विश्व को चुनौती देते हैं कि वे भारत की सभी बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा कर रहे हैं और करेंगे परंतु जिस खजाने की रक्षा का वे दम भरते हैं, चोर दरवाजे से उसी खजाने को चुपचाप ले जा रहे

हैं।¹⁹² स्थिति की वास्तविकता यह है कि देश की रक्षा करना तो दूर रहा, अंग्रेजी शासन तो विदेशी आक्रमण को स्थाई रूप दे रहा है, उसे बढ़ा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी संभावना में वृद्धि कर रहा है। इसके साथ ही अंग्रेजी शासन देश को समग्रतः परंतु धीरे धीरे विनाश के गड्ढे में धकेल रहा है।¹⁹³ वस्तुतः अंग्रेज निःकृष्टतम आक्रमणकारी था और भारत को इससे बुरे दुर्भाग्य का सामना कभी नहीं करना पड़ा।¹⁹⁴ जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लाभों के संबंध में दादा भाई ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

यह एक मिथ्या धारणा है कि भारत में देशवासियों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि सुरक्षा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। एक रूप में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा उपलब्ध है और वह इस प्रकार से है कि लग किसी प्रकार की हिंसा में, आपसी मार-पीट से तथा देसी निरंकुश शासकों के भय से सुरक्षित है। यह जीवन और संपत्ति की निस्संदेह वास्तविक सुरक्षा है और भारत इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने से इनकार नहीं करता, परंतु इंग्लैंड के स्वयं अपने पजे से उसे संपत्ति की किसी प्रकार की सुरक्षा सर्वथा ही प्राप्त नहीं है। फलतः जीवन की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं। जो सुरक्षित और पूर्णतः सुरक्षित है, वह है, इंग्लैंड, वह पूर्ण रूप में और समग्र रूप में सुरक्षित और सुरक्षित है तथा वह अपनी यह सुरक्षा बनाए रखना चाहता है ताकि वह वर्तमान दर पर 30,000,000 से 40,000,000 पौंड की संपत्ति प्रतिवर्ष भारत से ले जा सके और इसे हजम कर सके।...इसलिए मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि भारत को संपत्ति और जीवन की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इतना ही नहीं, उसे तो जान और बुद्धि की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है। भारत में लाखों करोड़ों लोगों के लिए तो जीवन का केवल यही अर्थ है, आधे पेट खाना नमीब होना, अथवा भूखी मरना अथवा दुर्भाग्य का सामना करना अथवा रोगों में जूझना।¹⁹⁵

कानून और व्यवस्था के संबंध में 1876 में दादा भाई ने लिखा :

एक भारतीय कहावत है कि 'किसी की पीठ पर भले ही लात मारो परंतु किसी के पेट पर कभी लात नहीं मारनी चाहिए'। देसी निरंकुश शासन में लोग अपने उत्पादन को सुरक्षित रख सकते थे और उनका उपभोग कर सकते थे। यह दूसरी बात है कि इसके पीछे उन्हें कभी कभी हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। ब्रिटिश निरंकुश शासन में लोगों को शांति तो प्राप्त है, हिंसा का अस्तित्व नहीं है परंतु उसका कोष शांतिपूर्वक, अनदेखे रूप से और चालाकी के साथ लूटा जा रहा है। अब भारतीय कानून और व्यवस्था के अंतर्गत शांतिपूर्वक भूखा मरता है और शांतिपूर्वक ही मृत्यु का ग्रास बनता है।¹⁹⁶

उन्होंने इसके साथ आगे कहा : मैं नहीं कह सकता कि अंग्रेजों की ऐसी स्थिति के बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी।

निकासी सिद्धांत ने भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को समझने की दिशा में उन पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार-उन्होंने अपने निबंध, 'दी पावर्टी आफ इंडिया' के लगभग निष्कर्ष के रूप में ही लिखा : निकासी के कारण सारा ही शासन

चक्र एक मलत, अप्राकृतिक और आत्मघाती दिशा में घूम रहा है।¹⁹⁷ 12 फरवरी 1895 को हाऊस आफ कामन्स में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत वास्तव में ब्रिटिश भारत ही था, भारत का भारत नहीं।¹⁹⁸ उन्होंने और आगे कहा, एक प्रकार से तो विपुलसंख्यक भारतीयों की स्थिति दक्षिणी राज्यों के दासों की स्थिति से भी बहतर है। '...दास मालिकों की भूमि पर और मालिकों के साधनों से काम करते हैं। मालिक उनके केवल श्रम का ही लाभ उठाते हैं, इसके विपरीत भारतीय अपनी ही धरती पर और अपने ही साधनों से काम करते हैं, इतने पर भी उन्हें अपने लाभ विदेशी मालिकों को सौंप देने पड़ते हैं।'¹⁹⁹ इसी प्रकार 31 जनवरी 1897 को लार्ड विलबी को लिखे अपने एक पत्र में दादा भाई ने बकालत की, वे (ब्रिटिश नागरिक) हमें मित्र नागरिक कहते हैं, उन्हें अपने इस कथन को अवश्यमेव यथार्थ का रूप देना चाहिए। इस समय तो सत्य की बजाय यह एक निरा भूठ और भद्दा मजाक है, इस समय तो दोनों का नाता दाम और स्वामी का ही है।²⁰⁰ दादाभाई यह देखकर आश्चर्य चकित रह गए कि उपकार के नाम पर ब्रिटिश ने शोषण का यह कैसा भ्रमजाल फैला रखा है। देश का शोषण ब्रिटिश राज्य द्वारा इंग्लैंड में किया जा रहा है कि देखने में न किसी प्रकार का दबाव खुले रूप में सामने आता है, न किसी प्रकार से जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, जिससे कि मसाले इम लूट को देख पाए और इस पर कांप उठे।²⁰¹ उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय खच्चों के इस चालू अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य भारत का उपकारी होने का ढोंग करता है। सत्य यह है कि ब्रिटिश राज्य भारत का हित करना तो दूर रहा, उमका खून ही चूम रहा है।²⁰² 1904 तक दादाभाई भारत में ब्रिटिश राज्य के वर्णन-प्रसंग में कटु और कठोर शब्दों का ही प्रयोग करने लगे थे। अगस्त 1904 में हेग में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में दादाभाई ने ब्रिटिश राज्य को 'असभ्य' बतलाया। उनके द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्द थे :

'असभ्यता' शब्द का क्या अभिप्राय है ? क्या इसका अर्थ यह है कि यदि एक क्रूर व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति को पिटाई करता है और उसे लूट लेता है तो उसका यह दूषित कर्म असभ्यता है ? यही बात राष्ट्रों पर ही लागू होती है, और इसी ढंग का प्रयोग ब्रिटेन भारत के प्रति कर रहा है। इसका अंत अवश्य ही होना चाहिए।

पशु शक्ति का साम्राज्य असभ्यता ही है।²⁰³

निकासी सिद्धांत ने एक अन्य रूप में भी दादा भाई के चिंतन को गहरापन दिया, धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रवादियों की इस परंपरागत धारणा पर अविश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि भारत में जो कुछ भी गलत काम होता है, उसका सारा दोष भारत में रहने वाले स्वार्थी और भारतीय अधिकारियों को अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करने को विवश करने वाले अंग्रेज अधिकारियों का है। विलबी कमीशन के समक्ष जिरह में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की बुरी कार्य प्रवृत्ति को नहीं प्रत्युत सरकार की गंदी पद्धति अथवा मशीनरी को ही निकासी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार उन्होंने कहा :

मेरा सामान्य प्रहार सरकारी अधिकारियों पर नहीं, प्रत्युत उस बुरी व्यवस्था

पर है, जिसके अंतर्गत उन्हें काम करना पड़ता है। उन्हें विवश होकर वह सब कुछ करना पड़ता है जिसका परिणाम ही असंतोषप्रद है।...बुरी व्यवस्था के ही ये कारण हैं, जिनके अंतर्गत वे कार्यरत हैं और जिस पर विचार करने और जिसके संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक ढंग से अपना कार्य कर सकें...।²⁰⁴

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां निकासी-सिद्धांत में दादाभाई ब्रिटिश राज्य की प्रवृत्ति को ममभले में सफल हुए, वहां कुछ एक अन्य नेताओं ने इस सिद्धांत का उपयोग ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को नंगा करने में किया। उदाहरणार्थ 9 जून 1900 के अपने अंक में 'अमृत वाजार पत्रिका' ने निकासी-सिद्धांत के समर्थन में इस आधार पर आवाज उठाई कि इसमें 'गोरे आदमी के कंधे पर भार' के सिद्धांत का प्रत्यक्ष खंडन होता है :

हमें सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य धारणा यह है कि इंग्लैंड को कभी भारत में बलपूर्वक खिराज नहीं लेना चाहिए। इंग्लैंड में तो यह विश्वास जम चुका है कि अंग्रेजों का काले भारतीयों का भार उठाना पड़ता है परंतु वे भारतीयों को अपना भार कभी नहीं उठाने देते। ब्रिटिश सरकार तो यह कभी नहीं मानेगी कि वह एक कौड़ी भी इस देश से ले लेती है, परंतु यदि यह दिखाया जा सके कि इंग्लैंड केवल भारत में खिराज ही नहीं लेता प्रत्युत बहुत भारी खिराज वसूल करता है तो अंग्रेजों को यह मानना पड़ेगा कि उन्हें अपनी अमहाय तथा पराश्रित प्रजा की हानि की पूर्ति के लिए कुछ-न-कुछ करना पड़ेगा।

निकासी के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करते रहने के उपरान्त भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रवृत्ति, चरित्र और उद्देश्यों के संबंध में निर्धारित धारणा ने उन्हें राजनैतिक युद्ध के मार्ग पर अग्रसर होने को बाध्य कर दिया। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने अत्यंत हल्की मांगों को प्रस्तुत करने के साथ ही अपना राजनैतिक जीवन प्रारंभ किया था, धीरे-धीरे एक वर्ष से दूसरे वर्ष और एक स्तर से दूसरे स्तर पर अपनी राजनीति और राजनैतिक मांगों में उत्तरोत्तर अतिवादी वनता गया।

प्रशासनिक नेवाओं के संकीर्ण क्षेत्र में दादाभाई ने भारत सरकार के यूरोपीय कर्मचारियों को 'जोक' बतलाया।²⁰⁵ और 1885 के प्रारंभ में ही उन्होंने माग पेश की कि नियंत्रण तथा अधीक्षण का उच्चतम अधिकार ही केवल अंग्रेजों के हाथ में रहना चाहिए तथा अन्य सभी नेवाओं की प्रबध व्यवस्था भारतीयों को सौंप देनी चाहिए।²⁰⁶ 1897 में उन्होंने अपनी माग का और अधिक स्पष्ट विश्लेषण किया तथा दृढ़ता से कहा कि केवल वायमराय, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल के पद ही अंग्रेजों के हाथ में रहने चाहिए।²⁰⁷

क्रांतिकारी मांगों को पेश करने में अथवा ऊंचे राजनैतिक स्तर के नारे देने में दादा भाई ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और प्रारंभ में निकासी समाप्त न करने की स्थिति में गंभीर परिणामों की चेतावनी देने के रूप में अपने नकारात्मक अतिवाद को प्रकट किया। हां, धीरे-धीरे परंतु अलक्षित रूप से इन चेतावनियों ने प्रत्यक्ष राजनैतिक नारों और मांगों का रूप अवश्य ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। 1880 में ही दादा भाई ने

ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी भारत के अतीत के शासकों के साथ तुलना न करने के लिए सबरदार किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश अपने आपको उच्च ज्ञान और श्रेष्ठ सम्यता के अनुपात में पर्याप्त श्रेष्ठ सिद्ध नहीं करते और यदि भारत उनके अधीन व्यापक प्रगति और समृद्धि प्राप्त नहीं करता, तो भारत में उनके टिके रहने में कोई औचित्य नहीं। इसके अतिरिक्त पिछली निकासी को दुर्भाग्य मानकर भले ही भुला दिया जाय और क्षमा कर दिया जाए परंतु एक बार मामला साफ हो जाने पर भविष्य में की जाने वाली इस प्रकार की निकासी को तो सीधी सादी भाषा में डकंती और विध्वंस ही कहा जाएगा।²⁰⁸ 1896 में उन्होंने टिप्पणी की कि यद्यपि भारतीयों को अब भी ब्रिटिश जानत के स्वस्थ अंत करण में पक्का विश्वास है परंतु वर्तमान व्यवस्था का परिणाम भारतीयों को इस निष्कर्ष पर पहुंचा देगा कि भारतीयों के सामने अपने वर्तमान प्रशासकों से पिंड छुड़ाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।²⁰⁹ और फिर 'यदि निकासी जारी रही तो ब्रिटिश शासन भी एक विदेशी निचोड़ने वाली क्रूर शक्ति बना रहेगा, जिस के फलस्वरूप जनता यूरोपीय शासकों से मुक्त होने को उत्कण्ठित रहेगी।'²¹⁰ 'असंतोष के कारण' पर लार्ड बिलबी को लिखे अपने पत्र में, ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी के महान उद्घोषक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में यह घोषणा करने का साहस किया था कि हमें बहादुरी से यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार हैं,²¹¹ उन्मी व्यक्ति ने पूर्वापेक्षा अधिक स्पष्ट वाणी में गर्जना की, क्या किसी भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह सोचना संभव है कि कोई एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर ले और फिर उससे वफादारी और स्नेह की आशा करे? यह मानना मानव प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा न ही आज तक कभी हुआ है और न ही कभी होगा।²¹² 1900 तक वफादार दादा भाई के मन में कदाचित् अज्ञात रूप से ही राजद्रोह की भावनाएं घर करने लगी थीं। उसी वर्ष उन्होंने शासकों को एक और चेतावनी दी, भारतीय आज तक ब्रिटिश द्वारा किए जा रहे शोषण का सहन करते आ रहे हैं और यह विश्वास करना एक भूल ही होगी कि उनकी वफादारी ढिग नहीं सकती और जिस रूप में आज है, उसी रूप में मदा के लिए बनी रहेगी।²¹³ भारतीय लोग अब स्थिति की वास्तविकता को समझने लगे हैं और यदि उनकी दशा को सुधारने के लिए कोई पग न उठाया गया तो हो सकता है कि वे शक्ति को नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने को प्रलोभित हो उठें।²¹⁴ यह तो थोड़े समय की ही बात थी, जबकि दादा भाई इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यदि निकासी को रोकना है तो भारत को अवश्य ही राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होना पड़ेगा। दादा भाई के दिल और दिमाग की ताजगी, जिन्दादिली और वीरता के लिए उनका अभिनंदन ही करना पड़ेगा कि उन्होंने 79 वर्ष की पक्की आयु में जबकि घमनियों ने रक्त प्रवाह शिथिल पड़ जाता है, ब्रिटिश के भारत पर शासन की अंतिम प्रकृति के सबंध में अपने पूर्व विश्वास से हटकर स्व-शासन की गुणात्मक छलांग लगाई।²¹⁵ 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, जिसने भारत के राष्ट्रवादी क्षेत्रों में विशेषतः उदारपंथी क्षेत्रों में यथार्थ में ही हलचल मचा दी, निकासी पर दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में दादा भाई ने अपनी राजनैतिक मान्यता को निम्न-

लिखित रूप से सुस्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी :

इसका एकमात्र उपाय भारतीयों को स्वशासन देना है। भारत के प्रति अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान ही व्यवहार अपेक्षित है। भारतीयों के इंग्लैंड के साथ संबंध अवश्य जुड़े रहें परंतु उन्हें दास बने रहने पर घोर आपत्ति है। वे अपने पर अपना ही शासन चाहते हैं तथा विश्व के अन्यान्य देशों के साथ प्रगति में भागीदार बनना चाहते हैं।²¹⁶

उनकी इस घोषणा को समाजवादी सम्मेलन के क्रांतिकारी वातावरण में उन्नेजित मन की एकाएक और जल्दवाजी में निकाली गई भड़ास नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इस कथन के एक ही वर्ष उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन को दिए गए अपने संदेश में विशेष निर्देश करते हुए सुस्पष्ट रूप से अपना दृढ़मन इस प्रकार से प्रकट किया :

स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकामी और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली घोर दरिद्रता दुर्भाग्य और विनाश से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। किसी प्रकार के कमी भी तसल्ली देने वाले उपाय क्यों न किए जाएं, प्रशामननत्र में किसी प्रकार की कमी भी रहो बदल अथवा इधर-उधर की हेर-फेर क्यों न की जाए, इनमें न तो कोई लाभ हो सकता है और न ही सर्वथा कोई लाभ होगा। स्वयं सरकार और स्वयं प्रजा ही निकासी को बढ़ा कर सकती है। भारत के दुर्भाग्य और व्यथाओं की निवृत्ति के स्वशासन ही एकमात्र उपचार है।¹¹⁷

यह याद स्मरणीय है कि ये दादा भाई ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक कलकत्ता अधिवेशन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रीय आंदोलन के भावी लक्ष्य का निर्देश करते हुए यह घोषणा की थी कि भारतीय जनता की सभी राजनैतिक मागों को जिस एक ही शब्द में समेटा जा सकता है, वह है, स्वशासन अथवा स्वराज्य, जैसा स्वराज्य इंग्लैंड में है अथवा दूसरे-दूसरे उपनिवेशों में है।²¹⁸

दादा भाई के इस अतिवादी दृष्टिकोण, निकासी भारत के दुर्भाग्य का एक महत्वपूर्ण कारण है, के राजनैतिक महत्व को भली प्रकार समझने के लिए उसकी राजनैतिक महत्ता के तथा भारत की दरिद्रता के कारण माने गए अन्यान्य तत्वों, आधुनिक औद्योगिकता का अभाव अथवा अत्यधिक भूमि लगान अथवा ऊंचे कराधान अथवा राजनैतिक अधिकारों की अनुपस्थिति, से तुलना अपेक्षित है। इनकी तुलना से पूर्व दो बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है क्योंकि उनकी उपेक्षा का अर्थ उपयुक्त परिप्रेक्ष्य से हाथ घोना होगा। प्रथम, अपने अंतिम विश्लेषण में स्वयं दादा भाई ने भी भारत में उद्योग के अभाव को ही भारत की दरिद्रता का कारण बताया। अंतर केवल यह है कि उन्होंने इस अभाव के कारण के रूप में निकासी को ही उत्तरदायी बताया। द्वितीय, भले ही इसे 'निर्धनता का औद्योगिक सिद्धांत' नाम दिया जाए, तात्त्विक विश्लेषण से तो हर हालत में ही यही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, राजनैतिक अनुमान निष्कर्ष के रूप में उभर कर सामने आता है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश उद्योग के हितों की रक्षा में ही तत्पर है तथा भारतीय उद्योग और व्यापार अपनी पूर्णता में तब तक नहीं आ

सकते जब तक कि प्रमुख रूप से भारतीय उद्योग के हितों की ही देखभाल के उद्देश्य को लेकर चलने वाला अपना ही राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं होता। फलतः 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल के और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के बहुत सारे उग्रवादी नेताओं यथा बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय और बी० सी० पाल ने भारतीय उद्योग के विकास पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रबल संघर्ष किया। इसी प्रकार भूमि लगान सिद्धांत और ऊंचे कराधान के सिद्धांत से भी समय-समय पर क्रांतिकारी राजनैतिक मार्गें उठीं। इस ग्रंथ में इन सब की चर्चा हम यथास्थान पहले ही कर चुके हैं।

निकामी तथा भारत की दरिद्रता के अन्यान्य सिद्धांतों के राजनैतिक परिणामों के बीच मुख्य अंतर इस तथ्य में निहित था कि किसी सीमा तक और कभी-कभी दरिद्रता के अन्यान्य सिद्धांत विदेशी शासन को सहन कर सकते थे परंतु निकामी सिद्धांत के बारे में यह नहीं कहा जा सकता।

उदाहरण के रूप में उद्योग के सिद्धांत को ही लीजिए, इस क्षेत्र में जहां भारत और ब्रिटेन के औद्योगिक हितों में संघर्ष के कारण बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हुए और उनमें कटुता भी बढ़ी, वहां इस कटुता के फलस्वरूप उत्पन्न राजनैतिक दुर्भावनाओं को दूर करने की दिशा में कुछ उपाय भी दिखाई देने लगे :— प्रथम, औद्योगिक सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार भारत में ब्रिटिश राज्य भारत के औद्योगीकरण के मार्ग में दुर्लभ बाधा नहीं था। वर्तमान आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ औद्योगिक विकास संभव था। अतएव औद्योगिक संघर्ष को स्वराज्य-आंदोलन के माध्यम से जोड़ने की कोई स्वाभाविक अथवा पूर्ण आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के रूप में जस्टिस रानाडे द्वारा राज्य-सहायता पर बल देने के बावजूद भारतीय उद्योग के विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं थी।²¹⁹

द्वितीय, कभी-कभी इस बात ने सारे मामले को और भी अधिक जटिल बना दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार प्रायः ही उद्योगीकरण के पक्ष में बोलती रहती थी और कभी-कभी तो स्वयं भारतीयों द्वारा प्रदर्शित उत्साह की अपेक्षा कथनी के रूप में भी औद्योगिक विकास के लिए अधिक उत्साह दिखाती थी।²²⁰ इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उद्योग के विकास के लिए 1905 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक पृथक् शाही विभाग की स्थापना और उसे सर्वोच्च महत्व देने के रूप में साधारण और नगण्य होने पर भी कुछ न कुछ पग तो उठाए ही थे।²²¹ किसी भी रूप में क्यों न हो, यह आशावादी दृष्टिकोण सदैव बना रहा कि कराधान और मंडारो, तकनीकी शिक्षा और राज्य सहायता आदि से संबंधित सरकारी नीति में भारतीयों की इच्छानुरूप ही परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि 1918 के उपरांत भारतीय उद्योग आयोग की सिफारिशों के उपरांत एक सीमित परिमाण में हुआ भी।²²² जब एक बार सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर लेती है तो उसे सतही तौर पर तो अधिक समय तक उद्योग-विरोधी घोषित नहीं किया जा सकता। उद्योग-सिद्धांत के समर्थक सदैव अपने तर्कों में जटिलता को अपनाने रहे और सदैव यह दिखाने का प्रयास करते रहे कि ब्रिटिश भारत की सरकार इस दिशा में काफी कुछ नहीं कर रही है और यदि भारत की अपनी सरकार होती तो वह इससे बहुत अधिक

ही करती। यह काम आसान नहीं था और इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ी। राजनीति में तो जब कोई भी कार्य विशेषज्ञों की सहायता से किया जाता है तो उसे जन साधारण पर प्रभाव की दृष्टि से नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। फलतः जहा भारत की निर्धनता के उपाय के रूप में औद्योगिक विकास पर अधिक बल देने की बात थी, इसे शिक्षित वर्ग को प्रभावित करने का साधन तो बनाया जा सकता था परंतु इसे जनता और सरकार के बीच राजनैतिक संबंध विच्छेद को गहरा करने का शस्त्र नहीं बनाया जा सकता था। इसके सर्वथा विपरीत सरकार, दिवाने के लिए, यह तर्क प्रस्तुत कर सकती थी कि उद्योग तो दोनों सरकार और राष्ट्रवादियों के लिए समान रूप से उद्यम का क्षेत्र जुटाता है।¹² तृतीय, उद्योग-मिद्धा के प्रवर्तकों को यह स्वीकार करना पड़ा कि जहा देश के औद्योगिक पिछड़ेपन का आंशिक आरोप ईमानदारी से ही सरकार पर लगाया जा सकता है, वहा आरोप के एक बहुत बड़े भाग के पात्र स्वयं भारतीय है, जिन्होंने स्वयं मशीन, प्रेम, उद्यम और तकनीक के उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में तत्परता नहीं दिखाई।¹³ उद्यम निष्कर्ष स्पष्ट था कि भारतीयों को अपने शान्तों पर आरोप लगाने और उनकी आलोचना करने में अपनी सारी शक्तियों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उद्यम अवश्य ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता चाहिए तथा अपनी प्रांभ को निजी प्रधान के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए।¹⁴ बहुत सारे सरकारी प्रवक्ताओं ने राष्ट्रवादियों के निजी प्रयास के दृष्टिकोण के सरकार के विरुद्ध संचालित राजनैतिक तथा आर्थिक आंदोलन को स्पष्टतः क्षीण बनाने वाला अनुभव किया और वे देश के औद्योगिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सारा दोष अपने कंधों से उतार कर स्वयं भारतीयों के ही कंधों पर डालना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उदाहरणार्थ, डफगिन ने 1888 में यह घोषणा की कि व्यापार पर लगी पाबन्धियाँ हटाकर और परिवहन के साधनों, मड़क, रेल तथा अन्यान्य यातायात सुविधाओं का बहुगुणा विस्तार करके हम उत्पाद और व्यापारिक गतिविधि को तीव्रता दे सकते हैं और इस समय भी अपनी ओर से यह सब कर रहे हैं परंतु उत्पादक केंद्रों का वास्तविक कार्य तो आखिर निजी उद्यमियों को ही करना चाहिए। इसके उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार जो काम नहीं कर पा रही, उसे करने में आप लोग पीछे क्यों रह रहे हैं?¹⁵ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से इस संबंध में एक घटना को उद्धृत करना बड़ा ही रोचक होगा। 1901 में कांग्रेस ने एक समिति का गठन इस उद्देश्य से किया कि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि क्या अगले अधिवेशन से इस प्रकार के प्रस्ताव उठाए जा सकते हैं, जिनके अंतर्गत राज्य की आर्थिक मंदी का तथा उत्पादन और वितरण के साधनों के ज्ञान के अभाव का भारी दायित्व सरकार पर डाला जा सके। इस समिति ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रसार के लिए यत्नशील बनें और इस तथ्य को स्वीकार करे कि पूँजी और साख का प्रश्न निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न है परंतु उसका हल स्वयं हमारे अपने ही हाथ में है। समिति ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे निरंतर और ईमानदारी के साथ पूँजी का संगठन करके देश की आर्थिक दशा के सुधार के मार्ग की कठिनाइयों में से एक को दूर

करने की चेष्टाएं करें।²²⁷ इन प्रस्तावों में 1890 में पूना में हुए प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में दिए गए जस्टिस रानाडे के भाषण की भावना को ही रूपायित किया जाना था। इसके उन्नायक कदाचित् लगभग तीन दशान्दियों तक कांग्रेस को सतत प्रेरणा देने वाले महानुभाव के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करना चाहते थे परन्तु ये प्रस्ताव कभी पारित नहीं हुए। हमें मीमित अथवा कांग्रेस द्वारा की गई इन प्रस्तावों की अस्वीकृति का कारण ज्ञात नहीं। हा, यह अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि ये प्रस्ताव यदि उठाए गए तो सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी दबाव के लिए निरंतर और क्रमशः बनाए जाने वाले वातावरण के प्रमुख लक्ष्य से हटकर राष्ट्रवादी शक्ति बिखर जाएगी। अतः कांग्रेस ने अपने नकारात्मक, अरचनात्मक और आदोलनात्मक पक्ष को ही अपनाए रखा। उसने देश की दरिद्रता के लिए निम्नलिखित तत्वों पर अभियोग लगाना ही जारी रखा। स्वदेशी उत्पादनों का ह्रास, सपदा की निकासी, अत्यधिक कराधान, अत्यधिक महंगा प्रशासन, तथा भूमि के भारी लगान,²²⁸ जिन सबके लिए अकेले सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन और उसकी कुछ आर्थिक नीतियां तथा इस विश्वास को कि भारत की आर्थिक दुर्बलता का अर्थात् औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण प्रमुख रूप से भारतीयों की अपनी ही दुर्बलताएँ थी, तथा 'निजी प्रयत्न' से इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, स्वीकार करने का यह परिणाम निकला कि औद्योगिक सिद्धांत ने भारतीय अर्थशास्त्रियों के एक आशावादी वर्ग को जन्म दिया और कम से कम प्रारंभ में तथा कुछ समय तक कोमल नीतियों के लिए आर्थिक सैद्धांतिक आधार का काम किया।²²⁹

इसी प्रकार यहाँ तक कि सरकार की मूराजस्व नीति का एक अतिवादी आलोचक भी भूमि लगान में कटौती कर देने से अथवा भविष्य में किसी प्रकार की वृद्धि न होने से अथवा यहाँ तक कि अपने मतव्य में सरकार द्वारा कपटपूर्ण ढंग में अतिशयोक्ति दिखाने पर सतोष कर लेता था जैसा कि 1901 में आर० सी० दत्त के मामले में कर्जन ने भूमि लगान पर अपने प्रस्ताव द्वारा किया। सरकार भी कराधान और व्ययों के इन समीक्षकों को इधर-उधर सीमित परिमाण में थोड़े बहुत कर भार को घटा कर तथा किसी लोक कल्याण अथवा विकास की गतिविधि अथवा विभाग में सरकारी खर्चों को बढ़ाकर थोड़ा-बहुत प्रसन्न कर सकती थी। रेलों की आलोचना जो पहले कितनी भी न्यायसंगत क्यों न हो, अब रेलों के उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हो जाने से क्रमशः धीरे-धीरे मद पड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजनैतिक प्रगति की मार्गों से उत्पन्न अतिवादिता को भी थोड़े-से प्रयत्न से सावधानी के साथ संगणित राजनैतिक रियायतों और सुधारों की खुराकें देकर शांत किया जा सकता था। किसी भी स्थिति में भारतीय राष्ट्रवादी फिर भी तर्क कर सकते थे और यह सिद्ध कर सकते थे कि इन सभी मामलों में और साथ ही साथ विदेश-व्यापार, मुद्रा तथा श्रम आदि के मामले में ब्रिटेन की आर्थिक नीति स्वार्थपूर्ण और भारतीय हितों के विरुद्ध थी। इस विषय में सरकारी तर्कों और बहानों के भ्रम जाल को उखाड़ने तथा वास्तविकता को देखने के लिए एक निश्चित परिमाण में राजनैतिक तथा आर्थिक सूक्ष्म दृष्टि अपेक्षित थी। यह सूक्ष्म दृष्टि नेताओं को भले ही प्राप्त हो,

परन्तु जनता को इस सूक्ष्म दृष्टि से परिचित कराना असंभव नहीं तो कठिन और लंबा कार्य अवश्य था।

निकासी-सिद्धांत के योद्धा दादा भाई नौरोजी ने और उनके साथी योद्धा 'अमृत बाजार पत्रिका' ने निकासी के अतिरिक्त अन्यान्य सिद्धांतों के राजनैतिक संघर्ष की प्रबलता को मद करने की भूमिका को अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए तो दादा भाई ने 1900 में भारत के नवयुवकों को भारत की दरिद्रता के लिए प्रस्तुत कारणों, स्वदेशी उद्योगों का हल्ला तथा ऊँचे भूमि लगान आदि, बहानों से सावधान रहने और बचने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सब मूल समस्या से ध्यान हटाने की एक चाल है। उन्होंने आगे कहा जब तक भारत का खून चूसना (निकासी) जारी है, भारत संपन्नता की कोई आशा कभी नहीं कर सकता।²³⁰ दादा भाई के जीवनी लेखक आर० पी० मसानी के अनुसार दादा भाई ने 1903 में आर० सी० दत्त को चेतावनी दी थी कि उनका भूमि लगान पद्धति के दोषों पर अधिक बल देना भारत की दरिद्रता के मूल कारण निकासी और उसके एकमात्र उपचार-स्वशासन में जनता का ध्यान हटाना है।¹ इसी प्रकार 'अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 9 जून 1900 के अंक में टिप्पणी की कि यह स्पष्ट है कि भूराजस्व भारत की दरिद्रता का कारण है परन्तु निकासी की अपेक्षा इस पर अधिक बल देना फिर भी गलत है। 'ऊँचे लगान के प्रश्न को उठाना फिर भी विवादाम्पद हो सकती है परन्तु वार्षिक निकासी पर तो किसी प्रकार के विवाद की संभावना ही नहीं।'²³² 28 मार्च 1901 के अंक में पत्रिका ने यह आशंका प्रकट की कि दल महाशय लगान के प्रश्न को उठाकर एक गौण विषय को महत्व दे रहे हैं, वे देखेंगे कि वे तर्कजाल में उलझ कर रह गए हैं। पत्रिका ने मलाह दी कि इस समय आवश्यकता उन निश्चित और सुस्पष्ट विषयों को उठाने की है, जिन पर हम दृढ़ता से बट सकें और अपनी बात स्पष्ट कर सकें।'²³³

औद्योगिक-सिद्धांत आदि के सर्वथा विपरीत निकासी सिद्धान्त ने देखा भारत की दुर्दशा के कारणभूत आर्थिक रोगों का मूल उद्गम स्वयं ब्रिटिश राज्य ही है। इसने बिना किसी मनाच के ब्रिटिश भारतीय सरकार की विदेशी प्रकृति तथा उसके शोषक स्वरूप को नंगा करके रख दिया। अपनी परिभाषा में ही निकासी समग्रतः ब्रिटेन के शासन का ही परिणाम था और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भारत की दरिद्रता का सारा दोष ब्रिटेन को अपने कंधों पर लेना ही चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार इस स्थिति में भारतीय निकासी को कम करने की दिशा में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो कुछ उनके बस में था, वह था भारतीयकरण के लिए, ब्रिटिश और भारत के मध्य खर्चों के समुचित बटवारे के लिए, गृह प्रभारों में कटौती आदि के लिए आंदोलन करना। इसके अतिरिक्त निकासी-सिद्धांत के पक्षधर केवल इतना ही नहीं मानते थे कि जब तक निकासी जारी है तब तक भारत आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता और इतना ही तर्क नहीं देते थे कि निकासी में सारे का सारा ब्रिटेन का दोष है, प्रत्युत इसकी परिभाषा देते हुए इसे ब्रिटिश राज्य और उसकी मूल आर्थिक और राजनैतिक नीतियों, संस्थाओं और अवस्थापना, जैसेकि, ब्रिटिश इंडियन सिविल सेवा, ब्रिटिश सेना, इंग्लैंड में भारतीय

कार्यालय, ब्रिटेन की पूंजी का भारत में निवेश, रेल, विदेश व्यापार, भूमि लगान और सामान्यतः कराधान का पर्यायवाची बताया और लोगों के मन में उन्होंने धीरे-धीरे यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और दरिद्रता का कारण प्रमुख रूप से स्वयं ब्रिटेन के शासन का भारत में अस्तित्व और विदेशी राज्य की नीतियां हैं। वही देश की उन्नति के मार्ग में प्रधान बाधाएं हैं। भारत परंपरा से दरिद्र नहीं है प्रत्युत स्वयं ब्रिटिश राज्य द्वारा बनाया गया है। सिविल सेवा के यूरोपीय चरित्र पर बल देने से भी वही राजनैतिक उद्देश्य सिद्ध होता था क्योंकि इसमें एक ओर तो जनता के सामने देश की राजनैतिक और आर्थिक पराधीनता के तथ्य को सामने रखने में सहायता मिलती थी और दूसरी ओर इससे इम मांग को बल मिलता था कि भारत में ब्रिटिश राज्य अवश्य बना रहे परंतु स्वयं ब्रिटिश लोगों को नहीं बना रहना चाहिए। स्पष्ट है कि इस मांग की स्वीकृति की कोई संभावना नहीं थी, फलतः इससे शासकों के विरुद्ध जनता के मन में रोष की भावना को भड़काने में सहायता मिलती।

इस प्रकार निकासी सिद्धांत ने एक जटिल समस्या को जन्म दिया और उस समस्या का एक ऐसा हल सुझाया कि जिससे भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ें ही कट जाती थी, और एक ऐसे श्रंतविरोध को उजागर किया जिससे अतिवादी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उदगम होता था, भारत सरकार और जनता के मध्य स्थायी रूप से राजनैतिक मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न होती थी और अंततः ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने की क्रांतिकारी राजनैतिक मांग को जन्म मिलता था। निकासी सिद्धांत के समर्थक तो राजनैतिक सुधारों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे क्योंकि इन सुधारों से निकासी किसी प्रकार कम होने वाली नहीं थी। अतः राजनैतिक सुधारों के किए जाने पर भी निकासी पर आधुनिक राजनैतिक संघर्ष में कमी नहीं होने जा रही थी।²³¹ इसके अतिरिक्त निकासी सिद्धांत ने भारतीय समाज के सभी आंतरिक भ्रगटों को पीछे धकेल दिया तथा सारे समाज का ध्यान विदेशी राज्य की देन निकासी की ओर ही समग्रतः केंद्रित कर दिया। इस प्रकार दादा भाई के आर्थिक दृष्टिकोण के निराशावादी चरित्र ने 1872 में प्रारंभ में स्वीकार करने के उपरांत अंत में उसे छोड़ने को विवश रानाड़े के आशावादी दृष्टिकोण की तुलना में, उन्हें विनाश का भविष्य-वक्ता बना दिया और 1904 में उस समय निश्चित रूप से नकारात्मक व निराशाजनक लगने वाले स्वराज्य के लिए आह्वान देने के योग्य बना दिया।

निकासी-सिद्धांत के क्रांतिकारी राजनैतिक अभिप्रायों से इसके समर्थक ही नहीं प्रत्युत आलोचक भी कहीं अधिक बढ़-चढ़ कर परिचित थे। 1886 में भारत राज्य सचिव रंडोल्फ चर्चिल ने निर्देश किया :

‘देश पर थोपे गए विदेशी राज्य के फलस्वरूप समझे जाने वाले और देश के बाहर हुए सचों की अतिरिक्त राशि की पूर्ति के लिए समग्रतः भार रूप में उठाए जाने वाले नए कराधान के भार का अधीरता एक गंभीर राजनैतिक सतरे का रूप धारण कर लेगी। हमें आशंका तो यह है कि भारत सरकार से संबंध अथवा उसकी जानकारी न रखने वाले महानुभाव इस सतरे की गुह्यता को समझ ही नहीं पाएंगे, परंतु जिनको भारत सरकार की जानकारी है और जिन पर उसके संचालन का दायित्व

है, उन्होंने बहुत पहले से ही इसे एक अत्यंत गंभीर प्रकृति का खतरा बताया है।²³⁵ इसी प्रकार जे० डी० रीस ने अपनी पुस्तक 'दि रियल इंडिया' में दादा भाई को बाढ़ें हाथों लिया कि उन्होंने इस तथ्य को समझा ही नहीं कि गृह-प्रभारों के बिना भारत में ब्रिटिश सरकार रह ही नहीं सकती थी।²³⁶ बहुत सारे भारतीयों ने निकासी सिद्धांत के प्रचंड प्रचार का इस आधार पर विरोध किया कि यह देर अंबेर राजनैतिक स्वतंत्रता की अपरिपक्व मांग को जन्म देगा।²³⁷ इसी कारण कदाचित् रानाडे ने निकासी पर आवश्यकता से अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति का विरोध किया।

संक्षेपतः निकासी सिद्धान्त अपने राजनैतिक आशयों में क्रांतिकारी तत्त्व था; इसने राजनैतिक अधिकार के प्रश्न को राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। इसकी स्वीकृति ने न केवल ब्रिटेन और भारत के स्वाभाविक राजनैतिक मघर्ष को सतह पर ला दिया प्रत्युत ब्रिटेन के भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व को भी अमान्य बना दिया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि कथो अन्यान्य कितने ही क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों द्वारा की गई ब्रिटिश की अर्थ-नीति की आलोचना और उसके फलस्वरूप उन राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा मुझाए गए उपचार तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल श्रद्धालुओं को भी स्वीकार्य थे, परन्तु निकासी की बात प्रबलतम क्रांतिकारियों तक को भी मान्य नहीं थी।

निकासी सिद्धान्त ने आर्थिक प्रश्न को राजनैतिक स्तर पर उठाकर सार्वजनिक जीवन को राजनैतिक प्रशिक्षण देने में भी सहयोग दिया। जहां अन्यान्य आर्थिक प्रश्न कदाचित् आर्थिक उपचारों द्वारा साध्य थे अतः विशेष परिस्थितियों में आर्थिक विवाद की परिधि में ही आते थे, वहां निकासी का हल केवल राजनैतिक था। अतः निकासी सिद्धान्त ने राजनैतिक निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने में भी योगदान दिया।

निकासी सिद्धांत में सर्वसाधारण लोकप्रिय बनने की प्रबल राजनैतिक क्षमता थी। यह एक ऐसी सरल और सीधी सादी धारणा थी कि जिसे एक किसान भी आसानी से समझ पाता था। राष्ट्रवादी वक्ता निकासी पर भाषण करते समय अपने अत्यंत अशिक्षित श्रोताओं से भी शीघ्र समझ जाने की प्रतिक्रिया पा लेते थे। एक देश से दूसरे देश को धन का स्थानांतरण, आर्थिक शोषण के सिद्धांतों का एक ऐसा विषय था, जिससे संवत्सा आसानी से समझा जा सकता था, क्योंकि यह उनके दैनिक अनुभव से संबंधित था। निकासी पर प्रहार को सुनते समय किसान इस प्रकार अनुभव करता था जैसे कि धन उसकी जेब से खिसक रहा है। उन्हें इस जैसा और कोई विचार इतना क्षुब्ध नहीं कर सकता था कि उन पर इसलिए कर लगाए जा रहे हैं कि दूर देश में रहने वाले गुलछरें उठा सकें। अतः निकासी में किसानों के देश को सघटित करने के नारे की सामर्थ्य थी। 'निकासी नहीं' एक ऐसा नारा था, जिसकी सभी सफल क्रांतियों को आवश्यकता रही है और वे इसे अपनाती रही हैं। इसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के ऊंचे और जटिल तर्कों की आवश्यकता नहीं, इसके बदले स्वतः स्पष्टता तो इसका आंतरिक गुण है। भारत के विषय में यह स्वतः सिद्ध थी और इस विश्वास ने कि भारत सोने की चिड़िया थी और धीरे धीरे उसकी सारी संपदा लूट ली गई है और उसे आज की दरिद्रता और दुर्भाग्य की स्थिति में ला फेंका गया है, जब भारतीय राष्ट्रीयतावाद चरम सीमा पर ही लटक रहा

था, उस समय उन वर्षों में राष्ट्रवादियों की शिकायतों ने अत्यंत लोकप्रिय और प्रबल शक्तिशाली रूप ग्रहण कर लिया। अतः यह आकस्मिक नहीं था कि निकासीवादी पर सरकारी और साथ ही साथ गैर सरकारी ब्रिटिश लेखकों ने पूरी शक्ति और निरंतरता के साथ तीखे प्रहार किए। संभवतः ऐसा भाग्य किसी भी अन्य सिद्धांत अथवा माग का नहीं रहा। इस सिद्धांत के प्रमुख जन्मदाता और प्रचारक दादा भाई नौरोजी की, जिनकी ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी सबसे गहरी थी और जिनका ब्रिटिश जनता में सबसे गहरा विश्वास था, स्वप्नदर्शी और अतिवादी रूप में निंदा की गई।²³⁸ यहाँ तक कि उन्हें धूर्त और छिपा विद्रोही कहा गया।²³⁹ परंतु दूसरी ओर गांधीयुग के राष्ट्रीयता की दृष्टि से उग्र विचार वाले नवयुवकों ने 19वीं शताब्दी के रानाडे, फिरोजशाह मेहता और गोखले जैसे अत्यंत कोमल और समझौतावादी नेताओं को थोड़े समय के लिए ही सही, घृणा की दृष्टि से देखा और उन्हें 'अर्जोन्वीस' कहकर उनका तिरस्कार किया। गांधी युग के राष्ट्रीय प्रेमी नवयुवकों की दृष्टि में उस समय भी दादा भाई अत्यंत सम्मानित थे और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के पिता के समान आदरणीय थे।

संदर्भ

1. नौरोजी, एसेज, पृ० 26-50.
2. वही, पृ० 29-31.
3. वही, पृ० 32-3. दादाभाई ने इस भेद को भी उजागर किया कि 20 वर्ष से भी काफी पहले भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों पर विचार करने के लिए कुछ थोड़े से हिंदू विद्वार्थी और विचार-शील लोग गुप्त रूप से बैठकें किया करते थे उनकी शिकायतों के प्रमुख भग थे : गृह प्रभार, विभिन्न रूपों में भारत में इंग्लैंड को संपत्ति का निष्कासन, भारत के संपूतों को अपने ही देश के प्रशासन में योगदान देने तथा विचार अभिव्यक्त करने की सुविधा का अभाव आदि. (वही) वास्तव से इससे बहुत पहले ही 1830 के आसपास भारत द्वारा इंग्लैंड को दिए जाने वाले उपहार-शुल्क के विरुद्ध राजाराम मोहन राय ने शिकायत की थी (बी० बी० मजूमदार : पूर्वोद्धृत, पृ० 71-2 पर)
4. नौरोजी, एसेज, पृ० 39 और देखिए पृ० 40-1 भारत के ससाधनों के विकास के इस विचार को दादाभाई नौरोजी के परवर्ती विचार, 'विदेशी पूँजी के भारत में निवेश का अर्थ है भारत की संपदा का अपहरण' में भिन्न रूप में देखना उचित है.
5. वही, पृ० 97-111.
6. वही, पृ० 112-36.
7. वही, पृ० 123
8. वही.
9. वही, पृ० 98-9, 108, 123.
10. वही, पृ० 133-4.
11. वही, पृ० 135-6.

12. वही, पृ० 102,
13. वही, पृ० 106.
14. नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 164.
15. वही, परिशिष्ट, पृ० 165 इसके साथ ही उन्होंने इस प्रवाह के हानिकारक परिणामों की चर्चा की : 'जहां तक इस समय में जांच पड़ताल कर सका है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस किसी प्रदेश पर अपना अधिकार करती थी, दरिद्रता भी उनके पद चिह्नों पर चलती हुई उस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेती थी' जब मैं सिवाई के लिए, रेल पथों के लिए, तथा अन्य लोक कार्यों के लिए श्रृंखला अमरीका के साथ युद्धों के लाभों की की दुर्लभ प्राप्ति लौट कर आई है तब से ऐसा लगना है कि भारत ने जो रक्त गवाया उसकी कुछ ही बूंदें लौटी हैं. (परिशिष्ट, पृ० 167) तथा देखिए, परिशिष्ट, पृ० 172, 181.
16. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 125.
17. 1901 में उन्होंने इस विषय पर अपेक्षाकृत अधिक सुप्रसिद्ध लेखों और भाषणों को 'पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' शीर्षक एक ही पुस्तक में संग्रहीत किया, जिसका शीर्षक स्वयं ही उनके राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण का संक्षिप्त रूप था उनके अन्य बहुत सारे लेखों, तथा भाषणों आदि को, जिनमें से उन्होंने प्रायः सभी में निकासी पर प्रहार किए हैं, 1887 में संग्रहीत किया. यह है उनके भाषणों, लेखों, निबंधों तथा प्रवचनों के संस्करण का सी० एल० पारिख तथा नटेशन ने 'नौरोजी : स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स' शीर्षक से संपादन किया है अगस्त 1904 में ऐमस्टरडम में हुई अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के समक्ष दिया गया उनका एक रोचक भाषण 'इंडिया' के 2 सितंबर 1904 के अंक में उपलब्ध है.
18. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 201
19. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 329
20. प्रधान और भागवत, पूर्वोद्धृत, पृ० 8 दुर्भाग्यवश हम इस भाषण की प्रति अथवा प्रतिवेदन को ढूँढ़ने में असफल रहे हैं, हमारे विचार में कदाचित्त कोई प्रति उपलब्ध नहीं है.
21. रानाड, एसेज, पृ० 23.
22. एम० एम०, मार्च 1873 खंड II पृ० 89-90 और देखिए पृ० 92-3
23. दत्त, स्पीचेज II पृ० 27, 47-8 61 84
24. दत्त, ई० एच० I पृ० XIII और देखिए पृ० XII.
25. वही, पृ० 420
26. दत्त, ई० एच० II पृ० XIV और देखिए पृ० 213, 344, 348, 529-9.
27. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 636-41, 683, 793-4; राय, पावर्टी, पृ० 6-8, 242, 278, 315-20, 328-29, और इंडियन फॉर्मिस, पृ० 37, मालवीय स्पीचेज, पृ० 232-3, 248-51; वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1846 पृ० 62, सी० पी० ए०, पृ० 602-07, रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 104, गोखले स्पीचेज, पृ० 15, 87-8, 908-10; जी० एस० अय्यर, विसबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18963 और ई० ए०, पृ० 59, 125. 128-9, 336-8, 357-8; एस० एन० बेंजर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 253-5, 269-70, 637, 708-11; बी० एम० मालबारी : इंडियन प्रॉब्लम (बंबई 1894) पृ० 23; 'स्टेडीज इन दि बंगाल रिनोसि (जादवपुर 1958) में अतुलचंद्र गुप्ता द्वारा संपादित. पृ० 209 पर राजनारायण बोस, आर० एन० मुधोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 41; ए० नंदी, इंडियन पालिटिक्स पृ० 124-7; 28 दिसंबर 1897 सदन की इंडियन

सोसाइटी द्वारा सम्मेलन में पारित प्रस्ताव; इंडिया, 14 जनवरी 1898; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए० पृ० 351-4, 366; सी० वाई० चिंतामणि, एच० आर० जनवरी 1902 पृ० 28-9; एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 762 और रिप० आई० एन० सी० 1904, पृ० 114; एल० एम० बोष, सी० पी० ए० पृ० 743, 750-3.

28. और देखिए ए० बी० पी०, 6 फरवरी 1880; 29 जनवरी और 18 जून, 1885; 22 मई 1892; 24 दिस० 1896; 13 फरवरी और 7 अप्रैल 1897; 22 फरवरी और 1, 8 और 9 जून 1900; 13 नव० 1901.
29. उदाहरण के लिए देखिए, साधारणी, 31 अक्तू० (आर० एन० पी० बंग०, 6 नव० 1880); मराठा, 6 फरवरी और 19 जून 1881 तथा 13 अप्रैल 1884; इंडियन स्पेंक्टेटर, 25 फरवरी (आर० एन० पी० बंब, 3 मार्च 1883); इंडियन स्पेंक्टेटर, 18 मई मिथ टाइम्स, 20 मई (वही, 24 मई 1884); समय, 30 जून (आर० एन० पी० बंग०, 5 जुलाई 1884); प्रतिकार, 22 अगस्त, (वही, 6 सित० 1884); सारस्वन पत्र, 6 सितंबर, (वही, 13 सित० 1884); पताका, 17 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1885); समय, 28 जून (वही, 3 जुलाई 1886); बगबासी, 7 अगस्त, प्रजाबधु, 6 अगस्त (वही, 14 अगस्त 1886); इंडियन स्पेंक्टेटर, 5 जुलाई 1885; भारतीय समाचारपत्रों के मत का संपादकीय सार सक्षेप, बी० ओ० आई०, अक्तू० 1887; इंदु प्रकाश, 5 सित० और ट्रिब्यून, 14 सित० (बी० ओ० आई०, अक्तू० 1887); हिंदू, 25 जून 1894, 7 जुलाई 1898; बंगाली, 13 मार्च 1897; हिंदुस्तान, 20 जुलाई, (आर० एन० पी० एन०, 27 जुलाई 1898); स्वदेशमित्र, 15 मई (आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1900); प्रभात, दिस० 1900, और राजहम, 2 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 12 जन० 1901); न्यू इंडिया, 16 सित० 1901; कासिम उल अखबार, 11 मई (वही, 16 मई 1903); हिंदू निशान, 27 मई (वही, 30 मई 1903); वृत्तान्त चिंतामणि, 14 नव० (वही, 14 नव० 1903); केसरी, 21 जुलाई (आर० एन० पी० बंब, 25 जुलाई 1903); केसरी, 9 मई (वही, 13 मई 1905). 1880 में पहले निकासी का विरोध करने वाले कुछ समाचारपत्र थे : इंदु प्रकाश, 13 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 18 दिसंबर 1875); जामे जमशेद, 23 अगस्त (वही, 26 अगस्त 1876); शुभसूचक, 15 जून (वही, 23 जून 1877); नेटिव ओपीनियन, 30 दिस० 1877 (वही, 5 जन० 1878).
30. प्रस्ताव XII.
31. आई० एन० सी० (1897, 1901, 1902 और 1904 के प्रस्ताव नं० IX, VIII (ए), III और III
32. नौरोजी, एसेज, पृ० 30-1. पावर्टी, पृ० 211, 638 तथा अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दिया गया भाषण, इंडिया 2 सित० 1904 पृ० 116; ए० बी० पी० 28 जुलाई 1870; जामे जमशेद, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 23 अगस्त, 1876); शुभ सूचक, 15 जून (वही, 23 जून 1877); समय, 28 जून (आर० एन० पी० बंग०, 3 जुलाई 1886); बगबासी, 7 अगस्त (वही, 14 अगस्त 1886); स्वदेशमित्र, त्रिचिरहित (आर० एन० पी० एम०, सित० 1887); मांस्र प्रकाशिका, 5 नव० (वही, नव० 1887); हिंदू, 29 जन० 1891. राय, पावर्टी, पृ० 251-3 विंसेंजर नाथ, एल० सी० पी० 1898 खंड XXXVII पृ० 519; बंगाली, 25 मई 1901; एच० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 709; दत्त, ई० एच पृ० 85.
33. प्रमाण के रूप में देखिए, इंडियन स्पेंक्टेटर ने अपने 5 जुलाई 1885 के अंक में लिखा : 'जाइ

कह सकते हैं कि जितना आपने हम पर कर लगा रखा है उससे दुगुना कर मुग़लों ने हम पर लगाया था उनके कराधान में क्या अंतर था, देखिए वे भारत के ही निवासी थे अथवा उन्होंने प्रत्येक रूप में भारत को अपनी जन्मभूमि के रूप में अपना लिया था कराधान, अत्याचार तथा लूटमार द्वारा वे जितना भी राजस्व वसूल करते थे, वह सारा इसी देश में खर्च होता था एक कौड़ी भी इस देश से बाहर नहीं जाती थी भले ही वह पैसा सिचाई नहरों के, लंबी दूरीवासी सड़कों के और पुलों के अथवा महलों और मसजिदों के निर्माण पर और यहाँ तक कि आतिश-बाजी और नाचने वाली मुंदरियों पर खर्च होता था, यह साग पैसा उन लोगों के पास वापस पहुँच जाता था, जिनसे लिया गया था' और देखिए, ए० बी० पी०, 18 जून 1885 राय, पावर्टी, पृ० 251-3; नौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 41, 52, ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 126; दत्त, ई० एच० I पृ० XII, 100, बाचा, सी० पी० ए०, पृ० 605, एल० एम० घाय, सी० पी० ए०, पृ० 759

34. नौरोजी, एसेज, पृ० 30, पावर्टी, पृ० 211, स्पीचेज, पृ० 238 9, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दिया गया भाषण, इंडिया, 2 मित० 1904, पृ० 116, समय, 30 जून (आर० एन० पी० बग०, 5 जुलाई 1884), मिथ टाइम्स, 20 मई (आर० एन० पी० बग०, 24 मई 1884), केमरी, 21 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1903), केसरी, 9 मई (वही, 13 मई 1905)

35. हम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चरित्रगत विशेषता थी निर्यातों में बचतें, जिमकी भारतीय नेताओं ने आलोचना की देखिए, इसी पुस्तक में विदेश व्यापार से संबंधित पाँचवा अध्याय वामनब में आवश्यक और समुचित परिणाम में आयातों से निर्यातों की अधिकता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्यातों का सरकारी तौर पर ही प्रोत्साहित किया गया था ब्रिटिश शासनकाल में व्यापार का समतुलन बनाए रखने के लिए निर्यातों को बढ़ाने का सरकारी प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख रूप से संचालक, साथ ही प्रमुख बिराधी तत्व था एक आर ना सरकारी नीति ब्रिटिश उद्योग के पोषण के लिए निर्यातों में वृद्धि करने की थी और दूसरी और आयातों के अपेक्षाकृत प्रचुरता ने आयातों पर निर्यातों की अधिकता को समुचित रूप दे दिया और इसका भुगतान समतुलन अव्यवस्थित हो गया और सरकार इंग्लैंड से ऋण लेने के उपाय को अपनाने के लिए विवश हो गई इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि इन ऋणों के भुगतान के लिए फिर और अधिक परिमाण में निर्यात करने की स्थिति उत्पन्न हो गई इस प्रकार भारत से होने वाले निर्यातों का उपयोग या तो ऋणों के भुगतान के लिए होने लगा अथवा आयातों के भुगतान के लिए इससे भारत से लाभार्हित उद्योगों और निर्यातकों के हितों का ब्रिटेन के लाभ संपन्न उद्योगों और निर्यात के हितों से सम्बंध का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था यह सम्बंध भारत से धन की निकासी पर ब्रिटिश प्रेस के और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के एक वर्ग द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रहार को स्पष्ट करता है ब्रिटिश शासन की सारी अवधि में भारत से संपत्ति की निकासी के राजनीतिक प्रभावों और परिणामों के संबंध में विभिन्न स्तर पर मतभेद बने ही रहे

36. नौरोजी, एसेज, पृ० 101, 113 4, पावर्टी, पृ० 33, 141, 198, 568-9, 574, स्पीचेज, पृ० 317-8, 323, 381-2, 665-7, परिशिष्ट, पृ० 42-3, ए० बी० पी०, 28 जुलाई 1870 और 6 फरवरी 1880; भोसानाथ चट्ट, एम० एम०, मार्च 1873, खंड II पृ० 89-90, मराठा, 25 मई 1884; सिंध टाइम्स, 20 मई इंडियन सर्वेक्टर, 18 मई (आर० एन० पी० बग०, 24 मई 1884); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 636-40, 683, 695; राय, पावर्टी, पृ० 7-8; आर० एन०,

मुघोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 40-1; ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 112-3, 125; हिंदू, 7 जुलाई 1898, न्यू इंडिया, 19 अगस्त और 16 सित० 1901; इंडियन पीपुल, 24 जुलाई 1903; दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 143, ई० एच० II पृ० 343-4, 528-9, स्पीचेज II पृ० 47-8; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 336, 338, 353, 357-8, गोखले, स्पीचेज, पृ० 87-8 एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 750, 753. और देखिए पीछे अध्याय 4 लार्ड सैलिसबरी द्वारा 26 अप्रैल 1875 के एक भाषण में की गई इस टिप्पणी का भारतीय नेताओं ने अक्सर हवाला दिया है कि 'भारत के सबंध में इस चोट का अतिरिक्त रूप में वर्णन किया जा रहा है कि वहां से बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष प्रतिदान के इतने अधिक राजस्व का निर्यात किया जा रहा है भारत में उन घबो में तो नश्वर चुभोकर वहां से रक्त निकालना ही चाहिए जहां उसका अत्यधिक समृद्ध हो गया है अथवा वह समृद्धि मात्रा में उपलब्ध है, पहले से ही, रक्त के अभाव से दुखियों निर्धनों और दुबलों को तो छुआ ही नहीं जाता (नोरोजी, पावर्टी, पृ० IX) और देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 130, 233, 288, परिशिष्ट, पृ० 13, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 708-09, दत्त, स्पीचेज II पृ० 84 और देखिए, जान स्ट्रेची, फाइनांशियल स्टेटमेंट (वित्त विवरण) 1878-9 कंठिका, 52 और रिपोर्ट आफ इंडियन कमिशन, 1880, पृ० 94.

- 37 नोरोजी, एसेज, पृ० 113-4; पावर्टी, पृ० 33, 131, 136-9, 198 स्पीचेज, पृ० 317-8, 381-2, 667. और देखिए, आर० एन० मुघोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 41 और जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 336-7
- 38 उदाहरणार्थ देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 32-33. उन्होंने कहा कि किसी देश के विदेश व्यापार की सामान्य स्थिति प्रायः यह होती है कि उसके निर्यात के बदले सदैव निर्यात के मूल्य और उसके लाभ का समकक्ष आयात होता है
39. वही, पृ० 131, 138, 196
- 40 वही, पृ० 33, 139 इसके अतिरिक्त जब बिलबी कमिशन ने उन पर यह सिद्ध करने के लिए दबाव डाला कि बताइए किम प्रकार आप यह कह सकते हैं कि निर्यातकों के लाभ भारतीय निर्यातों के वर्तमान मूल्यों से सम्मिलित नहीं किए गए हैं तो वे इसका सतोषप्रद और सशक्त उत्तर नहीं दे पाए (स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 53-4).
41. निम्न उद्धृत भणनामा में आकड़े पीछे और रुपये दोनों में दिए गए हैं, इसका कारण है यह कि दोनों के अनुपात में प्रायः भ्रंतर आता रहता था.
42. नोरोजी, एसेज, पृ० 50
43. वही, पृ० 115
- 44 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 34
45. वही, पृ० 566.
46. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 318-21.
47. वही, पृ० 667.
48. बोसो, पूर्वोद्धृत, पृ० 639-40.
49. सी० पी० ए०, पृ० 604, 606.
50. वही, पृ० 709.
51. दत्त, ई० एच० II, पृ० XIV तथा देखिए, पृ० 528-9.

52. राय, इंडियन कैमिस्ट, पृ० 37.
53. दत्त, स्पीचेज, II पृ० 21, 48, 85; ई० एच० I पृ० XII, ई० एच० II पृ० 613.
54. देखिए पीछे अध्याय-12.
55. नौरोजी, एसेज,, पृ० 47-9; दत्त, ई० एच० I पृ० XII, 263, 409, 420, ई० एच० II पृ० 115-6.
56. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 38-48; दत्त, ई० एच० I पृ० 408-20 ई० एच० II, पृ० 116, 123-6, 140, 213-4; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 330-4.
57. दत्त, ई० एच० II, पृ० 127.
58. विचारहीन भूतकालीन निकासी को हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं परंतु इसी प्रकार के भविष्य को हम सीधी सादी अंगरेजी में जानबूझकर डाला गया डाका और जानबूझकर किया गया विध्वंसमानते हैं (नौरोजी, पावर्टी, पृ० 218).
59. इस प्रकार उदाहरण के रूप में दादाभाई नौरोजी ने 1880 में शिकायत की कि भारत पहले शासक शिकार की खोज में इधर-उधर भटकने वाले कसाई थे. अंगरेज शासक अपने वैज्ञानिक नशतर मं दिल चीर-फाड़ कर रख देते हैं परंतु आश्चर्य यह है कि कहीं घाव का चिन्ह दिखाई देने को नहीं रहने देते और शीघ्र ही मम्यता की प्रगति की बड़ी बड़ी बातों आदि के पलस्तर से घाव को भरहमपट्टी कर देते हैं (पावर्टी पृ० 211). इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 14 अप्रैल 1881 के प्रक में शिकायत की कि विभिन्न दल विभिन्न रूपों में भारत का शोषण कर रहे हैं और आश्चर्य यह है कि वे विभिन्न दल न तो एक दूसरे के ठिकाने की और न एक दूसरे की कार्यवाहियों की जानकारी रखते हैं. वे तो यह भी नहीं मानते कि उनकी इन कार्यवाहियों से उनका रोबी किस विषम और अमरुत वेदना का शिकार बन गया है.
60. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 123, 135-6, 183-4, 565-6, स्पीचेज, पृष्ठ 134, 153, 287, 597, 614, परिशिष्ट, पृ० 3-6, 43; अमृत बाजार पत्रिका, 28 जुलाई 1870, 6 फर० 1880; मराठा, 6 फरवरी 1881, 20 दिस० 1885; वाचा, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 62, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 29, सी० पी० ए०, पृ० 605-07; ट्रिब्यून, 14 सित० (बी० ओ० आई० अक्टू० 1887); मालवीय, स्पीचेज, पृ० 232-3, 248-51, 514-5; राय, पावर्टी, पृ० 6, 318, 325-6; बंगाली, 19 जन० 1895; एस० एन० बेंजर्जी, सी० पी० ए० पृ० 269-70, 711; आर० एम० सयानी, एल० सी० पी० 1897 खंड XXXVI पृ० 191 और सी० पी० ए० पृ० 366; जी० एस० अय्यर, विलबी कमिशन, खंड III प्रश्न 18638; ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स पृ० 124; दत्त, ई० एच० I पृ० 410, ई० एच० II पृ० XIV-XV, 613; सी० वाई० चिंतामणि, एच० आर० जनवरी 1902 पृ० 28; एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 77; आई० एन० सी० 1903 का प्रस्ताव सं० II (सी).
61. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 123, 135, 183; स्पीचेज, पृ० 196, 339, 391.
62. (बस दिया गया) नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 115.
63. देखिए पीछे अध्याय 3.
64. देखिए आगे तथा साथ ही पीछे अध्याय 3.
65. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 38, 565, स्पीचेज, पृ० 596 और परिशिष्ट, पृ० 6; भोलानाथ चंद्र, एम० एस०, खंड II (मार्च 1873) पृ० 92; ए० बी० पी०, 28 जुलाई 1870, और 6 फरवरी 1880; मराठा, 6 फरवरी 1881; और 13 अप्रैल 1884; इंडियन स्पेक्टेटर, 25 फरवरी (आर०

- एन० पी० बंब, 3 मार्च 1883); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 618, 637-8; राय, पावर्टी, पृ० 6, 318-21; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 254; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 366; हिंदुस्तान, 20 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 27 जुलाई 1898); स्वदेशमित्रन, 15 मई (आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1900); बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 605; दत्त, स्पीचेज II पृ० 84, ई० एच० I पृ० XIII. ई० एच० II, पृ० XIV-XV, 127, 215, 613; केसरी, 21 जुलाई (आर० एन० पी० बब 25 जुलाई 1903); एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 752-3
66. 1902-03 में गृह प्रभारों की राशि 17, 700,000 पौड थी और इसका वितरण निम्नलिखित रूप से किया गया था; रेल पथ राजस्व खाता, 6, 500, 000 पौड; ऋणों का सूद और उनकी संचालन व्यवस्था, 2, 800,000 पौड; भंडार, 1, 800,000 पौड सेना के प्रभावी खर्च 1,300,000 पौड, नगर प्रशासन, 400,000 पौड; पनडुब्बों, 200,000 पौड; नगर तथा सैन्य सेवा के कर्मचारियों की पेशनों और अवकाश भत्तों पर होने वाले अप्रभावी खर्च 4,700,000 पौड इंपीरियल गेजेटियर आफ इंडिया (1908) खंड IV पृ० 194.
67. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 319-20; 397. परिशिष्ट पृ० 3; राय, पावर्टी, पृ० 315-6; दत्त: इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 143, सी० पी० ए०, पृ० 490, स्पीचेज II पृ० 47 ई० एच० I पृ० XIII ई० एच० II पृ० XV-XVI, 215-20, 373-5; ए० नंदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 113; एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 76; जी० एम० अय्यर, ई० ए०, 353. रेलवे के लिए देखिए पीछे अध्याय स० 5 भंडारों के लिए देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 35, 37; ए० बी० पी०, 14 अप्रैल 1881 और 17 अप्रैल 1884; राय, पावर्टी, पृ० 317. भारत सचिवालय के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के लिए देखिए पीछे अध्याय 12.
68. देखिए इसी पुस्तक के अध्याय 3 की पाद टिप्पणी में उद्धृत भारतीय नेता और ए० बी० पी०, 6 फरवरी 1880; पताका, 17 जुलाई (आर० एन० पी० बग; 25 जुलाई 1885); जी० एस० अय्यर, विलबी कमिशन, खंड III प्रश्न 18638; हिंदुस्तान, 20 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 27 जुलाई 1898); स्वदेशमित्रन, 15 मई (आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1900); हिंदू निम्नान, 27 मई (वही, 30 मई 1903); केसरी, 21 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 25 जुलाई 1903).
69. मसानी : पूर्वोद्धृत; पृ० 413-4, पर.
70. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 216 और देखिए, नोरोजी, एसेज, पृ० 114, 134; पावर्टी, पृ० 141, 199, 203, 217. 224-5, 655-6; स्पीचेज, पृ० 232, 250, 294, 315, 384-6, 389, 616 परिशिष्ट, पृ० 3, 23.
71. ए० बी० पी०, 28 जुलाई 1870, 29 जन० और 18 जून 1885. 22 मई 1892, 27 मार्च और 24 दिस० 1896, 13 फरवरी और 7 अप्रैल 1897, 22 फर० 1, 4, 8, 9 जून, 3 अगस्त और 1 अक्तू० 1900 13 नव० 1901
72. भोलानाथ चंद्र, एम० एम० खंड II (1873) पृ० 90, 93; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 640, 683, 794; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 232-3, 248-51, 514-5; बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 62, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 32 और सी० पी० ए०, पृ० 366 पृ० 604-07; राय, पावर्टी, पृ० 6-7, 241-2, 278, 315 और इंडियन फेरीस पृ० 37; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए० पृ० 254 269, 637, 708; आर० एम० सयानी. सी० पी० ए० पृ० 366; आर० एन०, मुघल-कर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 46-7; ए० नंदी इंडियन पालिटिक्स, पृ० 124-6; 28 दिसंबर

- 1897 के लन्दन इंडियन सीसाइटी के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव, इंडिया, 14 जन० 1898 पृ० 25; सी०वाई० चिंतामणि, एच०आर०, जनवरी 1902 पृ० 29, दन, स्पीचेज-I पृ० 13, स्पीचेज II पृ० 21, 48, 61-2, 84-5, ई०एच० I पृ० XIII-XVII 409, 420 ई०एच० II पृ० 14, 16, 127 पाट टिप्पणी, 343-4, 528, 612-3 जो०एस०अय्यर, विलबी कमीशन, खड III प्रश्न 186-38, ई० ए, पृ० 59, 357-8, एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1902 पृ० 76-7, इंदु प्रकाश, 13 दिस० (आर० एन० पी० बब 18 दिस० 1875), नेटिव ओपीनियन, 30 दिस० 1877 (वही, 5 जनवरी 1878), साधारणी, 31 अक्तू० (आर०एन०पी० बग, 6 नवंबर 1880), मराठा, 6 फरवरी 1881, और 13 अप्रैल 1884, बावे क्रानिकल 7 अक्तू० (आर० एन० पी० बब, 13 अक्तू० 1883), सिध टाइम्स, 20 मई (आर० एन० पी० बब, 24 मई 1884), साधारणी, 27 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त 1884), प्रनिकार, 22 अगस्त, (वही 6 सित० 1884), मजीवनी, 18 जुलाई, पताका, 17 जुलाई (वही, 25 जुलाई 1885), इंडियन स्पेक्टर, 5 जुलाई 1885, समय, 28 जून (आर० एन० पी० बग, 3 जुलाई 1886), बगवारी, 7 अगस्त (वही, 14 अगस्त 1886), स्वदेशामित्र, तिथिरहित (आर० एन० पी० एम, सितंबर 1887), आध्र प्रकाशिका, 5 नव० (वही, नवंबर 1887), ट्रिव्यन, 14 सित० (बी० ओ० आई०, अक्तू० 1887), हिंदू, 25 जून 1894, 7 जुलाई 1888, 5 अप्रैल और 4 जून 1900, बंगाली, 13 मार्च 1897, 24 और 25 मई 1901; हिंदुस्तान, 19 जून (आर० एन० पी० एन, 23 जून 1897), प्रपच मिलन, 19 जन० (आर० एन० पी० एम० 31 जन० 1900), स्वदेश-मित्र, 28 अप्रैल और 15 मई (वही, क्रमश 30 अप्रैल और 31 मई 1900), न्यू इंडिया, 16 सित० 1901, 7 अप्रैल 1902, कृष्ण पत्रिका, 1 सित० (आर० एन० पी० एम० 6 सित० 1902) वृत्तांत चिंतामणि, 14 नव० (वही, 14 नव० 1902) केसरी, 21 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 25 जुलाई 1903), एडवोकेट, 2 फरवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 4 फर० 1905)
- 73 आई० एन० सी० 1896 1897, 1901, 1902 और 1904 के प्रस्ताव क्रमश XII IX, VIII (a) III और III
- 74 उदाहरणार्थ देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 124, 184, 195, 203, 631, स्पीचेज, पृ० 135, 287, 547, परिशिष्ट, पृ० 5-6, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 233, राय पावर्टी, पृ० 329-30, एम० एन० बैंजर्जी, सी० पी० ए० पृ० 254, 709, आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 353, दन, स्पीचेज-II पृ० 48, 85
- 75 दत्त, ई० एच II, पृ० XIV और देखिए, 'एंग्ली फार दि स्वायलेशन आफ इंडिया, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 1885 (खड VII स० 3) पृ० 17
- 76 दत्त, ई० एच-I, पृ० 418-9, ई० एच II पृ० 213-4, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 129-30 296, परिशिष्ट, पृ० 13-4, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 251-2 और देखिए, एस० एन० बैंजर्जी, सी० पी० ए० पृ० 254, 709
- 77 सी० पी० ए०, पृ० 709
- 78 दत्त, ई० एच० I पृ० XI-XII और देखिए, वही, पृ० 100, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 759
- 79 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 184, स्पीचेज, पृ० 117, 668, परिशिष्ट पृ० 5.
- 80 दन ई० एच० I पृ० XII, 426; ई० एच० II पृ० XIV

81. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 286-7. और देखिए वही, पृ० 119, 134-5, 153, 615, परिशिष्ट, पृ० 5-6, 10; और नौरोजी, पावर्टी, पृ० 184, 195, 203, 216, 224, 566.
82. नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 181.
83. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 59.
84. वही, पृ० 56, 64.
85. वही, पृ० 135.
86. नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 595
87. वही, पृ० 152-3.
88. वही, परिशिष्ट, पृ० 52. और देखिए; वही, पृ० 196, 382, एसेज, पृ० 101, पावर्टी, पृ० 38, 217, 225
89. नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृष्ठ 18-21, 24.
90. मैं तो यही कहूँ कि उसने गलतफहमी से रहने का ढोंग रचा था क्योंकि उसके सभी प्रश्नों का स्वर यही सिद्ध करता है कि उसने मूल का मुखौटा धारण कर रखा था अन्यथा वित्तीय मामलों की गहरी पकड़ के लिए वह प्रसिद्ध था. उसने दादाभाई को परेशान करने के लिए जानबूझकर यह ढंग अपनाया. यह विपरीत धारणा कि इससे तत्कालीन सरकारी आर्थिक चिंतन का काफी हद तक पता चलता है यह सिद्ध करेगी कि बिलबी और सरकारी तर्क का स्तर बहुत नीचा था जो अपेक्षाकृत दादाभाई नौरोजी के महत्व को बढ़ाता है. कुछ भी हो इसमें कोई सदेह नहीं कि इस बहस में बिलबी को मुह की खानी पड़ी.
91. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 683
92. वही, पृ० 793-4 वह घोड़ा और आगे बढ़े और यह मत व्यक्त किया कि सरकार द्वारा देश के भीतर से ऋण लेना भी देश के पूँजीगत साधनों की निकासी का एक अन्य द्वार है क्योंकि इससे देश की बचत की रकम का एक बहुत बड़ा अंश अनुत्पादक मद में चला जाता है जिसका उपयोग अन्यथा देश की निवेशित पूँजी की वृद्धि में होता (वही, पृ० 794).
93. भोलानाथ चंद्र, एम० एम० खंड II (1873), पृ० 93; नेटिव ओपीनियन 30 सितंबर 1877 (आर० एन० पी० बंब, 5 जन० 1878); मराठा, 19 जून 1881, 13 अप्रैल 1884; बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 61-2. रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 104, मी० पी० ए०, पृ० 625; जी० एस० अय्यर, बिलबी कमीशन खंड III प्रश्न 18675, 18702 ई० ए०, पृ० 125; एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 114.
94. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 55-6, और देखिए पृ० 64 और 135.
95. वही, पृ० 217.
96. नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 9.
97. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 659 और देखिए गोखले, स्पीचेज, पृ० 909.
98. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 793-4
99. बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 625-6 और देखिए, वही, पृ० 602-03, 606; जी० एस० अय्यर, बिलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18702; बगाली, 19 जनवरी 1895; स्वदेशमित्र, 29 मई (आर० एन० पी० एम० 31 मई 1900)
100. बिलबी कमीशन, खंड III प्रश्न 18168-9.
101. नौरोजी, एसेज, पृ० 101, स्पीचेज, पृ० 232; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 695; जी०

एस० अय्यर; ई० ए०, पृ० 243; हितकारी, 3 अक्तू० (बार० एन० सी० अफ०, 7 नवंबर 1903) और देखिए बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 61

102. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 152-3, 196, 319, 382, परिशिष्ट पृ० 3, 5, 7-8 उसने आगे टिप्पणी की कि यदि हम अपनी पूँजी के सत्रह की पूर्ण स्वतंत्रता हो तो हम देश में आने वाली विदेशी पूँजी का ईमानदारी से बराबर मुकाबला कर सकते हैं और उस समय विदेशी पूँजी से हानि की अपेक्षा कदाचित्त लाभ ही अधिक होगा इस समय हमें विदेशी पूँजी की हानि से ही व्यथित होना पड़ता है क्योंकि हम असहाय हैं और पतित अवस्था में हैं (वही, परिशिष्ट, पृ० 7) तथा देखिए मोखले के दादाभाई के प्रश्नों के दिए गए उत्तर, क्लिनकी कमिशन, खंड III प्रश्न 18169-71, 18183-4
103. वही, पृ० 250 1 परिशिष्ट, पृ० 6-7
104. वही, पृ० 153 663
105. दत्त, ई० एच० II, पृ० XIV तथा पृ० 372-3.
106. वही, पृ० 348 9, 534-6
107. दत्त, स्पीचेज II, पृ० 27-8
108. बाबा, रिप० आई० एन० सी०, 1886 पृ० 61
109. देखिए पीछे अध्याय 4, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 641, ए० बी० पी० 17 बुलाई 1892 बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1898, पृ० 105, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 357-8
- 109-ए. ऐडम स्मिथ, 'दि वेलथ आफ नेशंस' (माडर्न लाइब्रेरी न्यूयार्क द्वारा प्रकाशित कैनन संस्करण, तिथिरहित) खंड 5 अध्याय 1 भाग III पृ० 710
- 109-बी 'ब्रिटिश इनकम्स इन इंडिया' न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून, 21 मिनबर 1857. 'माक्स एंड एजेल्स आन कानोनियलिज्म (माम्बा, तिथि रहित) पृ० 143
- 109-सी एन० एफ डेनियल्सन के नाम माक्स का पत्र, 19 फरवरी 1881, वही, पृ० 304
- 109 डी इंपीरियल मजेटियर आफ इंडिया (1908) पृ० 201 उदाहरणार्थ, अवकाश यात्रा भत्ते और सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में इंग्लैंड में ही भुगतान की गई राशि भारत के 1902-03 के कुछ वार्षिक राजस्व के 12 प्रतिशत के लगभग थी (उसमें से ही आठके लगभग किए गए हैं, पृ० 194, 201) 1895 में पी० सी० राय ने दावा किया कि यह अनुपात 16 प्रतिशत है (पावर्टी, पृ० 8) बहुत सारे भारतीय नेताओं ने भी 1892 के समदीय हिसाब खाते के आधार पर सगणना करने की चेष्टा की सैनिकों को छोड़कर यूरोपीय कर्मचारियों द्वारा बतनों और पेसों के रूप में भारत में और इंग्लैंड में प्राप्त किए जाने वाले धन की राशि, सगणना करने पर सचमुच चौंकाने वाली थी यह राशि लगभग 15 करोड़ रुपये थी जबकि दूसरे शब्दों में भारत सरकार के कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत थी नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 134, परिशिष्ट, पृ० 6, 89-90; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 232-3, 248, 515-6, राय, पावर्टी, पृ० 325 6; ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 124; बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 607; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 711; दत्त, ई० एच० I पृ० XIII, 427 पादटिप्पणी और देखिए मोखले, स्पीचेज, पृ० 1187-8.
110. मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 316 पर दादाभाई नोरोजी और देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 142, 200-01, 203, 574-6, स्पीचेज पृ० 115-6, 120, 361, 378, 527, 529-30 परिशिष्ट, पृ० 6, 26; लॉन इंडियन सोसाइटी द्वारा 14 जून 1898 को पारित प्रस्ताव पृ० 25; ए० बी० पी०, 4, 9 जून 1900, 28 मार्च 1901.

111. उदाहरण के रूप में देखिए, बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 61 और रिप० आई० एन० सी० 1898 पृ० 104; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 252; श्रीराम, एल० सी० पी० 1901 खड XL पृ० 238; दत्त, स्पीचेज I पृ० 13, 25, स्पीचेज II पृ० 21, 62, 87, ई० एच० I पृ० XIV, ई० एच० II पृ० XVII; आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव III और आई० एन० सी० 1902 का प्रस्ताव III एस० एन० बैंजर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 691, 711. जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 59, 129.
112. नोरोजी, एसेज, पृ० 123, पावर्टी, पृ० 226. स्पीचेज, पृ० 120, 525, परिशिष्ट, पृ० 52.
113. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 142, 201, 658 स्पीचेज, पृ० 115-6, 162, 232-3, 323-4, 530 दत्त, स्पीचेज, II पृ० 62-3, ई० एच० II, पृ० 613.
114. नोरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 164 तथा देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 233, 323
115. उदाहरणार्थ देखिए, नोरोजी, पावर्टी पृ० 123-4, 135, 142, 639, 657, स्पीचेज, पृ० 115, 196-7, 529, 580, परिशिष्ट, पृ० 5, 23 25, 74-5, बगाली, 28 अगस्त 1880; बाबा, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 61, डी० जी० पाध्या, रिप० आई० एन० सी० 1886 पृ० 99; आई० एन० सी० 1901, 1902, 1903 और 1904 के प्रस्ताव क्रमशः III, III, II (सी) और III (सी). आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 1901 पृ० 88; एस० एन० बैंजर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 709, 711; दत्त, स्पीचेज, I पृ० 93, स्पीचेज, II, पृ० 21
116. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 196-7, 529. तुलनीय रीस, पूर्वोद्धृत, पृ० 289.
117. देखिए पीछे अध्याय 7 की पादटिप्पणी स० 63 में उल्लिखित सदस्य, और देखिए, रानाडे, 'रिच्यू आफ फासेट्स ऑफ एसेज आन इंडियन फाइनांस' जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1880 (खड III स० I) पृ० 80, 'ट्रिब्यून', 26 जुलाई 1893; आई० एन० सी० 1893 का प्रस्ताव XVII पृ० ए० चार्ल्स, एल० सी० पी० 1896 खड XXXV पृ० 286, दत्त, स्पीचेज, I पृ० 13, 93, ई० एच० II, पृ० 612. इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 144.
118. देखिए पीछे अध्याय सख्या XII.
119. दत्त, स्पीचेज I पृ० 97-8. और ई० एच० II, पृ० XVII, 599, 612. और देखिए जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 106, 131-3.
120. देखिए पीछे अध्याय सख्या 12
121. जी० एम० अय्यर, विलबी कमीशन, खड III प्रश्न 18954-5; स्वदेवमित्रन 29 मई (आर० एन० पी० एम०, 31 मई 1900). और देखिए जामे जमनेद, 5 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 19 जुलाई 1880); समय, 3 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 8 मार्च 1884). दूसरी ओर जी० बी० जोशी स्टैलिश पौंड के ऋणों के पक्ष में वे वयक्तिक वे रुपये के रूप में मिलने वाले ऋण की अपेक्षा करते थे; रुपये के रूप में मिलने वाले ऋण उद्योग में निवेशित की जाने वाली पूंजी को निकाल कर उपलब्ध होते थे. इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रतिपा और सूक्ष्म चिंतन से यह पाया कि रुपये के रूप में मिलने वाले ऋण भी अधिकांशतया धनरेज ऋणकर्ता से प्राप्त होते थे घतः रुपये के रूप में ऋण प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य, निकासी रोकना, पूर्ण नहीं हो पाता था. (पूर्वोद्धृत, पृ० 114-30).
122. देखिए पीछे अध्याय 5 और दत्त, ई० एच० II पृ० 375.
123. ए० बी० पी०, 14 अप्रैल 1881; एस० के० नायर, रिप० आई० एन० सी० 1895, पृ० 74.

124. देखिए पीछे अध्याय 2 जी० ए० बय्यर, ई० ए०, पृ० 85, ए० ए० बॅनर्जी, सी० पी० ए० पृ० 709.
125. देखिए पीछे अध्याय 3.
126. देखिए पीछे अध्याय 12.
127. केसाक : पूर्वोद्धृत, पृ० 127 तथा देखिए, बे० सी० मोयाजी, 'रानाडेज वर्क ऐज ऐन इकोनामिस्ट' इंडियन जरनल आफ इकोनामिक्स, जन० 1942 खंड XXII स० 3 पृ० 308.
128. रानाडे, एसेज, पृ० 186-7.
129. देखें ऊपर.
130. जे० पी० ए० ए०, जुलाई 1881 (खंड IV, स० I), पृ० 16.
131. आई० ए० सी० 1896 और 1897 के प्रस्ताव XII और XI क्रमशः.
132. जी० बी० जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 640, 683, 793-4; गोखले, स्पीचेज, पृ० 15, 87-8, 908-10 और बिलवी कमीशन, खंड III प्रथम 18169-84 1905 तक गोखले के विचार बड़े ही सकोष-पूर्वक प्रस्तुत किए गए थे. (स्पीचेज, पृ० 15, 87-8, 908-10) परंतु 1905 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने दृढ़तापूर्वक घोषणा की कि अनेक वर्षों से देश से संपत्ति की भारी और विनाशकारी निकासी शुद्ध आयातों पर निर्यातों की अधिकता के (कांश सहित) रूप में चल रही है पिछले चालीस वर्षों में हुई इस निकासी की राशि 1 अरब स्टर्लिंग पाँच से कम नहीं होगी (सी० पी० ए०, पृ० 844).
133. निकासीवाद के प्रारंभिक खंडों में एक या जान स्ट्रेंची का प्रयास, जो उन्होंने 1878 के 'वित्तीय विवरण' में तथा 1880 के रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेमोन कमीशन भाग VIII, कड़िका-4 में प्रस्तुत किया हा विस्तृत खंडन सर्वप्रथम 1911 में ही देखने को मिला जो थियोडोर मोर्गिसन की पुस्तक 'दि इकोनामिक ट्रांजीशन इन इंडिया' से (नदन 1911) (1916 का पुन मुद्रण) अध्याय-7 और 10 में उपलब्ध है
134. ए० सी० ए० नोल्स : दि इकोनामिक डेवलपमेंट्स आफ दि ब्रिटिश ओवरसीज एंपायर (नदन 1928) पृ० 392-3. ऐंस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 909-11 तथा देखिए जी० फिडले शिराम : पावर्टी ऐंड किडर्न इकोनामिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया (भारत सरकार 1935, तृतीय संस्करण)
135. कड़िका-52
136. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 193, और देखिए, चिसनी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 397; नोल्स : पूर्वोद्धृत, पृ० 392-3. केवल जी० डी० रीस ने तथ्यों की उपेक्षा की और दृढ़तापूर्वक कहा : 'जो कुछ भी बाहर जाता है, उस सबका मूल्य चुकाया जाता है और उपभोग की ऐसी सभी वस्तुएं, उदाहरणार्थ, सूती सामान और सोना-चादी जो कि देश की सर्वाधिक मांगें हैं कल्पना कीजिए कि भारत व्यापक परिमाण में इनका निर्यात बंद कर देता है, इसके फलस्वरूप उसे उसी अनुपात में भुगतान भी कम मिलेगा और तदनुसार उसकी जनता दुखी होगी वस्तुतः बदले में बिना क्या सामान बचवा पैसा जनता को ही मिलता है न कि सरकार को (पूर्वोद्धृत, पृ० 302).
137. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 188-92; नोल्स : पूर्वोद्धृत, पृ० 392 ऐंस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 333. जी० ए० शिराम : पूर्वोद्धृत, पृ० 25.
138. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 184-6, 200-02, नोल्स : पूर्वोद्धृत, पृ० 392.
139. कर्वेन स्पीचेज, III पृ० 388, रीस, पूर्वोद्धृत, पृ० 302 यहां तक कि नोल्स का भी अनुमान था कि निष्पक्षीवाद के समर्थकों द्वारा संबंधित निर्यातों की अधिकता में होने वाली के आयात

सम्मिलित नहीं थे.

140. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 223.
141. स्ट्रेची, फाइनांशल स्टेटमेंट-1878, कड़िका, 52; रिपोर्ट आफ दि इंडियन कमीशन 1880, भाग VIII कड़िका-4; चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 397; स्ट्रेची : इंडिया (1903) पृ० 195-6, 235-6; रीस, पूर्वोद्धृत, पृ० 80, 124, 289, 302; मोरिसन, पूर्वोद्धृत, पृ० 205 तथा भाग, 218-222 नोल्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 392, ऐंस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 509; जी० एफ० गिरास, पूर्वोद्धृत, पृ० 23-4
142. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 224 ऐंस्टे, पूर्वोद्धृत, पृ० 509; जी० एफ० गिरास : पूर्वोद्धृत, पृ० 23-4.
143. रीस, पूर्वोद्धृत, पृ० 302 मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 239-41. ऐंस्टे, पूर्वोद्धृत, पृ० 509-11.
144. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 239 40 तथा देखिए जी० एफ० गिरास, पूर्वोद्धृत, पृ० 24
145. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 241 तथा देखिए ऐंस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 510.
146. चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 397. स्ट्रेची : इंडिया (1903) पृ० 194; रीस, पूर्वोद्धृत, पृ० 289, 302; मोरिसन : पूर्वोद्धृत पृ० 183, 204-16; जी० एफ० गिरास : पूर्वोद्धृत, पृ० 22, 24
147. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 205, 229
148. वही, पृ० 235-6. स्ट्रेची : इंडिया (1903) पृ० 236
149. स्ट्रेची, फाइनांशल स्टेटमेंट 1878 कड़िका 52 रिपोर्ट आफ दि इंडियन कमीशन, 1880, भाग VIII कड़िका-4; चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 397-8; जार्ज हैमिल्टन, हमांड (चौथी सिरिज) ख० XCIX, 1901, पृ० 1213; स्ट्रेची . इंडिया (1903) पृ० 192-5, इंग्लिश गजेटियर आफ इंडिया, (1908) पृ० 194; मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 237, वी० लावेट पूर्वोद्धृत, पृ० 236; नोल्स : पूर्वोद्धृत, पृ० 393; ऐंस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 510; जी० एफ० गिरास : पूर्वोद्धृत, पृ० 23
निकासीवाद के पीछे धासोचको का यह विश्वास काम कर रहा था कि राजनीतिक निकासी न केवल लाभदायक है प्रत्युत अपरिहार्य भी है इस प्रकार चिसनी ने 1893 में दृढ़तापूर्वक कहा कि यद्यपि गृह प्रभार और यूरोपीय कर्मचारियों द्वारा अपनी बचतों को इंग्लैंड ले जाना शब्द के अर्थ के रूप में सचमुच ही धन की निकासी थी परंतु इसके लिए शिकायत करना फूहड़पन ही था, क्योंकि इसका अर्थ तो यह अनुमान लगाना होगा कि प्रगरेज अधिकारियों द्वारा संचालित धनरेज प्रशासन के अभाव में भारत अपने आप आंतरिक क्षाति और सुरक्षा प्राप्त कर लेता. जो लोग इस विश्वास के पीछे किसी झुझतम आधार की भी कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें भारत के इतिहास की और भारतीय लोगों की साधारण सी भी जानकारी नहीं है, (पूर्वोद्धृत, पृ० 398) तथा देखिए स्ट्रेची . इंडिया (1903) पृ० 194-5.
150. मोरिसन : पूर्वोद्धृत, पृ० 237.
151. वही, पृ० 241.
152. नोरोजी, एसेज, पृ० 36, 85, 889, 101, 112-4, स्पीचेज, पृ० 665.
153. नोरोजी, एसेज, पृ० 101, 113, पावर्टी, पृ० 33, 137, 568-9. स्पीचेज, पृ० 382-3; जोर्जी, पूर्वोद्धृत, पृ० 618, 638-9; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 338, 353; मोक्षसे, स्पीचेज, पृ० 87-8.
154. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 320-1, 382, 666, और देखिए नोरोजी, पावर्टी, पृ० 131, 138, 196 तथा आगे, ऐंस्टे : पूर्वोद्धृत, पृ० 333 की पावर्टिप्पणी : यह ध्यान देने की बात है कि आयात की बोधित कीमत में मास बाढ़ा सम्मिलित है परंतु निर्यात के बोधित मूल्य में यह सम्मिलित

नहीं है, तथा ई० ला, एन० सी० पी० 1904 खड XLIII पृ० 538.

- 155 नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 320-1, 666.
156. देखिए पीछे अध्याय 3. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 33-4, 38, 566-9, स्पीचेज, पृ० 133, 319, 322, 615, परिशिष्ट, पृ० 3, 7-8, 55-6; जी० एम० अय्यर ई० ए०, पृ० 127-8; गोखले, विलजी कमीशन, खड III प्रश्न 18169, 18183-4.
157. देखिए पीछे अध्याय 5
- 158 देखिए पीछे अध्याय 3
- 159 देखिए अध्याय 5
- 160 देखिए अध्याय 3, 5.
- 161 देखिए अध्याय 3, 8.
- 162 देखिए अध्याय 3.
- 163 वही „ 3.
- 164 वही.
- 165 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 37, 131-2, 136 पादटिप्पणी, 141 568-9. 574 स्पीचेज, पृ० 382-3; मराठा 25 मई 1884; न्यू इंडिया, सितंबर 1902; और पीछे अध्याय 4
- 166 नोरोजी, पावर्टी, पृ० 3-4, 565, स्पीचेज, पृ० 133, 319, 596, दत्त, ई० एच II पृ० 375.
- 167 नोरोजी, पूर्वोद्धृत, पृ० 87, 746, इंडियन स्पेक्टेटर, 26 अक्टूबर 1884, मराठा, 9 अगस्त 1885 जैसाकि हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं, 1860 के आसपास तक तो दादा भाई भी रेल पथों के निर्माण के लिए विदेशों से ऋण लेने के पक्ष में थे (एमेज, पृ० 124-6, 132).
- 168 नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 319, दत्त, ई० एच II पृ० XV जी० एम० अय्यर, ई० ए०, पृ० 353
- 169 नोरोजी स्पीचेज, पृ० 319-20; दत्त, ई० एच० I, पृ० 398-9, 406-09, ई० एच० II पृ० XV-XVI, 215-20, 373-5, 604, एक दूसरे सदर्भ में भी भारतीयों ने निर्देश किया कि भारतीयों के रक्त और धन के मूल्य पर ही भारतीय साम्राज्य हथियाया गया है नोरोजी, पावर्टी पृ० 567, 640, स्पीचेज, 221-2, गोखले, स्पीचेज पृ० 1207, दत्त, ई० एच० I पृ० 399.
- 170 नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 319-20, गोखले, स्पीचेज, पृ० 1205-06, दत्त, ई० एच० II, पृ० XV-XVI, 604 और देखिए, अध्याय XII सैनिक व्यय संबंधी भाग.
- 171 नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 320-1.
172. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 35, 37
173. देखिए पीछे पादटिप्पणी 67
174. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 565
- 175 विशेषतया देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 42-3, 54.
176. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 196-7 395 और आगे, 484-5, 496-7, 506 परिशिष्ट पृ० 6, 25, 32, 47, 73, 171-2; गोखले, स्पीचेज, पृ० 908-09. 1866 के प्रारंभ दादाभाई ने 'दि यूरोपियन ऐंड एशियाटिक रसेस' शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख का उद्देश्य यह दिखाना था कि भारत और एशिया के लोगों में भी यूरोप के लोगों के समान ही ऊंची नैतिकता और उच्च स्तर की प्रतिष्ठा है (स्पीचेज, पृ० 535 और आगे)
177. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 47.
178. गोखले, स्पीचेज, पृ० 62.

179. देखिए पीछे अध्याय 2.
180. देखिए पीछे अध्याय 12.
181. आगे देखिए.
182. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 640-1; बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 605; गोखले, स्पीचेज, पृ० 908.
183. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 227, स्पीचेज, पृ० 134.
184. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 52-3 तथा देखिए बाबा, सी० पी० ए०, पृ० 607.
185. गोखले, स्पीचेज, पृ० 1188 और देखिए, उदाहरण के लिए नोरोजी, एसेज, पृ० 123, 374, पावर्टी, पृ० 56-8, 203-05, 225, 631, स्पीचेज, पृ० 134, परिशिष्ट, पृ० 171; सी० शंकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 388 9; गोखले, स्पीचेज, पृ० 120.
186. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 33.
187. उदाहरण के लिए देखिए नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 316-7, 319, 329, 361, 378.
188. वही, पृ० 339.
189. वही, पृ० 322. और देखिए पृ० 668.
190. वही, परिशिष्ट, पृ० 3 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कितने ही और भारतीय नेताओं ने भी इस बात पर ध्यान दिया था कि निकामी के मूल कारण राजनीतिक ही है देखिए जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 683; राय, पावर्टी, पृ० 7, 242; गोखले, स्पीचेज, पृ० 15
191. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 212.
192. वही, पृ० 211-2.
193. वही, पृ० 224.
194. वही, पृ० 225.
195. वही, पृ० 224-5. 31 जनवरी 1901 को लंदन के श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर दोहराया, 'जिस ढंग से तुम जीवन और संपत्ति की रक्षा दूसरों के द्वारा की जान वाली खुली हिंसा से करते हो उसका वास्तविक रूप यह है कि तुम संपत्ति की रक्षा इसलिए करते हो कि दूसरा कोई उस संपत्ति को न हथिया सके और तुम स्वयं उस पर अधिकार जमा सका। यदि ऐसा करना दुष्ट न होता तो ज़िदगी मज़ाक़ हो जाती है। ज़रा आँख उठा कर भारत के लाखों करोड़ों आर्द्धमर्यादों को देखिए तो सही जो दिन प्रति दिन, वर्ष प्रति वर्ष, अच्छी फसल के वर्षों में अभावग्रस्त जीवन बिनाने और दुःख भोगने को विवश हैं (स्पीचेज, पृ० 228)।
196. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 389
197. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 125.
198. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 153
199. वही, पृ० 153-4
200. वही, पृ० 400 पृ० 387 भी देखिए.
201. वही, पृ० 328.
202. वही, पृ० 329.
203. इंदिया, 2 सितंबर 1904. उन्होंने व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की : ब्रिटिश इस देश से संपदा बाहर ले जाते हैं। अतः जब देश में फसल कम होती है, लाखों-करोड़ों मनुष्य मर जाते होते हैं, तब ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी उदार मोकोपकारी प्रवृत्ति का यह प्रमाण दिया है।
204. नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 29, और देखिए, वही, परिशिष्ट, पृ० 4-5, 27, 78 और

- सी० पी० ए० पृ० 158. उन्होंने फिर भी निकासी के मामले में ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद को निदोष बताया परंतु ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों, भारत और ब्रिटिश सरकार के राज्य सचिव को पूरी तरह दोषी सिद्ध किया (वही, परिशिष्ट, पृ० 58-60).
205. उदाहरण के लिए देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 227.
206. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 120
207. वही, परिशिष्ट, पृ० 74 और देखिए, वही, परिशिष्ट पृ० 43, 75.
208. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 218 तथा पृ० 216.
209. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 334 उन्होंने लिखा: 'भारतीयों का प्यार ही एक ऐसी सुदृढ़ आधार शिला है जिस पर विदेशी शासक मजबूती और निरंतरता के साथ खड़ा हो सकता है अन्यथा वह एक दिन मरने की तरह बिखर जाएगा. (वही, पृ० 332)
210. वही, पृ० 368
211. नोरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 8
212. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 392
213. वही, पृ० 223
214. नोरोजी, पावर्टी पृ० 659
215. उदाहरण के लिए देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 21-2, 25-6.
216. इंडिया, 2 मितंबर 1904
217. नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 671 इन्हीं भाषाओं में दादाभाई ने इससे पूर्व दिसंबर 1903 में उस समय भी अभिव्यक्त किया था जब उन्होंने 'हिंदुस्तान रिव्यू' और 'कायस्थ समाचार' को भेजे गए अपने संदेश में ब्रिटिश सर्वाधिकार का अनगुन गवशान अथवा स्वराज्य की मांग की थी। (एच० आर० दिसंबर, 1903 पृ० 474)
218. नोरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 863 तथा देखिए, पृ० 883, 886.
219. देखिए 1890 का प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में उनका उद्घाटन भाषण. एसेज, पृ० 180-94. और देखिए यही, पृ० 119-20
220. उदाहरणार्थ 1858 के भारत में मद्रास की घोषणा में यह कहा गया था: 'भारत के शांतिपूर्ण उद्योग को पोषादन देना हमारी हासिक अभिलाषा है' डॉफो ने अपन सुप्रसिद्ध सेट में यूज भाषण में घोषणा की कि भारत की दरिद्रता का दूर करने के दो ही उपचार हैं: उत्पादक उद्योगों का विस्तार और उत्पादक (स्पीचेज, पृ० 242) कर्जन ने भी 1903 में बकालत की कि जब से मैं भारत में हूँ, जिन विषयों में मेरा गंभीर ध्यान आकृष्ट किया है, उनमें प्रथम है भारत की औद्योगिक निर्निधि का विभाग मेरी दृष्टि में अभी पर भारत की भावी आशा निर्भर है (स्पीचेज, III, पृ० 114) और देखिए, वही, पृ० 117, 133, 139-41 और देखिए जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 101-02
221. रिपोर्ट ऑफ दि इंडियन इंडस्ट्रियल कमिशन, पूर्वोद्धृत, 1916-18, पृ० 75-8, 105-07; एस्टे: पूर्वोद्धृत, पृ० 210 3 न्यायमूर्ति रानाडे ने 1890 में घोषणा की: 'यह ठीक है कि सरकार सहायता कर सकती है परंतु तगण्य रूप से प्रा 'भक्त' कार्य में नेतृत्व दीजिए, सरकार हमारी सहायता को उत्सुक है (एसेज, पृ० 190).
222. एस्टे: पूर्वोद्धृत, पृ० 216-26
223. रानाडे तक ने घोषणा की कि औद्योगिक क्षेत्र में शासकों और जासितों के हितों में किसी प्रकार

- का कोई संघर्ष नहीं. दोनों ही समान रूप से देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को अग्रसर करने को इच्छुक हैं (एसेज, पृ० 180). और देखिए, वही, पृ० 181-190.
224. रानाडे, एसेज, पृ० 187-188. 193-4. ए० एस० मुदासियर, रिप० आई० एन० सी०, 1886 पृ० 65; और पीछे अध्याय 2. तुलनीय जे० सी० गोयाजी, 'रानाडेज बर्क एंज ऐन इकानोमिस्ट' इंडियन जर्नल आफ इकानोमिक्स, जनवरी 1942, खंड XXII, सख्या 3 पृ० 307-16.
225. रानाडे, एसेज, पृ० 119-20, 187, 190-4; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 805-806, 814. और पीछे अध्याय 2.
226. स्फरिन, स्पीचेज, पृ० 242. और देखिए, कर्जन, स्पीचेज III पृ० 139-41. फ़रोजशाह मेहता खुले तौर पर यूरोपियों पर यह आरोप लगाने की सीमा तक बढ़ गए कि वे औद्योगिक विकास के आंदोलन का उपयोग भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन से विमुख करने के एक साधन के रूप में कर रहे थे (स्पीचेज, पृ० 817) इससे पूर्व मार्च 1904 में कर्जन यह घोषित कर चुके थे कि मे नहीं समझता कि भारत के विकास के वर्तमान स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में मुक्ति की मांग का कोई औचित्य है ? (स्पीचेज II पृ० 49).
227. आई० एन० सी० 1901 का प्रस्ताव XVI.
228. आई० एन० सी० 1902 का प्रस्ताव III और 1904 का प्रस्ताव III
229. 'भार० पी० पराजपे ने गोखले के राजनीतिक कार्यक्रम के 'नरम' साधनों का विश्लेषण निम्न-लिखित रूप से किया है : 'उनकी यह धारणा थी कि ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत और विश्व में अपना समुचित स्थान पाने के लिए 9-10 भाग का कार्य तो भारत में और स्वयं भारतीयों को ही पूरा करना है कार्य के इस बड़े अंश के संपन्न हो जाने पर विदेशी शासन भी नीकरशाही के कारण स्वाभाविक थोड़ी बहुत कठिनाइयों का आना स्वाभाविक ही है परंतु उन्हें दूर करने में बहुत समय नहीं लगेगा.' पराजपे ने जागें यह टिप्पणी ठीक है कि अपनी दृष्टियों के इतने गहरे ज्ञान का अर्थ यह- कदापि नहीं कि जनता के सामने गला फाड़ फाड़ कर अपने को बढ़ा घोषित करो और दूसरी की दृष्टि में नीचे गिरो 'गोपालकृष्ण गोखले' (पूना, 1915, द्वितीय संस्करण) पृ० 14 यद्वा जस्टिस रानाडे के स्तुलित राजनीतिक दृष्टिकोण की परिभाषा को जानना भी रोचक होगा 1896 में उन्होंने लिखा 'उपयुक्तता का अर्थ है कि अशुभ के पीछे घटकने का दम न करना, अथवा दुष्प्राप्य की कामना न करना प्रत्युत समझौता और औचित्य की भावना से यथामभव हस्तगत हो सकने वाले लक्ष्य के प्रति स्वाभाविक विकास के रूप में प्रतिदिन एक एक पग आगे बढ़ते जाना' आर्थिक क्षेत्र में जनता की घोर दरिद्रता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के उपरान्त रानाडे ने लिखा : 'हां, यह वस्तुस्थिति कल की तो है नहीं, और न ही यह विदेशी विजय और प्रतियोगिता का एकमात्र परिणाम है. यह तो पुरानी और बहुत पुरानी परंपरागत स्थिति है (एसेज, पृ० 182).
230. मसानी; पूर्वोद्धृत, पृ 414 पर
231. वही, पृ० 523.
232. वस्तुतः दादाभाई और 'पत्रिका' दोनों इसे निकासी से संबंधित न करने पर यह भानने को प्रस्तुत थे कि भारत में मूल लगान काफी बहुत ऊंचे कतई नहीं थे (नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 52 और ए० बी० पी०, 1 जून 1900). 'पत्रिका' ने 18 अक्टूबर 1900 के अंक में भी निर्देष्ट किया कि निकासी के प्रस्तुत तथ्य के अंतर्गत भुगतान करने के लिए अतः धन की उबाही तो

करनी ही है। यदि भूमि मगान घटाए गए तो देश को किसी और मद से धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी

- 233 उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि दत्त भूमि लगान पर आवश्यकता से अधिक बल देने की अपनी पूर्व स्थिति से बदल चुके हैं और अब भारत को निर्धन बनाने के लिए निकासी और उद्योग के अभाव पर भी बराबर आरोप लगाने लगे हैं
- 234 उदाहरणार्थ, दादाभाई ने 1887 में बाबा को लिखा विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व के सुधार मात्र से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक साथ में निकासी को बढ़ाने के अन्याय्य सुधार नहीं अपनाए जाते (मसानी पूर्वोद्धृत, पृ० 316 पर) तथा देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 361
235. 26 जनवरी 1886 को खजाने को लिखा गया पत्र, जो स० 26 दिनांक 28 जनवरी के डिस्पैच आफ सेक्रेटरी आफ स्टेट टु गवर्नमेंट आफ इंडिया (फाइनांस) में सलग्नक सक्ष्मा-2 के रूप में भेजा गया
- 236 रोस, पूर्वोद्धृत, पृ० 288.
237. उदाहरण के रूप में दिसंबर 1881 के 'बंगाल मैगजीन' ने लिखा 'इस प्रकार की जगली बात-चीत से श्रीमान दादाभाई का क्या अभिप्राय है ? राजस्व की जिस हानि पर दादाभाई विलाप करते हैं नहीं रक सकती है जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तथा स्वयं भारतीयों द्वारा ही प्रशासित होगा, परंतु वह दिन आने वाला नहीं है और बहुत लंबे समय तक आने वाला नहीं है अतः विदेशियों द्वारा देश के साधनों के उपभोग किए जाने की बात करना मूर्खता ही है (पृ० 177-8) और देखिए, 'न्यू इंडिया', 7 अप्रैल 1902
- 238 उदाहरण के लिए देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 77-8
- 239 1908 में जे० डी० रोस ने लिखा यह सत्य है कि ब्रिटिश राज्य में विश्वास की दृढ़ता के कारण दादाभाई बहुत से अभियोगों से बच निकलते हैं परंतु इस कथन को केवल इस फ्रांसीसी उक्ति के समान ही समझा जा सकता है 'हमारे दुर्भाग्य हमें खा न जाए, उससे पहले ही हमें उन्हें खा जाना चाहिए' (पूर्वोद्धृत पृ० 238).

अध्याय 14

भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था

सिद्धांत केवल व्यवहार का व्यापक रूप है और समीक्षार्थी कारणों के संदर्भ में सिद्धांत का अध्ययन ही व्यवहार है। जस्टिस रानाडे

समाज की प्रचलित परिस्थितियाँ तथा इसके भावी और समकालीन हित के संबंध में व्याप्त मान्यताएँ उन आर्थिक धारणाओं के निर्धारक तत्व हैं जिन्हें चिंतकों का अनुमोदन और राजनीतिज्ञों की स्वीकृति प्राप्त रहती है। जी० सुब्रह्मण्य ऐयर्स

हमारे अध्ययन का अंतर्गत अवधि में कुछ एक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 'भारतीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था' की धारणा को जन्म दिया। 1892 में दक्कन कालेज पूना में 'भारतीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था' पर अपने प्रतिष्ठित भाषण में जस्टिस रानाडे ने इस विषय का समग्र और पूर्ण रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया।¹ भारतीय अर्थशास्त्र के इतिहास में उनके मूल मित्रान् अन्यत्र प्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ उनके विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं।² परन्तु जो बात इतनी अच्छी तरह विदित नहीं है वह यह है कि उनके सिद्धांतों को कितने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं में मान्यता प्राप्त थी। इस विषय पर रानाडे के विचारों का हम यहाँ नीचे संक्षेप में विवेचन करेंगे।

क्लामिकी राजनैतिक अर्थव्यवस्था को सभी समयों में और सभी स्थानों पर, सार्वदेशिक रूप में समग्र रूप और प्रमाण रूप में तथा आर्थिक विकास के सभी स्तरों पर सही मानने का दावा वास्तविकता में कबो दूर था।³ क्लामिकी अर्थव्यवस्था का आधार वे प्रकल्पनाएँ थीं, जिन्हें सार्वदेशिक रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। वस्तुतः इंग्लैंड की विशेष परिस्थितियाँ ही उनके जन्म के लिए उत्तरदायी थी अन्यथा वे उस समय के किसी भी समाज के लिए अनुरूप कदापि नहीं थी।⁴ विशेषतः भारत जैसे पिछड़े, अप्रगतिशील तथा कृषि प्रधान देश के लिए तो, जिसमें प्रतियोगिता के बदले यथास्थिति और रस्मों का राज ही हावी रहते हैं, उनकी शायद ही कोई उपयोगिता थी।⁵ द्वितीय, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के अतीत में व्यवहार और अन्य देशों द्वारा किए जा रहे समकालीन

व्यवहार क्लासिकी अर्थव्यवस्था की मान्यताओं अथवा प्रकल्पनाओं की कदापि पुष्टि नहीं करते थे।⁹ वस्तुस्थिति तो यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने रेलों को प्रतिभूति देते हुए, बागान उद्योग को सहायता देते हुए अथवा भूमि पर राज्य-स्वामित्व का दावा करते हुए अथवा कानून के द्वारा किसानों की क्षुद्र संस्कृति की रक्षा करते हुए इन सिद्धांतों का कठोरता से पालन नहीं किया था।¹⁰ तृतीय, क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के दावों के आगे यूरोपीय और अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने प्रश्न-चिह्न लगा दिया था।¹¹ यहाँ तक कि उन पर कितने ही अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने भी प्रहार किया था।¹² इसके अतिरिक्त कुछ एक क्लासिकी अर्थशास्त्री स्वयं अपने आप ही अपने विज्ञान की सर्वव्यापकता और समग्रता के दावे को छोड़ने की पूरी चेष्टा कर रहे थे।¹³ चतुर्थ, क्लासिकी अर्थशास्त्री अधिक से अधिक निश्चल आर्थिक परिस्थितियों का ही विश्लेषण कर सकते थे परंतु वे गतिशील आर्थिक विकास पर प्रकाश डालने में लगभग असमर्थ थे।¹⁴ इन सब तत्वों को देखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यही निकलता था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अथवा नियम भौतिकी और गणित के नियमों के अनुसार अमूर्त तथा सार्वभौमिक नहीं थे प्रत्युत वे सापेक्ष और ऐतिहासिक दृष्टि से परिस्थिति पर निर्भर तथा इसी से निकलते थे। वह समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील थे।¹⁵ अतः किसी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए निर्णायक तत्व अमूर्त आर्थिक सिद्धांत न होकर आर्थिक विकास की विशिष्ट अवस्था ही होनी चाहिए।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रानाडे ने आर्थिक सिद्धांतों की उपयोगिता तथा अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक तर्कसंगति को मानने में कभी इनकार नहीं किया।¹⁶ इसके विपरीत उन्होंने अर्थशास्त्र को स्वतः सिद्ध कानूनों की स्थिति को कला का रूप देकर उसका अवमूल्यन करने वालों की विशेष रूप से ही भर्त्सना की।¹⁷ वे तो केवल व्यवहारिकता का मुद्दे आधार देकर उसे और अधिक सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक बनाना चाहते थे।¹⁸ उनका कथन था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है अतः उसके सिद्धांतों की स्थापना इतिहास के माध्यम से विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से ही करनी अपेक्षित है न कि वियोजक रीति के अनुसार, ताकि उन्हें ऐतिहासिक अनुभव, व्यावहारिक निरीक्षण तथा सामाजिक यथार्थता के साथ निकटता से जोड़ा जा सके। अथवा जैसा कि डी० जी० कर्वे ने लिखा है : रानाडे को केवल विस्तृत, समाजशास्त्रीय तथा रचनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण ही मान्य था।¹⁹ 1881 में रानाडे ने स्वतंत्र व्यापार के प्रश्न को समग्रतः आर्थिक दृष्टिकोण से देखने के लिए तथा प्रश्न के साथ जुड़े राजनैतिक तथा सामाजिक तत्वों की उपेक्षा करने के लिए अंग्रेज अर्थशास्त्रियों की तीव्र निंदा की तथा अपना निश्चित मत व्यक्त किया कि यदि राजनैतिक आधिक्यता को विद्यालय के अध्यापक की अध्यात्म विद्या से भिन्न रूप में ग्रहण करना है तो आर्थिक पक्ष को जनता के ऊँचे हितों और आकांक्षाओं के अधीन ही कर देना चाहिए। वस्तुतः उन्होंने निर्देश किया कि यही कारण है कि लोग व्यावहारिक अर्थात् राजनैतिक आधिक्यता की बात करते हैं विषुद्ध आधिक्यता की कोई बात नहीं करते।²⁰ इस संबंध में रानाडे क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के व्यवहार के प्रति ईमानदार रहे और उन्होंने प्रायः ही आधिक्यता का राजनैतिक आधिक्यता के रूप में जिक्र किया।

समय आने पर रानाडे की क्लासिकी आधिक्यता की आलोचना ने राष्ट्रीय अथवा

भारतीय राजनैतिक आर्थिक चिंतन की आधारशिला रखी। हमारा विश्वास है कि यह विकास प्रमुख रूप से इन दो तत्वों की उपज था : (ए) रानाडे का निष्कर्ष, इस विकास से उद्भूत था कि आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक यथार्थ पर अत्यंत निर्भर होने के कारण तथा आर्थिक व्यवहार की प्रतिबिम्बात्मक विशेषता लिए रहने के कारण सापेक्षता लिए रहते हैं। इस रूप में क्योंकि भारत के आर्थिक हित और परिस्थितियाँ इंग्लैंड के आर्थिक हितों और परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न हैं, अतः भारत पर लागू होने वाले आर्थिक सिद्धांत भी सर्वथा भिन्न होने चाहिए।¹⁸ की तथा अन्य बहुसंख्यक समकालीन राष्ट्रवादियों द्वारा रानाडे के पक्ष और निष्कर्ष की स्वीकृति।

इस प्रकार 1877 में ही के० टी० नैलिंग ने सभी देशों पर राजनैतिक आधिक्यता के सिद्धांतों के समान रूप से लागू न होने के तथ्य के प्रदर्शन के लिए एक अंग्रेज अर्थशास्त्री टी० ई० कलिफ़ बेमली को उद्धृत किया।^{18-ए} उनका यह भी कथन था कि व्यावहारिक प्रश्नों का निर्णय करते समय आर्थिक सिद्धांतों के केवल एक तत्व को ही नहीं लिया जा सकता। सामाजिक और राजनैतिक कल्याण के अन्य तत्व भी समान रूप से महत्व रखते हैं।¹⁹ दादाभाई ने अपने लेख, 'दी पावर्टी आफ इंडिया' में यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्वदेशियों द्वारा शासित देशों में राजनैतिक आधिक्यता सही हो सकती है परंतु गृह प्रचारों और संप्रेषणों की व्यवस्था करने को विदेशी विदेशियों द्वारा शासित देश में कठोरता से इसे लागू नहीं किया जा सकता।²⁰ पृथ्वीशचन्द्र ने भी राजनैतिक आधिक्यता के अमूर्त सिद्धांतों को लेकर किसी देश की समाज-शास्त्रीय स्थितियों पर विचार किए बिना ही उन सिद्धांतों को कठोरता से लागू करने की निंदा की। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में अंग्रेज अर्थशास्त्रियों की आत्मनूत हठधर्मी की गतियों के प्रमाण के रूप में अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूरोप के महाद्वीप को उद्धृत किया।²¹ जी० वी० जोशी ने आर्थिक सिद्धांत की सीधी चर्चा तो नहीं की परंतु उनके द्वारा राज्य की भूमिका, उन्मुक्त व्यापार, आदि प्रश्नों पर किए गए चिंतन से रानाडे के मौलिक मैक्रानिक कार्यक्रम के प्रति उनकी सहमति और औस्था स्पष्ट सिद्ध हो जाती है।²² आर० पी० दत्त ने आर्थिकवाद पर विचार प्रकट नहीं किए परंतु उन्होंने इस तथ्य को अवश्य देखा कि जब अंग्रेज लोग इंग्लैंड में उन्मुक्त व्यापार के पक्ष में आंदोलन चला रहे थे, उस समय भी इंग्लैंड में प्रवेश करने वाले भारतीय माल पर लगने वाले भारी करों की रिकार्डों, कोब्डन ब्राइट और राबर्ट पील उपेक्षा ही कर रहे थे। दत्त महोदय ने स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए यूरोपीय अर्थशास्त्रियों की प्रशंसा की जिन्होंने अंग्रेज राजनीतिज्ञों के इंग्लैंड और भारत में वर्तमान जाने वाले दोगले व्यवहार की निन्धा शब्दों में निंदा की।²³

यद्यपि वे स्पष्ट रूप से ही रानाडे के चरण चिह्नों का अनुकरण कर रहे थे तथापि उनका इस प्रश्न से संबंधित विवेचन ऐतिहासिक महत्ता लिए हुए है। उन्मुक्त व्यापार के प्रश्न पर विचार करते हुए उन्होंने यह दिखाने के लिए कि किसी देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण उस देश की आवश्यकताओं के सदृश होता है न कि आर्थिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, जर्मनी और अमेरिका की संरक्षक नीतियों को उद्धृत किया। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण ही

उसके अनुकूल बैठती है। भारत की परिस्थितियाँ तो इस संबंध में रूस और अमेरिका से ही भिन्न-भिन्न हैं।¹⁴ मित्रता की समस्या के रूप में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, क्लासिकी अर्थशास्त्र एकपक्षीय और अधूरा था। वह हमारे देशों पर लागू नहीं होता था।¹⁵ इसके अतिरिक्त उन्होंने टिप्पणी की और उसमें रानाडे के मत को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, आर्थिक विज्ञान के सत्य राष्ट्रीय विकास की विशिष्ट स्थितियों और विशिष्ट वातावरण तथा परिस्थितियों की अपेक्षा किये बिना सार्वभौमिक रूप से व्यवहार में आने योग्य नहीं है।¹⁶ उन्होंने यह भी निर्देश किया कि यूरोपीय राजनैतिक आधिक्यता कभी स्थिर नहीं रही है। उसकी मान्यताओं, धारणाओं, मित्रताओं और व्यावहारिक प्रयोगों में मध्य युग की विद्वान्ता के समय किन्हीं की परिवर्तन आए हैं।¹⁷ एडम स्मिथ स्वयं एक युगविशेष में सबधित है।¹⁸ जी० एम० गेयर ने आर्थिक चिंतन के सामाजिक उदगम-स्रोतों पर बल देते हुए लिखा, समाज की निर्दिष्ट स्थितियाँ, भविष्य के तथा समकालीन द्वितीय के मध्य में प्रचलित मान्यताएँ ही उन आर्थिक दृष्टिकोणों का निर्धारण करती हैं जिन्हें विचारकों का समर्थन और राजनीतिज्ञों की स्वीकृति प्राप्त होती है। अतः उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा था कि पुर्गने अर्थशास्त्रीय नियमों को भारत पर लागू करने में पूर्व उनमें सुधार अपेक्षित है, क्योंकि भारत के सरक्षणीय आर्थिक हित और परिस्थितियाँ यूरोप और अमेरिका के देशों और परिस्थितियों से भिन्न हैं।¹⁹ उन्होंने इस ओर भी निर्देश किया। भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त आर्थिक नियम यह स्पष्ट करते हैं कि पुर्गने नियमों के पालन करने के बहुत सारे अपवाद उपलब्ध हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश मित्रताओं का यह उल्लंघन केवल प्रबल वर्ग के हितों की सुरक्षा और मंगल के लिए ही किया जा रहा है।²⁰

आर्थिक मित्रताओं और भारत की विभिन्न स्थितियों में उनके प्रयोग की सापेक्षता के प्रश्न को भी वही-कभी लोकप्रिय प्रेम के स्तर तक मुद्दा अभिव्यक्ति दी गई। इस प्रकार उदाहरण के रूप में 1 दिसंबर 1870 के अंक में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने लिखा था, भारत की स्थितियाँ बहुत मामलों में सर्वथा भिन्न हैं अतः आवश्यक नहीं कि हमारे देशों में उपयोगी मित्रता का कानून भारत में भी सही मित्र हो। अपने 7 दिसंबर 1883 के अंक में हिंदू ने टिप्पणी की, यूरोपीय आर्थिक नियमों को यूरोपीय देशों पर लागू करने समय उन देशों की विशिष्ट स्थितियों पर विचार अवश्य करना चाहिए। '...आपसी राजनैतिक अव्यवस्था आखिर अपने आप में अन्तिम लक्ष्य तो नहीं है। 2 अप्रैल 1899 के अंक में 'मराठा' ने रमायनशास्त्र की तरह राजनैतिक अव्यवस्था को विज्ञान का दर्जा देने की चेष्टा करने वाले एडम स्मिथ और काबडन की तीखी आलोचना की। उन अर्थशास्त्रियों ने प्रारम्भ तो सही ढंग से किया। उन्होंने लिखा कि मूल प्रश्न तो यह है कि इंग्लैंड की संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रश्न ने क्रमशः अपनी विशिष्टता खो दी और वह आसानी से तथा शीघ्रता से विशेष से सामान्य का रूप ग्रहण कर गया। मराठा ने विभिन्न आर्थिक मित्रताओं के प्रयोग के मध्य में इस बात पर दृढ़तापूर्वक जोर दिया कि भारत की आर्थिक परिस्थितियाँ इंग्लैंड की आर्थिक परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न होने के कारण यहाँ भिन्न मित्रताओं के प्रयोग की आवश्यकता है। इन्होंने यह भी घोषित किया कि 'आर्थिक मित्रताओं की भ्रम में भारत को बेना नहीं जा सकता।' मराठा ने भारत सरकार

से अनुरोध किया कि वह घोषणा करे कि वह अपने अर्थशास्त्रीय सिद्धांत इंग्लैंड से उधार लेने नहीं जा रही है। निष्कर्ष रूप में इसने राष्ट्रीय आर्थिकता के निर्माण की बकालत की।³¹ विपिनचंद्र पाल के 'न्यू इंडिया' ने भी अपने 21 अप्रैल 1902 के अंक में आर्थिक सिद्धांतों की सापेक्षता पर विचार किया। इसके अनुसार भारत और अन्य यूरोपीय देशों की जनता में तथा उन दोनों देशों के सामाजिक संगठन और जलवायु तथा ऐतिहासिक वातावरण, में व्यापक भेद है। इसी प्रकार दोनों देशों के आर्थिक सिद्धांतों के सामाजिक मूल कारण भिन्न-भिन्न हैं। इसने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक दृष्टिकोण किंगी देश के किसी विशिष्ट समय की विशिष्ट औद्योगिक स्थितियों का परिणाम है अतः उनका एक युग में दूसरे युग में तथा एक देश से दूसरे देश में परिवर्तित तथा भिन्न रूप ग्रहण करना अनिवार्य है।³² बहुत सारे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में उन्मुक्त व्यापार के प्रयोग में लाए जाने के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन के गमय आर्थिक सिद्धांतों की सापेक्षता की ओर संकेत किया।³³

उपर्युक्त बहुत सारे नेता इस संबंध में रानाडे ने एक विषय में आगे बढ़ गए। वे यह समझने और कहने में सफल हो गए कि भारत की स्थितियों की इंग्लैंड में तथा यूरोप और अमेरिका के अन्य बहुत सारे राष्ट्रों की स्थितियों से भिन्नता का कारण इस देश की राज-नैतिक परिस्थिति ही थी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था और विन पर विदेशी सत्ता का नियंत्रण था।³⁴

राज्य की भूमिका

क्लासिकी अर्थव्यवस्था का एक पक्ष सरकार की तटस्थता नीति का सिद्धांत था जिसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने निरंतर और बड़ी प्रबलता के साथ चुनौती दी। उन्होंने इस धारणा को सर्वथा अस्वीकार कर दिया कि सरकार का कार्यक्षेत्र न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित है।³⁵ उन्होंने इस बात की बकालत की कि राज्य की गतिविधि का क्षेत्र इस प्रकार विस्तृत और व्यापक बनाया जाए कि जिससे उन सभी मामलों में, जिनमें राष्ट्रीय प्रयास की अपेक्षा निजी प्रयास कम प्रभावी हो सकते हैं, सरकार हस्तक्षेप कर सके।³⁶ राज्य को राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय इच्छा के सामूहिक अंग के रूप में ही कार्य करना चाहिए।³⁷ उनका यह और भी दृढ़ मत था कि पश्चिम के विकसित देशों की अपेक्षा भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश में राज्य द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक और औद्योगिक हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अधिक प्रबल थी क्योंकि लोगों की वंशानुगत दुर्बलताओं पर काबू पाने में राज्य ही सहायक हो सकता है। और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह देशवासियों की सशक्त विदेशियों के मुकाबले हीन स्थिति और जड़ता से उभरने में सहायता करे।³⁸ जी० वी० जोशी ने तो विशेष रूप से यह अनुभव किया कि भारत में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रतियोगिता के आर्थिक कानूनों के कठोर प्रवर्तन पर इस प्रकार से नियंत्रण करे और मांग प्रदर्शन करे कि जिससे दस्तकारी का आधुनिक उद्योगों में अप्रतिहार्य परिवर्तन इस प्रकार से नियमित हो जाए कि उसके फलस्वरूप होने वाली आर्थिक अर्थव्यवस्था और दुर्भाग्य न्यूनतम रह जाए।³⁹ राज्य के

आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की सीमा के संबंध में जस्टिस रानाडे और जी० बी० जोशी में थोड़ा बहुत मतभेद था। रानाडे किसी प्रकार की सैद्धांतिक सीमाओं के निर्धारण के विरुद्ध थे। उनका कथन था, 'राष्ट्रीय आवश्यकताएं ही एकमात्र कनौटी होनी चाहिए।' उनका यह सुद्ध मत था, 'प्रश्न तो समय अनुरूपता और उपयोगिता का है न कि स्वतंत्रता और अधिकारों का।'¹⁰ इसके दूसरी ओर जी० बी० जोशी का विश्वास था कि राज्य की कार्यवाही एक असामान्य उपाय था अतः उसे प्रतिबंधित करना आवश्यक था ताकि वह कहीं निजी प्रयास को सहायता देने के बजाय उसे दबाना और यहां तक कि अप्रदक्ष्य करना ही प्रारंभ न कर दे।¹¹

आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को व्यापकृत मिट्ट करने के लिए जस्टिस रानाडे और जी० सुब्रह्मण्य ऐयर ने भी 'आर्थिक व्यक्ति' 'स्वनिर्णयित आर्थिकता' त्रैमासिक धारणाओं के केंद्रबिंदु व्यक्तिगत सर्वोच्चता और व्यक्तिगत हितों के सिद्धांत पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने व्यक्ति हितों के संरक्षण के स्थान पर सामूहिक हितों के संरक्षण को प्राथमिकता देने के सिद्धांत का पक्ष ग्रहण किया। रानाडे ने अपने इस दृष्टिकोण को इस प्रकार में प्रस्तुत किया :

आधुनिक चिंतन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी भी सिद्धांत का केंद्रबिंदु, सच्चा केंद्रबिंदु, सामान्य जन अर्थात् समाज जिसके कि व्यक्ति निजी तौर पर मदद है, की (सर्वसाधारण की) सामूहिक रक्षा की और सामूहिक कल्याण की भावना ही होना चाहिए। यदि सिद्धांत कोणी कल्पना नहीं तो केवल व्यक्ति के अधिकार ही नहीं प्रत्युत समाज शिक्षा और अनुगमन तथा उसके कर्तव्यों को भी गौरव प्राप्त होना चाहिए।¹²

इसी प्रकार जी० एस० ऐयर ने ऐडम स्मिथ की, मनुष्य को विशुद्ध रूप में निजी लाभ की दिशा में एकरूपता से कार्यशील 'अहंवादी शक्ति' मिट्ट करने के लिए तथा इस तथ्य की ओर, कि मनुष्य को अपने पड़ोसियों, अपने देश और व्यापक रूप में मानवता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में मधुर संबंधों की स्थापना करनी चाहिए समुचित ध्यान न देने के लिए, आलोचना की। जर्मन ऐतिहासिक विचारधारा को दोहराते हुए उन्होंने लिखा :

समाज के पृथक् पृथक् सदस्यों के तात्कालिक निजी स्वार्थ कुल मिलाकर समाज को उच्चतम लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकते। इतना ही नहीं प्रत्युत प्रायः ही ने इस दिशा के विरोधी हैं। राष्ट्र की एकता और प्रगति बनाए रखने पर ही व्यक्तिगत सुरक्षा, कल्याण और सम्यता निर्भर है। अन्य सभी हितों के समान निजी आर्थिक हितों को भी राष्ट्रीयता की परिपूर्णता और सुदृढ़ता के सामने गौण बना देना चाहिए।¹³

जी० बी० जोशी ने इस दिशा में एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया कि वस्तुतः राज्य की तटस्थ नीति के सिद्धांत का जन्म इंग्लैंड में राज्य द्वारा समाज के एक समुदाय की उपेक्षा करके उसके मूल्य पर दूसरे समुदाय की सहायता करने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ है। उनका विचार था कि जहां राज्य एक वर्ग के प्रति पक्षपात करता हुआ, तथा राष्ट्रीय हितों के स्थान पर केवल वर्गगत अथवा जातिगत हितों का संवर्धन करता हुआ पाया जाए वहां राज्य के हस्तक्षेप पर आपत्ति सही समझी जा सकती है, परंतु उनका

कथन था कि भारत में तो स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। यहाँ तो हितों में किसी प्रकार का कोई वर्गगत संघर्ष नहीं है, अन्य स्थानों के समान इस देश में तो वर्गों में किसी प्रकार की कोई मोटी दरार नहीं है। यहाँ हम राज्य से एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग की सहायता करने अथवा पूँजीपति वर्ग के प्रति पक्षपात करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। हम तो राज्य से सारे समाज की ही वर्तमान असहाय स्थिति में उसकी सहायता के लिए निवेदन कर रहे हैं। भारतीय समाज के सभी वर्ग शक्तिशाली विदेशियों में प्रतिगोपिता में पिछड़े रहे हैं और दुखी हैं और सभी वर्ग समान रूप से भारत के द्रुत आर्थिक विकास में रुचि रखते हैं।¹⁴

राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप तथा निजी हितों के ऊपर सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता देने के जुड़वें सिद्धांत को आधार मानते हुए भारतीय नेताओं ने भारत सरकार ने माग की कि वह देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष, भुविचारित तथा मुनियमित नीति का अनुसरण करे क्योंकि उनकी दृष्टि में देश में औद्योगिक विकास राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण की एक आवश्यक शर्त थी।¹⁵ उनमें से बहुतों ने कृषि को भी राज्य द्वारा अनेक प्रकार से सहायता दिए जाने की बात कही।¹⁶ रानाडे ने तो इस सिद्धांत को इस रूप में लिया कि राज्य तो सारे समाज का संरक्षक है और जिस किसी भी क्षेत्र में दुर्बल को सबल में बदलने की आवश्यकता हो, राज्य का उधर प्रवृत्त होना कर्तव्य बन जाता है।¹⁷ उन्होंने किसानों को सुगम बनाने और माहूकानों को नियमित करने के लिए कानून बनाने का समर्थन किया।¹⁸ उन्होंने संपत्ति के और अधिक न्यायोचित वितरण की भी वकालत की।¹⁹ इसी प्रकार जी० एम० ऐयर ने श्रमिकों के पक्ष में राज्य के हस्तक्षेप की इस तर्क के आधार पर वकालत की कि श्रम और पूँजी का असमान संघर्ष में दुर्बल की रक्षा करना राज्य का दायित्व है।²⁰ यहाँ यह फिर दोहरा दिया जाए कि बहुत सारे अन्य भारतीयों ने शांतिपूर्वक चल रहे निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सरकारी हस्तक्षेप का तीव्र विरोध किया।²¹

यहाँ हम अपने पाठकों को मावधान करना चाहेंगे कि कहीं वे राष्ट्रवादियों के राज्य द्वारा आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सैद्धांतिक सुरक्षात्मक पक्ष में और समाजवादी तथा यहाँ तक कि लोक कल्याणकारी राज्य की इच्छा से उद्योग के लिए राजकीय सहायता की माग में, जो किन्हीं मामलों में स्वयं राज्य द्वारा किसी उद्योग के संचालन का रूप ले सकती थी,²² घपलान कर बैठें तथा इस विषय में सचेत रहें। समाजवाद और यहाँ तक कि सरकारी पूँजीवाद की वकालत करने की तो कोई बात ही नहीं थी, ये अर्थशास्त्री तो केवल यही चाहते थे कि सरकार कृषि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन जुटाए। इस रूप में ये नेता लोग केवल यही चाहते थे कि भारत जैसे पिछड़े देश में निजी उद्यम ही कमियों की पूर्ति सरकार करे। रानाडे राज्य की भूमिका में यही अभिप्राय लेते थे, इस तथ्य की पुष्टि उनके लेखों, 'नीदरलैंड्स इंडिया ऐंड दी क्लबिंग सिस्टम', 'वाइरन इंडस्ट्री, पायनीयर्स अटेंप्ट्स' तथा 'इंडस्ट्रियल कान्फ़ेस' के अध्ययन से सुस्पष्ट हो जाती है।²³ उनकी 1886 की एक अप्रसिद्ध रचना से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। जहाँ वे एक ग़ौर मामान्य रूप से भंडारों

के लिए अपेक्षित सामग्री के लिए सरकारी कारखानों में सभी प्रकार के कुशल उत्पादनों की बात करते हैं,⁵⁴ वहाँ वे 1886 की वित्त समिति के प्रतिवेदन में भी अपनी असहमति प्रकट करते हुए सरकार पर जेलों के उत्पादन पर लगे समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंधों को हटाने पर तीव्र आपत्ति करते हैं क्योंकि उनके विचार में इससे सरकारी धन की सहायता में सरकारी अधिकारियों को प्रतियोगिता में निजी उद्यम को पीछे धकेलने में प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से ही सरकारी कारखानों की सहायता में वाण्ययंत्र, छापाखाना, तंबू, बागज, गलीचे आदि बनाने के लिए जेलों का उपयोग करने की आलोचना की। दूसरे शब्दों में जिस सामान का उत्पादन निजी उद्यमी कर रहे थे, सरकार द्वारा उसी सामान के उत्पादन के लिए जेलों का उपयोग करने पर आपत्ति की।⁵⁵

जी० बी० जोशी ने सरकारी समाजवाद के अथवा सरकारी पूँजीवाद के किसी भी सुभाव का और भी अधिक सुदृढ़ता और स्पष्टता में विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने 1890 में लिखा, हमारी योजना निश्चित रूप से ही सरकारी समाजवाद जैसी योजना नहीं है, उदाहरणार्थ जैसे कि 1848 में अस्थायी सरकार ने घातक और दुर्भाग्यपूर्ण अमफचना के साथ चेष्टा की थी।⁵⁶ प्रथम, उन्होंने बार-बार दोहराते हुए यह टिप्पणी की कि राज्य की कार्यवाही का एकमात्र उद्देश्य शान्तिशाली और उन्नत विदेशियों के साथ शांतिपूर्ण भारत में उद्यमियों के असमान मधर्ष में मनुष्य की व्यवस्था करना है ताकि भारतीय उद्यम का आरम्भ में ही गलत न घोट दिया जाए।⁵⁷ द्वितीय, उनका दृढ़ मत था कि मूल रूप से औद्योगिक विकास निजी प्रयोग का ही कार्यक्षेत्र तथा अधिकार क्षेत्र है। राज्य की भूमिका तो निजी उद्यमी का स्वतंत्र रूप में दायित्व भंग करने के योग्य बनाने तक ही सीमित है। ज्यों ही निजी उद्यमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए न्यो ही सरकार को उसके मार्ग से एकदम हट जाना चाहिए। उस स्थिति में राज्य के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर एकाधिकार का प्रयत्न करना सर्वथा अनुचित ही होगा।⁵⁸ तृतीय, राजकीय सहायता द्वारा निजी उद्यम का नष्ट करने के लिए राज्य के आक्रामक और घातक रूप ग्रहण करने की आशंका को स्वीकार करने हुए उन्होंने उसके क्षेत्र, दिशा और अवधि पर कड़ी सीमाएँ लगाने का प्रस्ताव रखा।⁵⁹ अन्तिम, उन्होंने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि वह मिर्चवाई, वन मरक्षण और तनावी भत्ते जैसे कार्यों को अपने ही अधिकारों द्वारा पूरा कर रही है, जबकि ये सभी कार्य इस देश के ही निजी उद्यमियों द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए और सरकार का तो केवल इस दिशा में निजी उद्यमियों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इन कार्यों के संचालन के लिए यदि आवश्यकता हो तो उपदान देना चाहिए।⁶⁰

भूमि लगान : कर अथवा किराया

भारतीय नेताओं द्वारा सरकारी सिद्धान्तवादी ढंग पर आपत्ति किया जाने वाला क्षेत्र भूमि-राजस्व प्रशासन था। मतभेद के प्रमुख विषय थे, भूमि-लगान का स्वरूप और कृषि-भूमि पर अंतिम स्वामित्व। भारतीय प्रशासकों का यह व्यापक मत था कि अनन्त काल से भारत में भूमि पर राज्य का अंतिम अधिकार चला आ रहा है। ग्रन्थ धरती बोने वाले अथवा

जमींदार सरकार के किरायेदार है। फलतः जमींदारों द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला लगान किराया है कर नहीं।⁶¹ राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों और दूसरे नेताओं ने इस धारणा को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। उनका कथन था कि भारतीय जमींदार अपनी भूमि का ठीक उसी प्रकार स्वामी है, जिस प्रकार विश्व के किसी अन्य भाग का जमींदार अपनी भूमि का है। उन्होंने इस बात को दृढ़तापूर्वक सामने रखा कि अतीत इतिहास की गलत व्याख्या की जा रही है और यहाँ तक कि भूमि पट्टेदारी में निहित मिद्दानों की भी अवहेलना की जा रही है। अतः उनकी मान्यता थी कि सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला भूराजस्व एक कर है और सरकार की आवश्यकताओं के लिए उसे इस ढंग से वसूल किया जा रहा है, जिस ढंग से कि अन्य देशों में वहाँ की सरकारें करती हैं।⁶² यह एक रोचक तथ्य है कि सरकारी प्रवक्ता प्रायः इस बात पर बल देते थे कि ब्रिटिश शासक सारी भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए केवल देश के भूतपूर्व शासकों का ही अनुकरण कर रहे थे। जी० वी० जोशी ने बल देकर कहा कि यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी तार्किक कठोरताओं के साथ भारतीय जीवन के तथ्यों पर पश्चिमी सिद्धांतों को अविचारपूर्वक ही लागू किया जा रहा है।⁶³

रानाडे और जोशी जी ने भारतीय पद्धति के भूमि लगान के रिकार्डियन आधार पर भी प्रहार किया। सरकारी दृष्टिकोण और सिद्धांत के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि भारत में राज्य के किरायेदार अथवा जमींदार पूँजीपति किसान हैं और वह 'आर्थिक किराया' चुकाते हैं।⁶⁴ यही बढ़िया भूमि के उत्पादन के और सबसे अधिक घटिया भूमि, जिसे जोतकर केवल खर्चा पूरा होता है, के उत्पादन के बीच का मूल्य सबधी अंतर है। इस परिभाषा के अनुसार जोत के मूल्य के अतर्गत किसान के श्रम के मूल्य के साथ ही साथ लाभ की वर्तमान दर पर उसकी पूँजी का मूल्य भी सम्मिलित था।⁶⁵ इससे स्पष्ट था कि किराये के इस सिद्धांत के अनुसार सीमांत भूमि पर उत्पादन मूल्य द्वारा निर्धारित मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि किए बिना तथा मजदूरी को किसी प्रकार से प्रभावित किए बिना ही राज्य भूमि के स्वामी के रूप में भूमि के आर्थिक किराये को भूराजस्व के तौर पर हड़प सकता था।⁶⁶ रानाडे और जोशी ने रिकार्डों के किराये के सिद्धांत के मूल रूप की आलोचना नहीं की परंतु उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि भारत में इस सिद्धांत की कोई उपयोगिता है। क्लासिकी राजनैतिक अर्थव्यवस्था में पूँजीपति किसान का किराया पूँजी की प्रतियोगिता, जनसंख्या के आकार तथा भूमि की विभिन्न स्तरीय उत्पादन क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है।⁶⁷ रानाडे की आपत्ति यह थी कि क्योंकि राज्य देश में एकमात्र भू-स्वामी बन गया है अतः खेतिहरों को प्रतियोगी मूल्य न देकर एकाधिकार के रूप में मनमाना किराया चुकाना पड़ता है। सरकार मनमाने ढंग से जितना चाहे, किराया बढ़ा सकती है और यह प्रायः खेतिहरों के लाभों और परिश्रम पर छाप मारना है।⁶⁸ जोशी जी की इसमें और अधिक मौलिक आपत्ति यह थी कि उन्होंने निर्देश किया कि रिकार्डों के सिद्धांत के अनुरूप पूँजीपति किसानों की आवश्यकता है और भारत में पूँजीपति किसानों का अस्तित्व ही नहीं। भारतीय किसान जमींदारों और रैयतवाड़ी दोनों इलाकों में अधिक लाभों से प्रेरित पूँजीपति किसान की अपेक्षा भूस्वामी

से किराये पर लेकर भूमि जोतने वाला ही है। उनके अनुसार स्थिति के दो मौलिक पक्ष हैं : (क) खेतिहर का तात्कालिक उद्देश्य आजीविका प्राप्ति है न कि निवेशित पूँजी पर लाभ का अर्जन करना है। (ख) खेतिहरो में भूमि के लिए प्रबल प्रतियोगिता है। इसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या क्रमशः खेति योग्य खाली भूमि की उत्तरोत्तर अनुपलब्ध तथा कृषि उद्योगों की अमफलता आदि है। इनके फलस्वरूप किसान क्रूर आर्थिक आवश्यकताओं का शिकार बन गया है और उसे शीघ्र ही अपनी भूमि में हाथ घोने तथा भूमिहीन मजदूर बनने के बदले सरकार द्वारा अथवा निजी जमींदार द्वारा निर्धारित मनमाने किराये का भुगतान करने के लिए राजी होना पड़ता है, भले ही उसे इसके बिना क्यों न सामान्य जीवन के स्तर में भी नीचे का जीवन बिताना पड़े।⁶⁹

रानाडे और जोशी जी ने रिकार्डों के किराया सिद्धांत के प्राकृतिक परिणाम अनुपाजित आय के सिद्धांत की भी आलोचना की। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी भूखंड पर उस समय तक निवेशित पूँजी पर लाभ की चालू दर में अधिक किंगया बढ़ाया जाता है तो दोनों का अंतर किराये में अनुपाजित वृद्धि कहलाएगी, जो लाभ की दर में सामान्य गिरावट का तथा समाज की सामान्य प्रगति का परिणाम होगा। अतः उस पर समाज का ही न्यायाचित अधिकार होगा न कि दूसरों के रक्त को चूमने वाले भूखंड के स्वामी का।⁷⁰ रानाडे और जोशी जी का तर्क था कि भारतीय भूमि लगान पद्धति में इस सिद्धांत को लागू करने में समाज, अर्थव्यवस्था तथा किंगया ऊँचे हुए है और जमींदारी व्यवस्था की स्थिति स्थिर हुई है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में जहाँ पीढ़ियों में भूमि एक ही परिवार के हाथ में रहती आती है, वहाँ भारत में उसके विरुद्ध भूमि का स्वामित्व निरंतर बदलता रहता है। फलन पत्येक नया खरीदार भूमि का पूरा ही चालू मूल्य, उपाजित और अनुपाजित दोनों का भुगतान करता है। उस प्रक्रिया में भूतकाल की अनुपाजित आय-संबंधा लुप्त हो जाती है।⁷¹ इसके अतिरिक्त जोशी जी ने टिप्पणी की कि लगान अधिकारी प्रायः ही अनुपाजित आय की खोज में बलपूर्वक ही वृद्धि करने का रास्ता अपनाते हैं और इस प्रकार वेचारे किसानों की आजीविका को ही हड़प लेते हैं।⁷²

उन्मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण

राष्ट्रवादी प्रारंभ से ही उन्मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण के प्रश्न में गहरी रुचि रखते थे। 1877 में ही अपने विस्तृत लेख, 'फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन', में के० टी० नैलन ने एक भारतीय के दृष्टिकोण से टिप्पणी की कि यह विषय हमारे देश के समग्र भविष्य, सामाजिक, राजनैतिक व औद्योगिक, के साथ इतनी घनिष्टता से जुड़ा हुआ है कि इसके सबंध में सही दृष्टिकोण को अपनाने की महत्ता स्वतः सिद्ध है, इसमें किसी प्रकार की अतिरजना संभव ही नहीं।⁷³

राष्ट्रवादी नेताओं ने लगभग एक मत से ही यह मांग की कि देश के स्वस्थ आर्थिक विकास के हित में भारत सरकार को देश के विकासशील उद्योगों को संरक्षण देकर उसकी सहायता करनी चाहिए।⁷⁴ उदाहरणार्थ जी० सुब्रह्मण्य ऐयर ने 1903 में लिखा : 'कृषि

से अलग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अस्तित्व में लाना देश की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसकी पूर्ति... संरक्षण की नीति को अपनाने के द्वारा... ही हो सकती है। जब तक तथाकथित उन्मुक्त व्यापार और असमान प्रतियोगिता की स्थिति जारी है तब तक देश ऐसे किसी उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं कर सकता, जिसे भौतिक दृष्टि संपन्न कहा जा सके।... अपने देश के बाजारों में खपत के लिए देश में उत्पादित खाद्यान्न और कच्चे माल के निर्यात पर कर लगाने के माध्यम से उसे देश में ही सुरक्षित बनाना तथा देशी उद्योगों के विकास की दृष्टि से विदेशी प्रतियोगी उत्पादनो के आयात पर प्रतिरक्षात्मक शुल्क लगाकर उसे प्रतिबंधित करना, यही एक मात्र नीति भारत को बचा सकती है।⁷⁵ किन्तु, यह कम आश्चर्यजनक बात नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम बीस वर्षों के जीवन में एक बार भी संरक्षण की मांग नहीं की। इसका कारण अश्वतः शायद उनके अपने मित्र इंग्लैंड के क्रांतिकारियों को संतुष्ट रखने की भावना थी और अंशतः ब्रिटेन के उन्मुक्त व्यापार के प्रति दृढ़ और निश्चयात्मक रुझान के कारण हिच-किचाहट स्पष्टतया राजनैतिक दृष्टि से इस मांग को मनवाना संभव नहीं था।⁷⁶

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने उन्मुक्त व्यापार को, संरक्षण के माध्यम में, भारत के औद्योगिक विकास के मार्ग की एक प्रमुख बाधा अनुभव करते हुए भारतीय परिस्थितियों में उन्मुक्त व्यापार की उपयोगिता को निरर्थक सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उनका कथन था कि इसके विपरीत भारत के मुदीर्घ और व्यापक हितों में संरक्षण लाभदायक है न कि हानिप्रद। इस संबंध में 1877 में सर्वप्रथम और सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रयास पूर्वोद्धृत लेख के माध्यम से के० टी० तैलंग ने किया। बाद के बहुत सारे लेखक तैलंग महोदय के लेख को ही आधार बनाते दिखाई देते हैं।

उन्मुक्त व्यापार के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का प्रमुख तर्क यह था कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।⁷⁷ भारतीय नेताओं का कथन था कि इसने इंग्लैंड में उपयोगी भूमिका निभाई होगी परंतु यहाँ भारत में तो उमने उद्योग को बड़ी भारी हानि पहुँचाई है।⁷⁸ उन्होंने आगे दृढ़ स्वर में कहा कि वस्तुतः उन्मुक्त व्यापार तो बराबर के देशों के मध्य चल सकता है। यहाँ भारत और इंग्लैंड की स्थिति तो कुछ-कुछ ऐसी है कि एक (भारत) भूखा, थका-मादा (बीमार) और पंगु है तथा दूसरा (इंग्लैंड) केवल शक्तिशाली ही नहीं प्रत्युत उसके पास मवारी के लिए घोड़ा भी है।⁷⁹

कुछ एक भारतीय नेताओं ने इस धारणा, संरक्षण से उपभोक्ता की स्वतंत्रता और उद्यमी की स्वाधीनता प्रतिबंधित होती है, का भी खंडन किया। उनका कथन था कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अर्थ शायद असीमित प्रतियोगिता के द्वारा भारत के विकासशील उद्यम को नष्ट-भ्रष्ट करने की विदेशियों को खुली छूट देना नहीं हो सकता। वास्तव में भारतीय स्थितियों में वास्तविक स्वतंत्रता संरक्षण और कृत्रिम पोषण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगी, जबकि उन्मुक्त व्यापार का अर्थ ही अपेक्षाकृत सशक्त दल, इंग्लैंड, को संरक्षण प्रदान करना सिद्ध हो रहा है।⁸⁰ उपभोक्ता के लिए जहाँ तक संरक्षण के मूल्य का संबंध है भारतीय राष्ट्रवादी नेता इस बात से सहमत थे कि राष्ट्र इस भार को सहन कर लेगा क्योंकि मूल्यों के, गिरावट के वेतन और नौकरी में वृद्धि के तथा राष्ट्रीय

आय में सामान्य विकास के दूरगामी लाभ इस भार को पीछे ही छोड़ जाएंगे।¹¹ तैलंग महोदय को यह मित्र करने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि भारत में संरक्षण से केवल प्राकृतिक साधनों से ही पत्रों के मोड़ में सहायता नहीं मिलेगी प्रत्युत देश के बेकार धन सग्रहों से भी धन जुटाने में सहायता प्राप्त होगी।¹² उन्होंने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए आगे कहा कि जहां तक संरक्षण के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का संबंध है, इसके फलस्वरूप होने वाला औद्योगिक विकास समग्र रूप से लाभदायक ही होगा। इसमें मांग के बढ़ जाने के कारण श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा। इसमें उन्हें यह कहने पर विवश होना पड़ा कि संरक्षण किमी दग के कुल उत्पादन में भले ही हलाम ला दे फिर भी भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण के लिए उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा कि देशवासियों की विपुल जनसंख्या के मुखमरी और अभावग्रस्तता का शिकार बने रहने पर थोड़े से लोगों की संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यदि बहुसंख्यक जनता की मुखमरी और अभावग्रस्तता दूर की जा सके तो भले ही थोड़े से लोगों को मिलने वाली संपन्नता न भी मिले तो कोई बात नहीं।¹³

कितने ही भारतीय अर्थशास्त्रियों ने क्लेमिकी अर्थशास्त्रियों की इस मान्यता-उन्मुक्त व्यापार तुलनात्मक मूल्यों के माध्यम में काम करता हुआ श्रम के योग्यतम भौगोलिक विभाजन में सहायक होता है, के आगे प्रश्न चिह्न लगाया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि श्रम का किमी भी रूप में इस प्रकार का विभाजन लगभग लाभदायक होगा कि जिसमें भारत सदा के लिए कच्चे माल का उत्पादक देश बना रहे। उन्होंने इस धारणा को पूरे तौर पर मानन में टनकार कर दिया कि भारत सदा के लिए कच्चे माल का इंग्लैंड का निर्यात करे और इंग्लैंड में उत्पादित माल का आयात करे।¹⁴ उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि इतिहास, भूगोल और साधनों की दृष्टि में भारत एक महान उत्पादक देश के रूप में पूर्ण रूप में उपयुक्त देश है।¹⁵ किमी भी रूप में हो, यह जाचने के लिए कि नए देशों को उनके परंपरागत व्यवसायों की अपेक्षा नए उद्योग अनुकूल बैठते हैं कि नहीं, अस्थायी संरक्षण की आवश्यकता है।¹⁶ इसके अनिश्चित जब तक प्रत्येक देश की पूर्ण क्षमता का ज्ञान और विकास नहीं हो जाता, तब तक श्रम का पारस्परिक रूप में उपयोगी और न्यायोचित विभाजन हा ही नहीं सकता। इस समय सार्वभौमिक तथ्य के रूप में उन्मुक्त व्यापार को अपनाता श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन की चालू प्रणाली को अपरिवर्तित रूप देना है, जिसका अर्थ यह होगा कि जो देश पहले में ही विकसित हो चुके हैं, सदा के लिए औद्योगिक दृष्टि से अगुवा बने रहेंगे तथा भारत जैसे पिछड़े देश और अधिक पिछड़े जाएंगे तथा विशुद्ध रूप में कृषि प्रधान देश बनकर रह जाएंगे।¹⁷ के० टी० तैलंग ने किसी देश को एक ही उद्योग वाला देश बनाए रखने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि देश के उत्पादनों को प्रभावित करने वाले व्यवहारों, रूचियों और आवश्यकताओं में किसी प्रकार के परिवर्तन उस देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे।¹⁸

भारतीय नेताओं में से कितनों ने ही यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि एक सीमित अवधि के लिए शिशु उद्योग को संरक्षण देना तटस्थता की नीति के सिद्धांतों के भी विरुद्ध नहीं। उन्होंने जान स्टुअर्ट मिल के उन लेखों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया, जिनमें उन्होंने

भारत में व्याप्त स्थितियों जैसी स्थितियों में संरक्षण की स्वीकृति दी थी।⁸⁰ वस्तुतः भारत के लिए एक विशिष्ट स्थिति के रूप में संरक्षण की मांग करने वाले अपने को सिद्धांत रूप में स्वतंत्र व्यापारी सिद्ध करने का ही दावा कर रहे थे।⁹⁰

भारत के मामले में संरक्षण को उचित तथा न्यायमंगत सिद्ध करने के लिए भारतीय नेताओं में से कइयों ने एक बहुत ही बढ़िया तर्क प्रस्तुत किया। उदाहरणार्थ 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड में भारतीय उत्पादकों के आयात पर थोपे गए भारी करों को उद्धृत करते हुए के० टी० तैलंग ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को नष्ट करने के लिए अपनाया गया उपाय यही संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि सभी भारतीयों की यह मांग है कि हमारे विरुद्ध तलवार के रूप में प्रयोग किए गए शस्त्र का प्रयोग अब हमारे रक्षक के रूप में करना चाहिए।⁹¹ इसी प्रकार आर० सी० दत्त ने जली-कटी मुनास्ते हुए टिप्पणी की, उद्योगों के विरुद्ध संरक्षण ने भारत में जनता की उत्पादन-क्षमता को समाप्त कर दिया है और उसके उपरगत प्रतियोगी को पुनः प्रतियोगिता में आने में हटाने के लिए भारत पर उन्मुक्त व्यापार थोप दिया गया है।⁹²

अपनी संरक्षण की मांग को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नेताओं ने राजनैतिक आधिक्यता के सिद्धांतों के बरने राष्ट्रों के व्यवहार को देखने का अनुगोष किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया कि लगभग यूरोप और अमेरिका के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों और यहां तक कि कॅनेडा और आस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों ने विदेशी प्रतियोगिता के खतरे के उपस्थित होने पर अपने नवजान उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया है।⁹³ उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक यह देखा कि 18वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में स्वयं इंग्लैंड ने संरक्षण की देखभाल में ही अपने आधुनिक उद्योगों का विकास किया है। इसी संरक्षण की कृपा का ही फल था कि औद्योगिक-यंत्र गतिशील होकर पूर्णता के उम्र चरम शिखर पर पहुंचा कि जहां में इंग्लैंड स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत की घोषणा करने में समर्थ हो सका है।⁹⁴ आर० सी० दत्त और जी० मुन्नास्ते यह देखने में भी नहीं चूके कि जहां 18वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद में ऐडम स्मिथ जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत का गला फाड़कर प्रचार करते चले आ रहे हैं वहां ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने उन्मुक्त व्यापार का रूप बहुत पीछे ही ग्रहण किया और वह भी तब, जबकि उन्हें यह अपने अनुकूल लगा।⁹⁵ बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता इस सीमा तक कहने लगे कि ब्रिटेन ईमानदारी से उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता और उसका प्रयोग एक बढ़ाने के रूप में कर रहा है। जी० बी० जोशी ने भारत में अपने उत्पादनों को धकेलने के लिए और प्रतियोगी औद्योगिक विकास को रोकने के लिए इसे 'आध्यात्मिक ढाँचे' का नाम दिया।⁹⁶

उन्मुक्त व्यापार की आलोचना तथा उद्योगों के लिए संरक्षण की वकालत करते हुए भी किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता ने संरक्षण के पक्ष में कट्टर सैद्धांतिक नीति नहीं अपनाई। इस संबंध में उनका दृष्टिकोण विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित था। स्वभावतः ही उन्मुक्त व्यापार की अस्वीकृति भी किसी सिद्धांत विशेष पर आधारित नहीं थी। अन्यान्य आर्थिक विषयों में उनके दृष्टिकोण के समान उनकी सीमा-शुल्क नीति भी सामान्य आर्थिक

सिद्धांतों की उपज नहीं थी, प्रत्युत सुस्पष्ट आर्थिक विषयों में उत्पन्न और उनसे घनिष्ठता से संबंधित थी। संरक्षण के बचाव के संबंध में उनका यह सारग्राही दृष्टिकोण कभी-कभी अत्यंत सुस्पष्ट हो जाता था। उदाहरणार्थ आर० सी० दत्त ने 1901 में लिखा, मैं अपना विश्वास नहीं तो उन्मुक्त व्यापार के प्रति निश्चित करता हूँ और न ही संरक्षण के प्रति। मेरी मान्यता तो यह है कि भारत की जनता की संपन्नता और समृद्धि के लिए सर्वथा और सर्वाधिक अनुकूल नीति ही सच्ची नीति है और उसी नीति को भारत के लिए अपनाना चाहिए।⁹⁷ वास्तव में 20 वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष में जैसे कि कुछ एक राष्ट्रवादी नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहता प्रारंभ कर दिया कि वे संरक्षण को इतना नहीं चाहते जितना कि गोमा-गुल्क-नीति के निर्धारण में स्वतंत्रता चाहते हैं।⁹⁸ इस समय कुछ भारतीयों ने विभिन्न प्रकार के संरक्षणों के बीच अंतर करना भी प्रारंभ कर दिया और वे स्पष्ट रूप से देखने लगें कि जनतंत्र में संरक्षण का परिणाम विदेशी पूँजी का बड़े पैमाने पर अंतःप्रवाह होगा। विदेशी पूँजी का यह व्यापक प्रवाह संरक्षण के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र पर एकाग्रित हो जाएगा। इस प्रकार 'हिंदुस्तान रिव्यू' और कादम्ब्य समाचार के संपादक ने 1903 में लिखा : भारत की उन्नति के अधीन वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर्गत संरक्षण ही नीति को अपनाने का परिणाम आर्य भारतीयों (भारतीय उद्योग) उत्पादकों और तम्रण विदेशी शोषकों के पक्ष में उसके दुरुपयोग के रूप में सामने आने की ही सर्वाधिक संभावना है। यह सच है कि ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा विदेशी पूँजीपतियों के प्रति जो अपमान हो रहा है, उस समय यह और सभी विदेशी और दूसरे जाति भारतीयों का भी प्रतिफल नहीं रहेगी।⁹⁹

उसी प्रकार 13 अक्टूबर 1903 में अरुण हिंदू ने टिप्पणी की

भारतीय नागरिकों के हितों का उद्देश्य में पूँजी के निवेश के द्वारा प्रभुत्व जमाने वाले यूरोपीयों का अधिकार स्वतंत्र नहीं है। इस समय भारत के लिए वर्तमान माना जाने वाला संरक्षण वास्तव में ही यूरोपीय व्यापारियों की सहायता और व्यापारिकों का ही भाग्य निर्माता बन सकता है। जनता के कुछ भाग में भारत की हितों की रक्षा करने का फंश चल पड़ा है, भले ही उसमें वास्तविक फल देना जापान में सतत मुट्ठी-भर यूरोपियों का ही कर्तव्य न हो।¹⁰⁰

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

निष्कर्ष के रूप में राष्ट्रवादी आशास्त्रियों के सार्वजनिक दृष्टिकोण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की ओर भी ध्यान देना अनुचित न होगा।

राष्ट्रवादियों के आर्थिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष हमारा सामाजिक दृष्टिकोण था। जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों का यह अनुभव था कि सामाजिक दृष्टि से निर्धारित उद्देश्यों और परिप्रेक्ष्यों के सामने आर्थिक विचारों और नीतियों को गौण स्थान ही दिया जाना चाहिए। वस्तुतः राष्ट्रवादियों का समग्र आर्थिक चिंतन श्रमी धारणा से व्यापक था। जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, भारतीय अर्थशास्त्रियों ने अनुभव कर लिया कि आर्थिक चिंतन और नीति को सामाजिक रूप से एकीकृत लक्ष्यों

के अधीन करने की प्रवृत्ति ने भारतीय अर्थशास्त्र का विशिष्ट मूलतत्त्व दिया। आर्थिक विचारों और नीति के इस दृष्टिकोण ने प्रारम्भ से ही भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिए। इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं को इस योग्य बना दिया कि वे लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को देश की राजनैतिक पराधीनता की स्थिति से जोड़ सकें और भारतीय वास्तविकता के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक पक्ष पर विचार कर सकें कि भारत विदेशी शासक द्वारा आर्थिक शासन के लिए ही शासित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रवादी नेताओं का आर्थिक चिन्तन समकालीन अग्रणी चिन्तन से आगे था और यूरोप तथा अमेरिका के चिन्तन के साथ कदम में कदम मिला रहा था, जबकि वह इस बात पर बल दे रहा था कि आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान देशों के लिए एक में आर्थिक सिद्धान्तों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और दृढ़तापूर्वक यह मांग कर रहा था कि प्रत्येक देश के लिए आर्थिक सिद्धान्तों का विधान मबन्धित देश की सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनारे ही किया जाना चाहिए, तब भी भारतीय पद्धतियों के किसी नए आर्थिक विचार अथवा सिद्धान्त का उदय नहीं हुआ।¹⁰¹ आर्थिक चिन्तन के साथ 'भारतीय राष्ट्रवादी' जैसे विश्लेषण तो अवश्य जोड़े गए परन्तु भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने ऐसे नए आर्थिक नियमों का आविष्कार नहीं किया, जो अमान्य भारतीय परिस्थितियों की उपज हों और जिनका प्रयोग विशिष्ट भारतीय परिस्थितियों में ही संभव हो, इन्हीं में जो मिलता है, वह है कर्नामिकी अर्थशास्त्रियों और उनके परिवर्तित आलोचकों के चिन्तन का मिश्रित रूप। वस्तुतः भारतीय राजनैतिक आर्थिकता को आर्थिक चिन्तन की पद्धति न कहकर 'आर्थिक चिन्तन का एक दृष्टिकोण', 'भारतीय आर्थिक समस्याओं पर विचार' तथा 'आर्थिक विचार विमर्श की शैली' आदि नाम देना ही अधिक उपयुक्त होगा।

यह व्यापक रूप से इस तथ्य का परिणाम है कि राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों की आर्थिक सिद्धान्त में रुचि गौण अथवा परिस्थिति में उद्भूत थी। वे आर्थिक सिद्धान्तों के विकास में अथवा अर्थशास्त्र को भारतीय रूप देने में रुचि रखने वाले व्यावसायिक अर्थशास्त्री नहीं थे। अतः उन्होंने स्वयं सिद्धान्त के रूप में उस पर काबू पाने की कोई चेष्टा नहीं की। आर्थिक सिद्धान्त पर उनके विचारों को वस्तुतः समकालीन आर्थिक समस्याओं पर उनकी बहुत सी रचनाओं में ही निकाला जा सकता है। उनकी राजनैतिक अर्थव्यवस्था सर्वथा व्यावहारिक विचारों की ही उपज थी क्योंकि भारत के शामक राष्ट्रवादियों की मांग का विरोध करने के लिए क्लासिकी अर्थव्यवस्था का महारा लेते थे, इसलिए भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी कर्नामिकी अर्थव्यवस्था की सार्वदेशिकता को तथा भारत की परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता को चुनौती देना आवश्यक समझा। उनके आर्थिक चिन्तन के इस अपेक्षाकृत लौकिक उद्गम को उन्होंने कभी-कभी जानबूझ कर अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि उन्हें तटस्थता नीति के सिद्धान्त का खंडन करना है क्योंकि वह उद्योगों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण के मार्ग में बाड़े आता है।¹⁰² किराए के रिकार्डियन सिद्धान्त का खंडन उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका उपयोग भूमि सगानों की ऊँची

दरो को न्यायोचित मिट्ट करने के लिए तथा भूमि के स्थायी वसोवस्त की मांग को अस्वीकार करने के लिए तथा उनके इस आग्रह का खंडन करने के लिए किया गया था कि भारत में कराधान का परिमाण बहुत ऊँचा है।¹⁰¹ उन्मुक्त व्यापार का विरोध इसलिए किया, क्योंकि यह अग्रज कृषि के आयान पर लगे शुल्कों का हटाने के लिए, कृषि पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिए तथा स्वदेशी विकसनीय उद्योगों को संरक्षण देने में इनकार करने के लिए उत्तरदायी था।¹⁰²

भले ही राष्ट्रवादियों के आर्थिक चिन्तन में कुछ भी नया न हो फिर भी भारतीय दृष्टिकोण की केवल अभिव्यक्ति तथा भारतीय परिस्थिति में यूरोपीय चिन्तन को ढालना एक अपनी निजी महत्ता रखता है। आखिरकार विभिन्न सैद्धान्तिक स्थितियों में किसी एक स्थिति का चुनाव करना भी अपने आप में मिथ्यानीकरण है तथा सैद्धान्तिक दृष्टि में महत्वपूर्ण है। भारतीय नेता भले ही अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की उपज थे पर वे किसी भी स्थिति में इसके बहाव में नहीं बह गए और न ही उन्होंने अंग्रेजों के मन में जड़ पड़ने दकियानूसी विचारों पर प्रहार करने में किसी प्रकार का सकोच किया। इसके अनिश्चित वे आर्थिक विज्ञान के प्रति व्यापक और पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के श्रेय के ही भागी हैं। भले ही उन्होंने न समुचित आर्थिक मिथ्याता का विकास नहीं किया अथवा उन्होंने विकास की राजनैतिक अर्थव्यवस्था में याग नहीं दिया तथापि उन्होंने उससे अगला सर्वोत्तम मार्ग यह किया कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का समुचित पूर्ण और सही सबधित चित्र, उसमें रोगों उन रोगों का विदग्ध शासकों में सन्तुष्ट तथा प्रयाग किए जाने योग्य उपचारों का विवरण प्रस्तुत किया। हम इस सीमा तक कह सकते हैं कि उन्होंने विकास के राजनैतिक अर्थव्यवस्था के आखिरकार का प्रयास किया जिसमें अंतर्गत उद्योगों का विदग्ध व्यापार को, कराधान संबंधी नीति को तथा कृषि का परस्पर प्रतिष्ठता में सन्तुष्ट किया गया था और जिसका सारप्रथम दृष्टि में द्रुतगति में जाद्योगीकरण के लिए उपयोग किया गया था। इस सबध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय आर्थिकता की विशुद्ध, स्वदेशी अथवा आधुनिक में पूर्ववर्ती पद्धति का न्यायोचित मिट्ट करने के बदले आधुनिकीकरण की गति को तीव्र बनाने के लिए आर्थिक मिथ्याता की सापेक्षता तथा भारत की अपवादात्मक स्थिति की धारणा का उपयोग किया। उन्होंने क्लासिकी अर्थव्यवस्था को इसलिए अस्वीकार नहीं किया कि वह सदियों पुराने भारतीय जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही थी प्रत्युत इसलिए कि वह परंपरागत दुर्बलताओं तथा पुरानी मान्यताओं को निरंतर बनाए रखने वाले अपरिवर्तनशील और अविवेकपूर्ण व्यवहार का पोषण कर रही थी।¹⁰³ इसके अनिश्चित वह सामंतवादी तथा पदगत परंपरागत बंधनों को और अधिक सुदृढ़ बनानी थी।¹⁰⁴ इसके विपरीत भारतीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आर्थिक जीवन में द्रुतगति से परिवर्तन लाने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए ही अपनाया गया।

संदर्भ

1. रानाडे, एसेज, पृ० 1-39 बलामिक अर्थशास्त्र पर रानाडे के विचारों का प्रारम्भिक परिचय आगस्टस मोन्टेशियन के फ्री ट्रेड ऐंड इग्लिश कामर्स की उनकी समीक्षा से होता है जे० पी०एस० एम०, नुमाई 1881 (खंड IV सध्या 1) प० 50 और आगे तुलनीय मानकर, पूर्वोद्धृत, खंड-I पृ० 2 4-5
2. रानाडे के दृष्टिकोण की विस्तृत परीक्षा के लिए देखिए, जेम्स केलाक, 'रानाडे ऐंड आफ्टर', इंडियन जनरल आफ इकोनामिक्स, जनवरी 1942 (खंड XXII स० 3), भवतोष दत्त, 'द बैंक ग्राऊथ आफ रानाडेज इकोनामिक्स', वही: जे० पी० कोयाजी, 'रानाडेज वर्क ऐज ऐन इकोनामिस्ट' वही : वही० त्रा० कर्वे : रानाडे, 'द प्रोफिट आफ लिबरेटेड इंडिया (नूना, 1942), अध्याय 4 पी० के० गोपालकृष्णन, डेवलपमेंट आफ इकोनामिक्स आइंडियाज इन इंडिया (त्रिस्ली, 1959) अध्याय-3
3. रानाडे, एसेज, पृ० 2
4. वही, पृ० 4-5, 9-10
5. वही, पृ० 8-10, 22-3 42-3, और 'रिच्यु आफ फ्री ट्रेड ऐंड इग्लिश कामर्स', पूर्वोद्धृत, पृ० 51.
6. एसेज, पृ० 4-6, 14 उन्होंने यह भी निर्देश किया कि भारत की समस्याएँ और दशाएँ इंग्लैंड की अपेक्षा यूरोप और अमरीकी महाद्वीपों की समस्याओं और दशाओं से अधिक भेद खाती हैं। उन महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन से प्राप्त शिक्षा अंग्रेजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पाठ्यपुस्तकों में निहित नीतिवाक्यों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक प्रभाव डालेंगी
7. वही, पृ० 3, 28-9, 32-3, 89
8. वही, पृ० 16-21
9. वही, पृ० 10 11, 34-9
10. वही, पृ० 6-7, 16
11. वही, पृ० 8-9
12. वही, पृ० 1-5, 21-2 89-90. यहाँ रानाडे ने इंग्लैंड से भिन्न होने के आधार पर भारत के पारम्परिक राजनीतिक मन्थन एवं मंगरेज राजनीतिज्ञों के इनकार करने पर तो व्यंग्य प्रहार किया परन्तु आर्थिक नीतियों की चर्चा करते समय वे इस तथ्य का सर्वथा भूल गए (वही, पृ० 2, 4-5).
13. तुलनीय, केलाक, 'रानाडे ऐंड आफ्टर', पूर्वोक्त स्थान, पृ० 253, कर्वे पूर्वोद्धृत, पृ० 54-6.
14. रानाडे, एसेज, पृ० 21
15. उन्होंने लिखा : 'व्यापक व्यवहार का नाम ही तो सिद्धांत है तथा अनुमानित कारणों के संदर्भ में किया गया अध्ययन ही वस्तुतः व्यवहार है। सिद्धांत का निर्णायक तत्व व्यवहार ही है, वही उनकी सन्ध्या का परीक्षा करता है तथा गहरी जड़ पकड़े, स्थाई और विभिन्न मौलिक सत्यों की सुदृढ़ पकड़ के कारण विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है (वही).
16. कर्वे : पूर्वोद्धृत, पृ० 55 और रानाडे की टिप्पणियाँ भी देखिए. एडेड स्मिथ ने आर्थिक रूप और सामाजिक स्थिति को कभी पृथक् करके नहीं देखा और इस प्रकार उपयोगिता की स्थिति बनाए रखी, जिसे अब उसके उत्तराधिकारियों ने उसके सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल देते हुए छोड़ दिया है (एसेज, पृ० 16).

17. 'रिव्यू आफ "फ्री ट्रेड ऐंड इंग्लिश कामर्स"', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 51, 53-4.
18. वही, पृ० 56, एसेज, पृ० 11, 22 और आगे, 42-3, 89.
- 18-ए. तैलग : फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन—'फ्राम ऐन इंडियन पांटेड आफ व्यू' (बंबई, 1877) पृ० 47 तथा देखिए पृ० 2, 15, 17, 69
19. वही, पृ० 2-3, 53.
20. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 136.
21. राय, पावर्टी, पृ० 66. संरक्षण बनाम उन्मुक्त व्यापार विवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा : 'वास्तव में उन्मुक्त व्यापार और संरक्षण समय और स्थान की स्वतःसिद्ध कल्पनाएँ हैं। यह तो औचित्य का प्रश्न है न कि प्राकृतिक कानून का (वही, पृ० 65)।
22. उदाहरण के लिए देखिए, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 749, 808 और 886.
23. दत्त, ई० एच० पृ० 299-302 और देखिए उनकी स्पीचेज II पृ० 122-5.
24. जी० एस० अय्यर, ई० ए० 104-07.
25. वही, पृ० 129-30.
26. वही, परिशिष्ट, पृ० 4.
27. वही, परिशिष्ट, पृ० 5. उन्होंने व्यापारवाद के उदय से अंतिम जर्मन संप्रदाय तक यूरोप में आर्थिक चिंतन के विकास के संक्षिप्त इतिहास की खोज की (वही, परिशिष्ट, पृ० 7-22). यह भी पर्याप्त रोचक है कि जब उन्होंने व्यक्तिगत लाभ पर राष्ट्रीय विकास को गौरव देने के लिए आर्थिक सिद्धांतों और उनके ऐतिहासिक मोड़ों की सापेक्षता की समर्थक सूची की प्रशंसा की, उस समय उन्होंने यह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया था कि यह सूची समकालीन समाज के प्रभावी सुधार में सहायक होने के बदले व्यापारिता के नए रूप की स्थापना के लक्ष्य की ही साधक अधिक है. (वही, परिशिष्ट पृ० 22-3).
28. वही, परिशिष्ट, पृ० 5.
29. वही, परिशिष्ट, पृ० 1-2 तथा देखिए पृ० 210-1, 242, 267 और परिशिष्ट, पृ० 4.
30. वही, परिशिष्ट, पृ० 3.
31. और देखिए मराठा, 26 मार्च 1899.
32. और देखिए न्यू इंडिया, 18 दिसंबर 1902.
33. एस० एम० बैनर्जी, स्पीचेज I पृ० 202; ए० बी० पी०, 1 दिसंबर 1870; सोमप्रकाश, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० वय, 8 अप्रैल 1882); मद्रास स्टैंडर्ड, 21 जनवरी (आर० एन० पी० एम० 25 जनवरी 1902).
34. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 136; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 207; राय, पावर्टी, पृ० 38-9, 66; न्यू इंडिया, 18 दिसंबर 1902; जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 358 तथा देखिए ए० बी० पी०, 6 अप्रैल 1882.
35. रानाडे, एसेज, पृ० 32; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 809; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 155.
36. रानाडे, एसेज, पृ० 32; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 671-2, 74; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 155, परिशिष्ट, पृ० 6; मोहले, स्पीचेज, पृ० 54-5.
37. रानाडे, एसेज, पृ० 87; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 612, 746, 748, 785-6, 808; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, परिशिष्ट, पृ० 6, रानाडे ने 1896 में यह टिप्पणी की थी : 'आखिर राज्य का अस्तित्व इसलिये तो है कि वह असंगत अलग-अलग सदस्यों को उनमें सभी प्रयत्नों में सफल बनाते हुए उन्हें

अधिक ऊँचा, अधिक प्रसन्न, अधिक समृद्ध और अधिक पूर्ण बनाए' दि मिलेनियम राइटिंग आफ दि लेट आनरेबल मिस्टर जस्टिस एम० पी० रानाडे (बंबई 1915), पृ० 172 तथा देखिए वही, पृ० 78

- 38 रानाडे, एसेज, पृ० 86, 90-2, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 672-3, 747-8, 785-6, 807-09, 826. हा 1877 में रानाडे के विचार अवश्य कुछ भिन्न थे। पूना सार्वजनिक सभा की ओर से डकन राइट्स कमिशन की रिपोर्ट पर लिखे एक पत्र में उन्होंने घोषणा की देश की भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति में किसी प्रकार का स्थायी परिवर्तन लाना सरकार की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है। भारतवासी किसी विदेशी अधिकरण द्वारा सुधार किए जाने में विश्वास नहीं रखते। कम से कम विचार की तात्कालिकता की मांग के अनुसार इतने थोड़े समय में तो कुछ मुद्दा हो पाना संभव नहीं जो० गी० एम० एम०, जनवरी 1879 (खंड I सख्या 3) पृ० 36 तुलनीय मानकर पूर्वोद्धृत, खंड I पृ० 213
- 39 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 650-3 755-6
- 40 रानाडे, एसेज, पृ० 32 तथा लोक हा गौतमिधरम करने वाली सरकार को लोक हत्या की दिशा में सर्वोत्तम रूप में किए जाने वाले सभी कार्यों को अपने हाथ में लेने का अधिकार है और यह उसका तदनुरूप नैतिक दायित्व है, (वही, पृ० 87)
41. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 822
42. रानाडे, एसेज, पृ० 21
- 43 जी० एम० अथर, ई० ए० पृ० 130-1 तथा देखिए, उदा परिशिष्ट पृ० 6, 10-11
- 44 जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 748-9.
- 45 देखिए पीछे अध्याय 3, उदाहरणार्थ रानाडे, एसेज, पृ० 324, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 671-701, 752-830 राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा औद्योगिक विकास पर दिए गए विचारों के लिए देखिए, पीछे अध्याय 2
- 46 देखिए पीछे अध्याय 10
- 47 रानाडे एसेज, पृ० 31
- 48 देखिए पीछे अध्याय 10 उदाहरणार्थ देखिए एसेज पृ० 30-1 हा, इससे पूर्व 1881 में उन्होंने राज्य द्वारा जमींदारों और किरायादारों के संबंधों को नियमित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया था। उनके विरोध का आधार यह था कि ये मामले इतने नाजुक और इतने जटिल हैं कि इन्हें सुलझाने की बात निजी प्रयास और आपसी समझौते पर ही छोड़ देनी चाहिए। इस दिशा में किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयास का परिणाम असफलता और नैतिक रूप से कुछ के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलेगा (दि सेटल प्राविमंत्र नं० रेंवेन्यू ऐंड टेनेसी बिल, जे० पी० एम० एम०, अर्बन 1881 खंड III सख्या 4, पृ० 22) और देखिए पृ० 17 तुलनीय मानकर, पूर्वोद्धृत, खंड I पृ० 214
49. उन्होंने लिखा - 'प्रगतिशील मित्रता वहां हम स्वतंत्रता की अनुमति देता है जहां दो दल योग्यता और साधनों में मुकाबले में बराबर के हैं। परंतु जहां यह स्थिति नहीं है, वहां समानता और स्वतंत्रता की बात कोई भी ग्राह्य का काम करती है। इसी भावना से बहुत सारे जबरनतमों और थोड़े से क्षतिजालियों में उत्पादन के वितरण की व्यवस्था करनी है अर्थात् न्याय और औचित्य का ध्यान रखना है। इस प्रकार के मामलों में पुरातनपरियों के प्रति स्थिति के दृष्टिकोण को जीवन के सभी आयामों के सदर्भ में नए ढंग से देखना होगा (एसेज, पृ० 31)।

- 50 देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए, ई० ए० पृ० 227-8 तथा देखिए, मराठा, 1 जुलाई 1888
- 51 देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए, ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियम, 27 फरवरी 1879; 'फैक्टरी लैबरेशन इन इंडिया' जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1881 (खंड IV, सख्या 1) पृ० 31, इंदु प्रकाश, 9 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 14 फरवरी 1885), हिंदू, 14 मई 1889, 26 मार्च 1901
- 52 कम गे कम एक लेखक, डा० जी० कर्वे, यह डग गलती करने से नहीं बच सके (पूर्वोद्धृत, पृ० 119, 132) दूसरी ओर जेम्स स्नारु (रानाडे, पृ० 130), बी० दत्त (पूर्वोद्धृत, पृ० 262, 272), श्रीर गोपालकृष्णन (पूर्वोद्धृत, पृ० 124) स्पष्ट ही इस अंतर को देख सकते थे।
- 53 विशय ए प मे देखिए, एम० जे, पृ० 89-90, 169, 190, 193-4
- 54 वही, पृ० 33
- 55 रिपोर्ट आफ द फाइनाल कमटी 1886 गड I, पृ० 407
- 56 जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 819.
- 57 वही, पृ० 744-50, 820
- 58 वही पृ० 673-4, 808, 820, 826 हिंदू 21 अप्रैल 1902 भी देखें।
- 59 जार्ज प्रबोद्धन, पृ० 822
- 60 वही, पृ० 821 तथा देखिए पृ० 819 861-2
- 61 उदाहरण के लिए दोषाण, रिपोर्ट्स आफ इंडियन फैमिन कमीशन 1880, भाग II वर्ष VII कडिका-2, रिचार्ड स्टीव और जॉन स्टोन पूर्वोद्धृत पृ० 14-5; चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 331, कर्जन, स्पीचेज I पृ० 128 'रजा यूगा आफ दि गर्वमेट आफ इंडिया दिनांक 16 जनवरी 1902, कडिका-9, स्टीव इंडिया 1903) पृ० 120 ई० ला, एल० सी० पी०, 1904, खंड XLIII पृ० 539 यह उल्लेखनीय है कि कितने ही सरकारी अधिकारी और लेखक इस व्यापक दृष्टिकोण से अमहमन थे उदाहरण व रूप में देखिए, लुइस मैसेट, लार्ड सैलिसबरी एच० ई० मुलेवान की कार्यवाही और दत्त. फैमिस इन इंडिया, परिशिष्ट, एम० एन० ओ० क्यू० में उद्धृत; भारत सरकार के संप्रेषण दिनांक 8 जून 1880, होम (पब्लिक) प्राग 45 (ए) जून 1880; बोडन पावेन पूर्वोद्धृत, पृ० 49
62. माडलिक, स्पीचेज, पृ० 466, 488, 514-5; ज्ञान प्रकाश, 3 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 5 फरवरी 1881); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 547-8, 573-4, 824, 887; रानाडे, 'प्रोटैस्ट अगेस्ट न्यू डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेट इन लैंड पालिसी' जे० पी० एम० एम० अप्रैल 1884 (खंड VI सख्या-4) पृ० 45; पूना सार्वजनिक सभा का 4 जून 1884 का पत्र, जे० पी० एम० एम० जुलाई 1886 (खंड IX सख्या, 1) पृ० 5, स्वदेशमित्र, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 1897); पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 680-2; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 570; दत्त. फैमिस इन इंडिया, पृ० 94 और आगे, ई० एच० I पृ० 372-4, 381-2, ई० एच० II पृ० 140, 321-2. और देखिए, नौरोजी, पावर्टी, पृ० 60, 220-1, स्पीचेज, पृ० 316, परिशिष्ट पृ० 40, 182; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 223 पादटिप्पणी, राय, 'वर्टी, पृ० 254
63. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 886 उन्होंने आगे कहा 'यह समाजवादी मित्रात इस विषय के यूरोपीय अर्थशास्त्र संबंधी अपसिद्धांतों का अपभ्रंश मात्र है और जिसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति ब्रिटिश भारत के बाहर भूमि के राष्ट्रीयकरण के मतावली आंदोलन के माध्यम से होती है (पृ० 887)

जोशी एक दृष्टि से सही थे : न तो रिकाडों ने और न ही जेम्स मिल ने यह सुझाव देने का साहस किया कि अनुपाजित आय में निहित क्रांतिकारी कर नीति इंग्लिश परिस्थितियों में लागू की जाए तुलनीय, स्टोक्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 89-90.

64. देखिए स्टोक्स, पूर्वोद्धृत, विशेष रूप से अध्याय 2, पृ० 108-09, 114, 137.
65. वही, पृ० 88; डेविड रिकाडों : दि प्रिंसिपल्स आफ पोलिटिकल इकॉनोमी ऐंड टैंक्सेशन (एवरीमैन लायब्रेरी सस्करण, लंदन 1943). अध्याय 2 और 32, एरिक रोल : ए हिस्ट्री आफ इकॉनामिक थॉट (न्यूयार्क 1947), पृ० 195-6.
66. स्टोक्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 77, 89, 93, 127-8, 131-3.
67. वही, पृ० 135 तथा रिकाडों : पूर्वोद्धृत, अध्याय 2.
68. रानाडे, एसेज, पृ० 30. 'लैंड ला रिफार्म्स ऐंड ऐग्रीकल्चरल बैक्स' जे० पी० एस० एस०, अक्टूबर 1881 (खंड IV सख्या-2) पृ० 54
69. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 892-4, 900-01. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रानाडे और जोशी जान स्टुअर्ट के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर बहुत विश्वास करके चल रहे थे, अध्याय 10.
70. स्टोक्स : पूर्वोद्धृत, पृ० 89-90; रिकाडों : पूर्वोद्धृत अध्याय 2 और 32, उदाहरणार्थ अनुपाजित वृद्धि के सिद्धांत को लार्ड कर्जन के 10 जनवरी 1902 के भूमि प्रस्ताव में भी स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली. देखिए कड़िका-18 22.
71. रानाडे, एसेज, पृ० 29-30; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 363, 894-6.
72. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 894, 901. इस सरकारी तर्क पर कि सरकार के सारे समाज के न्यासधर होने के नाते उसके लिए लगान में अनुपाजित वृद्धि को समाज के एक छोटे से वर्ग विशेष के लाभ के लिए छोड़ना कहा का न्याय होगा, टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा : काश खेतिहर जनसंख्या का एक छोटा भ्रंश होते ? (वही, पृ० 902) यह सचमुच व्यागमक भले न हो परंतु विचित्र स्थिति अवश्य है कि इंग्लैंड में मुट्ठी भर जमींदारों के शोषण से विशाल जन समुदाय को बचाने के लिए इंग्लैंड के लेखक रिकाडों द्वारा दिए गए सिद्धांत का भारत में समाज के हित के नाम पर जनता के विशाल समुदाय पर ऊँचे कर थोपने के लिए प्रयोग किया जा रहा है.
73. पृष्ठ 1.
74. भोलानाथ चद्र, एम० एम०, जून 1873 (खंड II) पृ० 99, 109, 235; नीरोजी, पावर्टी, पृ० 62; सैलंग : फ्री ट्रेड ऐंड प्रोटेक्शन, पृ० 32, 62-4, 69-70. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 680-2, 749; रानाडे, एसेज, पृ० 25, राय, पावर्टी, अध्याय 1 (विशेष रूप से पृ० 44, 51); बोबले, बिलवी कमीशन, खंड III प्रश्न 18165-7; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 750; दत्त, इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 133, स्पीचेज II पृ० 127-8. इन इंडिया, 27 नवंबर 1903; जी० एस० बय्यर, ई० ए०, पृ० 101, 107, 255, 345-6, 349-50. 'ईस्ट ऐंड बैस्ट', अगस्त 1903 पृ० 884 पर; एस० एन० बेंनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 1896 पृ० 136. सी० पी० ए०, पृ० 636. जी० आर० एम० चित्तनवीस, एल० सी० पी० 1894 खंड XXXIII पृ० 156; पी० ए० चार्ल्स, एल० सी० पी० 1899 खंड XXXVIII पृ० 178-9; वाचा, स्पीचेज, पृ० 442. रास्त गुप्तार, 24 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 30 मार्च 1878); गुजराल मित्त, 7 अप्रैल (वही, 13 अप्रैल 1878); मराठा, 12, 19 जून, 4 दिस० 1881, 26 मार्च 1882, 11 अप्रैल 1897, 26 मार्च, 21 अप्रैल 1899, 11 नवंबर 1900, 30 मार्च 1902; बंबई समाचार, 8 जुलाई (आर० एन० पी० बंब 9 जुलाई 1881). 'ए स्टेटमेंट आफ इंडियन क्वेश्चंस', जे० पी० एम० एस०, जुलाई

1881 (खंड IV संख्या-1), पृ० 15; बंबई समाचार, 11 मार्च (आर० एन० पी० बंब 14 मार्च 1885); केरल पत्र, 21 नवंबर (आर० एन० पी० एम०, 30 नवंबर 1890); बंगाली, 15 अप्रैल 1893, 22 दिसंबर 1894, 19 मई 1901, 14 अक्तूबर 1903; ए० बी० पी०, 8 सितंबर 1897; हिंदू, 26 नवंबर 1900, 13 अक्तूबर 1903; मद्रास स्टैंडर्ड, 21 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 25 जनवरी 1902); न्यू इंडिया, 21 अप्रैल 1902.

75. ई० ए०, पृ० 350
76. अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने सरक्षण की मांग पर दबाव न डालने का कारण ब्रिटेन द्वारा उसकी स्वीकृति की असंभावना को बताया देखिए, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 749, 822; रानाडे, एसेज, पृ० 33, 189, 191; एन० पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 526-7; एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 696; दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 134
77. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 12, 15, 17, 69; ए० बी० पी०, 1 दिस० 1870; नोरोजी, पावर्टी, पृ० 62, रानाडे, एसेज, पृ० 25, राय, पावर्टी, पृ० 66; जी० एम० अय्यर, ई० ए० पृ० 240-2, 245, बंगाली, 15 अप्रैल 1893, 19 मई 1901; मद्रास स्टैंडर्ड, 21 जून० (आर० एन० पी० एम०, 25 जन० 1902). अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हुए मराठा ने अपने 26 मार्च 1899 के श्रक में लिखा : 'उन्मुक्त व्यापार का मित्रात भारत में विदेशी मत्ता को स्थिर रखने के लिए विदेशों ने नागा गया एक पौधा है परंतु भारत की भूमि इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं और आने वाले समय में इसे दीर्घकाल तक चलाया नहीं जा सकता अतः इसे स्थिर रखने के लिए बलपूर्वक किए जाने वाले सभी प्रयत्न असफल ही होंगे।
78. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 12, 49; गोम प्रकाश, 24 अप्रैल (आर० एन० पी० वग०, 29 अप्रैल 1882), जोशी, पूर्वोद्धृत पृ० 680; राय पावर्टी, पृ० 33-4, 51, गोखले, विलवी कमीशन खंड III प्रश्न 18141, 18155, 18163-4, वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 623; एस० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 692-3; पी० मेहता एपीजेज, पृ० 750; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 240, 350
79. नोरोजी, पावर्टी, पृ० 62 तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 65, मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी०, 1891, पृ० 21; राय, पावर्टी, पृ० 66, 70-3, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 103.
80. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 68-9, मराठा, 12 जून 1881; जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 684; राय, पावर्टी, पृ० 39; जी० एम० अय्यर, ई० ए०, पृ० 104, 329.
81. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 10-11; राय, पावर्टी, पृ० 136-7. जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 244-5.
82. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 14-24.
83. वही, पृ० 24 और देखिए, राय, पावर्टी, पृ० 47-8.
84. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 34-5; रानाडे, एसेज, पृ० 24-5; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 257-9, 274-5, 329-30 तथा देखिए, रानाडे, 'रिब्यू आफ़ फ्री ट्रेड ऐंड इंग्लिश कॉमर्स', पृ० 54-5.
85. रानाडे, एसेज, पृ० 25; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 274-5.
86. रानाडे, एसेज, पृ० 25; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 274-5. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 12-3. भी देखे.
87. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 34-5; मराठा, 12 जून 1881; हिंदू, 23 मार्च 1885; रानाडे, एसेज, पृ० 25-6.

88. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 36-7.
89. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 67; मराठा, 19 जून 1881; ए० बी० पी०, 6 अप्रैल, 1882; रानाडे, एसेज, पृ० 25; राय, पावर्टी, पृ० 45-6; एस० एन० बैंनर्जी, रिप० आई० एन० सी०, 1896, पृ० 136; दत्त, इंडिया, 27 नवंबर, 1903 मे.
90. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 822; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 750; वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 1895 पृ० 159 स्पीचेज, पृ० 422 पी० मेहता, स्पीचेज, की भूमिका पृ० 14 और तैलंग, स्पीचेज, पृ० XI-XII. नोरोजी, पावर्टी (पृ० 62) की भूमिका, सी० पी० ए०, पृ० 881; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 754 और देखिए, कर्वे . पूर्वोद्धृत, पृ० 134
91. उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में सरक्षण इंग्लैंड के प्रति अन्याय नहीं होगा। यदि यह अन्याय हो भी तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी अतः वह लागू किया जा सकता है (पूर्वोक्त स्थल, पृ० 63-4). और देखिए, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 750.
92. दत्त, ई० एच० I पृ० 302 दत्त ने अपनी 'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया' पुस्तक के दोनों खंडों में तथा अपने अनेक भाषणों और लेखों में इस विवरण को विस्तार के साथ प्रमाणित किया और देखिए ए० बी० पी०, 30 मार्च 1882; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 106, 242-3. वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 623, एम० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 692-6.
93. 'ए स्टेटमेंट आफ वर्कचम' जे० पी० एम० एम०, जुलाई 1881 (खंड IV स० 1), पृ० 15; ए० बी० पी०, 30 मार्च, 6 अप्रैल 1882 रानाडे, एसेज पृ० 25 राय, पावर्टी, पृ० 58-66, मराठा, 17 जनवरी 1886, 11 अप्रैल 1897, 11 नवंबर 1900, दत्त, ई० एच० I पृ० 302, इंडिया, 27 नवंबर 1903; एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 696; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 104-05, 109, 245, 328 ए० पृ० 521 एम० एन० बैंनर्जी इन सी० पी० ए०, पृ० 696 जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 104-05, 109, 245, 328
94. तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 65; राय, पावर्टी, पृ० 53-8; मराठा, 11 अप्रैल 1897; दत्त, इंडिया, 27 नव० 1903, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 244-5, 328, ईष्ट एंड वेस्ट, अगस्त 1903, पृ० 884; एन० जी० चंदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 526; एम० एन० बैंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 696
95. दत्त, ई० एच० I पृ० 302; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 252-3
96. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 674, मराठा, 17 जनवरी 1886, एम० एन० बैंनर्जी, रिप० आई० एन० सी०, 1896, पृ० 136, राय, पावर्टी, पृ० 39; दत्त, इंडिया, 27 नवंबर 1903, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 116-7, 258-9, 329
97. दत्त, स्पीचेज, II पृ० 127. इसी प्रकार 22 नवंबर 1903 के घक में मराठा ने घोषणा की कि भारत न तो उन्मुक्त व्यापार चाहता है न ही शुद्ध सरक्षण वह तो दोनों को इस रूप में चाहता है जिससे वर्तमान परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और देखिए, रानाडे, 'ट्रिब्यु आफ फ्री ट्रेड ऐंड इंग्लिश कामर्स', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 56; जोशी, पूर्वोद्धृत, [० 822, राय, पावर्टी, पृ० 65.
98. ट्रिब्यून, 1 अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 12 अप्रैल 1902); मराठा, 5 जुलाई 1903; इंडियन पीपुल, 16 अक्तूबर 1903 हिंदू, 27 नवंबर 1903; एच० आर० नवंबर 1903 पृ० 442; बंगाली, 13 फरवरी 1904.
99. पृ० 441.

100. और देखिए, इंडियन पीपुल, 16 अक्टूबर 1903. जी० के० गोखले ने 1911 में इस भावना को और अधिक अधिकृत अभिव्यक्ति दी. देखिए, गोखले, स्पीचेज, पृ० 514-5.
101. तुलनीय केलाक, 'रानाडे ऐंड आफ्टर' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 253. कर्वे : पूर्वोद्धृत, पृ० 45-47.
102. रानाडे, एसेज, पृ० 27-33
103. जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 574, 901; दत्त : फॉर्मिस इन इंडिया, पृ० 95.
104. तैलग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 1, रानाडे, 'रिब्यू ऑफ "फ्री ट्रेड एंड इंग्लिश कामर्स"' पूर्वोक्त स्थल पृ० 51; मराठा, 11 नवंबर, 1900; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० VI और परिशिष्ट पृ० 3.
105. रानाडे, एसेज पृ० 23.
106. वही, पृ० 65.

अध्याय 15

आर्थिक राष्ट्रवाद

वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी राष्ट्र एक ही समय विजेता राष्ट्र और पराजित राष्ट्र नहीं बन सकता।

अमृत बाजार पत्रिका, 22 फरवरी, 1892

आप अपने ब्रिटिश शासन के ईमानदार समर्थक होने की घोषणा करते हैं और उस शासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्यतः अपेक्षित तथा अविभाज्य स्थितियों और परिणामों की घोर निंदा करते हैं।

जार्ज हैमिल्टन.

भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप और उद्देश्य का विश्लेषण

हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण का निर्धारक तत्व अतः उसके स्वरूप और उद्देश्य का बोध था। उनमें से अधिकांश के बारे में यह जानकारी मैट्रिऑनिक तर्क वितर्क अथवा कोरी कल्पनाओं में प्राप्त नहीं थी। उनका मन्त्र और व्यावहारिक ज्ञान ही उनकी धारणा का मूल आधार था। उनकी इस जानकारी का एक क्षेत्र आर्थिक नीतियां थी। समकालीन प्रशासन और राजनीति में सर्वप्रथम लगभग प्रत्येक आर्थिक विषय पर एक ओर स्वयं भारतीयों के बीच आपसी विचार विमर्श का और दूसरी ओर भारतीयों तथा शासकों के बीच हुए तर्क वितर्क का इस मौलिक राजनैतिक जानकारी पर प्रभाव पड़ा। अतः में आर्थिक नीतियों और विशेषतः भारत की दरिद्रता के कारणों और परिणामी उपचारों के संबंध में उत्पन्न विविध वादविवादों में राष्ट्रवादी नेताओं के अनेक बड़े वर्गों, जी० के० गोखले, जी० बी० जोशी, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, डी० ई० वाचा और आर० सी० दत्त आदि को हिचकिचाहट व अस्पष्ट रूप से तथा दादा भाई नौरोजी, बी० जी० तिलक, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, अमृत बाजार पत्रिका और मराठा तथा अन्य अनेक राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं आदि जैसे को साफ़ तौर से, यह विश्वास करने को विवश होना पड़ा कि कुल मिलाकर भारत में ब्रिटिश

राज्य आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है और कदाचित् इसका उद्देश्य ही भारत को हानि पहुंचाना है।

बहुत सारे भारतीय नेता, विशेषतः कालांतर में समझौतावादी के रूप में प्रसिद्ध नेता ब्रिटिश शासन से बड़ी-बड़ी आशाएं रखते थे। वे भारत पर समकालीन विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील राष्ट्र ब्रिटेन के प्रारंभिक प्रभाव से ऋंधिया गए थे। उनकी दृष्टि में 18वीं और 19वीं शताब्दी की लगभग अराजकता की सी स्थिति के उपरान्त कानून और व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक केंद्रित प्रशासन, पश्चिमी लोक तंत्रीय विचार और ज्ञान के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का प्रसार, भाषण और लेख द्वारा विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक स्वाधीनता और इन सबसे कदाचित् बढ़ चढ़ कर थी, भारत के लोगों को एक सामान्य राष्ट्रीयता में ढालने की प्रक्रिया और उसके फलस्वरूप सारे ही देश में एक राष्ट्र के गिवामी होने की भावना का उदय तथा नए राजनैतिक जीवन का उद्भव, ये सब ब्रिटिश राज्य के आगमन के परिणाम थे; अतः इनका श्रेय ब्रिटिश राज्य को ही दिया जा रहा था। ब्रिटिश राज्य को इस प्रकार नव प्रभात का अग्रदूत माना जाने लगा था। वे लोग इस राज्य में देश के द्रुत औद्योगिक विकास का उज्ज्वल भविष्य देख रहे थे और इसमें वे ब्रिटिश राज्य के प्रति आकृष्ट थे। उनका विश्वास था कि पश्चिमी विज्ञान और तकनीक, आा। १९. गठन तथा पश्चिमी कठोर उद्यम का उदाहरण देश को आर्थिक पिछड़ेपन और गतिहीनता के गढ़ से निकाल सकेंगे। रेलें, सड़कें, नहरें और विश्व की समृद्ध मंडियों के साथ जुड़ जाना, प्रारंभिक सूती कपड़ा उद्योग तथा विदेशी वाणिज्य, उद्योग और बागान संबंधी उद्यम आदि उन्हें देश में आने वाली उम औद्योगिक क्रांति की तैयारी अथवा भूमिका के रूप लग रहे थे, जिनके प्रथम चिह्न पहले में ही दृष्टिगोचर हो रहे थे।¹

यह बात नहीं थी कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता देश में निर्धनता की व्यवस्था और अन्यान्य आर्थिक बुराइयों से परिचित नहीं थे, परंतु उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन का उज्ज्वल पक्ष उसके अंधेरे पक्ष को पीछे छोड़ देगा। उन्हें आशा थी कि समय बीतने के साथ आर्थिक रोगों में उत्तरोत्तर कमी और लाभों में अधिकाधिक वृद्धि ही होती जाएगी। दूसरे शब्दों में भौतिक क्षेत्र में वे नेता लोग वास्तविकता की अपेक्षा संभावना से और सिद्धि की अपेक्षा आशा में ही अधिक आकृष्ट थे।²

समय के बीतने के साथ देश की, भले ही मदगति में परंतु उत्तरोत्तर और अधिकाधिक, प्रगति की प्रतीक्षा करने के उपरांत कुछ एक ने धीरता में और कुछ एक ने अधीरता से अनुभव किया कि उनकी आशाएं निरर्थक ही सिद्ध हुई हैं और उनके पूरे होने की संभावना घटती ही जा रही है। इससे उन्हें निराशा और कुठा ही हाथ लगी। उनके मन में ब्रिटिश राज्य का उज्ज्वल स्वरूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। जहां तक आर्थिक जीवन का संबंध था, प्रगति बहुत ही मद थी और कुछ एक नेताओं को तो ऐसा लगा कि प्रगति के विपरीत देश आर्थिक दृष्टि में अधोगति की ओर उन्मुख हो रहा है। समय आने पर भारत की घोर दरिद्रता ने उनके समग्र आर्थिक चिंतन पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया। आशा की एक किरण थी, आधुनिक उद्योग का विकास, और यहा उन्हें लगा कि सरकारी आर्थिक नीतियां कदाचित् इस मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा थी।

आर्थिक मामलों के संबंध में कृतज्ञता और प्रशंसा का स्थान निरंतर की जाने वाली शिकायत और दोष निकालने की प्रवृत्ति ने ले लिया।¹⁵ भारतीय नेता यह शिकायत करने लगे कि निर्धनता इस देश में जड़ पकड़ रही है। सरकारी राजस्व अधिकारियों द्वारा किसान को लूटा खमूटा जा रहा है। स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया गया है और आधुनिक उद्योग को जानबूझकर निरुत्साहित किया जा रहा है अथवा कम से कम पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, देश के लिए आवश्यक माल सभरण का निर्यात किया जा रहा है। भारतीय उद्योग और कृषि के हितों के विरुद्ध ही मुद्रानीति अपनाई जा रही है। विदेशियों के स्वामित्व वाले बागान उद्योगों में भारतीय श्रमिक को दास बनाया जा रहा है, भारतीय राजस्व और कृषि विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा करके रेलों का विस्तार किया जा रहा है। कराधान का भार लोगों को निचोड़ रहा है। लोकान्धों का राष्ट्र निर्माण के विभागों से हटाकर इन भारतीय हितों के पोषण में, अनावश्यक आजीविका जुटाने में तथा विस्तारवादी युद्ध लड़ने में खर्च किया जा रहा है। अंतिम, सबसे भारी शिकायत उन्हें यह थी कि भारत में संपत्ति और पूँजी की निकासी की जा रही है। वे यह अनुभव करने लगे कि ये सभी आर्थिक दोष प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत में बरती जा रही ब्रिटिश आर्थिक नीति के ही परिणाम थे। यदि भारतीय आर्थिक जगत् असंगठित है तो व्यापक रूप से इसका दायित्व ब्रिटेन पर ही है। इस प्रकार इन राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि में ब्रिटिश राज्य के भूतकाल के और वर्तमान काल के अन्य सभी लाभ आर्थिक अवगति के सामने निरर्थक हो जाते हैं।¹⁶ 'विश्वास के इस भंग' ने न केवल ब्रिटिश शासन के परिणामों के संबंध में प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए, प्रत्युत 'क्यों', और 'किस-लिए' यह स्थिति है इस पर भी विचार करना प्रारंभ कर दिया। भारत ने भौतिक प्रगति क्यों नहीं की? इस संबंध में प्रारंभिक आशाओं की पूर्ति क्यों नहीं हुई? इस असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या भाग्य को यह क्षति भ्रनजाने पहुँची है अथवा जानबूझकर कर पहुँचाई गई है? दूसरे शब्दों में भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या था? निष्कर्ष रूप में ब्रिटिश राज्य के परोपकारी स्वरूप में उनका विश्वास उठने लगा और उन्हें यह दिखाई देने लगा कि ब्रिटिश शासन भौतिक विकास की दृष्टि से भारत के लिए हानिकारक ही रहा है।

जैसा कि सर्वविदित है, विशाल संख्या में भारतीय नेता वर्षों तक यह विश्वास करते रहे कि भारत की आर्थिक दुर्गति का कारण ब्रिटिश जनता ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा भारत की स्थिति से भली प्रकार परिचित न होना है अथवा अधिक से अधिक यह सब ब्रिटेन की दलगत राजनीति का फल है और उसके परिणामस्वरूप गलत नीतियों का प्रवर्तन होता है और नौकरशाही द्वारा सही नीतियों तक को भी गलत ढंग से लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंशतः स्वयं नेताओं द्वारा अपने ही देश में गलत नीतियों का अपनाया जाना है। दूसरे शब्दों में भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए शासकों का अज्ञान अथवा निर्णय में गलतियाँ अथवा अधिक से अधिक लोकतंत्रीय राजनीति के दोष ही उत्तरदायी थे न कि किसी प्रकार की सोच समझकर निर्धारित की गई नीति अथवा इच्छा का यह परिणाम था। अतः इन राष्ट्रवादी नेताओं के लिए तत्कालीन का मुख्य

आधार ब्रिटेन की जनता की न्यायपरायणता, ईमानदारी और उदारता अर्थात् इंग्लैंड के अंतःकरण में दृढ़ विश्वास था। अतः वे यह मानते रहे कि यदि भारत सरकार को, इंग्लैंड की सरकार को, ब्रिटेन की जनता को और ब्रिटेन की संसद को स्थिति की वास्तविकताओं का पूरा ज्ञान हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अतएव उन्होंने इस दिशा में यथावश्यक सभी कृष्ट किया, उन सबको स्थिति से परिचित कराने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए।¹⁶ परंतु ब्रिटिश आत्मा को जगाने के लिए उनके शैक्षिक अभियान, उनके अर्थशास्त्रीय विश्लेषण तथा उनके आर्थिक आंदोलन, आर्थिक कष्टों के निवारण में उनको अपेक्षित परिणाम न दिखवा सके। फलतः धीरे-धीरे उनका विश्वास हिल गया। शासकों की न्याय-परायणता पर उनकी आस्था डगमगा गई और घणा के बीज ने गहरी जड़ पकड़ ली।

धीरे-धीरे और समय के बीतने पर मुगल आर्थिक प्रश्नों विशेषतः सीमा शुल्क नीति और निवार्ता में संबंधित प्रश्नों पर आदालत में भारतीय जनता और नेताओं को¹⁷ यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश राज्य की आर्थिक नीतियां (निजी रूप से अंग्रेजों, प्रशासकों, और राजनीतिज्ञों की मद्भावना के होते हुए भी) तो ब्रिटिश राज्य के स्वरूप और प्रवृत्ति की देन हैं। निश्चिन्ता और आर्थिक पिछड़ापन इतना अधिक शासकों की सुविचारित गलतियों का परिणाम नहीं जितना कि उनके शासन के साथ संबद्ध दोषों का परिणाम है। इस शासन का मूल रूप में उद्देश्य ही आर्थिक दृष्टि में भारत का शोषण करना है अतः स्वभावतः वह भारत के आर्थिक विकास के लिए हानिप्रद है। भारत के आर्थिक साधनों को अपने लाभ के लिए उपयोग में लाने की इच्छा ने अंग्रेजों की न्यायपरायणता और उदारता पर काबू पाने दिया है। हम पहले ही विस्तार के साथ यह दिखा चुके हैं कि कैसे भारतीय नेता सरकारी आर्थिक नीति के विशेष उपायों से असंतुष्ट हुए और उनमें से बहुत कम ही मामलों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रिटेन भारत पर ब्रिटेन के हित में ही शासन कर रहा है न कि भारत के हित में। यहां हम केवल इतना जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारे नेता स्थिति के सामान्यीकरण के रूप में भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे।¹⁸ समाचार पत्रों में इस सामान्यीकरण को प्रायः ही अभिव्यक्ति इस प्रकार से मिली, 'भारत इंग्लैंड की कामधेनु' अथवा 'भारत इंग्लैंड के लिए दूध देने वाली गाय' है।¹⁹

भारतीय नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन की शोषण प्रवृत्ति को समझने और कालांतर में उसका प्रचार करने के ऐतिहासिक तथ्यों को अपेक्षाकृत और अधिक भली प्रकार से समझने के लिए तीन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम, भारतीय नेताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने, जिसके अंतर्गत प्रधान रूप से कुछ एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, किसी भी स्थिति में शासकों की उदार इच्छा पर विश्वास प्रकट नहीं किया। इस वर्ग के अंतर्गत वे लोग थे, जिन्होंने 1848 में ए० ओ० ह्यूम ने ऐसे आपत्तिजनक प्राणी बताया जो हमारे सर्वोत्तम तथा मित्रतापूर्ण संबंधों की निंदा करते हैं और गाली देते हैं तथा सरकार अच्छा, बुरा अथवा तटस्थ रूप में जो कुछ भी करे, उस पर नाक-भी सिकोड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं और उस सबका तिरस्कार करते हैं।²⁰ द्वितीय, उनमें से बहुतों के लेखों और भाषणों में विश्वास की विडंबना बनी रहे। एक ओर वे ब्रिटेन की लोकोपकारिता में विश्वास प्रकट करते रहे और दूसरी ओर ब्रिटिश स्वार्थपरता पर बल देते रहे। वे कभी

कभी तो एक ही सांस में ब्रिटिश स्वार्थपरता को उजागर करते रहे तथा ब्रिटिश के दूसरों की उन्नति के लिए मिशनरी भाव में अपनी आस्था की भी पुष्टि करते रहे, उन्हें अपने राजनैतिक विश्वास और आर्थिक बोध के बीच न सुलभ सकने वाला अंतर विरोध दिखाई ही नहीं दिया। उदाहरणार्थ दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन को 'अन-ब्रिटिश' कहकर ऐसा किया।¹⁰ तृतीय, समाचार पत्रों ने प्रायः ही जन नेताओं की अपेक्षा सामान्य राष्ट्रवादी नेताओं की भावनाओं को अधिक सुस्पष्ट, अधिक प्रत्यक्ष और अधिक सहस्रपूर्ण अभिव्यक्ति दी। इन पत्रों ने आर्थिक प्रश्नों पर और उनके राजनैतिक परिणामों पर लोकप्रिय राष्ट्रीय धारणा को विकसित करने तथा उसे एक विशेष रूप देने में महत्वपूर्ण योग दिया। किसी भी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जहां तक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय नेताओं व जनता का संबंध है, भारतीय नेताओं के सभी वर्गों द्वारा आर्थिक नीतियों से संबंधित चलाये गए आंदोलन ने ही ब्रिटिश सरकार के उपकारिता के भ्रम को तोड़ा।¹¹ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस रहस्य को भली प्रकार समझ लिया था कि ब्रिटिश मना का रहस्य केवल शारीरिक शक्ति न होकर नैतिक शक्ति भी था। यह मना खाली तलवार पर टिकी हुई नहीं थी, जिसमें उन्होंने इस देश को विजित किया था प्रत्युत जनता की लगातार महमति पर भी आधारित थी।¹² केवल राजनैतिक और भावनात्मक अपील ब्रिटिश राज्य के नैतिक आधार को कमजोर नहीं कर सकती थी। वे अधिक से अधिक ब्रिटिश राज्य की प्रगोपकारी निरकुशता के तौर पर निंदा कर सकती थी।¹³ मस्य तो यह है कि बहुत सारे ब्रिटिश प्रशासकों और राजनीतिज्ञों ने अपने शासनक निरकुश स्वरूप को प्रमत्तनापूर्वक न केवल अभिस्वीकार किया प्रत्युत उसका समर्थन भी किया। उनका दावा केवल यह था कि शासन की निरकुशता, मैकाले का मुद्दह शाही निरकुशतावाद, अथवा जिमकी प्रसिद्ध पैतृकवाद के रूप में हुई, लोकप्रकारिता के लिए आवश्यक थी और यह 'शक्ति' के बिना संभव नहीं थी।¹⁴ किसी भी स्थिति में राजनैतिक स्वतंत्रता का अभाव सबके सामने था परंतु यह अभाव एक राजनैतिक दोष था, जिसे विशुद्ध रूप में उन मीधे मादे लोगों को दिलाया जाना था, जो अपने आप में हम गुराई को नहीं देख सकते थे। अतः ब्रिटिश राज्य के दोनों, शुभपरिणामों और शुभ भावनाओं, के रूप में लोकप्रकारिता चरित्र के प्रांन लोकप्रिय विश्वास को क्रमशः क्षीण करने वाली आर्थिक नीतियों में संबंधित राष्ट्रवादी आंदोलन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हमें राजनैतिक वफादारी के क्षेत्र में अनिवार्यतया विश्वास की भावना क्षीण होना लगी। बहुत सुलभे हुए नेता भले ही कुछ कहते रहते, इस आंदोलन की अवधि में शासन पर लगाए गए आरोपों की प्रवृत्ति के कारण जनसाधारण के मन में वफादारी की भावना रह नहीं सकती थी।¹⁵ इस आंदोलन में सभी राजनैतिक विचारधारा के नेता, मृदु प्रकृति के दादा भाई नौरोजी, रानाडे, दत्त, गोखले और जोशी से लेकर उग्रवादी तिलक, दोनों भाई शिनिरकुमार और मोतीलाल चौध, और प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, ने समान रूप में भाग लिया। इस रूप में यह कहना सर्वथा न्यायसंगत होगा कि सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने विद्रोह का नहीं तो अमंतोष का बीज अवश्य बोया। वस्तुतः उन दोनों के बीच कदाचित् वास्तविक अंतर केवल यह था कि जहां कुछ एक

जानते हुए भी राजद्रोही थे, वहा दूसरे बफादार थे और अपनी राज्यभक्ति का दिहोरा पीटते थे और ब्रिटिश राज्य को स्थायी रूप देने के इच्छुक थे। ऐसे लोग व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिनों तक बफादार बने रहे परन्तु उन्होंने जहां भी उपयुक्त समझा, वहा ही वस्तुगत रूप में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वस्तुतः वे राजद्रोह के मूलाधार थे और यही प्रधान कारणों में से एक कारण है कि 1880-1905 की अवधि को बौद्धिक असंतोष और राष्ट्रीय जागरूकता के प्रसार, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत का काल कहा जाता है।

यह भी एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि बहुत सारे समकालीन सरकारी अधिकारियों और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया, कि अपने युग के राष्ट्रवादियों में सर्वाधिक मृदुभाषी नेता भी यही भूमिका वस्तुगत रूप में निभा रहे थे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि मृदु और समझौतावादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी सरकार में उपलब्ध दोषों के प्रति निरंतर आलोचनात्मक, दोषों को ढकने के बदले उन्हें अच्छी तरह उघाड़ने की, प्रवृत्ति के कारण परिवर्तित रूप लेती जा रही थी। इस प्रकार उदाहरण के रूप में भारत सचिव जार्ज हेमिल्टन ने 1897 में कांग्रेस की, भारतीय प्रशासन पर प्रहार करने का कोई अवसर न खोने के लिए तथा भारत की जनता पर उस प्रशासन का प्रभाव को क्षीण करने के प्रयास के लिए आलोचना की।¹⁶ जनरल चिसनी ने तो कांग्रेस को पूर्णतः राजद्रोही बनाया।¹⁷ राष्ट्रवादी प्रेम की भूमिका के संबंध में 1886 में डफरिन ने लिखा कि 'इस दृष्टि में निस्संदेह इन पत्रों के पढ़ने वालों के मन में एक भावना जट जमाती जाएगी कि हम अंग्रेज सामान्यतया मानव जाति के ओर विशेषतया भारतीयों के कट्टर शत्रु हैं।'¹⁸

आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध

1880-1905 की अवधि में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा आर्थिक नीति के जिस स्वरूप की बहालगी की गई उसमें इन वर्षों का 'आर्थिक राष्ट्रवाद के युग' का नाम दे दिया। इन नेताओं के अनुसार भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली समस्या आर्थिक समस्या थी जिसे 'निर्धनता' का नाम दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह एक राष्ट्रीय समस्या थी, अर्थात् यह भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों को बुरी तरह से दुष्प्रभावित करती थी। इससे भी बड़ चढ़ कर बात यह थी कि भारतीय नेताओं ने इस निर्धनता का दायित्व न तो प्रकृति पर डाला और न ही भारतीय समाज पर; प्रत्युत इसके लिए विदेशी शासकों को ही उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने निर्धनता से छुटकारे के कुछ उपचार सुझाए परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे नेता शासकों की ईमानदारी पर सदेह करने लगे और यह अनुभव करने लगे कि भारत द्वारा आर्थिक दृष्टि से उन्नति न कर पाने का मूल कारण विदेशी शासकों का और उनकी नीतियों का अस्तित्व ही है। वे यह मानने लगे कि जब तक देश सर्वप्रथम इन यूरोपीय शासकों से छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक देश का राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुद्धार हो ही नहीं सकता।

भारतीय नेताओं द्वारा सुझाए गए उपचारों अथवा उनकी आर्थिक नीतियों का स्वरूप साम्राज्यवाद-विरोधी था। वे ब्रिटेन और भारत के मध्य चालू आर्थिक संबंधों में मौलिक परिवर्तन चाहते थे। यहां तक कि जहां उनकी राजनैतिक मांगें मद्धु थीं वहां उनकी आर्थिक मांगें क्रांतिकारी रूप से राष्ट्रीय थीं। उनकी प्राथमिक नीतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें भारत पर ब्रिटिश के प्रभुत्व अथवा प्राधुनिक साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति के जटिल आर्थिक तंत्र की गहरी जानकारी हो गई थी। आर्थिक नीतियों के गठन के अंतर्गत सभी आर्थिक प्रश्नों की शृंखला पर विचार करने के तथा समग्र रूप में उनके पारस्परिक संबंधों के समर्थन में अध्ययन करने के उपरान्त ही उन्होंने यह मांगी जानकारी प्राप्त की, इससे पश्चात् इस पद्धति पर आधुनिक तदुत्तर सभी प्राथमिक नीतियों का ही उन्होंने विरोध किया। उन्होंने समसामयिक आर्थिक शोषणों के तीन रूपों पर विशेष ध्यान दिया, वाणिज्य के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से तथा वित्त के माध्यम से, और उन्होंने स्पष्ट रूप से समस्या की जड़ को पकड़ा कि ब्रिटिश आर्थिक साम्राज्यवाद का उद्देश्य भारत की अर्थ व्यवस्था को ब्रिटेन के अधीनस्थ करना है। विदेशी शासकों द्वारा भारत में उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था की मूल चरित्रगत विशेषताओं का निम्ननिम्नित रूप से विवर्णित करने की चेष्टा का भारतीय नेताओं ने बड़ी तीव्रता से विरोध किया। भारत को वच्चे मान के प्रत्येक देश का उप देना ब्रिटिश उत्पादनों की मण्टी बनाना तथा विदेशी पंजी के निवेश का क्षेत्र बनाना। उन्नीसवें देश के औद्योगिक विकास में सहायक होने के बदले घातक मिश्र होने तथा देश की औद्योगिक प्रगति में और अधिक बाधा करने वाले मिश्र हान के कारण सरकार की सीमा शुल्क, व्यापार, परिवहन और वसाधान की नीतियों का विरोध किया। इन नेताओं में बृहत्तो ने तो दोनों, राजनैतिक तथा आर्थिक, आधारों पर दोनों वागदान और उद्योगों में बड़े पैमाने पर विदेशी पंजी के आयात का तथा सरकार द्वारा इन क्षेत्रों का दी गई सुविधाओं का विरोध किया। सना और असीमर सना पर हो रहे व्ययों पर प्रहार करने हुए उन्होंने ब्रिटिश सर्वाधिकार के भीतर आधार को ही चुनौती दे डाली। सरकार की भूमि लगान और वसाधान की नीतियों पर प्रहार करने हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक आधार को कमजोर करने की चेष्टा की। उन्होंने भारतीय सना और भारतीय वित्तों के पणिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए प्रयोग को आर्थिक शोषण का एक अन्य रूप बताते हुए उसकी निंदा की। कुछ नेता तो इस सीमा तक बढ़ गए कि वे स्वयं ब्रिटिश शासन के पक्ष के मागे भारत का भारतीय वित्तों पर डालने के औचित्य पर ही प्रश्न करने लगे। निकागी के प्रश्न को तो उन्होंने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के आर्थिक दृष्टिकोण का सजीव उदाहरण बताया। उन्होंने साधारण लोकप्रिय परन्तु सशक्त भावनाओं के अनुसार इसे विदेशी आर्थिक शोषण का प्रतीक बताया।

उनकी सभी आर्थिक मांगों का अंततः मूल आधार यह इच्छा थी कि वास्तविक राष्ट्रीय आर्थिक नीति का निर्धारण इंग्लैंड के नही प्रत्युत भारत के हितों के ही समर्थन में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे भारतीय आधिकारिता की इंग्लैंड की अधीनता को कम करने और यहां तक कि समाप्त करने की

वकालत करते थे। अपने आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जब वे लोग ब्रिटिश भारतीय प्रशासन पर, ब्रिटिश जनता पर और ब्रिटिश संसद पर निर्भर कर रहे थे, उस समय भी उनका उद्देश्य एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की नींव डालना ही था, उनकी मांगों की स्वीकृति का परिणाम तम्रमण परन्तु निश्चित रूप से भारत में ब्रिटन की अधीनता वाली आर्थिक स्थिति में मुक्ति पाना ही था।

राष्ट्रवादी आर्थिक आंदोलन के दो अन्य पक्ष भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम, भारतीय नया प्रधान रूप से समग्रतया ही आर्थिक विकास की समस्या में मग्न रहते थे न कि लिट्टे हुए और छिन्न-छेदों में आर्थिक प्रगति में। उन्होंने आर्थिक विकास के मुख्य प्रश्न में प्रथम रूप से आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों की छानबीन करने का प्रयत्न कर दिया। उनका ध्यान था कि परिणतन तथा विविधतापूर्ण आर्थिक विकास का देश के आर्थिक विकास में उमने योगदान के महत्त्व में ही दृष्टि दी जाय। उनके अनुसार तो निर्धनता की समस्या तथा भी प्रमुख रूप से उत्पादन के स्तर और आर्थिक विकास की अनुपस्थिति का परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। उनका विचार था कि आर्थिक विकास का आधार प्रधान रूप से देश का सर्वनामुखी और द्रुत औद्योगिक विकास था। आर्थिक विकास का मूल मूल्य विदेश व्यापार के विकास में व्यवस्थापनायन के माध्यम से विकास से अथवा सरकार की कर उगाहन की क्षमता का प्रयोग सन्तुलित वजन देने करने से कदापि नहीं था प्रत्युत सामान्य औद्योगीकरण का ही था। दृष्टिकोण न उन्हे द्रुत औद्योगीकरण को पूर्ण तथा त्वरित रूप से देना था। निम्नी प्रत्युत उसके प्रति आनुर-भक्ति पकट करने को विवश कर दिया। औद्योगिक विकास उन नेताओं के लिए एक ऐसा मापदंड था, जिसके आधार पर ही उन्होंने लगभग सभी समकालीन आर्थिक प्रश्नों को न केवल देखा प्रत्युत उन पर निर्णय भी दिया। उन्होंने विदेश व्यापार, भेल सीमा शुल्क मुद्रा और विनिमय श्रम, लोकायत और तथा ना कि कृषि के क्षेत्र में सरकारों आर्थिक नीतियों का औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के ही महत्त्व में देखा। यहाँ तक कि निकासी पर उनके प्रहार का आधार भी नीतिगत पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव ही था।

यहाँ यह पुनः उल्लेखनीय है कि उन्होंने वाणिज्य के उद्देश्य के प्रति नहीं प्रत्युत उद्योग के उद्देश्य के प्रति ही अपनी निष्ठा प्रकट की। अपने औद्योगिक, विदेश व्यापार संबंधी, यातायात संबंधी, सीमा शुल्क संबंधी, विनिमय संबंधी तथा वित्तीय नीतियों में उन्होंने सदैव उद्योग के हितों को ही सर्वोच्चता दी न कि वाणिज्य के हितों को। सत्य तो यह है कि उन्होंने कई बार जान-बूझकर उद्योग पर वाणिज्य की नज़र चढ़ा दी।

द्वितीय, उन्होंने आर्थिक विकास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनका समग्र उद्देश्य समाज का सामान्य कल्याण था अतः उन्होंने समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया। उन्होंने कराधान की एक न्यायसंगत पद्धति अपनाने की वकालत की जिसके अंतर्गत भुगतान कर सकने में समर्थ लोग ही लोक वित्तों का भार सहन करे, विशेषतः उन्होंने भूमि लगान और नमक कर को घटाने के लिए निरंतर आंदोलन किया। उन्होंने द्रुत औद्योगीकरण पर इसलिए बल दिया ताकि राष्ट्रीय आय के

साधनो में वृद्धि की जा सके। उन्होंने सरकारी राजस्व को इस प्रकार से व्यय करने पर बल दिया जिससे समाज के अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यह ठीक है कि उन्होंने कृषक वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग की मांगों को अलग से नहीं उठाया, न ही उन्होंने जमीन की पट्टेदारी की चालू प्रथा में किसी प्रकार के सुधार की मांग को उठाया और न ही कारखाने के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को वाणी दी। यहाँ तक कि यह तत्व परिवर्ती समय में भी राष्ट्रवादी आंदोलन की एक दुर्बलता का ही सूचक है परंतु उनका यह विवेकपूर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उनका विश्वास था कि इस देश के समाज के सभी वर्ग ब्रिटिश राज्य में आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं और उनके आंदोलन के फलस्वरूप होने वाले राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुद्धार के व्यापक कार्यक्रम में सभी का लाभान्वित होना आवश्यक है।¹⁹ उनका विचार था कि जब वे सारे ही राष्ट्र के लिए आर्थिक न्याय और समानता की प्राप्ति के सघर्ष में सलग्न थे, वे वर्गों में न्याय और औचित्य के प्रश्न को नहीं उठाए तो अच्छा है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करने का निश्चय किया जिसमें लोगों में अलगाव की भावना पनपे जब कि समय की मांग सभी लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने की थी। इस परिप्रेक्ष्य में, जो उस समय निश्चित रूप से सही था, उन्हें समकालीन यथार्थता के अन्य पक्षों की उपेक्षा करने के लिए ही विवश किया। भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्बलताओं की उनके द्वारा विवेकपूर्ण पकड़ का ही यह परिणाम था कि उन्होंने अपना मार्ग ध्यान, सारा चितन भारत को औपनिवेशिक ढाँचे पर ही केंद्रित किया। इस कारण से कम से कम बौद्धिक प्रकाश की प्रथम चकाचौध में भारत के आंतरिक मस्थानगत ढाँचे की दुर्बलताएँ उनके ध्यान में ओझल ही हो गईं और वे यह नहीं सोच सके कि वे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की सीमाओं के अनर्गत दलित वर्गों और समुदायों के हितों के रक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उन्होंने इस दिशा में कुछ किया ही नहीं। अपने द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उन्होंने विशेषतः किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए आंदोलन किया। उदाहरण के रूप में उन्होंने बागान मजदूरों के संरक्षण के लिए व्यापक और प्रबल राजनैतिक आंदोलन किया, यहाँ उनके इस कार्य में भारतीयों के किसी अन्य हित के साथ कोई टकराव नहीं था क्योंकि इन श्रमिकों के नियोजक बागान मालिक विदेशी थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कई राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण में नया श्रमिक समर्थक रूप दिखाई देने लगा था। किसानों के मामले में उन्होंने भूमि लगानों को कम करने और स्थायी बंदोबस्त करने के लिए निरंतर और अंत में थोड़ा सफल आंदोलन किया। बहुतों ने जमींदारों द्वारा बहुत ऊँचे लगान लगाए जाने के विरुद्ध किसानों को संरक्षण देने की वकालत की।²⁰ इसके अतिरिक्त उनका विश्वास था कि उनका मुख्य संबन्ध किसानों की दृष्टिगत था, वह किसान उनके सारे आर्थिक आंदोलन में लगभग अदृश्य मानव के रूप में विद्यमान था। शायद ही कोई राष्ट्रवादी मांग थी, जिसका अंततः किसानों की महायत्ना से कोई सरोकार नहीं था। राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि जिस प्रकार आर्थिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार किसान था, उसी प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक विकास का वह प्रमुख लाभ प्राप्त करने वाला होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय

नेताओं का कृषि संबंधी दृष्टिकोण उनकी आर्थिक नीतियों की कदाचित् प्रधान दुर्बलता ही रहा ।

इसके साथ ही यह तथ्य भी यहां ध्यान देने योग्य है कि जहां भारतीय नेताओं ने किसानों और श्रमिकों के वर्गगत हितों की वकालत करना स्वीकार नहीं किया, वहां उन्होंने उनमें से अधिकांश के अपने ही संबंधित वर्ग, शहरी, शिक्षित मध्य वर्ग, के संकुचित हितों के विरुद्ध जाने वाली नीतियों को प्रस्तावित करके एक बहुत ही ऊंचे स्तर की परोपकारिता के सिद्धांत का पालन किया । दूसरे शब्दों में उनकी आर्थिक नीतियां रोजगार तलाश करने वाले मध्यवर्ग के हितों से प्रेरित नहीं थी । यह परिणाम उनकी आर्थिक नीतियों के अध्ययन का ही निष्कर्ष है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि यद्यपि मध्यवर्ग विदेशी वस्त्रों का प्रधान उपभोक्ता था तथापि उन्होंने कपास पर आयात शुल्क हटाने की मांग की उन्होंने उद्योगों के संरक्षण की मांग की । इसका मूल्य भी अंततः इसी वर्ग को चुकाना पड़ता । यद्यपि बढ़िया दानेदार चीनी का उपयोग इसी वर्ग द्वारा अधिकांशतः किया जाता था तो भी दानेदार चीनी पर लगे कर के औचित्य का इस वर्ग के बहुत सारे नेताओं ने समर्थन ही किया । यद्यपि विदेशी सामान अतेशाक्त अधिक सस्ते थे तो भी इन लोगों ने विदेशी का प्रचार किया । उन्होंने रुपये के अवमूल्यन का स्वागत किया यद्यपि इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि आयातित विदेशी सामान के खरीदार होने के नाते इस वर्ग के सदस्यों को, निश्चित आय वाले शिक्षित कर्मचारी होने के कारण, रुपये के किसी प्रकार के अधिमूल्यन से लाभ और अवमूल्यन से हानि ही संभावित थी । बहुतों ने आयकर का समर्थन और नमक शुल्क का विरोध किया । वे ऊंचे वेतनों में कटौती और निम्न वेतन-भोगियों, चपड़ासियों, सिपाहियों और क्लर्कों, के वेतनों में वृद्धि चाहते थे । उद्योग की उन्नति और लोक हितकारी गतिविधियों के लिए वे ऊंचे कराधान की वकालत करने को प्रस्तुत थे । उन्होंने मध्यवर्ग को आराम पहुंचाने वाले रेलों के विकास का विरोध किया और उसके बदले सिचाई और उद्योग के विकास का पक्ष ग्रहण किया । बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने विदेशी पूंजी से राष्ट्र के विकास का विरोध किया, यद्यपि इस विकास से शिक्षित भारतीयों के लिए आजीविका के अनेक नए क्षेत्र उपलब्ध होते थे । उन्होंने मुकदमेबाजी द्वारा किसानों का सर्वनाश करने वाली ब्रिटिश द्वारा निर्मित कचहरियों का स्थान समझौता न्यायालयों अथवा ग्राम पंचायतों को देने के लिए सक्रिय आंदोलन किया । यह ठीक है कि उन्होंने कुछ एक शहरी मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय लोगों की कुछ एक मांगों को उठाया परंतु भारतीय समाज के सभी वर्गों की आर्थिक मांगों के आधार पर किए जा रहे आंदोलन के एक अंग के रूप में ही यह सब कुछ किया ।

इस संबंध में दोनों, भारतीय और विदेशी, लेखकों द्वारा एक गलती प्रायः ही यह की जाती है कि प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी लेखकों, लोक नेताओं, पत्रकारों और चिंतकों को भारत के नए वर्गों के और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के बौद्धिक प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करने के स्थान पर उन्हें मध्यवर्गीय के रूप में ही देखा जाता है । बुद्धिजीवी होने के नाते उनमें से कुछ एक विभिन्न हितों और वर्गों और समुदायों का भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, परंतु क्योंकि वे बुद्धिजीवी थे, उनका चिंतन स्वार्थ

से प्रेरित न होकर जागरूकता के स्तर पर विचारधारा से ही प्रेरित था। एक चिंतक, एक दार्शनिक और परिभाषा के व्यापक रूप में एक बुद्धिजीवी अपनी जाति, वर्ग, समाज, जहाँ वह उत्पन्न हुआ है, के संकुचित स्वार्थों से ऊपर उठ सकता है और प्रायः उठता है। वह अपने निजी स्वार्थों की अपेक्षा वर्ग, समुदाय और राष्ट्र के हितों का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह बात द्रुत सामाजिक परिवर्तन के, पुराने सामाजिक राजनैतिक ढाँचे के नष्टभ्रष्ट होने के, नए वर्गों और आर्थिक तथा राजनैतिक पद्धतियों के उदय के समय और भी विशेष रूप से सही हो जाती है। मंपूर्ण विश्व के सभी इतिहासों में सर्वोत्तम और सच्चे चिंतकों तथा बुद्धिजीवियों के समान 19वीं शताब्दी के भारतीय विचारक और बुद्धिजीवी भी दार्शनिक ही थे, किसी दल अथवा वर्ग के भाड़े के टट्टू नहीं थे। यह ठीक है कि वे वर्गों और समुदायों से ऊपर नहीं उठ पाए तथा उन्होंने वर्गों और समुदायों के हितों का विशुद्ध रूप से प्रतिनिधित्व भी किया परंतु यह सब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस वर्ग अथवा जाति के सदस्य होने के नाते अथवा उसके वफादार सेवक होने के नाते नहीं किया प्रत्युत उन्होंने तो यह सिद्धांत के अंतर्गत ही किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपना सारा चिंतन व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही किया परंतु ऐसा हुआ कि वस्तुगत रूप से तथा अपनी सचेत धारणाओं के परिप्रेक्ष्य के बाहर उनका चिंतन सामाजिक हित से जुड़ने के साथ-साथ, जैसा कि वास्तव में हुआ, विशिष्ट दलों व वर्गों के हितों में भी जुड़ गया। विचारणीय विषय तो यह है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और लेखकों का चिंतन और उनकी गतिविधि का सुस्पष्ट रूप में अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसमें कि यह देखा जा सके कि वे किसका प्रतिनिधित्व करना चाहते थे और और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह किसी राजनैतिक नेता का अथवा व्यवहारशील बुद्धिजीवी का प्रथम किमी एन वर्ग अथवा जाति-विशेष से उद्भव मानना और फिर उस पर इस अथवा उस वर्ग अथवा जाति-विशेष का होने का ठप्पा लगाना यांत्रिक भौतिकवाद के बचकाना प्रयोग (समाज शास्त्रीय दृष्टि में भी) के अनिर्वृत्त और कुछ भी नहीं। वास्तव में प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी नेता अपने आप में कोई एक वर्ग नहीं थे। उनके आर्थिक विचार और नीतियों की प्रतिक्रिया का स्तर तथा अन्यान्य स्तर विचारक के थे न कि किसी संकुचित निजी स्वार्थों वाले शिक्षित समुदाय के।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का आर्थिक दृष्टिकोण मूलतः पूँजीवादी था। आर्थिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने पूँजीवाद के विकास की सामान्यतया और औद्योगिक पूँजीपतियों के हितों की विशेषतया वकालत की। परंतु यदि कभी-कभी ऐसा लगता है कि भारतीय नेताओं ने औद्योगिक पूँजीपतियों पर आवश्यकता से कुछ अधिक ध्यान दिया तो यह इसलिए नहीं हुआ कि उनका दृष्टिकोण इस वर्ग-विशेष के मिहित स्वार्थों तक ही सीमित था। वास्तविकता यह थी कि उनका यह विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में देश के पुनरुद्धार का एकमात्र उपाय पूँजीवादी प्रणाली पर औद्योगिक विकास था। अथवा, हमारे शब्दों में उस समय वस्तुगत रूप से औद्योगिक पूँजीपतियों का हित ही राष्ट्र के प्रमुख हित के साथ मेल खाता था। वे पूँजीपतियों के समर्थक थे क्योंकि उनका विश्वास था कि अपने भाषणों और लेखों में जिस द्रुत औद्योगीकरण की वे रट लगाते आ रहे थे,

उमे यही वर्ग कार्य रूप दे सकता था। वे केवल औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग का केवल इस रूप में प्रतिनिधित्व करते थे कि उनका आर्थिक चिंतन और कार्यक्रम पूंजीपतियों के पथ पर व्यवहार में आने वाले औद्योगीकरण की सीमा के बाहर जा ही नहीं पाता था।

इस संदर्भ में यह बात स्मरणीय है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग, औद्योगिक और व्यापारिक, मूलतः सरकार-समर्थक था और उसने पनपते राष्ट्रवादी आंदोलन को सक्रिय समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में कोश की कमी के रोने-चिल्लाने के अभिलेख का अध्ययन यह मानने को विवश करता है। मुख्य वाणिज्य और उद्योग प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को वित्तीय सहायता के रूप में एक पाई तक नहीं देते थे। दादाभाई नौरोजी, ए० ओ० ह्यूम और विलियम वेडरबर्न ने इंग्लैंड में काम करते समय अपना निजी धन लगाया। सक्रिय रूप से भारत समर्थक अंग्रेज लोक नेता विलियम डिंगबी को अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे भारतीय राजकुमारों के निजी हितों के इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व करने का काम करना पड़ा। जस्टिस गानाडे, ए० एम० योम, एल० एम० घोष, पी० एम० मेहता, डी० ई० वाचा, लाजपतराय, मदन मोहन मालवीय और अन्यान्य को अपनी व्यावसायिक आय पर जीवन निर्वाह करना पड़ा। लोकमान्य तिलक कानून के प्राइवेट छात्रों के लिए खोले गए ट्यूशन के कालेज में अपनी आजीविका चलाते थे। जी० के० गोखले दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में थोड़ा-सा ही वेतन पाते थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक प्राइवेट कालेज चलाते थे। जी० मुन्नाय्य और त्रिपिनचन्द्र पाल पत्रकार के रूप में काम करते थे। पाल मद्रोदय को को तो तुच्छ वेतन मिलता था। इस युग में राष्ट्रवादी पत्रकार सच्चे अर्थों में वह व्यक्ति होता था, जो मामूली से वेतन पर और प्रायः भूखे पेट राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करता रहता था। इस अवधि में कांग्रेस द्वारा इरुट्टी की गई विपुल धनराशि केवल राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक महाराजा दरभंगा जैम रात्रकुमारों और बड़े-बड़े जमींदारों में ही प्राप्त हुई। बम्बई सूची कपडा उत्पादक मिलों के प्रवक्ताओं ने गहा तक कि 1905 में भी स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने में इनकार कर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत ही भारतीय पूंजीपति वर्ग राष्ट्रवादी आंदोलन का उल्लेखनीय परिमाण में समर्थन और राष्ट्रवादी नेताओं तथा दलों को वित्तीय सहायता देने लगा।

यहां हम इस तथ्य को फिर दोहराना चाहेंगे कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका संचालन राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी, यदि आप कहना चाहें तो दार्शनिक, कर रहे थे। उन्होंने पूंजीवादी दृष्टिकोण इसलिए नहीं अंगनाया कि इसके पीछे उनके संकुचित स्वार्थ निहित थे प्रत्युत इसके पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा था कि पूंजीवादी विकास ही एक ऐसा मार्ग था कि जिस पर चलकर भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित और संपन्न हो सकता था। बुद्धिजीवी होने के नाते वे चालू सुस्थापित आर्थिक सिद्धांत और पश्चिमी व्यवहार के ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करते रहे परंतु इस समय के साथ उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी स्थिति अपनाई जिसका स्वाभाविक परिणाम भारत में साम्राज्यवाद के वर्तमान ढांचे को उखाड़ फेंकना और इस रूप में देश की आर्थिक गति-हीनता को समाप्त करना था। इसके आंतरिकतः ब्रिटिश भारतीय सरकारी अधिकारियों

के चिंतन की अपेक्षा इन नेताओं के चिंतन में समकालीन यथार्थता अधिक झलकती थी। ब्रिटिश भारतीय आर्थिक नीतियों की अपेक्षा इन नेताओं की आर्थिक नीतियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यह सत्य है कि उनका पूँजीवादी वर्ग को भारत का आर्थिक कर्णधार मानने का विश्वास आर्थिक दृष्टि से उनकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता सिद्ध हुआ। यह एक ऐसा पक्ष था जिसने प्रारम्भिक भारतीय नेताओं को राजनैतिक समर्थन के लिए जनता के कुछ एक उच्च और मध्यम वर्ग पर निर्भर रहने को विवश कर दिया। यही कारण था कि इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन में न गहराई आ पाई और न ही जन जन में उसे व्यापक समर्थन मिला, अतः वह अप्रभावी बन गया।

समय आने पर आर्थिक आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को राजनैतिक मांगें पेश करने को प्रेरित किया क्योंकि वे अब अनुभव करने लगे थे कि राजनैतिक शक्ति प्राप्त होने पर ही आर्थिक नीतियों को भली प्रकार लागू किया जा सकता है। वे अब स्वतंत्र औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के, विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से ही राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने लगे। हाँ, उनकी राजनैतिक रियायतों की मांग उनके आर्थिक अभिप्राय में हटकर ही उठाई गई। उनकी प्रशासन में सुधार और राजनैतिक सत्ता में भागीदारी की मांगों का एक महत्वपूर्ण कारण प्रशासन को आर्थिक विकास और लोककल्याण का एक बेहतर माधन बनाने की उच्छा थी। जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं कि लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने अथवा दूसरे वर्ग ने देश की राजनैतिक दृष्टि में परगधीनता की स्थिति के साथ अथवा राजनैतिक स्वशासिता के साथ अथवा कम-से-कम राजनैतिक अधिकारों में भारतीयों की भागीदार बनने की इच्छा के साथ जोड़ दिया।²¹ अतः बहुत सारे राष्ट्रीय नेता इस निष्कर्ष को निकालने पर विवश हो गए कि क्योंकि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन केवल शोषण के कार्य की पूर्ति का माधन था,²² अतः देश तभी आर्थिक दृष्टि में विकसित हो सकता है जब विशुद्ध ब्रिटिश शासन का स्थान एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था ले जिसमें भारतीय महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाए।

हमारे अध्ययन के अंतर्गत अवधि में यदि राष्ट्रवादी नेताओं के पास राजनैतिक अथवा आर्थिक लाभों के रूप में दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो इसका कारण कदाचित् उनके राजनैतिक कार्य और आंदोलन का एक अपना ही ढंग था। इस अवधि में राष्ट्रवादी गतिविधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष, विरल अपवादों को छोड़कर, लोकप्रिय आंदोलनों और गतिविधियों तथा राजनैतिक संघर्षों का अभाव था, जिनके बिना प्रस्तावों, स्मरण-पत्रों, समाचार-पत्रों के संपादकीयों और लेखों का कोई राजनीतिक प्रभाव ही नहीं पड़ सकता था। आर्थिक प्रश्नों की गहरी और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता पूर्ण जानकारी के बावजूद भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में यदि सफल नहीं हो पाए अथवा राष्ट्रवादी आंदोलन को विशेष शक्ति नहीं दे पाए तो इसका कारण उनकी आर्थिक नीतियों और मांगों के पीछे जनता के आंदोलन और संघर्ष का अभाव था। उनकी असफलता इस दोहरे विश्वास को न तोड़ने में निहित थी कि ब्रिटिश राज्य अपराजेय है और पूँजीवादी उत्पादन शैली एकमात्र संभव उपाय है। ब्रिटिश सत्ता

की पूर्ण शक्ति को चुनौती देने का आत्म विश्वास और सामर्थ्य जुटाने में उन्हें दशाब्दियां लग गईं। उस समय तक वे ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में सुधार की बात कहते थे जिससे कि उमे भारतीय आर्थिक विकास का एक अच्छा माधन बनाया जा सके। उन्होंने ब्रिटिश शासकों की खुशामद की, उन पर प्रभाव डालने की चेष्टा की परंतु उल्टाड-फेंकने की नहीं सोची। भारतीय नेता इसके अतिरिक्त स्वयं अपने और विशाल जनता के बीच की गहराई खाई को पाट नहीं सके अथवा जनता के विशाल समुदाय को राजनैतिक गति-विधि में अपना सक्रिय साथी नहीं बना सके। परंतु उनके पास मनुष्य के मन का अध्ययन करने की प्रतिभा थी। अतएव उनकी ठोस उपलब्धियों के अभाव का कारण सही आर्थिक जानकारी का अभाव और नीतियां न होकर राजनैतिक जन समर्थन का अभाव ही था। यह सुझाया जा सकता है कि यह वस्तुतः राजनैतिक जन समर्थन था न कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक जानकारी अथवा नीतियां अथवा उनकी बकालत थी, जो इस अध्ययन के अंतर्गत बाद के समय के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमारे अध्ययन के अंतर्गत-अवधि के आंदोलन में भिन्न करता है। इस प्रारंभिक काल में ही ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक परिधि की राष्ट्रवादी आलोचना की प्रमुख रूपरेखा का भली प्रकार और वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण किया गया। परवर्ती राष्ट्रवादियों को तो इस पर बहुत निर्भर करना पड़ा। निस्संदेह उन्होंने पुराने आर्थिक सत्यो और तर्कों का व्यापक परिमाण में प्रचार किया। उन्होंने पुराने सत्यों में राजनैतिक जीवन फूका परंतु फिर भी यह कहा जा सकता है कि वे इनसे आगे नहीं बढ़ पाए।

महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्होंने मुख्य आर्थिक प्रश्नों को इस ढंग से पेश किया कि उससे ब्रिटेन और भारत के आर्थिक हितों के मध्य मधर्ष उजागर हो गया। उन्होंने इस तथ्य का निर्देश किया कि भारतीय यथार्थता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक पक्ष यह था कि भारत आर्थिक घोषण के लिए विदेशी शक्ति द्वारा शासित किया जा रहा था। उनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का इंग्लैंड तथा यूरोपीय राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था से भिन्न पक्ष संक्षेपत यह था कि इस देश की अर्थव्यवस्था और वित्त विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित है। उन्होंने आर्थिक समस्या के समाधान के लिए स्पष्टतः ऐसे सुझाव दिए, जिन्हें ब्रिटिश सरकार कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, इस रूप में उन्होंने इस तथ्य को सामने रखा कि राष्ट्रीय आर्थिक मांगों की पूर्ति के लिए तथा नीतियों को लागू करने के लिए राजनैतिक स्वायत्तता आवश्यक थी। उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें शासक और शासित के बीच टकराव इस प्रकार में बढ़ता गया कि राजनैतिक सत्ता अथवा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अनिवार्य हो गया। एक बार विदेशी शासकों और राष्ट्रवादी आंदोलन कर्त्ताओं के बीच जब विवाद के मुख्य विषय इस रूप में प्रस्तुत किए गए, जब एक बार भारत व ब्रिटिश शासन के बीच अंतर्विरोध स्पष्ट हो गया तो सही रणनीति अपनाना तो समय की बात ही रह गई। वास्तविक राजनैतिक संघर्ष बाद में आ सकता था और आया। शक्तियों और रणनीति को समझने की गलतियों को प्रमुख संबंधित विषयों के संदर्भ में ठीक किया जा सकता था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस युग के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं की राज-

नैतिक गतिविधि जनता को सावधानी के साथ राजनैतिक शिक्षण देने तथा उन्हें आधुनिक राजनैतिक और राष्ट्रवादी चिन्तन तथा गतिविधि के योग्य बनाने के ही उद्देश्य को लिए हुए थी। भारतीय नेता यह भली प्रकार समझते थे कि उनका कार्य भावी राजनैतिक संघर्ष के लिए भूमिका तैयार करने का ही था। उदाहरणार्थ डी० ई० वाचा को 12 जनवरी 1905 को लिखे एक पत्र में बादा भाई नौरोजी ने लिखा—

कांग्रेस ने पनपती पीढ़ी के मन में स्वयं अपनी मंदगति और अप्रगतिशीलता के विरुद्ध असंतोष और अर्धव्यय के जो भाव उत्पन्न किए हैं, वह अपने आप में एक उपलब्धि है। यह उसका अपना ही विकास और प्रगति है... कार्य अपेक्षित क्रांति को सिरे चढ़ाना है, भले ही वह हिंसापूर्ण हो अथवा शांतिपूर्ण, क्रांति के स्वरूप का निर्धारण ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की बुद्धिमत्ता या मूर्खता पर निर्भर रहेगा।²³

इस युग के नेताओं की उपलब्धियां बहुत हैं। हां, इसके लिए तात्कालिक लाभों को सफलता का मापदंड नहीं बनाना होगा। उन्होंने भारत की जनता को सामान्य आर्थिक हितों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने भारतीयों को सामान्य शत्रु से परिचित कराया और इस प्रकार एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ बनाने में सहायता की। उन्होंने जनता को अपनी आर्थिक दुर्दशा और अपमानित स्थिति से तथा उसमें सुधार की संभावना से परिचित कराया। उन्होंने अस्पष्ट आर्थिक आकांक्षाओं को एक सुस्पष्ट राष्ट्रवादी स्वरूप दिया तथा आर्थिक विकास के विचारों का प्रचार किया। उन्होंने लोगों के मन में राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करने की लालसा उत्पन्न की और इसके लिए उनके सामने आर्थिक विकास का सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग की आर्थिक और राजनैतिक बाधाओं को और उन पर विजय पाने के उपायों का निर्देश किया। इन महान कार्यों को पूरा करने में दोनों, मृदु प्रवृत्ति और उग्रवादी, नेताओं ने समान रूप से ही योगदान दिया। दोनों ने ही आर्थिक विश्लेषण की उच्च स्तर की क्षमता और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया। हमारा यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि इतनी असफलताओं के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए सुदृढ़ आधारशिला रखी। इस प्रकार वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में गौरवमय स्थान रखते हैं। उस युग के नेताओं में से ही एक के निम्नलिखित वक्तव्य से बढ़कर कदाचित् इस युग के महापुरुषों के कार्यों का अधिक उत्तम मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है :

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की प्रगति की उस स्थिति में हैं, जहां हमारी उपलब्धियों का छोटा दिखाई देना स्वाभाविक है तथा हमारे लिए बारबार दुःखद असफलता का मुंह देखना भी स्वाभाविक है। इस संघर्ष में यही हमारी नियति है। हम जब सौंपे गए कार्य को निभा चुकते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। अब आगे का कार्य देश की भावी पीढ़ी को दिया जाना चाहिए ताकि वे सफलतापूर्वक देश की सेवा कर सकें। हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों को प्रमुख रूप से अपनी असफलताओं के साथ ही अपने देश की सेवा करने में संतुष्ट होना चाहिए। यह कहना कितना ही कठिन क्यों न हो, हमारी इन असफलताओं

से भावी पीढ़ी को वह शक्ति मिलेगी जिससे वह महान लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी।²⁴

संदर्भ

1. उदाहरण के रूप में देखिए, नौरोजी, एसेज, पृ० 26-7, और रानाडे, एसेज, पृ० 23, 65-6, 118-9
2. उदाहरणार्थ देखिए, नौरोजी, एसेज, पृ० 37, 131-5, 'दि एक्सीजेंसीस आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', जे० पी० एस० एस० अप्रैल 1893 (खंड XV सख्या 4) पृ० 15-6
3. यहा तक कि 1904 में बिल सदस्य एडवर्ड ला ने उस समय के नेताओं में सर्वाधिक मृदुभाषी जी० के० गोखले की सतत प्रलोचना के विरुद्ध उत्तेजित होकर इस प्रकार से चीखे चिल्लाए की : 'जब वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो वह कदाचित् अचेतन रूप से हैं, वे भ्रातृजन विलाप करने वाले की भूमिका और आचरण करने लगते हैं सरकार के दोषों पर उनका शोक और रुदन इतना अधिक करुणापूर्ण होता है मानो उन्होंने सबे अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा ऐसा किया है (एल० सी० पी० 1904 खंड XLIII पृ० 542)
4. उदाहरणार्थ, दादा भाई नौरोजी ने लिखा 'हमें बार बार यह याद दिलाना सर्वथा निरर्थक और ओछापन है कि ब्रिटिश राज्य ने अराजकता के बाद व्यवस्था ला दी है इसे देख के अनुवर्ती दोषों का तथा देश के भौतिक और नैतिक दिवालियेपन का स्थाई बहाना नहीं बनाया जा सकता आज के भारतीयों ने वह अराजकता न देखी है और न ही वह उसका अनुभव करते हैं भले ही वे उसे समझते हैं और व्यवस्था लाने के लिए आभार भी प्रकट करते हैं परंतु साथ ही वर्तमान में वे निकासी, दुर्गति, और बिनाश ही देख रहे हैं तथा उस पर विलाप कर रहे हैं (पावर्टी, पृ० 219) इसी प्रकार आर० सी० दत्त ने लिखा : 'ब्रिटिश शासन ने शांति अवश्य स्थापित की है परंतु ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में राष्ट्रीय संपदा के स्रोतों को उन्नत अथवा विस्तृत नहीं किया है (ई० एच० II पृ० VII) और केसरी ने अपने 31 मार्च 1903 के अंक में लिखा : 'भारतीयों में एकता और समानता है परंतु यह उमी प्रकार की एकता और समानता है जिस प्रकार की समानता एक स्वामी के सेवकों में पाई जाती है अथवा एक गडरिए की भेड़ों के समुदाय में पाई जाती है हमारे शासक हमें उत्तरदायी कार्य सौंपने को अथवा व्यापार और उद्योग में हमें सामर्थ्य बनाने को तैयार नहीं (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 1903), और देखिए प्रमाण के लिए, नौरोजी, पावर्टी, पृ० 209-12, 224-8 579, 652-3, मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 443, 447 पर उद्धृत, सी० पी० ए०, पृ० 22 पर, बनानी, 10 मई 1884, मराठा के 6 जून 1886 के अंक में ए० एस० राय का लेख; एल० एम० बोष, सी० पी० ए०, पृ० 762; आर० एन० मुखोलकर, इंडियन पार्लियामेंट, पृ० 37; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 330.
5. यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि समझौता पसंद नेताओं ने ही नहीं प्रत्युत अमृत बाजार पत्रिका और बी० बी० तिलक ने भी भारत के उद्देश्य के लिए ब्रिटिश जनता और संघ का हृदय जीतने की आवश्यकता अनुभव की. उदाहरण के लिए देखिए, ए० बी० पी० 8 अक्टूबर 1874,

26 अप्रैल 1883; तिलक, रिप० आई० एन० सी० 1904 पृ० 150-1, और प्रधान एंड भागवत, पूर्वोद्धृत, पृ० 80.

6. यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न नेताओं ने यह धारणा को विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न प्रश्नों के संबंध में अपनाई. उदाहरण के लिए आर० सी० इत के लिए संक्रमण 1897-1901 की थोड़ी सी अवधि में अर्थात् 'इंग्लैंड और इंडिया' ग्रंथ के तथा इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया के प्रथम खंड के वर्षों की मध्यावधि में आया.
7. नोरोजी, पावर्टी, पृ० V, VII, 211, 214, स्पीचेज, पृ० 142, 227-8, 276-8, 328, 396, 19 जनवरी 1898 के स्टेट्समैन में, 7 अगस्त 1903 के 'इंडिया' में पृ० 67; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 674-7; राय, पावर्टी, पृ० 37-9; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 815; जी० एस० अय्यर, ई० ए० लीचंक (प्रथम) पृ० तथा पृ० 116-7, 123-5, 239, 329. ईस्ट एंड वेस्ट, 1903 (खंड II) पृ० 888; दत्त, ई० एच० I पृ० XV ई० एच० II पृ० XVIII (वस्तुतः उनके 'इकोनामिक हिस्टरी' ग्रंथ के दोनों खंडों में यह भावना अन्तःप्रविष्ट है); प्रधान एंड भागवत; पूर्वोद्धृत, पृ० 72 पर तिलक; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 761; मोखले, स्पीचेज, पृ० 1084, 1156-7; 30 मई और 6 जून 1886 के मराठा में ए० एल० राय का लेख समाचारपत्रों के लिए देखिए, हितेच्छु, 25 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 3 अप्रैल 1880); ए० बी० पी० 19 अक्तू० 1882, 4 जून 1883, 7 अक्तू० 1886, 12 फर० 1892, 20 मई 1896; मराठा, 21 दिस० 1884, 30 दिस० 1894, 30 अक्तू० 1904; आनंद बाजार पत्रिका, 31 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 5 अप्रैल 1884); नवविभाकर, 21 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 1884); साधारणी, 15 जून (वही, 21 जून 1884); समय, 30 नव० (वही, 5 दिस० 1885); शमसुल अखबार, 12 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, अप्रैल 1886); खसमुल अखबार, 17 जून (वही, जून 1886); घूमकेतु, 20 मई (आर० एन० पी० बंग०, 28 मई 1887); बंगबासी, 30 जून (वही, 7 जुलाई 1888); 14 जून (वही, 21 जून 1890); तोहफा ए-हिंदू, 13 अगस्त, (आर० एन० पी० इन०, 19 अगस्त 1891); हिनकारी-तिथिरहित (आर० एन० पी० बंग०, 17 दिस० 1892); बगबासी, 1 सित० (वही, 8 सित० 1884); पूना वैभव, 15 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 21 मार्च 1896); जमी उल उलूम, 14 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 21 अप्रैल 1896); इंदु प्रकाश, 8 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 18 अगस्त 1898 बंगाली, 9 अप्रैल 1900; केसरी, तारीख नहीं है (आर० एन० पी० बंब 18 जन० 1902); इंडियन पोपुल 27 फर० 1903; हिंदू, 13 अक्तू० 1903; हिंद विजय 8 फर० (आर० एन० पी० बंब 11 फर० 1905).
8. उदाहरणार्थ, अरुणोदय, 15 मई (आर० एन० पी० बंब, 21 मई 1881); ए० बी० पी०, 19 अक्तू० 1882, 13 फरवरी 1894; सोम प्रकाश, 21 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 26 अगस्त 1882); हिंदी प्रदीप, जनवरी-फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 8 जून 1901); सी० वाई० चितामणि, 'एच० आर०' में, फरवरी 1903, पृ० 233.
9. ए० ओ० ह्यूम, 'ए स्पीच आन दि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स बोरिजिस, एम्स, एंड ओम्निकट्स' 30 अप्रैल 1888 को इलाहाबाद की जनसभा में दिया गया भाषण, पृ० 16.
10. क्रिरोजशाह मेहता ने इस धारणा को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को ब्रिटिश शासन के बनिया वाले भाग से अधिक परिष्कृत बनाने का एक प्रयास बताया. (स्पीचेज, पृ० 483).

11. 1903 में कांग्रेस के अध्यक्ष सारमोहन घोष ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया : 'हमें क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम उस नीति पर विश्वास करें जिसने बहुत वर्षों पूर्व हमारे स्वदेशी उद्योगों की हत्या कर दी है, अभी कल की ही बात है जिसने बिना किसी प्रकार का संकोच किए उदार प्रशासन के अंतर्गत हमारे सूती उत्पादों पर भारी उत्पादन कर लगा दिए हैं, जो निरंतर 200 लाख पौंड की सीमा तक प्रति वर्ष हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की निकासी कर रही है और जो हमारी कृषक जनता तथा कृषि उत्पादनों पर भारी कर बोध कर अतीत में सर्वथा अज्ञात विषम अकालों की तीव्रता व्यापकता और निरंतरता में वृद्धि कर रही है ? क्या हम विश्वास करें कि इन परिणामों को लाने के लिए उत्तरदायी विविध प्रशासनिक कृत्य ब्रिटिश राज्य के लोकोपकारी स्वरूप से ही सीधे प्रेरित थे ? (सी० पी० ए०, में पृ० 743 पर)।
12. ब्रिटिश दृष्टिकोण के लिए देखिए, (जार्ज हैमिल्टन के विचार) स्टोक : पूर्वोद्धृत, पृ० 300 पर. कर्जन, स्पीचेज I, पृ० VI भारतीय दृष्टिकोण के लिए देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 123, 332. एसेज, पृ० 36, पावर्टी, पृ० 216 सी० पी० ए०, पृ० 181 पर; आर० बी० घोष, स्पीचेज, पृ० 152; ए० एम० बोस०, सी० पी० ए०, पृ० 436, 'दि ब्रोकेन ग्लेज ऐंड इट्स फाल्सीक्वेंसेज' जे० पी० एस० एस०, जुलाई 1879 (खंड II संख्या-1) पृ० 43, 46; मगाठा, 1881; दत्त : इंग्लैंड ऐंड इंडिया, पृ० 118.
13. उदाहरण के रूप में देखिए, 'गोखले, स्पीचे, पृ० 1079.
14. उदाहरणार्थ कर्जन, स्पीचेज II पृ० 91 और स्पीचेज III पृ० 98; जे० स्टुडी० इंडिया (1903), पृ० 495-6; चिसनी, पूर्वोद्धृत, पृ० 390, 394, 398-9. इस दृष्टिकोण के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, स्ट्रोक्स : पूर्वोद्धृत, पृ० 65 और अध्याय 4. जेम्स मिल के दृष्टिकोण के लिए देखिए, डिग्वी, पूर्वोद्धृत, पृ० 264. डफरिन के अनुसार भारत में ब्रिटिश राज्य का आधार 'हमारी सेनाएं हैं जो अशिक्षित और उदासीन जनता की पराधीनता को बनाए हुए हैं और जनता के शेष वर्ग में यह सार्वभौमिक भावना जड़ पकड़े हुए है कि हमारे प्रशासन में कितनी ही दृष्टियाँ क्यों न हो, वह न्यायपरायण, निष्पक्ष और लाभकारी है और इसका एकमात्र विकल्प या तो मुसलमानों की क्रूरता और अराजकता को वापस लाना होगा अथवा रूस की भारत पर विजय' (डफरिन टु सेक्रेटरी आफ स्टेट, 9 जुलाई 1886 'डफरिन पेपर्स') इसी प्रकार 30 दिसंबर 1897 के धक में 'टाइम्स' ने यह श्रेणी बधारी कि उनकी अपनी जाति के इतिहास में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जिसमें अपनी भारत सरकार की अपेक्षा ब्रिटिश जनता किसी अन्य में अधिक गर्व का अनुभव करे. किसी और में ये सभी गुण, साहस, न्याय, दूरदृष्टि तथा आत्म त्याग, सर्वोत्तम रूप में निरंतर और गौरव के साथ दृष्टिगोचर नहीं हुए. ... किन्हीं विशेष बातों के लिए कितनी भी आलोचना क्यों न की जाए, मुख्य तथ्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती यह सब लिखने के उपरांत उसने घोषणा की : 'भारत में संसदीय सरकार के नियम लागू नहीं हो सकते उसने सिखा कि ऐसा करना अराजकता को बुसावा देना है भारत की जनता किसी भी रूप में स्वशासन के सर्वथा और पूर्णतया अयोग्य है और वे अपने देशवासियों द्वारा शासित होना कभी स्वीकार नहीं करेंगे.'
15. 1887 में जे० बी० पीले ने डफरिन को लिखे एक पत्र में टिप्पणी की : 'वास्तव में भारत के लोगों को ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिससे क्षुब्ध होकर वे शांति और चैन को परे फेंक दें तथा शासकों के विरुद्ध तत्काल निकास कर चढ़े हो जाएं (2 अक्टूबर 1887, डफरिन पेपर्स)

प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए आर्थिक आंदोलन ने इस शिकायत की भावना को ही जन्म दिया

16. हंसार्ड, चौथी सिरीज खंड XLV, 26 जनवरी 1897 लगभग 534. भारत सचिव जार्ज हैमिल्टन ने दादाभाई नौरोजी को 6 दिसंबर 1900 को लिखे एक पत्र में शिकायत की : 'आप स्वयं अपने को ब्रिटिश राज्य का सच्चा समर्थक घोषित करते हैं परंतु उस राज्य की व्यवस्था के लिए उसके साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी स्थितियों और परिणामों की आप निंदा करते हैं (मसानी : पूर्वोद्धृत, पृ० 459 पर) 30 दिसंबर 1897 के भ्रम में टाइम्स ने इसी प्रकार की भावना व्यक्त की लिखा, राष्ट्रवादी नेताओं के प्रति ब्रिटिश के झूठापूर्ण व्यवहार के लिए देखिए, एच० एम० सिंह पूर्वोद्धृत, अध्याय 4 तथा देखिए डब्ल्यू० एस० सितो कर, दि नेटिव प्रेम आफ इंडिया, एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू खंड VII, 1889 पृ० 62 रीस, पूर्वोद्धृत, अध्याय 10 और पृ० 286-8
17. उन्होंने आगे कहा : 'वे सदैव ब्रिटिश सरकार के प्रति बफादारी का दम भरते हैं परंतु जो प्रस्ताव बेपारित करते हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे इस सरकार के लिए काम करना असंभव बना देना चाहते हैं' (पूर्वोक्त स्पेल, पृ० 385 (पृ० 432-7 भी देखें)
18. डफरिन द्वारा 17 मई 1886 को भारत सचिव को लिखा पत्र, डफरिन पेपर्स कुछ महीनों के उपरांत 7 अगस्त 1889 को ए० ओ० ह्यूम को लिखे पत्र में डफरिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा : कि वह भारतीय समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की एक सीमा निर्धारित करना चाहते हैं इस तथ्य को दृढ़तापूर्वक कहने के उपरांत कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र प्रेस इस आवश्यक उद्देश्य के लिए दिया है कि वह सरकार के कार्यों की यथोचित आलोचना और समर्थन करे तथा जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दे, उन्होंने प्रेस से अपने निम्नलिखित दो दायित्वों के निष्ठाने की अपील करते हुए कहा 'प्रथम सरकार की आलोचना यथार्थ तथ्यों पर आवृत्त होनी चाहिए, सरकार के कल्पित अभिप्रायों अथवा अनुमान पर आश्रित धारणाओं को लेकर किसी प्रकार की निंदा कदापि उचित नहीं द्वितीय सरकारी नीति की किसी प्रकार की आलोचना क्यों न हो, ब्रिटिश प्रशासन पर इस देश में अथवा इंग्लैंड में यह अभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह यह सब कुछ द्वेषपूर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर कर रहा है' (डफरिन पेपर्स)
19. उदाहरण के रूप में दादाभाई नौरोजी ने 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सभापतिपद से भाषण करते हुए इस तथ्य पर बल दिया उन्होंने कहा मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें यह पूर्णतः विश्वास करना चाहिए कि हम जो भी राजनीतिक व राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करें, किसी ने किसी प्रकार से समाज के सभी वर्गों उनसे लाभान्वित होंगे प्रत्येक वर्ग को मिलने वाले लाभ का रूप भिन्न भिन्न होगा हम सबके हित समान हैं और हम एक ही दिशा में यत्नशील हैं हम इकट्ठे ही दूबेंगे और इकट्ठे ही तरंगें ... यदि देश संपन्न है और एक को यदि जीवन के एक क्षण में उन्नति का अवसर मिलता है तो दूसरे को दूसरे क्षण में मिलेगा। जैसे कि हमारे यहां देश में यह उचित प्रचलित है 'यदि कुएं में पानी होगा तो कुड़ में पहुंचेगा ही' यदि हमारे पास समृद्धि का कुड़ा है तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग ले सकेगा परंतु यदि कुड़ा ही सूखा है तो हम सबको बिल्कुल प्यासा रहने पर विवश होना पड़ेगा (इन सी० पी० ए०, पृ० 180-1 पर)। और देखिए, जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 748-9; बार० एम० खानी, सी० पी० ए०, पृ० 309.
20. यहां यह उल्लेखनीय है कि 1920 और 1940 के बीच की अवधि के दौरान अधिक प्रबलता के

साथ सक्रिय आंदोलन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा ग्रहण की गई भूमि लगानों को कम करने की मांग ही कृषि सबंधी एकमात्र मांग थी 1936 तक ऊँचे लगान से किसानों के सरक्षण के प्रश्न को अलग अलग निजी तौर पर कांग्रेसियों के प्रयत्नों पर ही छोड़ रखा था. 1936 में कांग्रेस ने पहली बार काश्तकारी पद्धति और भूमि लगान पद्धति में मौलिक परिवर्तन की मांग की. उन्होंने कृषि सबंधी करें और लगानों में छूट देकर छोटे किसानों की तत्काल सहायता करने की पहली बार ही मांग की (इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिजाल्यूशंस आन इकोनामिक पालिसी ऐंड प्रोग्राम, 1924-54, नई दिल्ली, 1954 पृ० 13-3) गांधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्यारह सूत्रों में कृषि सबंधी एकमात्र मांग थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के मूल्य के रूप में किसानों को भूमि लगान में कटौती के रूप में राहत (बी० पट्टाभि सीतारमैया . दि हिस्टरी आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885-1935 मद्रास 1935, पृ० 619)

- 21 यह पर्याप्त रोचक है कि आर० सी० दत्त ने कम से कम एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित करने का तथा उसे भूमि लगान, उद्योग और कृषि विभाग सौंपने का अनुरोध किया (सी० पी० ए०, पृ० 497-8)
- 22 इंडियन पीपुल, 27 फरवरी 1903 अन्यान्य सदस्यों के लिए देखिए, पीछे पृ० 7 पर पार्दाटप्पणी स० 79
- 23 मसानो पूर्वोद्धृत, पृ० 44। पर इसी प्रकार पूना सार्वजनिक सभा द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किए गए ज्ञापन पर सरकार की दो पत्रियों के उत्तर पर गोखले ने निराशा प्रकट की तो जमिंदार गानाडे ने समझाते हुए कहा आप अपने देश में इतिहास में अपने स्थान को क्यों नहीं समझते ये ज्ञापन नाममात्र के लिए सरकार को दिए जाते हैं, वस्तुतः ये जनता को संबोधित है ताकि वे यह समझ सकें कि इन मामलों में उन्हें क्या विचार करना है किसी प्रकार के सफल परिणामों की अपेक्षा किए बिना ही इस कार्य को वर्षों तक चलाना चाहिए क्योंकि इस देश में इस प्रकार की राजनीति सर्वथा एक नई वस्तु है गोखले, स्पीचेज, पृ० 929 पर).
- 24 गोखले, स्पीचेज, पृ० 1113.

ग्रंथसूची

नोट : संक्षेप की दृष्टि में केवल ग्रंथ में उद्धृत स्रोतों का ही उल्लेख किया जा रहा है ।
पुस्तक में प्रयुक्त संक्षिप्त शीर्षक प्रत्येक शब्द के पूरे शीर्षकों के पश्चात् कोष्ठक में दे दिए गए हैं

प्राथमिक स्रोत

(क) पुस्तकें

ऐबस्ट्रेक्ट्स आफ दि प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर जनरल आफ इंडिया,
कानून और विनियमों की रचना के उद्देश्य से संकलित (वार्षिक) 1877-1905
(एल० सी० पी०)

बैनर्जी सुरेंद्रनाथ, स्पीचेज, खंड 1-5, कलकत्ता, 1880, 1885, 1890, 1894, 1996
(स्पीचेज I आदि) स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (जी० ए० नारायण ऐंड कंपनी मद्रास
द्वारा निधि निर्देश के बिना प्रकाशित) (एस० ऐंड डब्ल्यू).

बंगाल नेशनल चेंबर आफ कामर्स रिपोर्ट (वार्षिक) 1887-91, 1894-1905 भरूचा,
एस० बी०, स्पीचेज आफ इंडियन एकोनामिक्स, (बंबई तिथि गृहित).

बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट (वार्षिक) 1885-6, 1886-7, चदावरकर
एन० जी०, स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स कैंकिनी द्वारा संपादित एल० वी० बंबई 1911.

कर्जन लाड (केडोलस्टोन) स्पीचेज, खंड 1-4 कलकत्ता, 1900, 1902, 1904, 1906
(स्पीचेज I आदि).

देसाई, अंबालाल शेखरलाल, स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (बंबई 1918) भारत सचिव द्वारा
तथा भारत सचिव को किए गए संप्रेषण, 1875-1905.

डफरिन, मारकिस आफ, ऐंड आवा, स्पीचेज (कलकत्ता 1889).

डफरिन पेपर्स माइक्रोफिल्म प्रतिलिपियां, के (नेशनल आर्काइव्स आफ इंडिया, नई
दिल्ली).

दत्त, आर० सी०; दि पैजटरी ग्राफ बंगाल 1874. इंग्लैंड ऐंड इंडिया, (लंदन 1897).

सर फिलिप फ्रांसिस मिनिट्स आन दि सबजेक्ट आफ ए परमनेंट सैटलमेंट फार बंगाल, बिहार ऐंड ओरिसा, आर० सी० दत्त द्वारा भूमिका (कलकत्ता 1901), फौमिस ऐंड लैंड एसैसमेंट इन इंडिया, (लंदन 1900) (फौमिस इन इंडिया), इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया, अर्ली ब्रिटिश रूल, 1956-1901 मे लंदन मे प्रथम प्रकाशित का मुद्रित रूप (ई० एच० I) इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया इन दि विक्टोरिया एज (लंदन में प्रथम प्रकाशित का छटा संस्करण) (ई० एच० II) स्पीचेज ऐंड पेपर्स आन इंडियन क्वेश्चंस, 1897-1900. (कलकत्ता 1904) (स्पीचेज II) ओपन लैटर्स टु लार्ड कर्जन, (कलकत्ता 1904) (ओपन लैटर्स).

एलगिन ब्रॉल आफ, स्पीचेज (कलकत्ता 1898).

ऐमिनेट इंडियंस आन इंडियन पालिटिक्स, सी० एल० पारिख द्वारा संपादित, (बंबई 1892) (ऐमिनेट इंडियंस).

फाइनास कमेटी रिपोर्ट आफ 1886.

फाइनांशल स्टेटमेंट आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया (वार्षिक 1877-1905).

घोष, लालमोहन, स्पीचेज दो भाग (कलकत्ता 1883-1884).

घोष. डा० राम विहारी, (स्पीचेज ऐंड गवर्नमेंट, तृतीय संस्करण मद्रास निधि रहित).

गोखले जी० के० स्पीचेज, जी० ए० नाटेमन द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण (मद्रास, 1916), पत्र व्यवहार, अप्रकाशित, दि लाइब्रेरी आफ दि गोखले इंस्टीच्यूट आफ पोलिटिक्स ऐंड इकोनामिक्स, पूना.

गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) के अधिनियम, 1880-1905.

हसाई (संमदीय विवाद) 1880-1905.

होम (पब्लिक) डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया, प्रोसिडिंग्स, 1880-1905.

ह्यूम, ए० ओ० : ए म्पीच आन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐंड इट्स ओरिजिन एम्स ऐंड आन्क्जेंट्स, 30 अप्रैल 1888 मे इलाहाबाद मे हुई जनसभा मे भाषण.

इंडियन एसोसिएशन की रिपोर्ट (वार्षिक) 1880-1905 छिटपुट (स्ट्रे रिपोर्ट).

इंडियन करेंसी कमेटी की रिपोर्ट, 1893, (कलकत्ता 1893).

इंडियन करेंसी कमेटी, मिनिट्स आफ एविडेंस ऐंड रीडिन्स 1893, सी-7060-2.

इंडियन डिबेट्स (हंसाईंस) फरवरी 1902.

इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट, 1883.

इंडियन फौमिन कमीशन की रिपोर्ट, (1880 लंदन).

इंडियन फौमिन कमीशन की रिपोर्ट (1898 कलकत्ता).

इंडियन फौमिन कमीशन की रिपोर्ट (1901 कलकत्ता).

इंडियन लीकलैट्स (इस्तहार) इंडियाज अपील टु दि इंग्लिश इलैक्टर्स पब्लिशिड ऐंड डिस्ट्रीब्यूटेड आन बिहाफ आफ पिपुल आफ इंडिया बाई दि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आफ कलकत्ता, दि बीबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन, दि पूना सार्वजनिक सभा

आफ मद्रास, दि सिंध सभा आफ कराची, दि प्रजा हितवर्धक सभा आफ सूरत, 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्टें (वार्षिक) 1885-1904 (रिप० आई० एन० सी०). इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटेनिंग फुल टेक्स्ट आफ प्रेसीडेंशियल ऐंड्रेस. रिप्रिंट आफ आल दि कांग्रेस रिजाल्यूशन्ज आदि. मद्रास, तिथि निर्देश नहीं (सी० पी० ए०). इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिजल्यूशन आन इकोनामिक पालिसी ऐंड प्रोग्राम 1924-54 (नई दिल्ली 1954).

इंडियन पानिटिक्स, (जी० ए० नटेसन, मद्रास द्वारा 1898 में प्रकाशित)

अय्यर, जी० सुब्रह्मण्य : सम इकोनामिक आस्पैक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया (मद्रास 1903) (ई० ए०).

अय्यर, एस० सुब्रह्मण्य (स्पीचेज ऐंड राइटिग, मद्रास, तिथि रहित)

जोशी जी० वी० : राइटिग ऐंड स्पीचेज, (पूना 1912).

लाजपत राय : लाला लाजपत राय, दि मैन इन हिज वर्ड, (मद्रास 1907).

लैंड प्रान्बल्स इन इंडिया, पेपर्स बाई आर० सी० दत्त ऐंड अदर्स, (मद्रास 1902).

लैंड रैवेन्यू पालिसी आफ इंडियन गवर्नमेंट, (कलकत्ता 1902) (इन्क्विराडिंग रिजाल्यूशन बाई दि गवर्नर जनरल आफ इंडिया इन कौमिल न० 1 तिथि 16 जनवरी 1902) ।

लैंसडोन, मारकिस आफ स्पीचेज, 1888-94, 2 खंड (कलकत्ता 1894).

मालाबगी, बहराम जी० एम० : दि इंडियन प्रान्बल्स (बंबई 1894).

मालवीय, मदनमोहन : स्पीचेज, (गणेश ऐंड कंपनी मद्रास द्वारा प्रकाशित, तिथि रहित)

माडलिक, वी० एन० : राइटिग ऐंड स्पीचेज (बंबई 1896).

मेहता फिरोजशाह एम० : स्पीचेज ऐंड राइटिग, सी० वाई० चितामणि द्वारा संपादित, (इलाहाबाद 1905) (स्पीचेज) सम अनपब्लिशड ऐंड लेटर स्पीचेज ऐंड राइटिग (बंबई 1918).

मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दि थर्ड डिसेनियल, जे० ए० बेंस द्वारा तैयार की गई, (लंदन 1894).

मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दि फोर्थ डिसेनियल, फासिस सी० ड्रेक द्वारा तैयार की गई, (लंदन 1903).

नौरोजी, दादाभाई : एमेज, स्पीचेज ऐंड राइटिग, सी० एल० पारिख द्वारा संपादित, (बंबई 1887) (एसेज) पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, (लंदन 1901) (पावर्टी) स्पीचेज ऐंड राइटिग, (जी० ए० नटेसन ऐंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण, मद्रास, तिथि रहित) (स्पीचेज).

पाल, विपिनचंद्र, दि न्यूस्पिरिट, (कलकत्ता 1907).

पेपर्स रिर्लेटिंग, टु चेंजेस इन दि इंडियन करेंसी सिस्टम, (शिमला 1893).

पार्लियामेंटरी पेपर्स (1876-1905) (पी० पी०).

पूना सार्वजनिक सभा, भारत से संबंधित विषयों को ईस्ट इंडिया फाइनांस कमेटी के समक्ष रखने के लिए सूचनाएं संग्रहीत करने के लिए नियुक्त पूना सार्वजनिक सभा

की उपसमितियों की रिपोर्ट, पूना 1873.

प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ मद्रास, 1898, 1899, 1902, 1903.

प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बॉम्बे, 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1905.

प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि लैफ्टिनेंट गवर्नर आफ बंगाल, 1898.

प्रोसीडिंग्स आफ दि लैजिस्लेटिव कौंसिल फार दि एन० डब्ल्यू० पी० ऐंड अवध 1901.

प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग आफ दि इंडियन करेंसी एसोसिएशन 13 जुलाई 1892.

प्रोसीडिंग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग हेल्ड ऐट दि फामजी कावसजी इंस्टीच्यूट अंडर दि आस्पेसिज आफ दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन आन सैटरडे, 15 जुलाई 1893.

(15 जुलाई 1893 को शनिवार के दिन बंबई प्रांतीय सभा द्वारा फामजी कावसजी संस्थान में हुई जनसभा की कार्यवाही).

प्रोसीडिंग्स आफ दि फस्ट नार्थ अरकाट डिस्ट्रिक्ट कांफेंस हेल्ड आन 21, 22 जुलाई 1900 ऐट चित्तौड़.

पब्लिक एजुकेशन कमीशन प्रोमोडिंग्स, 1887. 7 खंड (कलकत्ता).

रानाडे, एम० जी० : एस्सेज आन इंडियन इकोनामिक्स (बंबई 1898) (एस्सेज) दि मिसलेनियस राइटिंग्स, बाइ रमावाई रानाडे द्वारा प्रकाशित (बंबई 1915) 'प्ली फार प्रोटेक्शन, इंडियन शुगर इंडस्ट्री,' मई और जून 1890 को टाइम्स आफ इंडिया में दिए गए तीन लेख जिनकी भूमिका बी०जी० काले ने लिखी (बंबई तिथि रहित).

राय, पृथ्वीशचंद्र : दि पावर्टी प्रान्ब्लम्स इन इंडिया (कलकत्ता 1895) (पावर्टी) दि इंडियन शुगर इंड्यूस्ट्रीज (कलकत्ता 1899), इंडियन फैमिस, देयर काजेज ऐंड रेमेंडीज, (कलकत्ता 1901) (फैमिस).

रिजाल्यूशन आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, सर्कुलर नं० 96 एफ. 6-59, 19 अक्टूबर 1888, फैमिन प्राग नं० 19, सि० 1888.

रिजाल्यूशन आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया, 27 नव० 1893 (जनरल) फाइल नं० 95 सीरियल नं० 7.

रायल कमीशन आफ दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्सपेंडीचर आफ इंडिया, रिपोर्ट आफ खंड 3 और 4 पार्लियामेंटरी पेपर (हाउस आफ कामंस) 1900, खंड 29, सी 130 और सी 131 (विलबी कमीशन)

रणछोड़लाल छोटेलाल : लैटर्स आन दि करेंसी क्वेश्चन, (अहमदाबाद, 1895).

सेन, केशवचंद्र : लाइफ ऐंड वर्क्स आफ ब्रह्मानंद केशव, प्रेम सुंदर बसु द्वारा संकलित, (कलकत्ता 1940).

सोर्स मैटिरियल फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, (बंबई, खंड I 1957).

तेलंग, के० टी० : फ्री ट्रेड ऐंड प्रोटेक्शन : फाम ऐन इंडियन प्वाइंट आफ व्यू, (बंबई 1877) सिलेक्ट राइटिंग्स ऐंड स्पीचेज, (बंबई 1885) ।

वकील, एम० एच० : दि करेंसी प्रान्ब्लम इन इंडिया ऐंड सर डेविड बारबोर, दि ऐंग्लो

इंडियन, ऐंड दि रूपी, (बंबई 1892).

वाचा, डी० ई० : स्पीचेज ऐंड राईटिंग्स. (जी० ए० नटेसन ऐंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण, मद्रास, तिथिरहित) (स्पीचेज).

वाडिया, जे० ए० : दि आर्टिफिशल करेंसी ऐंड दि कामर्स आफ इंडिया, बंबई, 1902.

(ख) पत्र-पत्रिकाएं

अमृत बाजार पत्रिका, (कलकत्ता) 1870-1905 (ए० बी० पी०) *

एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, (लंदन) 1886-1905.

बंगाल मैगजीन, (कलकत्ता) 1873-82.

बंगाली, (कलकत्ता), 1880-1905.

ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन (कलकत्ता) 1878-1881.

कलकत्ता रिव्यू.

कनकाई, (कलकत्ता) 1887.

डान, (कलकत्ता) 1897-1905.

ईस्ट ऐंड वेस्ट, (बंबई) 1901-1905.

हिंदू, (मद्रास) 1880-1905.

हिंदुस्तान रिव्यू ऐंड कायस्थ समाचार (1899-1902) तक कायस्थ समाचार नाम से प्रसिद्ध (इलाहाबाद) 1899-1905 (एच० आर०)

इंडिया (लंदन) 1890-1905.

इंडियन पीपुल, (इलाहाबाद) 1903-04.

इंडियन रिव्यू, (मद्रास) 1901-1905.

इंडियन स्पेक्टेटोर ऐंड वायम आफ इंडिया, बंबई 1890-1901, (आई० एम० वी० ओ० आई०).

इंदु प्रकाश, (बंबई) 1883-1895 (छिटपुट प्रतिपा).

जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, (लंदन) 1867-1895.

जरनल आफ दि पूना सार्वजनिक मभा क्वार्टरली (पूना) 1878-1897 (जे० पी० एस० एस०)

जरनल आफ दि रायल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी, 1902, 1911.

मराठा, पूना 1881-1905.

मुकजी'ज मैगजीन, कलकत्ता 1872-1876 (एम० एम०).

* पत्रिका के तीन विभिन्न संस्करणों, नगर, मुफस्सिल और विदेश का प्रयोग किया गया है. इसकी तिथियों में एक सावधान पाठक को मिलने वाले अंतर का कारण इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगा. हमारे लिए इसके निवाय और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि पत्रिका के कार्यालय में संग्रहीत पत्रिका के अंक इसी रूप में उपलब्ध हैं. इस प्रकार सभी प्रयुक्त तिथियां कार्यालय के संग्रह के ही अनुरूप हैं.

नेटिव ओपीनियन (बंबई), 1880-1889 (बिखरी हुई प्रतियां).

न्यू इंडिया, (कलकत्ता) 1901-1904 (बहुत सारे संस्करण अप्राप्य).

रिपोर्ट आफ दि नेटिव प्रेस फार बौंदे (साप्ताहिक) 1870-1905 (आर० एन० पी० बंब).

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार बंगाल (साप्ताहिक) 1875-1905 (आर० एन० पी० बंग०).

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार मद्रास (मासिक और बाद में साप्ताहिक) 1875-1905 (आर० एन० पी० एम०)

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार पंजाब, नाथ वेस्ट प्राविसेज ऐंड अवध आदि (साप्ताहिक) 1875-1888 (आर० एन० पी० पी० एन०)

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार पंजाब (साप्ताहिक) 1888-1905 (आर० एन० पी० पी०)

स्टेट्समैन, हेमंत प्रसाद घोष द्वारा संकलित अखबार की कटिंग.

दि टाइम्स (लंदन) (छिटपुट प्रतियां).

टाइम्स आफ इंडिया, 11 और 18 मार्च 1896.

वायस आफ इंडिया बंबई 1883-89. न्यू सिरीज, 1901-1904 (वी० ओ० आई०)

गौण स्रोत

ऐंस्टे वीरा : दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया, (लंदन 1949), तृतीय संस्करण.

बेडेन पावेल, बी० एच० : ए शार्ट एकाउंट आफ दि लैंड रैविन्यू ऐंड इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया विद ए स्कैच आफ दि लैंड टैन्योर (आक्सफोर्ड 1894).

बागल, जे० सी० : हिस्टरी आफ दि इंडियन एमोमिएशन 1876-1951. (कलकत्ता, 1953).

बालफोर, लेडी बी० : दि हिस्टरी आफ लार्ड लिटंस इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन, 1876-80, (लंदन 1899).

बैनर्जी, पी० एन० : फिस्कल पालिसी इन इंडिया (कलकत्ता 1922). ए हिस्टरी आफ इंडियन टैक्सेशन (कलकत्ता 1930).

बैनर्जी, एस० एन० : ए नेशन इन मेकिंग, (कलकत्ता 1925).

बैरन पाल ए० : दि पोलिटिकल इकोनामी आफ ग्रेथ, (इंडियन एडिशन, न्यू दिल्ली 1957).

बसु, बी० डी० : दि रूइन आफ इंडियन ट्रेड ऐंड इंडस्ट्रीज, (तृतीय संस्करण, कलकत्ता 1935).

भाटिया, बी० एम० : फौमिस इन इंडिया 1860-1945, (बंबई 1963)

बांबे फैक्टरी लेबर कमीशन—रिपोर्ट 1885 (बंबई).

बोस, बिपिन कृष्ण : स्ट्रे थाट्स आन सम इंसीडेंट्स आफ माई लाइफ (कलकत्ता, 1919).

बुकानन, डी० एच० : दि डेवलपमेंट आफ कैपटलिस्टिक इंटरप्राइज इन इंडिया, (न्यूयार्क, 1934).

बुकलेंड, सी० ई० : बंगाल अंडर दि लैफ्टिनेंट गवर्नर 1854-1898, 2 खंड (कलकत्ता, 1901).

चबलानी, एच० एल० : स्टडीज इन इंडियन करेंसी ऐंड ऐक्सचेंज (बंबई 1931).

चमनलाल, डी० : कुली, दि स्टोरी आफ लेबर ऐंड कैपिटल इन इंडिया, 2 खंड, (लाहौर 1932).

चंद्रा, भोलानाथ : राजा दिगंबर मित्र, खंड-1 द्वितीय संस्करण, 1896, खंड-2 (कलकत्ता, 1906).

चिसने, जनरल जार्ज : इंडियन पालिटी (तृतीय संस्करण, लंदन 1904).

चौधरी, आर० : दि इवाल्याशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, (कलकत्ता 1939).

चितामणि, सी० वाई० : इंडियन पालिसीज सिस दि म्यूटिनी, (इलाहाबाद 1937), 1947 का पुनः मुद्रण.

क्लो, ए० जी० : इंडियन फैक्टरी लैजिस्लेशन, ए हिस्टोरिकल सर्वे इंडियन इंडस्ट्रीज ऐंड लेबर की बुलेटिन सं० 37 (कलकत्ता 1926).

कोयाजी, जे० सी० : दि इंडियन करेंसी सिस्टम 1835-1926 (मद्रास 1930).

डकोस्टा, जान : फैक्ट्स ऐंड फैलिसीज रिगार्डिंग इरिगेशन एज ए प्रिवेंटिव आफ फैमिन इन इंडिया, (लंदन 1878).

दास, आर० के० : फैक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया. (बर्लिन 1923) दि लेबर मूवमेंट इन इंडिया, (बर्लिन 1923); प्लाटेशन लेबर इन इंडिया (कलकत्ता 1931); हिस्टरी आफ इंडियन लेबर लैजिस्लेशन, (कलकत्ता 1931).

डेविस, सी० कोलिन : दि प्रॉब्लम आफ दि नार्थ वेस्ट फंटियर, 1890-1908 (केंब्रिज 1932).

डिगबी, विलियम : 'प्रास्पेयरस' ब्रिटिश इंडिया, (लंदन 1901).

फारेस्ट. जी० डब्ल्यू० : ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मारकिंस आफ लेंसडौन ऐज वायमराय ऐंड गवर्नर जनरल आफ इंडिया 1888-1894 (कलकत्ता 1894).

फेसर लावेट : इंडिया अंडर कर्जन ऐंड ग्राफटर (तृतीय संस्करण, लंदन 1912).

गाडगिल, डी० आर० : दि इंडस्ट्रियल इवाल्याशन आफ इंडिया इन रीसेंट टाइम्स, (चतुर्थ संस्करण, कलकत्ता 1948).

घोष, पी० सी० : दि डेवलपमेंट आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1892-1909 (कलकत्ता 1960).

गोपाल, एस० : दि वायसरायल्टी आफ लाई रिपन 1880-1884. (लंदन 1953).

गोपालकृष्णन, पी० के० : डेवलपमेंट आफ इकोनामिक आइडियाज इन इंडिया 1880-1950, (नई दिल्ली, 1959).

गुप्ता, जे० एन० : लाइफ ऐंड वर्क आफ रोमेश चंद्र दत्त, (लंदन 1911).

हेमिल्टन, सी० जे० : दि ट्रेड रिलेशंस ब्रिटवीन इंग्लैंड ऐंड इंडिया (1600-1896), (कलकत्ता 1919).

होमलैंड, जान एस० : गोपालकृष्ण गोखले, (कलकत्ता 1933).

ह्यूम, ए० ओ० : हिट्स आन ऐभीकल्चरल रिफार्म इन इंडिया, (कलकत्ता 1879).

हंटर, डब्ल्यू० डब्ल्यू० : दि मारकिस आफ डलहौजी (आक्सफोर्ड 1895).

इंडियन इकोनामिक जनरल 1953.

इंवीरियल गजेटियर आफ इंडिया, खंड-3 1908 खंड III 1908 (आक्सफोर्ड)

इंडियन फैक्टरी लेबर कमीशन रिपोर्ट 1890.

इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट 1918, कलकत्ता.

इंडियन जनरल आफ इकोनामिक्स, 1916

इंडियन नेशन बिल्डर्स 3 भाग (गणेश एंड कंपनी मद्रास द्वारा प्रकाशित, तिथि निर्देश नहीं).

जगतियानी, एच० एम० : दि रोल आफ दि स्टेट इन दि प्रोविजन आफ रेलवेज (लंदन 1924).

जॅक्स लिलेंड हैमिल्टन : दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपीटल टु 1875 (न्यूयार्क 1927).

काले, बी० जी० : गोखले एंड इकोनामिक रिफार्म (पूना 1916).

करंदीकर, एस० एल० : लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, (पूना 1957).

कर्बे, डी० जी० : रानाडे, दि प्राफिट आफ लिबरेटेड इंडिया, (पूना 1942)

केलाक, जेम्स . महादेव गोविंद रानाडे, (कलकत्ता 1926), लंदन

केन्स, जे० एम० : इंडियन करेंसी एंड फाइनांस (1924), 1913 के लंदन संस्करण पुनः मुद्रित संस्करण

नौल्स, एल० सी० ए० : दि इंडस्ट्रियल ऐंड कर्मशल रिवाल्याशन इन ग्रेट ब्रिटेन इयूरिंग दि नाइनटीथ संचुरी, (लंदन 1927) दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ दि ब्रिटिश ओवरसीज एंपायर (लंदन 1928)

कुजनेत्स, एस० एंड अदर्स : इकोनामिक ग्रोथ : ब्राजील, इंडिया, जापान, (इरहाम, एन० सी० 1955)

किड, जे० सी० : ए हिस्टरी आफ फैक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया, (कलकत्ता 1920)

लोवेट, वर्नी : ए हिस्टरी आफ दि इंडियन नेशलिस्ट मूवमेंट, (लंदन 1920)

लायल, आलफ्रेड . लाइफ आफ दि मारकिस डफरिन ऐंड आवा, 2 खंड (लंदन 1905).

मजुमदार, बी० बी० : हिस्टरी आफ पोलिटिकल थाट फ्राम राममोहन टु दयानंद (1821-84), खंड-1 (बंगाल, कलकत्ता 1934).

मलहोत्रा, डी० के० : हिस्टरी ऐंड प्राबल्म्स आफ इंडियन करेंसी, 1835-1945 (तृतीय संस्करण, लाहौर 1945).

मनकर, जी० ए० : ए स्केच आफ दि लाइफ ऐंड वर्क्स आफ दि लेट मिस्टर जस्टिस एम० जी० रानाडे, 2 खंड, (बंबई 1902).

मसानी, आर० पी० : दादाभाई नौरोजी, दि ग्रांड ओल्डमैन आफ इंडिया, (लंदन 1939).

मजुमदार, ए० सी० : इंडियन नेशनल इवाल्याशन, (मद्रास 1915).

मार्क्स, के० और एंगल्स, एफ० : आन कोसोनियलिज्म, (मास्को, तिथि नहीं).

- मेहता, एस० डी० : दि इंडियन काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, (बंबई 1953).
- मिट्जलेर, लायड ए० : दि थ्योरी आफ इंटरनेशनल ट्रेड, ए सर्वे आफ काटेंम्पररी इको-नामिक्स, हारवर्ड एस एलिस, द्वारा संपादित. (फिलाडेल्फिया, 1948).
- मिल, जान स्टुअर्ट : प्रिंसिपल्स आफ पोलिटिकल इकोनामी (लंदन 1920).
- मिश्र बी० बी० : दि इंडियन मिडिल क्लासेज, (लंदन 1961).
- मिश्र, बी० आर० : लंड रैविन्यू पालिसी इन दि युनाइटेड प्राविसेज अंडर ब्रिटिश रूल (बनारस 1942)
- मित्रा, ए० : संसद आफ इंडिया 1951 खंड-6 वेस्ट बंगाल, सिक्किम और चंद्रनगर भाग-1 ए रिपोर्ट (दिल्ली, 1953).
- मोदी, एच० पी० : सर फिरोजशाह मेहता : ए पोलिटिकल बायोग्राफी 2 खंडों में (बंबई 1921).
- मोरिसन, थियोडर : दि इकोनामिक ट्रांजीशन इन इंडिया, (लंदन 1916). 1911 के संस्करण का पुनः मुद्रण
- मुकर्जी, राधाकमल : लंड प्रावलम्स आरु इंडिया, (लंदन 1933).
- मुख्तार अहमद : फैंक्टरी लेबर इन इंडिया, (मद्रास 1930).
- मुरदोच जान : फैंमिन, फैंक्ट्स ऐंड फैलेमीज, (निधि रहित).
- नियोगी, जे० पी० : दि इवान्यूशन आफ इंडियन इनकम टैक्स, (लंदन 1929).
- पैसा फड मिल्बर जुबली नंबर (गुना 1935)
- पाल, विपिनचंद्र : मिमोरीज आफ माई लाइफ ऐंड टाइम, 2 खंडों में (कलकत्ता, 1932 और 1951).
- पालेकर, एन० ए० : ट्रेड इन इंडिया (बंबई 1944).
- प्रसाद, आई० दुर्गा : सम असपेक्ट्स आफ इंडियन फारेन ट्रेड 1757-1893, (लंदन 1932)
- पिल्लई, पी० पी० : इकोनामिक कंडीशंस इन इंडिया (लंदन 1925).
- प्रधान, जी० पी० और भागवत, ए० के० : लोकमान्य तिलक (बंबई 1958).
- पुणेकर, एम० डी० : ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, बंबई 1948.
- रामगोपाल : लोकमान्य तिलक (बंबई 1956)
- राव, वी० के० आर० वी० : टैक्सेशन आफ इनकम इन इंडिया (कलकत्ता 1931); एन एस्से आन इंडियाज नेशनल इनकम 1925-29 (लंदन 1939).
- दि नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया 1931-32, (लंदन 1940).
- राय, परिमल : इंडियाज फारेन ट्रेड सिम 1870, (लंदन 1934).
- रीस, जे० डी० : दि रियल इंडिया (द्वितीय संस्करण, लंदन 1908).
- रिकार्डो, डेविड : दि प्रिंसिपल आफ पोलिटिक्स इकोनमी ऐंड टैक्सेशन. (एवरीमैन्स लाइब्रेरी, लंदन 1943)
- रोल एरिक : ए हिस्टरी आफ इकोनामिक थाट : संशोधित संस्करण, (न्यूयार्क 1947).
- राय, पार्वती चरण : दि रेंट क्वेश्चन इन बंगाल (कलकत्ता 1883).

सान्याल, एन . डेवलपमेंट आफ इंडियन रेलवेज (कलकत्ता 1930)

सान्याल, रामगोपाल . ए जनरल बायोग्राफी आफ बंगाल सिलिब्रिट्रीज, (कलकत्ता 1889)

शाम्श्री, शिवनाथ मेन आई हैव सीन (कलकत्ता 1919)

सेन, अमित . नोट्स आन दि बंगाल रिनोमिया (द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 1957)

शाह, के० टी० . मिक्सटी डयर्स आफ इंडियन फाइनाम (बंबई 1921)

शाह, के० टी० और खभात के० जी० . वेल्थ ऐंड टैक्समबल कैपसिटी आफ इंडिया (बंबई 1924)

शिलवंबर, के० एम० . दि प्रब्लम आफ इंडिया (नदन 1940)

शिरास, जी० एफ० . पावर्टी ऐंड रिड्डेड इकानामीय प्रब्लम्स इन इंडिया (1935 तृतीय संस्करण)

सिंह, हीरालाल . प्रब्लम्स ऐंड पालिमीज आफ दि ब्रिटिश इन इंडिया 1885-1898 (बंबई 1963).

सीतारामैया, बी० पट्टाभि दि हिस्टरी आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885-1935 (मद्रास 1935)

स्मिथर, परसीवल इंडिया, ए माडर्न हिस्टरी (ऐन जॉर्जर 1961)

स्टेटिस्टिकल ऐक्सट्रैक्ट फार ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1891-2 टु 1900-01

स्टोक्स, एरिक दि इंग्लिश यूटिलिटीरियन ऐंड इंडिया (आक्सफोर्ड 1959).

स्ट्रैची जान और स्ट्रैची रिचर्ड दि फाउन्डेशन ऐंड पब्लिक वर्क्स आफ इंडिया फ्रॉम 1869 टु 1881 (नदन 1882)

ए० गुप्त (मपा०) स्टडीज इन दि बंगाल सिनेमा (कलकत्ता जादवपुर 1958).

तहमक़र डी० बी० चोखमान्य निलक (नदन 1956)

थाम्प्रसन ई० और गैरेट जी० टो० राइज ऐंड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया (नदन, 1935)

थामस, पी० जे० ग्राथ आफ फेडरल फाइनाम इन इंडिया (मद्रास 1939)

थानर, डेनियल : इन्वेस्टमेंट इन एंपायर (फिलाडेल्फिया, 1920)

तिवारी, शार० डी० . रेलवेज इन माडर्न इंडिया (बंबई, 1941)

वकील, सी० एन० और मुराजन एस० के० करेमी ऐंड प्राइमेज इन इंडिया (बंबई 1927).

वकील, सी० एन० . फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स इन माडर्न इंडिया (बंबई 1925)

वाडिया, पी० ए० और मर्चेन्ट के० टी० . अवर इकानामिक प्रब्लम (द्वितीय संस्करण बंबई 1946)

अनुक्रमणिका

अंतरदेशीय उत्सवाम अधिनितम, 313	220, 263, 286, 291, 292, 294,
अंतराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी मोडिक सिद्धांत, 249	295, 301, 319, 321, 370, 387,
अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 297	391, 399, 404, 405, 443, 446,
अंतराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, 608,	452, 457, 458, 460, 462, 464,
610, 611	466, 467, 472, 479, 513, 530,
अकबर, 14, 513	531, 532, 544, 576, 582, 592,
अकाल, 14, 22, 23, 139, 140, 171,	596, 609, 615, 639, 660
173, 213, 257, 391, 451, 515,	अय्यर एम० ए० स्वामीनाथन, 464
534, 574, 577, 592	अय्यर जी० मुन्नहय्य, 9, 86, 93, 126,
अकाल आयोग, 96, 155, 457	128, 133, 141, 158, 159, 160,
अखबारे आम, 101, 409	161, 164, 165, 250, 286, 305,
अखबारे सौदागर, 291	316, 323, 324, 364, 419, 542,
अनीमे हिंद, 403	576, 588, 636, 639, 641, 642,
अनुग्रह पोषित चीनी, 211, 212, 213,	645, 648, 671
215	अरुणोदय, 203, 292
अफगान युद्ध, 195, 521, 602	अलबर्ट बिल, 398
अफीम कर, 478, 481	अवध की ताल्लुकेदारी पद्धति, 365
अफीम राजस्व, 478, 479, 480, 481,	अवध पंच, 139, 389, 403
482	अवध रेंट ऐक्ट, 402
अफीम व्यापार निरोध संच, 478, 481	अ० प० श्रम और उत्पन्नवास बिल, 314, 315,
अफीम लगान, 479	317
अमृतबाजार पत्रिका, 3, 48, 100, 101,	आगरकर, जी० बी०, 291, 396
132, 138, 171, 197, 209, 212,	आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन, 665
	आनंदबाजार पत्रिका, 102, 398, 399,

- 480
 आबकारी नीति, 475
 आयगार बी० आर, चक्रवर्ती, 457, 458,
 आयकर, 15, 16, 450, 453, 455, 456,
 457, 458, 459, 461, 462, 472,
 474, 669
 आयकर बिल, 456
 आयात शुल्क 194, 196, 197, 202,
 203, 204, 207, 220, 471, 669.
 आर्थिक आंदोलन, 663, 672
 आर्थिक राष्ट्रीयतावाद का युग, 665
 आर्थिक साम्राज्यवाद, 666
 आय जन पररूपालिनी, 101
 आपादा, 102
 इंग्लिश फैक्टरी कानून, 296
 इंडियन एमामिशन, 213, 261, 309,
 310, 311, 395, 450, 459, 518,
 इंडियन रेन्सी एमोमिशन 247, 265,
 इंडियन कोमिल अधिनियम, 542
 इंडियन टैरिफ बिल, 220
 इंडियन डेली मेल, 403
 इंडियन नेशनल एमामिशन, 101
 इंडियन पालिटी, 443
 इंडियन पीपुल 91
 इंडियन पोलिटिकल एसोसिएशन, 537
 इंडियन फैक्टरी ऐक्ट, 290, 292, 295,
 297, 298, 303
 इंडियन माटम ऐक्ट, 303
 इंडियन माटम बिल, 302, 317
 इंडियन मोशल रिफार्मर, 523
 इंडियन एमिग्रेशन बिल, 309
 इंडिया कोमिल 534
 इंडिया लीग, 62
 इंदु प्रकाश, 99, 158, 174, 212, 292,
 299, 300, 305, 363, 454, 457,
 462
 इंपीरियल अखबार, 101
 इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसिल, 140,
 212, 213, 293, 443, 515, 537,
 540, 542, 543, 545
 ईडन एशले, 397
 ईस्ट इंडिया कंपनी, 54, 93, 153, 193,
 205, 350, 369, 523, 575, 586,
 602
 ईस्ट इंडिया एमोमिशन, 196, 573,
 741
 उग्रवादी दल, 3
 उग्रवादी नेता, 612
 उत्तर पश्चिम की महलवादी पद्धति, 365
 उत्तर पश्चिम प्रांतीय लगान अधिनियम,
 402
 उत्पादन शुल्क, 15, 204, 205, 210,
 453, 460, 474
 उत्पादन शुल्क की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया,
 210
 उद्योग मिद्वान, 612, 613
 उन्मुक्त व्यापार, 193, 195, 212
 उन्मुक्त व्यापार के मिद्वान, 193, 218
 उपराशनकारी, 400, 401, 402
 उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था, 666
 ऊचा कगधान, 16, 87, 518, 611, 669
 एटकिंसन, फ्रेड० जे०, 7, 14
 एमिग्रेशन ऐक्ट, 310, 311
 एलगिन, लार्ड 152, 157, 163, 203
 एलोट, सर चार्ल्स, 7
 ऐंड्रयूज, सेंट, 18
 औद्योगिक पूजी, 95
 औद्योगिक पूजीपति वर्ग, 306,
 औद्योगिक पूजीवाद, 288, 671
 औद्योगिक पूजीवादी अर्थव्यवस्था, 642
 औद्योगिक संघ, 67
 औद्योगिक सम्मेलन, 67

- कपास आयात कर, 195, 196, 197, 198, 199
 कपास और चीनी पर शुल्क संबंधी सरकारी नीति, 193
 कपास कर का पूर्ण निवर्तन, 197, 200
 कपास कर के निवर्तन का विरोध, 197, 198
 कपास शुल्क, 194, 202, 203, 211, 251
 कपास शुल्क बिल, 209
 कपास सीमा शुल्क, 108, 482
 कड़का, सोराबजी, 266
 कर्जन, लार्ड, 7, 12, 22, 51, 82, 86, 87, 91, 93, 94, 160, 163, 174, 175, 216, 217, 219, 315, 351, 360, 361, 364, 365, 367, 368, 520, 614
 करदाता, 454
 करनोमदार पट्टेदार, 403
 कर्वे, डी० जी०, 637
 कराची सिंध सभा, 518
 कराधान, 60, 446, 447, 449, 450, 452, 457, 458, 460, 462, 467, 471, 512, 513, 515, 541, 577, 614, 667
 करेसी कमेटी, 253
 काटन, हेनरी, 314
 कायस्थ समाचार, 171, 323, 544
 कार्नवालिस, लार्ड, 364
 काले, ए० डी०, 67
 काले, के० बी०, 106
 काले, वी० जी०, 218
 काश्तकारी कानून, 394, 396, 401
 किचनर, लार्ड, 524
 किचनर-कर्जन मतभेद, 524
 किसान जनसभाएं, 396
 किसान संघ, 396
 किमान समर्थक राष्ट्रवादी नेता, 401
 किमानो की फिजूलखर्ची, 21
 किसानो के मौखी हक, 393
 केन, डब्ल्यू० एम०, 480, 536
 कनेडी, प्रिगल, 468, 473
 केरल चट्टिका, 403
 केरल सचारी, 403
 केम, जे० एम०, 245
 केमर-ए-हिंद, 172, 260, 316, 391, 459
 केमरी, 5, 208, 305, 316, 358, 405, 419, 442, 446, 465, 471, 519, 530, 531
 कोयला खानो के श्रमिक, 302
 क्रयशक्ति, 17
 क्लामिकी अर्थव्यवस्था, 640, 644
 खपदे, जी० एस०, 474
 खरे, डी० ए०, 410
 खा शेख राजा हुसैन, 363
 खादी आंदोलन, 108
 खान उद्योग, 302, 304
 खान कानून, 304
 खामिस-उल-अखबार, 208
 खेतिहर वर्ग, 6, 12, 13, 16, 53, 349, 352, 353, 355, 397, 406, 408, 409, 449
 खोसले, जी० के०, 205
 गागुली, द्वारिकानाथ, 310, 311, 396
 गांधी, महात्मा, 58, 466
 गांधी युग की राष्ट्रीयता, 618
 गुजरात दर्पण, 263
 गुजरात मित्र, 459
 गैर खेतिहर जमींदारी, 408
 गैर मौखी किसान, 393, 394, 398, 399, 400

- गोखले, गोपालकृष्ण, 12, 13, 14, 97, 133, 152, 210, 252, 254, 256, 257, 262, 263, 410, 411, 412, 413, 443, 444, 448, 450, 451, 452, 466, 470, 471, 514, 516, 519, 522, 523, 525, 528, 531, 538, 539, 542, 543, 544, 546, 576, 589, 590, 596, 604, 618, 660 664, 671
 ग्रामीण ऋणग्रस्तता, 404 409, 411, 412, 541
 ग्रामीण ऋणदाता साहकार, 404
 ग्रामीण कर्जदार, 404, 405
 ग्रामीण दरिद्रता, 413
 ग्रेट इंडिया पेनिमुला रेलवे कंपनी, 153
 ग्रैंडमन, 199
 घोष, एल० एम०, 671
 घोष, एम० के०, 291, 481, 664
 घोष, जोगेंद्रचंद्र, 310
 घोष, मोतीलाल, 132, 291, 362, 530, 664
 चद्र, भोलानाथ, 2, 133, 135, 199, 200
 चंद्रावरकर एन० जी०, 205, 208
 चटर्जी, बकिमचंद्र, 389
 चमनलाल, डी०, 290
 चर्चिल, लार्ड रडोल्फ, 527, 616
 चांदी चदर शुल्क, 220
 चासलर, लार्ड, 244
 चानुर्वर्ण व्यवस्था, 65
 चाय उद्योग, 308
 चाय बागान, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314
 चाय बागान श्रमिक, 310
 चाय बागों में मृत्यु की ऊंची दर, 312
 चारलू, पी० आनंद, 209, 216, 307, 317
 चितामणि, सी० वाई०, 458
 चिसनी, जनरल, 445, 665
 चीनी शुल्क, 213, 214, 216, 217
 चीनी शुल्क अधिनियम, 215, 216 217 218
 चीनी शुल्क के विरोधी, 213
 चीनी शुल्क मशोधन अधिनियम, 218
 चीनी शुल्क के समर्थक, 214
 चुगीकर, 208
 चुकंदर चीनी का आयात, 211
 चैपमैन, जान, 157
 चौधरी, जे०, 104
 छोटे किसान तथा मजदूर, 12
 जनता पार्टी निधि, 67
 जन प्रस्ताव पत्र, 99
 जनसंख्या की वृद्धि, 19, 20
 जमींदारी तथा ग्रैनबारी पट्टे, 362
 जमींदारी विरोधी विप्लव, 392
 जरनल आफ पूना सार्वजनिक सभा, 1, 4, 351, 402, 468
 जामे-जमशेद, 292, 321
 जोशी, जी० बी०, 2, 9, 14, 19, 20, 21, 53, 55, 63, 67, 90, 92, 93, 97, 99, 128, 132, 133, 136, 137, 156, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 351, 356, 357, 390, 391, 413, 418, 443, 446, 448, 449, 451, 458, 459, 460, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 514, 516, 518, 525, 530, 537, 542, 576, 579, 588, 589, 590, 596, 638, 640, 641, 643, 644, 645, 648, 660, 664

- टाइम्स आफ इंडिया, 113, 299, 351
 टाटा जे० एन०, 62, 266, 450
 टैगोर, जितेंद्रमोहन, 474
 टैगोर, सुरेंद्रनाथ, 320
 ट्रिब्यून, 212, 466
 ठाकरसी, बी० डी०, 254, 266
 ठेका पद्धति, 476
 डफरिन जाच, 18
 डफरिन, लाड, 6, 465, 472, 613
 डलहौजी, लाड, 154, 581
 डाक कर, 15
 डान, 411, 417
 डिगबी, विलियम, 7, 671
 ढाका प्रकाश, 402
 तिब्बत अभियान, 521
 तिलक, लोकमान्य, 5, 66, 67, 103, 104, 158, 210, 292, 319, 349, 357, 364, 396, 419, 465, 481, 512, 514, 519, 531, 538, 612, 660, 671
 तैलंग, के० टी०, 66 291, 448, 638 645, 646, 647
 तोहफा-ए-हिंद, 403
 थामस, पी० जे०, 361
 दकन ऐग्रीकलचार्जिस्ट बिल, 407
 दकन सभा, 410
 दक्षिण के खेतिहरों के दगें, 349
 दक्षिण भारत की रैयतबारी पद्धति, 365
 दत्त, आर० सी०, 2, 3, 52, 128, 132, 139, 142, 168, 172, 173, 200, 205, 241, 247, 248, 256, 257, 259, 305, 311, 316, 349, 351, 355, 356, 359, 360, 361, 365, 366, 368, 369, 389, 390, 397, 448, 458, 479, 544, 575, 579, 580, 583, 584, 591, 594, 605, 614, 515, 638, 648, 649, 660, 664
 देशमुख, गोपालराव, 98
 देमाई, अबालाल, शंकरलाल, 254, 266
 देसी तिजारत कंपनी, 66
 दैनिक-ओ-समाचार चंद्रिका, 158, 203
 नडी, एल्फ्रेड, 14
 नबूदरी जमीदार, 403
 नमक कर, 15, 450, 453, 456, 458, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468 469, 471, 472, 473, 474, 542, 669
 नमक कर विरोधी आंदोलन, 470
 नमक पर कराधान की पद्धति, 463
 नया मजदूर वर्ग, 325
 न्याय सुधा 402
 न्यू इंडिया, 3, 312, 322, 323, 458, 460 640
 नवविभाकर 399, 401
 नशाबारी, 476
 नसीमे आगरा, 101, 403
 नाटिगेल प्लारम, 394
 नानु, बी० आर०, 364
 नाम जोशी, एम० बी०, 67, 102
 नायर त्रिचोलिंग, 403
 नार्थगुरु, लाड, 195
 निकासीवाद, 597, 618
 निकासी सिद्धांत, 572, 573, 574, 575, 576, 584, 591, 594, 597, 598, 599, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 615, 616, 617
 ेजी पूजा का निवेश, 355
 निरकुशतावाद, 664
 निर्धनता का औद्योगिक सिद्धांत, 611
 निर्यात व्यापार, 17
 निश्चय पत्रिका, 99

- नृलकर, राव बहादुर के० एल० 198
 नेटिव ओपीनियन 99, 101, 165, 173,
 292, 293, 299, 305, 418, 573
 नेशनल लिबरल फेडरेशन, 575
 नैयर, सी० शंकरन, 528
 नोल्म, एल० सी० ए० 597
 नौरोजी दादाभाई, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
 15, 17, 65, 84, 88, 89, 90, 92,
 106, 128, 130, 131, 138, 142,
 158, 160, 247, 249, 252, 253,
 258, 259, 261, 265, 290, 305,
 306, 444, 447, 448, 449, 451,
 458, 463, 468, 477, 479,
 481, 512, 514, 516, 522, 523,
 526, 528, 530, 532, 535, 536,
 544, 572, 573, 575, 577, 578,
 579, 581, 582, 584, 585, 586,
 587, 588, 589, 590, 591, 592,
 593, 594, 596, 603, 606,
 607, 608, 609, 610, 615, 616,
 618, 660, 664, 671, 674
 पञ्चात्र पब्लिकेशन ऐक्ट, 488, 410
 पञ्चात्र साक्षरकारी अधिनियम, 402
 पञ्चात्र भूमि संधरण विन, 409
 पतुलु बी० एम०, 464
 पगजय एम० एम०, 527
 पटसन, 59
 पट्टेदारी प्रथा, 362, 366, 416, 668
 पबना एगे, 349
 परिवहन क्रांति, 158, 159
 परोक्ष करगणन, 349
 पाण्डे, सर जार्ज, 83
 पारिख, गोकुलदाम के०, 351, 410
 पाल, क्रिस्तोदाम, 394, 463
 पाल, विपिनचंद्र, 3, 82, 85, 312, 317,
 332, 612, 640, 671
 पिट्स ऐक्ट, 367
 पिन्नेई, पी० रत्न सभापति, 403
 पूजी की निकासी, 662
 पूजीनिष्ठ बारखाना पद्धति, 305
 पूजीपन्थी औद्योगिकता, 326
 पूना वैभव, 102
 पूना सांस्कृतिक सभा, 2, 58, 97, 99,
 169, 198, 202, 261, 292, 293,
 407, 410, 450, 455, 516, 518,
 596
 पेटिट दिनगा, 472, 473, 474
 पैसा अखबार, 101, 104
 पैसा निधि, 66, 67
 प्रभाकर, 98
 प्रतिव्यक्ति आय, 13
 प्रथम औद्योगिक सम्मेलन, 614
 फडके का विद्रोह, 349
 फडके, वामुदेव, 99
 फाउलर कमेटी, 168, 247
 फाउलर, हेनरी, 3, 245, 445
 फाकड, बालाजी रामचंद्र, 290
 फ्रेजर, 361
 बगवामी, 9, 7, 102, 137, 203, 210,
 219, 389, 399, 402
 बगाल का ग्रेट गेट, 368
 बगाल का विभाजन, 98
 बगाल काश्तकारी बान्न्, 392, 416
 बगाल की जमींदारी पद्धति, 365
 बगाल के स्थाई बंदाबस्त, 361, 365
 बगाल बैंकिंग निगम, 66
 बगाल में किसान संगठन, 391
 बगाल में स्वदेशी आंदोलन, 98
 बगाली, 91, 128, 161, 199, 200, 201,
 207, 212, 251, 257, 291, 292,
 301, 305, 309, 310, 311, 315,
 380, 391, 395, 396, 399, 401

- 402, 458, 459, 462, 464, 472, 490
- बंगाली, एस० एस०, 291, 292, 298
- बंगाली रिपोर्ट, 10
- बंबई फैक्टरी आयोग, 297
- बंबई मिल बोर्ड एसोसिएशन, 265, 304
- बंबई समाचार, 292
- बर्मा-युद्ध, 604
- बरवे, एन० बी०, 467
- बहादुरजी, के० एन०, 299
- बहिष्कार आंदोलन, 103, 105, 107
- बागान उद्योग, 83
- बागान श्रमिक, 308, 668
- बागान श्रमिकों की दुर्दशा, 307
- बाबे फैक्टरी लेबर कमिशन, 287, 288, 291, 292, 304
- बिन्नी कर, 16
- बिचौलिया, 17, 399, 400
- बिहार हेराल्ड, 534
- बेयरिंग, मेजर, 12, 197
- बेलगाव समाचार, 199
- बैनर्जी, के० सी०, 63, 402
- बैनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, 9, 51, 62, 66, 91, 104, 196, 200, 206, 261, 262, 263, 291, 301, 305, 311, 364, 395, 396, 402, 443, 445, 452, 458, 481, 533, 534, 576, 579, 584, 660, 671
- बोध समाचार, 465
- बोस, ए० एम०, 63, 66, 396, 531, 542, 671
- बोस, विपिन कृष्ण, 99
- ब्रह्म समाज, 309
- ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 292, 295, 309, 479, 531
- ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 93, 518
- ब्रिटिश कर नीति, 219
- ब्रिटिश पूजा, 83, 154, 243
- ब्रिटिश फैक्टरी ऐक्ट, 291
- ब्रिटेन की पूजा का भारत में निवेश, 616
- बूमलम सम्मेलन, 244
- भाप री गाइडिया, 152
- भारत का आर्थिक पिछड़ापन, 662
- भारत का रचना मान, 53
- भारत का ग्रामीकरण, 52
- भारत की जनसंख्या, 18
- भारत का टूट खसोट, 83
- भारत का विदेशी बाजार, 52
- भारत गैज़ट 159, 459
- भारत 'ग्रैन व्यापार प्रतिभागिता, 54
- भारत गैज़ट, 102, 399
- भारत - व्यापारिक, 56
- भारत में आधुनिक चीनी उद्योग, 214
- भारत में फैक्टरी कानून 289, 295, 305
- भारत सरकार की मुद्रा नीति 242
- भारत में जनसंख्या 18
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर रत्ना का वास्तविक प्रभाव, 163
- भारतीय उद्योग आयोग, 612
- भारतीय वण्डा उद्योग, 197, 198, 199, 206
- भारतीय सरकार, 249
- भारतीय मजदूरों और गांवों की हस्तकलाओं एवं हस्तशिल्प का क्षय, 51
- भारतीय चीनी उद्योग, 215, 216, 217
- भारतीय सामाज्य आदर्श, 64
- भारतीय पूजा, 84, 87, 87, 170
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 4, 13, 18, 55, 61, 63, 91, 92, 108, 207, 209, 246, 247, 248, 254, 261, 299, 310, 315, 317, 323, 351, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366,

- 367, 388, 405, 443, 446, 448, 451, 457, 461, 464, 465, 468, 476, 515, 516, 519, 522, 526, 530, 535, 536, 538, 539, 540, 544, 545, 576, 582, 596, 610, 611, 613, 615, 646
- भारतीय राष्ट्रीयतावाद, 3, 615, 617, 618, 669
- भारतीय राष्ट्रवादी नेता, 5, 65, 83, 152, 204, 306, 307, 309, 310, 322, 390, 398, 402, 404, 445, 449, 476, 477, 512, 540, 634, 660, 661, 701
- भारतीय रथ पथ का विकास, 155
- भारतीय विनियम, 242
- भारतीय श्रमिक आयोग, 322
- भारतीय श्रमिक की उत्पादकता, 306
- भूमि का स्थाई बंदोबस्त, 651
- भूमि लगान सिद्धांत, 612
- भूमि की पट्टेदारी, 350
- भूराजस्व, 350, 351, 352, 359, 644
- भूराजस्व नीति, 407, 614
- मजदूर महिलाएं, 288
- मदिगा उत्पादन शुल्क, 476
- मदिगा की खपत, 475
- मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 315, 316
- मद्रास महाजन सभा, 516, 518
- मधोलकर, आर० एन०, 60, 134
- मराठा, 101, 104, 105, 170, 171, 172, 201, 208, 210, 212, 220, 248, 256, 259, 291, 300, 302, 305, 319, 320, 321, 363, 387, 389, 392, 396, 397, 407, 412, 410, 457, 462, 466, 472, 527, 530, 639, 660
- मलाबारी, एस० एम०, 458
- मसानी, आर० पी०, 615
- मांचेस्टर, 100, 101, 102, 105, 194, 200, 202, 204, 207, 306, 472, 513
- मांचेस्टर वाणिज्य सदन, 196, 199, 289
- मांडलिक, बी० एन०, 291, 456, 531
- मालवीय, मदनमोहन, 66, 101, 209, 448, 458, 461, 473, 515, 576, 671
- मात्स्यम सिद्धांत, 19
- मारिगम, 211, 212, 214, 215, 216, 217
- मिल, जान स्टुअर्ट, 647
- मिश्र, के० के०, 105, 311, 396
- मिश्र, बी० आर०, 361
- मिश्रित पूँजी समुदाय, 61, 66
- मित्र, नवगोपाल, 99
- मित्र, राजा दिगंबर, 463
- मित्र, विश्वनाथ नारायण, 99
- मुखर्जी, आशुतोष, 459
- मुखर्जी, तारापद, 66
- मुखर्जी, प्यारे मोहन, 394, 472, 474
- मुखर्जी, रगलाल, 396
- मुखर्जी, सतीशचंद्र, 58, 324, 325, 326, 411, 417
- मुद्रा अधिनियम, 246, 254
- मुद्रा नीति, 256
- मुद्रा परिवर्तन, 241, 249, 252, 256, 257, 258
- मुरलीधर, लाला, 102, 140, 405
- मेनन, के० पी० करुणाकर, 389
- मेयो, लार्ड, 445
- मेहता, पी० एम०, 410
- मेहता, फिरोजशाह, 60, 193, 208, 213, 291, 320, 411, 513, 515, 531, 537, 539, 618, 671

- मैकासे, 527, 606, 664
 मैसी, डब्ल्यू० एन०, 154
 मोटे कपड़े पर कराधान का भारतीय
 लोकमत पर प्रभाव, 205
 मोदबूत, 102, 106, 158
 मोपला विद्रोह, 389, 403
 मोरिसन, थियोडोर, 593, 597, 598
 मोरुसी हक, 394, 395, 398, 399, 400,
 402, 417
 मोरुसी हकदार किसान, 401
 यंग बंगाल, 445
 यांत्रिक भौतिकवाद, 670
 यूरोपीय पूजीवाद, 658
 रसडन, आर० डी०, 466
 राघवाचारा, सी० विजय, 403
 राजस्व के स्थाई बंदोबस्त, 360
 रानाडे, महादेव गोविंद, 2, 53, 54, 56,
 57, 60, 64, 66, 90, 91, 93, 94,
 95, 99, 136, 141, 158, 169,
 198, 212, 214, 216, 217, 218,
 246, 290, 304, 351, 352, 355,
 356, 357, 359, 362, 390, 407,
 411, 413, 414, 415, 416, 417,
 446, 481, 575, 595, 596, 605,
 612, 614, 616, 636, 637, 638,
 639, 640, 641, 642, 644, 645,
 664, 671
 राय, पी० सी०, 213, 216, 364, 368,
 390, 418, 450, 527, 576, 579,
 638
 राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, 60, 449
 राष्ट्रीय आंदोलन, 11, 56, 93, 201,
 208, 209, 211, 217, 314, 317,
 361, 473, 477, 529, 572, 578,
 664, 668, 671, 672, 673
 राष्ट्रवादी समाचार पत्र, 311, 320, 388,
 399, 457, 461, 462, 605, 663
 रास्त-गोपतर, 99, 291, 573
 रिकार्डियन सिद्धान्त, 354
 रिकार्डो, 638
 रिपन, लार्ड, 96, 128, 155, 168, 197,
 200, 201, 366
 रीम, जे० डी०, 349, 361, 617
 रेल उद्योग, 162
 रेल नीति, 161, 175
 रेल प्रवर समिति, 165
 रेलों का धानक प्रभाव, 158
 रेलों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण, 175
 रेलवे का निर्माण, 55, 152, 154, 155,
 163, 164, 168, 170
 रैनतवारी इलाके, 388, 391, 644
 रगतवारी पट्टेदारी, 363, 369
 रैनतवारी पद्धति, 358, 362, 363, 366,
 369, 416
 लकागायर, 101, 102, 105, 107, 153,
 194, 198, 202, 203, 204, 205,
 294, 295, 296, 301, 304, 305
 लदन डेली क्रानिकल, 450
 लगान, 353, 392
 लगान का स्थाई बंदोबस्त, 369
 लगान मनाही आंदोलन, 358
 लगान सघ, 396
 लाइसेंस कर, 453, 454, 455, 457
 लाजपतराय, लाला, 66, 611, 671
 लायल दुर्भिक्ष आयोग, 12
 लारेस, जान, 155
 लिटन, लार्ड, 195, 196, 261
 लेड रैवेन्यू अमेडमेट ऐक्ट, 409
 लेंसडोन लार्ड, 19, 175, 260, 261
 लोककर्म शुल्क, 459
 लोकनाथन, पी० एम०, 361
 लोखंडे, 296, 297

- वकील, सी० एन०, 452
 वसु, राजनारायण, 99
 वाचा, डी० ई०, 66, 107, 108, 128, 130, 158, 161, 174, 204, 206, 246, 247, 251, 254, 255, 257, 264, 321, 322, 443, 467, 468, 512, 516, 518, 519, 520, 529, 538, 543, 576, 579, 588, 589, 592, 660, 671, 674
 वाडिया, जे० ए०, 266
 वायम आफ इंडिया, 456
 वित्ते, एम० डी०, 419
 विदेशी पूँजी, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 581, 582, 600, 601, 669
 विदेश व्यापार, 16, 127, 128, 129, 130, 138, 157, 242, 255, 667
 विदेशी सामान का बहिष्कार, 211
 विनायक, देवराव, 417
 विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता, 259, 260, 261, 262, 263, 264
 विनिमय में गिरावट, 243, 244, 245, 250, 267
 विलवी कमीशन, 17, 514, 516, 523, 533, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 586, 589, 590, 604, 606, 608
 विलवी लाई, 586, 587, 605, 608, 610
 वेंकटरमन, जी० 403
 वेडरबर्न, विलियम, 536, 671
 वेस्टलैंड, जेम्स, 204, 443, 464, 469, 541
 शाह, के० टी०, 360
 संजीवनी, 102, 105, 310, 311, 313, 317, 458, 462, 472, 480
 संरक्षित पट्टेदारी, 414
 संसदीय प्रवर समिति, 155, 157
 सखाराम, राघव, 290
 समझौतावादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 665
 सयानी, आर० एम०, 171, 448
 सड़क शुल्क, 459
 सरकारी रेल नीति, 164, 165
 सहचर, 158, 166, 170, 196, 201, 456
 साधारणी, 399
 सामंती अर्धदास, 415
 साहूकारी पूँजी, 95
 सिंचाई कार्य, 171, 172, 173, 174
 सिंचाई आयोग, 174
 सिगनल कर्मचारियों की हड़ताल, 318, 319
 सिन्हा, शचीन्द्रनाथ, 91
 सिलेक्ट कमेटी, 468, 574
 सीमा शुल्क, 15, 16, 195, 204, 453, 467, 482, 666
 सीमा शुल्क नीति, 648, 649, 663
 सुरभि पताका, 301
 सूनी कपडा उद्योग, 84
 सूदखोर, 400
 मैलिसबरी, आर्ड, 193, 194, 195, 196
 मोमप्रकाश, 291, 389, 391, 458, 480
 स्टुअर्ट, जान, 138, 210
 स्थाई बदोबस्त पद्धति, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 391, 392, 393, 397, 668
 स्वदेशी आंदोलन, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 310, 311, 313, 317, 671
 हंटर, सर डबल्यू०, 7

ह्यू म, ए० ओ०, 663, 671

हस्तलिख्य उद्योगों का ह्रास, 52

हार्डिगटन, सार्ज, 196

हार्डिग, सार्ज, 153

हावर्ड, एम० एफ०, 83

हितवादी, 139, 303, 319, 402, 462

हिंदुस्तान, 96

हिंदुस्तान रिव्यू, 171, 323, 544

भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त कागज इस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है.

हिंदुस्तानी, 319, 403, 649

हिंदू, 90, 91, 171, 212, 248, 301, 305, 318, 319, 353, 403, 455,

457, 460, 462, 464, 472, 479,

480, 520, 531, 532

हिंदू पंच, 102, 203

हुसैन, मज्जाद, 389

हैमिल्टन, जार्ज, 1, 12, 252, 660, 665